PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES

1965

(FEBRUARY- MARCH- APRIL SESSION)

VOL. I Nos. 18-24

(PART III)

Dated :-

15th March, 1965

16th March, 1965

24th March, 1965

25th March, 1965 (Morning Sitting)

25th March, 1965(Afternoon Sitting)

26th March, 1965

29th March, 1965

....

Punjab Vidhan Sabha Debates

15th March, 1965

Vol. I—No. 18

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 15th March, 1965

Rs. 0.00 Paise.

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL I, NO. 18, DATED THE 15TH MARCH, 1965.

Read	*For*	*Page*	*Line*
Development	Develoment	(18)38	1
कोआप्रेटिव	को ाप्रेटिव	(18)89	27
एडमिनिस्ट्रेशन	ऐडमिनिस्ट्रशम	(18)90	27
Delete the word 'का'	before the word 'बेटा'	(18)99	8
Delete the word 'ਜਾ'	before the word 'ਤਾਂ'	(18)106	12
ਜੀ	ਜਮੀ	(18)121	1
ਐਨੀਆ	ਅਸੀਆ	(18)121	7
ਕੋਲ	ਕੋਲੋਂ	(18)121	14
ਬੈਡ ਕੈਰੈਕਟਰ	ਬਡ ਕਰਕਟਰ	(18)122	2
ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ	ਅਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ	(18)122	5
ਚਾਹ	ਚਾ	(18)124	20
देखू	देख	(18)125	Last but one
को	के	(18)126	4
पार्लियामेंटेरियन	पार्लियामेंटरियन	(18)126	7
कंस्ट्रक्टिव स्कीम्ज़	कंस्ट्रिक्टव स्कीमज	(18)126	14
ग्रीवेंसिज़	गरीवसिज	(18)126	23
सैशन	शेशन	(18)126	25
उलझ	उलझा	(18)126	31
बनाने	बनने	(18)128	30
सम्भाली	सभाली	(18)128	31

Read	For	Page	Line
Janta	yanta	(18)131	19
vigilant	vigilent	Appendix (vii)	29 from below
inherent	inherant	vii	26 from below
Allegations	Allegtions	xix	1
partisan	pertisan	xxi	4
corruption	curruption	xxiv	8 from below
possession	possessed	xxxi	24
Asthan	Astan	xxxii	14
crippled	cripplied	xxxv	37
forgeries	foregeries	xl	5 from below
by	bv	xliii	16
Shrimati	Shrimti	xlvi	11

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 15th March, 1965

The Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh, at 2.00 *p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS
*SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No. 7268

श्री मंगल सेन : मुख्य मन्त्री महोदय ने इस सवाल के उत्तर में कहा है कि इन्होंने 95 दिन और 90 रातें दिल्ली में काटी हैं और यह कहा है कि आप वहां पर मुख्तलिफ कामों के लिये गए थे, कुछ पब्लिक कामों के लिये और कुछ प्राइवेट मीटिंगज़ के लिये वहां पर गए थे। तो क्या वह इस बात पर रोशनी डालेंगे कि वह प्राइवेट मीटिंग्ज़ कौन सी थीं ?

मुख्य मन्त्री : वह सारे के सारे आफीशियल फंक्शन्ज़ थे।

श्री मंगल सेन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मुख्य मन्त्री जी ने जवाब पढ़ा नहीं। इस लिस्ट के नम्बर 16 पर लिखा है कि प्राइवेट मीटिंग थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह प्राइवेट मीटिंग किस सिलसिले में थी ?

श्री अध्यक्ष : 16 नम्बर देख लें। (The hon. Chief Minister may please refer to Sr. No. 16 of the statement.)

मुख्य मन्त्री : मैं ने देख लिया है। उस दिन आफीशियल फंक्शन भी था। मगर चूंकि उस दिन एक प्राइवेट फंकशन भी था इस लिये मैंने प्राइवेट ही दिखाया है और टी० ए० चार्ज नहीं किया।

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, पीछे जब यहां पर कांग्रेस असैम्बली पार्टी की मीटिंग हुई थी तो उस में इनके डंडे खड़के थे। तब यह हैडमास्टर साहिब के पास शिकायत करने गए थे और अगले दिन मानीटर को साथ ले आये थे........(विघ्न) इन का प्रोग्राम मेरे पास है कि यह वहां पर फलां फलां दिन गए।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहिब, यह सवाल पहले का है और वह मीटिंग बाद में हुई थी। (Chaudhri Sahib, the question was given notice of much earlier than the party meeting was held.)

चौधरी देवी लाल : क्या इसी किस्म के और भी प्रोग्राम हैं जो प्राइवेट हों और आफीशियल दिखाए गए हों ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं यह वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैंने कोई बेइमानी नहीं की है। ऐक्स चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी को अपने जमाने की याद आती है। मैं यह बात पूरी इमानदारी और दयानतदारी से कहता हूं कि मैंने एक दिन भी नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया हो तो बताएं। (तालियां)

---

*Starred question No. 7268 alongwith its reply appears in P.V.S. Debate Vol 1, No. 17, dated the 12th March, 1965.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : क्या मुख्य मन्त्री यह बताएंगे कि इसी पीरियड में आप के और आप के प्रैडीसैसर के टूर कैसे कम्पेयर होते हैं ?

मुख्य मन्त्री : जो सवाल आनरेबल मैम्बर ने उठाया है उस को मैं ने चैक किया है। पहले चीफ मिनिस्टर साहिब 6 महीने के अन्दर 48 डेज़ दिल्ली के अन्दर विज़िट पर रहे और उस के मुकाबले में मैं सात महीनों में 43 दिन रहा।

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, इस सवाल में फारमर चीफ मिनिस्टर के टूर प्रोग्राम को लाने की क्या जरूरत थी ? (विघ्न) क्या यह [* * * *] नहीं है कि यह पहले इस बारे में सलाह करके आए हैं ? (विघ्न) यह इस सवाल से उठता नहीं है। (विघ्न)

एक आवाज : *** का लफज़ वापस लें । (विघ्न)

चौधरी नेत राम : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब यह प्रदेश कांग्रेस के कामों या केंद्र के कांग्रेस के प्रधान के पास गए तो क्या उस मौके पर उन्होंने सरकारी कार इस्तेमाल की और सरकारी खर्चा हासिल किया ?

मुख्य मन्त्री : मैं ने सरकारी कार का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी कामों के लिये किया है और कांग्रेस या दूसरे कामों के लिये हमेशा प्राइवेट कार का इस्तेमाल किया है और गवर्नमैंट फंड्ज़ का मैंने किसी शकल के अन्दर भी नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया है । (तालियां)

चौधरी देवी लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मैंने जो सवाल किया था और जो जवाब लिया था उस में यह पूछने का मनशा हरगिज़ नहीं था कि इन्होंने कभी [* * * *] की हो। मेरा मनशा तो यह दिखाना था कि इन्होंने यह टाइम जायज़ कामों के लिए खर्च नहीं किया। सारे दिन दिल्ली में सलाह मश्विरा करने के लिये जाते रहे। क्या पंजाब सरकार दिल्ली के मश्विरे से ही चलेगी ? यह खाह-मखाह उस चीज़ को बीच में ले आए जिसे कि हम कहना नहीं चाहते थे।

मुख्य मन्त्री : पंजाब सरकार चीफ मिनिस्टर के मश्विरे से चलती है मगर दिल्ली सरकारी काम के लिए जाना पड़ता है। पंजाब सरकार ने पूरी हिम्मत के साथ तमाम कामों को सरअंजाम दिया है। (तालियां)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ?

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब, लोगों का विचार है और विश्वास है . . . . . .

Mr. Speaker: The hon. Member may please put a question,

(*Interruptions*)

श्री जगन्नाथ : मैं पूछना चाहता हूं कि इन को दिल्ली में जो भी आफीशियल काम होते हैं क्या हर एक में श्री कामराज इनवाल्वड होते है ?

---

*Note.—Expunged as ordered by the Chair.

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सारी डिटेल्ज़ दे दी हैं कि किस काम के लिये वह वहां पर गए थे। (He has given the details of his visits there.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਬਾਹਰ ਦੌਰੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦੇ ਪਰਪਜ਼ ਦਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
(He has stated the purpose of his visits.)

चौधरी नेत राम : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर। मेरा प्रश्न यह था कि प्रदेश कांग्रेस के कामों ग्रौर केन्द्र में कांग्रेस प्रधान से मिलने के लिये सरकारी काम में यह ग्रौर इन की पार्टी के जिम्मेदार ग्रादमी जाते रहे हैं ग्रौर श्री कामराज की कोठी पर सरकारी कार देखी जाती रही है। तो क्या यह गलत जवाब नहीं दे रहे। यह बताएं कि यह वहां पर ग्रपनी कार ले कर गए थे या नहीं ?

Mr. Speaker : It is not a point of order.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ—ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

मुख्य मन्त्री : दिल्ली के टूर के सिलसिले में जो रूल्ज़ सरकार ने बना रखे हैं मैं उन का पूरी तरह से पाबन्द रहा हूं ग्रौर उन पर ग्रमल किया है।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਇਵੇਸਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ.. .. .. ..

Mr. Speaker : The hon. Member should please take his seat.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਜਵਾਬ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਗ੍ਰਿਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ: ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਦਿਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸਫਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਲਜ਼ ਹਨ ਕਿ

[ਗ੍ਰਿਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ]

ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਹੀਕਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਦਿਲੀ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ੧੮ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ? ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਕੀ ਨੌਈਅਤ ਸੀ ?

मुख्य मन्त्री : मैं इन दोनों राजदूतों से मिलने गया तो प्राइम मिनिस्टर साहिब की इजाजत ले ली थी। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल करना चाहता था कि अमरीका की तरफ से जो टीम वाटरलागिंग के सिलसिले में पाकिस्तान में भेजी गई है उस से हमें क्या हैल्प मिल सकती है। इसलिये मैंने इजाजत ले कर ही अमरीका के राजदूत मिस्टर चैस्टर बाउल्ज़ और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मुलाकात की थी। (प्रशंसा)

चौधरी देवी लाल : मेरा सप्लीमैंटरी सवाल यह था कि आइटम नम्बर 16 में प्राइवेट काम और आइटम नम्बर 28 पर पब्लिक मीटिंग के बारे में दर्ज है और बाकी का सारे का सारा प्रोग्राम आफिशियल बनाया गया है तो मैं यह पूछना चाहता हूं सिवाए न दो दिनों के, जिसमें इन्होंने प्राइवेट टूर लिखा है, यह कांग्रेस आरगेनाइजेशन के किसी लीडर को कभी नहीं मिले ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने अपनी विज़िट्स की डिटेल जवाब में दे दी है। (He has already given the details of his visits in the reply.)

Chaudhri Darshan Singh : Sir, may I know from the hon. Chief Minister whether there is any legal bar to the use of official car for private purposes even on payment ?

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो इन्होंने पब्लिक मीटिंग के बारे में लिखा है कि ऐडरैस करने गए, तो वह किस सिलसिले में थी ?

मुख्य मन्त्री : यह मीटिंग लाला लाजपत राए सैन्टेनरी सेलिब्रेशन्ज़ के सिलसिले में थी। इसके बाद रोटरी क्लब को ऐडरैस किया जिसका सरकार की पालिसी से सम्बन्ध था। (विघ्न)

JUNIOR AUDITORS IN THE LOCAL FUND ACCOUNTS

***7882. Sardar Lakhi Singh Chaudhri** : Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Junior Auditors of the Local Fund Accounts were paid in the scale of the Senior Auditors while working in the vacancies of Senior Auditors in the scale of Rs 200—20—360/20—500 ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the system has now been changed and they will be paid in their own scale with a nominal charge allowance ;

(c) the number of persons affected by the said change ;

(d) the reasons for reduction in emoluments in spite of the fact that there has been no change in the duties and responsibilities ?

Sardar Kapoor Singh: (a) Yes. The scale of Senior Auditors held by unqualified hands was revised since 16th June, 1959 from Rs 200—20—360/20—500 to Rs 200—15—380/20—500.

(b) The practice has been modified by Government as follows :—

(i) In the case of totally unqualified hands, to revert them as Junior Auditors.

(ii) S.A.S., Part I hands who will not be successful in S.A.S., Part II Examination held in December, 1964, will also be reverted along with those who did not appear in that Examination, after the declaration of the result of S.A.S., Part II examination. If some of them are required to work as Senior Auditors in the interest of work even after declaration of the result, they will be given a special pay of Rs 40 per mensem in addition to their pay as Junior Auditors.

(c) Seven officials who were totally unqualified have already been reverted. The question of reversion of the other 19 officials who are S.A.S., Part I, qualified will arise after declaration of the result of Part II of S.A.S. Examination held in December, 1964.

(d) The unqulified hands have been getting the same scale of pay as qualified hands with the result that they have felt encouraged not to pass the S.A.S., Part II Examination in time. In fact there has been reluctance on their part to pass this test speedily. In order to discourage this tendency and to provide incentive to really keen unqualified hands to pass the final S.A.S. Examination, it has been decided that there should be separate grades for fully qualified hands and partly qualified hands.

ਸਰਦਾਰ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਡਿਟ ਫ਼ੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਇਡ ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਡ ਲਈ ਇਕੋ ਜਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇਕਉਲੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਫੀਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

श्री सागर राम गुप्ता : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो इन्हों ने फरमाया है कि आडिट के दो ग्रेड दिए जा रहे थे और अनक्वालीफाइड को भी ए. ए. एस. का ग्रेड दिया जा रहा था तो यह गलती उसके नोटिस में कब आई और यह गलती कब से चली आ रही है ।

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗਲ ਖਾਸੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਇਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਰੇਡ ਕੁਆਲੀਫਾਇਡ ਦਾ ਵਧ ਅਤੇ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਇਡ ਦਾ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਮਪਰੂਵ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋਵੇ।

श्री मंगल सैन : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि आप ने जो कहा है कि निगाह पड़ गई तब तबदीली करनी पड़ी, क्या यह बताया जा सकता है कि पिछले दिनों में इतने कितने ऐसे केसिज़ हुए जहां इन की निगाह पड़ गई ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਿਗਾਹ ਪੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਨੁਕਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਤਨੇ ਕੁਆਲਿਫਾਇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਡ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

TOUR BY MINISTERS IN JIND TEHSIL

***6787. Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister be pleased to state the names of the Ministers who visited Jind Tehsil, district Sangrur, during the period from 6th December, 1964 to 20th December, 1964 together with the names of the Ministers who remained on tour there during the month of December, 1964 and for how many days ?

Shri Ram Kishan : A statement is laid on the Table of the House

STATEMENT

Names of the Ministers who visited Jind Tehsil, district Sangrur during the period from 6th December, 1964 to 20th December, 1964	Names of the Ministers who remained on tour to Jind Tehsil during the month of December, 1964 other than the period mentioned in column (1)	Number of days spent in Jind Tehsil during the month of December, 1964
1	2	3
Comrade Ram Kishan, Chief Minister, Punjab	Comrade Ram Kishan, Chief Minister, Punjab	8 days (seven days private journey, one day on official tour)
Shri Darbara Singh, Home and Development Minister, Punjab	Shri Darbara Singh, Home and Development Minister, Punjab	6 days (Private journey)
Shri Prabodh Chandra, Education and Local Government Minister, Punjab	..	2 days (Private journey)
Shri Kapur Singh, Finance and Planning Minister, Punjab	...	1 day (Private journey)
Shri Harinder Singh, Revenue Minister, Punjab	Shri Harinder Singh, Revenue Minister, Punjab	3 days (Private journey)
Shri Rizaq Ram, Public Works and Welfare Minister, Punjab	..	6 days (Private journey)
Shri Sunder Singh, Deputy Minister, Welfare	..	2 days (Private journey)

श्री मंगल सैन : जैसा कि मुझे डीटेल दी गई है उस के मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहिब ने 7 दिन, होम मिनिस्टर साहिब ने 6 दिन, ऐजूकेशन मिनिस्टर साहिब ने 2 दिन, वित्त मंत्री जी ने 1 दिन, राजस्व मिनिस्टर साहिब ने 2 दिन, लोक कार्य मंत्री ने 6 दिन और यह जो आधे वज़ीर हैं उन्होंने 3 दिन जींद तहसील में प्राइवेट तौर पर लगाए और चीफ मिनिस्टर साहिब एक दिन वहां आफिशियल टूर पर गए। मैं पूछना चाहता हूं कि एक दिन जो आफिशियल काम में लगाया तो इन्होंने कौन-सा आफिशियल काम किया ?

मुख्य मन्त्री : आफिशियल काम जो हुआ वह यह था कि हम ने जो सरप्लस डिस्ट्रिक्टस हैं जैसा कि संगरूर, लुधियाना, भटिंडा, हिसार इन के डिप्टी कमिश्नर साहिबान और फूड आफिसर्ज़ की एक मीटिंग बुलाई थी ताकि जो उन के पास सरप्लस गेहूं और बाजरा है वह हासिल किया जा सके।

इस के साथ ही मैं यह भी अर्ज़ कर दूं कि मैं राष्ट्रपति को इस लिये मिला था क्योंकि देहली में हकीकत फिलम चलनी थी जिस का पंजाब के साथ सम्बन्ध है मैं बतौर एक चीफ मिनिस्टर के उन का स्वागत करने के लिये गया था।

श्री मंगल सैन : मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या चीफ मिनिस्टर साहिब यह बात बतायेंगे कि यह जो दौरा किया था आया यह इस बात के लिये ही था कि सरप्लस अनाज ही हासिल किया जाये या किसी और सम्बन्ध में भी बात चीत की गई थी ?

मुख्य मन्त्री : सरप्लस अनाज गंदम और बाजरा के 7 हासिल करने के सम्बन्ध में ही यह विज़िट थी जो कि यहां से महाराष्ट्र और गुजरात को भेजा गया।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या बताया जा सकता है कि जो प्रोईवेट विज़िट्स इनडीकेट किये गये हैं वह ऐज़ कामरेड राम किशन किये या ऐज़ चीफ मिनिस्टर आफ दी स्टेट किये ?

मुख्य मन्त्री : जैसा कि आनरेबल मैम्बर को मालूम ही है कि यह जींद का बाई लैक्शन था और यह प्राइवेट दौरा था।

Pandit Chiranji Lal Sharma : I want to know clearly, Sir, whether he went there in his personal capacity, as Comrade Ram Kishan, or as Chief Minister of the State ?

Chief Minister : I could go there as a Leader of the Congress Legislature Party.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ?

Mr. Speaker : This is no supplementary.

चौधरी देवी लाल : मेरा यही सवाल है जो सरदार कुलबीर सिंह जी ने किया कि क्या चीफ मिनिस्टर साहिब यह बतायेंगे कि उन के साथ सरकारी अफसर भी गये थे ?

मुख्य मन्त्री : मेरे साथ किसी सरकारी अफसर ने दौरा नहीं किया।

चौधरी देवी लाल : उदयपुर और पुरजनपुर में, जब कि श्री वृषभान जी भी वहां पर मौजूद थे. क्या वहां पर जब आप चाये पी रहे थे तो वहां पर अफसरों की कोई कतार नहीं लगी हुई थी ?

मुख्य मन्त्री : सिवाये पुलिस अफसरान के वहां पर कोई भी नहीं था। यह उन का अपना इंतज़ाम था जो पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी मैयर्ज़ के लिये किया जाता है।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਤਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ. . . . . .

मुख्य मंत्री : मैं ने यह कहा है कि उनके अपने इंतजामात थे हमारे अपने थे। उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं था ।

चौधरी इंदर सिंह मलिक : क्या इस सफर में चीफ मिनिस्टर साहिब ने लोगों को कुछ देने दिलाने के वायदे या कोई ऐसे आर्डरज़ पास नहीं किये . . . . . .

Mr, Speaker : This is not supplementary,

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂਰ ਵਿਚ ਸਰਪਲਸ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮੁਤਾਲਿਕ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਬਾਜਰਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ?

मुख्य मन्त्री : इन महीनों में बहुत सा बाजरा गुजरात, मैसूर और महांराष्टर में भेजा गया ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਖ ਵਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਠਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਉਥੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰਜ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ?

मुख्य मंत्री : बतौर चीफ मिनिस्टर के ही नहीं बल्कि बतौर एक एम.ऐल.ए. के भी मुझे सरकारी रैस्ट हाउस में रहने का हक है। जहां तक फाईलों का सवाल है, यह बतौर चीफ मिनिस्टर के मेरे पास आ और जा सकती है और इन पर आर्डर भी पास हो सकते हैं । हां; प्राईवेट विज़िट के दिनों में न कोई टी.ए. या डी.ए. चार्ज नहीं किया ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਹਨ ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਗਏ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ?

Mr. Speaker : He has said that he went there as Congress Member but he did not cease to be the Chief Minister. He has been disposing of the files as such.

चौधरी नेत राम : मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उप चुनावों में दौरा करते वक्त जो कार उन के पास होती थी वह किसी थापर ब्रादर्स की होती थी और पैट्रोल लेते वक्त जो नम्बर उस के दर्ज होते थे वह किस जगह होते थे ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहब, मेम्बर साहब को पता होना चाहिए कि मैंने उन दिनों जो टैलीफोन भी किए हैं, वह प्राइवेट अखराजात में डाले हैं ।

श्री जगन्नाथ : मैं स्पीकर साहब, इनसे यह बात पूछना चाहता हूं कि एक ओर तो ऐस०पी०और डी०सी० यह कहते हैं कि जींद का इलैक्शन मैंने जीता है और दूसरी ओर यह कहते हैं कि जींद का इलैक्शन मैंने जीता है, अब इन दोनों में से कौन सी बात सच है ?

Mr. Speaker : Mr. Jagan Nath, you have made certain allegations against the officers who are not present in the House........

अगर आप ऐसा समझते हैं कि कोई इरेग्युलेर टीज़ हुई हैं तो इलैक्शन पटीशन दे दीजिए ।

(Mr. Jagan Nath, you have made certain allegations against the officers who are not present in the House. If you feel that certain irregularities have been committed, you can file an election petition).

मुख्य मन्त्री : मैं स्पीकर साहब आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन बाइ-इलैक्शन में सरकारी मशीनरी का डाइरैक्टली या इनडाइरैक्टली कोइ इस्तेमाल नहीं हुआ है ?

कामरेड राम प्यारा : क्या कोई मैम्बर अफसरों का सीधा नाम ले कर वैसे अफसर के तौर पर उस को या डिपार्टमैंट को क्रिटीसाइज़ नहीं कर सकता ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने अपने सवाल में ऐस० पी० और डी० सी० के खिलाफ ऐसलीगेशंज़ लगाए हैं अगर इन्हें परसनलो इस बात की नालिज है, तो इलैक्शन पिटीशन करदें । (The hon. Member has made allegations in his question against the S.P. and the D.C. if he has some personal knowldge thereof then he may file an election petition.)

बाबू अजीत कुमार : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਮੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਨਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ?

मुख्य मंत्री : लोगों ने कांग्रेस पार्टी के असूलों और कामयाबी को देखते हुए अपनी राय दी है ।

चौधरी देवी लाल : क्या बाइ इलैक्शन के दौरान चीफ मिनिस्टर साहब या मिनिस्टर साहब अफसरों को अपने साथ ले जा सकते हैं या नहीं ?

मुख्य मंत्री : मैं कैटेगरीकली कहता हूं कि कोई अफसर किसी मिनिस्टर के साथ नहीं गया ।

चौधरी देवी लाल : मैंने स्पीकर साहिब, खुद इनके साथ रह कर देखा है कि अफसर इन के साथ जाते थे और गांव गांव में घूमते थे । उस के बाद यह यहां गलत बयानी करते हैं । यह सरासर झूठ बोलते हैं । इस का क्या इलाज है ?

मुख्य मन्त्री : इनको झूठ का भांडा इस तरह से फूट जाता है कि चौधरी देवी लाल ने किसी के खिलाफ कोई शिकायत आज तक गवर्नर को नहीं की है और न ही इनको ज़रूरत हुई ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी देवी लाल जी, अगर आप समझते हैं कि कोई बात किसी मिनिस्टर ने गलत कही है तो कायदन आप सैंसर मोशन ला सकते हैं। या फिर दूसरी बात यह कर सकते हैं कि मुझे लिख कर दें और उस में यह बातें लिखें जिन्हें आप समझते हैं कि गलत हैं। मैं मिनिस्टर साहिब से पूछूंगा कि इस में कहां तक सचाई है और फिर दोनों स्टेटमैंट हाउस की मेज़ पर रख दी जायेंगी। उन्हें जो मैम्बर चाहे इस्तेमाल कर सकता है।

(If the hon. Member, Chaudhri Devi Lal feels that any mistatement has been made by any Minister he may bring a censure motion as provided in the Rules or he may write to me about that. I will then enquire the facts from the Minister concerned and then both the documents will be laid on the Table of the House. Any hon. Member can make use of them if he so likes).

चौधरी देवी लाल : यहां इस हाउस में जब रोज़ रोज़ मिनिस्टर झूठ बोलते हैं तो हर बार सैंसर मोशन लाई जाएगी. अभी परसों की बात है कि श्री प्रबोध चन्द्र ने दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमैंट दिए। स्पीकर साहब, आप इस में हमारी मदद कीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप चाहें तो सैंसर मोशन का प्राविज़न मौजूद है (If the hon. Member likes, he can bring in censure motion).

चौधरी देवी लाल : हर झूठ के लिये कैसे सैंसर मोशन लाया जा सकता है ।

सरदार कुलबीर सिंह : स्पीकर साहिब, इन्होंने कहा है कि टी. ए./डी.ए. फार प्राइवेट परपज़िज़ तो इससे क्या समझा जाये? क्या सरकारी मशीनरी.....

मुख्य मन्त्री : कोई सरकारी मशीनरी प्राइवेट यूज़ के लिये इस्तेमाल नहीं हुई। मैं इसको कैटेगौरिकली डिनाई करता हूं।

चौधरी देवी लाल : इन्होंने कहा है कि दौरे पर कोई अफसर साथ नहीं रखे जाते । मैं इन से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अफसर इनके साथ हो और उसको जूते मारें तो क्या सरकारी काम में मदाखलत का केस बनाओगे या कि सैक्शन 323 के अंडर बनाओगे।

मुख्य मन्त्री : यह आप को ही शोभा देते हैं। आप पूरी शिकस्त खाने के बाद ऐसी बातें करते हैं।

Sardar Gurdial Singh Dhillon : On a point of Order. Mr. Speaker, I want your ruling whether points or questions which could have been or could be or in otherway, connected with an election petition could be aised through a supplementary question ?

Mr. Speaker : They cannot be.

श्री मंगल सेन : On a point of order, Sir. मुख्य मंत्री साहिब ने कहा था कि चौधरी देवी लाल को जुरंत नहीं पड़ी कि वह किसी गवर्नमैन्ट सरवैंट के खिलाफ गवर्नर साहिब के पास या चीफ सैक्रेटरी के पास शिकायत करते। 18 दिसम्बर, 1964 को मैं ने और प्रोफैसर शेर सिंह ने मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री को तार दी कि वहां के जो प्रिज़ाइडिंग आफीसर थे....... (विघ्न)।

Mr. Speaker : This is no point of order. I have already explained the p ocedure.

श्री मंगल सेन : तो फिर मैं आप को लिख कर भेज दूंगा।

Mr. Speaker : This is a matter for the Election Tribunal to decide.

Pandit Chiranji Lal Sharma : S r, a point o' Order was pu by Shri Gurdial Singh Dhillon to the effect as to whether a matter, which can be the subject mat.er in an election petition, could be raised through a supplementary. My point of Order is this. I want to know whether anything that happened during the elections, which affects the independence of the people, cuts direct at the ıots of democracy or hits at the very policy of the Government, can be raised through a supplementary or not ?

Mr. Speaker : The hon. Member is a lawyer. The question forum can be used for the purpose of eliciting information on facts and if a particular matter is sub-jidice that cannot form the basis of a question.

Pandit Chiranji Lal Sharma : There is no election petition and when there is no election petition can that be discussed in .he shape of supplemen ary or no. ?

Mr. Speaker : So far as 'he fac s are concerned it has been categorically stated that no officer accompanied any Minister.

Pandit Chiranji Lal Sharma : We are not challenging what the hon. Chief Minister has said. It is a procedure of law whether matters arising out of elections can be asked in the shape of supplementaries or not when there is no election petition ?

Mr. Speaker : They can be asked regarding facts only.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Only questions relating to facts can be asked.)

चौधरी देवी लाल : मुख्य मन्त्री साहिब ने कहा कि चौधरी देवी लाल को जुरंत नहीं पड़ी कि कोई शिकायत करते। शिकायत ही नहीं बल्कि मुख्य मन्त्री साहिब के खिलाफ और यू.पी. की मुख्य मन्त्री श्रीमती सुचेता कृपलानी के खिलाफ केसिज़ रजिस्टर हुए हैं। जो केस रजिस्टर हुए हैं उनकी कापी हमारे पास है।

Mr. Speaker : This is not point of order.

Mr. Speaker : Next question is in the name of Shrimati Prasanni Devi.

Dr. Mangal Sein : On her behalf 7,430.

Mr. Speaker : Has the hon. Member got written authority from her ?

श्री मंगल सेन : उन्होंने मुझ को कहा है कि सवाल पूछ लेना ।

Shri Roop Lal Mehta : Mr. Speaker, I have got written authority from the hon. Lady Member and I put the question on her behalf. 7,430.

Tours by Ministers

*7430. **Shrimati Prasanni Devi** (Put by **Shri Roop Lal Mehta**) : Will the Chief Minister be pleased to state the total mileage covered by each Minister on tour, month-wise, during the period from July, 1964, to January, 1965 together with the monthly expenses on pe rol and mobil oil and the amount drawn by each Minister on account of T.A. and D.A. during the said period ?

Shri Ram Kishan : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENTS

Serial No.	Name of the Minister	Month	Mileage covered	Monthly expenditure on petrol and mobil oil	Amount of T.A./D.A. drawn	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
			Miles	Rs		
1	Comrade Ram Kishan, Chief Minister	July, 1964	2,796	860.40	Rs 2,746.37 up to the end of January, 1965	The information in respect of columns 4 and 5 for the month of January, 1965 is not available with the P.T.C. as yet
		August, 1964	3,354	910.80		
		September, 1964	3,739	1,072.80		
		October, 1964	3,441	932.40		
		November, 1964	2,140	629.10		
		December, 1964	3,578	1,017.90		
2	S. Darbara Singh, Home and Development Minister	July, 1964	1,680	373.50	Rs 1,459.25 up to the end of December	T. A. bills for the month of January, 1965, has not yet been prepared
		August, 1964	4,239	407.70		
		September, 1964	2,588	734.40		
		October, 1964	3,027	874.80		
		November, 1964	2,472	650.70		
		December, 1964	4,076	1,149.30		
		January, 1965	4,163	1,192.50		
3	Shri Prabodh Chandra, Education and Local Government Minister	July, 1964	2,656	357.61	Rs 2,777.05 up to the end of December, 1964	Ditto
		August, 1964	2,870	581.05		

[Chief Minister]

Serial No.	Name of the Minister	Month	Mileage covered	Monthly expenditure on petrol and mobil Oil	Amount of T.A./D.A. drawn	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
		September, 1964	3,365	365.30		
		October, 1964	2,765	317.41		
		November, 1964	4,150	876.93		
		December, 1964	4,590	666.25		
		January, 1965	4,160	761.94		
4	Shri Kapoor Singh, Finance and Planning Minister	July, 1964	1,184	372.24	Rs 1,856.55 up to the end of January, 1965	
		August, 1964	2,222	668.66		
		September, 1964	1,673	501.54		
		October, 1964	2,242	582.15		
		November, 1964	1,760	642.90		
		December, 1964	1,604	590.35		
		January, 1965	3,461	883.05		
5	Shri Harinder Singh, Revenue Minister	July, 1964	363	87.30	No. T. A. and D. A. has been claimed up to the end of January, 1965.	
		August, 1964	890	124.83		
		September, 1964	2,009	330.59		

		October, 1964	2,167	299.08		
		November, 1964	1,262	211.18		
		December, 1964	1,683	253.64		
		January, 1965	662	133.94		
6	Shri Rizaq Ram, Public Works and Welfare Minister	July, 1964	1,028	212.42	Rs 2,634.80 up to the end of December, 1964	T. A. bills for the month of January, 1965 has not yet been prepared
		August, 1964	2,493	776.23		
		September, 1964	2,902	870.60		
		October, 1964	2,265	679.50		
		November, 1964	3,101	930.30		
		December, 1964	1,538	461.40		
		January, 1965	2,617	687.50		
7	Shri Sunder Singh, Deputy Minister, Welfare	July, 1964 to September, 1964	Used his own private car		Rs 5,534.00 up to the end of December, 1964	T. A. bills for the month of January, 1965, has not yet been prepared
		October, 1964	3,319	524.55		
		November, 1964	3,340	799.16		
		December, 1964	3,291	688.18		
		January, 1965	3,586	821.73		

श्री मंगल सेन : मुख्य मन्त्री साहिब ने बताया कि उन्होंने 2,746.37 रुपये टी.ए. लिया और जो आधे वजीर साहिब हैं उन्होंने 5,534 रुपया लिया। क्या मैं जान सकता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर ने जो इतना ज्यादा टी.ए. लिया है, उस की क्या वजह है ?

मुख्य मन्त्री : आपको स्टेटमैन्ट में इनफर्मेशन दे दी है।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Chief Minister as to whether instructions have been issued to the Ministers that as and when they go out on tour in the State they should send the copies of their programmes to the legislators ; and in case they do not send the same to them, what is the way out for the legislators to ventilate their grievances ? Should they write to the Chief Minister or raise this matter on the floor of the House?

मुख्य मन्त्री : इस को चैक करके आगे के लिये हिदायत जारी कर दी जायेंगी।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀ. ਏ. ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

मुख्य मन्त्री : जो पिछले रूल थे वही कायम हैं।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Chief Minister if he would consider the desirability of putting a check on the Ministers not to go out on tours so frequently but to concentrate on the file work also ?

मुख्य मन्त्री : मिनिस्टरज़ किसी गल्त काम के लिये खाह मुखाह बाहिर नहीं जाते; जब ज़रूरत होती है तो जाना पड़ता है।

Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : May I know from the Chief Minister whether there were any instructions from the late Chief Minister to the effect that an individual Minister would not be entitled to T.A./D.A. of more than Rs 1,000 in a month ?

मुख्य मन्त्री : यह सर सिकन्दर हयात खां के ज़माने में एक असूल था ; उस को हम ने नहीं अपनाया।

Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : On a point of Order, Sir. My question was whether there were any instructions from the late Chief Minister to that effect but he has talked of Sir Sikander Hayat Khan.......

Mr. Speaker : He says that no such restriction has been placed.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦਿਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary.

चौधरी देवी लाल : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब महसूस करते हैं या नहीं कि वज़ीरों के इस तरह दौरों पर रहने की वजह से जो लोग बाहिर ज़िलों में उन्हें मिलने आते हैं वह बहुत परेशान होते हैं ? जब मैं चीफ पार्लियामैन्ट्री सैक्रेटरी था तो पिछले चीफ मिनिस्टर साहिब को मैंने संजैशन दी थी कि चूंकि आप को लोगों से मिलने का बहुत शौक है इसलिये आपके साथ एक स्टेशन वैगन लगा दी जाये जो आप से मिलने वालों को ला कर आप से मिलाये। तो क्या मौजूदा चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहिब के ज़ेरे गौर ऐसी तजवीज़ है ?

मुख्य मन्त्री : आपकी तजवीज़ जिस तवज्जोह की मुस्तहिक है उसके मुताबिक उस पर तवज्जोह दी जायेगी (हंसी)।

श्री मोहन लाल दत्त : यह जो दौरे मंत्रियों ने किये हैं उन से पता चलता है कि कुछ जगहों पर तो यह मन्त्री बहुत जाते हैं लेकिन कई इलाकों को नजर अंदाज़ किया जाता है क्या मैं जान सकता हूं कि इस की क्या वजह है ?

मुख्य मन्त्री : मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तहसील ऊना को नज़रअंदाज़ नहीं किया जायेगा।

Electricity and water consumed at the residence of each Minister

*7429. **Shrimati Prasanni Devi** (put by Shri Roop Lal Meh a) : Will the Chief Minister be pleased to state the monthly ex enses electricity and water consumed at the official residence of each Minister at Chandigarh during the period from July, 1964 to January, 1965, separately ?

Shri Ram Kishan : A statement is laid on the Table of the House.

State

	13TH JULY, 1964 TO 19TH AUGUST, 1964			20TH AUGUST, 1964 TO 19TH SEPTEMBER, 1964			20TH SEPTEMBER, TO 19 OCTOBER, 1964	
	Elecy.	W/C	Total	Elecy.	W/C	Total	Elecy.	W/C
1. Shri Ram Kishan, Chief Minister ..	80.23	49.00	129.23	125.22	55.00	180.22	135.73	40.00
2. Shri Darbara Singh, Home and Development Minister ..	88.12	18.00	106.12	103.13	24.00	127.13	127.13	29.00
3. Shri Prabodh Chander, Education and Local Government Minister ..	64.54	13.00	77.54	85.83	30.00	115.83	110.00	21.00
4. Shri Kapoor Singh, Finance Minister ..	69.40	13.00	82.40	73.90	20.00	93.90	77.21	13.00
5. Shri Rizaq Ram, Public Works Minister ..	65.66	46.00	111.66	66.63	28.00	94.63	92.15	28.00
6. Shri Harinder Singh, Revenue Minister	..	15.00	15.00	..	23.00	23.00	..	23.00
7. Shri Sunder Singh, Deputy Minister, Welfare ..	..	7.00	7.00	..	14.00	14.00	..	11.00

ment

	20TH OCTOBER, 1964 TO 19TH NOVEMBER, 1964			20TH NOVEMBER, 1964 TO 19TH DECEMBER, 1964			20TH DECEMBBR, 1964 To 19TH JANUARY, 1965		
Total	Elecy.	W/C	Total	Elecy.	W/C	Total	Elecy.	W/C	Total
175.73	145.23	39.00	184.23	230.23	34.00	264.23	372.71	36.00	408.71
156.13	99.83	23.00	122.83	110.64	16.00	126.64	155.63	23.00	178.63
131.00	119.14	27.00	146.14	110.44	27.00	137.44	224.47	19.00	243.47
90.21	58.77	9.00	67.77	90.55	17.00	107.55	91.01	13.00	104.01
120.15	68.13	38.00	106.13	1.50	41.00	42.50	296.80	37.00	333.80
23.00	..	26.00	26.00	..	11.00	11.00	..	14.00	14.00
11.00	92.23	7.00	99.23	45.93	6.00	51.93	80.99	13.00	93.99

Note.—The electricity consumption bills in respect of Shri Harinder Singh, Revenue Minister, have not so far been received from the Electricity Board. Hence no expenditure has so far been incurred in his case.

श्री मंगल सेन : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि आपने तो 13 जुलाई, 1964 से 19 अगस्त, 1964 तक बिजली पानी के 129 रुपये 23 पैसे वसूल किये लेकिन चौधरी सुन्दर सिंह ने नकद 7 रुपये चार्ज किये तो क्या उप-मन्त्री साहिब ने जब से मंत्रीपद संभाला है उस वक्त से नहाना छोड़ दिया है या और कोई बात है ? (हंसी)

(No reply)

Administrative Reforms Commission

6746. Shri Mangal Sein : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of the sittings held so far by the Administrative Reforms Commission recently set up by the Government ;
(b) the number of persons interviewed by the said Commission ;
(c) the time by which the report of this Commission is likely to be finalised ?

Shri Ram Kishan : (a) & (b) 23 meetings were held and 20 persons interviewed till the 27th February, 1965 .

(c) By the end of August, 1965.

श्री मंगल सेन : मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया है कि इस कमिशन की 23 मीटिंग्ज़ हुईं जिस में उन्होंने 20 आदमियों से भेंट की और अगस्त, 1965 के आखिर तक सारी रिपोर्ट तैयार हो जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 20 आदमियों में कौन कौन सज्जन थे जिन से उन्होंने भेंट की ?

मुख्य मन्त्री : कमिशन ने 18 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक जिन साहिबान से इन्टरव्यू किया, उन में हमारे Ex-Chief Justice of India, Justice Mehar Chand Mahajan, Ex-Chief Minister of Punjab Shri Bhim Sen Sachar और दूसरे ऐसे ऐमीनैन्ट सिटीज़न्ज़ हैं।

श्री मंगल सेन : क्या कमिशन ने इन के इलावा हमारे पंडित मोहन लाल जी, मित्तल साहिब, चौधरी रणबीर सिंह, जी और दूसरे निकाले हुए मंत्रियों से भी भेंट की है ?

मुख्य मन्त्री : जैसा कि मैम्बर साहिब को मालूम ही है कमिशन ने तमाम M.L.As., M.L.Cs., M.Ps., Presidents of the Bar Associations, Presidents of the Municipal Committees, Chairmen of the Zila Parishads, Ministers, Administrative Secretaries and other eminent citizens of the State and jurists and industrialists of the country को एक क्वस्चनेयर भेजा है। इसके मुताबिक पंजाब और हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अन्दर कोई 2,860 आदमियों को यह क्वस्चन्नेयर जारी किया गया है ताकि जो जो जानकारी वह दे सकते हैं वह देने की कृपा करें।

श्री मंगल सेन : मैं उनके नोटिस में यह बात लानी चाहता हूं कि मैं भी पंजाब का एम. एल. ए. हूं लेकिन मेरे पास ऐसा कोई क्वस्चन्नेयर नहीं गया है।

Mr. Speaker : The hon. member may please write to the Commission in this connection.

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : क्या इस कमिशन में हरियाणा का भी कोई मैम्बर है या नहीं और अगर नहीं है तो उसकी क्या वजह है ?

मुख्य मन्त्री : अगर आप हरियाना से इतनी दिलचस्पी रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि हरियाना के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री टेक चन्द उसके मैम्बर हैं।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : यह तो कमिशन ही बता सकता है। जब रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा।

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि इस कमिशन पर कुल कितना खर्च आ चुका है और चेयरमैन को क्या पे किया जाता है ?

मुख्य मन्त्री : इस के लिये सैपरेट नोटिस चाहिये।

Expenditure incurred on follow-up action on Das Commission Report

***7790. Comrade Ram Chandra** : Will the Chief Minister be pleased to state the expenses incurred by Government on the follow-up action on the Das Commission Report by Shri Manchanda, Shri Krishnaswami and Shri Bagchi, I.C.S. showing separately :

(i) the period for which each of the above officer worked ;

(ii) the amount of salaries and allowances paid to each ; and

(iii) the amount of salaries and allowances paid to the staff who worked under the said officers ?

Shri Ram Kishan—

(i) Shri Manchanda	..	Ist July, 1964 to 30th August, 1964
Shri Krishnaswami	..	4th August, 1964 to 19th October, 1964
Shri Bagchi, I.C.S.	..	31st October, 1964—still continues

			Rs
(ii) Shri Manchanda	..	Salaries	5,572·42
		Allowances	439·60
Shri Krishnaswami	..	Salaries	7,268·82
		Allowances	246·60
Shri Bagchi, I.C.S.	..	Salaries	12,096·78
		Allowances	229·80
(iii) Staff with Shri Manchanda	..	Salaries	2,118·34
		Allowances	82·74
Staff with Krishnaswami	..	Salaries	5,473·65
		Allowances	206·32
Staff with Bagchi, I.C.S.	..	Salaries	3,991·78
		Allowances	240·40

(up to 28th February, 1965

Examination of report submitted by Shri Krishnaswamy

*7791. **Comrade Ram Chandra** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the date on which Shri Bagchi took charge of his duties to further process the report submitted by Shri Krishnaswamy;
(b) the number of cases submitted to Shri Bagchi up to date ;
(c) the number of cases of officers finalised by Shri Bagchi and submitted to the Chief Minister ;
(d) the action taken and orders passed by the Government on the said cases up to date ?

Shri Ram Kishan : (a) Shri Bagchi was appointed as the Commissioner for Enquiries and Special Secretary to Government, Punjab, on 31st October, 1964, to enquire into the cases specific lly referred to him.

(b) Three.
(c) None so far.
(d) Does not arise.

श्री मंगल सेन : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि आप ने जो कृष्णास्वामी रिपोर्ट के ऊपर इन्क्वायरी कमिशन के तौर पर बागची महो य को मुकर्र किया है तो क्या बागची की रिपोर्ट के ऊपर कोई और कमेटी या कमिशन भी बिठाने का विचार है ?

Chief Minister: Mr. Bagchi's Report is going to be final in this connection.

श्री मंगल सेन : आपने पहले भी फरमाया था कि कृष्णास्वामी रिपोर्ट फाइनल होगी तो क्या बागची साहिब की रिपोर्ट भी उसी तरह फाइनल होगी जिस तरह से कृष्णास्वामी रिपोर्ट फाइनल हुई है ?

मुख्य मन्त्री : मैं ने ऐसा नहीं कहा था।

कामरेड राम प्यारा : मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया है कि श्री बागची ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कृष्णास्वामी रिपोर्ट पर श्री बागची का कोई फैसला न होने के बावजूद गवर्नमैंन्ट ने कुछ अफसरों को एगजानरेट कर दिया है ?

मुख्य मन्त्री : श्री बागची के सपुर्द ऐसे केस ही किये गये थे जिन की मजीद इन्क्वायरी की ज़रूरत थी। कृष्णास्वामी रिपोर्ट की फाइंडिंग्ज़ आने के बाद जिन को चार्ज शीट किया गया था और जिनका ऐक्स्प्लैनेशन लिया गया था उन में से जिन का जवाब तसल्लीबख्श पाया गया उनको ही एगज़ानरेट किया गया है।

Mr. Speaker : Question hour is over now.

श्री मंगल सेन: क्या इस सवाल पर कल सप्लीमेंट्री क्वैश्चन कंटीन्यू होंगे ?

Mr. Speaker : All right. Supplementaries on this question will continue tomorrow.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Setting up a Hotel of International Standard in the Capital

***7407. Sardar Gian Singh Rarewala** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether Government is aware of the fact that several new hotels conforming to international standard have come up in India recently to meet the requirements of increased tourist traffic ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether Government intend building one such hotel in Chandigarh as there is none here at present ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes.

(b) The IndiaTourism Hotel Corporation set up by the Central Government for building luxury hotels at important tourist centres in the country has been requested to include Chandigarh in its Hotel Building Programme.

Development of Industries in Rohtak District

***6757. Shri Mangal Sein** : Will the Chief Minister be pleased to state whether in the month of November last he made an announcement at Sonepat to the effect that a sum of rupees forty crores would be expended in the coming years for the development of industries in district Rohtak if so, the intention of the Government in making the said announcement ?

Shri Ram Kishan : The requisite information is laid on the table of the House.

Yes. The intention of the announcement was that various large-scale industrial projects indicated below with a total capital outlay of about Rs 40 crores have recently been or are proposed in the near future to be set up in the Rohtak District. Except for the projects mentioned at serial Nos. 3, 6 and 7 which have been set up or are in the process of completion, the others are at the planning stage and will take time to implement.

Serial No.	Location	Name of the Project	Capital	REMARKS
			Rs in crores	
1	Ganaur ..	Punjab Seamless Tubes Ltd.	9.00	A State sponsored project
2	Do	Punjab Steel and Alloy Castings Ltd.	1.50	Ditto
3	Do	Bharat Steel Tubes Ltd.	4.00	Government have invested Rs 39,38,000 in its share capital
4	Do	Steel Castings Foundry	2.50	
5	Do	Steel Strip Mill ..	20.00	
6	Bahadurgarh ..	Hindustan Twyfords Ltd.	2.00	
7	Do	Hindustan National Glass Manufacturing Co.Ltd.	1.50	
		Total	40.50	

Representation from People of Hilly Areas for Iron Sheets

*7717. **Comrade Ram Chandra** : Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government received any representations from the people of the Hilly areas in the State requesting for the allotment of adequate quotas of iron sheets for the roofs of their houses in view of the damage caused by heavy rains in these areas, if so, the quantity of sheets allotted for these areas during the years 1963-64 and 1964-65 todate separately ?

Shri Ram Kishan : Yes, Sir.

1963-64 .. 127 MT
1964-65 (to-date) .. 133 MT

Technical Education in Polytechnic

*7920. **Sardar Balwant Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether technical education is imparted free in all Polytechnic Institutes in the State ;
(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative whether it is a fact that some amount is being charged from each trainee in the Government Polytechnic for Women, Chandigarh, in the shape of fee or contribution to some funds from all classes of students irrespective of the fact that some of them belong to backward classes ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes.

(b) Yes. Rs 5.50 per mensem as contribution towards the Students Fund which is utilised for the welfare of the students.

Urban Industrial Estate, Dadri, District Mahendragarh

*7949. **Shrimati Chandra Wati** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the progress made so far in establishing the Urban Industrial Estate sanctioned for Dadri, district Mahendragarh ;
(b) whether there is any proposal under the consideration of the Government to shift the said Estate from Dadri to Jind ?

Shri Ram Kishan : (a) The proposal for setting up Rural Industrial Estate at Dadri has since been dropped due to paucity of funds and experience of the functioning of Rural Industrial Estates already set up.

(b) Does not arise.

Cement Factory

*7975. **Shrimati Sarla Devi** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that a licence to start a cement factory in Kangra District was given to a firm during the period from Ist January, 1962 to 31st December, 1964, if so, its name ;
(b) the extent of progress so far made in this respect, if no progress has been made the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes. M/s. Surrendra Overseas Private Ltd., Calcutta.

(b) The licencees have since surrendered the licence. The possibility of finding another suitable party for implementing the project or taking it up in the public sector is being examined.

Stoppage of Bus Service from Dharamsala to Dehra - Gopipur via Haripur

*7730. **Bakshi Partap Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether he is aware of the fact that the bus service from

Dharamsala to Dehra Gopipur via Haripur has been discontinued by the Shiwalik Transport Company ;

(b) whether the Government has received any representation in connection with (a) above from the public of the said illaqa, if so, the action taken or proposed to be taken by the Government in the matter ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes.

(b) Yes. The service has since been ordered to be restored.

Punjab Roadways Buses

*7871. **Shri Banwari Lal** : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of buses of each depot of the Punjab Roadways at present in the State, make-wise ?

Shri Ram Kishan : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

		Tata Mercedes Benz	Leyland	Dodge	Total
(i) Punjab Roadways, Amritsar	..	229	..	..	229
(ii) Punjab Roadways, Jullundur	..	..	197		197
(iii) Punjab Roadways, Ambala	..	12	..	146	158
(iv) Punjab Roadways, Gurgaon	..	..	34	184	218
(v) Punjab Roadways, Pathankot	..	6	38	91	135
(vi) Punjab Roadways, Chandigarh	..	..	121	16	137
Total	..	247	390	437	1,074

Applications of Legislators for allotment of cars/scooters out of State Quota

*7968. **Sardar Lakhi Singh Chaudhri** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the names of the legislators with the dates of their applications who applied for the allotment of Fiat/Ambassador cars and scooters out of the State quota before Ist February, 1964 but who have not been allotted any cars/scooters up to 28th February, 1965;

(b) the names of the legislators with the dates of their applications for the allotment of Fiat/ Ambassador Cars out of the said quota who have been allotted the cars/scooters after the Ist June, 1963 ?

Shri Ram Kishan : (a) & (b) Two lists containing the requisite information are placed on the table of the House.

[Chief Minister]

Names of the Legislators with the date of their application who applied for the allotment of Fiat, Ambassador cars and scooters out of the State quota before 1st February, 1964 and have not yet been allotted any car / scooter upto 28th February, 1965

Serial No.	Name	Date of receipt of application	Choice car
	CARS		
1	Shrimati Prasanti Devi, M.L.A.	11-9-62	Fiat
2	Shri Dasundha Singh, M.L.C.	24-9-62	Do
3	Shri Lakhi Singh Chaudhry, M.L.A.	26-11-62	Do
4	Shri Gurdial Singh Dhillon, M.L.A.	17-6-63	Do
5	Shri Karam Singh Kirti, M.L.A.	17-6-63	Do
6	Shri Lachhman Singh Gill, M.L.A.	6-7-63	Do
7	Shrimati Savita Behan, M.L.C.	10-10-63	Do
8	Shri Jai Inder Singh, M.L.A.	9-1-64	Fiat Ambassador
	SCOOTERS		
1	Shri Rattan Singh, M.L.A.	24-9-62	Lambretta
2	Shri Harcharan Singh Brar, M.L.A.	6-10-63	Do
3	Shri Kartar Singh, M.L.A.	6-10-63	Do
4	Shri Gian Chand Gupta, M.L.A.	21-12-63	Do
5	Shri Lakhi Singh Chaudhry, M.L.A.	14-1-64	Do

Names of the legislators with the dates of their applications for the allotment of Fiat/ Ambassador cars out of the said quota who have been allotted the cars / scooters after 1st June, 1963

Serial No.	Name of applicant	Date of receipt of application	Make of car/ scooter allotted
1	Shri Kapur Singh, Chairman, Punjab Legislative Council, Chanigarh	20-11-62	Fiat
2	Giani Kartar Singh, M.L.A., Chandigarh	28-7-64	Do
3	Shri Des Raj, M.L.C.	24-8-64	Do
4	Shri Suraj Mal, M.L.A., ex-Member Personal Advisory Committee to Chief Minister, Punjab	22-6-63	Ambassador
5	Shri Prabodh Chandra, (ex-Speaker Punjab Vidhan Sabha) Minister for Education, Punjab	26-11-63	Do

Serial No.	Name of applicant	Date of receipt of application	Make of car/ scooter allotted
6	Rao Birender Singh, M.L.C., Hony. Advisor Defence Efforts, Punjab	26-11-63	Ambassador
7	Shri Ajmer Singh, M.L.A., ex-Revenue Minister, Punjab	16-7-63	Do
8	Shri Ranbir Singh, M.L.A., ex-Irrigation and Power Minister, Punjab	26-11-63	Do
9	Shri Gurbanta Singh, M.L.A., ex-Local Government and Welfare Minister, Punjab	26-11-63	Do
10	Shri Gulab Singh, M.L.A., ex-Chief Parliamentary Secretary, Punjab	26-11-63	Do
	SCOOTERS		
1	Shri Jai Inder Singh, M.L.A. ..	14-5-63	Lambretta
2	Shri Virendra, M.L.C. ..	14-5-63	Vespa

Route permits with the District Rohtak Transport Co-operative Society, Ltd. Rohtak.

*7969. **Shri Banwari Lal** : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the total number of route permits at present with the District Rohtak Transport Co-operative Society Ltd., Rohtak.

(b) the dates on which and the route for which each such permit was issued?

Shri Ram Kishan (a) & (b) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) 70.

(b) The Rohtak District Transport Co-operative Society is holding the route permits on the following routes :—

	Route		*Permits*	*Date of issue*
1.	Rohtak-Jhajjar	...	4	All these permits were issued in 1949 at the time of rehablitation in lieu of permit held by the Society in Pakistan
2.	Jhajjar-Delhi	..	9	
3	Rohtak-Jhajjar-Badli	...	2	
4	Jhajjar-Bahadurgarh	...	1	
5.	Bahadurgarh-Gurgaon	..	2	
6.	Delhi-Dujana	...	1	
7.	Delhi-Dujana-Beri	..	1	
8.	Delhi-Badli via Daboda	...	1	
9.	Delhi-Badli via Dhansa	..	1	
10.	Amritsar-Pathankot	...	22	
11.	Delhi-Hissar	...	2	17th August, 1962
12.	Rewari-Khund-Behror	...	1	18th February, 1962
13.	Gurgaon-Rewari via Pataudi	...	3	18th February, 1962

[Chief Mini ter]

14. Delhi-Sonepat	..	3	15th June, 1962
15. Tijara-Bhiwani-Rewari-Bawal	..	1	25th June, 1962
16. Amritsar-Moga	..	3	22nd February, 1961
17. Amritsar-Ferozepore	..	1	22nd February 1961
18. Amritsar-Quadian extended up to Harchoowal		1	26th November, 1961
19. Rohtak-Nohar via Jhajjar	..	1	26th October, 1961
20. Rewari-Kund-Behror	..	1	18th February, 1962
21. Rewari-Hissar via Jhajjar-Rohtak	..	1	5th September, 1962
22. Rewari-Bawal	..	1	5th September, 1962
23. Hissar-Narnaul via Tosham	..	1	24th May, 1963
24 Gurgaon-Rewari via Pataudi	..	1	24th May, 1963
25. Gorgaon-Rewari via Manesar	..	2	15th June, 1963
26 Delhi-Rewari via Manesar	..	1	9th August, 1963
27. Rewari-Mohindergarh	..	1	20th August, 1964
28. Amritsar-Chawinda Devi	..	1	21st April, 1956
Total	..	70	

Notices issued under the Punjab Capital (Periphery) Control Act, 1962

***7748. Sardar Prem Singh Prem :** Will the Chief Minister be pleased to state whether some notices for demolishing the buildings constructed or under construction within the Municipal limits of Dera Bassi have recently been issued to the owners thereof under the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952, if so, the number of such notices ?

Shri Ram Kishan : Yes. Eight notices were issued.

Chowkidars in the Capital Project Administration, Chandigarh.

***7902. Shri Sagar Ram Gupta :** Will the Chief Minister with reference to Unstarred Question No. 1430 printed in the list of Unstarred Questions for 4th March, 1964 be pleased to state—

(a) the reasons, if any, for keeping a large number of chowkidars (i.e. 179) referred to in part (a) of the said reply on the work charged basis and whether Government is considering any proposal to bring them on a regular cadre;

(b) the reasons, if any, for not allowing all the chowkidars weekly rest and whether overtime wages have been and are paid to the chowkidars who are not allowed this rest;

(c) whether overtime wages have been and are paid to chowkidars referred to in part (c) of the said reply, if not, the reasons therefor;

(d) the reasons for taking more than 8 hours work from the chowkidars referred to in part (d) of the said reply and whether overtime wages have been and are paid to them.

(e) whether the matter regarding the grant of weekly rest and the fixation of duty hours for the chowkidars, which according to part (e) of the said reply was under consideration has since been finally decided by the Government, if so, the details of the decision taken, if not, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : A statement contianing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The Chowkidars on work charged basis are required to look after the Central Stores and other stores including Kilns and tubewells throughout the Capital Project. The matter with regard to bringing the chowkidars having more than 5 years continuous service on regular cadre has already been taken up and is under consideration with Government.

(b) The instructions for allowing all the chowkidars weekly rest have already been conveyed to the Subordinate Offices and the same are being followed except in some cases wherein it could not be possible for want of provision in the estimates. Necessary instructions are being issued to the Subordinate Offices to follow instructions rigidly from ensuing year. No overtime wages were paid to the chowkidars who could not be allowed this rest.

(c) & (d) The nature of duties entrusted to the Chowkidars differs for various works. In case of Central Stores, the work is comparatively difficult and they perform 8 hours duty while in other cases the nature of work is very light wherein the duty hours cannot be restricted to eight hours. For example on the brick kilns the chowkidars are residing with their families at the site of works. They have to keep a watch on the stacks of bricks during day time and take full rest during night. Similarly there are small stores which do not warrant keeping of chowkidars for day and night separately in 8 hours shifts. At all such places chowkidars remain at site with their families and look after the store all the time. The question of payment of overtime wages does not arise.

(e) The question regarding weekly rest has already been decided as referred to in part (b) above. As regards duty hours for work charged Chowkidars the position has been clarified in parts (c) and (d) above.

Warm clothing to Work Charged Chowkidars

***7904. Shri Sagar Ram Gupta :** Will the Chief Minister be pleased to state whether warm clothing is being provided to the Work Charged Chowkidars of the Capital Project Administration, if not, the reasons therefor?

Shri Ram Kishan : No. The matter is under consideration of the Government.

Price of Slates in Kangra District

***7362. Bakshi Partap Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether he received a representation requesting that, in view of the rising prices of slates in the Kangra District, the slates obtained from the mines in the said district be declared as an essential commodity; if so, the action taken so far on this representation?

Shri Ram Kishan : Yes. The Government of India have been approached to declare slates as an essential commodity under the Essential Commodities Act, 1955

Reward to Soldiers decorated with Ashoka Chakra II Medal

***7984. Shrimati Chandra Wati :** Will the Chief Minister be pleased to state the reward, whether in the shape of land or cash, given by Government to the soldiers who are awarded Ashoka Chakra II medals, if cash, the amount thereof, if land, the area thereof ?

Shri Ram Kishan : No reward-cash or land is given to the winners of Ashoka Chakra II by the State Government.

Persons holding fire-arms licences in Karnal District

***7913. Shri Rulya Ram** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state the number of persons holding licences for fire arms in district Karnal who have been or are on Basta 'B' of the Police?

Sardar Darbara Singh : Two.

Providing Jeeps in Police Stations in the State

***7914. Shri Rulya Ram** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to provide Jeeps in all the police stations of the State?

Sardar Darbara Singh : Yes.

Panchayat Samiti in Karnal District

***7428. Shrimati Parsanni Devi** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state the names of all the Panchayat Samitis in Karnal District, the budget estimates of each for the year 1964-65, with the names of the employees of each Samiti and their pay scales?

Sardar Darbara Singh : (a) (1) Assandh, (2) Guhla, (3) Gharaunda, (4) Karnal, (5) Kaithal, (6) Ladwa, (7) Madlauda, (8) Nilokheri, (9) Nissang, (10) Pundri, (11) Panipat, (12) Rajaund, (13) Samalkha, (14) Shahbad, (15) Thanesar.

(b) The statement A & B are laid on the table of the House.

STATEMENT A

Budget Estimates of Panchayat Samitis during 1964-65 of Karnal District

Name of Panchayat Samiti		Receipts	Expenditure
			Rs
1. Assandh	..	99,010.00	62,650.00
2. Guhla	..	1,81,815.00	1,67,491.00
3. Gharaunda	..	97,180.00	97,180.00
4. Karnal	..	1,80,188.00	1,80,188.00
5. Kaithal	..	1,85,200.00	1,78,169.00
6. Ladwa	..	1,16,888.00	1,05,370.00
7. Madlauda	..	1,57,778.00	1,58,048.00
8. Nilokheri	..	3,69,214.00	3,59,667.00
9. Nissang	..	2,97,660.00	2,74,720.00
10. Pundri	..	2,39,400.00	2,36,960.00
11. Panipat	..	4,52,202.00	3,45,002.00
12. Rajaund	..	80,600.00	80,600.00
13. Smalkha	..	1,47,007.00	1,56,527.00
14. Shahbad	..	1,38,372 00	1,22,472.00
15. Thanesar	..	3,022,00.00	4,20,497.00

STATEMENT B

Panchayat Samiti Assandh

Name of employees	Designation	Scale of pay
		Rs
Shri Sat Pal Baluja ..	Head Clerk ..	150—10—300
Shri Shiv Dayal Kalra ..	Typist (Clerk) ..	60—4—80/5—120/5—175
Shri Ishwar Datt Ramnay ..	Tax Collector ..	Ditto
Shri Jeewan Ram ..	Clerk ..	Ditto
Shri Hari Chand Rathi ..	Peon (Tax Collector)	30—½—35
Shri Bal Kishan ..	Peon ..	Ditto
Shri Ram Narain ..	Panchayat Secretary	Rs 100. consolidated
Shri Ram Kishan ..	Ditto	Ditto
Shri Ved Bharat ..	Ditto	Ditto
Shri Surjit Singh ..	Ditto	Ditto
Shri Kundan Lal ..	Ditto	Ditto
Shri Jaswant Singh ..	Ditto	Ditto
	Panchayat Samiti, Guhla	
Shri Nirmal Singh ..	Tax Collector ..	60—4—80/5—120/5—175
Shri Ram Singh ..	Accounts Clerk ..	Ditto
Shri Ram Sarup ..	Clerk ..	Ditto
Shri Prabhu Ram ..	Process Server ..	30—½—35
Shri Shanker Lal ..	Peon ..	Ditto
Shri Deep Singh ..	Peon ..	Ditto
	Panchayat Samiti Gharaunda	
Shri Kartar Singh ..	Head Clerk ..	150—10—300
Shri Narsingh Dass ..	Tax Collector ..	60—4—80/5—120/5—175
Shri Gurbachan Vij ..	Accounts Clerk ..	Ditto
Shri Om Parkash ..	Clerk ..	Ditto
Shri Rattan Singh ..	Peon ..	30—½—35
Shri Om Parkash ..	Peon ..	Ditto
Shri Bishna Ram ..	Chaukidar-cum-Mali	Ditto

[Minister for Home and Development]

Name of employee	Designation	Scale of pay
		Rs
	Panchayat Samiti, Karnal	
Shri Ram Dia	Head Clerk	150—10—200/10—300
Shri Pritam Singh	Clerk	60—4—80/5—120/5—175
Shri Bhalla Singh	Do	Ditto
Shri Jai Pal Singh	Typist	Ditto
Shri Harkishan Dass	Tax Collector	Ditto
Shri Nihal Chand	Peon	30—½—35
Shri Ram Sarup	Peon	Ditto
	Panchayat Samiti, Kaithal	
Shri Abhey Singh	Accounts Clerk	60—4—80/5—120/5—175
Shri Choith Ram	Tax Collector	Ditto
Shri Om Parkash	Clerk	Ditto
Shri Vallahv Ram		
Shri Megh Raj		
Shri Om Parkash		
Shri Hari Ram		
Shri Gurdial	Secretaries (10)	100 Consolidated pay each
Shri Raghunandan		
Shri Mittar Parkash		
Shri Jado Ram		
Shri Chandi Singh		
Shri Ajit Singh	Peon	30—½—35
Shri Munshi Ram	Do	Ditto
Shri Charanji Lal	Patwari	60—4—80/5—120/5—175
	Panchayat Samiti Ladwa	
Shri Des Raj	Head Clerk	150—10—300
Shri Kanshi Ram	Accounts Clerk	60—4—80/5—120/5—175
Shri Sat Parkash	Tax Collector	Ditto
Shri Ram Dyal	Peon	30—½—35
Shri Ishwar Chand	Peon	Ditto

Name of employee		Designation		Scale of pay
				Rs
Panchayat Samiti, Madlauda				
Shri Chandgi Ram	..	Tax Collector	..	60—4—80/5—120/5—175
Shri Duli Chand	..	Process Server	..	30—½—35
Shri Dharam Singh	..	Peon	..	30—½—35
Shri Partap Singh	..	Head Clerk	..	150—10—300
Panchayat Samiti Nilokheri				
Dr. Tirath Singh	..	Incharge Poultry Unit		150—10—200/15—380
Shri Harbans Singh	..	Stock Assistant	..	75—5—100/5—125
Shri Mahi Lal	..	Mali	..	30—½—35
Shri Kabri	..	Sweeper	..	Daily paid
Shri Jag Parshad	..	Water Carrier	..	Ditto
Shri Krishan Gopal Sharma	..	Tax Collector	..	60—4—80/5—125
Shri Karan Singh	..	Head Clerk	..	150—10—300
Shri Prem Singh	..	Clerk	..	60—4—80/5—120/5—175
Shri Lakhpat Ram	..	Peon	..	30—½—35
Shri Sant Ram	..	Mali	..	Ditto
Shri Inder Singh	..	Peon	..	Ditto
Shri Gurpal Singh	..	Poultry Assistant	..	60—4—80/5—120/5—175
Shri Ram Pal	..	Patwari	..	Ditto
Panchayat Samiti, Nissang				
Shri Gian Singh	..	Head Clerk	..	150—10—300
Shri Raghbir Singh	..	Tax Collector	..	60—4—80/5—120/5—175
Shri Bhagwan Singh	..	Peon	..	30—½—35
Shri Nathi Ram	..	Patwari	..	Rs 100 fixed
Panchayat Samiti, Pundri				
Shri Kesho Lal	..	Head Clerk	..	150—10—300
Shri Gulab Singh	..	Tax Collector	..	60—4—80/5—120/5—175
Shri Jai Singh	..	Clerk	..	Ditto
Shri Jit Ram	..	Accounts Clerk	..	Ditto
Shri Mange Ram	..	Peon	..	.. 30—½—35

[Home and Development Minister]

Name of employee		Designation		Scale of pay
				Rs
Shri Kanshi Ram	..	Peon	..	30-½-35
Shri Sadhu Ram	..	Secretary	..	60—4—100
Shri Ram Sarup	..	Do		Ditto
Shri Parmatma Ram	..	Do		Ditto
Shri Tara Chand	..	Do		Ditto
Shri Radhe Sham	..	Do		Ditto
Shri Tarlok Singh	..	Do		Ditto
Shri Prem Chand	..	Do		Ditto
Shri Shiv Dayal Rava	..	Do		Ditto
Shri Bharat Singh	..	Do		Ditto
		Panchayat Samiti, Panipat		
Shri Brahm Datt Sharma	..	Head Clerk	..	150—10—300
Shri Kasturi Lal	..	Tax Collector	..	60—4—80/5—120/5—175
Shri Gopal Krishan	..	Clerk	..	Ditto
Shri Jagvoop Arora	..	Do		Ditto
Shri Tola Ram	..	Peon	..	30—½—35
Shri Ram Kishan	..	Do		Ditto
		Panchayat Samiti, Rajaund		
Shri Krishan Lal	..	Head Clerk	..	150—10—300
Shri Om Parkash	..	Accounts Clerk	..	60—4—80/5—120/5—175
Shri Jagat Singh	..	Tax Collector	..	Ditto
Shri Ramji Lal	..	Process Server	..	30—½—35
Shri Kali Ram	..	Peon	..	Ditto
		Panchayat Samiti, Samalkha		
Shri Vijai Singh	..	Head Clerk	..	150—10—300
Shri Mange Ram	..	Tax Collector	..	60—4—80/5—120/5—175
Shri Beli Ram	..	Clerk	..	Ditto
Shri Raj Kishore	..	Accounts Clerk	..	Ditto
Shri Ladha Ram	..	Peon	..	30—½—35
Shri Harkesh	..	Do		Ditto

Name of employee		Designation		Scale of pay
		Panchayat Samiti, Shahbad		Rs
Shri Hari Kishen Bhatnagar	..	Head Clerk	..	150—10—300
Shri Sham Lal	..	Accounts Clerk	..	60—4—80/5—120/5—175
Shri Yogainder Nath	..	Typist	..	Ditto
Shri Prem Chand	..	Tax Collector	..	Ditto
Shri Niranjan Singh	..	Peon	..	30—½—35
Shri Gurcharan Singh	..	Peon	..	Ditto
		Panchayat Samiti, Thanesar		
Shri Babu Ram	..	Head Clerk	..	150—10—300
Shri Hakim Rai	..	Tax Collector	..	60—4—80/5—120/5—175
Shri Chander Bhan	..	Toll Post Moharrir		40—2—60
Shri Atam Parkash	..	Ditto		Ditto
Shri Kirpa Ram	..	Peon	..	30—½—35
Shri Des Raj	..	Peon	..	Ditto
Shri Shadha Ram	..	Toll Post Chaukidar		75 consolidated
Shri Satya Pal	..	Ditto		Ditto
Shri Tara Singh	..	Kurukshetra Mela Store		Ditto

Decrease in Food Production

***7406. Sardar Gian Singh Rarewala** : Will the Minister for Home and Developmet be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there has been a great decrease in the food production since the start of the Third Five Year Plan;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative the steps so far taken to recoup the fall?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) A note is laid on the table of the House.

Note.—The following steps have been taken to recoup fall :—

(1) A sum of Rs 2.37 crores was provided for minor irrigation works. It is expected to bring an area of 1.18 lac acres under irrigation.

(2) With a view to checking soil erosion and for conserving moisture, soil conservation measures were intensified during the year and an area of 40,000 acres was covered.

(3) 2,500 acres of Banjar land will be broken and brought under cultivation during the year.

[Home and Development Minister]

(4) Intensive cultivation programmes were initiated during the year on Rice and Wheat in order to exploit the potential quickly on the following crops :—

(i) *Rice.*—Intensive cultivation work on rice was carried out in 22 blocks in the districts of Karnal, Gurdaspur, Amritsar, Hoshiarpur and Kangra covering a total area of 1.78 lac acres.

(ii) *Wheat.*—58 Blocks were selected for this purpose in the districts of Rohtak, Hissar, Bhatinda Ferozepur, Karnal, Hoshiarpur, Amritsar, Gurdaspur, Kapurthala and Sangrur covering a total area of 5.80 lac acres. In addition about 3 lac acres of wheat were covered under the Intensive Agricultural District Programme, Ludhiana.

In these Intensive cultivation blocks additional staff to the extent of one Extension Officer, Agriculture and Five Acricultural Sub-Inspectors were appointed for Gadh block. Training of farmers on extensive scale was taken up in these areas followed by adequate supplies of seed, fertilisers and pesticides.

(5) *Supply of Fertilisers.*—Applications of fertilisers to the crops is the quickest method of increase in Agricultural production. This state has made appreciable progress in this respect. The fertiliser consumption has stepped up from 37,000 tons in the year 1960-61 to 1.84 lac tons in the year, 1963-64. During the current year, it is estimated that the consumption will be well over 2.75 lac tons.

(6) *Seed.*—The seed distribution programme has been considerably expanded during the year. Against about 60,000 mds. of wheat seed supplied during the last year, more than 2.5 lac maunds of seed were supplied during the current year.

(7) Plant protection operations were also intensified during the year and the area covered is four times than last year.

(8) In order to boost Agricultural production the Punjab Government decided to :—

(i) make organisational changes for better coordination amongst various departments connected with the Agricultural production.

(ii) Various incentives were given to the farmers for increasing agricultural production. These are—

(a) In the supply of Cement and G.I. Sheets to the agriculturist, the preference will be given to the intensive agricultural areas.

(b) Previously only loans were given for the purchase of threshers. Now Government have decided to subsidise the purchase of Small threshers costing less than Rs 700 to the extent of 25 per cent subject to a maximum of Rs 150 per thresher.

(c) In order to encourage the installation of diesel driven tube wells/pumping sets in non-electrified areas subsidy equal to 25 per cent of the cost of diesel engine ; subject to a maximum of Rs 750 per diesel engine has been allowed.

(d) Previously 50 per cent subsidy was available on all insecticides in the Package Programme and Hill areas. In other areas, the subsidy available was 25 per cent. In order to promote the use of insecticides, Government have decided that the cost of pesticides should be subsidised to the extent of 50 per cent in all parts of the State.

(e) In order to step up the consumption of fertilizers Government have decided to subsidise the cost of Potassic fertilizers to the extent of 25 per cent. Previously subsidy equal to 25 per cent of the cost of fertilizer was being given in respect of only Phosphatic fertilizers.

(f) 50 per cent subsidy has been decided to be given on agricultural implements. Previously this facility was available in case of ploughs only and that too to the extent of 25 per cent.

(g) Electricity duty has been abolished in the case of tube-wells.

(h) For the benefit of the small growers, seed has been distributed on taccavi for the first time.

Introduction of Crop Loan System

*7409. **Sardar Gian Singh Rarewala :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether the Union Ministry of Community Development and Co-operation has suggested to the State Government the introduction of crop loan system ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative whether the said system has been introduced in all the districts of the State, if so, the basis for fixing the credit limit ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) The system was introduced on an experimental basis in the district of Ludhiana which is covered by Intensive Agricultural Development Programme. This experiment has now been extended to the intensive Cultivation districts of Rohtak, Karnal and Ferozepur. The basis of fixation of the credit limit under this system, which envisages fulfilment of short-term credit needs of each cultivator-member of the society, is determined with reference to the prevalent scales of production expenditure in respect of different crops. The credit is met up to the limit of the member's 'repaying capacity.

Deputy Registrars, Co-operative Societies

*7870. **Shri Banwari Lal :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of Deputy Registrars Co-operative Societies working in the State at present together with the names and qualifications of each ;

(b) the names of persons out of those referred to in part(a) above who have been recruited without written test held by the Public Service Commission ?

Sardar Darbara Singh : (a) There are twelve Deputy Registrars including those under the administrative control of the Director of Industries Punjab) working in the State at present. Their names and qualifications are given in the statement annexed.

(b) No written test has been prescribed for appointment/promotion to the post of Deputy Registrar. All such appointments and promotions are, however, made in consultation with Public Service Commission under the relevant service rules. With the exception of No. 5, Shri Shiv Lal, who was selected through Public Service Commission, from the open market, all other officers were promoted from the rank of Assistant Registrars Co-operative Societies

[Home and Develoment Minister]

ANNEXURE

Serial No.	Name	Qualifications
1	Shri L.R. Kapur, Deputy Registrar, Package Programme, Ludhiana	B.A.
2	Shri Rajinder Singh , Deputy Registrar (Marketing) ..	B.A.
3	Shri Mahipal Singh, Deputy Registrar, Co-operative Societies, Rohtak	B.A.
4	Shri Bhim Singh, Deputy Registrar, Co-operative Societies, Jullundur	B.Sc. (Agr.)
5	Shri Shiv Lal, Deputy Registrar (Ind.), Ludhiana ..	B.A., LL. B. (Hons.)
6	Shri Gurcharan Singh, Deputy Registrar (Planning) ..	B.A, LL. B.
7	Shri Behari Lal Rao, Deputy Registrar (Hill Areas), Hoshiarpur.	B.A.
8	Shri Hardyal Singh, General Manager, Batala Sugar Mills, Batala	B.A.
9	Shmt. B. K. Rai, Deputy Registrar, Co-operative Societies, Patiala	B.A.
10	Shri Dharam Singh, Deputy Registrar, Pong Dam (Talwara)	B.A., LL. B.
11	Shri Asdev Singh, General Manager, Patiala Central Co-operative Consumers Store, Patiala	B.A.
12	Shri R.M. Thapar, Deputy Registrar, Headquarters, Industries, Department.	B.Sc., LL. B.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Publicity Supervisors etc.

2381. Shri Hunna Mal : Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) the total number of Rural Publicity Superisors, Organisers and Workers retrenched in December, 1964, districtwise, and a list showing their names,designations and length of service at the time of retrenchment be laid on the Table of the House;

(b) the grounds on which the said employees were retrenched;

(c) the total number of Supervisors, Orgainsers and Workers who have been retained in service in the Public Relations Department and a list showing their names be placed on the Table of the House ;

(d) whether Government is considering any proposal to confirm the Supervisors and Organisers referred to in part (c) above;

(e) whether the Department has prepared any seniority list of Supervisors and Organises a' present;

(f) the details of the steps being taken to re-organise the Rural Publicity Wing and the time by which it is likely to be completely re-organised ?

Shri Ram Kishan : (a) and (c) Statements giving the requisite information are enclosed.

(b) The retrenchment was necessitated by the re-organisation of the Department.

(d) No. The posts of Supervisors and Organisers are expected to be replaced by the new cadre soon after the selection.

(e) No.

(f) In place of Supervisors, Organisers and Workers, a new cadre of Information Assistants/Field Publicity Assistants is being created. The recruitment is likely to be completed very soon.

STATEMENT 'A'

District	Serial No.	Name	Designation	Date of Appointment	Date of Termination
1	2	3	4	5	6
Hissar	1	Shri Yadvindra Singh ..	Supervisor	13-2-62	26-12-64
	2	Shri Sukhwant Singh	Do	6-12-62	26-12-64
	3	Shrimati Raj Josh ..	Do	21-12-61	25-12-64
	4	Shri Pat Ram Verma ..	Organiser ...	12-12-56	26-12-64
	5	Shrimati Jai Devi ..	R.P.W.	18-12-61	26-12-64
	6	Shri Krishan Datt ..	Do	10-6-61	1-1-65
	7	Shri Jassa Ram ...	Do	2-3-61	28-12-64
	8	Shri Phool Singh ..	Do	1-1-60	1-1-65
	9	Shri Des Raj ..	Do	10-12-59	26-12-64
	10	Shri Mangal Sain ..	Do	23-11-53	26-12-64
	11	Shri Sundar Dass ..	Do	29-7-55	26-12-64
	12	Shri Ram Lal ..	Do	14-12-56	26-12-64
	13	Shri Girdhari Lal ..	Do	15-12-56	31-12-64
Rohtak	1	Shri Dayal Chand Miglani	Supervisor	26-4-61	24-12-64

[Chief Minister]

District	Serial No.	Name	Designation	Date of Appointment	Date of Termination
1	2	3	4	5	6
	2	Shri B.R. Wadhera ..	Supervisor	20-6-59	24-12-64
	3	Shrimati Gulab Kaur	Do	11-10-63	24-12-64
	4	Shri Devider Singh ..	Organiser	4-5-63	24-12-64
	5	Shri Chander Bhan ..	R.P.W.	23-10-62	25-1-65
	6	Shri Ram Singh	Do	2-8-63	24-12-64
	7	Shri Sobha Ram ..	Do	20-9-62	24-12-64
	8	Shri Siri Ram ..	Do	25-9-62	24-12-64
	9	Shri Daya Kishan ...	Do	14-1-63	24-12-64
	10	Shri Yad Ram ..	Do	27-10-55	24-12-64
	11	Shri Ram Narain ...	Do	31-12-59	24-12-64
	12	Shri Mange Ram ..	Do	26-7-56	24-12-64
	13	Shri Munshi Ram ...	Do	2-1-57	24-12-64
	14	Shri Partap Singh ..	Do	24-7-53	24-12-64
Gurgaon	1	Shri Mohinder Singh ..	Supervisor	5-6-61	24-12-64
	2	Shri Om Parkash ..	Do	7-9-62	24-12-64
	3	Shri Hari Ram Arya ..	Do	2-1-57 R.P.O.	24-12-64
	4	Shri Govind Ram ..	Organiser	28-4-64	24-12-64
	5	Shri Jagdish Sharma ..	Do	23-12-61	24-12-64
	6	Shrimati Tara Devi ..	Do	15-7-60	24-12-64
	7	Shri Dharam Paul Singh ..	R.P.W.	31-7-57	24-12-64
	8	Shri Krishan Chander ..	Do	16-3-59	24-12-64
	9	Shri Ram Chander ..	Do	7-3-61	24-12-64
	10	Shri Kundan Lal ...	Do	17-1-64	24-12-64
	11	Shri Abdul Majid ..	Do	27-5-64	24-12-64
Karnal	1	Shri Hara Nand Swami ..	Supervisor	10-12-56	24-12-64
	2	Shrimati Daya Kumari	Do	8-7-60	24-12-64
	3	Shri Krishan Murari ..	Organiser	16-3-63	24-12-64
	4	Shri Sehan Singh Parwana ..	Do	26-12-62	23-12-64

District	Serial No.	Name		Designation	Date of Appointment	Date of Termination
1	2	3		4	5	6
	5	Shri Ranbhir Singh	..	R.P.W.	11-12-58	24-12-64
	6	Shri Babu Ram	..	Do	31-7-59	24-12-64
	7	Shri Chater Singh	..	Do	1-10-62	24-12-64
	8	Shr Pali Ram	..	Do	20-1-63	24-12-64
	9	Shri Uttam Chand	..	Do	15-3-63	24-12-64
	10	Shri Nishan Singh	..	Do	9-1-63	26-12-64
	11	Shri Siri Dutt Sanehi	..	Do	19-8-63	26-12-64
	12	Shri Parma Nand	..	Do	28-10-63	24-12-64
	13	Shri Ram Kishan	..	Do	4-7-64	26-12-64
Ambala ..	1	Shri Ravinder Singh	..	Supervisor	9-10-63	26-12-64
	2	Shri Arjan Singh	..	Organiser	12-10-60	26-12-64
	3	Shrimati Krishna Devi	..	Do	5-10-62	26-12-64
	4	Shrimati Abnash Kaur	..	Do	19-10-62	26-12-64
	5	Shri Imam Din	..	Do	7-9-56	26-12-64
	6	Shrimati Asa Malik	..	Do	25-4-64	26-12-64
	7	Shri Kirori Shah	..	Do	1-1-64	26-12-64
	8	Shrimati Kunti Devi	..	Do	10-1-63	26-12-64
	9	Shri Asa Singh	..	Do	10-10-62	26-12-64
	10	Shri Mehtab Singh	..	Do	9-10-61	26-12-64
	11	Shri Qammar-ud-Din	..	Do	1 -5-62	26-12-64
	12	Shri Sohan Singh	..	Do	21-10-55	26-12-64
	13	Shri Gian Singh	..	Do	19-4-55	26-12-64
Simla ..	1	Shri Yash Ram Bhardwaj	..	R.P.W.	19-3-65	24-12-64
	2	Shrimati Satya Devi	..	Do	1-7-64	24-12-64
Kangra ..	1	Shri S. D, Qammar	..	Supervisor	28-9-60	24-12-64
	2	Shri Sihv Dev Singh	..	Organiser	26-5-59	24-1 -64
	3	Shri C. R. Prem	..	Do	11-9-63	24-12-64
	4	Shri Amar Singh	..	Do	9-8-63	24-12-64

[Chief Minister]

District	Serial No.	Name	Designation	Date of Appointment	Date of Termination
1	2	3	4	5	6
	5	Shri Gurdip Singh ..	Organisor	26-1-58	24-12-64
	6	Shrimati Shakuntla Kalia ..	Do	25-3-63	24-12-64
	7	Shrimati Janki Devi ..	Do	11-11-59	24-12-64
	8	Shri Vijay Sharma ..	R.P.W.	20-12-58	29-12-64
	9	Shri Gopal Singh ..	Do	15-6-64	29-12-64
	10	Shri Chander Sheikher ..	Do	21-10-53	24-12-64
	11	Shri Bhrat Singh ..	Do	19-10-53	2-1-65
	12	Shri Chuni Lal ..	Do	20-10-53	24-12-64
	13	Shri Lachhi Ram Verma ..	Do	18-7-61	24-12-64
	14	Shri Amar Chand Goswami	Do	17-4-63	24-12-64
	15	Shri Jagdish Singh ..	Do	16-2-63	24-12-64
	16	Shri Khimi Ram ..	Do	5-9-63	24-12-64
	17	Shri Tulsi Ram ..	Do	1-8-63	24-12-64
	18	Shri Lachi Ram Sharma ..	Do	28-12-63	24-12-64
	19	Shri Durga Dass ..	Do	20-12-61	24-12-64
	20	Shri Lachman Singh ..	Do	18-7-61	24-12-64
Hoshiarpur	1	Shri Kans Raj Gohar ..	Supervisor	10-8-63	24-12-64
	2	Shri Khusi Ram Shukla ..	Organisor	4-7-60	24-12-64
	3	Shri Sukhdev Mittal.	Do	19-10-59	24-12-64
	4	Shri Baldev Singh ..	R.P.W.	23-4-60	24-12-64
	5	Shri Arjan Dass ..	Do	23-11-55	24-12-64
	6	Shri Hazara Singh ..	Do	18-8-60	24-12-64
	7	Shri Gandhi Ram ..	Do	10-1-57	24-12-64
	8	Shri Karam Singh ..	Do	30-7-56	24-12-64
	9	Shri Chint Ram ..	Do	17-12-59	24-12-64
	10	Shri Charan Dass ..	Do	26-12-58	24-12-64
	11	Shri Jiwan Singh Tej ..	Do	29-7-58	24-12-64
	12	Shri Parmeshwari Dass ..	Do	25-4-56	24-12-64
	13	Shri Faqir Chand ..	Do	9-1-56	24-12-64

District	Serial No.	Name	Designation	Date of Appointment	Date of Termination
1	2	3	4	5	6
Jullundur	1	Shri Ram Nath Azad ..	Supervisor	20-1-58	24-12-64
	2	Shri Sant Kumar Juneja ..	Do	3-1-62	24-12-64
	3	Shri Om Parkash ..	Organiser	11-1-58	24-12-64
	4	Shrimati Shanti Devi	Do	10-2-61	24-12-64
	5	Shrimati Hardep Kaur ..	Do	6-11-59 (R.P.W.)	24-12-64
	6	Shri Jawand Singh ..	R.P.W.	27-7-56	24-12-64
	7	Shri Kartar Singh ..	Do	25-7-56	24-12-64
	8	Shri Darshan Singh ..	Do	16-10-58	24-12-64
	9	Shri Chanan Singh ..	Do	9-1-56	24-12-64
	10	Shri Joginder Singh ..	Do	3-1-59	24-12-64
	11	Shri Jangli Dass ..	Do	30-8-61	24-12-64
	12	Shrimati Jasbir Kaur ..	Do	27-11-61	24-12-64
	13	Shri Gurcharn Singh ..	Do	16-2-62	24-12-64
	14	Shri Gian Chand ..	Do	14-1-63	24-12-64
	15	Shri Raminder Singh ..	Do	18-2-63	24-12-64
	16	Shri Bhim Sain ..	Do	..	24-12-64
	17	Shri Daulat Ram ..	Do	20-12-63	24-12-64
Ferozepure	1	Shri Harbhajan Singh	Supervisor	12-3-62	26-12-64
	2	Shri Swaran Singh ..	Do	15-3-62	26-12-64
	3	Shri Amar Singh Nasad ..	Do	8-9-62	26-12-64
	4	Shri Narinder Kumar Beri	Organiser	4-8-59	26-12-64
	5	Shri Vijay Kumar ..	Do	31-8-62	26-12-64
	6	hri Bhola Singh ..	R.P.W.	19-5-64	29-12-64
	7	Shri Ram Chand ..	Do	25-4-55	29-12-64
	8	Shri Mohinder Singh ..	Do	8-11-63	26-12-64
	9	Shri Gurbachan Singh ..	Do	5-1-59	26-12-64
	10	Shri Devid Gazi ..	Do	26-9-62	26-12-64
	11	Shri Sardara Singh ..	Do	27-2-63	26-12-64
	12	Shrimati Avtar Kaur ..	Do	22-7-63	26-12-64

[Chief Minister]

District	Serial No.	Name	Designation	Date of Appointment	Date of Termination
1	2	3	4	5	6
	13	Shri Wassan Singh ..	R.P.W.	31-12-59	26-12-64
Ludhiana	1	Shrimati Joginder Kaur ..	Supervisor	6-8-59	26-12-64
	2	Shri Karnail Singh ..	Organiser	23-10-58 R.P.W.	26-12-64
	3	Shri Ram Singh ..	Do	19-1-62	26-12-64
	4	Shri Bal Krishan ..	Do	10-10-60	26-12-64
	5	Shri Randhir Singh ..	Worker	29-1-59	26-12-64
	6	Shri Naginder Singh ..	Do	10-1-57	26-12-64
	7	Shri Inder Singh ..	Do	20-7-56	26-12-64
	8	Shri Mohinder Singh ..	Do	8-12-56	26-12-64
	9	Shri Ajaib Singh ..	Do	22-10-53	26-12-6
	10	Shrimati Sharan Kaur ..	Do	12-6-61	26-12-64
	11	Shri Mulk Ram Sharma ..	Do	28-12-61	26-12-64
	12	Shri Hazara Singh ..	Do	12-10-62	26-12-64
	13	Shri Kehar Singh ..	Do	21-11-64	26-12-64
Amritsar	1	Shri Gian Chand ..	Supervisor	19-6-59	23-12-64
	2	Shri Chatter Singh ..	Do	2-11-59	23-12-64
	3	Shri Puran Singh ..	Do	10-10-60	23-12-64
	4	Shri Parshotam Dass ..	Do	24-2-61	23-12-64
	5	Shrimati Gurdarshan Kaur	Do	23-11-59	23-12-64
	6	Shrimati Gurmit Kaur ..	Do	20-5-61	23-12-64
	7	Shri Swaran Singh ..	Organiser	30-6-60	28-12-64
	8	Shrimati Abanash Kaur ..	Do	14-12-61	28-12-64
	9	Shrimati Sukesh Kapoor	Do	28-2-63	28-12-64
	10	Shri Wasan Singh ..	R.P.W.	28-4-55	28-12-64
	11	Shri Gurnam Singh ..	Do	21-4-55	28-12-64
	12	Shri Jagir Singh ..	Do	20-10-53	28-12-64
	13	Shri Karnail Singh ..	Do	5-9-57	28-12-64
	14	Shri Barkat Ram ..	Do	1-12-58	28-12-64
	15	Shri Shingara Singh ..	Do	19-1-60	28-12-64

District	Serial No.	Name		Designation	Date of Appointment	Date of Termination
1	2	3		4	5	6
	16	Shri Dharam Singh	..	R.P.W.	6-8-60	28-12-64
	17	Shri Ajit Singh	..	Do	20-9-63	28-12-64
	18	Shri Arjan Singh	..	Do	2-12-57	28-12-64
	19	Shri Kesho Dass Parwana	..	Do	16-8-60	28-12-64
	20	Shri Kaka Singh	..	Do	6-1-61	28-12-64
	21	Shri Kehar Singh	..	Do	12-9-60	28-12-64
	22	Shri Anoop Singh	..	Do	20-2-61	28-12-64
	23	Shri Banta Singh	...	Do	25-2-63	28-12-64
	24	Shri Puran Singh	...	Do	1-1-62	28-12-64
	25	Shrimati Gurdas Kaur	..	Do	27-7-63	28-12-64
	26	Shri Sucha Singh Safri	..	Do	25-2-63	28-12-64
	27	Shri Atma Singh	..	Do	28-10-55	28-12-64
	28	Shri Kartar Singh	..	Do	31-1-57	28-12-64
	29	Shri Chet Singh	...	Do	7-2-57	28-12-64
	30	Shri Vir Singh	...	Do	27-10-55	28-12-64
Gurdaspur	1	Shri Sat Pal	..	Supervisor	12-10-62	26-12-64
	2	Shri Parlok Singh		Do	16-6-59	26-12-64
	3	Shrimati Sarla Prasher	..	Do	9-12-57	26-12-64
	4	Shrimati Swadesh Saikhri		Organiser	11-7-59	26-12-64
	5	Shrimati Indera Mohni	..	Do	5-10-62	26-12-64
	6	Shrimati Lal Devi	...	Worker	8-1-63	26-12-64
	7	Shri Devi Sarn Sharma	..	Do	18-1-63	26-12-64
	8	Shri Arjan Singh	..	Do	9-6-60	26-12-64
	9	Shri Ram Murti	...	Do	22-10-63	26-12-64
	10	Shri Gulzar Singh	...	Do	18-10-63	26-12-64
	11	Shri Baldev Raj	..	Do	21-10-53	26-12-64
	12	Shri Jagat Ram	...	Do	8-9-56	26-12-64
	13	Shri Piara Singh	..	Do	6-1-62	26-12-64
	14	Shri Chhaju Ram	...	Do	4-1-62	26-12-64
	15	Shri Phagu Ram	...	Do	21-9-60	26-12-64

[Chief Minister]

District	Serial No.	Name	Designation	Date of Appointment	Date of Termination
1	2	3	4	5	6
Patiala	1	Shri Harpal Singh Bedi	Supervisor	10-10-60	24-12-64
	2	Shri Gurcharan Singh Kohli	Organiser	10-10-60	24-12-64
	3	Shri Janak Singh ..	Worker	20-9-58	24-12-64
	4	Shri Dalip Singh ..	Do	23-7-60	24-12-64
	5	Shri Pala Singh Pal ..	Do	1-2-62	24-12-64
	6	Shri Babu Ram	Do	11-12-56	24-12-64
	7	Shrimati Partap Kaur ..	Do	21-12-56	24-12-64
	8	Srimati Kartar Kaur ..	Do	27-8-63	24-12-64
Kapurthala	1	Shri Mohinder Singh	Supervisor	25-5-59	25-12-64
	2	Shrimati Pritam Kharbanda	Organiser	5-10-62	25-12-64
	3	Shri Piara Singh ..	Worker	4-11-60	25-12-64
	4	Shri Bhagat Ram ..	Do	24-12-58	25-12-64
	5	Shrimati Vidya Vati ..	Do	22-8-63	25-12-64
	6	Shrimati Prem Kumari Sondhi	Worker	14-1-63	25-12-64
	7	Shri Inder Singh ..	Do	21-12-61	25-12-64
	8	Shri Harbans Singh ..	Do	16-8-60	25-12-64
Sangrur	1	Shri Hari Singh	Supervisor	6-11-63	24-12-64
	2	Shri Tulsi Ram ..	Organiser	19-7-63	25-12-64
	3	Shrimati Kusam Lata Bedi	Do	26-6-57	25-12-64
	4	Shrimati Padma Bindal ..	Do	24-11-61	..
	5	Shri Bhat Ram ..	Do	11-12-62	24-12-64
	6	Shri Munshi Ram ..	Do	7-1-59	24-12-64
	7	Shri Virsa Singh ..	Do	20-1-59	26-12-64
	8	Shri Rameshwar Sharma ..	Do	17-12-59	31-12-64
	9	Shri Chet Ram ..	Do	13-12-59	29-12-64
	10	Shri Gurbax Singh ..	Do	6-11-59	31-12-64
	11	Shri Banarsi Dass ..	Do	24-1-57	24-12-64
	12	Shri Ram Sarup ..	Do	28-10-58	31-12-64
Narnaul	1	Shri R.D. Joshi ..	Organiser	..	25-11-64

District	Serial No.	Name	Designation	Date of Appointment	Date of Termination
	2	Shri Udmi Ram	.. Worker	4-10-63	25-11-64
	3	Shrimati Shanti Devi	Do	1-7-64	25-11-64
Bhatinda	1	Shrimati Gurdial Kaur	.. Supervisor	6-3-63	24-12-64
	2	Shri Natha Singh	.. Organiser	23-4-55 R.P.W.	24-12-64
	3	Shri Raj Singh	.. Worker	13-11-58	24-12-64
	4	Shri Bhag Singh	.. Do	17-8-60	24-12-64
	5	Shrimati Surjit Kaur	Do	29-8-61	24-12-64
	6	Shri Darshan Singh	.. Do	8-12-61	24-12-64

STATEMENT 'B'

Supervisors ..
1. Shri Shankar Lal
2. Shri Chander Bhan
3. Shrimati Shakuntla Kumari
4. Shri Chatter Sain Goel
5. Shri A. N. Kavisher
6. Shri R.P. Dhawan
7. Shri Gurmukh Singh
8. Shri Rajbir Singh
9. Shri Subhash Narula
10. Shri A.K. Saigal
11. Shrimati Sharda Sethi
12. Shrimati Bhupinder Paul Kaur
13. Shrimati Laj Bedi
14. Shri B.L. Mehra
15. Shrimati Raman Sharma
16. Shri Vinod Kumar Lakhanpal
17. Shri Rajinder Kumar
18. Shri Sukhpal Vir Singh Hasrat
19. Shri S.K. Saroor
20. Shrimati Pushpa Jain
21. Shri Babu Singh
22. Shri Puran Chand
23. Shri Sulakhan Singh
24. Shri Basant Kumar Sharda
25. Shri Jagmohan Singh
26. Shri N.S. Shad
27. Shri Sat Vir Singh Rana
28. Shrimati Savitri Malik
29. Shrimati Promilla Kapoor

Organisors ..
1. Shri Shiv Singh
2. Shrimati Kusam Lata Jain
3. Shri B.J. Kapoor
4. Shri Sushil Chand Rattan
5. Shri Rup Chand Misra
6. Shri Amar Nath
7. Shri Dharam Paul
8. Shrimati Sukarma Sharma
9. Shrimati Raj Rani Bali
10. Shrimati Swadesh Kumari
11. Shrimati Jaswant Kaur
12. Shri Narinder Nath Sharma

[Chief Minister]

13. Shri Babu Singh
14. Shri Bishan Sarup Kaushik
15. Shrimati Swatantar Kapoor
16. Shrimati Shakuntla Kumari

Workers * * *

Landed Property of late Shri Dalip Singh in village Naudharani, tehsil Malerkotla, district Sangrur

2382. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is no legal heir of late Shri Dalip Singh, son of Shri Karam Singh of village Naudharani in tehsil Malerkotla, district Sangrur; if so, the total area of his landed property ;

(b) whether it is also a fact that the said land has not been transferred as Nazool land so far,if so, the reasons therefor ?

Sardar Harinder Singh Major: (a) The contested mutation in respect of inheritance of Shri Dalip Singh, son of Karam Singh of village Naudharani, is pending and it is yet to be decided as to who is entitled to get the inheritance in question. Accordingly, it is not possible to say at this stage that there is no legae heir of the deceased. The total area of the landed property of the deceased is 137 bighas and 4 biswas

(b) Since the mutation is pending, the property in question cannot be treated as Nazool land.

District Welfare Officer, Kangra

2383. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the academic qualifications if any, fixed for the post of District Welfare Officer ;

(b) whether the present district Welfare Officer, Kangra (Dharamsala) possesses the qualifications referred to in part (a) above: if not, the reasons for which he has been promoted as such ;

(c) the capacity in which he joined the Welfare Department ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) (i) In case of direct recruitment—

Graduate of a recognised University with at least 5 to 8 years experience of Social Work especially amongst Scheduled Tribes and Backward Classes. Persons with thorough understanding of Harijans' problems and imbued with a spirit of public service to be given special preference.

(ii) By promotion—

Matric with seven years, experience as Tehsil Welfare Officer and Social Worker.

---

*Note—Statement printed as received from Government.

(b) and (c) At present there is no District Welfare Officer, Kangra, at Dharamsala. The work is looked after by a Tehsil Welfare Officer as a stop gap arrangement.

Loan for starting Poultry Farms by Harijans

2417. Shri Fakiria : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Harijans are required to furnish two sureties of Rs 15,000 each in order to get a loan of Rs 5,000 for starting a poultry farm ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative whether the Government is aware of the fact that none from amongst the Harijans is capable of standing surety for Rs 15,000;

(c) whether he is further aware of the fact that four Harijans who had received poultry training had applied to the Uchana and Narwana Panchayat Samitis in Sangrur District for loans of Rs 5,000 each but who have not been advanced any loan; if so, the reasons therefor ;

(d) whether Government propose to issue instructions for reducing the amount of sureties to say Rs 5,000 to enable the Harijans to secure the said loans?

Shri Ram Kishan : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Loans under the State Aid to Industries Act are not granted by the Panchayat Samitis.

(d) Does not arise.

Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors Charge-Sheeted/Suspended in the State

***2418. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the number and names of Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors who were charge-sheeted/suspended in the State, district-wise, during the period from January, 1964 to-date and the reasons therefor in each case ;

(b) the number and names of Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors from amongst those mentioned in part (a) above who have been re-instated by the Government during the said period ?

Sardar Darbara Singh : (a) 307 Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors were charge-sheeted/suspended in the State during the period from January, 1964 to-date. Their names, District/Unit-wise, alongwith the reasons therefor are given in the enclosed statement No. I.

(b) 45 Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors were re-instated during this period by the competent Police authorities. None was re-instated by the Government. Their names District/Unit-wise are given in the enclosed statement No. II.

STATEMENT NO. I

List showing the names of Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors, who were Charge-sheeted/Suspended during the period from January, 1964 to-date and the reasons therefor

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/Reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	PUNJAB ARMED POLICE		
1	S.I. Roshan Lal, No. PAP/161	For absenting himself from PAP Guard, Hydel Channel Canal without permission and going to Anandpur Sahib where he was found drunk	Yes
2	S.I. Kulwant Singh, No. PAP/144	For mis-appropriation of Government money	Do
3	S. I. Bakhtawar Singh, AP Bn./12	For making a false statement before Court of Inquest-cum-Enquiry	No
4	S.I. Karnail Singh, 200 ..	For abusing each other after taking liquor	Do
5	S.I. Kartar Singh, 35/AP Bn	Ditto	Do
6	S.I. Amar Singh, 310 ..	For negligence and carelessness in taking out inadequate patrol party without permission from Coy. Hqrs.	Do
7	S.I. Mani Ram	For being found negligent in the performance of duty	Do
8	S.I. Darbara Singh, No. 121/PAP	For misconduct	Do
9	A.S.I. Sowaran Singh, No. 258	For having been found in a drunken condition at Picket, Kassoke	Yes
10	A.S.I. Sardara Singh , No. 255	For showing culpable negligence in pursuing a case on the border	Do
11	A.S.I. Sucha Singh, No. 356	Severe allegation of misconduct against them	Do
12	A.S.I. Charanjit Singh, No. 4562		
13	A.S.I. Surjan Singh, No. 50	For taking liquor and threatening two Consts. of his Picket with dire consequence	Do
14	A.S.I. Harbans Singh, No. 921	For not allowing the Coy. Commander to record a report against Const. Surjit Singh	Do
15	A.S.I. Surjan Singh, 50	For making a false statement before Court of Inquest-cum-Enquiry	No
16	A.S.I. Jagtar Singh, 2326	Collection of subscription and mis-appropriation of Rs 127	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/Reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	PUNJAB ARMED POLICE—CONCLD		
17	A.S.I. Jaldev Singh, 2988	Misbehaving with public under the influence of liquor	No
	GOVERNMENT RAILWAY POLICE		
18	S.I. Khushal Singh, No. R/6	Case under section 342, IPC wrongful confinement	Yes
19	A.S.I. Niranjan Singh, No. 723/GRP	Ditto	Do
20	A.S.I. Kirpal Singh, No. 17/GRP	Case under section 379, IPC.	Do
21	S.I. Bhiwani Shanker, No. 16/R	For disposing case property	No
22	S.I. Lachman Singh, No. R/1	Misbehaviour with public ..	Do
23	A.S.I. Raghu Nath, No. 8/R	Late submission of case diaries ..	Do
24	A.S.I. Hari Parkash, No. 29/R	Ditto	Do
25	S.I. Balbir Singh, No. 2/R	Charge of inefficiency ..	Do
26	S.I. Sant Parkash Singh, 18/R	Ditto	Do
27	S.I. Yog Dhian, No. 39/R	Ditto	Do
28	S.I. Jagdish Lal, No. R/7	Ditto	Do
29	A.S.I. Raghu Nath, No. 8/R	Ditto	Do
	HISSAR DISTRICT		
30	S.I. Mohar Singh, No. 202/A	For contravening the provisions of P. R. 18.38 (6).	No.
31	A.S.I. Guru Datt, No. 365/KNL	For writing case diaries with inordinate delay	No
32	A.S.I. Madan Lal, No. 513/GGN	Ditto	Do
33	A.S.I. Jai Pal, No. 304/GGN	Ditto	Do
34	A.S.I. Amar Nath, No. 683/RTK	Ditto	Do
35	S.I. Chuni Lal, No. 153/A	For accepting illegal gratification	Yes
36	S.I. Sohan Lal, No. A/16	Under section 5 (2) 47 of PC Act	Do

[Home and Development Minister]

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/Reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
		HISSAR DISTRICT—CONCLD	
37	A.S.I. Ram Parkash, No. 516/GGN	Under section 5(2) 47 of PC. Act	yes
38	A.S.I. Sardar a Singh, No. 855/Hissar	Under section 25/54/59, Arms Act	Do
39	A.S.I. Hardit Singh, No. 739/KNL	Under section 5 (2), 47 PC. Act	Do
40	A.S.I. Amir Chand, No. 95/KNL	Under section 5 (2). 47, PC. Act and under section 161 IPC	Do
		ROHTAK DISTRICT	
41	A.S.I. Raja Ram ..	Under section 325/342, IPC	Yes
42	S.I. Ram Rakha, No. A/132	Under section 5(2) 47 PC. Act	Do
43	A.S.I. Bhan Singh No. 31/A	Ditto	Do
44	S.I. Saudagar Singh, 58/A	For negligence in the investigation of case FIR No. 279, dated 23rd December, 1963, under section 302 IPC police station, Sonepat	No
45	S.I. Mehtab Singh A/80	Ditto	Do
46	S.I. Kundan Lal, 52/A	For submitting delayed case diaries	Do
47	S.I. Balwant Singh, 174/A	For lack of control, while posted S.H.O., police station, Salawas	Do
48	S.I. Lal Singh, No. 91/PAP	Failure to take preventive action against the assailants in case FIR No. 49/62, under section 302/148/149, IPC, police station Ganaur and defective investigation in case FIR No. 69/63, under section 457/380 IPC and 70 and 71/64 under section 9/1/28	Do
49	A.S.I. Havali Ram, 58/UMB	For recording false entry of his departure in the D.D. while posted at police station Sirvani, district Hissar	Do
50	A.S.I Pran Nath, 186/SML	For not taking care for the safe custody of case property while posted in C.I.A. staff, Rohtak	Do
51	A.S.I. Ude Ram 217/RTK	For negligence in the investigation of case FIR No. 279, dated 23rd December, 1963 under section 302, IPC, police station, Sonepat	Do
52	A.S.I. Hari Singh, 56/UMB	For poor work, while posted in Excise Staff at Sonepat	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/Reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	ROHTAK DISTRICT—CONCLD		
53	A.S.I. Haveli Ram, 58/UMB	For travelling without ticket in a Punjab Roadways Bus	No
54	A.S.I. Kuldip Chand, 187/RTK	For submitting delayed case diaries	Do
55	A.S.I. Avtar Kishan, 245/A	Ditto	Do
	GURGAON DISTRICT		
56	S.I. Harsarup, No. 247/A	For lack of control over his subordinates and over the B.Cs. of the Ilaqa	No
57	A.S.I. Des Raj, No. 48/A	For delaying the investigation of case FIR No. 22/63 under section 307/325 IPC, police station, Palwal	Do
58	S.I. Rachhpal Singh ..	For having accepted illegal gratification	Do
59	S.I. Kesar Singh, No. 56/A	For dela ying the submission of case diaries in many cases	Do
60	A.S.I. Pritam Singh, No. 419/GGN	D.D. of police station Chhansa and for accepting For making wrong entries in illegal gratication of Rs 175	Do
61	S.I. Tej Ram ..	For burking of cases	Do
62	S.I. Ritu Dhawaj ..	For corruption ..	Do
63	S.I. Darbara Singh, No. 230/A	For corruption and burking ..	Do
	AMBALA DISTRICT		
64	S.I. Gurnam Singh 240/A	He was detected travelling without tickect in Bus No. 5131 PNE and he refused to sign the statement when asked by the Special Squad Finance Department, Punjab	Yes
65	S.I. Harbachan Singh, 30A	Strictures in case under section 302, IPC, police station, Chandigarh, were passed against the S.I. by the Additional Sessions Judge, Ambala	Do
66	S.I. Madan Lal A/90	For having been arrested in case FIR No. 182, dated 29th April, 1964, under section 342, IPC, police station Chandigarh	Do
67	A.S.I. Madan Lal, 232/GGN	He obtained some fruits, vegetables and cloth from certain shopkeepers of Ambala Cantt. and Ambala City by misrepresenting facts. He gave out his wrong identity and employed deceitful means in order to obtain these articles without payment. He remained absent from the Police Lines on 6th March, 1964 and 8th March, 1964, without permission	Do

[Home and Development Minister]

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	Ambala Distt. Coutd.		
68	A.S.I. Ram Gopal, 142/ RTK	He was detected by the Special Squad Finance Department travelling without ticket in Bus No. 2346/PNU of Punjab Roadways on 9th October, 1964 near Ambala City	Yes
69	A.S.I. Jagat Singh, 35/ UMB	He, while posted at police station Ambala Cantt, was arrested and sent up in case FIR No. 272, dated 12th July, 1964 under section 354/294, IPC, police station Ambala Cantt. He was acquitted by the Chief Judicial Magistrate, Ambala on 11th January, 1965 by giving him benefit of doubt and is now facing departmental enquiry.	Yes
70	S.I. Ram Pat, No. 272/A	He did not take any action on the complaint of Shri Banta Singh of village Chalaki police station Morinda during his tenure at police station Morinda	No
71	S.I. Krishan Kumar, 172/A	He, while posted as O.A.S.I./S.P. office, Ambala, by his negligence allowed C. Gurdas Singh, 749 to continue as orderly to Inspector Gurnam Singh, when the Inspector was under suspension and was transferred to Karnal. He also tampered with the record of posting of constable	No
72	S.I. Moti Singh, A/7 ..	He was not vigilant about the party factions in village Burail, where hurt cases were registered against the parties.	No
73	S.I. Mohinder Singh ...	He was liable for the inherent defects in the investigation of case FIR No. 27, under section 307/148, IPC and 9/1/78, A. Act, police station Ambala Cantt.	No
74	S.I. Dalip Singh, A/44 ..	For acts of omission and commission detected by S.P., Ambala during the Inspection for the 3rd and 4th quarters of 1963. He did not use Scientific methods of investigations in any case	No
75	S.I. Sadhu Singh, 173/A ...	While posted at police station Kharar, he was responsible for various acts of omissions and commissions as noted in the Inspection note of police station Kharar for the last 6 months of 1963	No
76	S.I. Rattan Singh, 97/A ...	He did not register a case nor entered any report in the Daily Diary Register on receipt of a report from one Ram Singh of Sadhaura regarding theft of his trees from his fields	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Wrether suspended or not
1	2	3	4
	Ambala District Contd		
77	S.I. Krishan Kumar, 172/A	The S.I. used filthy language to Shri Sadhu Ram, Sarpanch of Shiampur when the later refused to withdraw the complaint under section 323/504, IPC, which he had filed in the court of J.M. Rupar against Shri Mohinder Singh, Inspector, Food and Supplies Rupar	No
78	P.S.I. Braham Sarup, R/144	For not fully representing the prosecution case in a court	No
79	S.I. Inderjit Singh, 34/A	He investigated case FIR No. 7, dated 23rd March, 1964 under section 302, IPC, police station Bilaspur. He told Shri Bhan Singh complainant at the initial stage of the investigation without verifying facts that it was a case of suicide and not of murder. Moreover, when Bhan Singh, father of the deceased along with others went to the police station on 23rd March, 1964, the S.I. misbehaved with them and forcibly turned them out of police station	No
80	P.S.I. Ishwar Parshad, R/36	The Additional Sessions Judge, Ambala while setting aside the conviction of an accused in case FIR No. 99, dated 10th July, 1963 under section 353, IPC police station Rupar made some observations regarding the manner in which the case was conducted on behalf of the prosecution in the court of J.M., Rupar	No
81	S.I. Harbachan Singh 30/A	In case FIR No. 16, dated 21st February, 1963, under section 162/163 IPC, police station Chamkaur Sahib while acquitting the accused the J.M., Rupar passed strictures against S.I. Harbachan Singh, that S.H.O. did bungling in the investigation of the case and against C. Darbara Singh that integrity of Constable was highly questionable	No
82	S.I. Kharati Lal, A/109 ..	No effort was made for service of notice on the accused in case St. Vs. Jaga and others under, section 363 IPC, police station Rupar, issued from the Sessions Court, Ambala with the result that all the witnesses had to return without examinating in court	No
33	S.I. Krishan Lal, A/13 ..	During the Inspection of police station Chandigarh by S.P for the first 2 quarters of 1964, it was seen that the S.I. was habitual in writing case diaries with delay	No
84	S.I. Jagdish Chander 171/HSR	He proceeded on 10 days C.L. from P.P. Sector 11 with out permission	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	Ambala Distt. –Contd.		
85	S.I. Gurchet Singh, 138/A	Strictures were passed against him in case FIR No. 76, dated 2nd October, 1962 under section 19/11/78 A. Act and 25/54/59A. Act police station Morinda by J.M., Rupar	No
86	A.S.I. Gurchet Singh, 138/A (now S.I.)	He did not take any action on the complaint of Shri Banta Singh of village Chalaki, police station Morinda during his tenure at police station Morinda	No
87	A. S.I. Babu Singh 497/SML	During the formal Inspection of police station Chandi Mandir for the 3rd and 4th quarters of 1963, various acts of omissions and commissions on the part of ASI particularly the delay with which he investigated the cases during his posting came to notice	No
88	A.S.I. Hira Lal, 258/A	S.H.O Mullana handed over some property taken into possession under section 550, Cr. P.C. in case FIR No. 11/62, under section 457/380, IPC, police station Mullana to A.S.I. Hira Lal with the direction that he should get deposited in police station Malkhana. He did not deposit the property although he got an entry made to this effect by H.C. Hari Singh 180 in the daily diary who was working as MHC in the absence of H.C. Hussan Lal 534	No
89	A.S.I. Shanti Sarup, 489/KNL	It was alleged in an annonymous complaint received from a Congress Worker that the A.S.I. had been receiving monthly from Satta gamblers of Yamuna Nagar. He had also accepted Rs 150 as bribe from one Kulwant Rai for hushing up a case against him	No
90	A.S.I. Ram Avtar, 26/A (now S.I.)	While posted at police station Kharar, he was responsible for various acts of Commissions and Commissions as noted in the Inspection note of police station Kharar for the last 6 months of 1963	No
91	A.S.I. Babu Singh, 497/SML.	It is alleged that the A.S.I., while posted at police station Chandigarh recovered a buffalo belonging to Shri B. R. Saraf from the possession of one Gopi Ram of Bajwara, under section 550 Cr.P.C. Thereafter he handed it over to Duni Chand of Bajwara on Sapurdari without obtaining any order of Magistrate. He neither registered a case when buffalo was recovered and identified by Shri B. R. Saraf nor made any entry to this effect in the daily diary	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	AMBALA DISTRICT—*Contd*		
92	A.S.I. Jagdish Chander, 191/HSR.	He, while posted at police station Sadhaura, investigated certain cases in which he committed grave irregularities	No
93	A.S.I. Tilak Raj, 503/SML.	He abused and misbehaved with one Kesar Singh a Social Worker of Manakpura, district Karnal on 13th November, 1963 in connection with a case under section 107/151, Cr.P.C. against Shangara Singh and others, while he was posted at police station Yamuna Nagar	No
94	A.S.I. Tilak Raj, 503/SML.	It is alleged that during his posting at Yamuna Barrier on U.P.-Punjab Border, he knowingly encouraged the import of gur, shakar and khandsari from the State of U. K. into the State of Punjab, after receiving illegal gratification	No
95	A.S.I. Kirpa Ram, 409/HSR.	He disobeyed the order of D.S.P./Rupar and did not take preventive action, as suggested by the D.S.P. and as a result of which rioting took place between the parties and 2 cross cases of hurt were registered	No
96	A.S.I. Jagat Singh, 35/UMB.	He along with 4 Constables and Shibu and Surat Singh, went to the house of one Din Mohd. in his absence and enticed away his daughter Mst. Rafiqan. The A.S.I. neither registered any case nor obtained any warrant in this connection	No
97	A. S.I. Jagjit Singh, 26/PR	He, while posted at Kharar, received the Chemical Examinors report on 6th August, 1958 in case FIR No. 127/57, under section 61/1/14 E. Act, police station Kharar, but negligently he misplaced the same with the result that the case could not be put in court within the period of one year and the case had to be referred to the Government for sanction of prosecution	No
98	A.S.I. Suraj Bhan, 556/KNL.	He, while posted as O.A.S.I. in Superintendent Police Office, Ambala, was responsible for loss of papers regarding preliminary enquiry against Inspector, Ishar Dass, ex-S.H.O., Ambala Cantt.	No
99	A.S.I. Naunihal Singh, 522	He gave beating to one Ganpat of village Rachheri at the instigation of Dalip Singh of the village and detained Ganpat and Ram Partap for the night in the Dharamsala. He let them off on the entreaties of Gurdit Singh and Ram Gopal, etc. of the village	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	AMBALA DISTRICT—CONCLD		
100	A.S.I. Ratti Ram, 241/A	Shri Krishan Lal, Member, Panchayat and Bakshi Ram, Harijan approached the A.S.I. with the complaint against Prem Singh, Tahl Singh which was duly endorsed by D.S.P., Chandigarh in the name of A.S.I. Ratti Ram. The A.S.I. instead of looking into the complaint as warranted by law, insulted, abused and assaulted them in the police station without any reason. As a result thereof Bakshi Ram and Krishan Lal received injuries	No
101	A.S.I. Rachhpal Singh, 689/GGN.	He maltreated one Satish Kumar of Naraingarh and when Shri Gurcharan Singh, S.I. Industrial Co-operative Societies, Naraingarh went to the police station and requested the A.S.I. not to maltreat Satish Kumar, the A.S.I. arrested and hand-cuffed S.I. Gurcharan Singh, Satish Kumar on one side and Mohan Lal on the other. Later the A.S.I. released S.I. Gurcharan Singh and removed his hand-cuffs without obtaining orders of the competent authority after he had been satisfied that he would be paid some money	No
102	A.S.I. Babu Singh, 499/KNL.	He was not vigilant about the party factions in village Burail, where hurt cases were registered against the parties headed by Phool Singh and Amarjit Singh	No
	KARNAL DISTRICT		
103	A.S.I.Om Parkash, 199/A	For disobeying the order, by which he was transferred from police station Thaska to police station Nissing in as much as he failed to carry out the same	Yes
104	A.S.I. Gurbux Singh, No. 2/A.	For not complying with the orders of Shri Y. S. Nakai, D.S.P., passed on the memorandum of case FIR No. 112, dated 8th November, 1961, under section 324 IPC., police station Sadar Sirsa	No
105	S.I. Ram Pat, 212/A. ..	For not taking cognizance of a complaint of Shri Banta Singh	No
106	A.S.I. Raj Kumar, No. 228/KNL.	For delaying the investigation of case FIR No. 135, dated 13th August, 1963, under section 325/324, IPC., police station Butana for about two months	No
107	A.S.I. Sampuran Singh, 405/HSR.	For not taking preventive action in respect of a fight between Jagdish Rai and Nihal Chand	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	KARNAL DISTRICT—CONTD		
108	A.S.I. Gurbux Singh, 2/A.	For failing to comply with the order of D.S.P., Sirsa requiring him to trace the identity of the woman, who gave birth to the child and threw it in the canal	No
109	S.I. Ram Pat, No. 212/A.	For having mis-behaved with Shri Ram Dhari, M.L.A.	Yes
110	A.S.I. Joginder Nath, No. 461/SML.	For dereliction of duty in as much as he delayed the investigation of case FIR No. 80 dated 19th October, 1962 under section 409/467, IPC.	No
111	A.S.I. Sampuran Singh, No. 405/HSR.	For late submission of case diaries	No
112	S.I. Gian Singh, No. 25/A	For late submission of case diaries	No
113	A.S.I. Shankar Dass, 380/Ambala	Ditto	No
114	A.S.I. Ram Chander, No. 21/A	For defective investigation in case FIR No. 131, dated 28th September, 1962 under section 307/148/149, IPC, police station Pehowa	No
115	A.S.I. Raj Kumar, 281/KNL.	For delaying the investigation of case FIR No. 115/64, under section 302, IPC., 161/64, under section 125(2)DIR and 162/64, under section 125(2) DIR, police station Sadar Karnal. (ii) For failing to carry out patrolling in the sensitive village. (iii) For refusing to obey the order of the S.H.O.	No
116	A.S.I. Raj Singh, 192/A	For delay in the submission of case diaries	No
117	S.I. Siri Ram, No. 96/A	For misbehaving and maltreating one Pritam Singh	No
118	Ditto ..	For overstaying after giving evidence at Kaithal	No
119	S.I. Gian Singh, No. 25/A	For not investigating a case impartially and favouring the accused person	Yes
120	A.S.I. Sampuran Singh, No. 406/H.S.R.	For having been mixed up with smugglers	Yes

[Home and Development Minister]

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	KARNAL DISTRICT—CONCLD		
121	A.S.I. Puran Singh, No. 186/Ambala	For having been arrested in case FIR No. 108, dated 18th July, 1964, under section 302 IPC, police station Sadar Panipat	Yes
122	A.S.I. Raj Singh, 192/A ..	For having been arrested in case FIR No. 93, dated 9th August, 1964, under secton 5(2) PC. Act, police station Pehowa	Yes
	SIMLA DISTRICT		
123	S.I. Sukhminder Singh, 102/A	For late submission of case diaries	No
124	A.S.I. Amar Chand, No. 314/SML.	He misbehaved with Sarpanch Panchayat etc.	No
	HOSHIARPUR DISTRICT		
125	A.S.I. Teja Singh, 298/HSP.	For faulty investigation in case FIR No. 12/62, under section 379 I.P.C., police station, Mukerian, while posted at CIA, Dasuya	No
126	S.I. Gurcharan Singh, 58/J	He was detected while travelling in Bus No. PNJ-6469 without ticket on 1st September, 1963 by the Special Squad while posted at Police station, Hajipur	No
127	A.S.I. Chuni Lal, 126/J ..	While posted at P. P. Nangal, he sent case diaries in certain cases with gross delay	No
128	AS.I. Sohan Singh, 122/J	While posted in police Lines, he absented himself without proper permission and excuse on various occasions	No
129	S.I. Harbhajan Singh, 417/LDH.	While posted at police station Sadar, he investigated case FIR No. 118/62, under section 302 IPC, police station, Sadar. During its trial in the Sessions Court, serious strictures were passed against him	No
130	S.I. Jagjit Singh, 168/J	The DIG/JR had remarked on the inspection report of police station Mahilpur for the quarter ending 30th September, 1963 that the Inspection Report depicts a disappointing reading and the working of the Police Station was thoroughly unsatisfactory	No
131	A.S.I. Amar Nath, 448/KGR.	The alleged misconduct on his part was that he failed to deal expeditiously with cases pending with him at the time of his transfer from City Hoshiarpur	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	LUDHIANA DISTRICT		
132	S.I. Manmohan Singh, 14/J	For burking of cognizable cases while posted as SHO, Sahnewal, district Ludhiana	Yes
133	S.I. Babu Ram, No. 321/ KGR.	Was arrested in case FIR No. 47, dated 23rd April, 1964, under section 376 IPC., police station, Sahnewal	Yes
134	S.I. Santokh Singh, No. 2959/PTL.	For not registering a case under section 457, 380 IPC., while he was posted as S.HO., police station, Raikot	No
135	A.S.I. Gurcharan Singh, No. 63/LDH.	For having been found travelling in a Bus No. 4912 without ticket and not paying the passenger tax	No
136	A.S.I. Rajinder Lal, No. 597/LDH.	For registering a false case under section 9/1/78 Opium Act, FIR No. 150, dated 28th September, 1963, police station, Raikot against Labh Singh of Sarabha	No
137	A.S.I. Shamsher Singh, No. 129/J	For overstaying from leave	No
138	A.S.I. Roshan Lal, No. 575/LDH.	Arrested in case FIR No. 264, dated 23rd February, 1965, under section 5/2/47 PC. Act, police Station City Kotwali Ludhiana	Yes
	JULLUNDUR DISTRICT		
139	S.I. Jaswant Rai, 113/J ..	For fabricating evidence and for corruption in case FIR No. 190/63, under section 302/34 IPC, police station, Kartarpur,	Yes
140	A.S.I. Khushal Singh, No. 55/HPR.	For his failure to make discreat enquiry regarding antecedents of Krishan Kumar son of Sri Ram, who had applied for passport	Yes
141	A.S.I. Ram Parkash, No. 524/HPR.	He accepted Rs 150 from one Amar Singh Karinda of Excise Vendor of Apra	Yes
142	AS.I. Darshan Singh, No. 133/J	While conducting a raid at village Apra, he recovered a bag of poppy husk from the possession of one Amar Singh Karinda of Excise Vendor of Apra. The quantity of poppy husk was reduced and one Malkait Ram Adharmi was challaned instead of aforesaid Amar Singh	Yes
143	S.I. Mukhtiar Singh, No. 77/J	For not registering a case in time, while posted as SHO, Nurmahal	No
144	A.S.I. Narsing Dass, 398/ HPR.	He was given medico legal report of one Babu of village Bilga by S.I. Mukhtiar Singh, SHO., Nurmahal, but he did not register the case in time	No
145	A.S.I. Des Raj, 237/JULL.	Ditto	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	JULLUNDUR DISTRICT—CONTD		
146	A.S.I. Harbans Lal, 149/ Jull.	He kept the illicit liquor in the pitcher and did not transfer it to the bottles or tins. As a result of his negligence, the illict liquor in the pitcher leaked or got dried	No
147	A.S.I. Shamsher Singh, No. 129/J	He put pressure on one Mukhtiar Kaur to compromise with one Surjit Kaur of Bahain, Police station Banga	Do
148	S.I. Charan Dass, No. J/73	He failed to prepare inquest report of one headless dead body, while he was informed by one Gurmukh Singh. He contravened the provision laid down in PR 25.31 and 25.33	Do
149	A.S.I. Harbans Lal, 132/ B/2/J.	He accepted Rs 50 from one Parkash *alias* Minto for booking a seat by air for him	Do
150	A.S.I. Jagir Singh, 110/J..	For not investigating the case carefully and also not thoroughly interrogated the accused in case FIR No. 47, dated 7th April, 1963, under section 307 IPC, police station, Dehlon, district Ludhiana	Do
151	S.I. Raj Kumar Singh, No. 1/J.	For not performing his duty satisfactorily, while posted as S.I. Security	Do
152	A.S.I. Wattan Singh, 108/J	(i) He removed 2 blank sheet forms from the Daily Diary Register, while posted at police station. Banga (ii) He accepted illegal gratification in case FIR No. 262/62, under section 376 IPC, police station, Banga (iii) For submission of case diaries with inordinate delay	Do
153	S.I. Mukhtiar Singh, 47/J	Was found negligent in performance of his duties, while posted as S.H.O. Nurmahal and misbehaved with one Joginder Singh	Do
154	A.S.I. Kartar Singh, No. 23/J.	Strictures were passed against him by High Court	Do
155	S.I. Kidar Nath, No. 74/J.	Lack of supervision, while posted as S.H.O., Adampur	Do
156	A.S.I. Ram Parshad, 543/HSR.	Wrong verification of Passport racketeers	Do
157	S.I. Darshan Singh, No. 136/J.	Clothing articles were found short in clothing godown during audit, while posted as Lines Officer, Ludhiana	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	JULLUNDUR DISTRICT—CONCLD		
158	S.I. Akal Sewak Singh	For delibrately avoiding the arrest of Passport racketeer in case FIR No. 41, dated 19th February, 1964, under section 419/420 IPC, police station Ajnala	No
159	S.I. Bhajan Singh, No. 178/A.	He took with him C. Charan Singh, while proceeding on leave	Do
	KANGRA DISTRICT		
160	A.S.I. Kundan Lal, No. 97/J.	For not doing enough work according to his rank and experience, both in the prevention and detection of crime against property as well as in Excise or in investigation of cases	Do
161	S.I. Partap Singh, No. J/19	For trying to rake up public agitation in order to get his transfer cancelled	Do
162	S.I. Partap Singh, No. J/19	For failing to prevent and detect crime, while posted as SHO, police station Jawalamukhi	Do
163	P.A.S.I. Gurdev Singh, No. 188/J.	For taking undue advantage of his official position in having a forced free lift in loaded truck	Yes
164	P.S.I. Bahadur Chand, J/104	For causing injuries to Rattan Lal, an accused in case FIR No. 67/73, under section 409/467 IPC, police station Kangra	No
165	S.I. Sewa Singh, No.J/26		
166	A.S.I. Kundan Lal, 102,/J.		
167	A.S.I. Gurcharan Singh, No. 239/LDH.	For his failure to take prompt legal action in a criminal case and gross neglect and dis-regard to the discharge of duties	No
168	A.S.I. Nasib Chand, No. 46/Jull.	For misconduct regarding his association with bad characters and for fraudulently and deceitfully calling Mst. Phullan Wanti from her in-laws and entrusting her to her mother with, whom he was in league against the wishes of her husband	Yes
169	A.S.I. Nasib Chand, No. 46/Jull.	For indulging in misconduct and irregularities during the course of investigation of case FIR No. 17 and 19, dated 24th May, 1964, under section 61/1/14 Excise Act Police Station, Sujanpur, district Kangra	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	KANGRA DISTRICT —*contd*		
170	A.S.I. Niranjan Singh, No. 281/Jull.	For dereliction of duty in making an enquiry on the complaint of one Bhumi Chand of Nagerh, while posted at police station Palampur	No
171	A.S.I. Harnam Singh, No. 140 KGR.	For pushing women folk and not taking legal action against them for obstructing the Police in the discharge of duty, in the course of investigation of case No. 17 and 19, dated 24th May, 1964, under section 61/1/14 Excise Act, police station Sujanpur	Do
172	S.I. Kishan Chand, No. J/119, Head Clerk, Office of the Superintendent of Police, Jullundur Kapurthla District	For receiving Rs 43.45 P. as Dearness Allowance and Hill Allowance fraudulently and irregularly	Do
173	A.S.I. Mukhtiar Singh, No. 186/ASR.	While posted to Police Station Phagwara, he obtained 5 days Casual Leave on the pretext of some urgent work from the D.S.P., Kapurthala, while the S.P., Kapurthala, was away from the District. He did not avail the leave then and proceeded on leave after a lapse of about 2 months without getting it approved or renewed by the Superintendent of Police	Do
174	A.S.I. Joginder Singh, No. 112/J.	He, while posted to Police Station Phagwara, delayed the investigation of case FIR No. 6/64, under section 9/1/78 Opium Act, inordinately	Do
175	A.S.I. Raghbir Singh, No. 423/KGR.	For drawing the Horse allowance on a false receipt	Do
176	S.I. Harnek Singh, No. 38/J.	While posted to Police Station, Phagwara, he was found negligent in that he detected 2 cases under section 61/1/14 Excise Act, police station Phagwara on 27th April, 1964, but failed to submit case diary till 27th July, 1964	Do
177	S.I. Harnek Singh, No. 38/J.	While posted to Police Station Phagwara, he was found negligent in that he sent samples in cases FIR Nos. 222 and 223, under setion 9, Opium Act and FIR No. 200, under section 61/1/14 to Chemical Examiner, Patiala after a considerable delay	Do
178	S.I. Balwant Singh, No. J/77	He failed to take effective preventive action, as a result of which one Sarwan Singh of village Moranwali, police station Garhshankar, district Hoshiarpur, was murdered by his opponents	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	KAPURTHALA DISTRICT—*concld*		
179	A.S.I. Mukhtiar Singh, No. 206/ASR.	For having been arrested in case FIR Nos. 57 and 58, under section 342/377/511 IPC, and 448 IPC, police station Phagwara	Yes
180	S.I. Joginder Singh, No. 132/J.	While posted as S.H.O., Bholath, he registered a false case against Kartar Singh of village Bassi, police station Bholath, under section 182/232/353/506 IPC	Do
	WIRELESS SECTION		
181	A.S.I. Sushil Kumar, No. 99/C.	(i) For committing grave misconduct in supressing the fact of his previous employment as a Clerk in the Textile Mills, Hissar, during the period of his dismissal from Police Radio Section (ii) For making un-substantiated allegations against a superior officer before the Vigilance Department (iii) For submitting application direct to higher authorities using therein intemperate language against S.P. (W)	No.
	KELONG DISTRICT		
182	S.I. Ram Lal, No. 140/J.	For claiming false T.A.	Do
	GURDASPUR DISTRICT		
183	A.S.I. Khushwant Singh, No. 165/ASR.	He, while posted to police station Majitha District Amritsar, arrested one Joginder Singh from whose possession 4 bottles of illicit liquor were recovered. He got a case under section 61/1/14 Excise Act registered against him. While appearing as P.W. in the above said case in the Court of M.I.C., Amritsar, he gave incorrect time of the raid. This resulted in the acquitted of the accused	Do
184	A.S.I. Joginder Singh, No. 183/B.	While posted as Officer-in-charge, police station D.B. Nanak, he failed to register a case under section 325/34 IPC, deliberately	Do
185	A.S.I. Bachan Singh, No. 237/B.	(i) Having failed to take preventive action against two party factions of village Ghot Pokhar, when directed by the DSP/H, which resulted in the occurrence of a hurt case (ii) He did not maintain his pony at the place of his posting and kept it in village Gharala and Tung and drew pony Allowance without actually maintaining the Pony at his own cost	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	GURDASPUR DISTRICT—*concld*		
186	A.S.I. Charanjit Singh, No. 136/B.	For delaying the investigation of case FIR No. 26, 58, 65 and 67 of 1964, while posted at police station Kalanaur and for not taking due interest in discharge of his Government duties	Yes
187	S.I. Tara Chand, No.100/B.	He had taken a bribe in a case in which a 10 year old boy was crushed under a Jeep near village Anandgarh in police station Muktsar, district Ferozepore	No
	AMRITSAR DISTRICT		
188	A.S.I. Tara Singh, No. 104/ASR.	For having been arrested in case FIR No. 40, dated 6th March, 1964, under section 304 IPC, police station Bhikhiwind	Yes
189	A.S.I. Piara Lal, No. 173/FZR.	For having accepted illegal gratification in case FIR No. 254, dated 4th December, 1964, under section 364 IPC, police station Civil Lines, Amritsar	Do
190	S.I. Sajjan Singh, 40/B. ..	Regarding serious discrepancies in the statements of S.I. Sajjan Singh and A.S.I. Harnam Singh for handcuffing of Shri Makhan Singh Tarsikka, M.L.A.	No
191	S.I. Ram Rachhpal Singh, 78/B.	Complaint of corruption while posted in Foreigners Staff, Jullundur	Do
192	S.I. Sajjan Singh, 40/B. ..	For unnecessarily delaying the investigation of cases, while posted as S.H.O., police station Jandiala	Do
193	S.I. Bawa Singh, 79/B. ..	For writing an objectionable report against his senior officer in the daily diary, while posted as S.H.O., police station Ajnala	Do
194	S.I. Man Singh, 28/GSP...	Strictures were passed against him by Shri Sant Singh, M.I.C., Amritsar in case FIR No. 146/63, under section 9/1/78 Opium Act, police station A. Division	Do
195	S.I. Sajjan Singh, 40/B. ..	Complaint regarding false registeration of case FIR No. 11/62, under section 506 IPC, police station Jandiala	Do
196	Ditto ..	For not taking legal action on the report made by Shri Inder Singh of Thathian regarding injuries inflicted on him with sharp and blunt weapons by Dalip Singh, etc.	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*		
197	S.I. Sajjan Singh 40/B ..	For not registering a case till Jamadar Makhan Singh appeared before SSP/ ASR., after which case FIR No. 94, under section 324/427/148/149 IPC was got registered by D.S.P./H.	No
198	S.I. Gurbux Singh, 106/B.	Regarding complaint from Sodhi Tarlok Singh of Jalalpura that S.I. threatened him to involve him in a false case	Do
199	A.S.I. Harpal Singh, 38/ PTL.	For showing wilful neglect in discharge of his duty and not taking proper care and caution before giving evidence in Court in case FIR No. 113/64, under section 19/11/78 Arms Act, police station City Tarn Taran	Do
200	A.S.I. Chan Parkash, 41/ GSP.	For travelling without ticket	Do
201	A.S.I. Pritam Singh, 2/ . GSP.	Strictures were passed against him by Shri T. R. Ghuman, MIC/ASR. in case, under section 61/1/14 Excise Act, police Station Sadar, Amritsar	Do
202	A.S.I. Niranjan Singh, 571/ASR.	Regarding complaint from Shri Chanchal Singh, son of Tara Singh of village Kot Kesra, police station Ramdas that he might be involved in a false case by the defaulter A.S.I.	Do
203	A.S.I. Hari Chand, 388/ FZR.	Strictures were passed against him in case FIR 86/62, under section 302/364 IPC, police station Sadar Amritsar	Do
204	A.S.I. Niranjan Singh, 571/ASR.	For not registering a case regarding the theft of mare belonging to Lakhbir Singh Sarpanch of village Bhim	Do
205	A.S.I. Tara Singh, 104/ ASR.	For accepting Rs 100 as illegal gratification from Shri Didar Singh	Do
206	A.S.I. Shanker Singh, 235/B.	For delaying unnecessarily 21 challans of Excise Act while posted at police station Verowal	Do
207	A.S.I. Sain Dass, 1095/ ASR.	For detaining a girl, who gave birth to an illegitimate child for investigation from 9th February, 1964 to 11th February, 1964	Do
208	A.S.I. Baldev Raj, 1423/ ASR.	Burking a case FIR 159/63, under section 457/380 IPC, police station Beas	Do
209	Ditto	For not taking action on the report of Sarvshri Joginder Singh and Udham Singh	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	AMRITSAR DISTRICT—*concld*		
210	A.S.I. Karnail Singh, 369/FZR.	Regarding showing gross carelessness and negligence in case FIR No. 64/64, under section 307/148/149 IPC, police station Ajnala	No
211	A.S.I. Tara Singh, 104/ ASR.	Strictures were passed against him in case FIR No. 182/63, under section 25/54/59 Arms Act, police station Lopoke	Do
212	A.S.I. Joginder Singh, 183/B.	For taking air gun from one Sowarn Singh in case FIR 74/61, under section 304 IPC, police station Jandiala and misappropriated the same for his personal use	Do
213	Ditto ..	Allegation of corruption, while posted at police station Jandiala	Do
214	A.S.I. Jai Singh, 173/ASR.	For delaying case FIR Nos. 22, 23, 38, 86 and $\frac{186}{64}$	Do
215	A.S.I. Kartar Singh, 379/ FZR.	Strictures were passed against him by Addl. Sessions Judge in case FIR 218/61, under section 302/148/149/120-B, police station Beas	Do
216	A.S.I. Bhag Singh, 368/ ASR.	Allegations of Corruption	Do
217	A.S.I. Shankar Singh, 235/B.	He did not send sample in case 194/ 204/63, under section 61/1/14, Excise Act, while posted at police station Verowal	Do
	FEROZEPUR DISTRICT		
218	A.S.I. Amrik Singh, 306/ASR	For acting in a very irresponsible manner and in gross negligence of instructions issued,—*vide* I.G.'s Memo. No. 22694-733/A, dated 17th November, 1960 in the execution of warrant issued, under section 408/379 IPC, for the recovery of Mst. Mehran Bai from village Shajrana, police station Sadar Fazilka	Yes
219	A.S.I. Harcharan Singh, No. 1501/ASR.	For partisan behaviour and abuse of authority, while registering a case FIR No. 57, dated 29th April, 1964, under section 379 IPC, police station Zira	Do
220	A.S.I. Pritam Singh, No. 641/GSP.	For being arrested in case FIR No. 4, dated 9th January, 1964, under section 5/2/47 P.C. Act, police station Khuyan Sarwar for accepting Rs 60 as illegal gratifications	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
		FEROZEPUR DISTRICT—CONCLD	
221	A.S.I. Jaswant Singh, No. 393/FZR.	For getting drunk in Government premises and also keeping a woman of ill-repute in his quarter	Yes ..
222	A.S.I. Amar Nath, No. 798/FZR.	For not properly investigating a case, under section 354/506 IPC.	No
223	S.I. Ajmer Singh, No. 138/B.	For gross negligence in investigation of case under section 302 IPC	Do
224	A.S.I. Saudagar Singh, No. 1268/ASR.	For accepting illegal gratification	Do
225	A.S.I. Kundan Singh, No. 437/ASR.	He wrongly registered and investigated a case under section 19/11/78 Arms Act	Do
		BHATINDA DISTRICT	
226	A.S.I. Sukhdev Singh, No.1404	For negligence shown by him in discharging of his official duties, while posted as Accountant, D.P.O., Patiala	Do
227	S. I. Gurdev Singh, PR/67	For having failed to register a case when Gurdev Singh, son of Dulla Singh of Talwandi Sano reported in police station Raman regarding theft of his cycle alongwith other articles	Do
228	A.S.I. Kirpal Singh, No. 378	For disobeying the orders of S.D.M., Faridkot in a function at Faridkot	Yes
229	A.S.I. Inder Singh, No. 10/PR.	For concocting a false story regarding the arrest of the accused and recovery of a ring in case FIR No. 78, dated 12th February, 1963, under section 302 IPC, police station Mansa	No
230	S.I. Bas Dev, No. 104/PR	For the preparation of false recovery memos and case diaries, etc. in case FIR No. 10, dated 7th March, 1963, under section 302 IPC, police station Maur	Do
231	S.I. Balwant Singh, No. 88/PR.	For defective investigation of case FIR No. 37, dated 24th March, 1964 under section 5(2) P.C. Act, police station Budhlada	Do
232	A.S.I. Nand Kishore, 202/PR.	For their failure to execute a warrant in respect of Ajaib Singh, retired DSP, issued by S.D.M., Faridkot	Do
233	A.S.I. Kartar Singh, 386/FZR.	Ditto	Do
234	A.S.I. Parshotam Dass ..	Ditto	Do
235	S.I. Abnash Chander, No. 154/PR.	For criminally assaulting and comm itting a rape on Mst. Joginder Kaur, w/o Mehar Singh of village Baluana	Yes

[Home and Development Minister]

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
		BHATINDA DISTRICT—CONTD	
236	A.S.I. Hardial Singh, 2016/SGR.	For criminally assaulting and committing a rape on Mst Joginder Kaur w/o Mehar Singh of village Bulnana	Both these A.S.I's. were only suspended
237	A.S.I. Harnarain Singh, No. 2177/SGR.		
238	S.I. Shamsher Singh, No. 112/PR.	For minimising the offence in case FIR No. 17, dated 1st February, 1964 under section 302/34 IPC, police station Mansa	No
239	S.I. Kartar Singh, No. 32/PR.	For not depositing the case property of case FIR No. 170, dated 19th September, 1963, under section 302/34 IPC, police station Sardulgarh in the Malkhana on the same day of recovery	Do
240	S.I. Iqbal Singh, No. 159/PR.	For not registering a case of theft	Do
241	A.S.I. Swarn Singh ..	..	..
242	A.S.I. Gian Singh, No. 608/BTI.	For not maintaining the cash book properly while posted as a cashier in Police Lines, Bhatinda	No
243	A.S.I. Karam Singh, No. 79/PR.	For taking illegal gratification in case FIR No. 11, dated 21st January, 1963, under section 460/302 IPC, police station Sardulgarh	Yes
244	S.I. Amarjit Singh, No. 265/PR.	For not registering case under section 305 IPC.	Do
245	A.S.I. Jasved Singh, No. 2052	For having failed to take adequate action in preventing the occurrence of a murder case	Do
246	S.I. Bas Dev, 104/PR. ..	For recording the FIR with delay in case FIR No. 9, dated 7th February, 1963, under section 302 IPC, police station Maur	No
247	S.I. Shamsher Singh, No. 112/PR.	For not carefully arranging the police raid which might have avoided the death of Baldev Singh, son of Jit Singh of village Raipur, police station Mansa	No
248	S.I. Kalwant Rai, No. 80/PR.	For not registering the case immediately when one Sham Lal, Harijan of Maur reported in police station Maur about the abduction of his minor girl Mst. Vidya	Do
249	A.S.I. Karnail Singh, No. 4655	Ditto	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
		BHATINDA DISTRICT—CONCLD	
250	A.S.I. Kartar Singh, No. 386/FZR.	Case under section 5(2) P.C. Act, police station Kotwali Faridkot	Yes
	Note.—Also *see* Serial No. 307 at page 75		
		SANGRUR DISTRICT	
251	S.I. Om Parkash, 199/PR.	Case FIR 83/64, under section 325/452/342/506/211/380 IPC and 61 Excise Act, police station Narwana	Yes
252	A.S.I. Zile Singh, 12/PR.	Case FIR No. 107/64, under section 5(2) P.C. Act, police station, Barnala	Do
253	A.S.I. Santa Singh, 193/PR.	Case FIR No. 313/64, under section 5(2) P.C. Act, police station City Rohtak	Do
254	A.S.I. Karam Dev, 13/PR.	Private complaint under section 323/342 IPC.	Do
255	A.S.I. Jagjit Singh, 3241 ..	For levelling false allegations against D.S.P./Headquarters	Do
256	A.S.I. Harikishan Lal, 192/PR.	Found asleep on Nakabandi point	Do
257	A.S.I. Charan Singh, 49/PTL.	For making false entries in Daily Diaries register of police station Mahal Kalan	Do
258	S.I. Bhag Singh, PR/47 ..	For not arresting accused of case FIR No. 191/63, under section 307 IPC, police station Payal	No
259	S.I. Harbans Singh, 72/PR.	Strictures were passed against him in case FIR No. 71/63, under section 302/201 IPC, police station Bhawanigarh	Do
260	S.I. Rajinder Singh, No. 176/PR.	For grave misconduct in the investigation of case FIR No. 40/63, under section 61, Excise Act, police station Mahal Kalan	Do
261	S.I. Bhag Singh, PR/147..	Negligence in the investigation of case FIR No. 74, 82, 98 of 1963, under section 457/380 IPC, police station Payal	Do
262	S.I. Bhag Singh, PR/147..	Paid a flying visit to the place of occurrence and went to Ludhiana without permission in a private car	Do
263	Ditto ..	For not taking timely preventive action in case FIR No. 16/64, under section 302/34 IPC, police station Payal	Do
264	S.I. Piare Lal, PR/12 ..	For irresponsible attitude, carelessness and negligence	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
		SANGRUR DISTRICT—CONCLD	
265	S.I. Piare Lal, PR/12 ..	For spoiling case under section 325/34 IPC, police station Longowal	No
266	S.I. Bhag Singh, PR/147..	For drinking and misbehaviour with public	Do
267	S.I. Surjit Rai ..	Negligence in case FIR No. 146/63, under section 9 Opium Act, police station Dhanaula	Do
268	A.S.I. Pritam Singh, 775/A.	Faulty investigation of case FIR No. 6/61, under section 300/307/149/IPC, police station Julana	Do
269	A.S.I. Harikishan Lal, 192/PR.	Strictures were passed against him by Sessions Judge, Sangrur in case FIR No. 71/63, under section 302/20, IPC, police station Bahadurgarh	Do
270	A.S.I. Ram Sarup, 736/BTI.	For not registering a case under section 363/366 IPC, police station Ghagga	Do
271	Ditto ..	For grave misconduct and not registering a case under section 447/IPC.	Do
272	Ditto ..	For travelling without ticket	Do
273	Ditto ..	For keeping buffalo in police premises without permission	Do
274	A.S.I. Hardev Singh ..	Negligence in case FIR No. 162/63, under section 302/IPC, police station Sunam	Do
		MOHINDERGARH DISTRICT	
275	A.S.I. Harbans Singh ..	For misbehaviour with public under influence of liquor	Yes
276	S.I. Naunidh Rai, No. PR/85	He appeared before the Chief Minister, Punjab, without obtaining the permission of the Department	No
277	A.S.I. Gurdip Singh, No. 30	While he was posted to police station Kaniana, he was deputed to dispose of an application under section 107/151 Cr.P.C., but he failed and both the parties started quarrelling in the presence of A. S. I.	Do
278	A.S.I. Nahar Singh, 121/H.	For corruption	Do
279	A.S.I. Hazura Singh, 3666	While posted as S.H.O., police station Kaniana, he had made changes in Death and Birth Register of the Police Station	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
		MOHINDERGARH DISTRICT—*concld*	
280	A.S.I. Babu Ram, No. 111	He was detected while travelling without ticket in a local bus by Chief Minister's Flying Squad	No
		PATIALA DISTRICT	
281	S.I. Chuni Lal, PR/24 ..	For late registration of case of abduction of two boys, while posted as S.H.O., police station Lalroo	Do
282	S.I. Rajinder Singh, 4/PR.	For illegal detention of Smt. Gurdial Kaur, resident of village Raungla, police station Sadar Patiala	Do
283	S.I. Gurdev Singh, 111/PR	For not carrying out investigation of case FIR No. 228/63, under section 379 IPC, police station Samana	Do
284	S.I. Sita Ram (now A.S.I.) 55/PR.	For trying to implicate a false case against one Tehail Singh on the complaint of Chanan Singh, son of Mehar Singh, resident of village Mohampur, police station Julkan.	Do
285	S.I. Jaswant Singh, PR/41	For leaving police Lines without making an entry in the Daily Diary	Do
286	S.I. Rajinder Singh, 4/PR.	For not taking up investigation of case FIR No. 179 and 183, etc.	Do
287	S.I. E. M. Massey, PR/4	For not taking action and delaying registration of case on the complaint of one Chhaju Singh	Do
288	S.I. Inder Singh, 10/PR. ..	For defective investigation of case FIR No. 78/63, under section 302 IPC, police station Mansa	Do
289	S.I. Rajinder Singh, 4/PR.	For failing to prepare case diaries in case FIR No. 96, 97, 98, 100 and 104, under section 61/1/14, police station Kot Sangrur	Do
290	S.I. Rajinder Singh, PR/33	For delaying registration of a case of theft of village Chalella, police station Mulepur	Do
291	S.I. Rajinder Singh, 4/PR.	For changing the Roznamcha entries of police station Sadar Patiala	Do
292	S.I. Kuldip Singh, PR/16	For not checking of F.Cs. during the quarter ending 31st March, 1964 in police station Rajpura	Do
293	S.I. Amarjit Singh, PR/84	For not taking preventive action on the complaints of one Pritam Singh, resident of Bhagwanpura against Jita Singh	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
		PATIALA DISTRICT—*concld*	
294	A.S.I. Pritam Singh, 775/PTA.	For delaying registration of cognizable offence when posted in police station Julkan	No
295	A.S.I. Gurtej Singh, 681/PTI.	For non-submission of case diaries in case FIR No. 4/64, under section 364 IPC, police station Kotwali, Patiala	Do
296	A.S.I. Jagjit Singh, 26/PR	For delaying the investigation of case FIR No. 127/57, under section 61/1/14, police station Kharar	Do
297	A.S.I. Bhup Singh, 31/PR.	For not taking legal action on the application of Bhajan Singh	Do
298	S.I. Bhag Singh, PR/47 ..	For not running police station Payal efficiently and for his poor out-put as S.H.O., and allegations of moral turpitude	Yes
299	A.S.I. Jarnail Singh, 751/PTA.	For suffering the escape of accuesd negligently	Do
		C. I. D.	
300	S.I. Jarnail Singh, No. 102/PR.	While posted as A.S.I. Incharge of Police Post, Shutrana, Patiala District, he did not register a burglary case involving a loss of clothes worth Rs 6,000 on the complaint of Shri Chander Bhan complainant, etc.	No
301	S.I. Sajjan Singh, No. 40/B.	For submission of case diaries with delay and for keeping the challans of certain cases with him unnecessarily	Do
302	S.I. Sajjan Singh, No. 40/B.	While posted as S.H.O., Jandiala in Amritsar District in the year 1962, he failed to register a case on the report of Shri Inder Singh, son of Narain Singh of village Thothian, police station Jandiala and thereby violated the provisions of section 154 Cr.P.C. and Police Rule 24.1	Do
303	S.I. Sajjan Singh, No. 40/B.	While posted as S.H.O., police station Jandiala Amritsar District in the year, 1962, he with a motivated mind to help Shri Sadhu Singh of Jandiala for getting possession of a disputed plot situated in Jandiala Town from Shri Hukam Singh, registered a false case FIR No. 11, dated 10th January, 1962, under section 506 IPC against Hukam Singh, arrested him without making proper investigation and knowing it well that Shri Hukam Singh did not criminally intimidated Shri Sadhu Singh	Do

Serial No.	Name, rank and number of police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	C. I. I—*Concld*		
304	S.I. Ranbir Singh, No. 85/A.	While posted as S.H.O., Dharampur, he received a written complaint from one Jaswinder Singh, son of Mohinder Singh of Mandi Bahadurgarh (Ludhiana) and without verifying its contents he took action in stopping Car No. DLE-670 belonging to Step mother of Jaswinder Singh, thereby caused unnecessary har ass-ment and inconvenience to the occupants of the Car, which was detained for nearly 4 hours at Kalka	No
305	S.I. Ranbir Singh, No. 85/A.	While posted as S.H.O., police station Assandh in district Karnal, he did not take prompt action in registering the case reported by one Jagir Singh, son of Phula Singh of village Ruksana about the commission of a burglary in his house	Do
306	A.S.I. Sadhu Ram, No. 1594/ASR.	While posted in Security Staff, Nangal, he collected Rs 10 from certain police personnel every month in respect of C.T.D. Pass-Books, but did not deposit the amount regularly with the Post Office	Do
	BHATINDA DISTRICT (SUPPLEMENTARY)		
307	S.I. Iqbal Singh, No. 159/PR.	For not registering a case of burglary	Do

STATEMENT No. II

List showing the names of Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors, who have been reinstated from suspension during the period from January, 1964 to-date

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer
1	2
	PUNJAB ARMED POLICE
1.	S.I. Kulwant Singh, No. PAP/144
2.	A.S.I. Sardara Singh, No. 255
3	A.S.I. Sucha Singh, No. 356
4.	A.S.I. Charanjit Singh, No. 4562
5.	A.S.I. Surjan Singh, No. 50

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer
1	2
	GOVERNMENT RAILWAY POLICE
6.	S.I. Khushal Singh, No. R/6
7.	A.S.I. Niranjan Singh, No. 723/GRP.
	HISSAR DISTRICT
8.	S.I. Chuni Lal, No. 153/A.
9.	S.I. Sohan Lal, No. A/16
	AMBALA DISTRICT
10.	S. I. Gurnam Singh, No. 240/A.
11.	S. I. Harbachan Singh, No. 30/A.
12.	S. I. Madan Lal, No. A/90.
13.	A.S.I. Madan Lal, No. 232/GGN.
14.	A.S.I. Jagat Singh, No. 35/UMB.
	KARNAL DISTRICT
15.	A.S.I. Om Parkash, No. 199/A.
16.	S.I. Ram Pat, No. 212/A.
17.	S.I. Gian Singh, No. 25/A.
18.	A.S.I. Sampuran Singh, No. 406/Hissar.
	LUDHIANA DISTRICT
19.	S.I. Babu Ram, No. 321/Kgr.
	JULLUNDUR DISTRICT
20.	S.I. Jaswant Rai No. 113/J.
21.	A.S.I. Khushal Singh, No. 55/HPR.
22.	A.S.I. Ram Parkash, No. 524/HPR.
23.	S.I. Darshan Singh, No. 136/J.
	KANGRA DISTRICT
24.	A.S.I. Gurdev Singh, No. 186/J.
25.	A.S.I. Nasib Chand, No. 46/Jull.
	KAPURTHALA DISTRICT
26.	A.S.I. Mukhtiar Singh, No. 206/ASR.
27.	S.I. Joginder Singh, No. 132/J.

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer
	GURDASPUR DISTRICT
28.	A.S.I. Charanjit Singh, No. 136/B.
	AMRITSAR DISTRICT
29.	A.S.I. Tara Singh, No. 104/ASR.
	FEROZEPORE DISTRICT
30	A.S.I. Amrik Singh, No. 366/ASR.
31.	A.S.I. Harcharan Singh, No. 1501/ASR.
32.	A.S.I. Pritam Singh, No. 641/GSR.
33.	A.S.I. Jaswant Singh, No. 593/FZR.
	BHATINDA DISTRICT
34.	A.S.I. Kirpal Singh, No. 773.
35.	A.S.I. Hardial Singh, No. 2061/SGR.
36.	A..I. Harnarain Singh, No. 2177/SGR.
37.	A.S.I. Karam Singh, No. 79/PR.
38.	S.I. Amarjit Singh, No. 121/PR.
39.	A.S.I. Jasdev Singh, No. 2052.
	SANGRUR DISTRICT
40.	S.I. Om Parkash, No. 199/PR.
41.	A.S.I. Harikishan Lal, No. 192/PR.
42.	A.S.I. Charan Singh, No. 40/PTI.
	MOHINDERGARH DISTRICT
43.	A.S.I. Harbans Singh, No. 2312.
	PATIALA DISTRICT
44.	S.I. Bhag Singh, No. PR/47.
45.	A.S.I. Jarnail Singh, No. 751/PTA.

Inspectors/Sub-Inspectors of Co-operative Societies.

2419. Shri Amar Singh : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the number and names of the Inspectors/Sub-Inspectors of the Co-operative Societies who were suspended/charge-sheeted in the State, district-wise, during the period from January, 1964)to date and the reasons therefor in each case ;

[Shri Amar Singh]

(b) the number and names of the Inspectors and sub-Inspectors from amongst those mentioned in part (a) above who have been reinstated by the Government during the said period ?

Sardar Darbara Singh : (a)—

Inspecotors	*Sub-Inspectors*	*Total*	
11	17	28	List of names is given in part (a) of Annexures A and B
(b)—			
9	7	16	List of names is given in part (b) of Annexures A and B.

ANNEXURE 'A'

(a) **The number and names of Inspectors of the Cooperative Societies who were suspended/ charge-sheeted in the State ; districtwise, during the period from January, 1964 to date and the reasons thereof in each case.**

Serial No.	Name of the Inspector	Reasons for suspension
1	2	3
	DISTRICT JULLUNDUR	
1	Shri Surrinder Paul Beri, Educational Inspector, Cooperative Societies, Jullundur now at Dasuya, district Hoshiarpur	Negligence in the discharge of duties and absence from duties
2	Shri Surrinder Singh Sandhu, Inspector, Cooperative Societies, Nakodar, district Jullundur now at Phul district Bhatinda	Negligence in the performance of duties
3	Shri Bakhshish Singh. Inspector, Cooperative Societies, Dasuya, district Hoshiarpur now Batala (Labour and Construction), district Gurdaspur	Negligence in the performance of duties
	DISTRICT SANGRUR	
4	Shri Gurbax Singh Bath Inspector, Cooperative Societies (Farming) Sangrur now Kartarpur at Jullundur	Committed irregularities in the perform ance of duties
5	Shri Kartar Singh, Inspector, Cooperative Societies, Barnala, district Sangrur now Inspector, Cooperative Societies (Consumer Stores), Yamuna Nagar, district Ambala	Negligence in the performance of duties
6	Shri Mehar Singh, Inspector, Cooperative Societies, Sangrur	He was arrested under section 457 I.P.C. and a case F.I.R. No. 82, dated 3rd July, 1964 under section 457 I.P.C., Police Station Sahnewal is still pending in the court of Magistrate, 1st Class, Ludhiana
	DISTRICT PATIALA	
7	Shri Molar Singh, Inspector, Cooperative Societies, Patiala now Nilokheri (Farming), district Karnal	Negligence in the performance of duties

Serial No.	Name of the Inspector	Reasons for suspension
1	2	3
	DISTRICT AMRITSAR	
8	Shri Tarlochan ingh, Inspector, Cooperative Societies, Naushehra Panwan, district Amritsar now at Fatehabad, district Hissar	Negligence in the performance of duties
	DISTRICT GURGAON	
9	Shri Manphul Singh, Inspector, Cooperative Societies, Hathin	He was arrested under section 409/420 I.P.C. and a case F.I.R. No. 55/63, under section 409/420 I.P.C.—Police Station Kharkhada was in the Court of Magistrate, 1st Class, Rohtak challaned. He was acquitted honourably
	DISTRICT KARNAL	
10	Shri Matu Ram, Inspector, Cooperative Societies, Shahabad, district Karnal now at Pundri, district Karnal	Negligence in the performance of official duty and also committed irregularities in the discharge of duties
11	Shri Raghbir Singh, Inspector, Cooperative Societies (labour and constructions) Karnal	Charging commission from Cooperative labour and construction societies and borrowed money from the members of Labour Societies

(b) The number and names of the Inspectors Cooperative Societies from amongst those mentioned in part (a) above who have been re-instated by Government during the said period.

Serial No.	Name of Inspector re-instated
1	2
	DISTRICT JULLUNDUR
1	Shri Surrender Paul Beri, Inspector, Cooperative Societies, Dasuya, district Hoshiarpur
2	Shri Surrinder Singh Sandhu, Inspector, Cooperative Societies, Phul, district Bhatinda
	DISTRICT HOSHIARPUR
3	Shri Bakhshish Singh, Inspector, Cooperative Societies (Labour and Construction) Batala, district Gurdaspur

[Home and Development Minister]

Serial No.	Name of Inspector re-instated
1	2
	DISTRICT SANGRUR
4	Shri Gurbux Singh Bath, Inspector, Cooperative Societies, Kartarpur at Jullundur
5	Shri Kartar Singh Inspector, Cooperative SocietiesInspector, Cooperative Societies Consumer Stores) Yamuna Nagar, district Ambala
	DISTRICT PATIALA
6	Shri Molar Singh, Inspector, Cooperative Societies (Farming) Nilokheri, district Karnal
	DISTRICT AMRITSAR
7	Shri Tarlochan Singh, Inspector, Cooperative Societies, Fatehabad, district Hissar
	DISTRICT GURGAON
8	Shri Manphul Singh, Inspector, Cooperative Societies, Hathin, district Gurgoan
	DISTRICT KARNAL
9	Shri Matu Ram, Inspector, Cooperative Societies, Pundri, district Karnal

ANNEXURE 'B'

(a) List of Sub-Inspector, Cooperative Societies who were suspended during the period from 1st January, 1964 to-date.

Serial No.	Name of Sub-Inspector	Reasons for suspension
1	2	3
	PATIALA DISTRICT	
1	Shri Gurmail Singh, Sub-Inspector, Patiala	Gross negligence in performance of his duties.
	GURGAON DISTRICT	
2	Shri Subh Ram, Sub-Inspector (Transport) Gurgaon	For alleged acts of misconduct as he travelled without ticket in bus on 8th August, 1963
3	Shri Lal Chand, Sub-Inspector, Ghasera (Gurgaon)	Misconduct and mis-using of societies money
4	Shri Dhanpat Singh, Sub-Inspector (Gurgaon)	Ditto
5	Shri Biram Singh, Sub-Inspector, Punhana (Gurgaon)	Black marketing of Sugar (Police)
6	Shri Raghu Nath Singh Sub-Inspector, Birthla (Gurgaon)	Arrested by the Police mis-appropriation and embezzlement of Socie ties Fund
7	Shri Sher Singh, Sub-Inspector, Palwal	Negligence in discharge of his duties
8	Shri Lala Ram, Sub-Inspector, Palwal	Assaulting the Inspector in the office

Serial No.	Name of Sub-Inspector	Reasons for suspension
1	2	3
9	Shri Manke Ram, Sub-Inspector ..	Embezzlement and mis-appropriation of Society Funds.
	AMBALA DISTRICT	
10	Shri Madan Mohan Sharma, Sub-Inspector, Rupar (Ambala)	Gross negligence in performance of his duties.
	ROHTAK	
11	Shri Ram Niwas, Sub-Inspector, Alewas (Rohtak)	Misconduct and mis-using of societies. funds
12	Shri Kesar Dass, Sub-Inspector (Audit), Cooperative Societies, Guhla	Mis-appropriation of Societies Funds,
13	Shri Hukam Chand, Sub-Inspector, Jhajjar	Arrested under Excise Act.
	FEROZEPUR	
14	Shri Jagiri Lal, Sub-Inspector, Mamdot (Ferozepur)	Negligence in discharge of his duties.
	HISSAR	
15	Shri Kanwal Singh, Sub-Inspector, Hansi East Hissar	Negligence in discharge of his duties
	HOSHIARPUR	
16	Shri Mohinder Singh, Sub-Inspector, Mukeriant, Hoshiarpur.	Arrested by the Police while he was intoxicated nature and making noise at public places
17	Shri Randhir Singh Sub-Inspector, Daulatpur (Hoshiarpur)	Arrested by police under section 406/420 in case of embezzlement of Rahlon Cooperative Leather products Industrial Society

(b) Total number of Sub-Inspectors reinstated out of above—Seven

Serial No.	Name of Sub-Inspector
1	2
	PATIALA DISTRICT
1	Shri Gurmail Singh
	GURGAON DISTRICT
2	Shri Subh Ram
3	Shri Dhanpat Singh
	AMBALA DISTRICT
4	Shri Madan Mohan Sharma
	ROHTAK
5	Shri Ram Niwas
	FEROZEPUR
6	Shri Jagiri Lal
	HOSHIARPUR
7	Shri Randhir Singh

Complaint against S.D.M., Rajpura

2420. Shri Amar Singh : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether the Government is aware of the fact that the then S.D.M. Rajpura quarrelled with one Legislator at the Railway Station, Ambala Cantt on 10th October, 1964 ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether any action has been taken against the officer concerned ; if so, what ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes, on 10th August, 1964 and not on 10th October, 1964 ;

(b) The officer was transferred from Rajpura.

Surplus area of Land in possession of Land-owners in district Hissar

2421. Shri Amar Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the details, including Khasra Numbers, of the surplus area of each land-owners in Hissar District, tehsilwise, owning more than 30 standard acres ;

(b) the Khasra numbers of such surplus area on which the ejected tenants have so far been resettled ;

(c) the area of banjar land in possession of each land owner in the said district ; tehsilwise, in excess of the permissible area of 30 standard acres owned and possessed by him ?

Sardar Harinder Singh Major : (a), (b) and (c) The time and labour involved in collecting and compiling the information would not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Enquiry into double allotment made to Shri Roop Singh Malhotra in Garden Colonies in Karnal and Ambala Districts

2422. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether any enquiry has been ordered or is being conducted by the Rehabilitation Department for the alleged double allotment made to Shri Roop Singh Malhotra in the Garden Colony, Jhundla, district Karnal and Garden Colony, Hardoi, near Barara, district Ambala ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the authority who ordered the said enquiry, the date when it was ordered, the name of the officer holding the enquiry and the present stage thereof ;

(c) whether the Additional Settlement Officer (Sales) Nilokheri received during February, 1965 any communication from any legislator of Karnal District on the subject of "Double allotment in Garden Colonies", if so, a copy thereof along with a copy of the reply if any, sent by the said officer, be laid on the Table of the House ;

(d) the details of the action so far taken on the communication referred to in part (c) above ;

(e) whether on receipt of the said communication the relevant files of the department were looked into by the Officer, if so, when ;

(f) the details of further action, if any, proposed to be taken in the matter ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Yes.

(b) On receipt of a copy of a complaint, Deputy Secretary, Rehabilitation, ordered Shri Hit Abhilashi, Assistant Registrar (Directory) on 18th February, 1965, to hold an enquiry. A notice has been issued to the allottee.

(c) Yes. A copy of the complaint received from Comrade Ram Piara, M.L.A., alongwith a copy of the reply sent to him by Additional Settlement Officer (Sales) Nilokheri is attached.

(d) A copy of the complaint was sent to the Tehsildars (Sales) Karnal and Ambala to send reports immediately. Reply from Tehsildar (Sales), Karnal, has been received, while that of the Tehsildar (Sales), Ambala is still awaited.

(e) The relevant files of the Department were seen by the Assistant Registrar (Directory) on 24th February, 1965.

(f) A Registered show cause notice has been issued to the allottee for 24th March, 1965. The excess allotment, if any, will be dealt with in accordance with rules.

Enclosure to Part 'C'

"RAM PIARA COMRADE,
M.L.A.

Phone No. 172,
L/309, *Model Town,*
Karnal.
9/11 /2/65

To

S. SOHINDER SINGH,
Settlement Officer (Sales),
Nilokheri.

Subject.—Double allotment in Garden Colonies.

DEAR SIR,

Shri B.S. Grewal, I.C.S. has advised me to write to you for immediate action as any delay in the action after the receipt of this letter can be harmful. Therefore, I am to request you to please take in possession both the files which I am mentioning as under —

It has been reported to me that one Shri Roop Singh Malhotra is an allottee of Garden Colony, Jundla, district Karnal. He is having a plot in Garden Colony most probably named as Hardoi in Ambala District. According to the information passed on to me this garden colony is situated near Barara, district Ambala.

This appears to me as double allotment against one claim which entitles him for one piece but he is in possession of two under one excuse or the other. I do not know, why, Department is unaware of this lapse, if the information passed to me is correct.

The details supplied to me are as under :—

(1) Shri Roop Singh Malhotra, son of S. Pritam Singh Malhotra one Plot in garden colony Jundla, district Karnal. One Plot in garden colony Hardoi near Barara, district Ambala.

(2) His brother S. Sewa Singh in Garden Colony Hardoi.

(3) His another brother S. Gurbans Singh, Garden Colony Hardoi. No. 1 is having two allotments where as No. 2 and 3 are genuine as they have their share for which they were entitled.

In the word Hardoi, there can be a Minor mistake in name but it is definite that that colony is near Barara, district Ambala

This fact has been brought by me to the Notice of Shri B.S. Grewal, I.C.S. who has advised me to write to you for immediate action. He also further told me that other letters written by me have been entrusted to you for immediate action and enquiry.

[Revenue Minister]

I have not received the reply of any one so far though little about Hemu Majra standing in the name of Shri Ranjit Singh has come to my notice. Will you acknowledge this letter without any loss of time and further inform me about the state of other enquiries issues entrusted to you so that I may further assist the Department in case you lack information and I may fortunately have that. Hoping for immediate acknowledgement and further action.

Thanking you.

Yours faithfully,

(Sd.) (Ram Piara, M.L.A.)

Copy of D.O. letter No. 507/AS (S), dated 17th February, 1965, from Shri Sohindra Singh, Additional Settlement Officer (Sales) to Shri Ram Piara, M.L.A., Karnal.

Kindly refer to your letter, dated 9th/11th February, 1965 regarding double allotment of Garden Colony plot to Shri Roop Singh Malhotra,. I have called for the records pertaining to the said allotment. After I have examined the same, I will be able to see whether your contention is correct or not.

x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x

Tape-recording of statements of certain accused in city Police Station, Karnal

2426. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the statements of some of the accused in the case State *versus* Tirlok Singh Santa and Hukam Chand alias Kuki, registered under section 307 I.P.C. at the city Police Station, Karnal during the period from 17th July, 1963 to 20th July, 1963 were tape-recorded, if so, by whom the tapes were tape-recorded and when and where ;

(b) the names of the officials/officers/non-officials who were sitting in the same premises where the said statements were being tape-recorded ;

(c) whether it is a fact that some of the non-officials referred in part (b) above were sent for by the D.C., Karnal, if so, the reasons for the same ;

(d) the idea underlying the tape-recording of the said statements ;

(e) whether the practice of tape-recording the statements is common with the police in the Punjab or it was followed only in the said case, if the latter, the reasons therefor ;

(f) the number of tape-recording machines with the Punjab Police as on 26th July, 1963 together with the number of those which were with the Police unit, district Karnal ;

(g) whether the tape recording machine (s) which was/were used in the said case belonged to the Punjab Police or some non-officials, if the latter, the names of those from whom the machines were obtained for the purpose and the name of the official who obtained them ;

(h) whether the said tape-recorded statement was attached with the the Ziminis ; if not, the reasons therefor ;

stand-
ledge
juiries
ck in-
ment

(i) whether it is a fact that in connection with the said case the Deputy Commissioner and the Home Minister made certain statement in the Public during the period from 17th July, 1963 to 25th July, 1963; if so, a copy of each be laid on the Table of the House ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes, of one accused. Through Shri Bahadur Chand Arora, son of Nihal Chand of Karnal on 25th July, 1963.

(b) (1) Ch. Randhir Singh.
(2) Shri A. N. Kapur.

(c) No ;

(d) To elicit truth ;

(e) Practice of tape recording the statements is not common with the Police in the Punjab. It was resorted to in this case as it was a case of special importance where in a legislator was assaulted and the political parties were trying to exploit the situation.

(f) Four with the Punjab Police. Nil with Karnal.

(g) The Tape-Recording Machine did not belong to the Punjab Police but it was arranged through Shri Bahadur Chand, son of Nihal Chand Arora of Karnal by the Investigating Officer.

(h) The Police file of the case has been sent to the District Magistrate, Meerut and in its absence it cannot be said with certainty as to whether or not the tape recorded statement was attached with the Ziminies.

(i) Yes. The statements appeared in the 'Tribune' and 'Indian Express', dated 20th July, 1963, 22nd July, 1963, and 25th July, 1963, which may please be seen.

Powers to fill up leave vacancies of the teachers in Government Schools

2430. Sardar Trilochan Singh Riasti : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) whether the Education Department has taken any decision empowering certain officers to appoint teachers in the Government Higher Secondary/High/Middle and Primary Schools against leave vacancies ; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(b) whether any appointment against a leave vacancy mentioned in part (a) above has been made by the District Education Officer instead of the Block Education Officers ; if so, their number ;

(c) whether there is any decision to the effect that all leave vacancies of teachers mentioned in part (a) above should be filled up through the Employment Exchanges ; if so, whether in contravention of this decision such leave vacancies have been filled up by candidates recommended by the Subordinate Services Selection Board ; and

(d) if the reply to part (c) above be in the affirmative, the total number of such appointments so far made in the Ambala District and the name of the authority which made them ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes. A copy of the instructions is laid on the Table of the House.

[Education and Local Government Minister]

(b) Name of the District has not been mentioned ; and if the information is intended to be collected regarding all the districts in the State, the time and labour involved in collecting it will not be commensurate wi th the advantage to be derived by the Honourable Member in getting it.

(c) Normally all vacancies are to be filled up by candidates récommended by the S.S.S. Board, Punjab and in case such candidates are not available vacancies are filled through Employment Exchanges on temporary basis.

(d) The information is being collected and will be supplied to the Member in due course.

Extract copy of C.M. No. 60-B( ), dated 17th October, 1960, from the D.P.I., Punjab, to the Inspectress of Schools, Jullundur Division, Jullundur.

The question now is how to fill vacancies temporarily, till regular appointments can be made for this purpose. It is, desired that the Headmasters/Headmistresses of High/Higher Secondary Schools should be authorised to fill vacancies on temporary three months basis. In filling these vacancies it should be seen that the qualification and the age limit that we have prescribed in regard to regular recruitment with the Board. should be strictly adhered to fill the posts of social studies Mistresses. The prescribed qualifications is that the candidates must have done besides English, two other subjects out of the following four in their B.A. ;

History ;
Geography ;
Economics ; and
Political Science.

Regarding Mathematics Mistresses and Masters the prescribed qualifications is graduation with double course of Mathematics and for Sc. Mistresses and Masters the qualification is graduation with at least one of the Sc. subjects. In the case of women we may have F.Sc., B.A.!B.Ts. The age limit prescribed is 30 years and no candidate should be appointed who is above this age.

The Divisional Inspectresses are requested to utilise the surplus J.B.T. candidates of Ludhiana, Amritsar and Jullundur and Rohtak in neighbouring districts first and then start making the temporary appointments in their other districts. The district Inspectors Inspectresses of Schools are also authorised to fill the posts of J.B.T.s on temporary basis subject to their satisfaying the age conditions qualifications. The usual restriction of selection only of those teachers/teachresses, masters/mistresses who are registered with the Employment Exchange will be observed.

Political sufferers employed in the Public Relations Department

2431. Sardar Kulbir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of Political sufferers employed in the Public Relations Department at present ;

(b) the total number of Political Sufferers working in the said department who have been retrenched recently ;

(c) the steps ; if any, being taken by the Government to rehabilitate the retrenched employees mentioned in part (b) above ?

Shri Ram Kishan : (a) and (b) This information is not available in the Department and will have to be collected from the individuals. It will involve a lot of labour which will not be commensurate with the benefits sought to be achieved ;

(c) All the retrenched employees have been permitted to apply for the new posts of Information Assistants/Field Publicity Assistants.

STATEMENTS

Mr. Speaker : The Chief Parliamentary Secretary will now lay some Statements on the Table of the House.

3.00 p.m

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House a Statement (Statement No. 1) in reply to the Call Attention Motion No. 10 moved by Shri Gian Chand Tutu, M.L.A., on the 2nd March, 1965, regarding the admission of students from all over India to Medical Colleges in the State of Punjab.

Sir, I also lay on the Table of the House a statement (Statement No. 2) in reply to the Call Attention Motion No. 14 moved by Chaudhri Net Ram, M.L.A., regarding the alleged beating of Shri Yog Raj Kapur by the Police in the Police Station at Hoshiarpur City.

STATEMENT NO. 1

Prior to 1963 admissions in the Punjab Medical Colleges were restricted to men and women candidates belonging to the Punjab State only. However, the National Integration Council in its meeting held in New Delhi in 1962 recommended to all the State Governments that admissions in the State Medical Colleges should not be denied to the nationals of India on the basis of caste, creed or place of birth. The Central Council of Health, *vide* their resolution No. 13-A (4) passed in the meeting held at Madras in November, 1963 also recommended that domicile restrictions on admission of candidates to Medical Colleges in the Indian Union should be abolished. The Punjab Government threw open admissions to the M.B.,B.S. course to the bona fide nationals of the Indian Union with effect from the academic session 1963. But merit was the sole criterion for selection. At the same time to ensure reciprocal facilities being made available to the Punjabi students the Government of India were requested to impress upon other State Governments the desirability of implementing the recommendations of the National Integration Council as well as the resolution of the Central Council of Health.

2. At the time of throwing admissions open to the nationals of the Indian Union it was anticipated that not more than 10 per cent seats would be lost to students domiciled in Punjab. The experience of 1964 admissions shows that only 7 per cent of the seats were filled in by candidates who were not residents of Punjab. Out of 400 admissions only 28 candidates were from outside the State. And even out of them several are in reality Punjabis settled in other States. Moreover, to become eligible for admission in Punjab Medical Colleges a candidate must secure at least 50 per cent marks in compulsory science subjects and pre-medical/F.Sc. (Medical) examination. Admissions are made strictly according to merit. The lowest percentage of marks obtained by a student admitted in 1964 was 58 whereas in several other States candidates securing as low as 45 per cent marks were admitted. The interests of Punjabi students seeking admission to Medical Colleges have not been adversely affected because normally all the students belonging to States other than Punjab getting marks above the minimum prescribed percentage are able to get admissions within the parent State and very few possessing the requisite merit like to move out of the State on grounds of economy and environment. Thus out siders with comparatively low merit only compete with Punjabi students and get rejected due to their low marks.

[Chief Parliamentary Secretary]

3. By throwing admissions in the State Medical Colleges open to the nationals of the Indian Union, Punjab Government has given a lead in promoting the cause of national integration. It is true that other State Governments have not so far reciprocated the gesture and taken up the lead given by the Punjab State but that does not mean that it is not a worthy cause or that the policy is wrong.

STATEMENT NO. 2

Shri Yog Raj Kapur is an employee of Life Insurance Corporation, Hoshiarpur. The building in question was taken on rent through P.W.D. in 1949 at Rs 25/2/- per month for housing the Police Post, Model Town, Hoshiarpur. It was taken in auction by Shri Yog Raj Kapur in May, 1964. As no other suitable accommodation was available to house the said Police Post it was not vacated up to 10th February, 1965. No legal notice for the vacation of this building was received from Shri Yog Raj Kapur. S.I., Om Parkash against whom he submitted a complaint to the D.C., Hoshiarpur regarding vacation of Kothi No. 11 had no concern in vacation of this building. No rent has so far been drawn, therefore, the question of obtaining receipt by the said S.I. does not arise. As regards beating to Shri Yog Raj Kapur, the matter is sub judice.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER *re* : (Panel of Chairmen)

Mr. Speaker : Under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following Members on the Panel of Chairmen :—

(1) Sardar Gurnam Singh.
(2) Shri Nihal Singh (Mahendragarh).
(3) Chaudhri Mukhtiar Singh Malik.
(4) Sardar Gurmit Singh 'Mit'.

PRESENTATION OF THE REPORTS—

(i) Committee on Estimates on the Budget Estimates for the Year 1964-65

Sardar Balwant Singh (Chairman, Committee on Estimates), Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Budget Estimates for the year 1964-65.

PRESENTATION OF THE TWENTY-FIRST REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Dr. Bal Krishan (Chairman, Public Accounts Committee) : Sir, I beg to present the Twenty-first Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation Accounts of the Punjab Government for the year 1962-63 and the Audit Report 1964 and the Finance Accounts of the Punjab Government for the year, 1962-63.

LEGISLATIVE BUSINESS

(i) Presentation of preliminary reports by the Chairman, Punjabi/Hindi Regional Committee on the Punjab Panchayat Samities and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1965 and extension of time for presenting final reports thereof.

ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ (ਸ੍ਰੀ ਰਲਾ ਰਾਮ) : ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਬਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

चेयरमैन, हिन्दी रिजनल कमेटी (श्री अमर नाथ शर्मा) : मैं हिन्दी रिजनल कमेटी की प्रारंभिक रिपोट बाबत पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक पेश करता हूं ।

Minister for Home and Development (Sardar Darbara Singh) : Sir, I beg to move —

That the time for presenting the Final Reports of the Regional Committees on the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, be extended up to the 30th March, 1965.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the time for presenting the Final Reports of the Regional Committees on the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, be extended up to the 30th March, 1965.

Mr. Speaker : Question is —

That the time for presenting the Final Reports of the Regional Committees on the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, be extended up to the 30th March, 1965.

The motion was carried

(ii) Presentation of the Report/Preliminary Report by the Chairman, Punjabi Regional Committee/Hindi Regional Committee on the Punjab Cooperative Societies (Amendment) Bill, 1965 and extension of time for presenting final report thereof.

ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ (ਸ੍ਰੀ ਰਲਾ ਰਾਮ) : ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਰਿਪਰਟ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

चेयरमैन हिन्दी रिजनल कमेटी (श्री अमर नाथ शर्मा) : मैं हिन्दी रिजनल कमेटी की प्रारम्भिक रिपोर्ट बाबत पंजाब कोआप्रेटिव सोसाइटीज (संशोधन) विधेयक पेश करता हूं ।

Minister for Home and Development (Sardar Darbara Singh) : Sir, I beg to move —

That the time for presenting the Final Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Co-operative Societies (Amendment) Bill, be extended up to the 30th March, 1965.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the time for presenting the Final Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Co-operative Societies (Amendment) Bill, be extended up to the 30th March, 1965.

Mr. Speaker : Question is —

That the time for presenting the Final Report of the Hindi Regional Committee on the Co-operative Societies (Amendment) Bill, be extended up to the 30th March, 1965.

The motion was carried

DEMAND(S) FOR GRANT(S)

(1) 19—General Administration
(2) 23—Police

(*Resumption of discussion*)

श्री अध्यक्ष : प्रिंस्पिल रला राम पिछले दिन बोल रहे थे। आप शुरु कीजीए।
(Principal Rala Ram was in possession of the house on the previous day. He may resume his speech.)

प्रिंसिपल रला राम (मुकेरियां) :– अध्यक्ष महोदय में 12 मार्च, 1965 को कह रहा था कि सरकारी दफतरों के अन्दर लोगों को शिकायत है कि उन की जो अर्जियां आती हैं तो उन की डिस्पोज़ल वक्त पर नहीं होती है और बहुत समय लग जाता है। अगर इस बारे में गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि दफतरों में काम करने वाले साढ़े तीन घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हैं। यह है ऐवरेज काम करने की। कई काम करने वाले व्यक्ति डेढ़ घंटे में सब कुछ टरका देते हैं। यह एक भारी दोष है जिस की वजह से उन की फाइल्ज़ क्लियर नहीं होती हैं और जनता क अन्दर इस कारण काफी असंतोष फैल रहा है। यदि वहां पर सुपरविज़न ठीक ढंग से की जाए तो मैं समझता हूं कि वह फाइल्ज़ जल्दी ही डिस्पोज़ आफ हो सकेंगी। रैड टैपिजम, किसी हद तक, होती हैं। मैं यह बात मानता हूं क्योंकि हर दफतर में जिस ढंग से फाइल्ज डिस्पोज़ आफ होती हैं, इस तरीके से ऐसा होना स्वभाविक है। इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। यह चीज तो काफी हद तक भ्रष्टाचार की तरफ लेजाती है। मुझे बहुत खेद से कहना पड़ता है कि इस वक्त जो रैड टेपिज़्म हमारे दफतरों में है, वह एक बहुत बड़ा दोष है और यह बहुत बुरी सूरत इख्तियार कर चुका है। यह कुरप्शन जिला स्तर और ऊपर तक मौजूद है। इस लिए रैड टेपिज़्म को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है ताकि लोगों की शिकायतें और उन की अर्ज़ियां अथवा केसिज जल्दी ही डिस्पोज़ आफ हो सकें। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में यह बात काफी आई है कि ब्लाक समितियों के अन्दर जो इलैक्शन्ज हुए, वहां काफी कुरप्शन हुई। मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त जितने भी इलैक्शन्ज होते हैं, सब से ज्यादा कुरप्शन इन ब्लाक समितियों के इलैक्शन्ज़ के अदर हुई। इस साल मिनिस्टर साहिब की कोशिश के कारण कुरप्शन पिछले इलैक्शनों की निस्बत कम हुई है। यह बात इस बार देखने में आई है। लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कुरप्शन बढ़ी हुई है। इस को दूर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के इलैक्शन्ज़ भी ब्लाक समितियों के इलैक्शनों के साथ ही हो जाने चाहिएं ताकि इस तरह से भ्रष्टाचार भी कम हो सके। मैं नहीं चाहता कि ब्लाक समितियां यानि इस इंस्टीच्यूशन को खत्म कर दिया जाए। यह बात अब सोचने की नहीं है आर्यों के ज़माने में भी इसी प्रकार की इंस्टीच्यूशन्ज़ थी। यह तरीका हजारों

सालों स चला आ रहा है। लेकिन इस वक्त तो इस इंस्टीच्यूशन को सुधारने की ज़रूरत है। यह संस्था ज़रूर चलायी जाए। इस सम्बन्ध में एक आनरेबल मैम्बर ने कहा कि जब होशियार-पुर ब्लाक समिति के इलैक्शन्ज हुए थे तो डिप्टी कमिश्नर और ए.आर. ने उस इलैक्शन में नाजायज़ दबाव डाल कर मदाखलत की। मैं ने इस बात की पिछले दो दिनों में काफी जांच पड़ताल की और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह इल्ज़ाम बिलकुल गलत है। वहां पर डिप्टी कमिश्नर तथा ए. आर. ने किसी तरह की मदाखलत नहीं की थी और कोई भी दबाव डालने का यत्न नहीं किया था। अध्यक्ष महोदय, आज कल दफतरों के अन्दर काफी हद तक काम सलो हो रहा है, मैं फीमेल स्टाफ के बारे में भी ज़िक्र करना चहता हूं। क्योंकि पुरूष और स्त्री को बराबर के हक हैं तो कोई कारण नहीं है कि दफतरों में फीमेल स्टाफ क्यों न रखा जाए। लेकिन इस के साथ ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आती है। अगर फीमेल स्टाफ को ठीक ढंग से नियुक्त न किया तो उस का दफतरों के काम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे दफतरों के अन्दर काम की आउटपुट ज्यादा होनी चाहिए। इस के लिये जो फीमेल हैंड्ज़ अपांयट किये जाते हैं वह बजाए इस के कि हर एक दफतर या सैक्शन के अन्दर सप्रैड ओवर कर दिये जाएं, मैं यह समझता हूं कि उन की अपायंटमैंट एक खास और स्पैसिफिक सैक्शन में होनी चाहिए और उन का इम्मी-जिएट बास स्त्री होनी चाहिए। इस से जो कबाहतें देखने में आ रही हैं वह बहुत हद तक दूर हो जाएंगी, काम की आउट पुट भी ज्यादा हो जाएगी और दफतरों के अन्दर जो शिकायत इस बारे में आती हैं उन के अन्दर खासी कमी हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, जैसे मैं ने पहले भी कहा था यह बात माननी चाहिए और इस बात में हमें फख्र भी है कि जहां तक दूसरे राज्यों के साथ हमारी पुलिस के मुकाबिले का प्रश्न है वह किसी से कम एफीशैंट नहीं है लेकिन जहां तक सीरियस क्राइम्ज़ का ताल्लुक है मुझे यह बात खेद के साथ कहनी पड़ती है कि उन को ट्रेस आउट करने में यह ना-कामयाब रही है। सरदार प्रताप सिंह कैरों के मर्डर को ट्रेस आउट, जैसे कि हम सुन रहे हैं, जल्दी ही कर लेंगे तो उस के लिये हमारी पुलिस विशेष सराहना की पात्र होगी। इस बात को एक तरफ रखते हुए मैं यह कहना चा ता हूं कि जहां तक सीरियस क्राईमज़ का ताल्लुक है हमारी पुलिस उन को ट्रेस आउट करने में काफी कामयाब नहीं रही और कामयाब नहीं होगी। उस के लिये फौरेंज़िक लैबारेटरी कायम की गई है ताकि हमारी पुलिस उन केसिज़ को साइकालोजीकली और सायंटिफिक ढग से हैंडल करे लेकिन उस का खातिर खाह नतीजा अभी तक हमारे सामने नहीं आया कि हमारी पुलिस सीरि यस क्राईम्ज़ को ट्रेस आउट करने में पहले की निसबत ज्यादा कामयाब हुई है। मेरे अपने ज़िले में पिछले तीन सालों में दस, बारह मर्डर ऐसे हुए हैं जो कि ट्रेस आउट नहीं हो सके। इसी हाउस के फलोर पर कहा गया कि इस स्टेट में पिछले दो तीन सालों में दो सो के करीब ऐसे मर्डर हुए हैं जो कि ट्रेस आउट नहीं हो सके। सीरियस क्राईम्ज़ की इतनी तादाद अनट्रेस्ड रहना डीज़ायरेबल बात नहीं है। इस लिये आप के द्वारा मैं यह कहूंगा कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहिब हैं उन के बारे में मुझे यह बात कहते हुए प्रसन्नता होती है कि जब कभी कोई दोष उन के नोटिस में लाया जाता है तो फौरन्, बड़ी प्राम्पटली वह उस शिकायत को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। पूरी जांच पड़ताल के बाद कोशिश करते हैं कि वह शिकायत

[प्रिंसीपल रला राम]

रफा हों। इस के लिये वह हमारी सराहना के पात्र हैं। लेकिन पुलिस के अन्दर चूंकि करप्शन काफी है, कुछ कम नहीं हुई इस लिये ग्राम गरीब जनता जब वह रिपोर्ट करने थाने के अन्दर जाती है तो अभी भी बहुत से केसिज़ ऐसे हैं जिन में उन को अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने में खासी तकलीफ होती है और मुश्किल पेश आती है। इस लिये मैं आप के द्वारा होम मिनिस्टर तक यह बात पहुंचाऊंगा कि जब तक एक मामूली ग्रामीण यह महसूस करता है कि उस की रिपोर्ट थाने में आसानी के साथ नहीं लिखी जाएगी तब तक यह एक ऐसा दोष है जिस को बहुत जल्द दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। अभी तक मैं अपने तजरुबे से यह कह सकता हूं कि साधारण जनता को अपनी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाते हुए काफी दिक्कत पेश आती है, इसे दूर करना चाहिये। हम यह चाहते हैं कि इस देश के अन्दर ऐडमिनिस्ट्रेशन टोनअप हो और ज्यादा ऐफिशैंट हो। इस के लिये जहां कैबिनट खासा पार्ट अदा कर सकती है और अफसर साहिबान बड़ा भारी पार्ट अदा कर सकते हैं वहां मैं यह कहना चाहता हूं कि हम बतौर एम. एल. एज़. काफी पार्ट अदा कर सकते हैं। हमें चाहिये कि इस हाउस के अन्दर हम आपस में कुकड़ युद्ध बन्द कर दें क्योंकि यह कुकड़ युद्ध सारे राज्य के वातावरण को खराब करता है और बजाए ऐडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करने के, बिगाड़ता है। इस सम्बन्ध में जहां कैबिनट का कर्त्तव्य है, जहां अफसर साहिबान का कर्त्तव्य है, वहां हमारा भी कर्त्तव्य है कि हम अपनी तवज्जोह ज्यादा तर कन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ लगाएं। इस से हमारी ऐडमिनिस्ट्रेशन टोन अप हो सकती है। हम यह भी चाहते हैं कि जन साधारण की शिकायात की रिपोर्ट जल्दी दर्ज हों, उन के केसिज़ जल्दी डील विद हो सकें, उन को तसल्ली बख्श जवाब पहुंचे। इस के लिये यह सब फैक्टर्ज़ काम करते हैं। अगर यह फैक्टर्ज़ मिल कर काम करें तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने राज्य के अन्दर ऐडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप न कर सकें। आप का धन्यवाद।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री (श्री प्रबोध चन्द्र) : जनाब आली, मैं आप का मश्कूर हूं कि आप ने मुझे वक्त दिया है। गो वैसे आज का दिन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये मखसूस था, पुलिस पर बहस होनी थी। मगर जो कुछ मैं ने अखबारों में पढ़ा और जो कुछ यहां आ कर सुना और स्पीचिज़ देखी हैं, खास तौर पर अपने दोस्त पंडित मोहन लाल की उन से मुझे मालूम हुआ है कि यह तो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं बल्कि सारा डीबेट प्रबोध चन्द्र पर हुआ है। जनाब आली, जो इल्ज़ाम मुझ पर गए लगाए हैं मैं उन का हर चीज़ का जवाब दूंगा और अगर फिर भी हाउस की तसल्ली न हो तो मैं समझता हूं कि उस बारे में हाउस मुनासिब कार्यवाही समझे करे, मुझे खुशी होगी।

और चीज़ों के इलावा मेरे मरहूम बच्चे का काफी जिक्र हुआ। इस से मेरे ज़ख्म फिर से हरे हो गए और अगर मैं जज़बात की रौ में बह कर कुछ कह जाऊं तो इस का मतलब यह नहीं कि मैं हाउस की शान में गुस्ताखी करना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जज़बात से काम न लूं बल्कि अपने आप को सिर्फ जवाब देने तक ही महदूद रखूं। मैं इस बात में बहुत विश्वास नहीं रखता कि चूंकि मुझे बुरा कहा गया है मैं भी उस को बुरा कहूं या मुझे चोर कहा गया है इस लिये मैं भी उसे चोर कहूं। कहने को तो, जनाब आली, अगर मुझे तीन चार दिन भी दे दें तो जो मेरे दोस्त पंडित मोहन लाल ने अवाम के जज़बात को कुचल कर और इस सूबे को गवर्नमैंट नहीं बलकि अपनी जागीर समझ कर लूट मार की है उस का चर्चा करूं तो भी कई दिन लग

जाएंगे । मैं ने एक बार इसी हाउस में कहा था, जब मुझे कहा गया कि तुम चीफमिनिस्टर के इलावा और किसी का ज़िक्र क्यों नहीं करते, पंडित मोहन लाल का ज़िक्र नहीं करते तो मैं ने कई साल पहले कहा था कि पंजाबी में एक कहावत है कि झोटा मर जाने दो चमजूआं तो खुद मर जाएंगी इसी लिये मैं पंडित मोहन लाल को और दूसरे साथियों को जो कि उस वक्त वजारत में थे कोई वुकअत नहीं देता था । इस के इलावा मैं अपनी डिगनिटी के नीचे समझता हूं कि उस आदमी का ज्यादा चर्चा करूं जिस आदमी का आज़ादी की जदोजहद में कोई हिस्सा न हो, अगर हिस्सा है तो वह यह कि उसने प्रदेश कांग्रेस के रीटर्निंग अफसर के तौर पर पैंनसिल और रबड़ खूब इस्तेमाल की । कांग्रेस की हिस्टरी में पहले भी धड़ेबाज़ी हुआ करती थी लेकिन जिस बेरहमी से इन्होंने पी. आर. ओ. होते हुए रबड़ और पैंनिसल चलाई उसकी मसाल शायद कभी नहीं मिलेगी । पी.आर. ओ.के तौर पर जो खिदमात इन्हों ने सरअंजाम दीं उसी की बदौल्त यह मिनिस्टर बने । आज से कई साल पहले जब कांग्रेस का सैशन गोहाटी में हुआ था । तो मैंने उस वक्त के कांग्रेस प्रेज़िडैंट को, पंडित जवाहर लाल जी को लिख कर दिया था कि इस शख्स ने जो कुछ कहा है, उसकी खिदमत का सिला यह होगा कि आज से चन्द महीने बाद यह वजारत का एक मेम्बर बन जाएगा । वही चीज़ हुई । आज जब इन को आंसू बहाते देखता हूं इन दी इन्ट्रैस्ट आफ दी पब्लिक लाईफ एंड प्योरिटी आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन तो मैं यह समझता हूं कि इस से बड़ा मजाक यह शख्स इस हाउस के साथ और अवाम के साथ और क्या कर सकता है ? हाउस के मैम्बर बड़े सहनशील हैं और बड़े डिगनीफाइड तरीके से काम करते हैं । मगर बड़ा ताज्जुब होता है कि वह शख्स जो हिन्दुस्तान की एक सब से बड़ी कमिशन से मुजरिम गरदाना गया हो, जिस के बारे में आज भी मेरे कानों में चालीस हजार आदमियों की अवाज आती है "मोने शाह, तुम को नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे" मारेल और आईडिल्ज़ का नाम लेकर इस हाउस के मैम्बरान की सहनशीलता का फायदा उठाए कि वह इन सब बातों को बरदाश्त करेंगे, भूल जाएंगे किसी के बारे में कि दास कमिशन ने उसके बारे में क्या कहा था और उसको आराम से सुनेंगे । तो खैर, मैं इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा ।

तो अपनी तकरीर करते हुए जनाब उन्होंने मेरे बारे में पहली बात यह कही थी कि मैंने कई लैक्चर देते हुए यह कहा था कि "कुरप्शन इज़ प्रिविलेंट" । स्पीकर साहिब, मैं आज भी यह कहता हूं कि हमारी गवर्नमैंट यह क्लेम नहीं करती कि हमने कुरप्शन का बीज मार दिया है । आखिर नौ साल के अन्दर यह जो कुरप्शन की जड़ें इतनी नीचे ले गए थे उन को रामकिशन वजारत क्या कोई भी वजारत आठ महीनों में नहीं निकाल सकती थी । हम ने इस सिलसिले में कोशिशें की हैं लेकिन मुझे इस बात के कहने में कोई गुरेज़ नहीं कि आज भी कुरप्शन काफी हद तक हमारे सूबा और देश में है ।

दूसरी बात यह कही गई थी कि इस गवर्नमैंट पर कोई एतबार क्यों करे जिस गवर्नमैंट के ऐजुकेशन मिनिस्टर ने यह कहा कि शूगर और सीमेंट बलेक मार्किट में बिकता है । यह तो जनाब हमें इस से वरासत में ही मिली हुई चीज थी और आहिस्ता आहिस्ता ही दूर होगी । यह देन पंडित मोहन लाल और इन के कमाश के आदमियों की ही है जिन्होंने स्टैंडर्ज़ आफ मारैलिटी को नौ साल तक बालाए ताक रखा और जिन के सामने सिर्फ एक ही निशाना था और वह यह कि किस तरह से जल्दी से जल्दी अमीर और ज्यादा अमीर बना जाए । आज वह कामरेड

[शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री]
राम किशन की वजारत की बाबत यह कहते हैं कि उस पर लोगों को एतबार नहीं क्योंकि उसका एक वजीर यह कहता है कि शूगर और सीमेंट ब्लैक में मिलता है और उसको मुजरिम गरदाना जाए ? ठीक है, जब यह वजारत में थे तो उस वक्त की वजारत में किसी को यह इज़ाज़त नहीं थी कि बुराइयों को बाहर लाया जाए, जो करता था उसको चुप करा दिया जाता था। लेकिन हमें हमारे चीफ मिनिस्टर की इज़ाज़त है कि जो सच्चाई हम देखें उसको कह दें। सो मैंने जरूर कहा और आज भी कहता हूं कि सीमेंट और चीनी ब्लैक मार्किट में मिलती है। यह बात कहना हकीकत से मुंह फेरना होगा कि एक पैसे की चीनी या सीमेंट ब्लैक मार्किट में नहीं मिलता।

चौधरी देवी लाल जी के साथ आजकल उनका बहुत प्यार हो गया मालूम होता है। इस बारे में जिक्र करते हुए पंडित मोहन लाल ने फरमाया कि मैंने इन से माफी मांगी और उन्होंने मुझे बख्श दिया। वह तो वह खुद ही कहेंगे कि मैंने माफी मांगी या क्या हुआ—बाबू बचन सिंह जी इस एवान के मैम्बर हैं, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, मगर उन का हवाला देकर यह अल्ज़ाम लगाया गया था। यह बात सुनकर मुझे एक पटवारी की बात याद आ गई। एक बार एक तहसीलदार ने एक पटवारी को कहा कि मैं ने तुम्हारे बारे में बड़ी शिकायत सुनी है कि इस ने फलां से रिश्वत ली है, फलां से रिश्वत ली है। पटवारी ने कहा, जनाब यह सब गलत है, मैं ने कोई पैसा किसी से नहीं लिया।" तब तहसीलदार ने कहा, "नहीं, हमें इस बात का पूरा यकीन है। यह लोग कोई झूठ थोड़े ही कहते हैं।" इस पर पटवारी ने तहसीलदार को बताया "जनाब, वह तो कल शाम एक भारी पब्लिक जलसे में यह कह रहा था कि तहसीलदार भी रिश्वत लेता है और उसने मुझसे घी का टीन लिया है।" तब तहसीलदार उस पटवारी से कहने लगा कि इस आदमी पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, यह बदमाश है, कमीना है। तो जनाब उस पटवारी ने फौरन कह दिया कि जब यह आप पर यह अल्ज़ाम लगाता है तो वह बदमाश और कमीना है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता है लेकिन जब यह मुझ पर अलजाम लगाता है तो फिर क्यों एतबार किया जाए ? तो इसी तरह मैं यह कहना चाहता हूं कि जब चौधरी देवी लाल ने मेरे बारे में कुछ कहा तो यह गास्पल ट्रुथ हो गया लेकिन क्या वह इस बात को भूल गए हैं कि उन्हीं चौधरी देवी लाल जी ने एक बोरी को इस एवान में पेश करके यह बताया था कि पंडित मोहन लाल बारह-बारह पंद्रह-पंद्रह मील साईकल पर चढ़कर जाते थे ताकि कोई केस मिल जाए और आनरेरी मेजिस्ट्रेट के अलावा और कोई जगह भी इन को नहीं मिलती थी। क्या वह इस बात को भूल गए कि नौ साल तक इसी हाउस में उन के खिलाफ सैंकड़ों अलज़ामात लगते रहे ? उन की बाबत तो इन की कान में जूं तक नहीं रींगी। और आज अगर किसी गलत फहमी में मेरे दोस्त ने मेरे बारे में कुछ कह दिया तो बार बार उसका चर्चा आता है। मैं पूछता हूं उस आनरेबल मैम्बर से कि क्या कभी उसने नौ साल तक उन बातों की तरफ तवज्जो भी दी जो लोग उसके बारे में कहा करते थे ? क्या वह इस बात को भूल गए कि यहां पर इस हाउस के एक मेम्बर सरदार प्यारा सिंह ने कहा था कि मोहन लाल फंड के नाम से हर एक शैलर और भट्टे में तीन सौ रुपया दर्ज होता है ? और इसी बात पर उस आनरेबल मेम्बर को, जिस ने यहां पर यह कहने की जुर्रत की, पार्टी से सस्पैंड कर दिया गया था। क्या वह इस बात को भूल गए कि सात लाख रुपए के करीब उन्होंने इलैक्शन के दौरान इकट्ठा किया था ? क्या वह इस बात से इनकार कर सकते हैं कि नदरन इंडिया इंजनियरिंग एसोसीएशन से बीस हज़ार रुपया इन्होंने

अपने इलैक्शन फंड में लिया। (शेम शेम की आवाज़ें)। क्या वह इस बात को भूल गए हैं कि बटाला फैक्टरीज एसोसिएशन में मोहन लाल फंड से चार आने फी मन के हिसाब से कोटे पर टैक्स लगा हुआ था ? और इस तरह 93 हज़ार रुपया आप के एकाउंट में जमा हुआ। जब पूछा गया तो कहने लगे कि साहिब, यह तो पुलिटीकल रीज़ंज़ के लिए दिया गया है। स्पीकर साहिब, इन का कच्चा चिट्ठा कहां तक खोलूं ? (आवाज़ें : खोल दो) अगर मैं उन सब बातों में जाऊं तो मैं समझता हूं कि इन पर काफी दिन लग जाएंगे। मगर मैं उन से कहूंगा कि मुझे अपनी ज़बान बन्द रखनी है और वह इसलिए कि मैं कुछ बदकिस्मती से एक ज़िम्मेदार कुर्सी पर बैठा हुआ हूं और दूसरे यह कि मैं भी उसी पार्टी का मैम्बर हूं जिस के यह मैम्बर हैं। मगर मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि शीशे के घरों में रहने वालों को कम अज़ कम इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि दूसरों पर पत्थर न फैंकें। जनाबआली, जिस शख्स के दामन में इतने दाग हों कि सारी गंगा और यमुना का पानी भी लगा दिया जाए तो भी साफ न हो पाएं, वह शख्स मेरे ऊपर यह इल्ज़ाम लगाए कि मैं ऐडमिनिस्ट्रेशन में दखल अन्दाज़ी करता हूं ? गुरदासपुर जाकर बैठा रहता हूं ? जनाब आली, मेरे पास अपने टूर्ज़ की सारी डिटेल्ज़ इस वक्त मौजूद हैं। मैं महीनों भर गुरदासपुर नहीं जाता रहा। मगर क्या चौधरी देवी लाल जी को पता नहीं है कि जब यह शख्स यहां का होम मिनिस्टर था तो अलीवाल, माधोपुर हर हफ्ते किस लिए जाया करता था ? मैं नहीं कहता कि वह किस लिए वहां पर जाया करता था मगर यह हकीकत है कि कोई हफ्ता खाली नहीं जाता था कि वह वहां न जाए। अब भी, जनाब वह वहां जाता है और सुप्रिटैंडैंट पुलिस और दूसरे अफसरान को कहता है कि "यह रामकिशन वज़ारत तो चार महीनों में खत्म होने वाली है। हमारे आदमियों को क्यों बुलाते हो और उन से बातें क्यों पूछते हो ?" स्पीकर साहिब, मुझे एक पंजाबी की कहावत याद आ गई है। कहते हैं, "खानगे जेहड़े चोपड़ियां धने सहनगे दुख"। जिन्होंने नौ साल तक लाखों रुपया गवर्नमैंट का कोटे, परमिटों में खाया वह क्यों न तड़पेंगे ? कोटे और परमिटों को सरे बाज़ार जा कर बेचा। मैं सिर्फ एक ही आदमी की बाबत ज़िक्र करूंगा जो कि इन का राईट हैंड मैन है जिस से मेरे बारे में गलत बातें कहलवाईं। जनाब आली, उन को 156 टन से भी कुछ ज्यादा पिग आयरन का कोटा मिला और वह इसलिए कि वह पाईप्स बनाकर अमरीका भेजेगा। लेकिन आप हैरान होंगे कि सिर्फ एक गाड़ी जिसकी कैपेसिटी बीस टन है वही ऐक्सपोर्ट की गई और बाकी का 136 टन बटाला के स्टेशन पर पच्चीस और तीस हजार के मुनाफे पर बेच दिया गया। आज मुझ पर अल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि मैं कुरप्शन करता हूं। स्पीकर साहिब, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि लोगों ने जो छोटे हिटलर पैदा किए थे उन को मैं बरदाश्त नहीं कर सकता। आज हम चाहते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ला हो, कानून की हकूमत हो।

स्पीकर साहिब, मेरे बारे में यह भी अल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं अफसरों के काम में जाकर दखल अन्दाज़ी करता हूं। लेकिन मैं आप को यह बता देना चाहता हूं कि मेरे ज़िला में इस वक्त जो अफसर हैं मैं उन में से 90 फीसदी अफसरों को अभी तक जानता नहीं हूं। मैं महीनों से कभी डिप्टी कमिश्नर, ऐस.पी. वगैरा से नहीं मिला। वह बताएं जब मैंने किसी अफसर को किसी काम के लिए टैलीफून भी किया हो। यह भूल गए हैं कि जब ज़िला परिषद् की इलैक्शन में पिछली बार मेरी मैजारिटी थी तो दो दिन पहिले इलैक्शन को इस बिना पर रोक दिया गया था

[शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री]

कि कांग्रेस सैशन आ रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि कांग्रेस सैशन की वजह से उस इलैक्शन को रोक दिया जाता। लेकिन असल बात यह थी कि जब तक कोटे और परमिट देकर उन लोगों को अपनी तरफ नहीं करा लिया तब तक ज़िला परिषद् की इलैक्शन नहीं कराई गई।

आज तक तो यह एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते रहे और अब मुझ पर यह इलज़ाम लगाया कि मैं ने ज़िला परिषद् की इलैक्शन में दखल दिया है। जनाबेआली, मैं पहले तो ज़िला गुरदासपुर में गया ही नहीं था और न ही उन दिनों वहां जाना ही चाहता था लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के एक दोस्त लण्डन से आए हुए थे और उन को मुझे चिट्ठी आई हुई थी कि उन्होंने धर्मशाला में दलाई लामा को मिलने जाना है इस लिए मुझे वहां जाना पड़ा। मैं 11 तारीख को धर्मशाला में गया और 13 तारीख को मैं ने गुरदासपुर में वहां के गवर्नमैंट कालेज के एक फंकशन पर प्रीज़ाइड करना था और अभी ज़िला परिषद् के चुनाव की तारीख भी फिक्स नहीं हुई थी जब से मैंने वहां प्रीज़ाइड करना कमिट किया हुआ था। यह कहते हैं कि मैं ज़िला परिषद् की इलैक्शन में इण्ट्रेस्ट लेता हूं हालांकि मैं ने इस में बिलकुल कोई दखल नहीं दिया। और अगर मैं उस इलैक्शन में इण्ट्रेस्ट लेता भी तो भी कोई एतराज़ वाली बात नहीं हो सकती क्योंकि बतौर एक सियासी आदमी होने के मैं अगर चाहता तो उस चुनाव में इण्ट्रेस्ट ले भी सकता था।

स्पीकर साहिब, आप देखें कि इन के बेहतरीन दोस्त पंडित गोरख नाथ हैं जो पहले इस हाउस के मेम्बर भी रह चुके हैं। जब तक वह इन के खिलाफ थे उस वक्त तो इन्होंने उस को कांग्रेस का टिकट भी नहीं लेने दिया और जब उन्हों ने इन का साथ देना मान लिया तो हालांकि वह सिर्फ मैट्रिक पास हैं लेकिन फिर भी उन को सबार्डिनेट सर्विसिज़ सिलैक्शन बोर्ड का मैम्बर बना दिया और अब उन को इस्तेमाल किया जाता है मेरे खिलाफ दिल्ली में बड़े २ लीडर्ज़ को कहने के लिए कि मुझे मिनिस्टरी में न रखा जाए। फिर आप देखें कि जब श्री कामराज जी गुरदासपुर में आए तो वहां पर चालीस हज़ार की हाज़री में इन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की जिस पर चालीस के चालीस हज़ार की हाज़री खड़ी हो गई और इन दोनों को एक लफज़ भी न कहने दिया और इन को सुनने से इनकार कर दिया। इस पर कामराज जी ने कहा कि यह शख्स बहुत बदनाम है। Is he so unpopular? इस के बाद जब मैं ने लोगों को बैठ जाने के लिए कहा तो वह चुप कर के बैठ गए। इस पर इन्होंने वहां के जो चार बेहतरीन कांग्रेस वर्कर थे उन को सस्पेण्ड कर दिया और उन पर यह ऐक्शन इस लिए लिया गया क्योंकि उन्हों ने इन के खिलाफ डिमानस्ट्रेशन की थी। मैं इन से पूछना चाहता हूं कि क्या यह भूल गए हैं कि इलेक्शन के दौरान जब यह अपनी कानस्टीच्यूएंसी में गए थे तो इन्हों ने वहां के एस. पी. को टेलीफोन किया था कि इन की ज़िंदगी को खतरा है। मैं अर्ज़ करता हूं कि जिस शख्श में इतनी जुर्रत न हो कि वह बगैर किसी खौफ के अपनी कान्स्टीच्यूएंसी में जा सके वह मेरी बाबत कहते हैं कि मैं बदनाम हूं।

जनाबे आली, मैं इन के खिलाफ इल्ज़ामों के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि इतने में ही इन की तसल्ली हो जायेगी क्योंकि अकलमन्द के लिये इशारा ही काफी होता है और अगर फिर इन्होंने कुछ कहा और फिर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर अर्ज करूंगा।

एक इन्होंने कहा है कि इलैक्शन का रिजल्ट जो था वह गज़ट नहीं किया गया और मैं ने गज़ट होने से रोक दिया । इस बारे में मैं अर्ज़ करता हूं कि जिस दिन प्रैज़ीडट का इलैक्शन हुआ उस के तीसरे ही दिन मेरे पास यह शिकायत आई कि वह आदमी अनपढ़ है इसलिये इस की इलैक्शन गज़ट नहीं होनी चाहिये । तो इस पर मैं ने अपने महकमा से दरियाफत किया कि क्या किसी अनपढ़ आदमी के लिये कोई बार तो नहीं है और जिस दिन मुझे मेरे महकमे वालों ने बताया कि इस में कोई बार नहीं है तो मैं ने लिख दिया कि इस इलैक्शन को फौरन गज़ट किया जाये । फिर, स्पीकर साहिब, जिस आदमी के बारे में इन्होंने यह एतराज किया है वह मेरे अपने आदमी हैं ।

फिर, जनाबे आली, इन्होंने धारीवाल म्युनिसिपल कमेटी की सीमिंट और ईंटों की चोरी का ज़िक्र किया । स्पीकर साहिब, सोने की चोरी और समगलिंग के बारे में तो सुनते थे लेकिन ईंटों की चोरी के बारे में कभी नहीं सुना था और इस में इलज़ाम यह लगाया गया है कि इस चोरी में मेरे बहनोई इनवाल्वड हैं और उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । मैं अर्ज़ करता हूं कि जब इस बारे में एक अर्ज़ी चीफ मिनिस्टर साहिब के पास आई तो उन्होंने मेरे पास भेज दी । उस अर्ज़ी पर कामरेड शमशेर सिंह जोश और कामरेड स्वतंत्र साहिब के दस्तखत थे । इतफाक से वह मेरे पास घर पर आए तो इन से मैं ने इस बार में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तो उस अर्ज़ी को पढ़ा ही नहीं और क्योंकि कामरेड राजकुमार, जो वहां के कम्युनिस्ट वर्कर हैं, ने इन को इस पर दस्तखत करने के लिये कहा था, इस लिये उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिये थे । जनाब आली, जब मैं ने देखा कि इस में मेरे बहनोई इनवाल्वड हैं तो मैं ने उस अर्ज़ी पर लिख कर चीफ मिनिस्टर साहिब को वापस भेज दिया कि क्योंकि इस में मेरे बहनोई इनवाल्वड हैं, इस लिये मैं इस बारे इनक्वायरी नहीं करना चाहता और लिखा कि इस बारे में आप किसी अच्छे अफसर की मार्फत इस मामले की इनक्वायरी करा लें । मैं इस में किसी किस्म का कोई दखल नहीं देना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर कोई हमारा नज़दीकी रिश्तेदार भी कोई इस तरह का फेल करता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिये । इस बारे में मैं इतना ज़रूर अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि कामरेड राज-कुमार ने दो महीने के लिये बतौर एक्टिंग प्रैज़ीडैंट के काम करना था और उस दौरान उन को इस चोरी का पता नहीं लग सका और चार तारीख को जब उन को पता लगा कि प्रैज़ीडैन्ट की इलैक्शन की गज़ट नोटीफिकेशन हो गई है तो वह पांच तारीख को डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाते हैं और उनको इस बार में शिकायत कर आते हैं । हालांकि तरीका यह था कि इस बारे में पहले एग्ज़ामीनर लोकल बाडीज़ के ज़रिये उस सारी चीज़ की जांच कराई जाती और बाद में उसे डिप्टी कमिश्नर के पास भेजा जाता फिर इस के बाद उन्होंने प्रैस कानफ्रेंस भी कर दी । इस सारे केस के बारे में चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे क्योंकि उन्होंने इस बार में इनक्वायरी कराई है । इतना मैं कह देता हूं कि कामरड राजकुमार जो कि दो वार्डो से इलैक्शन के लिये खड़े हुए थे, ने मेरे बहनोई से एक वार्ड में हार खाई थी ।

फिर, जनाबे आली, इन्होंने एक इलज़ाम मेरे खिलाफ यह लगाया है कि मैं ने अपने सन-इन-ला को फरीदाबाद कमेटी का मैम्बर नामज़द किया है । इस बारे में मैं गुज़ारिश

[शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री]
करता हूं कि फरीदाबाद एक नोटीफाइड एरिया कमेटी है जो कि 1960 में बनी थी जब कि इन्होंने, जो उस वक्त इस महकमा के इन्चार्च थे, एक नरेन्द्र नाथ को जो इनके लड़के के साथ हिंदुस्तान सरिंजिज़ में पार्टनर था उस कमेटी का मैम्बर नामज़द किया था फिर उस के दो साल बाद वहां के डिप्टी कमिश्नर ने एक लिस्ट नामज़दगी के लिये नामों की 1962 में भेजी तो उस को यह साल भर अपने पास दबा कर रखी रखा। फिर उस के साल बाद जब इस महकमा के वजीर सरदार गुरबंता सिंह बन गये तो एक साल तक उन्होंने उस लिस्ट को दबाए रखा और श्री नरेन्द्र नाथ को उस कमेटी का मैम्बर नाजायज़ तौर पर बने रहने दिया और नई नामज़दगी नहीं की। इतना कुछ करने के बाद यह कहते हैं कि मैं ने इन्टरफीयर किया है। फिर आप देखें इन की इन्टरफीयरेंस की हद कहां तक जाती है। ज्ञानी करतार सिंह जब इस महकमा के मिनिस्टर थे तो उन्होंने सरदार वरियाम सिंह के लड़के को एग्ज़ैक्टिव अफसर बनाने के लिये हुकम कर दिया था लेकिन उस के फौरन बाद महकमे बदल गए और यह महकमा इन के पास आ गया तो यह धारीबाल से आ रहे थे तो इन्होंने उस की बजाये अपने एक दोस्त के बहनोई को एग्ज़ैक्टिव अफसर मुकर्रर कर दिया। जहां तक मेरे सन-इन-ला की नामीनेशन का ताल्लुक है, इस बारे में मैं अर्ज करता हूं कि मैं आज तक न गुड़गांव गया ही हूं और न ही इस बारे में डिप्टी कमिश्नर को लिख कर भेजा है। हां, एक बार मैं पलवल ज़रूर गया था और मैं वहां के डिप्टी कमिश्नर को कभी आज तक नहीं मिला जो मैं ने उस को कहा हो कि मेरे सन-इन-ला का नाम वह नामजदगी के लिये भेज दे। पहले कुछ आदमियों के नाम नामजदगी के लिये भेजे थे वह गिनती में कम थे। इस पर मैं ने उसे लिखा था क्योंकि फरीदाबाद की आबादी बढ़ गई है इस लिये वह ज्यादा आदमियों के नामों की लिस्ट भेजे। इस पर उस ने 17 नामों की लिस्ट भेजी थी। उन 17 नामों में एक शख्स बाला सुन्दरम का था, जिस के खिलाफ यह शिकायत थी कि उसने नैशनल डिफेंस फण्ड की कुलैक्शन में मुखालिफत की थी। मेरे दोस्त महता साहिब से भी पूछा गया क्योंकि यह उसी ज़िला से आये हुए हैं तो इन्होंने भी बताया कि वह आदमी अच्छा नहीं है। तो उस के नाम को छोड़ कर बाकी के सारे नामों की नामज़दगी के लिये मैं ने आर्डर कर दिए जिन में मेरे सन-इन-ला का नाम भी था। मेरा सन-इन-ला वहां की लायन्ज़ कल्ब का सैक्रटरी है और स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन का प्रैज़िडैंट है और अगर उस का नाम वहां के डिप्टी कमिश्नर ने भेज दिया है तो कोई अनोखी बात तो नहीं हुई। फिर मुझे अपने रिश्तदारों पर एतबार है। इन को अपनें मैयार और अपने पैमाने से नहीं नापना चाहिए।

फिर, स्पीकर साहिब, यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं ने उस के प्रैज़ीडैन्ट चुने जाने में कोई दखल दिया है। इस बारे में मैं अर्ज करता हूं कि उस चुनाव में 15 मैम्बरों ने वोट डाले और इन 15 में से 10 ने मेरे सन-इन-ला को वोट दिया और पांच ने उस के खिलाफ दिया। फिर डिप्टी कमिश्नर भी वहां उस मीटिंग में मौजूद नहीं था जिस के बारे में कहा जा सके कि उस ने किसी को इनफ्लूयेंस किया हो। तो इन हालात में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी मिनिस्टर के किसी रिश्तेदार को यह हक हासल

नहीं है कि वह इलैक्शन लड़ कर किसी कमेटी का प्रैज़ीडैन्ट या वाईस प्रैज़ीडैन्ट बन सके ? फिर इस सिलसिले में इन्होंने यहां एक इशितहार पेश किया है जो कि इन्होंने और इन के हमवारियों ने छपवाये हैं। फिर मैं इन से पूछता हूं कि क्या यह भूल चुके हैं पंजाब के करोड़ों अवाम की धड़कनों को जो हजारहा इशितहार इन के खिलाफ छपवाते रहे थे जो आज यह यहां पोस्टर दिखा कर इस बात की चर्चा कर रहे हैं। फिर इसी पर ही बस नहीं, स्पीकर साहिब, कि इन्होंने अपने बेटे के पार्टनर को इस कमेटी का मेम्बर नामज़द किया और कई सालों तक उसे मैम्बर रहने दिया बल्कि वहां फरीदाबाद में जितने इण्डस्ट्रियलिस्ट्स थे, जिन में इनका का बेटा भी एक था, को फायदा पहुंचाने के लिये इन्होंने वहां आक्टराए में 20 फी सदी कमी कर दी। उसका नतीजा यह हुआ कि करीब पांच लाख का खसारा हुआ। और यहां यह शोर मचाते नहीं थकते कि कौन नामज़द हो गया। फैक्टरी वाले इस लिये रोते हैं कि जो रियायतें उन को पंडित जी के वक्त में मिली हुई थीं वह शायद छिन जायें। इस लिये नहीं रोते कि कोई गल्त आदमी नामज़द हो गया है। सारी चीज़ आप के सामने है। आप देखें कि जितनी वाइड सिलैक्शन हो सकती थी हुई है। मगर इस बात को ले कर कि उस में मेरा दामाद भी है एक तूफाने बद तमीज़ी पैदा कर दिया गया है। उस के नामज़द हो जाने से आफत क्या आ गई थी ?

फिर, मेरे असैट्स का ज़िक्र किया गया। इन्होंने, जनाबे आली, हवाला दिया कि मैं ने जो अपने असैट्स दिखाए हैं। उस में ६ एकड़ ज़मीन दिखाई है। जो कि अब 11-12 कमरों की कोठी बन गई है। जनाब, असैट्स की कापी मेरे पास है और इस की कापी मैं ने न सिर्फ चीफ मिनिस्टर को ही न सिर्फ कांग्रेस प्रैज़ीडैंट को ही बल्कि चीफ सैक्रेटरी, डायरैक्टर आफ इन्डस्ट्रीज़ को भी भेजी है। उस में लिखा है कि 6 एकड़ ज़मीन है मगर उसका जो सैकण्ड आइटम है उस में लिखा है 'small house at Gurdaspur worth about 15,000 "। जनाबेआली, मैं कल जा कर उस मकान की दीवारें गिरा नहीं आया। मैं कहता हूं कि इस हाऊस में कोई भी मैम्बर मेरे खर्च पर गुरदासपुर जा कर देख आए कि असलियत क्या है उस कोठी की। उस में दो तो बैड रूम्ज़ कोई 12 बाई 15 फुट के, एक डाइनिंग और ड्राइंग रूम है। और यह सब अभी नामुकम्मल है, कुछ भी नहीं, दरवाज़े नहीं, सैनेटरी फिटिंग्ज़ भी नहीं। मेरा बाप कोई छाबा तो नहीं लगाता था कि मेरे पास इतना मकान भी नहीं हो सकता जबकि पंडित मोहन लाल जी की यहां पर डेढ़ लाख की कोठी बन गई है ? मैं ने जो असैट्स दिये हैं चाहे फैक्टरी के बारे में हैं या किसी और चीज़ के बारे में हैं अगर उन में एक लफज़ भी गल्त हो, कोई हेरा फेरी हो तो मैं जिम्मेदार हूं अलबता उस में एक मिसप्रिंट जरूर है कि जहां एक लाख 80 हजार लिखा है वहां पर एका ज्यादा लग गया है जो कि 80,000 ही चाहिये। मगर इस बारे में तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। आप जरा गौर से देखें कि इन्होंने इस एवान में अपनी जबान से कहा था कि मेरे बरखुरदार भतीजे बेअन्त लाल का शराब के ठेके में हिस्सा नहीं है। (विघ्न) मंगल सेन जी की काल अटैन्शन मोशन थी इस सिलसिले में मगर इन के डंडे के जोर से वह बात दबी रही मगर अब चूंकि

[शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री]
वह लड़ पड़े हैं तो सारी बात बाहिर आई है कि किस तरह से इन के भतीजे उस में कमाई करते रहे हैं। वह जो लैजर है उस की फोटो स्टैट कापी में लाया हूं जो देखने से पता चलता है कि (विघ्न) (एक आवाज़ : मेज़ पर रखें) :। हां मेज़ पर रखूंगा। 52,705 रुपये की कमाई हुई। कल यह कहते थे कि हमारा एक मकान और सिगरेट बीड़ी की दुकान है। अपने भतीजे को शूगर सिंडीकेट बटाला का प्रैज़ीडैन्ट बना दिया। जो लोग फतेहगढ़ चूड़ियां में सिगरेट बीड़ी बेचते थे उन को वहां बैठा कर शूगर कन्ट्रोल आर्डर की मिट्टी प्लीद की। तीन आदमी नामज़द करवाये, डंडे के जोर से अपने भतीजे को उन का चेयरमैन बनवाया और एतराज़ करते हैं बहनोई या सन-इन-ला की नामीनेशन पर। फतेहगढ़ चूड़ियां की फाइल देखें तो पता चले कि क्या असलियत है।

स्पीकर साहिब, मैं एक सियासी आदमी हूं और मैं नौ साल तक यहां पर उंगली उठाता रहा हूं जो कि हर एक का हक बनता है। मगर कितने दुख की बात है कि मेरे मासूम बच्चे—जिस मासूम ने दुनिया अभी देखी ही नहीं थी उस पर इल्जाम लगाया गया कि उस ने कोई बेइमानी की है या गल्ती की है। जनाबेआली, 1940-41-42 में पहलगाम में हमारा होटल, रैस्टोरां और जैनरल मरचैंट्स का काम था। हमारे पास इन्द्रा जी, शेख अब्दुल्ला और बख्शी साहिब बगैरह ठहरते रहे हैं। जनाब दस अगस्त को मुझे लाहौर से तार आया कि मेरे फादर-इन-ला अरैस्ट कर लिये गये हैं, मेरी बहन टी.बी की तीसरी स्टेज में बीमार थी। जनाब, मैं वहां पहुंचते ही अरैस्ट हो गया और तीन साल तक कैद रहा। इस दौरान मैं सारी जायदाद खराब हो गई, तो बाद में कई बार बख्शी साहिब ने मुझे कहा कि हम पोलीटीकल सफर्रज़ को कम्पैनसेशन दे रहे हैं तुम भी ले लो। मैंने उन से कहा कि मेरा कोई काम करने वाला आदमी नहीं है इस लिये मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जब मेरा बेटा साढ़े 19 साल का हुआ तो उन्होंने आफर की। उन्होंने बताया कि होटल प्रैज़ीडैंशियल तो सरकार चला रही है तुम को ट्रांस्पोर्ट के परमिट दे देते हैं? तो 80 हजार रुपया नैशनल बैन्क आफ लाहौर से कर्ज ले कर उन को चलाया। उस को 25 हजार रुपये का मुनाफा हुआ। उस की एक पालीसी भी थी। मैं ने पंजाब सरकार का 30 हजार रुपया देना था, जिस में से 20 हजार रुपया दे दिया है और 10 हजार अभी देना है। 10 हजार रुपया मैं ने काशमीर गवर्नमैन्ट को दे दिया। 3,500 रुपये की एक और 500 रुपये की दूसरी रसीदें मेरे पास हैं, बाकी भी मैं पेश कर सकता हूं। मैं ने उस की आमदन में से एक पाई नहीं ली।

फिर, जनाब, यहां पर बड़ा चर्चा हुआ कि मैं ने कहा है कि मैं ने क्लेम नहीं दिया है और न कुछ लिया है। मगर यह कहते हैं कि मैं ने किसी जगह कहा है कि 24 हजार रुपये की जमीन क्लेम में मिली है। एक दूसरी जगह एक स्पीच में जो करैक्ट नहीं हुई, कहा है 24 हजार क्लेम का है मगर मैं इस हाउस में साफ कहता हूं कि मैं ने मेरी बीवी ने, या मेरे बेटे ने एक पाई का भी क्लेम न किया है और न किसी भी शक्ल में लिया है। 24,600 रुपय की मैं ने जमीन खरीदी है और उस पर फैक्टरी भी मैंने खुद बनाई है, वह जमीन ही थी और कुछ दुकानें थीं। मेरे पास डिप्टी चीफ़ कन्ट्रोलर,

मिस्टर नायर, की एक चिट्ठी है जिस में उन्होंने लिखा है कि 18,000 रुपया वसूल हो गया है और अभी 6 हजार रुपया लेना है। तो इस को यह कहना कि मैं ने 24,000 का क्लेम लिया है सरीहन गलत-बयानी है। तो मैं ने यह साफ लिखा है कि मैं ने 24,600 रु० की रैफयूजी लैंड ली थी। इस में से कुछ तो इन्स्टालमैंट्स के जरिये अदा कर दिया है और 6,000 रुपया अभी गवर्नमेंट को देना है। अभी तो मुझे उस जमीन के प्रोप्राइटी राइट्स भी नहीं मिले मगर इस हाउस में इस तरह से चर्चा किया गया कि पता नहीं क्या हो गया है। मेरे लिये तो यह हाउस ही मक्का और मदीना है, सियासी आदमी के लिये जितनी पवित्र यह जगह हो सकती है और कोई नहीं हो सकती मगर यहां पर भी बार २ मेरे मुताल्लिक गलत बयानी की गई। मेरे बारे में तो शोर मचाते हैं मगर आप अपने भतीजे के नाम बेनामी काम करके सारा सिलसिला चलाते रहे हैं, पता नहीं उस को किस तरह से कोटे और परमिट दिलाते रहे हैं। जब भानजे ने देखा कि भतीजे को दिला रहे हैं तो उस ने भी मांगा तो उस को भी डिपू और भट्ठे का लाइसेंस दिलाया। और पांच साल तक भट्ठा नहीं चलाया गया और कोला ब्लैक मारकिट में बेचा जाता रहा। फिर जब इन्हें यह पता चला कि इन के सर पर बादल मंडला रहे हैं तो इस भट्ठे को चलाया गया। इस बात की इन्क्वायरी चीफ मिनिस्टर साहिब करवा सकते हैं और सेल्ज़ टैक्स के रिकार्ड से इस बात का पता चल सकता है कि कब से इन्हें कोयला मिलना शुरू हुआ और कब से उन्होंने टैक्स देना शुरू किया।

इस के अलावा जनाबे आली, इन्होंने जालन्धर के मीडिएटर्ज़ का जिक्र किया है। यह ठीक है कि श्री वीरेन्द्र और लाला जगत नारायण मेरे दोस्त हैं और मुझे इन पर फखर है। इन जैसे सैन्कड़ों को इन दो पै कुरबान कर सकता हूं। यह उस वक्त से काम कर रहे हैं जब कि जेल जाना और फांसी के तख्ते को चूमना होता था और पंडित जी के वक्त के वरकर नहीं कि जिस वक्त डिपुओं और कोटे बांटे जाते रहे। इस लिये इस बात का ताना देना ठीक नहीं था।

एक चीज़ को खास तौर पर मैं चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाना चाहता हूं कि 24-9-63 को, जब पंडित जी इन्डस्ट्री के इन्चार्ज थे तो, इन्होंने कोटा दिया 114.50 टन खरायती राम को जिस की ड्यूटी सिर्फ यही है कि हर मास मेरे खिलाफ एक अर्ज़ी दे दे। फिर 25-11-63 को कोटा दिया जाता है 20-30 मीट्रिक टन और फिर 29-11-63 को 22 टन। तो इस तरह से कुल मिला कर 156.80 टन का कोटा दिया जाता है :

It was solely for the manufacture of pipes to be exported to America. Only 25 tons of pipes were exported and the rest of the pig iron wa s sold in the black-market and a profit of about Rs 25,000 was made.

तो मैं आप का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं ने जवाबी तौर पर अपनी पोज़ीशन वाजेह कर दी है। फिर भी हाउस को और अपोज़ीशन के लीडर्ज़ के सामने अपनी स्टेटमेन्ट आफ अकाऊंटस रखने को तैयार हूं और अगर एक पाई की भी गलती निकल आए तो मिनिस्टरी छोड़ देने को तैयार हूं। अस्तीफा तो क्या और कोई सज़ा आप चाहें,

[शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री]

लेने को तैयार हूं। जो आदमी सारी उम्र दूसरों पर उंगली उठाता रहा हो कि वह काले हैं अगर आप काला साबित हो जाए तो अस्तीफा तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी से बड़ी सजा लेने को तैयार है।

फिर यह कहा गया कि मेरा दस ग्यारह कमरों का मकान है। इस के बारे में इस हाउस का कोई भी मेम्बर इस बात की हकीकत देखना चाहे तो मैं उसे प्राइवेट तौर पर और प्राइवेट गाड़ी में वहां पर ले जाने के लिये तैयार हूं और दिखा सकता हूं कि वहां पर सिवाए चार कमरों के वह भी 10–12 फुट के और कुछ भी नहीं।

अगर पंडित जी को लै लाए हकूमत का खाब था और वह पूरा नहीं हुआ तो इस का जिम्मेदार मैं नहीं दास कमिशन है या इन का अपना करदार है। इन की तरह मैं नहीं कि एक लाइन में ओथ लेने चले गए कि कहीं घपला लग जाएं। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि अगर इन की बातों में रत्ती भर भी सचाई हो तो लोगों को इस के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं, मैं फौरन इस आफिस से अलग हो जाऊंगा। मैं तो ज़रा ज़रा डिफरैंससिज़ पर चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी और स्पीकर की गद्दी को छोड़ आया था। मुझे इन बातों से प्यार नहीं।

मैं इस हाऊस की इज्ज़त के लिये, जो कि मुझे सब से प्यारी है, आप से, स्पीकर साहिब इल्तजा करूंगा कि आप अपनी मर्जी की एक कमेटी बना दें। इसको चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहिब भी देख लें और जो कुछ मैं ने कहा है अगर इस में से एक फी सदी भी कमी हो तो मुझे और कहने की जरूरत नहीं। मेरी आप के ज़रिये इन से अर्ज़ है कि इस तरह की बातों को ज़रिया बना कर एक दूसरे पर गंदगी उछालना मुनासिब नहीं और इस तरह की बातें कर के कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिये तो बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन हरेक को हर वक्त के लिये नहीं। पंडित जी कल तक क्या थे और 8 साल की वज़ारत में क्या कुछ किया, सब जानते हैं। अगर इन की आठ सालों की तनखाह सारी की सारी मिला ली जाए तो भी इतनी बड़ी कोठी चन्डीगढ़ में यह नहीं बना सकते थे और इधर मेरा यह हाल है कि मैं ने यहां पर 4 क्नाल ज़मीन ली थी और सिर्फ एक किश्त ही अदा कर सका और 2500 दिया था तो 1700 ले कर किसी और को यह प्लाट दे दिया और उस आदमी ने इस को 60 हज़ार में बेचा अगर मेरे पास रुपया होता तो मैं भी इसे रख सकता था। मेरे पास 10-20 लाख रुपया नहीं जैसा कि इन के पास है। फिर सिन्डीकेट को छोड़ कर एक आदमी को इन्होंने लाइसेंस दिया और उस ने 3 लाख कमा लिया। यह अपने काम यही कर सकते थे। और इन के वक्त में हरेक पर जज़ीया लगा हुआ था मोहन लाल फन्ड बना हुआ था।

इन के खिलाफ इलैक्शन पैटीशन हुई तो इन्होंने अपने हलके में 20 इन्स्टीचूशनज़ को अपने डिसक्रीश्नरी फन्ड में से रुपया दे दिया और इस के मुकाबिले में मैं ने एक पाई भी अपने हल्का में नहीं दी। यह फन्ड तो एक अमानत के तौर पर होता है कि ज़रूरतमन्द को दिया जाए। लेकिन इन्होंने इस बात की प्रवाह नहीं की।

इस लिए मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि हमें इस इवान में अच्छी रवायात को कायम करना चाहिए ताकि आने वाली नसलें उन पर अमल करें। मुझे अफसोस है कि जब आने वाली नस्लें इस तरह की स्पीचों को पढ़ेंगी तो क्या कहेंगी कि हमारे बूढ़ों ने किस तरह की कनवेन्शन्ज़ कायम की हैं। अगर वह पंडित मोहन लाल और मेरी स्पीचें पढ़ेंगी तो कोसेंगी। इन अलफाज़ के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर उन्होंने फिर इस तरह की गुस्ताखी की तो उम्मीद है मुझे मौका मिलेगा।

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं आप के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बहस हो रही है। जहां तक श्री प्रबोध चन्द्र जी की बात है वह सच है। इस में एक प्वायंट रह गया था कि कल इन पर यह इलज़ाम लगाया गया था कि जो इन्होंने स्टेटमेन्ट दिया है कि मैं ने कोई कलेम नहीं लिया और न ही कोई कम्पैनसेशन लिया है और दूसरा यह स्टेटमेन्ट दिया है कि 24 हजार का क्लेम दे कर आदर्श फैक्टरी ली है, तो इन दोनों बातों में से कौन सी सच है।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : मैं ने इस के बारे में बारहा कहा है कि कि मैं ने यह कोई क्लेम एक पैसे का भी नहीं दिया और न ही कोई किसी किस्म की कम्पेनसैशन पंजाब गवर्नमेंट से या सैंट्रल गवर्नमेंट से ली और न ही किसी दुकान, मकान या कैश की शक्ल में कोई कम्पैनसेशन लिया। मुझे मेरी स्पीच की दो रिपोर्टें मिली हैं, एक में लिखा है कि 24,000 की खरीद की और इस में क्लेम का लफज़ है। यह रिपोर्ट में गलती हो गई और यह कुरैक्टिड स्पीच न थी। इस के लिये अगर जो कुछ मैं ने कहा है गलत हो तो जो सज़ा हाउस देना चाहे उस के लिये तैयार हूं।

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, सज़ा के लिये तो सरदार सुरेन्द्र सिंह कैरों और सरदार गुरेन्द्र सिंह कैरों ने रास्ता निकाल दिया है कि इन्होंने अपनी तमाम जायदाद सरैन्डर कर दी है। इसी तरह इन्हें भी कहा जाए कि यह दोनों ही अपनी तमाम जायदाद सरैन्डर कर दें।

श्री मोहन लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं आप का ध्यान इन की 3-3-65 की स्पीच की तरफ दिलाना चाहता हूं। (विघन) इस स्पीच के इलफाज़ यह हैं कि इस फैक्टरी पर 24 हजार के करीब जो कि गवर्नमेंट ने मेरे से क्लेम की शक्ल में मनजूर किये थे वह मैं ने लगाए....... (विघ्न)

Mr. Speaker : Please............

Shri Mohan Lal : Sir, I am coming to my point of Order.

Mr. Speaker : The statements made by the hon. Member as also by the hon. Minister for Education and Local Government are on record. What more does the hon. Member want ?

श्री मोहन लाल : मैं तो आप का ध्यान इन की 3-3-65 की स्पीच की तरफ दिलाना चाहता हूं (विघ्न) इस स्पीच के अलफाज़ यह हैं कि इस फैक्टरीज़ पर 24 हजार के करीब रुपया जो कि गवर्नमेंट ने मेरे क्लेम की शक्ल में मन्जूर किये थे....वह मैं ने लगाए

Mr. Speaker : That is already on record

Shri Ram Chandra Comrade : On a point of Order, Sir............

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat.

OBSERVATIONS BY THE SPEAKER REGARDING ALLEGATIONS AND COUNTER ALLEGATIONS MADE IN THE HOUSE AND NECESSITY TO CONSTITUTE A COMMITTEE TO DETERMINE THE CODE OF CONDUCT OF MEMBERS AND MINISTERS IN THE HOUSE

4.00 p.m.

Mr. Speaker : For the last many days, there has been a tendency to make allegations and counter allegations against honourable Members of this House. I have been feeling concerned over it. Today, I will consult the Leader of the House and the Leaders of various Groups and will try to find a way out as to how we can check that tendency. And, if all the Leaders agree, a Committee may be constituted to determine the Code of Conduct of Members and Ministers in this House.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼: On a point of order, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਗਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਲਸੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਲੀਅਰ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ, ਇਥੇ ਅਜ ਤਕ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਸਹੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is no point of order.

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, इस हाउस में पिछले कई दिनों से एक दूसरे पर इलज़ामात पंडित मोहन लाल और श्री प्रबोध चंद्र की तरफ से लगाये जा रहे हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जैसा कि आप ने कहा है एक कमेटी जांच पड़ताल के लिये बनाई है, आप इस के मुताल्लिक इनक्वायरी कर के हमें जरूर बतायेंगे........

Mr. Speaker : I had not said this, I have said differently.

Demands for Grants
I—19 General Administration
II—24 Police
(Resumption of Discussion)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਦਫਾ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ

ਨਾਲ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਾਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਰਪਟ ਸੀ, ਇਨਐਫੀਸੈਂਟ ਸੀ।

(At this stage Deputy Speaker occupied the Chair.)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਏਥੇ ਏਸੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਨੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਰਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ੨-3 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹਨ। ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਨਐਫੀਸੈਂਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਏਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕ ਅਸੂਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾਂ ਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਬਲ ਬੋਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਰਪਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਤੇ ਠੋਸਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ, ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਟਾਪ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਕਾ-ਪਰਸਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਨੋਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਦਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਇਕ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਜਿਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਏ ਔਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰ ਵੀ ਸੀਰਿਅਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਲੋਂ ਦੱਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਤਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ, ਫੇਵਰਟਿਜ਼ਮ, ਨੈਪੁਟਿਜ਼ਮ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਯਾ ਯਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇ-ਦਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਾ ਅਹਿਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੀਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਐਫੀਸ਼ਿਐਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਫਿਅਰੇਂਸ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਾਇਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਨਿਸਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਕਿ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ 100-100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਯੋਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਭਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ ਬਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੌਮਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਵਖਾਉਣ ਮਗਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ।

PERSONAL EXPLANATION BY CHAUDHRI DEVI LAL

चौधरी देवी लाल : On a point of personal Explanation, Madam. यह जो सरदार गुरनाम सिंह जी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह बयान दिया है कि 4 आदमी इधर से उधर जा रहे हैं, उस के बारे में मैं परसनल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। जो होम मिनिस्टर साहिब ने और चीफ मिनिस्टर साहिब ने मेरी बाबत यह कहा है कि आपकी जगह इधर है, यह बिलकुल गलत है। उपाध्यक्षा, जो हालत आज कांग्रेस की है, वह जिस किस्म की है, आप खुद देख रही हैं, उस में मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ने 4 मैम्बरों के सम्बन्ध में कल कहना था लेकिन लीडर आफ दी आपोज़ीशन ने आज ही छेड़ दिया। मेरे पास तमाम पी० आई० पी० के मैम्बरों के दस्तखत हैं जिन्होंने यह कहा है कि ट्रेज़री बैंचिज़ पर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं यह पढ़ कर हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं —

"Responsible Congress Ministers have stated that certain Members of the Opposition are negotiating to join the Congress and have also applied for being admitted to the Congress Party. Such statements are quite baseless. We, the Members of the Progressive Independent Party, have never thought of joining the Congress Party and have never entered into any negotiations with any Minister or any Congress Leader on the issue of joining the Congress Party. None of us have applied to anybody to admit any of us to the Congress Party."

इस पर मेरे दस्तखत हैं और तमाम मैम्बरान के दस्तखत हैं जो इस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं जैसे देवी लाल, बाबू बचन सिंह, पंडित मोहन लाल दत्त, श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री, पंडित चिरंजी लाल शर्मा, चौधरी इन्दर सिंह मलिक, श्री टेक राम, श्री जगन्नाथ। यह जो यहां बातें की जाती हैं यह नमूना है इन की पोलिटीकल कुरप्शन का।

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : इन्होंने जितने नाम लिए हैं, यह सब हमारे आदमी हैं।

चौधरी देवी लाल : मैं यह कहता हूं कि यह पोलिटीकल कुरप्शन है, हालांकि कांग्रेस का यह फैसला हुआ था कि उस वक्त तक किसी मैम्बर को शामिल नहीं किया जाएगा जब तक वह असैम्बली की सीट से इस्तीफा न दे दे।

उपाध्यक्षा : जिन्होंने उधर जाना है, वह जाते ही रहेंगे। (The people who are inclined to cross the floor would be doing so.)

Demands for Grants
i. 19-General Administration
ii. 23-Police
(Resumption of discussion)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਮੁਸੱਲਮਾ ਤੌਰ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ 64 ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 16-17 ਮੈਂਬਰਜ਼ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣਾਉ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈਡਿਆਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੱਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ———

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗਰੁਪ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹੋ . . . . . . (*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ । ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ—ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਗਲ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਥੇ ਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕੁਝ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਔਰ ਕੁਝ ਐਮ. ਪੀ. ਮੈਨੂੰ 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ? ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦ ਨਾਮ ਦਸਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਬੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੁਰਮ ਦੀ ਔਰ ਬਰਾਈਬਰੀ ਦੀ । ਹੁਣ ਵੀ ਡੁਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ । ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਨਾ ਉਛਾਲੋ, ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਜੇ ਕੋਈ ਗਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਬਦਅਨਵਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (We should decide this matter of levelling charges and counter-charges against each other if we are to establish good and healthy conventions in the House.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਇਸ ਡੀਬੇਟ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸੀਨੀਅਰਮੋਸਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਉ, ਤਾਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਰਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰਮੋਸਟ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਏਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

PERSONAL EXPLANATION BY THE EDUCATION AND LOCAL GOVERNMENT MINISTER

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री (श्री प्रबोध चन्द्र) : On a point of personal explanation, Madam मैं फिर कहता हूं कि काश वह मेरे हाथ आ सकते तो कभी भी वह निकल न सकते। वह 25 लाख की थैली नहीं ले कर आए थे। लेकिन उन्होंने तरीके तरीके से कहा कि आप ने नई नई हकूमत संभाली है, आप उसी तरीके को रहने दें, हम ने पहले 2 लाख दिया था चार लाख दिया था मगर अब 25 लाख देने को तैयार हैं। मगर मैं ने unilateral decision लिया जिस से 2 करोड़ 60 लाख का गवर्नमेंट को छः महीना में फायदा हुआ और अब पांच करोड़ रुपया बचा है। उन्होंने तरीक तरीके से कहा था कि हम 25 लाख रुपया देने के लिये तैयार हैं।

चौधरी देवी लाल : आप कह देते कि ले आओ।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री : मुझे यह डर था कि अगर वह लेकर आए हुए होते तो वह मुझे ही उलटा पकड़ लेते।

उपाध्यक्षा : जो ऐसे लोग हैं उन को जरूर एक्सपोज़ करना चाहिए ताकि कुरप्शन खत्म की जा सके। (Such people must be exposed so that corruption could be put to an end)

चौधरी नेत राम : On a point of order. डिप्टी स्पीकर साहिबा, शिक्षा मंत्री साहिब ने बयान दिया था कि मुझे कुछ लोग शराब के ठेके न कैंसल करने के लिये 25 लाख रुपया देते थे। उन को चाहिए कि वह ऐसे लोगों के नाम यहां बताएं। अगर वह नहीं बताते तो मैं समझता हूं कि वह रिशवत फैलाने वालों की हौसला अफज़ाई करते हैं।

Deputy Speaker: This is no point of order.

DEMANDS FOR GRANTS
(I) 19-GENERAL ADMINISTRATION
(23) 23-POLICE
(RESUMPTION OF DISCUSSION)

चौधरी रणबीर सिंह (कलानौर) : इस सदन के अन्दर कुछ मैम्बरों ने अपने आपसी इख्तलाफात का ज़िक्र किया है मैं उस को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता । लेकिन जो सरकार के खाते में आंकड़े छपे हैं, मैं उस की तरफ इस बहस को ले जाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्षा महोदया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर 1963-64 के हिसाब के खाते के मुताबिक 3,40,37,485 रुपया खर्च हुआ था जो रिवाइज़ड बजट एस्टीमेटस के मुताबिक 1964-65 में बढ़ कर 3,98,24,370 रुपए हो गया या होने का अन्दाज़ा है। इसी तरह से 1965-66 के लिये जो मांग रखी गई है वह 4,36,76,730 रुपए है। दूसरी मांग जो पुलिस के सिलसिले में रखी गई है उस पर 1963-64 में खाते के मुताबिक 10,10,26,466 रुपये खर्च हुआ था जो कि 1964-65 में रिवाइज़ड बजट एस्टीमेटस के मुताबिक 11,81,42,997 रुपए होगा । अब इस मांग पर खर्च करने के लिये जो पैसा मांगा गया है वह 12,51,97,320 रुपए है। आप जानती हैं कि यह दोनों महकमे कोई सेवा करने वाले महकमे नहीं हैं यह ऐसे दोनों महकमे हैं कि अगर निज़ाम अच्छा हो तो उस के ऊपर कम से कम खर्च हो। अगर कहीं कम्युनिज़म का नकशा देश में आ जाए तो शायद इन महकमों पर कुछ खर्च ही न हो और सतयुग या देवताओं के ज़माने में तो इन बातों पर कुछ होता ही नहीं था। अब भी हमारा इरादा है कि हम सतयुग ले आये और समाज को भलाई की तरफ ले जा रहे हैं और जब हम समाज को भलाई की तरफ ले जा रहे हैं तो इन मदों के ऊपर ज्यादा खर्च का होना हमारे प्रान्त के लिये शोभा की बात नहीं। इन के साथ साथ उपाध्यक्षा महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर कई दफा कई दोस्तों ने कई ढंग से कई बातें कहने की कोशिश की है। मैं उन सब की जानकारी के लिये एक ही निवेदन कहना चाहता हूं कि हमारे मन्त्रिमंडल ने जिस के अन्दर मैं भी वज़ीर रहा था, 1964-65 के हिसाब के खाते के मुताबिक 13 करोड़ 83 लाख रुपया बचा कर सरकारी बचत खाते में (Government Securities) में डाला था और दूसरे शब्दों में इस साल के हिसाब से पिछले साल 1963-64 के हिसाब का जो खाता था उस में सारे खर्चों को करने के बाद, जैसा कि मैंने निवेदन किया, 13 करोड़ 82 लाख रुपया बचाया था। अब की दफा जो खर्च हो रहा है 1964-65 के हिसाब के खाते के मुताबिक 20 लाख रुपया ही बचेगा और अगले साल वह करोड़ों रुपए के घाटे का बजट होगा जो कि आमदन खर्च 1965-66 में होगा। खैर इस वक्त मैं ज्यादा यह बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि इन बातों के कहने का सही वक्त या तो बजट की जनरल डिसकशन के वक्त होता है या फिर ऐप्रोप्रिएशन बिल की बहस के वक्त होता है। मैं चाहता हूं कि मैं सदन के सामने इस सारे आंकड़ों का हिसाब रखूं। मेरी अर्ज़ है कि मैं चाहता हूं कि ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के वक्त पर आप मुझे बोलने का मौका देंगी ताकि मैं इस प्रदेश के लोगों के सामने आप की मारफत आंकड़ों के ज़रिए खाते का हिसाब पेश कर सकूं, जो कहानियां हम रोज़ यहां करते हैं उन का कुछ अर्थ जम सके और लोग जिन्होंने हमारे प्रति न्याय करना है वह हमारे साथ न्याय कर सकें।

उपाध्यक्षा : वक्त तो हिसाब से ही मिलेगा। (There will be proportionate allotment of time.)

चौधरी रणबीर सिंह : हिसाब से बाहर मैं लेना भी नहीं चाहता । सब से पहले मैं इस बात की तरफ जाना चाहता हूं । उपाध्यक्षा महोदया, आप जानती हैं कि 26 जनवरी 1965 का दिन हिन्दुस्तान के अन्दर एक नया दिन था क्योंकि उस दिन हिन्दुस्तान के अन्दर जो हिन्दुस्तानी भाषाएं हैं और जिस जिस प्रदेश के अन्दर जो जो भाषा बोली जाती है उसके अन्दर ही सारा काम काज चालू हो जाना चाहिए था । हमारी जो विधान बनाने वाली सभा (Constituent Assembly) बैठी थी जिसका मैम्बर होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था ऐसा उसका फैसला था कि विधान के लागू होने के 15 साल बाद अंग्रेजी ने हिन्दुस्तान से चले जाना था । आप जानते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर जितने लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या अफसर हैं या इस सदन के मैम्बर हैं उन में कोई ऐसा नहीं है जो हिन्दी पंजाबी न समझ सकता हो तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिये कोई वजह नहीं है कि वह आज भी 26 जनवरी 1965 के बाद पंजाब सरकार का कार्यक्रम अंग्रेजी के अन्दर जारी रखे । अंग्रेजी को यहां से जरूर जाना है और यह कभी यहां पर कायम नहीं रह सकती । आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान के मुख्य मंत्रियों की एक सभा हुई और उस के अन्दर यह फैसला हुआ कि हिन्दुस्तान में जो हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश है और इलाके हैं वहां अंग्रेजी जारी रखने की कोई बात नहीं है । तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्होंने इस बारे में आर्डीनैंस जारी किया है उसके मुताबिक कानून बनाने की कोशिश न करे, उसे छोड़ दे, उस आर्डीनैंस को उस की अपनी मौत मरने दे, हमारे प्रदेश की जो हिन्दी पंजाबी भाषाएं हैं उन को पनपने दे और उन के अन्दर राज्य का काम काज चलने दे । इस के बाद उपाध्यक्षा महोदया, मैं आपकी मारफत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने अभी हिसाब बताया कि 1965-66 में जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्च 1964-65 के मुकाबले में बढ़ने जा रहा है उस की एक बड़ी भारी वजह यह भी है कि राज काज की मंज़िल में कड़ियां बहुत बढ़ती जाती हैं । मुझे मालूम है कि सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्ज़ कमीशन बैठाया है । शायद वह इस खर्च को और इन कड़ियों को घटा सके और शायद बनाया भी इसी मतलब के लिए है । यह जो इतनी कड़ियां छोटी से लेकर ऊपर बड़ी तक चल रही हैं उन का नतीजा यह भी होता है कि जब कोई गल्ती होती है तो कोई पकड़ में नहीं आता है सारा मामला इन कड़ियों में उलझ कर रह जाता है । नीचे की कड़ी वाले ऊपर वाली कड़ी से दस्तखत कराने की कोशिश करते हैं, उस से ऊपर वाली कड़ी वाले उस से ऊपर वाली कड़ी से और उस से ऊपर वाली कड़ी वाले अपने ऊपर की कड़ी से दस्तखत कराने की कोशिश करते हैं और इसी तरह यह सिल-सिले चलते चलते जब कैबिनेट के दस्तखत करा लेते हैं तो इस में वह समझते हैं कि उन की जान बख्शी हो गई । इस में समय ज्यादा लगता है और पैसा ज्यादा खर्च होता है । उस को हमें घटाना चाहिए ताकि काम भी ठीक चले और किसी पर जिम्मेदारी भी डाल सकें कि किसने कहां गलती की है । इस के लिए जरूरी होगा कि इन कड़ियों को घटाया जाए । इस सदन में बहुत सारे भाई जो इधर बैठे हैं और उधर भी बैठे हैं उन की यादाशत में ताजा करना चाहता हूं । 1941-42 का जमाना मुझे याद है जब हमारे मुख्य मंत्री और बाबू बचन सिंह जी जेल के अन्दर पुलिटिकल कैदियों में गांधीवाद का प्रचार करते थे और बताया करते थे कि हमारा गांधीवाद पर चलना जरूरी है, उस पर चल कर

[चौधरी रणबीर सिंह]

ही देश तरक्की कर सकता है। गांधीवाद की जेल में पहली बात हमें यह सिखाई जाती थी कि अंग्रेज़ साम्राज्य के खिलाफ हम प्रचार कर सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ हमें बुरा भला कहने को नहीं कहा जाता था और अंग्रेजी राज्य की कुरीतियों के खिलाफ प्रचार किया जाता था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमें यह शिक्षा देते थे कि हम अंग्रेज के खिलाफ हम कुछ न कहें। उपाध्यक्षा महोदया, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जिस मुख्य मंत्री से हम जेल में इस तरह का गांधीवाद का लैक्चर सुनते थे उस माननीय मुख्य मंत्री ने जिस वक्त काम सम्भाला तो यहां क्या हुआ। आप जानते हैं कि उनको काम संभालने का मौका भी बड़े आड़े वक्त मिला। इस प्रदेश के शासन के बारे में एक रिपोर्ट आई जिस का नाम दास कमीशन रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कुछ भाई पता नहीं क्या २ पढ़ते हैं मगर मैं ने तो उस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं देखी। इस में एक ही बात हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह के बारे में लिखी जो एक डाक्टर की बात थी। इस के बाद उन्होंने अस्तीफा दिया तो मन्जूर हुआ। उस के बाद नई वज़ारत आई और उस ने फिर राज्य का काम काज अपने हाथ में लिया।

वह वज़ारत उसी पार्टी की वज़ारत है जिस पार्टी के स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरों मुख्य मंत्री थे। मैं मानता हूं कि वह गांधी वादी असूलों पर चलने वाले थे और महात्मा गांधी के बताये हुए असूलों पर पिछले 15-16 सालों में किसी हद तक चलते रहे ताकि वह अच्छे साबित हो सकें। मैं चाहता हूं कि मैम्बरों को उनके कड़वे तजरुबे भी, यदि कोई उनके राज्य काल के बारे में हैं, तो उन बातों को भूल जाना चाहिये। जिस तरह अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेजों का राज्य खत्म होने के बाद हम ने उस वक्त के अफसरों की कुरीतियों को भुला दिया और भुलाने की कोशिश की। इस तरह से रजवाड़ेशाही के अन्दर जो कुरीतियां थीं, उन कुरीतियों को भुलाया और अच्छा इन्तजाम बनाने की कोशिश की। यहां पर दास कमिशन का जिक्र आया। मैं उस रिपोर्ट को मानता हूं। उस रिपोर्ट का हिन्दुस्तान के अन्दर की जितनी वज़ारतें हैं और खास कर पंजाब की वज़ारत के लिये सबक होना चाहिए और उस से हमें सबक सीखना चाहिये। यहां पर दो तीन दिन में जिस प्रकार के भाषण हुए हैं उस से दुख जरूर होता है। मैं किसी तरफ इशारा नहीं करता लेकिन एक बात जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 8 महीनों के इतिहास से पंजाब का सर ऊंचा नहीं होता है। पंजाब के राजनीति का सर ऊंचा नहीं होता। महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो रास्ता दिखाया, उस की तरफ आगे कदम नहीं बढ़े हैं। आठ महीनों के अन्दर पंजाब में क्या कुछ हुआ? मैं आप के द्वारा कुछ बातें सदन में रखना चाहता हूं। यह आप भी जानती हैं कि मंत्रीमंडल के त्याग-पत्र देने के बाद एक नहर के रैस्ट हाऊस से सरदार प्रताप सिंह कैरों को निकाल दिया था जब कि वहां पर हर एक एम. एल. ए. भी रह सकता है। यह महकमा पहले मेरे पास था और अब यह महकमा चौधरी रिज़क राम के पास है। इन को मेरी जगह इस मंत्री-मण्डल में सरदार प्रताप सिंह कैरों की सिफारिश से लिया गया था। मेरा नाम दास कमीशन की रिपोर्ट में कहीं भी नहीं आया। (विघ्न) 6-7 महीनों के अन्दर सब से

पहले सरदार प्रताप सिंह कैरों पर यह हमला होता है, वह कितना गिरा हुआ था। इस के बारे में सरकार की तरफ से कोई अफसोस का ब्यान नहीं निकलता है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आयी कि ऐसा व्यवहार वहां पर उन के साथ क्यों किया गया। सारे हिन्दुस्तान के समाचार-पत्रों में इस की चर्चा हुई लेकिन सरकार की तरफ से अफसोस का एक लफ्ज़ नहीं निकला। उस के बाद आगे उन के विरुद्ध क्या होता है? मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मंत्रि मंडल से त्यागपत्र देने के पश्चात् उन से मैम्बर-शिप से अस्तीफा तलब किया गया। अगर हमारी आल-इंडिया कांग्रेस के प्रधान श्री कामराज, उनका मैम्बरशिप का अस्तीफा मंजूर कर लेते तो वह शायद इस हाऊस के मैम्बर भी न रहते। वह इस सदन के मैम्बर 1937 से चले आ रहे थे और मृत्यू के समय तक इस हाऊस के मैम्बर रहे। उन से सदन से त्यागपत्र मांगने की कोशिश की। लेकिन मैं हाऊस को बतलाना चाहता हूं कि जब उन्होंने मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दिया तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे से और कोई कुरबानी चाहते हो तो वह भी मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कांग्रेस के प्रधान ने उन से मंत्रिमंडल का ही अस्तीफा मांगा। मैं हाऊस को बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने मंत्रीमंडल से अस्तीफा कांग्रेस हाई कमांड की सलाह देने से पहले किया था और वह अधिक कुरबानी करने के लिये भी तैयार थे। यह सत्य बात है। लेकिन उन के बाद उनके साथ और उनके खानदान के साथ क्या सलूक किया जाता है, वह सब को मालूम है। उस व्यक्ति ने इस पंजाब को हर प्रकार से विकसित करने के लिये 14 वर्ष कठोर परिश्रम किया और पार्टी के नेता के रूप में काम किया। हम सब उन के पीछे चले। मैं मान सकता हूं कि विरोधी दलों (आपोज़ीशन) में बैठने वाले उन की निन्दा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने मजबूती से हकूमत की। आप भी जानती हैं कि उन्होंने पंजाब को ऊपर उठाने के लिये 14 साल तक काम किया। आप को मालूम है कि वह यहां पर साढ़े आठ साल तक मुख्य मन्त्री रहे और हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री उसी की वज़ारत में 10 महीने 1957 में उप-मन्त्री रहे और 10 महीने 1962 में मन्त्री रहे। इसी तरह से माननीय गृह मन्त्री उनके मंत्रिमन्डल में 10 महीने 1957 में और सवा दो साल 1962 से 1964 तक मन्त्री रहे। हमारे वर्तमान शिक्षा मन्त्री भी उन के मंत्रिमंडल में 10 महीने 1957 में मन्त्री रहे। उनका गला उन की बुराई करते हुए खुशक नहीं होता है। उनको ऐसी बातें करते दुख नहीं आता। मैं भी सरदार प्रताप सिंह कैरों के साथ सवा दो साल मन्त्री रहा। मुझे उन के साथ काम करने का फखर है। अगर इस बात पर मुझे सजा देना चाहते हो मैं लेने के लिये तैयार हूं (विघ्न) (आपोज़ीशन की तरफ से आवाज़: मैं जाट के कैरैक्टर की दाद देता हूं।) मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उस के बाद सदन में सवाल पूछा गया तो उस का जवाब आया था कि कैरों फैमिली के खिलाफ 19 मकद्दमे हैं और केस चलते हैं। (विघ्न) मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि सरदार प्रताप सिंह कैरों के नाम पर एक स्टेडियम बना जिस की नींव (फाऊंडेशन स्टोन) स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रखी थी। उस वक्त सरदार प्रताप सिंह कैरों ने कहा था कि इस स्टेडियम का नाम प्रताप सिंह स्टेडियम रखा जाये ताकि महाराना प्रताप का नाम जीवित रह सके और उसकी याद ताज़ा हो सके। लेकिन इस बात को

[चौधरी रण बीर सिंह]

जनता ने नहीं माना। इस बिना पर सरदार प्रताप सिंह कैरों के नाम पर वह स्टेडियम बनाया गया। लोगों ने ज़मीन दी। वह रुपया जनता ने इकटठा किया और वहां पेर पंचायतों ने खर्च किया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि जब जनता आप के नाम पर स्टेडियम रखना चाहती है तो आपको क्या एतराज है। इस तरह से उसका नाम रखा गया। लेकिन जनता से इस बारे में कुछ नहीं पूछा गया और शिक्षा मंत्री महोदय ने किसी से पूछे बगैर वहां से उन के नाम का फटा उठा दिया। इतना ही नहीं, उनके चित्र किताबों से निकाले गये। उपाध्यक्षा महोदया, 6 फरवरी, 1965 का वाक्या है। यह हत्या कैसे हुई यह तो सब को पता है क्यों हुई? इस का पता किसी को नहीं है। अगर इस केस का पता चलेगा तभी भगवान की दया होगी। लेकिन कुछ कक्यात मेरे सामने हैं। वह वाकिया मेरे ज़िले में हुआ। मैं रोहतक में मौजूद था। वहां पर एस.पी. साहिब को 2 बजकर 15 मिनट पर कतल का पता लगता है और मुझे दो बजकर 20 मिनट में पता लगता है। उस वक्त ज़िला परिषद् की एक उप-समिति की मीटिंग थी। मैं चहाता था कि क्योंकि वह हत्या हमारे ज़िले के अन्दर हुई, इस लिये वहां पर अफसोस का प्रस्ताव पास करके मीटिंग उठ जाये और एडजर्न करदी जाये। उपाध्यक्षा महोदया, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि वहां जो सभापति था वह सरकारी अफसर था. उस ने कहा कि मीटिंग में अफसोस का प्रस्ताव तो पास किया जा सकता है लेकिन मीटिंग एडजर्न नहीं हो सकती है। वहां पर प्रस्ताव पास किया गया और उसके बाद में मैं तो चला आया लेकिन मानयोग सदस्य पंडित चिरंजी लाल जी शर्मा के कहने पर फिर मीटिंग बाद में एडजर्न कर दी थी। मेरे कहने पर नहीं की गई। जब मैं वज़ीर था उस समय वह अफसर मेरे सामने घंटों खड़े रहते थे। शायद उनका नुकता निगाह बदल गया हो। पंडित चिरंजी लाल ने मीटिंग एडजर्न करवा दी लेकिन मैं न करवा सका। पंडित जी ने जो पुरजोर वकालत की है उस के लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद पब्लिक मीटिंग हो रही थी..... (घंटी की आवाज) उपाध्यक्षा महोदय, बड़े काम की बात है मुझे दो चार मिनट और दे दीजिये। वहां हमारे एक मंत्री महोदय मौजूद थे। मुझे मालूम नहीं कि सरकारी तौर पर उन मन्त्री महोदय को किसी ने बताया या नहीं बताया लेकिन मैं चौधरी मुख्तियार सिंह एम. एल. ए. की मार्फत उन के पास खबर भेजी कि एस. पी. ने कहा है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों की हत्या हो गई है। मैं ने यह निवेदन किया। इन्होंने बताया यह नहीं माने और मीटिंग डेढ़ घंटा चलती रही। उस मीटिंग के अंदर शोक का प्रस्ताव भी पास नहीं हुआ। वह मन्त्री कौन से थे? वह मन्त्री थे जिन के गांव से डेढ़ मील के फासले पर सरदार प्रताप सिंह कैरों, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री की हत्या हुई थी। क्यों ऐसा हुआ? उसका एक ही कारण मुझे लगता है। बहुत से लोगों को यह डर था कि अगर कहीं सही कार्यवाही करेंगे तो शायद हमारा ओहदा चला जायेगा, नौकरी चली जायेगी और शायद वज़ारत से ही हाथ धोने पड़ें (विघ्न) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह बात गांधी जी ने नहीं सिखाई थी। बाबू बचन सिंह हमें गांधी वाद का सबक सिखाया

करते थे। उनकी शिक्षा यह थी कि जो दोषी है उसके खिलाफ मत लड़ो, दोष के खिलाफ लड़ो। सरदार प्रताप सिंह के जमाने में जो हकूमत चली वह अच्छी थी या बुरी थी उस में सरदार प्रताप सिंह की बुराई नहीं करनी चाहिये यह बात महात्मा गांधी ने सिखाई थी। इस देश के आजाद होने के बाद 1948 में महात्मा गांधी जी की गुण वायुमंडल के कारण हुई और उस बलीदान की वजह से देश में से फिरकाप्रस्ती और घृणा खत्म हुई इस को हुए 17 साल हो गए हैं यहां पर कांग्रेस की सरकार शान्ति से चलती रही और देश ने तरक्की की लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि महात्मा जी की शिक्षा का इस आठ महीनों की सरकार पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। मौजूदा सरकार आठ महीने भी नहीं चली लेकिन नतीजा यह निकला कि किसी नालाइक भाई ने, किसी भी भाई ने हौसला किया कि सरदार प्रताप सिंह पर हाथ उठाए। इस के इलावा मुझे आप के द्वारा होम मिनिस्टर साहिब से यह निवेदन करना है कि इन के हाथ में शक्ति है अगर इन को राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की शिक्षा का कुछ भी ख्याल है तो उन की कुछ चीजें करनी होंगी। बल्कि जो कुछ हुआ है उसका अफसोस भी करना होगा। पहले तो यह कि सरदार प्रताप सिंह के नाम का फट्टा सरदार प्रताप सिंह के स्टेडियम के सामने लगना चाहिये। और सरदार दरबारा सिंह की मजबूती इसी में है कि कल शाम तक फट्टा लग जाये जिस तरह से मानयोग शिक्षा मंत्री ने कहा था कि कल शाम तक हट जायेगा इसी तरह से इन को कहना चाहिये कि कल शाम तक लग जायेगा। इस के साथ ही मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे दुख है कि उन के बच्चों के खिलाफ जितने मुकद्दमे चल रहे हैं चाहे उन्होंने अपनी दौलत को सही तौर पर या गलत तौर पर कमाया था अभी तक तो गलत तौर पर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन इल्जामात को अभी तक साबित नहीं किया जा सका, उन को वापस लिया जाये क्योंकि उन्होंने जो कुछ कमाया था वह उन्होंने सरकार के हवाले कर दिया है। पहले ही कोई वजह नहीं थी लेकिन आज तो कोई वजह ही नहीं है कि उन के खिलाफ मुकद्दमा चलाया जाये। होम मिनिस्टर साहिब का अपना महकमा है इन को सारे मुकद्दमे वापस लेने चाहियें। उन के चित्र जहां से हटाए गए हैं उन को वहां पर लगाया जाये, इस लिये लगाया जाए क्योंकि हम ने देश के अन्दर नैशनल इंटैग्रेशन करनी है कौमी एकता के भाव पैदा करने हैं

(माननीय सदस्य और बोलना चाहते थे लेकिन उपाध्यक्षा ने सरदार हरचंद सिंह का नाम ले दिया।)

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ : On a point of order, Madam. ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ..

उपाध्यक्षा : मेरे पास जिन के नाम भेजे गए हैं मैं उन को बुला रही हूं। (I am giving opportunity to the Members to speak according to the names sent to the Chair.)

(श्री रूप लाल मेहता भी बोलने के लिय बहुत उत्सुक थे।)

[ਉਪਾਧਿਅਕਸ਼ਾ]

महता जी आप बैठिये, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आप का नाम आता है तो सीट पर नहीं होते । (I would request Shri Mehta to take his seat. I am constrained to remark that he is not found in his seat on his turn.)

श्री रूप लाल महता : मैं दो मिनट के लिय बाहिर गया था ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ (ਸਮਾਣਾ ਐਸ.ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗਲਾਂ ਵਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । 17 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦ੍ਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਭੱਠ ਹੀ ਝੋਂਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਟੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦੱਸਾਂ । ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ । ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹੇ । ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਗਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਇਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਚਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ (ਤਾਲੀਆਂ) ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਥੋਂ ਦੋ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਬੈਠੇ, ਦੋ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਬਨ੍ਹੇ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਇਥੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਰਜਰ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਕ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕੈਬਿਨਿਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ । (ਵਿਘਨ) ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲ ਤਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ

5.00 p. m.

ਅਹਿਲਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਸ਼ਮਾਲੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ । ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟਿਆਂ ਨਾਲ ਐਫਿਲੀਏਟਿਡ ਸੀ। ਸਨ 1935 ਤਕ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਂਸਤਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤਕ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿਠੱਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ

ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਉ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਚਲੇ ਜਾਉ, ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਵਸਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਪੋ ਅਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰੀਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਵੀ 40 ਲਖ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ 40 ਲਖ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ 3 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 14 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲਖ ਟੈਂਮਪਰੇਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ 1 ਕਰੋੜ 14 ਲਖ ਪਾਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਢੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਰੀਜਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਜਨਾ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੇਪਨਾਹ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰ ਲਉ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਵਿਚ 20 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ? 20 ਲਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 9 ਲਖ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਏ ਬਾਕੀ 11 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 11 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੂਦ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 9 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਥੇ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਇਸਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਹਾਸਾ) ਪਰ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ?

ਇਕ ਅਵਾਜ਼ : ਓਵਰ ਡਿਊ ਹੈ (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਜਾਬਤਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਅਲੁੱਕ ਹੈ ਇਕ ਮਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ 150 ਰੁਪੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟੈਨੋ ਸੀ ਅਜ 15 ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਨਾਸ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਨਤਾ ਦਾ 20 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਲੁਟਾ ਦਿਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲਗਾਉ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਉਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ]

ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਚੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚਮੜੇ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਟ ਦੇਣ।

ਕੁਝ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦਿਉ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ: ਉਸ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਫਲੈਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜ ਦਿਓ (ਹਾਸਾ) ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਫਲੈਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਟੈਨੋ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ 1,500 ਨਹੀਂ 2000 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ)? ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਰੀਜਨਾ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ 80 ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਨਾਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਲੋਂ ਨਾਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਆਏ। ਕੋਈ ਡੀ. ਸੀ. ਕੋਈ ਐਸ. ਪੀ. ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਘੰਟੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ (ਕਰਨਾਲ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜੈਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਉਤੇ ਅਜ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਪੜਾ, ਮਾਸਕਿਟੋ ਨਟ, ਟਰਬਨ ਕਲਾਥ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ 12 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਬੰਗਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ 12 ਲਖ ਦੀ ਬੰਗਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਜ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਗਲਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਬ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਨ—

(1) ਕੈਰੋਂ ਫੈਮਿਲੀ।

(2) ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਫੈਮਿਲੀ।

(3) ਮਿਸਟਰ ਬੀ. ਆਰ. ਕਪੂਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼।

(4) ਮੈਸਰਜ਼ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਤੀਰਥ ਰਾਮ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਰੁਪਿਆ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ

ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਬਕਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਿਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸਨਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਕ 12 ਲਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਇੰਕੁਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਟੋਰਜ਼ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਉਥੇ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ਟੈਮਪਰ ਵਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਵੇ ਨੀਲਮ ਸਿਨਮੇ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ Chief Minister wants to see the file unless officialy. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਣ ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿਚ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 12 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੰਗਲਿੰਗ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਫੀਸੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਫੀਸੈਂਟ ਬਨਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਪਰੋਪੋਜ਼ਲਜ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪਾਸ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ—

1. By saving in administration,
2. By awarding wasteful expenditure,
3. By plugging leakage in revenue,
4. By heavy taxation.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 7 ਫਰਵਰੀ 1963 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਤੰਬਰ, 1964 ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੋਪੋਜ਼ਲਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਸਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,

"The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained."

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੋਪੋਜ਼ਲਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੇਰੀ ਚਿਠੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

[ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ]

ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਰੈਵੇਨੀਓ ਤੇ ਕਨਟਰੋਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਪਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ । ਕਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਡੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨ-ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਔਰ ਲੈਕ ਆਫ ਕਨਟਰੋਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।

ਫਿਰ ਕਈ ਅਫਸਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਨਾਲਿਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਮ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਇਮ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੀਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਫੌਰਨ ਐਕਨਾਲਜ ਕਰਨ ।

ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਮਹਿਰੂਮ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਇਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਅਨ ਟਰੇਸਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ these should be declared un-traced ਫਾਈਲ ਕਰਾ ਦਿਤੇ ਸੀ । ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗ ਭਗ 75 ਜਾ 80 ਕੇਸ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਨਟਰੇਸਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਐਸੋ-ਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਵਾਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਟਰੇਸਡ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਹਾਸਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੁੱਰਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ । ਜੇ ਇਹ ਜੱਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ।

ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦੋ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ

ਕਿ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਆਈ. ਜਸੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਚਿਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਫਲਾਨੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਜਾਂ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸ. ਪੀ. ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਐਸ. ਪੀ. ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਬਗਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਐਸ. ਪੀ. ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਐਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੂਆ ਖੇਲਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਦੇ ਥਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਕੜਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ. ਜੀ. ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਕਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਰੰਨਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮਾ ਕਿਰਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਟੋਕਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦਸਣ ਤਾਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕੂਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਡੀਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੰਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੁਪਟੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਕੁਰਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

"It is not in public interest to disclose the contents"

ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਸੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਇਨਟਰੈਸਟ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇਨਟਰੈਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਜਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਰੀਵਾਲਵਰਾਂ ਔਰ ਪਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਜ਼ਲੀਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਹਨ

[ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ]

ਜਿਹੜੇ ਬਡ ਕਰਕਟਰ ਹਨ, ਅਨਡੀਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਟਿਸੀਡੈਨਟਸ ਬੁਰੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਕਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗੌਰੰਮਿੰਟ ਤਕੜੀ ਬਨ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਅਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ 29 ਮਈ, 1964 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਮਤੀ ਦਾ ਜਲਸਾ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸਕੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ., ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਰੇਂਜ ਦਾ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਤਫਾਕੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਰਨਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਥੇ ਉਸ ਰਾਤ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਥੇ ਸਾਬਕਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚਿਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

गृह तथा विकास मन्त्री (सरदार दरबारा सिंह): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा इस वक्त बोलने का इरादा नहीं था क्योंकि यही ख्याल था इस का जवाब चीफ मिनिस्टर साहिब ही देंगे। मगर चूंकि कुछ दोस्तों न कुछ बातें उठाई हैं इस लिय उस के बारे में मुझे कुछ कहना होगा। कुछ साहिबान इस तरह से बोले हैं जिस तरह से कि उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। जहां तक पार्टी की बातों का ताल्लुक है उस के मुताल्लिक सारी बातें पार्टी की मीटिंग में ही कही जानी चाहिएं, यहां नहीं । (तालियां) ऐसी बातों को यहां पर लाने की जरूरत नहीं है । और फिर अगर कुछ कहना ही हो तो निहायत मंजी हुई शायस्ता ज़बान में कहनी चाहिएं। अगर ऐसा न किया जाए तो लाजमन इस हाउस की डिगनिटी पर बुरा असर पड़ता है। यह जो हाउस है यहां से बहुत अच्छी बातें निकलती हैं और निकलनी चाहिएं क्योंकि यह हाउस सारे पंजाब का मालिक है, उस की किस्मत का मालिक है।. अगर हम इस में बैठकर लड़ते हैं तो उस से कोई अच्छी बात नहीं निकलती। नतीजा यह होता है कि हमारी बाहिर दुर्दशा होती है, लोग बातें बनाते हैं इस का मियार नीचा जाता है, इस बात को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए।

पुलिस के बारे में कुछ कहा गया। एक दो बातें चौधरी रणबीर सिंह जी न उठाई और भी दोस्तों ने उठाई। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता मगर यह देखने की बात है कि हमारी यह जो डैमोक्रेसी है इस में हमारा जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है यह मज़बूत हो और जहां पर ढील हो उस को दरूस्त किया जाए। मगर इस सब के लिए रुपया दरकार है। आप जानते हैं कि हमारी पी. ए. पी. कितना अच्छा काम कर रही है, जम्मू और काश्मीर पर उस का काम काबिले तहसीन काम है जिस की वजह से हम पंजाबी अपना सिर

ऊंचा कर चल सकते हैं। उन के उस काम की सतायश हिन्द सरकार ने भी की है। मगर यह सब कुछ डैमोक्रेसी का हिस्सा है। हमें इस में जहां कहीं भी ढील नज़र आए उस को दूर करना है। आप की तरफ से जितनी कान्सट्रक्टिव सजैस्टज़ आएंगी उन को यह सरकार अपने सामने रखेगी और जहां कोई कमी नज़र आयेगी, उस को दूर किया जाएगा। [Mr. Speaker occupied the chair.]

पुलिस के बारे में कहा गया कि इस पर खर्च ज्यादा है। फिर यह भी सवाल उठाया गया कि पुलिस कमिशन की सिफारशें क्या हैं, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन के लिये पूरे ज़राए सरकार के पास नहीं होते। हम चाहते हैं कि हर पुलिस स्टेशन में एक जीप होनी चाहिए ताकि फौरी तौर पर कार्यवाही की जा सके। अगर कहीं किसी किस्म की खराबी का एहतमाल हो तो उस का तदारक किया जा सके। फिर सिपाहियों की भी ज़रूरत है, अफसरों की ज़रूरत है, उन की तादाद बढ़नी चाहिए जैसे कि कमिशन ने सिफारिश की है। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि यह लम्बा चौड़ा मसला है मगर हमारी यह कोशिश रहेगी कि हर हालत में जरायम की तादाद को कम से कम किया जाए। इस बारे में अर्ज़ है कि 1964 में 45 स्मगलज़ मारे गए और ५५५ पकड़े गए और नौ लाख से ज्यादा का ज़र सोना अफीम वगैरह उन से पकड़ा गया। हम पूरी कार्यवाही करते हैं और चाहते हैं और भी सख्त कार्यवाही हो ताकि इस किस्म के जुर्म को बिल्कुल ही खत्म किया जा सके। पुलिस के बारे में मैं आप को बताऊं कि टोकियो में जो गेम्ज़ उन में जो हिन्दोस्तान की हाकी में जीत हुई तो वह ज्यादातर पंजाब पुलिस के जवानों की वजह से हुई (तालियां) मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता और मौका मिलेगा तो फिर अर्ज़ करूंगा। इस वक्त सिर्फ एक बात का ही और ज़िक्र करना चाहता हूं।

स्पीकर साहिब, यहां पर सरदार प्रताप सिंह के कत्ल की बात उठाई गई। हमें बड़ा दुख है और अब मेरे से पूछा गया तो मैं ने कहा कि हम अभी इस दुख से बाहिर नहीं निकल सके। हमें शर्म आती है कि ऐसा वाका हुआ है और इस का अब तक पता चल जाना चाहिए था मगर यह बदकिस्मती है कि बावजूद पूरी कोशिश के अभी तक उन को पकड़ा नहीं जा सका। क्लूज़ मिल रहे रहे हैं और हो सकता है कि कुछ दिनों में हम आप को बता सकें मगर फिलहाल हम उंगली नहीं कर सकते कि यह कलपरिट है। मैं अर्ज़ करूं कि हमारे सरदार प्रताप सिंह से ताल्लुकात रहे हैं और इस हाउस में अगर ताल्लुकात रहे हैं तो मेरे रहे हैं मगर पुलीटीकल तौर पर इख्तलाफ होते हैं मगर जिसमानी तौर पर नहीं होते। (तालियां) सरदार प्रताप सिंह यहां से जिस हालत में गए उस का हमें दुख है। उस दास कमिशन के फैसले के बाद हाई कमांड के फैसले पर चीफ मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ी। बहुत सी बातें कही गई कि फलां जगह के अन्दर उन को जाने नहीं दिया गया। जहां तक मुझे वाकफियत है रैस्ट हाउस में वह खुद ही नहीं गए कोई उन को बाहिर निकालने की जुरत नहीं कर सकता था, वह एम. एल. ए. तो थे ही। तो एसी बातें नहीं आनी चाहिएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो वाका हुआ है इस का हमें निहायत रंज है और मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि इस का सुराग नहीं निकलता। (तालियां) मैं आज बहुत दिनों के बाद बोला हूं और आप यकीन जानें कि जब तक यह केस नहीं निकलेगा यह बात दिमाग से बाहिर नहीं निकलेगी। हमारी यह बड़ी खुशकिस्मती होगी कि हम इस को निकाल सकें। इस बारे में आप साहिबान से एक अपील करता हूं कि यहां पर या बाहर ऐसे बयानात न दें जिन से इस केस की इनवैस्टीगेशन में रुकावट पड़ती हो। अगर आप

[गृह तथा विकास मन्त्री]
को कोई बात पूछनी हो तो आप मेरे से पूछ लें कि क्या हुआ है, हम बता देंगे मगर अखबारों तक न जाइये इस से क्लूज़ भागती हैं। आप में से जो साहिबान वकुला हैं वह जानते हैं कि जब मुतज़ाद बयानात दिये जाते हैं तो केस खराब होता है, मुखालफित बढ़ती है, चशमदीद गवाह खराब होते हैं। इस लिये दरखास्त है कि दीदा दानिसता ऐसी स्टेटमैंटस न दें। इस वक्त अगर पूछें तो हम किसी पर उगली नहीं रख सकते और यह ऐसी ही रहेगी जब तक कि इनवैस्टीगेशन पूरी नहीं हो जाती।

स्पीकर साहिब, आपने पढ़ा होगा कि जो सैंटर के होम मिनिस्टर श्री नन्दा जी ने बहुत लम्बा चौड़ा बताया था कि हमने कितने आदमियों के हाथों में इस केस की इन्वेस्टीगेशन को दे रखा है। हमें जहां भी कोइ क्लू मिलता है हम पुलिस को पास आन कर देते हैं जो कोई भी वाकफियत मिलती है सब पुलिस को पास आन कर देते हैं। हम लोगों की बातों से नहीं डरते। कल ही मेरे पास एक चिट्ठी आई है कि आप का हाल भी सरदार प्रताप सिंह कैरों जैसा होगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं लेकिन इस बात की ज़रूर है कि हम इस शर्म से निकल सकें। हमें इस बात का दुःख है कि अभी तक सुराग नहीं निकाला जा सका। जिस तरह की लम्बी चौड़ी इन्वेस्टीगेशन शुरू की गई है आज तक पंजाब की हिस्टरी में नहीं की गई थी। हर रोज़ चीफ मिनिस्टर साहिब और मैं टैलिफोन पर पता करते हैं और फिर आप भाग भाग कर जाते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि हमें किसी पर ऊंगली रखन का मौका है या नहीं। मैं यह बात कह सकता हूं कि हम इस केस का पता लगा लेंगे। (प्रशंसा) स्पीकर साहिब, जितने भी आदमी सरकारी बैंचों पर बैठे हैं खा वह वजीर हैं हरेक का काम यह है कि इस बात की देख भाल करे और जो भी कोई क्लू मिले उसे पुलिस के सपुर्द किया जाए। चीफ मिनिस्टर साहिब ने हाउस को बताया था कि हमारे पास वेलयूएबल इनफार्मेशन पहुंची है और इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यह सवाल नहीं कि केस निकलता है कि नहीं बल्कि सवाल इस बात का है कि फौरी तौर पर इस केस का पता लगे। निकलेगा तो जरूर लेकिन हम जल्दी से जल्दी इस का सुराग लगाना चाहते हैं ताकि इस हाऊस की सैटिसफैक्शन हो सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरदार प्रताप सिंह से हमारी कोई अदावत नहीं थी और उस की फैमली को उसी दिन से चीफ मिनिस्टर साहिब ने प्रोटैक्शन का इन्तजाम कर दिया। मैं उस वक्त कादियां में था और एक मीटिंग को एड्रैस करना था लेकिन मैं एक लफज तक न बोल सका और वह मीटिंग सोग में बदल गइ। लीडर बहुत मुश्किल से बनता है और इस बात को सालहा साल लग जाते हैं लेकिन खत्म फौरन हो जाते हैं। मेरी उन से कोई दुशमनी नहीं थी और न अब है। मेरी उनसे दोस्ती थी और मैंने उन के या उन के घर के खिलाफ कोइ लफज तक नहीं कहा। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि अगर कोई आज आफिस में नहीं तो उसकी बदखोई शुरू कर दूं। लोग ऐसे लोगों की बुराई करते हैं जिन

के हाथ में ताक़त न रहे । मुखालिफित करते हैं लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूं । (प्रशंसा) न कोई बात उनके खिलाफ कही थी न कहता हूं और न कहूंगा । मैं तो इस बात के लिए और भी शरमिन्दा हूं कि दोस्त होने के नाते इस का सुराग जल्दी निकाल सकूं । मुझे इस के बारे में कुछ और कहना सरोकार नहीं । ऐडमिनिस्टेटर होने के नाते यह फर्ज बनता है कि कातिलों का जल्द से जल्द पता लगाएं । इस के बारे में आप चिन्ता न करें ।

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वायंट आफ इन्फारमेशन । होम मिनिस्टर साहिब ने पुलिस कमिशन का जिक्र करते यह कहा है कि पुलिस कमिशन की रिपोर्ट हम छाप नहीं सकते ।

Minister for Home and Development : Mr. Speaker, Sir, I have only said that we have not made the recommendations of the Police Commission public becuase of financial implications.

बाबू बचन सिंह : आप ने कहा है कि अभी तक इस को हाऊस के सामने नहीं ला सकते क्योंकि इस में फिनांशल इम्पलीकेशन्ज की बात है । लेकिन इस के साथ ही इन्होंने यह कहा है कि हर थाने में एक जीप होनी चाहिए । तो इस के बारे में अगर सारे सूबे के थाने में नहीं तो जिन इलाकों में हालत खराब हैं जिस तरह भटिण्डा में क्या ऐसी जगहों पे जीप स्पलाई करने को होम मिनिस्टर साहिब तैयार हैं ? जिस तरह एग्रीक्लचर के लिए पैकेज प्रोग्राम बना हुआ है इसी तरह क्या कुछ जिलों में स तरह का इन्तजाम किया जा सकता है या नहीं ?

गृह मन्त्री : इस के बारे में चीफ मिनिस्टर साहिब स्टेटमेंट करेंगे तो सारी बात आप के सामने रखेंगे ।

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) स्पीकर साहिब, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की डिमांडों पर जो बहस दो दिन से चल रही है इस में 15 भाईयों ने हिस्सा लिया है । मुझे इस बात का दुःख है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने और बेहतर बनाने के लिए सुझाव नहीं दिए गए । बहुत से मैम्बरों नें जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर डिस्कशन करते हुए परसनल रेंगलिंग के तौर पर इस को अखाड़ा बना लिया है और इस हाउस को इस्तेमाल किया है । मुझे बतौर इस हाऊस के लीडर होने के और इस हाऊस का मैम्बर होने के अजहद दुःख है । मैं यह समझता हूं कि पंजाब की असैम्बली की डिगनिटी और शोहरत सारे हिन्दुस्तान में मशहूर थी । जिन भाइयों ने इलजामात उठाए हैं बेहतर होता अगर यह बातें हाऊस में न उठा कर पार्टी में उठाई जातीं । लेकिन खैर । बतौर मैम्बर असैंम्बली के उन को हक था इस तरह कहने का । मैं, स्पीकर साहिब, बतौर लीडर आफ दी हाउस के, बतौर चीफ मिनिस्टर के और बतौर इस पंजाब क अदना सेवक के इन भाइयों से कहूंगा कि जो इल्जामात उन्होंने, इन्होंने लगाए हैं वह सारे स्पेसेफिक एलीगेशन्ज मुझे लिख कर दे दें । मैं बतौर चीफ मिनिस्टर के अपना फर्ज समझता हूं कि उनको देख and I shall look into it (प्रशंसा)

[मुख्य मन्त्री]

दूसरी बात जो मैंने सुबह भी आप से, स्पीकर साहिब, की है आप की मारफत इस हाऊस के मैम्बरों से भी कहना चाहता हूं कि खाह कोई मेम्बर ट्रेजयरी बैंचों पर हो या आपोजीशन में, उन्हें अपने जाती इख्तलाफात और जाती झगड़ों के इस असेंबली में किसी भी शकल में नहीं लाना चाहिए। हमारा यहां पर कहा गया एक एक लफ्ज पंजाब की फिजा को बेहतर भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इस हाउस में सब मैम्बर बड़े तजरबाकार हैं और एक्सपीरिन्सड हैं और पालियामेंटरियन हैं और इन्हें आपने वतन का और अपने राज का दर्द है। इस लिए मैं आशा रखता हूं कि हम आगे के लिए इस तरह की कन्वेन्शनज और ट्रडिशनज कायम करेंगे कि जिस से पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके, पंजाब आर्थिक तौर पर मजबूत बन सके। इन बातों की तरफ ध्यान देने से पंजाब उज्जवल बन सकता है। हरेक भाई में सहनशीलता होनी चाहिए और अगर किसी गलती या कमजोरी की तरफ तवज्जो दिलाई जाए तो ऐसी बातों को बरदाश्त करना चाहिए।

मैं हाउस को यकीन दिलाता हूं कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्टिव स्कीमज हमें देंगें तो हम उनका स्वागत करेंगे। मैंने तो आफिस में यह हिदायात भी कर दी है कि बजट डिमांड के अन्दर जो भी भाई और बहन तकरीरें करते रहे हैं जिस जिस ने भी जो जो बातें अपनी अपनी कान्स्टीचुएंसी के मुताल्लिक की हैं, यह यहीं पर खत्म न समझी जाएं बल्कि इस के बाद हमारा फर्ज बन गया है कि हम एक एक भाई की गरीवेंसिज को सुनें और उन पर गौर करते हुए उन को रफा करने की कोशिश करेंगे। (तालियां) मैं कोई एक ग्रुप से तनखाह नहीं लेता। मेरा फर्ज तो आपकी और सारे पंजाब की सेवा करने का है। जैसे आप अपनी अपनी कांस्टीचुएंसी के एक एक मैम्बर को जवाब देते है, इस तरह से कुछ हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि हम आपके हलकों की गरीवांसिज सुनें और उनको रफा करने की कोशिश करें। इस लिए मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि जो जो भी गरीबेंसिज आप ने अपने अपने हलके मुताल्लिक जाहिर की हैं इन पर बजट शैशन के फौरन बाद ही गौर किया जाएगा, आप इतमीनान रखें। कुछ सवालात सरदार गुरनाम सिंह जी ने अपनी तकरीर में उठाए कि चन्द मैम्बरान ने यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में कुरप्शन और इंटरफियरेंस का जिकर करते हुए एक दूसरे पर एलीगेशनज लगाए। मैं इस बात का, स्पीकर साहिब, हाउस को यकीन दिलाता हूं कि जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है यह सरकार सैकुलरिइजम और डैमोक्रेटिक सैकुलरिइज्म पर बनी है। कोई कम्यूनल बाडी की नहीं जो इस तरह की बात में उलझ कर रह जाएगी। हम ने इस आजादी की जंग में मतवातर 30—40 साल इसी बात पर स्टरैस किया है कि हम हिन्दुस्तान के लिए एक सैक्यूलर किसम का निजाम चाहते हैं कोई कम्यूनल हकूमत नहीं और नतीजा के तौर पर आज हम इस मुल्क के लिए एक ऐसा कान्स्टीच्यूशन हासिल कर पाये हैं कि जो न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि आज सारे संसार में माना जाता है। जो बहतरीन किसम का कान्स्टीच्यूशन कहा जा सके वह आज इस मुल्क के लिए हैं। इसी के मुताबिक ही हम यह राज प्रबन्ध पूरी तरह से चला रहे हैं। अगर किसी

तरह स हम से गलती होती है, हम कोई एसी गलती करते हैं जो इस कान्स्टीच्यूशन क मनशे के खिलाफ है तो यकीनन आप को हक है कि आप इस तरफ हमारी तवज्जुह दिलाएं, हम जरूर गौर करेंगे । अगर किसी अफसर के साथ हमारी तरफ से किसी तरह की भी बेइनसाफी होती है तो आप हमारे नोटिस में लायें । हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम उस को रफा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे । यह अकेले मुख्य मन्त्री का राज्य नहीं है, सैंटर का राज्य नहीं है, यह हम सब का सांझा राज्य है जिस को चलाने के लिए हम सब को कोशिश करनी चाहिए । मेरा और मेरे साथियों का यह फर्ज है कि हम किसी तरह भी कोई ऐसी बात न होने दें जो हमारे कान्स्टीच्यूशन के हितों के खिलाफ हो । आज हम अपने इस आशय की तरफ बढ़ रहे हैं । इस को पूरा करने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे । हम सब मिल कर बैकवर्डनैस को दूर करेंगे ।

Educational and Industrial point of view से हम काफी कुछ उठ पाए हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है । इस राज्य के हम पूरी तरह से बराबर के हिस्सेदार हैं । हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं और इस बात की तरफ हम पूरी तवज्जोह दे रहे हैं । यह कोई मामूली सी बात नहीं है । इस के लिये अभी और वक्त चाहिये । मैं अर्ज कर दूं कि Rome was not built in a day, इस तरह के काम को पूरा करने के लिए सदियां लग जाया करती हैं । आप अदांजा लगाएं कि पिछले आठ महीनों के अन्दर जो काम हम ने इस सूबे की सरकार को चलाने के लिए किऐ हैं वह सब आपके सामने ही हैं । आप देखें कि जो पालिसी सटेटमेंट 11 points का इस सरकार ने इतने थोड़े से अर्से में पंजाब के लोगों के सामने पेश किया है, मैं समझता हूं कि आज तक पिछले 17 साल के अर्सा में किसी सूबा ने पेश नहीं किया । कम्युनल बातों का भी इस हाउस में रैफरेंस आया । मैं कहता हूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती । हम ने इस पालिसी सटेटमेंट के एक एक पैरा के अन्दर जो कुछ भी दिया है हम इस पर पाबन्द हैं और पाबन्द रहेंगे । यह हो सकता है कि हम में कुछ कमजोरियां हों, खामियां हों। हो सकता है कि हमारे अन्दर किसी तरह की नातजरुबेकारी भी हो । मगर इन सारी बातों के होते हुए भी हम किसी से आज दबते नहीं हैं । To err is human; हर इनसान गलती करता है और हर कोई गलती कर सकता है । हम ने अपनी तरफ से देश के हित के लिए देखते हुए आज तक सभी काम किए हैं। अगर कोई गलती भी की होगी तो नेक नियती की बिना पर ही की होगी और किसी परपज़ से नहीं । कई दफा गलत फैसले हो जाते हैं मगर यह सही करवाये जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी नीयत साफ है और इसी लिए हम जनता के हित की बा तें करने से नहीं डरते ।

यहां पर सरदार प्रताप सिंह कैरों के मर्डर का जिक्र किया गया । मैं इसके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता । मैं तो सिर्फ इतना ही यहां पर कहूंगा कि

[मुख्य मन्त्री]
जितनी भी मेरी मुलाकातें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी स हुई, मैंने उन को जो गलत फहमियां सरदार साहिब के मुताल्लिक पड़ी हुई थी उन को दूर करने की कोशिश की थी और किसी हद तक इस मामले में मैं कामयाब भी हुआ। इस बात की गवाही आज भी उनके नजदीकी रिश्तेदार दे सकते हैं। अगर आप जिंदा होते मैं यह बात दावे से कह सकता हूं कि आप इस मुलक की डिवैलपमेंट में एक जबरदस्त रोल पले करते। यह हमारी बदकिसमती है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों की बरुटल असेसीनेशन हुई। हमें दुःख है कि ऐसी घटना हुई, हम इस दुख में उनके रिश्तेदारों में शामिल होते हैं। वह दिन रात इस मुल्क की डिवैलपमैंट के लिए काम करने वाल आदमी थे। जैसे होम मिनिस्टर साहिब ने कहा है, यह हमारे उपर सदूर है। यह बात मैंने उस दिन भी कही थी जिस दिन कि यह वाका हुआ है। बहर हाल हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे सारे साधन जितने भी हमें मिल सकते थे आज इस बात की तरफ लगें हुए हैं। हम अपना पूरा जोर लगा रहें हैं कि जैसे भी हो कातिलों का सुराग लगाया जाए। हम ने अपने आई.जी. को, ऐस, आईज को और ऐ. ऐस. आईज को जितने भी लायक से लायक पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन में आफीसर हैं लगाए हुए हैं। सब आफीसरज को हिदायात हैं कि जहां से जैसे भी इनफरमेशन मिले वह हासिल करे और टरेस आऊट करें। मैंने तो हिन्दुस्तान के प्राईम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को यहां तक भी कह दिया है कि अगर इस मिनिस्टरी के मुताल्लिक इस कतल के सम्बन्ध में किसी तरह का भी कोई इलजाम हो तो हम मिनिस्टरी से रिजाईन करने को तैयार हैं और इस इलजाम के मुताबिक कटहरे में आने को तैयार हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस को किसी तरह से छुपाया जा सकता हो। यह हमारा इखलाकी फर्ज है कि हम इस कत्ल का सुराग लगाए। सरदार प्रताप सिंह हमारे नेता रहे हैं। इस से पहले भी कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने पंजाबियों की सी टरैडीशन्ज को कायम रखा है। हमारा भी फर्ज है कि हम उसी राह पर चलते हुए इस मुलक की डिवैलपमैंट करें। हमारी पुलिस ऐडमिनिस्टरेशन इस मामले पर पूरी तरह से तफतीश कर रही है। मैं उमीद करता हूं कि यकीनी तौर पर हमारी पुलिस सुराग लगाने में कामयाब होगी।

इस बहस को यहीं खत्म करते हुए मैं आपका ध्यान अब पंजाब की ऐडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ले जाना चाहूंगा। जहां तक पंजाब राज्य की ऐडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है, हमारा फर्ज है कि हम इसको अच्छे से अच्छा बनान की तरफ तवज्जोह दें। हम ने जिस दिन से इस राज की बाग डोर सभाली है हमने उसी दिन से अपना पालिसी सटेटमैंट दिया था और उस प्रोग्राम पर चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम पंजाब को effective, efficient और honest administration दें। 1953-54 में ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर सुधार लाने के लिए ग्रेपल की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी उस के आधार पर तवज्जोह देते हुए हम ने एक Organisation and Method Committee बनाई है।

स्पीकर साहिब, पंजाब में एक और चीज जो की गई है, वह पंजाब में मिसलें बरामद करने की तरफ की है । इस काम के लिए हम ने असैसमेंट यूनिटस बनाई हैं जिन्होंने ६,००० के करीब ऐसे केसिज वर्क आऊट किये हैं जो डिले होते थे और रैडटैपिज्म की वजह से प्रापरली डील नहीं किए जाते थे । उस पर कुछ अमल दरामद किया गया । यहां पर पंडित रला राम जी ने और सरदार गुरनाम सिंह व कामरेड रामप्यारा ने यह कहा कि डिले और रैडटैपिज्म कंटीन्यूड है । यह ठीक है, कुछ खामियां हैं, मैं उनको दूर करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से अहसास करता हूं । क्योंकि यह ठीक है कि जब तक ऐडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त नहीं हो जाता तब तक इस राज्य की कोई भी प्लैन कामयाब नहीं हो सकती । इसीलिए हमने ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन बनाया है, और यह कोई आर्डीनेरी कमीशन नहीं है । यह एक स्टेटुटरी बैंकिंग वाला कमीशन है ....

बाबू बचन सिंह : क्या इस कमीशन के साथ वही सलूक नहीं होगा जो आप लोगों ने पुलिस कमीशन के साथ किया ?

मुख्य मन्त्री : आप फिक्र न कीजिए । मैं यह अर्ज कर रहा था कि जब इस कमीशन की रिपोर्ट आएगी जिसका कि मैंने जिक्र किया तो मैं बाबू बचन सिंह जी को यह कहना चाहता हूं कि अगले इलैकशन से पहले पहले हम उसकी रिपोर्टस को मद्देनजर रख कर अमली जामा पहिना देंगे । हमने इस कमीशन के द्वारा 2,834 अशखास को एक जनरल क्वैस्चनएयर भेजा है और 499, आफीसर्ज को स्पैशल क्वैस्चन-एयर भेजा है । और मैं समझता हूं कि पंजाब का कोई भी इम्पार्टैंट आदमी नहीं रह जाता जिसको सुजैशन देने के लिए इनवाइट न किया गया हो । मैं अपोजीशन वालों को भी यही कहता हूं कि अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन के सुधारने में उनकी दिलचस्पी हो, तो अपने अपने सुझाव जो मूल्यमान हों उनको अवश्य दें ।

हमारा यह कमीशन दुनिया के प्राग्रेसिब कंट्रीज के ऐक्सपीरिएंस से पूरा पूरा फायदा उठाएगा । यह एक सही बात है कि जिन देशों ने अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन में तरक्की की और सुधार किया उन्होंने इस तरह के कमीशन बनाए । अमेरिका ने हूवर कमीशन बनाया था, स्कैंडनेवियन कंट्रीज ने और कैनेडा ने कमीशन के जरिए अपने ऐडमिनि-स्ट्रेशन में सुधार किया था । 1958 में डनमार्क ने अपने यहां कमीशन बैठाया और 1962 में न्युजीलैंड ने कमीशन बैठाया था । और अभी हाल में 3 नवम्बर को इंगलैंड में जब वहां की मलका ने पार्लियामेंट को ऐडरैस किया तो यह कहा था कि लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रायरटी देना चाहिए । यह इंगलैंड का ज़िक्र किया जिसने पिछले 400 साल से डैमाक्रेटिक रवायात कायम की और जस्टिस का रास्ता और देशों को दिखाया । जब दुनियां के अन्दर सारे देशों का यह हाल है तो आप चाहते हैं कि हमने पंजाब में कुल 8 महीने के अर्से में जमीन और आसमान एक क्यों नहीं कर दिया । हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो था नहीं कि जिसके जरिए जो आप सोचते थे वह पूरा हो जाता है फिर भी मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैंने जो कुछ किया या इस सरकार ने जो कुछ किया वह पिछले कई सालों से नहीं हो पाया था । (प्रशंसा)

चौधरी देवी लाल : यह जो सारी दुनियां का चर्चा किया लेकिन हरियाना जो 28 हजार मुरबा मील है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिब ने क्यों रिप्रेजटेशन नहीं दी ?

मुख्य मन्त्री : यह कोई रीजन के हिसाब से या जिला के हिसाब से कमीशन नहीं बनाया गया बल्कि सारे प्रान्त के लिए है और उसमें जो बैस्ट एबिलिटी के लोग मिल सकते थे उनकी सर्विसिज हासिल की हैं ।

चौधरी देवी लाल : क्या आपको 90 लाख की आबादी में से कोई आदमी एबिल नहीं मिला ?

मुख्य मन्त्री : जहां तक जस्टिस टेक चन्द का सवाल है, क्या आपको पता नहीं कि वह किस इलाके से आते हैं ? तो मैं कह रहा था कि कमीशन की रिपोर्ट आएगी और गवर्नमैंट उसके मुताबिक अमल करेगी । हां, अगर उस वक्त हरियाना को इगनौर कर दिया जाए तो यह कह सकते हैं और उस वक्त सरकार का कसूर हो सकता है । और अगर आप सुधार करने के लिए सलाह दें तो बेशक दें। आपके लीडर आफ दी आपोजीशन उसमें आपको रिप्रिजेंट करते हैं ।

चौधरी देवी लाल : हमें स्पीकर साहिब, यह गवाह से ज्यादा दर्जा नहीं देते।

मुख्य मन्त्री : तो हम, इस कमीशन के जरिए ऐडमिनिस्ट्रेशन को स्टीम लाइन करना चाहते हैं, रैडटैपिज्म और डिले को दूर करना चाहते हैं । और हमने कुछ हिदायतें जारी की हैं वह यह हैं कि—

Special attention has been paid to elimination of delay in the disposal of cases. Some of the important measures taken in this direction are enumerated below :—

6.00 p.m.

(1) The standing instructions are that 'Immediate' cases should be disposed of on the day they are received, 'Urgent' cases in not more than 3 days, and 'Ordinary' cases in not more than 6 days.

(2) Weekly arrear statements of cases which are not disposed of within the prescribed time limits are required to be furnished and their submission is insisted upon .

(3) Work "measurements" have been taken in various offices with the object of removing delays by streamlining procedures. In addition to the existing single Work Study Unit, more Study Teams have been constituted.

(4) Wide financial and administrative authority had been delegated to officials at the lower rungs of the administrative hierarchy, and this is likely to assist in eliminating some of the delay.

(5) Measures have been taken to tighten general supervision at all levels and to ensure that the system of inspections prevailing in the various Departments is adequate and is enforced.

हम तो इस से भी और आगे जाना चाहते हैं । हम ने Administration Reform Commission को यह भी लिखा है कि अगर उसकी interim report हो तो वह हमारे पास भेज दें । यहां पर District Co-ordination Committee की तशकील पर एतराज किया गया था । मैं इस सम्बन्ध

में बताना चाहता हूं कि हमारी कैबिनेट ने फैसला किया है कि हर District Co-ordination Committee के अन्दर जितने भी उस जिले के M.L.As हैं, M.L.Cs., हैं without any party consideration वह उस के मैम्बर होंगे, जिला परिषद का चेयरमैन उस का मैम्बर होगा , Municipal Committee का President उस का मेम्बर होगा, बार एसोसिएशन का प्रेजीडेंट भी उस का मेम्बर होगा । फिर एक farmer और एक trader भी मैम्बर होगा। जब भी उस की meeting होगी तब हमारा एक मन्त्री उसे preside करेगा । हम public के grievances को पंजाब के कोने कोने में district level पर, secretariat level पर दूर करना चाहते हैं। यही नहीं हम S.D.Os. level पर भी यह चीज करना चाहते हैं। हम ने एक और बेहतरीन फैसला किया है वह यह किया है कि हर महीने दो महीने के बाद हमारा एक मिनिस्टर हर District Headquarter पर जाएगा और उस के जाने से एक महीना पहले हम अपने programme को announce करेंगे और यह बताएंगे कि फला फलां दिन हमारा मिनिस्टर वहां पर होगा । उस जगह Financial Commissioner, Electricity Department का बड़ा अफसर, और इसी तरह Revenue और Irrigation Department के बड़े officers भी वहां मौजूद होंगे ताकि लोगों को चण्डीगढ़ की राह देखने की बजाए उन की शिकायतें वहां पर ही दूर की जाएं और उन को इनसाफ मिल सके । (शोर)

पंडित मोहन लाल दत्त : On a Point of order, Sir. स्पीकर साहिब यह जो flying yanta है इस की speed को control किया जाए । हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रहे हैं ।

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं आप की मारफत इस हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह मिनिस्टरी स्टेबल है और यह पार्टी पूरी strength से और इत्तफाक से काम कर रही है । वह सामने वाले हमारी बात को उछालने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हुआ अच्छा नहीं लगता क्योंकि बात हलकी है लेकिन सच्चाई कहनी ही पड़ती है । मैं इन को यह कहना चाहता हूं कि 41 मैम्बर होते हुए भी अगर आप के इखलाफात न होते तो आज लीडर तो चुन लिया होता । जरा आप अपनी तरफ भी निगह रखें । मैं चौधरी देवी लाल जी का मशकूर हूं जब उन्होंने कहा कि आप दो की क्या बात करते हो हमारी सारी पार्टी के साथ फैसला करो तो हम सब आने को तैयार होंगे ।

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, यह खामुखाह ऐसी बातें करते हैं । इन को सिवाए इस के और कोई काम ही नहीं है ।

श्री मंगल सेन : On a Point of order, Sir. स्पीकर साहिब, कामरेड साहिब इतने खुश न हों । सरदार प्रताप सिंह के वक्त में तो प्रजातन्त्र बना था मगर अब कोई और तंत्र बनेगा । यहां से वहां जाने की इधर वालों को जरूरत नहीं । वहां के ही इधर आएंगे ।

मुख्य मन्त्री : हमारी पंजाब सरकार ने पंजाब की administration को पूरी खुली छुट्टी दी है कि वह बगैर किसी डर के अपनी राए दें । हम उनकी कदर करते

[मुख्य मन्त्री]

हैं । हम ने पिछले सात आठ महीनों में देखा है कि हमारे जो officers हैं खाह secretariat में, खाह field में या Divisional level पर हैं उनकी तरफ से हमें पूरी co-operation मिल रही है । आज हमारे पंजाब में जनता और administration में coordination इस तरह से ही है जैसे हम welfare State कायम करना चाहते हैं । हम ने Deputy Commissioners कान्फ्रेंस की थी जिस में कई बातों की वज़ाहत की थी ।

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मेरा व्यवस्था प्रश्न है कि यह जो M.L.As. सरकारी बैंचों पर बैठे हैं वह दास कमिशन की रिपोर्ट के मुताबिक सज़ायाफता हैं, इस लिए इन का कोई हक नहीं सरकारी बैंचों पर बैठने का ।

मुख्य मन्त्री : हम Districts में administration को मज़बूत कर रहे हैं और सब चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं । जहां तक corruption का ताल्लुक है मैं मानता हूं कि corruption है । मगर corruption को दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने कई इकदामात उठाए हैं और उस को और मुअस्सर करने के लिए हमारी एक सनथानम कमेटी बैठी थी । उस की रिपोर्ट के मुताबिक तीन-चार चीज़ें हैं जो corruption को दूर करने में useful साबत हो सकती हैं । आज जो rules हैं उन के मुताबिक corruption case में कुछ रुकावट हो जाती है । इसके अन्दर कई दफा अटकाव आ जाता है । तो इसे दूर करने के लिए और अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए उन सारी चीज़ों पर जो सनथानम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दी हैं, पंजाब गवर्नमैंट ने पूरी तरह से गौर किया है । उस सारी रिपोर्ट को एगज़ाइमन करने के बाद जिस तरह से गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने हमें ऐडवाइज़ किया है कि किस तरह से सनथानम कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल किया जाए उसके मुताबिक उन सारी चीज़ों पर अमल दरामद करने के लिए ऐडापट किया है । इन सिफारिशात पर अमल करने के लिए और कुरप्शन को मुअस्सर तरीके से खत्म करने के लिए हम ने गवर्नमैंट आफ इंडिया को सजैस्ट किया है कि जितने हमारे Civil Service Punishment and Appeal Rules हैं उनके अन्दर अमैंडमैंट की ज़रूरत है । हमारे चीफ सैक्रेटरी इस सिलसिले में ऐल०आर० से बात करके सलाह करके देख रहे हैं कि कहां-कहां इन रूल्ज़ को सकरैप करने की ज़रूरत होगी और कहां-कहां अमैंडमैंट करने की ज़रूरत होगी ताकि कुरप्शन को दूर कर सकें । हम पूरी तवज्जुह दे रहे हैं । (cheers) मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम ने सैंट्रल गवर्नमैंट को यह भी लिखा है कि इन सिफारिशात पर अमल दरामद करने के लिए Indian Penal Code and Prevention of Corruption Act, 1947 में जहां जहां भी तबदीली करने की ज़रूरत है वहां उन को अमैंड करें । तो गवर्नमैंट आफ इंडिया इस सिलसिले में लैजिसलेशन तैयार कर रही है जिसके मुताबिक जहां २ पर इन एकटस और रूल्ज़ में तबदीली लाने की ज़रूरत होगी वह आएगी (cheers) । सनथानम कमेटी ने कुरप्शन को दूर करने के लिए review of certain Rules, Laws, Procedure and Practices की भी सिफारिशात कीं हैं और इस के साथ साथ जहां कहीं

डिसक्रीशनरी पावर का गल्त इस्तेमाल होता था उस बारे में जो कमेटी ने सिफारिशात की हैं हम उनको पूरी तरह एगज़ामन कर रहे हैं ताकि इस सम्बन्ध में एक किसम का जनरल नेचर का गाइडिंग फैक्टर गवर्नमैंट को दे सकें । हम ने यह भी फैसला किया है कि पंजाब गवर्नमैंट के जितने महकमे हैं उन एक-एक महकमा में विजीलैंस सैल कायम करेंगे जिन में टैकनीकल, लीगल और दूसरे आदमी भी होंगे इसके साथ साथ.....

श्री मंगल सेन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । क्या इस हाउस में कोई मेम्बर, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कोई ऐसी बात कह सकता है जो आधी मुंह में रह जाए आधी बीच में रह जाए जिसे रिपोर्टर्ज, जो लिख रहे हैं, फालो न कर सकें और न कुछ मैम्बरान के, जो सुन रहे हैं, पल्ले पड़े ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष : मेरा रूलिंग यह है कि आपने वास्कट ठीक नहीं पहनी हुई है (हंसी) (My ruling is that hon. Member has not put on his waist coat properly.) (*Laughter*)

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वायंट आफ इन्फार्मेशन, सर । मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं ने होम मिनिस्टर साहिब की तकरीर के बाद एक प्वायंट आफ इन्फार्मेशन रेज़ किया था तो उन्होंने कहा था......

Chief Minister : I am coming to that also.

बाबू बचन सिंह : अच्छा तो इसके साथ साथ एक बात और पूछना चाहता हूं कि 1959 में जो गवर्नमेंट ने ज़िलों की रीआरगेनाइज़ेशन के सिलसिले में कमिशनर्ज़ की कमेटी बनाई थी उस सिलसिले में इस गवर्नमेंट ने पिछले 8 महीने में क्या किया है ?

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ । ਮੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਾਰ ਨਾਮੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਹੇਠ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪੁਆਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ? (ਸ਼ੋਰ)

मुख्य मन्त्री : तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सनथानम कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक पंजाब में मौरल और सदाचार की कलाइमेट पैदा करने के लिए हमने सदाचार समितियों की तरफ तवज्जुह दी है । गवर्नमैंट आफ इंडिया ने भी हिदायात जारी की हैं कि सदाचार समितियों की तरफ से जो शिकायतें आएंगी उन्हें प्रायरटी दी जाएगी । हम पंजाब में मौरल कलाइमेट पैदा करना चाहते हैं और मैं आशा रखता हूं कि तमाम मैम्बर साहिबान की तरफ से ऐसा करने के लिए पूरा सहयोग मिलेगा । जहां तक पुलिस सर्विस कमीशन की सिफारिशात का सबंध है उसके लिए हम ने एक कमेटी बिठाई है जिसके होम सैक्रेटरी, आई. जी. पुलिस मैम्बर्ज हैं जो इस चीज़ की देख भाल कर रहे हैं कि आज के बदले हुए हालात के मुताबिक जिन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है उस की छानबीन कर रहे हैं । पंजाब की पुलिस देश में एक बहतरीन पुलिस

[मुख्य मन्त्री]

है और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि पंजाब में ला ऐंड आर्डर कायम रखने के लिए, पीस और ट्रांकुइलटी रखने के लिए और लोगों का एतमाद लेने के लिए हम अपनी पुलिस को माडल तरीकों से और साइंटिफिक मैथड्ज़ से लैस करने की तरफ पूरी तवज्जुह दे रहे हैं । फिर यहां पर पंडित चिरंजी लाल जी ने एक केस का ज़िक्र किया था । That case is under investigation. I am looking into that case. कामरेड राम प्यारा जी ने भी एक केस का ज़िक्र किया था । उसकी पूरी तरह से इन्क्वायरी हो रही है और हम उसकी तरफ पूरी तवज्जोह दे रहे हैं। किसी किसम की गफलत नहीं कर रहे हैं । इसी तरह से जोगा साहिब ने पटवारियों और कुछ ट्रांस्पोर्ट के बारे में.........

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿਘ ਜੋਗਾ : On a Point of order, Sir. ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜੋ....

Mr. Speaker : This is not a point of order.

मुख्य मन्त्री : मैं ज़िक्र कर रहा था कि जोगा साहिब ने कुछ पटवारियों का सवाल उठाया था और कुछ ट्रांस्पोर्ट के केस का ज़िक्र किया था । मुझे खुशी होगी अगर वह कोई सपैसेफिक केसिज़ हमारे नोटिस में लायें । हम पूरी तरह इन्क्वायरी करने के लिए तैयार हैं । श्री मंगल सेन जी ने डगाना के एक सरपंच का सवाल उठाया था । उसकी विजीलैंस डिपार्टमैंट ने इन्कवायरी की थी , रिपोर्ट आ गई है डी०सी० ने भी उस की इन्कवायरी की थी लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है उसके मुताबिक जो कार्यवाही हम कर सकते हैं जरूर करेंगे । सरदार अजायब सिंह ने भी कुछ सवाल उठाए थे उनकी तरफ भी हमारी पूरी तवज्जोह है कोई गफलत नहीं कर रहे हैं। मैं फिर एक दफा हाउस से निवेदन करना चाहता हुं कि पंजाब के अन्दर अच्छा वायुमंडल पैदा करने के लिए आप हमारी मदद करें । मैं चाहता हूं कि अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन लाने के लिए सब से अच्छी मिसाल मिनिस्टर्ज़ को पेश करनी पड़ेगी और मैं अपने आपको आपके सामने पेश करता हूं । मैं आशा रखता हूं कि आपोज़ीशन भी अपना सही रोल जो कि डैमोक्रेसी के अन्दर आपोज़ीशन को अदा करना चाहिए कि constructive criticism करना है उसे अदा करेगी । इसी तरह हमारी यह डैमोक्रेसी मज़बूत होगी अगर हम अपने अपने रोल को पहचानेंगे और इमानदारी के साथ उसे अदा करेंगे, इस तरह करने से ही हम लोगों के सामने सुरखुरू होंगे और हो सकते हैं । बजाए एक दूसरे की लान तान करने के अगर हम सब अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए अपने-अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हुं कि हमारा यह पंजाब आगे ही आगे बढ़ता जाएगा । (cheers)

Mr. Speaker : Now I will put cut-motions to Demand No. 9 (19-General Administration) to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Cut-motion No. 2 stands in the name of Principal Rala Ram.

Principal Rala Ram : Sir, I beg to withdraw my cut-motion.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be allowed to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : The next cut-motion is from Shri Rup Singh 'Phul'.

Shri Rup Singh 'Phul' : Sir, I beg to withdraw my cut-motion.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be allowed to withdraw his cut-motion ?

Voices : No.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Cut-motion No. 4 is from Sardar Pritam Singh Sahoke.

Sardar Pritam Singh Sahoke : Sir, I beg to withdraw my cut-motion..

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be allowed to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Cut-motion No. 5 stands in the name of Chaudhri Ran Singh.

Chaudhri Ran Singh : Sir, I beg to withdraw my cut-motion.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be allowed to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Cut-motion No. 6 has been received from Shri Ram Chandra Comrade.

Comrade Ram Chandra : Sir, I beg to withdraw my cut-motion.

Mr. Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker :

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : The next cut-motion stands in the name of Sardar Prem Singh 'Prem'.

Shardar Prem Singh 'Prem' : Sir, I beg to withdraw my cut-motion.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be allowed to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be recuced by Rs 100.

The motion was lost

Mr. Speaker : Cut-motion No. 8 has been received from Chaudhri Darshan Singh.

Chaurhdri Darshan Singh : Sir, I leave it to the pleasure of the House.

Mr. Speaker : May I know the sense of the House ?

Voices : He may be allowed to withdraw his cut-motion.

Voices. : He may not be allowed to withdraw his cut-motion.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Cut-motion No. 10 stands in the name of Shri Babu Dayal Sharma.

Shri Babu Dayal Sharma : Sir, I beg to withdraw my cut-motion.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be allowed to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 4,47,34,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66 in respect of charges under head 19—General Administration.

The motion was carried. **(Cheers)**

Mr. Speaker : I will now put cut-motions to Demand No. 12 (23—Police) to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Cut-motion No. 2 stands in the name of Principal Rala Ram.

Principal Rala Ram : Sir, I beg to withdraw my cut-motion.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be allowed to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : The next cut-motion stands in the name of Shri Rup Singh 'Phul'.

Shri Rup Singh 'Phul' : Sir, I beg to withdraw my cut-motion.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be allowed to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

Cut-motion No. 3 is missing.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Cut-motion No. 4 stands in the name of Shri Roop Lal Mehta.

Shri Roop Lal Mehta : Sir, I beg to withdraw my cut-motion.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be allowed to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker : Quertion is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Cut-motion No. 5 has been received from Shri Babu Dayal Sharma.

Shri Babu Dayal Sharma : Sir, I beg to withdraw my cut-motion.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be allowed to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be recuced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : The next and the last cut-motion stands in the name of Chaudhri Dal Singh.

Chaudhri Dal Singh : Sir, I beg to withdraw my cut-motion.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be allowed to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 12,51,24,770 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66 in respect of charges under head 23—Police.

After ascertaining the votes of the Members present by voices, Mr. Speaker gave an opinion. The opinion was challenged. The question was put again and carried by a voice vote.

The motion was declared carried. (*Cheers*)

6.27 p.m.

(*The House then adjourned till* 9.30 *A.M. on Tuesday, the* 16*th March*, 1965)

4481 P.V.S.15-7-65—C.P. & S., Pb., Chandigarh.

APPENDIX
to
The P.V.S. Debate Volume I, No. 18, dated the 15th March, 1965.

COMPLAINTS FOR DRAWING SUGAR ON BOGUS PERMITS BY RESIDENTS OF CERTAIN VILLAGES IN AMRITSAR DISTRICT.

@*6986. **Comrade Makhan Singh Tarsikka:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any complaints have been received by the district authorities against the residents and Sarpanches concerned of village Lola (Tarsikka Block), village Chohla (Chohla Block) and village Uboke (Naushehra Block) for drawing sugar etc. on bogus permits of sugar obtained in connection with marriages etc. in district Amritsar.

(b) if the reply to part (a) above be in affirmative whether any investigation has been made into the said complaints, if so, the details of the reports of the investigating Officers in connection with each of the said villages be laid on the table of the House.

(c) whether any cases were registered at the police station on receipt of the reports of the said Investigating Officers if so, the summaries of the F.I.R.s in each case be laid on the table of the House?

Shri Ram Kishan: (a), (b) and (c) A statement containing the required information is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) Yes.

(b) Yes ; the enquiry has been/is being made into the complaints the details of which are given below:—

VILLAGE LOLA (TARSIKKA BLOCK)

(i) A complaint was received in the office of the Deputy Commissioner, Amritsar from one Shri Bantoo, son of Shri Gadi of village Lola against Shri Gehlo, son of Shri Labh Singh and Shri Jailo, son of Shri Labh Singh and Shri Jailo, son of Shri Harnam Singh of the same village alleging therein that they obtained sugar for the marriage ceremonies of their daughters and sold it in black-market, as the marriage ceremonies did not actually take place. The Assistant Registrar, Co-operative Societies, Amritsar who enquired into this complaint reported that this case was already under consideration with Shri T.N. Gupta, P.C.S., Magistrate, Amritsar for registration of a case with the police. The said Magistrate summoned the parties at Jandiala on 19th September, 1964 when Shri Makhan Singh Tarsikka M.L.A. was also asked to assist in the enquiry. Thereafter, a case under section 125 of D.I.R. was registered by the Jandiala Police on 19th September, 1964 against Sarvshri Soudagar Singh, Banta Singh, Gehal Singh, Jelu and Shangara for obtaining sugar on bogus applications. All of them are on bail now and the case is under investigation.

(ii) A complaint was received in the office of the Deputy Commissioner, Amritsar, from one Shri Solakhan Singh against Shri Lal Singh village Lola. It is under enquiry by the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Amritsar.

VILLAGE CHOHLA

A complaint was received during January, 1965, the office of the Deputy Commissioner, Amritsar, from Shri Makhan Singh of village Cholha Sahib, tehsil Tarn Taran against one Shri Bhag Singh, of the same village. It is still under enquiry by the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Tarn Taran.

@*Note*:—converted as Unstarred under directions of the hon. Speaker.

VILLLAGE UBOKE (NAUSHERA BLOCK)

A complaint was received in the office of the Daputy Commissioner, Amritsar from Shri Dalwinder Singh of village Uboke, tehsil Tarn Taran, against one Shri Sadhu Singh of the said village. It was alleged in the complaint that Shri Sadhu Singh in complicity with the village Sarpanch obtained sugar against the permits for marriage ceremonies of his two grand daughters, but actually performed the marriage ceremony of only one grand daughter, and sold the sugar drawn for the second function in black-market. The complaint was enquired into by the Assistant Registrar, Co-operative Societies Tarn Taran by the Assistant Registrar, Co-operative Societies Tarn Taran, who reported that Shri Sadhu Singh did obtained two permits for sugar for the marriages of his two grand daughters, but in fact only one marriage was celebrated. The allegeation about the disposal of sugar by him in black-market could not, however, be substaniated. The matter for taking legal action against Shri Sadhu Singh, for his obtaining two sugar permits for the marriages of two grand daughters but celebrating the marriage of only one grand daughter, has been referred to the District Attorney Amritsar, for his legel advice. Further action will be taken on receipt of his advice

(c) Only one case has been registered at the Jandiala Police station the details of which have been given against item (b) (i) above in respect of village Lola.

C. T. D. ACCOUNTS OF THE CHOWKIDARS OF THE CAPITAL PROJECT ADMINISTRATION.

***7903. Shri Sagar Ram Gupta :** Will the Chief Minister with reference to the reply to Unstarred Question No. 1434 printed in the list of Unstarred Questions for 6th March, 1964, be pleased to state—

(a) Whether the C.T.D. accounts of all the Chowkidars employed in the Capital Project have since been opened?

(b) Whether the interest accruing to each Chowkidar on his C.T.D. deposit amount for the period from April, 1961 to the date of opening of the account has also been credited into his account. If not, the reasons therefor and the manner in which the Government proposes to compensate these Chowkidars for the loss of interest ?

Shri Ram Kishan: (a) Yes.

(b) Yes, in so far as regular Chowkidars are concerned. In the case of work-charged Chowkidars the matter is being looked into.

SUB INSPECTORS AND ASSISTANT SUB-INSPECTORS CHARGE-CHARGE SHEETED/SUSPENDED IN THE STATE.

2418. Shri Amar Singh : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the number and names of Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors who were charge-sheeted/suspended in the State, districtwise, during the period from January, 1964 to date and the reasons therefor in each case;

(b) the number and names of Sub-Inspectors and Assistant Sub Inspectors from amongst those mentioned in part (a) above who have been re-instated by the Government during the said period?

Sardar Darbara Singh: (a) 307 Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors were charge-sheeted/suspended in the State during the period from January, 1964 to-date. Their names District/Unit-wise, alon gwith the reasons therefore are given in the enclosed statement No.I

(b) 45 Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors were re-instated during this period by the competent Police authorities. None was re-instated by the Government. Their names District/Unit-wise are given in the enclosed statement No. II.

Note : —Converted as Unstarred under directions of the hon. Speaker.

STATEMENT NO. I

List showing the names of Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors, who were charge-sheeted suspended during the period from January, 1964 *to-date and the reasons therefor—*

Serial No.	Name, rank and number of Police officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
		PUNJAB ARMED POLICE	
1	S.I. Roshan Lal, No. PAP/ 161	For absenting himself from PAP Guard Hydel Channel Canal without permission and going to Anandpur Sahib where he was found drunk	Yes
2	S.I. Kulwant Singh, No. PAP/144	For misappropriation of Government money	Do
3	S. I. Bakhtawar Singh, AP Bn. /12	For making a false statement before court of Inquest-cum-enquiry	Do
4	S.I. Karnail Singh 200	For abusing each other after taking liquor	Do
5	S.I. Kartar Singh 35/ PAP Bn.	Ditto	Do
6	S.I. Amar Singh 310	For negligence and carelessness in taking out inadequate patrol party without permission from Coy. H.Qrs.	Do
7	S.I. Mani Ram	For being found negligent in the performance of duty	Do
8	S.I. Darbara Singh No. 121/ P.A.P.	For misconduct	Do
9	A.S. I. Sowaran Singh No. 258	For having been found in a drunken condition at Picket Kassoke	Yes
10	A.S.I. Sardara Singh 255	For showing culpable negligence in pursuing a case on the border	Do
11	A.S.I. Sucha Singh, No. 356	Severe allegation of misconduct against them	Do
12	A.S.I. Charanjit Singh No. 4562		Do
13	A.S.I. Surjan Singh No. 50	For taking liquor and threatening two Constables of his Picket with dire consequence	Do
14	A.S.I. Harbans Singh No. 921	For not allowing the Coy. Commander to record a report against Constable Surjit Singh	Do
15	A.S.I. Surjan Singh 50	For making a false statement before Court of Inquest-cum-enquiry	Do
16	A.S.I. Jagtar Singh 2326	Collection of subscription and mis-appropriation of Rs 127	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police officer	Allegations/reasons	Whether sus pended ror not
1	2	3	4
		PUNJAB ARMED POLICE	
17	A.S.I. Jaldev Singh 2988	Misbehaving with public under the influence of liquor	Do
		GOVERNMENT RAILWAY POLICE	
18	S.I. Khushal Singh No. R/6	Case under section 342 I.P.C. wrongful confinement	Yes
19	A.S.I. Niranjan Singh No. 723/GRP	Ditto	Do
20	A.S.I. Kirpal Singh No. 17/GRP	Case under section 379 I.P.C.	Do
21	S.I. Bhiwani Shandker No. 16/R	For disposing case property	No
22	S. I. Lachman Singh No. R/1	Misbehaviour with public	Do
23	A.S.I. Raghu Nath No. 8/R	Late submission of case diaries	Do
24	A.S.I. Hari Parkash No. 29/R	Ditto	Do
25	S.I. Balbir Singh No. 2/R	Charge of inefficiency	Do
26	S.I. Sant Parkash Singh 18/R		
27	S.I. Yog Dhian No. 39/R		
28	S.I. Jagdish Lal No. R/7		
29	A.S.I. Raghu Nath No. 8/R		
		HISSSAR DISTRICT	
30	S.I. Mohar Singh No. 202/A	For contravening the provisions of P.R. 18.38(6)	No
31	A.S.I. Guru Datt, No. 365/KNL	For writing case diaries with inordinate delay	No
32	ASI Madan Lal, No. 513/GGN	Ditto	Do
33	A.S.I. Jai Pal No. 304/GGN	Ditto	Do
34	A.S.I. Amar Nath, No. 683/RTK	Ditto	Do
35	S.I. Chuni Lal No. 153/A	For accepting illegal gratification	Yes
36	S.I. Sohan Lal No. A/16	Under section 5(2) 47 of P.C. Act	Do
37	A.S.I. Ram Parkash No. 516/GGN	Ditto	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
38	A.S.I. Sardara Singh, No. 855/Hissar	Under section 25/54/59 Arms Act	Yes
39	A.S.I. Hardit Singh, No. 739/KNL	Under section 5(2)47 P.C. Act	Do
40	A.S.I. Amir Chand, No. 95/ /KNL	under section 5(2)47 P.C. Act and under section 161 I.P.C.	Do
	ROHTAK DISTRICT		
41	A.S.I. Raja Ram ..	Under section 325/342 I.P.C.	Yes
42	S.I. Ram Rakha, No. A/132	Under section 5(2)47, P.C. Act	Do
43	A.S.I. Bhan Singh, No. 31/A	Ditto	Do
44	S.I Saudagar Singh, 58/A	For negligence in the investigation of case F.I.R. 279, dated 23rd December, 1963, under section 302 I.P.C. police station Sonepat	No
45	S.I. Mehtab Singh, A/80	Ditto	Do
46	S.I. Kundan Lal, 52/A ..	For submitting delayed case diaries	Do
47	S.I. Balwant Singh, 174/A	For lack of control, while posted S.H.O., police station, Salawas	Do
48	S.I. Lal Singh, No. 91, PAP	Failure to take preventive action against the assailants in case F.I.R. No. 49/62, under section 302, 148/149, I,P,C, ,police station Ganaur and defective investigation in case F.I.R. No. 69/63, under section 457/380, I.P.C., and 70 and 71/64 under section 9/1/28	Do
49	A.S.I. Havali Ram, 58/UMB	For recording false entry of his departure in the D.D. while posted at police station Sirvani district Hissar	Do
50	A.S.I. Pran Nath, 186/SML	For not taking care for the safe custody of case property while posted in C.I.A. Staff, Rohtak	Do
51	A.S.I. Ude Ram, 217/RTK	For negligence in the investigation of case F.I.R. No. 279, dated 23rd December, 1963 under section 302, I.P.C., police station Sonepat	Do
52	A.S.I. Hari Singh, 56/UMB	For poor work, while posted in Excise Staff at Sonepat	Do
53	A.S.I. Haveli Ram, 58/UMB	For travelling with out ticket in a Punjab Roadways Bus	Do
54	A.S.I. Kuldip Chand 187/ RTK	For submitting delayed case diaries	Do
55	A.S.I. Avtar Kishan 245/A	Ditto	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
	GURGAON DISTRICT		
56	S.I. Harsarup No. 247 A	For lack of control over his subordinates and over the B. Cs. of the Illaqa	No
57	A.S.I. Des Raj, No. 48/A	For delaying the investingation of case F.I.R No. 22/63, under section 307/325 I.P.C., police station Palwal	Do
58	A.S.I. Rachhpal Singh .	For having accepted illegal gratification	Do
59	S.I. Kesar Singh, No. 67/A	For delaying the submission of case diaries in many cases	Do
60	A.S.I. Pritam Singh , No. 419/GGN	D.D. of police station Chhansa and for accepting for making wrong entries in illegal gratification of Rs 175	Do
61	S.I. Tej Ram	For burking of cases	Do
62	S.I. Ritu Dhawaj .	For corruption	Do
63	S.I. Darbara Singh, No. 230/A	For corruption and burking	Do
	AMBALA DISTRICT		
64	S.I. Gurnam Singh, 240/A	He was detected travelling without ticket in Bus No. 5131 PNE and he refused to sign the statement, when asked by the Special Squad Finance Department, Punjab.	Yes
65	S.I. Harbachan Singh , 30/A	Strictures in case under section 302, I.P.C. police station Chandigarh were passed against the S.I. by the Additional Sessions Judge, Ambala	Do
66	S.I. Madan Lal, A/90	For having been arrested in case F.I.R. No. 182, dated 29th April, 1964 under section 342, I.P.C. , police station Chandigarh	Do
67	A.S.I. Madan Lal, 232/GGN	He obtained some fruits, vegetables and cloth from certain shopkeepers of Ambala Cantt and Ambala City by mis-representing facts. He gave out his wrong identity and employed deceitful means in order to obtain these articles without payment. He remained absent from the Police Lines on 6th March, 1964 and 8th March, 1964 without permission	Do
68	A.S.I. Ram Gopal, 142/RTK	He was detected by the Special Squad Finance Department travelling without ticket in Bus No. 2346/PNU of Punjab Roadways on 9th October, 1964 near Ambala City	Do

Serial No.	Name, rank and number of Police officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
69	A.S.I. Jagat Singh, 35/UMB	He, while posted at police station Ambala Cantt., was arrested and sent up in case F.I.R. No. 272 dated 12th July, 1964, under section 354/294, I.P.C., police station Ambala Cantt. He was acquitted by the Chief Judicial Magistrate, Ambala, on 11th January, 1965 by giving him benefit of doubt and is now facing departmental enquiry	Yes
70	S.I. Ram Pat, No. 212/A	He did not take any action on the complaint of Shri Banta Singh of village Chalaki, police station Morinda during his tenure at police station Morinda	Do
71	S.I. Krishan Kumar, 172/A	He, while posted as O.A.S.I./S.P. office, Ambala, by his negligence allowed C. Gurdas Singh 749 to continue as orderly to Inspector Gurnam Singh, when the Inspector was under suspension and was transferred to Karnal. He also tempered with the record of posting of const.	No.
72	S.I. Moti Singh, A/7 ..	He was not vigilent about the party factions in village Burail, where hurt cases were registered against the parties	Do
73	S.I. Mohinder Singh ..	He was liable for the inherant defects in the investigation of case F.I.R. No. 27, under section 307/148, I.P.C., and 9/1/78 A, Act police station Ambala Cantt.	Do
74	S.I. Dalip Singh, A/44 ..	For acts of omission and commission detected by S.P., Ambala, during the Inspection for the 3rd and 4th quarters of 1963. He did not use Scientific methods of investigation in any case	Do
75	S.I. Sadhu Singh, 173/A ..	While posted at police station Kharar, he was responsible for various acts of omissions and commissions as noted in the inspection note of police station Kharar for the last 6 months of 1963	Do
76	S.I. Rattan Singh, 97/A ..	He did not register a case nor entered any report in the Daily Diary Register on receipt of a report from one Ram Singh of Sadhaura regarding theft of his trees from his fields	Do
77	S.I. Krishan Kumar, 172/A	The S.I. used filthy language to Shri Sadhu Ram, Sarpanch of Shiampur, when the later refused to withdraw the complaint under section 323/504 I.P.C., which he had filed in the court of J.M., Rupar against Shri Mohinder Singh, Inspector, Food and Supplies, Rupar	Do

Serial No.	Name, rank and number of police officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
78	P.S.I. Brahm Sarup, A/144	For not fully representing the prosecution case in a court.	No
79	S.I. Inderjit Singh, 34/A	He investigated case F.I.R. No. 7, dated 23rd March, 1964, under section 302, I.P.C. police station Bilaspur. He told Shri Bhan Singh, complainant at the initial stage of the investigation without verifying facts that it was a case of suicide and not of murder. Moreover, when, Bhan Singh father of the deceased alongwith others went to the police station on 23rd March, 1964 the S.I. misbehaved with them and forcibly turned them out of police station	Do
80	P.S.I. Ishwar Parshad, R/36	The Additional Sessions Judge, Ambala, while setting aside the conviction of an accused in case F.I.R. No. 99 dated 10th July, 1963 under section 353 I.P.C., police station, Rupar, made some observations regarding the manner in which the case was conducted on behalf of the prosecution in the court of J.M., Rupar	Do
81	S.I. Harbachan Singh, 30/A	In case F.I.R. No. 16, dated 21st February, 1963, under section 162/163, I.P.C., police station Chamkaur Sahib while acquitting the accused, the J.M. Rupar passed strictures against S.I. Harbachan Singh, that S.H.O. did bungling in the investigation of the case and against C. Darbara Singh that integrity of Const. was highly questionable	Do
82	S.I. Kharati Lal, A/109 ..	No effort was made for service of notice on the accused in case St. Vs. Jaga and others under section 363, I.P.C., police station, Rupar, issued from the Sessions Court, Ambala with the result that all the witnesses had to turn without examining in court.	Do
83	S.I. Krishan Lal, A/13 ..	During the Inspection of police station, Chandigarh by S.P. for the first 2 quarters of 1964, it was seen that the S.I. was habitual in writing case diaries with delay	Do
84	S.I. Jagdish Chander, 171/ HSR	He proceeded on 10 days C.L. from P.P. Sector 11 without permission	Do
85	S.I. Gurchet Singh, 138/A	Strictures were passed against him in case F.I.R. No. 76, dated 2nd October, 1962, under section 19/11/78 A. Act and 25/54/59 A. Act police station, Morinda by J.M., Rupar	Do
86	A.S.I. Gurchet Singh, 138/A (now S.I.)	He did not take any action on the complaint of Shri Banta Singh of village Chalaki, police station Morinda during his tenure at police station Morinda	Do

Serial No.	Name, rank and number of police officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
87	A.S.I. Babu Singh, 497/SML	During the formal inspection of police station Chandi Mandir for the 3rd and 4th quarters of 1963, various acts of omissions and commissions on the part of A.S.I. particularly the delay with which he investigated the cases during his posting came to notice.	No
88	A.S.I. Hira Lal, 258/A ..	S.H.O. Mullana handed over some property taken into possession , under section 550 Cr. P.C. in case F.I.R. No. 11/62 under section 457/380, I.P.C. police station Mullana to A.S.I. Hira Lal, with the direction that he should get deposited in police station Mulkhana. He did not deposit the property although he got an entry made to this effect by H.C. Hari Singh, 180 in the daily diary who was working as M.H.C. in the absence of H.C. Hussan Lal 534.	Do
89	A.S.I. Shanti Sarup, 489/ KNL	It was alleged in an annonymous complaint received from a congress worker that the A.S.I. had been receiving monthly from Satta gamblers of Yamuna Nagar. He had also accepted Rs 150 as bribe from one Kulwant Rai for hushing up a case against him	Do
90	A.S.I. Ram Avtar, 26/A (now S.I.)	While posted at police station Kharar, he was responsible for various acts of omissions and commissions as noted in the Inspection note of police station Kharar for the last 6 months of 1963	Do
91	A.S.I. Babu Singh, 497/ SML	It is alleged that the A.S.I., while posted at police station Chandigarh recovered a buffallo belonging to Shri B.R. Saraf from the possession of one Gopi Ram of Bajwara , under section 550 Cr. P.C Thereafter he handed it over to Duni Chand of Bajwara on supardari without obtaining any order of Magistrate. He neither registered a case when buffalo was recovered and identified by Shri B.R. Saraf nor made any entry to this effect in the daily diary	Do
92	A.S.I. Jagdish Chander, 191/HSR	He, while posted at police station Sadhaura, investigated certain cases in which he committed grave irregularities	Do
93	A.S.I. Tilak Raj, 503/SML	He abused and misbehaved with one Kesar Singh a social worker of Manakpura, district Karnal on 13th November, 1963 in connection with a case under section 107/151 Cr.P.C. against Shangara Singh and others, while he was posted at police station Yamuna Nagar	Do

Serial No.	Name, rank and number of police officer	Allegations/Reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
94	A.S.I. Tilak Raj, 503/SML	It is alleged that during his posting at Yamuna barrier on U.P. Punjab Border, he knowingly encouraged the import of gur, shakar and khandsari from the State of U.P. into the State of Punjab, after receieving illegal gratification	No
95	A.S.I. Kirpa Ram, 409/HSR	He disobeyed the order of D.S.P./Rupar and did not take preventive action, as suggested by the D.S.P. and as a result of which rioting took place between the parties and 2 cross-cases of hurt were registered	No
96	A.S.I. Jagat Singh, 35/UMB	He along with 4 constables and Shibu and Surat Singh, went to the house of one Din Mohd. in his absence and enticed away his daughter Mst. Rafiqan. The A.S.I. neither registered any case nor obtained any warrant in this connection	No
97	A.S.I. Jagjit Singh, 26/PR	He, while posted at Kharar received the Chemical Examiners report on 6th August, 1958 in case F.I.R. No. 127/57, under section 61/1/14 E. Act., police station Kharar, but negligently he misplaced the same with the result that the case could not be put in court within the period of one year and the case had to be referred to the Government for sanction of prosecution	No
98	A.S.I. Suraj Bhan, 556/KNL	He, while posted as O.A.S.I. in S.P.Office Ambala, was responsible for loss of paper regarding preliminary enquiry against Inspector Ishar Dass, Ex- S.H.O. Ambala Cantt	No
99	A.S.I. Naunihal Singh, 522	He gave beating to one Ganpat of village Rachheri at the instigation of Dalip Singh of the village and detained Ganpat and Ram Partap for the night in the Dharamshala. He let them off on the entreaties of Gurdit Singh and Ram Gopal. etc., of the village	No
100	A.S.I. Ratti Ram, 241/A	Shri Krishan Lal, Member, Panchayat and Bakshi Ram , Harijan approached the A.S.I. with the complaint against Prem Singh, Tahal Singh which was duly endorsed by D.S.P., Chandigarh, in the name of A.S.I. Ratti Ram. The A.S.I. instead of looking into the complaint as warranted by law, insulted, abused and assaulted them in the police station without any reason. As a result thereof Bakshi Ram and Krishan Lal received injuries	No

Serial No.	Name, rank and number of police officer	Allegations/Reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
101	A.S.I. Rachhpal Singh, 689/GGN	He maltreated one Satish Kumar of Naraingarh and when Shri Gurcharan Singh, S.I. Industrial Co-operative Societies, Naraingarh went to the police station and requested the A.S.I. not to maltreat Satish Kumar, the A.S.I. arrested and hand-cuffed S.I. Gurcharan Singh, Satish Kumar on one side and Mohan Lal on the other. Later the S.I. released S.I. Gurcharan Singh and removed his hand cuffs without obtaining orders of the competent authority after he had been satisfied that he would be paid some money	No
102	A.S.I. Babu Singh, 499/KNL	He was not vigilant about the party factions in village Burail where hurt cases were registered against the parties headed by Phool Singh and Amarjit Singh	No
	KARNAL DISTRICT		
103	A.S.I. Om Parkash, 199/A	For disobeying the orders by which he was transferred from police station Thaska to police station Nissing inas much as he failed to carry out the same	Yes
104	A.S.I. Gurbux Singh 2/A	For not complying with the orders of Shri Y.S. Nakai, D.S.P., passed on the memorandum of case F.I.R. No. 112, dated 8th November 1961, under section 324, I.P.C. police station Sadar Sirsa	No
105	S.I. Ram Pat 212/A ..	For not taking cognizance of a complaint of Shri Banta Singh	No
106	A.S.I. Raj Kumar No. 228/KNL	For delaying the investigation of case F.I.R. No. 135 dated 13th August, 1963 under section 325/324 I.P.C., police station Butana for about two months	No
107	A.S.I. Sampuran Singh 405/HSR	For not taking preventive action in respect of a fight between Jagdish Rai and Nihal Chand	No
108	A.S.I. Gurbux Singh 2/A	For failing to comply with the order of D.S.P., Sirsa, requiring him to trace the identity of the woman who gave birth to the child and threw it in the canal	No
109	S.I. Ram Pat, No. 212/A	For having misbehaved with Shri Ram Dhari, M.L.A.	Yes
110	A.S.I. Joginder Nath No. 461/SML	For dereliction of duty inas much as he delayed the investigation of case F.I.R. No. 80, dated 19th October, 1962, under section 409/467 I.P.C.	No
111	A.S.I. Sampuran Singh No. 405/HSR	For late submission of case diaries	No

Serial No.	Name, rank and number of police officer	Allegations/Reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
112	S.I. Gian Singh No. 25/A	For late submission of case diaries	No
113	A.S.I. Shanker Dass, 380/ Ambala	Ditto	No
114	A.S.I. Ram Chander, No. 21/A	For defective investigation in case F.I.R. No. 131 dated 28th September, 1962 under section 307/148/149 I.P.C. police station Pehowa	No
115	A.S.I. Raj Kumar, 281/KNL	For delaying the investigation of case F.I.R. No. 115/64 under section 302, I.P.C. 161/64 under section 125(2)D.I.R. and 162/64 under section 125 (2), D.I.R. police station Sadar Karnal. (ii) For failing to carry out pattrolling in the sensitive village. (iii) For refusing to obey the order of the S.H.O.	No
116	A.S.I. Raj Singh, 192/A	For delay in the submission of case diaries	No
117	S.I. Siri Ram, No. 96/A ..	For misbehaving and maltreating one Pritam Singh	No
118	Ditto	For overstaying after giving evidence at Kaithal	No
119	S.I. Gian Singh, No. 25/A	For not investigating a case impartially and favouring the accused person	Yes
120	A.S.I. Sampuran Singh No. 406/HSR	For having been mixed up with smugglers	Yes
121	A.S.I. Puran Singh, No. 186/Ambala	For having been arrested in case F.I.R. No. 108 dated 18th July, 1964, under section 302, I.P.C., police station Sadar Panipat	Yes
122	A.S.I. Raj Singh, 192/A ..	For having been arrested in case F.I.R. No. 93 dated 9th August 1964, under section 5(2), P.C. Act, police station Pehowa	Yes
	SIMLA DISTRICT		
123	S.I. Sukhminder Singh 102/A	For late submission of case diaries	No
124	A.S.I. Amar Chand, No. 314/SML	He misbehaved with Sarpanch Panchayat etc.	No
	HOSHIARPUR DISTRICT		
125	A.S.I. Teja Singh, 298/HSP	For faulty investigation in case F.I.R. No. 19/62 under section 379 I.P.C., police station Mukerian, while posted at C.I.A, Dasuya	No

Serial No.	Name, rank and number of police officer	Allegations/Reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
126	S.I. Gurcharan Singh 58/J	He was detected while travelling in Bus No. PNJ-6469 without ticket on 9th September, 1963 by the Secial Squad while posted at police station Hajipur	No
127	A.S.I. Chuni Lal 126/J	While posted at P.P. Nangal he sent case diaries in certiain cases with gross delay	No
128	A.S.I. Sohan Singh 122/J	While posted in Police Lines he absented himself without proper permission and excuse on various occasions.	No
129	S.I. Harbhajan Singh 417/LDH	While posted at police station Sadar he investigated case F.I.R. No. 118/62 under section 302 I.P.C. Police station Sadar During its trial in the Sessions Court, serious strictures were passed against him	No
130	S.I. Jagjit Singh, 168/J ..	The D.I.G./JR had remarked on the inspection report of police station Mahilpur for the quarter ending 30th September, 1963 that the Inspection Report depicts a disappointing reading and the working of the police station was thoroughly unsatisfactory	No
131	A.S.I. Amar Nath, 448/KGR	The alleged misconduct on his part was that he failed to deal expeditiously with cases pending with him at the time of his transfer from City Hoshiarpur	No
		LUDHIANA DISTRICT	
132	S.I. Manmohan Singh, 14/J	For burking of cognizable cases while posted as S.H.O., Sahnewal, district Ludhiana	Yes
133	S.I. Babu Ram, No. 321/KGR	Was arrested in case F.I.R. No. 47, dated 23rd April, 1964 under section 376 I.P.C., police station, Sahnewal	Yes
134	S.I. Santokh Singh, No. 2959/PTL	For not registering a case under section 457/380 I. P.C., while he was posted as S.H.O. police station Raikot	No
135	A.S.I. Gurcharan Singh No. 63/LDH	For having been found travelling in a bus No. 4912 without ticket and not paying the passenger tax	No
136	A.S.I. Rajinder Lal, No. 597/LDH	For registering a false case under section 9/1/78 Opium Act, F.I.R. No. 150, dated 28th September, 1963, police station, Raikot against Labh Singh of Sarabha	No
137	A.S.I. Shamsher Singh, No. 129/J	For overstaying from leave ..	No

Serial No.	Name, rank and number of police officer	Allegations/Reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
138	A.S.I. Roshan Lal, No. 575/LDH	Arrested in case F.I.R. No. 264, dated 23rd February, 1965 under section 5/2/47, P.C, Act police station City Kotewali Ludhiana	Yes
	JULLUNDUR DISTRICT		
139	S.I. Jaswant Rai, 113/J ..	For fabricating evidence and for corruption in case F.I.R. No. 190/63, under section 302/34 I.P.C., police station, Kartarpur	Yes
140	A.S.I. Khushal Singh, No. 55/HPR	For his failure to make discrete enquiry regarding antecedents of Krishan Kumar, son of Shri Ram, who had applied for passport	Yes
141	A.S.I. Ram Parkash No. 524/HPR	He accepted Rs 150 from one Amar Singh, Karinda of Excise Vendor of Apra	Yes
142	S.I. Darshan Singh, No. 136/J	While conducting a raid at village Apra, he recovered a bag of poppy husk from the possession of one Amar Singh, Karinda of Excise Vendor of Apra. The quantity of poppy husk was reduced and one Malkiat Ram Adharmai was challaned instead of aforesaid Amar Singh	Yes
143	S.I. Mukhtiar Singh, No. 47/J	For not registering a case in time, while posted as S.H.O. Nurmahal	No
144	A.S.I. Narsingh Dass, 398/ HPR	He was given medico legal report of one Babu of village Bilga by S.I. Mukhtiar Singh S.H.O. Nurmahal, but he did not register the case in time	No
145	A.S.I. Des Raj, 237/Jull. ..	Ditto	No
146	A.S.I. Harbans Lal, 149/ Jull	He kept the illicit liquor in the pitcher and did not transfer it to the bottles or tins. As a result of his negligence, the illicit liquor in the pitcher leaked or got dried	No
147	A.S.I. Shamsher Singh, No. 129/J	He put pressure on one Mukhtiar Kaur to compromise with one Surjit Kaur of Bahain, police station Banga	No
148	A.S.I. Charan Dass, No. J/73	He failed to prepare inquest report of one headless dead body, while he was informed by one Gurmukh Singh. He contravened the provision laid down in P.R. 25.31 and 25.33	No
149	A.S.I. Harbans Lal, 132/ B/2/J	He accepted Rs 50 from one Parkash at Minto for booking a seat by air for him	No
150	A.S.I. Jagir Singh, 110/J ..	For not investigating the case carefully and also not thoroughly interrogated the accused in case F.I.R. No. 47, dated 7th April, 1963 under section 307, I.P.C., police station, Dehlon district Ludhiana	No

Serial No.	Name, rank and number of police officer	Allegations/Reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
151	S.I. Raj Kumar Singh, No. 1/J	For not performing his duty satisfactorily, while posted as S.I. Security	No
152	A.S.I. Wattan Singh, 108/J	He removed 2 blank sheets forms from the Daily Diary Register, while posted at police station Banga	No
		(ii) He accepted illegal gratification in case F.I.R. No. 262/62, under section 376 I.P.C. police station Banga	
		(iii) For submission of case diaries with inordinate delay	
153	S.I. Mukhtiar Singh 47/J	Was found negligent in performance of his duties, while posted as S.H.O., Nurmahal and misbehaved with one Joginder Singh	No
154	A.S.I. Kartar Singh, No. 25/J	Strictures were passed against him by High Court	No
155	S.I. Kidar Nath, No. 74/J	Lack of supervision, while posted as S.H.O. Adampur	No
156	A.S.I. Ram Parshad, No. 543/HSR	Wrong verification of passport racketeers	No
157	S.I. Darshan Singh, No. 136/J	Clothing articles were found short in clothing godown during audit, while posted as Lines Officer, Ludhiana	No
158	S.I. Akal Sewak Singh ..	For deliberately avoiding the arrest of passport racketeer in case F.I.R. No. 41, dated 19th February, 1964 under section 419/420 I.P.C., police station, Ajnala	No
159	S.I. Bhajan Singh, No. 178/A	He took with him C. Charan Singh while proceeding on leave	No
		KANGRA DISTRICT	
160	A.S.I. Kundan Lal, No. 97/J	For not doing enough work according to his rank and experience, both in the prevention and detection of crime against property as well as in excise or in investigation of cases	No
161	S.I. Partap Singh, No. J/19	For trying to rake up public agitation in order to get his transfer cancelled	No
162	S.I. Partap Singh, No. J/19	For failing to prevent and detect crime, while posted as S.H.O. police station Jawalamukhi	No
163	P.A.S.I. Gurdev Singh, No. 188/J	For taking undue advantage of his official position in having a forced free lift in loaded truck	Yes

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
164	P.S.I. Bahadur Chand, J/104	For causing injuries to Rattan Lal, an accused in case F.I.R. No. 67/73 under section 4.09/467, I.P.C., police station Kangra	No
165	S.I. Sewa Singh, No. J/26		
166	A.S.I. Kundan Lal, 102/J		
167	A.S.I. Gurcharan Singh, No. 239/LDH	For his failure to take prompt legal action in a criminal case and gross neglect and disregard to the discharge of duties	No
168	A.S.I. Nasib Chand, No. 46/Jull	For misconduct regarding his association with bad characters and for fraudulently and deceitfully calling Mst. Phullan Wanti from her in-laws and entrusting her to her mother, with whom he was in league with against he wishes of her husband	Yes
169	A.S.I. Nasib Chand, No. 46/Jull	For indulging in misconduct and irregularities during the course of investigation of case F.I.R. No. 17 and 19, dated 24th May, 1964, under section 61/1/14 Excise Act, police station Sujanpur, district Kangra	No
170	A.S.I. Niranjan Singh, No. 281/Jull	For dereliction of duty in making an enquiry on the complaint of one Bhumi Chand of Nagerh, while posted at police station Palampur	No
171	A.S.I. Harnam Singh, No. 140/KGR	For pushing womenfolk and not taking legal action against them for obstructing the Police in the discharge of duty, in the course of investigation of case No. 17 and 19, dated 24th May, 1964, under section 61/1/14, Excise Act, police station Sujanpur	No
172	S.I. Kishan Chand, No. J/119, Head Clerk, office of the Superintendent of Police, Jullundur	For receiving Rs 43.45 nP. as Dearness Allowance and Hill Allowance fraudulently and irregularly	No
		KAPURTHALA DISTRICT	
173	A.S.I. Mukhtiar Singh, No. 186/ASR	While posted to police station Phagwara, he obtained 5 days casual leave on the pretext of some urgent work from the D.S.P., Kapurthala, while the S. P., Kapurthala, was away from the district. He did not avail the leave then and proceeded on leave after a lapse of about 2 months without getting it approved or renewed by the Superintendent of Police	No
174	A.S.I. Joginder Singh, No. 112/J	He while posted to police station Phagwara delayed the investigation of case F.I.R. No. 6/64 under section 9/1/78, Opium Act, inordinately	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
175	A.S.I. Raghbir Singh, No. 423/KGR	For drawing the Horse allowance on a false receipt	No
176	S.I. Harnek Singh, No. 38/J	While posted to police station Phagwara, he was found negligent in that he detected 2 cases under section 61/1/14, Excise Act, police station Phagwara on 27th April, 1964, but failed to submit case diary till 27th July, 1964	No
177	S.I. Harnek Singh, No. 38/J	While posted to police station Phagwara, he was found negligent in that he sent samples in cases F.I.R. Nos. 222 and 223 under section 9, Opium Act and F.I.R., No. 200 under section 61/1/14 to Chemical Examiner, Patiala, after a considerable delay	No
178	S.I. Balwant Singh, No. J/77	He failed to take effective preventive action as a result of which one Sarwan Singh of village Moranwali, police station Garhshanker, district Hoshiarpur, was murdered by his opponents	No
179	A.S.I. Mukhtiar Singh, No. 206/ASR	For having been arrested in case F.I.R. Nos. 57 and 58 under section 342/377/511 I.P.C. and 448, I.P.C., police station Phagwara	Yes
180	S.I. Jaginder Singh, No. 132/J	While posted as S.H.O., Bholath, he registered a false case against Kartar Singh of village Bassi, police station Bholath, under section 182/232/353/506, I.P.C.	Yes
		WIRELESS SECTION	
181	A.S.I. Sushil Kumar, No. 99/C	(i) For committing grave misconduct in suppressing the fact of his previous employment as a clerk in the Textile Mills, Hissar, during the period of his dismissal from Police Radio Section (ii) For making unsubstantiated allegations against a superior officer before the Vigilance Department (iii) For submitting application direct to higher authorities using therein intemperate language against S.P. (W)	No
		KEYLONG DISTRICT	
182	S.I. Ram Lal, No. 140/J	For claiming false T.A. ..	No

Serial No.	Name, rank and number of Police officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
		GURDASPUR DISTRICT	
183	A.S.I. Khushwant Singh, No. 1695/ASR	He, while posted to police station Majitha, district Amritsar, arrested one Joginder Singh from whose possession 4 bottles of illicit liquor were recovered. He got a case under section 61-1-14, E. Act, registered against him. While appearing as P.W. in the above-said case in the court of M.I.C., Amritsar, he gave incorrect time of the raid. This resulted in the acquitted of the censure	No
184	A.S.I. Joginder Singh, No. 183/B	While posted as Officer-in-Charge, police station Dera Baba Nanak, he failed to register a case under section 325/34, I.P.C., deliberately	No
185	A.S.I. Bachan Singh, No. 237/B	(i) Having failed to take preventive action against two party factions of village Ghot Pokhar, when directed by the D.S.P./H, which resulted in the occurrence of a hurt case (ii) He did not maintain his pony at the place of his posting and kept it in village Gharala and Tung and drew pony allowance without actually maintaining the pony at his own cost	No
186	A.S.I. Charanjit Singh, No. 136/B	For delaying the investigation of case F.I.R. No. 26, 58, 65 and 67 of 1964, while posted at police station Kalanaur and for not taking due interest in discharge of his Government duties	Yes
187	S.I. Tara Chand, No. 100/B	He had taken a bribe in a case in which a 10 years old boy was crushed under a jeep near village Anandgarh in police station Muktsar, district Ferozepur	No
		AMRITSAR DISTRICT	
188	A.S.I. Tara Singh, No. 104/ASR	For having been arrested in case F.I.R. No. 40, dated 6th March, 1964, under section 304, I.P.C., police station Bhikhiwind	Yes
189	A.S.I. Piara Lal, No. 173/FZR	For having accepted illegal gratification in case F.I.R. No. 254, dated 4th December, 1964, under section 364, I.P.C., police station Civil Lines, Amritsar	Yes
190	S.I. Sajjan Singh, 40/B ..	Regarding serious discrepancies in the statements of S.I. Sajjan Singh and A.S.I. Harnam Singh for handcuffing of Shri Makhan Singh Tarsikka, M.L.A.	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegtions/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
191	S.I. Ram Rachhpal Singh, 78/B	Complaint of corruption while posted in Foreigners Staff, Jullundur	No
192	S.I. Sajjan Singh, 40/B ..	For unnecessarily delaying the investigation of cases, while posted as S.H.O., police station Jandiala	No
193	S.I. Bawa Singh, 79/B ..	For writing an objectionable report against his senior officer in the daily diary, while posted as S.H.O., police station Ajnala	No
194	S.I. Man Singh, 28/GSP	Strictures were passed against him by Shri Sant Singh, M.I.C./Amritsar, in case F.I.R. No. 146/63, under section 9/1/78, Opium Act, police station A Division	No
195	S.I. Sajjan Singh, 40/B ..	Complaint regarding false registration of case F.I.R. No. 11/62 under section 506, I.P.C., police station Jandiala	No
196	Ditto	For not taking legal action on the report made by Shri Inder Singh of Thathian regarding injuries inflicted on him with sharp and blunt weapons by Dalip Singh, etc.	No
197	Ditto	For not registering a case till Jamadar Makhan Singh appeared before S.S.P. Amritsar, after which case F.I.R. No. 94, under section 324/427/148/149 I.P.C. was got registered by D.S.P./H.	No
198	S.I. Gurbux Singh, 106/B	Regarding complaint from Sodhi Tarlok Singh of Jalalpura that S.I. threatened him to involve him in a false case	No
199	A.S.I. Harpal Singh, 38/PTL	For showing wilful neglect in discharge of his duties and not taking proper care and caution before giving evidence in court in case F.I.R. No. 113/64, under section 19/11/78, Arms Act, police station City Tarn Taran	No
200	A.S.I. Chan Parkash, 41/GSP	For travelling without ticket	No
201	A.S.I. Pritam Singh, 2/GSP	Strictures were passed against him by Shri T.R. Ghuman, M.I.C., Amritsar, in case under section 61/1/14 Excise Act, police station Sadar Amritsar	No
202	A.S.I. Niranjan Singh, 571/ASR	Regarding complaint from Shri Chanchal Singh, son of Tara Singh of village Kot Kesra, police station Ramdas that he might be involved in a false case by the defaulter A.S.I.	No
203	A.S.I. Hari Chand, 388/FZR	Strictures were passed against him in case F.I.R. 86/62 under section 302/364, I.P.C., police station Sadar Amritsar	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
204	A.S.I. Niranjan Singh, 571/ ASR	For not registering a case regarding the theft of mare belonging to Lakhbir Singh, Sarpanch of village Bhim	No
205	A.S.I. Tara Singh, 104/ASR	For accepting Rs 100 as illegal gratification from Shri Didar Singh	No
206	A.S.I. Shanker Singh, 235/B	For delaying unnecessarily 21 challans of Excise Act while posted at police station Verowal	No
207	A.S.I. Sain Dass,1095/ASR	For detaining a girl, who gave birth to an illegtimate child for investigation from 9th February, 1964 to 11th February, 1964	No
208	A.S.I. Baldev Raj, 1423/ ASR	Burking a case F.I.R. 159/63 under section 457/380 I.P.C., police station Beas	No
209	Ditto	For not taking action on the report of Shri Joginder Singh and Udham Singh	No
210	A.S.I. Karnail Singh, 369/ FZR	Regarding showing gross carelessness and negligence in case F.I.R. No. 64/64, under section 307/148,149 I.P.C., police station Ajnala	No
211	A.S.I. Tara Singh, 104/ASR	Strictures were passed against him in case F.I.R. No. 182/63 under section 25/54/59 Arms Act, police station Lopoke	No
212	A.S.I. Joginder Singh, 183/B	For taking air gun from one Sowarn Singh in case F.I.R. 74/61, under section 304 I.P.C., police station Jandiala and misappropriated the same for his personal use	No
213	Ditto	Allegation of corruption, while posted at police station Jandiala	No
214	A.S.I. Jai Singh, 173/ASR	For delaying case J F.I.R. Nos. 22, 23, 38, 86 and 186/64	No
215	A.S.I. Kartar Singh, 379/ FZR	Strictures were passed against him by Additional Sessions Judge in case F.I.R. 218/61, under section 302/148/149/120-B, police station Beas	No
216	A.S.I. Bhag Singh, 368/ASR	Allegations of Corruption	No
217	A.S.I. Shanker Singh, 235/B	He did not send sample in case 194/204/63 under section 61/1/14 Excise Act, while posted at police station Verowal	No
		FEROZEPORE DISTRICT	
218	A.S.I. Amrik Singh, 306/ ASR	For acting in a very irresponsible manner and in gross negligence of instructions issued,—*vide* I.G's. Memo No. 22694-733/A, dated 17th November, 1960, in the execution of warrant issued under section 408/379 I.P.C. for the recovery of Mst. Mehran Bai from village Shajrana, police station Sadar Fazilka	Yes

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
219	A.S.I. Harcharan Singh, No. 1501/ASR	For pertisan behaviour and abuse of authority, while registering a case F.I.R. No. 57, dated 29th April, 1964 under section 379 I.P.C., police station Zira	Yes
220	A.S.I. Pritam Singh, No. 641/GSP	For being arrested in case F.I.R. No. 4, dated 9th January, 1964 under section 5/2/47 P.C. Act, police station Khuyan Sarwar for accepting Rs 60 as illegal gratifications	Yes
221	A.S.I. Jaswant Singh, No. 393/FZR	For getting drunk in Government premises and also keeping a women of ill-repute in his quarter	Yes
222	A.S.I. Amar Nath, No. 798/FZR	For not properly investigating a case under section 354/506 I.P.C.	No
223	S.I. Ajmer Singh, No. 138/B	For gross negligence in investigation of case under section 302/I.P.C.	No
224	A.S.I. Saudagar Singh, No. 1268/ASR	For accepting illegal gratification	No
225	A.S.I. Kundan Singh, No. 437/ASR	He wrongly registered and investigated a case under section 19/11/78 Arms Act	No
		BHATINDA DISTRICT	
226	A.S.I. Sukhdev Singh, No. 1404	For negligence shown by him in discharging of his official duties, while posted as Accountant D.P.O., Patiala	No
227	S.I. Gurdev Singh, PR/67	For having failed to register a case when Gurdev Singh, son of Dulla Singh of Talwandi Sabu reported in police station Raman regarding theft of his cycle along with other articles	No
228	A.S.I. Kirpal Singh, No. 378	For disobeying the orders of S.D.M. Faridkot in a function at Faridkot	Yes
229	A.S.I. Inder Singh, No. 10/PR	For connecting a false story regarding the arrest of the accused and recovery of a ring in case F.I.R. No. 78, dated 12th February, 1963 under section 302 I.P.C., police station Mansa	No
230	S.I. Bas Dev, No. 104/PR	For the preparation of false recovery memos and case diaries, etc. in case F.I.R. No. 10, dated 7th March, 1963 under section 302 I.P.C., police station Maur	No
231	S.I. Balwant Singh, No. 88/PR	For defective investigation of case F.I.R. No. 37, dated 24th March, 1964 under section 5(2) P.C. Act, police station Budhlada	No
232	A.S.I. Nand Kishor, 202/PR	For their failure to execute a warrant in respect of Ajaib Singh retired D.S.P. issued by S.D.M., Faridkot	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whethe r suspended or not
1	2	3	4
233	A.S.I. Kartar Singh, 386/FZR	For their failure to execute ..	No
234	A.S.I. Parshotam Dass	Ditto	No
235	S.I. Abnash Chander, No. 154/PR	For criminally assaulting and committing a rape on Mst. Joginder Kaur, w/o Mehar Singh of village Baluana	Yes Both the A.S.Is. were only suspended
236	A.S.I. Hardial Singh, 2016/ SGR		
237	A.S.I. Harnarain Singh, No 2177/SGR		
238	S.I. Shamsher Singh, No. 112/PR	For minimising the offence in case F.I.R. No. 17, dated 1st February, 1964 under section 302/34 I.P.C., police station Mansa	No
239	S.I. Kartar Singh, No. 32/ PR	For not depositing the case property of case F.I.R. No. 170, dated 16th September, 1963 under section 302/34 I.P.C., police station Sardulgarh in the Malkhana on the same day of recovery	No
240	S.I. Iqbal Singh, No. 159/ PR	For not registering a case of theft	No
241	A.S.I. Swarn Singh ..	..	...
242	A.S.I. Gian Singh, No. 608/ BTI	For not maintaining the cash book properly while posted as a cashier in Police Lines, Bhatinda	No
243	A.S.I. Karam Singh, No. 79/ PR	For taking illegal gratification in case F.I.R. No. 11, dated 21st January, 1963, under section 460/302 I.P.C., police station Sardulgarh	Yes
244	S.I. Amarjit Singh, No. 265/ PR	For not registering a case under Section 385 I.P.C.	Yes
245	A.S.I. Jasved Singh, No. 2052	For having failed to adequate action in preventing the occurance of a murder case	Yes
246	S.I. Bas Dev, 104/PR ..	For recording the F.I.R. with delay in case F.I.R. No. 9, dated 7th February, 1963, under Section 302 I.P.C., police station Maur	No
247	S.I. Shamsher Singh, No. 112/PR	For not carefully arranging the police raid which might have avoided the death of Baldev Singh, son of Jit Singh of village Raipur, police station Mansa	No
248	S.I. Kalwant Rai, No. 80/ PR	For not registering the case immediately when one Sham Lal, Harijan of Maur reported in police station, Maur, about the abduction of his minor girl Mst. Vidya	No
249	A.S.I. Karnail Singh, No. 4655	Ditto	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
250	A.S.I. Kartar Singh, No. 386/FZR	Case under Section 5(2) P.C. Act, police station Kotwali, Faridkot	Yes

Note.—Also see serial No. 307 at page 23.

SANGRUR DISTRICT

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
251	S.I. Om Parkash, 199/PR	Case F.I.R. 83/64, under section 325/452/342/506/211/380, I.P.C. and 61 Ex. Act, police station Narwana	Yes
252	A.S.I. Zile Singh, 12/PR	Case F.I.R. No. 107/64, under Section 5(2), P.C. Act, police station Barnala	Yes
253	A.S.I. Santa Singh, 193/PR	Case F.I.R. No. 313/64, under Section 5(2) P.C. Act, police station City Rohtak	Yes
254	A.S.I. Karam Dev, 13/PR	Private complaint under Section 323/342, I.P.C.	Yes
255	A.S.I. Jagjit Singh, 3241	For levelling false allegations against D.S.P./Headquarters	Yes
256	A.S.I. Harikishan Lal, 192/PR	Found asleep on Nakabandi point	Yes
257	A.S.I. Charan Singh, 49/PTL	For making false entries in DD. register of police station Mahal Kalan	Yes
258	S.I. Bhag Singh, PR/47	For not arresting accused of case F.I.R. No. 191/63, under Section 307, I.P.C., police station Payal	No
259	S.I. Harbans Singh, 72/PR	Strictures were passed against him in case F.I.R. No. 71/63, under Section 302/201, I.P.C., police station Bhawanigarh	No
260	S.I. Rajinder Singh, No. 176/PR	For grave misconduct in the investigation of case F.I.R. No. 40/63, under Section 61, Excise Act, police station Mahal Kalan	No
261	S.I. Bhag Singh, PR/147	Negligence in the investigation of case F.I.R. No. 74, 82, 98 of 1963, under Section 457/380, I.P.C., police station Payal	No
262	Ditto ..	Paid a flying visit to the place of occurrence and went to Ludhiana without permission in a private car	No
263	Ditto ..	For not taking timely preventive action in case F.I.R. No. 16/64, under Section 302/34, I.P.C., police station Payal	No
264	S.I. Piare Lal, PR/12	For irresponsible attitude, carelessness and negligence	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
265	S.I. Piare Lal, PR/12 ..	For spoiling case under Section 325/34, I.P.C., police station Longowal	No
266	S.I. Bhag Singh, PR/147	For drinking and misbehaviour with public	No
267	S.I. Surjit Rai ..	Negligence in case F.I.R. No. 146/63, under Section 9, Opium Act, police station Dhanaula	No
268	A.S.I. Pritam Singh, 775/A	Faulty investigation of case F.I.R. No. 6/61, under Section 300/307/149/I.P.C., police station Julana	No
269	A.S.I. Harikishan Lal, 192/PR	Strictures were passed against him by Sessions Judge, Sangrur in case F.I.R. No. 71/63, under Section 302/201, I.P.C., police station Bhawanigarh	No
270	A.S.I. Ram Sarup, 736/BTI	For not registering a case under Section 363/366, I.P.C., police station Ghagga	No
271	Ditto ...	For grave misconduct and not registering a case under Section 447, I.P.C.	No
272	Ditto ..	For travelling without ticket	No
273	Ditto ...	For keeping buffaloe in police premises without permission	No
274	A.S.I. Hardev Singh ...	Negligence in case F.I.R. No. 162/63, under Section 302, I.P.C., police station Sunam	No
	MOHINDERGARH DISTRICT		
275	A.S.I. Harbans Singh ..	For misbehaviour with public under influence of liquor	Yes
276	S.I. Naunidh Rai, No. PR/85	He appeared before the Chief Minister, Punjab, without obtaining the permission of the department	No
277	A.S.I. Gurdip Singh, No. 30	While he was posted to police station Kaniana, he was deputed to dispose of an application under Section 107/151, Cr. P.C., but he failed and both the parties started quarreling in the presence of A.S.I.	No
278	A.S.I. Nahar Singh, No. 121/H	For curruption	No
279	A.S.I. Hazura Singh, 3666	While posted as S.H.O., police station Kaniana, he had made changes in Death and Birth Register of the police station	No
280	A.S.I. Babu Ram, No. 111	He was detected while travelling without ticket in a local bus by Chief Minister's flying squad	No

Serial No.	Name, rank and number of Police officer	Allegations/reasons	Whether suspened or not
1	2	3	4
		PATIALA DISTRICT	
281	S.I. Chuni Lal, PR/24 ..	For late registration of case of abduction of two boys, while posted as S.H.O., police station Lalroo	No
282	S.I. Rajinder Singh, 4/PR	For illegal detention of Smt. Gurdial Kaur, resident of village Raungla, police station Sadar, Patiala	No
283	S.I. Gurdev Singh, 111/PR	For not carrying out investigation of case F.I.R. No. 228/63 under Section 379, I.P.C., police station Samana	No
284	S.I. Sita Ram (now A.S.I.) 55/PR	For trying to implicate a false case against one Tehail Singh on the complaint of Chanan Singh, son of Mehar Singh, resident of village Mohampur, police station Julkan	No
285	S.I. Jaswant Singh, PR/41	For leaving Police Lines without making an entry in the Daily Diary	No
286	S.I. Rajinder Singh, 4/PR	For not taking up investigation of case F.I.R. No. 179 and 183, etc.	No
287	S.I. E.M. Massey, PR/4	For not taking action and delaying registration of case on the complaint of one Chhaju Singh	No
288	S.I. Inder Singh, 10/PR	For defective investigation of case F.I.R. No. 78/63, under Section 302, I.P.C., police station Mansa	No
289	S.I. Rajinder Singh, 4/PR	For failing to prepare case diaries in case F.I.R. No. 96, 97, 98, 100 and 104, under Section 61/1/14, police station Kot Sangrur	No
290	Ditto ..	For delaying registration of a case of theft of village Chalella, police station Mulepur	No
291	Ditto ..	For changing the roznamcha entries of police station Sadar, Patiala	No
292	S.I. Kuldip Singh, PR/16	For not checking of F.Cs. during the quarter ending 31st March, 1964, in police station Rajpura	No
293	S.I. Amarjit Singh, PR/84	For not taking preventive action on the complaints of one Pritam Singh, resident of Bhagwanpura against Jita Singh	No
294	A.S.I. Pritam Singh, 775/PTA	For delaying registration of a cognizable offence when posted in police station Julkan	No
295	A.S.I. Gurtej Singh, 681/BTI	For non-submission of case diaries in case F.I.R. No. 4/64, under Section 364, I.P.C., police station Kotwali, Patiala	No
296	A.S.I. Jagjit Singh, 26/PR	For delaying the investigation of case F.I.R. No. 127/57, under Section 61/1/14, police station Kharar	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
297	A.S.I. Bhup Singh, 31/PR	For not taking legal action on the application of Bhajan Singh	No
298	S.I. Bhag Singh, PR/47 ..	For not running police station, Payal, efficiently and for his poor out-put as S.H.O. and allegations of moral turpitude	Yes
299	A.S.I. Jarnail Singh, 751/PTA	For suffering the escape of accused negligently	Yes
		C.I.D.	
300	S.I. Jarnail Singh, No. 102/PR	While posted as A.S.I. Incharge of Police Post, Shutrana, Patiala District, he did not register a burglary case involving a loss of clothes worth Rs 6,000 on the complaint of Shri Chander Bhan, complainant, etc.	No
301	S.I. Sajjan Singh, No. 40/B	For submission of case diaries with delay and for keeping the challans of certain cases with him unnecessarily	No
302	S.I. Sajjan Singh, No. 40/B	While posted as S.H.O., Jandiala in Amritsar District, in the year 1962, he failed to register a case on the report of Shri Inder Singh, son of Narain Singh of village Thothian, police station Jandiala and thereby violated the provisions of section 154, Cr. P.C. and Police Rule 24.1	No
303	S.I. Sajjan Singh, No. 40/B	While posted as S.H.O., police station Jandiala District in the year, 1962, he with a motivated mind to help Shri Sadhu Singh of Jandiala, for getting possession of a disputed plot situated in Jandiala Town from Shri Hukam Singh, registered a false case F.I.R. No. 11, dated 10th January, 1962, under Section 506, I.P.C., against Hukam Singh, arrested him without making proper investigation and knowing it well that Shri Hukam Singh did not criminally intimidate Shri Sadhu Singh	No
304	S.I. Ranbir Singh, No. 85/A	While posted as S.H.O., Dharampur, he received a written complaint from one Jaswinder Singh, son of Mohinder Singh of Mandi Bahadurgarh (Ludhiana) and without verifying its contents he took action in stopping car No. DLE-670, belonging to step-mother of Jaswinder Singh, thereby caused unnecessary harassment and inconvenience to the occupants of the car, which was detained for nearly 4 hours at Kalka	No

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer	Allegations/reasons	Whether suspended or not
1	2	3	4
305	S.I. Ranbir Singh, No. 85/A	While posted as S.H.O., police station Assandh in district Karnal, he did not take prompt action in registering the case reported by one Jagir Singh, son of Phula Singh of village Ruksana, about the commission of a burglary in his house	No
306	A.S.I. Sadhu Ram, No. 1594/ASR	While posted in Security Staff, Nangal, he collected Rs 10 from certain police personnel every month in respect of C.T.D. Pass-Books, but did not deposit the amount regularly with the Post Office	No
	BHATINDA DISTRICT (SUPPLEMENTARY)		
307	S.I. Iqbal Singh, No. 159/PR	For not registering a case of burglary	No

STATEMENT NO. II

List showing the names of Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors, who have been reinstated from suspension during the period from January, 1964 to date

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer
1	2
	PUNJAB ARMED POLICE
1.	S.I. Kulwant Singh, No. PAP/144
2.	A.S.I. Sardara Singh, No. 255
3.	A.S.I. Sucha Singh, No. 356
4.	A.S.I. Charanjit Singh, No. 4562
5	A.S.I. Surjan Singh, No. 50
	GOVERNMENT RAILWAY POLICE
6.	S.I. Khushal Singh, No. R/6
7.	A.S.I. Niranjan Singh, No. 723/GRP
	HISSAR DISTRICT
8.	S.I. Chuni Lal, No. 153/A
9,	S.I. Sohan Lal, No. A/16

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer
1	2
	AMBALA DISTRICT
10.	S.I. Gurnam Singh, No. 240/A
11.	S.I. Harbachan Singh, No. 30/A
12.	S.I. Madan Lal, No. A/90
13.	A.S.I. Madan Lal, No. 232/GGN
14.	A.S.I. Jagat Singh, No. 35/UMB
	KARNAL DISTRICT
15.	A.S.I. Om Parkash, No. 199/A
16.	S.I. Ram Pat, No. 212/A
17.	S.I. Gian Singh, No. 25/A
18.	A.S.I. Sampuran Singh, No. 406/Hissar
	LUDHIANA DISTRICT
19.	S.I. Babu Ram, No. 321/Kgr.
	JULLUNDUR DISTRICT
20.	S.I. Jaswant Rai, No. 113/J
21.	A.S.I. Khushal Singh, No. 55/HPR
22.	A.S.I. Ram Parkash, No. 524/HPR
23.	S.I. Darshan Singh, No. 136/J
	KANGRA DISTRICT
24	A.S.I. Gurdev Singh, No. 188/J
25	A.S.I. Nasib Chand, No. 46/Jull.
	KAPURTHALA DISTRICT
26.	A.S.I. Mukhtiar Singh, No. 206/ASR
27.	S.I. Joginder Singh, No. 132/J
	GURDASPUR DISTRICT
28.	A.S.I. Charanjit Singh, No. 136/B
	AMRITSAR DISTRICT
29.	A.S.I. Tara Singh, No. 104/ASR
	FEROZEPUR DISTRICT
30-	A.S.I. Amrik Singh, No. 366/ASR

Serial No.	Name, rank and number of Police Officer
1	2
31.	A.S.I. Harcharn Singh, No. 1501/ASR
32.	A.S.I. Pritam Singh, No. 641/GSP
33.	A.S.I. Jaswant Singh, No. 393/FZR
	BHATINDA DISTRICT
34.	A.S.I. Kirpal Singh, No. 378
35.	A.S.I. Hardial Singh, No. 2061/SGR
36.	A.S.I. Harnarain Singh, No. 2177/SGR
37.	A.S.I. Karam Singh, No. 79/PR
38.	S.I. Amarjit Singh, No. 121/PR
39.	A.S.I. Jasdev Singh, No. 2052
	SANGRUR DISTRICT
40.	S.I. Om Parkash, No. 199/PR
41.	A.S.I. Harikishan Lal, No. 192/PR
42.	A.S.I. Charan Singh, No. 49/PTL
	MOHINDERGARH DISTRICT
43.	A.S.I. Harbans Singh, No. 2312
	PATIALA DISTRICT
44.	S.I. Bhag Singh, No. PR/47
45.	A.S.I. Jarnail Singh, No. 751/PTL

COMMUNICATION FROM A LEGISLATOR OF KARNAL TO D.C. Karnal

2425. Comrade Ram Piara: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Deputy Commissioner, Karnal received any letters/communications from any Legislator of Karnal District during the period from 1st August, 1964 to date complaining about the unlawful possession of the lands of the Sadhus in Karnal city near Abrahim Mandi (the place known Dera Beri Wala Bagh); if so, a copy of each be laid on the Table of the House;

(b) whether he himself also received any communication from the said Legislator on the said subject during the month of September, 1964; if so, a copy thereof along with a copy of their reply, if sent, be laid on the Table of the House;

(c) whether any reply to the communication referred to in part (a) above was sent by the Deputy Commissioner, Karnal to the said Legislator during the said period; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House;

(d) whether it is a fact that the Deputy Commissioner, Karnal referred the enquiry to the Police; if so, when and a copy of the enquiry report, if any, received by Deputy Commissioner from the Police be laid on the Table of the House;

(e) whether the said Deputy Commissioner, wrote any letter or sent any reply to the higher authorities in Chandigarh; if so, the details thereof;

(f) whether the enquiry into the complaints referred to in part (a) above was conducted by the General Assistant, Karnal; if so, the details and broad features of the report submitted by him in this respect;

(g) whether any final action/decision has been taken so far on the report referred to in part (f) above if so, the details therof?

Sardar Harinder Singh Major: (Revenue Minister) (a) Yes; relevant copies are placed on the Table of the House.

(b) Yes; a copy of the reply given is placed on the table of the House.

(c) Yes; a copy of the reply given is placed on the Table of the House

(d) Yes; a copy of the Police enquiry is placed on the Table of the House.

(e) Yes; it related to the possession of some land at Karnal.

(f) The matter was looked into by the General Assistant, Karnal and it appeared to involve issues of civil nature.

(g) A reply has duly been se .t to the representationist suggesting him to contest the case in a civil court.

Copy of a letter, dated the 7th November, 1964, from Comrade Ram Piara, M.L.A., Karnal, to the Deputy Commissioner. Karnal.

Subject.—Representation of Swami Krishna Nand.

I am in receipt of the copy of letter No. 8145, dated the 5th November, 1964, addressed to Swami Krishna Nand of Karnal, regarding Bagh Beriwala in which you have been pleased to mention the detailed inquiry by G. A.

I am happy that you and Government has come to the conclusion that the title of this land is under dispute but I do not agree with your this finding that the case is of civil nature. Supposing one person in collusion with the Patwari and Revenue staff cheats the other and gets falsely revenue record recorded in his name and further when the aggrieved cries for justice, the administration because indifferent, what the poor fellow should do. I understand that it is fit case of cheating and 420 against the persons in possession of land, against the revenue authorities and further against the person who went with arms to get the site vacated and which was vacated. I do not want to presume that the administration is meant for the help of aggressors or cheats but for the aggrieved. Do you not agree that it is a clear cut fraud played with the helpless Sadhus ? As regards the inquiry by the G. A., I am sorry to point out that this inquiry took many months and the idea behind this delay was to afford time to the unauthorised occupants and I have no hesitation in saying that if you look to the dates fixed, you will be convinced that G. A. was acting as an Agent of the unauthorised. In fact Shri Nishan Singh was and is a party and the unauthorised person is his partner in his Brick-kiln business. In Kairon time how this revenue staff could dare against the wishes of that particularly when D. C. and G. A., of that time were openly acting as his supporters.

Hence I assert that there is a clear fraud and when the case is registered, the unauthorised occupants will have to prove, how Girdawari was entered in their name when they were neither leased out nor gifted, nor sold, nor they became the followers. It is a simple problem, I wonder how you have referred to the civil side. Hoping to be favoured with a line in reply and oblige.

Copy of a letter, dated the 3rd December, 1964, from Comrade Ram Piara, M.L.A., Karnal, to the Deputy Commissioner, Karnal.

Subject.—Land of Sadhus-Dera Beriwala now under forcible possession by ousting the Sadhus.

I want to draw your attention towards my letter, dated 7th November, 1964 which I wrote to you immediately after the receipt of your letter No. 8145/CEA., dated 5th November, 1964 in respect of application of Swami Krishna Nand of Karnal.

As I have not heard anything from you so am enjoying an opportunity to remind you.

Just possible that you might have either written or talked to S. P., or he on his own initiative on the representation submitted to him, visited the spot and asked both the parties to produce their positive proofs.

He will be in a better position to tell you the facts brought to his notice but unless I receive anything positivei n writing, I cannot comment, but may urge upon you that Girdawari stands in the name of others than Sadhu (now in possession) after 1957 or so but the Sadhu had been in possession till 1963.

They have proofs and signatures of the officers that they represented to them in May, 1963 about the high handedness they were facing.

Besides this, the Pattedar Puran Singh and his brother Deep Chand were denvolved in a bogus case at Batala, district Gurdaspur and they were forced to leave the land under all possible pressure, rather below the belt.

It was a criminal conspiracy between the persons in possession and the revenue authorities. Moreover, it is yet to be seen, how they took possession. Hence it is a serious matter. The party in possessed on can spend anything for keeping this land with them because the land is not less than of Rs one lakh. It is therefore, again requested that immediate steps be taken to get this land vacated and action against the conspirators. May I expect a line in reply.

Thanking you.

Copy of letter, dated 10th/12th December, 1964 from Comrade Ram Piara, M.L.A., Karnal, to Shri R. C. Kapila, I.A.S., Deputy Commissioner, Karnal.

Subject.—Representation of Swami Krishna Nand.

Dear Sir,

Please refer to your letter No. 8694/CEA, dated 2nd December, 1964 received by me on 9th December, 1964.

I have noted the contents carefully but with great surprise. It appears to me that I have not been able to clear my view point otherwise you must have appreciated.

You have written that disappearance of the name of Bhagwana Dass from the Revenue Records can be on account of some mutual deal between Bhagwan Dass deceased and Dewan Chand, etc.

May I know, whether and document on mutual deal has been produced or seen by the Enquiry Officer, if so, what are its contents, if not, how do you presume so. Why they are feeling shy in presenting that document which lead to the Enquiry Officer as a mutual deal and on that basis to you.

For your information, I may say, the property is not less than one lakh rupees.

Again the name of Bhagwan Dass has not totally disappeared but in 1/4th is there in 1956-57 when for the 1st time Dewan Chand and Raghbir Singh appeared on the scene. Is Bhagwan Dass or any other in possession of 1/4th today ?

Then Puran as Patedar of the Sadhus has been in cultivation till 1963 when he and Deepa, his other, were involved in a bogus case at Batala by this party which in conspiracy with the Revenue authorities had girdawaris in their name.

On return from Batala through one mischief or the other they were forced to surrender the possession to Shri Dewan Chand Raghbir Singh, etc., can we call it a fair play and mutual deal between Dewan Chand and Bhagwan Dass.

Now you say that statement does not mention the force used by Dewan Chand or Nishan Singh as the person with whose support, the land in question is alleged to have been occupied by Dewan Chand etc., illegally. Mr. Kapila, this was the Kairon Regime and Nishan Singh was considered to be a little Hitler in some of the circles. The complainant at that time did not approach me otherwise there would have been no delay. The Sadhus, at that time in possession of the Samadhis could not dare resist and so ran away. Swami Krishna Nand became a complainant at a later stage. Therefore, how, he could say that he was threatened.

Now what could be an agreement between the Sadhus and Dewan Chand etc. ? The property was not the ownership of any individual Sadhu but a Dera for the Sadhu Dharam Astan. Who could be a fool to leave this property of one lakh unless he was threatened for dire consequences as Puran and Dalipa faced a case in Batala. Only an enquiry into the antecedents of Batala bogus case will prove the mala fide.

Then I shall suggest that call for the approved plans submitted by the house owners (just adjacent to this land) submitted by them to the Municipal Committee , Karnal at the time of construction of their houses . You will find in cases, written Dharam Asthan while mentioning the boundaries of their houses.

This is a Dharam Asthan and it can only be a Dharam Asthan for the common use of the people and not for any individual and that too a property of one lakh free of cost, simply because the Revenue Machinery could not say "No". to these........new entrants without the least justification. The wrong done by the Revenue Staff and pointed out a little late, cannot become a universal truth.

As regards Nishan Singh, I am only to say that Shri Kairon attached two Brick-Kiln to this firm, one in the name of Shri Surat Singh, Joginder Singh father and other in the name of Pritam Singh Nilokheri, Joginder Singh's maternal uncle and both these brick-kilns are being run by Shri Dewan Chand.

Hence there is no question of advising Swami Krishna Nand to approach the Civil Court but the administration will have to ask Shri Dewan Chand and others to explain in writing, how they took for the 1st time and how Girdwari was entered in their name and whether 1/4th till today is in the name of Bhagwan Dass and from whom they took possession and when the mutual deal took place and with whom took place and then a copy of that mutual deal should be submitted by them to prove their bona fide and after that the administration should judge whether a criminal case is there or not.

In the end, I am really sorry to point out the sentence used by you in your letter No. 8694/CEA, dated 2nd December, 1964 delivered to me on 9th December, 1964. The disappearance of the name of Bhagwan Dass from the Revenue Record can be on account of some mutual deal, between Bhagwan Dass deceased and Dewan Chand. etc., because the word can be shows that till the writing of the letter to me, the authenticity of the deal has not been verified and innocently believed otherwise "CAN BE" would not have been there and Dharam Asthan about one lakh would not have been fraudulently in hands other than Sadhus.

Hoping to be favoured with a line in reply at your earliest convenience.

Thanking you.

Copy of a letter dated the 20th February, 1965, from Comrade Ram Piara, M.L.A., Karnal to Shri R. D. Kapoor, Deputy Secretary to Government, Punjab, Revenue Depart ment, Chandigarh, copy to the Deputy Commissioner, Karnal.

Subject.—Application from Swami Krishna Nand regarding Registration of Property.

Thanks for your letter No. 7336-R-II-64/444, dated the 3rd February, 1965, I have noted the contents carefully . I am late in reply because I was in Election as well as to Meerut and Ludhiana.

It appears to me that the findings of the Revenue Department are based on the enquir held by Shri Jatinder Paul some time back G. A., to D. C., Karnal, I have no hesitatio

in saying that G. A. did not act honestly and he was practically a willing and convenient tool in the hands of usurpers. I can go further and am in a position to attribute motives and doubts to his—integrity and associations, he had in Karnal, . Shri Mohinder Singh Bedi, Deputy Commissioner, Karnal was also at their back.

I presume that two enquiries are still in progress, one by the Police, Karnal, and the other by Shri Damodar Dass Ji Additional Secretary, Revenue. A number of documents were looked into. It was clear at that time that some for gery has been committed in the Revenue Records. Let us see on whose instance and why those were not enearthed by G. A., and others who——— communicated to me the result. Before the restoration of landaction...... against the revenue staff responsible for tampering is very necessary.

When action is taken much more will come to light. Of course guilt stands proved but Revenue Department and the Government wants to run away from the responsibility for setting the things right which have become wrong due to unholly alliance of the usurpers and the Government machinery concerned. Of course some other influence is not ruled out. I cannot appreciate the suggestion that Krishna Swami if advised by his lawyers may knock the door of the civil court.

Do you mean that this heavy machinery of the Government is more to help the usurpers by forgeries and tampering. This is very sad state of affair. The irregularities are there and are visible in the darkest night.

Hence I am reluctant to accept these findings. Will Government or Department be anxious to leant that Government moved seriously in cases where guilt was 1/4th if compared to this ? The only difference or difficulty that the aggrieved in this case is a pauper where as the usurpers are millionaires. May I know, whether the Government stands for the aggrieved or the usurpers ?

Are you or your Department or the Government in a position to say that there is neither any tampering nor any forgery nor any serious lapses ?

If you will send the same in writing, I shall feel satisfied. May I expect an acknowledgment of this letter ?

Copy

Chandigarh.

September, 1964.

My Dear,

I have received your letter, dated the 18th September, 1964 regarding illegal possession of Bagh Beriwala in Saddar , Karnal. I am having the matter investigated.

With regards,

Yours sincerely,

(RAM KISHAN)

Shri Ram Piara Comrade, M.L.A.,
L/309, Model Town, Karnal.

No. 11065-CMP-64, dated 18th September, 1964.

A copy with the letter in original received from Ram Piara Commrade, M.L.A., is forwarded to D. S./Rehabilitation, Jullundur City, for immediate enquiry and report in the matter.

(Sd.) RAM KISHAN,
Chief Minister.

Copy of memorandum No. 8694/CEA, dated the 2nd December, 1964, from the Deputy Commissioner, Karnal to Comrade Ram Piara, M. L. A., L/309, Model Town, Karnal

Subject —Representation of Swami Krishna Nand.

Reference your letter, dated the 7th November, 1964, on the subject noted above.

2. The case has again been looked into. In the original complaint there is mention of S. Kishan Singh as the person with whose support the land in question is alleged to have

carefully occupied by Dewan Chand, etc. illegally. In the statement, however, of the comlainant before the Enquiry Officer and further evidence led by him in this behalf there is no such mention and only Dewan Chand, party has been complained against. The revenue record and other evidence seems to show complete possession of Dewan Chand etc. Moreover, the complainant has now where mentioned in his statement that he was forcibly dispossessed by any body. The disapearance of the name of Bhagwan Dass from the revenue record can be on account of some mutual deal between Bhagwan Dass deceased and Dewan Chand etc. No evidence has been led to show that Dewan Chand etc. came in possession of the land by use of force. No report of the occurrence was lodged with the police if at all forcible possession had taken place. In view of all this it appears to be a case of civil nature and the complainant (Swami Krishna Nand) may seek his remedy in a competent court of law, if so advised. It is open to Shri Krishna Nand to lodge a report with the police or to file a regular criminal complaint.

Copy of letter No. 642-PII, dated 3rd March,1965 from Shri Brijinder Singh, IPS. Superintendent of Police, Karnal to the Deputy Commissioner, Karnal.

Subject —Complaint of Shri Ram Piara ,MLA.
Continuation of this office letter No. 122/P-II, dated 13th January, 1965.

2. A copy of the report of the District Inspector, who had the enquiry into the complaint is sent herewith. The original applicaion of Shri Ram Piara, M.L.A. received with your Memo. No. 8856/CEA,dated 17th December, 1964 is returned herewith in original

This case relates to the possession of a plot Khasra No. 4766 in City Karnal, which measures 5 Bighas and 3 Biswas. In his petition to the Commissioner Ambala Division one Swami Krishna Nand, claiming himself as a successor of deceased Bhagwan Dass Sadh had alleged that Sarv Shri Nishan Singh and Diwan Chand etc. of City Karnal had taken unlawful possession of this plot, cut trees in it and ejected his tenants forcibly. On that application an enquiry was conducted by Shri Jatinder Pal, P.C.S., Magistrate Ist Class General Assistant to the Deputy Commissioner, Karnal. In his findings Shri Jatinder Pal concluded that Khasra No. 4766 belongs to Shamlat of Karnal. Till Rabi 1961 the entries in the Khasra Girdawari showed that 1/4th share of this Khasra No. was in possession of deceased Bhagwan Dass Sadh and 3/4th in that of Sarvshri Diwan Chand and Raghbir Singh. In 1962, the name of Bhagwan Dass Sadh disappeared from the Revenue Record and Sarvshri Diwan Chand Ram Lal and Raghbir Singh appeared as comshares of the entire Khasra No. by 1/3rd share each. The disappearance of name of the Bhagwan Dass from the Revenue Record could be on account of any mutual deal between Bhwawan Dass and Diwan Chand etc. Since the Revenue Record and other evidence seemed to show complete possession of Diwan Chand etc. It was difficult to accuse them or encroachment. No evidence had come on the file touching Shri Nishan Singh on any account in this connection. In the end of his report Shri Jatinder Pal remarked that the matter was of civil nature and parties could contest their title in a civil Court.

The complainant was accordingly advised by the Deputy Commissioner Karnal, *vide* is letter No. 8145/CEA, dated 5th November, 1964 to seek remedy in a Civil Court of competent jurisidication. A copy of this intimation, as he had also addressed some communication in this behalf to the Chief Minister, Punjab.

Shri Ram Piara, M.L.A—*vide* his letter, dated 10th December, 1964 addressed to the Deputy Commissioner, Karnal raised the following issue:

(i) That if there was any mutual deal between Bhagwan Dass deceased and Diwan Chand etc. it should be produced.

(ii) That it should be clarified whether Bhagwan Dass was still in possession of 1/4th land in the said Khasra number.

(iii) That Puran as a leasee of the Sadhu's had been cultivating this plot till 1963 when he was forced to surrender its possession through the pressure of a bogus case at Batala. An enquiry into the antecedents of Batala case could prove the malafides.

(iv) That under these circumstances it should be examined whether a criminal case was made out or not.

The reference of Shri Ram Piara Comrade was forwarded to the Superintendent of Police, Karnal for comments. A copy of it had already been sent by the Comrade to the Superintendent of Police. Both these references were marked to me for enquiry.

Though an enquiry had already been conducted by an officer of the status of Magistrate 1st Class yet regarding the fresh issues, I had to examine Sarvshri Puran Chand, Diwan Chand, Chander Bhan, Bakhshish Singh, Lachhman Sarup and Mehar Chand, Patwaris. I had also to take copies of certiain document from the parties concerned and a report from the Tahsildar Karnal, based on facts relevant to these issues. Shri Puran Lodha of Karnal in his statement before me deposed that he had taken this plot on lease from Bawa Kidar Dass a successor of Baba Bhagwan Dass on 12th September, 1961 for three years. The lease money for two years was paid to him. Three separate lease deeds (copies enclosed) each for one year were got executed simultaneously; Then in 1963 Shri Diwan Chand and Shri Nishan Singh exercised verbal pressure on him that he should leave possession of the land in their favour. On his refusal, a bogus case under section. 406 I.P.C. was filed against him in a court at Batala through some unknwon complainant, He was summoned in that court on warrants and had to undergo an expenditure of more than 200 rupees, which he could not bear. Sarvshiri Diwan Chand etc. conveyed to him that if he came on terms with them they could get that case filed at Batala. A compromise was struck through Chander, Bhan Commission Agent, Subzi Mandi, Karnal, and he received four hundred rupees from Diwan Chand, executed a receipt and left possession over the plot . Bawa Kidar Dass also took four hundred rupees from Diwan Chand and quitted.

Shri Bakshish Singh through whom verbal pressure was alleged to have been exercised on Puran, and Chander Bhan, who had intervened for bringing Puran, and Dewan Chand to terms, both contradicted Puran regarding any pressure exercised on him Shri Chander Bhan said that Dewan Chand and Puran had come to him. Diwan Chand alleged that Puran was his leasee for one year. He brought them to terms. Puran was paid Rs. 100/- as cost of the new crops sown by him and he agreed to leave possession of the land. There was no talk regarding the Batala case. A receipt of Rs. 100/- was executed which was attested by him and Bakhshish Singh.

Shri Lachman Sarup, Patwari who had recorded the Girdawari of Kharif, 1962, in the names of Diwan Chand, Ram Lal and Raghbir Singh in three equal shares for the whole plot, deposed that at that time no cultivator of the name of Puran was in cultivation of land there. or the other had servants of these three persons were doing the job. All these three persons were shareholders in the land of Thulla Quadian as well as in its Shamlat. Khasra No. 4766 was a Shamlat of the said Thulla. He had enquired from Puran on whose name Girdawari existed for 1/4th land in the records earlier to Kharif, 1962. Puran had not alleged any high handedness against Diwan Chand etc. there was no successor of Bhagwan Dass Sadh at that time in this Khasra. Number.

Shri Mehar Chand Patwari (Revenue) who now cripplied and unable to move was examined at his house. He admitted that before Rabi, 1956, the whole of this plot was being shown in the possession of Bhagwan Dass Sadh as a "Cher Maurusi" cultivator in the Revenue Records. In 1956, S/Shri Raghbir Singh and Diwan Chand who are owners of land in Thulla Kadian approached Bhagwan Dass and he voluntarily allowed them to cultivate this land in 3/4th share. At that time there was no cultivation in the plot and Bhagwan Dass was sick. He felt apprehension that if some one else out of the land owners of Thulla Kadian took possession over the plot and ousted him , he would find no place to take shelter. These persons ensured him of his retension there till his life time, and so he agreed to allow them ingress. There was no pressure on him.

Shri Diwan Chand stated that he, Ram Lal and Raghbir Singh, were share holders of land in Thulla Kadian as well as in its shamlat. In 1956, though Bhagwan Dass Sadh was present in this plot yet the land was lying uncultivated. He and Raghbir Singh having title over the Shamlat entered into this plot with the consent of Bhagwan Dass. Thereafter the girdawari for 1/4th Share of the plot which could not be cultivated remained in the name of Bhagwan Dass. The consent of Bhagwan Dass was not taken in writing and no deed was executed for that. After Bhagwan Dass's death Puran had taken the land on lease from them w/o any lease deed for one year. He sowed the crop for the next year also without their permission. They wanted to oust him. Shri Chander Bhan being a common porson to both the parties brought about a compromise. They paid Rs. 100/- to Puran as cost of the crop sown by him and he left possession over the land voluntarily. A receipt(copy enclosed) was executed for this amount. Bawa Kidar Dass who lived there was also paid Rs. 400/- and he too executed a receipt. These are now on the file of Shri Jatinder Pal. Since Ram Lal was also a share holder in Thulla Kadian and in its Shamlat, he too, joined them in possession of this land by an equal share in 1962. Shri Diwan Chand pleaded ignorance about anycase u/s 406 IPC instituted at Batala against Puran. He said that now ne S/shri Ram Lal and Raghbir Singh were in full possession of the land in dispute which were under cultivation with their servants.

A report obtained from the Tehsildar Karnal speaks that the entire land of Thulla Kadian with the owners was 6831 Bighas and 6 Biswas. The Shamlat of Thulla Kadian measures 960 Bighas 11 Biswas. Shri Diwan Chand and Ram Lal has purchased land in Thulla Kadian after partition. The share of Shri Bhagwan Dass in the Shamlat of Thulla Kadian comes to 10 Biswas and that of Shri Ram Lal only 13 Biswas. The share of Shri Raghbir Singh is much more than even DiwanChand's because he is the biggest land holder in this Thulla. Even before the year, 1956 when the name of Shri Diwan Chand came in Khasra Girdhari, his share in Shamlat Thulla Kadian was 4 Bighas 8 Biswas. He purchased land even after that and his share increased accordingly. Shri Ram Lal, brother of Shri Diwan Chand owns 4 Bighas 10 Biswas of land in Thulla Kadian which he had purchased on 27th November, 1959 alongwith its share in the Shamlat. This date of purchase is of course earlier to the date of the inclusion of his name in Khasra Girdawari of No. 4766 in Kharif, 1962. The entire land owned and purchased by Diwan Chand in this Thulla measures 71 Bighas and 10 Biswas. The Tehsildar has also reported that before 1956 according to Revenue records Bhagwan Dass Gher Maurusi was the cultivator of Khasra No. 4766. Mehar Chand Patwari was the predecessor of Lachhman Sarup Patwari at Karnal. Hecould through light as to how 3/4 the land in this plot was suddenly shown under cultivation of Sarvshri Diwan Chand and Raghbir Singh in the year 1956. Shri Bhajan Lal had since died and Mehar Chand gone on retirement.

Sudden transfer of possession of 3/4th share to S/Shri Diwan Chand and Raghbir Singh in the year 1956, sudden elimination of even the 1/4th share of Bhagwan Dass in Kharif 1962 inclusion of Ram Lal as an equal shareholder in 1962 especially when his share in the total shamlat of Thulla Kadian does not exceed 13 Biswas the difference in the amount of compensation paid to Puran according to his own statement, and that recorded in the receipt, and the absence of any deed between S/Shri Diwan Chand, etc. and Bhagwan Dass Sadh, are facts which cast a shadow of doubt with regard to the bonafiedes of S/Shri Diwan Chand, Ram Lal and Raghbir Singh. But the complainant can get benefit ofi it only in a court of competent jurisdiction. The receipt of Rs 100 paid to Puran and that of Rs 400 paid to Kidar Dass, were executed in May, 1963, whereas the name of Puran as cultivator for 1/4th share was eliminated from the Revenue records in Kharif, 1962.

Although Puran had submitted two applications to D.C., Karnal, on 29th /20th May, 1963, to the effect that the opponent group were putting presssure on him for vacating the land, yet acceptance of money on his part, and on the part of Kidar Dass and then leaving possession of the plot, could not be termed involuntary. Documentary evidence of receipts and affidavit of Kidar Dass cannot be ruled but, neither the inference that formerly even if they did not want to quit this plot, later on they might have agreed to the real complainant for the incident of 1956 can only be Bhagwan Dass whose silence during his life time, and absence at present have clinched that issue. Similarly the complainant for 1962-63 can be Puran whose acceptance of the compensation and execution of a document ment have also clinched the 2nd issue. There was sufficient time for Bhagwan Dass Sadh from 1956 till his death in 1960 or 1961 for making a complaint of criminal trespass with the Police. Similarly if Puran had felt the pressure and opposed it, he should not have yielded to the temptation of the compensation.

So far as the alleged pressure of a case under section 406, IPC instituted in a criminal court at Batala against Puran Singh is concerned, it is beyond my jurisdiction to comment on the merits of that case. A criminal court had taken cognizance of it and none of the claimants for the plot in dispute i.e. Diwan Chand or their alleged helper Nishan Singh are complainants in it. Puran Chand or Swami Krishana Nand feel that it was a bogus case instituted simply to put pressure on them for vacating the plot, they could very well fight it out, and secure the verdict from that court, or its appellant court, in their favour. And then only the plea of this pressure could be accepted legally.

For police cognizance under the circumstances no act of Shri Diwan Chand, etc. much less that of Shri Nishan Singh, who is not in picture in the Revenue records, falls under the definition of section 441 IPC. In the absence of any judicial verdict of malafide prosecution in the 406 IPC case of Batala, even the element of extraction covered under section 383 IPC which is not cognizable, cannot be said to be *prima facie* proved.

I am, therefore, of the opinion that no criminal case worth cognizance by the Police is made out at this stage. It is for the Revenue Department to scrutinize the conduct of S/Shri Lachhman Sarup and Mehar Chand Patwaris according to the Land Revenue Manual.

KRISHAN GOPLA,
District Inspector of Police, Karnal.

Copy of Memorandum No. 5519/CEA, dated the 2nd July, 1964, from the Deputy Commissioner, Karnal, to the Deputy Secretary (II) to Government, Punjab, Chandigarh.

Subject :—Application dated 27th December, 1963, from Shri Krishna Nand, Dera Baba Huba Sadar Bazar, Karnal, regarding restoration of property.

Reference your endorsement No. 24-R(II)-64/52, dated the 1st February, 1964, on the subject noted above.

2. The matter was inquired into through the General Assistant, Karnal and a copy of his detailed report dated the 26th/29th June, 1964, is sent herewith for your perusal. I agree with this report.

3. The petition of Swami Krishna Nand, dated the 27th December, 1964, is also returned herewith in original as desired.

Copy of a memo. No. 8054/CEA, dated the 27th October, 1964, from the Deputy Commissioner Karnal, to the Private Secretary (Public) to the Chief Minister, Punjab, Chandigarh.

Subject : Representation of Swami Krishna Nand of Karnal.

Reference endorsement No. 9 (60-RM)SU-64-49232, dated the 26th September, 1964 from the Deputy Secretary to Government, Punjab, Rehabilitation Department, Jullundur City, to your address, on the subject noted above.

This case has already been inquired into on an identical application of Swami Krishna Nand of Karnal, received directly in this office. A copy of the report of the Inquiry Officer dated the 26/29th June, 1964, is sent herewith for the information of the Chief Minister. I will be seen from this report that the question of title to the land in dispute is involved in this and as such it is a case of civil nature. The complainant should, therefore, seek his remedy in a civil court of competent jurisdiction.

3. The letter of Comrade Ram Piara, M. L. A., dated the 12th September, 1964, and the petition of Swami Krishna Nand are sent herewith in original.

Copy of endorsement No. 8055/CEA, dated the 27th October, 1964, by the same officer, on the above.

A copy is forwarded to the Deputy Secretary to Government, Punjab, Rehabilitation Department, Jullundur City, for information, with reference to his memo. No. 9(60-RM) SU-64/49231, dated the 28th September, 1964.

Subject : Complaint of Swami Krishna Nand of Sadar Bazar, Karnal, against Sarvshri Dewan Chand, etc., for illegal possession of land.

Swami Krishna Nand Chele Swami Ugan Anand of Dera Baba Huba Singh, Sadar Bazar, Karnal, made a complaint to the Commissioner, Ambala Division, Ambala which was received in the Deputy Commissioner's Officer, Karnal, for enquiry and report. It was entrusted to me for making the necessary enquiry. The following allegations have been made in the said complaint :—

(1) That Sarvshri Nishan Singh and the members of his party have unlawfully taken into their possession the land belonging to the complainant and known as Bagh Samadhwala. It measures 5 bighas 3 biswas.

(2) that 35 trees of Beris and 2 trees of Mulberry have been cut from the said land and one Shri Dewan Chand has made residential quarters thereon. He has also constructed a boundary wall and has started living there. The persian wheel and the kothas, etc. belonging to the complainant have been illegally taken into possession by Sarvshri Nishan Singh and Dewan Chand, etc. The wood of the trees has been converted to his own use by Shri Dewan Chand.

(3) That the tenant of the complainant has also been turned out of the disputed land forcibly and a false case has been made against him in Batala.

2. It has been prayed in the complaint that the land of the Dera known as Samadh wala or Beriwala may be got vacated from the said Shri Dewan Chand and compensation to the extent of Rs 8,000 for the trees may also be given.

3. The complainant was summoned and heard. He stated on oath before me that the Beriwala Bagh situated in Sadar Bazar, Karnal, is the "Dera" of Mahant Ganga Giri. After Ganga Giri, Shri Radha Giri came into possession of this Dera. Thereafter anotherNath (Sadhu) came into possession of this Dera after Radha Giri. In this way the complainant and one Shri Bhagwan Dass came int o possession of this Dera in the year 1951-52 and remained there till 1961. The complaint moves about and leaving Shri Bhagwan Dass on the Dera he had gone to the Mela of Kumbh. He returned back in Baisakh last. Bhagwan Dass had died in his absence. He saw a new Sadhu sitting in the Dera of Ganga Giri Beriwala Bagh) measuring 5 bighas and 3 biswas. This Dera is in the Shamlat Deh of Karnal. The Girdawari of this dera is in the name of Ganga Giri. The name of this new Sadhu is not known to the complainant. This sadhu had leased out the land of the dera to some one alongwith the Beri Trees. This sadhu mostly lives in village Kanipla, tehsil Thanesar. The lease was given to Punna Lodha. Sarvshri Harbhagwan and Shri Bhagwan were in possession of the land. Both these persons had cut the Beri and Mulberry trees and had burnt these in their Bhatta (Brick Kiln). Again said that one beri trees was still standing at the spot. Sarvshri Bhagwan Dass etc. and Punna came into conflict and litiation started between them. In this case Shri Punna gave the crop valuing about Rs 700 to Harbhagwan, etc. Besides this, Sarvhsri Harbhagwan etc. purchased the persian wheel and the kotha from the sadhu Kapla for a sum of Rs 400. The complaint further stated that the dera of Ganga Giri and Radha Giri came into possession of Bhagwan Dass, deceased and himself and as such they are the real owners of the said dera. The sale of the dera by the sadhu of Kanipla of Punna at the hands of Sarvshri Harbhagwan and Shri Bhagwan is illegal. He has been cheated and the matter may be inquired into. He will produce Chaudhri Gappu Ram of Sadar Bazar, Karnal, and Deep Chand Vegetable Seller, who are in the know of facts of this affair.

The complainant Swami Krishna Nand submitted an aplication on the 19th February, 1964, alleging that he had wrongly mentioned the name of Shri Bhagwan in his application. It is as a matter of fact Dewan Chand.

The complainant did not produce Sarvshri Gappu Chaudhri of Sadar Bazar Karnal and Shri Deep Chand, Vegetable seller, but there other witnesses, Namely Shri Nil Kanth a tehsil, peon under suspension, Puran Chand of Karnal and Shri Kldar Dass Pujari of Kaniplawere produced in their place.

6. Shri NilKanth, P. W. I. has stated that he knows Swami Krishna Nand. He used to go to hisDera to eat cherries. He lives in the city. He has been seeing Swami Krishna Nand in this Dera sicce 1951. Some other Sadhus were also seen which the complainant living in the said dera. Swami Krishna Nand, at times used to go out on Yatrafor several months. He had not seen any body in the Dera in the absence of Krisnna Nand. Swami Krishna Nand was out for the last 5/6 months. He was seen in Karnal for the last 5/6 days. He inquired from Shri Krishna Nand as to where he was now staying. He told that some people had illegally occupied their dera. He further stated that some other persons had also told him about this illegal possession. The dera, where Swami Krishna Nand used to live is the dera of the Sadhus and there were sadhu in the said dera.

7. P.W. 2. Shri Puran Chand of Karnal has stated that from the year 1959 Swami Krishna Nand has been visiting the Samadhs, near Ibrahim Mandi, Karnal. He used to go there to eat cherries.

8. P. W. 3. Shri Kidar Dass, Pujari of Shivji Mandir, Kanipla, has stated on oath that there are the Samadhs of Ganga Giri and Radha Giri in the Bagh Beriwala, situated near Ibrahim Mandi, Karnal, land measuring 5 bighas and 3 biswas is also attached to these Samadhs. This dera belongs to the Sanyasis and his Guru Bhagwan Dass used to live there. After the death of his Guru, he came to the said Dera and stayed there for three years. Shri Dewan Chand told him about six months back that the Bagh Beriwala had been allotted to him and asked for the delivery of its possession. He offered to pay the expenses incurred on repairs, etc. There were 36 trees of Beries in this land. He took Rs 400 from Shri Dewan Chand for repairs carried out to the Samadhs and gave him a receipt. He did not sell any land or beri trees to Dewan Chand.

In cross-examination he stated that he had no Kursi Name of the Samadhies in his possession. After the death of Shri Bhagwan Dass, the Girdawari of the land in question was entered in his name. He has no receipt for the payment of land revenue. He will, however, produce the copy of Girdawari entries.

9. The complainant in his statement before me did not mention the name of Shri Nishan Singh anywhere, but implicated only Shri Dewan Chand. He was summoned by me and his statement was also recorded. He has stated that the land in dispute

was lying Banjar in the year 1954-55. In one portion of this land there were samadhs and the rest was Banjar. As a share-holder in the joint Khewat, he broke the said Banjar land and constructed a boundary wall thereon by spending Rs 2,500. In the year 1959, Swami Kidar Dass made a hut near the Samadhies on the said land with his permission. After 3 or 4 years there was a quarrel between Kidar Dass and his servant. He went to the land and Baba Kidar Dass told him that he (Kidar Das) would not live there as nothing was available to eat and his servant also quarrelled with him. Baba Kidar Dass demanded the cost spent by him on the construction of the hut and showed his inclination to leave the place. He demanded Rs 400 and this amount was paid to him (Shri Kidar Dass). An affidavit and a receipt were taken from him. The application of Shri Krishan Nand is baseless. He was never seen during the last 8/9 years. Shri Krishan Nand has been sent by Shri Kidar Dass for extracting some money by giving this application. The land belongs to him and Shri Krishna Nand has no concern with it. The people residing in the immediate neighbourhood never saw Shri Krishna Nand living on the land in dispute.

In cross-examination he has stated that there is a persian wheel on the well in the land in question. He had fixed it there in the year 1959. The well is not bored. He does not know when Baba Bhagwan Dass had died.

10. In support of his version he has given three witnesses, namely, Shri Balbir Singh, son of Kartar Singh, Romesh Nagar, Sadar Bazar, Karnal, (2) Shri Amar Singh, son of Lal Singh Jat Sikh, Ibrahim Mandi, Karnal, and(3) Shri Chanan Singh, son of Ganga Singh Milk Seller, Romesh Nagar, Karnal.

All of them have unanimously stated, in brief, that they are living in the close vicinity of the land in dispute. They have been seeing Shri Dewan Chand in possession of the disputed land. In 1919 one Sadhu came to this place. He remained there for 2 to 4 years and thereafter left the place. A sum of Rs 400 was taken by him from Shri Dewan Chand as the cost of Malba of the Kotha constructed by the said Sadhu. This amount was paid to the Sadhu and he went away. Shri Krishna Nand, complainant, was never seen there. There was a fight between the Sadhu (Kidar Dass) and the servant of Shri Dewan Chand. The Sadhu declined to live there and went away.

11. Shri Dewan Chand has also produced an affidavit of Shri Kidar Dass, dated 20th June, 1963 as also a stamped receipt of Rs 400 in token of the sale of Malba of the Kotha in the land in dispute constructed by Shri Kidar Dass. These are Exh. D. A. and D.B., respectively. It is also mentioned in the affidavit Exh. D. A. that the land measuring 5 bighas and 3 biswas was in possession of Sarvshri Ram Lal and Dewan Chand.

12. As the result of the above mentioned evidence and the Khasra Girdawari produced in this case, it seems to me that Khasra No. 4766 belongs to Shamlat Thula Kadian of Karnal. The entries in the revenue record show that till 1956, 1/4th share of this Khasra No. was of Bhagwan Dass Sadh, deceased, and 3/4th share of Sarvshri Dewan Chand and Raghbir Singh. This entry persisted up to Rabi, 1961. In 1962, the name of Bhagwan Das disappeared from the revenue record, and Sarvshri Dewan Chand, Ram Lal and Raghbir Singh appeared as co-sharers of the entire Khasra No. 4766 by 1/3rd share each. It is not clear how the share of Bhagwan Dass Sadh in respect of 1/4th share disappeard. Bhagwan Dass died somewhere in 1 960, and the complainant Shri Krishna Nand was then away on pilgrimage . This disappearance of the name of Bhagwan Dass from the revenue record can be on account of any mutual deal between deceased Bhagwan Dass and Dewan Chand etc. No evidence has, however, been led as to how Dewan Chand etc. came in full possession of the land in question. The land in question is presently cultivated by Dewan Chand etc. through a tenant and a small area of about 5 square yards has been left occupied by samadhs. Only the tenant of Dewan Chand etc. lives on the whole area and no Sadhu now lives there to look after the Samadhs. The evidence led has shown that during the interim period between the death of Bhagwan Dass and the complete possession of Dewan Chand etc. Kidar Dass Sadhu of Kanipla, lived in a Kotha in this number and looked after the smadhs. He appeared to have sold this Kotha for Rs 400 to Dewan Chand etc. which brought about a complete exit of all Sadhu element on this land and gave clearance to Dewan Chand party. The question of re-entry of Swami Krishna Nand complainant in this case arose when he returned from the pilgrimage and found total elimination of the Sadhu rights over this land at which he made this complaint. It appears that before achieving complete exit of the Sadhu element over this land, there were a number of beri trees. Finding that since they were in sole possession of the khasra number, Dewan Chand party cut out all beri trees leaving only one at this land. Another small kotha was added to the premises by Dewan Chand etc. and cultivation in a more systematic manner started. Incidentally, in the original complaint, there is mention of S. Nishan Singh as the person with whose support the land in question is alleged to have been fully occupied by Dewan

Chand etc. illegally. In the sttement of the complainant and further evidence led by him in this behalf, Nishan Singh is not touched and only Dewan Chand party appars to be involved. Since the revenue record and other evidence seems to show complete possession of Dewan Chand etc. it is difficult to accuse them of encroachment on this land. As indicated by me that the name of Bhagwan Dass suddenly disappeared from the revenue record in 1962 and Bawa Kidar Dass of Kanipla is responsible only for the sale of the kotha, and nothing beyond it, the matter does not appear to be free from doubt as also the bonafides of Dewan Chand etc. The contending parties, no doubt, appear to be on solid grounds in their own way. Therefore, in my opinion this matter is of a civil nature and the parties should contest the matter in a civil court, so as to prove or disprove the title to this land of either of the two parties particularly when the verdict through an executive way may be difficult to enforce on any of the parties without there being a proper legal decree behind.

If approved, the Commissioner, Ambala Division, may be informed accordingly.

JITENDRA PAL,
General Assistant,
Karnal.
26-6-64

Repairs to Road Bridge in Village and Post Office Pabowal Tehsil Una, District Hoshiarpur

2416. Shri Surinder Nath Gautam : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether he received any communication from any legislator of Hoshiarpur District in September, 1964, regarding repairs of the road bridge in village and post office, Pabowal, tehsil Una, district, Hoshiarpur; if so, the details of the action so far taken thereon and the approximate time by which the repair work is likely to start ?

Sardar Darbara Singh (Minister for Home and Development) : No such communication was received regarding the repairs of any culvert in village Pabowal or any road of Zila Parishad in September, 1964.

Tampering with the Revenue Record of Karnal City (Sadar Area)

2427. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether the Revenue Department or the Additional Secretary conducted any enquiries during the period from 1st September, 1964, to date, into the complaints submitted by Sadhus regarding the land in 'Dera Beriwala Bagh' in the Saddar area locality in Karnal City which is alleged to have been usurped or occupied unlawfully by certain individuals; if so, the details of the complaints and the facts that came to the notice of the Enquiry Officer;

(b) whether any tampering with or forgeries in the Revenue Record were noticed by the said Enquiry Officer, if so, a copy of his report thereon be laid on the Table of the House together with the details of the action taken or proposed to be taken by the Government against the Revenue Official responsible for the said grave irregularities ;

(c) the total number with names of the Revenue Officials involved in the said irregularities together with the names of those who were handling Revenue Records at the time when the tampering or foregeries took place ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) A complaint about the illegal occupation of Khasra No. 4756 in village Thula Qadian (Karnal) was received. It was found to be a dispute of Civil nature and the complainant was advised to seek remedy in a Court of law.

(b) No tampering of revenue records was noticed. A copy of the report of G.A., who held regular inquiry in the case, is placed on the Table of the House.

(c) Since no tampering with records was found, the question of fixing any responsibility on revenue officials does not arise.

Subject.—Complaint of Swami Krishna Nand of Sadar Bazar, Karnal, against Sarvshri Dewan Chand etc. for illegal possession of land.

Swami Krishna Nand chela Swami Ugan Anand of Dera Baba Huba Singh, Sadar Bazar, Karnal, made a complaint to the Commissioner, Ambala Division, Ambala, which was received in the Deputy Commissioner's Office Karnal, for enquiry and report. It was entrusted to me for making the necessary enquiry. The following allegations have been made in the said complaint :—

(1) That Shri Nishan Singh and the members of his party have unlawfully taken into their possession the land belonging to the complainant and known as Bagh Samadhwala. It measures 5 bighas 3 biswas.

(2) That 35 trees of Beries and 2 trees of Malberry have been cut from the said land, and one Shri Dewan Chand has made residential quarters thereon. He has also constructed a boundary wall and has started living there. The persian wheel and the kothas etc. belonging to the complainant have also been illegally taken into possession by Sarvshri Nishan Singh and Dewan Chand etc. The wood of the trees has been converted to his own use by Shri Dewan Chand.

(3) That the tenant of the complainant has also been turned out of the disputed land forcibly and a false case has been made against him in Batala.

2. It has been prayed in the complaint that the land of the Dera known as Samadhwala or Beriwala may be got vacated from the said Shri Dewan Chand and compensation to the extent of Rs 8,000 for the trees may also be given.

3. The complainant was summoned and heard. He stated on oath before me that the Beriwala Bagh situated in Sadar Bazar, Karnal, is the "Dera" of Mahant Ganga Giri. After Ganga Giri, Shri Radha Giri came into possession of this dera. Thereafter another Nath (Sadhu) came into possession of this Dera after Radha Giri. In this way the complainant and one Shri Bhagwan Dass came into possession of this Dera in the year 1951-52 and remained there till 1961. The complainant moves about and leaving Shri Bhagwan Dass on the Dera, he had gone to the Mela of Kumbh. He returned back in Baisakh last. Bhagwan Dass had died in his absence. He saw a new Sadhu sitting in the Dera of Ganga Giri (Beriwala Bagh) measuring 5 bighas and 3 biswas. This dera is in the Shamalt Deh of Karnal. The Girdawari of this Dera is in the name of Ganga Giri. The name of this new Sadhu is not known to the complainant. This sadhu had leased out the land of the dera to some one along with the Beri Trees. The sadhu mostly lives in village Kanipla, tehsil Thanesar. The lease was given to Punna Lodha. Sarvshri Harbhagwan and Bhagwan were in possession of the land. Both these persons had cut the Beri and Malberry trees and had burnt these in their Bhatta (Brick-kiln). Again said that one beri tree was still standing at the spot. Sarvshri Bhagwan Dass etc. and Punna came into conflict and litigation started between them. In this case Shri Punna gave the crop valuing about Rs 700 to Harbhagwan etc. Besides this, Sarvshri Harbhagwan etc. purchased the persian wheel and the kotha from the sadhu of Kanipla for

a sum of Rs 400. The complainant further stated that the dera of Ganga Giri and Radha Giri came into possession of Bhagwan Dass, deceased and himself and as such they are the real owners of the said dera. The sale of the dera by the sadhu of Kanipla or Punna at the hands of Sarvshri Harbhagwan and Bhagwan is illegal. He has been cheated and the matter may be inquired into. He will produce Chaudhri Gappu Ram of Sadar Bazar, Karnal, and Deep Chand, Vegetable Seller, who are in the know of full facts of this affair.

4. The complainant Swami Krishna Nand submitted an application on the 19th Feburary, 1964, alleging that he had wrongly mentioned the name of Bhagwan in his application. It is as a matter of fact Dewan Chand.

5. The complainant did not poduce Sarvshri Gappu Chaudhry of Sadar Bazar, Karnal and Shri Deep Chand, Vegetable Seller, but three other witnesses namely, Shri Nil Kanth, a Tahsil Peon (under suspension), Puran Chand of Karnal and Shri Kidar Dass, Pujari of Kanipla, were produced in their place.

6. Shri Nil Kanth, P.W.I., has stated that he knows Swami Krishna Nand, He used to go to his Dera to eat cherries. He lives in the City. He has been seeing Swami Krishna Nand in this Dera since 1951. Some other Sadhus were also seen with the complainant living in the said dera. Swami Krishna Nand, at times, used to go out on Yatra for several months. He had not seen any body in the Dera in the absence of Krishna Nand. Swami Krishna Nand was out for the last 5-6 months. He was seen in Karnal for the last 5-6 days. He inquiried from Shri Krishna Nand as to where he was now staying. He told that some poeple had illegally occupied their dera. He further stated that some other persons had also told him about this illegal possession. The dera, where Swami Krishan Nand used to live, is the dera of the Sadhus and there were sadhus in the said dera.

7. P.W.2, Shri Puran Chand of Karnal, has stated that from the year 1951, Swami Krishna Nand has been visiting the Samadhs, near Ibrahim Mandi, Karnal. He used to go there to eat cherries.

8. P.W. 3, Shri Kidar Dass, Pujari of Shivji Mandir, Kanipla, has stated on oath that there are the Samadhs of Ganga Giri and Radha Giri in the Bagh Beriwala, situated near Ibrahim Mandi, Karnal, Land measuring 5 bighas and 3 biswas is also attached to these Samadhs. This dera belongs to the Sanyasis and his Guru Bhagwan Dass used to live here. After the death of his Guru, he came to the said Dera and stayed there for three years. Shri Dewan Chand told him about six months back that the Bagh Beriwala had been allotted to him and asked for the delivery of its possession. He offered to pay the expenses incurred on repairs etc. There were 36 trees of Beries in this land. He took Rs 400 from Shri Dewan Chand for repairs carried out to the Samadhs and gave him a receipt. He did not sell any land or beri trees to Dewan Chand.

In cross-examination he stated that he had no Kursi Name of the Samadhies in hispossession. After the death of Shri Bhagwan Dass, the Girdawari of the land in question was entered in his name. He had no receipt for the payment of land revenue. He will, however, produce the copy of girdawari entries.

9. The complainant in his statement before me did not mention the name of Shri Nishan Singh anywhere, but implicated only Shri Dewan Chand. He was summoned by me and his statement was also recorded. He has stated that the land in dispute was lying Banjar in the year 1954-55. In one portion of this land there were samadhs and the rest was Banjar. As a share-holder in the joint khewat, he broke the said banjar land and constructed a boundary wall thereon by spending Rs 2,500. In the year 1959, Swami Kidar Dass made a hut near the Samadhies on the said land with his permission. After 3 or 4 years there was a quarrel between Kidar Dass and his servant. He went to the land and Baba Kidar Dass told him that he (Kidar Dass) would not live there as nothing was available to eat and his servant also quarrelled with him. Baba Kidar Dass demanded the cost spent by him on the construction of the hut and showed his inclination to leave the place. He demanded Rs 400 and this amount was paidto [illegible] Shri Ki[illegible] Dass). An affidavit

and a receipt were taken from him. The application of Shri Krishan Nand is baseless. He was never seen during the last 8/9 years. Shri Krishan Nand has been sent by Shri Kidar Dass for extracting some money by giving this application. The land belongs to him and Krishna Nand has no concern with it. The people residing in the immediate neighbourhood never saw Shri Krishna Nand living on the land in dispute.

In cross-examination he has stated that there is a persian wheel on the well in the land in question. He had fixed it there in the year 1959. The well is not bored. He does not know when Baba Bhagwan Dass had died.

10. In support of his version he has given three witnesses, namely, Shri Balbir Singh, son of Shri Kartar Singh, Romesh Nagar, Sadar Bazar, Karnal (2) Shri Amar Singh, son of Lal Singh Jat Sikh, Ibrahim Mandi, Karnal and (3) Shri Chanan Singh, son of Ganga Singh, Milk Seller, Romesh Nagar, Karnal.

All of them have unanimously stated, in brief, that they are living in the close vicinity of the land in dispute. They have been seeing Shri Dewan Chand in possession of the disputed land. In 1919 ore Sadhu came to this place. He remained there for 2 to 4 years and there after left the place. A sum of Rs 400 was taken by him from Shri Dewan Chand as the cost of Malba of the Kotha constructed by the said Sadhu. This amount was paid to the Sadhu and he went away. Shri Krishna Nand, complainant was never seen there. There was a fight between the Sadhu (Kidar Dass) and the servant of Shri Dewan Chand.. The Sadhu declined to live there and went away.

11. Shri Dewan Chand has also produced an affidavit of Shri Kidar Dass, dated 20th June, 1963 as also a stamped receipt of Rs 400 in token of the sale of Malba of the kotha in the land in dispute constructed by Shri Kidar Dass. These are Exb. D. A. and D. B. respectively. It is also mentioned in the affidavit Exb. D. A. that the land measuring 5 Bighas and 3 Biswas was in possession of Sarvshri Ram Lal and Dewan Chand.

12. As a result of the above-mentioned evidence and the Khasra Girdawari, produced in this case, it seems to me that Khasra No. 4766 belongs to Shamlat Thula Kadian of Karnal. The entries in the revenue record show that till 1956 1/4th share of this khasra No. was of Bhagwan Dass Sadh, deceased, and 3/4th share of Sarvshri Dewan Chand and Raghbir Singh. This entry persisted upto Rabi, 1961. In 1962, the name of Bhagwan Dass Sadh disappeared from the revenue record, and Sarvshri Dewan Chand, Ram Lal and Raghbir Singh appeared as co-sharers of the entire Khasra No. 4766 by 1/3rd share each. It is not clear how the share of Bhagwan Dass Sadh in respect of 1/4th share disappeared. Bhagwan Dass died somewhere in 1960, and the complainant Shri Krishna Nand was then away on pilgrimage. This disappearance of the name of Bhagwan Dass from the revenue record can be on account any mutual deal between deceased. Bhagwan Dass and Dewan Chand etc. No evidence, has, however, been led as to how Dewan Chand etc. came in full possession of the land in question. The land in question is presently cultivated by Dewan Chand etc. through a tenant and a small area of about 5 square yards has been left occupied by Samadhs. Only the tenant of Dewan Chand etc. lives on the whole area and no sadhu now lives there to look after the Samadhs. The evidence led has shown that during the interim period between the death of Bhagwan Dass and the complete possession of Dewan Chand etc. Kidar Dass Sadhu of Kanipla, lived in a kotha in this number and looked after the smadhs. He appeared to have sold this kotha for Rs 400 to Dewan Chand etc. which brought about a complete exit of all sadhu element on this land and gave clearance to Dewan Chand party. The question of re-entry of Swami Krishna Nand complainant, in this case arose when he returned from the pilgrimage and found total elimination of the Sadhu rights over this land at which he made this complaint. It appears that before achieving complete exit of the Sadhu element over this land there were a number of beri trees. Finding that since they were in sole possession of the khasra number, Dewan Chand party cut out all beri trees leaving only one at this land. Another small kotha was added to the premises by Dewan Chand etc. and cultivation in a more systematic manner started. Incidentally, in the original complaint, there is mention of S. Nishan Singh as the person with whose support the land in question is alleged to have been fully occupied by Dewan Chand etc. illegally. In the statement of the complainant and further evidence led by him in this behalf, Nishan Singh is not touched and only Dewan Chand party appears to be involved. Since the revenue record and other evidence seems to show complete possession of Dewan Chand etc. it is diffucult to accuse them of encroachment on this land. As indicated by me that the name of Bhagwan Dass suddently disappeared from the revenue record in 1962 and Bawa Kidar Dass of Kanipla is responsible only for the sale of the kotha, and nothing beyond it, the matter does not appear to be free from doubt as also the bonafides of Dewan Chand etc. The contending parties, no doubt appear to be on solid grounds in their own way. Therefore in my opinion this matter is of a civil nature and the parties should contest the matter in a civil court, so as to prove or disprove the title to this

and of either of the two parties particularly when the verdict through an executive way may be difficult to enforce on any of the parties without there being a proper legal decree behind.

If approved, the Commissioner, Ambala Division, may be informed accordingly.

JITENDRA PAL,
General Assistant, Karnal.
(26-6-64)

Leave vacancie of Teachers filled in Ambala District

2428. Sardar Trilochan Singh Riasti : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the manner in which the leave vacancies of teachers in Ambala district are being filled up, whether on the recommendation of the Head of the School or on the recommendations of the Employment Exchange or according to the list of candidates recommended for regular appointment by the Subordinate Services Selection Board, Punjab;

(b) whether the manner in which the vacancies are filled up as mentioned in part (a) above is in accord with the Government instructions ;

(c) whether it is a fact that the leave vacancies of teachers have been filled up by some Heads of Institutions in the said district from amongst the candidates recommended by the Block Education Officers during the period from September, 1964, to-date; if so, the names of the candidates recommended by the Block Education Officers to fill up the said leave vacancies ;

(d) the names of the candidates who were selected and appointed in leave vacancies ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Normally all vacancies are to be filled up by candidates recommended by the Subordinate Services Selection Board, Punjab and in case such candidates are not available, vacancies are filled through Employment Exchange on temporary basis.

Exception has, however, been made in the case of Shrimati Kultar Kaur who was appointed in Government Higher Secondary School, Sector 21, on compassionate grounds due to sudden death of her husband.

(b) Yes.

(c) No.

(d) A list is enclosed.

List of Candidates (J. B.T. Men and Women) who were appointed on temporary basis against leave vacancies during the period from September, 1964 to date

Serial No.	Name of the Candidate	Serial No.	Name of the Candidate
1	Shri Radhey Kishan	32	Shrimati Paramjit Kaur
2	Shri Sant Ram	33	Shrimati Basant Mala
3	Shri Balwant Singh	34	Shrimati Tilak Chibba
4	Shri Sham Lal	35	Shrimati Sparsh Bala
5	Shri Harish Chander	36	Shrimati Lachmi Devi
6	Shri Prem Nath	37	Shrimati Surjit Kaur
7	Shri Balwant Singh	38	Shri Roshan Lal
8	Shri Sham Lal	39	Shri Sham Lal
9	Shri Inder Singh	40	Shri Shushil Kumar
10	Shri Raj Kumar	41	Shri Chander Singh
11	Shri Ram Rattan	42	Shri Puran Chand
12	Shri Balbir Singh	43	Shri Bhushan Kumar
13	Shri Ranbir Singh	44	Shri Krishna Anand
14	Shrimati Shantosh Kumari	45	Shri Hari Krishan
15	Shri Mohinder Singh	46	Shrimati Bimla Devi
16	Shri Krishan Lal	47	Shrimati Prem Wati
17	Shri Jai Kumar	48	Shrimati Saneh Lata
18	Shri Mehar Chand	49	Shrimati Kamlesh Kumari
19	Shri Om Parkash	50	Shrimati Kulwant Kaur
20	Shri Gurdial Singh	51	Shrimati Nirmal Jaura
21	Shri Chaman Lal	52	Shrimati Dhiraj Rani
22	Shri Ravi Datt	53	Shrimati Rukamni Devi
23	Shrimati Lekh Kumari	54	Shrimati Kailash Kumari
24	Shrimati Veena Kumari	55	Shrimati Siroj Devi
25	Shrimati Krishna Vati	56	Shrimati Romesh Kumari
26	Shrimati Harcharan Kaur	57	Shrimati Kamlesh Kumari
27	Shrimati Amrit Devi	58	Shrimati Veena Roy
28	Shrimati Shiana Rani	59	Shrimati Diksha
29	Shrimati Ramesh Kumari	60	Shrimati Shanti Devi
30	Shrimati Saroj Bala	61	Shrimati Saroj Kohli
31	Shrimati Bimla Sharma		

Serial No.	Name of the candidate	Serial No.	Name of the candidate
62	Shrimati Sudesh Mehta	94	Shrimati Pushpa Gharmbhir
63	Shrimati Sudarshan Bhatia	95	Shrimati Nirmal Gupta
64	Shrimti Shashi Bala	96	Shrimati Chander Prabha
65	Shrimati Sudesh Kumari	97	Shrimati Krishna Kumari
66	Shrimati Krishna Sikka	98	Shrimti Sushma Vohra
67	Shrimati Rama Basur	99	Shrimati Kamlesh Agg.
68	Shrimati Raj Kumari	100	Shrimati Balbir Kaur
69	Shrimati Raj Kumari	101	Shrimati Sudesh Gupta
70	Shrimti Kailash Sahai	102	Shrimati Kailash Sahai
71	Shrimati Mohinder Kaur	103	Shrimati Balbir Kaur
72	Shrimati Satish Bala	104	Shrimati Janaki Devi
73	Shrimati Santosh Sethi	105	Shrimati Amarjit Kaur
74	Shrimati Raj Dulari	106	Shrimati Balwant Kaur
75	Shrimati Usha Gupta	107	Shrimati Krishan Devi
76	Shrimati Nirmal Gulati	108	Shrimati Kamlesh Agg:
77	Shrimati Kuldip Kaur	109	Shrimati Santosh Kumari
78	Shrimati Usha Chopra	110	Shrimati Sudesh Kumari
79	Shrimati Krishna Sood	111	Shrimati Usha Taneja
80	Shrimati Jeet Kaur	112	Shrimati Santosh Sethi
81	Shrimati Kanchan Bala	113	Shrimati Mavinder Kaur
82	Shrimati Sudershan Nayyar	114	Shrimati Gursaran Kaur
83	Shrimati Sneh Lata	115	Shrimati Prem Bala
84	Shrimati Kaushlya Devi	116	Shrimati Sudesh Kumari
85	Shrimati Gurbachan Kaur	117	Shrimati Sarla
86	Shrimati Sudesh Nayyar	118	Shrimati Sudershan Naraula
87	Shri Om Parkash	119	Shrimati Gurcharan Vohra
88	Shrimati Savitri Yadev	120	Shrimati Kulwant Kaur
89	Shrimati Kashayama Rani	121	Shrimati Shish Kaur
90	Shrimati Vidya Wati	122	Shrimati Kultar Kaur
91	Shrimati Jasbir Kaur	123	Shrimati Mohinder Kaur
92	Shrimati Sudershan	124	Shrimati Kamlesh
93	Shrimati Kulwant Kaur	125	Shri Ajmer Ram

Serial No.	Name of the candidate	Serial No.	Name of the candidate
126	Shri Chaman Lal	131	Shri Harish Chand
127	Shri Madan Gopal	132	Shri Shyam Sunder
128	Shri Gian Chand	133	Shri Jagdish Kumar
129	Shri Tilak Raj	134	Gobind Ram
130	Shri Gian Chand		

4481PVS—367—24-7-65—C.P. & S., Pb., Chandigarh.

PUNJAB VIDHAN SABHA
DEBATES

16th March, 1965

Vol. I—No. 19

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

PAGE

Tuesday, the 16th March, 1965

Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh

Price : *6.95*

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. I, No. 19, dated the 16th March, 1965

Read	*For*	*Page*	*Line*
रहे हैं	रहे	(19) 2	1
वर्कर्ज	वर्कज	(19) 2	4,11,13
साहिब	साहिव	(19) 2	9
मीटिंग	मीटिग	(19) 3	9
मेन	मैन	(19) 3	16
SUPPLEMENTA-RIES	SUPPLMEENTA-RIES	(19) 4	7 from below
मुख्य मंत्री	मुख्य मत्री	(19) 5	5 from below
कार्यवाही	कार्यँवाही	(19) 6	7
गवर्नमेन्ट	गवर्नँमेट	(19) 6	7
मिस्टर	निस्टर	(19) 6	11
में	मैं	(19) 6	21
साहिब	साहिग	(19) 6	24
ने	ते	(19) 6	27
supplementaries	s pplementaries	(19) 8	8-9 from below
ਪ੍ਰੋਮੈਂਟ	ਪ੍ਰੋਮੈਂਟ	(19)11	19
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿਘ	ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿਘ	(19)11	Last but one
ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ	ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ	(19)12	9
Converted	Convested	(19)12	Last
High	Hfgh	(19)20	Last but one
Girls	Giris	(19)21	8 from below

Read	*For*	*Page*	*Line*
Higher Secondary	Higher	(19)22	7 from below
Private	Prlvate	(19)25	18
Government	Governmeut	(19)26	8
lists	ists	(19)30	3
per	pe	(19)30	19
Securities	Securites	(19)30	3 from below
Guides	Guids	(19)31	6
Preliminary	Premilitary	(19)32	2
candidates	candidases	(19)32	6
start	starts	(19)32	10
begin	being	(19)32	14 from below
in	the	(19)33	7 from below
प्रीवियस	प्रीवीग्रस	(19)39	13
डाक्टर बलदेव प्रकाश	डाक्टर बलदव प्रकाश	(19)40	1
QUESTIONS	QUESTIONSL	(19)42	7
	QUESTIONS	(19)51	Heading
Officer	Offlcer	(19)44	14
Totoli	Totli	(19)45	6
village	vlllage	(19)45	7 from below
Shri	Shr	(19)46	12
for	fos	(19)46	16
be	the	(19)47	8 from below
Chandigarh	Chandtgarh	(19)48	6
altogether	altogethre	(19)48	Last
Chaudhri Ranbir Singh	Chaudhr Ranbir Singh	(19)49	2
Copies	Copics	(19)50	20

Read	*For*	*Page*	*Line*
Holdings	Hclciugs	(19)50	12 from below
	Holcingss	(19)51	3
Minister	Ministers	(19)54	25 from below
The	Tha	(19)54	24 -do-
Institute	Institute	(19)54	20 -do-
ascertained	asceratained	(19)54	19 -do-
reclaiming	:e.lamming	(19)54	16 -do-
	:e lamining	(19)54	14 -do-
discontinued	dis.otinued	(19)55	6-7
Five	Feve	(19)56	28
premises	Permises	(19)56	28
embezzlement	embazzlemen:	(19)60	2-3
सर्विस	सविस	(19)66	21
वाबस्ता	वावस्त	(19)66	23
मार्किट्स	मांकिटस	(19)66	10 from below
ज्यादा	न्यादा	(19)66	5 -do-
यूनिवर्सिटी	पनिबर्मिटी	(19)67	Last
ਮੌਕੇ	ਮਕੇ	(19)70	7
ਅਫਸਰਾਂ	ਅ ਸਰਾਂ	(19)72	4
ਰੁਪਏ	ਰੁਪ	(19)73	3
ਅੰਤ	ਅਤ	(19)73	9
ਬਾਹਰੋਂ	ਬਾਰਰੋਂ	(19)75	10
ਬਾੜੀ	ਦਾੜੀ	(19)75	13
ਬੋਲੂ	ਬੋਲ	(19)76	6
Autonomous	outonomous	(19)77	10
absolutely	obsolutely	(19)77	12

Read	*For*	*Page*	*Line*
ਇਸ	ਇਸ਼	(19)77	8 from below
Delete the word 'ਨੂੰ' after the word 'ਸਕੀਮ'		(19)77	Last but one
ਲਈ	ਲੜੀ	(19)79	1
much	m ch	(19)82	12
our	or	(19)85	3
ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ	ਸਰਦਾਰ ਲ ਸਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ	(19)94	11 from below
	ਸ਼ਰਦਾਰ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ	(19)117	3 -do-
ਫਸਲ	ਫਸ਼ਲ	(19)96	3
ਡਿਸਟਰਿਕਟ	ਡਿਸਟਰਿਟ	(19)101	Last
ਹਜ਼ਾਰ	ਰਜਾਰ	(19)104	14 from below
ਫਾਰਮਿੰਗ	ਫ਼ਾਰਮਿਗ	(19)105	3 -do-
ਉਥੇ	ਉ `	(19)106	4 -do-
ਸਹੂਲਤਾਂ	ਸ ੁ ਲਤਾਂ	(19)106	3 -do-
ਮੌਸਮ	ਮੌਸ਼ਮ	(19)106	Last but one
ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ	ਇਮਪਾਰਟੈਂ	(19)110	Last
ਕਹੀ	ਕਹੀ	(19)113	3 from below
ਮੁਤਾਬਿਕ	ਮੁਤਾਬੀਕ	(19)118	6 -do-
VIDHAN	VIDOAN	(19)120	Heading
demand	dcmand	(19)130	8
Governor	Governer	(19)130	7 from below
for	fo	i	3 -do-
Rs.	Bs	ii	5

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 16th March, 1965

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh at 9.30 a. m. of the clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTION AND ANSWERS

*SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No. 7338

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री: पौंग डैम, बयास डैम की पहली आईटम के सम्बन्ध में लेबर मिनिस्टर ने यह उत्तर दिया है कि उन की जो 25 परसेंट डी० ए० की डीमांड थी उस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो एलान किया है 17.50 परसेंट, 10 परसेंट, 15 परसेंट का वह उन पर भी लागू होगा । मैं यह उन से डैफिनिट उत्तर चाहता हूं कि क्या चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो एलान किया है वह पौंग डैम के वर्कज़ पर भी लागू होगा या नहीं होगा ?

Public Works and Welfare Minister: It has been stated in the reply that the Punjab Government have recently increased D. A. of Government employees including workcharge staff.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री: आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर । मैंने यहीं तो पूछा है कि यह एलान उन वकर्ज़ पर लागू होगा याकि नहीं होगा । इस का जवाब हां में या नहीं में दें ।

मन्त्री. इस से ज़ाहर तो यही होता है, ज्यादा मालूम कर लेंगे ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : स्पीकर साहिब, मैं इस प्रश्न का डैफिनिट उत्तर 'हां' या 'न' में चाहता हूं ।

मुख्य मन्त्री : अगर वे गवर्नमैंट सरवैंटस हैं तो लाज़मी तौर पर लागू होगा ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह फरमाया है कि अगर गवर्नमैंट सरवैंटस हैं तो लागू होगा । मैं जानना चाहता हूं कि आया वे लोग गवर्नमैंट सरवैंट हैं या नहीं ?

---

*Starred Question No. 7338 alongwith its reply appears in P. V. S. Debates Vol. 1 No. 15, dated 11th March, 1965 (Morning Sitting).

मुख्य मन्त्री : अगर आप गवर्नमैंट सरवैंटस का सवाल कर रहे तो यकीनन वे गवरनमैंट सरवैंट्स हैं ।

श्री श्रोम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या मैं मुख्य मन्त्री साहिब से यह पूछ सकता हूं कि उन वर्केज़ की साढे पच्चीस परसैंट डी० ए० वाली डीमांड के बारे में क्या इकदामात किये गए हैं ?

मुख्य मन्त्री : जो कदम उठाए गये हैं उन की पूरी तरह से अनाऊंसमैंट कर दी गई है ।

श्री सागर राम गुप्ता : स्पीकर साहिब, मैं जो सप्लीमेंटरी पूछ रहा हूं उस की ज़रूरत इस लिये महसूस हुई है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी इवेसिव ढंग से जवाब दिया है और मिनिस्टर साहिब ने भी बात क्लीयर नहीं की । जब वहां पर हड़ताल चल रही थी तो मिनिस्टर साहिब ने जवाब दिया था कि वर्कज़ को बुलाया था उन को सैटिसफाई कर दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस वक्त जो बात चीत हुई थी उस वक्त से लेकर अब तक वर्कज़ की डीमांड को इन्हों ने राईटिंग में या किसी तरीके से सैटिलमैंट के ज़रिये से माना है या कि नहीं माना । क्या बयास कंट्रोल बोर्ड ने उन की डीमांड को कंसिडर किया है या कि नहीं किया ?

लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री : बयास कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग अभी नहीं हुई । मीटिंग मुकर्रर हुई थी लेकिन गवर्नमैंट के एलान की वजह से मुल्तवी करनी पड़ी बात चीत हुई थी, उस के मुताल्लिक एशोरैंस दी गई थी लेकिन ज़बानी याद नहीं है कि क्या क्या बात हुई थी ।

श्री श्रोम प्रकाश अग्निहोत्री : एक आईटम के जवाब में बताया गया कि ड्राफट स्टैंडिंग आर्डर्ज़ लेबर कमिश्नर के दफतर में तीन साल से पैंडिंग हैं मैं जानना चाहूंगा कि इतने अर्सा तक पैंडिंग रखने की क्या वजह है, कब तक मंजूरी हो जाएगी ?

मन्त्री..जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री सागर राम गुप्ता : स्पीकर साहिब, मिनिस्टर साहिब ने अभी फरमाया है कि बयास कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि इतनी देर से मीटिंग नहीं हुई क्या मन्त्री महोदय हाउस में ऐसी एशोरैंस दे सकते हैं कि इतने दिनों तक मीटिंग हो जाएगी और उन लोगों की डीमांड का फैसला कर दिया जाएगा ?

मन्त्री : गवर्नमैंट आफ इंडिया के जो इरीगैशन सेक्रेटरी हैं वह मीटिंग मुकर्रर करते हैं इस लिये मैं तारीख के बारे में एशोरैंस नहीं दे सकता ।

श्री अमर सिंह : मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि सैटलमैंट हुई थी लेकिन मुझे याद नहीं है, ज़बानी नहीं बतला सकता । मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि जिन टर्म्ज़ पर फैसला हुआ था क्या वह उन को मानने को तैयार हैं ?

मन्त्री : जो बात उस समय मान ली गई थी उस को तो हम अब भी मानने को तैयार हैं ।

श्री फतेह चंद विज : क्या मन्त्री महोदय फरमाएंगे कि जब इतनी देर तक मीटिंग नहीं हुई तो क्या वह रीमाईडर के तौर पर सैक्रेटरी इरीगेशन एंड पावर, गवर्नमैंट आफ इंडिया को लिखेंगे कि मीटिंग जल्दी बुला ली जाए ?

मुख्य मन्त्री : यह मीटिंग केवल पंजाब की ही नहीं बल्कि पंजाब, राजस्थान और गवर्नमैंट आफ इंडिया के रीप्रिजेंटेटिव्ज़ की होती है । दो बार यह मीटिंग मुकर्रर की गई थी लेकिन दोनों बार मीटिंग को मुल्तवी करना पड़ा । एक बार तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को वह डेट सूट नहीं करती थी इस लिये नहीं की गई । दूसरी बार गवर्नर साहिब तशरीफ नहीं ले जा सकते थे, बीमार हो गए थे । दोनों गवर्नमैंटस की यह खाहिश है कि जल्दी ही मीटिंग काल की जाए और सेंटर वाले भी पूरा ज़ोर दे रहे हैं । हम आशा रखते हैं कि बजट सैशन के बाद वह मीटिंग राजस्थान के अंदर या पंजाब या दिल्ली के अंदर जल्दी ही की जाएगी, ताकि तमाम मामलात का फैसला कर लिया जाए ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जब पोंग डैम तलवाड़ा टाउनशिप हाजीपुर ब्लाक में है और उन तमाम को वहां पर हिल अलाऊंस मिलता है तो डैम पर काम करने वालों को हिल अलाउंस क्यों नहीं दिया जाता ?

मुख्य मन्त्री : इस सवाल का मैन सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है । हिल एरियाज़ के और भी सवाल आए हैं, आप अलग नोटिस दें, जवाब दे दिया जाएगा ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : इस सवाल के बीच में ही यह भी पूछा गया है ।

लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री : हिल अलाउंस के मुताल्लिक जवाब दिया गया है कि हिल अलाउंस इस लिए नहीं दिया गया क्योंकि उन को वहां पर ओवर टाईम मिलता है दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकतीं ।

श्री सागर राम गुप्ता : मिनिस्टर साहिब ने अभी फरमाया है कि चूंकि उन को वहां पर ओवर टाईम दिया जाता है इस लिये हिल अलाउंस नहीं देते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि ओवर टाईम तो फैक्टरी एक्ट के मातहत अगर आप किसी से आठ घंटे से ज्यादा काम लेंगे तो अवश्य ही देंगे, यह बात तो न सिर्फ पौंग डैम पर ही है बल्कि सारे पंजाब में लागू होती है, इस का हिल अलाउंस से क्या ताल्लुक है ?

कामरेड राम चन्द्र : क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि पौंग डैम के एरिया में से जिन लोगों को आउस्ट किया जा रहा है उन के लिये जब तक किसी आलटरनैटिव ज़गह का इन्तजाम न हो जाए उस वक्त तक उन्हें आउस्ट नहीं किया ज़ायगा ?

मन्त्री : इस सवाल से पौंग डैम के आउस्टीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन मैं आप की इजाज़त से अर्ज़ करना चाहता हूं कि उन के लिये राजस्थान गवर्नमैंट से जमीन हासिल करने के लिये जो भी इकदामात किये जा सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी कल ही इरीगेशन मिनिस्टर से मिल कर आया हूं उन्हों ने यकीन दिलाया है कि अप्रैल के शुरू में ही राजस्थान गवर्नमैंट से मिल कर उन के रीप्रिजेंटेटिव से मिल कर जल्दी ही फैसला करेंगे। उन को निकालने का जो नोटिस दिया हुआ है उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्रोजैक्ट का जो काम शुरू किया गया है उस को तो कतई तौर पर ससपैंड नहीं किया जा सकता लेकिन हम इतना जरूर करेंगे कि जहां तक हार्डशिप को रोका जा सकता है वह रोका जाए। और जहां तक मुमकिन हो सकता है उस हद तक मुल्तवी कर दिया जाए।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : प्राविडैंट फंड की बाबत बताया गया है कि फंडज़ की कमी की वजह से यह स्कीम वहां पर लागू नहीं हो सकती। क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि प्राविडैंट फंड सारे का सारा वर्कर को अदा करना पड़ता है या उस में से निस्फ हिस्सा सरकार को भी देना पड़ता है?

मन्त्री, जो भी प्राविडैंट फंड के रूल्ज़ हैं उस के मुताबिक वर्कर भी कन्ट्रीब्यूट करता है और कुछ हिस्सा गवर्नमैंट भी देती है।

श्री सागर राम गुप्ता : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अर्ज़ यह है कि मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया गया। या तो गवर्नमैंट की तरफ से जवाब दिया जाए या मैं दूसरा सप्लीमैंटरी करता हूं। इस की मुझे इजाज़त दी जाए।

Mr. Speaker : Next question please.

Shri Sagar Ram Gupta : My supplementary has not been replied to Sir.

Mr. Speaker : The Government do not propose to reply. Next question please.

SUPPLMEENTARIES TO STARRED QUESTION No 7791

कामरेड राम प्यारा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जिन के ऊपर मिस्टर कृष्णास्वामी ने ऐक्शन लेने के लिए कहा था वह कौन सा अफसर या कौन सा मिनिस्टर है जिसने उन को ऐग्ज़ोनरेट कर दिया?

मुख्य मन्त्री : एग्जोनरेट तो गवर्नमैंट करती है।

---

*Starred Question No. 7791 alongwith its reply appears in P. V. S. Debate Vol. 1 No. 18 dated 15th March, 1965.

Comrade Ram Piara : Has the Chief Secretary or the Chief Minister himself exonerated him ?

Mr. Speaker : The Chief Minister has stated that it is done by Government.

Comrade Ram Piara : May I know, Sir, whether the Chief Secretary is the Government ?

Mr. Speaker : Government means Secretary to Government.

कामरेड राम प्यारा : मिस्टर कृष्णास्वामी ने तो चीफ सैक्रेटरी तक की रिपोर्ट की है। इस वजह से चीफ सैक्रेटरी को उस से नीचे का कोई अफसर तो ऐग्ज़ोनरेट कर नहीं सकता। इसी लिए मैंने यह सवाल पूछा है कि क्या इस सम्बन्ध में ऐग्ज़ोनरेट करने के आर्डर किसी अफसर ने पास किए या चीफ मिनिस्टर साहिब ने ?

Chief Minister : The Chief Minister as Head of the Government has passed orders.

Chaudhri Darshan Singh : Practically, all the officers have been exonerated. May I know from the hon. Chief Minister whether the non-officials, who have been mentiond in the Das Commission Report, have been exonerated by the Chief Minister ?

मुख्य मन्त्री : इस सवाल का इस के साथ क्या ताल्लुक है ?

कामरेड राम प्यारा : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि ऐसे केसिज़ भी हैं जहां पर मिस्टर कृष्णास्वामी ने किसी एक को बजाए दूसरे को मुजरिम करार दिया लेकिन दोनों को ऐग्ज़ोनरेट कर दिया गया लेकिन गलती, जिसके केसिज़ पर उन को मुजरिम करार दिया गया था, कायम है ? उस सम्बन्ध में आप क्या ऐक्शन ले रहे हैं ?

मुख्य मन्त्री : मैंने पहिले भी कई बार कहा है, कि इस सम्बन्ध के ऊपर पूरी तरह से छानबीन की गई है। एक बार ऐडीशनल चीफ़ सैक्रेटरी ने एक एक केस को देखा उसके बाद दुबारा ऐडीशनल चीफ़ सैक्रेटरी ने सारे केसिज़ की छानबीन की। फिर उसके बाद मैंने उनके हरेक पहलू को देखा। उसके बाद जिस केस में मैंने समझा कि उनकी रिप्लाई सैटिस्फैकटरी है, उन को ऐग्ज़ोनरेट कर दिया गया है।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन नान आफिशियल्ज़ के नाम इस रिपोर्ट के अन्दर आए हैं उनको अभी तक पब्लिक में न लाने के क्या वजूहात हैं ?

मुख्य मन्त्री : इस के मुताल्लिक भी मैं कई बार इस हाउस में बता चुका हूं। उन नान आफिशियल्ज़ के अन्दर जहां तक ऐक्स मिनिस्टर्ज़ का ताल्लुक है उन के सम्बन्ध में जो भी रिपोर्ट श्री कृष्णास्वामी ने की थी, उनके केसिज़ को सैंट्रल होम मनिस्टर को भेज दिया हुआ है। उनकी टर्म्ज़ आफ रैफ़रैंस के मुताबिक वहां पर उन्होंने कार्यवाही करनी है और उसके बाद उन्होंने हमें इनफ़ार्म करना है।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या चीफ मनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो उन्होंनें कहा कि नान आफिशियल्ज़ के बारे में सेंट्रल गवर्नमैंट ने फैसला करना है क्या उन्होंनें आप को ऐक्शन लेनें के लिए हिदायात करनी है या कि पंजाब गवर्नमैंट खुद ऐसे केसिज़ पर ऐक्शन लेने के लिए फाईनल अथारिटी है ?

मुख्य मन्त्री : टर्म्ज आफ रैफरेंस के मुताबिक, जहां तक फार्मर मनिस्टर्ज का तालुक है, होम मनिस्टरी को उन के केसिज फारवर्ड कर दिए गए हैं। वह वहां पर उनकी छानबीन करके मुनासिब कार्यवाही के लिए पंजाब गवर्नमैंट को हिदायात भेजेंगे ।

कामरेड राम प्यारा : क्या चीफ मनिस्टर साहिब बताएंगे कि नीलम सिनेमा के एक चार्ज के बारे में मिस्टर दास ने एक ऐक्स मनिस्टर पर हाथ डाला था और उसी इशू के ऊपर जब मिस्टर कृष्णास्वामी छानबीन कर रहे थे उन्होंनें उस कसूर को सैक्रेटरी कैपिटल के ऊपर डाला। दोनों ऐग्ज़ोनरेट हो गए हैं लेकिन जो कसूर था वह वहीं का वहीं हैं । इसकी क्या वजूहात है कि कसूर होनें पर भी दोनों को ऐग्ज़ोनरेट कर दिया गया ?

मुख्य मन्त्री : मैंने कहा है कि नान आफिशियल्ज़ के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ । वह सारा मामला होम मनिस्टरी आफ दी सैंटर के पास ज़ेरे गौर है ।

कामरेड राम प्यारा : क्या चीफ मनिस्टर साहिब बतांएंगे कि अगर सैक्रेटरी ऐग्ज़ोनरेट हो गया है तो क्या किसी ऐक्स मनिस्टर के खिलाफ केस पैंडिंग पड़ा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बताया तो है कि किसी ऐक्स मनिस्टर के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ । (He has already stated that no decision has so far been taken about any ex-minister.)

श्री मंगल सैन : मुख्य मंत्री साहिब ने फरमाया है कि अभी तक नान आफिशियल्ज़ के खिलाफ कोई ऐक्शन नही लिया गया । क्या वह बताएंगे कि ऐसे जो गुनाहगार या मुजरिम है, उनके बारे में दास कमिशन ने अपना फैसला दिया और श्री कृष्णास्वामी ने तस्दीक की, उन के खिलाफ कब तक फैसला लेंगे ? क्या इस सम्बन्ध के ऊपर आप कोई निश्चित टाइम लिमिट बता सकते हैं ?

मुख्य मन्त्री : मैं किसी को गुनाहगार तसव्वर नहीं करता जब तक कि कोई खास कार्यवाही नहीं हो जाती । मैंने बार बार इस हाउस में कहा है कि ऐसे तमाम केसिज़, जिन की तरफ डाक्टर मंगल सेन जी ने इशारा किया है उन तमाम को सैंटर के होम मनिस्टर साहिब को भेज दिया हुआ है। जिस केस की तरफ कामरेड राम प्यारा जी ने इशारा किया है, आनरेबल मेम्बर को मालूम है कि उस सम्बन्ध में उनकी चिट्ठी का मैंने मुनासिब जवाब दे दिया हुआ है । जिस ऐक्स मनिस्टर के मुतालिक आप ने इशारा किया मिस्टर कृष्णास्वामी ने उनको पूरी तरह से ऐग्ज़ोनरेट कर दिया है ।

Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : May I know from the hon. Chief Minister whether the findings of Shri Krishnaswamy on the Das Commission Report were sent to the Home Ministry with or without the comm ents of the Government ?

मुख्य मन्त्री : उन पर मेरी अपनी कोई रिकमैंडेशन नहीं है । जो रिपोर्ट मिस्टर कृष्णास्वामी ने की वह हुबहु उन को भेज दी गई थी टर्म्ज़ आफ रेफ्रेंस के मुताबिक ।

श्री जगन्नाथ : चीफ मनिस्टर साहिब ने इशारा किया है कि एक ऐक्स मनिस्टर को ऐग्ज़ोनरेट कर दिया गया है । क्या वह उन मनिस्टर साहिब का नाम बताने की कृपा करेंगे ? (विघ्न)

श्री फतेह चन्द विज : क्या चीफ मनिस्टर साहब बताएंगे कि जैसा कि कल उन्हों ने बताया था कि वह ऐक्स चीफ मनिस्टर के बारे में गलत फहमियां दूर करने के लिए कोशिश करते रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अब भी वह इस बारे में गलत फहमियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल पैदा नहीं होता (It does not arise.)

मुख्य मन्त्री : इस सप्लीमैंटरी का इस सवाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है । वैसे मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि कल जो मैं ने तकरीर यहां दी थी उस को अगर यह गौर से पढ़ें तो इन को इस बारे में ठीक तरह से पता चल जाएगा ।

श्री मंगल सैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मैं इस बारे में आप की रूलिंग चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि कृष्णास्वामी की जो रिपोर्ट है वह सीक्रेट है और अभी एक सप्लीमैंटरी के जवाब में उन्हों ने बताया है कि जो एक भूत पूर्व मंत्री थे उन को कृष्णास्वामी ने ऐग्ज़ोनरेट कर दिया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमैंट की किस बात को ठीक समझा जाए ?

मुख्य मंत्री : मैं ने हमेशा ही फलोर आफ दी हाउस पर यही कहा है कि जो रिपोर्ट है वह सीक्रेट है और उस पर जो एक्शन लिया गया है उस में कोई सीक्रेट नहीं है और जो जो भी एक्शन गवर्नमेंट इस सिलसिले में किसी के खिलाफ लेती रही है वह मैं वक्तन फवक्तन यहां बताता रहा हू ।

Mr. Speaker : Government can claim privilege about any document.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ, । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇਕ ਸਿਮਿਲਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੀਪਲਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਐਕਜ਼ਾਨੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ?

मुख्य मंत्री : मैं ने यह कहा है कि कृष्णास्वामी ने उस साबिका वज़ीर को ऐग्जोनरेट कर दिया है और वह केस भी होम मिनिस्टरी को भेज दिया गया है।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਰੀਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : अभी तक तो सरकार के ज़ेर गौर इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं। अगर माननीय मेम्बर के नोटिस में कोई ऐसी चीज़ है तो वह हमारे नोटिस में ले आएं, हम उस पर गौर कर लेंगे।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री : स्पीकर साहिब, मैं इस बारे में आप की तवज्जुह इस हाउस के उस फैसले की तरफ दिलाना चाहता हूं जो इस ने एक बार यहां किया था कि आम तौर पर एक सवाल पर पांच से ज़यादा सप्लीमेंटरीज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी क्योंकि अगर बे हिसाब सप्लीमेंटरीज़ पूछने की इजाज़त दी जाए तो इस का नतीजा यह होता है कि बहुत कम सवालों के जवाब यहाँ पर दिए जा सकते हैं और आप देखें कि एक एक सवाल पर गवर्नमेंट का कितना टायम और लेबर खर्च होता है और अगर एक सवाल का जवाब यहां पर न दिया जाए तो वह सारी लेबर वेस्ट हो जाती है। इस लिए मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस फैसला पर अगर स्टिक करें तो बेहतर होगा। वैसे तो आप की यह मर्ज़ी है, और जिस तरह आप चाहें कर सकते हैं। मगर यह एक कनवेन्शन भी बन चुकी है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से मुतफिक होंगे कि दास कमिशन के बारे में यह हाउस काफी से ज़यादा टची है इस लिए इस बारे में ज़यादा सप्लीमेंटरी पूछने की इजाज़त दी जा रही है वरना आम तौर पर इतने सप्लीमेंटरीज की इजाज़त नहीं दी जाती। (The hon. Minister will agree with me that the House is very touchy about questions on the Das Commission Report and that is why more supplementaries are being allowed on this questions otherwise normally so many supplementaries are not allowed on any question.)

श्री बलरामजी दास टन्डन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगें कि क्या लीगली अफीशियलज़ के खिलाफ एक्शन लेने के लिए फाइनल एथारेटी पंजाब गवर्नमैंट को हासल है या इस ने सेंट्रल गवर्नमैंट को रिकमेंड ही करना है ? इस के साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सम्बंध में कितना समय मांगा है ? उन को यह सारा फैसला करने में कितनी देर और लगेगी ?

मुख्य मंत्री : पंजाब गवर्नमैंट को इस बारे में ऐक्शन लेने की फाइनल एथारेटी है वैसे जहाँ तक नान-आफिशियलज़ और साबिका मिनिस्टर्ज़ के खिलाफ एक्शन

लेने का ताल्लुक है उस बारे में जो रिपोर्ट श्री कृष्णा स्वामी ने दी है वह हम ने सेंटर की मिनिस्टरी आफ होम को भेज दी है । जहां तक सरदार प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ कोई ऐक्शन लेने का ताल्लुक है इस बारे में होम मिनिस्टरी ने अपना यह फैसला दे दिया है कि सरदार प्रताप सिंह के खिलाफ कोई मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता । जहां तक दूसरे फार्मर मिनिस्टर्ज़ का ताल्लुक है उन के बारे में होम मनिस्टरी अभी विचार कर रही है ।

श्री बलराम जी दास टन्डन : उन को इस बारे में फैसला करने में अभी कितनी देर और लगेगी ?

Chief Minister: I have been sending them many reminders.

कामरेड राम चन्द्र : मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह दरियाफत करना चाहता हूं कि श्री बागची 31 अक्तूबर, 1964 को एप्वांयट हुए थे और उन को यह काम करने में साढ़े चार महीने हो चुके हैं और इस दौरान 12 हजार रुपया उन की तनखाह पर और साढ़े चार हजार उन के स्टाफ की तनखाहों पर खर्च हो चुका है। तो क्या वजह है कि अभी तक उन्हों ने कुल तीन केसों के बारे में ही अपनी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं की है ?

मुख्य मंत्री : वह इन केसों की पूरी तरह से छान-बीन कर रहे हैं क्योंकि उन केसों में कई चीजें ईनवाल्वड हैं । वह इन दिनों में कोई बेकार नहीं बैठे रहे और उन के जिम्मे कई और काम भी लगाए गए थे । उन को स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर चीफ सेक्रेटरी के साथ लगाया गया था ताकि सेक्रेटेरियेट की एस्टेबलिशमेंट और दूसरी एस्टेबलिशमेंट के अन्दर और फूड डिपार्टमेंट के अन्दर कुछ सुधार वह सुजेस्ट कर सकें । उन के तजुरुबे का पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है ।

Mr. Speaker : Next question, please.

Comrade Ram Piara : on a point of Order, Mr. Speaker. About the non-officials referred to in the Das Commission Report, two views have been expressed by the hon. Chief Minister; one that all the cases have been referred to the Ministry of Home Affairs and they are yet under consideration and the other view expressed by the hon. Chief Minister is that Mr. Krishnaswami has exonerated an ex-Minister, to whom I made a reference. May I know, Sir, which of the two views expressed by the hon. Chief Minister may be considered as correct ?

मुख्य मन्त्री : इस सम्बंध में मेरा जो जवाब है वह विल्कुल सही है। मैंने जवाब में यह कहा है कि एक साबिका मिनिस्टर के केस में श्री कृष्णास्वामी ने उसको ऐग्ज़ोनरेट किया है और मैंने यह नहीं कहा कि उस मिनिस्टर का केस हमने होम मिनिस्टरी को नहीं भेजा । हम ने उस का केस और श्री कृष्णा स्वामी की रिपोर्ट भी होम मिनिस्टरी के पास भेज दी हुई है ।

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहब, मैंने तो पूछा है कि क्या इन की स्टेटमैंट ठीक है....

Mr. Speaker : No, please. I will expect that the hon. Ministers will not give reply unless I allow a point of order or a Supplementary Question.

Next Question, please.

PROMOTION OF SCHEDULED CASTE KANUNGOS IN HISSAR DISTRICT

***7090. Chaudhri Net Ram** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of Kanungos belonging to the Scheduled Castes working as on the 11th September, 1963 in district Hissar;

(b) whether some of the Kanungos referred to in part (a) above have been promoted or are proposed to be promoted as Naib-Tehsildars, if so, from what date and their number ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Two.

(b) No.

चौधरी नेत राम : मैं आप के द्वारा माल मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिला हिसार में कुल कितने कानूनगो हैं और उन में से कितने हरिजन हैं जिन को नायब तहसीलदारी के लिए प्रोमोशन दी गई है—उन में कितने स्वर्ण जाती के हैं और कितने हरिजन हैं और क्या हरिजनों को प्रोमोशन्ज में जो दस फी सदी हिस्सा सरकार ने देना कर रखा है वह वहां भी पूरा किया गया है ?

माल मन्त्री : अगर माननीय मैंबर सवाल के जवाब को अच्छी तरह से पढ़े तो इन को इन सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा : सवाल के पार्ट (ए) में पूछा गया है :

"the number of Kanungos belonging to the Scheduled Castes working as on the 11th September, 1963...." and to this I have replied that there are two. The second part of his question is—

"whether some of the Kanungos referred to in part (a) above have been promoted or are proposed to be promoted as Naib Tehsildars,........"

तो मैंने इस के जवाब में कहा है कि '(नां)' मुझे समझ नहीं आ रही कि इन को और कौनसी इनफर्मेशन चाहिए ।

श्री अध्यक्ष: ठीक है । (This is allright.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਈਸ਼ੂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 10 ਪਰਸੈਂਟ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਸ਼ੈਡੀਉਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾ ਫਿਰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ 10 ਪਰਸੈਂਟ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਕ ਸਪੈਸੇਫ਼ਿਕ ਸਵਾਲ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਜੇ ਕਰ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਏ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਾਨੂੰਗੋ

10 A.M.

ਸਨ ਸ਼ਡੂਲਡਕਾਸਟ---(ਵਿਘਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਟੇਜ ਮੁਤਾਬਕ । ਕੀ ਇਸ ਪਰਸਨਟੇਜ ਨੂੰ ਜੇਰਗੌਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੂੰਕਿ ਵੇਕੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ੇਰਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੇਕੈਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰਖਾਂਗੇ ।

श्री अमर सिंह : इन्होंने कहा है कि शैडयूल्ड कास्टस के दो कानूनगो हैं । क्या यह बताएंगे कि 10 % रिज़र्वेशन को मेनटेन करते हुए उन की तादाद दो ही है या ज्यादा है ?

Minister : I require notice for that.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜਨਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲਜ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਕਨਸਿਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਤੌਰ ਨਾਇਬਤਸੀਲਦਾਰ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਕ ਜਰਨਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੈਸੇਫ਼ਿਕ ਨਹੀਂ । ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਕੈਂਸੀ ਹੋਈ ਪਰ ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ । (The question of the hon. Member relates to Hissar District and he wants to know whether any vacancy arose and was not offerred to a Scheduled Caste candidate.)

Minister : It is not to my knowledge at the moment. I will find out.

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਸਦੱਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਇਬ-ਤਸੀਲਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ........(ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਪੈਸੇਫ਼ਿਕ ਕਵੇਸਚਨ ਕਰੋ । (The hon. Member may please put a specific question).

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਸਪੈਸੇਫ਼ਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ-ਤਸੀਲਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡ਼ਵੀਜ਼ਨ ਚੋਂ ਬਣਨੇ ਹਨ...., ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰੇ ਹੈ । (The question relates to the Hissar District only.)

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो यह दो प्रोमोट नहीं हो सके आया वह मैरिट पर नहीं आ सके या 10% रीज़र्वेशन का कोई ख्याल नहीं किया गया ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਕੈਂਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਦ ਵੇਕੈਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟਸ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ; ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਨਸਿਡਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਕਾਨੂੰਗੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20—25 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ?

Minister : The hon. Member has given information; I will look into it.

STARRED QUESTION NO. 6881.

Mr. Speaker : Now we take up the regular list of Starred Questions for the 16th March. First Question *6881 is in the name of Comrade Makhan Singh Tarsikka. It is converted into an Unstarred Question.

J. B. T. CLASSES IN THE STATE

†*6881. **Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the names of places at present where J. B. T. classes have been opened in the State and the number of students admitted in each of the said classes together with the names of the places where the said classes exist for girls;

(b) the details of the criteria kept in view at the time of admission to the said classes; and

(c) whether the Department issued any instructions in connection with the admission to the D. E. O.s of the districts concerned, if so, the details there of and a copy of the instructions be laid on the Table of the House ?

Shri Prabodh Chandra : (a) A statement giving the available information is laid on the Table of the House. The information regarding the number of candidates actually admitted to each unit is being collected and will be supplied separately.

(b) A copy of the criteria and rules for admission to J. B. T. classes is laid on the Table of the House.

(c) Yes.

A copy of detailed instructions is laid on the Table of the House.

*Convested into unstarred question under direction of the Hon. Speaker.

Allotment of J. B. T. Units for Session 1964

Serial No.	Name of the Institution	No. of Unit		Total
		Men	Women	
1	2	3	4	5
	AMBALA DISTRICT			
	Government Institutions			
1.	Government Basic Training School, Naraing rh ..	2	—	2
2.	Government High School, Mullana	½	½	1
3.	Government Girls High School, Nalagarh ..	—	1	1
4.	Government Basic Training Centre, Chandigarh ..	½	½	1
5.	Government Girls High School, Naraingarh ..	—	1	1
6.	Government High School, Nalagarh	1	—	1
7.	Government Basic Training College, Chandigarh ..	—	2	2
8.	Government Girls High School, Yamunanagar ..	—	1	1
	Total	4	6	10
	Privately-managed Institutions			
9.	S. L. Training College, Ambala City ..	1	1	2
10.	Dev Samaj College, Ambala City ..	—	2	2
11.	Christian High and Basic Training School, Kharar ..	1	—	1
12.	Khalsa Girls High School, Morinda	—	1	1
13.	Arya Kanya Vidhyala, Kharar ..	—	2	2
14.	Khalsa Higher Secondary School, Kurali ..	1	—	1
15.	Adarash Jain Kanya Pathshala, Sadhaura ..	—	1	1
16.	S. D. Kanya Mahavidyala, Ambala ..	—	1	1
	Total ..	3	8	11
	GRAND TOTAL	7	14	21

[Education and Local Government Minister]

1	2	3	4	5
	ROHTAK DISTRICT			
	Government Institutions			
1.	Government Janta College, Dujana ..	2	—	2
2.	Government High School, Farmana ..	1	—	1
3.	Government Girls/School, Jhajjar ..	—	1	1
4.	Government High School, Chhara ..	2	—	2
5.	Government Girls High School, Gohana ..	—	1	1
6.	Government High School, Beri ..	1	—	1
7.	Government High School, Rajlugarhi	1	—	1
8.	Government High School, Ladian ..	1	—	1
9.	Government Girls Higher Secondary School, Bahadurgarh ..	—	2	2
10.	Government High School, Lakhan Majra ..	1	—	1
11.	Government Girls Higher Secondary School, Rohtak ..	—	1	1
12.	Government High School, Kosli ..	½	½	1
	Total ..	9½	5½	15
	Private Institutions			
13.	C. R. College of Education, Rohtak ..	1	1	2
14.	Kanya Gurukul Khanpur, Kalan ..	—	2	2
15.	D. A. V. High School, Hasangarh ..	2	—	2
16.	Arya National High School, Mohana ..	1	—	1
17.	Janta Higher Secondary School, Butana ..	2	—	2
18.	G. B. High School, Rohtak ..	1	—	1
19.	Vaish High School, Rohtak ..	1	—	1
20.	S.M.H./S Sonepat ..	2	—	2
21.	Haryana Public High School, Gohana ..	2	—	2
22.	D.A.V. High School, Mokhra ..	1	—	1
	Total ..	14	3	17
	GRAND TOTAL ..	23½	8½	32

1	2	3	4	5
	GURGAON DISTRICT			
1.	Government Basic Training School for Women, Gurgaon ..	—	2	2
2.	Government Basic Training School, FaridabadTo wnship ..	1	1	2
3.	Government High School, Palwal ..	1	—	1
4.	Government Girls Higher Secondary School, Palwal ..	—	1	1
5.	Government High School, Pataudi ..	1	—	1
6.	Government High School, Hodal ..	1	—	1
7.	Government High School, Nagina ..	1	—	1
8.	Government High School, Hathin ..	1	—	1
9.	Government High School, Kund ..	1	—	1
10.	Government High School, Bahin ..	1	—	1
	Total	8	4	12
	Privately-managed Institutions			
11.	Teacher Training College, Rewari ..	2	—	2
12.	B.L. High School, Khol ..	1	—	1
13.	M.D. High School, Faridabad ..	1	1	2
14.	B. B. Ashram, Rampura Rewari ..	—	1	1
15.	Rashtria Girls High School, Rewari ..	—	1	1
16.	Hindu High School, Nuh ..	1	—	1
17.	Brayns Meo High School, Nuh ..	1	—	1
18.	Sarvodya High School, Patili ..	1	—	1
	Total ..	7	3	10
	GRAND TOTAL ..	15	7	22
	DISTRICT KARNAL			
	Government Institutions			
1.	Government Normal School, Karnal ..	2	—	2
2.	Government Girls Higher Secondary and Basic Training School, Karnal ..	—	1	1
3.	Government Girls J. B. T. Centre, Pundri ..	—	1	1

[Education and Local Government Minister]

1	2	3	4	5
	DISTRICT KARNAL—concld			
	Government Institutions—concld			
4.	Government High School, Ladwa ..	½	½	1
5.	Government Girls Higher Secondary School, Kaithal ..	—	1	1
6.	Government Higher Secondary School, Gharaunda ..	½	½	1
7.	Government Higher Secondary School, Kaithal ..	1	—	1
8.	Government Higher Secondary School, Shahbad ..	½	½	1
9.	Government High School, Taraori ..	½	⅓	1
10.	Government High School, Assand ..	1	—	1
11.	Government High School, Naguran ..	1	—	1
12.	Government High School, Padla ..	1	—	1
13.	Government High School, Pehowa ..	1	—	1
14.	Government High School, Karora ..	1	—	1
	Total ..	10	5	15
	Private Institutions			
15.	Daya Nand Training School for Women, Karnal ..	—	1	1
16.	L. I. B. Higher Secondary School, Panipat ..	1	—	1
17.	Mata Harkaur Arya Girls High School, Model Town, Panipat ..	—	1	1
18.	Gandhi Memorial High School, Naraina ..	1	—	1
19.	Janta High School, Kaul ..	1	—	1
20.	A.S. High School, Pundri ..	1	—	1
	Total ..	4	2	6
	GRAND TOTAL ..	14	7	21
	DISTRICT HISSAR			
	Government Institutions			
1.	Government Basic Training School, Pabra ..	2	—	2
2.	Government Girls Higher Secondary School, Hissar ..	—	1	1
3.	Government Girls Higher Secondary School, Bhiwani ..	—	1	1
4.	Government High School, Podhan ..	1	—	1

1	2	3	4	5
	DISTRICT HISSAR—concld			
	Government Institutions—concld			
5.	Government Girls Higher Secondary School, Sirsa ..	—	1	1
6.	Government Girls High School, Fatehbad ...	—	1	1
7.	Government High School, Narnaud ...	1	—	1
8.	Government J.B.T. Centre, Jamalpur Sheikhon ..	1	—	1
9.	Government J. B. T. School, Bal Masand ..	1	—	1
10.	Government J. B. T. Centre, Rakhi Shahpur ..	1	—	1
11.	Government High School, Dhaowali	1	—	1
12.	Government High School, Chonala ..	1	—	1
13.	Government High School, Dhanana ..	1	—	1
14.	Government Girls High School, Hansi ..	—	1	1
	Total ..	10	5	15
	Private Institutions			
15.	Jat High School, Hissar ..	2	—	2
16.	Vaish Higher Secondary School, Bhiwani ..	1	—	1
	Total ..	3	—	3
	GRAND TOTAL ...	13	5	18
	DISTRICT BHATINDA			
	Government Institutions			
1.	Government Basic Training School, Faridkot ...	2	—	2
2.	Government Basic Training School, for Women, Faridkot ..	—	2	2
3.	Government High School, Baja Khana ..	½	½	1
4.	Government Girls High School Budhlada ..	—	1	1
5.	Government High School, Mandi School ..	1	—	1
6.	Government Girls High School, Phul ..	—	1	1
7.	Government Girls High School, Mansa ..	—	1	1

[Education and Local Government Minister]

1	2	3	4	5
	DISTRICT BHATINDA—*concld.*			
	Government Institutions—*concld.*			
8.	Government High School, Jhunir ..	1	—	1
9.	Government High School, Khara ..	1	—	1
10.	Government High School, Wander Jatana ..	½	½	1
11.	Government High School, Bhikhi ..	½	½	1
	Total ..	6½	6½	13
	Privately-managed Institutions			
12.	S.B. Bhai Pheru Khalsa High School, Faridkot ..	1	—	1
13.	Moti Ram S.D. Kanya Maha Vidyala, Bhatinda ..	—	1	1
14.	S. D. Higher Secondary School, Bhatinda ..	1	—	1
15.	M. H. P. Higher Secondary School Bhatinda ..	1	—	1
16.	Dev Samaj Girls High School, Mandi Phul ..	—	1	1
17.	S. D. Girls High School, Mandi Phul ..	—	1	1
18.	Gandhi High School, Mansa ..	1	—	1
19.	Khalsa High School, Mansa ..	1	—	1
	Total ..	5	3	8
	GRAND TOTAL ..	11½	9½	21
	DISTRICT LUDHIANA			
	Government Institutions			
1.	Government Basic Training School, Jagraon ..	1	1	2
2.	Government Girls High School, Samrala ..	—	1	1
3.	Government Girls High School, Narangwal ..	—	1	1
4.	Government Girls High School, Raikot ..	—	1	1
5.	Government High School, Killa Raipur ..	1	—	1
6.	Government Girls Higher Secondary School, Khanna ..	—	1	1
7.	Government High School, Payal ..	1	—	1
8.	Government High School, Jarg ..	1	—	1
9.	Government High School, Doraha ..	½	½	1
	Total ..	4½	5½	10

1	2	3	4	5
	DISTRICT LUDHIANA—*concld.*			
	Privately-managed Institutions			
10.	Basic Training College for Women, Sidhwan Khurd ..	—	2	2
11.	Sargodha Girls High School, Ludhiaha ..	—	2	2
12.	Khalsa Girls High School Raipur ..	—	1	1
13.	Malwa Training College, Ludhiana ..	½	½	1
14.	Khalsa High School, Jaspalon ..	1	—	1
15.	Khalsa Training College, Guru Sar Sudhar ..	1	—	1
16.	Khalsa High School, Guru Sar Sudhar ..	1	—	1
	Total ..	3½	5½	9
	GRAND TOTAL ..	8	11	19
	DISTRICT FEROZEPUR			
	Government Institutions			
1.	Government Junior Basic Training School, Jalalabad West ..	1	1	2
2.	Government Junior Basic Training School, Phullanwala ..	1	—	1
3.	Government High School, Fazilka ..	1	—	1
4.	Government Girls High School, Fazilka ..	—	1	1
5.	Government Girls High School, Patto Hira Singh ..	—	1	1
6.	Government High School, Mukatsar ..	1	—	1
7.	Government Girls Higher Secondary School, Abohar ..	—	1	1
8.	Government Basic Training Centre, Dhudeke ..	—	1	1
9.	Government Higher Secondary School, Guruhar Sahai ..	1	—	1
	Total ..	5	5	10
	Privately-managed Institutions			
10.	Sikh Kanya Mahavidyala, Ferozepore ..	—	1	1
11.	Dev Samaj College for Women, Ferozepore	—	2	2
12.	Village Teachers Training School, Moga ..	1	1	2

[Education and Local Government Minister]

1	2	3	4	5
	DISTRICT FEROZEPORE—*concld.*			
	Privately-managed Institutions—*concld.*			
13.	Malwa Khalsa High School, Ferozepore ..	1	—	1
	Total ..	2	4	6
	GRAND TOTAL ...	7	9	16
	DISTRICT SIMLA			
	Government Institutions			
1.	Government Training College for Women, Simla ..	—	1	1
2.	Government Higher Secondary School, Kandaghat ..	1	—	1
3.	Government JBT. Centre, Kasauli ..	—	1	1
	Total	1	2	3
	Private Institutions		Nil	
	GRAND TOTAL ..	1	2	3
	SANGRUR DISTRICT			
	Government Institutions			
1.	Government JBT School, Khunga Kothi ..	2	1	3
2.	Government Girls High School, Jind ..	1	—	1
3.	Government High School, Malerkotla ..	1	—	1
4.	Government Girls Higher Secondary School, Sangrur ..	—	1	1
5.	Government Girls High School, Sunam ..	—	1	1
6.	Government Girls High School, Munak ..	—	1	1
7.	Gove nment High School, Sukhpur Moran ..	1	—	1
8.	Government High School, Dhanudha Kalan ..	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
9.	Government High School, Balu ..	1	—	1
10.	Government High School, Kalayat ..	1	—	1
11.	Government High School, Safidon ..	1	—	1
12.	Government Girls High School, Dhuri ..	—	1	1
13.	Government High School, Lehra Gaga ..	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
14.	Government Hfgh School, Bhadaur ..	1	—	1
	Total ..	10	6	16

1	2	3	4	5
	Private Institutions			
1.	MGMN Higher Secondary School, Ahmedgarh ..	2	—	2
2.	Jain Muni Kanya Mahavidyala, Ahmedgarh ..	—	1	1
3.	Jat High School, Jind ..	1	—	1
4.	Akal Higher Secondary School, Mastuana ..	1	—	1
5.	Khalsa High School, Bakhatgarh ..	1	—	1
6.	S. S. Jain Girls Higher Secondary School, Malerkotla ..	—	1	1
	Total ..	5	2	7
	GRAND TOTAL ..	15	8	23

DISTRICT PATIALA

1	2	3	4	5
	Government Institutions			
1.	Government JBT. Institution, Nabha ..	2	—	2
2.	State College of Education, Patiala ..	½	1½	2
3.	Government Girls High School, Gobindgarh ..	—	1	1
4.	Government High School, Nandpur-Kesho ..	1	—	1
5.	Government High School, Bassi Pathana ..	½	½	1
6.	Government High School, Samana ..	1	—	1
	Total ..	5	3	8
	Privately Managed Institutions			
7.	Arya Girls High School, Nabha ..	—	1	1
8.	Union High School, Rajpura ..	1	—	1
9.	Jain Girls High School, Dehra Bassi ..	—	1	1
10.	A.P.S.D. Girls Higher Secondary School, Patiala ..	—	1	1
11.	Mohindra Kanya Vidayala, Patiala ..	—	1	1
12.	Sewa Girls Samiti Hindu High School, Patiala ..	—	1	1
13.	S. D. Girls High School, Nabha ..	—	1	1
	Total ..	1	6	7
	GRAND TOTAL ..	6	9	15

[Education and Local Government Minister]

1	2	3	4	5
	MOHINDERGARH DISTRICT			
	Government Institutions			
1.	Government High School, Mohindergarh ..	1	—	1
2.	Government Girls Higher Secondary School, Mahindergarh ..	—	1	1
3.	Government High School, Gokalpur	1	—	1
4.	Government High School, Narnaul ..	1	—	1
5.	Government Girls Higher Secondary School, Narnaul ..	—	1	1
6.	Government Higher Secondary School, Dadri ..	1	—	1
7.	Government High School, Kanina ..	1	—	1
8.	Government Girls Higher Secondary School, Dadri ..	—	1	1
	Total ..	5	3	8
	Privately Managed Institutions			
9.	S. D. Higher Secondary School, and J. B. T. Institution, Narnaul ..	2	—	2
	Total ..	2	—	2
	Grand Total ..	7	3	10
	DISTRICT AMRITSAR			
1.	Government Basic Training School, Sarhali ..	2	—	2
2.	Government High School, Sathiala ..	1	—	1
3.	Government High School, Patti ..	1	—	1
4.	Government High School, Khalra ..	1	—	1
5.	Government High Sehool, Bhangali ..	—	1	1
6.	Government Girls High School, Kairon ...	—	1	1
7.	Government Girls Higher Secondary School, The Mall, Amritsar ..	—	1	1
8.	Government Girls High School, Rayya ..	—	1	1
9.	Government Girls Higher School, Ajnala ...	—	1	1
10.	Government Girls High School, Jandiala Guru ..	—	1	1
11.	Government Girls Higher Secondary School Patti ..	—	1	1
	Total ..	5	7	12

1	2	3	4	5
	Privately Managed Institutions			
12.	Guru Arjan Dev Khalsa High School, Tarn Taran ..	1	—	1
13.	S. I. S. Trust High School, Verka ..	1	—	1
14.	S. D. Higher Secondary, School. Amritsar ..	1	—	1
	Total ..	3	—	3
	GRAND TOTAL ..	8	7	15

DISTRICT GURDASPUR

1	2	3	4	5
	Government Institutions			
1.	Government Normal High School, Gurdaspur ..	—	2	2
2.	Government Basic Training Centre, Tughalwala ..	½	½	1
3.	Government High School. Dalhousie	½	½	1
4.	Government High School, Dera Baba Nanak ..	1	—	1
5.	Government Girls High School. Dera Baba Nanak ..	—	1	1
6.	Government High School, Kahnuwan	1	—	1
7.	Government Girls High School, Batala	—	1	1
8.	Government High School, Harpur Dhandori ..	1	—	1
9.	Government High School, Narot Jaimal Singh ..	1	—	1
10.	Government Basic Training Centre, Behrampur ..	1	1	2
11.	Government Girls High School, Siri Hargobindpur ..	—	1	1
12.	Government High School. Siri Hargobindpur ..	1	—	1
13.	Government High School, Bhanguri	1	—	1
	Total ...	8	7	15
	Privately Managed Institutions			
14.	S.D. High School, Fatehgarh Churian	1	—	1
15.	S.D. School, Geeta Bhavan, Gurdaspur	—	1	1
	Total ..	1	1	2
	GRAND TOTAL ..	9	8	17

[Education and Local Government Minister]

DISTRICT HOSHIARPUR

1	2	3	4	5
	Government Institutions			
1.	Government Basic Training School, Dholbaha ..	2	—	2
2.	Government Girls Higher Secondary School, Hoshiarpur ..	—	1	1
3.	Government Girls High School, Nangal Township ..	—	1	1
4,	Government Girls High School, Dasuya ..	—	1	1
5.	Government Girls High School, Mahilpur ..	—	1	1
6.	Gevernment, Basic Training Centre Mubarikpur ..	½	½	1
7,	Government Higher Secondary School, Talwara ..	1	—	1
8.	Government Higher Secondary School. Garhshankar ..	1	—	1
9.	Government High School, Urmar ..	1	—	1
10.	Government Girls High School, Bedal ..	—	1	1
11.	Government J.B.T. Centre, Khunkhun Kalan ..	2	—	2
	Total ..	7½	5½	13
	Privately Managed Institutions			
12.	D.A.V. High School, Una ..	1	—	1
13.	Rajpur High School, Binjon ..	1	—	1
14.	Guru Gobind Sahib Khalsa High School, Maini ..	1	1	2
15.	D.A.V. High School. Gardiwala ..	1	—	1
16.	D.A.V. High School, Bala Chaur ..	1	—	1
17.	D.A.V. High School, Bassi Kalan ..	1	—	1
18,	Okara Putri Pathshala Gardiwala ..	—	1	1
19.	S. D. Higher Secondary School, Basdhera ..	1	—	1
20.	Khalsa Co-educational High School, Baddon ..	1	—	1
21.	S. D. High School. Anandpur Sahib	1	—	1
	Total ..	9	2	11
	GRAND TOTAL ..	16½	7½	24

1	2	3	4	5
	DISTRICT JULLUNDUR			
	Government Institutions			
1.	Government Basic Training School, Naura ..	—	2	2
2.	Government High School, Shankar ..	—	1	1
3.	Government High School, Samrai Jandiala ..	1	—	1
4.	Government Girls High School, Nakodar ..	—	1	1
5.	Government Girls High School, Khurdpur ..	—	1	1
6.	Government Girls High School. Banga	—	1	1
7.	Government High School, Rahon ..	1	—	1
8.	Government High School, Daroli Kalan	1	—	1
9.	Government High School, Nur Mahal	1	—	1
	Total ..	4	6	10
	Private Institutions			
10.	M. G. M. Basic Training College, Jullundur ..	—	2	2
11.	S. D. High School, Shankar ..	1	—	1
12.	Shri Guru Ravi Dass High School, Jullundur ..	—	1	1
13.	Khalsa High School, Rurka Kalan ..	1	—	1
14.	Khalsa High School, Nangal Ambia ..	1	—	1
15.	Gandhi Vanita Ashram, Jullundur ..	—	—	1
16.	Public High School, Lambra ..	1	—	1
	Total ...	4	4	8
	GRAND TOTAL ..	8	10	18
	DISTRICT KANGRA			
	Government Institutions			
1.	Government Basic Training School, Hamirpur ..	2	—	2
2.	Government Basic Training School, Dharamsala ..	—	2	2
3.	Government Girls High School, Pragpur ..	—	1	1
4.	Government Higher Secondary School, Sujanpur Tira ..	½	½	1
5.	Government Girls High School, Nurpur ..	—	1	1

[Education and Local Government Minister]

1	2	3	4	5
6.	Government Higher Secondary School, Rajpur ..	1	—	1
7.	Government High School, Rakkar ..	1	—	1
8.	Government Girls High School, Chudhiar ..	—	1	1
9.	Governmeut Girls High School, Nadaun	—	1	1
10.	Government Girls High School, Bani ..	½	½	1
11.	Government Basic Training College, Dharamsala ..	1	—	1
12.	Government Girls High School, Hamirpur ..	—	1	1
	Total ..	6	8	14
	Privately Managed Institutions			
13.	S. D. Teachers Training School, Baijnath ..	2	—	2
14.	S. M. R. High School, Indora	1	—	1
15.	Sood A. S. Higher Secondary, School, Garli ..	2	—	2
	Total ..	5	—	5
	GRAND TOTAL ..	11	8	19
	Government Institutions			
1.	Government Basic Training School, Kulu ..	1	1	2
	Total ..	1	1	2
	DISTRICT KAPURTHALA			
	Government Institutions			
1.	Government Janta College, Sheikhupura ..	2	—	2
2.	Government Girls Higher Secondary School, Sanghian ..	—	1	1
	Total ..	2	1	3

1	2	3	4	5
	Privately Managed Institutions			
3.	Mont. Basic Training School Kapurthala ..	—	2	2
4.	Ramgarhia Training College, Phagwara	1	1	2
5.	M. D. S. D. Higher Secondary School, Kapurthala ..	½	½	1
6.	S. D. Higher Secondary School, Sultanpur Lodhi ..	1	—	1
	Total ..	2½	3½	6
	GRAND TOTAL ..	4½	4½	9

To

The Heads of all Government/Private Junior Basic Training Institutions in the State.

Memo No. 1862-4/53—64—PBE (5),
Dated Chandigarh, the March, 1965.

Subject—Rules and Regulations for admission to JBT Classes.

In supersession of all the rules and regulations issued from time to time, the following rules and regulations will be observed for admissions to the Junior Basic Course for the Session 1964-66.

Duration—The duration of the JBT Course will be two years and there shall be an examination at the end of each year which will be conducted by the Department. The academic year would mean from first of November, to 31st of October, each year. After the examination of the first year, the class will continue in 2nd Year in an institution in anticipation of the results of the departmental examination for the first year. The departmental annual examination of I year class will be held in October, 1965 and final examination for these candidates will be held in October, 1966.

Each unit shall consist of 40 seats, provided that Director of Public Instruction, Punjab, may allow additional seats not exceeding six in hard cases, but reason in each case shall be recorded.

Qualifications—The minimum qualifications for admission shall be 2nd class in Matriculation with English as one of the subjects in Matriculation and a knowledge of Hindi and Punjabi. Vidya Vinodini qualification is not now recognised by the Punjab Education Department/ Punjab University. In case a candidate has acquired a qualification higher than Matriculation viz., Intermediate (full), Prabhakar, Gyani, Shastri etc., he/she shall be accepted for admission irrespective of his/

[Education and Local Government Minister]

her division in the Matriculation. Further the minimum qualification for admission may be relaxed to a pass in Matriculation with English as one of the subjects in Matriculation and a knowledge of Hindi and Punjabi in the case of women candidates and candidates belonging to Scheduled. Castes/Tribes and Backward Classes/areas. However, in relaxation of normal rules, the adult women having passed their Matric/school examination under the Central Social Welfare Board Scheme condensed course of training for adult women shall be allowed admission to J.B.T. course.

Merit—The minimum qualification for admission being a pass in Matriculation Examination or its equivalent the merit of the candidate will be determined as under :—

(i) Total marks to be awarded for academic attainment on the basis of marks obtained in the Matric. Examination should be ½ (one half) and then two left hand digits (i.e. $\frac{900}{2}=450=45$)

(ii) Marks for interview :—

(a) Suitability (physique, intelligence, proficiency in sports etc.) ...... 20 marks.

(b) Teaching Experience:—Three Marks shall be awarded for each year's teaching experience after the first year with an upper limit of 6 marks. The teaching experience shall be certified by the District Education Officer concerned on the basis of the report of the Block Education Officer of the area. This experience shall cover only genuine teaching work for which a candidate has been borne on the staff of a recognised school as a paid teacher. Honorary service in a recognised school shall not be allowed any credit.

(iii) Special Claims—

(a) Military Service (the person concerned, son/daughter/wife/husband).........?

(b) Son/daughter/wife of a teacher or a political sufferer....7

(c) Seven marks will be awarded for Urdu knowing candidates at the time of admission in J.B.T. Institutions in Malerkotla Tehsil of Sangrur and Ferozepur-Jhirka and Nuh Tehsil of Gurgaon District.

The marks obtained by candidates with equivalent qualifications from outside the jurisdiction of Punjab University, will be reckoned out of 900 for consideration with Matriculates of Punjab University. Provided further that candidate possessing following qualifications will be given preference over matriculates in the matter of admission in the order given below:—

(i) Gianies, Prabhakar or Shastri who have also passed matriculation or equivalent examination in all subjects including English.

(ii) Those who have passed Higher Secondary/Post Basic/Pre-University course or Senior Cambridge, Intermediate or B. A. Examinations.

Reservation of seats—Reservation of seats will be made as under:—

(a) 20% of the seats for candidates belonging to Scheduled Castes/Tribes.

(b) 2% of the seats for candidates belonging to backward classes.

(c) 40% seats shall be reserved for candidates who are bona fide residents of rural and backward areas. Before the claim of the candidate in this respect is entertained he/she shall be required to produce a backward area certificate both from the Sarpanch of the Panchayat concerned as well as of the Head of the institution from which he/she passed Matric/Higher Secondary etc. examination.

(d) 8% of the seats for women candidates who are widows, destitutes or unhappy women.

(e) 2%seats for sportsmen of outstanding distinction having played in Divisional/Inter-Divisional Tournments.

Besides above reservations, local candidates shall be first admitted then admission of out siders will take place to fill the remaining seats.

Bond—Before a candidate is admitted to a training institution, he/she have to execute a legal bond for Rs 800 in the case of stipendiary candidates and a sum of Rs 600 in the case of non-stipendiary candidates to serve in the Punjab. (A specimen copy of the bond to be executed is enclosed.)

SUBMISSION OF APPLICATIONS

A candidate seeking admission to the J. B. T. class shall submit the application in duplicate, on the prescri bed form (copy enclosed) one copy to the Head of the institution in which admission is sought and the other copy to the District Education Officer concerned within ten days of the advertisement for admission by the head of the Institution or within such extended period as the Director of Public Instruction Punjab may specify. The date of interview shall be fixed by the head of the institution in consulation with the District Education Officer concerned. The selection of candidates shall be made by the Board consisting of D. E. O. or his/her Deputy. Head of the institution concerned and head of another Institution Government/Private situated and head of another Institution Government/Private situated locally or within five miles from the place of location of a particular institution (to be nominated by the District Education Officer). The Head of the institution shall ensure that dates prescribed for advertising admission, holding interview, for selection are strictly followed and regular classes are started immediately after the admission has been completed but not later than the date fixed by the Director of Public Instruction, Punjab.

[Education and Local Government Minister]

Waiting lists will be prepared separately for reserved and general categories and vacancies will be filled up according to these ists. In case, however, the candidates from the reserved categories are not forthcoming within 15 days, the vacancies will be offered to the candidates of general category.

Age Limit—The age of a candidate shall be counted as on the first November. The age limit shall be as under :—

Men : Minimum—Plus 16 years.

Maximum—30 years relaxable upto 33 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Backward Classes and those belonging to Kangra and Mohindergarh Districts.

Women : No minimum and maximum age restriction.

Provided that the Director of Public Instruction Punjab or an Officer he delegates with powers may be special circumstances relax the minimum age limit in respect of men candidates.

Prospectus—The prospectus of an institution shall not be sold at a price exceeding 25 P. pe copy. Nothing shall be charged for the admission form.

LEVY OF FEES AND STUDENTS FUNDS

The Government/Private J. B. T. Institutions shall levy fees and funds as under :—

		Boys	Girls.
(a)	Tuition fee	Rs 8 P. M.	Rs. 4 P. M.

All concessions will be available to the JBT students as in high and higher secondary schools.

(b) Admission fees Rs 1

(c) Electricity fee. Boarders will have to pay the entire electricity bill if electricity is provided.

(d) Late fees for transfer certificates .. 50 P.

(e) Science fee .. 40 P.

(f) Hostel fee. Boys Rs 1 Girls .. 50 P.

Fine—

(a) Fines for absence 25 P. each day or a part of a day.

(b) Finc for late fee payment 10 P. per-day.

Securites—

(a) Library Security (Rs 10 refundable).

(b) Hostel Security (Rs 15 refundable).

Funds—

(a) Amalgamated fund for boys & girls Rs 2 P. M.

(b) Red Cross per mensum.

(c) Health Fund & Scouts : 25 P.

(d) Audio-visual Funds 15 P.

(e) Divisional Scouts & Guids and Rally Fund 15 P. P.M-

(f) Domestic Science Fund : 40 Paise only from girls students taking Home Science.

(g) Magazine Fund : 25 Paise per month.

(h) The private institutions will also allow requisite number of fee concession to the Trainees as given in the Punjab Education Code.

MEDICAL EXAMINATION

(a) Medical examination shall be compulsory for all candidates seeking admission to Government or Private Institutions. It shall be conducted by the Medical Officer of the Institution or by the incharge local Government Civil Dispensary and if neither of them is available in the area by a registered medical practitioner.

(b) Women candidates in the family way will not be admitted to the course. The candidates who get into this condition during the course of training will be required to quit the class.

From

The Director, Public Instruction, Punjab.

To

All the Heads of Government/Private JBT Institutions in the State.

Memo. No. 7/23—64—PBE (5)

Dated Chandigarh, the 20th October, 1964

Subject—Admission to the Junior Basic Training Course for the Session 1964-66.

The Institutions mentioned in the enclosed list have been sanctioned JBT unit/units for the session 1964—66. The number of units allotted to each school is mentioned against the name of that school. Each unit consists of 40 Seats. The admission should be made strictly in accordance with the rules and regulations (copies enclosed).

All institutions should advertise admissions in at least one English Newspaper and one Modern Indian Language Newspaper so that wide publicity is given for admission. The following time schedule should be observed.

[Education and Local Government Minister]

(i) Premilitary work in connection with the printing of application forms,, fixing last date for receipt of application, date of interviews etc., in consultation with the DEO concerned, and issue of notice in the News-paper may for wide publicity be arranged by the 26th October, 1964.

(ii) Selection of candidases by the selection board, medical examination, payment of dues should furnish by 13th November, 1964 or earlier.

(iii) The last date of the receipt of application should be the 4th November, 1964.

(iv) The regular class work should starts w. e. f. 14th November, 1964. positively.

The Selection Board shall consist of the District Education Officer or Deputy District Education Officer. The Head of the institution in which admission has to take place; and the Head of the Government/ Private institution in the neighbourhood within a radius of five miles to be nominated by the District Education Officer. The Selection Board for the admission of JBT class given to a Government Training College or an institution under the administrative control of its Principal, of a Government Training College shall consist of three members nominated by the Principal concerned.

The list of selected candidates in each of the six categories, viz.

(a) General.

(b) Candidates belonging to the backward areas.

(c) Candidates belong to the scheduled caste.

(d) Candidates belonging to the backward classes.

(e) Women candidates deserted and destitute ladies.

(f) Adult women who have passed the condensed course organised by the Social Welfare Department.

must be finalised on the day when the interview is held and must be exhibited on the Notice Board the same day. Copies of such list duly signed by the members of the Selection Board should be supplied to Deputy Circle Education Officer, Teachers Training concerned and Assistant Director (Teachers Training) by name by 20th November, 1964. The dues to be charged from the candidates should be exhibited on the Notice Board and should be charged by 13th November, 1964 or earlier. Class work must being on 14th November, 1964 positively. Tuition fee etc., should be charged from 1st November, 1964.

Any vacant seat is to be filled up from the candidates on the waiting list immediately but not later than 15 days after the commencement of the classes.

No migration will be allowed from the original station of admission except in very hard cases and that too upto 15th December, 1964, After this only those cases of migration in which transfers of parent guardians are involved, will be considered.

It may be emphasized again that the admission should be made strictly in accordance with the rules and regulations laid down for the purpose. No provisional admission should be made in any case. All cases of relaxation in age limit should be referred to this office by 20th November, 1964.

STAFFING PATTERN ACCOMMODATION FURNITURE AND EQUIPMENT FOR PRIVATE INSTITUTIONS

It is desirable that newly started private institutions are run efficiently and the management concerned should make adequate provision for staff, accommodation, equipment as given in the enclosed Annexure. They should also make hostel arrangements for as large a number as possible but in no case less than 50% of the candidates admitted by them. The management should send a certificate to the Deputy Circle Education Officer Teachers training concerned and Assistant Director Teachers Training by name that they have made arrangements for adequate staff, accommodation and equipment in this connection. They should also see that a high standard of training is maintained as units sanctioned to them are provisional and subject to their satisfactory performance.

Observance of Rules—It is emphasised again that admission should be made strictly in accordance with the rules and regulations laid down for this purpose. In the past, some of private institutions used to indulge in malpractices as noted belows :—

(1) Acceptance of donations from the candidates over and above the fees and funds prescribed by the Department.

(2) Charging higher rate of fees and funds than those prescribed by the Department.

(3) Unauthorised collections.

(4) Non-maintenance of proper receipt of applications and other record concerning admission of candidates.

(5) Irregular selection on account of favouritism, nepotism, and under undue pressure etc.

The Heads of the Private Managed Institutions are required to avoid such mal-practices. Government will take a serious view if any such malpractice is repeated. Penalty may even go to the extent of withdrawing JBT unit/units.

The instructional work should be carried on the accordance with the revised JBT syllabus which can be had from the Controller, Printing and Stationery Department, Chandigarh, on payment.

Please acknowledge its receipt.

Sd/
Deputy Director (Pirmary Education.)
for Director of Public Instruction, Punjab.

REPRESENTATION FOR OPENING A DEGREE COLLEGE AT AMB, IN HOSHIARPUR DISTRICT

***6886. Pandit Mohan Lal Datta** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) whether Government has decided to open a degree College in each Sub-Division of the backward hilly areas of the State;

(b) whether it is a fact that there is no College in tehsil Una;

(c) the number of High and Higher Secondary Schools in Una Sub-Division with the population and the area thereof;

(d) whether the Government propose to open a College in the said Sub-Division, if so, when;

(e) whether Government has received any representation from a number of M.L.A s from Una and the adjoining hilly areas of Kangra District requesting for the opening of a College at Amb, a central place for the areas of Hoshiarpur and Kangra District, if so, the action taken or proposed to be taken in this behalf ?

Shri Prabodh Chandra : (a) No.

(b) Yes.

(c) (i) Number of High/Higher Secondary Schools .. 38.

(ii) Population .. 3,59,967.

(iii) Area .. 4,41,761 Acres.

(d) No.

(e) Yes. The matter is under consideration.

पंडित मोहन लाल दत्त : यह जो सब डिवीज़न है इस में 38 हाई स्कूल हैं और इस के मुकाबला में जहां पर बहुत कम स्कूल हैं वहां पर भी सरकारी कालिज हैं मसलन टांडा में। तो क्या कारण है कि इस इतने बैकवर्ड हिल्ली एरिया में जहां पर चार लाख की आबादी है आज तक क्यों इस बात पर गौर नहीं किया गया कि वहां पर कालिज खोला जाए ?

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : आज तक क्यों गौर नहीं किया जा सका इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जब से यह वजारत बनी है इस ने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा ऐजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्ज़ बैकवर्ड इलाकों में खोले जाएं मगर पैसे की तंगी की वजह से हमारा ख्याल नहीं कि हम वहाँ पर कालिज खोल पाएंगे।

पंडित मोहन लाल दत्त : इस में कुछ कन्ट्राडिक्शन सी मालूम देती है। इसे जवाब में कहा गया है कि वहां पर कालिज खोलने का इरादा नहीं है मगर दूसरी तरफ जब पुछा गया कि कांगड़ा ज़िला के एम० एल० एज़० की तरफ से कोई रिप्रीज़ैंटेशन मिला है तो बताया गया है कि वह ज़ेरे गौर है। तो एक तरफ तो नो कहते हैं और दूसरी तरफ जेरेगौर बताते हैं। तो क्या बात सही है ?

मन्त्री : कोई भी रिप्रीज़ैंटेशन जो किसी की तरफ से आता है खास तौर पर जो लेजिस्लेटर्ज़ की तरफ से आता है तो उस पर गौर तो होता ही है। मैंने कहा है कि मौजूदा माली मुश्किलात को सामने रखते हुए यह मुम्किन नहीं होगा कि ऊना में कोई कालिज खोला जा सके।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी सब-डिवीज़न में कालिज खोलने के लिये किन किन बातों को मद्देनज़र रखा जाता है।

मन्त्री : इलाके की जरूरतों को सामने रखा जाता है। यह भी देखा जाता है कि इस कालिज को फीड करने के लिये उस इलाके में कितने हाई स्कूल हैं। ऊना यह कन्डीशन पूरी तो करता है--हम ने कभी नहीं कहा कि वहां पर कालिज की जरूरत नहीं है--मगर जो माली मुश्किलात सरकार की हैं उनकी वजह से यह इस काबिल नहीं है कि बहां पर नया कालिज खोला जाए।

श्री बनवारी लाल : इन्होंने जवाब में कहा है कि इन के पास बजट में पैसा नहीं है अगर यह बात है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि बैकवर्ड इलाकों का ऐजुकेशन के लिहाज़ से दूसरे इलाकों के बराबर लेवल लाने का यह क्या इन्तज़ाम सोच रहे हैं ?

मन्त्री : अर्ज़ यह है कि इस सिलसिले में सरकार की यह हिदायत है कि जितने नए इन्स्टीटयूशन्ज़ खोलने हैं या अपग्रेड करने हैं उस वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो इलाके पिछड़े हुए हैं वहां पर ज्यादा स्कूल खोले जाएं या अपग्रेड किए जाएं बनिसबित उन इलाकों के जो आगे निकले हुए हैं।

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, कुल 55 लाख रुपया मन्जूर हुआ है 50 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिये। ऐजुकेशन मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और और खोलने के काबिल नहीं है मगर जहां पर बाई इलैक्शन होता है वहां पर तो वायदा कर देते हैं तो यह काबिल कैसे नहीं हैं और इस सरकार के यहाँ पर बैठने की क्या जरूरत है ?

मन्त्री : जनाब मैं यह गलत फहमी दूर करना चाहता हूं कि कोई वायदे हमने किए हैं। मुझे नहीं पता कि कोई किया गया या कि नहीं किया गया। जहां पर भी मैं गया हूं मैंने साफ कहा है कि मैं किसी वायदे को नहीं जानता, स्टेट की पालिसी यह है कि बैकवर्ड इलाके में स्कूल खोले जाएंगे इसी के मुताबिक खोले ज़ाएंगे न कि यह ख्याल रखा जायेगा कि कोई वायदा किया गया है या कि नहीं।

पंडित मोहन लाल दत्त : सरकार ने अपनी माली मुश्किलात की वजह से अपनी मजबूरी जाहिर की है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उस इलाके के लोग जमीन दें 25–30 एकड़ और कुछ रुपया भी दें तो क्या उस सूरत में यह वहां पर कालिज खोलने पर गौर फरमाएंगे ?

मन्त्री : जनाब सवाल सिर्फ एक बार कालिज खोल देने का ही नहीं है बल्कि उस पर जो रेकरिंग खर्च होते हैं उन को कैसे पूरा किया जाए इस बात को देखते हुए सरकार की यह पालिसी है कि जो पहले चल रहे हैं उन के सटैंडर्ड को ही ऊंचा किया जाय बजाए ऐसे कालिज खोल दिए जाएं जहां न बिल्डिंग हो, न बैठने को जगह वगैरह :

ਸਰਦਾਰ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਇਕ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਹੈ.. .

Mr. Speaker : This question relates to Hoshiarpur District.

ਸਰਦਾਰ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਰਾਉ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੰਡਜ਼ ਵੀ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਫੰਡਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਿਕੋਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਬਾਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜ਼ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਨਾਬੇਆਲੀ, ਅਗਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ।

Mr. Speaker : Next question, please.

Sardar Lachhman Singh Gill : Mr. Speaker, I want to put one more supplementary.

Mr. Speaker : No, please. I have called the next question.

Sardar Lachhman Singh Gill : I would again request the Chair to kindly allow me to put one more supplementary.

MR. Speaker : No, please.

चौधरी देवी लाल : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर सर। अभी अभी एजूकेशन मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि अगली पांच साला योजना में एक ही कालिज खोला जाएगा तो क्या यह सच नहीं कि बरनाला के हल्का में चुनाव के दौरान चन्धवाल में चीफ मिनिस्टर ने एक हाई स्कूल का मुग्रायना किया ग्रौर उस के रजिस्टर में लिखा कि इस को तो कालिज होना चाहिए। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस हाऊस के ग्रन्दर ग्रौर बाहर मिनिस्टर साहिबान एक ही ज़बान क्यों नहीं बोलते, यहां पर कुछ ग्रौर कहा जाता है ग्रौर बाहर चुनाव हल्कों में ग्रौर ही बात की जाती है ।

मुख्य मन्त्री : ग्रान ए पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन । जो बात चौधरी देवी लाल जी ने कही है मेरा ख्याल है कि इन्होंने रजिस्टर के मेरे इन्दराज को पढ़ा ही नहीं । मैंने उस स्कूल की हर चीज का मुग्रायना किया ग्रौर लिखा था कि एग्रीकलचर के संबंध में टयूब-वेल के लिहाज़ से यह एक बेहतरीन इन्स्टीचूट है ग्रौर हमारी जो एग्रो-इन्डस्टरी की पालिसी है उस पर यह स्कूल पूरा उतरता है ग्रौर इस इन्स्टीचूट को मदद दी जा सकती है ।

PERSONS RECOMMENDED FOR THE POST OF PRINCIPALS OF GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOLS.

*7502. **Sardar Kulbir Singh (Put by Shri Mangal Sein)** : Will the Minister for Education and local Government be pleased to state—

(a) the number of Headmasters/Headmistresses recommended by the Punjab Public Service Commission for the posts of Principals of Government Higher Secondary Schools in the State in P. E. S. Class II who have not so far been issued selection Cards together with the reasons therefor and the time by which such cards will be issued to them;

[Sardar Kulbir Singh]

(b) whether it is a fact that Selection Cards have been issued in the cases of some of those Headmasters/Headmistresses whose increments had been stopped ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Forty-three persons have not been issued intimation to the effect that their names have been recommended by the Public Service Commission. It is not in the public interest to disclose the reasons as the whole matter is still under the consideration of Government.

(b) Yes. There are a few such cases.

श्री मंगल सेन : क्या शिक्षा मन्त्री महोदय बताएंगे कि आप ने इस सवाल के जवाब में पार्ट 'बी' में कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं तो मैं उन के नामों की लिस्ट जानना चाहता हूं । क्या इन आदमियों में ऐसे आदमी भी सिलैक्ट कर लिए गए हैं जिनकी इन्क्रीमैन्ट रुकी हुई थी और अगर चुन लिया गया तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : मैंने अर्ज़ किया है कि 218 आदमी रिकमेन्ड किए गए थे पब्लिक सरविस कमिशन की तरफ से । इन में से 175 आदमियों को कलीयर चिट दे दी गई है । कुछ केसों में शिकायतें आई हैं कि उनकी कान्फीडैन्शल रिपोर्ट खराब है और रिकार्ड खराब है जिन को कि पब्लिक सरविस कमिशन के द्वारा चुना गया है तो इन शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डायरैक्टर को कहा है कि सारे केसों की सक्रूटनी की जाए और जो ठीक हों उनको रख लिया जाए ।

श्री मोहन लाल : स्पीकर साहिब, मैं यह जानना चाहूंगा कि एजूकेशन मिनिस्टर ने एक सवाल के जवाब में पंजाब लैजिस्लेटिव कौंसिल में यह ब्यान दिया था कि पब्लिक सरविस कमिशन की तरफ से जो यह सिलैक्शन की है यह आरबिटरेरी है और मेरिट पर नहीं और मैं चीफ मिनिस्टर को लिखूंगा कि वह इस सिलैक्शन को रिजैक्ट कर दें ।

मन्त्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि कुछ शिकायतें ऐसी आई हैं कि जो आदमी सिलैक्ट हुए हैं उन का रिकार्ड अच्छा नहीं था और उन के मुकाबला में कुछ आदमी जो रिजैक्ट किए गए हैं उनका रिकार्ड निहायत शानदार था और कई केसों में दिखाई हमें भी देता है कि गलेरिंगली उन को सिलैक्ट नहीं किया गया । तो मैंने कहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर से कहूंगा कि वह इस केस को पब्लिक सरविस कमिशन को फिर रैफर कर दें ताकि वह इन हालात में अपनी सिफारशों को रीकंसिडर करें या चीफ मिनिस्टर इन रिकमैंडेशन्ज़ को मानने से मजबूरी ज़ाहिर कर दें । क्यों कि पब्लिक सरविस कमिशन का मसला डैलीकेट है इस लिए इसके बारे में मैं स्पीकर साहिब, आप की मारफत हाऊस के मेम्बरों से इल्तजा करूंगा कि वह कमिशन के बारे में सवाल न करें तो अच्छा होगा ।

Shri Mohan Lal : Mr. Speaker, I rise on a point of Order. My supplementary question has not been answered. I put categorically to the Education Minister if he had stated in the Punjab Legislative Council that the selections made by the Public Service Commission were not on merits and were arbitrary and that he would write to the Chief Minister to reject those selections. This is what my supplementary was. No answer has come to it. I want a categorical reply as to whether he made such a statement in the Punjab Legislative Council or not ?

मंत्री : मुझे एग्ज़ैक्ट वर्डिंग याद नहीं । जहां तक मेरा ताल्लुक है । मैं ने यह नहीं कहा कि पब्लिक सर्विस कमिशन की सारी रिक्मेन्डेशन्ज़ गलत हैं मैं ने यह कहा था कि इन रिक्मेन्डेशन्ज़ के बारे में शिकायतें आई हैं कि जहां पर प्रीवीअस रिकार्ड अच्छा न था इन्हें सिलैक्ट कर लिया गया है और जहां पर रिकार्ड अच्छा था उनको रिजैक्ट कर दिया गया है । तो इन केसों की स्क्रूटेनी करने के लिए कहा था ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ . ..

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वांइट आफ आर्डर, सर । आप ने हुकम दिया था कि जो कोई प्वांयट आफ आरर्ड रेज़ करते समय सप्लीमेन्ट्री सवाल करेगा वह नहीं गिना जाएगा...............

Mr. Speaker : I have already requested the hon. Ministers that before replying to such questions my findings may also be awaited but when some Minister wants to intervene I do not stand in the way.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ?

Mr. Speaker : This is no point of Order. The hon. Member can put a supplementary.

चौधरी राम सरूप : On a point of Order sir. मैं यह पूछना चाहता हूं कि आया इस बात की गवर्नमैंट की अथारिटी है कि जिस को पब्लिक सर्विस कमिशन रिकमैंड कर दें उस को माने या न माने और जिस का पब्लिक सर्विस रिजैक्ट कर दे उस को कंसिडर करे ?

श्री अध्यक्ष : इस के मुताल्लिक रूल्ज बने हुए हैं । गवर्नमैंट को इख्तियार है कि नहीं, यह सब इन रूल्ज़ में हैं । (There are rules on the subject and whether the Government is competent or not to do so, is provided therein.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं वज़ीर साहिब से यह पूछना चाहूंगा कि आया यह सरकार की पालिसी है कि अगर पब्लिक सरविस कमिशन की सिफारिशात गवर्नमैंट के व्यूज़ के अगेंस्ट हों तो सरकार उन रिकमैंडेशन्ज़ पर दोबारा गौर करने के लिए नहीं भेजती ?

मन्त्री : वैसे तो पब्लिक सरविस कमिशन की सिफारिशात हम मान लेते हैं लेकिन अगर कोई गलेयरिंग चीज़ हमारे नोटिस में लाई जाए तो उसे हम रिजैक्ट भी कर सकते हैं । मैं आप से दरखास्त करूंगा और बेहतर यही होगा कि हम इस बहस को इस हाउस में और ज्यादा न बढ़ाएं, हमें यह बात भूलनी न चाहिये कि पब्लिक सर्विस कमिशन की सैंक्टिटी को बरकरार रखनें के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ । Still the Public Service Commission recommended their names. May I know from the hon. Education Minister the cases in which the records of the applicants were not satisfactory as also the reasons for referring those cases to the Public Service Commission ?

मन्त्री : मैं इस के मुताल्लिक और ज्यादा कहना नहीं चाहता, जैसे कि मैं ने पहले भी कहा था कि अगर इस मामले पर और चर्चा न की जाए तो मुनासिब होगा । पब्लिक सरविस कमिशन की सैंक्टिटी को हमें बरकरार रखना चाहिए । We are taking up the matter with the Public Service Commission also. ऐसे केसिज़ भी हुए हैं जो टर्म्ज़ फुलफिल नहीं करते थे मगर फिर भी वह ले लिये गये थे ।

श्री मोहन लाल : स्पीकर साहिब, मैं यह बात वाज़ेय तौर पर याद कराना चाहूंगा कि ऐजूकेशन मिनिस्टर साहिब ने लैजिस्लेटिव कौंसल में यह इलफाज़ कहे थे कि सिलैक्शन आर्बिट्रेरी हुई है और आन मैरिट्स नहीं है । एक सवाल के जवाब में भी उन्हों ने माना है ।

श्री अध्यक्ष : जो कुछ आप कहते हैं वह तो उन्हों ने पहले ही से मान लिया है अब आप और क्या चाहते हैं ? (What the hon. Member says has already been conceded by the hon. Minister. What else does he want ?)

Shri Mohan Lal : Sir, I want to proceed further. I want to put a supplementary question.

Mr. Speaker : The reply is on record.

Shri Mohan Lal : Unfortunately, that supplementary question has lapsed.

Mr. Speaker : The reply is there on record.

Shri Mohan Lal : Now the hon. Education Minister has taken a different stand. He says that he does not remember.

Mr. Speaker : He may not remember what he has already said. But his reply is on record.

Shri Mohan Lal : I have to put another supplementary question. Let him concede or deny.

श्री अध्यक्ष : अगर कोई सवाल आये और ओवरआल वह मान लिया जाये, then nothing further is required. (If any point arises and the overall position is accepted, then nothing further is required.)

Shri Mohan Lal : But the hon. Minister for Education and Local Government says that he does not remember.

Minister : Sir, if you permit me, I will explain the position. I have at no stage either in this House or in the Punjab Legislative Council said that all these recommendations were arbitrary. What I said was that complaints have reached me that some of the recommendations of the Public Service Commission have not been made on merit. I also added that in one or two cases, I feel that these people should not have been selected. This is what I said. I do not know what the hon. Member from Batala is driving at ?

Mr. Speaker : Reply to the points referred to has come. What more is required ? The reply is on record.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या शिक्षा मन्त्री बताएंगे कि जिन केसिज़ इन्हों ने देखा कि आन मैरिट फैसला नहीं हुआ क्या इन्हों ने उन को पब्लिक सर्विस कमिशन को रैफर बैक नहीं किया ?

मन्त्री : अभी नहीं किया । इन की अभी सक्रूटनी कर रहे हैं । 218 में से 175 को कलीयरैंस चिट दे दी गई हैं । सरकार ने अब यह पालिसी भी बना ली है कि रिज़लट्स की बिना पर हम किसी की भी प्रोमोशन रोकना नहीं चाहते ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੈਡਮਿਸਟਰੈਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਬਲਿਕ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰ ਮੁਤਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੀ ਨਾਲਜ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ।

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, may I know from the hon. Minister for Education and Local Government whether any of the rejected persons represented to the Government or the Government moved in the matter on its own ?

Mr. Speaker : Question Hour is over now. Supplementary Questions on this Question will continue.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONSL LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

CADRES OF TEACHERS

*7514 **Chaudhri Tek Ram** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the cadres of Teachers in the State have been split upinto two or more parts; if so, the names of such parts.

(b) whether there is any provision in the rules relating to the said cadres which places the senior Teachers of pre-provincialized Schools in a disadvantageous position as compared to their Junior counterparts; if so, the reasons therefore ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes, two: State and provincialised cadres.

(b) No. Teachers on each cadre are governed by a separate set of Service Rules.

ARREARS OF SOME LADY TEACHERS IN AMBALA DISTRICT

*7751 **Sardar Ajaib Singh Sandhu** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) whether it is a fact that certain lady Teachers in Ambala district have not been paid their arrears of pay for the periods of their Maternity Leave or due to them for their Selection Grades, if so, the details thereof and the reasons therefor;

(b) whether the Government comtemplate taking steps for the expeditious disposal of such cases, if so, when?

Shri Parbodh Chandra : (a) Yes.

(i) A statement containing the details and the reasons for non-disbursement of arrears of pay for Maternity Leave periods to the concerned Lady Teachers is laid on the Table of the House. Annexure †A

(ii) There are 17 cases of Lady Teachers who have not been paid arrears for their Selection Grades. The payment could not be made earlier as their promotionorders to Selection Grades were issued in January, and February, 1965. Their bills for promotion grades have been prepared and the payment is being arranged. The particulars of the incumbents are being collected and will be furnished separately.

(b) Yes. Instructions have been issued to the District Education Officer, Ambala. to expedite the disposal of all these pending cases as early as possible.

—Please see page (i) of Appendix to this debate

Note : For particulars please see Annexure 'B' at page ii & iii of Appendix to this Debate.

LIST SHOWING DETAILS OF MATERNITY LEAVE CASES IN RESPECT OF AMBALA DISTRICT

Sr.	Name of the teacher and School.	Period	Amount	Reasons
1	2	3	4	5
1.	Shrimati Devinder Saini, Government M. S. Hodel Town, Yamna Nagar.	4.1.65 to 3.4.1965	522·00	Leave case has not yet been sanctioned.
2.	Shrimati Amrit Kaur, G. M. S. Singh Pura	1-9-64 to 27-9-64	120·00	Leave sanctioned on 11th February, 1965. The bill has now been sent to the Treasury for pay order.
3.	Shrimati Baljit Kaur G. G. M. S., Sohana	5-64 to 7-64	349·25	Leave sanctioned on 17th February, 1965. Now the bill has been sent to the Treasury for pay order.
4.	Shrimati Shata Rai, G. M. S. Panjokra.	10-64 to 12-64	205·55	Leave sanctioned on 27th February, 1965. Now the bill has been sent to the Treasury for pay order.
5.	Shrimati Raj Sharma, G. M. S. Pinjora	7-64 to 9-64	204·20	Leave sanctioned on 11/64. Now the bill has been sent to the Treasury for pay order.
6.	Shrimati Ram Piari, G. M. S. Ugala	3-63	112·00	Leave sanctioned on 8.64. Now the bill has been sent to the Treasury for payment.
7.	Shrimati Shakuntla Arora, GMS. Sohana	9-63 to 10-64	216·00	Leave sanctioned on 23rd October, 1963. At the time of sanction of leave the teacher worked in a Primary School. Now the Bill is under correspondence with the A. G. Punjab for according sanction to the payment of the time barred claim.

[Education and Local Government Minister]

8.	Shrimati Mohinder Kaur, G. G. M. S. Chamkaur Sahib	23-8-64 to 16-2-65	600·00	Leave not yet sanctioned.
9.	Shrimati Purna Sharma, G. M. S. Sector 27 Chandigarh.	31-7-64 to 10-9-64	200·00	Ditto
10.	Shrimati Raj Kumari Do	10-64	225·00	Ditto
11.	Shrimati Kamla Sud Do	11-64	125·00	Ditto
12.	Shrimati Raj Kumari P. S. Rurkee Parao	22-7-64 to 27-10-64	384·00	Leave cases under consideration.
13.	Shrimati Bhagwant Kaur Do	14-7-64 to 28-11-64	2191·25	Ditto
14.	Shrimati Krishana Sethi, P. S. Kalka	October 64 to 23-3-65	520·00	Ditto
15.	Shrimati Usha Madan Do	Details are awaited which will be Supplied later on.		Ditto
16.	Shrimati Gita Devi, P. S. Barsal pur	1-10-64 to 14-265-486		Ditto
17.	One Teacher of Primary School Naraingarh	12-64 to 2-64	230·65	Bill prepared but certain objections have been made by the Treasury Officer which are being settled.
18.	Shrimati Sudesh Kumari, Government High School, Nalagarh	3-9-62 to 9-11-62	471·70	Bill pending for want of service book.
19.	Urmal Vaid, Govt, High School, Khizrabad West.	Details are awaited which will be Supplied later on.		Ditto
20.	Sirtaj Kaur, G.G.H.S., Rupar.	5-63 to 6-63	378·00	Bill passed by the Treasury Officer, Rupar and payment is being made.

GOVERNMENT GIRLS SCHOOL TOTOLI TEHSIL AND DISTRICT ROHTAK

*7951. **Chaudhri Ranbir Singh** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state :

(a) whether Government has received any representation from the residents of village Totoli Tehsil and district Rohtak for upgrading the Government Girls Middle School, Totli to a High Standard.

(b) whether he is aware of the fact that the residents of the said village have constructed two rooms for the purpose in the said school building and have collected Rs. 30,000/ and started constructing 11 more rooms for the said purpose ;

(c) the total area of land attached to the said school;

(d) whether it is a fact that there is not a single Girls Highs School within a redius of 10 miles of the said village;

(e) if the replies to parts (a), (b) and (c) above be in the affirmative, whether Government propose to upgrade the school mentioned in part (a) above, if not, the reasons therefore ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes.

(b) One room has been constructed and another three additional rooms are under consideration.

(c) 4 acres.

(d) No. There are five Girls High/Higher Secondary Schools in Rohtak town which is at a distance of six mile from village Totoli.

(e) The matter is under consideration.

UPGRADING OF SCHOOLS IN AREAS OF VILLAGE PANCHAYATS MORKHI BHARTANA AND LUDANA TEHSIL JIND DISTRJCT SANGRUR

*7955. **Chandhri Inder Singh Malik** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state whether it is a fact that on instructions from the Government, the Panchayats of Village Morkhi, Bhartana and Ludana in Tehsil Jind, District Sangrur, have deposited Rs. 8000/- each in the Bank, in the name of Government, for upgrading their Primrary Schools to the Middle Standard, if so, the details of the action so far taken for upgrading the Schools ?

Shri Parbodh Chaddra : The Gram Panchayats of vIllage Bhartana and Ludana are reported to have not deposited any money, The Panchayat of village Morkhi has, however, deposited Rs. 7810/- in Government Treasury. This has been done by the Panchayat after it was enquired of all the Panchayats if any of them were willing to deposit Rs. 7810/- for the upgrading of School of their village. No directive was given to the Panchayats to deposit the money.

The question of upgrading of Schools including the Schools for which contribution has been deposited by the Panchayats is under the consideration of Government.

DELAY IN THE PUBLICATION OF THE REPORT ON THE WORKING OF MUNICIPAL COMMITTEES FOR 1960-61.

*7507. **Shri Babu Dayal Sharma** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state whether the department is aware of the fact that the report on the working of Municipal Committee in the state for the year 1960-61 has been published in 1965; if so, the reasons therefor, the person responsible for this delay and the action, if any, taken against him ;

Shr Parbodh Chandra : *Part* (*i*) The report on the working of Municipal Committees for the year 1960-61 was published in 1964 and not 1965.

Part (*ii*) The delay occurred in the Government Printing Press Responsibility fos the delay is being fixed by the Printing and Stationery Department.

TOWN AREA COMMITTEE FARIDABAD

*7581. **Sardar Kulbir Singh** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state ?

(a) the names of the newly nominated members of the Town Area Committee, Faridabad town, district Gurgaon stating the criteria kept in view for nominating them ;

(b) the steps being taken to have an elected municipality in the said town, the probable time likely to be taken for the completion of the formalities and the approximate date by which elections thereto are likely to be held ;

(c) copies of the representations of the people of Faridabad, regarding the nomination of the members of the said Town area Committee along with the Government's reply thereto be laid on thc Table of the House ?

Shri Prabodh Chandra (a) A statement giving the names of the persons appointed as members of the Notified Area Committee Faridbad Township, is laid on the Table of the House. The criterion kept in view for making these appointments was that persons representing all interests, such as industry, trade, labour, social workers, and general public should be nominated.

(b) The Notified Area Faridabad Township has been replaced by the Municipality Faridabad Township. The Director of Elections(Local Bodies), Punjab, has been asked to conduct elections to the new Municipal Committee expeditiously.

(c) The time and trouble involved in supplying copies of a large number of the representations received by government during an unspecified period regarding nomination of the members of the Notified Area Committee Faridabad Township will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Statement indicating names designations of persons appointed as members of N. A, C. Faridabad Township.

1.	The Deputy Commissioner, Gurgaon.		Ex-officio member(President)
2.	The Senior Medical Officer, Badshaha Khan Hospital, Industrial Township, Faridabad.	..	Ex-officio Member
3.	The Executive Engineer, PWD. Public Health Industrial Township Faridabad.	..	Ditto
4.	The Assistant Settlement Officer, Ministry of Rahabilitation Government of India Industrial Township, Faridabad.	..	Ditto
5.	Shri U. M. Jain General Manager, East India Cotton Manufacturing Co. (Pvt.) Ltd., Industrial Township, Faridabad.	..	Member
6.	Shri Inder Singh Ubherai, Production Manager, Motoren Industries, 15 Industrial Area, Faridabad Township	..	Ditto
7.	Shri Krishan Chawla, Proprietor, K. Krishana and Company, Industrial Area, Industrial Township, Faridabad	..	Ditto
8.	Shri Ladha Ram, Proprietor, Paul Rubber Works, Industrial Area, Industrial Township, Farldabad.	..	Ditto
9.	Shri Dayal Chand Bhutani President, Beopar Mandal, 2C/93, Industrial Township, Faridabad.	..	Ditto
10.	Shri Hans Raj President, Sardha Sabha, Neighbourhood No. 5 Industrial, Township, Faridabad.	..	Ditto
11.	Dr. F. A. Dean, Seva Samiti Hospital, Industrial Township Faridabad.	..	Ditto
12.	Shri Kanwal Nain Gulati, General Secretary, INTUC IC/52, Industrial Township, Faridabad.	..	Ditto
13.	Shri Inder Lal, Headmaster, Mahadev Desai High School and Joint Secretary Nehru College, 5N/5, Industrial Township, Faridabad	..	Ditto
14.	Shri Lachaman Dass 2H B-80, Industrial Townsh, Faridab ad	..	Ditto
15.	Shri Asa Nand Dhingra, 3A/154, Industrial Township, Faridabad..	..	Ditto
16.	Shri Kalyan Singh, Neighbourhood No. 1, Industrial Township Faridabad.	..	Ditto
17.	Shri Madan Lal Bhasin, Bhasin wood works, Industrial Township, Faridabad.	..	Ditto

ALLOPATHIC DISPENSARIES

***6768 Pandit Mohan Lal Datta** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state :—

(a) the total number of Allopathic dispensaries opened by Government in the State—Block—wise during the past 3 years of the IIIrd Five Year Plan in the Plains and the Hilly areas of the state, respectively ;

(b) the total number of such dispensaries proposed to the opened during the year 1965-66 giving the names of the places where there are proposed to be opened ;

(c) the number of dispensaries referred to in part (b) above allocated to the Hilly areas ?

Shri Prabodh Chandra : (a) A statement is laid on the table of the House.

(b) and (c) 4 places are yet to be decided.

The following Allopathic Dispensaries have been opened since 1961-62.

Plains

1. Aliwal, District Gurdaspur.
2. Bhedalpur District Hoshiarpur.
3. Sector 8, Chandigarh.
4. Sector 20, Chandtgarh.
5. New Secretariat Building Chandigarh.

Hilly Areas

6. Kangu District Kangra.
7. Madhopur District Gurdaspur.
8. Rehan District Kangra.

Lahaul and Spiti District

9. Tabo
10. Sagnam
11. Jispa (Now at Gemur)
12. Kibber

SALE OF COUNTRY LIQUOR IN THE STATE

***6884 Pandit Mohan Lal Datta** : will the Minister for Education and Local Government be pleased to state :—

(a) the quantity of country liquor sold in the state during the years 1963 and 1964 respectively ;

(b) the income that accrued to the Government from the sale of liquor in Government licensed shops during the years 1963 and 1964 respectively ;

(c) the cases of illicit distillation detected during each of the years mentioned in part (b) above ;

(d) the steps taken or proposed to be taken to stop illicit distillation ?

Shri Prabodh Chandra : (a, b, c, and d) A statement is laid on the table of the House.

Statement showing the quantity of country liquor sold, income accrued from the sale of liquor at Government licensed shops and the cases of illicit distillation detected during the years 1963 and 1964 and the steps taken to stop illicit distillation.

Year	Country liquor sold.	Revenne accrued	No. of cases of illicit distillation detected
	Proof litres		
(a, b, c) 1963	38,77,529	6,02,19,938	19,089
1964	58,28,155	9,04,70,865	17,573

(d) steps taken :—

(i) The police officers not below the rank of inspectos have been authorised to check the excise Vend premises ;

(ii) The police and the Excise Departments officers conduct joint raids at places where illicit distillation is suspected.

(iii) The sentence for repeated offences has been enhanced.

(iv) The offence of possession of a working still has been declared to be non-bailable.

(v) The import of rectified spirit by the chemical works has been controlled.

(vi) The supply of liquor is being increased to drive away illicit liquor from the market altogethre.

PARTAP SINGH KAIRON STADIUM, RAI DISTRICT ROHTAK

*7953 **Chaudhr Ranbir Singh** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the foundation stone of Partap Singh Kairon Studium, Rai District Rohtak, was laid by the late Prime Minister, Pandit Jawahar Lal Nehru ;

(b) whether it is also a fact that the land for the said stadium was donated by the residents of the said village and funds were collected by the Panchayats for its construction.

(c) whether the said stadium was named after Partap Singh Kairon at the instance of the residents of the said area;

(d) whether the said stadium is situated at a distance of about one mile from village Rasoi, where the former Chief Minister Sardar Partap Singh Kairon, was assassinated ;

(e) whether Government propose to reinstal the Partap Singh Kairon stadium signboard in the memory of the former Chief Minister, which was removed under orders of Government without ascertaining the views of the public; if not, the reasons therefor;

(f) whether the Government propose to instal a statue of the former Chief Minister in his memory in the premises of the said stadium at a suitable place or to permit the public to do so, if not the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes

(b) The land for the said stadium was donated by the adjoining Panchayats of Rai, Badmalik and Badkhalsa. Only Rs. 20,000 was spent on this stadium out of the collections made from Panchayats, where as the rest of the expenditure was incurred by Sports Department.

(c) The said stadium was named after Partap Singh Kairon by the Governing Body of Kamla Nehru Panchayat Shiksha Kendra, Rai, with the approval of Government.

(d) The distance between village Rasoi and the said stadium is about a mile.

(e) The matter is under the consideration of Government.

(f) No such proposal is under consideration.

CONSOLIDATION OF VILLAGE HATHWALA, TEHSIL JIND DISTRICT SANGRUR

*7954. **Chaudhri Inder Singh Malik** : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the consolidation of village Hathwala, tehsil Jind, district Sangrur was revoked at the stage of valuation in 1960 by the Government, if so, a copy of the orders passed in this connection be laid on the Table of the House;

(b) the year in which the said orders were implemented, if they were not implemented, the reasons therefor;

(c) whether any complaint of any right holders regarding the implementation of the said orders is pending in the office of the Director of Consolidation, Punjab, if so, the action proposed to be taken thereon;

(c) whether the new valuation of the village Land has been done, if not, the reasons therefor?

Sardar Harinder Singh Major : (a) (i) Yes.

(ii) Copics of the orders are laid on the table of the House.

(b) 1961 and 1962.

(c) (i) Yes.

(ii) The comments of the Settlement Officer/Consolidasion of Holdings, Sangrur were called for which are awaited.

(d) (i) No.

(ii) The new valuation was not done as the majority of the right-holders were satisfied with the old valuation and this fact was further ascertained by the Settlement Officer/Consolidation of Holdings, Sangrur at the time of confirmation of the scheme.

Office of the Settlement Officer, Consolidation of Holdings, Sangrur.

No. 230 Dated 1st September, 1960

Order-

In compliance with the order contained in Memo No. 2224-DII-60/4081 30th June. 1960 from the Deputy Secretary to Government, Punjab Consolidation Department, Chandigarh to the Director. Consolidation of Holdings, Punjab, Jullundur conveyed to this office,—vide Director, C/H, Pb.'s endst. No. LAPI/PS/-1228, dated 11th July, 1960, the draft scheme of village Hathwala, tehsil Jind, hereby revoked under section 36 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act from the valuation stage.

Sd/- , . .,
Settlement Officer, C/H
Sangrur.

No. PB-3184. Dated 1st Sepetmber, 1960

COYIES to ;—

1. Director, Consolidation of Holdiugs, Punjab. Jullundur with reference to his endorsement No. GAPI/PS-1228, dated 11th July, 1960 for information,

2- Consolidation Officer, Lehragaga in continuation of this office endorsement No. PB/2606, dated 18th July, 1960 for information and neeessary action. The C/H work should be started afresh, keeping in view the resolution No. 396, dated 17th October, 1958 passed by the rightholders, in case, the valuation is found correct on checking up and the rightholders do not object to it, it will be retained, as it is.

Sd/- , . .,
Settlement Officer, C/H
Sangrur.

COPY of memo No. 2244-DII-60/4081, dated 30th June, 1960 from Deputy Secretary to Government, Punjab, Consolidation Department Chandigarh to the Director, Consolidation of Holdingss, Punjab Jullundur City.

Subject : Complaint about the irregularities in consolidation work of Village Hathwala, tehsil Jind, district Sangrur.

Referenee your endorsement No. GAPI/AS-228, dated the 8th March, 1960.

2. In order to set right the irregularities pointed out by the Settlement Officer, Consolidation of Holdings, Sangrur, you are authorised to allow him to revoke the scheme under section 36 of the Consolidation of Holdings, Act.

EVACUEE LAND IN KAITHAL AND NARWANA TEHSILS

***7372 Shrimati Om Prabha Jain** : Will the minister of Revenue be pleased to state :—

The area of evacuee land, allotted and unallotted, separately lying in Kaithal and Narwana tehsils, village-wise?

Sardar Harinder Singh Major : The time and Labour involved in the collection of the information will not be commensurate with the possible benefit to be obtained.

UNALLOTTED MUSLIM EVACUEE LAND IN CERTAIN VILLAGES OF TEHSIL SIRSA, DISTRICT HISSAR

***7905 Shri Kesra Ram** : Will the Minister for Revenue be pleased to state the Area of Muslim evacuee land lying still unallotted in the following villages of tehsil Sirsa, district Hissar at present :—

1 Ahmadpur Dariwala.
2. Ganga.
3. Sadiwala.
4. Abub Shahar.
5. Bujwali.
6. Modi.
7. Lambi.

Sardar Harinder Singh Major : The unallotted evacuee area in these villages is as under :—

		K	M
1.	Ahmadpur Dariwala.	58	5
2.	Ganga.	=	=
3.	Sadiwala.	282	12
4.	Abub Shahar.	456	19
5.	Bujwali.	29	7
6.	Modi.	3	9
7.	Lambi.	5	18

WATER LOGGED AREA

*6879. **Comrade Makhan Singh Tarsikka** : will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state :—

(a) The waterlogged area of land, district-wise, at present;

(b) Districtwise area of land referred to in part (a) above which has been totally affected by thur;

(c) The details of the special steps, if any, taken by the Government to remove waterlogging from the State and the expenditure incurred thereon, districtwise?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) to (c)

A statement is laid on the Table of the House.

Statement.

(a) District-wise figures of waterlogged area in the state are not maintained in the Irrigation Branch. However, areas in canal tract where the water table is with in 5 feet of ground based on October, 1963 observations are as under :—

Name of the Tract	Area in acres
(i) U. B. D. C.	2,12,582
(ii) Bist Doab.	55,296
(iii) Ferozepur Circle.	2,38,388
(iv) Sirhand Canal Circle.	4,11,648
(v) Patiala I. B. Circle	3,01,056
(vi) 1st Bhakra Main Line Circle.	1,81,862
(vii) 2nd Bhakra Main Line Circle.	2,458
(viii) W. J. C. West Circle.	3,98,131
(ix) W. J. C. East Circle.	5,19,783
(x) Grey Canal Tract.	3,72,327
Total	26,93,531 acres

(b) Districtwise figures about the area affected by thur are not maintained by the Irrigation Branch. However, canal tract-wise figures are as under :—

Name of the circle	Thur area in acres
(i) W. J. C. East circle.	1,00,525
(ii) W. J. C. West circle.	43,825
(iii) 1st B. M. L. circle.	27,160
(iv) 2nd B M. L. circle.	5,429
(v) Sirhind Canal circle.	36,103
(vi) Ferozepore canal circle.	1,42,929
(vii) U. B. D. C.	1,15,988
(viii) Patiala I. B. circle.	24,624
(ix) Nangal circle.	6,656
Total	5,03,278 acres

(c) Remedial antiwater-logging measures are :—

(i) Constructing flood protection embankments along rivers to prevent spilling.

(ii) Adequate Drainage System;

(iii) Lining of irrigation channels.

(iv) Installing of shallow antiwater-logging tubewells;

(v) Construction of seepage drains with pumping schemes where necessary.

(iv) Deep discharge tubewells;

(vii) Under ground drains etc. etc.

Flood protection embankments and adequate drainage are pre-requisite to any other antiwaterlogging measures. Different treatments have to be given to different areas according to the conditions prevalent at site by adopting the above mentioned measures individually or collectively in different combinations.

Figures of districtwise expenditure are not maintained. However, the expenditure incurred during the 2nd and 3rd Five year Plans for Flood Control and Drainage and Antiwaterlogging Schemes upto December, 1964 is about Rs 28.00 crores.

REPRESENTATION AGAINST THE DIRECTOR LAND RECLAMATION AND IRRIGATION AND POWER RESEARCH INSTITUTE AMRITSAR

*6880. **Comrade Makhan Singh Tarsikka:** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to State:—

(a) whether the Chief Minister, the Home Minister, the Minister-in-charge and the Chief Secretary received any complaints containing allegations of misappropriation of Government funds corruption etc. against the Director, Land Reclamation and Irrigation and Power Research Institute, Amritsar from the officials of the said Department during the last six months, if so, a copy each of the representations be laid on the Table of the House;

(b) the details of the action, if any taken on the complaints?

Chaudhri Rizaq Ram: (a) Some complaints have been received from Shri Daya Shankar, who was a clerk in the Irrigation and Power Research Institute, Punjab. A copy of one of the complaints is laid on the Table of the House. In other complaints he has simply repeated the allegations mentioned in the said complaint.

(b) The complaints have been enquired into and have been found baseless.

No. 518-19/DSK/L. R./Contd. Dated 17th November, 1964

From

Shri S. S. Grewal, I. A. S.,
Secretary to Government, Punjab,
Irrigation and Power Departments,

To

Shri J. S. Sidhu, P. S. E. I.,
Chief Engineer (Drainge),
Irrigation Works, Punjab.

Subject; No Demand/Clearance Certificate in respect of Shri H. L. Uppal, Director, Land Reclamation, Irrigation and Power Research Institute, Punjab, Amritsar.

Reference Secretary No. 6552-IEII-64/11403, dated 7th August, 1964,

The points stated below are brought to your considaration and early action:—

Extension for Five years and Thickly relationship with former Chief Ministers S. Partap Singh Kairon

Tha extension was granted by the Former Chief Minister S. Partap Singh Kairon on the entire basis of Reclamation of 5 Acres of land owned by S. Jaswant Singh the brother of the said Chief Minister at Amritsar in 1958. (See Food production Series No. 4 Publication of Land Reclamation, Irrigation and Power Researeh Institute Amritsar.)

a. It must be asceratained under what authority this land had been Particularly selected for the reclamation purpose when there were so many other of the worst type.
b. The cost of expenditure involved in reclamming should be known.
c. How much the owner of the land had returned the amount to the Government against this expenditure after reclamining the land.
d. The T. A. Bills of the Subordinates and officer, who frequently visited the site and to inspect the site may be verified to know the extent of interest of Shri Uppal in this matter.
c. Government material and machinery used can also be attempted to know from the S. D. O's of the Land Reclamation, Irrigation and Power Research Institute Amritsar.
f. Drainge Circles allotted to Uppal by the former Chief Minister S. Partap Singh Kairon at places where they wanted to construct there own properties and other works near by contracts of works of these schemes profusely allotted to Kairon family member of group thus establishing a big league of corruption.

2. **Undue Placement of Orders for Supply.**

1 Order of supply of angle irons and M. S. Bars worth.

Rs 50 lacs was placed with the Firm M/s Amin Chand, Piara Lal Jullundur on the entire settlement of providing his son Shri Om Parkash Uppal who has returned from England with empty knowledge of education on a salary of Rs 350 per month. He remained in service for two years earning an increment of Rs 100 per annum. As soon as the contract was over and no hope for further orders of the same material, the firm discotinued the services of his son.

ii. Governmet Car was used by his son named Shri Om Parkash Uppal who was employed in the above firm, on every holidays. The Government Car No. 6769 PNA lifted him from above firm Jullundur to Amritsar and Next Day Amritsar to Jullundur. Special Tour was made by Uppal for this purpose.

iii. Fourth Class Establishment were habitual to go to his residence and worked day and night. S.D.O. Chattar Singh has deputed his work charge establishment at the disposal of his domestic work.

ARGUMENTS

i. Under the Administration and discipline of the Government, no Government employee is allowed to take the under benefits of his position at the cost of the Government,

ii. Why he placed orders particularly this firm when there are so many others who would offer better qualities and cheaper rates and also give concession to the Government.

iii. It can be said without hesitation that behind this bargain if even it may be good or bad for the Government, to get his son employed.

3. **Personal Benefit to the Relatives.**

a. An Elder son named Sat Paul Uppal has been running Precision Instrument Company, in Islamabad, at Amritsar for the last eight years for which a special concession for supply of empty wooden boxes for packing of material so manufactured from the office that are being received from the firm on placing of orders to the various firms for office use. As a rule such wooden empty boxes must be stored in the office for use in the office for Government purposes. These have been supplied to the above company free of cost and placed the orders to supply the scientific. Apparatus to the Land Reclamation, Irrigation and power Research Institute, Punjab, Amritsar with the help of some R. O's and A. R. O's the personal influence of his father being a Director, Land Reclamation, Irrigation and Power Research Institute, Amritsar. Probably office carpenters, who usually deputed for packing purposes of this firm.

b. For an other Mechanical and Technical help to this firm for its development Shri Dina Nath a Forman of this Directorate has been purposely appointed who's own progress for the Government, in the office is absolutely nil. His T. A. Bill may please be verified in the object to know if he had over gone outside for the Government purpose or the firm own under who's order of S.D.O's concerned.

c. There is one photographer named Shri Satya Nand who has closest relation who's provision had through out been made in the estimates of works on higher scale simply to give him the maximum financial benefits. Moreover, his head quarter has been fixed at Malakpur (Pathankot) and often called at (Head quarter Amritsar) for at least 10 days thrice a month with a view of give him benefit of T. A. and D-A. to its maximum.

d. What necessity is usually felt to call him off and on at the head quarters when another photographer Shri Om Parkash has been employed at Amritsar.

Public Works and Welfare Minister]

e. It has also been seen that much efforts have been done by the Director, to confirm Shri Satya Nand in the higher grade for which the finance department was approaehed several times. This shows a great favourtism.

f. There is another close relative named Shri Ashwani Kumar working as a silt analysist at Hoshiarpur who's academic qualifications is entirely nill and for the level of silt analysist. He has recently been made regular from the work charged. His services may be verified and his education may also be examined whether he suits high grade i. e. 90-5-140/8-200.

g. There is another relative named Shri Subhash Chander working at Madhopur headworks as a silt analysist having no progress and enjoying at the cost of the position of the relative.

4. **Miscellaneous abuse of Powers.**

a. There is one firm called M/s Faqir Chand Sharma Electric Company Hall Bazar, Amritsar, who having served with free goods of Electric at the newly constructed bunglow of Director Uppal at Chandigarh received an order of supply of Electrict goods for fitting in the newly constructed Building in the premises of the Irrigation and Power Research Institute, Amritsar. Worth Rs 4,50,000 the payment has been made to the firm though according to the rules and regulations, such heavy order should not be placed to the single company. This is evident that the firm has given free installation and wiring to his bunglow at Chandigarh.

b. The same case is one of the Contractor Shri Achar Singh and six more labourers are also with him who are employed in the institute, who has also done free service at the same Bunglow and in return to that he was given sufficient construction work at the headquarters worth Rs. 1,00,000.

5. **Feve Storeyed Building and other Buildings in the Permises of D. I. P. R. Amritsar without Anticipation sanction of the Budget.**

Most of the construction work of buildings is being carried out without the sanction of proper funds for the purpose and the expenditure is adjusted against sanctioned schemes where no actual work is originally carried out against the sanctioned schemes,

———

6. **Sutlej Canalization Scheme from Rupar to Harike Head works**

This Scheme costs 1.79 crores of rupeee. As a rule any scheme requires recommendation from T.C. before its execution. But on this scheme lot of work has been carried out at sit for costing Rs. 1.0 crores inspite of fact that the scheme has not yet been recommended by the T. C. The Anticipation sanction for the execution of scheme was obtained by Uppal at personal level through Shri Kairon who had always been kind to him in order to have benefit for his family. Its execution was started during *Chinese Aggression* and when Emergency was declared, Shri Satinder Singh Executive Engineer, was the incharge of this scheme. In view of grave situation and Emergency days due to Chinese Aggression it was decided by the State Government to execute only those schemes which have deep military concern and stop all other schemes to save the money for Defence purposes. Consequently a Circular was issued by Dr. Uppal to all officers of the Directorate for their suggestion in this respect. Most of the officers had their opinion to stop this scheme but fearing from Shri Kairon and Dr. Uppal no officer came forward except Shri Satinder Singh Executive Engineer. Being a young blood and true well wishers of the Country Boldly pointed out that this scheme is not sound. He, after thorough inspection of site and in view of critical position of the country during the days of Emergency appealed Dr. Uppal to close this scheme so that the amount which was to be spent on this scheme could be utilised towards Defence purposes. He was justified to point out in closing the scheme because it was not technically some and

could not serve the purpose of Defence in any way. It was a big amount to cope with the demands of National Defence. As a matter of fact this patriotism minded gentleman should have been rewarded for his valuable suggestion but on the other hand he was raprimanded. His voice was crushed and on this very reason he was got transferred to Gurdaspur in the same month. This is what he got for his love towards his country. How it is justified that when a person speaks in the interest of country especially during the days of Emergency his suggestion is pushed aside and to supress his voice he is being transferred. This scheme was put up in 41st meeting of T. C. where a number of objections were raised by Shri G. S. Sidhu, C. E., Irrigation Works, Punjab. Sardar Jatindar Singh, C. E., Hydel, Mr. Wahi and other Members of the T. C. The Chairman Mr. Fletcher went up to this extent that the schemes are being got approved (Shri Kairon) through back doors and even work is carried out at site and then put up to T.C. for recommendations. The scheme has not yet been recommended by the T. C. due to the facts that it is not technically sound. The work on the scheme has so haphazardly been carried out that most of the bunds were washed away by the floods of 1964, and the land documents are all wrong as the Secretary, Irrigation and Power Department has not accorded a approval for the Notification and Declaration issued so far for the possession of land required for the Bunds. To overcome the irregularities, efforts are being made by Uppal to get the scheme approved through Union Irrigation and Power Minister Dr. K. L. Rao who too is being kept in Dark. I may point out that the views of Satindar Singh, Executive Engineer must be obtained in detail before the scheme is considered for approval. An enquiry be set up in orders to know that how much heavy expenditure was booked when the scheme was not technically sound and was not recommended by the T. C. Dr. Uppal who has committed so many irregularities may also be taken to task and the amount spent lavishly be recovered from the Defaulter. There are duplicate estimates on the same site amount to Rs. 8 lacs for Kaimewala and 6 lacs and for Bhgela to estimates framed for one site for Rs. 14,00,000/-. The construction of Bund at Kaim-wala and Bhgela where actually no work has been done the previous one has already been washed away. It is nothing but nearly wastage of National Money. needs special enquiry at site.

7. **Cheating with Government and Chief Engineers of Punjab.**

It is the general practice of D.I.P.R. to frame the scheme at low cost which are not technically so sound as these should have been. Though these schemes had objection by the other Technical members of the S.F. Control Board and T.C. yet these were got approved through the influence of the former Chief Minister. (S. Partap Singh Kairon). It is reliably learnt that during discussion on schemes of Dr. Uppal other resound engineers like Shri S. N. Kapur, Shri C. L. Handa, Shri K.L. Bhatia, Shri Jatinder Singh and Shri G.S. Sidhu have been challenging to Uppal in technically draw back of the schemes but to no effect. On the other hand these Engineers were insulted by the Chief Minister Shri Kairon in one way or the other. This fact can be well ascertained from these people even now.

The schemes which were specially prepared at low costs, just to be in the good books of (Kairon), and to let down the other Chief Engineer but were got revised later in order to complete the schemes though still not sound technically. In these cases the revised cost has been gone up twice, thrice and even four times then the original cost in some cases. To support this fact the following schemes may be referred.

1. Scheme for the Protection of village Burewal and Sujokalia on River Beas had gone about 6 times higher than the original cost.

2. Protection works at Kaimewala had borne thrice the expenses that the original cost of the scheme. In this case there is duplicacy of estimates even.

3. Scheme of Nasrala Choe too has raised the expense quite higher than the original cost.

4. The Scheme of Patiala Ki Rao and Janta Devi Ki Rao has raised its revised cost twice than the original cost. The scheme was not recommended by the Technical Committee, State Flood Control Board and was got pushed through back.

5. The revised cost of Patiala Ki Rao near Chandigarh is more than double the cost for which it was recommended by T.C.

[Public Works and Welfare Minister]

In the end it is requested that all the allegations levied should be formed correct whereas one or two or sufficient to satisfy the Government. It is once again requested to carry out the Enquiry at an early date.

Thanking you.

Yours faithfully,

Sd- . . .,

(Daya Shanker Kanwal)

Land Reclamation Sub-Division,
Land Reclamation, Irrigation & Power Research, Institute, Punjab,
Amritsar.

No. 520—24—DSK/LR/Confd, Dated 14th November, 1964.

C. C.

1. Shri Gulzari Lal Nanda,
   Union Home Minister, New Delhi.
2. Shri K. L. Rao,
   Union Irrigation and Power Minister, New Delhi.
3. Shri Ram Kishan,
   Chief Minister, Punjab, Chandigarh.
4. Chief Secretary to Government, Punjab, Chandigarh.
5. Secretary to Government, Punjab, Anti-Corruption Department. Chandigarh.

KAITHAL-KHANAURI DRAIN

*7369. **Shrimati Om Prabha Jain** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total length of the Kaithal-Khanauri Drain and its estimated cost;

(b) the total mileage which has been dug till 31st January, 1965;

(c) the time by which the entire drain is expected to be completed?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Length—33 miles.

Cost—About Rs. 40 lacs.

(b) Pilot section in a length of about 25 miles.

(c) Pilot section is expected to be completed by monsoon of 1965.

REMOVAL OF FLOOD WATER IN KAITHAL TEHSIL

*7370 **Shrimati Om Prabha Jain** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether the area of land along the Sirsa Branch in Kaithal Tehsil was flooded in the rainy season during the years 1962 and 1964;

(b) whether there is any scheme under consideration of the Government to drain out the flood water and remove seepage of the said area by any method, i. e., surface tubewells and drains, if so, details thereof and the time by which it is likely to be taken up and completed?

Chaudhri Rizaq Ram (a) Yes.

(b) Amin and Pundri Drains on either side of Sirsa Branch are proposed to be constructed. There is no proposal to instal shallow tube-wells. The execution of the drains will be taken up as soon as the funds for the same become available.

CASES OF THE EMPLOYERS OF THE IRRIGATION DEPARTMENT PENDING CONFIRMATION.

*7504. **Sardar Kulbir Singh** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the number of cases of employees of the Irrigation Department, section-wise, pending confirmation since 1960 or earlier;

(b) the steps, if any, proposed to be taken to deal with the said cases?

Chaudhri Rizaq Ram (a)

1.	Class	I	15
2.	Class	II	Nil.
3.	Class	III	588
4.	Class	IV	126
		Total	729 (in all)

(b) Action would be taken to finalise these cases expeditiously.

TALU MINOR IN HISSAR DIVISION

*7515. **Chaudhri Tek Ram** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether there is any minor named Talu under the jurisdiction of the Hissar Division; if so, whether Government had under its consideration any proposal to re-model the minor with its sub-minors;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the estimated expenditure on the remodelling of the said Minor and its sub-Minors;

[Chaudhri Tek Ram]

(c) whether Government received any complaint regarding embazzlement during the said re-modelling; if so, the name of the officer who conducted the enquiry, if any, into the complaint and the details of his findings?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes.

(b) The detailed estimate is under preparation. The estimated cost of earth work comes to Rs. 34,999.00.

(c) Yes. Shri G. P. Dewan, Superintending Engineer, Western Jumna Canal (West) Circle got the measurements of earth work checked by Sarvshri G. R. Maini, B. L. Sharma, Executive Engineers.

The check measurement revealed some excess payment made. Action to recover the amount and to punish the persons responsible is being taken.

EXTENDING MEANS OF IRRIGATION IN A CERTAIN AREAS OF TEHSIL NAKODAR DISTRICT JULLUNDUR.

*7698. **Sardar Dalip Singh:** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether there are any schemes under the consideration of the Government for extending the means of Irrigation, for increase in Agricultural Production, in the Bet and Dotha areas of Lohian, tehsil Nakodar, district Jullundur, if so, the details thereof?

Chaudhri Rizaq Ram: No.

CONSTRUCTION OF A BRIDGE ON BAHADURPUR SINK DRAIN IN DISTRICT KARNAL

*7956 **Chaudhri Inder Singh Malik :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether Government have received any representation from the residents of village Sink, district Karnal, regarding the construction of a bridge on Bahadurpur Sink Drain, if so, the time within which it is likely to be constructed?

Chaudhri Rizaq Ram: Yes.

Construction will, however, be undertaken on the availability of funds and the site for the bridge has been selected by the Deputy Commissioner concerned.

TAKING OVER OF ELECTRIC LINE RUNNING ALONG WITH THE GREAT RAJASTHAN CANAL AND SIRHIND FEEDER FROM THE IRRIGATION DEPARTMENT

*7574. **Sardar Jagjit Singh Gogoani :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state:—

(a) whether the Punjab State Electricity Board is willing to take over from the Irrigation Department the 11,000 K. w. electric line running along the great Rajasthan Canal and Sirhind Feeder right from the Harike Headworks upto Faridkot alongwith the sub-stations attached to it which are no longer required by that Department;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the time by which the take over is expected to be completed to make the line available for use by the consumers; if in the negative, the reasons therefor?

Chaudhri Rizaq Ram (a) Yes.

(b) After June, 1965 upto which the line is required for Irrigation Works.

PRIORITY FOR ENERGISING TUBEWELLS IN BET AND BARANI AREAS

*7702. **Sardar Dalip Singh** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether any priority is given in the matter of energising tubewells in the Bet and Barani Areas of the State over other areas with a view to increase agricultural production?

Chaudhri Rizak Ram After meeting the earlier commitment, first priority will be given to areas not commanded by canals.

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN SANGRUR DISTRICT

*7883. **Sardar Ranjit Singh** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the revised Project Estimate for Electrification of Ahmedgarh and 48 villages around Ahmedgarh in Tubewell Zones A and G, in Sangrur District, was sanctioned in January, 1962;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the total number of villages so far electrified under the said Project;

(c) the names of villages likely to be electrified during the year 1965-66 and the time by which all the villages included in the said Project are proposed to be electrified?

Chaudhri Rizaq Ram (a) Yes,

(b) 12

(c) Programme for electrification of fresh villages has not been finalised. It is, therefore not possible to indicate the names of the villages likely to be electrified during 1965-66 nor it is possible to indicate the time by which all the villages included in the Project will be electrified.

ELECTRIFICATION OF HOUSES AND ENERGIZING OF TUBEWELLS IN MAHAL KALAN BLOCK

*7884. **Sardar Ranjit Singh** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether it is a fact that no village or tubewell has so far been electrified/energized in the Mahal Kalan Block in tehsil Barnala, district Sangrur.

[Sardar Ranjit Singh]

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether any villages/tubewells in the said block are proposed to be electrified/energised; if so, when and the time by which the project estimate for the purpose is likely to be prepared and finally sanctioned?

Chaudhri Rizaq Ram (a) Yes.

(b) Yes, village Sangerha, Wazid Kalan, Sekhan and villages *enroute* towards North of Barnala during the year 1965-66, subject to the availability of funds. The subsidiary Project Estimate already stands sanctioned.

CALL ATTENTION NOTICE (No. 17)

Shri Om Parkash Agnihotri : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the Sweepers Union, Phagwara, which presented their demands to the Municipal Committee, Phagwara regarding increase in the pay of the Municipal employees to Rs. 97.50P., maternity leave and for supplying Jharhoo and Tokri etc. and a copy thereof was sent to the Conciliation Officer, Jullundur. Thereafter, a telegram was also sent to him on 10th March, 1965 at Jullundur. Since he did not take any action in time, Shri Sagli Ram, President, Sweepers Union, had to resort to hunger strike on 14th March, 1965 as a result thereof. This matter may be discussed.

श्री अध्यक्ष : यह काल अटैंशन मोशन (No. 17) मैंनें इस लिए ऐडमिट की है कि गवर्नमैंट ने अपने इम्पलाईज की तनखाहें तो 97½ रुपए कर दी है, मगर म्यूनिस्पैलिटी ने नहीं की । Government may like to clarify the whole position in this respect. (I have admitted call attention Motion (No. 17) because whereas the Government has increased the pay of its Sweepers Employees to Rs. 97.50, this Municipality has not done so. The Government may like to clarify the whole position to this respect.)

Walk-out

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਅਸੀਂ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਦ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਮਗਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ..

Mr. Speaker : Order please.

चौधरी देवी लाल : यह मामला बहुत अहम है; इस लिहाज़ से कि जो मैम्बर इस हाऊस के हैं, उनको इजाज़त न हो और स्मगलर को पैरोल पर छोड़ दिया जाए और वह इलैक्शन लड़ के वापस चला जाए ।

श्री अध्यक्ष : जब दो दिन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बहस रही उस वक्त यह प्वाईंट ला सकते थे.... (These points could be raised during the discussion on the General Administration which continued for two days).

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहब, इससे ज्यादा और क्या इनजस्टिस हो सकती है कि एक लैजिस्लेटर को तो रिहा न किया जाए और उसके मुकाबले एक स्मगलर को रिहा कर दिया जाए ?

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛਡਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ......

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ । ਇਸ ਗੌਮਿੰਟ ਨੇ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਕ ਹਾਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਡਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, (ਘੰਟੀ) ਇਕ ਇਤਨਾ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ । (*At this stage all the members from Communist groups stood up and staged a walkout*)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ । ਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Please take your seat.

DEMANDS FOR GRANTS—31. AGRICULTURE

Minister for Revenue (Sardar Harinder Singh Major) : Sir, I beg to move—

> That a sum not exceeding Rs. 6,07,79,210 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 31—Agriculture.

Sir, I also beg to move—

> That a sum not exceeding Rs. 1,13,41,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head 95—Capital Outlay on Schemes of Agriculture Improvement and Research.

Mr. Speaker : Motions moved—

That a sum not exceeding Rs. 6,07,79,210 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 31—Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 1,13,41,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head 95—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

All the cut motions given notice of will be deemed to have been read and moved :

(Demand No. 19)

1. Comrade Shamsher Singh Josh :

That the demand be reduced by Rs. 100-.

2. Shri Rup Singh Phul :

That the demand be reduced by Re. 1-.

3. Chaudhri Dal Singh :

That the demand be reduced by Re. 1/-.

4. Sardar Hari Singh:

That the demand be reduced by Re. 1/-.

5. Sardar Ranjit Singh :

That the demand be reduced by Rs. 100/-.

6. Shri Surinder Nath Gautam :

That the demand be reduced by Re. 1/-.

7. Chaudhri Darshan Singh :

That the demand be reduced by Rs. 101-.

Mr. Speaker : Sardar Gian Singh Rarewala.

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला (सिरहंद) : जनाब, स्पीकर साहब, हाउस के सामने ऐग्रीकल्चर की मद पेश हुई है । इसके सिलसिले में मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं । यह बात मुसल्लमा है कि जो खुराक की पोज़ीशन है वह सारे ही सूबे की तशवीशनाक है और पंजाब जो कि ग्रेनरी आफ इंडिया समझा जाता था, पिछले दिनों इसमें भी खुराक में कमी वाक़िया हुई है । अगर रिपोर्ट का मुतालया किया जाए तो पता चलेगा कि हमारा टारगेट तो था 69 लाख टन का मगर 1961 से 1964 तक पैदावार सिर्फ 57 लाख टन हुई है । और जो पहले हम पैदा करते थे वह 62 लाख टन के लगभग होती थी । यानी जो हम पैदा करते थे उसमें भी कमी हो गई बढ़ना तो क्या था । इस लिए जो वजूहात हैं इस कमी के उन पर गौर करना है । आज कल जो पोज़ीशन हमारे पंजाब की है वह स्टैगनेंट पोज़ीशन है——

श्री अध्यक्ष: हर मैम्बर को 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा ।

(No member will get more than fifteen minutes.)

Minister for Home and Development : I hope, Sir, I would be given one hour to reply to the debate.

Mr. Speaker : The restriction of time imposed by me does not apply to the Ministers.

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला : बहुत अच्छा जी, मैं टाइम के अन्दर ही खत्म करने की कोशिश करूंगा हालांकि यह मज़मून बहुत वसीह है और 20 मिनट में इस पर कुछ कहना नामुमकिन बात है ।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम इस वक्त स्टेगनेशन की स्टेज पर पहुंचे हुए हैं । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जो इजनास की कीमतें हैं, वह चूंकि रिम्यूनरेटिव मुकर्रर नहीं होती इस लिए लोगों का रजूह कैश क्राप्स की तरफ ज्यादा हो गया है । जो लिट्रेचर हमें सप्लाई किया गया है उससे मालूम होता है कि जो जमीन इजनास पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती थी उसको शूगर केन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है ।

मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को इस की तरफ तवज्जो देनी होगी कि मुल्क को फीड करने के लिए गल्ला पैदा करना है । वह कहां से आएगा ? जमीन से ही पैदा होगा । अगर दूसरी इजनास की पैदावार ज्यादा शुरू कर दी तो हम गल्ले की पैदावार पूरी नहीं कर सकेंगे, यह वन आफ दी फैक्टर्ज है । यहां पंजाब के अंदर दिन बदिन जमीन सेम की नजर होती जा रही है और जो काबले काशत जमीन है वह कम होती जा रही है । सेम के ऊपर काबू पाने के लिए प्लैन्ज़ बनाने की जरूरत है लेकिन अभी तक हम सेम पर काबू नहीं पा सके जिस की वजह से लाखों एकड़ जमीन इजनास पैदा करने के नाकाबिल होती जा रही है । मैं ने इसी सैशन में एक सवाल पूछा था और उस का मुझे जवाब भी दिया गया था कि इतने इनसैंटिव्ज प्रोवाईड किए गए हैं जो किसानों को 1965-66 में दिए जाएंगे । ठीक है कुछ न कुछ तवज्जो इधर हुई है । लेकिन महज यह इनसैंनटिव्ज देना ही काफी नहीं है, सब से ज्यादा जरूरत ऐक्सीक्यूशन की है और इम्पलीमैंटेशन की है । यह न हो कि यह वादे, वादे ही रह जाएं जैसा कि पहले होता रहा है । हम प्राइसिज का इनसैंटिव देने की कोशिश कर रहे थे और उस के लिए उज्जल सिंह कमेटी बनी थी । लुध्याने के एक सरदार साहिब ने फरमाया था कि उन की रिपोर्ट मौसूल हो गई है लेकिन स्पीकर साहिब, हमें पता नहीं कि क्या रिपोर्ट हुई है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इजनास के जो रेटस इस वक्त मुकर्रर हुए हैं वह कतई तौर पर इनसैंटिव प्रोवाईड नहीं करते । इस मसले को गौर से देखना होगा कि क्या जमीदार की कास्ट प्राईस है, कितना उसका खर्चा आता है । जमीदारों का जो वक्त लगता है, सारा खानदान खेतों में काम करता है वह

[सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला]

कास्ट निकालने के वक्त काऊंट नहीं किया जाता । बहुत सी बातें हैं जिन को काऊंट नहीं किया जाता । मैं सच कहता हूं कि उन को स्कवेयर मील भी नहीं मिलते । वह पेट पर पत्थर बांध कर काम करते हैं । उन को किसी शुमार में किया ही नहीं जाता । अगर इन सब हालात को मद्देनजर रखते हुए उज्जल सिंह कमेटी ने रिपोर्ट की है तो उस को जल्दी से जल्दी पब्लिश कर देना चाहिए ताकि लोग उस से फायदा उठा सकें । जो मौजूदा प्राईसिज मुकर्रर की हुई हैं खास कर गेहूं की और चावल की उन को ज़रूर ज़यादा करना चाहिए । जहां तक ज्यादा पैदावार बढ़ाने का ताल्लुक है उस के बारे में मेरा कन्कर्मड व्यू है कि जब तक हम मैकेनाइज़ेशन को ऐडाप्ट नहीं करेंगे हम पर एकड़ यील्ड ज्यादा नहीं कर सकेंगे । इस की तरफ क्या स्टैप्स हैं जो लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से । मैं अर्ज करूंगा कि जिन्हों ने शौक से टरैक्टर कल्टीवेशन शुरू की थी वह मायूस हो रहे हैं । उन के ट्रैक्टर्ज़ की सर्विस का और रिपेयर का कोई इन्तज़ाम नहीं और उन्हें कोई इमदाद नहीं मिल रही । मैकेनाईज़ेशन को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि जगह बजगह ट्रैक्टर सर्विस सैंटर्ज कायम किए जाएं जहां न सिर्फ उन की सर्विस का ही इन्तज़ाम हो बल्कि ट्रैक्टर्ज किराए पर भी दिए जाने का इन्तज़ाम होना चाहिए ताकि खेती बाड़ी का काम मशीनों से हो । मैं ज़ाती तजरुबे की बिना पर कहता हूं कि ट्रैक्टर्ज़ पर काम करना इस वक्त निहायत मुश्किल हो रहा है, देहली के सिवाए हम को स्पेयर पार्टस नहीं मिल सकते बल्कि देहली वाले भी कह देते हैं कि बम्बई से मंगवा कर देंगे । इस लिए ट्रैकटर सैंटर्ज कायम करने की बहुत जरूरत है ताकि वहां सर्विस और रीपेयर हो सके और ट्रैक्टर्ज़ किराए पर मिल सकें । इस के इलावा जहां ज़यादा पैदावार करने का सवाल है उस के साथ वाबस्त सवाल है कि मार्किटिंग का क्या इन्तज़ाम हो रहा है । हमारे इस हाउस ने एक कमेटी बनाई हुई है जो कि मार्किटिंग के सवाल पर गौर कर रही है और देख भाल कर रही है । मैं भी उस का मैंम्बर हूं । मुझे देख कर हैरानी हुई है कि अभी तक हमारी मार्किट्स की वही हालत है जो 20 साल पहले थी, कोई तरक्की के आसार नजर नहीं आते । ठीक है जमींदार ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा करें लेकिन इस के साथ मार्किटस का सवाल उस से भी ज्यादा अहम है । इस वक्त 25%/30% नुकसान ज़मीदारों का मार्किट्स की वजह से हो रहा है । अमृतसर की मण्डी मण्डी कहलाने की मुसतहिक नहीं है । पटियाला में 10 साल हुए प्लाट नीलाम हुए थे लेकिन अभी तक एक भी पत्थर नहीं रखा । मुझ को वह दिन याद है जब भाखड़ा डैम बन रहा था तो खत पर खत आते थे कि इस से बहुत ज्यादा गल्ला पैदा होगी उस के लिए मण्डियों का इन्तजाम होना चाहिए। मुझे स्पीकर साहिब, खन्ने की मन्डी का भी पता है कि कितने साल वहां महज सलैक्शन आफ साईट पर गुजार दिए गए । अफसरों ने किस तरह रुकावटें डालीं कि यह जगह ठीक नहीं वह जगह ठीक नहीं । मैं उस वक्त ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर था और यह हम ने फैसला किया था कि उस जगह मण्डी

बननी चाहिए। मैं अकसर वहां के पास से जी० टी० रोड पर से गुजरता हूं, मैं ने देखा है कि उस का काम वहुत सुस्त रफतारी से हो रहा है। इसी तरह छतराने की मण्डी का भी इतना अर्सा सवाल पेंडिंग रहा, उस का फैसला नहीं हुआ। उस का नतीजा यह निकला है कि पातड़ां के लोगों ने खुद मण्डी बना ली है। इसी तरह खमाणों में भी लोगों ने खुद मन्डी बना ली है। आप मुझे मुआफ फरमाएंगें अगर मैं यह कहूं कि जब से मार्किटिंग बोर्ड बना है हम बजाए तरक्की के तनज्जली की तरफ जा रहे हैं। कोई ऐसी मार्किट नहीं जहां से यह शिकायत न मिलती हो कि यह जो बोर्ड है यह हमारे रास्तें में बहुत बड़ी रुकावट है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि बजाए इस के कि यह लोगों के लिए हैल्पफुल साबत हो रुकावट बन गया है। महीनों नहीं सालों तक यहां से जवाब नहीं जाता है। गवर्नमेंट ने जब यह कानून बनाया था तो हम समझते थे कि इस में इम्प्रूवमैंट होगी लेकिन यह रुकावट साबत हो रहा है। इस लिए मैं अर्ज करता हूं कि गवर्नमैंट इस चीज को रीकंसिडर करे और अगर मुनासब समझे तो मैं समझता हूं कि अगर डायरैक्टोरेट बना दे तो अच्छा रहेगा ताकि लोगों को वहां से डायरैक्शन तो मिल सके। इस के इलावा मैं कहना चाहता हूं कि इस बात से मेरा ताल्लुक था कि यहां पंजाब में एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी बनाई जाए। मैं यह फख्र के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं इतनी कोशिश न करता और आँजहानी सरदार प्रताप सिंह से यह न कहलवाता कि अगर गवर्नमैंट आफ इन्डिया हमारी मदद नहीं भी करेगी तो हम अपने खर्च से इसे चलाएंगे तो यह यहां कायम न होती और राजस्थान में चले जाती। खैर यह बन गई लेकिन इसका फायदा जमीदारों को अभी नहीं पहुंचा है। मैं खुद लुध्याना के करीब का रहने वाला हूं और मैं कह सकता हूं कि वहां से कोई रिसर्च हो कर फील्ड में नहीं आई है। फिर मैं अर्ज करता हूं कि यह यूनिवर्सिटी पंजाब के लिए बनाई गई थी और उस वक्त जब यह बनी तो बहुत सारे सीनियर अफसर पंजाब के उधर चले गये थे लेकिन आज वहां क्या हालात हो रहे हैं? मैं ने यह रिपोर्ट पढ़ी है और आपनें भी पढ़ी होगी जिस में कहते हैं कि वहां पी० एच० डी० ही लेते हैं और अब वहां 10 की बजाए 15 पी० एच० डी० हो गए हैं। मैं समझता हूं कि महज़ पी० एच० डी० से ही कोई बात नहीं बनती है। पंजाब के अफसर ज्यादा तजरुबा होने की वजह से और लोकल कन्डीशन्ज़ को जानने की वजह से ज्यादा मौजूं थें लेकिन वह वहां से स्पेयर हो रहे हैं और यहां खाह मखाह पोस्टें क्रियेट करके उनको जज़ब करने की कोशिश की जा रही है। आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तवज्जुह क्यों नहीं दिलाते कि यह क्या हो रहा है। यह तो थी स्टाफ की बात और अब आप देखें कि स्टूडैंट्स के सिलसिले में क्या हो रहा है। कितने स्टूडैंट्स शहरों से लिए जाते हैं और कितने दिहात से लिए जाते हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा कि 60 फी सदी लड़के वहां शहरों के हैं। मैं नहीं समझता कि खेती बाड़ी से उन का क्या ताल्लुक है। मैं आखिर में यही अर्ज करता हूं कि इसे सही मायनों में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया

[सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला]

जाए । यह नहीं होना चाहिए कि स्टूडैंटस का रिसर्च करने वालों का सवाल आए तो शहरों की तरफ निगाह चली जाए और जब स्टाफ रखना हो तो पी० एच० डी० का बहाना लगा कर सारे यू० पी० और दूसरे सूबों के आ जाएं । इस वक्त इस यूनिवर्सिटी का फायदा पंजाब को नहीं पहुंच रहा है । (घंटी) इस लिए मैं पुरजोर अलफाज में अर्ज करूंगा कि इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाए ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਜਗਰਾਉਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਤਅੱਲਕ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਫੂਡ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਇਧਰ ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਲੇਕਨ ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਬਾਹਰ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਨ ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 17-18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਟਰੇਯਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਇਥੇ ਆਏ ਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 6 ਫੀ ਸਦੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਕਰੋੜਾਂ

ਰੁਪਏ ਅੰਨ ਲਿਆਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਨਿਸਟਰ ਤਕ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਗਰ ਸਿਰਫ 6 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਝੂਠੇ ਵਾਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਨ ਲਈ ਇਧੱਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰਕੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਗਰ 6 ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲਿਉਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਛ ਗਿੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਜਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜ ਕਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਾ [illegible] ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣੋਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੈਲਥ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੈਲਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲੇਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 80% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਸ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ 4% ਸੂਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ $1\frac{1}{2}\%$ ਸੂਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

(ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ)

ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4% ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਕੋਲੋਂ $1\frac{1}{2}\%$ ਸੂਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆਨੈਸਟ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰਅਲਿਸਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਬਲਮਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ 2, 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਔਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੰਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 7, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਐਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘਟ ਸੂਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋ ਘਟ ਸੂਦ ਲਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਕ ਮਾਰਕੇ ਛਡ ਦੇਣ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਜੁਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 80% ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ

ਹਨ । ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾਂ ਧੋਖਾ ਹੈ । ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੁਦ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈਕੇ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗਲ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਗਜ ਵਾਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ । ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 14 ਰੁਪਏ ਮਣ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਫ਼ੀ ਮਣ ਭਾੜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ 26 ਰੁਪਏ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕ ਗੁੜ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 3,600 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 5, 6 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਆਦਮੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 500 ਜਾਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ-ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਗਸ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 5, 7 ਆਦਮੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਉਹ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਗਸ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਵੱਜੋਹ ਮੋਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਗੜੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਕੁਰਪਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੰਡ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਦ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਉ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਚੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਿਉ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੰਨੋ ਦੇਵੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ........

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ...... ਖੈਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਚਾਹੇ ਗਲਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਚਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਮੈਂ ਬੜੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਰ ਭੇਜੀ ਜਾਉ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਗੇ ਹੋ, ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ । ਮੈਂ ਸੁਝਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤੁਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਐਨੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ

ਚਲ ਸਕਦੇ । ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ਇਹ ਡੀਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਉਪਰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ । ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪੈ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 7,000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 14,000 ਨੂੰ ਠੋਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ $2\frac{1}{2}$ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ $2\frac{1}{4}$ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਨ ਵਧੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋਵੇ । (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੀਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਖੀਏ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਚਪੇ ਚਪੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ । ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬਲੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਕਫ ਸਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਥੇ I.C.S. ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਉਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਸਾਂਢਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਗਲ ਘੁਟਣ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰੀਆ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਨੰਬਰ 31 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੇਤੀ–ਬਾੜੀ-ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।......

(ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਤਸਕ ਸਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਜੈਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦਿਤਾ ਹੈ । (He could not get any time during the general discussion of the Budget. So he has been given time.)

Dr. Bal krishan : Sir, So is the case with me.

Mr. Speaker : Your name is also on the list.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ,

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

17-18% ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਲੇਮ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਗੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ । ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ.... (*Interruptions*) (ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ) ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਾਚ ਡਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਕਿ ਜੇ ਕਰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੈਕਰ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਚ ਡਾਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲਤ ਪਕੜੇ । ਪਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਰ ਤਾਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਉ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾ ਪਕੜੋ । (ਵਿਘਨ) ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਚੋਰ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵਿਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਧਰਤੀ 3 ਕਰੋੜ 3 ਲਖ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 197 ਲਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਇਕ ਕਰੋੜ 6 ਲਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਅਵੱਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।......

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਕਤਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ Interrupt ਨਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1962 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ 62 ਲਖ ਟਨ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਾਊਨ ਫਾਲ ਆਇਆ । 1965-66 ਦਾ ਟਾਰਗਟ 71 ਲਖ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਰਗਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਹੋਸ਼ਿਆਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਚ 14% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਇਰੀਗੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 8% ਏਰੀਆ ਹੀ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵੀ ਹੈ । ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ (*At this stage Chaudhri Mukhtiar Singh Malik Member of the Panel of Chairmen occupied the Chair*) ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਥੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।

ਭੈਣਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਉਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਮੇਰਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਔਰ ਦਸੰਬਰ 1964, ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤਨੀ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤਨਾ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ੁਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 27,000 ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 28,000 ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 27,000 ਟਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਔਰ 28,000 ਟਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਬਾਰਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ? ਮੈਂ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਉਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾੜੀ ਉਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬੇ ਸਾਹਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

"ਜ਼ਹਾਨੇ ਕੁਹਨਾ ਕੇ ਗਫਲੂਜ ਫਲਸਫਾ ਦਾਨੋ
ਨਜ਼ਾਮੇ ਨੌ ਕੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈਂ।
ਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਆ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਉਗਲਾ ਥਾ,
ਕਿ ਨਸਲੇ ਆਦਮ ਓ ਹਵਾ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਮਰੇ ।
ਮਿਲੇ ਇਸੀਲੀਏ ਰੇਸ਼ਮ ਕੇ ਢੇਰ ਬੁਨਤੀ ਹੈ,
ਕਿ ਦੁਖਤਰਾਨੇ ਵਤਨ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕੋ ਤਰਸੇਂ
ਚਮਨ ਕੋ ਇਸਲਿਏ ਮਾਲੀ ਨੇ ਖੂਨ ਸੇ ਸੀਂਚਾ ਥਾ,
ਕਿ ਉਸ ਕੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹੇ ਬਹਾਰ ਕੋ ਤਰਸੇਂ ।।"

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇਤਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ, 1964, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਸਫੀਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ "Food problem is not the problem of today it is a problem which is century old," ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਪਰਾਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਰਾਬਲਮ ਹੈ । ਇਹ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਨਡਸਟਰੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ । ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਜ਼ਸਮਾਨ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਜ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਥ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮਬਾਰੇ ਇਕ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 400

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਡੀਆਂ ਇਸ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ 259 ਫੈਮੀਲੀਜ਼ ਅਪਰੂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਟੁਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 25-25, 30-30 ਫੁਟ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਆਬ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲ, ਕੱਫਨ ਫਾੜੂ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੇਟ ਉਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ 1/4 of the Punjab rates ਹੈ । ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 80,00,000 ਰੁਪੈ ਦਾ ਬਿਲ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 80,00,000 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਔਰ ਮਰਹੂਮ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਕੇ ਦੋਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ 30,00,000 ਰੁਪੈ ਤੇ ਮਨਵਾ ਦਿਤਾ । ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਸੇ ਰੇਟ ਉਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਰੇਟ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ (ਵਿਘਨ) ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਡਿਲੇ ਔਰ ਰੈਡਟੈਪੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਆਵੇ । ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਸਟ ਪੇਪਰ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ it is not the office that matters, but it is the person who holds that office or sits in the Chair which matters. ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਮ ਨਾ ਗਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ । ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਿਗੜ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ । ਜਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਕ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ, ਜਨਾਬ, 115 ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ । ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹਨ ? ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ । ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ । ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਉਤੇ ਹੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ

ਕਲਰਡ ਤਸਵੀਰ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਉਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 32,000 ਰੁਪਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਐਨੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ he may be sacked or he should be impeached. To say that it is an outonomous body and Government cannot do anything in the matter is obsolutely no answer to the grievances and difficulties of the public.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਔਰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 21,269 ਪਿੰਡ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1960 ਵਿਚ 3,092, 1961 ਵਿਚ 825, 1962 ਵਿਚ 815, 1963 ਵਿਚ 276 ਔਰ 1964 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 54 ਪਿੰਡ ਇਲੈਕਟਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ । ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਿਲਣ । ਵਰਨਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਹੀਂ । (ਘੰਟੀ)

(At this stage Deputy Speaker occupied the Chair)

Deputy Speaker : May I remind the honourable Member to wind up please ?

Chaudhri Darshan Singh : Only five minutes have passed, Madam, since I started speaking. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1940-41 ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਫਿਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਖ ਵਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਦਸ ਵਾਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਵੇ । ਜਿਤਨਾ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਦੂਜੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀ ਅਨਾਜ ਕਨਜ਼ੀਊਮਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਥੇ ਗਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਰਖਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਤਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ।

ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 24 ਜਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਣ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਢੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਪਰਾਫਿਟ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਾਫਿਟ ਪਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਅਮੀਰ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਗਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਜ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਲੈਂਡ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 172 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 80 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਔਰ ਕੋਠੀ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੀਕਲੇਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 1961 ਦੀ ਜਮਾਂ ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਗੱਲ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਹੈ ਉਥੇ ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਥੇ ਹੁਣ 66 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਉਥੇ ਖ਼ੁਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਚਾਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕੋਈ

ਤਕਾਵੀ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਣ ।

पंडित मोहन लाल दत्त : (ग्रम्ब) डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे पंजाब के अन्दर इतने पन शक्ति के साधन मौजूद हैं और दूसरे इतने कुदरती साधन मौजुद हैं लेकिन यह अफसोस और शर्म की बात है कि हमारी सरकार इन का फायदा नहीं उठा रही और यही कारण है कि हमारे यहां इस अन्न संकट में अनाज की पैदावार में इज़ाफा नहीं हो रहा । इस का मेन कारण तो यह है कि इस सरकार में गम्भीरता का एहसास नहीं है, स्पिरट ग्राफ ग्ररजैंसी नहीं है, डाइनेमिज़म नहीं है, काम करने का जोश नहीं है और न ही काम की ज़ील है । कई दफा मैं काम में बड़ी कोताई देखता हूं । बी० डी० ग्रोज़० को ऐग्रीकल्चर काम सौंप रखा है लेकिन उन के हवाले और इतने काम दे रखे हैं कि वह उस तरफ कुछ ध्यान भी नहीं दे पाते । फिर जो डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर डिवेलपमेंट कमेटियां बनी हुई हैं उनमें कुछ काम भी नहीं हो रहा । मिनिस्टरज़ को खुद देहात में जाना चाहिए और वहां की हालत को इन्हें खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए लेकिन हालत यह है कि यह देहात में जाने की बजाए दिल्ली को जाते रहते हैं और इन को देहात के लोगों की ज़रा भी फिक्र नहीं, इन को तो अपनी ही फिक्र रहती है । चाहिए तो यह है कि यह देहात में जाए और किसानों के पास जा कर उन की तकलीफें पूछें और उन की समस्याओं को जानने की कोशिश करें । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह महसूस करता हूं कि यह जो बड़े बड़े आदमी हैं इन की यह बड़ी मुजरमाना गफलत है । इस बारे में मैं अर्ज करता हूं कि इन की इस गफलत के कारण वहां मेरे इलाके के लोगों में यह बात महसूस की जा रही है कि यह जो अनाज की पैदावार के बढ़ाने का काम है वह सिर्फ प्लेनज़ का ही काम है और पहाड़ के लोगों का काम नहीं है। उन के मन में इन्होंने यह एक वहम बना रखा हुआ है । इस लिए, बीबी जी मैं आप के द्वारा ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर साहिब से, जो एक बड़े तकड़े आदमी हैं और यह हमारी खुशकिस्मती है कि वह सरदार प्रताप सिंह की तरह दलेरी से काम करते हैं, बड़ी नम्रता से यह निवेदन करता हूं कि वह वहां एक बार तशरीफ ले आएं और खुद अपनी आंखों से वहां के हालात को देखें कि वहां कितना पोटेंशल है और वहां पैदावार बढ़ाने के कितने साधन मौजूद हैं लेकिन उन को टैप नहीं किया जा रहा वहां पर पैदावार कम होने की वजह यही है कि वहां पर जो नैचूयरल रिसोर्सिज़ हैं उन को मेक्सीमम तौर पर युटेलाईज़ नहीं किया जा रहा । वहां सरवे किया जाता है, स्कीमें बनती हैं लेकिन जब वह स्कीमें यहां पर सरकार के पास पहुंचती हैं लेकिन उस के बाद उन का कुछ पता भी नहीं चलता । वैसे सरकार हिली एरियाज़ पर बड़ा रुपया खर्च कर रही है लेकिन इस का नतीजा कुछ नहीं निकल रहा । जो हिल्ली एरियाज़ एडवाईज़री बोर्ड बना हुआ है उस की रिपोर्ट जो 14 स्तम्बर 1964 को छपी है उस रिपोर्ट में वहां के वाटर पोटेंशल के बारे में सफा 96 पर लिखा हुआ है—

[पंडित मोहन लाल दत्त]

"The S. D. O. Irrigation Branch explained that Lift Irrigation Schemes proposed to be taken up on both sides of the Swan Nadi with two-fold object of reclaiming the water-logged area and providing irrigation to barani area on other side where crops usually failed for want of water. He, however complained that these schemes cannot be implemented till the requisite electricity connections were provided."

यानी वहां 40 मील लम्बी स्वां नदी है । इस का पानी पैरीनियल तौर पर बहता है । इस में उन्होंने उस पानी के बारे में बताया है कि इस पानी की वजह से उस नदी के दोनों तरफ जो जमीन है वह सेम जदा हो चुकी है और कितनी ही जमीन बारानी पड़ी है । यहां पर एक तजवीज़ आई कि यह जो पानी जमीन बरबाद में हो रहा है इस को उपर उठा कर बारानी ज़मीन को दिया जा सकता है चाहे शैलो ट्यूबवैल्ज़ लगा कर या कुछ और कर के ।

(इस समय कोई मैम्बर गृह मन्त्री के पास बात करते हुए देखे गए ।)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब भी हमें कोई इम्पॉर्टेंट मसला वजीर साहिब की खिदमत में पेश करने का मौका मिलता है तो वज़ीर साहिब की तवज्जुह किसी और बात में लग जाती है । वैसे यहां का तीन चौथाई वक्त आपसी गालियों में ही गुजर जाता है ।

(इस समय मैम्बर जो गृह मन्त्री से बातें कर रहे थे उन के पास से उठ कर चले गए ।)

तो मैं वज़ीर साहिब का ध्यान इस बात की तरफ दिला रहा था कि स्वां नदी में जो पानी है और जिस ने 40 मील लम्बा रकबा सेमज़दा कर रखा है उस पानी के साथ लगती जमीन जो कि बारानी है के काम में लाया जा सकता है इस से जहां बारानी इलाका सैराब होगा साथ ही जो इलाका सेमज़दा हो गया है वह भी काबिले काश्त हो जाएगा । उस पानी को शैलो ट्यूबवैल्ज़ के जरिये उठाया जाए । वह बेचारे किसान सब को कहते फिरते हैं मगर कोई सुनता ही नहीं । We have knocked the doors of each and every agency. यहां पर पता ही नहीं लगता, कई एजैंसियां बना रखी हैं और उन में तालमेल नहीं है । सायल कन्ज़रवेशन वाले हैं, एग्रीकल्चर का महकमा है, कम्यूनिटी डिपार्टमैंट भी है, इरीगेशन का महकमा भी है, बिजली बोर्ड भी है इस तरह से इस काम को करने के लिये कई एजैंसियाँ हैं जिन का आपस में ताल मेल नहीं है । अगर इरीगेशन के ऐस० डी० ओ० साहिब ने एक स्कीम बनाई तो बिजली वाले पावर नहीं देते । यही नहीं वहां पर आज तक कनसालीडेशन नहीं हो सकी । ऐस० डी० ओ० साहिब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि—

Another difficulty was that the people were not eager to have water till the consolidation operations had taken place.

जनाब गगरेट के पूरे के पूरे बलाक की कनसालीडेशन नहीं हुई। यह हमारी खुशकिसमती है कि इस महकमा के वजीर सरदार दरबारा सिंह जी हैं इन से हमें बहुत तवक्कोह है कि पूरे जोर के साथ काम करेंगे। ठीक है इन को अब तक यही मजबूरी रही है कि इन को टाइम ही नहीं मिला। जैसे कि गिल साहिब ने कहा था सब झगड़े छोड़ कर इस तरफ तवज्जुह दें। मैं अर्ज़ करूं कि कुछ रकबे ऐसे हैं जहां पर ट्यूब वैल्ज़ कामयाब हो सकते हैं इन का जो ट्यूब वैल्ज़ ऐक्सप्लोरेटरी डिवीजन बना हुआ है करनाल में उस के ऐक्स० इ० ऐन० ने जो सर्वे किया है उस के मुताबिक उन्होंने ट्रायल बोर्ज़ के लिये 13 जगहें सीलैक्ट भी की हैं मगर चूंकि वहां पर छोटे २ गरीब मालिकान हैं इस लिये वह खुद इस काम को नहीं कर सकते। तो यह काम सरकार को करना चाहिए वहां पर दो गांव हैं कलोह और टटेड़ जहां पर ट्यूबवैल्ज़ कामयाब भी हुए हैं जो कि वहां के कुछ बड़े जमींदारों ने आप लगाए हैं। मगर चूंकि वह बड़े लैंडलार्ड थे इस लिये वह तो लगा सकते थे मगर छोटे किसान यह काम खुद नहीं कर सकते। स्कीम बनी हुई है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार के पास सिर्फ एक ही रिग है जिसे यह रोटरी कम प्रोडक्शन रिग कहते हैं मगर हिन्द सरकार का है और कभी कहीं चला जाता है और कभी कहीं चला जाता है। इधर यह तैयारी करते हैं ट्रायल बोर्ज की मगर वह रिग नहीं आता। इस लिये यह प्रार्थना करूंगा कि इन गरीब लोगों की इस बात की तरफ ध्यान दिया जाए, यह बैकवर्ड हिल्ली एरिया है और यहां पर आबपाशी के साधन नहीं हैं। आप के इन्जनियर्ज एक स्कीम पेश कर रहे हैं तो इस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। सिर्फ कागज़ी घोड़े दौड़ाने से पैदावार नहीं बढ़ सकती।

एक और अर्ज करूं कि वहां पर रैक्लेमेशन का भी प्राबलम है। वह जमीन बरबाद हो चुकी है और काफी अर्सा से बन्जर कदीम पड़ी है। यह जो जमीन स्वां के साथ साथ है इस को रीक्लेम किया जाना चाहिए। सायल कन्ज़रवेशन डिपार्टमैंट ने एक एकड़ जमीन वहां पर रीक्लेम नहीं की। इस को रीक्लेम करने से दो परपज़ हल होंगें। एक तो यह जमीन रीक्लेम हो कर पैदावार बढ़ाएगी दूसरे उस इलाके में सरपलस लैंड न होने से जो वहां पर लैंडलैस पैज़ेंट क्लास है उस को इस 40 मील के रकबे में जो अब जमीन बेकार पड़ी है उस पर सरकार द्वारा ठीक कर के उन को बसाया जा सकता है। लैंडलैस लेबर और हरिजनों को उस जमीन को ठीक कर के और पानी के साधन पहुंचा कर उन को कोआपरेटिव सोसाइटियां बना कर वहां पर बसाया जा सकता है। इस तरह से उन लोगों का मसला हल हो जाएगा जो वहाँ पर मेहनत करते आए हैं। इस सम्बन्ध में महकमा ने एक कानून बनाया है युलाइज़ेशन आफ लैंडज़ एक्ट। उस में यह रखा गया है कि गरीब आदमी अर्जी दें जमाबन्दी को फर्द बता कर कि यह जमीन खला पड़ी है, डिप्टी कमिश्नर, ऐस०डी०ओ० या तहसीलदार के नोटिस में लाएं कि यह बात है। मगर ऐसा वह नहीं कर सकते। वह गरीब कानून नहीं जानते, पैसा उन के पास नहीं,

[पंडित मोहन लाल दत्त]

ताकत उन में नहीं यह काम वह नहीं कर सकते । यह तो आप अपने इन अफसरों की डियूटी लगाएं कि वह जाएं और खुद ही जा कर देखें कि कौन सी जमीन 6 फसलों से खला पड़ी हुई है और खुद ही ऐक्वायर करें रीकलेम करें । इस तरह से उन की ड्यूटी लगाएं कि खुद ही इस बात को जल्दी करें वरना कोई दरखास्त देने आप के पास नहीं आयगा । मुझे इस का तजरूबा है । मेरे अपने गांव में हरिजनों के सौ घर हैं और उन को दो साल हुए दरखास्त दिए हुए कि यह जमीन तीन साल से खाली पड़ी है हम लैंडलैस टैनैंटस को जमीन दी जाए । मगर उस पर अमल ही नहीं होने में आता । कभी ऐस० डी० ओ० पटवारी को लिख देता है कि जमीन का नम्बर दो और कभी पटवारी के पास वह कागज़ पड़े रहते हैं इस तरह से डिले होती है .....

उपाध्यक्षा: आप कितना टाइम और लेंगे ? (How m ch more time will the hon. member take ?)

पंडित मोहन लाल दत्त: पांच सात मिनट और दें ।

उपाध्यक्षा. पांच मिनट में खत्म करें । (He may finish in five minutes.)

पंडित मोहन लाल दत्त: बहुत अच्छा जी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, खेती बाड़ी के लिये पशुधन की बहुत जरूरत रहती है । हमारे उस इलाके में जो मशीनरी से तो खेती होती नहीं बैलों के जरिये ही होती है सरकार मुरगियां और सुरों के पालने पर तो ज़ोर दे रही है और खर्च करती है मगर गउओं और बैलों की नसल सुधारने के सम्बन्ध में हमारे इलाके में तो कुछ नहीं किया । और इलाकों में कई स्कीमें बनी हुई हैं लेकिन हमारे इलाके में कोई स्कीम नहीं दी गई । हमारे इलाके में कैटल ब्रीडिन्ग फार्म नहीं है । पेडिग्री बुलज़ और साहीवाल जरसी के लिए एक स्टेशन पालमपुर में है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐनीमल हस्बैन्डरी का कोई भी इन्तजाम तहसील ऊना के अन्दर नहीं है ।

इस के अलावा अच्छी चरांद नहीं है । इस लिए कोई भी इस इलाके में अच्छी गाए अच्छी भैंस और अच्छा बुल नहीं रख सकता । इस के लिए मैं यह सुझाव दूंगा कि इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दिए जाएं । जो जंगल हैं वहां पर घास अच्छी किस्म का नहीं और उसका न्यूटीशन अच्छा नहीं । मुझे पता है कि ऐग्रीकलचर रिसर्च इन्स्टीचूट में ऐग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट ने कई किस्म की वरायटीज़ ग्रास की निकाली हैं जैसे नेपियर ग्रास है । इस के बारे में हमारे इलाके में भी प्रचार किया जाना चाहिए और जानकारी लोगों को दी जाए । लेकिन इस के बरअक्स क्लोयर्ज लगाए हुए हैं । और जंगल की डिवैल्पमेंट के लिए कुछ नहीं किया जाता । और बंदश लगा दी है कि यहां पर पशु न लाओ और तोड़ किया जाता है ।

इस के साथ ही मैं एक बात कैटल इन्शोरेंस के बारे में करना चाहता हूँ ताकि अच्छे पशू रखे जा सकें। वहाँ कोई वैटनरी इन्सपैक्टर तक नहीं। आज हालत यह है कि अगर किसी का अच्छा बैल या अच्छी गाए मर जाए तो वह तमाम उमर इस नुक्सान के नीचे दबा रहता है। इस लिए कैटल इन्शोरेंस की सकीम को यहां पर लागू करना चाहिए।

बरानी इलाके में क्राप इन्शोरेंस की स्कीम को लागू करना चाहिए क्योंकि बारानी इलाके में बारिश न होने की वजह से फसल फेल हो जाती है। इस लिए मैं अर्ज़ करूंगा कि क्राप इन्शोरेंस का इन्तज़ाम कर दिया जाए।

यह सरकार प्लेन्ज में तो कई तरह की स्कीमें चालू करती है। पैकेज प्रोग्राम भी है जिस के द्वारा इन्टैनसिव डिवैलपमैंट को हाथ मे लिया गया है ताकि किसी खास इलाके को उन्नत किया जाए। तो क्यों न हमारी तहसील में भी एक इलाका इन्टैनसिव डिवैल्पमैंट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए। हमारे हां भी इस तरह का इलाका है। गगरेट से सवां तक 18 मील का रकबा है जिस को इस काम के लिए लिया जा सकता है। इस पर आप अगर पाइलट प्राजैक्ट लगा दें तो इस इलाके की डिवैलपमेंट हो सकती है। और यह इलाका इन्टेनसिव कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है और भी इलाका इन दो बलाकों में चुना जा सकता है और इन्टेनसिव डिवैल्पमैंट का काम चल सकता है। इतना कह कर मैं आप का धन्यवाद करता हूं।

डाक्टर बालकृष्ण (होशियारपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का वक्त दिया है चूंकि मुझे इस सेशन में बोलने का मौका नहीं मिला था। और पहली मरतबा ही इस ऐग्रीकल्चर की डिमांड पर बोल रहा हूं। पेशतर इस के कि डिमांड के मुताल्लिक कुछ अर्ज़ करूं मैं आप की मारफत गवर्नमेन्ट पर ऐग्रीकल्चर की इम्पार्टेन्स को ऐम्फेसाइज़ करना चाहता हूं और इस की महानता बताना चाहता हूं। पंजाबी में कहावत है कि—

उत्तम खेती मध्य व्यापार
नखिध चाकरी भीख गंवार।

इस लिए ऐग्रीकल्चर सब कामों से उत्तम है और इस को बढ़ाना नेशनल ड्यूटी है। इस के प्राबलम्ज़ को हल करने के लिए मैं दो बातों को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। एक तो यह है कि—(i) India is a land of villages and shall continue to be so (ii) Agriculture has been the main stay or the basic industry of the people of this country, particularly the Punjab from times immemorial and it is so to-day.

[डाक्टर बाल कृष्ण]

हमारी 80 फी सदी पापूलेशन देहात में रहती है और अगर उनकी प्राबलम को हल कर दिया जाए तो आटोमैटीकली बहुत सी बाकी प्राबलमज हल हो जाती हैं। मैं इस सिलसिले में श्री टैगोर के अलफाज कोट करना चाहता हूं। मुझे उन के लफज़ याद हैं उन्हों ने कहा था कि--

Our country is the cradle of Agricultural civilization and in the keeping of villages lies the cradle of the race.

यही नहीं डिप्टी स्पीकर साहिबा, हिन्दुस्तान के अंग्रेज हुकमरान जो 15 अगस्त को चले गए उन में से एक ने ऐग्रीकलचर की महानता को इम्पारटेंट समझा था। The memorable words cf Lord Linlithgo are worthy of quotation here, who said-

"Those who govern and those who aspire to govern must never allow themselves to forget that India's wealth in an overwhelming degree is her Agriculture and that upon the fields of her cultivators is founded the whole structure of Indias economy. The peasant now, as ever, is the chief source and creator of both her wealth and her greatness and of him, may with truth be said that he is India.

और इसी इम्पारटेंस को हमारी गवर्नमेंट ने रीआलाइज़ किया। उन्होंने तीसरी फाइव यीअर प्लान के अन्दर जो रकम एगीकलचर प्रोडक्शन के लिए रखी उस में से 3 करोड़ 76 लाख पिछले तीन साल के अन्दर खर्च कर दी है और 3.07 करोड़ रु० की रकम 1964-65 के लिए रखी गई थी और बाकी की 3.78 करोड़ सन 1965-66 में खर्च होगी। इस के लिए जहां मैं इस सरकार को बधाई देता हूं वहां सरकार से इलतजा भी करना चाहता हूं कि हम थयूरीज़ को ही एक्सपाऊंड न करें और स्कीमों को कागजों पर ही न रखें बल्कि इन को अमली जामा पहनाएं। इस के बारे में हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू के वह अलफाज़ यहां पर पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने डिवैल्पमैन्ट कमिश्नर्ज़ की कम्यूनिटी प्राजैक्टस के बारे हुई कानफ्रेन्स में अपने इनआगोरल ऐडरेस में 7 मई 1952 को कहे थे।

The Prime Minister observed—

"I suppose there is hardly a country (and I speak with due deference to other countries) in the world, which has such high ideals as India. I may add there is hardly a country where the gap between the ideals and performance is so wide as in India. So it is dangerous thing to talk very big and then not to go anywhere near the objective of what you are talking about.

इसी तरह से हमारी इस से पहले की गवर्नमेंट ने यह दावा किया था कि हम ऐग्रीकलचर प्रोडक्शन को डबल कर देंगे। यह निशाना अनरियलिस्टक था। मैं यह समझता हूं कि हमें इस तरह की अनरियलिस्टक चीजों के ऊपर अपने मुल्क का दारोमदार नहीं रखना चाहिए, because mere mathematical calculations based on assumptions do not increase the agricultural production. अगर हम 18, 20 या 25 परसेन्ट भी प्रोडक्शन को बढ़ा

सकें तो यह एक भारी अचीवमेन्ट होगी । Let us not be pleased with the rosy picture supplied by the departments but let us expose our weaknesses and face the realities boldly. That would be the right way to progress.

मैं तो यहां तक कहूंगा that we should be after achieving good results within the minimum period and must face all obstacles squarely.

डिप्टी स्पीकर साहिबा इस वक्त जब कि हमारी आज़ादी अभी इनफैनसी में है, हमारी डैमोक्रेसी जब कि इम्मैचेयोर (immature) है गुरबत हमारे चारों तरफ फैली हुई है और आबादी हमारी लगातार बढ़ती जा रही है तो ऐसे हालात में प्रोडक्शन का बढ़ाना बहुत ज़रूरी है । मगर हालत यह है कि ड्यूटी का हमें बिलकुल भी अहसास नहीं है खाह हम पब्लिकमैन हैं खवाह हम पालिटीशीयन हैं, चाहे हम सर्विसमैन हैं । ऐसी पोज़ीशन में हमें सही हालत अपने नैशनल लीडरज़ के सामने रखनी चाहिये ताकि ऐगजैजरेटिड फिगर्ज़ को हम अपने लीडरज़ के सामने न रखें । असलियत को छुपाना मैं समझता हूं अपने आप को धोखा देना है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की विसातत से गवर्नमैंट के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारा देश अभी तक खुराक के मुआमला में सैल्फ सफीशैंट नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें हर साल करोड़ों मन अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता है । प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये मैं चंद ज़रूरी फैकटर्ज़ आपकी मारफत सदन में रखना चाहता हूं । वह यह हैं :

1. Irrigation and drainage.
2. Manure and Fertilizers.
3. Seed.
4. Technical guidance.
5. Holdings
6. Credit.
7. Improved implements.
8. Plant protection measures.
9. Conservation of soil and to avoid its erosion.
10. Marketing.

मैं इन सारे फैकटरज़ के बारे में एक एक करके कुछ ना कुछ एक एक मिनट के लिये अर्ज़ करना चाहुंगा ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, थर्ड प्लैन में माइनर इरीगेशन और डरेनेज़ के लिये कोई 6½ करोड़ रुपया अलाट किया गया था । इस में से पहले तीन सालों में जो खर्च हो चुका है यह कोई 2.98 करोड़ रुपये हैं, 1964-65 में जो खर्च किया गया वह 2.37 करोड़ है मगर अभी तक लोगों की पानी की डीमांड पूरी नहीं हुई और अब 1965-66 में 1.68 करोड़ ही खर्च होना है । आप जानते हैं कि

[डाक्टर बाल कृष्ण]

पैदावार बढ़ाने के लिये पानी सब से ज्यादा जरूरी फैक्टर है । यह कहावत भी है कि जमीन वह रानी जिस के सर पर पानी । Irrigation is the most important and fundamental factor which would bring about increase in production.

मेरे ज़िला होशियारपुर से भाखड़ा नहर निकलती है मगर बदकिस्मती से मेरे ज़िले की ज़मीन को यह सैराब नहीं करती । मैं आपकी मारफत गवर्नमैंट की तवज्जोह इस जिला की इरीगेशन की जरुरियात की तरफ दिलाना जरुरी समझता हूं । इस के लिये मैं यह निहायत जरूरी समझता हूं कि सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा रुपया इरीगेशन के लिये इस ज़िले को दिया जाये ताकि वहां के लोग भी टयूबवैल्ज, पम्पिंग सैट्स और परकोलेशन वैल्ज़ वगैरा लगाकर अनाज की उपज में इज़ाफा कर सकें । मुझे यह मालूम हुआ है कि गवर्नमैंट ने 10 लाख रुपया होशियारपुर जिला के लियें मनजूर किया था यह खबर मुझे डी० सी० होशियारपुर से मिली थी—मगर वह रुपया अब तक खर्च नहीं किया गया । यह रुपया इसी फाईनैनशियल ईयर में खर्च किया जाना था । मैं इस के लिये सरकार को कहना चाहता हूं कि इस के मुताबक फौरन ही डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी की जायें ताकि यह रुपया ज़िला की बेहतरी के लिये ही खर्च किया जा सके । इस के साथ ही एक बात और जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि टियूबवैल्ज़ और परकोलेशन वैल्ज़ लगाने में आम तौर पर जो प्रैक्टीकल डिफीकल्टी आती है, वह यह है कि जल्दी जल्दी इलैक्ट्रिकल कुनैकशन नहीं मिलते । ऐसी जगह पर लोगों ने मोटर्ज़ लगायें हुये हैं जहां से 11 के० वी० लाईन चंद फुट के फासले से ही गुज़रती है मगर वह लोग बहुत कोशिशों के बावजूद भी कुनैकशन नहीं ले सके पता नहीं यह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करता है कि जहां इतनी अहम ज़रूरत हों वहां भी सालों तक ध्यान नहीं दिया जाता । बोर्ड बनाने का आबजैक्ट था (1) To exercise economy. (2) To improve efficiency and (3) To avoid Red-Tapism. जहां तक इस बोर्ड से किसी तरह की इकानोमी का सवाल है वह तो यह है कि from the very inception of the State Electricity Board, it is running at a loss और जहां तक इससे किसी तरह की ऐफीशियैंसी का सवाल है आप देख ही रहे हैं कि आगे की निसबत बिजली के ब्रेकडाउन ज्यादा होते हैं रैड टैपिज्म का यह हाल है कि 6—6 महीने हो गये हैं मगर अभी तक लोगों को कुनैक्शन नहीं मिले । हज़ारों की तादाद में केसिज पड़े हुये हैं मगर महकमे वाले जल्दी जल्दी ध्यान देने का नाम नहीं लेते । इस के मुताल्लिक मेरी गवर्नमैंट से एक ही प्रार्थना है कि either mend this Board or end this Board. There is no other alternative.

दूसरी चीज जो मैं ने अर्ज करनी है वह फर्टेलाईज्र के मुताल्लिक है । मैं तीन साल से इस हाउस में भी लगातार कहता आ रहा हूं और मैं ने कई मीटिंगज़ में

भी इस के मुतालिक कहा हैं, डिस्ट्रिक्ट लैवल पर भी मैं ने इस के मुताल्लिक कहा है कि हमें टाइमली और ऐडीक्वेट सप्लाई खाद की नहीं मिलती । अगर पैदावार को बढ़ाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा मिकदार में खाद सप्लाई की जाये, और इस की कास्ट को सब्सेडाईज किया जाए ।

Deputy Speaker : Kindly wind up.

डाक्टर बालकृष्ण : मैं जब से बजट पर डिसकशन चली है पहली दफा बोलने लगा हूं । उम्मीद है आप मुझे थोड़ा वक्त और देंगे ।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे ज़िला में लोगों को खाद की पूरी सप्लाई नहीं मिलती इस लिये मैं गवर्नमैंट की तवज्जोह इस तरफ दिलाना चाहता हूं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फर्टेलाईज़र मिले । अम्बाला की फर्टेलाईज़र फर्म के मुताल्लिक पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी की रिपोर्ट में भी लिखा गया था कि बोगस फर्म है इसके एकाऊंट्स प्रापर नहीं हैं । इस के मुताल्लिक मैं कहूंगा कि सरकार को चाहिये कि इस तरफ जल्दी से जल्दी तवज्जोह दें ।

सीड्ज के मुताल्लिक मैं दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूं । एक किस्म तो न्यूक्लियर सीड की है जो ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तैयार करती है और दूसरा फाऊंडेशन सीड है जो गवर्नमैंट फार्मज में पैदा किया जाता है । फिर यह सीड गवर्नमैंट के रजिस्टर्ड गरोअर्ज की मारफत मल्टीपलाई किया जाता है । इस के बाद आम लोगों को दिया जाता है । अच्छे सीड की यह निशानी है कि एक वह rust resistant, draught resistant high yielding and potentiality, का होता है । इन चार गुणों का होना अच्छे सीड के लिये निहायत ही जरूरी है । अगर आप को कभी मेरे फार्म पर जाने का इत्तेफाक हो तो पता लगे कि कौन सी अच्छी फसल होती है । हम अच्छी से अच्छी कवालिटी के सीड्ज इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा हो । इसी तरह मैं पोटेटो के सीड के मुताल्लिक भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि पंजाब सरकार यह सीड हिमाचल प्रदेश से मंगवाती है । हम यह सीड शिमला या डलहौज़ी या कुल्लू में आसानी से पैदा करके लोगों की डीमाँड भी पूरी कर सकते हैं और लाखों रुपया बचा सकते हैं ।

लास्ट चीज़ जो मैं अर्ज़ करनी चाहता हूं, वह एक पर्सनल ऐक्सप्लनेशन के मुताल्लिक है । यहां एक बात कहीं गई है जिस का मैं जवाब देना चाहता हूं । बदकिस्मती से आप समझें या खुशकिस्मती से मैं भी कास्ट आफ प्रोडक्शन कमेटी का मैंबर रहा हूं । एक आनरेबल मेम्बर ने मेरा इस बात का मज़ाक उड़ाया कि मुझे खेती के मुताल्लिक पूरी वाकफियत नहीं है । मैं उन की वाकफियत के लिये बता दूं कि मैं अपने फार्म में 10 घंटे तक रोज़ाना ट्रैक्टर पर काम करता हूं । मेरे पास दो ट्रैक्टर हैं । वह मेरे फार्म पर आकर ट्रैक्टर चलता हुआ देखें । उन को शायद मेरे मुताल्लिक गलत फहमी लगी है । इन इलफाज से साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਮਜੀਠਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਤਨੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖਣ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੱਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 80-85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੈ । ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਪੜੇ ਪਾਊਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸ਼ੋਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਨਾਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ । ਨਾ ਅਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਣਾ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ । ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ, ਸਿਆਲ ਅਤੇ ਕੜਕਦੀਆਂ ਧੁਪਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ । ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਨੇ ਤੰਗ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 80-85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਤੇ ਭੁਖੀ ਮਰਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਹਾਲਤ ਭੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ । ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆਪ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਂਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਅੱਲੁਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵਧਾ ਸਕਣ ।

ਇਥੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਦ, ਟਯੂਬਵੈੱਲ ਸੀਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਗਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ

ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਟਾ ਥੋੜਾ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਯੂਬਵੈਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਪੁਲੀਆਂ, ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਲ਼, ਸੀਡ ਰਖਣ ਲਈ ਸ਼ੈਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੀਮਿੰਟ ਘਟੋ ਘੱਟ ਜੇ 80% ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਖਾਦ ਦੀ ਗਲਤ ਡਿਸਟਰੀਬਿਯੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜੋ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਮਿਟ ਕਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਈ ਕਈ ਬੈਗਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਬਜਾਈ ਕੁਝ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੇਟ ਵਰਾਇਟੀ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਨੂੰ procure ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਥੇ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਆਈ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਸਰੀ ਹੀ ਸੁਸਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜੋ late variety ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਕੇ ਰਖਣ। ਅਜ ਕਲ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਰਖ ਲਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁਸਰੀ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ 10% ਵੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਣੀ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਮਗਰ ਉਹ ਬੀਜ ਇਤਨਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ

[ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]

ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ 80 ਜਾਂ 90 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਲਾਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਚੇ ਹੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਪਟਸੁਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਕੇ ਦਿਖਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਏਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ । ਏਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਜੋ ਹਾੜੀ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ procure ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਦੇਣ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਬੀਜ ਦੇਣ ਅਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ । ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਨਗਹਿਲੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਰੀ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨੌਲਜ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਰਸਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੀਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਕ ਹੌਰਸਪਾਵਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਲਗੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਹੌਰਸਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਪਿਗ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਗਈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨਕਮ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ

ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਏਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਬਣੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣੇ । (ਘੰਟੀ) ਬਸ ਜੀ, ਇਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖੀ ਹੈ । ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ । ਮਗਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ । ਲੈਂਡ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਬਣਾਉ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ । ਉਦੋਂ ਏਥੇ ਸੀਲਿੰਗ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ । ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਉੱਚਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਟ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਸੌ ਏਕੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਏਕੜ ਤਕ ਆ ਗਈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਹਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ । ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਟ ਦੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁਟ ਮਚਾਉਣ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਸੈਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰਨਗੇ । ਉਹ ਲੁਕੋਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਵਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਫਸਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਟ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਕਮਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਟ ਪੈਦਾਵਾਰ 18% ਵਧਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਰਕਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਵਧੀ ਵਿਖਾਕੇ ਉਹ ਇਨਾਮਾਤ ਵੀ ਖੁਦ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਵਿਚ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ

[ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]

ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉ । ਮਗਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ । ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨ ਹਲਵਾਹਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਜਾਂ 20 ਹਰੀਜਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਸ ਸਕਣ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਵਧਾਉਣ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨ ਫੈਮੀਲੀਜ਼ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ । ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਲਹਿਦਾ ਦਸ ਦਿਆਂਗੀ । ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਕ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਹਨ । ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਵਡਾ ਖਤਰਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਸਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਚੂੰਕਿ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦਨੀ ਛਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿਉਗੇ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਦਿਉਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । (ਸ਼ੋਰ)

Deputy Speaker : No interruption please.

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਹੀ ਸੁਝਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸੁਝਾ ਕਹਾਂਗੀ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਹਿਬਾ, ਅਜ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਮਦ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੁਗਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤਿਗਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਥਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁਗਣੀ ਵਧਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਭਜ ਗਿਆ ਤੀਜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਾਲ 1963-64 ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਹੀ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ :

> "......There was stagnation in the output of foodgrains during the past three years, the fall during 1962-63 as compared to 1961-62 having been 5.04 lakh tons. During 1963-64 the production was slightly less than in 1962-63 (56.57 lakh tons as against 56,99 lakh tons)".

ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਥੋਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਥੋਥੇ ਦਾ ਥੋਥਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਾਂ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਕੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਢ ਲਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸ ਨੌਂਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦਬੁਰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ

(ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)

ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਾਸ 1400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟਬੱਰ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜ ਜੀ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਚਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਢ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਨਾਟਪਲੇਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਅਜ ਉਸ 1400 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲਸ ਏਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1400 ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ 90 ਏਕੜ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ । ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਹਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਰਾਈਆ ਗਈਆਂ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਸਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਤਹਸੀਲਦਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ । ਫਿਰ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ । ਉਸੇ ਜਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤਦੇਹ ਦਾ ਵੀ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਸ਼ਾਮਲਾਤਦੇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਚਕੌਤੇ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾ ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚਕੌਤਾ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੇਰਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ: ਇਹ ਗਲ ਤੁਸਾਂ ਉਸਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ?

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇਕੋ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੂਪਹੋਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਦਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਤੇਨੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair)

ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਸੀ । ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੀ 2,000 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ । ਉਥੇ 3-4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਉਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਬਨਿਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ । (ਘੰਟੀ)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਹਰੀਕੇ ਪਤੱਨ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤਾਈਂ ਰੀਫਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁੜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਥੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਵੀ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 10, 10 ਮੀਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੀਕਲੇਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਪਰ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ?

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਫਾਰਮਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਵਾਲਾ ਵਿਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ । ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 1/3 ਹਿਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਣ 1/2 ਹਿਸਾ ਬਟਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਈ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ । ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੀਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ।

(ਘੰਟੀ)

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਈਸ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਘੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । 1964 ਦੀ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 8594-R/I-24/24 dated 9th March, 1944 ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਬਿਆਨਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਘੰਟੀ)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1/4 ਹਿਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਟੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਉਤੇ ਡੀਜਲ ਇੰਜਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ ।

EXTENSION OF TIME OF THE SITTING

Chief Parliamentary Secretary : Sir, I beg to move that in order to accommodate more Members who want to speak on this important issue, the sitting of the House be extended by half-an-Hour.

(Voices: One hour)

Mr. Speaker: Is it the pleasure of the House that the sitting of the House be extended by one hour ?

(Voices: Yes. Yes)

Mr. Speaker: All right. The House will sit up to 3.00 P. M.

DEMANDS FOR GRANTS

(i) 31—Agriculture

(ii) 95—Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research.

(**Resumption**—concld)

श्री मुलतान सिंह (बुटाना) : स्पीकर साहिब वैसे तो एग्रीकल्चर का महकमा बहुत ही इम्पोंटैंस रखता है लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। आज तक किसी सूबे के मुख्य मंत्री ने इस महकमें को अपने हाथ में लेना मुनासिब नहीं समझा । इस से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार इस की ओर ध्यान कम दे रही है । वैसे तो पहली पंच वर्षीय योजना में, दूसरी पंच वर्षीय योजना में और तीसरी पंच वर्षीय योजना में इस की ओर टाप प्रायरिटी देने का वायदा किया गया लेकिन सही मायनों में इस की ओर तवज्जोह नहीं दी जा रही है । यही वजह है कि हम ज़यादा से ज़यादा अनाज इम्पोर्ट करते जा रहे हैं । मैं तो इस नतीजे पर

पहुंचा हूं कि हमारा देश इम्पोर्टिंग देश बन गया है । हम कभी भी इस बारे में सरप्लस नहीं हो सकेंगे । 1952 में हमारे प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि तीन सालों के अन्दर सैल्फ सफीशैंट हो जाएंगे । लेकिन हम ने 1955 में 16 लाख टन गन्दम फारेन कन्ट्रीज़ से इम्पोर्ट की, 1957-में साढ़े पच्चीस लाख टन गन्दम इम्पोर्ट की, 1963 में 50 लाख टन गन्दम इम्पोर्ट की और पिछले साल 65 लाख टन गन्दम इम्पोर्ट की । आप अंदाज़ा लगायें कि अब हम चार गुना ज़यादा अन्न इम्पोर्ट कर रहे हैं । हम ने क्या तरक्की की है ? पिछले साल दिसम्बर के महीने में बहुत ज़यादा मंहगाई हुई । मार्च के महीने में होती तो और बात थी या फरवरी में भी होती तो भी मान सकते थे लेकिन उस महीने में क्यों हुई ? मैं सरकार से पूछता हूं कि सरकार ने अनाज का पहले से ही क्यों इन्तजाम नहीं किया ? इतने थोड़े से अर्से में प्राइसिज़ में 23 प्रसैंट इनक्रीज़ होती है और हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते । मैम्बरों को और देश वालों को गवर्नमैंट को इम्पीचमेंट करनी चाहिये। क्यों इस ने अपनी इनएफीशिसी की वजह से प्राईसिज़ इतनी बढ़ने दी? इसे गल्ले की इम्पोर्ट का पहले से ही इनतज़ाम करना चाहिये था । मैं आप से अर्ज करूं कि 1958-59 में जितना गल्ला यहां हुआ था उस के बाद कभी उतना नहीं हुआ । 1956-57 में 7992 हज़ार टन अनाज हुआ था, 1958-59 में 9060 हज़ार टन हुआ, 1960-61 में 9011 टन, 1961-62 में 8961 हज़ार टन, 1963-64 में 8138 हज़ार टन गल्ला हुआ । आप देख सकते हैं कि गल्ले की पैदावार बतदरीज घटती ही गई है । अगर पंजाब की यह हालत है तो हिन्दोस्तान के और सूबों की क्या हालत होगी । फिर लुत्फ की बात यह है कि इस दौरान हम फरटेलाईज़र पर भी ज़यादा खर्च करते रहे हैं, इरीगेशनल फैसिलीटीज़ भी ज़यादा दी हैं और इस के साथ ही दूसरे इनसैंटिव मसलन कीड़ों को मारने पर भी ज्यादा खर्च किया है । इस के बावजूद भी क्या कारण है कि हमारी पैदावार कम हुई है । अगर आप गहराई से सोचें तो मालूम होगा कि हमारी लैंड रीफार्म्ज़ ठीक नहीं हुई । इस साल हम ने राइस की पैदावार में 15 परसैंट तरक्की की है । सरप्लस रखने के लिये हमें स्टोर भी बनाने चाहियें । स्टोर न होने के कारण हमारा गल्ला 15 परसैंट और कई हालतों में 50 परसैंट तक भी ज़ाया हो जाता है । जहां हम इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े डैम बना रहे हैं वहां हम को स्टोर भी बनाने चाहियें जहां पर कि किसान अपना सरप्लस गल्ला जमा रख सकें । जो मौजूदा स्टोर बने हुए हैं वहां पर किसान अपना दस परसैंट गल्ला भी नहीं रख सकता । अपने घरों में रखने से भी बड़ा नुकसान होता है, चूहे वगैरह बहुत सा गल्ला खा जाते हैं । हिन्द समाचार अखबार में कल एक आर्टिकल था कि बाहर से जो अनाज मंगवाया गया उस में से 85 फी सदी की क्वालिटी खराब हो गई और बाकी में भी 55 फीसदी की कमी हो गई क्योंकि उस को स्टोर करने के लिये प्रापर स्टोर नहीं थे । बड़ी हैरानी की बात है कि अनाज बाहर से भी मंगवाते हैं और फिर प्रापरली स्टोर कर के भी नहीं रखा जाता । कई लोग जापान की तरक्की की मिसाल देते हैं कि देखिये साहिब जापान ने थोड़े ही अरसे

[श्री मुल्तान सिंह]
में कितनी तरक्की की है । कई मैम्बर अमरीका की मिसाल देते हैं कि अमरीका ने कितनी तरक्की की है । हमें न तो जापान की नकल करना है और न ही अमरीका की नकल करना है लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जापान में 1947 में 7,000 हैंड ड्रिवन ट्रैक्टर थे, 1953 में उन का नम्बर 35,000 हो गया, 1955 में 85,000 तो 1961 में उन की तादाद 10 लाख हो गई । लेकिन हमारे देश में सारे संसार का एक चौथाई तो मवैशी हैं । फिर अच्छे बैल भी काश्त करने के लिये नहीं मिलते । जहां पर स्माल होलडिंग्ज़ हों वहां पर बैलों से खेती कामयाब नहीं हो सकती । यहां पर जब सरकार ने मैक्सिमम होल्डिंग्ज़ 30 स्टैंडर्ड एकड़ रखी है तो मिनिमम सीलिंग भी रखी जानी चाहिये । क्योंकि जब बैलों के द्वारा काश्त करनी है तो कम से कम चार बैलों के चारे के लिये भी तो 6,7 एकड़ ज़मीन चारे की काश्त के लिये चाहिये अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में अनाज की पैदावार बढ़े तो किसानों को काश्त करने के लिये हाथ से चलाये जाने वाले ट्रैक्टर सप्लाई करिये । यह बहुत ज़रूरी है वरना मवैशी रखने से तो बैल, गाए और भैंसों के लिये चारा काश्त करने के लिये भी कितनी ही ज़मीन की ज़रूरत होती है । या तो आप कैटल वैल्थ को खत्म करें और या फिर होल्डिंग्ज़ को बढ़ाइये । इस साल भी फाईनैंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहिब ने किसानों के लिये काफी स्कीमें रखी हैं जिन से प्रोड्यूस बढ़ाई जा सकती है । उन्होंने 18 फीसदी इनक्रीज़ का निशाना रखा है । मैं कहता हूं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है हम 50 फीसदी की इनक्रीज़ भी कर सकते हैं । पहले चीफ मिनिस्टर कहते थे कि हम ज़रायती पैदावार को डबल करना चाहते हैं और मैं कहता हूं कि डबल ही नहीं बल्कि ट्रेबल भी की जा सकती है । लेकिन हमारी नेशन बहुत आईडल नेशन है और काम करने से हमारे लोग किनाराकशी करते हैं । लैक्चर बाज़ी में ज्यादा विश्वास रखते हैं और काम करना नहीं चाहते । इन में काम करने की स्पिरिट पैदा करने की ज़रूरत है । किसानों को ट्यूबवैल लगाने के लिये सही तौर पर कर्ज़े दिये जाने चाहियें । हमारी सरकार ने यह शर्त लगा रखी है कि जब तक लाइन सुप्रिनटैंडैंट और एस० डी० ओ० फार्म पर दस्तखत नहीं करेंगे और सिफारिश नहीं करेंगे उस वक्त तक किसानों को ट्यूबवैल लगाने के लिये कर्ज़ा नहीं दिया जाएगा । इस में किसानों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है लाईन सुप्रिनटेंडैंट और एस० डी० ओ० उन को दस्तखत नहीं कर के देते, नतीजा यह होता है कि बेचारों को सैंकड़ों चक्कर बलाक्स में दफ्तर के लगाने पड़ते हैं । या तो उन को रिश्वत दी जाए और या फिर कोई बड़ी सिफारिश डाली जाए फिर वे लोग दस्तखत कर के देते हैं और तब जा कर कहीं किसानों को कर्ज़ा मिल पाता है । मार्च का महीना खत्म होने वाला है लेकिन अभी तक उन बेचारों को कर्ज़ा नहीं मिला । वे लोग 6 महीने से उन के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं । इस कमी को दूर किया जाना चाहिये ।

दूसरी बात मैं सरप्लस ज़मीन की बाबत करना चाहता हूं । मैं अर्ज़ करूं कि

ज़मीन कैसे सरप्लस बन जाता है । कोई बूढ़ा 70,80 साल का अगर ज़िंदा है, उस की डैथ नहीं हुई और उस की ज़मीन 80,90 एकड़ है तो वह सरप्लस बन जाती है चाहे उस के पांच लड़के हों और वह सब अलग अलग ही काश्त करते हों । उन का कसूर क्या है, उन बेचारों का कसूर यही है कि उन का बूढ़ा पिता नहीं मरा और वह ज़मीन उन के नाम पर इन्तकाल नहीं की गई । इस लिये उस को सरप्लस डीक्लेयर कर दिया गया । यह तो उन के साथ ज़ुल्म करने वाली बात है । इस सूबे के अन्दर ऐसी एक नहीं हज़ारों मिसालें है । जो बड़े-बड़े और होशियार जमींदार थे वह सरप्लस के झगड़े से बच गए लेकिन जो सारा सारा दिन खेतों में रहते थे, शहरों में नहीं आते थे उन की हालत बहुत खराब है । मैं सैकड़ों मिसालें अपने ज़िला की ही दे सकता हूं जहां लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरह से भी करना है । छोटे छोटे काश्तकारों के साथ यह एक बहुत जबर्दस्त धक्का हुआ है : घंटी :

मैं ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर साहिब से कहूंगा कि अगर आप के पास रुपया नहीं है तो और कई दूसरे जराय हो सकते है जिन से हम इस पहलू में तरक्की कर सकते है । वह यह है कि अगर कोई जमींदार अपने पैसे से ट्रैक्टर खरीदता है तो आप उसको तीन किल्ले जमीन और छोड़ दो, अगर कोई अपने पैसों से ट्यूबवैल लगाता है तो उसको दो किल्ले ज़मीन की और छूट दे दो और इसी तरह से अगर कोई अपनी जमीन में रहने के लिए मकान बना लेता है, क्योंकि इस की भी जरुरत है तो उस को आप एक किल्ला जमीन और दे दो । इस तरह से गांव की भी तरक्की होगी और मसला भी बहुत पेचीदा नहीं बन पाएगा । इस तरह से आप एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दो (घंटी)

जहां तक सीड का ताल्लुक है मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे करनाल ज़िला में पोटैटो की क्राप होती है । पिछले साल फसल कुछ खराब हो गई थी । इस साल भी फसल खराब हो गई । लेकिन वहां पर भी काफी शोर पड़ा, लोगों ने काफी तरीकों से गवर्नमैंट के कानों तक यह बात पहुंचाई कि एक लखन नाम का आदमी है उसने 115 मन आलू का बीज वहां से खरीद कर कनक या दूसरी जगहों पर भेजा । वह बीज खराब था, डिजीज्ड था । इस सिलसिले में सैंट्रल फूड मिनिस्टर साहिब को लिखकर भेजा गया । मैं अपने डी. सी और ऐस. पी के नोटिस में भी लाया । डायरैक्टर साहिब के नोटिस में भी लाया गया कि यह सारे का सारा बीज खराब था जिसे करनाल में कोई उठाता नहीं था । इसे न मालूम कहां कहां भेजा गया । मैंने खुद लखन शाह से बात की । उसने बताया कि इस हेरा फेरी में मुझे पांच लाख रुपया मुनाफा हुआ है । मैं आप की मार्फत सरकार से यह दरखास्त करता हूं कि इस सारी चीज़ को इसी तरह से चैक किया जाए और उस सीड़ को लैबारेटरियों में भेजा जाए ताकि उसकी सही हालत का पता लग सके । उसने करनाल के उस सीड पर 'पटना सीड' के लेबल लगाकर बंगाल, बिहार वगैरा सूबों में भेजा है ।

[श्री मुल्तान सिंह]
(घंटी) वहां की फार्मज़ ऐसोसीएशन ने भी इस सम्बन्ध में रैज़ोल्यूशन पास किए, प्रापेगंडा भी किया लेकिन उन को कामयाबी नहीं हुई (घंटी) मैं चाहता हूं कि कोआप्रेटिव्ज़ हों लेकिन इस सिलसिले में कुरप्शन को चैक किया जाना चाहिए (घंटी)

बस मैं दो मिनटों में खत्म ही करने वाला हूं हमारे सूबा में जो शूगर मिल्ज़ हैं उनका ऐरिया मुकर्रर किया हुआ है । वहां के किसानों को लाज़मी तौर पर अपना गन्ना उसी शूगर मिल्ज़ में देना होता है । हमारे एलाके में जो शूगर मिल्ज़ का असिस्टैंट इंजनियर है उसने बेनामी तरीके से ठेका ले रखा है । वहां मशीन पर लोगों के ट्रक आठ आठ घंटे खड़े रहते हैं लेकिन उन का नम्बर नहीं आता । लोग शोर मचाते हैं, कोई सुनता नहीं । डी. सी. साहिब भी मेम्बर हैं लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । वहां पर जो कंडा, वे ब्रिज लगा हुआ है, कहा जाता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च $2\frac{1}{2}$ महीनों में से सिर्फ एक महीना चला, $1\frac{1}{2}$ महीना बन्द रहा । (घंटी) जिन जमींदारों के पास तीन तीन चार चार किल्ले ज़मीन है और उन्होंने वहां गन्ना बीज रखा है वह बहुत मुश्किल में हैं । ऐसी हालत में उनको सिर्फ 25 फीसदी की इजाज़त है बाकी उन्हें वहीं लाना पड़ता है । मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि उन्हें क्रशिंग की इजाज़त दी जानी चाहिए । वह भूखें मर रहे हैं । इन शब्दों के साथ आप का शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी सीट पर बैठता हूं ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਲੌਟ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱਦ-ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਕੇ ਨਾਰੇ ਅਤੇ ਜਗਲਰੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਟਾਰਗੈਟਸ ਸਨ। ਗ਼ਲਤ ਟਾਰਗੈਟਸ ਬਣਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਬਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਲੈਨ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਮਗ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੁਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਹੱਮਲਮਿਜ਼ਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਫਾਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦਿਤੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ।

(*At this stage Comrade Ram Piara was talking with the Home Minister.*)

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਦਸ ਮਿਨਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨਾਂ ਉਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਵੀਟ ਥਰੈਸ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੇਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । (Comrade Ram Piara appears to be talking about some important matter with the Home Minister.)

(*At this stage Comrade Ram Piara went to his own seat.*)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ: ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਹਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਇਤਨੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਇਕਾਨੋਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਣ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5.22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 3.76 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਥਰਡ ਪਲੈਨ ਵਿਚ 6.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3.87 ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 2.98 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਖਰਚ ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਟਰਾਂਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਉਂ ਇਕਨੌਮੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉ। ਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲ ਤੇ ਪਰਾਇਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਰਿਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵਧਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੇਡ ਵਧਾਉ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ]

ਔਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਹੋਰ ਦਿਓ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਣ । ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਨ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਨ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਰੇਟ ਉਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੱਲਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੀ ਜਿਸਨ ਦੀ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਨ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਖਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚੋਂ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਮਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਣਕ ਥੁੜ ਕੇ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਦਿਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦਿਉ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਖੜਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਤਨਾ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਏਰੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੇਰ ਕਾਸ਼ਤ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਇਨਟੈਨਸਿਵ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਟੈਨਸਿਵ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਕਾਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਅਨਇਕਨਾਮੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖੋਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸਿਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੀਫਲੈਟਸ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲਿਟਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵਲ ਤਾਂ ਲੀਫਲੈਟਸ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲਿਟਸ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜੇ ਛਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਟੈਨਸਿਵ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ

ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੁਗਨੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕੁਛ ਬਾਟਲ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਟਲ ਟੈਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਲੋਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਆਈਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਕ ਦਿਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਪਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ ਮਰਚਾਂ ਤੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਔਰ ਗਨੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 80 ਜਾਂ 90 ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੂਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁਕਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਦ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਰਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੇਵੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਸ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੌਰਨ ਸਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਾਂ ਦੇਣ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਸੂਦ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਫਸਲਾਂ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਕਰਾਪਸ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਨਜ਼ੀਉਮਰ ਏਰੀਏਟਿਡ ਪਾਲੇਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀਟ ਇਸ ਲਈ ਘਟ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਨਜ਼ੀਉਮਰ ਦੇ ਹਿਤ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਵੀਟ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਪਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 4.4 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ]

ਗਰੇਨਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2.66 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮਰ-ਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਪਸ ਅਤੇ ਓਆਇਲ ਸੀਡਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪਰਾਫਿਟ ਪਾ ਕੇ ਰੇਟ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰੇ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਜ਼ੀਉਮਰ ਲਈ ਭਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਗਰੀਬ ਕਨਜ਼ੀਉਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਣਾ ।

ਇੰਨਟੈਨਸਿਵ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਔਰ ਪਾਵਰ ਟਿਲਰਜ਼ ਇਥੇ ਲੋਕਲੀ ਤੀਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ 20 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਨ-ਇਕੋਨਾਮੀਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ ਇਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਪਾਵਰ ਟਿੱਲਰ ਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਫਿਰ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਟੀਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖੁਲੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਰੂਰਲ ਈਲੈਕਟਰੀ-ਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਈਲੈਕਟਰੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਅਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰਪਜ਼ਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਊਬਵੈਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਗ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਤੇ 7 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 11 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਦੇ ਹਨ ।

ਫਿਰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਸਤੇ ਭਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਫੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਦਾ ਭਾ $15\frac{1}{2}$ ਰੁਪਏ ਫੀ ਬੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਨੰਗਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਥੇ 2.70 ਲਖ ਟਨ ਖਾਦ ਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 3.20 ਲਖ ਟਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸਭਾਵਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਰ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤਦ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕੇਗੀ ।

ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਰਾਪ ਸਪਰੇਇੰਗ ਦਾ ਇਨਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸ਼ਲ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟਨ ਦੀ ਫਸ਼ਲ ਤੇ ਸਪਰੇਇੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਂਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਘਟ ਨੇ ਔਰ ਇਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਕਪਾਹ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੋਡੀਉਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖੱਪਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਹੋਰ ਲਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਐਸੇ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਰਖਦੇ ਹੋਣ । ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਤਕ ਅਫਸਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਵ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇਗੀ ।

ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਸਕਣ । ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਡ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਇਕ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਸੋਆਇਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਣ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ ।

ਥਰੈਸ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਤੇ ਥਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਧ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰੈਸ਼ਰ ਤੇ 2 ਜਾਂ 2½ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰੁਪਏ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਉਥੇ ਉਹ ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਵੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦੀ ਫੀਲਡ ਪਰ ਏਕੜ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿੰਗਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਣ ਵਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਸਲਨ—

1. ਐਨੀਮਲ ਹਜ਼ਬੈਂਡਰੀ (ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ) ।
2. ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿਗ (ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਨ) ।
3. ਪਿਗਰੀਜ਼ (ਸੂਰ ਪਾਲਨ) ।
4. ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ (ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ)

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ]
ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ, ਵੇਹਲੇ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ।

ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 13.8 ਪਰਸੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਰੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਘਟਾ ਲਈ ਹੈ । ਜੇ ਇਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਹਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਕਸ ਹਨ । ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਸ ਨੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਚੰਗੇ ਹਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਔਰ ਪਾਵਰ ਟਿੱਲਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਨਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਰਖਣ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਅਛੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗੇ ਸੀਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਪਰੈਕਟਿਸ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 95 ਫੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਚੁਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸੀਡ ਲਈ ਆਈ ਵੀਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ । ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਆਬੀਆਨਾ ਮੀਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਫ਼ਾਰਮਰ ਵਰਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਬੀਆਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਆਬੀਆਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਾਈਨਰਜ਼ ਤੇ ਤਜਰਬਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਥੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬੜਾ ਸਖਤ ਨਾਕਸ ਹੈ । ਮਾਰਕਿਟਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਮ ਸਟਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਥੇ ਦੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਬੰਬਈ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਭਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਆਦਿ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀ-ਕਲਚਰਲ ਪਰਪਜ਼ਿਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਸਤਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਐਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਥੇ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਵਾਹੀ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ (ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਨਸੈਟਿਸਫ਼ਾਈਡ ਹਨ । ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਬਲਾਕ ਹੈਡਕੁਵਾਟਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਨਾ ਵਕਤ ਸਿਰ ਐਡਵਾਈਸ, ਨਾ ਬੀਜ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ । ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ । ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਜੋ ਇਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ । ਇਸ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉ ਤਾਕਿ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪਾਸ, ਜੋ 5-10 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਾਦ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਣ । ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਚੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ । ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਮ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਹੈਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੁਰਤਲਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਧੋੜੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਵੀ ਲਭ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਲਭਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ

[ਸਰਦਾਰ ਮਖਣ ਸਿੰਘ]

ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ । ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ, ਖਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਿਚ ਡੋਬਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ? ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੈਲਫ਼ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਫਿਰ ਕਣਕ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਾਸੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ । ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਆਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਹੀ ਪੁਟੇ ਹਨ । ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਮ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਚਿੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੀਜ ਚੁਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਉਗੱਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਚਿੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗਲਾਂ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਮਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਤੀਸਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਖਾਦ ਮਿਲੇ ।

ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਪਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪਾਵੇ ਤਕਾਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਗਰਾਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗਰ ਵੇਚੇ, ਢੱਗਾ ਵੇਚੇ, ਗਾਂ ਮੱਝ ਵੇਚੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਲੋਨਜ਼ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 20-25 ਰੁਪਏ ਖਾਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁਟਦੇ ਹੋ । ਇਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ

ਫਸਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਲ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੁਤੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਾਇਬ ਤਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਜੁਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ, ਮਝਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਦੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਬਾਦ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਗਰ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀ। ਘਟੋ ਘਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਬੇਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10-10 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕਠਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਏ. ਬੀ. ਸੀ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਕਮਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫੇਂਰਸ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਹੀ ਐਗ਼ਰੀਕਲਚਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਗਰਜ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰਕੀ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਹਿਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ ਤੇ ਜੋ ਸੂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਇਨਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੂਦ ਹੈ ਉਸ ਹਦ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰ ਦੇਣ।

[ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ]

ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਖਾਦ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਗੁਥੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ? ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮਾਲਕ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜ਼ਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ।

ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀਹ ਪਚੀ ਮੀਲ ਦਾ ਬੇਟ ਏਰੀਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਬੰਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਲਬ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਲਫ ਸ਼ਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਵਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੋਈਏ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚਕਰ ਕਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਾਂਟ ਸਹੀ ਮਹਿਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ।

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਨਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਵ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ———

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਬਰੀਫਲੀ ਕਹਿ ਦਿਉ ਫਿਰ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕੇ ਕਿ ਇਮਪਾਰਟੈਂਟ ਪੌਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । (I would request

the hon, Member to state his points briefly. Otherwise he would complain that some important points have been left.)

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। (The hon. Member will not be given more than 10 minutes).

Captain Rattan Singh : Then I resume my seat, Sir.

चौधरी नेत राम (हिसार, सदर) : स्पीकर साहिब, खेती बाड़ी के मसले पर आप के द्वारा मैं अपनी सोशलिस्ट पार्टी के सुझाव हाउस के सामने रखना चाहता हूं। सन 1948 में खेती बाड़ी से सरकार को 2 करोड़ की आमदन थी और इस वक्त 18 करोड़ की आमदन है। दूसरी तरफ इन्कम टैक्स के द्वारा बहुत ही कम आमदनी है। खेती बाड़ी से सरकार को इन्कम टैक्स से 9 गुना ज्यादा आमदन होती है लेकिन सरकार खेती बाड़ी की तरफ इसी हिसाब से खर्च नहीं कर रही है। यह शहरों की तरफ ध्यान देती है और दिहात की बिलकुल परवाह नहीं की जाती। देहात वालों से आमदन सरकार को कहीं ज्यादा होती है। और जो रुपया देहात वाले देते हैं और सरकारी खज़ाने में जाता है वह शहरी लोगों पर खर्च किया जाता है। इस लिए मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दे।

इस के इलावा एक और बात है कि शहरों के अन्दर जिसकी 3,600 रूपया साल की आमदन हो सारा खर्च काट कर उस पर इन्कम टैक्स लगता है तो क्या वजह है कि एक दिहाती पर, एक किसान पर जिस के पास केवल एक ऐक्ड़ जमीन है उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है ? (प्रशंसा) जब कि सरकार के अपने आंकड़ों के हिसाब से 1 ऐक्ड़ में दो मन से ज्यादा अनाज नहीं निकल सकता और फिर यह भी तब अनाज पैदा होता है जब कि किसान को सर्दी, आन्धी, महामारी, चिड़ी, ओले, कीड़े और इस तरह की अन्य मुसीबतों को सहारना पड़ता है और कई और ढंग से फसलें तबाह हो जाती हैं। और खेती का काम आसान नहीं मुशकिल का काम होता है और इतना कुछ करने के बाद वह छ: ऐक्ड़ ज़मीन पर 12 मन अनाज पैदा कर सकता है और उस से टैक्स वसूल कर लिया जाता है। क्या ऐसी कहीं मिसाल है, क्या यही सरकार का शोशलिज्म और शोशलिस्ट वाद है जिस का ढन्ढोरा यह आए दिन पीटते हैं ? (प्रशंसा) यह यहां पर दावे करते हैं कि हम समाज में बराबरी चाहते हैं और हम समाजवाद चाहते हैं। अगर इन के इरादे नेक हैं तो क्यों नहीं यह 6 ऐक्ड़ जमीन वालों को हर प्रकार के टैक्स से मुब्बर्रा कर देते ?

[चौधरी नेत राम]

लेकिन असल बात यह है कि यह सरकार सरमायादाराना निज़ाम को कायम रखना चाहती है । यह सरकार करोड़पतियों की है । आप देख सकते हैं कि इस सरकार को और किस की सरकार कहा जा सकता है आप सोचिए तो, स्पीकर साहिब, कि खेती करने वालों से हर तरह का टैक्स वसूल किया जाता है और इस से 18 करोड़ की आमदन सरकार को इन के अपने आंकड़ों के मुताबिक बहुत कम होती है और दूसरी तरफ इंकम टैक्स से आमदन होती है । खेती वालों से 9 गुना ज्यादा रुपया वसूल किया जाता है । शहरी हल्कों में टैक्स कम है इस लिये आज करोड़पतियों और लाखपतियों का राज है । यह कहां से आते हैं? दूसरे मुल्कों से हम रुपया मंगवा कर खर्च करते हैं और इन करोड़पतियों को यह सरकार पालती है । आज जो बजट हमारे सामने पेश है इस में 259 क़रोड़ का खर्च दिखाया गया है और इस में से 200 करोड़ रुपये का भार तो जनता पर यह डालेंगे । और हमारी प्रांत की आबादी 2 करोड़ है यानी हर व्यक्ति से 100 रुपया से ज्यादा वसूल किया जाएगा । और इसी तरह 63 करोड़ का कर्ज़ लिया जाएगा, इस तरह से हर व्यक्ति से 106 या 107 रुपया की वसूली की जाएगी । और यह रुपया सारा शहरों से करोड़पतियों की तजोरियों में चला जाएगा । इस तरह की बेइनसाफी को हम और पंजाब की जनता कब तक बरदाश्त करेगी ?

आज देहाती और शहरी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है आप इस का स्पीकर साहिब, अंदाजा लगाएं । चीनी गन्ने से पैदा होती है और किसान जो सारा दिन और रात एक करके गन्ने की खेती को तैयार करता है उस का बच्चा आज चीनी के लिए तरस रह है और शहर में रहने वाला पकोड़ीमल जिस ने कभी खेत नहीं देखा और न ही देहात को देखा है चीनी आराम से ले रहा है । और दूसरी तरफ किसान को चीनी नहीं दी जा रही जिस ने एक तरफ तो खेती को इतनी मुसीबतों के साथ तैयार किया और दूसरी तरफ अपने बेटों को नेफा और लद्दाख में इसी पकौड़ी मल की हिफाज़त के लिए गोली खाने के लिए भेजा । (प्रशंसा) क्या यही सलक है जो आप आज देहात वालों के साथ कर रहे हैं ?

[Deputy Speaker in the Chair]

इसी तरह आप सीमेंट का हाल देख लें कि अगर किसी देहात वाले को सीमेंट की जरूरत है अपने कच्चे मकान की मुरम्मत करने के लिए या जिसके मकान का परनाला टूट गया हो उस की मुरम्त कराने के लिये तो ज़रा से सीमेंट के लिए बी० डी० ओ० के दफतर में धक्के खाने पड़ते हैं और यह कांग्रेसी जो यह कहते हैं कि हमारा राज है, मिल मिला कर हज़ारों थैले ब्लेक में बेचते हैं और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि यह करोड़पतियों की क्लास से संबंध रखने वाले हैं । (प्रशंसा) आज मुझे यह बात बड़े ज़ोर से कहनी पड़ती है कि आज सब चीज शहरों की तरफ ही खेंची जाती है, देहातियों को जिन की 80 फी सदी आबादी है, कोई पूछता तक नहीं है । सारा सरमाया उन लोगों के हाथों में जमा होता जा

रहा है जो बड़ी मुश्किल से 2-3% हैं । यह चंद एक बड़े बड़े सरमायेदार ही हैं । आप लोगों को न पूरी तरह से खाद मिलता है न मकान बनाने के लिये सीमेंट ही मिलता है । 2-3 साल तक ट्यूब वैल लगे को हो जाते हैं मगर कुनैक्शन की मनजूरी नहीं मिलती । खेती करने वाले को जिस ने जनता के लिये अनाज पैदा करके देना है कोई सुविधा नहीं दी जाती । आज जाकर देहातों में जमीदारों की हालत तो देखो कि उन का हाल क्या है । गरीब आदमी जो आपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिये सरदार लछमन सिंह गिल जैसे के पास काम करता है, सारा दिन मज़दूरी करने के बाद उस गरीब को आठ आने दिये जाते हैं, मज़दूरी के । आप अंदाज़ा लगायें कि यह वह शख्स है जिस के मां बाप इसी ज़मीन पर रोटी पैदा करते चले आये हैं मगर आज इस को रोटी के लिये गैरों से आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं । आप ही अंदाज़ा लगायें कि यह कहां का इनसाफ होगा । अगर 3-4 रोटियां खाने वाले आदमी को ½ रोटी दे कर कहा जाये कि यह तेरे लिये काफी है । आज गरीब को तो यह कहा जाता है कि तेरे को खाने की तमीज़ नहीं है, मगर वह लोग जो दिन रात सिवाये पेट भरने के और कुछ करते ही नहीं उन्हें अकलमंद और तमीज़वाले समझा जाता है । मैं तो कहूंगा कि देहातियों को उतने ही आराम हों जितने अमीरों को दिये जाते हैं । आज एक तरफ तो उन लोगों का पल्ला भारी है जो कोठियों में ऐश करते हैं और कारों पर चढ़े फिरते हैं, गुलछरे उड़ाते हैं मगर इन के गोडाऊन्ज़ के रखवाले चौकीदार को महज़ 20 रु० महीना तनखाह मिलती है, जिस की सालाना तरक्की 5 रु० से ज्यादा नहीं होती । सारी उमर अगर वह वहीं काम करे तो 35 रु० महीने से ज्यादा कभी ले ही नहीं सकता । 7/8/रु० महीना उसे महंगाई अलाऊंस दिया जाता है । भला एक गरीब आदमी जिस के 5, 4 बच्चे हों इतनी आमदन में कैसे गुज़ारा कर सकता है । इस के लिये मैं सरकार को कहूंगा कि ऐसे छोटे मुलाज़मों के लिये एक परिवार के गुज़ारे मुताबिक रकम फिक्स करें और उस हिसाब से माहवार रकम उन लोगों को दें ।

उपाध्यक्ष : आप खेती बाड़ी के मुताल्लिक भी कोई सुझाव दें । The hon. may suggest something about agriculture)

चौधरी नेत राम : जी हां, यह आपने बहुत अच्छी बात इस मौका पर कही । खेती बाड़ी के मुतालिक मेरी अर्ज़ है कि आज 11 लाख ऐकड़ ज़मीन सरप्लस पड़ी है जो सुधार करके खेती योग्य बनाने वाली है । मेरी अर्ज़ यह है कि अगर यह ज़मीन बजाये इसके कि ठेकेदारों की मारफत नौतोड़ करवाई जाये

[चौधरी नेत राम]

इस के लिये यह तरीका इख्तयार होना चाहिये कि यह जमीन महज़ उन लोगों को ही दी जाये जो पहले ही काशत का काम करते हैं। आज खेती बाड़ी के माहर भी इस बात को मानते हैं कि यह जमीन काबले काशत बनाई जा सकती है, फिर क्या वजह है कि यह जमीन अभी तक वैसे ही रखी पड़ी है। एक बात मैं और कहनी चाहता हूँ वह यह है कि मुजारों से जबरी बेगार ली जाती है इस से उन लोगों के काम में बड़ा भारी हर्ज होता है। इस तरह वह अपनी खेती की भी संभाल नहीं कर सकते। एक यह भी कानून बनाया जाये जो खुद ज़मीन काशत करते हैं वही ज़मीन के मालक होने चाहियें, जो भी बड़े बड़े ज़मीनों के मालक हैं इनकी यह ज़मीन उन को मिलनी चाहिये जो खुद खेती करते हैं, खुद काम करते हैं। आज यह शहरों में रहने वाले बड़े २ तकड़ी मार उन गरीबों को लूटे जा रहे हैं। जब यह जिनस पैदा करके बेचने की गर्ज़ से मंडी में लाता है तो इस की जिनस की भी मनमानी कीमत लगाते हैं। इस तरह की खेती में जो तकलीफें हैं यह दूर होनी चाहियें। (घंटी) बस एक बात कहकर मैं बैठ जाऊंगा। वह यह कि मैंने खेती बाड़ी के माहिरों से बात चीत की है। मौसम के लिहाज़ से पंजाब में दो फसलें ही आम तौर पर की जाती हैं। एक हाड़ी और दूसरी सावनी। अगर सरकार लोगों को पूरी सहूलियतें दे और काफी मिकदार में खाद दे तो इस से और ज्यादा फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। जहां नहर का पानी नहीं जाता वहां सरकार को ट्यूबवैल्ज़ लगा कर पानी देना चाहिये नहीं तो नहर के पानी की किसी तरह से कोई कमी नहीं होनी चाहिये। इस से हम ज्यादा फसल पैदा करने में कामयाब होंगे और दो फसलों के इलावा और भी छोटी छोटी फसलें हम पैदा कर सकेंगे। इस के साथ ही मैं यह बात भी दावे से कह सकता हूँ कि जहाँ आज दो मन फी एकड़ की औसत पैदावार है अगर हम इसी तरह से पानी और खाद वगैरा की बहुतात पर ज़ोर देते रहे तो वह 5, 6 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार देने लग जायेंगे। मगर आज पूरी फसलें न होने की वजह से, बरसात की वजह से सेम आ जाने से किसान अपना पेट भर भी नहीं सकते और न ही यह सरकार उनकी कोई इमदाद करती है। इन लोगों में गरीबी दिन बदिन बढ़ती जा रही है। मुझे इस सिलसले में एक चुनाव की बात याद आई है कि पिछले दिनों में मियूनिसिपल कमेटी के जो चुनाव हुए हैं उस में इन गरीबों ने अपना पेट भरने के लिए पैसा ले कर वोट दिये। 10 से 15 रु० तक एक एक कुनबे ने अपनी 4, 5 वोटों को बेचा और यह कहते हुए सुने गये कि हम ने इन पार्टियों से क्या लेना है, चाहे किधर वोट चली जाये हमने तो अपना पेट भरना है। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपनी वोटें खुले आम बेचीं और कुरप्शन का बीज बोया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज पैसे के ज़ोर से इलैक्शनों में सरमायेदार लोग धड़ा धड़ दाखिल हो रहे हैं। आप ही बतायें कि यह लोगों की, जनता की, क्या रहनुमाई करेंगे जो खुद कुरप्ट हैं। आज मुलक के हालात

दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं; मुल्क में गरीबी बढ़ती जा रही है और गरीब लोग घबराहट में हैं । अगर इन की हौसला अफजाई सरकार ने न की और अगर देश को किसी तरह का भी खतरा हुआ तो इस की जिम्मेवार यह कांग्रेस सरकार होगी । यही लोग हैं जिन्होंने आज इस मुल्क को इस हालत तक पहुँचाया है । इन इलफाज़ के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ ।

ਗ੍ਰਿਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : (ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਅਪੜਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਸੋਂ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਆਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਤਆਲੁਕ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਏਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ । ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 80%ਉਸ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇ-ਟੂ-ਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਆਲੁਕ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 20% ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 80% ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਆਲੁਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 25 ਲੱਖ । ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਸਕੇ । ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਡਬਲ ਕਰਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਏਰੀਆ ਇਕ ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਹੈ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ

ਗ੍ਰਿਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ

ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਰੂਰਲ ਇਲਕਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲੈਨ ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਦੂਸਰੀ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਸਮਾਲ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਟੈਨੇਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਲਾਜ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ।

ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।

30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹਲ ਵਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਬਿਗ ਐਬਸੈਂਟੀ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹਮਿਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਥੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1961 ਵਿਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ 78·50 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਆਇਲਸੀਡ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ, ਸ਼ੁਗਰ 8 ਤੋਂ 13 ਤੇ ਕਾਟਨ 9 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਬੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟੀਚੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਗਰ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਟਯੂਬ ਵੈਲਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜੇ ਗਲਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਸਕੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਕੋੜ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਅੱਵਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਵਾਟਰ ਲੋਗਿੰਗ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। 21 ਲੱਖ ਐਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਵਾਟਰ ਲਗਿੰਗ ਹੈ, 6 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ 15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਲਾਗਡ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। 2·9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਬੂਰ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਥੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪਸ ਵਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ ਇੰਪਰੂਵਡ ਸੀਡ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3·20 ਲੱਖ ਟਨ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਆਵੇਗਾ ਮਗਰ ਉਹ 2·85 ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹਾਈਬਰਿਡ ਮੇਜ਼ ਵਿਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦਾ ਸ਼ੌਰਟਫਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੌਰਟਫਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਣਕ ਦੇ ਥਲੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤਕ ਨਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਕਰਾਪਿੰਗ

ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਥਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2·82 ਲੱਖ ਟਨ ਮਿਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਰਗੈਟਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ 24 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਇਆ। 1960-61 ਦੇ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਦੇ ਥਲੇ 59 ਲੱਖ ਏਕੜ ਏਰੀਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 1963-64 ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 54 ਲੱਖ ਏਕੜ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਫੇਰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਥਲੇ ਤੋਂ ਲਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ 18·5 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਔਰ ਜੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਧ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਤੇ ਅਧ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਿਉਂ ਘਟੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਦਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲਡ ਪਾਲੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਰਾਈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸ਼ਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਸਨ ਔਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਰੀਮਿਊਨਰੇਟਿਵ ਪਰਾਈਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਡੀ ਦਾ 35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 42 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਣਕ ਦਾ 49 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 53 ਰੁਪਏ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾਨੇ ਦਸੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਰਜਨਲ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਣ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇੰਪਰੈਸ ਅਪਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਦਾਰ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਧਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਜੇ ਧੱਕਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ

[ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕਟ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਆਹਿਸਤਾ ਅਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਆਵਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਇਹਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਹਾਈ ਪਰਾਈਸ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਖ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚਲਣਾ ਹੈ । ਪਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਘਟ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ਼ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਣਾ ਹੈ ।

चौधरी नेत राम : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम कीमतों का ख्याल रख रहे हैं। क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि खेतीं से पैदा होने वाली चीजों का और कारखाने में पैदा होने वाली चीजों की कीमतों का फर्क मिटा कर वह ज़मीदारों की हौसला अफजाई करेंगे ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, यह बात मैं ने पहले भी कही थी। मिनिस्टर साहिब ने उसे शायद समझा नहीं था।

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਲ ਰੀਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੈ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਈਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ । ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਾਸਟ ਆਫ਼ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1-5, 5-10 ਅਤੇ 10-15 ਏਕੜ ਦੇ ਸਲੈਬ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਸੋ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚ

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਰੋਡਕਸਨ ਕਿਤਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿਤੀ ਹੈ ।

ਇਕ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿਸਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਤੌਰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਠ ਆਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ । ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰਜ਼ 500 ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । 500 ਸਪਰੇਅਰਜ਼ ਜੋ ਬੰਬਈ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਅਤੇ ਇਮਪਰੂਵਡ ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਥਰੈਸ਼ਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹਦ 150 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੱਦ 400 ਰੁਪਏ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਵਰ ਥਰੈਸ਼ਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਇੰਨਟੈਨਸਿਵ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ । 75 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਗੜ੍ਹ ਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਫਿਰ ਇਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ 10/12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਕਿ ਫਾਲਤੂ ਅਨਾਜ ਉਥੇ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਘਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਚਲ ਸਕੇ । ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਇਸੇ

(1) (2) (3)

[ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਪੈਨਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਲੀ ਗਲ ਜੇ ਪੁਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਡ ਆਉਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿਉ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਰਖ ਲਓ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਈਏ ਜੋ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬੈਠੇ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਕੁਆਪਰੇਟਵ ਡਿਪੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 4,500 ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਸੀਡਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਸਕਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ । ਰਿਸਰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੈਜ਼ੇਂਟ ਵਿਰਾਈਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹਾਇਰ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੁਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰਾਈਟੀਜ਼ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਸੀ 306 ਵਿਰਾਈਟੀ ਕਢੀ ਹੈ ਜੋ ਢਹੇਗੀ ਨਹੀਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰਾਇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਘਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਈਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 18 ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਰਾਇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਝਾੜ 70 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ । ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖੁਰਾਕ ਨੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫੂਡ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਜ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਥੋੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਕ ਇਕ ਖੇਤ ਜਿਸ ਦਾ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੈਲਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ

ਇਤਨੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਜਿਸ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਪ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। 50 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਏਰੀਆ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨਇਰੀਗੇਟਿਡ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਪ ਪਰਾਇਰਟੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਲੈਕਟਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਲਾਟੂ ਜਗਾਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਨਪਰੋਡਕਟਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਚੀਅਰਜ਼) ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇਲ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੀਜੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤਕ ਅਸੀਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਇਲ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਕੁਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ 12 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਢ ਲਖ ਮਣ ਅਸੀਂ 1963-64 ਵਿਚ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲਖ ਮਣ 1964-65 ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1965-66 ਲਈ 6 ਲਖ ਮਣ ਸੀਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰੋਵਿਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 55 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਲਖ ਏਕੜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਡਿਵੱਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਤਵੱਜੁਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆਂ, ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ, (ਵਿਘਨ)

ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ: ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ।

ਗ੍ਰਹਿ **ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ**: ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਫੀਸ਼ਿਅਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਕਿ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲੇ। ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੀਡਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੀਜ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1969-70 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ

[ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੁਲ ਲੋੜ ਦੇ $\frac{1}{5}$ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੀਜ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਐਸੀ ਜਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਰੋਡਯੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਅਸੀਂ ਨੀਉਕਲੀਅਰ ਬੀਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ । ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਰ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਨੋ ਤਰਫ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਇਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਾਉ । ਅਸੀਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । 1965-66 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 4 ਲਖ ਟਨ ਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਾਨੂੰ ਫਰਟੇਲਾਈਜਰ ਫੈਕਟਰੀ, ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਰਟੇਲਾਈਜਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਵਿਗਰ ਵਰਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਨਹੀਂ ਜੀ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ 80–90% ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ 40,000 ਟਨ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ 4 ਲਖ ਟਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕੇ । ਸਿੰਦਰੀ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਖਾਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦ ਦੇਣਾਂ ਹੈ । ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ

ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਖਾਦ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ । ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਈ ਵੇਰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਪਾਕੇ ਕਦੇ 10 ਤੇ ਕਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਖਾਦ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ (ਤਾੜੀਆਂ) ਮੈਂ ਗਰੀਨ ਮੈਨੋਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਚਾਂ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ । 23 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਇਸ ਖਾਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਕੜ ਦੇ ਹਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਾਵਰ ਟਿਲੱਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਂ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੈਂਟਿਵ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ 11 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ । 3 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਪਾਵਰ ਥਰੈਸ਼ਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ । 100 ਪਾਵਰ ਟਿਲਰਜ਼ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਨਸ਼ਨਜ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਪਾਣ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-4 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਵੇਲੇ 40, 50 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵੇਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 40-50 ਮੀਲ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਖੁੰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਰਮੰਗਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਈ. ਐਮ. 1 ਹੈ । ਇਹ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ 3 ਟਰੇਕਸ ਹਨ । ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਹਰ 10 ਮੀਲ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੈਫੇਟੇਰੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਖੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ।

ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਰਕ-ਸ਼ਾਪਸ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿਚ 10, 12, ਜਾਂ 14 ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਸਰਨਡ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ

[ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ]

ਅਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਪਾਵਰਸਪਰੇਜ਼, ਟਰੈਕਟਰਜ਼, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟਿੱਲਰਜ ਵਗੈਰਾ ਇਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨਵੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 9% ਜਾਂ 10% ਪੌਦੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਇਆ ਬੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਇਆ ਬੀਨ ਵਿਚ 44% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਸੋਇਆ ਬੀਨ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਕਿ ਸੋਇਆ ਬੀਨ ਤੋਂ ਨ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਡਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ **constituents** ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਫੂਡ ਵੈਲਯੂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ,ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਜ਼ **uneconomic** ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਸੀਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਇਕੋਨੋਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਛਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਚ ਸੇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ 8 ਆਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸੈਪਲਿੰਗ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਬਾਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਕ ਪੌਦਾ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾ ਛਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਰਸ਼ਲ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਥੇ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾਂ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਜੀਟੇਬਲਜ਼ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹਿਸਾਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਨੀਪਤ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਹੋਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਟੀਵੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਨ ਪੁਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਟੈਨਸਿਵ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨ ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨਟੈਨਸਿਵ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ 3 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ 270 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 113 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਇਜਿਪਟ ਵਿਚ 94 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਦ ਪਰ ਏਕੜ ਇਨਟੈਨਸਿਵ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਇਨਟੈਨਸਿਵ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਇਥੇ ਇਨਟੈਨਸਿਵ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਯਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ : ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ । ਕ੍ਰਾਪ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਸ ਵਿਚ ਅਸਾਂ 23% ਦਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਜਰੇ ਵਿਚ ਪਲੱਸ 13% ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਰ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵੀਟ ਵਿਚ 9% increase ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 30-31 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਨੀ 9% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ । ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ 10.99 ਤੋਂ 13.50 ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 23% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਮੇਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂ । ਉਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 11-4-63 ਨੂੰ 24 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਉਸ ਵਿਚ ਅਸਾਂ 2, 3 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 4,48 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੀਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ । ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ । ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈਏਬਲ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ

[ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਦੇਰ ਲਗੇਗੀ । ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ interest charges during the construction period to be wholly warned and thereafter simple interest at 3% to be levied. ਤੀਸਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ unproductive ਪਾਰਟ ਦਾ 50% ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਵੇ । ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਅਨਪਰੋਡਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਇੰਟਰੈਸਟ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝਾ ਉਹੋ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ । ਪਾਰ-ਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਤਾਸਰਾਤ ਹੋਏ ਸਨ । ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸਨ । ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ।

ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰੀਂ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਅਜ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਅਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ 1965-66 ਵਿਚ trial basis ਵਾਸਤੇ ਪਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੋਰਟ Hilly areas ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਤੇ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਮੈਂ ਐਗ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ 40 ਮੀਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ । ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਅਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 4th Plan ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੇਲ ਹੈਡ ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਪਰੋਡਿਊਸ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਣ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਫਰਟੇਲਾਈਜਰਜ਼ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ 5-7 ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਛਡੋ । ਅਗੇ Processing of flour mills ਹੈ ਅਜ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਲ ਸੇਲਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੀਟੇਲਰਜ਼ ਹਨ । ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੰਟੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਜੁਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਾਈਨਜ਼ ਕਢਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਕੇ ਭੇਜਣ । ਕਾਟਨ 320 ਐਫ. ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਯੱਰ ਉਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ 50% ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ ਅਤੇ 50% ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ । 320 ਐਫ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਕਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 40% ਹੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 50% ਉਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਹਾਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਮਿਡਲਮੈਨ ਇਸ ਵਿਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ 120 ਰੁਪੈ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 120 ਕਿਥੇ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਡੇ ਲੈਵਲ ਉਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਕੈਟਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਮਝਾਂ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨਾ ਭੇਜੀਏ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਆਂਧਰਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਮਾਲ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ । ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੂਇਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ ।

ਫਾਡਰ ਔਰ ਫਰੂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਆਉਣ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਫਰੂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਗੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿਚ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੌਥੀ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਮਾਲਟੇ ਸੰਗਤਰੇ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਵੇਸਟ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ।

ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਬਰਸੀਮ, ਸੇਂਜੀ ਔਰ ਲੂਸਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਹੈ ।

[ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। (cheers)

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੈਡੀ ਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 36 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ 36 ਦੀ ਬਜਾਏ 32 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚਾਉਲ ਦਾ ਭਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਬੇਲਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਦੇਣ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਿਲ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੀੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ (ਪ੍ਰਸੰਸਾ)

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਰੀਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਾਪ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਫਰੂਟ ਦੀ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿਘ ਗਿੱਲ: ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤੀ : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ।

ਗਰੀਨ ਮੈਨਿਉਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵਜੁਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ । ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਦੇ ਰੇਟਸ ਹਨ ਉਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲਏ ਜਾਣ । ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਾਮਾਕੂਲ ਨਹੀਂ (ਹਾਸਾ) (ਵਿਘਨ) ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਕੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ । ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਫ ਹੈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟਸ ਇਕੋ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਔਰ

ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਿਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੀਫਾਈਨੈਨਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੈਂਕ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਰੀਫ਼ਾਈਨੈਨਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ । ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਵੇ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਡੀਜ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਜ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਡਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਔਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । (ਪ੍ਰਸੰਸਾ)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਔਰ ਡਰੇਨੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੁਵੀਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨਾ ਫੂਡ ਸਰਪਲਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ । ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ । ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । (ਪ੍ਰਸੰਸਾ)

31—AGRICULTURE

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100

The motion was lost.

Mr. Speaker. : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the dcmand be reduced dy Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next Cut Motion stands in the name of Chaudhry Darshan Singh.

Chaudhri Darshan Singh : Sir, I beg to ask for leave to withdrawmy Cut Motion.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the house that leave be granted to the hon. Member to withdraw his cut motion

Voices : Yes, please.

Voices : No, please.

Mr. Speaker : Since the leave is refused, I will put the Cut Motion to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 101.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceedıng Rs 6,07,79,210 be granted to the Governer to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head 31—Agricuture.

The motion was carried (Thumping).

95—CAPITAL OUTLAY ON SCHEMES OF AGRICULTURAL IMPROVEMENT AND RESEARCH

Mr. Speaker : There are no Cut Motions to this Demand.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 1,13,41,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under Head 95—Capital outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 2-00 P. M. on Wednesday, the 24th March, 1965.

(The Sabha then adjourned till 2-00 P. M. on Wednesday, the 24th March, 1965).

1446 PVS—368—16-3-65—C., P., S., Pb., Patiala.

APPENDIX

TO

Punjab Vidhan Sabha Debate Vol. I, No. 19, dated the 16th March, 1965

Reply to Part (ii) of Starred Question No. 7751, printed at page 19(42) in the Debate

ANNEXURE 'A'

List showing details of maternity leave cases in respect of Ambala District

Sr. No.	Name of the Teacher/School	Period	Amount	Reason
			Rs. P.	
1.	Shmt. Gita Devi, Govt. Primary School, Bar-sal Pur	3-8-64 to 23-10-64	267·74	Leave not yet sanctioned. The matter is under corres-pondence
2.	Shmt. Urmal Vaid, Govt. High School, Khizrabad West	6-6-64 to 3-9-64	305·05	Bill sent to the Treasury fo payment

ANNEXURE 'B'

Detailed information regarding payment of grade, promotion, Arrears to Teachers of Ambala District

Sr. No.	Name of the teacher	Period of claim	Amount	Reasons
1	2	3	4	5
			Bs P.	
1.	Shri Joginder Lal, Teacher, Govt. Middle School, Hangola	1-10-62 to 31-12-64	1,442.95	Promotion order released,—*vide* District Education Officer, Ambala's No. 801, dated 5-1-1965. Bill prepared and sent to the Treasury for payment order
2.	Shri Ramesh Chand Garg, Teacher, Govt. Middle School, Talakaur	1-10-62 to 31-12-64	1,296·15	Ditto
3.	Shri Jai Parkash, Teacher, Govt. Middle School, Sarwan	1-10-62 to 31-12-64	1,471·10	Order released,—*vide* District Education Officer's No. 4796-99, dated 5-2-65. Bill prepared and sent to the Treasury for payment.
4.	Shri Nathu Ram, Teacher, Govt. Middle School, Rattewali	1-10-62 to 31-12-64	1,433·80	Order released,—*vide* D.E.O.No. 816—19, dated 5-1-65. Bill prepared and sent to Treasury Officer for payment.
5.	Shrimati Lajwanti, Teacher, G. G. M. S. M.T., Yamunanagar	1-10-62 to 28-2-65	2,398·00	Ditto
6.	Shrimati Harbans Kaur, Teacher, G. G. M. S., Charnkaur Sahib	1-3-63 to 28-2-65	1,452·66	Order released—*vide* D.E.O. No.20017-19, dated 26-11-64. Bill is being prepared and sent to the Treasury for payment.
7.	Shrimati Daler Kaur, Teacher, G.G.M.S., Sector 27, Chandigarh	1-3-63 to 28-2-65	272·50	Order released,—*vide* D.E.O. No.797—800, dated 5-1-65. Bill is being prepared and sent to Treasury for payment.
8.	Shri Muni Lal, Teacher, Govt. Middle School, Sauta	18-12-63 to 28-2-65	677·00	Order released,—*vide* D.E.O. No. 4846—49, dated 6-2-65. Bill is being prepared and sent to the Treasury for payment.

9.	Shrimati Motia Rani, Teacher, G.M.S., Shahpur	1-3-62 to 31-10-63	1,254·20	Order released,—*vide* D.E.O. No. 4846—49, dated 6-2-65. Bill is being prepared and sent to the Treasury for payment.
10.	Shrimati Sumitra Devi, G.G.M.S., Babyal	1-3-63 to 28-2-65	480·50	Order released,—*vide* D.E.O. No. 6073-76, dated 25-2-65. Bill is being prepared and sent to the Treasury for payment.
11.	Shrimati Daya Wanti, Teacher, G.G. M. S., Shahpur	1-3-63 to 28-2-65	450·00	Order released—*vide* D.E.O. No.5074—77, dated 25-2-65. Bill is being prepared and sent to the Treasury for payment.
12.	Shrimati Sudarshan Kaur, Teacher, G.B.P.S. No. 2, Sector 23-A, Chandigarh	16-6-63 to 30-9-64	832·50	Order released by the D.E.O. in the month of October, 1964. Bill has been sent to Treasury for payment.
13.	Shrimati Santosh Gupta, Teacher, G.B.P.S. No. 2, Sector 23-A, Chandigarh	16-4-63 to 30-9-64	907·75	Ditto
14.	Shrimati Promila Khanna, Teacher, G.B.P.S. No. 2, Sector 23-A, Chandigarh	16-4-63 to 30-9-64	908·50	Ditto
15.	Shrimati Kailash Kumari, Teacher, G.B.P.S., Sector 23, Chandigarh	1-2-64 to 31-1-65	804·00	Ditto
16.	Shrimati Harwinder Anand, Teacher, G.B.P.S., Sector 23, Chandigarh	1-3-63 to 30-9-64	976·65	Promotion order released in the last week of February, 1964. Bill prepared and is under correspondence with the Treasury for payment.
17.	Shrimati Saranjit Kaur, Teacher, Govt. Basic Primary School, Rurki Purao, Chandigarh	16-4-63 to 30-9-64	970·60	Ditto

CONSTRUCTION OF A SLAUGHTER HOUSE AT PIAO MANIARI NEAR 17TH MILESTONE ON G. T. ROAD.

***7952. Chaudhri Ranbir Singh** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether the Government have received any representation dated 19th February, 1965 signed by the Sarpanches and Panches of Rai Panchayat Samiti, tehsil Sonepat, district Rohtak, against the construction of a slaughter house at Piao Maniari near the 17th milestone on the G. T. Road;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative; whether the Government propose to stop the construction of the said slaughter house keeping in view the sentiments of the people of the area who are vegetarians; if not, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes.

(b) It is not proposed to stop the construction of the factory for the following reasons :—

(1) The factory is being set up in pursuance of an agreement entered into by the party with the Government of India, Ministry of Food and Agriculture, the salient features of which are :—

(a) That the Government of India will set up a Quality Control and Research Laboratory in the premises of the firm's factory with the following objectives:—

(i) To exercise quality control on the meat and meat products manufactured at the Meat Processing Unit.

(ii) To standardise the methods of Meat production and its processing.

(iii) To carry-out research for improving the processing technique suitable to the Indian conditions and environments.

(iv) Investigate the possibilities of introducing new products for export as well as home consumption.

(v) To work on Research problems connected with quality, storage, canning, etc., of meat and processed meat products.

(vi) To assist the industry in solving their problems.

(b) That pending introduction of comprehensive Legislation governing the quality of meat and meat products and the hygienic standards that should prevail in slaughter houses, the firm shall abide by such standards as may be prescribed by the Government from time to time for specific application to the Abattor-cum-processing unit to be set up.

(c) That all reasonable facilities shall be provided by the firm for imparting training in the techniques of meat processing, etc., to persons nominated by institutions and industries sponsored by Government.

(d) That high priority shall be given by the firm for the supply of meat to the Defence Services and for the requirements of the Government.

(2) They have given an undertaking to the State Government that the whole processing and other operations will be done in covered premises so as to completely eliminate the attracting of birds or animals or near the high-way which may impair flow of traffic.

Adequate safeguards have thus been provided in the agreement made by the party with the Government of India and the undertaking given by them to the State Government.

EJECTMENT OF TENANTS IN SIRSA SUB-DIVISION

***7906 Shri Kesra Ram** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of tenants ejected in the Sirsa Sub-Division during the period from 1962 to 1964 together with the reasons for their ejectment;

(b) the number of the tenants mentioned in part (a) above against whom *ex parte* decrees were passed together with the reasons therefor;

(c) the number of tenants in the said sub-division who were ejected for their failure to pay the land revenue ?

Sardar Harinder Singh, Major : (a) Altogether 1185 tenants have been ejected; 1066 tenants have been ejected under section 9 (I) (i) of the the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, being tenants under small land owners and have been resettled on alternative land. 119 tenants have been ejected for non-payment of rent under section 9 (I) (ii) of the **Act** *ibid.*

(b) 165. They failed to attend the court in spite of service effected upon them.

(c) Nil.

BURSTING OF A BUDA TYPE ENGINE AT FARIDABAD

*7981. **Sardar Jagjit Singh Gogoani** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether a Buda type engine burst at Faridabad during drilling operation about 2 years back;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether an enquiry was held for fixing responsibility for the said loss amounting to about Rupees twelve thousand ;

(c) the details of action, if any, taken against the staff due to whose negligence the said loss took place ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No.

(b) and (c) Question does not arise.

Published under the Authority of the Punjab Vidhan Sabha and Printed by the Controller, Printing & Stationery, Punjab, at the Govt. Press, Patiala.

Punjab Vidhan Sabha Debates

24th March, 1965

Vol. I—No. 20

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 24th March, 1965

Price Rs. 12.70 Paise

(Not concld.)

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I, NO. 20,
DATED THE 24TH MARCH, 1965.

Read	*For*	*Page*	*Line*
कामरेड	कामरड	(20)9	1
scrutinised	scruitinised	(20)10	18
Panchayats	Panchavats	(20)11	Last but one
require	required	(20)29	10
mileage	milieage	(20)29	13
places of	places	(20)30	17
Mehmud Pore	Menmud Pore	(20)33	Last but one
and	ane	(20)35	14 from below
(20)39	(1)39	(20)39	Page
nursery	ursery	(20)39	12
Energy	Emergy	(20)73	4 from below
Commercial	Commerical	(20)76	11
therefor	therefore	(20)76	Last and last but one
Ranges	Ra ges	(20)84	9, 11
verified	v rified	(20)87	24
Macleodganj	Maceodganj	(20)98	11
Gobindgarh	Gohindgarh	(20)101	S. No. 12
basis	baisis	(20)103	6
year	yar	(20)103	8 from below
dispensers	dispensors	(20)104	16 from below
end	and	(20)104	11 from below
under	undes	(20)106	8 from below
Delete 'OE' before the	word 'Panchayat'	(20)109	11
section	seetion	(20)115	2
Government	Governuəɯt	(20)117	11
accompanied	accompanien	(20)118	27
able to	to able	(20)118	13 from below

Read	*For*	*Page*	*Line*
be made	be	(20)119	4
malice	malious	(20)119	5
Detenu	Detenus	(20)119	12
Satwant Singh	twant Singh	(20)121	S. No, 13
Increase	n crease	(20)134	1
any	eauy	(20)140	5
progress	progrees	(20)146	2
*11	5	(20)151	2 from below
the	he	(20)153	20
jurisdictions	jurisdications	(20)155	6
questions	ques ions	(20)159	25
and	aund	(20)164	1
Welfare	Welfeare	(20)166	1
he	the	(20)171	20
Tarsikka	Tarsikha	(20)176, 187,	1,22
showing	showihg	(20)176	9 from below
quota	qaota	(20)184	8
Manochal	Manocha	(20)189	18 from b low
Speaker	Sqeaker	(20)197	7 from below
anticipated	anticipted	(20)197	7 from below
ਗੜਿਆਂ	ਗਲਿਆਂ	(20)200	10 from below
ਚੁਕਿਆ	ਚੁਕਆ	(20)201	23
को	की	(20)205 (20)213	23 7 from below
देने से	देने	(20)205	36
general	gerneral	(20)206	2
Delete the word 'in' after the word 'election'		(20)206	26
guilty	quilty	(20)209	17
कैरों	कै ों	(20)210	5
मुकर्रर	मुकर्र	(20)212	21
तैयार	नैयार	(20)213	7 from below

*Note.—The correction has been made on the basis of the revised reply received from Government in substitution of the original reply.

Read	*For*	*Page*	*Line*
हूं	है	(20)213	5 from below
ਦੋਹਾਂ	ਦੋਹ	(20)214	4 from below
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ	ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਨ	(20)214	3 from below
चौधरी राम सरुप	चौधरी राम स्वरुप	(20)215	19
दोनों	ोनों	(20)215	20
granted	ganted	(20)216	18
ਕੰਮ	ਕਰਕੇ	(20)218	7 from below
ਜ਼ਾਇਆ	ਜ਼ਾਇਙ	(20)219	10
ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ	ਕੰਪਨੈਸੇਸ਼ਨ	(20)219	8 from below
ਲਾਗਿੰਗ	ਲੌ ਗਿਗ	(20)219	4 from below
ਸੁਆਰੀ	ਸਿਆਰੀ	(20)220	14
है	ई	(20)221,222	9, 14
पसमान्दगी	पसमार्दगी	(20)221	12 from below
हैं	ह	(20)221 (20)233	6 from below 16
की ने हुम त	के मेहमत	(20)222	9 from below
पहुंचा	पर्हुचा	(20)222	5 from below
Delete the word 'दफा' before the word 'पंजाब'		(20)223	5
को	का	(20)225	12
रिजर्व	रिज़व रिर्ज़व	(20)225 (20)225	19 23
लोग	लोगों	(20)225	Last
धुस्सी	घुस्सी	(20)226	12
गवर्नमेंट	गर्वनमेंट	(20)228	5 from below
ग्राप	ाप	(20)229	18
में	मैं	(20)231	6
ड्रेन	डेन	(20)232	2

Read	*for*	*Page*	*Line*
फैसला	फसला	(20)235	16
सें	स	(20)235	24
ਹੋਰ	ਹੋ	(20)238	11
Minister	Minist	(20)239	33
*Expunged	Expunaged	(20)239	last
is	s	(20)240	13
पर	प	(20)240	17
ਬਹੁਤ	ਬਹਤ	(20)242	16
नम्रता से	नम्रता	(20)244	1
ਸਿੱਖ	ਸਿਖ	(20)245	23
ਕਰਨਾ	ਕਰਨ	(20)246	10
मलिक	मल्कि	(20)247,249	7, 12
poster contains.)	poster (contains.)	(20)247	21
Delete the words '(RESERVATION OF DISCUSSION)' after the words 'DEMANDS FOR GRANTS'		(20)251	Heading
मैम्बर	मैंबम्बर	(20)251	2
Delete the words 'ਦੇ ਕਾਰਨ' before the word 'ਹਾਊਸ'		(20)251	14
प्वायंट	प्वायंड	(20)252	10
एडजर्न	एडर्जन	(20)252	12
रखना	रखना	(20)252	7 from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the [illegible] March, 1965

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh, at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Supplementaries to Starred Question No. 7502*

श्री मोहन लाल : स्पीकर साहिब, आज तो मिनिस्टर साहिब याददाश्त ताज़ा कर के आए होंगे । इस लिए पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सवाल नम्बर 87 के जवाब में पंजाब लैजिसलेटिव कौंसिल में 15 सितम्बर को यह कहा था कि पब्लिक सर्विस कमिशन ने जो सीलैक्शन्ज़ की हैं वह आर्बिटरेरीली की गई हैं और कि यह उन से सैटिसफाईड नहीं हैं ?

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : जनाबे आली, उस सिलसिले में मैं ने यह कहा था कि कुछ रिकमैंडेशन्ज़ जो हैं उन के बारे में चर्चा यह है that they have been made in a very arbitrary manner. मैंने आगे कहा है कि कुछ मेरे परसनल इल्म में भी है जिन की सीलैक्शन के बारे में मुझे बहुत खुशी नहीं हुई है ।

Shri Mohan Lal : Sir, I want to draw the attention of the hon. Minister to the reply given to Question No. 7320. The Question reads :—

"Whether the selections of the candidates for the posts of Principals of the Higher Secondary Schools, made by the Public Service Commission, were made arbitrarily ?".

The reply given was "Yes". सवाल के अगले पार्ट में पूछा गया था

"Whether he was not satisfied with the selections made", and the answer given was "Yes".

इन्होंने यह बात कैटागोरिकली कही थी कि यह जो सीलैक्शन हुई यह आर्बिटरेरीली हुई और कि यह उस से सैटिसफाईड नहीं हैं । तो क्या मिनिस्टर साहिब यह कहेंगे कि इन्होंने वहां पर यह स्टेटमेंट दी थी या कुछ और कहा था ?

Minister : I cannot say exactly because the reply in question is not before me. However, from memory, I can say that I did not say categorically about all the selections. What I said was that it is said that some of the selections have been made in a very arbitrary manner. Then, I said that in some of the cases, I too shared the feelings of the general public that some of the selections have not been made on merits.

---

*Starred Question No. 7502 along with its reply appears in P. V. S. Debate Vol. 1 No. 19 dated 16th March, 1965.

Comrade Shamsher Singh Josh : May I know, Sir, whether any of the rejected persons made any representations to the Government against the arbitrary manner of selections made by the Public Service Commission, or the honourable Minister acted on the basis of any information supplied to him by some one ?

Minister : Sir, representations were received by me. A large number of persons also met me in deputation. Different Teachers' Organisations sent their deputations to me bringing to my notice the manner in which some of the selections were made. I remember one case in which a candidate was rejected for P.E.S., Class III. After two months, he was selected for P.E.S., Class II. He went on saying that two months earlier he had no person to influence, I do not konow how far that assertion is correct. But, it is a fact that the candidate was rejected for P.E.S., Class III, and therafter selected for P.E.S. Class II. That too confirms my view that there is something wrong some where, but not in all the cases of the selections made. The second thing is that out of 200 and odd recommendations, we have admitted about 175 cases confirming their selections. There are now about 40 cases in dispute, some of them having bad records. After verifying the confidential reports of all these candidates, we are trying to finalise their cases as early as possible.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know, Sir, from the honourable Education Minister as to who is the authority to make these selections ?

Minister : After the receipt of a numbers of representations from Teachers, Organisations individuals as well as collective representations, I asked the Education Commissioner and the D.P.I. to review each case on the basis of the confidential reports of the officers concerned. And, in cases where there was an agreement between the findings of the Public Service Commission and the Departmental Heads, they should be given clearance. But, where they differ, we will ask the Commission to review such cases and if they again do not agree and recommend the same person, we will see what is to be done.

श्रीमती सरला देवी : क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि उस दिन सीलैक्शन बोर्ड में ऐजुकेशन महकमा की तरफ से कौन गया हुआ था ?

Minister : I cannot say off hand, but the ordinary procedure is that one senior officer of the Education Department sits alongwith the Members of the Public Service Commission when selections are made.

श्री फतेह चन्द विज : क्या मन्त्री महोदय बातएंगे कि जैसे उन्होंने कहा था कि सीलैक्शन होने के बाद 43 को डीटेन कर लिया गया था तो क्या वह अब भी 43 ही हैं या उस के बाद कुछ को तरक्की दे दी गई है ?

मन्त्री : जब मेरे पास जवाब आया था तो करीब 43 पेंडिंग थीं । अप-टू-डेट पोजीशन मैं पता कर के बता सकता हूं कि आया उन में से कुछ को ले लिया गया है या नहीं ।

श्री मोहन लाल : स्पीकर साहिब, मालूम होता है कि मिनिस्टर साहिब ने ग्रांउंड शिफट की है । सवाल नम्बर 7320 के जवाब में इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वह आर्बिटरेरी सीलैक्शन्ज़ हैं अब फरमाते हैं कि कुछ के मुतअल्लिक कहा था । मैं जानना चाहता हूं ....

Mr. Speaker : The hon. Minister has given the latest position and has made things clear.

श्री मोहन लाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि जितनी सीलैक्शनन्ज़ के मुताल्लिक इन्होंने कहा था कि वह आर्बिटरेरी हुई तो इस कन्क्लूयन पर पहुंचने का इन के पास क्या बेसिज़ था ?

एक आवाज़ : जो आप का हुआ करता था । (विघ्न)

मन्त्री : जनाब, मैं अपने मोहतरिम दोस्त से कहूंगा कि वह मुझ पर यह इल्ज़ाम न लगाएं कि जिस तरह से वह करते थे मैं भी करता हूं मैं तो सारी बातें साफ 2 करता हूं । (विघ्न) पंडित जी ने पूछा कि क्या क्राइटीरिया है तो मैंने आगे भी कहा है कि इस बारे में लिखे हुए रीप्रेज़ैन्टेशन्ज़ आए, डैपुटेशन्ज़ भी मिले और एक दो अफसरों ने भी कहा कि वह महसूस करते हैं कि कुछ केसिज़ में फरदर स्क्रूटनी का स्कोप है ।

Not that I correct myself. Even then I had not said that all the selections made were arbitrary. What I remember having said was that there is a general impression that some of the selections were made arbitrarily and in a few cases I also shared the feelings of the general public that the selections were made arbitrarily.

Sardar Gurnam Singh: May I know, Sir, from the honourable Education Minister as to who the senior officer of the Education Department was, who sat with the Public Service Commission, and whether he agreed with the opinion of the Commission at the time of interviews in these cases ?

मन्त्री : उस में जनाबेआली, ऐसा नहीं होता कि कोई रिकार्ड हो कि कौन हक में है या कौन खिलाफ । कुछ रिमार्कस देते हैं और जैनरल कनसैंसस को देख कर पब्लिक सर्विस कमिशन रिकमेंडेशन करता है, तो यह गवर्नमेंट की मर्ज़ी होती है कि उस को माने या न माने । वह अपने तौर पर फैसला नहीं करता ।

बाबू अजीत कुमार : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਦਸ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗ ਗਏ ਹਨ । ਅਜ ਜੋ ਪੋਸਟਪੋਨਡ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ......

Mr. Speaker: I know that. Please take your seat.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि जो लिस्ट पब्लिक सरविस कमिशन की तरफ से सरकार को भेजी जाती है उसको फाईनल मान लिया जाता है या यह सरकार की स्वीट विल पर है कि जिस को चाहे उस लिस्ट में से रख ले । क्या उनकी रिकमेंन्डेशन्ज़ का मेंडेटरी इफैक्ट नहीं होता ?

मन्त्री : उनकी रिकमेंन्डेशनन्ज़ सरकार पर बाईडिंग नहीं है लेकिन आम तौरपर उन के स्टेटस के लिहाज़ से उनकी सारी की सारी और ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंन्डेशनज़ को मान लिया जाता है । अगर खास केसों में गवर्नमेंट महसूस करती हो तो इनको फिर पब्लिक सरविस कमिशन को रैफर करती है फिर भी अगर वह सरकार के नज़रिये को न मानें तो सरकार दोबारा गौर करती है कि क्या फैसला किया जाए

श्री मोहन लाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में गवर्नमेंट ने पब्लिक सरविस कमिशन को कुछ लिखा या पब्लिक सरविस कमिशन ने गवर्नमेंट को लिखा इस सिलसिले में कि जो इन्होंने पंजाब लैजिस्लेटिव कौंसिल में यह स्टेटमेंट दिया था कि यह सिलैक्शन आर्बिटरेरी की गई हैं ?

मन्त्री : मैंने यह बात कही है कि हम ने अभी तक कोई चीज़ फाइनेलाईज नहीं की जो हम फाइनल रिकमेंन्डेशन्ज़ करेंगे तो हर एक के बारे में अपनी राए देंगे कि इस लिहाज़ से हम महसूस करते हैं कि इन की रिकमेंन्डेशन्ज़ पर रिव्यू किया जाना चाहिए और अगर उन्होंने रिव्यू न किया तो देखा जाएगा कि क्या होता है ।

Shri Mohan Lal : On a point of Order, Mr. Speaker Sir, my question was very straight and clear. I asked whether the Government have written to the Public Service Commission in regard to the alleged arbitrary selections made or if the Public Service Commission wrote to the Government in regard to the statement which the hon. Minister was pleased to make in the Legislative Council the other day ? So, Mr. Speaker, I would like to have a categorical answer from the hon. Minister in this regard.

मन्त्री : जनाबआली, न तो पबलिक सरविस कमिशन ने आफिशली कोई चीज़ लिखी है और न ही सरकार ने लिखी है । एक आध चिट्ठी मेरी तरफ से पब्लिक सरविस कमिशन के चेयरमैन को और एक आध चेयरमैन की तरफ से मुझे आई है जिस में अपनी फीलिन्गज थी इस के आगे मेरी उन से कोई बात चीत नहीं हुई ।

Mr. Speaker : Next question please.

Shri Mohan Lal : Mr. Speaker, Sir, there are many contradictory statements made by the non, Minister. I would, therefore, request you to please allow half-an-hour discussion on this matter.

Sardar Lachhman Singh Gill : No. ਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਈਏ ?

Mr. Speaker : No. Please. I have already allowed supplementaries for about half an hour on this question.

Shri Mohan Lal : But, Mr. Speaker, there are some contradictory statements made by the hon. Minister.

Mr. Speaker : If the hon. Member considers that there are contradictory statements, he may write to me.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ, ਕੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਾਲ ਅਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ?

Mr. Speaker : But I have not allowed him to ask the supplementary. How has the hon. Member presumed ?

Code of Conduct for Members of Cabinet

*6773. **Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government has approved any 'Code of Conduct' for the Members of the Cabinet: if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(b) the names of the Members of the Cabinet who have so far implemented the provisions of the said Code ;

(c) the details of the statements regarding the 'assets and liabilities' given by any or all of the Members of the Cabinet be laid on the Table of the House ;

(d) the names of those Members of the Cabinet who have not so far implemented the Code with the reasons therefor ;

(e) the action taken or proposed to be taken against those mentioned in part (d) above ?

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Yes. The Code of Conduct has already been laid on the Table of the House on 24th February, 1965.

(b) All the members of the Cabinet have implemented the provisions of the Code of Conduct.

(c) The Code of Conduct for Ministers does not require that the particulars furnished by Ministers regarding their assets be made public or laid on the Table of the Houses of the State Legislature.

(d) and (e) In view of (b) above, Question does not arise.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि मिनिस्टर साहिबान ने जो लिस्ट अपने एसैट्स और लायबिलिटी की दी है उन की तफसील क्या है ?

Chief Parliamentary Secretary : I have already stated the position in answer to part (c) of the main Question. I may again read it out for the information of the hon. Member. It reads—

"(c) The Code of Conduct for Ministers does not require that the particulars furnished by Ministers regarding their assets be made public or laid on the Table of the Houses of the State Legislature."

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या यह बताएंगे कि अगर यह चीज़ पब्लिक नहीं होनी तो यह कैसे पता लगेगा कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वह ठीक है या ठीक नहीं है ?

Mr Speaker : The hon. Member need not argue it.

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । अगर कोड आफ कन्डक्ट के मुताबिक सारे मिनिस्टरों ने अपनी और अपने रिश्तेदारों के जिन को लिमट कर दिया गया है ने अपनी लायबिलिटी और एसैट्स की लिस्ट दे दी है तो इस बात का पता कैसे लग सकता है कि यह ठीक है या नहीं और ऐसी स्टेटमेंट को कौन कंट्राडिक्ट करेगा ?

Mr. Speaker : That may be the opinion of the hon. Member. But the Government is claiming privilege.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ: ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਡ ਆਫ ਕਾਨਡਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : कोड आफ कन्डक्ट की कापी को मेज़ पर रख दिया गया था अगर मेम्बर ने उस को पढ़ा होता तो इस तरह का सवाल न करते।

श्री अध्यक्ष : बेहतर यह होगा कि कोड आफ कन्नडक्ट के लिए एक दिन जो बहस के लिए रखा गया है उस में इस तरह की सारी चीजें आप ले आएं। (It would be better if such matters are brought on the day which has been allotted for the discussion of the Code of Conduct for the hon. Ministers.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਜਨਾਬ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I wanted to draw your attention....

Mr. Speaker : Government of India have formulated a Code of Conduct for the Ministers and the Punjab Government have adopted it.

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ....

Mr. Speaker : The Government can claim privilege.

Sardar Gurnam Singh : May I know if there is any proposal under the consideration of the Government to have a list of assets, etc., of the Members of the Legislature as well ?

Mr. Speaker : This matter concerns me also and the Santhanam Committee Report also contains some suggestions in regard to the Code of Conduct of Members of the Legislature etc. I may sooner or later take the Group Leaders into confidence and frame a Code of Conduct for Member as well.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਸੈਟਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं और किसी ने तबदीली नहीं की,

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੇਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਕੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਵਜੋ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥਲੇ ਥਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰਜ਼ ਕਿਥੇ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : Please take your seat.

चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी : स्पीकर साहिब, ऐसी कोई बात नहीं है । मिनिस्टर को कोड आफ कन्डक्ट चीफ मिनिस्टर को सबमिट करना होता है । यह समझ नहीं आया कि इस में क्या ग़लत मलत होने की बात है ।

डा० बलदेव प्रकाश : कोड आफ कंडकट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की लिमिट है यह कहां तक है ?

श्री अध्यक्ष : कोड आफ कन्डक्ट की एक कापी टेबल पर तो रख ही दी गई है । अभी इस पर डिसकशन होनी है। (A copy of the Code of Conduct has already been laid on the Table of the House and it is still to be discussed.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या कोड आफ कन्डक्ट में यह प्रोवीज़न भी है कि मिनिस्टर हर साल अपने असैटस की लिस्ट देते रहेंगे क्योंकि इन की आमदन में तो अज़ाफा होता ही रहता है ।

Mr. Speaker : It is a suggestion for action.

Quota of Iron and Steel, etc., for starting Industries in Hill Areas

***7716. Comrade Ram Chandra** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government have decided to allot quotas of Iron, Steel, Copper and Zinc, etc., to the people of Hill Areas in the State starting industries in these metals ;

(b) the names of the persons or firms in the Hill Areas receiving the said quotas, along with the quantity of the quota granted in each case and the date since when it is being received by them ?

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Yes, Sir, provided their schemes are approved by the Industries Department.

(b) The information is laid on the Table of the House.

Statement showing the names of the persons or firms in Hill Areas getting quota of Iron and Steel, Copper and Zinc, along with the quantity received by each of them

District	Serial No.	Name and Address of the quota-holder	Date of allotment of the quota for the first time	*Quantity allotted in M.T.*		
				Iron Steel	Copper	Zinc
1	2	3	4	5	6	7
Kulu ...	1	Shri Gurdev Singh, son of Shri Dharam Singh, Kulu	8-3-63	0.337	..	..
	2	M/s Pritam Dass Malhotra and Sons, Kulu	2-1-65	2.004	..	..
Hoshiarpur	1	M/s Rama Engineering Company, Hoshiarpur	7-3-63 April-September, 1962	..	1.00	0.60
	2	M/s Khushal Small Scale Industries, Hajipur	February, 1964	...	1.00 (Copper and Zinc)	..

[Chief Parliamentary Secretary]

District	Serial No.	Name and Address of the quota-holder	Date of allotment of the quota for the first time	Quantity allotted in M.T.		
				Iron Steel	Copper	Zinc
1	2	3	4	5	6	7
	3	M/s Rajput Trunk House, Gagret (District Hospiarpur)	March, 1964	0.843	..	..
Ambala	1	M/s Associated Engineering Products, Pinjore, district Ambala	2-1-65	..	2.00	1.300
	2	M/s Surrendra Mechanical Works, Pinjore	2-1-65	..	5.00	0.300
	3	M/s B. M. G. Metal Industry, Pinjore, district Ambala	2-1-65	..	3.00	2.00
Simla	1	M/s United Trading Corporation Dharampur, district Simla	2-1-65	..	3.00	2.00
	2	M/s Atma Ram-Radhe Kishan, Simla	2-1-65	..	3.00	2.00
	3	M/s Hill Metal Products, Dharampur, district Simla	2-1-65	..	3.00	2.00
	4	M/s Metal Products, Dharampur, district Simla	2-1-65	..	3.00	2.00
Kangra	1	Shri Amar Singh, Proprietor, Amar Engineering Industries, Chari Road, Dharamsala	2-1-65	..	3.00	0.250
	2	M/s Bhagat Electrical Components, Kangra	2-1-65	..	5.00	..
	3	M/s Rishi Raj Walia, Vishnu Bhawan, Kotwali Bazar, Dharamsala	2-1-65	..	3.00	2.00
	4	M/s Amrit Lal Chaudhry, C/o Shri Som Parkash, Advocate, Kaithal Mandi (For Kangra District)	2-1-65	..	3.00	2.00
	5	Shri Roshan Lal Soni, Proprietor, Pran General Stores, Palampur	2-1-65	..	3.00	2.00
	6	Shri Radhe Sham of M/s Lekhi Ram-Radhe Sham, Dharamsala	2-1-65	..	3.00	2.00
	7	M/s Narain Industries C/o M/s. Gurbax Rai-Lehnu Ram, P. O. Tohnni Devi, tehsil Hamirpur, district Kangra	2-1-65	..	3.00	0.250
	8	M/s Shivalak General Industries, C/o Shri Ghanighaur Misra, Kangra	2-1-65	..	3.00	2.00
	9	M/s Ashoka Industries, Industrial Estate, Kangra	2-1-65	..	3.00	2.00

कामरेड राम चन्द्र : स्पीकर साहिब मुझे जो लिस्ट दी गई है इस में बताया गया है कि एक फर्म जो होशियापुर में है उस को 7 मार्च, 1963 को एक एम. टन कापर का परमिट दिया गया । और उसे ही 60 एम. टन ज़िंक दिया गया। इसी तरह अम्बाला और शिमला की 7 दुकानों को कापर भी दिया गया और ज़िंक भी दिया गया । एक दुकान धर्मशाला में है इसको 3 एम. टन कापर दिया गया । इसको ही 2.50 एम. टन ज़िंक भी दिया गया । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो 7-8 दुकानों को कोटा दिया गया है यह किन बेसिज़ पर दिया गया ।

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : इस मामला के मुतअलिक रूलज़ ऐंड रैगूलेशन्ज़ बने हुए हैं । एक बाकायदा सकीम के तहत सब चीज़ों को देखते हुए कोटा दिया जाता है ।

कामरेड राम चन्द्र : चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब ने जो फरमाया है, मैं यह बात तसलीम करता हूं कि कुछ रूलज़ हैं जिन के तहत यह कोटा दिया जाता है । मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह कौन से पुरज़े है जिन की मैनूफैकचर की बिना पर इंन्डस्टरी डिपार्टमेंट नें इन 7 दुकानों को कोटा दिया है ।

श्री स्पीकर: अगर कोई इनफारमेशन हो तो दे दें या नोटिस की डिमांड करें । (If the Chief Parliamentary Secretary has any information he may give it or ask for a separate notice.)

Chief Parliamentary Secretary : Sir, I require a separate notice.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਜੋ ਕੋਟਾ ਇਕ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਐਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ । (The hon. Member may ask question regarding taking over.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਦਿਤਾ, ਕੁਝ ਡੀਲਰਜ਼ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ?

चीफ़ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : इस के लिए मुझे सैपरेट नोटिस चाहिए ।

श्री जगन्नाथ : हर बात में यह नोटिस मांगते हैं और बताते हैं टेलेंट । क्या इन के पास यही टेलेंट है कि नोटिस, नोटिस और नोटिस चाहिए ?

श्री स्पीकर । और आप के पास यही टेलेंट है कि आप हर बात को ऐंटीसीपेट करें । (And the hon. Member has the talent to anticipate every thing.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ; ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸੇਦਾਰ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਹਨ ?

Mr Speaker : It does not arise.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਸੀਚੂਐਂਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : It does not arise. The hon. Member may please take his seat. Moreover, quotas do not go by constituencies.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Parliamentary Secrertary kindly state as to who is the final authority to decide the allotment of quotas so far as the State Government is concerned ? Is it on the sweet will of any single officer to decide whether the demand is genuine or not and what is the criterion for the allotment of these quotas ?

Chief Parliamentary Secretary : Sir, in the Industries Department there is also a Technical Expert. First of all the scheme is to be submitted to the Industries Department through the District Industries Officer which is scruitinised and after that is approved, quota is allotted to the manufacturers according to their capacity by the Department.

Arrests of Republican Party Satyagrahis in the State

***6804. Comrade Jangir Singh Joga** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of Republican Party Satyagrahis arrested so far in the State, districtwise ;

(b) the major demands of the Satyagrahis and the steps so far taken by the Government in this connection ?

Sardar Darbara Singh : A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The total number of Republican Party Satyagrahis arrested so far (upto and including 13th January, 1965) is 958, of which the district-wise detail is a under :—

Hissar	Karnal	Rohtak	Gurgaon	Ambala	Jullundur	Amritsar	Hoshiarpur
42	19	75	90	20	628	8	12

Ludhiana and	Ferozepur
44	20

(b) No demands were put up by the Satyagrahis when they resorted to Satyagrah. However, towards the end of June, 1964, a memorandum, as presented to the Prime Minister of India by the Republican Party, was received by the State Government. It contained the following demands —

(i) Appointment of a High-powered Commission to tackle the problem of distribution of land to the landless agricultural labourers, particularly the Harijans ; and

(ii) all waste land, village common land, surplus area determined under the Punjab Security of Land Tenure Act, 1953, and the Pepsu Tenancy and Agricultural Land Act, 1955, land belonging to Former Rulers and Biswadars of Pepsu, inferior evacuee lands, lands reserved under the Panchayat Scheme and land possessed by the Religious institutions in the State, etc. etc., may be distributed amongst the landless agricultural workers particularly Harijans.

These demands were examined by the Government. A decision was taken by the Government in early September, 1964, that all evacuee land in rural areas should be auctioned to the Harijans exclusively and for purposes of affording them monetary assistance, a sum of Rs. two crores was advanced as loans from out of the Harijans Kalyan Fund collections. Action on allotting other Government lands to the Harijans is also being taken, wherever legal and practicable.

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿਘ ਜੋਗਾ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਿਹੀ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ?

ਗ੍ਰਿਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ: ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਜੇ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੀਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ?

Mr. Speaker: This does not arise. The programme of the Congress cannot be the subject matter of questions.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾਇਆ?

ਮੰਤਰੀ: ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੰਡਜ਼ ਪਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਕਾਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼: ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕ ਡਿਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ "Appointment of High powered Commission to tackle the problem of distribution of land to the landless agricultural labourers ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ?

ਮੰਤਰੀ: ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। (I think that if the hon. Member had read the reply to the question he would not have put this supplementary)

Area of Shamlat Deh and Tikka in Kangra District

***7747. Shrimati Sarla Devi**: Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total area of Shamlat Deh and Tikka which vests in the Panchayats of Kangra District ;

(b) the income derived by the Panchayats from the said shamlat areas during the year 1961-62, 1962-63 and 1963-64 ;

[Shrimati Sarla Devi]

(c) the total area of Shamlat called 'Bansarkar' which is vested in Panchayats ?

Sardar Darbara Singh : (a) 603,419 acres.

		(Income in rupees)
(b) 1961-62	...	2,13,103.49
1962-63	...	2,13,129.51
1963-64	...	2,65,559.39

(c) 434,122 acres.

श्रीमती सरला देवी : इस सिलसिले में क्या वजीर मुग्रतल्लिका यह बातएंगे कि उन पंचायतों की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन मिली है ?

गृह तथा विकास मन्त्री : जी हां ।

श्रीमती सरला देवी : शामलात टीका वाली जो एमेंडमेंट है, क्या वह इस बजट सैशन में हो जाएगी ?

मन्त्री : यह तो नहीं करेंगे मगर यह ठीक है, कि सरकार इस को थारोली एग्ज़ामिन कर रही है ।

Employees retrenched from Public Relations Department

*6945. **Comrade Bhan Singh Bhaura** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of gazetted and non-gazetted , Class III and Class IV employees of the Public Relations Department retrenched recently ;

(b) the steps taken or proposed to be taken to re-employ them ?

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : The information is laid on the Table of the House—

(a) The services of 224 non-gazetted employees including 154 paid out of contingencies all temporary were terminated ;

(b) The retrenched employees will be allowed to appear before the Selection Board when the new posts are advertised.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਖੇ ਗਏ ਸੀ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Chief Parliamentary Secretary as to how much service these employees had put in when their services were terminated and what emergency had cropped up which forced the Government to retrench these employees ?

Mr. Speaker : How can the Chief Parliamentary Secretary tell the duration of service of all these employees off hand.

चीफ पार्लियामेंटरी सक्रेटरी : यह इस प्रकार के 224 इम्पलाईज़ हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ; ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?

चौधरी देवी लाल : जो गर्ग साहिब ने फरमाया कि यह लोग किसी बोर्ड या कमिशन के द्वारा नहीं रखे गए बल्कि ऐवें ही रख लिए गए, इसका क्या मतलब हुग्रा ।

श्री अध्यक्ष : यह पंजाबी का लफ़ज़ है आप की समझ में नहीं आएगा । (This is a Punjabi word, you may not be able to understand it.)

चौधरी देवी लाल : उन 224 लोगों में कुछ पुलिटिकल सफरर्ज़ भी थे उनको भी निकाल दिया क्या इस सरकार ने वह हर बात उलट करनी है जो पहली सरकार ने की थी।

चीफ पार्लियामेंटरी सक्रेटरी : इन लोगों ने उस समय बोगस टी. ए. और डी. ए. बनाए थे । यह चार्ज था इन पर ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਟਾਏ, ਮਗਰ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਬਾਰੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी ; बात यह है कि नान-गजटिड की इनक्वायरी हुई थी और रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें रिट्रैंच किया गया ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : इन 224 कर्मचारियों को किस आधार पर निकाला गया ?

चीफ पार्लियामेंटरी सक्रेटरी : इसी आधार पर कि 1964 में उनके खिलाफ एक इन्कवायरी इंस्टीचूट हुई थी उसकी रिपोर्ट में यह बात आई कि इन्होंने बोगस टी. ए. और डी. ए. बनाए ।

श्रीमती सरला देवी : स्पीकर साहिब, क्या चीफ पालियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब यह बतलाएंगे कि इन सारे लोगों के खिलाफ एक जैसा चार्ज था ?

चीफ पार्लियामेंटरी सक्रेटरी : मेरी बहिन मेरे पास आई थीं और कुछ महिलाओं के निकल जाने के बारे में पूछ रहीं थीं मैंने इन्हें उस वक्त भी जवाब दे दिया था ।

श्रीमती सरला देवी : मैंने किसी पर्टीकुलर केस के बारे में नहीं बल्कि सारे लोगों के बारे में जनरल तौर पर कहा था ।

श्री मंगल सैन : On a point of Order, Sir. स्पीकर साहिब, अभी एक लेडी मैम्बर ने सवाल पूछा था और चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब ने बड़ी अदा और नज़ाकत से कुछ महिलाओं के बारे में कहा । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह से बात कह कर किसी लेडी मैम्बर को दबाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : अगर आप नहीं घबराये तो सरला देवी जी कैसे घबरा सकती हैं। (When the hon Member, himself has not felt deterred how could the Lady Member, Shrimati Sarla Devi, feel so ?)

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब मैं ने पूछा था कि रिट्रैंचमेंट के लिये क्राइटेरिया क्या था तो चीफ पार्लियामेंटरी सक्रेटरी साहिब ने जवाब दिया था कि जिन्होंने शहरों में बैठ कर गलत टी. ए. बिल क्लेम किये थे उन को हटाया था तो क्या मैं जान सकता हूं कि जो मनिस्टर गलत टी. ए. चार्ज करते रहे हैं उन के खिलाफ भी ऐक्शन लिया जायेगा।

Mr. Speaker: No, please. This question does not arise.

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहिब, जो पुलीटीकल सफरंज थे, जिन्होंने सजाएं काटी थीं वह रूरल पब्लिसिटी सुपरवाईज़र्ज़ वगैरा बनाये गये थे। उन के बारे में इन्होंने बताया है कि उन्होंने फाल्स टी. ए. क्लेम किया था इस लिये उन्हें रिट्रैंच किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि जो गज़टिड पोस्टस पर लगे हुए थे उन के बारे में कुछ नहीं था। उनको भी निकाला जाना चाहिये था।

Mr. Speaker : The Chief Parliamentary Secretary has already replied to this question.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖ ਲਏ ਗਏ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰਖਣੇ ਹਨ।

कामरेड राम प्यारा : चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहिब ने फरमाया है कि वह ऐवें ही रखे गए थे और फिर उन्होंने फरमाया कि उन्होंने टी. ए./डी. ए. फरजी लिये थे। क्या मैं जान सकता हूं कि उन की जरूरत नहीं थी या उन की जगह और लोगों को रखने के लिये गवर्नमैन्ट ने उन्हें निकाला है।

चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रटरी : हम ने इस महकमे को रीआर्गेनाइज़ किया है। जिन की सर्विसिज़ को टर्मीनेट किया गया है वह आन दी बेसिज आफ बैड रिपोर्ट किया है। आप जिसकी फाइल चाहें मेरे पास आकर देख सकते हैं।

Sardar Gurnam Singh : The Chief Parliamentary Secretary in one of his replies has stated that the non-Gazetted employees whose services have been terminated were submiting wrong T. A. Bills. Will he kindly state whether charge-sheets were served on those employees asking them to explain their conduct before their services were terminated ?

चीफ पार्लियामैन्टरी सक्रेटरी: वह कंटेनजैंसी पेड टैम्परेरी इम्पलाइज़ थे। उन का काम हमें सूट नहीं किया इस लिये उन्हें हटा दिया गया था।

Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : Sir, may I know from the Chief Parliamentary Secretary if those posts have been abolished altogether or the Government is thinking of reviving those posts ?

चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी : हम ने रीआर्गेनाईज़ेशन के अंदर पब्लिसिटी वर्करज़ की पोस्टस को एबालिश कर दिया है और जो पब्लिसिटी सुपरवाईज़रज़ थे उन की जगह असिस्टैन्ट इन्फरमेशन आफीसरज़ की पोस्टस बनाई हैं जो कि परमानैंट पोस्टस होंगी और उन को सिलैक्शन पब्लिक सर्विस कमिशन करेगा।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?

Mr. Speaker : The Chief Parliamentary Secretary has said that checking was done.

Shri Rup Singh Phul : Sir, may I know the agency through which the checking was done and on whose report the services of the non-Gazetted employees were terminated ?

Chief Parliamentary Secretary : Through the revenue district authorities.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੀ।

Mr. Speaker : Next question please. It stands in the name of Comrade Bhan Singh Bhaura.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I may be permitted to put one supplementary question.

Mr. Speaker : I would request the hon. Member to co-operate.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I always co-operate. I request that I may be permitted to put one supplementary question.

Mr. Speaker : No please. I have already called upon Comrade Bhan Singh Bhaura to put his question.

Community Listening Sets

***6948. Comrade Bhan Singh Bhaura** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of community listening sets so far sold to the Gram Panchayats, district-wise ;

(b) whether any survey regarding regular working of these sets has been conducted in the State ; if so, the result thereof ;

(c) the percentage of such sets with the Panchayats in each district which are out of order at present and the steps taken or proposed to be taken to get them repaired ?

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary): (a) District-wise statement 'A' giving the total number of Community Listening Sets so far allotted to Gram Panchayats is placed on the Table of the House. The sets are not sold but allotted to Panchayats for the purpose of community listening on payment of a certain percentage of the cost of the set.

(b) Yes. Last Survey was conducted in April, 1964 ; 1,216 sets were found to be lying idle for want of batteries or other repairs.

(c) A statement 'B' is placed on the table of the House. The allottees are being persuaded to get the sets repaired and purchase new batteries.

Statement "A"

Serial No.	District		Number of Community Listening sets with Panchayats
1	Hissar	..	391
2	Rohtak	..	375
3	Gurgaon	..	346
4	Karnal	..	349
5	Ambala	..	694
6	Simla	..	70
7	Kangra	..	360
8	Hoshiarpur	..	674
9	Jullundur	..	536
10	Ferozepore	..	452
11	Ludhiana	..	647
12	Amritsar	..	716
13	Gurdaspur	..	537
14	Patiala	..	556
15	Kapurthala	..	313
16	Narnaul	..	291
17	Sangrur	..	419
18	Bhatinda	..	352
19	Kulu	..	77
20	Lahaul and Spiti	..	28
	Total	..	8,183

Statement 'B'

Number of Community Listening Sets with Panchayats district-wise which are out of order with percentages—

District		Number of sets out of order	Percentage
Hissar	..	97	24.80
Rohtak	..	31	8.26

District	Number of sets out of order	percentage
Gurgaon	22	6.35
Karnal	43	12.32
Ambala	61	9.65
Simla	4	5.62
Kangra	157	43.61
Hoshiarpur	81	12.01
Jullundur	18	3.36
Ludhiana	161	24.88
Ferozepore	79	17.47
Amritsar	95	13.30
Gurdaspur	50	9.31
Patiala	22	3.94
Kapurthala	125	39.60
Narnaul	29	9.96
Sangrur	30	7.13
Bhatinda	98	27.81
Kulu	13	16.88
Lahaul and Spiti	..	..

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ: ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ repair ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਨਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ: ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Mr. Speaker : It is a relevant question.

श्री मंगल सेन : पार्ट (बी) के जवाब में बताया गया था कि 1,216 लिस्निंग सैट्स बेकार पड़े हुए हैं और आप ने कहा कि हम ने लोगों को कहा है कि वह बैटरियां ले लें। मैं जानना चाहता हूं कि आप की सलाह को मानने के बाद कितने सैटों में बैटरियां लगी हैं और कितने बेकार पड़े हैं ?

चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी : री-आर्गेनाइज़ेशन के अन्दर हम ने उन सब सैट्स को आर्डर में लाने का इन्तजाम किया है। इस के लिये टैक्नीकल मकैनिक्स का प्रबंध किया है और जलदी ही वह आर्डर में किये जायेंगे।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਇਹ ਜੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੈਟਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ? (ਹਾਸਾ)

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਪੀਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਪੇਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਲੇਕਨ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਪੇਕਿੰਗ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਹਾਸਾ)

ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। (ਹਾਸਾ)

श्री मंगल सैन : उन्होंने फरमाया है कि मास्को और पेकिंग ज़रूर लगता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह उनकी जानकारी में है कि रोहतक जो देहली से 20 मील है वहां पर दिहाती प्रोग्राम भी वहां से नहीं आता है।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿਚ ਜੋ ਸੈਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ 43.61 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਕੀ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਥੇ ਕਾਰੀਗਰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

कामरेड राम प्यारा : यहां बताया गया है कि एक हजार से ज्यादा सैटस खराब पड़े हैं जो काफी अर्से से ठीक नहीं हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आया गवर्नमैंन्ट की ऐसी भी कोई हिदायात हैं कि जो सैटस पंचायतों ने खरीदने होते हैं वह किसी खास फर्म या कंपनी से खरीदने होते हैं और रिपेयर कराने होते हैं और इसी वजह से वह जल्दी खराब हो रहे हैं और उनकी रिपेयर भी नहीं हो रही है ?

चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी : यह जो सैटस खरीदे जाते हैं गवर्नमैंन्ट आफ इन्डिया की मारफत खरीदे जाते हैं और उन्हें with a maximum of Rs. 150.00 subsidize करते हैं। तो यह आल इन्डिया बेसिज़ पर खरीदे जाते हैं।

Advisory Committee for Jails Department

***6950., Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Chief Minister be pleased to state the names of the members of the Advisory Committee for the Jails Department constituted in December, 1964, and the names of the Political Party to which each of them belongs ?

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) :

Names of members of the State Advisory Committee for Jails	*Political party to which they belong*
(1) Shri Narain Singh Shahbazpuri, M.L.A.	Congress
(2) Chaudhri Chuhar Singh, M.L.A. ..	Congress
(3) Shri Dev Raj Anand, M.L.A. ..	Congress
(4) General Mohan Singh, M.P. ..	Congress
(5) Pandit Amar Nath, M.P. ...	Congress
(6) Shri Jaswant Singh Sodhi, M.L.A. ..	Congress
(7) Shri Pritam Singh Sahoke, M.L.A. ..	Congress

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब यह बड़ा अहम मामला है इस का जवाब जरूर आना चाहिये। आपोजीशन के मैम्बरान ने ही आखिर अन्दर होना है इस लिये यह देखना जरूरी है कि वहां जेल में कैदियों को क्या सहूलतें मिलती हैं और क्या नहीं मिलती हैं लेकिन यह जवाब नहीं दे रहे हैं। (शोर)

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਕੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁਣ ਜੇਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। (ਹਾਸਾ)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੇੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲੀਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਡਿਊ ਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਂਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਏ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਤੇ। (ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਤੇ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾਂ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ: ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗੇ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਗੇ ਲਈ ਕੰਨਸਿਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨ।

चौधरी देवी लाल : इन्होंने फरमाया है कि पुरानी कमेटी बनी हुई है। मैम्बरों के नामों से तो ऐसा मालूम होता है कि नई बनी हुई है। खैर, इनका काम वायदे करना है अमल करना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी जरूरी कमेटी जिसका वास्ता आपोजीशन से पड़ेगा उनके लिये आपोजीशन में से कोई आदमी भी ऐसा इन को नहीं मिल सका जो जेलों में गए कैदियों को सहूलतों के बारे में एडवाइज कर सके ? क्या सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि जिनका काम उन्हीं को साजे ?

Mr. Speaker : Question hour is over now.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब हमें कल इस पर सप्लीमैन्टरी करने की इजाज़त दी जाए यह बहुत जरूरी सवाल है।

Mr. Speaker : The Home Minister has stated that this is an old Committee. He has given an assurance that, in future, he will consider the nominations of Members on Committees from the Opposition side also.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਸੰਬਰ, 1964 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

Mr. Speaker : Question Hour is over now.

चौधरी देवी लाल : आन ए. प्वायंट आफ आर्डर, सर........

श्री अध्यक्षा : आप कल इस के बारे में सप्लीमैन्टरी सवाल कर लें। (The hon. Member may put supplementary question in this connection tomorrow.)

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर.......

श्री अध्यक्ष : जब क्वैश्चन आवर खत्म हो जाये तो आनरेबल मैम्बर फिर मैटर टेक अप न करें (When the question hour is over the hon. Member should not take up that matter.)

कुछ आवाजें : इस सवाल पर कल सप्लीमैन्टरी करने की इजाज़त दी जाए।

Mr. Speaker : All right. Supplementaries on this question will continue tomorrow.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Setting up Heavy Electricals Factory in the State

*7929. **Shri Fateh Chand Vij** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is considering any proposal for setting up a Heavy Electricals Factory in the State during the IV Five Year Plan Period ;

(b) If the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the Government would consider the advisability of stetting up of the said Factory at Panipat or some other place in Haryana?

Shri Ram Kishan : (a) Yes. The Government of India have been approached for the grant of an industrial licence for setting up a heavy electrical factory in this State in the public sector.

(b) Provisionally it has been decided to locate the factory at Nangal. A final decision will be taken after making detailed investigations into the relevant economic and technical factors in due course. ..

Buses of Punjab Roadways plying in certain Districts

*6834. **Pandit Chiranji Lal Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of buses of the Punjab (Gurgaon) Roadways at present plying in the district of Gurgaon, Rohtak, Hissar, Karnal and Ambala ;

(b) the years in which the said buses were purchased and put on the road ;

(c) the makes of the said buses and the number of buses of each make ;

(d) whether he is aware of the fact that there is a general complaint from the people in the districts mentioned in part (a) that condemned and worn out buses have been allocated to these districts; if so, the measures which Government propose to take to improve transport facilities in these districts and thus remove the grievances of the people at large;

(e) whether Government propose to re-lace some old and defective buses by new ones in these districts ?

Shri Ram Kishan : (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

[Chief Minister]

Statement

(a) Total fleet strength of Punjab Roadways, Gurgaon, is distributed as per details given below :—

Gurgaon	..	40
Hissar	..	39
Rewari	..	15
Dabwali	..	9
Rohtak	..	44
Delhi	..	71
Total	..	218

There is no sub-depot of Punjab Roadways, Gurgaon, at Karnal and Ambala.

(b) and (c) The information is given as under :—

Year of purchase/ putting on the road		*Make of vehicle*			Source of purchase
		Dodge	Forgo	Leyland	
1959-60	..	38	32	..	M/s Premier Automobiles, Kurla Road, Bombay
1960-61	..	40	32	..	Ditto
1961-62	..	22	19	..	Ditto
1962-63	..	22	29	..	Ditto
1963-64	..	14	11	..	Ditto
1964-65	..	..	..	17	M/s Ashok Leyland, Madras
Total	..	136	123	17	
Less transferred to Punjab Roadways, Chandigarh	..	..	2	..	
Balance	..	136	121	17	
Less condemned since the date of incorporation of this unit		34	22	..	
Net	..	102	99	17	Total .. 218

(d) The department is already seized of the condition of fleet operating and has taken adequate steps to retrieve the vehicles in bad repairs and to replace the unserviceable vehicles by vehicles of Leyland make. The maintenance facilities, have also been augmented. It is hoped that the operational efficiency would be fully restored shortly

(e) Yes .

Traffic Managers, Works Managers and General Managers in Punjab Roadways

*7725. **Sardar Trilochan Singh Riasti** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number and names of the Traffic Managers, Works Managers and General Managers, at present, working in the various depots of the Punjab Roadways seniority-wise, with their date of joining the Roadways/Transport Department and the date since when each one of them is holding his present post ;

(b) whether any seniority list has been prepared by the P. T. C's. Office or by the Government in the Transport Department for purposes of promotions to the posts of General Manager ; if so, when and a copy of the said list be laid on the Table of the House ;

(c) the number of posts of General Managers which are likely to fall vacant during the next financial year (1965-66) and the names of the Traffic Managers who are likely to be promoted as General Manager; if none, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) A seniority list was prepared by the Provincial Transport Co-roller's Office in September, 1962. TA copy of the same is laid on the Table of the House. It is still a subject of examination due to objections received.

(c) None.

Statement

Name of Officer	Date of joining Department/Roadways	Date since when holding the present post
(a) General Manager-6		
1 Shri B. S. Dewan, P. R., Gurgaon ..	22nd May, 1950 ..	22nd May, 1950
2 Shri Raghbir Singh Sarkaria, P. R., Pathankot	17th December, 1948	7th May, 1956
3 Shri Mohan Lal (on deputation) ..	14th October, 1943	20th July, 1959
4 Shri Gurcharan Singh, P. R. Ambala	30th September, 1948	27th July, 1959
5 Shri M. R. Pahwa, (Under suspension)	21st July, 1941 ..	27th July, 1959
6 Shri Naunihal Singh, P. R., Chandigarh	18th August, 1950	27th July, 1959
7 Shri Saran Singh, P. R., Jullundur	23rd October, 1940	10th May, 1963
8 Shri R. N. Sawhney, P. R. Amritsar	3rd November, 1955	10th May, 1963
Traffic Managers 6-		
1 Shri D. S. Kohli, P. R., Amritsar ..	4th September, 1950	1st August, 1959
2 Shri Lal Singh, P. R., Ambala ..	September, 1945	6th September, 1959

[Chief Minister]

Name of officer	Date of joining Department/Road ways	Date since when holding the present post
3 Shri H. S. Randhawa, P. R., Jullundur	26th June, 1961 ..	26th June, 1961
4 Shri Jagdish Chander, P. R., Gurgaon	1st September, 1950	6th January, 1962
5 Shri Dalip Singh, P. R., Chandigarh	8th August, 1948 ..	10th June, 1963
6 Shri G. S. Mahya, P. R., Pathankot	8th May, 1948 ..	26th March, 1964
Works Managers-6		
1. Shri R. N. Bhatia, P. R. Amritsar	8th March, 1951 ..	8th March, 1951
2. Shri B. S. Khurana, P. R.. Jullundur	11th December, 1959	11th December, 1959
3. Shri Bishan Singh, P. R., Pathankot	1st April, 1963 ..	1st April, 1963
4. Shri Ram Saran, P. R., Gurgaon ..	1st December, 1951	31st December, 1964
5. Shri O. P. Katyal, P. R., Ambala ..	1st February, 1954	2nd January, 1965 (afternoon)
6. Shri J. N. Durani, P. R., Chandigarh	..	11th September 1962 (Re-employed after superannuation)

JOINT SENIORITY LIST OF PROVINCIAL TRANSPORT DEPARTMENT (OFFICERS)

Serial No.	Name and Designation	Date of birth	Date of commencement of service	Present post held	Date of promotion to the present post	Sub-post held	Date of confirmation in sub-post	Present salary	Annual increment	Confirmed in the scale with date	Officiating scale with date	REMARKS, IF ANY
								Rs	Rs	Rs	Rs	
1	Major Gurjit Singh	18-8-20	11-7-52	JPTC(I)	16-5-59	JPTC(I)	15-3-53	1,000	50	600—1,200	No question arises	Seniority decided by Government
2	Shri Raj Krishan	12-8-13	15-7-55	JPTC(II)	1-11-56	JPTC(II)	...	880	40	600—1,200	Ditto	
3	Shri Sita Ram ...	15-4-16	19-3-43	DTC (T&C)	27-9-50	DTC (T&C)	27-9-51	1,020	Maximum reached	650—1,020	Ditto	
4	Shri Shiv Kumar	15-7-12	17-1-49	G.M.	17-8-50	G.M.	17-8-51	900	Ditto	600—900 17-8-51	Ditto	
5	Shri R. S. Dewan	13-8-11	22-5-50	G.M.	22-5-50	G.M.	22-5-52	900	Ditto	600—900 ; 22-5-52	Ditto	
6	Shri Raghbir Singh	20-7-16	17-12-48	G.M.	7-5-56	G.M.	7-6-57	725	25	600—900 ; 7-6-56	Ditto	
7	Shri Mohan Lal	6-5-16	37	G.M.	10-1-57	G.M.	10-1-58	725	25	600—900 ; 10-1-58	Ditto	
8	Shri M. R. Mahindru	29-9-12	1-10-48	EATC (S&C)	13-10-59	Secy., RTA	1-10-49	650	30	300—900 ;	Ditto	

[Chief Minister]

9	Shri Ujagar Singh	25-11-12	2-2-49	Secy., RTA	2-2-49	Ditto	2-2-50	600	25	300—900 ; 2-2-50	Ditto	
10	Shri L. C. Dharmani	27-2-21	6-1-47	EATC (T)	6-1-47	EATC (T)	6-1-48	600	25	300—800 ; 6-1-48	Ditto	
11	Shri Gurcharan Singh	4-6-10	30-9-48	O.S.D.	27-7-59	T.M.	6-9-52	625	25	350—550 ; 6-9-52	600—900 ; 27-7-59	
12	Shri M. R. Pahwa ...	12	21-7-41	G.M.	27-7-59	S.S.S.	9-9-51	675	25	200—350 ; 9-9-51	600—900 ; 27-7-59	Approved by the Public Service Commission for appointment as T.M. and also G.M.P.R. in the scales of Rs 600—900
13	Shri Naunihal Stngh	1-1-10	18-8-50	G.M.	27-7-59	S.S.	..	675	25	200—350	600—900 ; 27-7-59	
14	Shri Saran Singh	15-12-20	...	Secy. RTA	23-7-58	EATC (A&G)	10-8-51	650	30	350—650/ 10-8-51	300—900 ; 23-7-58	The confirmation/substantive appointment being in that of Ministerial Gazetted
15	Shri R. N. Bhatia	29-9-09	8-3-51	W.M.	8-3-51	W.M.	8-3-52	530	20	350—550 ; 8-3-52	No question arises	
16	Shri J. N. Durani	10-9-07	8-9-51	W.M	8-9-51	W.M.	8-9-53	510	20	350—550 ; 8-9-53	Ditto	
17	Shri R. N. Sahni	21-5-23	8-11-55	W.M.	3-11-55	W.M.	3-11-59	470	20	350—550 ; 3-11-59	Ditto	
18	Shri Gian Chand	3-12-12	11-5-42	EATC (S&C)	30-5-61	Supdt.	11-9-51	575	25	350—450 ; 11-9-51	300—800 ; 30-5-61	Ministerial confirmed
19	Shri I. N. Datta...	16-6-12	5.40	EATC (A&G)	30-5-61	Do	2-9-51	500	25	320—400	350—650	Ditto

Serial No	Name and Designation	Date of birth	Date of commencement of service	Present post held	Date of promotion to the present post	Sub. post held	Date of confirmation in sub. post	Present salary	Annual increment	Confirmed in the scale with date	Officiating in scale with date	Remarks, IF ANY
								Rs	Rs	Rs	Rs	
20	Shri D S. Kohli	14-10-16	49-50	T.M	1-8-59	I.O.	3-6-57	410	20	250—400; 3-6-57	350—550; 1-8-59	
21	Shri Pr hlad Chander	15-1-18	..	Secy RTA	17-6-60	Assistant Secy. RTA	27-4-50	350	25	150—250; 27-4-50	300—900; 17-6-60	
22	Shri Lal Singh ..	4-3-18	September, 1945	T.M.	5-9-59	C.I.	28-6-49	375	20	106—200; 28-6-49	350—550; 5-9-59	
23	Shri B. S. Khurana	...	11-12-59	W.M.	11-12-59	..	...	390	20	..	350—550; 11-12-59	
24	Shri Harbans Singh	...	26-6-61	T.M.	26-6-61	..	...	375	20	..	350—550; 26-6-61	
25	Shri Jagdish Chander	...	30-8-50	T.M.	6-2-62	..	...	350	20	...	350—550; 6-2-62	

Payment of Travelling Allowance to Drivers and Conductors of Punjab Roadways, Amritsar

7726. Sardar Trilochan Singh Riasti : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the amount of travelling allowance to the Drivers and Conductors for the period from 1st September, 1964 to date in Punjab Roadways, Amritsar, has been paid ; if so, when ?

(b) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay and the approximate time within which it is likely to be paid ;

(c) the action, if any, proposed to be taken against the officials responsible for the said delay in making the said payment ?

Shri Ram Kishan : (a) No.

(b) The payment of Travelling Allowance for the months of September, October and November, 1964 had been completed by 8th February, 1965. T. A. bill for the month of December, 1964 has been drawn and the payment is being made. The T.A. bills for the months of January and February, 1965 are under preparation.

(c) Question does not arise.

Overtime Allowance to Officials in the Punjab Roadways

***7727. Sardar Trilochan Singh Riasti :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the amount of overtime allowance due to the workshop staff, drivers and conductors working in the Punjab Roadways, Amritsar, for the period from 1st September, 1964 to date, has been paid, if so, when ;

(b) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay, and the approximate time within which it is likely to be paid ;

(c) the action, if any, proposed to be taken against the officials responsible for the delay in making the said payment ?

Shri Ram Kishan : (a) No.

(b) The payment of overtime allowance to the workshop staff, drivers and conductors have been made up to the months of November and December, 1964, respectively on 22nd March, 1965. The remaining bills are ready and would be paid in April, 1965, on receipt of new Budget grants.

(c) Question does not arise.

Permits of Private and Public Buses

***7966. Lieut. Bhag Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of route permits of private and public buses seperately, in force at present Regional Authority wise ;

(b) the number of buses, public and private, actually plying at present, Regional Authority wise ;

(c) the percentage of private and public buses plying at present ;

(d) whether the percentage referred to in part (c) above is based on the 50 : 50 shares ; if not, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

	Jullundur		Ambala		Patiala	
	Public	Private	Public	Private	Public	Private
(a)	576	993	484	600	233	1,002
(b)	493	845	507	640	212	1,007
(c)	37%	63%	44%	56%	20%	80%

(d) According to 50 : 50 scheme, 50 per cent of the route mileage is to be taken over by the Punjab Roadways which has been done in respect of the metalled mileage. Taking over of 50 per cent of the route mileage on Kacha-Pucca routes has commenced. 50 : 50 scheme does not required sharing the buses also on this basis.

In Patiala region, the accepted policy is of 100 per cent nationalisation. More buses are kept by private permitholders as they have more milieage at present as also smaller routes for utilisation of their vehicles.

Fair Price Shops for Rural Areas

***6777. Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that up to December, 1964 no fair price shops for the distribution of imported wheat were opened in the rural areas of the State; if so, the reasons therefor ;

(b) whether any depots for the distribution of imported wheat have been opened in the rural areas after December, 1964 up to now, if so, the names of the places where these have been opened ?

Shri Ram Kishan : (a) No.

(b) Yes, 1,144. The time and labour involved in supplying the information about the location of each of these depots will not be commensurate with any possible benefit to be derived from it.

Sugar Quota for Urban/Rural Areas

***6778. Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the residents in the rural areas are being given less quantity of sugar per head than the people in the urban areas ; if so, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : The consumers in the urban areas of the State are allowed sugar quota at the scale of 1 kilogram per head per month while there is no fixed quantum of issue for consumers in the rural areas of the State as the sugar requirements of villagers vary from place to place The allocation of sugar to the rural areas is being made keeping in view past consumption there and availability of stocks.

Increase in price of American Wheat

***6779. Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the price of American Wheat has been raised by Rs 10 per quintal from 1st January, 1965; if so, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : Yes. The price of imported wheat has been raised from Rs 37.51 to Rs 48 per quintal with effect from the 1st of January, 1965.

The price is determined by the Government of India and not the State Government. They have raised the price to reduce the element of subsidy as in the case of rice also.

Brick kiln Licences

***6833. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of brick kiln licences issued to individuals, district-wise in the State during the last 7 months alongwith the names of persons to whom these have been issued and the places their business.

(b) The criteria kept in view by the authorities while issuing the said licences?

Shri Ram Kishan : A statement containing the requisite information is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a)

Name of District	No. of Kiln issued	Name of parties	Place of business
1. Ambala ..	6	(1) Shri Swinder Singh	Ambala City
		(2) Shri Jagdish Chander	Village Boh
		(3) M/s Thath Singh-Labh Singh	Village Alipur
		(4) Shri Mohinder Singh	Sirhind Canal, Rupar
		(5) M/s Nand Lal & Bros.	P.W.D. Contractor
		(6) M/s Harbans Lal-Harbir Singh	P.W.D. Contractor
2. Simla ..	Nil	Nil	Nil
3. Amritsar ..	2	(1) M/s Tara Singh-Kartar Singh	Village Nonian
		(2) M/s Sunder Singh-Roshan Lal	Village Sangatpura
4. Jullundur ..	9	(1) Shri Surjit Singh, son of Hari Singh	Village Pragpur

Name of District	No. of Kiln issued	Name of parties	Place of business
4. Jullundur—*concld.*		(2) Shri Piara Singh, son of Mara Singh	Village Naugajia
		(3) Shri Balak Chand-Gian Chand	Village Shahkot
		(4) Chakhalan Brick-Kiln Production-cum-Sale Co-operative Society Ltd	Village Chakkalan
		(5) Gram Panchayat, Billi, Bricks Nakodar.	Village Billi Briades
		(6) Mohinder Singh-Madan Lal	Village Kang Khurd
		(7) Bishna Ram Ex-M.L.A.	Village Saloh
		(8) Dina Nath, son of Puran Chand	Village Gunachur
		(9) Shanti Parkash	Village Khiranwali (Kapurthala)
5. Patiala ..	Nil	Nil	Nil
6. Sangrur ..	7	(1) Shri Piara Lal Singla	Village Ramgarh
		(2) Hakikat Rai	Village Samlokalan
		(3) Shri Hargain Singh	Village Khatkar
		(4) Shri Mange Ram	Village Lalitkhera
		(5) Shri Rup Chand	Village Bhayagkhera
		(6) Shri Chattar Singh	Village Gangoli
		(7) Shri Sube Singh	Village Bawana
7. Ferozepore ..	7	(1) Shri Piara Singh, son of Daulat Singh	Village Ferozepur Cantt.
		(2) Shri Gandhi Ram, son of Paras Ram	Village Bilaspur
		(3) Shri Arjan Singh, son of Hukam Singh	Village Muktsar
		(4) The Gram Panchayat	Village Sunher
		(5) Shri Hari Kishan Lal	Village Arniwala
		(6) Shri Chiranji Lal Gagneja	Village Abohar
		(7) Shri Mukand Lal Bhanderi	Village Muktsar
8. Dharamsala ..	Nil	Nil	Nil

[Chief Minister]

Name of district	No. of Kiln issued	Name of parties	Place of business
9. Bhatinda ..	1	(1) Shri Inder Singh, son of Kirpal Singh	Village Kingre
10. Ludhiana ..	1	(1) Shri Navrang Singh	Village Basi Gujran
11. Hissar ..	17	(1) M/s Balkishan Dass-Gulab Chand	Village Siswal
		(2) Shri Bhag Mal, son of Nanak Jat	Village Kharian
		(3) Shri Manohar Lal, son of Benarsi Dass	Village Kalanwali
		(4) M/s Shiv Kumar-Ram Niwas	Village Uklana
		(5) M/s The Gram Panchayat	Village Surtia
		(6) Shri RamsaranDass Bansal	Village Siwani
		(7) M/s Lachhman Dass-Subhash Chand	Village Harauli
		(8) M/s Narain Dass & Co.	Village Dingsara
		(9) Shri Puran Chand Mittal	Village Muklana
		(10) M/s Dewan Chand & Sons	Village Dhand
		(11) Shri Duni Chand, son of Bidh Ram	Village Umara
		(12) M/s Hari Chand Joshi & Co.	Village Mithathal
		(13) Shri Romesh Kumar Maheshwary	Village Jagmalwaii
		(14) M/s Roshan Lal-Babu Ram	Village Dadu
		(15) Shri Gurdev Singh, son of Shri Kaur Singh	Village Barabadi
		(16) Shri Babu Ram, son of Kasturi Lal	Village Goriwala
		(17) Shri Balwant Singh, son of Sher Singh	Village Hussangarh
12. Gurdaspur ..	Nil	Nil	Nil
13. Narnaul ..	2	(1) Shri Onkar Singh, son of Ganpat Singh	Village Kotia
		(2) Shri Om Parkash & Co.	Village Ranila
14. Karnal ..	3	(1) M/s Aggarwal Bhatta Co.	Village Bhana
		(2) M/s Goel Bhatta Co.	Village Dharamgarh
		(3) M/s Sharma Bhatta Co.	Village Uplana
15. Hoshiarpur ..	Nil	Nil	Nil

Name of District	No. of Kiln issued	Name of parties	Place of business
16. Gurgaon ..	9	(1) Shri Megh Raj	Village Khani
		(2) Shri Bhupan, son of Sarpanch	Village Gairatpur
		(3) Shri Mool Chand	Village Rewari
		(4) Shrimati Basanti, w/o Jaisukh Lal	Village Faridabad
		(5) Shri Sant Singh	Village Faridabad
		(6) Shri Kanya Lal Budal	Village Rewari
		(7) M/s Chug Bros.	Villages Gharsaitili and Sikri
		(8) Shri Narinder Dev Kalra	Village Gurgaon
		(9) Shri Sukhbir Singh Kang	Village Ballabgarh
17. Rohtak ..	14	(1) M/s Haryan Brick-kiln Production Society Ltd.	Village Titoli
		(2) Shri Hari Kishan Grotra	Village Lahli
		(3) The Balind Brick-kiln Industrial Co-operative Society	Village Balind
		(4) Shrimati Kalawati Jagbir	Village Bohar
		(5) Shri Prabh Dayal	Village Sheikhupura
		(6) The Thana Rai Labour Co-operaiive Construction Society	Village Kamashpur
		(7) Jemadar Fateh Singh-Mehbub Singh	Village Jhajjar
		(8) Friends Brick-kiln Production-cum-Sale Co-operative Industrial Society	Village Khatiwar
		(9) Tara Chand-Ved Parkash	Village Kostu
		(10) Shri Ram Kishan	Village Kahin
		(11) Shri Mool Chand	Village Rabra
		(12) Shri Harkesh Ram, son of Tikka Ram	Village Mundlana
		(13) Mohinder Singh	Village Saman
		(14) Darya Singh-Jai Singh	Village Menmud Pore
18. Kulu ..	Nil	Nil	Nil

[Chief Minister]

(b) Prior to the 11th August, 1964, the selection of persons/parties for the grant of Brick Kiln Licences was made from amongst political sufferers, social workers, Co-operative Societies, Harijans, Goldsmiths and other deserving persons, etc., in keeping with the Government instructions without any inter-se priorities to the best advantage of the area and the Public. However, under the liberalized policy brick kiln licences are granted by District Magistrate to person whosoever applies provided he fulfils the following conditions :—

(i) The applicant or any members of his family does not hold any interest directly or indirectly in any of the existing brick kiln licences of coal depots or any other depot of controlled commodities under the Food and Supplies Department;

(ii) The site selected by the applicant for setting up kiln is atleast 5 miles from any of the existing kiln ;

(iii) the land selected for the proposed brick kiln is not under agricultural production ;

(iv) the setting up of the proposed kiln conforms to the statutory requirements for the grant of the licence applied for.

Supply of Rice for Free Sale in the Market

***6842. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any rice stocks have recently been made available for free sale to markets ;

(b) the names of major cities and town in the State where the free sale of rice has been introduced ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes.

(b) The State Government is procuring rice on behalf of the Government of India under the Punjab Rice Procurement (Levy) Order, 1958 Under this order, every licensed rice miller/dealer has to deliver to the Punjab Government (Food Department) 2/3rd of the total quantity of rice milled or got milled by him .The balance 1/3rd of the rice is released in favour of the dealers, who are free to sell it any where within the Northern Rice Zone comprising of the State of Punjab and the Union Territories of Delhi and Himachal Pradesh.

Fixing Fair Prices of Hosiery Goods

***7021. Comrade Babu Singh Master :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government intend to fix the fair prices for the hosiery goods in the State, if so, the time by which these are likely to be fixed ?

Shri Ram Kishan : No, Sir.

Increase in prices of Imported Wheat/Atta

***7047. Comrade Jangir Singh Joga :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the price of the imported wheat and atta has been increased recently ; if so, the reasons thereof ?

Shri Ram Kishan : Yes. The prices of imported wheat and its atta are determined by the Government of India.

Supply of Cement in Rural Areas

*7072. **Chaudhri Ran Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the supply of cement in the rural areas of the State is not adequate enough to meet their requirements, if so, the steps taken or proposed to be taken to increase the supply ?

Shri Ram Kishan : Yes, there is acute shortage of cement both in urban and rural areas due to the production not keeping pace with the increasing demands and priority being given by the Government of India in the matter of allotment and supply of cement to consumers like Defence etc. The matter is being constantly pursued with the Government of India for increased allocations and full implementation of the quotas given.

Sugar supplied to the residents of villages situated in Faridkot N.E.S. Block

*7139. **Comrade Babu Singh Master :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the month in which the last supply of sugar was made to the residents of villages situated in the Faridkot N.E.S. Block ;

(b) the name of the month when supply later than that referred to in part (a) above was made to the residents of the said villages and the reasons for not supplying them sugar during the intervening period ;

(c) whether it is a fact that the Co-operative Marketing Union responsible for supplying sugar to the said villages was allotted sugar from the Mills of U.P., if so, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : (a) October, 1964.

(b) January, 1965. During the months of November and December, 1964, no supply of sugar was made to consumers as no stocks could be transported from the sugar factories in U.P. by the Co-operative Federation on account of railway booking restrictions and non-availibilty of rail wagons. This quantity was ultimately moved by road in January, 1965, and distributed to consumers in the same month.

(c) Yes, because 2/3rd of the State monthly sugar quota is allocated by the Government of India from the sugar factories in U.P. and only 1/3rd from the sugar factories in Punjab.

Starred Question No. 7983

Subject : —Representation Complaint from Military Personnel regarding illegal occupation of land.

The answer to Starred Assembly Question No. 7983 on the above subject asked by Shri Jagir Singh Dard, M.L.A. appearing in the list of Questions for 24th March, 1965 is not ready as the information is awaited from Deputy Commissioner, Amritsar who has been requested to furnish it. This information is sent to the Speaker who is requested to extend the time for answering this Question, under *proviso* (ii) to rule 41 of the Rules of Procedure ane Conduct of Business in Punjab Legislative Assembly. This question may kindly be included in the list of Questions for any date after 8th April, 1965.

Sd. Chief Minister, Punjab.

To

The Speaker,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U. O. No. 3545—9HM—65. dated the 22nd March, 1965.

Cases registered against hoarders and Black-marketeers

*6832. **Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the number of cases registered in the State against hoarders and black-marketeers during the last seven months ?

Sardar Darbara Singh : 394 cases.

Death of one Dalip Singh Harijan of village Aklia, district Bhatinda, in Police Custody

*7143. **Comrade Jangir Singh Joga** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that one Dalip Singh Harijan of village Aklia, district Bhatinda, was arrested by the Police and he died in Police Custody ;
(b) whether it is also a fact that his dead body was not handed over to his relatives ;
(c) if answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the circumstances in which his death occured and also the reasons for not handing over the dead body to his relatives ;
(d) whether any enquiry into the said incident has been held, if so, with what result ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) No.

(c) Dalip Singh, son of Inder Singh was, arrested on 17th January, 1965 in execution of a warrant of arrest issued by M.I.C., Mansa in connection with case FIR No. 154, dated the 18th May, 1964 under section 325/324/506, I.P.C.,P.S. Mansa. He was lodged in the lock-up of P.S. Mansa on 17th January, 1965, at 7.30 p.m. and was found dead on the next morning at 8.30 a.m.

(d) Yes. Result of enquiry still awaited.

Seniority List of Secretariat Employees

*8004. **Shri Brish Bhan** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the date on which the Government of India communicated to the Punjab Government their final decision on the seniority list of the Secretariat Employees (Assistant to Superintendent Group);

(b) whether the list so approved by the Government of India has been given effect to with effect from 1st November, 1956, if not, the reasons therefor ;

(c) whether it is a fact that the employees declared senior have not been given their due positions and status while their juniors are holding higher posts;

(d) whether it is a fact that the Government of India have been repeatedly asking the Government to implement their decisions in this behalf with effect from 1st November, 1956 as has been done in the other States throughout India;

(e) the details of the correspondence that took place between the Government of India and the State Government in this respect be placed on the table of the House ?

Sardar Darbara Singh : (a) 12th October, 1964.

(b) Yes, in the equated ranks as held on 1st November, 1956.

(c) Accordng to the instructions issued by the Punjab Government in consultation with he Government of India, promotions are to take effect from the dates on which these are ordered and seniority in promoted ranks

counts from the date of officiation in such higher ranks. All the employees have been given positions according to these instructions and the question of supersession of any employees does not arise.

(d) The final decisions of the Government of India fixing seniority in the equated ranks as held on 1st November, 1956 have since been implemented. The question of adjustment of seniority in the promoted ranks is, however, under consideration of the State Government in consultation with the Central Government and will be decided before long.

(e) The matter is *sub-judice* and the original correspondence is in the High Court.

Inclusion of Mukerian Block in Hilly Blocks

***7774. Principal Rala Ram** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Dasuya Block has been included in the Hilly Blocks, whereas Mukerian Block has not been so included although both the Blocks have sub-mountainous area within their jurisdiction ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether Government has received any representation from the Block Samiti, Mukerian, for categorising the Mukerian Block as Hilly Block, if so, the action, if any, taken thereon ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes, but Mukerian Block has not been included in the Hill Areas as it does not come within the definition thereof.

(b) No.

Panchayats

***7481. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the names of the villages in the State, districtwise, where Panchayats have not been established so far;

(b) whether Government propose to establish Panchayats in the villages referred to in part (a) above before the end of the current year ?

Sardar Darbara Singh : The information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The names of the villages in State, districtwise, where Panchayats have not been established so far are given below :—

Serial No.	Name of District	Names of the villages where Panchayats have not been established
1	Gurdaspur ..	1. Sheikhowal
		2. Alipur Berah
2	Jullundur	1. Gidderpindi
		2. Gazipur
		3. Bir Phillaur

(Minister for Home and Development)

Serial No.	Name of District	Names of the villages where Panchayats have not been established
3	Ferozepur	1. Chak Romewala 2. Koel Khera 3. Janisar 4. Lohra Nawab Sahib 5. Nathu Chisti
4	Bhatinda	1. Manuana
5	Karnal	1. Hansu Majra 2. Matak Majri

(b) Yes.

Complaints against Block Development and Panchayat Officer, Nihalsingh Wala, District Ferozepur

***7605. Comrade Gurbux Singh Dhaliwal :** Will the Minister for Home and Development with reference to the reply to the starred Question No. 6431 included in the list of questions for 21st September, 1964 be pleased to state—

(a) whether the enquiries referred to in the statement annexed to the said reply have since been conducted and completed by the D.C./D.D. and P.O., Ferozepur, if not, the reasons therefor ;

(b) whether the complaints were present at the time of the enquiries if held, if not, the reasons therefor ;

(c) whether any fresh cmplaints against the B.D. and P.O. have been received during the period from 14th August, 1964 to date, if so, the dates of their receipt, the dates of their disposal and the details of the action, if any, taken, thereon ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes .

(b) In some cases complainants were present at the time of enquiries, while in others they were not summoned as the Inquiry Officer did not think it necessary to do so.

(c) Yes. The dates of receipt of complaints and their disposal and details of the action taken thereon are given in the enclosed statement.

STATEMENT

Serial No.	Name of the Complainant	Date of receipt	Date of disposal	Action taken
1	Shri Gurbux Singh M.L.A.	20-10-64	26-2-65	On enquiry allegations against the B.D. and P.O. have remained unsubstantiated

Loss caused to Citrus Plants and Cotton Crop in the State

***6905. Comrade Jangir Singh Joga :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether any survey has been conducted by the Horticulture Department, Punjab, to assess the loss to citrus plants in the state and to the cotton crop by early frost this year ;

(b) the estimated loss caused to the plants and crop mentioned in part (a) above, respectively, and the areas which have been so affected ?

Sardar Darbara Singh : (a) No regular suervey has been done.

(b) By rough estimates about 10 to 15 per cent loss has been caused on ursery and young citrus (malta) plantations in Abohar area. No loss on early varieties of cotton, viz., H-14, 320-F and Desi has been caused. However L.S.S., a late maturing variety grown in Fazilka and Muketsar tahsils of Ferozepur District has been affected adversely to some extent but the damage is not appreciable to warrant any special survey.

Construction of Godowns

***7994. Shri Ram Dhari Gaur :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether the Government in the Co-operative Department is considering any proposal to construct Co-operative Rural godowns for use by the Agricultural Service Co-operative Societies in the State, if so, the number of such godowns proposed to be constructed in the Punjabi and the Hindi regions separately?

Sardar Darbara Singh :(i) Yes.

(ii) (a) Hindi Region .. 348

(b) Punjabi Region .. 518

Co-operative Marketing Society Rewari

***6860. 1. Chaudhri Khurshed Ahmad**
2. Rao Nihal Singh : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether the Co-operative Marketing Society Rewari has been running at a loss or profit;

(b) the number and names of Managers who have worked in the said Co-operative Marketing Society so far together with tenure of their office in each case;

(c) the profit or loss of the said Society during the tenure of each of these Managers separately;

(d) whether the said Society is having any Manager at present, if not, the reasons therefor;

(e) the reasons for which the Managers of the said Society working earlier left the Society;

(f) whether any of the Managers who have worked previously in the said Society had applied to work as a Manager after completing any period of leave or otherwise, if so, a copy of such applications be laid on the Table of the House;

(g) the action taken by the Government on such representation or representations, if not taken, the reasons therefor?

Sardar Darbara Singh: (a) to (g): Requisite information is laid on the table of the House.

[Minister for Home & Development]

STATEMENT

(a) Profit.

(b) One wholetime Manager, besides three departmental officials who have been acting as Managers in addition to their own duties as per details given below:

Serial No.	Name of Manager	Tenure of Office		
		From	To	
1	Shri Rajinder Singh ..	7-3-63	28-1-64	
2	Shri Sher Singh, Departmental Sub-Inspector	29-1-64	27-3-64	Acted as Manager in addition to his own duty
3	Shri Surat Singh, departmental Inspector	28-3-64	28-7-64	Ditto
4	Shri Kanwal Singh, departmental Inspector	29-7-64	Continues	Acted as Manager in addition to his own duties up to 7th October, 1964 and from 8th October, 1964 onwards working as an Administrator of the Society

(c)

Serial No.	Name of the Manager		Amount of Profit	Amount of Loss
			Rs.	Rs.
1	Shri Rajinder Singh	..	16,465.33	..
2	Shri Sher Singh	..	..	2,652.92
3	Shri Surat Singh	..	12,608.18	..
4	Shri Kanwal Singh	..	8,953.91	..

(d) No. The Managing Committee of the said Society having been superseded, the affairs of the Society are presently managed by an Administrator appointed by the department.

(e) (1) Shri Rajinder Singh — Proceeded on three months leave expiring on 26th April, 1964 and did not join thereafter.

(2) Shri Sher Singh — Placed under suspension having committed serious irregularities in the working of the Society.

(3) Shri Surat Singh — Replaced by Shri Kanwal Singh the present Administrator of the Society on administrative grounds.

(f) Yes, only Shri Rajinder Singh. A copy of his petition dated 4th December, 1964, is enclosed.

(g) The petition referred to under para (f) above is under active consideration.

To

Hon'ble S. Darbara Singh,
Home & Development Minister,
Chandigarh.

Subject.—Redress against the victimisation committed in the times of Sardar Partap Singh Kairon ex-Chief Minister, Punjab.

SIR,

The petitioner beg to submit as follows:

The petitioner was appointed as Managers on 7th March, 1963 by the Managing Committee of the marketing society, Rewari.

The petitioner by dint of hard labour and honesty earned a profit of Rs 8000-to the said society.

That Sardar Partap Singh Kairon effected political reproachment with Rao Birendra Singh, M.L.C. and Rao Birendra Singh forced him to exist under pressure upon me to apply for three months forced leave.

That Sardar Partap Singh wanted to oblige Rao Birendra Singh in consideration of fresh reproachment and he instructed the D.R., Rohtak to take a forced application of three months leave from the petitioner.

The then Deputy Registrar in order to save his own position, achieved through undue promotion, forced me to apply for three months' leave, failing which, the applicant was threatened to be implicated in false criminal cases.

As the petitioner seemed no way out the petitioner applied for three months forced leave on 27th January, 1964.

The leave of the petitioner expired on 26th March, 1964 but the petitioner was not allowed to resume duty as the influence of Rao Birendra Singh was still prevailing.

Since then the petitioner has remained unemployed.

That as the period of terror and victimisation has come to an end, the petitioner beg to approach your honour with a request that the Deputy Registrar, Co-operatives Socities, Rohtak may be asked to order the Administrator of the society to order the petitioner to resume duty of the Manager of the said society.

Thanking you,

Dated the 4th December, 1964.

Yours faithfully,
Sd./ RAJINDERA SINGH,
S/o Rao Ramji Lal,
Village & Post Office, Pithrawas,
tehsil Rewari,
District Gurgaon.

Passenger tax in the Punjab

*7142. **Comrade Babu Singh Master** : Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state whether Government intend to modify or change the current system of collecting passenger tax in the state, if so, when and the reasons therefor ?

Sardar Kapoor Singh : Part I. No.
Part II. Does not arise.

System of Recovery of Passenger Tax from Private Passengers Transport Companies

***7930. Shri Fateh Chand Vij** : Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to change the present system of recovery of passenger tax from the private passengers Taransport Services in the State ; if so, the details thereof and the date from which the new system is expected to come into force ?

Sardar Kapoor Singh : Part I. No.
Part II and Part III Does not arise.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Hill Compensatory Allowance

2432. Shri Jit Ram : Will the Minister for finance and planning be pleased to state—

(a) the names of the Hill Stations where hill compensatory allowance is at present, being given to Government employees drawing pay between Rs 350 and 850 p.m. and the date from which it is being given ;

(b) whether the said allownace is being given to Government employees stationed at Kulu, if so , from which date ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Kapoor Singh : (a) The whole of Kangra District.
The whole of Simla district.
Dhar Kalan Block of Gurdaspur district.

Nalagarh, Raipur Rani, Naraingarh and Bilaspur blocks of Ambala District.

Amb, Gagret, Una and Nurpur Bedi Blocks of Tehsil Una and Hajipur Block of Dasuya Tehsil of Hoshiarpur District.
w.e.f. 1st January, 1964.

(b) As the Government employees stationed at Kulu are already in receipt of higher rates of Compenstory Allownace as compared to the places mentioned at (a) above, the question of giving the said allowance does not arise.

Construction of Narwana Tohana Road

2433. Shri Fakiria : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to include the construction of a road from Narwana to Tohana, over a length of about 20/22 miles in

the current plan so as to provide a direct road from Delhi to Ferozepur via Tohana ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the said road will pass through Dharodi, Laun, Dhamtan Sahib and kalwan village and will join the Hissar road which already passes across the Bhakra Canal, thereby obviating the necessity of constructing another bridge near Tohana over the said Canal ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No ; not in the III Plan. Its inclusion in the IV Plan is, however, under consideration.

(b) Its alignment will be decided after carrying out a detailed survey when the road comes up for actual construction.

Free travel passes for students in certain areas of Amritsar District.

2434. **Comrade Makhan Singh Tarsikka** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the students, whith their parentage and addresses who have been issued free passes to travel by Buses belonging to the Amritsar and Jullundur Depots of the Punjab Roadways in the areas of the Rayya, Jandiala, Chogawan and Verka Blocks of the Amritsar district separately, during 1964-65 together with the names of the routes for which these passes have been issued in each case ;

(b) the names ofthe students in the said areas with their addresses whose applications are still pending with the department and the names of those whose applications were rejected during the said period together with the dates when they submitted their aplications ;

(c) the criteria kept in view while issuing free passes to the students ?

Shri Ram Kishan : (a) The information is given in the enclosed statements.

(b) No applications are pending. Applications which do not fulfil the required conditions are, however, rejected, and returned to the applicants at the time of their presentation.

(c) Free passes are issued to the bonafide students of recognised Institutions on the production of a certificate by the Head of the Institution concerned to the effect that the student is financially weak and is unable to afford payment of fare as follows—

(i) To all students upto and including 10th class in flood affected areas.

(ii) To all girl students upto 10th class.

(iii) To all boy students upto and including 8th class.

[Chief Minister]

Statement relating to the issue of Free Passes by Punjab Roadways Jullundur

Serial No.	Name of students	Father's Name	School	From	To
1	2	3	4	5	6
1	Shrimati Vijay Kumari	Shri Bachan Singh	Government Girls High and Basic School, Rayya	Beas	Rayya
2	Shrimati Saraj Lata	Ditto	Ditto	Do	Do
3	Shrimati Surinder Jit	Shri Karam Singh	Ditto	Do	Do
4	Shrimati Surinder Kaur	Shri Man Singh	Shahid Gehal Singh High School, Tangra	Rayya	Tangra
5	Shrimati Joginder Kaur	Shri Suba Singh	Ditto	Do	Do
6	Shri Devinder Kumar	Shri Sham Singh	Government Model School, Rayya	Beas	Rayya
7	Km. Surinder Paul	Shri Dutta Ram	Government Girls High and Basic School Rayya	Do	Do
8	Shrimati Amarjit	Shri Rattan Singh	Ditto	Do	Do
9	Shrimati Inderjit	Shri Amar Singh	Ditto	Do	Do
10	Shrimati Shashi Bala	Shri Ram Chand	Ditto	Do	Do
11	Shrimati Santokh Kaur	Shri Charan Singh	Ditto	Do	Do
12	Shrimati Satwant Kaur	Shri Arjan Singh	Shahid Gehal Singh Higher Secondary School, Tangra	Rayya	Tangra
13	Shrimati Asha Rani	Shri Lakhbir Singh	Government Girls High and Basic School Raya	Beas	Rayya

14	Shrimati Amarjit	Shri Sant Singh	Ditto	Do	Do
15	Shrimati Sarla Devi	Shri Gurdhan Dass	Ditto	Do	Do
16	Shrimati Balwant Kaur	Shri Gurdit Singh	Ditto	Do	Do
17	Shrimati Shakuntla Devi	Shri Lakshma Dass	Ditto	Do	Do
18	Shrimati Ranjit Kaur	Shri Charan Singh	Ditto	Do	Do
19	Shri Surjit Singh	Shri Gurbax Singh	Government Model School, Rayya	Do	Do
20	Shri Hari Chand	Shri Munshi Ram	Ditto	Do	Do
21	Shri Harbhajan Singh	Shri Teja Singh	Ditto	Do	Do
22	Shri Bhupinder Singh	Shri Hardev Singh	Ditto	Do	Do
23	Km. Paramjit	Shri Sohan Singh	Government Girls High and Basic School, Rayya	Kichar	Do
24	Shri Balwant Singh	Shri Mewa Singh	Government Model School, Rayya	Beas	Do
25	Shri Mohinder Singh	Shri Jail Singh	Ditto	Do	Do
26	Shri Sardar Singh	Shri Darshan Singh	Ditto	Do	Do
27	Shri Ashok Kumar	Shri Om Parkash	Ditto	Do	Do
28	Shri Gurdial Singh	Shri Mohan Singh	Ditto	Do	Do
29	Shri Inderjit Singh	Shri Gurcharan Singh	Ditto	Do	Do
30	Km. Bhupinder	Shri Sohan Singh	Government Girls High and Basic School, Rayya	Kichar	Do
31	Km. Ranjit Kaur	Shri Rewal Singh	Ditto	Do	Do
32	Km. Surjit Kaur	Shri Thakur Singh	Ditto	Do	Do
33	Km. Parkash Devi	Shri Lachhman Dass	Ditto	Beas	Do

[Chief Minister]

1	2	3	4	5	6
Serial No.	Name of Student	Father's name	School	From	To
34	Kumari Daljit Kaur	Shri Buta Singh	Shahid Gehal Singh Higher Secondary School, Tangra	Jandiala	Tangra
35	Kumari Balbir Kaur	Shri Prem Singh	Ditto	Beas	Do
36	Shri Karnail Singh	Shri Bir Singh	Government Model Middle School, Rayya	Do	Rayya
37	Shri Karnail Singh	Shri Teja Singh	Government Girls High and Basic School, Rayya	Do	Do
38	Shri Vijay Kumar	Shri Daulat Ram	Government Model School Rayya	Do	Tangra
39	Kumari Balbir Kaur	Shri Karam Singh	Shahid Gehal Singh High School, Tangra	Kichan	Do
40	Kumari Vir Kaur	Shri Karam Singh	Ditto	Do	Do
41	Kumari Joginder Kaur	Shri Charan Sihgh	Ditto	Do	Do
42	Kumari Balinder Kaur	Shri Charan Singh	Ditto	Do	Do
43	Kumari Kulwant Kaur	Shri Harnam Singh	Ditto	Do	Do
44	Kumari Gurdev	Shri Jagir Singh	Ditto	Do	Do
45	Kumari Lakbir Kaur	Shri Gurcharn Singh	Ditto	Do	Do
46	Kumari Harinder Pal Kaur	Shri Shangra Singh	Ditto	Rayy	Do
47	Kumari Narinder	Shri Uttam Singh	Ditto	Do	Do
48	Kumari Sutinderjit	Shri Amar Singh	Ditto	Khichan	Rayya

49	Kumari Saroj Bala	Shri Inderjit Sharma	Government Girls High and Basic School, Rayya	Beas	Rayya
50	Kumari Yash Bala	Shri Inderjit Sharma	Ditto	Do	Do
51	Kumari Kulvinder Kaur	Shri Dharam Singh	Ditto	Do	Do
52	Kumari Lakhbir Kaur	Shri Charan Singh	Ditto	Do	Do
53	Kumari Kanta Devi	Shri Pritam Singh	Ditto	Do	Do
54	Kumari Narinder Kaur	Shri Mukhtar Singh	Shehid Gehal Singh High School, Tangra	Butari	Tangra
55	Kumari Surjit Kaur	Shri Karam Singh	Ditto	Do	Do
56	Kumari Narinder	Shri Pritam Singh	Government High and Basic School, Rayya	Beas	Rayya
57	Shri Suwaran Singh	Shri Rewal Singh	Government Model Higher Secondary School, Rayya	Do	Do
58	Shri Avtar Singh	Shri Karam Singh	Ditto	Do	Do
59	Kumari Gurnam Kaur	Shri Gian Singh	Shahid Gehal Singh Hingh School, Tangra	Butari	Tangra
60	Kumari Amarjit Kaur	Shri Shangra Singh	Ditto	Do	Do
61	Shri Kulijt Singh	Shri Prem Singh	Government Model School, Rayya	Do	Rayya
62	Shri Surjit Singh	Shri Prem Singh	Ditto	Do	Do
63	Shri Beena Kumar	Shri Prem Singh	Ditto	Do	Do
64	Shri Jagdish Chander	Shri Kishan Dass	Ditto	Beas	Do
65	Shri Jagiro Ram	Shri Nathu Ram	Ditto	Do	Do
66	Kumari Indra Kumari	Shri Naranjan Dass	Government Girls High and Basic School, Rayya	Do	Do
67	Kumari Ljeri Devi	Shri Balwant Rai	Ditto	Do	Do
68	Kumari Jagdish Kaur	Shri Teja Singh	Shehid Gehal Singh High School, Tangra	Bhutari	Tangra

[Chief Minister]

1	2	3	4	5	6
Serial No.	Name of Student	Fathers name	School	From	To
69	Kumari Satnam Kaur	Shri Puran Singh	Shehid Gehal Singh High School, Tangra	Bhutari	Tangra
70	Kumari Diljeet Kaur	Shri Hari Singh	Ditto	Do	Do
71	Kumari Savinder Kaur	Shri Karam Singh	Ditto	Rayya	Do
72	Kumari Jasbir Kaur	Shri Achar Singh	Ditto	Do	Do
73	Kumari Satjit Kaur	Shri Rewal Singh	Ditto	Do	Do
74	Kumari Gurmit Kaur	Shri Achhar Singh	Ditto	Do	Do
75	Shri Jagan Nath	Shri Gobind Ram	Government Model School, Rayya	Beas	Rayya
76	Kumari Shaghi Bala	Shri Gobind Ram	Government Girls High and Basic School, Rayya	Do	Do
77	Kumari Kamlesh Kumari	Shri Nanak Chand	Ditto	Do	Do
78	Kumari Nirmal Kanta	Shri Karam Chand	Ditto	Do	Do
79	Kumari Jaspinder Kaur	Shri Avtar Singh	Shehid Gehal Singh High School Tangra	Rayya	Tangra
80	Kumari Sukhir Kaur	Shri Gurcharan Singh	Ditto	Malian	Do
81	Kumari Narinder Kaur	Shri Partap Singh	Do	Rayya	Do
82	Kumari Harjinder Kaur	Shri Randhir Singh	Ditto	Do	Do
83	Kumari Harbhajan Kaur	Shri Mohan Singh	Ditto	Do	Do

84	Kumari Palwinder Kaur	Shri Sadhu Singh	Ditto	Do	Do
85	Kumari Mohinder Kaur	Shri Charan Singh	Ditto	Do	Do
86	Kumari Vinay Kumari	Shri Tirath Ram	Government Girls Higher Scondary School, Rayya	Beas	Rayya
87	Kumari Harbhajan Kaur	Shri Prem Singh	Ditto	Do	Do
88	Kumari Sudesh Kumari	Shri Faqir Chand	Ditto	Do	Do
89	Kumari Manjinder Kaur	Shri Buta Singh	Ditto	Do	Do
90	Shri Mohinder Singh	Shri Buta Singh	Government Model School, Rayya	Do	Do
91	Shri Avtar Singh	Shri Atma Singh	Ditto	Do	Do
92	Shri Harbans Lal	Shri Hari Singh	Ditto	Do	Do
93	Kumari Kushvir Kaur	Shri Sadhu Singh	Shehid Gehal Singh High School, Tangra	Rayya	Tangra
94	Kumari Balwant Kaur	Shri Hira Singh	Ditto	Butari	Do
95	Kumari Sukhwant Kaur	Shri Parsa Singh	Ditto	Do	Do
96	Kumari Prisin Kaur	Shri Banta Singh	Ditto	Rayya	Do
97	Kumari Jagir Kaur	Shri Amrik Singh	Ditto	Do	Do
98	Kumari Harjinder Kaur	Shri Moga Singh	S.M. Girls High School, Baba Bakala	Butari	Baba Bakala
99	Kumari Kalash	Shri Faqir Chand	Ditto	Do	Do
100	Kumari Sudesh Kumari	Shri Mela Ram	Ditto	Do	Do
101	Shri Gurnam Chand	Shri Sohan Singh	Government Model School, Rayya	Beas	Rayya
102	Kumari Narinder Kaur	Shri Lachham Singh	S.M. Girls High School, Baba Bakala	Ghagal Bharan	Baba Bakala
103	Shri Surinder Singh	Shri Ram Nath	B.K. Higher School, Amritsar	Tangra	Amritsar
104	Kumari Jagit Kaur	Shri Ranjinder Singh	Shehid Gehal Singh High School, Tangra	Butari	Tangra

[Chief Minister]

1	2	3	4	5	6
Serial No.	Name of Students	Father's name	School	From	To
105	Shri Om Parkash	Shri Harnam Singh	Government Model School, Rayya	Beas	Rayya
106	Shri Gurdial Singh	Shri Amar Singh	Ditto	Do	Do
107	Shri Balwant Singh	Shri Rattan Singh	Ditto	Do	Do
108	Shri Kulwant Singh	Shri Rattan Singh	Ditto	Do	Do
109	Shri Rajinder Parkash	Shri Dawarka Dass	Ditto	Do	Do
110	Shri Vijay Kumar	Shri Kidar Nath	Ditto	Do	Do
111	Shri Karamjit Singh	Shri Mohan Singh	S.M. Girls High School. Baba Bakala	Do	Baba Bakala
112	Kumari Surinder Kaur	Shri Gian Singh	Shahid Gehal Singh Girls High School Tangra	Rayya	Tangra
113	Kumari Madhu Bala	Shri Prem Nath	Government Girls High and Basic School. Rayya	Beas	Rayya
114	Kumari Paramjit	Shri Sohan Singh	Ditto	Khalchi	Tangra
115	Kumari Surinder Kaur	Shri Surbkh Singh	Shehid Gehal Singh Girls High School Tangra	Rayya	Khalchi
116	Shri Kashmir Singh	Shri Hazara Singh	Janta High School, Khalchian	Khalchian	Rayya
117	Kumari Kanta Rani	Shri Chanti Lal	Government High School, Rayya	Beas	Do
118	Shri Tarlok Singh	Shri Ajit Singh	Government High School, Rayya	Khalchian	Do

119		Shri Daljit Singh	Ditto	Beas	Do
120	Kumari Santosh Kumari	Shri Ganda Ram	Government High School, Jandiala	Butari	Jandiala
121	Kumari Asha Rani	Shri Ganda Ram	Ditto	Do	Do
122	Kumari Veena Kaur	Shri Lachman Dass	Government Girls High and Basic School, Rayya	Beas	Rayya
123	Kumari Baljit	Shri Inder Singh	Shehid Gehal Singh High School, Tangra	Malhi	Tangra
124	Kumari Gurmit	Shri Inder Singh	Ditto	Do	Do
125	Kumari Harjinder Kaur	Shri Sohan Singh	Ditto	Do	Do
126	Kumari Sukbir Kaur	Shri Gurcharan Singh	Ditto	Do	Do
127	Kumari Vidya Devi	Shri Bhan Singh	Government Girls Middle School, Rayya	Beas	Rayya
128	Kumari Amarjit Kaur	Shri Ram Singh	S.M.G. Girls High School, Baba Bakala	Ghaggal Bhan	Baba Bakala
129	Shri Kulbir Singh	Shri Pal Singh	Janta High School, Khalchian	Rayya	Khalchian
130	Shri Harbhajan Singh	Shri Santa Singh	Government Model School, Rayya	Beas	Rayya
131	Shri Dalbir Singh	Shri Tora Singh	Shehid Gehal Singh High School, Tangra	Khalchian	Tangra
132	Shri Jaswant Singh	Shri Pritam Singh	Government Model School, Baba Bakala	Beas	Baba Bakala
133	Kumari Sukhinder	Shri Gurpal Singh	Shehid Gehal Singh High School, Tangra	Mulian	Tangra
134	Kumari Virjinder Kaur	Shri Gurdial Singh	Ditto	Do	Do
135	Kumari Santokh	Shri Pritam Singh	Ditto	Khalchian	Do
136	Shri Mohan Singh	Shri Sohan Singh	Janta High School, Khalchian	Rayya	Khalchian
137	Kumari Gurmit Kaur	Shri Lukhbir Singh	Government Middle School, Chhajjalwaddi	Do	Do
138	Shri Kuljit Singh	Shri Pritam Singh	Government Middle School, Rayya	Beas	Rayya

[Chief Minister]

1	2	3	4	5	
Serial No.	Name of Students	Father's name	School	From	To
139	Shri Iqbal Singh	Shri Mukhtar Singh	Government Middle School Rayya	Beas	Rayya
140	Shri Malkit Singh	Shri Nagar Singh	Janta High School, Khichian	Do	Khichian
141	Shri Joginder Singh	Shri Shangara Singh	Ditto	Do	Do
142	Shri Gian Singh	Shri Banta Singh	Ditto	Do	Do
143	Kumari Surinder	Shri Magar Singh	Government High School, Tangra	Do	Do
144 *	Shri Harjinder Singh	Shri Harnam Singh	Janta, High School, Khichian	Rayya	Khichian
189	Kumari Balwant Kaur	Shri Gurdit Singh	Government Girls High School, Rayya	Beas	Rayya
190	Kumari Saroj Lata	Shri Bachan Singh	Ditto	Do	Do
191	Kumari Vijay Kumari	Shri Bachan Singh	Ditto	Do	Do
192	Kumari Parkash Devi	Shri Lakshma Dass	Ditto	Do	Do
193	Kumari Inderjit	Shri Gurcharan Singh	Ditto	Do	Do
194	Kumari Benna Kumari	Shri Lakshmi Dass	Ditto	Do	Do
195	Kumari Jaswant Kaur	Shri Hardial Singh	Government High School, Tangra	Jandiala	Tangra
196	Kumari Balwinder Jit	Shri Surat Singh	S.M.G.G. High School, Baba Bakala	Butari	Baba Bakala
197	Kumari Balbir Kaur	Shri Udham Singh	Shehid Gehal Singh, Girls High School, Tangra	Rayya	Tangra
198	Shri Paramjit Singh	Shri Teja Singh	Government Middle School, Baba Bakala	Beas	Baba Bakala

**Note*—Statement Printed as received from Government.

199	Kumari Kashmir Kaur	Shri Sardara Singh	Shehid Gehal Singh Girls High School, Tangra	Rayya	Tangra
200	Kumari Gurdip Kaur	Shri Bahad Singh	Ditto	Do	Do
201	Kumari Prisin Kaur	Shri Banta Singh	Ditto	Do	Do

[Chief Minister]

PASSES ISSUED BY PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR

LIST OF FREE PASSES ISSUED IN JANDIALA BLOCK

Serial No.	Name of student	Class No.	Name of the route	Name of the School
1	Shri Nirmal Singh	9th	Manawala to Jandiala	Government Higher Secondary School, Jandiala Guru
2	Bibi Veena Kumari	6th	Ditto	Government Girls Higher Secondary School, Jandiala
3	Bibi Kulbir Kaur	9th	Bundhla to Jandiala	Ditto
4	Shri Jasbir Singh	8th	Ditto	Government Higher Secondary School, Jandiala
5	Bibi Permjit Kaur	9th	Ditto	Government Higher (Girls) Secondary School, Jandiala
6	Shri Major Singh	7th	Ditto	Government Higher Secondary School, Jandiala
7	Shri Gurcharan Singh	8th	Daburji to Amritsar	Ditto
8	Shri Jaswant Singh	8th	Ditto	Ditto
9	Shri Didar Singh ..	8th	Ditto	Ditto
10	Shri Ashwani Kumar	9th	Manawala to Jandiala	Ditto
11	Shri Puran Singh	6th	Ditto	Ditto
12	Shri Didar Singh ..	6th	Daburji to Amritsar	Government Higher Secondary School, Amritsar
13	Bibi Salwainder Kaur	8th	Bundala to Jandiala	Government Girls Higher Secondary School, Jandiala
14	Shri Jaswant Singh	8th	Ditto	Government Higher Secon - dary School, Jandiala
15	Shri Gurdip Singh	9th	Manawala to Jandiala	Ditto
16	Shri Nirander Paul	9th	Bundala to Jandiala	Ditto
17	Shri Ram Rattan ..	10th	Ditto	Ditto
18	Shri Sardara Singh	6th	Daburji to Amritsar	Government Higher Secon - dary School, Amritsar
19	Bibi Santosh Kaur	6th	Ditto	Government Girls Higher Secondary School, Amritsar
20	Shri Pritam Singh	9th	Ditto	Government Higher Secon - dary School, Amritsar
21	Bibi Surinder Kaur	8th	Manawala Jandiala	Government Girls Higher Secondary School, Jandiala
22	Bibi Balwinder Kaur	8th	Bundala to Jandiala	Ditto

Serial No.	Name of student	Class No.	Name of the route	Name of School
23	Shri Gurcharan Singh	6th	Daburji to Amritsar	Government Higher Secondary School, Amritsar
24	Shri Amar Singh ..	8th	Ditto	Ditto
25	Shri Dhanwant Singh	8th	Bundala to Jandiala	Government High School, Jandiala
26	Shri Jarnail Singh	8th	Ditto	Ditto
27	Shri Harbhajan Singh	6th	Shafipur to Tarn Taran	S.D. High School, Tarn Taran
28	Shri Gurbhajan Singh	6th	Ditto	Ditto
29	Shri Parwinder Singh	6th	Manawala to Jandiala	Government High School, Jandiala
30	Shri Surinder Singh	7th	Ditto	Ditto
31	Shri Tarsem Singh	6th	Daburji to Amritsar	Government High School, Amritsar
32	Shri Satish Kumar	7th	Ditto	Government High School, Jandiala
33	Shri Amar Singh ..	6th	Shaffipur to Tarn Taran	Government High School, Tarn Taran
34	Bibi Nirmal Kaur	10th	Bundala to Jandiala	Government High School, Jandiala (Girl)
35	Shri Rattan Singh	7th	Daburji to Amritsar	Government High School, Amritsar
36	Shri Banta Singh ..	8th	Shaffipur to Tarn Taran	Government High School, Tarn Taran
37	Shri Nand Singh ..	8th	Ditto	Ditto
38	Shri Nirmal Singh..	6th	Ditto	Ditto
39	Bibi Gurbachan Kaur	7th	Jandiala to Amritsar	Government Girls High School, Amritsar
40	Bibi Sukhminder Kaur	7th	Bundala to Jandiala	Government High School, Jandiala
41	Shri Kashmir Singh	9th	Bundala to Tarn Taran	Government High School, Tarn Taran
42	Bibi Gurmukh Kaur	8th	Bhagatupur to Jandiala	Government High School, Jandiala (Girl)
43	Shri Jaswant Singh	7th	Khabe Dograin to Bundala	Government Middle School, Bundala
44	Shri Ramesh Kumar	8th	Bhagatopur to Jandiala	Government High School, Jandiala
45	Shri Anup Singh ..	6th	Daburji to Amritsar	Ram Garhia High School, Amritsar

[Chief Minister]

Serial No.	Name of student	Class No.	Name of the route	Name of School
46	Shri Gurbachan Singh	9th	Shaffipur to Tarn Taran	Government High School, Tarn Taran
47	Bibi Manjit Kaur ..	9th	Bundala to Tarn Taran	Government Girls High School Tarn Taran
48	Bibi Asha Rani ..	9th	Ditto	Ditto
49	Bibi Rajinder Kaur	9th	Ditto	Ditto
50	Bibi Narinder Kaur	10th	Ditto	Ditto
51	Bibi Charan Kaur	10th	Ditto	Ditto
52	Bibi Anup Kaur ..	9th	Ditto	Ditto
53	Bibi Updesh Kaur	10th	Shaffipur to Tarn Taran	Ditto
54	Shri Narinderjit Singh	6th	Ditto	S.D. High School, Tarn Taran
55	Shri Randip Singh..	6th	Ditto	Ram Garhia High School, Amritsar
56	Shri Nand Singh ..	7th	Ditto	S.D. High School, Tarn Taran
57	Shri Hardial Singh	6th	Daburji to Amritsar	Ram Garhia High School,
58	Bibi Phula Rani ..	8th	Bundala to Tarn Taran	Government High School, Tarn Taran
59	Shri Jaswant Singh	6th	Khabe Dogran to Bundala	Government Middle School, Bundala
60	Bibi Kulbir Kaur	6th	Railway Station , Jandiala , Jandiala City	Government High School, Jandiala
61	Shri Satnam Singh	3rd	Ditto	Ditto
62	Shri Dalbir Singh	5th	Ditto	Ditto
63	Shri Jagdeep Singh	3rd	Ditto	Ditto
64	Bibi Gurdip Kaur	9th	Ditto	Ditto
65	Bibi Charanjit Kaur	9th	Ditto	Ditto
66	Bibi Gurdial Kaur	5th	Ditto	Ditto
67	Bibi Surinder Kaur	6th	Manawala to Jandiala	Government Girls High School, Jandiala
68	Bibi Kulwant Kaur	9th	Bundala to Jandiala	Ditto
69	Shri Harkishan Singh	7th	Khabe Dogran to Tarn Taran	Government High School, Tarn Taran
70	Bibi Kulwant Kaur	7th	Railway Station , Jandiala to Jandiala City	Government Girls High School, Jandiala

Serial No.	Name of student	Class No.	Name of the route	Name of School
71	Shri Satpal Singh	6th	Khabe Dogran to Bundala	Government Middle School, Bundala
72	Bibi Goginder Kaur	9th	Manawala to Amritsar	Government High School, Amritsar
73	Shri Surjit Singh ..	6th	Ditto	Ditto
74	Bibi Suraj Kaur	6th	Ditto	Government High School (Girl), Amritsar
75	Bibi Manjit Kaur ..	9th	Bundala to Tarn Taran	Government Girls High School, Tarn Taran
76	Bibi Balbir Kaur ..	8th	Gheri to Jandiala	Government Girls High School, Jandiala
77	Shri Salwinder Singh	6th	Shaffipur to Tarn Taran	Government High School, Tarn Taran
78	Shri Baljit Singh ..	7th	Manawala to Jandiala	Government High School, Jandiala
79	Shri Gurmukh Singh	7th	Daburji to Amritsar	Government High School, Amritsar

LIST OF FREE PASSES ISSUED IN CHOGAWAN BLOCK

Serial No.	Name of the student	Class No.	Name of the route	Name of the School
1	Shri Ramesh Chander	10th	Kohali to Lopoke	Government High School, Lopoke
2	Bibi Nirmal Kaur	6th	Bhopa Rai to Chogawan	Ditto
3	Shri Santokh Singh	6th	Ditto	Ditto
4	Shri Yashano Dass	8th	Kohali to Chogawan	Ditto
5	Bibi Prem Kanti ..	6th	Ditto	Government High School, Tapiala
6	Bibi Darshan Kumari	8th	Ditto	Ditto
7	Shri Supinder Singh	8th	Ditto	Ditto
8	Shri Guru Dutt ..	6th	Ditto	Government High School, Chogawan
9	Bibi Manmohan Kaur	10th	Chogawan to Amritsar	Shazada Nand School, Amritsar
10	Bibi Narinder Kaur	7th	Kohali to Chogawan	Government High School, Tapiala
11	Bibi Lila Devi ..	7th	Ditto	Ditto
12	Shri Kapur Singh ..	8th	Chogawan to Fatehpur Rajputan	Fatehpur Guru Nanak H/S Fatehpur Rajputan

Serial No.	Name of student	Class No.	Name of the route	Name of School
13	Shri Kulwant Singh	8th	Chogawan to Fatehpur Rajputan	Guru Nanak High School, Fatehpur
14	Gurbaksh Singh ..	8th	Ditto	Ditto
15	Shri Piara Lal ..	8th	Ditto	Ditto
16	Shri Baldev Singh ..	8th	Ditto	Ditto
17	Shri Darshan Singh	6th	Tarapur to Chogwan	Government High School, Chogawan
18	Bibi Krishana Rani	7th	Kohali to Chogwan	Government High School, Tapiala
19	Bibi Kailash Rani	7th	Ditto	Ditto
20	Bibi Vir Kaur ..	7th	Ditto	Ditto
21	Bibi Balwant Rani	6th	Taook to Chogwan	Government High School, Chogwan
22	Shri Prem Nath	8th	Ditto	Ditto
23	Shri Kabul Singh	6th	Kohali to Chogwan	Ditto
24	Shri Manjit Singh	8th	Ditto	Government Middle School, Chogwan
25	Shri Kulwant Singh	8th	Chogwan to Fatehpur	Government High School, Fatehpur
26	Shri Gurbaksh Singh	9th	Ditto	Ditto
27	Shri Ganga Bahadur	8th	Kohali to Hall Gate, Amritsar	Government High School, Amritsar
28	Shri Gurbachan Singh	9th	Tapiala to Ajnala	Government High School, Ajanala
29	Bibi Kashmir Kaur	9th	Ditto	Ditto
30	Bibi Rajinder Kaur	9th	Ditto	Ditto
31	Shri Santosh Singh	7th	Kohali to Chogwan	Government High School, Chogwan
32	Bibi Sudesh Kumari	10th	Chogwan to Ajnala	Government Girls High School , Ajnala
33	Bibi Sukhwant Kaur	6th	Kohali to Chogwan	Government School, Tapiala
34	Bibi Rahinder Kaur	10th	Tapiala to Ajnala	Government Girls High School, Ajnala
35	Shri Davinder Paul	7th	Kohali to Chogwan	Government High School, Tapiala
36	Bibi Gurbachan Kaur	7th	Ditto	Ditto
37	Bibi Manjit Paul ..	7th	Ditto	Ditto

LIST OF FREE PASSES ISSUED IN VERKA BLOCK

Serial No.	Name of the student	Class No.	Name of the route	Name of the School
1	Shri Dhanjit Singh	9th	Verka to Amritsar	Government High School, Ram Bagh, Amritsar
2	Shri Gulzar Singh	8th	Valla to Fatehpur Rajputan	Guru Nanak Khalsa High School, Fatehpur-Rajputan
3	Shri Satnam Singh	6th	Valla to Amritsar	Ram Garhia High School, Amritsar
4	Shri Harbhajan Singh	6th	Ditto	Ditto
5	Shri Tarsem Paul	7th	Valla to Fatehpur-Rajputan	Guru Nanak Khalsa High School, Fatehpur-Rajputan
6	Shri Gurdial Singh	8th	Ditto	Ditto
7	Shri Sohan Singh	8th	Ditto	Ditto
8	Shri Baldev Singh	8th	Ditto	Ditto
9	Bibi Lakhwinder Kaur	8th	Ditto	Ditto
10	Bibi Puspa Kumari	7th	Ditto	Ditto
11	Shri Baldev Singh	8th	Ditto	Ditto

Termination of services of conductors and drivers of Punjab Roadways, Jullundur

2436. **Comrade Makhan Singh Tarsikka** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) The names of conductors and drivers of the Punjab Roadways, Amritsar and Jullundur separately whose services were terminated by the higher authorities during the last two years with the reasons thereof ;

(b) the details of the charge sheets given to the persons referred to in part (a) above and the replies given by them be laid on the Table of the House ;

(c) whether the persons mentioned in part (a) above appealed to the Provincial Transport Controller, Chandigarh, if so, with what results ?

Shri Ram Kishan :(a), (b) (c) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained. Information will be supplied in any particular case if sought.

Construction of certain Bridges in Amritsar District

2437. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the reasons for not constructing bridges on the following places on the Kasur Drain and its branches in Amritsar District so far ;

(i) Between Fatoo and Chawindo Devi Kacha Road ;

(ii) Between Matawala and tahli Sahib Kacha Road ;

(iii) Between Tarsikka and Dehriwala on Patti Drain ;

(iv) Between Bundala and Varpal on Kasur Drain ;

(v) Between Jund and Fatehpur Rajputan on Kasur Drain ;

(b) the approximate time and date upto which the said bridges are likely to be constructed ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Paucity of funds. A bridge exists near villages Jund and Fatehpur Rajputana.

(b) No definite date can be given.

Untrained Teachers in erstwhile District Boards/Municipal Boards Schools in Amritsar District.

2439. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the names, addresses and qualifications of untrained teachers who were working in the Local Bodies (Both District Boards and Municipal Committees) Primary, Middle, High School before they were taken over by the Government in 1957 in Amritsar District.

(b) the names of the teachers referred to in part (a) above who have not been given special certificates todate : and the names of those who have not been given special certificates alongwith the reasons, if any, therefor ?

Shri Prabodh Chandra : (a) A statement marked Annexure 'A' giving the requisite information is laid on the Table of the House.

(b) All the teachers mentioned in the statement (Annexure 'A') have been given the special certificates except 17 teachers mentioned in Annexure 'B' whose cases are under examination.

Particulars of untrained teachrs in Local Bodies Primary, Middle and High Schools in Amritsar District in 1957 before provincialisation of such schools.

Serial No.	Name of the teacher	Qualifications	Name of schools
1	2	3	4
1	Sohan Singh ..	Matric ..	High School, Mianwind
2	Teja Singh ..	Do	High School, Tarn Taran
3	Partap Singh ..	F.A.	High School, Vachoya
4	Gowardhan Parshad ..	Matric	High School, Mianwind
5	Jaswant Ram ..	B.A.	High School, Butala
6	Ram Labhai ..	Prabhakar ..	Middle School, Gago Bua
7	Kundan Singh ..	B.A.	High School, Kanga
8	Pritam Singh ..	B.A., Gyani	High School, Tahli Sahib
9	Mangat Ram ..	Ditto	High School, Bhallarwal
10	Ranga Singh ..	Matric, Drg.	High School, Ram Dewali
11	Jaswant Singh ..	F.A.	Middle School, Chamyari
12	Raj Bindra ..	Matric	High School, Attari
13	Gurdish Singh ..	Do	High School, Verpal
14	Inder Singh ..	Do	High School, Chabbal
15	Krishna Kumari ..	B.A. (Eng.)	Middle School, Akalgarh Dhappaian
16	Ajit Singh ..	Matric	High School, Fatehbad
17	Kartar Singh ..	Do	High School, Sabhra
18	Avtar Singh ..	Do	High School, Noshehra Panwan
19	Shangara Singh ..	Do	High School, Chahartta
20	Madan Mohan ..	Sanskrit	High School, Wadala Virum
21	Krishan Avtar ..	B.A.	High School, Mir Megha
22	Ram Parkash ..	Matric	Middle School, Khiala Kalan
23	Gurdip Singh ..	B.A, Gyani	Middle School, Chola Sahib
24	Jatinder Singh ..	Matric, Gyani	Middle School, Fatehbad
25	Gurbachan Singh ..	B.A, Gyani	Middle School, Chamyari
26	Romesh Chand ..	Matric	High School, Khem Karan
27	Tilak Raj ..	Matric, Prabhakar	High School, Chand

[Minister for Education and Local Govt.]

Serial No.	Name of the teacher	Qualification	Name of school
1	2	3	4
28	Ajit Singh ..	Matric, Gyani	Middle School, Bhuchar Sohal
29	Surinder Pal Singh ..	Matric	High School, Wadala Virum
30	Saran Dass ..	Prabhakar	High School, Butala
31	Karta Ram ..	Matric	Middle School, Kirtowal
32	Sukhdev Singh ..	Do	High School, Kanga
33	Madan Mohan ..	Matric, Drg.	High School, Sur Singh
34	Lakhbir Singh ..	Matric, Gyani	High School, Khem Karan
35	Surinder Singh ..	Matrci, Drg.	High School, Mianwind
36	Puran Chand ..	Matric, Prabhakar	Middle School, Kirtowal
37	Gurdip Singh ..	Matric, Gyani	High School, Kacha Pakka
38	Narinder Kumar ..	Matric, Prabhakar	High School, Rajoke
39	Jagdish Chand ..	F.A., Prabhakar	High School, Khem Karan
40	Sunder Dass ..	Middle, J.B. Failed	School Kohli
41	Banwari Lal ..	Middle	School Panjwar
42	Gulzari Lal ..	Do	School Bhilowal
43	Sohan Lal ..	Do	School Ratta Gadda
44	Mansa Mal ..	Matric, Gyani	SchoolTahli Sahib
45	Hazara Singh ..	Middle	School Bhullar
46	Harbans Singh ..	Do	School Chubbal
47	Gurbakhsh Singh ..	Do	School Jhita Kalan
48	Mukand Lal ..	Do	School Pakharpura
49	Viran Devi ..	Middle, J.B. Plucked	School Othian
50	Maya Ram ..	Middle	School Sham Nagar
51	Mangat Ram ..	Middle, S.V. Plucked	School Bhagwanpura
52	Mangat Ram ..	Ditto	S. Nimak Mandi, Amritsar
53	Harbans Lal ..	Matric, S.V.	S. Nimak Mandi, Amritsar
54	Megh Raj ..	Matric	School Ram Dewali
55	Girdhari Lal ..	Do	School Pakharpura

Serial No.	Name of the teacher		Qualifications	Name of Schools
1	2		3	4
56	Durga Dass	..	Matric	Primary School, Lachhmansar
57	Chanan Singh	..	Do	School, Bhiani Rajputan
58	Lartam Singh	..	Middle, Gyani	S. Awan
59	Sant Singh	..	Matric	S. Gunowal
60	Brahm Dutt	..	Do	S. Syalka
61	Niranjan Dass	..	Do	S. Nimk Mandi, Amritsar
62	Bishan Singh	..	Middle	S. Buchar Khurd
63	Amar Kaur	..	Do	Ditto
64	Harbans Kaur	..	Primary	S. Jaura
65	Teja Singh	..	Do	S. Tarn Taran
66	Gurmej Singh	..	F.A.	Dhar
67	Harbans Singh	..	Matric, Gyani	S. Mehta Bangal
68	Gurbux Singh	..	Middle	Gandhiwind
69	Avtar Chand	..	Middle, S.C.	Miran Kot
70	Ganga Ram	..	Middle	Sohal
71	Natha Singh	..	Do	Bhakna Khurd
72	Gurbachan Kaur	..	Do	Lachkari Nangal
73	Jaswant Kaur	..	Do	Talwandi Dogran
74	Raj Kishan	..	Do	Bundala
75	Harcharan Kaur	..	Do	Kang
76	Joginder Singh	..	Matric, S.C.	Sohian Kalan
77	Som Raj	..	Matric	Ugar Aulakh
78	Surinder Singh	..	Do	Dago Bua
79	Ajit Singh	..	Do	Bharowal
80	Madan Mohan	..	Do	Pandori Gola
81	Mohinder Kaur	..	Do	Devdas Pura
82	Om Parkash	..	Do	Sangat Pura
83	Bhupinder Singh	..	B.A., S.C.	Verka
84	Niranjan Singh	..	Matric	Rushiana
85	Kartar Singh	..	Do	Bath
86	Dewan Singh	..	Do	Jhawaspur

[Minister for Education and Local Government]

Serial No	Name of the teacher	Qualifications	Name of Schools
1	2	3	4
87	Pawinder Kumar ..	Matric	Bainka
88	Iqbal Singh ..	F.A.	Sarangra
89	Amrik Kaur ..	Middle	Rure Asal
90	Gyan Kaur ..	Matric	Udho Nangal
91	Joginder Singh ..	Matric	Chak Bamba
92	Ram Pyari ..	Middle	Buttari
93	Pritam Singh ..	F.A.	Timmowal
94	Shirnagat Singh ..	Middle	Jarmastpura
95	Manohar Lal ..	Matric	Matewal
96	Amar Kaur ..	Middle	Jastarwal
97	Kewal Krishan ..	Matric, Prabhakar	Kakkar
98	Mohinder Kaur ..	Middle	Pahuwind
99	Harbans Singh ..	Matric	Kotla Gujran
100	Ram Saran ..	B.A.	Mughal Chak
101	Nil Kanth ..	Matric	Cheema Bath
102	Harbans Singh ..	Middle	Dhoitna
103	Dharam Pal ..	Matric	Siampura
104	Darshan Kumar ..	Do	Wadala Virum
105	Amar Singh ..	Do	Burg
106	Chattarpal Singh ..	Matric, Gyani	Devdas Pura
107	Kehar Singh ..	Matric	Suga
108	Dev Dutt ..	Do	Mari Kalan
109	Santosh Kumari ..	Middle	Pheurwan
110	Inderjit Kaur ..	Matric, Gyani	Kohali
111	Amrit Kaur ..	Matric	Noshehra Panwan
112	Mansa Ram ..	Matric, Gyani	Chadanke
113	Nand Gopal ..	Matric	Balair
114	Gurcharan Singh ..	Do	Lohark Khurd
115	Bhupinder Singh ..	Do	Sohina Khurd
116	Bimla Datta ..	Do	Raja Sansi

1	2		3	4
117	Jaswant Singh	..	Matric	Mehl-Kandiala
118	Chander Parkash	..	Matric, J.B.T. failed	Mule Chak
119	Ram Pyari	..	Middle failed	Bullar
120	Hans Raj	..	Matric	Mode
121	Inder Singh	..	Do	Chabbal
122	Baldev Raj	..	Matric, Drg. Mater	Jandiala
123	Gulzar Singh	..	Matric, J.B.T. failed	Khidowal
124	Anup Singh	..	Matric, Gyani	Shazada
125	Datar Kaur	..	Middle, Gyani	Kotli Saru Khan
126	Jarnail Singh	..	Matric	Kallah
127	Harbhajan Kaur	..	Middle	Thathian
128	Pritam Kaur	..	Do	Pheruwan
129	Jai Lall	..	Matric	Dhardev
130	Narinder Kumar	..	Matric, Gyani	Bhaghiari
131	Amarjeet Kaur	..	Middle, Gyani	Mananwalla
132	Gurbachan Singh	..	Matric	Bhaini Matwam
133	Amrik Singh	..	Do	Jaspal
134	Maluk Singh	..	B.A., Gyani	Ballarwal
135	Sulkhan Singh	..	Matric, J.B.T., failed	Naraingarh
136	Tilak Raj	..	Matric, J.V. failed	Chachowali
137	Sital Kaur	..	Ditto	Malian
138	Mohan Singh	..	Ditto	Mangal Sarai
139	Jaspal Singh	..	Matric	Bindi Sayeedan
140	Kundan Singh	..	Do	Manga Sarai
141	Rajinder Kaur	..	Do	Lopoke
142	Surjit Singh	..	Do	Ranike
143	Maulak Singh	..	Do	Ahlowal
144	Hari Mittar	..	Do	Rampur
145	Jai Gopal	..	Do	Mahna Singh Road M.C., Amritsar

[Minister for Education and Local Government]

1	2	3	4
146	Tara Singh ..	Matric	Mode
147	Pyara Singh ..	Do	Jabbowal
148	Hari Singh ..	Do	Havelian
149	Tarlok Singh ..	Do	Sabhra
150	Balwant Singh ..	Do	Sanarangdev
151	Shangara Singh ..	Do	Bhagowal
152	Gyan Singh ..	Do	Chak Kera Khan
153	Harcharan Kaur ..	Middle	Toota
154	Raj Kumar ..	Matric	Chichrewal
155	Hans Raj ..	Do	Wan
156	Balwant Kaur ..	Do	Mahawa
157	Nirmal Kanta ..	Matric, Gyani ..	Bhala Pind
158	Sudesh Sood ..	J.B.T. failed	Nushehra Panwan
159	Darshan Singh ..	Ditto	Tahthi Jaimal Singh
160	Kailash Tondan ..	J.V. plucked	Shahartta
161	Satnam Singh ..	F.A., Gyani	Bhindi Sheedan
162	Bhupinder Singh ..	Matric	Verpal
163	Harbhajan Singh	Do	Abu Said
164	Avtar Kaur ..	Middle, J.B.T. failed	Nathupur Toda
165	Ajit Kaur ..	Do	Muradpura
166	Uppar Kaur ..	Ditto	Raja Sansi
167	Daulat Ram ..	Matric	Dhardeo
168	Paramjit Kaur ..	Do	Kaironwal
169	Jagjit Singh ..	Matric, J.B.T.	Shehron
170	Harbans Singh ..	Matric	Dhon
171	Kamla Devi ..	Middle, J.V. failed	Manan
172	Mota Singh ..	Matric, J.V. failed	Lohian
173	Rajinder Kaur ..	Middle	Prit Nagar
174	Nirmal Singh ..	Do	Gangowal

1	2	3	4
175	Jasvir Singh	.. Matric, J.B.T. failed	Bahaipur Dogran
176	Jaswant Kaur	.. Matric	Shadipur
177	Dharam Vir	.. Do	Menana
178	Rattan Singh	.. Matric, J.B.T. failed	Timmowal
179	Susheel Kaur	.. Middle	Sheikh Chak
180	Balwant Singh	.. Matric, Gyani	Thakar Kaura
181	Balwant Kaur	.. Middle, J.V. failed	Bahmniwala
182	Harjinder Singh	Matric	Lopoke
183	Yash Pal	.. Matric, J.V. failed	Gangar Bhana
184	Balwant Kaur	.. Middle	Gumtala
185	Surjit Kaur	.. Do	Manochahl
186	Sheela Wanti	.. Middle failed	Ghanupur
187	Faquir Chand	.. Middle	Jasraur
188	Sewa Singh	.. Matric, Gyani	Khem Karan
189	Lakhbir Singh	.. Matric	Chak Pundori
190	Mohan Singh	.. Do	Manga Sarai
191	Brij Mohan	.. Do	Molike
192	Sewa Singh	.. Do	Kamalpura
193	Mohinder Lal	.. Do	Daoke
194	Surmukh Singh	.. Do	Rakhdenewal
195	Rajinder Singh	.. Matric, Gyani	Buge
196	Karam Singh	.. Ditto	Maluwal
197	Sawarn Singh	.. Matric	Kot Sidhu
198	Arjan Singh	.. Do	Rurewal
199	Harbans Kaur	.. Middle	Kohala
200	Hans Raj	.. Matric	Wan
201	Amar Singh	.. Do	Chichrewal
202	Prem Nath	.. Do	Rangarh

[Minister for Education and Local Government]

1	2		3	4
203	Gurmej Singh	..	Matric	Dinewal
204	Karnail Singh	..	Do	Thoba
205	Mahan Singh	..	Do	Chicha
206	Ajit Singh	..	Matric, Gyani	Buchar Sohal
207	Harbhajan Singh	..	Matric	Kot Khara
208	Gurdev Singh	..	Do	Malowal
209	Gurbachan Singh	..	Do	Dhulka
210	Prem Singh	..	Do	Algon
211	Gurdeep Singh	..	Do	Banwalipur
212	Nand Lal	..	Do	Chola
213	Roshan Lal	..	Do	Dhulka
214	Jagjit Singh	..	Do	Khak
215	Kuldip Singh	..	Do	Amina Kalan
216	Darbara Singh	..	Do	Kotli Saru Khan
217	Atma Singh	..	B.A.	Hoshiar Nagar
218	Sardara Singh	..	F.A.	Ram Dewali
219	Daleep Singh	..	Matric	Nipal
220	Arjan Singh	..	Do	Shahid
221	Raja Singh	..	Matric, Gyani	Shekikh
222	Gyan Singh	..	Matric	Sangat Pura
223	Joginder Singh	..	Do	Mehta
224	Charan Dass	..	Do	Jodha Nagri
225	Sajan Singh	..	Do	Chola Sahib
226	Surjit Singh	..	Do	Raja Tal
227	Joginder Singh	..	Do	Lola
228	Santokh Singh	..	Do	Issa Pura
229	Raghubans Lal	..	Do	Khem Karan
230	Tarlok Chand	..	Do	Wan
231	Mohinder Singh	..	Do	Phangwen
232	Satwant Kaur]	..	Do	Chiddan

1	2		3	4
233	Tilak Raj	..	Matric	Bhilowal
234	Balbir Singh	..	Do	Atari
235	Gurnam Singh	..	Do	Dhun
236	Puran Chand	..	Matric, J.B.T.	Kirtowal
237	Niranjan Singh	..	Ditto	Harsechina
238	Harbhajan Singh	..	Ditto	Chak Kamal Khan
239	Gurdeep Singh	..	Ditto	Amar Kot
240	Hardeep Singh	..	Matric, Gyani	Gunowal
241	Harbhajan Singh	..	Ditto	Maurekamirpur
242	Rachpal Singh	..	Ditto	Kalanjar Manawa
243	Mohinder Singh	..	Ditto	Sur Singh
244	Ajaib Singh	..	Ditto	Pahoke
245	Jaswant Singh	..	Ditto	Chak Sakander
246	Avtar Singh	..	Ditto	Marhena
247	Banwari Lal	..	Ditto	Dhariwal
248	Mohan Singh	..	Ditto	Chola Sahib
249	Surjit Singh	..	Ditto	Saidpur
250	Ram Parkash	..	Ditto	Talwandi Nahar
251	Raja Ram	..	Matric	Rayya
252	Partap Kaur	..	Middle	Dhand
253	Surinder Kaur	..	Middle, J.T., failed	Bhoma
254	Shanti Devi	..	Middle, Prabhakar	Muchal
255	Rup Rani	..	Middle	Bhiki Wind
256	Shubh Karni	..	Ditto	Mehta
257	Surjit Kaur	..	Do	Jallopur Khera
258	Anup Kaur	..	Do	Sarhali Kalan
259	Kartar Kaur	..	Do	Lakhowal
260	Swarn Kaur	..	Do	Fatehpur Rajputan
261	Iqbal Kaur	..	Middle, J.V., failed	Shebhazpur
262	Parkash Kaur	..	J.V., failed	Nagoke

[Minister for Education and Local Government]

1	2		3	4
263	Sushila Kumari	..	Middle	Urdhan
264	Suhagwanti	..	Do	Vachoian
265	Ajit Kaur	..	Do	Jalala Bad
266	Vidya Wati	..	Do	Jalala Bad
267	Mohan Kaur	..	Do	Khem Karan
286	Satya Sethi	..	Do	Dede Pura
269	Kamla Kumari	..	Do	Sultanwind
270	Gurnam Kaur	..	Prabhakar	Bachola
271	Kailash Kumari	..	Middle, J.B.T. failed	Bohalwal
272	Samitra Devi	..	*	Chatenapura
273	Gurdyal Kaur	..	Middle	Sarhali
274	Sushila Bedi	..	Basic failed	Khalra
275	Krishna Devi	..	*	Chawinda
276	Kailash Kaur	..	*	Sur Singh
277	Rajwant Kaur	..	*	Rayya
278	Devinder Kaur	..	*	Sur Singh
279	Paramjit Kaur	..	*	Tarn Taran

*Qualifications of the teachers are being ascertained from the D.E.O. Amritsar and will be supplied to the Honourable Member on receipt of the reply from the District Education Officer.

ANNEXURE B

List of Teachers who have not been awarded Special Certificates so far

Serial No.	Name of the teacher		Place of posting
1	Nirmal Kanta	..	Government Primary School, Lachaman Sar
2	Gian Singh	..	Government Primary School, Udhoke
3	Harbans Singh	..	Government Primary School, Majjupura
4	Kundan Lal	..	Government Primary School, Bhla
5	Dev Dutt	..	Government Primary School, Murari Kalan
6	Hardeep Singh	..	Government Primary School, Vadala Viram

1	2	3	4
7	Harbans Kaur	.. Government Primary School, Lachman Sar	
8	Gajjan Singh	.. Government Primary School, Jabbowal	
9	Bhagwan Dass	.. Government Primary School, Bal Vidyala, Amritsar	
10	HariSharam Sharma	.. Government Primary Bal Vidyala, Amritsar	
11	Jagjit Kaur	.. Government Primary School, Cantt Board, Amritsar	
12	Jaswant Rai Sharma	.. Government High School, Butala	
13	Gurcharan Singh	.. Middle School, Vadali Guru	
14	Satya Sethi	.. Government Girls Middle School, Sultanwind	
15	Raj Wans Kumari	.. Tr. Shejanda Nad School, Amritsar	
16	Natha Singh	.. Government Primary School, Bhakhana	
17	Faqir Chand	.. Government Primary School, Suhawa	

Urban Community Development Centre in Jandiala Guru, District Amritsar

2440. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state whether Government has any proposal under its condsideration to start an Urban Community Development Centre in Jandiala Guru, District Amritsar, as has been done in other towns in the State if so, when and the details thereof ?

Shri Prabodh Chandra : (i) No.

(ii) Does not arise.

Rates of Electricity

2441. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the rates of electricity charged from the consumers including the electricity duty according to the Punjab Electricity Duty (Amendment) Act, 1963.

(b) whether Government have recently decided to reduce the rate of the said duty, if so, to what extent and the reasons therefor.

(c) the rate per unit, at which electricity is being supplied to the Nangal Fertilizer Factory and other neighbouring States i.e. Delhi, U.P., Himachal Pradesh and others ;

(d) the cost price, per unit, of electricity generated by the Punjab State Electricity Board ;

(e) the rate, per unit, at which electricity is being supplied for Industrial and Agricultural purposes etc,, in the State at present ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) The rates of the Electricity charges/Electricity Duty for various categories of consumers are given in Annexure A & B below :—

[Minister for Public Works and Welfare]

(b) No.

(c) Rates at which Electricity is supplied to —

(i) Fertiliser-Factory, .. Nangal 2.9. pies per unit, subject to the minimum payment based on 90 per cent load factory adjustable at the close or every year.

(ii) Delhi .. As per standard schedule of Rates for Common Pool Supply viz.

Demand charge at Rs. 5.00 K.V.A. per month *plus* Energy Charge at
2.81 paisa per Kwh for the first 500,000 kwh/month.
2.65 paisa per Kwh for the next 1500.000 kwh/month.
2.50 paisa per Kwh for all above 20,00,000 Kwh/month.
Subject to an overall maximum of 5 paisa per KWH.

(iii) U.P.—

Demand charges at Rs 5,50 K.V.A. per month *plus* Energy charges at
4.38 paisa per KWH for the first 10,000 KWH/month.
4.06 paisa per KWH for the next 20,000 KWH/month
3.75 paisa per KWH for all above 30,000 KWH/month

(iv) Rajasthan .. As per rates mentioned against Delhi, above.

(v) Himachal Paradesh (i) For supplies given from Grid points of Ganguwal, Solan and Jutog :—
As per rates mentioned against Delhi/ Rajasthan, above.
(ii) For supplies given from points other than grid S/S including Joginder Nagar from where 500 KWH are given free of charge, under old mandi Darbar Agreement of 1925.
as per standard schedule of rates for supplies to distributing Licensees viz ;

Demand Charges at Rs 5·50 per KVA month *plus* Energy charge—
4.38 paisa per KWH for the first 10,000 KWH/month
4.06 paisa per KWH for the next 20,000 KWH/month
3.75 paisa per KWH for all above 30,000 KWH/month.
Subject to an overall maximum of 7·81 paisa per KWH.

(vi) Jammu and Kashmir (i) for supply from Pathankot :—
As per standard schedule of rates under C.P. II for non-participating States,

Demand charge at Rs 5.00 per KVA per month. *plus* Energy charge.

3.50 paisa per unit for the first 500,000 KWH/month.
3.25 paisa per unit for the next 1500,000 KWH/months.
3.00 paisa for per unit for all above 20,00,000 KWH/month.

(ii) From 11 KV Sub- Station at Dhar Kalan for Basohili Town:—
At rates as per item (ii) under Himachal Pradesh, above.

(d) Uhl River Scheme—1.40 paisa per unit.
Bhakra Nangal Project—1.49 paisa per unit.

(e) The rates of Electricty being charged in the State are given below against each of the following categories :—

(i) *Agricultural*.—for loads not exceeding 20 K.W. (26 B.H.P.)

9.38 paisa per KWH for first 1500 KWH/month.

7.81 paisa per KWH in excess of 1500 KWH/month.

The above rates are net. A surcharge of 2 per cent per month is leviable, if the bill is not paid within the specified period.

(ii) *Industrial* (*Large Supply*)—

for loads exceeding 100 K.W.

Demand charge Rs 500 per KVA per month *plus* Energy charges.

4.06 paisa per KWH for first 100,000 KWH/month.

3.75 paisa per KWH for next 200,000 KWH/month

3.44 paisa per KWH for all in excess of 300,000 KWH per month.

Subject to.—

(i) A rebate of 0.94 paisa per KWH for all units in excess of 360 KWH per KVA per month or in excess of 420 KWH per KW per month if the demand charge is based on kilowatts.

(ii) A maximum overall rate of 5.63 paisa per KWH.

The above rates are net. A surcharge of 1 per cent per month is leviable if the bill is not paid within the specified period.

(iii) *Medium Industrial Power Supply*.—for loads ranging from 21 K.W. to 100 K.W.

Demand Charges.—

Rs. 6.00 per month (i) per KW of connected load upto a connected load of 70 KW.

(ii) Per KW of maximum demand for connected load in excess of 70 KW *plus* Energy Charges.—

5.31 paisa per KWH for the first 5,000 KWH/month

4.69 paisa per KWH for the next 10,000 KWH/month

4.38 paisa per KWH for all in excess of 15,000 KWH/month,

Subject to a maximum overall rate of 9·38 paisa per KWH.

The above rates are net. A surcharge of 2 per cent per month is leviable if the payment of the bill is not made within the specified period.

(iv) *Small Industrial Power*.—for loads not exceeding 20 KW.

10.94 paisa per KWH for the first 500 KWH/month.

9.38 paisa per KWH for the next 1,000 KWH month.

7·81 paisa per KWH for all in excess of 1,500 KWH/month.

The above rates are net. A surcharge of 2 per cent per month is leviable if the payment of the bill is not made within the specified period.

ANNEXUR A

Schedules of Tariffs for supply of Power from the Uhl River and Bhakra Nangal Hydro-Electric Projects

1. SCHEDULES LARGE INDU STRIAL POWER SUPPLY

(Available for loads above 100 K.W·)

Demand charge:—	Rs 5,00 per KVA per month.
plus Emergy charge:	4.06 Paisa per KWH for first 100,000 KWH/month.
	3.75 Paisa per KWH for next 100,000 KWH/month.
	3,44 Paisa perKWH for all above 300,000 KWH/months.

[Minister for Public Works and Welfare]

Subject to (a) rebate of 0.94 Paisa per KWH for all units in excess of 360 KWH per month.

(b) A maximum overall rate of 5.63 Paisa per KWH.

Note.—The above trariff is for supply at 11 KV, 6, 6 KV and 3.3 and supply at 400 V will be charged under Schedule Medium Industrial Power Supply.

2. SCHEDULE MS-MEDIUM INDUSTRIAL POWER SUPPLY

(Available for loads from 21 KW to 100 KW).

Demand charge:— Rs 6.00 per KW per month
plus
Energy charge 5,31 Paisa per KWH for first 5,000 KWH/month.

4.69 Paisa per KWH for next 10,000 KWH/month.

4.38 Paisa per KWH for all above 15,000 KWH/month.

Subject to a maximum overall rate of 9.38 Paisa per KWH.

Note.—Above tariff is for supply at 400 V and rebate of 7½ per cent will be given for supply at 11,000 volts.

3. SCHEDULE SP—SMALL INDUSTRIAL POWER SUPPLY

(Available for loads not exceeding 20 KW)

Energy Charge—10.94 Paisa per KWH for first 500 KWH/month.

9.38 Paisa per KWH for next 1,000 KWH/month.

7,81 Paisa per KWH for all above 1,500 KWH/month.

4. SCHEDULE AP—AGRICULTURAL AND COTTAGE INDUSTRIAL SUPPLY

(Available for Irrigaion pumping upto the load not exceeding 20 KW (26 BHP) and Cottage Industry in rural areas upto a load of 10 BHP).

Energy charge—9.38 per KWH for first 1,500 KWH/month.

5. SCHEDULE CS—COMMERCIAL SUPPLY.

(Available for lights, fans appliances and small motors upto the demand of 10 KV for all non-residential premises such as business houses, Clubs Cinemas, Schools, Hospitals etc.

Energy charges:— .. 31.25 nP. per KWH for the first 30 KWH/month.

12,50 nP. per KWH for the next 50 KWH/month.

9,38 nP. per KWH for the all above 80 KWH/month.

SCHEDULE DS—DOMESTIC SUPPLY

(Available to all residential premises for lights, fans, domestic pumps and house hold appliances)

Energy charge—31.25 nP KWH for the first 15 KWH/month
12.50 nP per KWH for the next 25 KWH/month
6.25 nP per KWH for all above 40 KWH/month

7. SCHEDULE SL—STREET LIGHTING SUPPLY

(Available for street lighting supply system in Municipalities, Panchayats etc.).

Energy Charge .. 14,06 nP. per KWH/month.
plus

Line Maintenance and Lamp renewal charges (a) For lamps of up to 40 watts—Rs 1.50 per lamp/s.

(b) For lamps of 60 and 75 watts, —Rs 1.75 per month.

(c) For lamps of 100 Watts—Rs 2.00 per lamp/month.

(d) For lamps of 150 watts—Rs 2.25 per lamp/month.

(e) For lamps of above 150 watts and special lamps—Special quotations.

(b) MERCURY VAPOUR LAMPS

(i) Lamps of 80 Watts.... Rs 8,00 per lamp per month.

(ii) Lamps of 125 Watts..Rs 8,50 per lamp per month.

(iii) Lamps of 250 Watts..Rs 14.50 per lamp per month.

(iv) Lamps of 400 Watts..Rs 17.00 per lamp per month.

(c) Floure scent tubes (1) 2x20 Rs 7.00 per set/month.

(2) 2x40 —Rs 10.50 per set/month.

Note.—In the case of street lighting supply to village Panchayats a rebate of twenty five per cent over the standard Tariff i.e. energy charges and line, maintenance and lamp renewal charges (all categories) is allowed with effect, from 1st April, 1964.

8. SCHEDULE G.S.—GRID SUPPLY TO DISTRIBUTING LICENSEES

(Available to distributing licensees for resale to ultimate consumers.)

Demand charge .. Rs 5.50 per KVA month
plus

Energy charge .. 4.38 nP. per KWH for first 19,000 KWH/month

4.06 nP. per KWH for next 20,000 KWH/month.

3.75 Paisa per KWH for all above 30,000 KWH/month.

Subject to an overall maximum of 7.81 Paisa per KWH without prejudice to the minimum monthly payment which is to be calculated at the rate of Rs 5.05 per KVA per month.

Note.—The above rate is for supply at 11,000 V and a surcharge of 7½ per cent will be levied if supply at 400 V is given.

9. SCHEDULE C.P.—COMMON POOL SUPPLY

(Available to participating States and other States for resale to distributing licensees and consumers).

Demand charge .. Rs 5.00 per KVA per month.
plus

Energy charge Rs 2.81 nP. per KWH for first 500,000 KWH/month

Rs 2.66 nP. per KWH for next 1,500,000 KWH/month.

Rs 2.50 nP. per KWH for all above, 2,000,000 KWH/month.

Subject to an overall maximum of 5.00 nP. per KWH without prejudice to the minimum payment which is to be calculated at the rate of Rs 5.00 per KVA per month.

[Minister for Public Works and Welfare]

ANNEXURE B

1. RATES OF ELECTRICITY DUTY.

The present rates of electricity duty for various categories of consumers are given below :—

(a) *General Supply*——

(i) Domestic Supply—

First 15 KWH/month—3 nP. per KHW.
Next 25 KWH/month—17.50 nP per KWH.
Above 40 KWH/month —8.75 nP· per KWH.

(ii) Commerical Supply—

First 30 KWH/month—3 nP. per KWH.
Next 50 KWH/month—17,50 nP. per KWH.
Above 80 KWH/Month—8.62 nP. per KWH.

(iii) Supply for illumination purposes. —

Energy supplied to consumer through a temporary connection or temporary extension for the purpose of illumination on the occasion of marriage or a social function connected with marriage (*See* also item V below) .. Rs. 1 per KWH

(b) *Industrial/Agriculture Supply*—

(i) For loads upto 20 KW—15 per cent of the cost of the energy.

(ii) For loads from 21 to 5000 KW —20 per cent of the cost of energy.

(iii) For loads above 5000 KW—25 per cent of the cost of the energy.

Other Categories of Supply.—

Viz street lighting, etc—25 per ccent on the cost of energy.

(d) Temporary supply (Other than for illumination purposes on the occasion of a marriage or a social function connected with marriage).

(i) Domestic Supply .. As per rate against item 1(a)(i) above.

(ii) Commercial Supply .. As per rate against item 1(a) (ii) above.

(iii) Industrial Supply .. As per rate against item 1 (b) (i) to (iv) above.

Senior Superintendents/Superintendents of Police

2442. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the names of the officers working as Senior Superintendents of Police and Superintendents of Police in the State, districtwise, at present ;

(b) whether any of the officers referred to in part (a) above has superseded the officers who were senior to him, if so, the names of the persons so superseded together with the reasons therefore in each case ?

Sardar Darbara Singh : (a) A list is placed on the table of the House.

(b) The question of supersession in the matter of postings as Senior Superintendents or Surperintendents of Police, incharge of districts does not arise as the officers so posted retain their original seniority without reference to the place of their posting.

List of Superintendents of Police and Senior Superintendents of Police, districtwise at present (6th March, 1965).

Serial No.	Name of the District	Names of officers posted
1	Hissar	.. Shri M.K. Luthra, I.P.S.
2	Rohtak	.. Shri Bahal Singh
3	Karnal	.. Shri Brijinder Singh I.P.S.
4	Gurgaon	.. Shri S.S. Palta
5	Ambala	.. Shri Birbal Nath, I.P.S.
6	Simla	.. Shri J.S. Dulat.
7	Jullundur	Shri Amar Singh
8	Ludhiana	.. Shri Harjit Singh I.P.S.
9	Kangra	.. Shri Avinash Chandra, I.P.S.
10	Hoshiarpur,	.. Shri Inderjit Verma, I.P.S.
11	Kapurthala	.. Shri Dalip Singh, I.P.S.
12	Kulu	.. Shri B.L. Chhibber
13	Keylong	.. Shri P.S. Bhinder, I.P.S.
14	Patiala	.. Shri Harjit Singh
15	Bhatinda	.. Shri C.K. Sawhney, I.P.S.
16	Sangrur	.. Shri M.S. Bawa, I.P.S.
17	Mohindergarh	.. Shri Inderjit Singh Sodhi, I.P.S.
18	Amritsar	.. Shri Gurbhagat Singh, I.P.S. (Senior Superintendent of Police) Shri Sukhpal Singh (Additional Superintendent of Police)
19	Ferozepore	.. Shri P.A. Rosha, I.P.S., (Senior Superintendent of Police) Shri Ranbir Singh Yadav (Additional Superintendent of Police)
20	Gurdaspur	.. Shri V.K. Kalia.

Profit Earned by the Punjab Roadways

2443. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of profit earned by the Punjab Roadways since its inception, year-wise and depot-wise ?

Shri Ram Kishan : A statement, containing the requisite information is attached.

[Chief Minister]

STATEMENT

Year	Punjab Roadways, Amrisar	Punjab Roadways, Jullundur	Punjab Roadways, Ambala	Punjab Roadways, Gurgaon	Punjab Roadways, Chandi-garh	Punjab Roadways, Pathankot
1	2	3	4	5	6	7
	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
1948-49	9,392	1,06,574	..	..	..	..
1949-50	1,00,633	63,486	..	..	..	..
1950-51	2,32,077	1,85,126	1,54,833	..	..	..
1951-52	2,97,519	2,24,544	2,87,945	..	—	—
1952-53	14,356	3,6,287	2,32,295	—	—	..
1953-54	4,64,163	303,100	2,27,916	..	..	..
1954-55	9,50,923	7,37,232	2,56,909	..	..	..
1955-56	9,69,168	11,67,119	8,10,333	..	..	..
1956-57	17,19,092	9,92,701	11,34,351	...	..	..
1957-58	19,11,672	12,63,124	19,41,219	..	..	..
1958-59	16,76,726	14,81,027	21,79,726	..	..	..
1959-60	19,03,113	21,12,916	17,01,642	4,85,577	..	..
1960-61	23,41,891	26,94,941	18,31,174	16,28,134	..	..
1961-62	31,53,381	38,78,879	26,15,994	22,40,385	..	..
1962-63	37,82,245	41,86,173	31,33,248	26,52,758	..	..
1963-64	31,48,608	34,05,714	24,13,957	17,08,478	13,68,203	11,98,806

Seniority List of I.C.S. Officers, etc.

2444. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state whether Government has prepared any joint seniority list of I.C.S., I.A..S. and P.C.S. Officers, serving in the State, ; if so, a copy of the list as at present showing their academic qualifications, date of birth and date of entry into Government service together with a copy of the list as it stood in 1948 and 1957 giving the aforementioned particulars be laid on the Table of the House ?

Shri Ram Kishan : The time and labour involved in collecting the desired information will not be commensurate with any possible benefits to be obtained.

Collection of House Tax by Gram Panchayats in District Amritsar

2445. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total amount of House Tax (Chuhla Tax) collected by the Gram Panchayats in Amritsar District during the years 1962-63, 1963-64, and 1964-65, blockwise,

(b) the amount collected by the panchayats mentioned in part (a) above by way of fines, and as court fee while trying the cases during the said period in the said district, block-wise ?

Sardar Darbara Singh : (a) & (b) Statements I & II containing the required information are laid on the Table of the House.

STATEMENT I

Serial No.	Name of Block	Total Amount of House Tax (Chula Tax). collected by the Gram Panchayat in the Amritsar district, during the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65		
		1962-63	1963-64	1964-65
		Rs	Rs	Rs
1	Jandiala ..	2,690.50	18,146.14	28,476.00
2	Patti ..	9,403.50	9,908.75	12,587.00
3	Valtoha ..	929.00	1,528.00	1,522.00
4	Chohla Sahib ..	2,865.00	4,640.00	4,014.00
5	Rayya ..	4,793.00	13,303.00	15,882.69
6	Khadur Sahib ..	3,888.25	17,303.69	28,628.00
7	Tarn Taran ..	6,240.50	15,743.60	18,114.00
8	Ajnala ..	2,788.00	12,041.00	32,895.00
9	Chogawan ..	5,020.00	7,062.75	16,182.00
10	Gandi wind ..	3,066.50	2880.50	14,918.90
11	Bhikhi wind ..	5,137.00	9,780.00	3,130.00
12	Verka ..	7,513.82	10,699.25	27,124.00
13	Majitha ..	5,629.50	22,724.00	23,537.00
14	Tarsikka ..	Nil	7,879.50	1,869.00
15	Naushera Pannuan ..	958.00	19,455.00	16,292.00

[Minister for Home and Development]

STATEMENT II

DISTRICT AMRITSAR

Serial No.	Name of Block		The amount collected by Panchayats mentioned in part (a) above by way of fines and as court fee while trying the cases during the said period in the said district, blockwise		
			1962-63	1963-64	1964-65
			Rs	Rs	Rs
1	Jandiala	..	1,111.36	760.25	685.00
2	Patti	..	775.00	560.00	617.00
3	Valtoha	..	..	..	...
4	Chohla Sahib	..	..	..	...
5	Rayya	..	901.49	1,048.22	..
6	Khadur Sahib	..	466.75	825.50	659.00
7	Tarn Taran	..	539.00	396.00	...
8	Ajnala	..	429.25	806.34	386.25
9	Chogawan	..	456.00	801.75	819.75
10	Gandi wind	..	..	469.25	..
11	Bhikhiwind	..	38.00	30.00	...
12	Verka	..	687.87	497.00	812.25
13	Majitha	..	512.25	104.75	...
14	Tarsikka	..	512.00	623.00	572.00
15	Naushera Pannuan	..	..	..	..

Raids to detect evasion of Sales Tax

2446. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state—

(a) the total number of raids conducted in Amritsar and Jullundur during the months of December, 1964, and January and February, 1965, in connection with the detection of evasion of the Sales Tax ;

(b) the total number of the raids referred to in part (a) above which proved successful with the total amount of evasion detected in each case ?

Sardar Kapoor Singh : (a) 258.

(b) Part (i) 132.

Part (ii) Rs 2,91,825.77 Paise in Amritsar and Rs 5,14,592.40 Paise in Jullundur.

Zila Parishad Employees

2447. Comrade Makhan Singh Tarsikka: Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the names and qualifications of all the employees working at present in the office of the Zila Parishad, Amritsar, stating their present scales of pay and the pay at present being drawn by each ;

(b) whether any proposal is being considered by the Government to increase the pay-scales of the employees of Zila Parishads, if so, when ?

Sardar Darbara Singh : (a) Statement is laid on the table of the House.

(b) No please.

[Minister for Home and Development]

STATEMENT

Serial No.	Name of employee	Designation	Qualifications	Pay-scale	Present pay
				Rs	Rs
1	Shri Harcharan Singh ..	Secretary, Z.P.	B.A. (Hons), LL.B., L.S.G.D.	400—25—600/40—920	760 Exclusive of other allowances
2	Shri Jawala Singh ..	Taxation Officer, Z.P.	B.A., LL.B. (Cuttock University)	100—7½—160/10—220	220 Do
3	Shri Ram Partap ..	Accountant	Matric	100—6—160/8—200/10—250	250 Do
4	Shri Karnail Singh ..	Head Clerk	Do	Do	192 Do
5	Shri Harnam Singh ..	Clerk	Do	106—6—160/8—200	176 Do
6	Shri Gurcharan Singh ..	Do	Do	60—4—80/5—120/5—175	135 Do
7	Shri Arjan Singh ..	Flood Relief In-charge	Do	Do	120 Do
8	Shri Inder Singh ..	Clerk	Do	Do	105 Do
9	Shri Teja Singh ..	Record Keeper	B.A.	Do	105 Do
10	Shri Harpal Singh ..	Steno Typist	F,Sc.	Do	95 Do
11	Shri Parkash Chand ..	Clerk ..	F.A. (English only) Giani	Do	95 Do
12	Shri Raj Kumar ..	Do	Intermediate	Do	76 Do
13	Shri Surinder Singh ..	Do	B.A.	Do	60 Do

14	Shri Jarnail Singh	..	Superintendent, Arboriculture	Matric	80—6—104/8—176	176	Do
15	Shri Bachan Singh	..	Daftri	Under Matric	45—1½—60	46.50+30 D.A.	
16	..		Record Lifter	Post vacant	Do	..	
17	Shri Bhagwati Parshad		Mali	..	..	46.50+30 D.A.	
18	Shri Swarn Singh	..	Peon	L. Middle	35—1—40	36+35 D.A.	
19	Shri Gurpal Datt	..	Do	Do	Do	36+35 D.A.	
20	Shri Bahadur Singh	..	Do	..	Do	36+35 D.A.	
21	Shri Dogar Singh	..	Do	(Lower)	Do	36+35 D.A.	
22	Shri Balwant Singh	..	Do	L. Middle	Do	36+35 D.A.	
23	Shri Sham Lal	..	Chaukidar I	..	Fixed	70 Inclusive of all allowances	
24	Shri Sampuran Singh	..	Do II	..	Do	70	Do
25	Shri Waryam Singh	..	Shabilia	..	Do	70	Do
26	Shri Joga	..	Sweeeper	..	Do	75	Do
27	Shri Bakhshish Singh	..	Beldar	.	Do	70	Do

Promotion of Head Constables and of Assistants as A.S.Is. in Jullundur and Border Ranges

2448. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state the names and addresses of Head Constables of Police, Head Assistants and Assistants working in Police Off'ces who were promoted as A.S.Is. in the Jullundur Range and in the Border Range in the years 1963-64 and 1964-65, stating the period for which they worked as Head Constables/Head Assistants/Assistants in the respective Ra ges ?

Sardar Darbara Singh : No posts of Head Assistants/Assistants exist in District Police Offices in Jullundur and Border Ra ges. These offices are manned by the executive clerks. The required information about the executive clerks promoted as Head Constables, Assistant Sub-Inspectors and Sub-Inspectors during the period in question in Jullundur and Border Ranges is given in the enclosed statement.

Statement showing details of Executive Clerks promoted as Head Constables/Assistant Sub-Inspectors/ISub-Inspectors in Jullundur and Border Ranges during the years 1963-64 *and* 1964-65

(a) Executive Clerks promoted as Head Constables.

Serial No.	Name and address	Period during which served as Head Constable (C.R.C./R.K. etc.)
1	H.C. Kishan Dev, Office of Superintendent of Police, Kapurthala	1st April 1956 to 23rd December, 1963
2	H.C. Kartar Singh, Office of Senior Superintendent of Police, Amritsar	20th March, 1957 to 8th November, 1963
3	H.C. Mulkh Raj, Office of Senior Superintendent of Police, Ferozepore	11th November, 1957 to 11th August, 1964
4	H.C. Ari Jang , Office of Sernior Superintendent of Police, Amritsar	17th April, 1958 to 11th August, 1964
5	H.C. Om Parkash , Office of Senior Superintendent of Police, Ferozepore	24th September, 1958 to 11th August, 1964
6	H.C. Siri Ram, Office of Superintendent of Police, Ludhiana	6th January, 1959 to 31st August, 1964
7	H.C. Murari Lal , Office of Superintendent of Police, Hoshiarpur	28th August, 1959 to 8th September, 1964
8	H.C. Darshan Singh, Office of Superintendent of Police, Gurdaspur	31st August, 1959 to 25th August, 1964

(b) Executive Clerks promoted as Assistant Sub-Inspectors

Sr. No.	Name & address	Period during which served as Head Constable (Assistant Clerk)
1	A.S.I. Hamir Chand, on deputation S.I.B., Amritsar	10th May, 1959 to 24th November, 1963 to

Sr. No.	Name & address	Period during which served as Head Constable (Assistant Clerk)
2	A.S.I. Ujagar Singh, Office of Police Recruits Training Centre, Jahan Khelan	5th September, 1959 to 9th October, 1963
3	A.S.I. Mela Ram, Office of Senior Superintendent of Police, Amritsar	8th August, 1959 to 19th November, 1963
4	A.S.I. Hans Raj, office of Superintendent of Police, Kulu	16th November, 1958 to 13th March, 1964
5	A.S.I. Shiv Ram Narain, on deputation to P.A.P.	9th June, 1959 to 12th June, 1964
6	A.S.I. Harbans Lal, on deputation to S.I.B., Amritsar	5th September, 1959 to 27th May, 1964
7	A.S.I. Krishan Sarup, Office of Senior Superintendent of Police, Ferozepore	10th September, 1959 to 27th May, 1964
8	A.S.I. Ram Labhaya, Office of Senior Superintendent of Police, Amritsar	1st April, 1958 to 22nd July, 1964
9	A.S.I. Kewal Krishan of Finger Print Bureau, Phillaur	9th November, 1960 to 7th August, 1964

(c) Executive Clerks promoted as Sub-Inspectors

Sr. No.	Name & address	Period during which served as A.S.I. (Assistant Clerk)
1	S.I. (Head Clerk) Avtar Singh, Office of Superintendent of Police, Kapurthala	14th September, 1957 to 9th December, 1963
2	S.I. (Head Clerk) Karam Chand, Office of Superintendent of Police, Wireless, Punjab, Chandigarh	28th January, 1959 to 16th June, 1964
3	S.I. (Head Clerk) Sohan Lal, Office of Finger Print Bureau, Phillaur	3rd June, 1959 to 30th June, 1964
4	S.I. (Head Clerk), Dhani Ram, Office of Superintendent of Police, Ludhiana	31st March, 1960 to 9th October, 1964

Civil Aviation Consultative Committee

2449. Rao Nihal Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Adviser, Civil Aviation, Punjab, has been nominated as the Chairman of Civil Aviation Consultative Committee, and the Commissioner for Home Affairs as the Vice-Chairman

(b) whether it is also a fact that the Commissioner for Home Affairs has not so far attended any meeting of the said committee;

(c) the original term of the said Committee and whether it has now been extended by the Government ?

Shri Ram Kishan : (a) (i) No.
(ii) Yes.

(b) Yes.

(c) The original term of the said Committee was one year which has not been extended by Government.

Adviser, Technical Education and Industrial Training, Punjab.

2450. Rao Nihal Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the details of the duties assigned to the Adviser, Technical Education and Industrial Training, Punjab Government together with his academic qualifications and experience for each such duty?

Shri Prabodh Chandra (Education and Local Government Minister) :

(a) (i) Qualifications and Experience of the Adviser.—(i) M.I.S.E.; M.Ae. S.I., M.I.E. (Ind.), M.I. Prod. E. (Lond.) ; M.I.Mech. E. (London); A.F.R. Ae.S. (London).

(ii) First Indian elected to the Experimental Aircraft Association of America.

(iii) Aircraft Maintenance Engineer in all the categories 'A', 'B' , 'C', 'D' and 'X' open for all types of aircraft up to Dakota.

(iv) 33 years experience in Air Force.

(v) Designer and Architect of Kanpur I and Kanpur II Aircraft.

(vi) Has been holding Private Pilot Licence and Commercial Pilot Licence and also has been a Test Pilot.

(vii) Visited number of foreign countries in various purchase Missions (Aircraft etc.).

(viii) Director of Hind Provincial Flying Club, U.P., for 10 years.

(ix) President of Flying Club, Kanpur, for 15 years.

(x) Member of the Northern India Flying Club for 16 years and Delhi Flying Club, 12 years.

(xi) First I.A.F. Officer, who was awarded Vashisht Seva Medal, Class I, by the President of India for most exceptional and meritorious services rendered in building the Indian Air Force and setting up a Transport Air-Craft Factory (AVRO 748) in a record time of 18 months from blue-print to a flying aircraft stage.

(xii) For 8 years has been Air Officer Commanding-in-Chief of a Command of the Indian Air Force, which controlled over two dozen Units of I.A.F. s read all over India.

(xiii) First Officer in I.A.F., who planned the Technical Training Schools in I.A.F., as Wing Commander, Technical Training in, 1946. Since then has trained thousands of technicians at Kanpur both Civilians and Airmen in all Technical Trades both for overhaul and manufacturing of aircraft.

II. *Duties assigned to the Adviser.* —To advise the Government in the formulation and implementation of various Plans/Schemes for expansion and improvement of Technical Education and Industrial Training in the Punjab State.

Tours by the Adviser, Technical Education and Industrial Training, Punjab

2451. Rao Nihal Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the number of days in a month, for which the Adviser, Technical Education and Industrial Training, Punjab, remains away from Head quarters on tour ;

(b) the names of the places which he is generally expected to visit together with the mode of his travel ;

(c) whether the said Adviser has been allowed to countersign his own travelling allowance bills; if not, the designation of the countersigning authority who sanctions and passes his bills ;

(d) whether the travelling allowance bills of the said Adviser are at any stage, checked or verified, as normally required under the rules ;

(e) whether Government has, at any time, considered the advisability of placing a staff car at the disposal of said Adviser for undertaking official journeys ?

Shri Prabodh Chandra (Education and Local Government Minister) :

(a) The Adviser is usually away on tour from the headquarters for more than 8 days in a month, by making use of the afternoons and Saturdays.

(b) The places he generally visits are—

(i) Pioneer Technical Training Institute, Mahilpur.

(ii) Delhi and other flying clubs in Punjab.

His mode of travel is his personal high-powered car and some times his personal Aircraft.

(c) The Adviser has been allowed to countersign his own T.A. bills;

(d) No.

(e) There is no such proposal under the consideration of Government so far as Technical Education Department is concerned.

Honorary Adviser, Technical Education and Industrial Training, Punjab

2452. Sardar Harchand Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the present Honorary Adviser, Technical Education and Industrial Training, Punjab, does not possess the qualifications and experience required for handling the work which has been entrusted to him ;

(b) whether it is also a fact that the said adviser is getting Conveyance Allowance when a Government Staff Car has been placed at his disposal and the monthly mileage covered on official journeys is very small;

(c) whether it is further a fact that large expenditure was incurred for furnishing an office for the said Officer in Chandigarh, although there was very little staff attached to him ;

(d) the amount of different allowances and concessions per month sanctioned by the Government for the said Officer?

Shri Prabodh Chandra (Education and Local Government Minister) : (a) No.

(b) No staff car has been provided by the Technical Education Department to the Adviser. He is being granted a fixed T.A. at the rate of Rs. 800 Per Mensem on the condition that he travels not less than 1,500 miles in a month.

(c) A sum of Rs. 10,114.90 was spent for providing furniture and fixtures to the Office of the Adviser up to September, 1964. This expenditure has been necessary and in keeping with the requirements of his office the strength of which is 21 excluding class IV servants.

(d) (i) Fixed T.A. @ Rs. 800 per mensem.

(ii) Free furnished house of the status of a Deputy Minister of the rental value of Rs 340 per mensem

(iii) Free water and electricity at his residence to the extent of Rs 750 per year.

Development of Civil Aviation in Punjab

2453. Sardar Harchand Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the progress made in the development of Civil Aviation in the Punjab during 1962-63, 1963-64 and 1964-65;

(b) the detailed reasons which led to the replacement of the Adviser, Civil Aviation, Punjab, who had prepared the Scheme for the development of Civil Aviation, by an Air Force Officer ;

(c) the qualifications and experience of the present Adviser, in Civil Aviation, i.e., in the development and construction of Aerodromes, gliding and flying training.

Shri Ram Kishan : (a) A statement is laid on the table of the House.

(b) The former Adviser, Civil Aviation, Punjab, had applied for leave himself and had completed his term of deputation on the 22nd February, 1964. A.V.M. Harjinder Singh joined as Honorary Adviser after he proceeded on leave.

(c) Annexure 'A' attached.

STATEMENT

1962-63—

Construction work was started at Patiala, Amritsar, Hissar and Ludhiana Airfields. Abandoned Airfield at Patiala was brought in serviceable condition and flying started in November, 1962. The Flying Club at Patiala logged 783 hours flying. A site for Karnal Air Field was also selected. A total number of Pushpaks were procured. 47 boys were awarded scholarships for free flying training. Two candidates were sponsored for Winch Operators Training Course. About 4500 acres of sugarcane crops were sprayed from Air on contract. 26 candidates got Student Pilot Licence. Total amount of Rs. 13.74 lacs was spent.

1963-64 —

Various works were sanctioned for the construction of number of buildings at Patiala, Hissar, Amritsar, Ludhiana, and Karnal, including the construction of three Hangars, one each at Patiala, Amritsar and Hissar, but without doors. Administrative approvals for the construction of runway at Patiala and Ludhiana and Technical Workshop were also conveyed.

At Amritsar, flying operation started in August, 1963, on the existing aerodrome at Raja Sansi belonging to the Government of India. The Flying Club at Patiala Logged 2871 hours of flying and the Flying Club at Amritsar logged 1014 hours flying. About 100 candidates obtained flying training upto 5 hours solo and four boys obtained advance flying training on refundable scholarship basis. Three candidates were sponsored for Gliding Instructor Training Course and five candidates were trained for Ground Classes up to Commercial Pilot Licence standard. 90 N.C.C. cadets were given air experience. 48 candidates got Student Pilot Licence. First batch consisting of about 50 Air Force cadets also completed their flying training. Two more Pushpaks were added during the year. Three gliders were purchased and distributed one each to Hissar, Amritsar and Patiala Aviation Clubs. A total sum of Rs 24.80 lacs was spent.

1964-65—

1.(a)	Patiala Aviation Club	Flying hours logged from April, 64 to February, 1965	3717.19
(b)	Amritsar Aviation Club, Amritsar.	Do	1018.54
(c)	Northern India Flying Club, Jullundur.	Do	1461.35
		Total	6197.08

[Chief Minister]

2. Total No. of candidates who have done flying beyond solo stage—

(a) Air Force.	..	142
(b) Air force Officers	..	3
(c) Civilians.	..	28
3. N.C.C. Cadets (air experience)	..	78
4. Total No. of candidates who got student Pilot Licence	..	85
5. (a) Total No. of candidates who got Private Pilot Licence.	..	..
(b) Total No. of candidates who are under training of Private Pilot Licence.	..	13
6. (i) Gliding Launches by the Patiala Aviation Club from December, 1964 to February, 1965	..	871
(ii) Gliding Instructors (under training)	..	2

First Gliding wing of the Patiala Aviation Club, Patiala, started functioning from the Ist week of December, 1964, and it has done 871 launches within 12 weeks. One Winch and two gliders were added to the fleet during the last six months.

7. At Hissar, all the technical staff including the Instructor Incharge and Engineer Incharge have since been reecruited and flying training since started.

8 All necessary arrangements foi complete overhaul of Pushpaks were made at Patiala, 4 Certifcates of Airworthiness of the Pushpaks belonging to the Punjab Government have already been done and the remaining aircraft are under the process of major overhaul. Most of the buildings at Patiala have already been completed. Pucca runway and other buildings are nearing completion. Runway at Ludhiana is also under construction.

9. All the essentialities for starting gliding at Amritsar have also been completed. The gliding training will be started very soon.

ANNEXURE 'A'

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE OF AIR VICE MARSHAL HARJINDER SINGH, HONORARY ADVISER, CIVIL AVIATION, PUNJAB.

(i) M.I.S.E.; M.Ae.S.I. M.I.E.(Ind.) M.I. Prod. E. (Lond) ; M.I. Mech. E. (Lond.); A.F.R.Ae.s. (Lond.)

(ii) First Indian elected to the Experimental Aircraft Association of America.

(iii) Aircraft Maintenance Engineer in all the categories 'A','B','C','D' and 'X' open or all types of aircraft upto Dakota

(iv) 33 years experience in Air Force.

(v) Designer and Architect of Kanpur I and Kanpur II Aircraft.

(vi) Has been holding Private Pilot Licence and Commercial Pilot Licence and also has been a Test Pilot.

(vii) Visited number of foreign countries in various Purchase Missions (Aircraft, etc.)

(viii) Director of Hind Provincial Flying Club, U.P. for 10 years.

(ix) President of Flying Club, Kanpur, for 15 years.

(x) Member of the Northern India Flying Club, for 16 years and Delhi Flying Club, 12 years.

(xi) First I.A.F. Officer who was awarded Vashisht Seva Medal Class I by the President of India for most exceptional and meritorious services rendered in building the Indian Air Force and setting up a Transport Aircraft Factory (AVRO 748) in a record time of 18 months from blue print to a flying aircraft stage.

(xii) For 8 years has been Air Officer Commanding-in-Chief of a Command of the Indian Air Force, which controlled over two dozen Units of I.A.F. spread all over India.

Technical Education and Industrial Training to Government employees.

2454. Chaudhri Dharshan Singh : Will the Minister for Public Works and welfare be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to start evening classes to impart technical education and industrial training to those Government employees who want to get it, If so the time by which it is likely to be finalised stating the criteria to be kept in view for admission to the said classes ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Part time Diploma course has been started at the following institutions with effect from the session 1964-65—

(i) Central Polytechnic Chandigarh : Civil Engineering with an in-take of 20.

(ii) Guru Nanak Engineering College, Ludhiana : Mechanical Engineering with an in-take of 40.

(iii) Thapar Polytechnic, Patiala : Electrical Engineering with an in-take of 40.

(b) The minimum qualification for admission is Matriculation with Science. The duration of the Course is four years. The admission is open to the employees who are engaged in Engineering profession.

Accidents in Training Aircrafts.

2455. Chaudhri Khurshed Ahmad : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of training aircraft belonging to the State Government ;

(b) the percentage of the aircraft referred to in part (a) above which are serviceable ;

(c) the number of accidents that occurred to the said aircrafts during 1962-63, 1963-64 and 1964-65;

(d) the hourly cost of operation for flying and whether there has been any increase in this cost during the last one year; if so, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan (a) 17

(b) 82% (including aircraft under C of A)

(c) 1962-63 .. *Nil*
1963-64 .. *Nil*
1964-65 .. 3

(d) (i) About Rs. 120 per hour.

(ii) Yes. Nominal increase, due to increase in cost of petrol.

Setting up Aviation Club at Karnal

2456 **Chaudhri Khurshed Ahmad :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the progress made in the matter of construction of the aerodrome for the setting up of Aviation Club at Karnal, during the last one year ;

(b) the time by which all arrangements to start flying training at Karnal are likely to be completed ;

(c) whether he or any other senior officer has visited the aerodrome since the work started at the place mentioned in part (a) above ?

Shri Ram Kishan : (a) Acquisition proceedings for acquiring additional land were taken in hand.

(b) The airfield will be commissioned as soon as the additional land is finally acquired, technical buildings, including hangar, are constructed and necessary staff recruited.

(c) Adviser, Civil Aviation, has visited Karnal Aerodrome twice.

Grant given to Northern India Flying Club, Jullundur.

2457. **Chaudhri Khurshed Ahmad :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government has been giving any grant to the Northern India Flying Club, Jullundur for imparting training in flying to boys from poor families free of charge; if so, the total amount given as grant ;

(b) the total number of boys expected to be trained by the said Club and the number of those who have actually qualified so far ;

(c) whether it is a fact that a part of the said grant was utilised by the Club to meet the deficit on the pleasure flying of its influential members and their friends;

(d) whether it is fact that a for two years the grant remained unutilised and finally it had to be refunded to the Punjab Government ;

(e) whether it is also a fact that the grant for the purpose mentioned in part (a) above has now been stopped ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes. Rs. 10,000 in 1960-61. Rs 10,000 in 1961-62

(b) Expected number of boys to be trained in a year is 20. 31 have actually qualified.

(c) No. The amount was spent for the purpose for which it was given.

(d) Yes, partly. a sum of Rs. 13,972.78 had to be refunded to the Punjab Government in 1963-64.

(e) Yes.

Flying Clubs

2458. Chaudhri Khurshed Ahmad : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of flying clubs functioning at present in the State and the number of such clubs proposed to be started;

(b) the number of the existing clubs which had to suspend flying during the year 1964-65, together with the reasons therefor and the period of suspension in each case ;

(c) the total amount of the salaries paid to the staff of the clubs mentioned in part (b) above for the period during which there was no flying ?

Shri Ram Kishan : (a) (i) 4 (ii) 3 more.

(b) and (c) (i) Hissar Aviation Club, *Nil.* (ii) Patiala Aviation Club, *Nil.* (iii) Northern India Flying Club, 15 days, due to non-availability of petrol—About Rs 3500 were paid to the staff.

(iv) Amritsar Aviation Club. A statement is attached/-

STATEMENT

Serial No.	Month	Period of suspension	Reasons	Amount paid to staff
(1)	May and June, 1964	6 days	(i) No Fuel (ii) Tempo duly approved for carrying fuel was out of order. (iii) Death of Prime Minister Nehru.	699.03

[Chief Minister]

Serial No.	Month	Period of suspension	Reasons	Amount paid to staff
(2)	July, 1964,	11 days	(i) The only Engineer failed and extreme shortage of aircraft Maintenance Engineers.	1,383.87
			(ii) Bad weather	
(3)	August, 1964	7 days	(i) Bad weather	1,196.77
			(ii) Engineer on deputation has gone to appear in his Exam.	
(4)	October, 1964	20 days	(i) Pilots deputed to ferry Pushpaks from Bangalore	2,967.75
			(ii) Non-availability of Engineer	
(5)	November, 1964	13 days	Pilots away to ferry Pushpaks	2,240.00
(6)	December, 1964	7 days	Instructors on leave	1,083.88
(7)	February, 1965	3 days	Instructors and Engineer on leave	557.14

Health Centres and Hospitals, etc., without Doctors, Compounders and Nurses.

2461. Comrade Ram Chandra : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the number and names of Government Health Centres, Hospitals dispensaries and Ayurvedic Dispensaries in the State which have been working without (i) Doctors, (ii) Compounders and (iii) Nurses for the last two years or less, one year or less and six month or less, separately ;

(b) the steps taken by the Government to fill the vacancies referred to in part (a) above ?

Shri Prabodh Chandra : (a) and (b) The required information is given in the attached statements.

STATEMENT

Designation of post	Total No. of posts lying vacant	No. of posts lying vacant for six months or less with names of dispensaries	No. of posts lying vacant for one year or less with names of dispensaries	No. of posts lying vacant for two years or less with names of Dispenaries
1	2	3	4	5
a)				
P.C.M.S.II	62	13	17	32
		1. P.H.C., Mado Singhana (District Hissar)	1. R.D., Darbaklan (Hissar)	1. R.D., Jasrur (Amritsar)
		2. C.D., Alakh Pura (District Hissar)	2. R.D., Bass (Hissar)	2. P.H.C., Sauja (Patiala)
		3. C.H., Kandaghat (Simla)	3. C.D., Kibar (Lahaul and Spiti)	3. R.D,. Kalaran (Patiala)
		4. R.D., Jari (Kangra)	4. C.D., Saganam (Lahaul and Spiti)	4. R.D.,Sohal Thathi (Amritsar)
		5. P.H.C.,Hambran (Ludhiana)	5. C.D., Tabo (Lahaul and Spiti)	5. R.D.,Bhaindi Aulakh Amritsar)
		6. C.D., Mohleka (Amritsar)	6. P.H.C., Muzaffarpur (District Jullundur)	6. R.D.,Chahar Pur (Amritsar)
		7. R.D., Mari Mehga (Amritsar)	7. P.H.C., Thathi Bhai (Ferozepore)	7. R.D., Rehan (Kangra)

[Minister for Education and Local Government]

1	2	3	4	5
		8. P.H.C., Narot Jaimal Singh (Gurdaspur)	8. R.D.,Mallan Wala (Ferozepore)	8. Leprosy Centre, Kandbari (Kangra)
		9. R.D., Villa Teja (Gurdaspur)	9. C.D., Dunera (Gurdaspur)	9. P.H. C., Bhoranj (Kangra)
		10. R.D., Ghania Kebet. (Gurdaspur)	10. P.H.C., Gogrian (Sangrur)	10. R.D., Khundian (Kangra)
		11. P.H.C., Amlehor (Hosniarpur)	11. R.D., Kalwa (Sangrur)	11. R.D., Baroh (Kangra)
		12. P.H., C. Baba Bakala (Amritsar)	12. P.H.C., Sehlong (Mahendragarh)	12. R.D., Kangoo (Kangra)
		13. P.H.C., Bhadson (Patiala)	13. R.D., Kot (Ambala)	13. R.D., Lambochar Kalan (Ferozepore)
			14. R.D., Nurpur Bet (Ludhiana)	14. R.D., Kanianwali (Ferozepore)
			15. P.H.C., Sursingh (Amritsar)	15. R. D., Laduka (Ferozepore)
			16. C.D., Bahadurgarh (Rohtak)	16. P.H.C.,Mand (Gurdaspur)
			17. P.H.C., Fatehgarh Churian (Gurdaspur)	17. R.D., Fathegarh (Sangrur)
				18. R.D., Herika (Sangrur)
				19. R.D., Dhaliwal (Kapurthala)
				20 R.D., Talwandi Chaudhari (Kapurthala)

				21. P.H.C., Gopi (Mohindergarh)
				22. P.H.C., Dohana (Mohindergarh)
				23. P.H.C., Adhan (Hissar)
				24. R.D., Behal (Hissar)
				25. P.H.C., Mirchpur (Hissar)
				26. R.D., Jakhauli (Rohtak)
				27. P.H.C., Dhakla (Rohtak)
				28. R.D., Sohlra (Gurgaon)
				29. P.H.C., Ahar (Karnal)
				30 R.D,. Chattar (Karnal)
				31. Fourth touring Dispensary, Mohindergarh
				32. T.B. Hospital, Chetru
Assistant Medical Officers (male and female)	38	14	4	20
		Hoshiarpur—		
		C.D., Mahalpur	..	C.D., Garhdiwala
		C.D., Miani		
		P.R. T.C., Jahankhelan		
		Rohtak—		
		R.D. Matanhaili	C.D., Kosli	C.D., Bhalot
				R.D. Parmana

[Minister for Education and Local Government]

1	2	3	4	5
		Kapurthala—		
		R.D., Nadala	..	R.D., Bhullarai
		Gurgaon— R.D., Laharukhera	..	R.D., Bhangraula
				R.D., Mirpur R.D., Dahinazainabad
				R.D., Ujina
				C.D., Mohna
				Mat. Hospital, Haili Mandi
		Kangra—		
		C.D., Maceodganj	..	R.D., Jawali
				C.D., Sujanpur Tira
				R.D., Lador
				C.D., Saini
		Ferozepur— R.D., Lambi		
		C.D., Malout P.A.I., Hospital	R.D., Sarawan	
		Hissar—		
		..	C.D., Loharu	R.D., Bhiwanikhera

		Karnal— ..	..	R.D., Dhatrath
		Ambala— ..	..	C.D., Boothgarh
		Bhatinda— ..	..	C.D., Gohlewala
		Amritsar— ...	C.D., Mehta	C.D., Atari
		Patiala— R.L., Tanda Bada	..	C.D., Bahadurgarh Fort.
		Sangrur— C.D., Hadiya	...	...
		Gurdaspur— P.R.D., Qadian	..	...
			..	
		Jullundur— R.D., Mukandpur	..	...
Dispensers	27	2	12	13
		Simla— ...	B.D., Clinic, Dharampur	...
		Karnal— ..	..	P.H.C., Balah. Canal Dispensary, Munak
		Keylong— ..	Kibbar	...
		Amritsar— ..	R.D., Chawindadevi	Thicrewala

[Minister for Education and Local Government]

1	2	3	4	5
		Jullundur—		
		..	P.H.U., Shahkot.	..
		Hoshiarpur		
		..	R.D., Bahbalpur	P.H.U., Paldi
		Ludhiana—		
		P.H., Machiwara	...	
		Kangra—		
		...	R.D., Gillore R.D., Bhorang	R.D., Chari R.D., Baroh P.H.C., Annipur
				P.H.C., Hamirpur
		Rohtak—		
		..	P.H.U., Dighal	R.D., Machhrauli
			P.H.C, Kathura	P.H.U., Nahar
			P.H.C., Dhakla	
		Hissar—		
		R.D., Sisaibola	...	
		Gurgaon—		
		...	R.D., Ujina	R.D., Dhauj
		...	P.H.C., Phunhana	R.D., Tapabilochpur
				P.H.C., Dadola

Staff Nurses	14	..	..	14 **Primary Health Centres—** 1. Rajaundh 2. Bahuna 3. Tosham 4. Khol 5. Ballah 6. Thural 7. Aurangabad 8. Khande-kheri **E.S.I. Dispensaries—** 9. Hissar 10. Phagwara 11. Kapurthala 12. Gohindgarh 13. Rajpura 14. Panipat.
Vaidya/Hakims	13	4 G.A.D. Jahanda (Gurgaon) G.A.D. Doji (Ambala) G.A.D. Khunni (Kulu) G.A.D. Pachahli (Kulu)	5 G.U.D. Jhumba Bhai (Ferozepore) G.U.D. Jangliana (Hoshiarpur) G.U.D. Umra (Gurgaon) G.U.D. Barwala (Ludhiana) G.A.D. Kangoo (Kangra).	4 G. U. D. Bathu Tippri (Kangra) G.U.D. Massanian (Gurdaspur) G.U.D. Goela Panner (Ambala) G.A.D. Nithar (Kulu)

[Minister for Education and Local Government]

1	2	3	4	5
Dispensers (Ayurvedic and Unani)	39	18	10	11
		G.U.D. Kund (Gurgaon)	G.U.D. Kot Sarkari (Ambala)	G.U.D. Saha (Ambala)
		G.U.D. Rehna (Gurgaon)	G.U.D. Khanpur Dhada (Jullundur)	G.U.D. Alampur Bakka (Jullundur)
		G.A.D. Buchher (Kulu)	G.U.D. Kakkar (Kangra)	G.U.D. Raghupur (Kangra)
		G.A.D. Khunni (Kulu)	G.U.D. Dharan (Gurgaon)	G.U.D. Farmana (Rohtak)
		G.A.D. Behlolpur (Ludhiana)	G.U.D. Dhan Doi (Gurdaspur)	G.A.D. Mani Karan (Kangra)
		G.A.D. Alipur Jahangir (Ambala)	G.U.D.Khubru (Rohtak)	G.A.D. Sarga(Kulu)
		G.A.D. Doli (Ambala)	O.U.D. Kalwan (Hoshiarpur)	G.A.D. Marhianwala (Gurdaspur)
		G.A.D. Sindhar (Jullundur)	GA.D. Dhaul Kalan (Ludhiana)	G.A.D. Bir (Kangra)
		G.A.D. Gondpur Tarif (Hoshiapur)	G.A.D. Khanni (Kangra)	G.A.D. Dalash (Kulu)
		G.A.D. Pachahli (Kulu)	G.U.D. Chamkrur (Kangra)	G.A.D. Burwa (Kangra)
		G.A.D Deel (Kangra)		G.A.D. Khao (Kangra)
		G.A.D Gaggal (Kangra)		
		G.A.D. Bara (Kangra)		
		G.A.D. Karoa (Kangra)		
		G.A.D Lohardi (Kangra)		
		G.A.D. Khera (Kangra)		
		G.A.D. Chowki Manyar Kangra		
		G.A.D. Jaunji (Simla)		

Doctors. (P.C.M.S. II)

1. Usually only one doctor instead of two is posted at every Primary Health Centre and Dispensary till all the Primary Health Centres and Dispensaries which are totally without doctors are provided with at least one Doctor.

2. The candidates as soon as they become available are employed on six months baisis in anticipation of their selection by the Punjab Public Service Commission for regular appointment.

3. Some of the Dispensaries which are without Doctors, have been attached with nearly Primary Health Centres/Dispenaries having doctors for being visited by the Doctor of latter type of Primary Health Centres/Dispensaries twice a month on fixed dates.

4. Scale of pay of C.A.S. I (G) has been revised from Rs. 250-20-330/20-430/20-550 to Rs.250-25-375/25-500/25-750 w.e.f. 1st June 1961.

5. Rural Allowance has been sanctioned for doctors serving in rural areas as under —

(i) C.A.S.II (NG)	(a) MBBS.Rs. 75.00 P.M. (b) LSMF.Rs.50.00 P.M.
(ii) C.A.S.I (G)	Rs. 100.00 P.M.

6. Age limit for recruitment has been raised upto 50 years.

7. Retired and superannuated doctors are re-employed upto the age of 60 years.

8. (a) Candidates who join as C A. S. II (N.G.) after having done private practice before joining Government Service are granted one increment for every 3 years of private practice subject to the maximum of three increments.

(b) Candidates who join 3 C.A.S.I (G) in P.C.M.S. II with sufficient experience to their credit are granted one increment for every 3 years experience subject to a maximum of 5 increments on the recommendation of Punjab Public Service Commission.

9. Candidates who are admitted to the condensed M.B.B.S. course at the Medical College, Amritsar and Patiala are required to execute a bond to serve the rural area for 3 years.

10. One hundrad and fifty seats (50 in each of the Government Medical College at Amritsar, Patiala and Rohtak) have been increased in the M.B.B.S. course with effect from 1963-64.

11. The period of study in the Medical College has been reduced from 5½ to 4½ years

12. The final M.B.B.S examination is now held thrice a year instead of twice

13. Ten seats (6 in each of the Government Medical College at Amritsar and Patiala) have been increased in the condensed M.B.B.S. course with effect from 1963-64.

14. With effect from the year 1964 all M.B.B.S students doing compulsory housemanship are required to execute a bond to serve the State Government for a period of 2 years after completion or housemanship. They are paid Rs. 150 P.M. remuneration during the period of compulsory housemanship.

15. With effect from the year 1964 all students admitted to Ist yar M.B.B.S class in Government Medical Colleges in Punjab State are required to execute a bond for 3 years service after completion of M.B.B.S., Course.

16. In order to make it obligatory for every doctor to serve in rural areas it has been decided that no doctor be allowed to cross the 2nd efficiency Bar unless he/she has worked in Rural areas or at other specified place, for two years. In the case of PCMS II officers possessing post Graduate qualification their period is, however, reduced to one year.

[Minister for Education and Local Government]

Assistant Medical Officers.

(i) Candidates recommended by the S.S.S. Board have been offered appointment.

(ii) There is a proposal to upgrade the vacant posts of Assistant Medical Officers of Important hospitals/Dispensaries to that of P C Ms II because the LSMF doctors will not be available from the Arya Medical School, Ludhiana during the years to come because the classes have since been discontinued.

(iii) The selection of the licentiate doctors for admission to the condensed M.B.B.S. course has been made more liberal because the services of the young graduates are required in the rural areas of the State and they can join the posts on the condition that LSMF serving doctors should execute a bond to serve the State for five years and in default he would be required to pay Rs 10,000 in terms of bond.

The following Dispensaries have also been attached with the Primary Health Centres noted against each, to meet the shortage of doctors.

1. R D Farmana (Rohtak)	PHC	Kharkhoda (Rohtak)
2. C D Bhalot (Rohtak)	Do	Do
3. R D Bhangrola (Gurgaon)	Do	Pataudi (Gurgaon)
4. R D Dahinazainabad	Do	Khol
CD Sainj (Kulu)	Do	Khol Banjar (Kulu)
C.D. Garhdiwala (Hoshiarpur)	Do	Banjar Dasuya (Hoshiarpur)
C.D.Sarawan (Farozepore)	Do	Dasuya (Hoshiarpur)

Dispensers

1. Store-keepers are proposed to be posted against the vacant posts of dispensers till the suitable dispensers are available.

2. Retired dispensors are re-employed

Nurses

1. No. of seats of General Nursing students have been increased from 212 in 1962 to 752 by the end of 1965.

2. No. of Auxiliary Nurse Midwives increased from 370 in 1962 to 524 at the and of 1965.

Vaidyas/Hakims/Ayurvedic and Unani Dispensers

So far as the posts of Vaidyas are concerned, candidates recommended by the S.S.S. Board have been offered appointments.

As regards the posts of Hakims steps are being taken to have the candidates from other States, being not available in Punjab.

As regards filling up the posts of Dispensers a steps are being taken to recruit the candidates from the open market. It is proposed to notifiy among the qualified Up- Vaid yas of Ayurvedic College, Patiala, either to get themselves registered with the Employment Exchange or to apply to this Department for appointment. These posts are likely to be manned shortly.

Assessment of Sales Tax on Iron and Steel Products

2462. Comarde Ram Chander : Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state—

(a) whether the District Excise and Taxation Officers in the State receive the figures relating to the sales of Iron and Steel products from the officers of the Industries Department for purposes of assessment of the Sales Tax ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the Industries Officers of Jullundur, Amritsar and Ludhiana supplied such figures to their respective District Excise and Taxation Officers during 1962-63, 1963-64 and 1964-65 and whether the latter assessed the Sales Tax on the basis of those figures ?

Sardar Kapoor Singh : (a) Yes. This arrangement has recently been made in consultation with the Industries Department.

(b) The District Industries Officer, Jullundur, has supplied the information relating to the year 1963-64 only. Some information has been received from the District Industries Officer, Amritsar. The in-information relating to the District Industries Officer, Ludhiana, has also been obtained for the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65. The figures supplied by the Industries Officers are utilized by the respective officers for purposes of assessment of the concerned dealers.

Verification of utilization of Iron and Steel Quota by the Quota Holders

2463. Comrade Ram Chandra : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the District Industries Officers or Inspectors check the accounts of the Iron and Steel Manufacturers to verify if the iron, steel, copper and zinc quota issued to them, is fully and properly utilised ;

(b) whether in any case during the last three years, it was found that the quota had not been fully and properly utilized by the quota holders, if so, the action taken by the Department against them ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes Sir.

(b) Yes, quotas in such cases were suspended/cancelled. Their number yearwise is given below :—

		Iron and Steel	*Copper and Zinc*
1962	..	145	455
1963		188	59
1964	..	134	115

Masters/Mistresses of Social Education

2464. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state the total number of Masters/Mistresses of Social Education at present posted in the rural and urban areas of the State alongwith their grades of pay separately ?

Shri Prabodh Chandra :

Serial No.	Designation of post	Total No.	Grade of pay
1	Social Education Workers for Urban Scheme (for Jullundur and Ambala Circles only)	69	Rs 50—3—80/4—100 with usual allowances
2	Squad Teachers for rural areas (for Jullundur and Ambala Circles only)	53	Ditto
3	Bonus Workers (Part-time) for rural scheme (for Jullundur and Ambala Circles only)	13	Rs 40 per mensem Consolidated as Honorarium

4. Information in respect of Rohtak and Bhatinda Circles is under collection and will be supplied later.

Development of Civil Aviation in the State

2465. Sardar Harchand Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that during 1964-65, little or no progress was made for the development of Civil Aviation in the State ;

(b) the number of officers and of the other staff in the Aviation Department at present and the number of those among them who possess any experience, training or the prescribed qualifications for the nature of work required to be done by them ;

(c) whether he has visited any of the Aerodromes under construction or the Aviation Clubs in the State to make personal assessment of the progress ?

Shri Ram Kishan :

(a) No. the Civil Aviation Department has made sufficiently good progress

(b) Annexure 'A' and 'B' are printed as undes :—

(c) No.

ANNEXURE 'A'

Qualifications and experience of Air Vice Marshal Harjinder Singh, Honorary Adviser, Civil Aviation, Punjab

(i) M. I. S. E., M. A. E. S. I., M. I. E. (Ind.)
M .I. Prod. E. (Lond.) ; M. I. Mech. E. (Lond.) ;
F. R. C. S. (Lond.)

(ii) First Indian elected to the Experimental Aircraft Association of America.

(iii) Aircraft Maintenance Engineer in all the categories 'A', 'B', 'C', 'D' and 'X' open for all types of aircraft up to Dakota.

(iv) 33 years experience in Air Force.

(v) Designer and Architect of Kanpur I and Kanpur II Aircraft.

(vi) Has been holding Private Pilot Licence and Commercial Pilot Licence and also has been a Test Pilot.

(vii) Visited number of foreign countries in various purchase Missions (Aircraft, etc.)

(viii) Director of Hind Provincial Flying Club, U. P. for 10 years.

(ix) President of Flying Club, Kanpur, for 15 years.

(x) Member of the Northern India Flying Club, for 16 years and Delhi Flying Club, 12 years.

(xi) First I. A. F. Officer, who was awarded Vashisht Seva Medal, Class I, by the President of India for most exceptional and meritorious services rendered in building the Indian Air Force and setting up a Transport Aircraft Factory (AVRO 748) in a record time of 18 months from blue print to a flying aircraft stage.

(xii) For 8 years has been Air Officer Commanding In-Chief of a Command of the Indian Air Force, which controlled over two dozen units of I. A. F. spread all over India.

ANNEXURE 'B'

Qualifications and experience of the Supporting Staff

1. Adviser Civil Aviation, Punjab .. As in annexure 'A'

2. Administrative-cum-Publicity Officer .. (*vacant*) Being recruited from the Punjab Civil Secretariat

3. Store Purchase Officer .. (*Vacant*) Not available

4. Superintendent .. Proceeded on terminal leave with effect from 16th March, 1965

5. Technical Assistant .. One

Shri A. S. Bhullar has seven years flying experience and has done 370 hours as pilot, 262 hours as Navigator, and well experienced in Flying Clubs and Aerodromes Organisations.

6. Assistants .. Two

Shri V. G. Goel has about 7 years administrative experience and had obtained training in various branches of Aviation and Gliding Flying Clubs Administration.

7. Accountant	One	Usual qualifications prescribed by the Punjab Government
8. Stenographer Senior Scale	One	
9. Stenographer Junior Scale	One	
10. Steno-typist	One	
11. Clerks	Four	one post vacant

[Chief Minister]

12. Daftri	..	One	Vacant
13. Draftsman	..	One	
14. Driver	..	One	
15. Peons	..	Five	Two posts vacant
16. Chaukidar-cum-Mali	..	One	

Persons proceeded against under Section 105 of Punjab Gram Panchayats Act, 1952, in Gurgaon District

2465. **Chaudhri Har Kishan :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the names and addresses of the persons in Gurgaon District who have been proceeded against under section 105 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952, together with the latest position in respect of each of these persons ?

Sardar Darbara Singh : A statement showing the information is laid on the Table of the House.

Serial No.	Names and addresses of persons against whom action under section 105 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 is proceeded	Latest position
1	Shri Pirbhu Singh, ex-Sarpanch, Panchayat Daboda, Block Gurgaon	Final notices have been issued
2	Shri Medu Ram, ex-Sarpanch, Panchayat Mubarikpur, Block Gurgaon	
3	Shri Karan Singh, ex-Sarpanch, Allika, Block Palwal	Notice has since been served
4	Shri Pala Singh, ex-Sarpanch, Ghughera, Block, Palwal	Notice has since been served. The explanation of the Sarpanch is under consideration
5	Shri Jawahar Singh, ex-Sarpanch, Dhatir, Block, Palwal	The ex-Sarpanch has filed an appeal against the order of B. D. O., to the Assistant, Director of Panchayats Punjab, Ambala Division
6	Shri Dharmi, ex-Sarpanch, Pelak, Block Palwal	Final orders under section 105 have been issued
7	Shri Sohan Lal, ex-Sarpanch, Durgapur, Block Palwal	Ditto
8	Shri Lachhman Singh, ex-Sarpanch, Solra, Block Palwal	Final orders under section 105 have been issued

Serial No.	Names and addresses of persons against whom action under section 105 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1962 is proceeded	Latest position
9	Shri Bijai Ram, ex-Sarpanch, Pirthla, Block Palwal	Final orders under section 105 have been issued
10	Shri Jagdish ex-Sarpanch, Akbarpur Dakora, Block Palwal	The ex-Sarpanch has filed an appeal against the order of B.D.O., to Assistant. Director of Panchayats, Punjab, Chandigarh
11	Shri Devi Ram, ex-SarpanchŒ Panchayat Jodhpur, Block Palwal	Final orders passed by the B. D. O.
12	Shri Ganpat Singh, ex-Sarpanch, village and post office, Nangli Godha, tahsil Rewari, Block Khol	Notice has been issued and final action is being taken
13	Shri Ram, ex-Sarpanch of Panchayat Jatuwas, post office, Rewari, Block Khol	Ditto
14	Shri Amar Singh, ex-Sarpanch of Panchayat Kalaka, post office, Majra Gurdas, Block Khol	Ditto
15	Shri Ishar Singh, Present Sarpanch of Gram Panchayat MandiaKalan, post office, Majra Gurdas, tahsil Rewari, Block Khol	Ditto
16	Shri Puran Singh, ex-Sarpanch, Khijuri, tahsil Rewari, Block Khol	Ditto
17	Shri Chandgi Ram, ex-Sarpanch, Nangal Jamalpur, Block Khol	Notice has been issued and final action is being taken
18	Shri Suraj Mal, ex-Sarpanch, Khol, tahsil Rewari, Block Khol	Ditto
19	Shri Jasmal Khan, ex-Sarpanch, village Rethora Block Nuh	Notices have been issued
20	Shri Sahzad Khan, ex-Sarpanch, village Tain, Block Nuh	Ditto
21	Shri Moh. Alyas, ex-Sarpanch, Akera, Block Nuh	Ditto
22	Shri Nasib Khan, ex-Panch, Panchayat Akera, Block Nuh	Ditto
23	Shri Bhondu, ex-Panch, Panchayat Akera, Block Nuh	Ditto
24	Shri Umrao, ex-Panch, Panchayat Akera, Block Nuh	Ditto
25	Shri Het Ram, ex-Panch, Panchayat Akera, Block Nuh	Ditto
26	Shri Lal Man, ex-Sarpanch, village Kalarpuri, Gram Panchayat Didhara, Block Nuh	Ditto

Serial No.	Names and addresses of persons against whom action under section 105 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 is proceeded	Latest position
27	Shri Gobardhan, Ex-Panch, village Kalapuri, Gram Panchayat Didhara, Block Nuh	Notices have been issued and reply awaited
28	Shri Jai Singh, Ex-Panch, village Kalapuri, Gram Panchayat Didhara, Block Nuh	Ditto
29	Shri Ram Parshad, Ex-Panch, village Didhara, Gram Panchayat Didhara, Block Nuh	Ditto
30	Shri Dholi, Ex-Panch, village Didhara, Gram Panchayat Didhara, Block Nuh	Ditto
31	Shri Ramji Lal, Ex-Panch, Chondhika, Gram Panchayat Didhara, Block Nuh	Ditto
32	Shri Hukam Singh, Ex-Sarpanch, Kaliaka, Gram Panchayat Kaliaka, Block Nuh	Ditto
33	Shri Puran, Ex-Sarpanch, village Saroli, Gram Panchayat Saroli, Block Nuh	Ditto
34	Shri Yasin Khan, Ex-Sarpanch, village, Bainsi, Gram Ponchayat Bainsi, Block Nuh	Ditto
35	Shri Umrao Khan, Ex-Panch, village Bainsi, Gram Panchayat Bainsi, Block Nuh	Ditto
36	Shri Tej Ram, Ex-Panch, village Bainsi, Gram Panchayat Bainsi, Block Nuh	Ditto
37	Shri Pritam Singh, Ex-Panch, village Bainsi, Gram Panchayat Bainsi, Block Nuh	Ditto
38	Shri Ram Chand, Ex-Panch, village Bainsi, Gram Panchayat Bainsi, Block Nuh	Ditto
39	Smt. Makhi, Ex-Panch, village Bainsi, Gram Panchayat Bainsi, Block Nuh	Ditto
40	Shri Basir Ahmad, Ex-Sarpanch, Patti Karwari, Gram Panchayat Shahsola, Block Nuh	Ditto Ditto
41	Shri Ahmad Hussain, Ex-Panch, Patti, Bhutlaka, Gram Panchayat Shahsola, Block Nuh	Ditto
42	Shri Nawal Khan, Ex-Panch, Patti, Patuka, Gram Panchayat Shahsola, Block Nuh	Ditto
43	Shri Chet Ram, Ex-Panch, Patti Pipaka, Gram Panchayat Shahsola, Block Nuh	Ditto
44	Shri Zahoor Khan, Ex-Panch, Patti Ghus Bathi, Gram Panchayat Shahsola, Block Nuh	Ditto
45	Shri Mohmandi, Ex-Panch, Patti Ghus Bathi, Gram Panchayat Shahsola, Block Nuh	Ditto
46	Shri Fateh Moh. Ex-Sarpanch, village Shikarpur, Gram Panchayat Shikarpur, Block Nuh	Ditto

Serial No.	Names and addresses of persons against whom action under section 105 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 is proceeded	Latest position
47	Shri Raghbir Singh, Ex-Panch, village, Gangoli, Gram Panchayat Gangoli, Block Nuh	Notice has been issued and reply is awaited
48	Shri Duli Chand, Ex-Panch, village, Gangoli, Gram Panchayat Gangoli, Block Nuh	Ditto
49	Smt. Badan Kaur, Ex-Panch, village Gangoli, Gram Panchayat Gangoli, Block Nuh	Ditto
50	Shri Makhan Singh, Ex-Sarpanch, village and Gram Panchayat Bharavti, Block Nuh	Ditto
51	Shri Jita Singh, Ex-Sarpanch, village and Panchayat Indri, Block Nuh	Ditto
52	Shri Kanhya Singh, Ex-Panch, village and Panchayat Indri, Block Nuh	Ditto
53	Shri Kale Khan, Ex-Sarpanch, Gharora, Gram Panchayat Charora, Block Nuh	Ditto
54	Shri Kanhiya Singh, Ex-Sarpanch, Kurthla, Block Nuh	Ditto
55	Shri Shankar Singh, Ex-Sarpanch, Alduka, Block Nuh	Ditto
56	Shri Rashola, Ex-Sarpanch, Rehna, Block Nuh	Decided
57	Shri Shakura Khana, Ex-Sarpanch, Padheni, Block Nuh	Notice has been issued and reply is awaited
58	Shri Yasin Khan, Ex-Sarpanch, Malab, Block Nuh	Ditto
59	Shri Ishmail Khan, Ex-Panch, Malab, Block Nuh	Ditto
60	Shri Feroz Khan, Ex-Panch, Malab, Block Nuh	Ditto
61	Shri Nabi Khan, Ex-Panch, Malab, Block Nuh	Ditto
62	Shri Nathu, Ex-Panch, Malab, Block Nuh ..	Ditto
63	Shri Ishmal, Ex-Panch, Malab, Block Nuh	Ditto
64	Smt. Chandbi, Ex-Panch, Malab, Block Nuh	Notices have been issued
65	Shri Badri Parshad, Ex-Panch, Malab, Block Nuh	Ditto
66	Shri Shitab Khan, Ex-Sarpanch, Dohana, Block Nuh	Ditto
67	Shri Bakhtu, Ex-Panch, Dehana Block Nuh	Ditto
68	Shri Dhammat, Ex-Panch, Dehana, Block Nuh	Ditto
69	Shri Ishak, Ex-Panch, Dehana, Block Nuh	Ditto

[Home and Development Minister]

Serial No.	Names and addresses of persons against whom action under section 105 of the Punjab Gram Panchayat Act 1952 is proceeded	Latest position
70	Shri Ghosan, Ex-Panch, Dehana, Block Nuh	Notices have been issued and reply is awaited
71	Shri Ganeshi Lal, Ex-Sarpanch Nangal Teju, Block Bawal	Ditto
72	Shri Usaf Khan Ex-Sarpanch, Sakras, Block Bawal	Ditto
73	Shri Ismail Khan, Ex-Sarpanch, Padla Shahpur, Block Bawal	Ditto
74	Shri Hushmal Khan, Ex-Sarpanch, Ghagas, BlockBawal	Ditto
75	Shri Husain Khan, Sarpanch, village Ghagas, Block Bawal	Ditto
76	Shri Zahur Khan, Sarpanch, village Naoli, Block Bawal	Ditto
77	Shri Chao Khan, Ex-Sarpanch, Rigarh, Block Bawal	Ditto
78	Shri Sugra Khan, Ex-Sarpanch Bhadus, Block Bawal	Ditto
79	Shri Mohd. Shafi Sarpanch, Baded, Block Bawal	Ditto
80	Shri Sufed Khan, Sarpanch, Ainchwari, Block Bawal	Ditto
81	Shri Ibrahim Khan, Sarpanch, village Malhuka, Block Bawal	Ditto
82	Shri Dalpat, Sarpanch, village Jalalpur, post office Nuh, Block Bawal	Ditto
83	Shri Abdul Rao Sarpanch, Kherli Nuh, Block Bawal	Ditto
84	Shri Chahat Khan, Sarpanch, Uleta, Block Bawal	Ditto
85	Shri Rura Khan, Sarpanch, Patkheri. Block Bawal	Ditto
86	Shri Moti Ram, Ex-Sarpanch, Pingore, Block Bawal	Necessary loss has been assessed
87	Shri Naval Singh, Ex-Sarpanch, Dakora, Block Bawal	Their replies are being examined
88	Shri Panni, Panch, Panchayat, Dakora, Block Bawal	
89	Shri Lakhi, Ex-Sarpanch, village Karwan, Block Bawal	

Serial No.	Names and addresses of persons against whom action under section 105 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 is proceeded	Latest position
90	Shri Kachera Ex-Sarpanch, Gulawad, Block Bawal	Their replies are being examined
91	Shri Digamber Singh, Ex-Sarpanch, Sondha, Block Bawal	
92	Shri Khiman, Ex-Sarpanch, village Tikri Gujar, Block Bawal	
93	Shri Khili, Ex-Sarpanch, village Ramgarh, Block Bawal	His reply is awaited
94	Shri Bhagirath Singh, Ex-Sarpanch, Bhiduki, Block Bawal	His reply is being examined
95	Shri Prabhu Dayal, Sarpanch, Karawara Manakpur, Block Bawal	Notices have been issued. Reply is awaited
96	Shri Shiv Rattan, Sarpanch, Dharuhera ..	Notices have been issued. Reply is awaited
97	Shri Raghubir Singh, Sarpanch, Ramgarh	Ditto
98	Shri Gian Singh, Sarpanch, Gokalpur ...	Ditto
99	Shri Ram Sarup, Sarpanch, Nanukhurd ..	Ditto
100	Shri Bansi Ram, Sarpanch, Turkapur	Ditto
101	Shri Phul Singh, Sarpanch, Lohchab ..	Ditto
102	Shri Shambu Dayal, Ex-Sarpanch, Gangechia Jat, Rewari	Ditto
103	Shri Ram Sarup, Sarpanch, Gokalgarh, Block Rewari	Ditto
104	Shri Khem Ram, Ex-Sarpanch, Kanwali, Block Rewari	Ditto
105	Shri Bharat Singh, Ex-Sarpanch, Bhoria Kamalpur, Block Rewari	Ditto
106	Shri Manphool Khan, Ex-Panch, Bhoj, Block Ballabgarh	Ditto
107	Shri Ram Chander, Ex-Sarpanch, Badrola, Block Ballabgarh	Ditto
108	Shri Khazan Singh, Ex-Sarpanch, Bhukharpur, Block Ballabgarh	Ditto
109	Shri Chander Sukh, Ex-Sarpanch, Sagarpur, Block Ballabgarh	Ditto
110	Shri Mange Ram, Ex-Sarpanch, Nawada Tigaon, Block Ballabgarh	Ditto
111	Shri Parmanand, Ex-Sarpanch, Jharsetli, Block Ballabgarh	Ditto
112	Shri Sawan Singh, Ex-Sarpanch, Deeg, Block Ballabgarh	Ditto

[Home and Development Minister]

Serial No.	Names and addresses of persons against whom action under section 105 of the Punjab Gram Panchayat Act 1952 is proceeded	Latest position
113	Shri Nanak Chand, Ex-Sarpanch, Mohla, Block Ballabgarh	Notices have been issued. Reply is awaited
114	Shri Subedar, Ex-Sarpanch, Badkhal, Block Faridabad	Ditto
115	Shri Sangat Ram, Ex-Sarpanch, Meola Maharajpur, Block Faridabad	Ditto
116	Shri Chuni Singh, Ex-Sarpanch, Ajronda, Block Faridabad	Ditto
117	Shri Ram Chander, Ex-Panch, Ajronda, Block Faridabad	Ditto
118	Shri Sukhan Lal Ex-Panch, Ajronda, Block Faridabad	Ditto
119	Shri Ghamandi, Ex-Panch, Ajronda, Block Faridabad	Ditto
120	Shri Dhantili, Ex-Panch, Ajronda, Block Faridabad	Ditto
121	Smt. Champi Devi, Ex-Panch, Ajronda, Block Faridabad	Ditto
122	Shri Dal Chand, Ex-Panch, Ajronda, Block Faridabad	Ditto
123	Shri Lekhi Ram, Ex-Sarpanch, Itmadpur, Block Faridabad	Ditto
124	Shri Basanta, Ex-Panch, Itmadpur, Block Faridabad	Ditto
125	Shri Puran Chand, Ex-Panch, Itmadpur, Block Faridabad	Ditto
126	Shri Chandi Ram, Ex-Panch, Itmadpur, Block Faridabad	Ditto
127	Shri Bhole, Ex-Panch, Itmadpur, Block Faridabad	Ditto
128	Smt. Attro, Ex-Panch, Itmadpur, Block Faridabad	Ditto
129	Shri Jag Ram, Ex-Sarpanch, Bhainsawali, Block Faridabad	Ditto
130	Shri Jagmal, Ex-Panch, Bhainsawali, Block Faridabad	Ditto
131	Shri Lekh Ram, Ex-Panch, Bhainsawali, Block Faridabad	Ditto
132	Shri Sameru, Ex-Panch Bhainsawali, Block Faridabad	Ditto

Serial No.	Names and addresses of persons against whom action under seetion 105 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 is proceeded	Latest position
133	Smt. Dalip Kaur, Ex-Panch, Bhainsawali, Block Faridabad	Notices have been issued. Reply is awaited.
134	Shri Bucha, Ex-Sarpanch, Tigaon, Block Faridabad	Ditto
135	Shri Lakhi Ram, Ex-Panch, Tigaon, Block Faridabad	Ditto
136	Shri Mohinder Singh, Ex-Panch, Tigaon, Block Faridabad	Ditto
137	Shri Lakha, Ex-Panch, Tigaon, Block Faridabad	Ditto
138	Shri Chet Ram, Ex-Panch, Tigaon, Block Faridabad	Ditto
139	Shri Ramou, Ex-Panch, Tigaon, Block Faridabad	Ditto
140	Shri Bishani, Ex-Panch, Tigaon, Block Faridabad	Ditto
141	Shri Harchandi, Ex-Panch, Tigaon, Block Faridabad	Ditto
142	Smt. Ram Bala, Ex-Panch, Tigaon, Block Faridabad	Ditto
143	Shri Sultan Singh, Ex-Panch, Sarai Khawaja, Block Faridabad	Ditto
144	Shri Ramesh, Ex-Panch, Sarai Khawaja, Block Faridabad	Ditto
145	Smt. Kapuri, Ex-Panch, Sarai Khawaja, Block Faridabad	Ditto
146	Shri Baldhari, Ex-Panch, Sarai Khawaja, Block Faridabad	Ditto
147	Shri Dalip, Ex-Panch, Sarai Khawaja, Block Faridabad	Ditto
148	Shri Umrao Singh, Ex-Sarpanch, Manesar, Block Sohna	Ditto
149	Shri Kanwar Singh, Ex-Sarpanch, Kankrola, Block Sohna	Ditto
150	Shri Manohar Lal, Ex-Sarpanch, Makalwas, Block Sohna	Ditto
151	Shri Abdul Rehman, Ex-Sarpanch, Papra, Block Punhana	Ditto
152	Shri Rehmat Khan, Ex-Sarpanch, Bisru, Block Punhana	Ditto
153	Shri Jhaman, Sarpanch, Godhola, Block Punhana	Ditto
154	Shri Dhanpat Rai, Ex-Sarpanch, Hathin, Block Hathin	Ditto

[Home and Development Minister]

Serial No.	Names and addresses of persons against whom action under section 10ç of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 is proceeded	Latest position
155	Shri Narain Singh, Ex-Sarpanch, Manpur, Block Hathin	Notices have been issued. Reply is owaited.
156	Shri Singram, Sarpanch, Janacholi, Block Hathin	Ditto
157	Shri Lakhpat, Sarpanch, Roopraka, Block Hathin	Ditto
158	Shri Usaf Khan, Ex-Sarpanch, Malai, Block Hathin	Ditto
159	Shri Mauzam Khan, Ex-Sarpanch, Ghuraoli, Block Hathin	Ditto
160	Shri Manchi Ram, Ex-Sarpanch, Janacholi, Block Hathin	Ditto
161	Shri Puran Singh, Ex-Sarpanch, Puthli, Block Hathin	Ditto
162	Shri Chhutmal, Ex-Sarpanch, Utawar, Block Hathin	Ditto
163	Shri Rehmat Khan, Ex-Sarpanch, Khiluka, Block Hathin	Ditto
164	Shri Jaroor Khan, Ex-Sarpanch, Kalinjar, Block Hathin	Ditto
165	Shri Nawal Khan, Ex-Sarpanch, Sanpalki, Block Hathin	Ditto
166	Shri Jallukhan, Ex-Sarpanch, Duranchi, Hathin	Ditto
167	Shri Tek Ram, Sarpanch, Kondal, Block Hathin	Ditto

Representation from a Municipal Commissioner, Hissar (under Detention)

2467. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether Government has received any representation from Shri Rachhpal Singh, Municipal Commissioner, Hissar (now under detention under the D.I.R.) for making necessary arrangements to administer oath to him as a Municipal Commissioner ; if so, the action taken thereon so far ;

(b) if no action has been taken, the reasons therefor and a copy of the said representation be placed on the Table of the House ?

Sardar Darbara Singh (Home and Development Minister) : (a) Yes. The representation was rejected and he was informed that he could take oath after his release from detention.

(b) A copy of the representation is placed on the Table of the House.

(COPY)

To

The Minister for Local Bodies, Government of Punjab,
Chandigarh.
Through Superintendent, Jail Gurgaon.

Subject.—Taking of oath as member of Municipal Committee Hissar.

Shriman Ji,

I beg to draw your kind attention towards the following facts for your kind consideration and an early action.

(1) That I was declared elected as member of Hissar Municipal Committee on 15th November, 1964, and my name appeared in *Punjab Government Gazette*, published in the first week of January, 1965.

(2) That at present I am under detention in Gurgaon Jail, since 30th December, 1964, and is unable to take oath as member of Municipal Committee Hissar according to law.

(3) That I had sent applications to D.I.G., C.I.D. Chandigarh and D.C., Hissar, respectively on 13th January, 1965 through Superintendent, Jail Gurgaon in this connection. But received no reply so far.

(4) That I was elected from Ward No. 9 comprising Hissar Textile Mills area and Industrial Labour Colony inhabited by Mills Labour only.

I was opposed by an official of the Mills actively helped by the Hissar Textile Mills management.

The Hissar Mills management is very influential in District officials and they might use their influence for delaying my oath taking.

It is, therefore, requested that appropriate authorities may please be directed to facilitate my oath taking, so that I may not be disqualified for no fault of mine.

An early action on this application is requested.

Yours truly,
(Sd/-) Rachpal Singh,
Detenu, Gurgaon Sub-Jail.

The 19th January, 1965.

Representation from Shri Satya Mandan a detenu regarding search made in his house

2469. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether the Government has received any representation from Shri Satya Mandan (Sarpanch of village Shahpur first) district Mohindergarh, now Detenu under the D.I.R. alleging illegal search of his house at Narnaul on or about the 23rd January, 1965, while his wife was an indoor patient in Civil Hospital in Narnaul and nobody was in the house and it was locked, if so, the action so far taken thereon and a copy of the said representation be placed on the Table of the House ;

(b) the reasons for the said search.

(c) a copy of the first search report lodged in the Thana Daily Diary before the Police started for the search mentioned above be also placed on the Table of the House ;

(d) a copy of the search memo with the details of the recovery made as a result of the search along with the report in the Daily Diary regarding the arrival of the search party at the Police Station be laid on the Table ?

Sardar Darbara Singh : (a) A copy of the representation is laid on the Table . When the search party reached the house of Shri Satya Mandan, it was locked. His son Shri Anand was sent for. The keys were not handed over to the search party and, therefore, the lock was broken in the presence of Shri Anand and two reliable witnesses. All formalities in connection with house search were completed.

(b) The house was to be searched to find out any prescribed or any anti-national documents or publications.

(c) & (d) Copies are placed on the Table of the House.

Shri Darbara Singh,
Home Minister, Punjab, Chandigarh.

Through the Superintendent, District Jail, Rohtak.

Subject.—My house twice ransacked by police.

Shriman Ji,

I am in detention here under rule 30 (1) (b) of the D.I.R. I was arrested in the early morning of 29th December, 1964 and was brought here the same day. In the absence of my wife in hospital, who is the only member in my family save myself. My house was opened by breaking the lock and Kunda, and searched inspite of the fact that my hou se had already been searched the day after my arrest in the presence of my wife and my father. The house has totally been upset and ransacked. The full facts are as under :—

(1) That after my arrest my house was searched by the Police in the presence of my wife and my father, who lives apart from me.

(2) That my wife was ailing for quite some time past and after my arrest, as there was nobody to look her after and serve her, she got herself admitted in the Civil Hospital Narnaul.

(3) That she had gone on admission in the hospital after safely locking the house.

(4) That in the early morning of 23rd January, 1965, two police officials accompanien by some constables came and began to break open the lock and Kunda of the house. That several persons gathered and objected to the breaking the lock and Kunda on the ground that there was nobody at the house. They even offered to call for my father and requested them to wait until he comes. But they did'not hear them and even threatened them and broke the lock and Kunda of the house and searched the house at their own sweat will, and virtually looted it.

(5) That my wife has informed me that rupees fifty kept by her in a drawer, are missing.

(6) That rupees hundred had been kept by me in an almirah and the key of the same had been kept by me safely. I Do not know the fate of this amount as my wife was not aware of serious sickness. I have written her to let me know about it. This amount had to be returned to two friends from whom I had borrowed .

(7) That besides this there was a sewing machine and some jewellery of my wife, also household utensils and other articles, what of them are missing she has not yet been to able convey me fully because she is still seriously sick and burdened with grief and shock at this outrage. I have wrote her to convey me full details of the missing articles.

(8) That there is a valuable and costly collection of books in my house. I don't know the fate and condition of these books for being not so much educated. Also there was a huge lot of material collected for writing a book and material for writing fiction.

(9) That in an iron almirah there was huge record of a co-operative society and also some record of Gram Panchayat of which I am the sarpanch. I was working on that record the very night of my arrest.

(10) That what has been the loss to the things given in para Nos. 8 and 9, i.e. what are missing and what have been damaged and to what extent. I can only tell after thoroughly going through them.

All this is illegal and a virtual loot by unscrupulous officials. I may be provided an opportunity to see the belongings of my house thoroughly to ascertain my loss.

And the officials who acted in such an arbitrary, ruthless, vindictive and illegal manner be dealt with properly and my loss be good from them. There are some officials in Police who bear malious to me. That I can tell if the names and ranks of the officials who searched my house, are known to me, and I can tell that with a convincing proof.

Soliciting a prompt consideration and action.

Dated the 18th February, 1965.

Yours faithfully,
(Sd/-) SATYA MANDAN,
son of Rao Madho Singh village Shahpur
District Mohindergarh,
Detenus
District Jail, Rohtak.

नकल रपट नं० 30, तारीख 23 जनवरी, 1965, थाना नारनौल

क्रम संख्या	नाम इतलाही	रपट किस्म	रपट का खुलासा
30	एस. आई. मंगत राय, एस. एच. ओ., नारनौल	रवानगी खुद	समय 6-15 ए.एम.

मय एस. आई. मये ए. एस. आई तेलू राम, सि. हनुताराम 136, पहलाद सिंह 118, सोहन लाल 218, राम नारायण 119, कालू राम 326, राम नारायण 3, राम चन्दर 276, बगज़ अदाए खुफिया ड्यूटी रवाना शहर नारनौल का हुआ। और ए.एस. आई. नाहर सिंह सि. रूप चन्द 245, सुल्तान सिंह 295 की बगज़ करने रैड़ मुतलका खुफिया डियूटी होशियार सिंह हरिजन के मकान पर मामूर किया गया। डियूटी के बारे मुनासिब हिदायत दी गई और जवानों को एक एक अदद लाठी मालखाना थाना से दिलाई जाकर रिवालवर खुद 38 बोर मय 18 कारतूस दरुस्त हासल किया गया।

हस्ताक्षर सदा राम, एच. सी.,
थाना नारनौल
23-1-65।

साक्षायाकित
मुख्य क्लर्क,
पुलिस कार्यालय, नारनौल।
10-3-65।

[Home and Development Minister]

फरद खाना तलाशी

रबरू, गवाहान निम्न लिखित खाना तलाशी सत्य मंडण पुत्र माधो सिंह, नारनौल बमौजूदगी आनंद, पुत्र मुनबन्ना सत्यनारायण ली गई कोई चीज़ बरामद हो कर क़ब्ज़ा पुलिस में नहीं ली गई।

(हस्ताक्षरित) मंगत राये,
एस. एच. ओ.,
नारनौल ।

भागीर्थ, पुत्र हीरा नंद सैनी, नारनौल (द:)भार्गीर्थ	आन्नद दस्तखत करने से इनकारी है हस्ताक्षरित: मंगत राये, एस. आई. 23-1-65	श्री नेत राम, पुत्र माम राज, नारनौल (द:) नेत राम, एम.सी.

साक्ष्याकित
मुख्य क्लर्क,
पुलिस कार्यालय, नारनौल।
10-3-65 ।

नकल रपट नं० 9, तारीख 23-1-65, थाना नारनौल

क्रम संख्या	नाम इतलाही	रपट किस्म	रपट का खुलासा
9	मंगत राए, एस. एच. ओ.	वापसी	समय : 10.40 बजे शुबा मन

एस. एच. ओ. मय मुलाज़मान बहवाला रपट नं० 30 रोजनामचा बन्दशुदा बाद खाना तलाशी मंगल, सत्य मन्डन, मान, होशियार सिंह, देवकी नन्दन, सी. पी. आई. वर्कर वापिस आया। फरदात खाना तलाशी अलैदा मुरतब हुई व खुद मुकर्रर ए. एस. आई. नहार सिंह को वापस खाना लाइन का किया गया।

हस्ताक्षरित : मंगत राय, एस. एच. ओ.,
नारनौल ।
23-1-65

साक्ष्याकित
मुख्य क्लर्क,
पुलिस आधिक्षक, ज़िला महेन्द्रगढ़,
नारनौल ।
10-3-65

Communist Detenus and treatment given to them in Jails

2471. Comrade Makhan Singh Tarsikka Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of communist detenus recently arrested in the State together with the details of the treatment being given to them in the Jails ;

(b) whether the Legislator detenus have been given 'A' class if not, the reasons therefor and the action Government proposes to take against the officers who are responsible for not giving the status due to the Legislator ;

(c) the daily diet allowance being given to the detenus at present according to the Detenus Rules, 1950 ;

(d) whether in view of the high prices the Government has reviewed or proposes review the present diet allowance etc. which was fixed keeping in view price index of 1950 ; if so, the approximate time by which a final decision in the matter is likely to be taken ?

Shri Ram Kishan : (a) A list containing the names of the communist detenus arrested and detained in the State Jails is given as under. (ii) The detenus are treated according to the Punjab Detenus Rules, 1950.

(b) (i) No.

(ii) The Legislator detenus have been classified as B Class detenus by the District Magistrates concerned in accordance with the instructions issued by the Government in this regard. The question of taking action against any official, therefore, does not arise.

(c) 'A' class detenus at Rs 2.25 per day.

'B' class detenus at Rs 1.75 per day.

'C' class detenus according to the scale as allowed to criminal prisoners of 'C' class.

(d) Yes. The matter is under the consideration of Government and a final decision is expected to be taken soon..

LIST OF COMMUNIST DETENUS

1. Chattar Singh.
2. Satya Mandan.
3. Vidya Dev Longowal.
4. Fauja Singh Bhullar.
5. Chanan Singh Dhutt.
6. Dalip Singh Tapiala.
7. Gajjan Singh.
8. Daya Singh Prem.
9. Makhan Singh Tarsikka.
10. Darshan Singh Jhabal.
11. Gurbux Singh Dakota.
12. Bhag Singh Sajjan.
13. [illegible]twant Singh.
14. Harnam)Singh Chamak.
15. Bhim Singh Advocate.
16. Chanan Singh Brar.
17. Raghbir Singh Jhakkar.
18. Rachhpal Singh.
19. Ram Singh Harindu.
20. Hazara Singh.
21. Ude Singh Keshav.
22. Janak Singh Bhattal.
23. Dharam Singh.
24. Gandharab Sen.
25. Ghuman Singh Urgrahan.
26. Balbir Singh.
27. Gurbux Singh Atta.
28. Dr. Bhag Singh.

[Chief Minister]

29. Hardit Singh Bhattal.
30. Prem Chand Bhardwaj.
31. Mange Ram Vats.
32. Gian Singh.
33. Gurcharan Singh.
23. Ram Kishan Bharolian.
35. Rachhpal Singh.
36. Dhanpat Rai Nahar.
37. K. R. Palta.
38. Kishori Lal Rattan.
39. Ishar Singh Sodhi.
40. Dharam Singh Kasni.
41. Kesar Singh.
42. Kartar Singh.
43. Hazara Singh.
44. Amarmeet Singh.
45. Sulakhan Singh.
46. Karnail Singh Phide.
47. Bishen Singh.
48. Sarwan Singh Cheema.
49. Mehar Singh.
50. Gurnam Singh.
51. Ganda Singh
52. Devki Nandan.
53. Bhajan Singh.

Electrification of certain villages in Jandiala and Tarsikka Blocks

2473. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the number and names of villages which were to be electrified in the years, 1963-64 and 1964-65 in Amritsar District ;

(b) the names of the villages referred to above which have since been electrified together with the reasons for not electrifying the remaining villages ;

(c) the time within which Bhagwan, Guli, Rana Kala villages in Jandiala Block and Naraingarh, Talwandi shapure and Tand Taharpur, Sarai, Bulara and other remaining villages of Tarsikka Block are expected to be electrified.

Chaudhri Rizaq Ram : (a) (i) 4 villages were to be electrified during the year 1963-64. 37 villages were actually electrified.

(ii) Due to paucity of funds no programme for the electrification of fresh villages to be electrified during the year, 1964-65 was prepared.

(b) (i) List printed in Annexure I and II.

(ii) In view of the reply against (a) (ii) above the question of supplying the list of remaining villages does not arise.

(c) It is not possible to indicate the time by which the villages Bhagwan, Duli and Rana Kalan of Jandiala Block and villages Naraingarh, Talwandi Shahpur, Tand, Taharpur, Saria, Bhalara and other remaining villages of Tarsikka Block will be electrified as no specified programme for electrification to fresh villages during the year 1964-65 and onwards has been framed so far for want of funds.

Annexure I

Amritsar 1963-64—

1. Punga.
2. Maidikhurd
3. Chak Dewan Singh
4. Sarhali Mandan
5. Umer Pura.
6. Lala Afghan.
7. Shazada.
8. Kairon Nangal.
9. Kotli Jamil Singh
10. Kuraliam.
11. Bajwah.
12. Ranipur Khurd.
13. Rajoke.
14. Shangerpur.
15. Kot Mohammad Khan.
16. Raishaiana.
17. Tur.
18. Rampura
20. Kanwan (Hassanwala).
21. Ramdewali (Musal-manan).
22. Bathu Chak.
23. Kale.
24. Useluttar.
25. Talwandi Speahimal.
26. Phirewaryah.
27. Bule Nangal.
28. Burj.
29. Bullianwala
30. Aima Mallian.
31. Dhianpur.
32. Kaler (Juman).
33. Dhanial.
34. Chola Kurd (Nawanchoh).
35. Subraon.
36. Phagupur.
37. Sangwal.

Annexure II

Amritsar 1964-65—

1. Guguwind Hinduan.
2. Kacha Pacca.
3. Boh.
4. Burj Puhla.
5. Baharmapur.
6. Rahlchal.
7. Samrai.
8. Tarpai.

Selection Boards for the Industrial Training Institutes in Amritsar District

2475. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names, designations and addresses of the present members of the Selection Boards of the Industrial Training Institutes in Amritsar District ;

(b) the dates, when the said Selection Boards were constituted for the first time giving the names and designations of the members at that time ;

(c) the criteria kept in view for appointing the members of the Selection Boards for the said Institutes ?

Shri Ram Kishan : (a) and (b) A statement showing the required information is given as under—

(c) The constitution is in accordance with the instructions received from the Director-General, Employment and Training, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

[Chief Minister]

STATEMENT

Name of the Institute	Names of the present members		Date on which the Selection Committee was consolidated for the first time	Names of the Members of the Committee constituted for the first time	
1	2		3	4	
1. Dayanand Polytechnic Institute, Amritsar	(i) Shri B.N. Vaid PIS (I) A.A.A. Representative of Director of Industrial Training, Punjab ..	Chairman	July, 1954	(i) Regional Director or his nominee	Chairman
	(ii) Shri N.N. Sarin, Principal, Dayanand Polytechnic Institute, Amritsar	Secretary		(ii) Shri Ram Chand Principal, D.P.I. Amritsar	Secretary
	(iii) Shri M.C. Mehra, G.M. Metopole Sound Product, Amritsar (Representative of Employer)	Member		(iii) Shri Brij Kumar Steno-House Agency, Amritsar (Representative of Employers)	Member
	(iv) Shri Parduman Singh, Secretary, Mazdoor Textile Union, Amritsar (Representative of Workers)	Member		(iv) Shri B.S. Val, Sub-Divisional Employment officer, Amritsar	Co-opted Member
	(v) Shri Narain Singh Shabazpuri, M.L.A. ..	Member		(v) Capt. Manmohan Singh, Secretary, D.S.S.A. Board, Amritsar	Co-opted Member
	(vi) Shri Gurdial Singh Dhillon, M.L.A. ..	Member			
	(vii) Capt. Joginder Singh, Secretary, I.S.S.A., Board, Amritsar	Co-opted Member			

	(viii) Shri P.N. Bhandari, Representative of Director of Employment Exchanges.	Co-opted member		
	(ix) Representative of Director Welfare and Scheduled Castes ..	Co-opted member		
2. Industrial Training Institute, Patti	(i) S.D.O. (Civil) Patti	Chairman	May, 1964	1. S.D.O. Civil Patti
	(ii) Principal, I.T.I. Patti ..	Secretary		2. Principal, I.T.I. Patti
	(iii) Shri Tarlochan Singh Prop., M/s Harnam Singh & Sons Representative of the Employers	Member		3. Shri Tarlochan Singh, Prop. M/s Harnam Singh & sons. (Representative of Employers)
	(iv) Shri Hardeep Singh, President, Zila Parishad and Market Committee (Representative of the Workers)	Member		4. Shri Hardeep Singh, Presisident Zila Parishad and Market Committee. (Representative of workers)
	(v) Shri Umrao Singh, M.L.A. ..	Member		5. Shri Umrao Singh, M.L.A.
	(vi) Shri Tara Singh, M.L.A. ..	Member		6. Shri Gurmej Singh, M.L.A.
	(vii) Secretary, D.S.S.A. Board ..	Co-opted member		7. Secretary, D.S.S.A. Board
	(viii) Representative of Director Employment Exchanges ..	Co-opted member		8. Representative of Director Employment Exchanges
	(ix) Representative of Director of Welfare and Scheduled Castes	Co-opted member		
3. Industrial Training Institute, Sarhali	(i) S.D.O. (Civil) Tarantaran ..	Chairman	October, 1962	1. S.D.O. Civil Tarntaran
	(ii) Principal. I.T.I. Sarhali ..	Secretary		2. Shri Roshan Lal Supervisor Incharge, I.T.I. Sarhali

[Chief Minister]

1	2	3	4
	(iii) B.D.O. Chola Sahib, (Representative of Empoyers) ..	Member	3. B.D.O. Chola Sahib, (Representative of Employers)
	(iv) Shri Santokh Singh Sarpanch, Sarhali (Representative of worker ..	Member	4. Shri Santokh Singh, Sarpanch (Sarhali Representative of workers)
	(v) Shri Gurmej Singh, M.L.A. ..	Member	5. Shri Gurmej Singh, M.L.A.
	(vi) Dr. Parkash Kaur, M.L.A. ..	Member	6 Shri Jai Inder Singh, M.L.A.
	(vii) Secretary, D.S.S.A. Board ..	Co-opted member	7 Secretary, D.S.S.A. Board.
	(viii) Representative of Director Employment Exchanges ..	Co-opted member	8. The Employment Officer, Amritsar
	ix) Representative of Director Welfare and Scheduled Castes ..	Co-opted member	

Sales Tax on Tractor Tyres and Tubes and Spare Parts thereof

2476. Shri Hunna Mal : Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state —

(a) the rate of sales-tax leviable on the tractor parts including tractor tyres and tubes ;

(b) whether it is a fact that hitherto the sales-tax on tyres, tubes and other spare parts of tractors was charged at the rate being charged on general goods ;

(c) whether it is also a fact that the authorities have now begun charging the said tax on the said goods at the rate which is being charged for luxury goods ;

(d) the detail of the steps the Government is taking to reassess the persons who have hitherto been charged Sales-Tax on the said goods at the rate charged on general goods ;

(e) whether it is further a fact that the Government propose to notify that the Sales-Tax on Tractor tyres and tubes and other spare parts will be and ever to have been charged at the rate chargeable on general goods ?

Sardar Kapoor Singh : (a) Ten per cent *ad-valorem.*

(b) Yes ;

(c) Yes ;

(d) No steps are being taken to re-assess the dealers who had been charging sales-tax at low rate on the sales of tractor tyres, tubes and other spare parts of tractors. This is because hitherto the Department's view was that these items are not luxury goods.

(e) No.

Complaints against the Superintending Engineer (Public Health), Rohtak

2477. Chaudhri Har Kishan : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state —

(a) whether Government or the Chief Engineer (Public Health) received any complaints against the present Superintending Engineer (Public Health), Rohtak for various irregularities committed by him in the acceptance of various tenders and favourtism shown to the tenderers since his taking over charge of the said circle ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether any enquiry was conducted and complainants given any opportunity to substantiate the allegations before the enquiry officer; if so, with what result and if not, the reasons therefor ;

(c) the names and addresses of each of the tenderers whose tenders were accepted by the said S.E. since his taking over in the said circle and the names of the works to which they relate, together with the original estimated cost of each work at the time of inviting tenders, the total amount paid to the contractor after the finalisation of the work and the reasons for increase, if any, in the estimated cost?

Shri Rizaq Ram : (a) Yes.

(b) On a preliminary examination, it was found that the allegations were not based on facts. Hence it was not considered necessary either to conduct a regular inquiry or to call upon the complainant to substantiate the charges.

(c) A statement is enclosed.

[Minister for Public Works and Welfare]

P. W. D. PUBLIC HEALTH CIRCLE (SOUTH) ROHTAK

Serial No.	Names and addresses of tenderers whose offers were accepted	Name of works	Original estimated cost of work	Whether in progress or completed	Total amount paid to the contractor to-date	Increase over the estimated cost, if any	Reasons for excess
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rs		Rs	Rs	
	ROHTAK PUBLIC HEALTH DIVISION						
1	Shri Charan Singh, Government contractor, Phagwara	Providing Beri Water supply Scheme District Rohtak	2,57,000	completed	2,09,016	..	..
2	Shri Inder Singh, Government contractor, 886, East Park Road, Karol Bagh. New Delhi-5	Providing Water Supply Scheme Bahadurgarh, district Rohtak (1st instalment)	3,05,000	In progress	2,44,238	..	..
3	M/s Sutlej Construction Co., Gobindgarh	Providing 24" x 36" Egg shaped Sewer of Civil Road, Rohtak	80,000	Completed	73.351	..	..
4	Shri Jagminder Dass Jain, Government Contractor, Gurgaon	Providing P. H. Amenities in Government Polytechnic, Jhajjar	25,000	In progress	8,273	..	..
5	M/s S. D. Marker and Co., 57, Punchkhuin Road, New Delhi	Providing P. H. Amenities for Government Medical College, Rohtak (Internal w/s S. I. and Sewerage for Residential quarter)	1,40,000	Completed	1,31,439	..	..

6	Shri Tirlok Nath Anand, Government Contractor, 3 Krishna Nagar, Delhi	Providing P. H. Amenities in Industrial Estate, Sonepat (Sewerage and S. I.)	30,000	Completed	23,430	..	..
7	Shri Jagminder Dass Jain, Government Contractor, Gurgaon	Providing W/s scheme Jatheri, Badmarlk, Bad Khalsa and Rai and K. N. S. K. & P. S. at 20th Mile Sonepat, District Rohtak	35,000	In progress	6,152	..	..
8	Shri Atam Parkash Contractor 2597/4, Beaden Pura, Karol Bagh, New Delhi-5	Providing Water-supply Scheme Jhajjar, district Rohtak construction of Inlet Channel, storage tank filter beds suction well. scour well etc.	2,49,000	Completed	2,61,891	12,891	Due to minor changes in structural work done at site
9	Shri Kartar Singh, Governmnt Contractor, 91, Jiwan Nagar, Sonepat, district Rohtak	Providing P. H. Amenities in Government Polytechnic at Jhajjar (Estate Water Supply)	43,000	In progress	36,305	..	
10	Ditto	Ditto	29,000	Ditto	21,911	..	
11	M/s Sutluj Construction Co., Gobindgarh	Extension of 24" x 36" sewer from D. L. F. Junction to circular Road Junction with Delhi Hissar Road at Rohtak	32,000	Completed	1,01,027	...	Amount of agreement enhanced to Rs. 1,01,100 *vide* Supdg. Engineer P. H. Circle (South) Rohtak No. 12607, dated 5th June, 1963, when the work was let out, it was anticipated that the sewer would be constructed in dry soil but due to abnormal rise in the spring level, the scope of the work was changed in as much as the sewers had to be constructed under water necessitating the sinking of well

[Minister for Public Works and Welfare]

Serial No.	Names and addresses of tenderers whose offers were accepted	Name of works	Original estimated cost of work	Whether in progress or completed	Total amount paid to the contractor to-date	Increase over the estimated cost, if any	Reasons for excess
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rs.		Rs.	Rs.	
12	M/s D. P. Gupta and Co., Asaf Ali Road, New Delhi	Providing W/S., S. I. and Sewerage in Hospital Block in Government Medical College, Rohtak	4,60,000	Completed	4,60,446	446	Minor excess
13	Shri Girdhari Lal, Government Contractor, Gandhi Camp, Rohtak	Providing W./S. Scheme for village Kharkhoda	35,000	Work abandoned	18,643	..	..
14	Shri Kartar Singh Government Contractor, 91, Jiwan Nagar Sonepat, district Rohtak	Construction of Overhead reservoir 30,000 gallons capacity at Medical College, Rohtak	45,000	Completed	39,482	..	...
15	Shri Sunder Lal Jain, Government Contractor, Gurgaon	Providing W/S Sanitary Installation and Sewerage in P. S. Rest House 3 Nos. Staff Quarters and 8 Nos. Junior staff quarters in K. N. S. K. 20th Mile, Sonepat	28,000	Do	3,784	...	Balance work done departmentally
16	M/s Faquir Chand and Sons, Chawari Bazar, Delhi	Providing P. H. Amenities in Government Medical College, Rohtak-Nurses Hostel	35,000	Do	26,986	...	..

17	Shri Sudershan Lal, Government Contractor, 2597/4, Beadenpura Karol, Bagh, New Delhi-5	Providing P. H. Amenities in Government Rental Housing Scheme, Rohtak	45,000	Do	34,389	..	..
18	Shri Kartar Singh, Government Contractor, 91, Jiwan Nagar Sonepat, district Rohtak	Providing Estate Sewerage scheme in H. N. S. K. 20th Mile, G. T. Road, Sonepat	48,000	Do	51,508	3,508	Due to minor changes in construction work at site
19	Shri R. K. Arora, Government Contractor, Model Town, Rohtak	Providing W/S Scheme for Sugar Mills, Rohtak	40,000	In progress	69,426	...	Amount of agreement enhanced—*vide* S. E. P. H. Circle (South) Rohtak No. 23390, dated 18th October, 1963. The tenders were invited on the basis of provision in the rough cost estimate. During the execution of work, design of various structure have had to be changed according to conditions at site
20	M/s D P. Gupta and Co., Asaf Ali Road, New Delhi	Providing W/s Sanitary Installation in 14-J quarters in Medical College, Rohtak	1,10,000	Completed	1,03,452	..	..
21	Shri Gian Chand Nawal, Government Contractor, Bans Gate, Rohtak	Providing P. H. Amenities in Government Medical enclave Medical College, Rohtak. Storm water Drain	1,50,000	In progress	1,02,011	..	..
22	M/s S. D. Marker and Co., 57, Punchkuin Road, New Delhi	Providing internal water supply and Sanitary installation, sewerage in Block No. 2 Hostel Building in Government Medical College, Rohtak	50,000	Ditto	58,582	..	Due to provision of extra sanitary fittings according to actual requirement for works
23	Shri Girdhari Lal, Government Contractor, Gandhi Camp. Rohtak	Providing Estate Water supply in I. T. I., Hassangarh	70,000	Ditto	32,250	..	

[Minister for Public Works and Welfare]

Serial No.	Names and addresses of tenderers whose offers were accepted	Name of works	Original estimated cost of work	Whether in progress or completed	Total amount paid to the contractor to-date	Increase over the estimated cost, if any	Reasons for excess amount
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rs.		Rs.	Rs.	
24	M/s S. D. Marker and Co., 57, Punchkuin Road, New Delhi	Providing W/S S. I. Sewerage and Gas supply and other works in Government Medical College, building Rohtak	1,60,000	In progress	74,266	..	..
25	M/s Janta Furniture, Jhajjar Road, Rohtak	Providing W/S S. I. Sewerage Gas Supply and Lab. Tables in College Building Government Medical College, Rohtak	1,00,000	Ditto	62,450	..	..
26	M/s Bombay Amonia Pvt. Ltd., New Delhi	Providing W/S, S. I. Sewerage Gas supply and Lb. Tables in Government Building Medical College, Rohtak (Providing Cold Storage Plant for dead house)	60,000	Ditto	45,696	..	..
	GURGAON PUBLIC HEALTH DIVISION						
1	Shri Jawahar Lal, Government Contractor Mohindergarh	Providing W/S Scheme, Mohindergarh construction of well 15′ dia.	1,70,000	In progress	63,917	..	..

2	Shri Hoshiar Singh, Government Contractor, village Kaila, Tehsil Charkhi Dadri	Providing W/S Scheme Village Kaila	41,660	Ditto	30,462	..	..
3	Shri Sham Lal, Government Contractor, Guru Nanak Pura, Narnaul	Providing Sewerage Scheme Industrial Estate, Narnaul	32,500	Completed	27,742	..	..
4	Shri Suraj Bhan, Government Contractor, 150 Jakampura, Gurgaon	Renovation of W/S arrangement, New Township, Gurgaon	29,500	In progress	23,911	..	..
5	Shri Vishan Dass, Government Contractor, 152, Model Town Gurgaon	Providing W/S, I.T.I., Gurgaon	27,000	Completed	12,343	..	..
6	Ditto	Providing Sewerage Scheme, Sohna Town	1,00,000	Completed	81,207	..	..
7	Shri B. Narain, Government Contractor, Rewari	Rewari Town Drainage Scheme	1,85,000	In progress	1,74,578	..	..
8	Shri Siri Ram Bhargawa, Government Contractor, Gurgaon	Providing W/S Scheme, Gurgaon	70,000	Work not executed	..	..	..
9	Shri Pritam Singh, Government Contractor, Narnaul, district Mohindergarh	Sinking of percolation well Government Seed Farm, Gokalpur	28,000	Completed	22,874	..	..
10	Shri R. C. Sharma, Government Contractor, Palwal (district Gurgaon)	Dewatering low lying area near Sweepers' Colony, Palwal	66,000	Do	53,923	..	..
11	Shri Pritam Singh, Government Contractor, Narnaul	Providing W/S Government College, Narnaul	31,000	In progress	4,854	..	..
12	Shri Puran Chand, Government Contractor, Gurgaon	Providing W/S Scheme, GGN (Construction of percolation well)	70,000	Completed	4,212	..	..

[Minister for Public Works and Welfare]

Serial No.	Names and addresses of tenderers whose offers were accepted	Name of works	Original estimated cost of work	Whether in progress or completed	Total amount paid to the contractor to-date	n crease over the estimated cost, if any	Reasons for excess
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rs.		R .	Rs.	
13	(i) Lat. Shri Ishar Dass, Government Contractor, Gurgaon (ii) Shri Gopal Singh, Government Contractor, Palwal (balance work)	Providing P.H. Amenities in I.T. I., Palwal	85,000	In progress	40,808	..	..
14	Shri Pritam Singh, Government Contractor, Narnaul	Providing P. H. amenities in I. T. I., Narnaul	1,15,000	Ditto	77,981	..	..
15	Shri Jawahar Lal, Government contractor, Mohindergarh	Providing P. H. amenities in I. T. I., Mohindergarh	40,000	Ditto	18,313	..	..
16	M/s Aravli Corporation 23 F, Sector 21 Chandigarh	Providing Sanitary Installation W/S in I.T.I., Gurgaon	23,500	Ditto	10,900	..	..
17	Shri Suraj Bhan, Government Contractor, 150, Jakampura Gurgaon	Construction of S. W. pipe sewer pump chamber, I.T.I., Gurgaon	32,000	Completed	13,954	..	..
18	Shri Jamail Singh, Government Contractor, Rewari	Puplic Health Amenities, Leather training Institute, Rewari	31,000	In progress	13,487	..	..
19	Shri Tirlok Nath, Government Contractor	Providing drain in Mud Huts, Palwal	25,000	Ditto	3,640	..	..

20	Shri Suraj Bhan, Government Contractor, 150, Jakampura Gurgaon	Providing W/S Scheme in Group of Villages Bhadas, Shadipur, Aklimpur in Teh. Ferozepur Jhirka	1,45,000	Ditto	2,013	..	..
21	Ditto	Providing W/S Scheme in Industrial Estate, construction of 15′ i/d well etc., Gurgaon	57,200	Ditto	3,130	..	..
22	Shri Kartar Singh, Government Contractor, 91, Jiwan Nagar, Sonepat, district Rohtak	Construction of 2 Nos. storage and Sedimentation tank Charkhi Dadri	1,60,000	Ditto	17,526	..	..
23	M/s Aravali Corporation 23-F, Sector 21-D, Chandigarh	Providing Industrial Estate W/S and S/F, Gurgaon	65,000	Ditto	13,927	..	..
24	Shri Vishan Dass, Government Contractor, 152, Model Town, Gurgaon	Providing Estate Sewerage Disposal works, Gurgaon	94,000	Ditto	6,952	..	..
25	Shri Kartar Singh, Government Contractor, Narnaul	Narnaul Town Sewerage Scheme	72,000	Ditto	17,850	..	..
26	Shri Ram Chand, Government Contractor, Gurgaon	Providing Sewerage Scheme, Sohna 2nd instalment	90,000	Ditto	No running payment made	..	..
27	Shri Trilok Nath, Government Contractor, Krishan Nagar, Karol Bagh, Delhi	Drainage scheme, Gurgaon ..	2,05,000	Ditto	Ditto	..	..
28	M/s Faqir Chand and Sons, Chawri Bazar, Delhi	Providing W/S villages Shahpur, Ferozepur Namak	56,000	Ditto	38,285	..	..
	Shri Suraj Bhan, Government Contractor, 250, Jakampura, Gurgaon	Salaheri Palla etc. Nuh					
29	M/s Educational Scientific, Stores, Mathura	Providing W/S, S. I. Gas Supply, Government College, Gurgaon	34,000	Completed	17,148	..	..

[Minister for Public Works and Welfare]

Serial No.	Names and addresses of tenderers whose offers were accepted	Name of works	Original estimated cost of work	Whether in progress or completed	Total amount paid to the contractor to-date	Increase over the estimated cost, if any	Reasons for excess
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rs.		Rs.	Rs.	
30	Shri Suraj Bhan, Government Contractor, 150, Jakampura, Gurgaon	Providing W/S Village Tigaon Gurgaon	30,000	In progress	14,191	—	—
31	Shri Harnam Singh, Government Contractor, Palwal, district Gurgaon	Providing W/S for village Ferozepur Jhirka	95,000	Ditto	55,405	—	...
32	Shri Tirlok Nath, Government Contractor, Krishan Nagar, Karol Bagh, Delhi	Providing P. H. amenities Government Employees Rental Housing Scheme, Gurgaon	32,000	Ditto	20,066	—	...
33	Shri Pritam Singh, Government Contractor, Narnaul	Providing W/S Scheme Ateli Mandi	77,000	Ditto	59,288	—	—
34	Shri Prem Mistry, contractor, Jhajjar Gate, Charkhi Dadri	Providing W/S Sangarwas Phogt	38,000	Ditto	30,560	—	—
35	Shri Sham Lal, Government Contractor, Guru Nanak Pura, Narnaul	Providing W/s Scheme, Bhani Tikkan Kalan	44,000	Ditto	37,490	—	—

	FARIDABAD PUBLIC HEALTH DIVISION						
1	Shri Chaman Lal, Government Contractor, 13, New Colony, Gurgaon	Providing Estate Services (W/S and Sewerage) in proposed Industrial-cum-Housing Estate at Faridabad Intramural and Extramural sewers and temporary disposal for Industrial area	3,16,000	Ditto	19,000	..	..
2	Shri Kailash Chander, Government Contractor, Jagadhri Road, Yamuna Nagar	Providing Sewerage Scheme, in the Industrial Township, Faridabad—construction of extramural Sewers of 36″ i/d R. C. C. cum-Brick Circular Sewer. 33″ i/d brick circular sewer 24"x36″ egg shaped and all other works contingent thereto	4 lakhs	Ditto	35,000	..	..
3	M/s Hazara National Multi-purpose Co-op. Society, Faridabad	Providing Sewerage Scheme Faridabad Township. Constructing of Brick a masonry temporary disposal work screening chamber, Two Nos. collecting tank and Pump chamber and all other works contingent thereto	1 lakh	Ditto	No running payment made	..	..
4	Shri Kailash Chander, Government Contractor, Jagadhri Road, Yamuna Nagar, district Ambala	Providing Intramural sewers in Industrial area in the Industrial-cum-Housing Estate, Faridabad and all other works contingent thereto	3 lakhs	Ditto	Ditto	..	..
5	M/s Ram Parkash, Government Contractor, 23-D/18-A, Chandigarh	Providing Intramural sewers in the Residential area in the Industrial-cum-Housing Housing Estate, Faridabad and all other works contingent thereto	58,000	Ditto		..	..

[Minister for Public Works and Welfare]

Serial No.	Names and addresses of tenderers whose offers were accepted	Name of works	Original estimated cost of work	Whether in progress or completed	Total amount paid to the contractor to-date	Increase over the estimated cost, if any	Reasons for excess
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rs.		Rs.	Rs.	
6	M/s Hazara National Multi-purpose Co-operative Society, Faridabad	Providing Intercepting and outfall drains in Industrial-cum-Housing Estate, Faridabad and all other works contingent thereto	3 lakhs	In progress	No running payment made	..	..
7	Shri Nabh Raj, Government Contractor 3-A, 135, New Industrial Township, Faridabad	Providing W/S distribution pipe line in Industrial-cum-Housing Estate, Faridabad and all other works contingent thereto	65,000	Ditto	Ditto	..	..
	PUBLIC HEALTH DIVISION						
1	Shri Chaman Lal, Government Contractor, 13, New Colony, Gurgaon	Providing Sewerage and Drainage scheme, Mandi Town, Fatehabad, 2nd Instalment	1,80,000	Completed	1,93,026 6,740 recovered—*vide* Vr. No. 15 dated 26th February, 1964 1,85,286	..	Amount of work enhanced to Rs. 1,90,000—*vide* S. E. P. H., Circle (S), No. 32408, dated 20th November, 1962 due to construction of boundary wall and sullage carrier
2	Ditto	Providing sewerage and drainage, Mandi Town, Fatehabad 1st Instalment Part 11	70,000	Completed	69,872	..	..

3.	Shri Jawahr Lal, Government Contractor, Mohindergarh	Sirsa Town Drainage Scheme, 2nd Instalment	51,000	in progress	56,715	5,715	Amount of agreement enhanced to Rs 75,(00—*vide* S. E. P. H. Circle (S), No. 18476, dated 27th August, 1962 on account of following reasons :— Due to change in the alignment of sewers necessitating the construction of additional length of sewers
4.	Shri Balwant Singh, Government Contrator, House No. Mohalla Dogran, Hissar	Providing Sewerage and Drainage scheme, Hissar, 3rd Instalment	1,00,000	Completed	89,296	...	..
5.	M/s. Jiwan Ram-Badri Nath, Auto Service Station Ateli Road, Sirsa	Providing W/S Scheme Village Odhan	44,000	Do	38.844	..	..
6.	Shri Inder Singh, Government Contractor, 886, East Park, Karol Bagh, New Delhi	Providing W/S Scheme, Sirsa	4,10,000	In progress	3,22,777	..	..
7.	Shri Gajja Singh, Govern ment Contractor, V. & P. O., Kalanwali, district Hissar	Providing Sewerage and Drainage scheme, Sirsa, 2nd instalment	3,00,000	Ditto	1,63,228	..	..
8.	Shri Ram Chander, Governmen Contractor, s/o Ami Lal building Moh. Sainian, Hissar	Construction of open drains, Screening Chambers, Laboratory Block, Government Live stock Farm, Hissar	80,000	Completed	52,198	...	..
9.	Shri Rattan Chand Syal, Government Contractor, Prem Nagar, Hissar	Providing W/S Sewerage and Sanitary fittings, in New Civil Hospital, Hissar, providing external services	32,000	Ditto	12,379	...	..

[Minister for Public Works and Welfare]

Serial No.	Names and addresses of tenderers whose offers were accepted	Name of works	Original estimated cost of work	Whether in progress or completed	Total am unt aid to the contractor to-date	Increase over the estimated cost, if eauy	Reasons for excess
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rs.		Rs.	Rs.	
10	M/s Labhu Ram-Harsh Kumar, Contractors. Sector 21-A I-Street, Kothi No. 104, Chandigarh	Providing W/S Sewerage and Sanitary fittings, New Civil Hospital, Hissar. Providing Sanitary fittings in Hispital Block, residential buildings, etc.	51,000	Completed	66,130	15,130	Amount of agreement —enhanced to Rs. 67,000.— *vide* S. E. P. H. Circle (S), No. 19945, dated 16th September, 1962 on account of following reasons:— (i) Less provision for sanitary fittings in the Notice inviting tenders than that in the detailed estimate (ii) Extra work of sanitary installations having been carried out due to certain changes in the structural work carried out by the P. W. D., Buildings and Roads Branch
11	Shri Trilok Nath Anand, Government Contractor,	Providing W/S Sewerage and Sanitary fittings for Rental Housing Scheme, Hissar. Pro-	21,000	completed but running payment made	13,503	..	..

	3-Krishan Nagar, Karol Bagh, New Delhi	viding sewers, Septic tank sullage carrier etc.					
12	Ditto	Providing water-supply sewerage and S. I. for Rental Housing Scheme, Hissar. Providing S. I. and works contingent thereto	37,000	Ditto	8,841	—	...
13	M/s Banwari Lal-Neki Ram, Government Contractors, Water Works, Hissar	Providing W/S Scheme, Hissar Town-Construction of Storage and Sedimentation tank etc.	5,00,000	Ditto	4,68,474	—	...
14	Shri Gian Chand, Government Contractor, Daulatpur, district Hissar	Providing external water-supply in progeny Testing Unit Research Unit and study of Sheep breeding unit in Government Live Stock Farm, Hissar	1,45,000	Completed	1,67,869	22,869	Amount of agreement enchanced to Rs. 1,77,000, —*vide* S. E. P. H. Circle (S) Rohtak No. 6617, dated 25th March. 1964 on following reasons:— (i) Provision of cost of various structures made in the Notice inviting tenders was less than that actually provided at site (ii) Increase in cost of structures due to change in design during the course of execution of work
15	Shri Pehlad Rai, Government Contractor, Mohalla Raj Garh, Hissar	Providing Estate sewerage in Progeny Testing Unit at Hissar	1,20,000	In progress	91,422	—	...
16	M/s Bombay Amonia Refrigahan Co., Ltd., New Delhi	Providing of Storage Plant in B. P. Section, Punjab Veterinary College, Hissar	40,000	Ditto	31,540	—	...
17	Shri Pehlad Rai, Government Contractor, Mohalla Raj	Providing P. H. amenities in the proposed I. T. I. Building	35,000	completed	25,640	—	...

Minister for Public Works and Welfare

Serial No.	Names and addresses of tenderers whose offers were accepted	Name of works	Original estimated cost of work	Whether in progress or completed	Total amount paid to the contractor to-date	Increase over the estimated cost, if any	Reasons for excess
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rs.		Rs.	Rs.	
	Garh, Hissar	Hostel and Staff quarters Internal services, Hissar					
18	Shri Balwant Singh, Government Contractor, House No. 387, Mohalla Dogran, Hissar	Providing P. H. amenities in the proposed Government College, Hostel at Hissar Internal services W/S and S.I.	28,000	Completed	22,332	...	...
19	Shri Pehlad Rai, Government Contractor, Mohalla Raj Garh, Hissar	Providing P. H. amenities (external services) in Sector No. 1 of Home Farm, Hissar, under the reorganization of Government Live Stock Farm, Hissar. Construction of Overhead Service Reservoir	37,000	In progress	3 6,772	...	...
20	Shri Ram Parkash, Government Contractor, Gali Dr. Harari Lal, Bhiwani	Providing P. H. amenities in I. T. I. Bhiwani-External Sewerage disposal works and other works contingent thereto	34,000	Ditto	28,795	...	...
21	Shri Hawa Singh, Government Contractor, V. & P. O. Ugalan, district Hissar	Providing Estate W/S in the Industrial Estate and Development Colony at Hissar	25,000	Ditto	25,591	591	Amount of agreement enhanced to Rs. 28,000, —*vide* S. E. P. H., No.

							20977, dated 11th December, 1964 due to the following reasons:— (i) Provision of additional lengths of pipe line than that provided for in the Notice inviting tenders
22	Shri Malikiat Singh, Government Contractor, Gandhi Nagar, Colony, Opp. P.W.D. Rest House, Hansi	Providing W/S Scheme for Uklana Mandi	87,000	Ditto	..	..	No payment yet made
23	Shri Mahabir Parsad, Bawaniwala Government Contractor, Bhiwani	Providing P. H. Amenities (internal) in I.T.I. Hostel Building and Administrative Block at Bhiwani	48,000	Ditto	33,164	..	..
24	Shri Ram Chand, Government Contractor, Hissar	Providing Estate Sewerage in the Industrial Estate and Development colony, Hissar	56,000	Ditto	67,147	11,147	Amount of agreement enhanced to Rs. 70,000 *vide* S. E. P. H. Circle (S) Rohtak No. 4612, dated 8th March, 1965, due to the following reasons:— (i) Provision of additional inspection chambers and manholes (ii) Construction of bigger boundary wall acquisition of more land than that for in the estimate

[Minister for Public Works and Welfare]

Serial No.	Names and addresses of tenderers whose offers were accepted	Name of works	Original estimated cost of work	Whether in progress or completed	Total amount paid to the contractor to-date	Increase over the estimated cost, if any	Reasons for excess
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rs.		Rs.	Rs.	(iii) Provision of R.C.C. lintals in place of lintals in staff quarters and provision of cement plaster in place of lime point.
25	Shri Rattan Chand Syal, Government Contractor, Prem Nagar, Hissar	Providing P. H. amenities in work sheds (A&B) for the Industrial Estate and Development Colony, Hissar	67,000	In progress	35,465	..	..
26	M/s American Refrigeration Co., Ltd. New Delhi	Providing refrigeration in the Laboratory of the B.P. Section Punjab Veterinary College, Hissar	88,000	Ditto	No payment yet made	..	..
27	Shri Ram Chand, Government Contractor, Hissar	Providing W/S Scheme, for proposed Mandi Town, Adampur	1,80,000	Ditto	No running payment yet made	..	..
28	Shri Ram Gopal, Government Contractor, Sirsa	Providing W/S Scheme for Punjab Agricultural University at Hissar	400,000	Ditto	14,870	..	..
29	Shri Nihal Singh, Government Contractor, village Ishapur	Providing W/S Scheme Group of village A/11 in Hissar District	50,000	Ditto	No running payment yet made	..	..

	Kheri, P. O. Bhutana, district Rohtak						
30	Shri Inder Singh, Government Contractor, S/o Shri Ram Gopal, Contractor, Sirsa	Providing sewerage scheme in Punjab Agricultural University Campus, Hissar	90,000	Ditto	Ditto	..	..
31	M/s Inder Singh Brij Lal, Government Contractor, 791 East Park Road, Karol Bagh, New Delhi	Providing water-supply scheme, Mandi Town, Sirsa	2,80,000	Completed final bill yet to be paid	4,85,414	..	*Amount of agreement enhanced to Rs. 46,000 as approved vide Chief Engineer Punjab, P.W.D., P. H. Branch, No. 22954 dated on account of higher premium on which water was allotted and change of specification in pitching and flooring of storage and sediment in tank necessitated due to sandy strata encountered during the construction. Amount of agreement further enhanced to Rs. due to construction of some additional work e. g. donkey ramp etc.
	SIRSA PUBLIC HEALTH DIVISION (*Defunct*)						
1	Shri Ram Gopal, Government Contractor, Sirsa	Providing internal sewerage and drainage scheme, Mandi Town, Sirsa	1,30,000	Completed and finalized	76,954	..	..
2	Shri Gian Chand, Government Contractor, village Daulatpur, district Hissar	Providing combined Rural W/S Scheme for village Sanchla Bhani and Bhog Raj, Tehsil Fatehgarh, district Hissar	48,000	Ditto	45,893	..	..
3	M/s Jiwan Ram Badri Nath C/o Sirsa Auto Station, Dabwali Road, Sirsa	Providing W/S Scheme for village Kagdana, tehsil Sirsa, district Hissar	25,000	In progress	9,487	..	

*Printed as received from Government.

[Minister for Public Works and Welfare]

Serial No.	Names and addresses of tenderers whose offers were accepted	Name of works	Original estimated cost of work	Whether in progrees or completed	Total amount paid to the contractor to date	Increase over the estimated cost, if any	Reasons for excess
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rs.		Rs.	Rs.	
4	Shri Munshi Ram, Government Contractor, Sirsa	Providing Estate W/S for Polytechnic Building at Sirsa	40,000	Completed and finalized	18,608	..	..
5	Shri Hans Raj, Government Contractor, Dabwali	Providing extension of drainage scheme in Mandi Dabwali	1,87,000	Completed	1,37,683	..	..
6	Shri Jarnail Singh, Government Contractor, 886, East Park Road, Karol Bagh, New Delhi	Providing Drainage Scheme in Mandi and Old Town, Sirsa	2,40,000	In progress	1,83,884	..	..
7	Shri Karam Chand Mehta, Government Contractor, Fatehabad	Providing Drainage Scheme in Old Town, Fatehabad	1,33,000	Completed and finalized	88,116	..	..
8	Shri Lekh Raj, Government Contractor, Sirsa	Providing W/S Scheme, Mandi Town, Dabwali, district Hissar	1,70,000	Ditto	99,148	..	..
9	M/s Om Parkash Jagmohan, Government Contractor, Sirsa	Providing Water-supply Sanitary Installation and Drainage in Hostel Block in Polytechnic, Sirsa	35,000	In progress	26,305	..	..

	BHIWANI PUBLIC HEALTH DIVISION (DEFUNCT)						
1	Shri Malkiat Singh, Government Contractor, Gandhi Nagar Colony, Opp. P.W.D. Rest House, Hansi	Providing Water-supply Scheme, village Datta, district Hissar	28,000	Completed but running payment made	2°,394	394	Minor excess
2	Shri Phool Chand, Government Contractor, Mata Gate, Rohtak	Skeleton Water-supply Scheme, Hansi Town	2,00,000	Ditto	2,14,083	14,083	The excess is due to extra filling involved in the construction of inlet channel
3	Ditto	Drainage Scheme, Hansi, 2nd Instalment	1,54,062	In progress	1,22,178	..	..
4	Shri Sarwan Singh, Government Contractor, c/o Shri Charan Singh, Contractor, Phagwara	Providing Tile Lining Additional Storage and Sedimentation Tank No. 3 W/W, Bhiwani	1,29,000	Completed	Figures not received. Final payment was, however, within the amount of agreement	..	..
5	Shri Phool Chand, Government Contractor, Mata Gate, Rohtak	Providing W/S Scheme, Hansi, Construction of Storage and Sedimentation Tank	42,000	Ditto	22,282	..	..
6	Shri Malkiat Singh, Government Contractor, Gandhi Nagar Colony, Opp. P.W.D. Rest House, Hansi	Providing Water Supply Scheme, village Masuadpur	33,900	Completed but running payment made	30,415	..	..
7	M/s The Hansi Co-operative Labour and Construction Society Ltd., Hansi	Providing W/S Group of Villages, Batol Jatan, Jitpur, etc.	96,000	In progress	70,616	..	..
8	Shri Hawa Singh, Government Contractor, V. & P. O., Ugalan, district Hissar	Providing W/S, villages Ugalan, Baklana Kheri, Rangran, district Hissar	81,500	Completed	71,678	..	..

Water-suply Scheme in Gurgaon District

2478. Chaudhri Har Kishan : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) the names of the various water-supply schemes sanctioned so far in Gurgaon district, the estimated cost of each such scheme and the villages likely to be benefited by it;

(b) the year when the work was started on each of the said schemes and the name of the contractor doing the work ;

(c) the names of the water-supply schemes referred to above which have since been completed and the time by which the schemes which are yet incomplete are likely to be completed stating the total amount of expenditure incurred so far on each ;

(d) the population of each beneficiary village and the number of stand posts provided in each village ;

(e) whether the Public Health Department has handed over the control of various water-supply schemes in Gurgaon district to the respective Panchayats and Municipal Committees; if not, the time by which it is expected to be done ;

(f) whether it is a fact that various Panchayats and Municipal Committees have shown their inability to maintain the said water-supply schemes; if so, whether the Government propose to give financial assistance to such bodies for the purpose;

(g) whether it is also a fact that the measurement books of the Palwal Water-supply scheme have been disfigured with water and the original entries of the supply of material are not visible; if so, the name of the officer responsible for the same and the action, if any, so far taken against him ?

Shri Prabodh Chandra : (a) to (d) A statement containing the requisite information is enclosed.

(e) and (f) No. The Rural Water-supply Schemes are maintained by Government. The urban schemes which are to be maintained by the Local Bodies are also yet maintained by Government as the local bodies have yet not been able to take over these schemes. The question of grant to these bodies, therefore, does not arise at present.

(g) Some measurement books had become rain soaked during November, 1963 and entries therein became illegible. Shri Sham Lal, Sectional Officer who was Incharge of these measurement books, has been reported to be responsible for this butthe investigation is not yet complete. Disciplinary action will be taken against the officer/officials held liable.

Annexure

Serial No.	Name of Scheme	Estimated cost	Date of Commencement	Name of Contractor doing the work	Date of Completion	Expenditure incurred	Population	No. of stand posts	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rural Water Supply Schemes								
1	Providing water-supply scheme in group of villages Kherara, Uleta, Aklim Pura and Jatika in tehsil Ferozepore Jhirka	1,21,262	2-5-60	Shri Suraj Bhan	Water-supply for villages Kherara Uleta completed on 12th May, 1960 and others in July, 1962	1,11,059	Kherera 500	2	Nil
							Uleta 280	2	
							Aklimpur 120	..	
							Jatika 200	2	
2	Providing water-supply scheme in group of villages Bhadas, Shadipur, Akhtiar-Pur Badarpur, Bolai of tehsil Ferozepore Jhirka	5,02,001	5-11-64	Shri Suraj Bhan	Work in progress and likely to be completed up to November, 1965	34,076	Bhadas 1,061		The construction of percolation well is in progress, while the work of laying of C.I. Pipe lines will be taken in hand shortly. 15 stand posts are to be constructed as provided in the estimate
							Shadipur 177		
							Akhtiarpur 161		
							Badarpur 644		
							Bolai 470		
							Sarial 153		
3	Providing Water-supply scheme in group of villages Feroze-	3,06,000	September, 1960	Shri Suraj Bhan M/s Faqir Chand	Work for villages Pala and Shahpur completed	2,59,218	FerozepurNamak 1,100	1	
							Pala 110	2	
							Shahapur 470	2	

[Minister for Education and Local Government]

Serial No.	Name of scheme	Estimated cost	Date of commencement	Name of contractor doing the work	Date of Completion	Expenditure incurred	Population	No. of stand posts	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pur Namak, Pala, Shahpur, Salaheri and Salambia			and Sons	During August, 1962		Salaheri Salembia	770 830	2 2
4	Providing Water-supply scheme in group of villages, Shamshpur	39,890	December, 1958	Shri Nounihal Singh Shri Parbh Dayal	Completed September, 1959	30,711	Shamshpur .	700	6
5	Providing water-supply scheme in group of villages, Kundal	40,260	1960	Shri Jaimal Singh, Shri Harnam Singh	Completed, 1961	32,464		800	8
6	Providing water-supply scheme in group of villages, Majra Bhalki	8,375	1960	Shri S. Narain	Completed, 1962	36,245		1,250	12
7	Providing water-supply scheme in group of villages, Rampura	81,475	1958	Shri B. Narain	Completed, 1960	82,183		1,000	3+4
8	Providing water-supply scheme in group of villages, Araungabad	1,07,372	June, 1960	Shri Waryam Singh	Completed February, 1961	115,341		5,000	28
9	Dighaut	71,570	1960	Shri Harnam Singh	Head Works and practical distribution system	62,806		5,000	1 battery of taps running 3 No. has also been constructed bu[illegible]

					completed. Balance expected to be completed during 1965-66				still to be connected
10	Water-supply scheme Alimeo	64,042	1960	Shri Harnam Singh	Completed	55,903	3,500	15	
11	Water-Supply Scheme Kurali	51,983	May, 1960	..	Completed	58,796	1,085	5	
12	Water-supply scheme Tigaon	93,585	June, 1961	...	Completed	73,389	4,724	16	

Nangal Workshop

2479. Comrade Didar Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether Government has any scheme under its consideration to convert the workshop at Nangal into a commercial concern in the public sector ?

Chaudhri Rizaq Ram : No. However, it is proposed to run the workshop on more commercial basis within the Bhakra Project Administration for undertaking jobs of other projects on competitive basis.

Production of Sugar in Sugar Mills

2480. Comrade Didar Singh : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the total production of sugar in each of the Sugar Mills in the State ;

(b) the reasons why the said mills are not working to their full capacities ;

(c) the causes for the low production in the said mills and the steps being taken to remove these causes ?

Sardar Darbara Singh :

(a) Name of factory		Sugar Production (Quintals)	Date of Report
Sugar Mills, Yamuna Nagar	..	260,340	8-3-65
Sugar Mills, Phagwara	..	57,902	9-3-65
Sugar Mills, Dhuri	..	63,705	9-3-65
Sugar Mills, Panipat	..	1.16 lac	10-3-65
Sugar Mills, Rohtak	..	0.82 lac	10-3-65
Sugar Mills, Morinda	..	0.57 lac	10-3-65
Sugar Mills, Bhogpur	..	0.48 lac	10-3-65
Sugar Mills, Batala	..	0.38 lac	10-3-65

(b) At the start of the current crushing season the prices of gur/khandsari ruled very high, while the cane price payable by the Sugar Mills was fixed by the Government at Rs. 5.36 per quintal at factory gate and Rs. 5.04 at the purchasing centres. The cane-growers got almost double the price of their cane crop by converting it into gur than by selling it to the Sugar Mills. As such they did not come forward to execute agreements for supply of cane to the Sugar Mills.

(c) Low production is due to inadequate supplies of Sugar-cane to the Mills. Steps taken by the Government to improve the supplies of cane are :—

(i) Areas have been reserved under the Sugar-cane (Control) Order, 1955, where it has been made obligatory for the cane-growers to supply 75 per cent of their cane crop to the Mills.

(ii) Production of gur by crushers driven by power has been banned within the gate areas of the Sugar Mills, as also in the areas

of a number of cane purchasing centres, under the Defence of India Rules, 1962.

(iii) Working hours of khandsari units operating in the reserved areas have been restricted.

(iv) No new licences have been issued in the reserved areas of Sugar Mills.

(v) The Mills have been allowed to distribute sugar to the cane-growers at the rate of one kilogram per tonne of cane supplied.

(vi) The Government of India has been persuaded not to bar the import of gur from U.P. to Punjab State.

Corporation to Build Cement and Paper Factories in the State

2481. **Comrade Didar Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the reasons for which the Government propose to constitute a Corporation to put up Cement and Paper Factories in the Public Sector ?

Shri Ram Kishan : No such proposal is under consideration at present.

Issue of free passes to students

2482. **Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state he names and addresses of students who were issued free passes by the Amritsar Roadways and Jullundur Roadways on the following Roads in the year 1964-65:—

(i) Chogawan Lopoke to Ajnala, district Amritrar.

(ii) Chogawan Lopoke to Amritsar, district Amritsar.

(iii) Beas to Amritsar, district Amritsar

(iv) Tarn Taran to Jandiala Guru, district Amritsar ?

Shri Ram Kishan : No free passes were issued on these routes by the Punjab Roadways, Jullundur. The information in respect of Punjab Roadways, Amritsar, is given in the enclosed statement.

Statement of issue of free passes to the students for travelling in Buses in Punjab Roadways, Amritsar

Serial No.	Names and addresses of the free pass-holders	Particulars of the route on which the free passes have been issued to the students
1	(i) Shri Ramesh Chander, 10th Class, Lopoke, Government High School, Lopoke	Chogawan Lopoke to Ajnala, district Amritsar
	(ii) Shri Gurbachan Singh, 9th Class Government High School, Ajnala	
	(iii) Kashmir Kaur, 9th Class, Government Higher Secondary School, Ajnala	
	(iv) Rajinder Kaur, 9th Class, Government Higher Secondary School, Ajnala	
	(v) Sudesh Kumar, 10th Class, Government Higher Secondary School, Ajnala	

[Chief Minister]

Serial No	Names and addresses of the free pass holders	Particulars of the route on which the free passes have been issued to the students
	(vi) Rajider Kaur, 10th Class, Government Higher Secondary, School, Ajnala	
2	(i) Shri Manmohan Kaur, 10th Class, High School, Amritsar	Shahjadanand Chogawan Lopoke to Amritsar, district Amritsar
	(ii) Sh. Ganga Bahadur, 8th Class, Government Higher Secondary School, Amritsar	
3	Nil ..	Beas to Amritsar, district Amritsar
4	(i) Miss Kulbir Kaur, 9th Class Government G.S.S. Jandiala	Tarn Taran to Jandiala Guru, district Amritsar
	(ii) Shri Jasbir Singh, 8th Class, Government Higher Secondary School, Jandiala	
	(iii) Miss Paramjit Kaur, 9th Class, Government Higher Secondary School, Jandiala	
	(iv) Shri Major Singh, 7th Class, Government Higher Secondary School, Jandiala	
	(v) Miss Salwainder Kaur, 8th Class, Government Girls Higher Secondary School, Jandiala	
	(vi) Shri Jaswant Singh, 8th Class, Government Higher Secondary School, Jandiala	
	(vii) Shri Narinder Paul, 9th Class, Government Higher Secondary School, Jandiala	
	(viii) Miss Balwinder Kaur, 8th Class, Government Girls High School, Jandiala	
	(ix) Shri Dhanwant Singh, 8th Class, Government Higher Secondary School, Jandiala	
	(x) Shri Jarnail Singh, 8th Class, Government Higher Secondary School, Jandiala	
	(xi) Shri Harbhajan Singh, 6th Class, Government Higher Secondary School, Jandiala	
	(xii) Shri Amar Singh, 6th Class, Government Higher Secondary School, Jandiala	
	(xiii) Shri Gurmukh Singh, 6th Class, Government Higher Secondary School, Jandiala	
	(xiv) Miss Nirmal Kaur, 10th Class,,Government Girls Higher Secondary School, Jandiala	
	(xv) Shri Banta Singh 8th Class, Higher Secondary School, Jandiala	
	(xvi) Shri Nand Singh, 8th Class, Government Higher Secondary School, Jandiala	
	(xvii) Shri Nirmal Singh, 6th Class, Higher Secondary School, Jandiala	

Jurisdiction of Wage Inspector, Gobindgarh and Labour Inspector, Patiala

2483. Comrade Jangir Singh Joga, Comrade Babu Singh Master : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether the Labour Commissioner, Punjab, and the Labour Officer, Patiala received any representation regarding the respective jurisdications of the Wage Inspector, Gobindgarh and the Labour Inspector, Patiala; if so, the action taken thereon ?

Chaudhri Rizaq Ram : Yes, a representation dated 22nd October, 1964 was received by the Labour Commissioner, Punjab, from the General Secretary, Labour Union, Gobindgarh requesting for inclusion of area of Gobindgarh and Amloh in the jurisdiction of the Labour Inspector, Patiala.

The suggestion of the union was not considered feasible in the interest of efficiency of work, as there is aleady a Wage Inspector at Gobindgarh who can better look after the complaints of this area.

Representation from Labour Union, Gobindgarh

2484. Comrade Jangir Singh Joga, Comrade Babu Singh Master : Will the Minister for Public Works and Welfare with reference to the reply to unstarred question No. 741 printed in the list of Unstarred Qustions dated 14th March, 1963, be pleased to state whether the matter regarding the inclusion of the Industrial Housing Colony, Gobindgarh in the Municipal limits has since been decided; if so, the details of the decision taken; if not, its present stage ?

Choudhri Rizaq Ram : No. The necessary papers i.e. Schedule of boundaries and plan of extended area are yet awaited from the Deputy Commissioner, Patiala. The required notification for inclusion of labour Colony in the limits of Municipal Committee, Gobindgarh, will be issued on receipt of the complete proposal from the Deputy Commissioner, Patiala.

Vehicles and employees in service of P.R.T. C. Patiala

2486. Comrade Jangir Singh Joga , Comrade Babu Singh Master : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of vehicles and the total number of employees, category-wise, in the service of the Pepsu Road Transport Corporation, Patiala as on 31st January, 1965 ?

Shri Ram Kishan (i) & (ii) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

(i) Total number of vehicles	..	211 buses 1 Truck 1 Staff Car 1 Staff Jeep
(ii) Total number of employees category-wise		1134

[Chief Minister]

S. No.	Name of post		No. of employees
	A—Officers		
1	General Manager	..	1
2	Works Manager	..	1
3	Traffic Superintendent	..	1
4	Chief Accounts Officer	..	1
5	Technical Officer (Temporary)	..	1 Vacant
	B—Direction Staff		
1	Office Superintendent	..	1
2	Resident Auditor	..	1
3	Medical Officer	..	1
4	Junior Auditors	..	2
5	Accountant	..	1
6	Legal Assistant	..	1
7	Assistant Accountants	..	6
8	Chief Store-keeper	..	1
9	Assistants	..	7
10	Stores Purchase Assistant	..	1
11	Cashier	..	1
12	Stenographer	..	1
13	Ledger Keeper	..	1
14	Assistant Storekeepers	..	8
15	Assistant Cashier	..	8
16	Steno-typist	..	1
17	Typists	..	2
18	Clerks	..	32
19	Dispenser	..	1
20	Ticket Verifier	..	3
21	D. P.A.	..	9
	C—Operation Staff		
1	Station Supervisors	..	4

S. No.	Name of post		No. of employees
2	Chief Inspectors	..	2
3	Welfare Inspectors	..	1
4	Motor Stand Inspectors	..	2
5	Inspectors	..	34
6	Drivers	..	282
7	Conductors	..	281
8	Staff Car Drivers	..	2
9	Booking Clerks	..	55
10	Adda Conductors	..	23
11	Yard Masters	..	4
	D—Workshop Staff		
1	Supervisor	..	1
2	Head Mechanics	..	3
3	Head Electrician	..	1
4	Service Station Incharges	..	3
5	Machinist	..	1
6	Head Blacksmith	..	1
7	Head Carpenter	..	1 **Vacant**
8	Mechanics	..	18
9	Tyremen	..	6
10	Fitters	..	43
11	Borers	..	2
12	Welders	..	5
13	Carpenters	..	9
14	Uphosters	..	4
15	Painters	..	5
16	Blacksmiths	..	6
17	Electricians	..	11
18	Radiator Repairers	..	5
19	Turners	..	2

[Chief Minister]

S. No.	Name of post		No. of employes
20	Vulcanizer	..	1
21	Battery Attendant	..	1
22	Assistant Tyremen	..	2
23	Assistant Fitters	..	8
24	Helpers	..	72
25	Cleaners	..	57
26	Sweepers	..	12
27	Chowkidars	..	43
	IV—Class Direction		
1	Daftri	..	1 Vacant
2	Record Lifter	..	1
3	Peons	..	13
4	Store-boys	..	4
5	Gate-keepers	..	3
6	Ward servant	..	1
7	Malies	..	2
8	Gunman	..	5
		..	1,134

Employees, State Insurance scheme

2487. Comrade Jangir Singh Joga
Comrade Babu Singh Master } Will the Miniser for Public Works and Welfare be pleased to state —

(a) whether the Government is considering any proposal to enforce the Employees' State Insurance Scheme at Nabha and Malerkotala where the number of workers is more than 500 at each station ;

(b) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

Chaudhri Rizaq Ram : Due to the shortage of medical and paramedical personnel in the State and paucity of funds, the Employees' State Insurance Scheme could not be extended to Nabha. It will be extended to that area as soon as the funds and the above category of staff are available. The Employees' State Insurance Scheme cannot be extended to Malerkotla as there are less than 500 workers and according to the present policy of the Employees' State Insurance Corporation, such places are not coverable.

Technical Supervisor, P. R. T. Corporation, Patiala

2488. Comrade Jangir Singh Joga
Comrade Babu Singh Master } : Will the Chief Minister be pleased to state whether the post of a Technical

Supervisor exists at present in the Pepsu Road Transport Corporation, Patiala; if so, the functions and duties of the post and the name of its present incumbent ?

Shri Ram Kishan : (i) No.

(ii) Question does not arise.

Bringing hotels and their managements under the Minimum Wages Act

2489. Comrade Jangir Singh Joga
Comrade Babu Singh Master : Will the Minister for Public Works and Welfare with reference to the reply to Starred Question No. 4042, included in the list of Questions 18th for September, 1963, be pleased to state whether any decision regarding the application of the Minimum Wages Act to hotels and their managements has been taken; if so, the details thereof ?

Chaudhri Rizaq. Ram : Hotels, restaurants and tea stalls have been included in the employment in shops and Commercial Establishments which have recently been added to the schedule of the Minimum Wages Act, 1948, for fixing the minimum rates of wages in any employment. Action to constitute an Advisory Committee for this purpose is being taken.

Memorandum from Pepsu Road Transport Corporation Workers Union, Patiala

2490. Comrade Jagir Singh Joga,
Comrade Babu Singh Master : Will the Chief Minister with reference to the reply to Starred Question No. 4194, included in the list of ques ions for 27th September 1963 be pleased to state whether any action has s far been taken on the Memorandum referred to in the said reply, if so, the details thereof ?

Shri Ram Kishan : A statement is enclosed.

Statement

Item No.	Action taken
1	2
1	The matter was got examined legally and the case is now being placed in the next meeting of the Corporation in the light of the legal advice.
2	The Union has not yet been recognised.
3	Motor Transport Workers Act, 1961 is a recent enactment. Most of its clauses are being implemented. A few remaining items are being examined with a view to early implementation. During Tripartite meeting held on 4th March, 1965, it was agreed that all the clauses of Motor Transport Workers Act and Rules should be implemented within five weeks.
4	At present bonus is not being paid nor it is mandatory. Employees are being given cash rewards.
5	Rs. 5 have been paid to Class IV employees with effect from 1st April, 1961.
6	In accordance with the decision arrived at in the meeting of the Corporation held on 8th April, 1960, cases in which the emoluments fall short of the actual pay of the employees were fixed at the appropriate stage including pay and other allowances so as to conform to the minimum wages whereas such employees were allowed to draw personal pay absorbable, in future increments. All the workers on or after 12th May, 1960 have been granted regular increments.

[Chief Minister]

Item No	Action taken
1	2
7	The allegations of the workers against the management are baseless.
8	No papers are being lost. Intimation of acceptance or rejection of all applications is invariably given.
9	The allegation is vague and unfounded.
10	Shri Jagandan Singh had been promoted as M. S. I., on the basis of merit. Long before his appointment as such he was functioning as Incharge Local Bus Stand.
11	The allegation is baseless.
12	The request stands implemented.
13	The work is progressing.
14	Wherever any worker works overtime he is paid overtime charges regularly.
15	Time-tables are fixed by the R. T. A. on reckoning at an overall speed of 24 M. P. H., to allow halts at the bus stages. Time for the journey is calculated at 30 miles an hour.
16	Allegation is baseless. Buses are disinfected according o a fixed schedule.
17	The Corporation has concentrated on the use of one make Dodge/Fargo group. This make is on the approved manufacturing programme in the country. No vehicle is defective. Fitness certificate is issued to every vehicle before it is sent out of the shed. The stocks of spare parts are maintained and every effort is made that there is no shortage.
18	Better make of vehicles, i.e., Leyland has since been introduced. By the end of financial year 1964-65 the Corporation would have had 63 Leylands on its fleet. Even otherwise fleet maintenance is receiving improved attention.
19	There is no provision in the uniform rules to supply special uniforms to the electricians.
20	Allowance is paid regularly in accordance with the T. A. Rules. Weekly rests are being given regularly. Leave is liberally allowed subject to exigencies of service but this cannot be claimed as a matter of right. Fines are imposed where workers are at fault. In other cases these are reimbursed.
21	Operational staff is not given holidays falling on 26th January, 15th August, 2nd October, etc. But they are being given compensatory leave in lieu thereof.
22	The workers are given medicines as prescribed by the M. O. Re-imbursement is not allowed but if the medical officer feels the need for a medicine not in stock, it is purchased for use by patient.
23	The Corporation has since permitted grant of Hospital leave to the employees of the Corporation in accordance with the provisions of Punjab C. S, R. Volume I (Punjab Civil Services Rules).
24	The allegation is baseless.

Cost of Living Index at Patiala

2491. Comrade Jangir Singh Joga
Comrade Babu Singh Master: Will the Minister for Finance and Planning be pleased to lay on the Table

of the House a statement showing cost of living index in respect of Patiala, month-wise, since 1948 to date ?

Sardar Kapoor Singh : A statement showing the Consumer Price Index Numbers for Working Class in respect of Patiala from January, 1956 is laid on the Table of the House. The Index numbers prior to January, 1956 are not available.

Statement showing Consumer Price Index Numbers for Working Class for Patiala Centre (from January, 1956 to January, 1965)

Base : 1952-53-100.

——		1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
January	..	96	109	105	122	118	125	132	132	151	172
February	..	97	113	103	127	122	125	133	131	159	..
March	..	101	109	107	126	120	127	136	134	159	..
April	..	99	110	110	126	122	130	138	137	156	
May	..	104	107	109	122	123	130	137	137	153	..
June	..	104	107	110	124	121	128	135	138	156	..
July	..	104	113	116	119	122	132	135	142	158	..
August	..	106	112	115	119	126	129	136	145	158	..
September	..	107	111	120	121	128	130	135	144	160	..
October	..	108	110	121	121	127	127	134	142	166	..
November	..	113	109	119	121	127	130	131	144	165	..
December	..	111	110	119	119	128	133	132	147	174	..

Case Registered with Police Station Thanesar, district Karnal

2492. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether the P. W. D. (Health Section) of Karnal District registered any case at the Police Station, Thanesar, district Karnal during the month of May, 1964 regarding the theft of pig lead or some other material; if so, a copy, of the F. I. R., be laid on the Table of the House ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the value and the quantity of the material alleged to have been stolen ;

(c) the details of the facts which have come to the notice of the P. W. D. (Health Section) in connection with the said theft together with the steps so far taken for the recovery of the stolen material ;

[Comrade Ram Piara]

(d) whether any correspondence on the subject has taken place between the officers of the said department; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(e) whether any information regarding the said case has also been sent to the Accountant-General, Punjab; if so, when to gether with a copy of the communication addressed to the Accountant-General, Punjab, be laid on the Table ;

(f) whether the above said case has since been decided; if so, with what result ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes ; Shri Pritam Chand, Sectional Officer, Kurukshetra, Public Health Section lodged a complaint about the theft of pig lead at Police Station, Thanesar, in June, 1964 and not in May, 1964. This complaint was registered as F. I. R. No. 82/64 under section 380 I.P.C. (Copy enclosed).

(b) The quantity of Pig lead reported by the Sectional Officer as stolen was 1,304.75 kilograms costing Rs. 2,156. (Rs. 2,210.68 paise inclusive of three per cent stora e charges).

(c) The details of the facts as furnished by the Chief Engineer, Public Health, Punjab are as under :—

On preliminary investigation, it was found that the Keys of the store were with the chowkidar and that the locking arrangements were also not perfect. The Executive Engineer concerned therefore ordered physical verification of all the store so as to arrive at shortages, if any, of all the articles lying in the store. During verification it was found that certain Indents for lead had not been accounted for by the Sectional Officer and thus the case of theft registered with the Police was wrong. The Superintendent, Police , Karnal was advised accordingly by the Executive Engineer. All the relevant records were seized and compilation of accounts taken up. The Superintending Engineer, Ambala appointed an independent stock verifier to know the existing ground balances. A senior Accounts clerk was also deployed to complete the store accounts who has completed the initial record and it is being checked by another Sub-Divisional clerk to arrive at final shortages and surpluses.

(d) Yes ; correspondence has taken place on the subject between various officers of P. W. D., Public Health Branch copy of all 11 Nos., letters, as per list attached, is enclosed.

(e) Intimation regarding the said theft was sent to the Accountant-General, Punjab, Simla,—*vide* Executive Engineer, Karnal, Public Health Division letter No. 7775, dated 20th June, 1964. (Copy enclosed).

(f) No. The Sectional Officer has been charge-sheeted and his reply is under consideration of Superintending Engineer, Ambala.

(Devnagri version copied from Persian Script).

थाना थानेसर ज़िला करनाल रिपोट इब्तदाई इत्तलाह नम्बर 82 तारीख वक्त वकूआ शब दर्मियानी । बहवाला रपट नम्बर 38 मवर्रखा १६ जून १६६४ वक्त ८-१० वजे सुबह बज़रिया दरखास्त प्रीतम चन्द S.O. पबिलक हेल्थ, कुरू क्षेत्र बफासला दो फरलांग जानिब शमाल पुलीस की तरफ से कोई देरी नहीं हुई दो बजे दिन 16 जून 1964,

To the Station House Officer, Police Station, Kurukshetra, Sub-Theft of pig lead from Public Health Store. It is reported to me by the Chowkidar Shri Roor Singh and Madan Dass today at 6.30 p.m., that pig lead silies have been stolen last night from the store. The number of silies of pig lead stolen will be intimated on receipt of stock register from Karnal. At present only fourteen silies are lying in the store. You are requested to register the case for investigation. The material that is pig lead belongs to Government Department Public Health, Kurukshetra. The room was unlocked and found open as reported by Chowkidar. Yours faithfully, (Sd.) Pritam Chand, S/O
Public Health, Kurukshetra, dated 16th June, 1964.

*

(Sd.) JAI NARAIN. M.H.C.
Police Station, Thanesar.

List of letters exchanged between various officers of P. W. D. .Public Health Branch.

(1) Copy of letter No. 15892, dated 17th July, 1964 from the Superintending Engineer, Public Health Circle(S), Rohtak to the Chief Engineer, Public Health Branch, Pa tiala.

(2) Copy of letter No. 294-CPH/Gii, dated 27th July, 1964 from the Chief Engineer, Public Health Branch, to the Secretary to Government, Punjab, P. W. D., B. & R. /Public Health Branches, Chandigarh.

(3) Copy of letter No. 220—222, dated 16th June, 1964 from Shri Pritam Chand S. O., Kurukshetra to the Station House Officer, Police Station, Kurukshetra.

(4) Copy of letter No. 7775/EE, dated 20th June, 1964 from the Executive Engineer, Public Health, Division Karnal to the Accountant-General, Punjab, Simla.

(5) Copy of letter No. 8395, dated 1st July, 1964 from the Executive Engineer, Karnal to the Superintendent of Police, Karnal.

(6) Copy of letter No. 9703, dated 28th July, 1964 from the Executive Engineer, Karnal to the Superintendent of Police, Karnal.

(7) Copy of letter No. 421/G, dated 14th August, 1964 from the Superintending Engineer, Public Health Circle (S) Rohtak to the Executive Engineer, Public Health Construction Division, Ambala.

(8) Copy of D. O. No. 10848-BRIII-5-64/ dated 7th December, 1964 from the Under-Secretary to Government, Punjab, P. W. D., B. & R.,/Public Health Branches, to the Superintending Engineer, Public Health Circle(S), Rohtak and copy to Chief Engineer, Public Health Branch, Patiala.

(9) Copy of letter No. 30142-PH/Gii, dated 11th December, 1964 from the Chief Engineer, Public Health Branch, Patiala to the Superintending Engineer, Public Health Circle (South) Rohtak, and copy to the Secretary to Government Punjab, P. W. D., B. and R./Public Health Branches.

(10) Copy of D. O. No. 11005-BR-III-5-64/1159, dated 13th January, 1965 from the Deputy Secretary to Government , Punjab, P. W. D., B. & R./Public Health

Note: The illegible Hindi portion of the Statement received from Government has not been printed please.

[Minister for Public works aud welfare]

Branches to Shri I. N. Mehta, Chief Engineer, Public Health Branch, Patiala and copy to Superintending Engineer, Public Health Circle, Ambala Cantt.

(11) Copy of letter No. 3565-PH/Gii, dated 16th February, 1965 from the Chief Engineer, Public Health Branch, Patiala to the Superintending Engineer, Public Health Circle, Ambala Cantt., and copy to the Secretary to Government, Punjab, P. W. D. B. & R./Public Health Branches, Chandigarh.

Copy of letter No. 15892, dated 17th July, 1964 from the Superintending Engineer, Public Health Circle(S), Rohtak to the Chief Engineer, P. W. D., Public Health Branch. Patiala.

Subject.—Theft of Pig Lead at Public Health Stores, Kurukshetra.

It has been reported by the Executive Engineer, Public Health Division, Karnal that 1,306.75 K.G., of pig lead valuing Rs 2,210.68 nP., has been stolen from the Public Health Stores, Kurukshetra. The loss was discovered by the Sectional Officer on the 16th June, 1964 who lodged a report with the Police. The Executive Engineer, Karnal is however of the opinion that the theft of pig lead took place in stages between the first week of April and 16th June, 1964. The Executive Engineer, Karnal has been instructed to conduct a departmental enquiry and submit his report.

A report of the loss has already been made to the Accountant-General, Punjab as required under the rules, —*vide* Executive Engineer's Memo. No. 7775, dated 20th June, 1964 (copy enclosed).

A further report in the matter will be submitted in due course.

D.A./none.

Copy of endorsement No. 15893 of even date by the same office.

A copy is forwarded to the Executive Engineer, Public Health Division, Karnal for information with reference to his endorsement No. 7776, dated 20th June, 1964. It is requested that a departmental enquiry may please be conducted in accordance with the instructions contained in Appendix 2 of Punjab Financial Rules, Volume II and a detailed report submitted to this office.

FROM

The Chief Engineer, Punjab,
P. W. D., Public Health, Branch, Patiala.

To

The Secretary to Government, Punjab,
P. W. D. B. and R./Public Health Branches, Chandigarh.

Memo No. 294-CPH/Gii, dated the 27th July, 1964.

Subject.—Theft of pig lead at Public Health Stores, Kurukshetra.

The Superintending Engineer, Public Health Circle (South), Rohtak has reported, *vide* his Memo. No. 15892, dated 17th July, 1964, copy enclosed, that 1,306.75 Kg., of pig lead valuing Rs 2,210.68 nP., has been stolen from the Public Health Stores, Kurukshetra. A report has already been lodged with the Police authorities who is investigating the matter. The Accountant-General, Punjab has also been informed about the theft. Further development s of the case will be reported to Government.

(Sd.) . . . ,
ASSISTANT ENGINEER, DESIGNS,
for Chief Engineer, Punjab,
P. W. D., Public Health Branch, Patiala

Endoresment No. 295-CPH/Gii, dated 27th July, 1964.

A COPY is forwarded to the Superintending Engineer, Public Health Circle (South) Rohtak for information with reference to his Memo. No. 15892, dated 17th July, 1964. Further development of the case may also pleased be reported to this office.

(Sd.) . . . ,
ASSISTANT ENGINEER, DESIGN;,
for Chief Engineer, Punjab.
P. W. D., Public Health Branch, Patiala.

Copy of letter No. 220-222, dated 16th June, 1964 from Shri Pritam Chand, Sectional Officer, Kurukshetra to the Station House Officer, Police Station, Kurukshetra.

Subject.—Theft of pig lead from Store.

In continuation of my report of to-day, i.e., 16th June, 1964, the Stock Registers have been received from Public Health Sub-Division, Karnal and verified that 1,306.3/4 Kgs. of Pig Lead have been stolen which approximately comes to Forty (40) Silies taking average silly of thirty -three (33) Kgs.. The approximate value of Pig Lead stolen comes to Rs. 2,156.

Copy to the Sub-Divisional Officer, Public Health Sub-Division , Karnal in continuation of my No. 217-219, dated 16th June, 1964 for favour of information and further action.

Copy to the Executive Engineer, Public Health Division, Karnal in continuation of my No. 217-219, dated 16th June, 1964 for favour of information and further action please.

Copy of letter No. Nil, dated Nil, by Shri Pritam Chand, S. O., Kurukshetra to the Station House Officer, Police Station, Kurukshetra.

Subject.—Theft of Pig Lead from Public Health Stores, Kurukshetra.

It is reported by the Chowkidar Shri Roor Singh and Maton Dass today at 6.30 a.m. that Pig Lead silies have been stolen last night from the store. The number of silies stolen will be intimated on receipt of stock registers from Karnal. At present only fourteen silies are lying in the store. You are, requested to register the case for investigation. The material belongs to Government Department (P. W. D., Public Health, Kurukshetra). The room was unlocked and found opened as reported by the Chowkidar.

Copy to the S. D. O., Public Health Sub-Division, Karnal, for information and necessary action. I am sending Shri Chuni Lal to collect the Stock Registers, M. Books and Indent Books which may kindly be sent. The Case has been registered F.I.R. No. 82/64, under section 380. I. P. C.

Copy to the Executive Engineer, Public Health Division, Karnal for favour of information and necessary action. The case has been registered. F. I. R. No. 82/64, under section 380 I. P. C.

(Sd.) PRITAM CHAND,
Sectional Officer, Kurukshetra.
dated 16th June, 1964.

Copy of letter No. 7775/E.E., dated 20th June, 1964 from the Executive Engineer, Public Health Division, Karnal to the Accountant-General Punjab, Simla.

Subject.—Theft of Pig Lead at Public Health Stores, Kurukshetra.

This is to report to you as required under Rule 2.34 and 2.35 of P. F.R., Volume I, that a theft of lead has occurred in the Public Health Stores at Kurukshetra. The details of investigation so far made are as under :—

[Minister for Public works and welfeare]

(1) The loss has occurred due to theft of Lead Weighing 1,306.75 Kgs., costing Rs. 2,156 at Rs 1.65 nP., per Kg., and including three per cent storage charges comes to Rs 2,210.68 nP. The Storage charges have to be added, as the Lead was lying on mater ial at site account of following two works :—

(i) Provd. Water supply in order to develop Kurukshetra and surrounding places of Pilgrimage under National Water-supply and Sanitation Scheme. Estimated cost Rs 3,33,421.
Quantity of Lead—1,710.25 Kilogramms.

(ii) Provd.Waters-supply, Sanitary Installation in Government Girls Hostel, Kurukshetra.
Quanatity of Lead—70.50 Kilogramms.

From which the above quantity of lead has been stolen, i.e., 1,306.75 Kilogramms. On inspection it has been found that no proper arrangements for lock and key have been made.

2. The loss is for Rs. 2,210.68 nP. The theft has occurred between first week of April, 1964 and 16th June, 1964 most probably in stages. The loss was rendered possible by not securily locking the stores.

3. The technical responsibility for the safeguard of the Government material is that of Sectional Officer. But so far as the theft is concerned, the case has been lodged with the Police by the Sectional Officer ,—*vide* his F. I. R., No. 82/64 under section 380 I.P.C., dated 16th June, 1964 when he detected the theft.

4. As stated above the case has been given to the Police and is being investigated and when the result of investigation is received, it will be communicated.

5. New Locks have been provided.

6. Being a permanent Sectional Officer no security is required.

7. The Sectional Officer is in service. So far as the recovery is concerned, after the receipt of the report from the Police, the responsibility will be fixed and amount of loss to be recevered if any from the Sectional Officer of others will be fixed.

The report is sent to you in duplicate as required· D.A./One.

Copy of endorsement No· 7776, dated 20th June, 1964 by the same officer.

Copy to the Superintending Engineer, Public Health Circle (South), Rohtak for information in continuation of this office No. 7619, dated 18th June, 1964.

Copy of endorsement No. 7777, dated 20th June, 1964 by the same officer.

Copy to the Sub-Divisional Officer, Public Health Sub-Division,Karnal,for information with reference to his No. 1810, dated 20th June, 1964.

Copy of letter No. 8395, dated 1st July, 1964 from the Executive Engineer, Public Health Division, Karnal to the Superintendent of Police, Karnal.

Subject.—Theft of Pig Lead at Public Health Stores, Kurukshetra.

Pig lead weighing approximately 1,306.75 Kilogramms and costing about Rs. 2,210.68 nP., has been stolen from the Public Health Stores at Kurukshetra. The theft came to the notice of Shri Pritam Chand Sectional Officer, Public Health, Kuukshetra on 16th June, 1964. This official had lodged the report with the Station House Officer, Police Station , Kurukshetra on 16th June, 1964 which was registered as No. F.I. R. 82/64 under section 380 I. P. C.

It is requested that necessary investigation may please be carried out and the culprit brought to book. The result of your investigation may also please be intimated at an early date to enable this office to inform the higher authorities.

Copy of endorsement No. 8396, of even date by the same officer·

Copy forwarded to the Station House Officer, Police Station, Kurukshetra for information and necessary action with reference to letter No. 1813, dated 20th June, 1964 from the Sub-Divisional Officer, Karnal, Public Health Sub-Division to his address.

Copy of endorsement No. 8397, of even date by the same officer.

Copy forwarded to the Sub-Divisional Officer, Public Health Sub-Division, Karnal for information and necessary action with reference to his endorsement No. 1814, dated 20th June, 1964.

Copy of letter No. 9703/E.E., dated 28th July, 1964 from the Executive Engineer, Public Health Division, Karnal to the Superintendent of Police, Karnal.

Subject.—Theft of Pig Lead at Public Health Stores, Kurukshetra.

Reference.—This office No. 8395, dated 1st July, 1964 and your endorsement No. 38521, dated 16th July, 1964·

On thorough investigation of records, i.e., Indent Books, Stock and Material at Site Registers maintained by Shri Pritam Chand, Sectional Officer, Kuruksnetra, it has been found that some Indents which contain transactions of lead have not been entered into these Registers. It is, therefore, requested that the case registered by the Sectional Officer, Kurukshetra,—*vide* F. I. R. 82/64, dated 16th June, 1964 at Police **Station**, Kurukshetramay be withdrawn. Action is being taken separately on the Sectional **Officer**, departmentally.

Copy of endorsement No. 9704, of even dated by the same officer.

Copy to Station House Officer, Police Station, Kurukshetra for information in continuation of this office endorsement No. 8395, dated 1st July, 1964.

Copy of endorsement No. 9705 of even date by the same officer.

Copy to Assistant Sub-Inspector of Police, C. I. A., Kurukshetra for information.

Copy of endorsement No. 9706 of even date by the same Officer.

Copy to Shri Chitwant Singh, Deputy Superintendent of Police, Headquarters, Karnal for information.

Copy of endorsement No. 9707 of even date by the same officer.

Copy to the Sub-Divisional Officer, Public Health Sub-Division, Karnal for information in continuation of this office endorsement No. 8397, dated 1st July, 1964. He should now continue the checking and verification of stores, till such time all the stores is checked. It was ordered by the undersigned Yesterday, i.e., on 27th July, 1964 that all the records should be kept in his lock and key, so that no tempering can be done.

Copy of endorsement No. 9708 of even date by the same officer.

Copy to the Superintending Engineer, Public Health Circle(S), Rohtak for information with reference to his endorsement No. 15893, dated 17th July, 1964. The following seven Indents have not been accounted for by the sectional Officer in his Registers. These contain following quantities of lead :—

[Minister for Public Works and Welfare]

	Indents No.	Date	Quantity
1.	43/386	18-12-62	1,327 lbs.
2.	61/386	19-1-63	24 lbs.
3.	66/386	22-1-63	36 lbs.
4.	9/150	20-8-59	1,417 lbs. Accounted in wrong work.
5.	15/150	8-10-59	1,034 lbs.
6.	56/150	12-2-60	0-6-0-9 lbs.
7.	70/539	6-8-61	Not Accounted.

In this indent No. 70/539 at item No. 7 no quantity of lead has been shown by the Sectional Officer. The column for quantity is blank. When he was interrogated for this indent he told that all the three copies are in the Indent Book, this may be considered as cancelled. But it was found that some of the items from this indent have already been posted in the Register, which clearly shows that this indent needs accounting and filling up of quantity of lead, which was issued and which has not been taken into account by him. Copy of the statement of Shri Pritam Chand, Sectional Officer, Kurukshetra regarding the information of entries of these indents is enclosed for ready reference.

Amendment issued ,—*vide* No. 10250, dated 5th August, 1964 for the correction of S. No. 2 and 3 above to read as indent No. 61/386 instead of 61/11 and 66/11.

Copy of letter No. 421/G dated 14th August, 1964 from Shri L.M. Chaudhri, Superintending Engineer, P.H. Circle, Ambala Cantt. to the Executive Engineer, P.H. Construction Division, Ambala.

Subject.—Physical Verification of Stores.

The Physical Verification of Stores at Kurukshetra is to be conducted by the independent agency immediately. Shri Upkar Singh, S.D.O. is hereby directed to proceed to Kurukshetra immediately and conduct the Physical Verification of the stores at Kurukshetra within 15 days and report compliance. The date of departure of Shri Upkar Singh, S.D.O. may be intimated to this office as well as to the Executive Engineer, Public Health Division, Karnal.

Copy of endst. No. 422/G of even date by the same officer.

A copy is forwarded to the Executive Engineer, Public Health Division, Karnal for information with reference to meeting on 7th August, 1964. The local staff at Kurukshetra may please be directed to get the Physical Verification of stores done within 15 days without fail. In case any extra labour is required for handling the stores, the same may please be engaged and no time should be wasted for getting the sanction and going through other formalities.

Copy of endst. No. 423/G of even date by the same officer.

Advance copy is forwarded to Shri Upkar Singh, S.D.O. 1st Public Health Construction Sub-Division, Model Town, Ambala for information and necessary action.

Copy of D.O. No. 10848-BRII-5-64 dated 7th December, 1964, from the Under Secretary to Government, Punjab, P.W.D. B & R/P.H. Branches, to the Superintending Engineer, P.W.D. Public Health Circle (South), Rohtak.

Subject.—Theft of pig lead at Public Health Stores, Kurukshetra.

Please refer to the correspondence resting with the Chief Engineer, P.W.D., Public Health's endst. No. 6-39/367-CPH/Gii, dated the 8th September, 1964, to your address, on the subject noted above.

2. It is requested that a detailed report may be sent immediately also indicating if any special audit has been ordered. The file of the case may also be supplied for perusal of the Public Works Minister.

No. 10848-BRII-5-64/dated the 7th December, 1964.

A copy is forwarded demi-officially to Shri I.N. Mehta, Chief Engineer, P.W.D., Public Health, for information and his comments immediately.

(Sd) . . .
Under-Secretary to Government, Punjab,
P.W.D., B. & R./P.H.

Copy of letter No. 30142-PH/Gii, dated 11th December, 1964 from the Chief Engineer, Punjab P.W.D. Public Health Branch, Patiala, to the Superintending Engineer, Public Health Circle (South), Rohtak.

Subject.—Theft of Pig lead at Public Health Stores, Kurukshetra.

Reference this office endorsement No. 6-49/367-CPH/Gii dated 8th September, 1964 and Secretary B & R/P.H. Branches, D.O. No. 10848-BRIII-(5)-64/ dated 8th December, 1964 to your address on the above noted subject.

2. You were asked to send a detailed report in the matter after overhauling the store accounts thoroughly, which is yet awaited. I am, therefore, desired to request you to kindly look into the matter and expedite the requisite report as Government are pressing for its early submission.

No. 30143-PH/Gii , dated 11th December, 1964

Copy forwarded to Secretary to Government, Punjab P.W.D. B. & R./P.H. Branches, Chandigarh for information with reference to his U.O. No. 8063-BRIII(5)-64, dated 30th November, 1964 and endst. No. 10848-BRIII(5)-64, dated 8th December, 1964.

(Sd.) . . .
for Chief Engineer, Punjab,
P.W.D., Public Health Branch.

Copy of D.O. No. 11005-BRIII-5-64/1159, dated 13th January, 1965 from Shri P.C. Suri, Deputy Secretary to Government, Punjab, P.W.D., B. & R./P.H. Branches, to the Chief Engineer, Punjab, Public Health Branch.

Subject.—Theft of pig lead at Public Health Stores, Kurukshetra.

Please refer to the correspondence resting with your endst. No. 30143-PH/Gii, dated the 11th December, 1964, on the subject noted above.

2. It is requested that a detailed report may be sent in the matter immediately, indicating if any special audit has been ordered. The S.E., Rohtak Circle has intimated that the control of Public Health Division Karnal, as also the relevant papers has been transferred to the Superintending Engineer, Ambala. He may, therefore, be asked to send a detailed report, along with the file of the case with your comments at the earliest.

Copy of endst. No. 11005-BRIII-5-64/1160, dated 13th January, 1965 by the same officer.

A copy is forwarded to the Superintending Engineer, Ambala Public Health Circle, Ambala Cantt., with reference to D.O. No. 2792/Gii, dated the 10th December, 1964 from the S.E., Public Health Circle (South), Rohtak.

[Minister for Public Works and Welfare]

He is requested to please supply the requisite file immediately for the perusal of the Public Works Minister, along with a detailed report.

Copy of Memo. No. 3565-PH/Gii dated 16t February, 1965 from the Chief Engineer, Punjab, P.W.D. Public Health Branch, Patiala, to the Superintending Engineer, Public Health Circle, Ambala Cantt.

Subject.—Theft of pig lead at Public Health Stores, Kurukshetra, district Karnal

Reference your Memo. No. 487/G, dated 6th January, 1965 on the subject noted above.

2. It is requested that a detailed report in the matter giving results of overhauling of accounts and verification of stores, etc., may be sent immediately with your comments for submission to Government.

This also disposes of your Memo. No. G/1457, dated 19th January, 1965.

No. 3566PH/Gii, dated 16th February, 1965

A copy is forwarded to the Secretary to Government, Punjab P.W.D., B. & R/P.H. Branches, Chandigarh for interim information with reference to his D.O. No. 11005-BRIII-5-64/1159, dated 13th January, 1965. A copy of an interim report sent by the Superintending Engineer, P.H. Circle Ambala Cantt., with his memo. No. 487/G, dated 6th January, 1965 together with a copy of Executive Engineer, Public Health Division, Karnal's letter No. 16560, dated 26th December, 1965, is sent, herewith, for information of Government. A detailed report about the overhauling of store, accounts etc., will be submitted on receipt from the Superintending Engineer, Ambala Cantt. who has deputed special staff for this purpose.

(Sd.) . . .,
for Chief Engineer, Punjab,
P.W.D. Public Health Branch, Patiala.

DA/Copy of Memo
with encl.

Copy of letter No. 487/G, dated 6th January, 1965 from the Superintending Engineer, P.W.D. Public Health Circle, Ambala to the Chief Engineer, Punjab, P.W.D. Public Health Branch, Patiala.

Subject.—Theft of pig lead at Public Health Stores, Kurukshetra, District Karnal.

Ref. correspondence resting with your letter No. 31666, dated 30th December, 1964

2. A copy of the letter No. 16560 dated 26th December, 1964 received from the Executive Engineer, Karnal regarding the theft of pig lead at Public Health Stores, Kurukshetra is enclosed herewith for further necessary action, in duplicate.

3. The written orders for over hauling the accounts of the Sectional Officers have already been issued by the Superintending Engineer, P.H. Circle (South), Rohtak. After the transfer of Karnal Division to this Circle, Shri Upkar Singh, S.D.O. was directed to carry out the physical varification at site and the same has been done by him. The record of the Sectional Officer was in very bad condition and nothing could be made out of it. A Special Senior Accounts Clerk has been deputed for this work and during the last inspection of the Division it was found that the accounts are being systematically overhauled and even made up to date by that Accounts clerk under the direct supervision of the Executive Engineer. About 70 per cent record has been made up to date. It will take a few months to make the balance record upto-date when the clear picture will come out. The Executive Engineer in the detailed report has also give details of other arrears created by the Sectional Officer and the S.D.O. The action to clear them is being taken separately. The file concerning the theft case is enclosed herewith.

Copy of letter No. 16560 dated 26th December, 1964 from the Executive Engineer, Division, Karnal to the S.E, P.H. Circle, Ambala.

Subject.—Theft of pig lead at P.H. Stores, Kurukshetra district, Karnal.

Reference Your endst No. 9709, dated 16th December, 1964.

The detailed history of the case is as under :

Shri Pritam Chand, S.O. was transferred to Kurukshetra during the month of May, 1959 and remained there till he was relieved on 10th November, 1964. He had been there for nearly 5 years. During these years he had been provided with a store-munshi for all the period. In the beginning Shri Gian Chand worked as Store Munshi and thereafter Shri Chuni Lal is working against that post, After my taking over the charge a directive of Public Accounts Committee was received that physical verification should be carried out in all the Public Works Divisions immediately. In pursuance of the same all the S.D.O's. were instructed to carry out the physical verification in their own Sub-Divisions. All the S.D.O's. could carry this out in various sections under them except in Kurukshetra section, as Shri Pritam Chand did not complete the records required for the same. He was, therefore, directed to do the same vide this office No. 11804 dated 16th August, 1963 and subsequently S.D.O. Karnal had sent a number of reminders in this respect but to no effect.

In the mean-while during the transfer season, the orders for transfers of various S.Os. were issued vide, S.E. South No. 6996, dated 30th March, 1964 in which the was transferred to Yamunanagar in being relieved by Shri Sudhir Kumar, S.O. even before hand when his transfer orders were contemplated he was informed in writing *vide*—this office letter No. 4036-38 dated 25th March, 1964 that he was likely to be transferred during this transfer season and therefore he should complete his record. Even in spite of this he has not completed his record till to-date.

Shri Sudhir Kumar, S.O., who was to come in his place however could not join and therefore the transfer orders had to be held in abeyance.

In the mean-while on 16th June, 1964, Shri Pritam Chand S.O. lodged a report with Station House Officer, Police Station, Thanesar *vide* his letter, dated 16th June, 1964 under intimation to this office for the theft of 1306-3/4 Kgs. of pig lead i.e., 40 bars cost of which is approximately Rs. 2,156, This office therefore wrote to the Superintendent of Police, Karnal to carry out the investigation and simultaneously sent a report to the A.G., Punjab and the Superintending Engineer, P.H. Circle (S),.. Rohtak, as required under the rules No. 2.34 and 2.35 of P.F.R. Vol. I vide this office No. 7775/EE, dated 20th June, 1964. After carrying out the preliminary investigation, it was found that

(a) Shri Pritam Chand, S.O., was keeping the keys of the stores with Roor Singh Chowkidar.

(b) Some of the Locks were not working properly and

(c) There was no sign of damage to the room or to the lock of the room in which the pig lead was stored and from which the lead was alleged to have been stolen.

The S.O. was therefore ordered to change the locks immediately and keep the keys in his own custody and complete his records.

The S.O.M. was instructed to complete his records at this time also which he did not do. A check of his stock registers was done and it was found that most of the registers were incomplete and a report in this respect was made to the S.E. P.H. Circle (South), Rohtak *vide* this office letter No. C/253 dated 3rd July, 1964. The S.E., P.H. Circle (S) Rohtak then instructed the undersigned to carry out the departmental inquiry as required under Appendix-2 of Punjab Financial Rules Vol. II. For this purpose the Executive Engineer, P.H. Division, Karnal, S.D.O. P.H. Sub-Division, Karnal and S.D.O. P.H. Sub-Division, Yamunanagar went to Kurukshetra and carried out the check of various indent books to find out, if any indent for issue and receipt of pig lead remained to be accounted for. It was found that the following 7 indents were not accounted for and the quantity of lead of these indents was approximately 1½ tons.

[Minister for Public Works and Welfare]

(1) No. 43/386, dated 18th December, 1962.

(2) No. 61/11 dated 19th January, 1963.

(3) No. 66/11, dated 22nd January, 1963.

(4) No. 9/150, dated 20th August, 1959.

(5) No. 15/150, dated 8th October, 1959.

(6) No. 56/150, dated 12th February, 1960.

(7) No. 70/539, dated 6th August, 1961.

One of the indents did not contain even the quantity of lead that was issued. When this was found the Executive Engineer, Karnal ordered that all the rcords pertaining to this section should be kept under lock and key by the S.D.O. P.H. Sub-Division, Karnal and account compiled by his office. The matter was reported to the S.E. South *vide* this office endst. No. 9708 dated 28th July, 1964. The Superintendent of Police Karnal was also informed vide this office No. 9703 dated 28th July, 1964 that the case may be withdrawn as the S.O. had not accounted the material.

The ground balances were got checked independently from the S.D.O. Rural Investigation Sub Division, Ambala Shri Upkar Singh and a separate Senior Accounts Clerk has been posted to complete the registers to find out the discrepancies, if any, in addition to the lead, as the store contains many items which are costlier than lead viz., spare parts of machinery. The Senior Accounts Clerks posted specially for this purpose has up to date chcked 13 indent books and made necessary missing entries of issue and r eceipt of the scrutiny of these 13 indent books is as under :—

(a) The number of indents not accounted so far or partially accounted for is 363.

(b) Number of indents against which material has been issued without getting the same approved from proper authority is 433.

(c) 69 indents do not carry the signatures of receiving persons.

(d) 94 indents do not carry the signatures of indenting persons.

(e) 29 indents do not carry the signatures of issuing persons.

In addition to the above, it was found that the Sectional Officer had in his possession :—

(a) About 45 A.Ts. from the year 1954 which he had neither verified nor returned for the additional information, if any required, by him.

(b) Eight A.G. Memos, ranging from the year 1959 which he had not verified.

(c) It was further found that he had with him about 94 indents from other Sections and Divisions against which material had been issued, but which he had not sent to the S.D.O. for accounting of the material and necessary adjustment.

(d) He has further got about 60 bills of various contractors to be finalled up ranging from the period 1959 and for which contractors are clamouring.

In the first instance on 29th August, 1964, he informed that he had only 13 indent books while on further search on 3rd September, 1964 it was foundthat he had one more indent book relating to his period. When this was found, this office recommended that he may be shifted from this place and asked Shir Jit Singh, S.O. to take the charge of Kurukshetra Section from Shri Pritam Chand, S.O's additional charge, which he gave very reluctantly and in an incomplete manner without completing his record or without completing his bills.

In the meanwhile it was found that a S.O. was required urgently at Sunder Nagar and therefore his transfer was ordered by the S.E., Ambala which he had not complied with. On the findings of unaccounting of lead he was served with charge-sheet, but it could not be served for a long time, as he was absent from the Head quarters without giving any address and all the registered letters sent to his permanent address as well as to the residential address at Kurukshetra were returned by the postal authorities undelivered, even though he claimed that he was not well.

A full report as to the shortages, if any, will be given on completion of the record. Special audit is being carried out, as desired by the Superintending Engineer, P.H. Circle (South) Rohtak under appendix-2 of Punjab Financial Rules Vol. 11.

It will thus be seen that though the Divisional office as well as Sub-Divisional office is making all possible efforts for completing the records in an expeditious manner, there is no co-operation from the Sectional officer and therefore the case is getting delayed.

Grant of Old age Pension

2494. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the names of the blind persons belonging to the Amritsar and Sangrur Districts from whom applications for the grant of Old age pension have so far been received by the Government together with the names of those among them who have been granted such pensions and the amount thereof in each case;

(b) the reasons, if any, for not granting the said pension to the remaining applicants, a copy of each of their applications be laid on the Table of the House;

(c) the time likely to be taken in sanctioning old age pension to the persons referred to in part (b) above?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) and (b) No separate record of the blind persons is maintained. Moreover the time and labour involved in the collection of the requisite data will not be commensurate with the benefit desired to be achieved.

(c) Efforts will be made to clear the pending applications by the end of the year 1965-66, subject to availability of funds.

Representation from Gram Panchayat of village Tandian, Police Station Sardulgarh, District Bhatinda

2495. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state whether Government received in 1964-65 any representations from the Gram Panchayat of Village Tandian, Police Station Sardulgarh, District Bhatinda for killing mad dogs in the said village; if so, the number of such representations, the action, if any, so far taken thereon and a copy of each application be laid on the Table of the House?

Sardar Darbara Singh (Home and Development Minister) : No such representation was received by the Government during the year 1964-65 in this behalf.

Water Works of Village Tandian, Police Station Sardulgarh, District Bhatinda

2496. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether Government received any representations in 1964-65 from the Gram Panchayat Tandian, Police Station Sardul-

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

garh, district Bhatinda regarding the irregularities committed in running the village water works; if so, the number of such complaints ;

(b) the number of complaints entered by the Sarpanch of the Gram Panchayat of the said village in the complaint book kept at the water works station ;

(c) a copy of each complaints referred to in parts (a) and (b) above be laid on the Table of the House together with the details of the action, if any, so far taken thereon ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes. One.

(b) One.

(c) Copies of the entry in Gram Panchayat Register and of complain are enclosed. The driver who was responsible for the irregularities in running that water works was removed from service, and replaced by another driver. The Gram Panchayat is now satisfied with the working arrangement of that water works. A report to that effect from Sarpanch is also placed on the Table of the House.

ਸਰਪੰਚ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਟਾਂਡੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਨਸਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੰਡਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਮਿਤੀ 8/11/64 ਦੀ ਸਹੀ ਨਕਲ।

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਵੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਵਕਤ ਸਿਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਉਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੀ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਸਹੀ
ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ,
ਸਰਪੰਚ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਟਾਂਡੀਆਂ
ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ।

ਨਕਲ ਅਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ:
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੰਡਲ, ਬਠਿੰਡਾ।

ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਟਾਂਡੀਆਂ ਤਸੀਲ ਮਾਨਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀ-ਨੀਅਰ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੰਡਲ, ਬਠਿੰਡਾ, ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਮਿਤੀ 17/3/1965 ਦੀ ਸਹੀ ਨਕਲ।

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ (Water works) ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵਕਤ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ।

ਸਹੀ
ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ
ਸਰਪੰਚ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਟਾਂਡੀਆਂ,
ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਨਸਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ।

ਨਕਲ ਅਸਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਹੈ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਨ
ਸਿਹਤ, ਮੰਡਲ, ਬਠਿੰਡਾ ।

The copy of the complaint entered into the Log Book of Water Works Tandian at page 8 is as under, made by the Sarpanch Mukhtar Singh, Gram Panchyat Tandian.

ਮਿਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 1964 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਮਿਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 1964 ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 1964 ਤਕ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ।

(1) ਦਸਖਤ ਸਰਪੰਚ
(ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ)
(2) ਅੰਗੂਠਾ ਨਿਸ਼ਾਨ
(ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ)

Attested.

Sd/— Niranjan Singh
B.D. & P.O. Jhunir.

Attested.

Sd/ D.D. & P.O,
Bhatinda.
23.3.65

Up-grading of Government Primary School, Tarsikka, District Amritsar

2497. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to upgrade the Government Primary School Tarsikka, district Amritsar ;

[Comrade Makhan Singh Tarsikha]

(b) if the answer to part (a) above is in the affirmative, whether Government intend to upgrade the said school during April-May, 1965 ;

(c) the number of students studying at present in each class in the said school together with the names of the teachers therein with their academic qualifications ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes.

(b) No definite date schedule can be indicated at this stage.

(c) The requisite information is enclosed.

No. of Students Class-wise—

I Class	..	116
II Class	..	91
III Class	..	105
IV Class	..	87
V Class	..	59

Names of Teachers with Qualifications—

(1) Shri Mohinder Singh	..	Matric, J.B.T.
(2) Smt. Gurmit Kaur	..	Matric, J.B.T.
(3) Smt. Gurnam Kaur	..	Matric, J.B.T.
(4) Shri Gurdial Singh	..	Matric, J.B.T.
(5) Smt. Charanjit Kaur	..	Matric, J.B.T.
(6) Smt. Santosh Kumari	..	Matric, J.B.T.
(7) Smt. Mohinder Kaur	..	Matric, J.B.T.
(8) Smt. Balwant Kaur	..	Middle., J.B.T. Plucked.
(9) Shri Chuhr Singh	..	Middle, J.V.
(10) Smt. Amarjit Kaur	..	Matric, J.B.T.

Betterment Levy

2499. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Revenue be pleased to lay on the Table of the House a statement showing the amount of betterment levy assessed and realised, separately, distrct-wise in the State during the period from 1958 to-date ?

Sardar Harinder Singh Major : A statement giving the required information is laid on the Table of the House.

Statement showihg the amount of Betterment levy assessed and realised during the period from the year 1958 to January 1965

District		Total amount assessed from the year 1958 to January, 1965	Total amount recovered from the year 1958 to to January, 1965
		Rs	Rs
Hissar	..	3,88,05,529	3,52,74,727
Rohtak	..	43,28,134	38,81,351

District		Total amouut assessed from the year 1958 to January, 1965	Total amount assessed from the year 1958 to January, 1965
Karnal	..	73,31,417	61,17,725
Ambala	..	3,72,698	3,18,768
Hoshiarpur	..	13,800	13,735
Jullundur	..	17,03,995	15,61,392
Ludhiana	..	10,66,923	10,48,710
Ferozepur	..	1,31,67,751	1,20,54,815
Kapurthala	..	1,55,257	1,48,382
Patiala	..	38,07,651	33,01,521
Bhatinda	..	1,33,43,322	1,20,12,123
Sangrur	..	1,15,67,752	1,10,81,405
Mohindergarh	.	13,85,740	13,82,592

Note.—In the remaining districts Betterment levy was not chargeable.

Scheme to increase revenue during the Fourth Five-Year Plan

2500. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state the details of the proposals or schemes submitted or proposed to be submitted by the Government to the Fourth Finance Commission regarding an increase in the revenue of the State and to assess the financial requirements of the State on revenue account during the Fourth Five-Year Plan period ?

Sardar Kapoor Singh : A copy of the brief summary of the Memorandum is attached.

MEMORANDUM TO THE FOURTH FINANCE COMMISSION

(A SUMMARY)

The Fourth Finance Commission, appointed by the President is required to make recommendations with regard to the principles which should govern the distribution of such Central levies the net receipts from which are to be distributed partly or wholly to the States in accordance with the provisions of Article 280 of the Constitution. It is also required to make recommendations for grant-in-aid of revenues to such States as have a deficit in their revenue budget under Article 275(1) of the Constitution.

[Minister for Finance and Planning]

2. The Commission has been specifically asked to consider only the revenue requirements of the State Governments for the Fourth Plan period, i.e., 1966-67 to 1970-71. It is not required to look into either the capital requirements or the Plan requirements for this period.

3. With a view to ascertain the requirements on non-Plan revenue account, a forecast of receipts and expenditure has been prepared for the period 1966-67—1970-71. The receipts have been estimated on the basis of the current rates of taxes, budget estimates for the year 1964-65, and the likely increase on the basis of actuals for the last 4 years. Recent decisions taken by the State Government in respect of certain taxes, such as, Stamp Duty and Marla Tax, etc., have also been taken into account. The likely increase in receipts from various taxes, such as, Sales-tax, etc., as a result of increase in incomes, generated by the increased Plan Out-lays, has also been kept in view.

4. The revenue expenditure has been estimated on the basis of budget provision for the year 1964-65, keeping in view the normal increase on account of annual increments and contingencies, etc. An attempt has also been made to estimate the committed expenditure which would have to be provided on the non-plan side during the Fourth Plan period for the maintenance and continuance of such Third Plan schemes as would have been completed by the end of the Third Plan period and would not form part of the Fourth Plan. The total committed expenditure in this regard comes to about Rs 70 crores for the entire Fourth Plan period.

5. The total revenue receipts, excluding the receipts from the share of Central taxes, have been estimated at Rs 444.48 crores. The total revenue expenditure including the committed expenditure for the maintenance of Third Plan schemes has been estimated at Rs 588.89 crores. Thus the deficit on the non-Plan revenue account comes to about Rs 144 crores.

6. According to the present arrangements, which are based on the recommendations of the Third Finance Commission, the State Government receives a sum of nearly Rs 15 crores per annum from the Central Government on account of shared taxes and grant—in lieu of tax on railway fares. Tentatively, a sum of Rs 78 crores has been estimated to accrue from this source during the Fourth Plan period. Receipts from this source, however, would depend upon the formula recommended by the Fourth Finance Commission with regard to the share and manner for the distribution of such taxes between the Centre and States and amongst the States.

7. The case for grant-in-aid to this State under Article 275(1) has been prepared on the following grounds :—

A. MAINTENANCE OF FLOOD CONTROL AND ANTI-WATERLOGGING WORKS

The State is required to incur a very heavy expenditure on the maintenance of flood control and anti-water-logging works. So far, the provision made for the maintenance of such works has not been adequate because of lack of funds. In the forecast of expenditure for the Fourth Plan period, only Rs 100 lakhs have been provided for the maintenance of Flood works on the basis of the budget provision for the year 1964-65. The requirement, however, is of the order of Rs. 5 crores, and, hence, an additional sum of Rs 4 crores is to be provided in case these works are to be kept in absolut ely efficient condition.

B. Border Police

The State Government is required to incur considerable expenditure on the maintenance of the Border Police. A detailed case has been prepared, requesting the Finance Commission, that the entire expenditure on the Border Police should be treated as a liability of the Central Government. The amount required for expenditure on this account has, however, been included inthe forecast of expenditure which partly explains the huge deficit.

C. Maintenance and Repairs of Roads

A case has been made out for additional funds to the tune of Rs 3.50 crores over and above what has been included in the forecast of expenditure for the maintenance and repairs of roads. The justification for this additional requirement is as follows :—

(a) The condition of roads has been badly affected because of floods and water-logging.

(b) The roads in Punjab have to carry a very heavy military traffic and, therefore, a part of the maintenance expenditure should be borne by the Central Government ; and

(c) The State has one-fifth of its total area in the hilly region where the cost, both for the construction and maintenance of roads, is higher than for the plains.

The Third Finance Commission had emphasised the need for proper maintenance of existing roads and construction of new roads to open up backward areas, breaking down barriers of isolation and stagnation and to mobilise economic resources. Adequate funds for roads maintenance are however, not being provided because of limited resources at the disposal of the State Government. At present, the maintenance grant is sanctioned @ Rs 1,800 per square mile, whereas the requirement is @ Rs 3,000 per square mile. The Third Finance Commission had set apart a sum of Rs 36 crores for the distribution amongst the States which were in need of additional funds for the construction of roads. The Punjab State was, however, not allocated any sum from this fund. It has been urged in the memorandum that the Fourth Finance Commission should consider the requirements of this State in the context of various factors enumerated above.

D. Maintenance of the Post-Graduate Institute for Medical Education and Research at Chandigarh

It has been estimated that the revenue requirement for this Institute would be about Rs. 6.67 crores during the Fourth Plan period. As against this requirement, only Rs. 3 crores have been included in the forecast of expenditure on the basis of the budget allotment for 1964-65. An additional sum of Rs 3.67 crores will have, therefore, to be provided which would further add to the deficit.

E. Requirements to finance the committed expenditure of Punjab, Kurukshetra and Punjabi Universities

It has been estimated that these three Universities will require a sum of Rs 3.19 crores to meet their committed expenditure during the Fourth Plan period. No account has been taken of this requirement in the forecast of expenditure for 1966-67 to 1970-71. In addition to this, the Kurukshetra and Punjabi Universities would require another sum of about Rs 3.80 crores for their expansion programme. Since the Finance Commission is not considering the requirements of capital expenditure and as the developmental expenditure should be provided in the Plan, no account of it has been taken in the forecast of expenditure.

F. Revision of pay-scales of Lecturers and Teachers

The question of an upward revision of the pay-scales of Teachers/Lecturers is being considered in the context of tight resources position of the State Government and a case has been made out for Central grant in this regard.

[Minister for Finance and Planning]

G. Revision of pay-scales and other allowances to the employees of the State Government

The State Government have announced certain concessions to its employees which would involve an additional expenditure of Rs 21.90 crores during the Fourth Plan period. This expenditure too has not been included in the forecast of expenditure and, hence a separate case has been prepared in this regard.

H. Servicing of Debt

It has been calculated that the State Government would require a sum of about Rs.29.49 crores for the servicing of debt which will have to be raised during the Fourth Plan period for financing the Plan. A separate statement in this regard has been prepared and submitted to the Fourth Finance Commission.

8. The case for special grant-in-aid to this State under Article 275(1) has been prepared to meet the various requirements enumerated earlier. It has been urged in the memorandum that considering the over all financial position of the State Government and its commitments to solve some of the most emergent problems, the State deserves a handsome grant-in-aid so that its budgetary position may be stabilized.

9. Though not strictly, within the terms of reference of the Fourth Finance Commission, a separate chapter has been devoted to the financial arrangements for the repayment of the loans obtained for the Bhakra-Nangal Project. It has been argued that State Government is not in a position to pay a sum of about Rs 82 crores during the Fourth Plan period on account of principal of loans obtained for the Bhakra Project. Unless some suitable formula is evolved to stagger these payments, it will have a very crippling effect on the resources position of the State Government and it is felt that as a consequence the State would not be able to contribute its share towards the financing of the Fourth Plan.

10. In a separate chapter the question of mounting debt of the Centre on the State has been discussed vis-a-vis the resources position of the State. It has been argued that as a result of Plan finance, the liability of the State Government on account of loans raised from the Centre and open market is increasing very heavily. It would be clear from the fact that as against the total debt liability of Rs 78.37 crores on 1st April, 1952, the total debt liability on 1st April, 1964, is of the order of Rs 350.60 crores. It has been urged that the Fourth Finance Commission should consider the problems both with regard to payment of this mounting debt and its servicing in the context of the deteriorating financial position of the State Government. It has also been explained that on the one hand the tax resources of the State Government are not as elastic as those of the Centre and, on the other the expenditure on account of committed liability is increasing as a result of the completion of Five -Year Plans.

11. The views as incorporated in the memorandum with regard to the manner of distribution of the shared taxes, are as follows :—

(i) *Income-tax.*—(a)It has been suggested that the corporation tax and the surcharge should also be made a part of the divisible pool from which the distribution is made amongst the various States. At present, the corporation tax and the surcharge are exclusively retained by the Central Government.

(b) It has, further, been suggested that the share of the States should be raised from 66.2/3 per cent to 80 per cent as the expenditure of the State Governments is continuously rising on account of committed liability for Plan maintenance.

(c) As regards the manner of distribution *inter se* between the States, it has been urged that the factor of collection should be eliminated altogether and distribution be made entirely on the basis of population. The share of the State at present is determined to the extent of 80 per cent on the basis of population and 20 per cent on the basis of collection. It has been argued that the States which are deficient in natural and mineral resources, etc., and consequently could not reach the desired level of industrial development should not be put to disadvantage in the matter of distribution of Income Tax for no fault of their own. As a matter of fact, the distribution should be on the basis of population so that the disparity obtained in the levels of industrial development amongst the States may be eliminated in due course of time.

(ii) *Estate Duty.*—The Second Finance Commission had decided that the Estate Duty should be distributed on the basis of collection, i.e., every State should receive broadly the amounts which it would have raised if it had the power of levying and collection of the Estate Duty. This principle is unquestionable and, therefore, has been endorsed.

(iii) *Grant in lieu of Tax on Railway Fares.*—The Second Finance Commission had decided that the proceeds in this regard should be distributed on the basis of route mileage within each State with due allowance for wide variation in the intensity of traffic between various zones and between the various gauges in each zone. Accordingly, the share of the Punjab Government was fixed at Rs 1.01 crores per annum by the Third Finance Commission. It has, however, been urged in the memorandum that actual receipts from this levy would have yielded increasing revenues to the States with the growth in passenger traffic and increase in fares and, therefore, the share of the State Government should be increased.

(iv) *Excise Duty.*—At present, 20 per cent of the Excise Duty on all commodities is distributed amongst the States. It has been urged in the memorandum that this share should be raised from 20 to 30 per cent as the States are in need of more funds to finance their continuously increasing revenue expenditure. It has been further urged that the distribution between the States should be on the basis of population till reliable data on consumption are available.

(v) *Distribution of Additional Excise Duties.*—These duties are levied on mill-made textiles, sugar and tobacoo including manufactured tobacoo in lieu of the sales-tax under an agreement with the States. The Third Finance Commission had decided that the Punjab State should be given a sum of Rs 175 lakhs as assured sum and 5.25 per cent of the remaining sum after the distribution of assured sum amongst the States. These amounts were fixed on the basis of the income from sales-tax on these commodities in the year 1957-58. It has been argued in the memorandum that the rate of General Sales-tax has been increased in this State by about 87.5 per cent since 1957-58, and, therefore, the share of the State Government should also be increased accordingly. The total income which should accrue to the State Government according to the increase in the rate of General Sales-tax in the year 1964-65 comes to about Rs 328 lakhs whereas the actual allocation by the Centre is only 175 lakhs, thus causing a loss of Rs 153 lakhs.

12. The Commission is also required to consider the combined incidence of the State Sales-tax and Union Duties of Excise on the production, consumption or export of commodities or products on which both these duties are levied and recommend the adjustment if any, to be made in the State's share of Excise duties in case the rate of Sales-tax is increased beyond a limit to be specified by the Commission. Any idea of imposing a limit on the rate of Sales-tax has been opposed in the memorandum on the ground that it is the only elastic source of tax revenue and, therefore, be left at the discretion of the State Government. If, however, it is felt that the combined incidence of both of Sales-tax and Union Excise Duties is too heavy a burden on the trade and commerce of a particular commodity, the necessary reduction may be made in the Excise Duty rather than limit the rate of the Sales-tax which is governed by various factors such as, pattern of consumption and local preferences from area to area.

13. It has been mentioned in the memorandum that though the size of the Fourth Plan of the State has not yet been finalized in consultation with the Planning Commission, a sum of Rs 150 crores out of the proposed Fourth Plan outlay of Rs 500 crores may be assumed on the revenue account. The total deficit in the revenue budget both on Plan and Non-Plan account for the Fourth Plan period has therefore been worked out as follows :—

Item		*Rs. in crores*
(i) As reflected in the Forecast	..	144.41
(ii) Concessions granted to Government employees	..	21.90
(iii) Servicing of Debt	..	29.49
(iv) Revenue component of the Plan	..	150.00
(v) Additional requirements to solve various problems already discussed		23.32
Total	..	3,69.12

[Minister for Finance and Planning]

Receipts from the shared taxes during the Fourth Plan period would depend upon the recommendations of the Fourth Finance Commission. Tentatively, however, a sum of Rs 78 crores may be expected on the basis of the present arrangements, thus reducing the net deficit to Rs 291 crores. It has been indicated in the memorandum that according to 1964-65 budget estimates, Punjab is the third most heavily taxed State in the country and, therefore, the scope for any major additional taxation effort is very limited. The Fourth Finance Commission has, therefore, been requested to consider and suggest as to how and in what ways this State would be able to cover such a huge gap in its revenue budget as of the order of Rs 291 crores for financing the inescapable and committed non-Plan expenditure, the revenue component of the Plan and to solve some of the most emergent problems during the Fourth Plan period.

Land Development and Seed Corporation

2501. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state the details of the Land Development and Seed Corporation proposed to be set up by the Government during the current year together with the total amount expected to be spent thereon and a copy of the rules and regulations, if framed, regulating its functions etc., be laid on the Table of the House ?

Sardar Darbara Singh : A copy of the *Memorandum and Articles of Association of the Corporation is added for laying it on the Table of the House.

Licensees of Methylated Spirit in Narnaul

2506. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the names of the firms and of individuals who are licensees and quota-holders of denatured (methylated) Spirit at Narnaul since 1962 to-date ;

(b) whether Government received any complaints from the residents of Narnaul regarding the sale of spirit by some of the said licensees in the black-market, if so, the names of the individuals/firms complained against and the action, if any, taken on the complaints ;

(c) whether the licence of Shri Hari Kishan Sanghee, who was an old licensee was cancelled ; if so, the reasons therefor ;

(d) whether any representations have been received from the ex-licensee mentioned in part (c) above; if so, copies thereof be laid on the Table of the House, along with the details of the action, if any, taken thereon ;

(e) the quantity of quota given to the various licence-holders mentioned in part (a) above during the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65.

Shri Prabodh Chandra : (a) and (c) A statement is enclosed.

(b) A complaint was received against Shri Daya Ram, Licensee which on enquiry was found to be baseless.

(c) *Part I*—No.

Part II—Does not arise.

(d) Does not arise.

---

*Placed in the Library.

(a) and (e) A statement showing the names of the firms and of individuals who are licensees of denatured spirit at Narnaul since 1962 to-date and the quantity of spirit imported by them.

	Name of the licensee	*Quantity of denatured spirit imported. (No quota is allotted, but permits are issued)*		
		1962-63	1963-64	1964-65
1.	Shri Hari Shanker Singh ..	260 B. Litres and 40 gallons	..	160 B. litres
2.	Shri Ghasi Ram Bansal ..	..	400 B. litres	..
3.	Shri Daya Ram ..	..	400 B. litres 200 B. litres (stock not yet received)	400 B. litres

Iron and Steel quota holders in Mahendragarh District

2507. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state the names and addresses of the firms and of individuals who got Iron and Steel Quota in district Mahendragarh during the year 1962-63, 1963-64 and 1964-65 and the quantity given to each during this period yearwise ?

Shri Ram Kishan :

Year	Serial No.	Name and address of the party	Quantity
1962-63	1	M/s Ishwar Industries, Charkhi Dadri	10 MT CRBP Sheets
	2	M/s Baldev Trunk House, Charkhi Dadri ..	10 MT CRBP Sheets
	3	M/s Gian Chand Trunk Factory, Narnaul ..	5 MT CRBP Sheets
1963-64		Nil	Nil
1964-65	1	M/s Arya Trunk Factory, Narnaul ..	B.P. Sheets 16-20 0.200 Mt.
	2	M/s B.D.P.O. Baund Kalan at Charkhi Dadri	0.200 Mt. B.P. Sheets 16-20
	3	M/s Baldev Trunk House, Charkhi Dadri ..	0.200 Mt. B.P. Sheets 16-20G
	4	M/s Ishwar Industries, Charkhi Dadri ..	0.200 Mt. B.P. Sheets 16-20G
	5	M/s Hazari Lal Radhe Sham, Mohindergarh	0.200 MT. B.P. Sheets 16-20G

Quota of Methylated Spirit given in Amritsar District

2598. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state the names of licensees both firms and individuals for denatured (Methylated) spirit in district Amritsar for the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65 and the quantity given to each during this period, year-wise.

Shri Prabodh Chandra : A statement is enclosed.

Statement showing the names of the licensees and qaota of denatured spirit given to them during the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65

Serial No.	Names of the Licensees	*Quantity of D/Spirit given during the years*		
		1962-63 B/Litres	1963-64 B/Litres	1964-65 B/Litres
1	Shri Surjan Singh, Queens Road, Amritsar ..	109,800	36,500	6,300
2	Shri Surinder Singh, Chowk Farid, Amritsar ..	30,400	5,200	4,300
3	M/s Siri Ram Ganga Ram, Amritsar ..	..	600	200
4	M/s Malik Singh & Sons, Amritsar ..	362	843	200
5	M/s Sukhdev Singh & Sons, Amritsar ..	818	2,400	3,400
6	M/s B. Kesar Singh & Sons, Amritsar ..	400	400	200
7	Dr. Madan Lal Khanna & Sons, Amritsar ..	..	1,400	600
8	M/s Khushal Singh & Sons, Bazar Mai Sewan, Amritsar ..	8,500	3,700	1,000
9	Shri Harbhajan Singh, Ram Bagh, Amritsar	1,800	1,800	600
10	M/s Partap Singh-Joginder Singh, Ram Bagh, Amritsar ..	..	200	..
11	Shri Kartar Singh, son of Partap Singh, Ram Bagh, Amritsar ..	400	400	600
12	M/s H. Sehagal & Co., Putligarh, Amritsar	780	400	60
13	M/s National Laboratories, Chheharta ..	600	1,000	200
14	Shri Roop Lal, Chowk Phyllanwala, Amritsar	..	200	200
15	Shri Madan Lal, Bhairo Asthan, Amritsar ..	..	..	600
16	Shri Chuni Lal, Bazar Pashamwala, Amritsar	623	800	3,200
17	M/s S. Sobha Singh & Co., of Kohinoor Paints Works ..	800	600	800
18	M/s N.S. Sobha Singh, Bazar Misri, Amritsar	600	400	600

Serial No.	Names of the Licensees	Quantity of D/Spirit given during the years		
		1962-63 B/Litres	1963-64 B/Litres	1964-65 B/Litres
19	Shri Parma Nand, Kot Baba Deep Singh, Amritsar ..	400	1,400	1,200
20	Gurbachan Singh, Bazar Kathiana, Amritsar ..	..	600	600
21	M/s Kishore Brothers, Cooper Road, Amritsar	..	200	..
22	M/s B. Uttam Singh Kesar Singh, Darshani Deori, Amritsar ..	200	200	..
23	M/s Friends Chemist, Chawal Mandi, Amritsar	..	..	200
24	Shri Sher Singh, Bazar Sodhian, Amritsar ..	..	1,200	3,200
25	M/s Gurdit Singh-Natha Singh, Tarn Taran (Amritsar) ..	..	600	600
26	M/s Gurbax Singh & Sons, Tarn Taran ..	..	600	600
27	Shri Harsharan Singh, Tarn Taran ..	200	..	200
28	M/s Sohan Singh & Sons, Hall Bazar ..	600	Cancelled	..
29	Hakim Tek Chand, Jandiala ..	908	1,400	1,400
30	M/s Ajaib Singh-Joginder Singh, Bhikhiwind	..	..	800
31	M/s Hakam Singh-Darbara Singh, Chowk Darbar Sahib, Amritsar ..	..	200	..
32	Shri Inder Singh, Dhanta Chemical Works, Patti	400	900	1,000
33	Shri Ranjit Singh, Bazar Pashamwala ..	..	1,400	4,400
34	M/s Punjab Distilling Industries, Khasa ..	3,077	2,195	1,000
35	Shri Raghbir Singh Kataria of Kataria General Stores, Amritsar ..	1,000	2,600	2,400
36	Shri Muni Lal, Kt. Mohar Singh, Amritsar ..	..	800	28,00
37	M/s Kansh Ram Lal-Yogesh Chander, Lohgarh, Amritsar ..	..	800	3,400
38	M/s Kansh Ram-Sham Lal, Bazar Papran, Amritsar ..	32,600	15,200	5,300
39	Shri Ganga Singh, Bazar Papran, Amritsar ..	7,400	2,400	1,400
40	Shri Harbhajan Singh, son of Amri Chand, Bazar Jallianwala, Amritsar ..	..	800	4,000
41	Shri Inder Singh Sohal of Sohal Medical Store, Patti ..	200	1,000	200
42	M/s R.S. Marjara & Co., Hall Bazar, Amritsar	1,000	800	200

[Minister for Education and Local Government]

Serial No.	Names of the Licensees	Quantity of D/Spirit given during the years		
		1962-63 B/Litres	1963-64 B/Litres	1964-65 B/Litres
43	Shri Ram Rattan Singh, son of Hakam Singh, Chowk Darbar Sahib, Amritsar	..	700	1,200
44	M/s Tek Chand and Sons, Ramtirth Road, Amritsar	..	800	1,000
45	Shri Ram Labhaya, son of Feroze Chand, Lohgarh Gate, Amritsar	..	1,400	3,850
46	M/s R.N. Balbir Singh & Co., Ram Bagh, Amritsar	..	1,600	7,900
47	The General Manager, Amritsar Central Co-operative Consumer Stores, Coper Road, Amritsar	..	1,000	4,650
48	Shri Roshan Lal, son of Puran Chand, Darshani Deori, Amritsar	..	..	3,000
49	Shri Harbans Lal, son of Jaswant Rai, Bazar Bikanarian, Amritsar	..	200	600
50	Shri Jagtar Singh, Chowk Lachhmansar, Amritsar	400	..	..

Utilisation of loan given to Jandiala Municipal Committee

2510. Comrade Makhan Singh Tarsikka, : Will the Minister for Education and Local Government with reference to the reply to Unstarred question No. 1097 included in the list of questions for the 16th September 1963, be pleased to state —

(a) whether the amount of Rs 25,000 given as loan to the Jandiala Municipal Committee for the construction of Ekka Stand and for a Municipal Park has since been utilised for the purpose for which it was given;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the details of the construction work so far done by the said committee and if in the negative, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra : (a) No.

(b) The land has not yet been acquired by the Committee for the construction of Ekka Stand and Municipal Park.

Dramas and Public meetings etc. arranged by the Public Relations Department, Punjab in Amritsar District

2511. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the names of the places where conferences, Dramas, Kavi Darbars, and Public Meetings were organised by the Public Relations Department in Amritsar District, in the year 1963-64and 1964-65 together with the purposes of the meetings and the amount spent on each function in detail ;

(b) the names of the persons who addressed the abovementioned meetings in each case ?

Shri Ram Kishan : The time and labour involved in compiling the required information will not be commensurate with the advantage sought to be desired. The services of entire Rural Publicity staff at Amritsar have since been terminated.

Loans/Grants given to certain Housing Co-operative Societies

2512. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state the names and addresses of the office bearers and members of the following co-operative housing societies, with the details of loan, if any, granted to them by the Government :—

(i) the Chandigarh Friends Co-operative House Building Society (Ltd);

(ii) Mano Chahal Co-operative House Building Society (Ltd.) village and post office Mano Chahal, Tehsil Tarn Taran, district Amritsar.

(iii) the Jhabal Kalan Co-operative House Building T.T. Society (Limited), village and post office Jhabal Kalan, tehsil Tarn Taran, district Amritsar ?

Sardar Darbara Singh : The requisite information is enclosed.

Reply to unstarred Vidhan Sabha Question No. 2512 by Comrade Makhan Singh Tarsikha, M. L. A. regarding loans/grants given to certain Housing Co-operative Societies

Serial No.	Name of Society	Names and Addresses of office bearers	Names of members, with addresses	Amount of loan granted to member by the Government
1	2	3	4	5
1	The Chandigarh Friends Refugees Co-operative House Building Society Ltd.	1. Shri Nand Singh, President, 598 Model Town, Jullundur, City.	1. Shri Santokh Singh Deputy Superintendent C/o the Director, Consolidation of Holding, Punjab, Jullundur	..
		2. Shri Behari Lal, Vice President Sanitary Superintendent, Municipal Committee, Jullundur	2. Shri Kishan Chand Tanali, Katra Sher Singh , Amritsar	..

[Minister for Home and Development]

1	2	3	4	5
		3. Giani Pritam Singh, Secretary, 248, Model Town, Ambala City	3. Dr. K.N. Gaind Katra Sher Singh, Amritsar	..
		4. Shri Balwant Singh Hazooria, Cashier, Book Seller, Adda Hoshiarpur, Jullundur City	4. Mrs. Nirantra Gaind, daughter of Shri Kishan Chand Tanoli, Katra Sher Singh, Amritsar	..
		5. Shri Baldev Singh II Lieut, Member Committee, 33 Polo Ground Jodhpur	5. Baba Harbhajan Singh Bedi C/o Shri Kuldip Singh Bindra, Agricultural Officer, Ludhiana	.. ..
			6. Shri Kuldip Singh Bindra, Agricultural Officer, Ludhiana	..
			7. Shri Jagdish Singh Grover, C/o Giani Pritam Singh, B. A., 248 Model Town, Ambala City	..
			8. Shri Gian Singh, B.A., B.T., "SHANTINAKTAN" 4-C, Model Town, Phagwara	
			9. Shrimati Prem Kaur, B.A.B.T. 248-Model Town, Ambala City	..
			10. Shri Ramesh Chandra Sharma, 3-Rajas Road, Dehradun	..
			11. Prof. Sardul Singh, E.P. 243 Pakka Bagh, Jullundur City	..
			12. Bhai Amar Singh Vaid, Village Shahabpura, Tehsil Tarn Taran, district Amritsar	
			13. Shri Nand Singh, 598, Model Town, Jullundur City	
			14 Shri Behari Lal, Sanitary Superintendent, Municipal Committee, Jullundur	..
			15. Giani Pritam Singh, 248-Model Town, Ambala, City	

1	2	3	4	5
				Rs.
			16. Shri Balwant Singh Hazooria Book-seller, Adda Hoshiarrpur, Jullundur City	..
			17. Shri Baldev Singh, II Lieut, 233-Polo Ground, Jodhpur	
2.	The Manochal Kalan Co-operative House Building Society, village and post office Manochal Kalan, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar	1. Shri Sampuran Singh, son of Shri Sundar Singh, President, Manochal Kalan.	1. Shri Khanda Singh son of Shri Suchet Singh, village and post office Manochal Kalan	5,300
		2. Shri Teja Singh, son of Shri Sunder Singh, Vice President, village and post office Manochal Kalan	2. Shri Anokh Singh, son of Shri Sundar Singh, village and post office Manochal Kalan	8,000
		3. Shri Hazara Singh son of Shri Kishan Singh, Treasurer, village and post Office Manochal Kalan	3. Shri Kishan Singh, son of Shri Mangal Singh, village and post office Manochal Kalan	8,675
		4. Shri Chain Singh, son of Shri Narain Singh, Committee Member, village and post office Manochal Kalan	4. Shri Sampuran Singh, son of Shri Sundar Singh, village and post office Manochal Kalan	9,780
		5. Shri Surat Singh, son of Shri Sundar Singh, Committee Member, village and post office Manocha Kalan	5. Shri Hazara Singh, son of Shri Kishan Singh village and post office Manochal Kalan	6,000
			6. Shri Mota Singh son of Shri Wasan Singh, village and post office Manochal Kalan	8,200
			7. Shri Teja Singh, son of Shri Surindar Singh, village and post office Manochal Kalan	3,450
			8. Shri Sohan Lal, son of Shri Badri Nath Brahman, village and post office Manochal Kalan	2,900
			9. Shri Chain Singh, son of Shri Narain Singh, village and post office Manochal Kalan	4,500

[Minister for Home and Development]

1	2	3	4	5
				Rs
			10. Shri Sohan Singh, son of Shri Bishan Singh, village and post office Manochal Kalan	5,000
			11. Shri Chanchal Singh, son of Shri Tara Singh village and post office Manochal Kalan	2,100
			12. Shri Pritam Singh, Son of Shri Jinder Singh, village and post office Manochal Kalan	8,000
			13. Shri Bahal Singh, son of Shri Bhan Singh, village and post office Manochal Kalan	7,200
			14. Shri Tara Singh, son of Shri Wasawa Singh, village and post office Manochal Kalan	6.000
			15. Shri Pal Singh, son of Shri Ujagar Singh, village and post office Manochal Kalan	4,000
			16. Shri Joginder Singh, son of Shri Harnam Singh, village and post office Manochal Kalan	1158/25
			17. Shri Naib Singh, son of Harbans Singh, village and post office, Manochal Kalan	3,500
			18. Shri Inder Singh, son of Shri Harnam Singh, village and post office, Manochal Kalan	1,000
			19. Shri Des Raj, son of of Shri Lachhman Dass Brahman, village and post office Manochal Kalan	2,800
			20. Shri Chain Singh, son of Shri Harnam Singh, village and post office Manochal Kalan	5,155
			21. Shri Surat Singh, son of Shri Sundar Singh, village and post office Manochal Kalan	2,700

1	2	3	4	5
				Rs.
			22. Shri Harbans Singh, son of Shri Harnam Singh, village and post office Manochal Kalan	3,500
			23. Shri Ganda Singh, son of Shri Kharak Singh Ghumar, village and post office Manochal Kalan	2,250
			24. Shri Gurpal Singh, son of Shri Karam Singh, village and post office, Manochal Kalan	3,150
			25. Shri Balwant Singh, son of Shri Dalip Singh, village and post office Manochal Kalan	4,500
			26. Shri Ujjagar Singh, son of Shri Nihal Singh, village and post office Manochal Kalan	4,696.25
			27. Shri Mukhtiar Singh son of Shri Achhar Singh, village and post office Manochal Kalan	2,200
			28. Shri Jagir Singh, son of Shri Jermej Singh village and post office Manochal Kalan	4,200
			29. Shri Chanan Singh, son of Shri Sundar Singh, village and post office, Manochal Kalan	2,700
			30. Shri Chuhar Singh, son of Shri Thakar Singh, village and post office, Manochal Kalan	3,500
3.	The Chabhal Kalan Co-operative House Building Society, Ltd. village and post office Chabhal Kalan, Tehsil Tarn Taran district Amritsar	1. Shri Krishan Dev, son of Shri Babu Ram, President, village and post office Chabhal Kalan	1. Shri Sat Dev, son of Ram Datta Mal, village and post office Chabhal Kalan	..

[Minister for Home and Development]

1	2	3	4	5
		2. Shri Bhagwan Dass, son of Shri Shambu Nath, V. President, village and post office, Chabhal Kalan	2. Shri Inder Dev, son of Shri Babu Ram village and post office Chabhal Kalan	..
			3. Shri Labh Singh, son of Shri Atma Singh Rajput, village and post office Chabhal Kalan	
		3. Shri Inder Dev Treasurer, son of Shri Babu Ram, village and post office Chabhal Kalan	4. Shri Chain Singh, son of Shri Atma Singh village and post office Chabhal Kalan	..
		4. Shri Sukhdev Raj, son of Babu Ram Committee member, village and post office Chabhal Kalan	5. Shri Kishan Dev, son of Shri Babu Ram village and post office Chabhal Kalan	..
		5. Shri Piara Lal, son of Shri Saran Dass, Committee member, village and post office, Chabhal Kalan	6. Shri Bhagwan Dass, son of Shri Shambhu Nath, village and post office Chabhal Kalan	..
			7. Shri Inder Dev Sharma son of Shri Ram Narain, village and post office Chabhal Kalan	..
			8. Shri Mukand Lal, son of Shri Chuni Lal, village and post office Chabhal Kalan	..
			9. Shri Mula Singh, son of Shri Harnam Singh, village and post office, Chabhal Kalan	..
			10. Shri Amar Nath, son of Shri Kartar Singh Khatri, village and post office, Chabhal Kalan	..
			11. Shri Sukhdev Raj, son of Shri Babu Ram, village and post office Chabhal Kalan	..
			12. Shri Gian Singh, son of Shri Kartar Singh Khatri, village and post office Chabhal Kalan	..

1	2	3	4
			13. Shri Piara Lal, son of Shri Saran Dass, village and post office Chabhal Kalan ..
			14. Shri Shanti Sarup son of Shri Durga Dass, village and post office Chabhal Kalan ..

Applicability of the Motor Transport Workers Act, 1961 to Pepsu Road Transport Corporation, Patiala

2513. Comrade Babu Singh Master, Comrade Jangir Singh Joga: Will the Minister for Public Works and Welfare with reference to the reply to unstarred question No. 1763 included in the list of Unstarred questions for 18th September, 1964, be pleased to state the details of the advice given by the Legal Remembrancer in regard to the applicability of the provisions of the Motor Transport Workers Act, 1961 to the Transport undertakings in the Public Sector and whether it is being acted upon ?

Chaudhri Rizaq Ram : The Legal Remembrancer, Punjab had advised that in view of the provisions of Section 38 (1)(ii) of the Motor Transport Workers Act, 1961 the said Act was applicable to Government undertakings as well . The advice given by the Legal Remembrancer is being acted upon and the matter regarding implementation of the provisions of the Motor Transport Workers Act, 1961 by the Pepsu Road Transport Corporation and the Punjab Roadways has been taken up with the Transport Department. They have been allowed six weeks time to fully implement the provisions of the Act and the Rules framed thereunder.

Agro-Industrial Corporation

2514. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government has decided to establish an Agro-Industrial Corporation, if so, the details of the decision including the amount to be spent on the proposed Corporation during 1965-66 ;

(b) the details of the functions of the said Corporation and a copy of the Rules and Regulations, if framed, in this connection, be laid on the Table of the House ?

Sardar Darbara Singh (Minister for Home and Development) : (a) Government have decided, in principle, to establish an Agro-Industrial Corporation in the State. Details have not yet been decided. However a sum of Rs 5 lacs has been provided provisionally, during 1965-66.

(b) No.

Amendment in Northern India Canal and Drainage Act, 1873

2515. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether the Government

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

propose to bring forward a legislative measure amending the Northern India Canal and Drainage Act, 1873 so as to remove the difficulties being experienced by the cultivators ?

Chaudhri Rizaq Ram : The Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill, 1965 has already been introduced in the Vidhan Sabha.

ADJOURNMENT MOTION

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, मेरी एक एडजर्नमैंट मोशन है। उस का क्या बना है ?

Mr. Speaker : The hon. Member must have got the intimation that it has not been allowed.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से यह मोशन एडमिट नहीं की गई ?

Mr. Speaker : Please take your seat.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आपने उसे क्यों एडमिट नहीं किया ?

Mr. Speaker : Strike has never been the basis of an Adjournment Motion.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब मैं बैठने के लिये तैयार हूं मगर आप मेरी बात को तो सुनें। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री की सारे पंजाब के अंदर हड़ताल हो रही है। यहां पर सिचुएशन बिल्कुल अपसैट हो जायेगी और खराब हो जायेगी। कनसर्न्ड डिपार्टमैंट ने डैलिबरेटली ऐसी नोटीफिकेशन जारी कर दी है जिस से स्टेट में अनरैस्ट फैल गई है।

Mr. Speaker : Please take your seat.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : पंजाब के अन्दर इस बारे में जलूस निकलेंगे। हज़ारों की संख्या में मज़दूर बेकार हो रहे हैं और आप टैक्नीकल ग्राऊंड पर इस को डिसअलाऊ करते हैं।

Mr. Speaker : One day has been allotted for Industries Demand and this matter can be discussed then.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करनी चाहता हूं कि कनसर्न्ड डिपार्टमैंट ने एक नोटीफिकेशन जारी करके सारे पंजाब में अनरैस्ट फैला दी है। मज़दूर बेकार हो रहे हैं। इसका कोई न कोई हल ढूंढना चाहिये।

Mr. Speaker : Please take your seat. I have already informed the hon. Member that he may send a 'Call Attention Notice'. I will not admit it as an Adjournment Motion.

(इस वक्त हाउस में बहुत शोर था और श्री बलरामजी दास टंडन कुछ बोलने के लिये उठे।)

Mr. Speaker : Order please. Take your seat.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, यह सवाल जरूर पैदा होता है। सारे पंजाब में टैकस्टाइल इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस ठप्प हो रहा है। हजारों की संख्या में मज़दूर बेकार हो रहे हैं। सारा काम पैरेलाइज़ हो रहा है......

श्री अध्यक्ष : जब एक आनरेबल मैम्बर बोल रहा हो तो आप बीच में क्यों खड़े हो गए ? क्या इस तरह का नया प्रोसीजर बना है ? (Why should the hon. Member rise and start speaking while another hon. Member is already in possession of the House? This is against the procedure.)

श्री बलरामजी दास टंडन : अगर यह बात कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। मैं इतनी जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि सारे पंजाब में टैक्सटाइल इंडस्टरीज का बिजनेस ठप्प हो जाएगा लेकिन यहां पर इस मामले को डिसकस नहीं कर सकते हैं....... (शोर)

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, मैं पूछना चाहता हूं कि यह ऐडजर्नमैंट मोशन किस बिना पर डिसअलाऊ कर दी है ?

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, सारे पंजाब में इस इंडस्ट्री का काम खराब हो रहा है। इस की सारी प्रोडक्शन खत्म हो जायेगी। इस के बावजूद भी इस पर डिस्कशन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

Mr. Speaker : This is not proper.

Shri Balramji Dass Tandon : A similar Adjournment Motion is being discussed in the Punjab Legislative Council.

Mr. Speaker : The hon. Member should please take his seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4-3-1965 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੇ ਰੇਟਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਰੇਟਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker : Please do not make a statement.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟੀ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ .... (ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : Please take your seat. now.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਕੰਸਿਡਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋਗੇ ?

Mr. Speaker : I will see to it if it pertains to that matter.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर। स्पीकर साहिब, इस सिचुएशन को जितना लाइटली ग्राप ने लिया है, उतना लाइट यह नहीं है।

Mr. Speaker : The only difficulty is that I am not in the Opposition.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, यह ग्रापोजीशन की बात नहीं है। You are the custodian of the House. यहां पर सारे सूबे में 50 हजार के लगभग मजदूर बेकार हो रहे हैं। कनसर्न्ड डिपार्टमैंट ने जानते हुए इस तरह का नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। वह सरकार को लैट डाऊन करना चाहते हैं......

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, ऐडजर्नमैंट मोशन के लिये रूल्ज बने हुए हैं। रूल्ज के मुताबिक यह है कि रीसैंट ग्रकैंस का मामला हो या सिचुएशन पब्लिक इंट्रैस्ट के कारण खराब हो रही है तो मोशन एडमिट होनी चाहिये। इस केस में भी 50 हजार के लगभग मजदूर बेकार हो रहे हैं तो इस से ज्यादा पब्लिक इंट्रैस्ट का सवाल कौनसा हो सकता है।

Mr. Speaker : I have to interpret the Rules as they are.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर। स्पीकर साहिब, इस ऐडजर्नमैंट मोशन को डिसग्रलाऊ करने से पहले ग्राप सरकार से पूछ लेते कि क्या वह इस बारे में कोई स्टेटमैंट देना चाहते हैं या नहीं ?

Mr. Speaker : A Call Attention Motion on the same subject is coming before the House tomorrow and Government will be asked to make a statement.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, ग्राप इस एडजर्नमेंट मोशन को ऐडमिट करें ग्रौर इस पर डिस्कशन करने की इजाजत दें।

Mr. Speaker : The hon. Member may discuss this matter during the discussion on Industries Demand. One day has been allotted for this Demand.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, जब ग्रापने यह मोशन ऐडमिट नहीं की है तो काल ग्रटैनशन मोशन एडमिट करने की क्या जरूरत है ?

Mr. Speaker : Only to know the position of the Government.

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, जब ग्राप ने यह ऐडजर्नमेंट मोशन रीजैक्ट कर दी है तो यह फिर क्यों इनसिस्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह सरकार इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स के द्वारा रूल कर रही है इस लिये डाक्टर बलदेव प्रकाश के बरखिलाफ डिफैंस ग्राफ इंडिया रूल्ज के ग्रधीन ऐक्शन लिया जाना चाहिए, (हंसी) डाक्टर बलदेव प्रकाश को इस तरह से परेशान करना चाहिए। (हंसी)

Mr. Speaker : The hon. Member should please take his seat.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहिब, रूल्ज़ में प्रोवीज़न है कि जिस मामले में पब्लिक इंट्रैस्ट मालूम होता हो या रीसैंट अर्केंस का मामला हो तो उस के लिये अडजर्नमेंट मोशन या काल एटैंशन मोशन ऐडमिट हो सकती है । लेकिन जब से मैं इस हाउस में चुन कर आया हूं तब से यहां पर एक भी ऐडजर्नमेंट मोशन रूल्ज़ के मुताबिक ऐडमिट नहीं हुई है । अगर कोई मोशन ऐडमिट नहीं करनी है तो मैं समझता हूं कि It becomes a farce

Mr. Speaker : That is my attempt that an Adjournment Motion should not become a farce ; I have not allowed these because they are not proper Adjournment Motions.

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब, आप ही बता दीजिए कि कौन सी एडजर्नमैंट मोशन ठीक हो सकती है ।

Mr. Speaker : It will take many more years before the hon. Member learns.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, इस से बड़ी गम्भीर बात सारे पंजाब में क्या हो सकती है ? यह मामला भी रीसैंट अर्केंस का है और इस में पब्लिक इंट्रैस्ट इनवालव्ड है । हज़ारों की संख्या में मज़दूर बेकार हो रहे हैं । इस प्रकार का नोटीफिकेशन हिन्दुस्तान भर में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में नहीं मिलेगा । मैं समझता हूं कि कनसर्न्ड डिपार्टमैंट ने सरकार को लेट डाऊन करने के लिए इस प्रकार का नोटीफिकेशन जारी किया है ताकि जनता में अनरैस्ट फैले और सरकार बदनाम हो सके । मैं चाहता हूं इस मोशन को ऐडमिट किया जाए ताकि इस पर डिटेल्ज़ में डिस्कशन हो सके । यह मोशन रूल्ज़ के मुताबिक है ।

Mr. Speaker: There is Rule 68 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly pertaining to Adjournment motions and I do expect that the hon. Members must have gone through it closely. Sub-rule (viii) of this Rule says—

> "the motion shall not anticipate matter which has been previously appointed for consideration in determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be had by the Sqeaker to the probability of the matter anticipted being brought before the Assembly within a reasonable time;"

Time for discussion on the demand for Industries has already been fixed. This matter can be discussed then.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, जो कुछ हो रहा है हम उस सिचुएशन को डिस्कस करना चाहते हैं ।

Mr. Speaker : Please take your seat.

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : There is a Call Attention Notice (No. 18) given by Sardar Gurnam Singh

Sardar Gurnam Singh : Sir, I beg to draw the attention of the Punjab Government to an unauthorised construction contravening the provision of Punjab Capital (Development and Regulation) Building Rules, 1952 of four rooms on a plot of land situate in Street z Sector 8-C, Chandigarh and that too in the immediate vicinity of a Sikh Gurdwara with the object of disturbing the Sikh Congregation and actually disturbing it when they are saying their daily prayers in their shrine. This Act is most likely to disturb public peace.

This is a matter of urgent public importance and requires immediate attention of the Punjab Government.

Mr. Speaker : This Call Attention Motion, No. 18 is admitted. The Government may please make a statement about it.

Chief Parliamentary Secretary : We will make a statement.

Mr. Speaker : The next Call Attention Motion (No. 19) has been given notice of by Sardar Ajaib Singh Sandhu.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the orders of termination of services of about one hundred Surveillance Inspectors of the Malaria Department of the Punjab Government who have put in more than three years' service. These Surveillance Inspectors should have been absorbed in some other vacancies or their services should not have been terminated under the present circumstances of daily rise in cost of living.

Mr. Speaker : This is admitted. The Government may please make a statement about it.

Next Call Attention Motion (No. 20) is by Shri Om Parkash Agnihotri.

Shri Om Parkash Agnihotri : Sir, I beg to draw the attention of theMinister concerned towards a serious accident that took place with the bursting of a tyre of a Punjab Roadways bus on 18th March, 1965 at a distance of 28 miles from Jullundur near Mehta Town on the Jullundur-Batala route as a result of which three passengers including Bhagat Ram Kishan, Municipal Commissioner, Jullundur were killed. Twenty-five passengers received serious injuries and the driver named Sardar Charan Singh is lying unconscious. The lives of the injured persons are not out of danger as yet. This accident has occurred due to the mis-management, use of inferior quality of material and for want of proper and timely checking of the vehicles by the management. The Punjab National Roadways Worker's Union have many a time made oral and written complaints to the Transport Minister, Punjab and P.T.C., Punjab, that break downs and accidents of the vehicles of the Punjab Roadways take place due to the use of inferior quality of material. But the P.T.C. has not paid any heed to it. This accident is due to criminal negligence of the Transport Department and the Punjab Government. A judicial inquiry about the accident be held immediately and a Judge of the High Court be appointed to hold this inquiry and compensation be paid to the successors of the victims and the injured persons.

In view of the public importance of this Call Attention Notice the matter may be discussed in the House.

Mr. Speaker : This is also admitted. The Government may please make a statement.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I rise to make a statement about it.

The accident, which occurred on the 18th March, 1965, at 11.45 A.M. on Jullundur-Qadian road in which bus No. PNQ-46 toppled over, was investigated by the Police and was declared accidental. The driver was, therefore, not prosecuted.

Shri Sita Ram Budhiraja, Deputy Transport Controller (Technical and Commercial), who has over 20 years experience in the transport operation was deputed to inspect the site of occurrence. He, in his findings, states that there may not have been any casualty in respect of this accident if the driver of the bus had not been encountered with a cyclist, who had to be saved at the cost of the safety of the bus. He further states that the complexion of the movements of the bus was completely changed by the emergence of the cyclist. He added that if the cyclist had not been there, there were vast fields on the right and the vehicle would have glided across the fields and stopped anywhere without any topple over. He has also agreed with the Police findings that the incident was accidental.

The tyre, which got burst was of Firestone—one of the premier four tyre manufacturing companies. The statement that the material was of inferior quality is not, therefore, correct. No mis-management was involved in this case of tyre failure. The portion of the road between Bias and Batala is wavy and it may have been due to imbalance that there was over-load on the front tyre leading to this failure. The tyre, which was burst, was inspected by this officer, who found that it had original tread over it and has only done 30,000 miles against the normal performance of 40,000—45,000 miles.

The judicial enquiry will not help in case of such accidental nature.

The question of compensation is, however, being considered by Government separately.

The latest reports received from Jullundur on telephone, indicate that those injured and now in the hospital including the driver, are out of danger.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : On a point of Order, Sir....

Mr. Speaker : There can be no discussion on the statement.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : On a point of order, Sir. ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਡੀਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇ ਲੈਂਡ ਬਸਾਂ ਵਿਚ 12 ਪਲਾਈ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਲੰਧਰ ਡੀਪੋ ਵਾਲੇ 9 ਪਲਾਈ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 9 ਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : I pass on your expert advice to the Government.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : On a point of order, Sir. ਇਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

Mr. Speaker : Arrest of a Member does not form the basis of a privilege.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ?

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

Mr. Speaker : If any hon. Member is arrested or detained under the provisions of law, that is not a matter of privilege.

Next Call Attention Motion (No. 21) is by Sardar Ajaib Singh Sandhu.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the destruction and damages to crops caused by the hailstorm this week in the State and measures taken or to be taken by the Government to help the people affected.

Mr. Speaker : This is admitted. The Government may please make a statement about it.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : On a point of Order, Sir .....

Mr. Speaker : Does the hon. Member want to raise a point of order on my ruling ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ।

Mr. Speaker : Please take your seat.

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿਦੰਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜ ਡੇਢ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਇਤਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। Government is fully aware of it. ਇਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੀਸੋਰਸਿਜ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰੀਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : On a point of order, Sir. ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਰੈਵਿਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ । ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਪਸ ਨੂੰ ਡੈਮਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਔਰ ਜੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। (The difficulty is that if the statement has been made immediately, the hon. Member does not feel satisfied and if the same is made a little later it is complained as to why it has not been made earlier. It will be better if the hon. Minister consults the hon. Member, Sardar Ajaib Singh before making the statement.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ।

I am fully aware of my responsibilities. Whatever I say I say with a full sense of responsibility and for that definitely time is required.

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ (The hon. Member may discuss this matter during the discussion of the reports pertaining to the Electricity Board.)

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ: ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁਕਆ ਹਾਂ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁਕਆ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈਂ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼: on a point of order, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਉਸ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰਿਪ੍ਰਿਜ਼ੇਂਟੇਟਿਵ ਲਏ ਜਾਣ।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਵਾਯੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ....

Mr. Speaker : It is also a violation that you are making a speech after I have disallowed the motion.

Statements Laid on the Table of the House

Chief Parliamenary Secretary : Sir I beg to lay the following statements on the Table of the House.

*(1) Statement in respect of Call Attention Notice No. 17 moved by Sarvshri Om Parkash Agnihotri and Net Ram, M.L.As. regarding the demands of Sweepers, Municipal Committee, Phagwara.

---

*(i) Call Attention Notice No. 17 appears in PVS Debate, Volume I, No. 19, dated 16th March, 1965.

[Chief Parliamentary Secretary]

**(2) Statement in respect of Call Attention Notice No. 13 moved by Comrade Shamsher Singh Josh, M.L.A., in the Budget Session, 1965, of the Punjab Vidhan Sabha regarding the refusal of Commissioner, Jullundur Division to sanction supplementary Budget of the Municipal Committee, Jullundur.

**(3) Statement in respect of Call Attention Notice No. 11 moved by Sardar Tara Singh Lyallpuri regarding the posting of police near Chowk Baba Atal Sahib within the precincts of Gurdwara, Amritsar.

**(4) Statement in respect of Call Attention Notice No. 12 moved by Chaudhri Net Ram regarding the admission of Harijan students in M.Sc. (Agriculture) of the Agriculture University, Ludhiana.

***(5) Statement in respect of Call Attention Notice No. 16 moved by Shri Gian Chand Totu regarding the imposition of Goods Tax in the case of vehicles plying on hilly roads.

Statement in respect of Call Attention Notice No. 17 moved by Sarvshri Om Parkash Agnihotri and Net Ram, M.L.As. regarding the demands of Sweepers, Municipal Committee, Phagwara.

The Municipal Sweeper Union (Regd.), Phagwara served a demand notice on the Executive Officer, Municipal Committee, Phagwara on 6th March, 1965 requesting therein that the demands (ten in number) contained in the Demand Notice may be accepted within 7 days of the receipt of notice. The Municipal Committee, Phagwara considered the demands of Sweepers Union in its emergent meeting held on 10th March, 1965 and resolved that it was not possible for the Committee to accede to the demands of the Union except that the demand regarding the increase of wages would be considered on receipt of Government orders in this connection. The Executive Officer, accordingly, informed the sweepers union on 11th March, 1965.

2. The Deputy Commissioner, Kapurthala discussed the matter with the President and members of Municipal Committee and the representatives of Sweepers Union. He advised the Committee to consider the demand for increase in wages on receipt of Government Orders and also provide brooms etc. The Deputy Commissioner, also advised the representatives of the Sweepers Union that they should quote the instances where maternity leave benefit has been allowed by other Municipalities. The Deputy Commissioner, Kapurthala further advised the Union not to resort to strike.

3. The Conciliation Officer of the Labour Department informed the Sweepers Union on 12th March, 1965 that the Conciliation proceedings would be taken at Phagwara on 19th March, 1965 and requested that parties should attend with the relevant record. But the Union instead of waiting for the meeting on 19th March, 1965 and have the demands amicably settled resorted to strike on 14th March, 1965. The Conciliation Officer heard both the parties on 19th March, and asked them to meet him on 22nd March, 1965 at Jullundur.

4. Shri Sagli Ram, President, Sweepers Union started the fast on the 14th. It is reported that one man remains on 24 hours fast. No Sweeper of Municipal Committee has so far gone on fast. The Sweepers Union did not send any intimation that they will go on fast to any local officer or the Committee.

Notes :—

**(ii) Call Attention Notices Nos. 13, 11 and 12 appear in PVS Debate Volume I, No. 14, dated 10th March, 1965.

***(iii) Call Attention Notice No. 16 appears in PVS Debate Volume I, No. 17, dated 12th March, 1965.

About 40 Sweepers gave in writing to the Executive Officer that they had withdrawn their support to the demand notice, as demand No. 10 pertaining to victimization of Shri Joginder Paul had been added without their approval. The Municipal Committee has categorically denied the allegation of any discrimination or victimization having ever been made.

6. The financial position of the Municipal Committee, Phagwara is too lean to meet the demands of Union. The Committee is spending more than half of the total expenditure of establishment on conservancy staff. Despite this the Committee has promised to consider the demand regarding the enhancement of emoluments. In view of this it was not desirable for the Sweepers' Union to resort to strike particularly when the Sweepers' Union was informed by the Conciliation Officer on 12th March that the Conciliation proceedings would be taken on 19th March, 1965. The Union should have waited uptill 19th March, 1965.

As regards the increase in the emoluments of employees it is stated that the Municipal Committees are autonomous bodies and are free to fix the salaries of their employees according to their respective financial position and the State Government can only advise and not force them to adopt a certain scale of pay in respect of its employees. The Committee will, however, be advised to effect economy and tap new resources of income to meet the genuine demands of Sweepers.

Statement in respect of Call Attention Notice No. 13 moved by Comrade Shamsher Singh Josh, M.L.A., in the Budget Session, 1965, of the Punjab Vidhan Sabha regarding the refusal of Commissioner, Jullundur Division to sanction Supplementary Budget of the Municipal Committee, Jullundur.

The revised Budget, 1964-65 of the Municipal Committee, Jullundur, was received by the Deputy Commissioner, Jullundur on 7th December, 1964. After scrutiny and examination, he considered it necessary to find out whether the amount of Rs 2,72,000 on account of payment of instalment of flood channel could be deposited before 31st March, 1965. He made a reference in this connection to the Executive Engineer, Drainage Division, Jullundur, and asked him to send reply by return of post. Subsequently, the Deputy Commissioner, Jullundur, reminded the Executive Engineer on telephone and also in writing on 3rd February, 1965. The Executive Engineer, Drainage Division, Jullundur intimated Deputy Commissioner, Jullundur, on 11th February, 1965 that the amount could be deposited with his Department. The Deputy Commissioner, Jullundur, then forwarded the revised Budget to the Commissioner, Jullundur Division on 12th February, 1965 with the recommendations that it might be sanctioned. The Commissioner pointed out the following two objections on the revised Budget to the Deputy Commissioner and the Municipal Committee :—

(i) The Municipal Committee had not indicated the Heads from which the proposed additional grant of Rs 4,82,722 was to be transferred for re-appropriation.

(ii) No explanatory note was furnished to indicate as to why the original works were not shown in the original Budget of the year under report and why necessity was felt of making provision in its revised Budget at the end of November, 1964, when it was the time for preparation of next year's Budget, i.e., 1965-66.

2. The Executive Officer, Municipal Committee, Jullundur,,—*vide* his communication, dated 27th February, 1965 explained the various Heads from which it was proposed to draw out the additional expenditure to meet the expenses of the new items of various original works, etc. which also included a contribution of Rs 25,000 to the Desh Bhagat Memorial Hall. The revised Budget of the Municipal Committee, Jullundur has since been sanctioned by the Commissioner, Jullundur Division, with the exception of one item relating to the purchase of one jeep which has been advised to be deferred to the next financial year.

PRABODH CHANDRA,
Education and Local Government Minister.

Dated, Chandigarh, the 23rd March, 1965.

Statement in respect of Call Attention Notice No. 11 moved by Sardar Tara Singh Lyallpuri, M. L. A., regarding the posting of Police near Chowk Baba Atal Sahib within the precincts of Gurdwara, Amritsar.

On the 29th July, 1964, there was a clash between the two rival groups of Master Tara Singh and Sant Fateh Singh over the possession of the S.A. Dal building at Amrit-

[Chief Parliamentary Secretary]

sar in occupation by the Master group. A case FIR No. 259, dated 29th July, 1964 was registered at Police Station Kotwali, Amritsar in this connection under section 380/342/353/145/149 IPC, on the report of S. Atma Singh, General Secretary of the S.A. Dal (Master Tara Singh group). In view of this clash and the persistent strained relations between the two groups, a Police guard usually patrols the area and bazars in the neighbourhood of the Gurdwara to maintain public peace. It is incorrect that Police has been posted near Chowk Baba Atal Sahib within the prec inctsof Gurdwara since long whereby religious feelings of Sikhs are being injured. This guard has never entered the precincts of the Gurdwara.

Statement in respect of Call Attention Notice No. 12 moved by Chaudhri Net Ram, M.L.A. regarding the admission of Harijan students in the M.Sc. (Agriculture) of the Agricultural University, Ludhiana.

The facts are as under :—

The minimum qualifications prescribed for admission to the M.Sc. (Agri.) Programme in this University was IInd Class B.Sc. (Agri.) with 50 per cent marks in the aggregate.

2. This University has framed a policy to admit students to M.Sc. (Agri.) course as follows:—

After deducting 20 seats reserved for candidates from States other than Punjab and 20 per cent seats for in service candidates of the Punjab Agricultural University, from the total number of seats available (133), reservation was made on the following basis for different categories of students from the balance of the seats available :—

(i) Reserved for Scheduled Castes/Tribes	.. 20 per cent
(ii) Reserved for Backward Classes	.. 2 per cent
(iii) Reserved for Backward Areas	.. 10 per cent
(iv) Reserved for outstanding sportsmen	.. 2 per cent
(v) Open competition	.. Balance

3. There were only 4 applicants belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Out of these 4, only 1 fulfilled the minimum qualifications for admission and he was admitted accordingly. The remaining 3 were third divisioners in B.Sc. (Agri.) and could not be admitted.

4. The seats reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes category were transferred to backward classes candidates and the seats left vacant after admitting all eligible backward-classes candidates were then transferred to candidates from backward areas. One candidate belonging to Scheduled Castes, 14 candidates belonging to backward classes and 9 candidates belonging to backward areas were admitted to the M.Sc. (Agri.) Programme in the year 1964-65.

Statement in respect of Call Attention Notice (No. 16) moved by Shri Gian Chand regarding imposition of Goods Tax in the case of Vehicles plying on hilly roads.

When the passengers and Goods Taxation Act was enacted in 1952, it stipulated the levy of passengers tax and goods tax at 1/12 of fare and freight respectively. With the passage of time this rate of 1/12 was raised to 1/4 in the case of plains and 1/6 in the case of hills. However, the owners of public carriers repres ented against this mode of tax and pressed the Government for accepting some composition fee in lieu thereof. After a meeting with the representatives of the association the Government decided to levy composition fee in lieu of the tax on the freight in the year 1952, and the Act was accordingly amended. Thus it is expressly at the request of

the owners of public carriers that instead of the existing normal rate of 1/4 or 1/6 of the freight they are charged composition fee which in fact, is much less than the rate prescribed by the Act.

2. It was also agreed to by the representatives of the association that the composition fee paid by the owners of public carriers plying in the hills be 50 per cent higher than in the plains and consequently, in 1952 itself, the composition fee for the plains was fixed at Rs 360/- per annum while that for vehicles plying in the hills it was Rs 540/- per annum. The composition fee for vehicles plying in the hills was higher by 50 per cent because of higher freight charges in the hills. The composition fee has been enhanced from time to time and the prevailing rates are Rs 810/- for public carriers plying in the plains and Rs 1,215/- for those plying in the hills. It will be seen that there is no emergency in the matter since this difference of 50 per cent has existed since the very inception of the composition fee, i.e. since 1952.

3. However, it may be mentioned that following the receipt of certain representations from the public carriers' associations in the hills, the prosposal for bringing the composition fee on public carriers in the hills at par with those in the plains, is under consideration of the Government.

Personal Explanation by Shri Mohan Lal

Shri Mohan Lal : Sir, I rise on a point of personal explanation Shri Prabodh Chandra in his speech delivered in the house on 15th March, 1965 made a large number of baseless allegations against me ....

श्री मंगल सैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, आपने शुरू से ही हाउस को कानून के मुताबिक चलाया है और इसे कानून के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी इस बात पर रूलिंग चाहता हूं कि आज से नौ दिन पहिले जो एजुकेशन मिनिस्टर साहिब ने कहा था उसके बारे में आज इनको परसनल ऐक्स्प्लेनेशन की इजाजत क्यों दी जा रही है। क्या इतने दिनों के बाद वह अपनी सफाई दे सकते हैं?

Mr. Speaker : He wanted to see the proceedings before giving the explanation.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या इसमें कोई टाईम लिमिट नहीं है?

Mr. Speaker : Within a reasonable time.

Dr. Baldev Parkash : There should be some definite time limit. If the allegations are levelled in this session can personal explanation be given in the next session ?

Mr. Speaker : No, he wanted to see the proceedings.

श्री मोहन लाल : स्पीकर साहिब, इस सिलसिले में यह वाजेह कर देना मुनासिब होगा कि मैंने जवाब देने पहिले उन की स्पीच की कापी लेने के लिए स्पीकर साहिब को ऐपलाई किया था क्योंकि मैं चाहता था कि उन की स्पीच का जो रिकार्डिड वर्शन है वह मेरे पास आए और उसके मुताबिक मैं अपना ऐक्सप्लेनेशन दूं। जिस दिन वह मुझे मिला उसके बाद आफ डेज़ आ गए। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। The charges levelled against me are so wide and wild that it may not be feasible for me in this explanation to deal with everything said by him.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : on a point of order, sir, ਕੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Yes. It is optional.

Shri Mohan Lal : Some of the allegations made by him were gerneral and some of them specific. Whereas I repudiate vehemently the allegations made in general, I would like to explain the specific allegations made as follows:—

(1) To start with he made a reference to my' association with the Congress Organisation as Pradesh Returning Officer. It is an organisational affair irrelevant in this debate and it would not be proper for me to go into any detailed reply. All I wish to say is that his insinuation and allegations are absolutely baseless and incorrect.

(2) He alleged that in the last General Elections I had collected a sum of Rupees seven lacs or so. If his reference was to the collections made by the Punjab Pradesh Congress Committee for the General Elections, I have to concede that I did associate myself with the collections made by the President of the Pradesh Congress Committee and the Chief Minister. Of course, I am not in a position to give the exact amount collected. If his insinuation is towards my personal election, I repudiate it with all the vehemence at my command. He is aware of the fact that so far as my election from Batala Constituency was concerned, it was mostly managed by the City Congress Committee, Batala through a Committee appointed for this purpose in which some of the close associate of Shri Prabodh Chandra were also associated. The election in campaign in Batala City and its suburbs was mainly organised by the City Congress Committee and the funds for this purpose were collected and disbursed by them. I had no hand in its collection or disbursement. It is absolutely a false accusation that the Northern India Engineering Association or the Batala Factories Association made any contribution to me direct. Whatever they contributed was to the City Congress Committee.

Sardar Lachhman Singh Gill : What about indirect. ?

Shri Mohan Lal : It was alleged that in the year 1963 when I held the portfolio of Industries, a quota of 156 tons of pig iron was given to Shri K.R. Sarin and other quotas were similarly given and that some of them were sold in the black market. The portfolio of Industries was never in my charge after the 1962 General Elections and I am unaware of any quotas sanctioned or being sold in the black market. It is a blatant untruth that I was associated in either the sanction or the disposal of any quota.

(4) It was further alleged by Shri Prabodh Chandra that I have been telling some officers in Gurdaspur District that the Ram Kishan Ministry is going to be finished within a few months. It is a pure concoction. It is also incorrect that I ever rang up the Superintendent of Police that I feared any danger to my life. It is also incorrect that when the Congress President visited Batala, a gathering of 40,000 people refused to hear me. It was only a small number of people, mostly labourers, who in accordance with a pre-planned scheme prepared by some close associates of Shri Prabodh Chandra were made to sit in certain strategic points in the gathering who

created some disturbance. It was all a managed and a pre-planned show.

(5) It is an absolutely false accusation that the pamphlet which was published at Faridabad about the alleged act of nepotism by Shri Prabodh Chandra in nominating his son-in-law to the Notified Area Committee, Faridabad, was done by anybody at my instance. It was published by one Pt. Amar Nath, Convener, Citizen Council, New Industrial Town, Faridabad and was received by me through dak. In fact, I also came to know of the said nomination through this pamphlet and the Gazette Notification. I have nothing to do with Shri Amar Nath.

(6) It is entirely incorrect that I sanctioned reduction in octroi on the imported raw-material in the Faridabad township to benefit any individual or individuals. Whatever sanction I gave was after full consideration and in the larger interest of the Industry in this important growing industrial town.

(7) It is reckless charge to suggest that I have spent rupees 1½ lakhs on building a house in Chandigarh. I purchased the plot in Chandigarh in the very first allotment in the year 1952-53. The amount that I have spent on the construction of this house is about Rs 61,000/- out of which about one-third is loan amount. The house has been built on a two kanal plot in Sector 18-D.

(8) In regard to the allegation about my nephew, Beant Lal, being a co-sharer in any liquor contract , I have to draw your attention to the proceedings of the Punjab Vidhan Sabha, dated 31st March, 1964. On a similar reference by Comrade Ram Chandra, then, I had informed the House that I had written to my then colleague-Minister-in-charge for Excise and Taxation on 11th March, 1964 that the offer of Beant Lal may not be accepted I had given specific reasons that even though I was separate from my brother for over 25 years, nevertheless, acceptance of such offer from a nephew of mine will invite unnecessary criticism and political capital might be made out of it. It is worthy of note that Shri Prabodh Chandra who now makes this allegation repeatedly raised it as a point of Order then that my writing this letter was an interference in the normal working of the Government. He also said that if I had not written this letter, my nephew would have got this contract. He further said that my writing was reprehensible when charges are made that Ministers are interfering in the administration. One fails to understand how does it lie in his mouth now to raise the present objection. All I know is that Shri Beant Lal was not given the contract then. I am unaware of his subsequent association with the contract. In fact, there could not be direct or indirect responsibility upon me for his any such-association even if it happened.

(9) As regards the allegation that I got my nephew Beant Lal elected as President of the Sugar Syndicate at Batala, it is again a baseless allegation. This objection was also taken in the Vidhan Sabha in the last year's debate on 'No confidence motion' and I would refer to the reply that I gave on 30th March, 1964. I had categorically stated then that I or the

[Shri Mohan Lal]

Government had nothing to do with this election. It is a non-Government private syndicate of which all the licencee were members. ....

Shri Jagan Nath : On a point of Order, Sir.

Mr. Speaker : Let the hon. Member first finish.

Shri Jagan Nath : I have risen on a point of Order.

स्पीकर साहब, मैं इस बारे में आप की रूलिंग चाहता हूं कि अब पंडित मोहन लाल यहां अपने बारे में आप ही कलीन चिट ले रहे हैं हालांकि इन के खिलाफ दास कमिशन ने बहुत कुछ लिखा है तो क्या यह ऐसा कर सकते हैं ?

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat.

Shri Mohan Lal : In their meeting they made unanimous election of office-bearers. Government had nothing to do with it. I took absolutely no interest in the election and was not even aware of it till this question was raised in the Vidhan Sabha.

(10) In regard to the insinuation that I had made reference to the deceased son of Shri Prabodh Chandra about the acquisition of two buses, I have been misunderstood by him. I only referred to the statement of his assets a copy of which has been laid on the Table of the House, by Shri Hardwari Lal wherein Shri Prabodh Chandra has shown the two buses as his own property under the heading 'moveable owned by himself'. Evidently, the inference that could be drawn from the property statement is that the buses belong to Shri Prabodh Chandra even though they were in the name of his son.

(11) I have been amazed to hear from him in his speech that I made a mis-statement about his sanctioned claim of Rs 24,000. I had only quoted his speech dated 3rd March, 1965 which is clear and unambiguous.........

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਹਾਉਸ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਥੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਇਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਕੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਉਸ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

Mr. Speaker : Order, please.

Shri Mohan Lal : In this speech he had clearly stated that he had invested in the Adarsh Foundry a sum of Rs 24,000 which the Government had sanctioned by way of his claims. I have made a separate request to you, Mr. Speaker, that this statement which is clear, definite and unambiguous should not be permitted to be deleted under the guise of the correction of his speech.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੱਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat. There should be some limit on the points of Order.

Shri Mohan Lal: (12) It is a pure concoction and mischievous accusation that I did any work Benami in the name of my nephew or that I ever got him any quota or permit. In regard to a brick-kiln licence obtained by one of my nephews at Gurdaspur, all I know is that the District authorities some years back granted him one licence. I have no knowledge about the rest and have no responsibility for any of his deeds.

(13) He has without name stated that by by-passing a syndicate, I had granted a licence to somebody who earned rupees three lakhs. It is again a baseless concoction. A similar reckless charge has been made that a fund was raised for my interest. Nothing could be more baseless and mischievous.

(14) He made certain graceless references to my heritage. I am proud to have been born in a very small village and in an unknown family. I am proud of the fact that I am a self-made man. If it is an accusation in a democratic set-up, I plead, I plead quilty to it. My slate is clean. I have been sending, when a Minister, a statement of my assets to the Congress President.

(15) It is also incorrect that after the Election Petition was filed against me, I had made donations from my discretionary fund towards 20 institutions. It could be verified from the Government record.

There are some other general, vague and wild allegations made which I repudiate with full vehemence. He has made all this in a most irresponsible manner and with a purpose.

श्री मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहब, आप जो इस अगस्त हाउस में प्रिजाईड कर रहे हैं, मैं आप को इस मामला पर रूलिंग चाहता हूं कि यह जो पुराने वज़ीर अपने पर लगे इलजामों के जवाब में अपने आप को क्लीन स्लेट दे रहे हैं हालांकि हिन्दुस्तान की सब से बड़ी अदालत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में इन्हें गुनाहगार करार दिया हुआ है, क्या यह इस तरह से अपने आप को क्लीन चिट दे कर उस कमिशन के फैसले को यहां चुनौती दे सकते हैं ?

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat.

(*Interruptions*)

Every honourable Member has equal rights under the Rules to make his position clear. The question is that if there are allegations of a personal nature against any honourable Member, he has the right, under the Rules, to give his own personal explanation. The allegations and personal explanations are both before the House. It is now for the House to draw any conclusions about them. I think, it will be better if there is no further discussion on this matter.

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब मैं यह जानना चाहता हूं कि पंडित मोहन लाल जी पर जो चौधरी देवी लाल जी ने इल्ज़ाम लगाया था और मेज पर बोरी रखी थी, वह बोरी तो यह खा गए....... (विघ्न)

Mr. Speaker : Please take your seat.

कामरेड राम प्यारा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं आप की रूलिंग चाहता हूं कि अगर किसी आनरेबल मैम्बर के खिलाफ़ इल्ज़ाम लगे तो कितने दिन तक उस को ऐक्सपलेनेशन देने का हक है ?

Mr. Speaker : Within reasonable time.

कामरेड राम प्यारा : रीज़नेबल टाइम की कोई लिमिट भी होनी चाहिए। मैं आप का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि मैं ने इस हाउस में कहा था कि (विघ्न) सरदार प्यारा सिंह पर इल्ज़ाम लगाया था (विघ्न) करनाल में खा गए हैं। मैं ने इल्ज़ाम लगाया था कि 12 लाख का जो माल खरीदा गया था (विघ्न) उस में कै ों फैमिली . .

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। क्या आज एक और ऐलीगेशन लगाना चाहते हैं? (विघ्न) (Does the hon. Member want to level another allegation to day?) (*Interruptions*)

कामरेड राम प्यारा : I am repeating (विघ्न)।

सरदार लछमन सिंह गिल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : यह प्रापर नहीं लगता कि इस तरह से, फ्रंट बैंचिज़ से प्वायंटस आएं। (This does not look proper that such points be raised by the front benches.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੇਂ-ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣ।

Mr. Speaker : Please take your seat.

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : जनाबेआली, इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता मगर मैं देख रहा हूं कि पंडित जी ने अपना ऐक्सपलेनेशन देते हुए कुछ लफज़ इस्तेमाल किए हैं जैसे कि mischievous, baseless, false, etc. They were absolutely uncalled for. आप ने मुनासिब समझा और उन को इन की इजाज़त दी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन हाउस का काफी वक्त इस बात में लग गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी या पंडित जी की वजह से हाउस का वक्त ज़ाया हो, पंजाब की पब्लिक लाइफ गंदी हो। मगर यह तो बात है कि हम दोनों में से एक तो मुजरिम ज़रूर है (आपोज़ीशन की तरफ से तालियां) अगर मैं ने झूठ बोला है तो मुझे मिनिस्टर बनने या विधान सभा के मैम्बर बनने का हक नहीं है। मैं ने सरदार गुरनाम सिंह जी से बात की थी कि मैं आप की बात को मानता हूं, आप की सजैशन को वैलकम करता हूं किसी आदमी को या किसी कमेटी को मुकर्रर करने बारे-चाहे वह आपोज़ीशन में से हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो। मैं ने तो अभी चार्जिज़ लगाए ही नहीं। अपनी डिफैंस में ही कुछ कहा है। मैं बहुत कुछ और कह सकता हूं........

श्री अध्यक्ष : तो आज आप और चार्जिज़ लगाना चाहते हैं? (Does the hon. Minister want to level more charges?)

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : नहीं लगाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने एक्स्पलेनेशन दिया और उन्होंने जो लफज़ कहे उस का आप ने जवाब दे दिया। (The Member gave his personal explanation. The Minister has also given his reply.)

Minister for Education and Local Government : I will not say anything more on this subject, except that there is the highest authority such as the Vigilance Commission in Punjab, and let the honourable Member put his case before that and I will also do the same. Let that body decide as to who is unworthy of public life.

डा० बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, हाउस के सामने दो कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमैंट्स आई हैं, इस बात के लिये इस हाउस के फोरम को ऐक्सपलायट किया गया है। मैं दरखास्त करूंगा कि यह मैटर प्रिविलिजिज़ कमेटी को भेजा जाए ताकि यह पता लग सके कि कौन ठीक और कौन गलत है सारी बात का फैसला हो जाए।

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब यह हाउस सारे पंजाब के लिये है अकेले गुरदासपुर जिले के लिये नहीं है, दो आदमियों के लिये नहीं है। ऐलीगेशन्ज़ आज नहीं लगाई गई हैं, यह परसनल ऐक्सपलेनेशन अब से डेढ़ साल पहले आना चाहिए था दोनों तरफ से। हाउस दोनों को मान चुका है कि दोनों सच्चे हैं। किसी को झूठा नहीं कहते मगर हाउस को इस तरह से सफाई देने के लिये इस्तेमाल किया गया है। मैं याद कराना चाहता हूं कि 13 जुलाई, 1963 को हम ने राष्ट्रपति के सामने मैमोरैंडम रखा था और फैसला 11 जून सन 1964 को हुआ था। इन का तो उससे भी बड़ा केस है। प्रिविलिजज़ कमेटी इसे क्या देखेगी जिस की कि आठ सफे की रिपोर्ट होती है जैसा कि हम ने इस की अभी तीन रिपोर्टस देखी हैं। 88 सफे की तो ऐलीगेशन्ज़ हो हैं। इस लिये कहता हूं कि यहां पर टाइम वेस्ट न किया जाए बल्कि कमीशन गुरदासपुर का फैसला करे। क्या इस तरह से हाउस का टाइम जाया किया जा सकता है इस बारे में आप की रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहिब, आप ने बड़ा अच्छा प्वायंट आफ आर्डर रेज़ किया है कि हाउस में ऐलीगेशज़ और काउंटर ऐलीगेशज़ नहीं लगनी चाहिए। आज इर्रीगेशन की बहस को वक्त कम मिलेगा, बाकी कल मिलेगा। मैंने यहां पर अपनी राए जाहिर की थी कि बेहतर हो कि हम इस हाउस के मैम्बरों के लिए कोई कोड आफ कंडक्ट हो। मैं ने अर्ज़ किया था कि मैं आपोजीशन ग्रुप्स के लीडरों से भी और लीडर आफ दी हाउस से भी बात चीत करूंगा। मैं सब से रिक्वैस्ट करूंगा कि यहां पर ऐसी कोई मोशन आए कि हम कोई कमेटी बनाएं जो मैम्बरान के लिये कोड आफ कंडक्ट बनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी कोइ मोशन आयगी। मालूम नहीं यह कल या परसों आ जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसी मोशन आए कि इस बारे में हाउस की कोई कमेटी बनाइ जाए जो इस एलीगेशन्ज़ और काउंटर ऐलीगेशन्ज़ के मामले पर ध्यान दे और कोई कोड बनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इस बारे में कोई पोजीशन लेगा। (The hon. Member has raised a good point that charges and counter charges should not be levelled in the House. Today, the House will get less

[Mr Speaker]

time for discussing the Demand for Irrigation. However more time will be given tomorrow. Sometime ago I had opined that we should frame some code of couduct for the Members of this House. I had stated that I would consult the varions party leaders in the House and request them to give notice of a motion to constitute some Committee which may be entrusted the work of framing a code of conduct for the Members. I hope such a motion will come within a couple of days. I want such a Committee to carefully go into the matter of making allegations and counter allgeations and frame a code of conduct. I think the House will take some position with regard to this matter.)

बाबू बचन सिंह: ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर। स्पीकर साहिब, इस हाउस के दो मैम्बरान के खिलाफ करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगे हैं ग्रौर हिन्दोस्तान में चर्चा है कि इस वक्त सारे मुल्क में करप्शन फैली हुई है। ग्रगर एक मिनिस्टर जो पहले रह चुके हों उन के खिलाफ ग्रौर एक जो ग्रब मिनिस्टर हों उन के खिलाफ़ इस हाउस में जिस की कार्यवाही ग्रोपन टू दी पब्लिक है चार्जिज लगें ग्रौर उस पर भी उन की इन्क्वायरी न हो तो मेरे ख्याल में हम किसी मुलाजम के खिलाफ इन्क्वायरी करने में हकबजानब हो नहीं सकते। मैं ग्राप की रूलिंग इस सिलसिले में चाहता हूं कोई कमेटी मुकर्र करने के मुताल्लिक न कि कोड ग्राफ कन्डक्ट के सिलसिले में कि क्या ग्राप इस बात के लिये तैयार होंगे कि एक कमेटी बनाई जाए जो साबक होम मिनिस्टर ग्रौर मौजूदा ऐजूकेशन मिनिस्टर के खिलाफ़ इन्क्वायरी करे ग्रौर उन के चार्जिज के बारे में ग्रपना फैसला बताए, ?

Mr. Speaker : It is not for me to decide the matter. It is for the House to take a decision about it.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : स्पीकर साहिब, बाबू बचन सिंह जी ने जो तजवीज़ रखी है कि हाउस कोई इन्क्वायरी कमेटी बैठाए, मेरे ख्याल में ऐसी कमेटी न तो पहले कभी बैठी है ग्रौर न शायद ऐसा करना मुमकिन ही हो। इस हाउस का ऐसा शायद कोई मैम्बर भी नहीं होगा जिस का इधर या उधर बायस न हो। बाकी कोड ग्राफ कन्डक्ट के सिलसिले में कमेटी जरूर बननी चाहिए।

ग्राप को इन्हेरैन्ट पावर है ग्रौर ग्राप वह पावर्ज इस्तेमाल कर के जो कमेटी चाहें बना सकते हैं। लेकिन ग्रगर इस तरह के इल्ज़ामात ग्राते हैं ग्रौर एक मैम्बर दूसरे मैम्बर के खिलाफ़ कोई ऐलीगेशन्ज़ लगाता है तो यह इल्ज़ामात ऐसे हैं जिनको इन्क्वायरी से ही दरुस्त किया जा सकता है। मेम्बरज़ ग्रापस में क्या कर लेंगे। यह काम इन के लिये मुश्किल नज़र ग्राता है।

कामरेड शमशेर सिंघ जोश: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ

ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਣ ਤਾਂ .ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਇੰਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਚ ਕਈ ਐਕਸ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਇਕ ਗਲ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਖਸ 8 ਸਾਲ ਤਕ ਮਨਿਸਟਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸਨ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਤਸਫੀਆ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਸਲੈਸ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਜ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ।

श्री बलरामजी दास टंडन: मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि यह मामला कई दिनों से इस हाउस में जेरे बहस है। जो साबका होम मिनिस्टर साहिब हैं उन्होंने मौजूदा एजूकेशन मिनिस्टर पर इल्जाम लगाए हैं और इन्होंने उन पर लगाए हैं और स्पीकर साहिब, यह बात कही गई है कि इन इल्जामात की कोई इन्क्वायरी हो। दोनों आनरेबल मेम्बर साहिबान इन्क्वायरी को फेस करने के लिये तैयार हैं तो इस की इन्क्वायरी करानी चाहिए इस बात को जैनरल आबजरवेशन्ज़ के साथ यहां पर छोड़ देना मुनासिब नहीं। इस लिये जैसा कि आप ने कहा है मैं यह मूव करता हूं कि इस हाउस की एक कमेटी बना दी जाए जिस में सरदार गुरनाम सिंह, सरदार गुरदयाल सिंह ढिलों और . . . . .

श्री अध्यक्ष : Please take your seat पहली चीज यह है कि आप काफी ऐक्सपीरियन्स्ड मैम्बर हैं और आप को पता होना चाहिए कि पाइन्ट आफ आर्डर पर इस तरह की मोशन कैसे मूव

[श्री अध्यक्ष]
को जा सकती इस को मेरे पास भेजने का तरीका है और फिर प्राइवेट मेम्बर की मोशन लाने का और तरीका है। अगर आप मोशन मूव करना चाहते हैं तो आप इसे मेरे पास भेज दीजिए । It will be dealt with in accordance with the rules. please take your seat. In the first instance a very experienced member of your standing ought to know that no motion of this nature can be moved on a point of order. There are set rules for moving a motion in the House. In case of the motions of the private members the procedure has already been laid down in the rules. If the hon. Member wants to move this motion he may send the same to me. it will be dealt with in accordance with the rules)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ?

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦਗਿਲ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਆਪ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਸਨ ....
(ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : I think the hon. Member is wrongly informed. Pandit Nehru was never the Chairman.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਬਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਨ ਪਰੋਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਰਪਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੀਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਪਰੋਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਰੂਲ 63 ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੈਟੀਚਿਊਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਰਸਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਐਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ 20 ਰਸਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਡਿਕਟ ਸਾਬਕਾ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਜ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਤੇ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ।

चौधरी राम स्वरूप : मेरी अर्ज़ यह है कि यह सारे हाउस के वकार का सवाल है आप भी इस बात को समझते हैं और मैं भी समझता हूं। इस वक्त दोनों मैम्बरों के वकार का सवाल नहीं हाउस के वकार का सवाल है। वह दोनों खुद भी चाहते हैं और हाउस भी चाहता है कि इस बात की इन्क्वायरी होनी चाहिए इस लिए आप इस हाऊस की एक कमेटी मुकरर कर दें जैसा आप मुनासिब समझें ताकि इस बात की पूरी तरह से पड़ताल हो सके।

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE SUBORDINATE LEGISTATION COMMITTEE

Sardar Gurmit Singh (Chairman, Subordinate Legislation Committee) : Sir, I beg to present the Seventh Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1964-65.

DEMANDS FOR GRANTS

Public Works and Welfare Minister (Shri Rizaq Ram) : Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs 5,88,52,620 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66 in respect of charges under head 42—Multipurpose River Schemes.

Mr. Speaker : It would be better if the Hon. Minister moves the other demands also so that these can be discussed together.

Public Works and Welfare Minister : All right, Sir. I also beg to move—

That a sum not exceeding Rs 5,23,98,910, be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of

[Public works and Welfare Minister]

charges under head 43—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial.)

That a sum not exceeding Rs 2, 75,33,150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head Charges on Irrigation Establishment.

That a sum not exceeding Rs 19,59,48,620 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head 98—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs 5,50,02,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head 99—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

Mr. Speaker : Motions moved—

That a sum not exceeding Rs 5,88,52,620 be g anted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66 in respect of charges under head 42—Multipurpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs 5,23,98,910 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head 43—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works [(Commercial).

44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non- Commercial).

That a sum not exceeding Rs 2,75,33,150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head Charges on Irrigation Establishment.

That a sum not exceeding Rs 19,59,48,620 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head 98—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs 5,50,02,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under had 99— Capital Outlay on Irrigation, Navigation Embankment and Drainage works (Commercial).

All the Demands will be discussed together and voted upon separately.

Notices of cut-motions which have been received from various members to these Demands will be deemed to have been read and moved and can be discussed along with the Demands.

Demand No. 26

(42—Multipurpose River Schemes).

1. **Comrade Jangir Singh Joga** :

That the demand be reduced by Rs 100/-

Demand No. 27

(43—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial) and

44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)).

1. Shri Roop Lal Mehta :

that the demand be reduced by Re 1/-.

Demand No. 48

(99—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

1. Sardar Pritam Singh Sahoke :

That the demand be reduced by Rs 100/-.

Mr. Speaker : Sardar Gurcharan Singh to initiate the discussion.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ(ਮੋਗਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (The time being limited each Member will get only 15 minutes to speak.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਲੱਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ 1955 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਰਫਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ 1955 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1965 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਫਲੱਡਜ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰਚ ਤਾਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair.)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੱਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੀਮਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਕਮ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਲੱਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੀਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਰੀਲੀਫ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੇਨਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਿਕਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਪੁਟਣੀਆਂ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਜਬਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨਜ਼ ਪੁਟਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੈਚੂਰਲ ਫਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਦਰ-ਭਾਨ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਡਗਰੂ ਡਰੇਨਜ਼ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 10—10 ਦਫਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸੀਆਂ ਆਊਟ ਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਚੰਦ ਭਾਨ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਘੱਗਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸੀਆਂ ਆਊਟ-ਫਾਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 6-7 ਦਫਾ ਇਸ ਆਊਟ ਫਾਲ ਦੀ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਡੀਮਾਰਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਤਲਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸੀਆਂ ਆਉਟ-ਫਾਲ ਦੀ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸੀਆਂ ਆਊਟ-ਫਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ 10 ਜਗਾਹ ਤੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡੀਪਾਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਐਨਬਲਾਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਕੇ ਅਤੇ ਸੈਦੋਕੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੈਸਟਿਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੈਚੂਰਲ ਫਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਢਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਝੂਠ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲਾਈਨ-ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਕ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਨਾ ਅਹਿਲ ਅਫਸਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ

ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੇਨ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ?

ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਭਾਨ ਡ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਏ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਰੋਡਜ਼ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,25/30,30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹ ਪੁਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਈਆਂ ਬਨਾਣ ਤੋਂ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪੁਲ ਟੁਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਪਣੀ ਡ੍ਰੇਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਬੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 4 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਸਦਾ ਇਕ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਆਊਟ ਫਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਡ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਲਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਰਿਸਵਤ ਦੇਕੇ ਜਿਥੋਂ ਪੁਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਹਟਵਾ ਕੇ ਗੈਰ ਐਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੁਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਥੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰ ਭਾਨ ਡ੍ਰੇਨ ਪੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਪਖਰਬਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਦੀਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਕਸੇ ਵਿਚ ਪੁਟਣ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸੀ ਮਗਰ ਪੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੇ ਥਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਇਕ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਥੇ ਗਏ ਔਰ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਥਾਂ ਪੁਟਣ ਲਈ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਥੇ ਪੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਚੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰੈਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੇਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਐਪਰੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਜੁਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਜਿਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਔਰ ਬੇਇੰਸਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? (ਘੰਟੀ)

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਡ੍ਰੇਨ ਸੰਨ 1955 ਵਿਚ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਫਰਟਾਇਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਖੀਰ ਟੇਲ ਤੇ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੁਟਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਬਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਤਰਲੇ ਕਢੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਅਫਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲਵਾਉ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਿਆ ਦਿਉ। (ਘੰਟੀ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਥੋਂ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦ-ਕੂੜਾ ਰੇਹ-ਆਦਿ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਫਾਇਤ ਸਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਮਗਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री रूप लाल मेहता : (पल्लवल) डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज सदन में इरीगेशन की डिमांड पर बहस हो रही है मैं भी इस के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। ठीक है इरीगेशन की डिमांड इस सदन ने पास तो करनी ही है और की जाएगी लेकिन गुड़गावां में इस महकमे की लापरवाही से जितना नुकसान हुआ है वह बयान से बाहिर है। इस महकमे की गफलत की वजह से सोलड़ा और खादर के 416 गांव फलड इफैक्टिड हुए। लोगों के घर गिर गए और वह बेचारे सिरकियां डाल कर बाहिर बैठे रहे। जो गौंची ड्रेन है उस की ऐलाइनमैंट बिलकुल गलत की गई थी जिस की वजह से वह लिंक ड्रेनज़ का पानी ऐक्सैप्ट नहीं करती। उसकी वजह से फल्लड आता है और लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हम कई बार गवर्नमेंट की तवज्जो इस बात की तरफ दिला चुके हैं कि वहां के लोगों को मुसीबत से नजात दिलाने के लिए गौंची ड्रेन के जो किनारे हैं वह ऊंचे किए जाएं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अभी कल जब मैं अपने हलके में गया तो मेशपुर और अलीका गांवों के लोग मुझे मिले और कहने लगे कि अगर इस ड्रेन के किनारे बरसात आने से पहले ऊंचे न किए गए तो फिर हम फलड्ज़ में डूबेंगे। सरकार हर साल जितना रुपया खर्च कर रही है वह सारे का सारा वेस्ट जाता है और उस के इलावा किसानों का हर साल उस से कई गुना ज्यादा नुकसान होता है।

(At this stage, Chaudhri Nihal Singh, a member of the Panel of Chairmen occupied the Chair)

जहां तक गुड़गावां कैनाल का ताल्लुक है वह अधूरी ही पड़ी है, कभी उस की खुदाई शुरू कर देते हैं कभी बन्द कर देते हैं। मैं ने इसी सैशन में ऐप्रोप्रियेशन बिल पर बोलते वक्त अर्ज़ की थी कि आर. डी 110 के नीचे इस नहर की खुदाई को बंद

किया जा रहा है । मैं यह बात मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाया था तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम खुदाई जारी रखेंगे । पिछली दफा ऐमर्जेंसी की वजह से गुड़गावां कैनाल को बंद किया गया था, दूसरी बार फिर उस की खुदाई को मुलतवी किया गया । अब तीसरी बार फिर उस का चर्चा चल रहा है । मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि उस नहर को मुकम्मल करने के लिए माकूल फंड्ज़ प्रोवाइड किए जाएं ताकि उस इलाके के लोगों को आबपाशी के लिए पानी दिया जा सके और पैदावार में इज़ाफा हो सके । छाइसा में चौधरी रणबीर सिंह जो उस वक्त इरीगेशन मिनिस्टर थे, ने कहा था कि सन् 1965 में पानी दे दिया जाएगा । लेकिन अब 1965 का चौथा महीना आने वाला है अभी तक बात वहां की वहां ही है, पता नहीं कब वह साल आएगा जब वहां के लोगों को पानी आबपाशी के लिए दिया जाएगा । मैं पंजाब सरकार से गुज़ारिश करूंगा कि गुड़गावां की नहर को मुकम्मल करने के लिए खास फंड्ज़ प्रोवाइड करे वर्ना जिस ढंग से अब खर्च किया गया है वह वेस्ट करने के बराबर है । यही नहीं बल्कि जो ड्रेनों के लिए रुपया लगाया जा रहा है वह भी कतैयी वेस्ट हो रहा है । जिन गावों की ज़मीनें ड्रेन के पार आ जाती हैं उन के गुज़रने के लिए पुल नहीं बनाए गए और उनको पांच पांच मील का चक्कर काट कर जाना पड़ता है । महकमें वालों को चाहिए था कि हरेक गांव के लिए एक छोटा और एक बड़ा पुल बनाते ताकि लोग आसानी से आ जा सकते और अपना माल मण्डियों में ले जा सकते । गौंची ड्रेन पर जहां जहां पुल नहीं बनाए गए मंत्री महोदय अपने चीफ़ इंजनियर को बुला कर कहें कि वहां पर पुल प्रोवाइड करवाने का प्रबन्ध करें । इसके इलावा मैं पिछले तीन सालों से अर्ज़ करता आ रहा हूं कि गुड़गावां ज़िले के 14/15 गांव यू.पी. की तरफ जा रहे हैं । इस सिलसिले में ऐस. डी. ओ. बुलंद शहर और ऐस. डी. ओ. पलवल की मीटिंग फिक्स हुई जिस में ऐस. डी. ओ. पलवल बीमारी की वजह से नहीं जा सके । छाइसा के मुकाम पर दरिया के रुख बदलने की वजह से हमारे 15 गांव यू.पी. की तरफ चले जाएंगे । मैं गुज़ारिश करूंगा कि इस बात की तरफ तवज्जो दी जाए । यह बात अहम मामला है । आप हर इजलास की प्रोसीडिंग्ज़ निकलवा कर देख लें मैं गुड़गावां ज़िले की पसमार्दगी की तरफ अपनी सरकार की तवज्जो दिलाता रहा हूं । वहां एक सोलड़ा गांव है उन की जितनी ज़मीन थी और कुएं थे वह सारे यू.पी. में चले गए ह । मैं ने देखा है वहां का हस्पताल और स्कूल भी डूब गया है और जेहर नाले पर बांध अभी तक नहीं बांधा गया । जो पिछले साल बांधा था वह बिल्कुल कच्चा था इस लिए टूट गया .पानी यू. पी. की बजाए पंजाब की तरफ डाइवर्ट हो गया है । वह गांवों चूंकि उन की हद में चले गए है इसलिए यू.पी. वाले कहते ह कि वह गांव हमारे हो गए हैं । यह सब इरीगेशन डिपार्टमेंट की लापरवाही का नतीजा है । जो चीज़ें जरूरी हैं वह फ़ौरी तौर पर करनी चाहिएं वह उन के बारे में कोताही करते हैं । इस महकमे के लोग अगर ठीक ढंग से काम करें तो जो करोड़ों रुपया हर साल जाया होता है और उस से कई गुना लोगों का फसल मवैशियों वगैरा का नुकसान होता है वह बचाया जा सकता है । इस तरफ पूरी तवज्जो देने की जरूरत है । मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि

[श्री रूप लाल मेहता]
अगर इस चीज़ को जंगी सतह पर हल न किया गया तो वाटर लौगिंग से जैसे पहले दूसरे इलाकों की ज़मीन तबाह हो चुकी है ऐसे ही उस इलाके की ज़मीन भी खराब हो जाएगी जिस से प्रोडक्शन पहले की निसबत बहुत कम हो जाएगी । हमारा पंजाब का सूबा जो पहले सारे हिन्दुस्तान को अनाज देता था आज खुद इसे मोहताज होना पड़ा है । यह ठीक है महकमा जरायत वाले हर साल फिगर्ज़ छाप देते हैं कि इस साल इतना अनाज होगा, इतना फलां होगा । कभी कहते हैं पैदावार बढ़ गई है कभी कहते हैं नहीं बढ़ी है । वह महज आफिस में बैठ कर कागज़ी अदादोशुमार दिखा देते हैं जब कि हकीकत कुछ और होती है । जब तक ऐसे महकमों के कर्मचारियों को खींचा नहीं जाता तब तक काम ठीक नहीं हो सकता । गुड़गावां में जितनी मुसीबत पिछले साल आइ थी उतनी ही उस से पहले साल में आई थी इसी तरह रोहतक संगरूर और पंजाब के कई औंर ज़िलों का हाल है । इस लिए 'इस मसले को जंगी सतह पर हल किया जाए । पंजाब में जो नहरी सिस्टम ने तरक्की की है उस के लिए हमारी सरकार मुबारिकबाद की मुस्तहिक ई लेकिन हकीकत में देखा जाए तो पता चलता है कि महकमें की गफलत और लापरवाही की वजह से लोगों को हर साल फलड्ज़ का सामना करना पड़ता है । पिछले दिनों एक लम्बी चौड़ी स्कीम शुरू हुई थी । गुड़गावां के पास एक नजफ्गढ़ ड्रेन है । उसके बारें में कहा गया कि वह 49 मील लम्बी, 100 फुट चौड़ी और दाएं बाएं उसके 100 फुट पटड़ी भी बनेगी । फिर यह भी सुना गया कि दीवारें भी और ऊंची बनाई जाएंगी । खैर भला हो इस सरकार का कि वह स्कीम ड्राप हो गई जिस पर 15 करोड़ रुपया लगना था । लेकिन इस में यह बात देखने वाली है कि किस तरह से महकमा वाले वज़ीर साहिबान को लोगों को बचाने के नाम पर लोगों की बरबादी की सकीमें देते हैं और स्टेट की अकानोमी की बरबादी का बाइस बनते हैं । अगर यह स्कीम सिरे चढ़ती तो हमारा भारी नुकसान होता । पिछले पांच सात साल में हमारे जो तबाही हुई है उसकी अगर इन्क्वायरी कराई जाए और ज़िम्मेदारी डाली जाए तो चीफ इन्जीनियर से लेकर ऐस सी वगैरा तक एक एक उसके लिए ज़िम्मेदार है और जितनी तबाही हुई है उसके लिए वह मुजरिम हैं क्योंकि उन्होंने अपने फरायज़ेमन्सबी को इमानदारी और असलियत के साथ अदा नहीं किया है । पाकिस्तान बनने से पहले भाखड़ा डैम नहीं था और उसके बाद भाखड़ा डैम के मेहमत जो सरकार ने पंजाब को दी इस से हम बहुत खुश है लेकिन इसके ऊपर जितना रुपया लगा है वह भी देखें और जो रिटर्न हमें इस से मिल रही है उसे भी देखें । इस वक्त हमारे ऊपर एक अरब से भी ज्यादा कर्ज़ है जिस पर हमें करोड़ों के हिसाब से सूद अदा करना पड़ता है । अब हमारे गुड़गांव को जो नहरों का फायदा पहुंचा है वह भी देख लें । हमें अंग्रेज़ों के ज़माने से ही अपर आगरा कैनाल से पानी मिलता है और उस पानी का हमें पंजाब से दुगना वाटर रेट देना पड़ता है । हम ने कई दफा सरकार से अर्ज की है कि इस कैनाल को अपने हाथ में ले लें । अगर और नहीं तो कम से कम जो हिस्सा नहर होडल तक नहर का पंजाब के इलाके में आता है उसे ही ले लें और अपने हिस्से का पानी खुद ले कर उनके हिस्से का पानी

उनको दे दें । इस बारे में पारटीशन से ले कर अब तक काफी मीटिंगज़ यू0पी0 सरकार के साथ होती रहती हैं लेकिन अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो सका है । अपर आगरा कैनाल उसी तरह से यू.पी. सरकार के अंडर है । पटवारी और आमीन उनके ही हैं । आज हमारी वहां गन्ने की फसल तबाह हो गई है क्योंकि उसे कीड़ा लग गया इसलिए यील्ड कम हो गई है । हम कई दफा दफा पंजाब सरकार को कह चुके हैं कि गवर्नमैंट लैवल पर यू0पी0 सरकार को लिखा जाए कि गन्ने पर वाटर रेट माफ किया जाए लेकिन अभी तक पता नहीं लग सका कि उस पर क्या ऐक्शन लिया गया है । यह अपर आगरा कैनाल तो हमारे लिए ज़हमत बन गई है । पानी तो हमें मिलता है लेकिन वाटर रेट हमें यू. पी. सरकार को जालंधर और लुध्याना के मुकाबले में जो वह पंजाब में देते हैं दुगना देना पड़ता है । मैं सरकार से कहूंगा कि या तो उस नहर का जो हिस्सा हमारे इलाके में पड़ता है उसको अपने हाथ में लेकर अपने हिस्से का जो पानी बनता है वह लोगों को दें या उस सारी नहर को यू.पी. सरकार को मुआवज़ा दे कर अपने कबज़े में ले कर लोगों को पानी दें ताकि उस का वाटर रेट उसी रेट पर हमें देना पड़े जिस रेट पर जालन्धर लुध्याना वाले देते हैं । इस तरफ सरकार को फोरी तौर पर ध्यान देना चाहिए . तभी गुड़गांव ज़िला के लोगों की भलाई हो सकती है और तभी हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार को गुड़गांव ज़िला का पूरा ख्याल है यह ठीक है कि गौंची डैम हमारे फायदा के लिए बनाया था लेकिन उस में कई नुक्स हैं जिन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है मैं कई दफा यह बात सरकार के और महकमा के नोटिस में ला चुका हूं कि इस के किनारे ऊंचे किए जाएं और इसकी गहराई ज्यादा की जाए और उसका लैवल ठीक करें लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है । उसकी गलत एलाइनमैंट की वजह से बहुत नुकसान हुआ है । मैं अभी पिछले दिनों ज़िला परिषद चुनाव के सिलसिले में मेवात में गया और मैं ने कोटला बांध ने जो नुकसान किया है उसे देखा है । मैं उसे ब्यान नहीं कर सकता । खैर अब उजीना ड्रेन वहां बन रही है और अगर वह पूरी हो गई तो शायद मेवात का एरिया तो बच जाएगा लेकिन होडल पलवल का इलाका नहीं बच सकेगा क्योंकि वहां कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है । ऐस. इ. की चिट्ठी से मालूम होता है कि work has been undertaken और मौनसून शुरू होने से पहले काम खत्म कर दिया जाएगा । लेकिन ठेकेदारों से जब पूछते हैं तो वह कहते हैं कि कोई हुक्म नहीं मिला है । (घंटी) मैं कहना चाहता हूं कि अब सिर्फ तीन महीने बाकी रह गए हैं । अगर इस वक्त में काम खतम न हुआ तो फिर हमारा इलाका तबाह होगा आप गुड़गांव ज़िला को पंजाब का हिस्सा समझ कर वहां गौंची डैम के किनारे ऊंचे कर दें तभी गुड़गांव बचेगा वरना जिस तरह पिछली दफा 416 गांव पानी में डूबे थे उसी तरह फिर हमें नुकसान बरदाशत करना पड़ेगा । मैं सरकार से अर्ज़ करता हूं (घंटी) कि गुड़गांव लिफट स्कीम को टाप परायरटी दी जाए चाहे दाएं बाएं कहीं बजट से पैसा निकालें चाहे कोई और सकीम बंद करें तभी गुड़गांव ज़िला की भलाई हो सकती है और वहां समाजवाद का ढांचा कायम हो सकता है वरना लोग कहेंगे कि हम असेम्बली में जा कर मांग करते हैं और वायदे भी लेतें हैं

[श्री रूप लाल मेहता]
लेकिन जब वापस आते हैं तो बात वहीं रहती है और सरकार को गुड़गांव का ध्यान नहीं है । इन अलफाज़ के साथ, चेयरमैन साहिब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो आपने मुझे टाइम दिया है ।

श्री रला राम (मुकेरियां) : चेयरमैन साहिब, ब्यास डैम मेरे हलके में है और वहां उसका काम बड़े ज़ोरों के साथ जारी है लेकिन इस संबंध में कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके द्वारा सरकार के ध्यान में लाना ज़रूरी समझता हूं । सब से पहली बात यह है कि जो लोग वहां से उठ रहे हैं डिसपलेस हो रहे हैं या होने वाले हैं उनको रिहैबीलीटेट करने का अभी तक सरकार कोई पूरा इन्तज़ाम नहीं कर पाई है । तलवाड़ा टाउनशिप के लिए जो ज़मीन हासिल की गई है उस बारे ठीक है कि उसका लोगों को मुआवज़ा जल्दी अदा हुआ लेकिन उनके रोज़गार का और उनकी रिहैबली-टेशन का मसला उसी तरह है । वह ज़मीन जो ली गई है बड़ी ज़रखेज़ थी और सारे इलाके में वहां सब से ज्यादा अन्न पैदा होता था । अब वह सारी की सारी डैम में आ गई है और बाकी जो बची भी है वह अब जो हाइडल चैनल निकलने वाली है उसके अन्दर आ जाएगी । मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन उजड़ने वाले लोगों का मसला मुआवज़ा दे देने से ही हल नहीं हो जाता है । यह ठीक है कि सरकार की पालीसी है कि उनको राजस्थान में ज़मीन मिलेगी लेकिन यह बात तो देर की है । इस वक्त हालत यह है कि जो रुपया लोगों को मुआवज़े का मिला है उसका बहुत सारा हिस्सा लोग खा चुके हैं । वहां पर आउस्टीज़ की कुआप्रेटिव सुसायटीज़ बनीं और मैं भी बतौर आउस्टीज़ उन में शामिल हुआ लेकिन वह कुआप्रेटिव सुसाइटीज़ चाहे नातजरुबेकारी की वजह से या और कुछ वजुहात की वजह से फेल हो गई और जो थोड़ा बहुत रुपया बतौर मुआवज़ा लोगों को मिला था उस का बहुत सारा हिस्सा इनकी फ़ेलियोर की वजह से ज़ाया हो गया है । अब उनकी हालत काबिले रहिम है । इस लिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उन लोगों को रोज़गार दिया जाए । आज 90 फीसदी आउस्टीज़ की हालत खराब है । अगर सरकार ने उनके रोज़गार का मुनासिब इन्तज़ाम न किया तो उनकी हालत और भी खराब हो जाएगी । यह ठीक है कि उनके लिए काफी रोज़गार लेबर की शक्ल में पैदा हुआ और काफी लोग मज़दूर की शकल में वहां जज़ब हुए लेकिन मेरी एक शिकायत है जो मैं समझता हूं कि जायज़ और सही शिकायत है । वह यह है कि उन आउस्टीज़ को बेलदार या चौकीदार के तौर पर तो लिया है लेकिन जहां तक सकिल्लड लेबर का सबंध है उस में उनको नहीं लिया गया है हालांकि वह बहुत सारे सिकिल्लड लेबर के तौर पर लिए जा सकते थे। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरफ ऐडमनिस्ट्रेशन ने कोई ध्यान नहीं दिया है । मैं समझता हूं कि उन आउस्टीज़ की शिकायत ठीक है कि उनको चौकीदार और बेलदार की लेबर में तो रखा जाता है लेकिन इस से बेहतर पोस्टों के काबिल होते हुए भी उनको नहीं लिया जाता है ।

सभापति महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं कि नंगल टाऊनशिप से जो लेबर डिस्प्लेसड हो रही है उस को सरकार तलवाड़े में एब्जार्ब कर रही है । मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है । मैं तो सरकार से इतनी ही अर्ज करना चाहता हूं कि वहां क ग्राउस्टीज को रोज़गार देने के लिए भी प्रबन्ध करें । वहां के लोगों की ज़मीनें सरकार ने ले ली हैं ग्रौर वहां 90, 95 प्रतिशत जनता एग्रीकल्चर पर निर्भर थी। इस लिए उनकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए । इस में सरकार ने काफी काम किया है फिर भी इस में कुछ कमियां रह गई हैं उन की तरफ सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिए ।

सभापति महोदय, वहां पर बहुत से गांवों को उजाड़ कर एक लेक बनाई जा रही है । इस के लिए सरकार को इन के बारे में जल्दी ही कदम उठाने चाहिएं ताकि उन को कोई न कोई रोज़गार मिल सके । सरकार के लिए ठीक होगा कि उन गांवों का उजाड़ने से पहले उन लोगों के बसाने के लिए ग्रौर रोज़गार मुहैय्या करने के लिए प्रबन्ध करे । वहां के लोगों के दिलों में काफी ग्रसंतोष फैला हुग्रा है ग्रौर फैल रहा है । सरकार ने उन के लिए कुछ स्कीमें भी बनाई हैं ग्रौर वह स्कीमें उन के सामने नहीं ग्राई हैं । उन्हें इन स्कीमों के बारे में बताया जाना चाहिए ताकि उन के दिलों में ग्रसंतोष न बढ़ें । मैं चाहता हूं कि सरकार उन स्कीमों को वहां के लोगों के साथ डिटेलज़ में डिस्कस करे ग्रौर उन को बसाने ग्रौर रोज़गार मुहैय्या करने के लिए प्रबन्ध करे । तलवाड़ा टाउनशिप के ग्रन्दर कुछ सैक्टर्ज़ उन के बसाने के लिए रिज़र्व किए गए हैं । सरकार ने यह ग्रच्छी बात की है क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं ग्रौर वहां पर रोज़गार भी पा सकेंगे । इस लिए मैं सरकार से ग्राप के द्वारा प्रार्थना करना चाहता हू कि सरकार को उन गांवों के उजाड़ने से पहले सारी स्कीमज़ उन्हें समझाए ताकि उन के दिलों में ग्रसंतोष की लहर कम हो सके । वहां पर सरकार ने इंडस्ट्रीयल एरिया भी रिर्ज़व किया है। सरकार ने नंगल में फैक्टीज़ बनायी थी ग्रौर वह फैक्टरी तभी लगाई गई जब वहां पर डैम तैयार हो गया था, वह वहां पर बहुत देर के बाद स्थापित की थी । यहां पर भी सरकार कोई न कोई फैक्टरी स्थापित करेगी । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार पहले ही इस बारे में ग्रनाउंसमैंट करे ताकि ग्रभी से वहां पर काम शुरू किया जा सके । डैम के बनने के बाद वहां फैक्टरी स्थापित की जाएगी ग्रगर सरकार इस बारे में ग्रभी ग्रनाऊंस मैंट कर दे तो लोगों को काफी हौसला हो जाएगा ग्रौर फैक्टरी लगने से डिसम्प्लेस्ड ग्रादमियों को भी काफी रोज़गार मिल सकेगा ग्रौर काफी हद तक उन को सहूलतें मिल सकेंगी । इस तरह से उन को ग्राबाद होने में भी काफी मदद मिल सकेगी । इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस ग्रोर शीघ्र कदम उठाए । (घंटी)

सभापति महोदय, वहां पर वाटर वर्कस तैयार हो रहे हैं ग्रौर यह काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा । वहां से पीने का पानी लोगों को मुहैय्या किया जाएगा । ग्राजकल वहां के लोगों पहाड़ों में बस रहे हैं । इस लिए मैं ग्राप के द्वारा सरकार से प्रार्थना

[श्री मला राम]

करना चाहता हूं कि लोगों को पीने का पानी वहां पर पहुंचाया जाए, जहां पर वह आज कल बस रहे हैं । इस वाटर वर्कस से तलवाड़ा के आस पास के गांवों को जोकि 4,5 हैं अर्थात् तलवाड़ा, भेड़ा, डौहर और नंगल गांव हैं, उन सब को पानी पहुंचाया जाए । मैं समझता हूं कि सरकार उन की तकलीफों को शीघ्र ही दूर करने का प्रबन्ध करेगी ।

सभापति महोदय मुकेरियां, के नजदीक से दरिया ब्यास गुजरता है। जब वहां पर मानसून के वक्त या किसी और समय बाढ़ आती है तो उस से दरिया के निकट के इलाके को बहुत भारी खतरा पैदा हो जाता है । यह ठीक है कि गवर्नमेंट ने 3 स्पर्ज़ वहां की हिफाज़त के लिए लगाए हैं लेकिन उस से लोगों के दिलों में बहुत बेचैनी ही रही है । और लोगों को बाढ़ के कारण नुक्सान का डर रहता है । ब्यास के दूसरी तरफ ज़िला गुरदासपुर लगता है । वहां पर सरकार ने घुस्सी बान्ध और स्पर्ज़ वहां के लोगों की हिफ़ाजत के लिए बनाए हैं । जब वहां पर बाढ़ आयगी तो वहां पर पानी इन में डाईवर्ट हो जाएगा और इस तरह से वह सुरक्षित रह जाएंग । मैं इस बांध को तुड़वाने के हक में नहीं हूं । मैं इतनी ही अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीच्युएंसी इस इलाके में तीन लाख मन पैडी प्रोड्यूस होती है । इस इलाके में से वह राइस पंजाब के दूसरे हिस्सों और हिन्दुस्तान के अन्य स्थानों में जाता है । अगर दरिया ब्यास का रुख मेरी कांस्टीच्युएंसी की तरफ आ गया तो मैं समझता हूं कि वह ज़मीन नाकाबलेकाश्त हो जाएगी जिस से बड़ी मात्रा में अनाज की कमी हो जाएगी । आप को मालूम ही है कि हमारे देश की हालत पहले ही अनाज की कमी के कारण खराब है लेकिन बाढ़ का रुख बदल जाने से लोगों की ज़िन्दगी महफूज़ नहीं रह सकती । इस लिए, मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पर सरकार लोगों की ज़मीनें बचाने के लिए स्पर्ज़ तैयार करे ताकि उस का रुख बदलने से लोगों का नुक्सान न हो । मैं चाहता हूं कि धुस्सी बान्ध उसी तरह से कायम रहे । मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मेरे इलाके की तरफ भी सरकार शीघ्र प्रबन्ध करे ताकि लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके।

सभापति महोदय, चोओं का मसला तो ज़िला होशियारपुर में सब से ज्यादा है। हमारे सिंचाई मन्त्री महोदय इस के बारे में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं । वह स्वयं महंगरवाल गए और वहां पर जा कर सारी हालत का मुआयना किया । यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है । मैं समझता हूं कि सरकार ने इन के बारे में कुछ स्कीमें तैयार की हैं और कर रही है लेकिन वह अभी तक फाइनेलाइज़ नहीं हुई हैं । मैं चाहता हूं कि यह स्कीमें शीघ्र ही फाइनेलाइज़ की जाएं ताकि वहां की 3, 4 लाख एकड़ ज़मीन इन चीजों से बर्बाद न हो सके इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके । यह सारी ज़मीन ज़ेरे काश्त हो सके । मैं मानता हूं कि मन्त्री महोदय ने स्वयं जा कर वहां का निरीक्षण किया है और काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं । मैं मंत्री महोदय का इस बारे में धन्यवाद करता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं आप के द्वारा फिर

प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन स्कीमों को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए ताकि यह स्कीमें लागू हो सकें। (घंटी) सभापति महोदय, मैं कुछ और प्वायंटस आप के द्वारा मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाना चाहता हूं लेकिन आपने घंटी बजा दी है, इस लिए मैं आप का धन्यवाद करके अपनी सीट संभालता हूं।

बाबू बचन सिंह (लुधियाना उत्तर) : चेयरमैन साहिब, इस वक्त पंजाब के सामने दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि इरीगेटिड एरिया को किस तरह से बचाया जाए और दूसरा सवाल यह है कि सेमज़दा इलाके को किस तरह से कम किया जाए। मैं तो इन दो सवालों को एक ही समझता हूं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पंजाब में 1955 से फलड्ज आ रहे हैं और इस से ज़मीन तबाह होती जा रही है। किसानों का भारी नुक्सान होता आ रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार ने इस के बारे में कुछ भी नहीं किया है। अगर सरकार यह दावा करती है कि इस नैरेस को रोकने के लिए इस ने कुछ किया है तो मैं समझता हूं कि वह अहमकों वाली दुनिया में ही बस रही है। इस से ज्यादा अच्छे लफ्ज़ मुझे नहीं मिल रहे हैं जिन से मैं इन को विभूषित कर सकूं। मैं मौजूदा मिनिस्टर की जात पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं उन की तारीफ ही करना चाहता हूं, क्योंकि वह इस मसले को सुलझाने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और लोगों से सुजेशनज लेने के लिए भी तैयार हैं। अगर मैं यह कहूं कि सरकार ने इस बड़े मसले को काबू करने में कोताही की है तो इस में मुबालगा नहीं होगा। आटम सैशन के वक्त सेम के मसले के ऊपर एक कमेटी बिठाई गई थी जिस का चेयरमैन श्री फलैचर को बनाया गया था। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि उस कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं की है। यहां पर इतना सीरियस मामला हो और सरकार इस समस्या को वार फुटिंग पर सुलझाना न चाहती हो तो इस बात से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि यह सरकार इस गम्भीर मसले को कितनी प्रेफरेंस दे रही है। इस वक्त पंजाब की हालत पहले जैसी नहीं है। आजकल पंजाब में पानी की कमी नहीं है और सेम के कारण गांवों का नुक्सान हो रहा है। एक तरफ तो लोग सेम से नुक्सान उठा रहे हैं, बाढ़ से नुक्सान उठा रहे हैं और दूसरी तरफ अबोहर, सिरसा, भिवानी और रिवाड़ी के लोग पानी के लिए चीख रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें पानी मिलना चाहिये। अगर कोई अकलमंद आदमी गवर्नमेंट में होता तो वह जानता कि मामूली जमा तफरीक, प्लस और माईनस का सवाल है। (विघ्न) मैं ने पहले ही कह दिया है कि चौधरी साहिब की ज़ात से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे दिल में उन के लिए श्रद्धा है। आज से बीसों साल पहले ही हिन्दोस्तान के लोगों को पता चल गया था कि जहां जहां पर नहरों का पानी गया है वहां वहां पर लानत बन जाएगा। आप जानते नहीं कि लायलपुर में क्या हुआ था, आप जानते नहीं कि शेखुपुरा में क्या हुआ था, आप को पता नहीं कि गुजरांवाला में क्या हुआ था, वही हालत आज इस इलाका की हो रही है। क्या पंजाब का सारे का सारा एरिया इरीगेटिड हो गया है, चालीस, पैंतालीस फीसदी एरिया ही इरीगेटिड है, सौ फीसदी होना चाहिए।

[बाबू बचन सिंह]

लेकिन अगर सौ फीसदी न करें तो कम से कम 80, 90 फीसदी एरिया तो इरीगेट करें । कहते हैं कि इतना पानी हमारे पास नहीं है । मैं डैफीनेटली कहता हूं कि इस वक्त भी 80, 90 फीसदी एरिया इरीगेट करने के लिए पानी दे कर भी पानी बच रहता है । फिर क्या वजह है कि एक तरफ तो लोग शिकायत करते हैं कि हमें पानी मिलता नहीं और दूसरी तरफ फसलें सेम से मारी जा रही हैं। इस में सिवाए इनएफीशेंसी और सिवाए बलर्ड वीयन के और कोई बात नहीं है । यह जानते नहीं हैं कि हम बीसवीं सदी के दूसरे हिस्से में से गुजर रहे हैं, दुनियां कहां की कहां पहुंच गई है और हम कहां पर बैठे हुए हैं। कहते हैं कि फलां ड्रेन खोदी जा चुकी है, फलां ड्रेन खोदी जा रही है, सिरसे से और हिसार से आगे राजस्थान वाले पानी नहीं जाने देते । मैं कहता हूं कि अरे बाबा, तुम राजस्थान को पानी क्यों दो ? हमें खुद जरूरत है कि पंजाब में पानी इस्तेमाल करें । मुझे शर्म आती है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के वजीर कहते हैं कि अभी हमें कितने ही साल तक बाहर से अनाज मंगवाना पड़ेगा । मैं कहता हूं कि अकेले पंजाब में ही दुगना अनाज पैदा हो सकता है, दुगने से भी ज्यादा अनाज पैदा हो सकता है । लेकिन इस बात की फिक्र किस को पड़ी है । मिनिस्टर साहिब को शायद मालूम होगा कि डाक्टर लोक नाथन की टैकनो-इकोनौमिक सरवे की रिपोर्ट में कहा गया है कि गवर्नमेंट दस साल में 70 फीसदी एग्रीकलचर इकौनोमी बढ़ा सकती है । क्या पैदावार बढ़ाई है आप ने ? 1958 के बाद एक दाना अनाज का भी नहीं ज्यादा पैदा हुआ, बल्कि अनाज की पैदावार कम हो रही है । सरदार कपूर सिंह, फाइनेन्स मिनिस्टर साहिब कहते हैं कि हम ने कैश क्राप्स बढ़ा दी है । मैं पूछता हूं कि क्या इस बात का फख्र आप को हासिल है ? आप लोगों ने तो कैश क्राप्स को तबाह करने के लिए टैक्स लगाया है फिर कहते हो कि कैश क्राप्स बढ़ा दी है । आज तो देश को कैश क्राप्स की ज्यादा से ज्यादा ज़रूरत है क्या गन्ने की ज़रूरत नहीं है अगर चीनी बाहर भेजी तो क्या वह फारिन एक्सचेंज नहीं लाती, क्या तेल की ज़रूरत नहीं है, क्या काटन की ज़रूरत नहीं है ? इन चीज़ों की इतनी ही ज़रूरत है जितनी कि अनाज की । असल बात तो यह है कि अनाज बढ़ना चाहिए, तेल बढ़ना चाहिए, काटन बढ़ना चाहिए, गन्ना बढ़ना चाहिए, गर्जे कि हर पहलू में तरक्की करने की जरूरत है । मैं सूबे में क्या देखता हूं ? मैं देख रहा हूं कि लोग कहते हैं कि हमें फलां चीज मिलनी चाहिए, फलां चीज़ मिलनी चाहिए लेकिन इस गवर्नमेंट के पास देने को कुछ नहीं है । यह सरकार फेल हो रही है । आज से पांच साल पहले सारे पंजाब में 40,000 टन फर्टेलाईजर इस्तेमाल होता था । लेकिन आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि अकेले लुधियाना जिला में 40, 50 हजार टन फर्टेलाईजर इस्तेमाल होता है, लोग मांगते थे लेकिन गवर्नमेंट के पास देने को नहीं है । मैं अबोहर गया, मैंने देखा कि वहां के लोग पानी मांगते हैं, सिरसे के लोग पानी मांगते हैं लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि पानी नहीं है लेकिन कई इलाकों में लोग पानी में डूब रहे हैं । जहां पर लोग बिजली मांगते हैं वहां पर गवर्नमेंट लोगों से कहती है कि हमारे पास बिजली नहीं है । आप भाखड़े में जाकर देखो । मुझे शर्म आती है कि पांच जैनरेटरों में से तीन चलते हैं । चौथा इसलिए नहीं चलता क्योंकि इन के पास डिस्ट्रीब्यूशन लाईन नहीं है ।

जिस गवर्नमेंट की यह हालत हो कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद लोगों में बिजली डिस्ट्रीब्यूट न कर सके उस को कैसे हक पहुंचता है कि वह गद्दियों पर बैठी रहे। कहीं पर सेम और फलडज से फसलें तबाह हो रही हैं और कहीं पर लोगों को पानी की बूंद मुयस्सर नहीं होती। ऐसी गवर्नमेंट को हक नहीं है कि वह लोगों पर हकूमत करें। सवाल यह नहीं है कि 1947 से पहले क्या था या अंग्रेजों के ज़माने में क्या था, सवाल तो यह है कि आज प्रदेश की क्या जरूरत है। जहां तक अफसरों का ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है मुझे शर्म आती है कि मौजूदा गवर्नमेंट के ऐसे अफसर हैं, ऐसी गंदी और राटन एडमिनिस्ट्रेशन है जो कहते हैं कि फर्स्ट क्रिएट दी प्राबलम एंड देन साल्व दी प्राबलम। हमारे सूबे में 30 से 35 इंच औस्तन से ज्यादा बारिश नहीं होती लेकिन फिर भी सेम के नाले खोदने पड़ रहे हैं। कहते हैं कि 28 करोड़ रूपया नालियां खोदने पर खर्च कर दिया गया है। अरे बाबा यह बीमारी तो आप ने ही पैदा की है। जब मैं बच्चा था तो देखता था कि छोटी छोटी लड़कियां जब बादल घिरते थे तो नाचती थीं और सावन के महीने में गाया करती थीं कि रबा रबा मीह वरहा, साडी कोठी दाने पा। लेकिन आज क्या होता है। जब बादल आते हैं तो लोग पुकारते है कि इस बारिश से बचाओ, क्या आज बारिश लानत हो गई है जो कि पहले रहमत हुआ करती थी? मैं कहता हूं कि बारिश पहले भी बरकत थी और आज भी बरकत है। इस को लानत बनाने वाले आप जिम्मेदार बैठे हैं। ाप ने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या काम किया है, किस तरह से किया है? जो ड्रेन्ज आप ने खोदी हैं उन के लिए, माफ करना वज़ीर साहिब, 1955 से बाद किसी को कम्पलीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। ड्रेन्ज पर पुल नहीं बनाए गए। किसी नाली की सफाई नहीं की गई। फिर आप फख्र करते हैं, क्या इसी का नाम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी है? गजब खुदा का हो रहा है जो नालियां खोदी गई थीं वह फिर से भर रही हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन में से पानी गुज़रना मुश्किल हो गया है और पंजाब की सरकार यह कहती हुई थकती नहीं कि हम ने वह नाली खोद दी, वह नाली खोद दी। (घंटी की आवाज़) चेयरमैन साहिब, आज बहुत सा समय दूसरे मसले ने ले लिया है इसलिए हमें बोलने के लिए साढ़े तीन घंटे तो मिलने ही चाहियें। इस के लिए अगर टाईम बढ़ाने की जरूरत हो तो बेशक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : हर एक मैम्बर के लिए 15 मिनट टाईम मुकर्रर हुआ है। अगर हाउस का समय बढ़ाना होगा तो इस पर बाद में गौर कर लिया जाएगा। (Every hon. Member has been allotted 15 minutes to speak. In case the time of the sitting is to be extended, it will be seen later on.)

बाबू बचन सिंह : यह मसला बड़ा इम्पार्टेंट है क्योंकि इस से देश की 70 फीसदी आबादी का ताल्लुक है। तो मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि फलेचर कमेटी की रिपोर्ट हाउस में जल्दी से जल्दी पेश हो ताकि हाउस इसी सैशन में उस पर गौर कर सके। अगर इस सैशन में रिपोर्ट पेश न की गई तो बाद में बारिशें आ जाएंगी और जब पंजाब तबाह होने लगेगा लोगों के पास कोई चारा नहीं होगा, सैशन नहीं होगा तो लोग अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकेंगे।

[बाबू बचन सिंह]

इस लिए सरकार को चाहिए कि उस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी पेश करने के लिए कहे ताकि उस पर गौर किया जा सके ।

5.0) p.m. *(At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair)*

दूसरी बात यह है कि इस के लिए कोई जामे स्कीम बनाइए कि किस तरह से पानी का ज्यादा से ज्यादा और सही इस्तेमाल करना है । आप अब तक ऐसे ऐक्सपर्टस की राए पर अमल करते आए हैं जिन को, मैंने देखा, यह आदत ही पड़ी हुई है कि वह ट्रेडीशन्ज पर काम करते हैं । छः छः साल पुरानी बातों को ही दिमाग में बनाए हुए हैं । अगर आप उन की राए पर ही चलेंगे तो पंजाब की यह बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती, मर्ज़ बढ़ता जाएगा आप चाहे सौ इलाज करें । आज इन पुरानी ट्रेडीशन्ज को छोड़िए, इन पुराने ढर्रों को छोड़िए । कम अज़ कम आज आप को यह फैसला करना होगा कि पंजाब के अन्दर जहां जहां पर पानी ऊंचा आ गया, पंद्रह पंद्रह फुट से ज़्यादा ऊंचा आ गया है वहां पर किसी सूरत में पैरीनियल इरीगेशन न दी जाए । अगर आप ऐसे इलाके में पैरीनियल इरीगेशन देंगे जहां पर पानी पंद्रह फुट से ऊंचा आ गया है तो आप सैंकड़ों और हजारों ड्रेन्ज खोद लें, फलड ज़ से आप उन इलाकों को महफूज नहीं कर पाएंगे । इस के अलावा जो दूसरी बात करनी जरूरी है वह यह है कि जहां पर पानी साठ सत्तर हाथ पर है वहां पर नहरों से पानी दीजिए । इस तरह से आप रैशनल डिस्ट्रिब्यूशन आफ वाटर करें तो समस्या का कोई हल सामने आ सकता है । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक इस मसले का कोई हल हो ही नहीं सकता ।

मैंने पहले भी अपनी बजट पर जो स्पीच की थी उसमें कहा था और आज फिर उस बात को दुहराता हूं कि आप लुधियाना की मिसाल से सबक लीजिए । लुधियाना का दो-तिहाई एरिया इरीगेटिड है लेकिन वहां पर सेम का सब से कम सवाल है । (घंटी) मैं आप की मार्फत अपने इरीगेशन मनिस्टर साहिब का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप इस बात को देखें कि जहां जहां कैनाल इरीगेटिड एरिया ज्यादा है, जहां जहां पर कैनाल इरीगेशन की इंटेंसिटी ज्यादा है वहीं पर सेम ज्यादा हुई है । इस सेम को दूर करने का एक तरीका यही है कि वहां पर पैरिनियल कैनाल वाटर को कम करो । नालियों से यह समस्या हल नहीं होती । इस से पार्शल तौर पर तो बेशक हो जाए लेकिन सही तौर पर नहीं । आप प्लस और माईनस के इस सवाल को समझें । जो पानी आप के खेतों को नुक्सान पहुंचाता है उस को नीचे लाना है और जहां पर पानी नहीं है वहां पर आप ने पानी की सप्लाई करनी है । आप को इस बात का फौरी तौर पर फैसला करना होगा । (घंटी)

मैं समझता हूं कि पिछले आठ साल तक हमारे सूबा में जो गवर्नमेंट चलती रही है उसके कान तक तो जूं नहीं रींगी । वह तो किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी और उस के काम करने का सिर्फ एक ही तरीका था और वह यह कि जो मन में आए वही करना है । उसने कुछ ऐसे पिट्ठू अफसर रखे हुए थे जो वही करते

जो ऊपर से पसन्द होता था। ऐसे अफसर अब खत्म हो रहे हैं, शट आउट हो रहे हैं । आप की मार्फत इरीगेशन मिनिस्टर साहिब से कहूंगा कि आप के महकमा के अन्दर जो इस किस्म के अफसर हैं उन को शंट आउट कीजिए । वह लोग सूबे को लानत साबित हो रहे हैं । आप को दलेरी से काम लेना चाहिए । इस बात में पंजाब के लोग आप के साथ हैं । आप इस बात का यकीन कीजिए । ज़माना अब बदल गया है । इस ज़माने में, बलदते हुए ज़माने में आप को भी बदलना चाहिए । (घंटी) यहां पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं ।

Deputy Speaker : Wind up please.

बाबू बचन सिंह : बस एक मिनट में खत्म ही करने वाला हूं । एक मिसाल देकर खत्म कर दूंगा ।

उपाध्यक्षा : आप उन क पास ही आ जाइए और वहां आ कर उन को मज़बूत कर दीजिए । (The hon. Member should impart strength to the Treasury Benches by joining them.)

बाबू बचन सिंह : अगर यह आप की मर्ज़ी है तो वह भी कर लूंगा । लेकिन इस वक्त एक मिनट में बात कर खत्म कर दूंगा ।

तो मैं लुधियाना के सिलसिले में एक मिसाल देता हूं। वहां पर मैं एक दफा एक सुप्रिंटेंडेंट इंजिनियर से मिला । उसने कहा कि यहां पर दो हज़ार किलोवाट की जगह पर तीन हज़ार किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है । मैंने कहा कि बारह हज़ार का लगाओ । उस ने कहा कि 35 से 49 तक दो हज़ार से तीन हज़ार का नहीं लग सकता आप बारह हज़ार की बात करते हो। मैंने कहा कि आप किस दुनिया में रह रहे हो ? वह पुरानी दुनिया एक तरफ रह गई है । अब ज़माना बदल गया है, आप को भी बदलना होगा । वही हुआ । लुधियाना की आप हालत देखें । वहां किस तरह से इंडस्ट्रियलाईजेशन हो रही है । अब 32 से 48 और 48 से 60 हज़ार किलोवाट का विचार हो रहा है। इसी तरह से मैं यह कहूंगा कि आप बिजली का भी मुकम्मल इन्तज़ाम कीजिए । लोग आप को पूरा तुआवन देंगे, आप को अनसटिंटिड कोआपरेशन मिलेगी । आपका फर्ज़ है आप लोगों की जरुरियात को समझने की कोशिश कीजिए और उन को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जय हिन्द ।

चौधरी हरकिशन (हस्सनपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज एक बड़ा अहम मसला हाउस में ज़ेरे ग़ौर है । अगर मैं पिछले सालों की तरफ हाऊस की तवज्जो दिलाऊं तो आप देखेंगे कि जहां पर सन 1956-57 में फलड कंट्रोल, ड्रेनेज और ऐन्टी वाटर लागिंग की स्कीमों पर सिर्फ सात लाख रुपया खर्च किया गया था वहां पर सन् 1963-64 में 816.20 लाख और 1964-65 में 6.24 करोड़ रुपया खर्च किया गया । लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि ज्यूं ज्यूं इलाज करते जाते हैं त्यूं त्यूं फलड का मसला बढ़ता ही जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह तो वही बात है कि—

मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की

चूंकि वक्त थोड़ा है, इसलिए मैं आप की सेवा में सिर्फ जिला गुड़गांव की बाबत ही अर्ज़ करूंगा । वहां पर सन् 1957-58 में गौंछी ड्रेन को बनाने का काम

[चौधरी हर किशन]

शुरू किया गया । लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक वह ड्रेन मुकम्मल नहीं हो पाई । इस के लिए अगर मैं यह कहूं कि महकमा ड्रेनेज के अफसर की नातवज्जो और लापरवाही ही जिम्मेदार है तो बेहतर होगा। इस ड्रेन की कुल लम्बाई 46 मील है । लेकिन मौज़ा बंचारी से आगे पानी जाता ही नहीं। इस ड्रेन की खुदाई कहीं कहीं पर बीस बीस फुट है लेकिन कहीं कहीं पर छः छः इंच भी नहीं। इस का नतीजा यह होता है कि जब बरसात में फलड आता है तो इस मौज़े से आगे ड्रेन का पानी ठीक तरह से नहीं पहुंचता और बेइन्तहा नुक्सान होता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस ड्रेन की सात लिंक ड्रेन्ज हैं। ये सभी अभी तक भी नामुकम्मल पड़ी है । मैं बीसियों बार यह बात गवर्नमेंट के नोटिस में ला चुका हूं । मिनिस्टर साहिब को भी मौके पर दिखाया गया है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई । जो अफसर गलत रिपोर्ट भेज देते हैं कि काम मुकम्मल है उन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती । मैंने एक सवाल जिसका नम्बर स्टार्ड 6562 था पिछले सैशन में किया था । उसका जवाब 23 सितम्बर 1964 को दिया गया कि जितनी इसकी लिंक ड्रेन्ज हैं वह तकरीबन तकरीबन सब मुकम्मल ही हो गई है । लेकिन आप यह सुनकर हैरान होंगी कि एक हस्सनपुर ड्रेन है । उस के बनाने के लिए अभी तक सारी जमीन भी एक्वायर नही की गई। मैं हैरान हूं कि असलियत के बरखिलाफ क्यों इस तरह से जवाब दिए जाते हैं । इतना ही नहीं जो अफसर गलत जवाब देते हैं उन के खिलाफ सख्त और फौरी तौर पर ऐक्शन लिया जाना चाहिए । मैं आप के ज़रिए दरखास्त करूंगा कि जिन लिंक ड्रेन्ज का बैड लैवल अभी तक उंचा है उनकी ठीक तरह से खुदाई करके उन को पूरा किया जाए ताकि उन का पानी गौंछी ड्रेन में जा सके और वहां पर भी खुदाई को ठीक किया जाए । इस तरह से जो तबाही और नुक्सान होता है उसको बचाया जाए । मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरफ जरुर ध्यान दिया जाएगा ।

इस के अलावा जो दूसरी तबाही हमारे इलाके में आती है वह यू. पी. की ड्रेन्ज़ की वजह से है । वहां पर यू. पी. की कोई 15 के करीब ड्रेन्ज़ है जो तबाही मचाती है । ये ड्रेन्ज यू. पी. सरकार ने अपनी नहर आगरा और इसकी डिस्ट्रिब्यूटरीज़ की प्रोटैक्शन के लिए बनाई थीं । लेकिन आजकल इन ड्रेन्ज़ से हमारे इलाके में फलड आ जाते हैं । मिसाल के तौर पर एक पंजाब की ड्रेन 'दीघौट' ड्रेन है । उसका आउटफाल पिंगौर ड्रेन में है जो यू. पी. की है। पिंगौर ड्रेन का आउटफाल गौंछी ड्रेन में पड़ता है । जब तक पिंगौड ड्रेन चार फुट गहरी न खोदी जाएगी तब तक वह दीघौट ड्रेन के पानी को ऐबज़ार्ब नहीं कर सकती । लेकिन इस पर हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान की तरफ से एतराज़ यह उठाया जाता है कि चूंकि यू. पी. की ड्रेन है उस लिए हम इस पर कोई पैसा नहीं खर्च कर सकते और न ही इसमें तब्दीली वगैरा कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले जून में यू. पी. के नुमाइन्दों के साथ एक मीटिंग भरतपुर में हुई थी । उस में यह फैसला किया

गया था कि अगर इन यू. पी. की ड्रेन्ज़ पर पंजाब सरकार पैसा खर्च कर ले और ठीक कर ले तो उन को कोई एतराज नहीं होगा। जब मिनिस्टर साहिबान के पास जाते हैं तो वह तो यह कह देते हैं कि हम यह काम कर देंगे लेकिन अफसर कहते हैं कि हमारे पास इस तरह के कोई आर्डर नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरह के लीतोलाल को खत्म किया जाना चाहिए और मुनासिब कदम उठाकर उस इलाका को इस तबाही से बचाया जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा आप यह सुन कर हैरान होंगी कि पिछले साल दीघौट ड्रेन को खोदा गया लेकिन पिंगोर ड्रेन को डीपन और वाइडन नहीं किया गया तो इस का नतीजा यह हुआ कि चार पांच गांव यानी दीघौट, मीतनाल, औरंगाबाद, रादास्का वगैरह पानी की वजह से बिल्कुल तबाह हो गए क्योंकि दीघौट ड्रेन का पानी पिंगोर ड्रेन के ज़रिए ही गौंछी ड्रेन में जा सकता है और उस की खुदाई न होने के कारण वह पानी वहीं रुक गया था। इस सम्बन्ध में जब चण्डीगढ़ सितम्बर, 1964 में मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में मिस्टर सिन्धू जो चीफ एनजेनीयर हैं तशरीफ लाए थे तो उन से मैंने उस इलाके के फल्ड के बारे में कहा तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि अक्तूबर तक दीघौट गांव इत्यादि का सारा पानी निकाल दिया जाएगा लेकिन आज तक दीघोट गांव का पानी नहीं निकाला गया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप चल कर देख सकती ह कि वहां पर वह पानी अब भी खड़ा है और इस की वजह यह है कि दीघौट और पिंगोर दोनों ड्रेनें अभी तक ना मुकम्मल पड़ी हुई हैं।

दूसरी चीज़ जिस की तरफ में हाउस का और वज़ीर साहिब का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे जिला गुड़गावां का 64 फीसदी रकबा आगरा कैनाल से सैराब होता है। आप सुन कर हैरान होंगे कि ज़िला गुड़गावां पंजाब का हिस्सा होते हुए भी वहां के लोगों को आबयाना बाकी पंजाब के लोगों से दुगना और तिगुना देना पड़ता है। मैं आप की मारफत हाउस को आबयाने के वह रेटस बताना चाहता हूं जो वहां के लोगों को देने पड़ते हैं जो आगरा कैनाल के पानी से अपनी जमीनों में खेती करते हैं और जो बाकी पंजाब के लोगों को आबपाशी के लिए आबयाना देना पड़ता है :

	आगरा कैनाल के पानी से जो आबयाना फी एकड़ देना पड़ता है	पंजाब के बाकी इलाको में नहरों के पानी पर फी एकड़ जो आबयाना देना पड़ता है
	रुपए	रुपए पैसे
गन्ना ..	32	16.50
संघाड़ा ..	14	11.25

[चौधरी हरकिशन]

		आगरा कैनाल के पानी से जो अबयाना फी ऐकड़ देना पड़ता है	पंजाब के बाकी इलाकों में नेहरों के पानी पर फी एकड़ जो आबयाना देना पड़ता है
		रु०	रु० पैं०
चावल	..	14	9.75
मसालेदार अशिया	..	12	8.25
बागात व सबजीजात	..	14	8.25
जौ जवी	..	12	6.37
गंदम	..	12	5.84
खरबूजा	..	9	7.50
मक्की	..	7	6.50
तिल	..	9	6.37
सौंफ	..	14	
तारा मीरा	..	9	
तोरिया	..	14	
मट्टर, बाजरा मांश और मूंग	..	9	4.88
चने	..	9	4.47
और चारे पर	..	3	3.57

देने पड़ते हैं ।

तो इस तरह से डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे ज़िला गुड़गावां के लोगों के साथ डिसक्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट किया जा रहा है । मैंने सितम्बर, 1964 में एक प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में अपने माल मंत्री जी को दिया था और उन्होंने मुझे बड़ा सिम्पेथैटिकली हीयर भी किया था और यकीन दिलाया था कि यह डिसक्रिमिनेशन खत्म कर दिया जाएगा लेकिन आज तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया । मैं कहता हूं कि जब हम पंजाब में बाकी जिलों के लोगों की तरह से रहते हैं तो हम से आबयाना ज्यादा रेट पर क्यों लिया जाता है और अगर सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार को ज्यादा

रेट पर यह देना ही पड़ता है तो इसे चाहिए कि लोगों से यह उसी रेट पर ले जिस रेट पर यह पंजाब के बाकी इलाकों के लोगों से लेती है और बाकी रकम अपने पास से डाल कर पूरी कर देनी चाहिए ।

इस सम्बन्ध में मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिला में पंजाब के कुछ दूसरे इलाकों की तरह अकसर फलडज़ आते रहते हैं और पंजाब सरकार उन जमीनों का लगान और आबयाना मुआफ कर देती है जहां 50 फीसदी नुकसान हुआ होता है लेकिन हमारे इलाका के लोगों को लगान तो मुआफ कर दिया जाता है लेकिन आबयाना इस लिए मुआफ नहीं किया जाता क्योंकि वह उत्तर प्रदेश की सरकार को देना होता है । इस लिए मैं अर्ज़ करता हूं कि जब हम भी पंजाब के रहने वाले हैं और जब पंजाब के दूसरे जिलों के लोगों को जहां फलडज़ से 50 फीसदी से ज़्यादा नुकसान होता है आबयाना और लगान दोनों मुआफ कर दिए जाते हैं तो हमारा आबयाना माफ क्यों नहीं किया जाता । यह डिसक्रिमिनेशन भी दूर होनी चाहिए । हमारे इलाके में कई ऐसे गांव हैं जहां 70 फीसदी या इस से भी ज़्यादा नुकसान फलड़ज से होता रहा है लेकिन उन से पूरा आबयाना वसूल होता रहा है और अब भी हो रहा है। मैंने इस बारे में मिनिस्टर साहिब को लिखा था कि यह डिसक्रमिनेटरी ट्रीटमेंट हमारे जिला के लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है । परन्तु अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है।

इस के बाद मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके की ड्रेन्ज़ के मसले को हल किया जाए और खास तौर पर डिगोट और पिंगोर की जो दो ड्रेनज़ हैं इन को डीपन और वाईडन किया जाए । इसी तरह से सिलोठी की जो ड्रेन है इसको डीपन और वाइडन किया जाए तो सिलोठी, अटोहां, व वारणी खेड़ा, लाड़ीयाका, नंगल ब्राह्मण आदि गांवों में से फलड वाटर को निकाला जा सकता है और इस में सिर्फ एक मील लम्बी खुदाई करनी पड़ती है । मैं इस सम्बन्ध में मिनिस्टर कनसर्नड स भी मिला था तो उन्होंने कहा था कि यह खुदवा दी जाएगी लेकिन जब मैं सरदार मनोहर सिंह जो एक्स० ई० एन० कनसर्नड हैं से मिला तो वह कहने लगे कि यह कैसे हो सकता है, मिनिस्टर साहिब तो ऐसे ही कह देते हैं हमें तो फाइनांस डिपार्टमेंट मंजूरी जब तक नहीं देता यह कैसे खोदी जा सकती है । इस लिए मैं कहता हूं कि जब तक फाइनांस डिपार्टमेंट इस तरह से अपनी लात बीच में अड़ाता रहेगा तो उस वक्त तक यह ड्रेन्ज़ खोदी नहीं जाएगी और हमारे इलाका को फलडज़ से नहीं बचाया जा सकेगा ।

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायेंट आफ आर्डर, मैडम । अभी चौधरी हरकिशन ने कहा है कि ज़िला गुड़गावां के लोगों के साथ डिसक्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो रहा है तो जब मैंने मिनिस्टर साहिब को कहा है कि आप के राजदुलारे यह कह रहे हैं तो इन्होंने कहा है कि यह ऊपर ऊपर से कहते हैं दिल से नहीं कहते हैं । अगर यह बात है तो मैं आप से दरखास्त करूंगा कि टैरेयरी बैंचों वालों को कुछ कहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए ।

उपाध्यक्षा : यह कोई प्वायंट आफ़ आर्डर नहीं है । (It is not a point of order.)

चौधरी केसरा राम (डबवाली एस. सी.) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज आबपाशी और ड्रेन्ज़ की मद पर बहस हो रही है। पानी एक ऐसी चीज है जिस से इनसान की ज़िन्दगी बन भी सकती है और तबाह भी हो सकती है और हालत पंजाब में यह है कि जहां पानी की ज़्यादा ज़रूरत है वहां यह पहुंचता नहीं और जहां इस की ज़रूरत नहीं है वहां यह बहुत है। और जहां पानी पहुंचता है वहां ज़्यादा पानी होने की वजह से पैदावार नहीं होती और जहां यह पहुंचता नहीं वहां सूखे की वजह से पैदावार नहीं होती। सरकार ने भाखड़ा डैम पर दो अरब रुपए खर्च किए हैं जिस से ज़्यादातार फायदा ज़िला हिसार को होना था। यह ठीक है कि वह सूखा इलाका, जहां पानी की भारी मांग थी वहां कुछ न कुछ पानी पहुंचा है लेकिन असल हालत ऐसी है कि हमारी सरकार तो खुले दिल से और फराखदिली से उन इलाकों को पानी देने के लिये खर्च करती है लेकिन जो उस रुपये को इस्तेमाल करने वाले अफसर हैं वह उस को ठीक तरह से खर्च नहीं करते और उसे बरबाद कर देते हैं और यही रुपया हमारे इलाके के लिये मुसीबत का कारण बन जाता है। हमारे इलाका में एक घघर दरिया है जिस में लातादाद ड्रेनज़ इन्होंने डालनी शुरू कर दी हैं और इस दरिया के पानी को कन्ट्रोल नहीं किया गया और उस दरिया के पानी को आगे निकालने के बारे में तो सोचा ही नहीं गया लेकिन उस में कई ड्रेनज़ डाल दी गई हैं, जिस का नतीजा यह हुआ है कि इस दरिया के पानी से कई गांव डूब गए हैं और वहां कई इलाके तो ऐसे हैं जहां लोग पानी के लिये तरसते हैं और उन्हें पानी नहीं मिलता।

(इस समय अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर विराजमान हुए)

स्पीकर साहिब, अभी मैं अपने हल्के से हो कर आया हूं और मैं अपने मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करता हूं जो इस वक्त हाउस में बैठे हुए हैं कि महकमा नहर की तरफ से जितने भी आदादो शुमार दिये जाते हैं वह सारे के सारे गलत होते हैं (आपोज़ीशन के बैंचों से तालियां) मैं इस बारे में आपको सबूत देना चाहता हूं। ऐसी ऐसी मिसालें हमारी नज़र में आई हैं कि ज़मीन तो सिर्फ 5 एकड़ होती है लेकिन आबपाशी की परची 22 एकड़ की पटवारी दे देता है। जब मुताल्लिका आदमी उस के पास जाता है तो कोई सुनवाई नहीं होती। उसे कहा जाता है कि आब्याना तो उसे इतना देना ही पड़ेगा अगर नहीं चाहता तो फाइनैंशल कमिश्नर के पास अपील कर लो। इस लिये मैं चौधरी साहिब से अर्ज़ करता हूं कि भला एक मामूली किसान आब्याना ज़्यादा लग जाने पर फाइनैंशल कमिशनर के पास कैसे अपील कर सकता है। इस लिये आबपाशी के लगान की पड़ताल के लिये इन्हें कोई कमेटी बनानी चाहिए जो इस बारे में पड़ताल करे। जितने आदादोशुमार महकमा नहर की तरफ से दिए जाते हैं वह गलत होते हैं उन की पड़ताल की जानी चाहिए। यह सब कुछ नहर के पटवारी करते हैं जिन की तनखाह सरकार ने अभी अभी बढ़ा कर 175 रुपए तक कर दी है। इस लिए मैं सरकार से अर्ज़ करूंगा कि वह इस बारे में कोई ठोस कदम उठाए। और अगर यह पैदावार बढ़ाना चाहती है तो किसानों को पानी, खाद और अच्छे बीज दिये जाने चाहिएं। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो बताओ कोई डाक्टरी नुसखा है कि जिस से

उस की पैदावार बढ़ेगी ? यहां तो पानी का सवाल है। यह कहीं पर तो इतना ज़्यादा है कि तबाही लाता है और कहीं इस को लोग तरसते हैं। फिर खाद की बात है इस का ऐसा नाकस इन्तजाम है कि यह किसानों को सप्लाई नहीं होती। हालांकि सरकार इस पर करोड़ों रुपया खर्च करती है। इस बारे में सरकार को पूरा २ ध्यान देना चाहिए कि इस रुपए का इस्तेमाल सही हो।

अब मैं ड्रेनज़ के बारे में भी कुछ अर्ज कर दूं। मैं समझता हूं कि इस बारे में हमारे टैक्नीकल लोगों को कोई समझ नहीं है। लसाड़ा ड्रेन सौ मील लम्बी कर दी जब कि पहले यह जिन इलाकों से गुज़रती थी उन सूखे इलाकों को पानी मिल सकता था मगर किया यह कि उस ड्रेन को जा कर राजस्थान के इलाके में डाल दिया गया और अब दो महीने से राजस्थान के साथ झगड़ा चल रहा है और हालत यह है कि सिरसा के इलाके को तबाह कर दिया गया है। चौधरी साहिब से दरखास्त करूंगा कि इस बारे में कोई ठोस कदम उठाएं ताकि उस इलाके के लोगों की ज़िन्दगी को बचाया जा सके। सिरसा और हिसार के इलाके में खुश्कसाली की वजह से कहत पड़ रहा है और लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं मगर नहरों से बारी पर पानी मिलता है मगर दूसरी तरफ लोग पानी की वजह से रोते हैं कि भाई इस को ले जाओ। तो सरकार ऐसी स्कीमें बनाए कि जहां पर पानी ज़्यादा है वहां से पानी ले जाकर खुशकसाली वाले इलाके में दिया जा सके इस के साथ ही साथ पटवारियों के ज़ुल्म से लोगों को बचाया जाए।

एक और सजैशन मैं चौधरी साहिब को देना चाहता हूं। वह जो इलाका है वह रेतीला है और इतना पानी नहीं है कि खेतों तक जा सके। इस का एक इलाज है। आप ने बजट में करोड़ों रुपया खर्च करने के लिये रखा है तो यह निहायत ज़रूरी है कि नहर के खालों को पक्का किया जाए। इस तरीके से बहुत से पानी को बचा कर खेतों को दिया जा सकता है।

फिर इस साल फसल का खराबा बहुत है। उन को कहा गया है कि 20 फरवरी तक इस के लिये दरखास्त दो। वह लोग हैं बेचारे अनपढ़ तो वह दरखास्त कैसे दें। इस लिये उन को और ज़्यादा टाइम देना चाहिए और इस तारीख को 20 मार्च कर दिया जाए या फिर इस काम पर आप किसी अफसर को लगा दो जो मौके पर खराबे की तफतीश कर के उस को दर्ज कर ले वरना हालत यह है कि लोगों को तो फसल से आब्याना भी पूरा नहीं हो सकेगा। सारी की सारी फसल खराब हो गई है।

एक और यह बात है कि वहां पर दो लैवी लगा रखी हैं एक खुश हैसियती और दूसरी बैटरमैंट। दोनों एक ही चीज़ हैं। एक उर्दू का लफ़्ज़ है तो दूसरा अंग्रेजी का। एक पांच रुपए और दूसरी 10 रुपये लगा रखी है। लोगों ने काफी देर से दरखास्तें दे रखी हैं कि इस का फैसला किया जाए मगर अभी तक बैटरमैंट लैवी का फैसला नहीं किया गया। उन लोगों को पता नहीं कि उन को क्या कुछ देना है। इस सारे मामले को खटाई में नहीं डालना चाहिए। लोग हम से पूछते हैं कि उन को क्या देना होगा मगर हम उन को क्या बताएं जब इस का फैसला ही नहीं हुआ। लोगों ने दो दो सौ फी एकड़ रुपया दिया है मगर इस बात का अभी तक फैसला नहीं किया गया, यह जल्दी होना चाहिए।

[चौधरी केसरा राम]

एक बात मैं लसाड़ा ड्रेन के बारे में और कहना चाहता हूं। यह जो ड्रेन है इस को बठिंडा से डभवाली सड़क पर से दो दफा गुजारा गया है। यह अफसरों की नालायकी है और मैं समझता हूं कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कमेटी बना कर कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी तरह से जिन पटवारियों ने गलत इन्दराज किये हैं, गलत गिरदावरियां की हैं उन के खिलाफ भी ऐक्शन लेना चाहिए। खाद को जमींदारों तक पहुंचाया जावे। बैटरमैंट लैवी का फैसला किया जावे ताकि किसान खेती में दिलचस्पी ले सकें। आबपाशी के सही इन्दराज देखने के लिये हर डिवीज़न में एक कमेटी बनाई जावे ताकि किसानों पर नाजायज़ बोझ न डाला जा सके। आप का शुक्रिया।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕ ਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : He wants to make some important statement.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਇਨਟਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : If the Government wants to make some important statement they can do it.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕਿਸ ਦਫਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। (The hon. Member may please resume his seat. I will let him know.) (*Interruptions*)

चौधरी मुख्तयार सिंह मलिक : मैं यह पूछना चाहता हूं क्या कोई ऐसा प्रीसीडैंट है कि इस तरह से इन्ट्रप्शन की जा सकती है (विघ्न) or you want to create new precedents ?

Mr. Speaker : Rule 64 of the Rules of Procedure lays down

> "A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the permission of the Speaker but no questions shall be asked nor discussion take place there on at the time the statement is made."

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਡਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਕ ਦੇਣ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੋ। ਆਮ ਪ੍ਰੌਸੀਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਨ-ਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੌਜੁਡਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। It may prejudice the case.

श्री बलरामजी दास टंडन : हाउस का टाइम इतना ही ऐक्सटैंड कर दिया जाये।

Mr. Speaker : I will not extend the time.

Shri Balramji Das Tandon : Then the Government should not make the statement.

Mr. Speaker : I can agree only to this कि जितना time Chief Minister साहिब की statement में लगेगा उतना हाउस को extend कर दूंगा (I can agree only to this that I will extend the sitting for the period which the Chief Minister takes in making his statement).

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, you were pleased to refer to Rule 64 of the Rules of Procedure. Well, we do not question the discretion of the Speaker in allowing the Chief Minister and any member of the Cabinet to make a statement. The only point involved in the case is whether during the discussion on a particular Demand a statement not relating to that Demand can be made by the member of the Cabinet even with the permission of the Speaker.

Mr. Speaker : Yes, yes.

With regard to the discussion on the Demand any Minister can intervene.

Chief Minister : (Shri Ram Kishan) :

[* * * * * *

* * * *]

Sardar Gurnam Singh : On a point of Order, Sir. Are these the offenders, culprits and killers or only the alleged offenders, culprits, killers, etc. ? By saying them as culprits/killers, we are doing the work of a court of law. The executive have themselves decided that they are offenders.

Chief Minister : The word "alleged" may be added before the word 'principal' as also before the word 'killer'.

Sardar Lachhman Singh Gill : Sir, the word "alleged" does not appear in the statement which has been distributed among the Members.

Mr. Speaker : The hon. Chief Minister has amended the statement.

Chief Minist :

[* * * * *

* * * *

* * * * *]

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। आप किसी को किलर नहीं कह सकते और न ही अफैन्डर कह सकते हैं जब तक कि यह साबित ना हो जाए।

Mr. Speaker : The Chief Minister has already amended it.

Note. Expunaged as ordered by the Chair.

Baboo Bachan Singh : On a point of order, Sir. The case is *sub-judice* and a positive statement cannot be made here on the Floor of the House.

Sardar Gurnam Singh : Unfortunately, the Government is establishing the murder here on the Floor of the House instead of in a Court of Law. This, Mr. Speaker, is an indiscreet statement..

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a point of order, Sir. Sir, you have been an Advocate yourself. Is it, Sir, not a discussion on the merits of the case which is *sub-judice*. ?

Sardar Gurnam Singh : Sir, we are establishing a bad practice.

Chief Minister : Mr. Speaker, Sir, I would request that the words..

[* * * * * *
* * * * * *]

be deleted from the statement if there s any objection.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । जो स्टेटमैन्ट चीफ मिनिस्टर साहिब दे रहे हैं यह सारी की सारी एक सबजुडिस मामले से ताल्लुक रखती है। इस लिये इस को हाउस की प्रोसीडिंगज़ से ऐकसपंज किया जाये। क्योंकि रीकार्ड आफ दी हाऊस पर आ जाने से इस बात की जिम्मेवारी हम सब प आ जायेगी We will become a party to the case.

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਕ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼: ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਟੇਟ-ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੀ. ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ

[* * * *
* * * *]

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਤੁਸੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਉਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਰੀਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

*Note :—These words stand expunged in view of the orders of the Chair to expunge the statement read out by the Chief Minister.

***Note*— Expunged in view of the order of the Chair to expunge the statement read out by the Chief Minister.

ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat. A copy of the statement has been given to me just now. I will go through it before I allow the hon. Chief Minister to proceed further with the statement. I will call the Advocate-General in my Chamber and will discuss the matter with him (Cheers). In the meantime, the discussion on the Demands for Grants will continue (Cheers).

Whatever portion of the statement has been read over by the hon. Chief Minister will *not form part of the record of the proceedings of the House unless I allow it.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

चौधरी देवी लाल : आप के इस फैसला करने के बाद मैं आप की रूलिंग चाहूंगा कि क्या यह मौजूदा मिनिस्टरी के खिलाफ नो कनफीडेंस नहीं साबित होता ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a point of order, Sir. The statement, a protion of which has been read over by the hon. Chief Minister, has been distributed among the hon. Members of this House. May I know, Sir, whether it would be deemed to have been read because it has already been distributed. I would like to have your ruling.

Mr. Speaker : I would request the hon. Member, Pandit Chiranji Lal Sharma to wait for a few minutes. Let me consider the whole matter. I will consider all the legal aspects.

Now I call upon the hon. Minister for Public Works and Welfare. to Speak.

Voices : No. No.

(*Interruptions and noise in the House*).

सरदार रणजीत सिंह नैनावालिया ; स्पीकर साहिब, अभी तो इस डिमांड पर बहस खत्म ही नहीं हुई कि आप ने मिनिस्टर साहिब को जवाब देने के लिये कह दिया है। अभी तो हम सब ने बोलना है।

Mr. Speaker : Much of the time of the House has been taken on points of order and other things. I cannot help it.

बाबू बचन सिंह : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि पहला $1\frac{1}{2}$ घंटा तो श्री प्रबोध चंद्र और पंडित मोहन लाल की आपसी कशमकश पर खर्च हो गया। अब जब कि इतने बोलने वाले हैं आपने मिनिस्टर इनचार्ज को काल अपौन कर लिया है।

Extension of Time of the Sitting

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the time be extended ?

Voices from the Opposition : Yes, yes, please.

Chief Parliamentary Secretary : You may, Sir, extend the time of the House by half an hour.

---

*Note:—The order to expunge the statement read out by the Chief Minister, was again confirmed by the Chair on 25th March, 1965, when the Home Minister informed the House that the statement of the Chief Minister, copies of which had been distributed on 24th March, 1965, had been withdrawn by Government after taking legal advice. For reference please see P.V.S. debate Vol. I No. 21 dated 25th March, 1965 (Morning Sitting.)

Mr. Speaker : Should the time be extended by half an hour ?

Voices : Yes, yes, please.

Mr. Speaker All right, the time of the House is extended by half an hour.

(*At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair.*)

DEMANDS FOR GRANTS

(*Resumption of Discussion*) (*Not concld*)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀਟਿਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਫਲੈਚਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੇਨਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਪੁਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਹੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫੈਲ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹਿਊਜ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਪਲੈਨਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੰਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ **ਇਸ ਤੋਂ** ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਪਰੈਲ-ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਇਮਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹਨ। ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਖੁਰਦਬੀਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਕਰਾਨਾ ਨਾਲੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ (*Interruptions*) (ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ)।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : On a point of order, Madam. ਕੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ?

ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : [* × × × ×)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰੇਨ ਨੈਚਰਲ ਫਲੋ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਲੰਧਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (Interruption)

**Note* Expunged as ordered by the Chair.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : On a point of order, Madam. क्या कोई ग्रानरेबल मैम्बर इस ग्रागस्ट हाऊस में किसी को ऐसे एड्रैस कर सकता है कि क्या तू ने मेरा (* * *) देखा है ? यह लफज़ सरदार लच्छमन सिंह गिल ने कहे हैं ग्रौर हाऊस की डिग्निटी डिमांड करती है कि यह लफज़ वापस होने चाहियें।

उपाध्यक्षा : ग्राप खुद ही ग्रंदाज़ा लगायें कि इस हाऊस की डिग्निटी क्या रह गई है। This is not an August House. यह तो एक बच्चों का खेल सा हो गया है। (The hon. Member can himself well imagine as to what extent the dignity of this House is now left. It no longer appears to be an August House. It has been reduced to a children's club.)

श्री मंगल सेन : On a point of order, Madam. मैं ग्रापका इस बात पर रूलिंग चाहूंगा कि ग्राया किसी को कोई ग्रपना (* * *) दिखा सकता है ?

उपाध्यक्षा : सरदार लछमन सिंह जी ग्रगर ग्राप ने कोई ऐसे लफज़ कहे तो वापिस लिये जायें You are the Deputy Leader. (If the hon. Member Sardar Lachhman Singh Gill has said any such thing, he should withdraw that. He is the Deputy Leader of his party.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह हाऊस की प्रैस्टीज ग्रौर डिग्निटी का सवाल है। इन्होंने यह कहा है कि जो कुछ ग्राप ने कहा है में वही वापस लेता हूं। Does it amount to withdrawal.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ [* * *] ਦੇਖਿਆ ਹੈ । ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਹਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌ ਦਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।

उपाध्यक्षा : ग्रगर मगर की बात नहीं। (It should be withdrawn unconditionally.

Pandit Charanji Lal Sharma :—He should witndraw the words in unequivocal terms.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਅਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।

---

*Note—Expunged as ordered by the chair.

श्री मंगल सैन : On a point of order, Madam. मैं बड़े अदब से और नम्रता आपका रूलिंग इस बात पर चाहता हूं कि जैसे आप ने कहा है **'This is not an August House'** मैं चाहूंगा कि आप के होते हुए इस हाऊस की डिग्निटी को नुक्सान पहुंचता है ....

उपाध्यक्षा : इस का मतलब यह है कि आप इस हाऊस की कार्रवाई चलने नहीं देना चाहते । (It means that the hon. Member does not want the House to proceed.)

श्री मंगल सैन : मैं तो आपके हाथ मजबूत करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्षा : मेरे हाथ कमजोर नहीं हैं, काफी मज़बूत हैं । (I am quite capable of dealing with the situation)

कैप्टन रत्न सिंह : मेरा प्वायंट ग्राफ आर्डर यह है कि **ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਆਗਸਟ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ।** This is an insult.

उपाध्यक्षा : आप अपने मन में सोचिए कि क्या इस तरह से कोई डिग्निटी इस हाऊस की रह गई है । (The hon. Member should himself realise if such a behaviour as has been witnessed here, is in keeping with the dignity of the House.)

चौधरी अमर सिंह : क्या इस हाऊस में कोई मैम्बर किसी दूसरे मैम्बर को (* * *) दिखा सकता है ? यह जो सरदार लछमन सिंह हैं, इन्होंने सरदार जयइंद्र सिंह को (* * *) दिखाया है । [शोर]

डाक्टर बलदेव प्रकाश : कैप्टन रत्न सिंह ने यह कहा है कि हाऊस की डिग्निटी आप नहीं रहने देतीं यह बड़ा डैरोगेटरी रिमार्क है और यह इनको विदड्रा करना चाहिए ।

उपाध्यक्षा : अगर इन्होंने यह कहा है, तो अपने लफज़ वापिस लें । (If he has said so, he should please withdraw the words.)

कैप्टन रत्न सिंह : मैं ने तो वही दुहराया है, जो कुछ आपने कहा है । अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा अगर कोई और बात है तो विदड्रा करता हूं ।

लाला रुलिया राम : अगर आज एक मैम्बर ने (* * *) दिखाया तो कल यह भी हो सकता है कि वह इसे फेंक भी दे । इसके लिये कोई रोक लगनी चाहिए ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरदार लछमन सिंह गिल ने (* * *) दिखा कर क्या लफज़ वापिस कर लिया है ? (शोर)

*Note—Expunged as ordered by the chair.

उपाध्यक्षा : श्री रिज़क़ राम, देखिये क्या हो रहा है। This is the last warning from the Chair. अगर इस तरह से हालत जारी रही तो मैं हाउस को एडजर्न कर दूंगी (Let the hon. Minister Chaudhri Rizaq Ram see what is happening here. He should control the members of his party. This is the last warning from the Chair. If this state of affairs continues then I will adjourn the House.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਅਫਸਰ ਟਰਕਾਉਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡ੍ਰੇਨਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਗਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਵਿਨਿਊ ਮਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਰਗਾ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਰਮ ਰਵਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਆਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਸੱਤਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਘੇ ਵਿਚੋਂ ਘਸੀਟੋ ਤਾਂ ਮੋਘਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਡੇਰੋਗੇਟਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। (Shame shame from Opposition) ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ?

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿਘ : ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿਰਸਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ।

चौधरी इंद्र सिंह मलिक : On a point of order, Madam। इस हाउस में एक ऐसा इश्तिहार बांटा जा रहा है, जिस में लिखा है कि कैरों कत्ल केस में एक वज़ीर का हाथ है और ....

उपाध्यक्षा : आप बैठ जाइए। सरदार कुलबीर सिंह, आप बोलिये। ((The hon. Member should resume his seat and let Sardar Kulbir Singh proceed with his speech.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਕ ਇਕ ਫਿਕਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਕਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵਾਰਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਡੀਲੇ ਕੀਤੀ

[ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਕਬਾ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੋਘੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਏਥੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ ਮੋਘੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਘੇ ਨਾਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖਦ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਫਨ ਉਚੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸੁਕੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਹਿਰ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਵਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਬਾਹੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੈਡੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਬਾਹੇ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ।

श्री मंगल सैन : On a point of order, Madam. डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह पोस्टर हमें दिया गया है जिस में लिखा है "कैरों साहिब के कत्ल में एक मंत्री महोदय का हाथ है" उस में आगे लिखा है "लुधियाने के एक करोड़पति मिल मालिक ...."

(*Interruption*)

Deputy Speaker :—Will you please take your seat? मैं पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगी। आप इसे टेबल पर रख दें। (Will you please take your seat ? I do not allow it to be read. You may place it on the Table.) (Noise).

श्री मंगल सैन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस को हाउस की टेबल पर रखता हूं। (शोर)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : On a point of Order, Madam. ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

Deputy Speaker : Please resume your seat.

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? (ਸ਼ੋਰ)

श्रीमती प्रेम प्रभा जैन : On a point of order, Madam. डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन्होंने किस बेसिज पर वह पैम्फलैट हाऊस की टेबल पर ले किया है ? क्या आपकी इजाजत इस मामले में उनको है ?

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : यह अब हाऊस की प्रोपर्टी बन चुका है क्योंकि टेबल पर ले कर दिया गया है। (शोर)।

Deputy Speaker : Please resume your seat. Pandit Chiranji Lai Ji, I seek your help.

Chaudhri Darshan Singh : Madam, I rise on a point of order.

Deputy Speaker : Excuse me. I am not going to permit you. Will you please take your seat?

Chaudhri Darshan Singh : Madam, I want your ruling on a particular point.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਦੋ ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ point of order raise ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ part of the proceedings of the House ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ brush aside ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਦਿਉ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀ ਹੈ। (Let me see what that poster (contains.)

Chaudhri Darshan Singh : Madam, till your ruling it should not form part of the proceedings of the House .

Deputy Speaker : Order, order.

6.10 p.m. *(Interruptions and noise)*

Deputy Speaker : I adjourn the House.

(The House then adjourned and reassembled at 6.40 *p.m.)*

Mr. Speaker : Comrade Jangir Singh 'Joga'.

Sardar Lakhi Singh Chaudhri : On a point of order, Sir. The House was adjourned and no time limit was fixed.

Mr. Speaker : It was adjourned for half an hour only.

Sardar Lakhi Singh Chaudhri : Sir, all the hon. Members of the House will bear me out that it was not adjourned for half an hour.

Mr. Speaker : It was adjourned for half an hour only.

श्री मंगल सैन : श्रान ए प्वायंट श्राफ श्रार्डर, सर, मैं श्राप का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यहां पर एक बात श्राई श्रौर उसके ऊपर श्रौर बातें होती रहीं। इस पर डिप्टी स्पीकर साहिबा ने कहा कि 'I adjourn the House' उन्होंने हाऊस एडजर्न करते वक्त न कोई टाइम बताया श्रौर न कोई दिन बताया कि कब

[श्री मंगल सेन]

तक के लिये एडजर्न किया गया है। उनके इस तरह हाउस एडजर्न करने से वैधानिक स्थिति जो अब पैदा हो गई है वह यह है कि अब हाउस को समन करने के लिये गवर्नर साहिब की तरफ से समन जाना ज़रूरी है इस के बाद ही यहां पर कोई कार्यवाही हो सकती है। अगर ऐसा न किया गया तो जितनी कार्यवाही भी अब इसके बाद होगी वह अवैधानिक होगी। यह बात सही तौर पर आपके ध्यान में ला दी है और आप इस पर अपना रूलिंग दें।

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat.

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਦੇ ਉਪਰ ਅਜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। (ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : Order, please.

श्री मंगल सेन : यह तो दूसरी बात है। पहली बात तो यह है कि यह मीटिंग जो हो रही है अवैधानिक है और . . . . . . (शोर, विघ्न)

Mr. Speaker: I have verified from the Deputy Speaker that the House was adjourned for half an hour only.

Voices : No, no.

Mr. Speaker : It was adjourned for half an hour.

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहिब, यह एक अहम कन्स्टीट्यूशनल प्वायंट है इस पर ज़रूर रूलिंग आना चाहिये आगे आपकी मर्ज़ी है। सही बात यह है कि डिप्टी स्पीकर साहिबा ने कहा था " I adjourn the House."

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਐਡਜਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਡਜਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚ ਐਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਜੁੱਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਸੇ। ਮੈਂ ਜੁਰੱਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। I will resign my seat if it is wrong.

ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Sardar Lakhi Singh Chaudhri : Sir, I would request that the sanctity and the dignity of the House may be maintained.

Mr. Speaker : Shrimati Shanno Devi, Deputy Speaker, was presiding over the meeting of the Sabha when it adjourned. She was in the Chair. It was she who adjourned the House. I have verified from her. It was adjourned for half an hour only. That ruling of the Chair has to be implemented. As the House was adjourned for half an hour only, this meeting of the Sabha is proper and in order.

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।

Mr Speaker : Now I will not listen to any point of order in this connection. I have already given my ruling.

चौधरी मुख्तयार सिंह मलिक : मेरी आप बात तो सुन लें। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस हाऊस के सारे के सारे मैम्बर झूठे हैं फिर तो ठीक है वरना अगर कहीं सचाई बाकी है तो कोई मैम्बर खड़ा होकर अपनी छाती पर हाथ रख कर कह दे कि एडजर्न करते वक्त कोई टाइम बताया गया था। आप रिकार्ड देख सकते हैं कि कोई टाइम नहीं दिया गया है........ (शोर)

Mr. Speaker : The hon, Member should please resume his seat. I have given my ruling. Now we will proceed in accordance with that ruling. Their will be no further discussion in this connection.

(Interruptions and Noise in the House. Many hon. Members rose on Points of Order).

श्री मंगल सेन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, यह बड़ी सीरियस बात है। इस हाऊस में खड़े हो कर एक मैम्बर साहिब ने यहां तक भी कह दिया है कि अगर यह बात गलत हो तो वह त्यागपत्र दे कर चले जायेंगे। यही सही बात न सिर्फ हम ने ही कही है बल्कि उधरसे कैप्टन साहिब, चौधरी लखी सिंह और दूसरों ने भी कही है। इस लिये मेरी अर्ज़ है कि हमारी बात को स्वीकार करें। बीबी जी ने उस वक्त चेयर से यह नहीं कहा था कि आधे घंटे के लिये हाऊस एडजर्न करती हूं। हम ने सारी बात बड़े गौर से अपने कानों से सुनी है और अपनी आंखों से देखी है।

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : स्पीकर साहिब, जब हाऊस एडजर्न हुआ मैं बाहर था। मैं अपने कागज़ उठाने के लिये जब अन्दर आया तो सब से पहले मुझे मंगल सैन जी ही मिले। मैं ने उन से पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने किसी इश्तिहार वगैरा का झगड़ा बताया। फिर मैं ने पूछा कि अब किस वक्त मीट करेंगे तो उन्हों ने कहा after half an hour. । (शोर)

श्री मंगल सैन : आन ए प्वायंट आफ परसनल ऐक्सपलेनेशन, सर। ढिल्लों साहिब, एक प्रकार से मेरे गुरू हैं और जब वह ऊपर उस कुर्सी पर बैठते थे तो मैं ने उन से काफी पारलियामैन्टरी प्रोसीजर सीखा तो मेरी अर्ज़ है कि जब उन्हों ने मुझ से यह बात पूछी तो

[श्री मंगल सेन]
मैं ने उनको यही बताया कि बीबी जी अब मैम्बरान से पूछने पर कह रही हैं कि आधे घंटे के लिये एडजर्न किया है लेकिन हम ने यही सुना है कि उन्हों ने सिर्फ यही कहा कि मैं हाऊस एडजर्न करती हूं।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੋਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗੇ ਚਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ)

चौधरी मुख्तयार सिंह मलिक : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरी अर्ज़ यह है कि इस हाऊस के अन्दर दो वर्शन्ज़ आये हैं। एक हियर से का है जो ढिल्लों साहिब और प्रेम सिंह जी ने दिया है और दूसरा उन मैम्बरान की तरफ से आया है जो उस वक्त यहां मौजूद थे। जितने मैम्बर उस वक्त यहां हाऊस में मौजूद थे अगर उन में से कोई कस्म खा कर खड़ा हो कर यह जुर्रत से कह दे कि हाऊस एडजर्न करते वक्त कोई टाइम दिया गया था तो मैं इस सीट से अस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। (तालियां) आखिर कोई इस हाऊस की सैंकटिटी भी होनी चाहिये। यह क्या तमाशा है। क्या कोई सचाई बाकी रह भी गई है कहीं या नहीं...... (शोर) .... कल का अगर अखबार वाले मछली मारकिट का नजारा लिखेंगे तो प्रिवलिज मोशन ले कर आ जायेंगे लेकिन आप खुद देख लें जो हालत यहां पर हो रही है जो कुछ हाऊस में हो रहा है उसे देख कर निहायत अफसोस हो रहा है। यह पंजाब के कैरैक्टर पर रिफलैक्ट करता है। टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा गया। गर्ग साहिब एक एक मैम्बर से मिल कर कहते रहे कि ठहरो आधे घंटे के लिये एडजर्न हुआ है वरना सारे मैम्बर जा रहे थे। इस हाऊस की भी कोई सैंक्टिटी होनी चाहिये, अगर असैम्बली की प्रोसीडिंग्ज़ का यह हाल है तो पंजाब की जनता का क्या हाल हो सकता है।

कामरेड राम चन्द्र : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अगर डिप्टी स्पीकर साहिबा ने 'House Stands adjourned' कहा होता तो हाउस के सारे मैम्बर घरों को चल दिये होते। हाऊस में सारे के सारे मैम्बर मौजूद हैं, इस से साफ जाहिर होता है कि डिप्टी स्पीकर ने हाऊस आधे घंटे के लिये ऐडजर्न किया था। स्पीकर साहिब, मैं आपकी विसातत से हाऊस के तमाम मैम्बरों से अपील करना चाहता हूं कि हाऊस की डिग्निटी को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी स्पीकर साहिबा के हुकम को मानना चाहिये, उन के हुकम के मुताबिक हाऊस 1/2 घंटे के बाद फिर इक्ट्ठा हुआ है। इस लिये इस कंट्रोवर्सी को छोड़ कर हाऊस की कार्यवाही बाकायदा चलाई जाये। तमाम पार्टीज़ के इख्तिलाफात को दूर रखते हुए हाऊस की कार्यवाही ठीक ढंग से चलाई जाये।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਰੂਲਿੰਗ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ....

श्री अध्यक्ष : यह प्वायंट आफ आर्डर और है। इस प्वायंट आफ आर्डर को इस वक्त टेक अप न किया जाये। जब कि आनरेबल मैंबम्बर एक बार अपने विचार प्वायंट आफ आर्डर द्वारा हाऊस में व्यक्त कर देगा तो उस को दोबारा अपने विचार प्रकट करने के लिये प्वायंट आफ आर्डर के द्वारा इजाज़त नहीं दी जायेगी। मैं आनरेबल मैम्बरों के विचार सुनने के बाद अपनी रूलिंग दूंगा और उस के बाद प्वायंट्स आफ आर्डर्ज़ रेज़ करने की इजाज़त नहीं दूंगा। (शोर)। (This is a different point of Order. This may be left aside for the present. When once an hon. Member has raised some point through a point of Order, he will not be allowed to raise another point of order on the same subject. I will give my ruling after hearing the hon. Members and will not allow the raising of any point thereafter, (*Noise*)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ " House stands adjourned" ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਐਡਜਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Order please. Take your seat.

Chaudhri Darshan Singh : I rise on a point of Order, Sir. A pamphlet..............

Mr. Speaker : Leave aside this matter.

Chaudhri Darshan Singh : May I understand, Sir, that that portion of the proceedings will not form a part of the record of the House.

श्री अध्यक्ष : यह बात आगे आयेगी। (शोर)। Please take your seat.
[The mater will be taken up shortly (*noise*) Plese take your seat.]

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਐਡਜਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'House-stands adjourned' ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਹਾਊਸ ਅਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਗੈਲਰੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਲਤੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। (ਸ਼ੋਰ, ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the sitting be extended by one hour ?

Voice : No, Sir. Not at all.

चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी (श्री राम प्रताप गर्ग) : स्पीकर साहिब, मैं ने अपने दोस्तों से कहा था कि डिप्टी स्पीकर साहिबा ने हाउस 1/2 घंटे के लिये एडजर्न किया था। आज इरीगेशन की डिमांड्ज़ पर डिस्कशन हो रही है और अभी तक बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार हाउस में रखने हैं, इस लिये हाउस का वक्त एक्सटैंड कर दिया जाए, अगर हाऊस का टाइम ऐक्सटैंड नहीं होना हो तो यह डिमांड कल पहले टेक अप की जानी चाहिए। (शोर) (विघ्न)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जिस वक्त हाउस एडजर्न हुआ था, मैं हाउस में मौजूद था, डिप्टी स्पीकर साहिबा ने कहा था कि House stands adjourned उन्होंने ½ घन्टे के लिए एडर्जन करने के बारे में बिलकुल नहीं कहा था........ (शोर) (विघ्न)

Mr. Speaker : Order please. Take your seat.

(At this stage Sardar Prem Singh rose to raise a point of order)

Mr. Speaker: The hon. Member has already spoken. I will not allow him to speak again now.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ, । From all the sides of the House various Members of the Parties ਨੇ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਉਤੇ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ) ਕਿ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ (ਵਿਘਨ)

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बरों ने इस विषय में अपनी राय दे दी है। जब हाउस एडजर्न हुआ था तो उस वक्त डिप्टी स्पीकर साहिबा प्रीज़ाइड कर रही थीं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, प्रीज़ाइडिंग आफिसर है। जैसा कि मैं ने उन से वैरीफाई किया और उन्होंने कहा कि हाउस आधे घंटे के लिये एडजर्न किया था। (शोर) (विघ्न)। (श्री अमर सिंह द्वारा विघ्न) It is not proper, please take your seat. मैं हाउस से दरखास्त करना चाहता हूं कि वह इस कंट्रोवर्सी में न पड़ें। हमें ठीक ढंग से हाउस की कार्यवाही चलानी ही चाहिये। हमें चेयर की डिगनिटी का ख्लाय रखाना ही चाहिये। जब प्रीजाइडिंग आफीसर कोई बात कह दे तो वह बात हमें माननी ही चाहिये। इस लिये मैं हाउस के मैम्बरों से अपील करना चाहता हूं कि वह इस कंट्रोवर्सी को बन्द कर दें और हाउस की कार्यवाही ठीक ढंग से चलनी चाहिये। (शोर) (विघ्न) (The hon. Members have expressed their views on the matter. The Deputy Speaker was in the Chair when the House adjourned. She is a Presiding Officer. I have verified from her that

the House was adjourned for half an hour (Noise) (*Interruption*) (Interruption by Shri Ram Singh) It is not proper. Please take your seat. I would request the House to leave this controversy aside and proceed with the business in a proper manner. We should keep in mind the dignity of the Chair and accept its words. So, I appeal to the hon. Members to stop this controversy and let the House proceed with its business) (Noise) (Interruptions)

Mr. Speaker : Should the time of the House be extended ?

Voices : No please.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 8.30 a.m. tomorrow.

7 00 p. m.

(The Sabha than adjourned till 8·30 a. m. on Thursday, the 25th March, 1965).

APPENDIX
to
Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. I, No. 20 dated the 24th March, 1965.

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE VOL. I, No. 20, DATED THE 24TH MARCH, 1965.

Representation/complaint from Military Personnel regarding illegal occupation of his land.

***7983. (C.U.) Sardar Jagir Singh Dard** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Chief Minister/Deputy Commissioner, Amritsar, has received any representation/complaint from a resident of village Bhinder, district Amritsar (serving in Military) alleging that some portion of his land has been illegally occupied by some persons;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the steps taken by the Government in this regard;

(c) a copy of the said representation/complaint be placed on the Table of the House?

Shri Ram Kishan: (a) In the absence of full particulars, i.e., the name of the complainant and the date of submission of the application, it is not possible to trace out the reference. However, all the complaints/ representations of military personnel are invariably forwarded to the concerned authorities for affording all possible help and redressing genuine grievances.

(b) and (c) In view of (a) above, question does not arise.

Further Information re. Unstarred Question No.2464

Information in respect of Bhatinda and Rohtak Circles required in Unstarred Vidhan Sabha Question No.2464 asked during Budget Session 1965. (24-3-1965)

Serial No.	Designation of post	Total	Grade of Pay
1	Social Education Workers for Urban Scheme	24	Rs 50—3—80/4—100 with allowances
2	Squad Teachers for Rural Areas	90	Rs 50—3—80/4—100 with allowance
3	Bonus Workers (part-time) for Rural Scheme	28	Rs 40/- P.M. consolidated as Honorarium

Construction of Roads in Amritsar District.

2474. Comrade Makhan Singh Tarsikka: Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total sum so far spent on the construction of pucca roads included in the 2nd and 3rd five-year plans in district Amritsar tehsil-wise with special reference to Sarhali, Patti, Bhikhiwind, Majitha, Ajnala and Jandiala Constituency in the said district;

(b) the details of the roads proposed to be constructed in 1965-66 in Amritsar district;

(c) the reasons, if any, for not constructing, Khozala (which is on the Mehta road) to Tarsikka Block Headquarter road and Tangera Adda to Tarsikka Block Headquarter road so far;

(d) whether it is also a fact that the construction of roads mentioned in part (c) above was decided in the meeting of the Engineers of the Department held at the residence of the then Minister-in-charge in November, 1963 in the presence of the Legislator representing the area?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Statement I and II are added.

(b) Nil

(c) (i) Village Kohala lies on Amritsar Sirigobindpur road. This village will be connected by a three mile link road from Tarsikka to Amritsar Sirigobindpur road, which had been provided in the 3rd Five-Year Plan under Approach Roads Schemes at an estimated cost of Rs 1.60 lacs. This road is likely to be started shortly and will be completed early in the 4th Plan period.

(ii) The distance between Tangra to Tarsikka is 5.50 miles and construction of road between these villages will cost about Rs 5.50 lacs. This road has not been provided in any scheme so far, due to paucity of funds. Efforts will, however, be made to adjust it in the 4th Plan, if the financial position permits.

(d) Yes, but only for c (i) above.

STATEMENT I

AMRITSAR CIRCLE PWD B&R BRANCH AMRITSAR

Statement showing expenditure booked in Amritsar circle on the construction of Roads in 2nd, 3rd Five Year Plan

Serial No.	Name of road	Tehsil	*Expenditure incurred on five Year Plan* 2nd Five Year Plan	3rd Five Year Plan
			Rs	Rs
1	Constructing Dhotian Jama Rai Road	Taran Taran	2,77,407	
2	Constructing Fatehabad Chola Sahib Road	Ditto		
3	Construction Lalpura Approach road	Ditto		6,74,643 24,258

Serial No	Name of road	Tehsil	Expenditure incurred on five YearPlan	
			2nd Five Year Plan	3rd Five Year Plan
				Rs
4	Constructing Jandiala Verowal road	Tarn Taran 4,98910 Amritsar 62141	5,61,051	
5	Constructing Majitha Fatehgarh Churian Road	Amritsar	1,44,558	
6	Constructing Majitha By-pass ..	Do		1,558
7	Constructing ap roach road, Tarsikka to Amritsar Siri Hargobindpur Road	Do		153
8	Constructing approach road, Tung Pain on A.P.K.Road	Do		4,675
9	Constructing Patti Khem Karan Road	Patti	8,39,363	
10	Constructing Ajnala Fatehgarh Churiah Road	Ajnala	8,04,651	
11	Constructing Chogwan Ajnala Road	Do	5,92,173	
12	Constructing Harsa China Fatehgarh Churian Road	Do		19,187
13	Constructing approach road to village Chhidan on G.T. Road ..	Do		2,250
14	Constructing Raja Sansi Jhanjoti Road	Do		4,030
15	Constructing Haras China to Ajnala Guru Ka Bagh Road	Do		386
			32,19,203	7,31,140

		Abstract Tehsil wise	Abstract Plan wise	
Amritsar Tehsil	...	2,13,085	2nd	32,19,203
Taran Taran Tehsil	..	14,75,218	3rd	7,31,140
Ajnala Tehsil	...	14,22,677		
Patti Tehsil	...	8,39,363		
		39,50,343		39,50,343

STATEMENT II

List of Roads proposed to be constructed in 1965-66, in Amritsar District

Serial No.	Name of Road	Length	Upto date expenditure	Remarks
1	Approach Road to village Lalpura ..	0·75	Work is in progress	
2	Patti Khem Karan (Section Patti to Valtoha)	11·30	Work completed	
3	Majitha Fatehgarh Churian (part Length)	2.00	Ditto	
4	Verpal to 8th mile of Amritsar Taran-Taran Road	0.50	Ditto	
5	Fatehabad Chola Sahib Gandi wind	11.75	Ditto	
6	Chobal Attari Road ...	14.28	Ditto	
7	Jandiala Verowal ...	12.37	Ditto	
8	Sarhali Patti ..	7.26	Ditto	
9	Taran Taran Manochabal ...	5.56	Ditto	
10	Ram Dass Railway Station to Town	0.90	Ditto	
11	Ajnala Fatehgarh Churian ..	0.90	Ditto	
12	Jandial Verowal Road ..	0.37	Ditto	
13	Raja Sansi Shanjoti Road ...	2.50	Preliminary to be completed during III Plan	
14	Village Tungpain to Amritsar Gurdaspur Road	0.40	Ditto	
15	Khalra to China Bidhi Chandi Road	3.50	Ditto	
16	Village Sahraon to Khalra Harike Road	3.00	Ditto	
17	Village Tirsika to Amritsar Siri Gobindpur Road	3.00	Ditto	
18	Village Bariwala to Gandi wind Chola Sahib Road ...	1.50	Ditto	
19	Village Lalpur to Sheikh Chak on Taran Taran Goindwal road	1.80	Ditto	
20	Hansi China to Guru Ka Bagh on Amritsar Ajnala Road ...	1.50	Ditto	
21	Village Chiden to G.T. Road mile 287/6	0.50	Ditto	
22	Village Khawaspur to Tarn Taran Goindwal Road	0.30	Ditto	

Serial No.	Name of Road		Length	Upto date expenditure Remarks
23	Sheikh Chak to Kang	..	2.00	Preliminary to be completed during III Plan
24	Patti Khem Karan Road (Section Voltoha Khem Karan)	..	6.00	Ditto
25	By passat Majitha	..	2.00	Ditto
26	Harseh Chhina to Fatehgarh Churian Road		13.00	Ditto
27	Sheran Dhotian Jamera Road	..	6.75	Work in progress
28	Approach road from Ghariala Railway Station to Patti		0.75	Work being started
29	Approach road from Patti Sirhali Road to Patti		1.00	Ditto
30	Cheema to Kot Budha Road	..	6.00	Ditto

National College, Sathiala, District Amritsar.

2498. Comrade Makhan Singh Tarsikka: Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to take over the National College, Sathiala, District Amritsar;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the details of the correspondence so far exchanged between the Managing Committee of the said college and the Government be laid on the Table of the House;

(c) whether it is a fact that he and the Chief Minister promised the people of the illaqa that Government would take over the said College during August or December, 1964; if so, the steps, if any, so far taken in this direction?

Shri Prabodh Chandra: (a) Yes.

(b) The salient details of the correspondence are as under:—

The Managing Committee of the National College, Sathiala requested that this College be taken over by the Government as the people of the illaqa were not in a position to run it smoothly and efficiently. The Government decided to take over this institution from the academic session of 1964. To implement this decision, the Departmental Inspection Committee inspected the College and reported certain deficiencies. The Managing Committee assured the Government to make up the deficiencies in building, equipment and Amalgamated Fund. Subsequently the matter came up for discussion at a meeting held on 1st July, 1964 between the representatives of the Government and the Management. The Management pointed out certain difficulties and they agreed to make up the deficiencies, if the period is

extended up to the 31st December, 1964. In view of this, Government fixed 1st January, 1965, as the tentative date for taking over the College. It was as late as the 8th March, 1965, that the Management informed the Government that they had made up the outstanding deficiencies and fulfilled the conditions excepting that the Principal's residence was yet under construction. This reply will now be checked up by the Education Department and further action will be taken in the light of the result of this check up.

The Management of the College have requested that the Endowment Fund pledged to the Registrar, Punjab University, be released to them and that a special grant of Rs 50,000/- be given to them. This request is being considered by the Government.

(c) No such promise was extended by me. As regards the Chief Minister, reply will be sent separately.

Reply to part (*c*) *of Unstarred Question No.* 2498.

(c) No such promise was extended by the Chief Minister also.

Western Jamuna Canal Hydro Electric Scheme

2504. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the details of the investigations so far completed regarding the Western Jumna Canal Hydro Electric Scheme and the Mukerian Hydel Project with the details of the approximate amount proposed to be spent on each of them?

Chaudhri Rizaq Ram : 1. W.J.C. Hydro electric Scheme:- Preliminary surveys for hydel channel, collection of hydrological matrological and other data, 55 per cent of Geological Surveys and exploration, of the scheme have been completed. Rs 666.24 lacs (Rs 512.30 lacs for stage 1 and Rs 153.94 lacs for stage II) are proposed to be spent on the scheme.

2. **Mukerian Hydel Project.**—The investigations are in hand and, survey etc. is being done by the 'Survey of India' and as such the cost of the Scheme has not yet been worked-out.

4716 PVS—383—9-8-65—C., P. & S. Pb., Chandigarh.

PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

25th March, 1965
(Morning Sitting)

Vol. I—No. 21

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 25th March, 1965

Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh.

Price Rs : 6.35

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. I, No. 21, dated the 25th March, 1965.

(Morning Sitting)

Read	*For*	*Page*	*Line*
मिलनी	मिलवी	(21) 1	3 from below
कर	क।	(21) 4	6
बताया	बतया	(21) 8	last but one
टेक	`क	(21) 14	last
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ	ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼	(21) 16	17
किया	किमा	(21) 19	21
allocated	alocated	(21) 22	27
टैक्सेशन	टेपसेशन	(21) 23	6 from below
चौधरी	चोधरी	(21) 23	3 —do—
joke	Seoke	(21) 24	5
exception	exemption	(21) 24	13
on your request to	to your request on	(21) 24	17
check	ckeck	(21) 32	last
Rule 45	Rule	(21) 33	Heading
roads	road	(21) 35	11
agreed	agred	(21) 37	10
धोका दें	धोक दें	(21) 51	11 from below
sub-judice	sub-gudice	(21) 53	16 —do—
stepped	stopped	(21) 53	3 —do—
ਮਤਾ	ਮਤਾ	(21) 58	9 —do—
में	ें	(21) 59	13 —do—
	म	(21) 65	12 —do—
कमिश्नर	किमिश्नर	(21) 65	13
रही है	रहा	(21) 65	14
गौंची डरेन	गौंचीड रेन	(21) 66	12 from below
लिए	लये	(21) 67	5 —do—
मुमकिन	ममकिन	(21) 68	9 —do—
कार्य	कायं	(21) 69	15
पड़े	पड़	(21) 73	17
जरूरत	ज़रूत	(21) 78	12

P. T. O.

Read	*For*	*Page*	*Line*
गवर्नर	ग नर	(21) 79	6
आर्डर	आडरे	(21) 79	12
म्युनिसिपल	म्यनिसपल	(21) 79	20
त खाँहैं	तमखाहैं	(21) 82	14 from below
हैं	ह	(21) 82	10 —do—
छोटे	छोट	(21) 83	7
रुपया	रूपये	(21) 83	12 from below
उस	उसके	(21) 83	11 —do—
लेकिन	लकिन	(21) 83	last but one
		(21) 84	6, 11, 22
		(21) 87	14 from below
रहते	रहत	(21) 84	6
किसी	लोन किसी	(21) 84	18
बने	बन	(21) 84	7 from below
बगैरह	बगरह	(21) 86	3
लेबर	लबर	(21) 86	5
डिसिप्लन	प्लन	(21) 88	13
ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ	ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹਸ	(21) 90	1
ਮਿਊਂਸਪਲ	ਮਿੳਂਸਪਲ	(21) 90	16
੨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ	੨ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ	(21) 91	10

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 25th March, 1965

(*Morning Sitting*)

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan Sector Chandigarh at 8.30 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

*SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No 6950

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 1964 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ. । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 1964 ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲਈ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਔਫ ਹੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक : होम मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि यह कमेटी दिसम्बर, 1964 में बनाई गई थी और उस वक्त यह ख्याल नहीं था। गवर्नमेंट ने 29 ऐसी कमेटियां और सबकमेटियां बनाई हैं जिनमें 77 एम.एल.एज़ लिये और आपोजीशन के सिर्फ तीन मैम्बर लिये हैं। एक बार श्री प्रबोध चन्द्र ने यहां पर औबजर्वेशन करते वक्त कहा था कि आपोजीशन भी गवर्नमेंट का विंग है और उसको भी पूरी रिप्रेजैंटेशन मिलनी चाहिए। अब इनका कितनी और कमेटियां बनाने का इरादा है....

Note: Starred question No 6950 with its reply appears in the Punjab Vidhan Sabha Debates Vol I No. 20 dated the 24th March. 1965.

Mr. Speaker : Please confine yourself to this Committee only.

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक : मैं पूछता हूँ कि आइंदा और कितनी कमेटियां बनाने का इरादा रखते हैं ?

Mr. Speaker : No, not allowed.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਦਿਸੰਬਰ,1964 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ । ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਆਇੰਦਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ...

Mr. Speaker: Please don't repeat the reply.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਰੀਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਐਨੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਲਉ । ਅਸੀਂ ਗ਼ੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ।

TEHSILDARS POSTED IN AMBALA AND PATIALA DIVISIONS

***7080. Sardar Piara Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of Tehsildars belonging to the Patiala Division but posted in the Ambala Division who have been sent back to Patiala;

(b) the number of Tehsildars belonging to the Patiala Division who still remain posted in the Ambala Division, and a list showing their names be laid on the Table of the House ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Two.

(b) Ten.

The names of Tehsildars belonging to Patiala Division but working in Ambala Division at present are given below:—

(1) Shri Harcharan Singh
(2) Shri Badal Singh.
(3) Shri Narinder Nath
(4) Shri Tika Ram.
(5) Shri Rajwant Singh
(6) Shri Balwant Singh.
(7) Shri Devinder Singh
(8) Shri Om Parkash Singh Rao
(9) Shri Dev Raj
(10) Shri Jagmal Singh

ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 12 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹਨ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਡੀਸੀਯਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪਾਸੀਬਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

कामरेड राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि जिन अम्बाला डिवीज़न वाले तहसीलदारों का हक था उनको उस वक्त क्यों नहीं पोस्ट किया गया ?

Minister : This decision was taken in the interest of fair chances of promotion and good and efficient administration.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਉਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : It was an administrative decision.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Is it a fact that a decision was taken by the present Government that tehsildars belonging to Ambala Division will remain posted in Ambala Division or if posted in another Division will be reverted to Ambala Division and *vice versa* and this decision was not implemented ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਵਕਤ ਡੀਸੀਯਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਰਨ ਟਰਾਂਸਫਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਜਨਰਲ ਫੀਲਿਗ ਨੂੰ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਟਰਾਂਸਫਰਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ disparity ਕਿਉਂ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

Mr. peaker : It does not arise.

कामरेड राम प्यारा : क्या रैवेन्यू मिनिस्टर साहब बताएंगे कि मौजूदा गवर्नमेंट की क्या पालिसी है कि तहसीलदारों को अपनी अपनी डिवीज़न में लगाया जाए या कि कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, और उनकी प्रोमोशन्ज़ डिवीज़न वाईज़ होती है या स्टेट वाईज़ ?

मन्त्री : डिवीज़न वाईज़ प्रोमोशन्ज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, रिकार्ड को देख कर, सीनियारिटी को देख क और मैरिट्स पर प्रोमोशन्ज़ की जाती हैं।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : On a point of order Sir ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : It is not a point of order.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ...

Mr. Speaker : Please take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ...

Mr. Speaker : Please take your seat.

चौधरी इन्द्रसिंह मलिक : कुछ तहसीलदार पटियाला डिवीज़न के कई सालों से अम्बाला डिवीज़न में काम कर रहे थे अब उनको पटियाला डिवीज़न में बदला जा रहा है या उनकी डिमोशन करके उनको नायब-तहसीलदार बनाया जा रहा है ?

Minister : To find out facts and figures, I require a separate notice.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया था कि वे अपनी रैस्पैक्टिव डिवीज़न में जाएं क्या यह हकीकत है कि वह आर्डर इस वजह से इम्पलीमैंट नहीं हुआ कि कुछ तहसीलदार पटियाला डिवीज़न के अम्बाला डिवीज़न में लगे हुए थे अगर वे इधर उधर जाते थे तो रीवर्ट होते थे और अगर अम्बाले में रहें तो तहसीलदार रहते हैं। क्या बात थी कि इण्टरफियर किया गया, इसका कारण क्या है ? सवाल यह है कि मार्च अप्रैल तक जो दरखास्तें आईं क्या इस बिना पर ट्रांसफर्ज पोस्टपोन की गई थीं ?

मन्त्री : मेरे पास किसी ने एप्रोच नहीं किया और न ही मुझे इसके मुताल्लिक कहा गया है। मैं वाज़ेह तौर पर दोबारा एशोरेंस दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो डिसीज़न लेती है, कोई सवाल पैदा नहीं होता कि कोई बड़ा या छोटा अफसर उसमें रुकावट डाल सके ।

Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : May I know from the Revenue Minister whether Government has adopted a uniform and stable policy in

respect of its Tehsildars now ?

Mr. Speaker : This is the latest policy as enunciated.

कामरेड राम प्यारा : क्या रेविन्यु मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार पैप्सू में पोस्टिड थे व जूनियर थे और अम्बाला डिवीजन में पोस्टिंग पर सीनियर हो गए ? इस की क्या वजह है ?

Mr. Speaker : He says that he requires a separate notice.

Comrade Ram Piara : It is a fundamental question, Mr. Speaker.

Mr. Speaker : He says that he requires a separate notice.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਏ' ਵਿਚ ਦੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਪਰਾਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਚ ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

TEHSILDAR, THANESAR

***7081. Sardar Piara Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the number of times the Tehsildar of Thanesar was reverted as a Naib-Tehsildar and again promoted as Tehsildar during the year 1964 together with the reasons for frequent reversions/promotions ?

Sardar Harinder Singh Major : No reversion of Tehsildar, Thanesar took place during the year 1964 and the question of his repromotion did not, therefore, arise.

ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ?

Minister : I have already stated in reply that "No reversion of Tehsildar Thanesar, took place during the year 1964". ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1964 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ । I will certainly look into it and take action if I feel that the information supplied to me is not correct.

TEHSILDARS AND NAIB TEHSILDARS UNDER SUSPENSION

***7484. Chaudhri Darshan Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of the Tehsildars and Naib-Tehsildars suspended up to 7th February, 1965 with the date of suspension of each ;

(b) the names of Tehsildars/Naib-Tehsildars referred to in part (a) above who have remained under suspension for more than six months ;

(c) the reasons for not completing the enquiry into the cases mentioned in part (b) above within 6 months ?

Sardar Harinder Singh Major :

(a)

	Name of Tehsildar/Naib-Tahsildar	Date of suspension
1.	Shri Jagjit Singh, Tehsildar.	.. 30-7-1964
2.	Shri Dewan Chand, Naib-Tahsildar	.. 16-7-1962
3.	Shri Jai Ram Dass, 'A' Class Tahsildar candidate (under training as Naib-Tehsildar)	.. 20-7-1964
4.	Shri Gopal Singh, Naib-Tahsildar	.. 4-1-1964

(b) As in part (a) above.

(c) Cases at Serial Nos. 1 to 3 in part (a) above are under trial in courts of Law and Government instructions for completing enquiries within six months do not apply in such cases. The case at Serial No. 4 was originally with the Commissioner, Patiala Division, but was later on transferred to Commissioner, Jullundur Division through the Revenue Department in accordance with a policy decision that such cases should be dealt with by the Commissioner in whose Division the acts of omission and commission have taken place. The case is at present with the Commissioner Jullundur Division and it is likely to be finalized by the end of June, 1965.

Chaudhri Darshan Singh : At serial No. 2 it has been stated that the officer was suspended on 16th July , 1962. May I know from the Revenue Minister as to when the challan was put in the court of law ?

Minister : For that I require a separate notice.

Chaudhri Darshan Singh : At serial No. 4 the officer was suspended on 4th January, 1964 and the suspension lasted for more than a year. May I know from the Revenue Minister why policy of six months suspension has not been taken into consideration.

Minister : Sir, I have already stated that cases at serial Nos. 1 to 3 are under trial in the courts of law.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मन्त्री महोदय ने जवाब में बताया है कि एक नायब-तहसीलदार को जुलाई, 1962 में सस्पेंड किया था। क्या वह बतायेंगे कि **जब** किसी नायब-तहसीलदार, **तहसीलदार** या दूसरे गवर्नमेंट आफीशियल को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसकी **इन्क्वायरी** करने के लिये कितनी देर लगती है ?

श्री अध्यक्ष : उनका जवाब है कि चारों केसिज़ कोर्ट में चल रहे हैं। (The Honourable Revenue Minister has stated in the reply that all the four cases are under trial in Courts of Law.)

Chaudhri Darshan Singh : At serial No. 4 the officer was suspended a year ago and the case is not pending in the court of law..............

Mr. Speaker : The Minister says that it is pending.

Chaudhri Darshan Singh : In the reply given it is not pending.

Minister : The case at serial No. 4 is not pending in the court of law.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

Minister : If anything has been done in contravention of any Government policy and instructions I shall certainly look into it and take action.

TENANTS EJECTED IN JIND TEHSIL

***7926. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of tenants ejected in Jind tehsil in the years 1963 and 1964, separately;

(b) the number of tenants mentioned in part (a) above who were allotted surplus land in Jind tehsil in 1964 and 1965 (to-date) separately and the total area allotted to each ;

(c) the number of tenants mentioned in part (b) above who sold lands allotted to them in 1964 and 1965 stating the total area of land sold year-wise;

(d) whether he is aware of the fact that big landlords have got their surplus lands allotted in the names of their tenants and get the sale price of the same themselves;

(e) whether Government propose to impose some restrictions on the alienation of the surplus allotted land ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) (i) Nil.
(a) (ii) Seven.

(b) (i) Seven tenants allotted 19.3$\frac{3}{4}$ standard Acres as under:—

			S. As.	Units
(1)	Lachhman, son of Asa of village, Kalta	..	2	9$\frac{3}{4}$
(2)	Baso,son of Piara of Village Kalta	..	2	12$\frac{3}{4}$
(3)	Khema, son of Asa Ram, village Kalta	..	4	4$\frac{1}{4}$
(4)	Darya, son of Asa Ram, village Kalta	..	4	14$\frac{1}{4}$
(5)	Hari Ram, son of Bhola of village Baroda	..	1	1$\frac{1}{2}$
(6)	Hazur Singh, son of Mangal Singh, village Memnabad	..	1	12$\frac{1}{4}$
(7)	Kapur Singh, son of Sohan Singh, village Memnabad	..	1	12$\frac{1}{2}$

(b) (ii) Nil.

(c) (i) Nil

(c) (ii) Question does not arise.

(d) No.

(e) No.

चौधरी दल सिंह : क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन हरिजनों को सरप्लस जमीनें एलाट की गई हैं और उन्होंने एलाटमेंट के फौरन बाद उनको फरोख्त कर दिया है क्या सरकार उनके सेल डीड्ज़ को कैन्सल करने का विचार रखती है ?

मंत्री : नो, सर !

चौधरी दल सिंह : अगर मैं मिनिस्टर साहब के नोटिस में कई ऐसे केसिज लाऊं जिनमें हरिजनों को सरप्लस ज़मीन एलाट हुई हो और उस एलाटमेंट के फौरन बाद उन्होंने इस जमीन को फरोख्त कर दिया हो तो क्या यह उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिये तैयार होंगे ?

Minister : Sir, if it is brought to the notice of Government that certain provisions of the Act had not been enforced, then it is the bounden duty of the Government to see that those provisions are implemented.

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਸਕੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This does not arise out of the main question.

चौधरी देवी लाल : अभी चौधरी दल सिंह जी ने बताया है कि जो सरप्लस लैण्डज निकली थीं और हरिजन टेनेंट्स को एलाट की गई थीं वह उन्होंने एलाटमेंट के

फौरन बाद आगे बेच दी हैं तो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी फर्जी एलाटमेंट का क्या कोई फायदा है और इस तरह से सरप्लस लैण्डज़ के निकालने का कोई फायदा है ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब उन्होंने दे दिया है कि वह देखेंगे कि आया वाकई कोई ऐसी चीज़ हुई है और उन के खिलाफ कोई एकशन कानून के तहत लिया जा सकता है। (The Honourable Minister has already replied to this supplementary that he would examine such cases and see whether some action can be taken against them under the provisions of the Act.)

चौधरी अमर सिंह : मिनिस्टर साहब ने चौधरी दल सिंह के सवाल के जवाब में अभी बताया है कि अगर कोई ऐसा केस उनके नोटिस में लाया जाय तो वह उसको ठीक कर देंगे तो मैं उन से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह उन केसों में भी एक्शन लेने के लिये तैयार हैं जिन केसों में बहुत सारे टैनेंटस को जबरदस्ती इजेक्ट कर दिया जाता है और फर्जी गिरदावरियां अपने रिश्तेदारों के नाम करवा ली गई हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है। (He has already replied to this supplementary.)

चौधरी देवी लाल : क्या माल मंत्री जी बताएंगे कि जिस तरह से रूरल लैण्ड्ज़ में से सरप्लस लैण्ड्ज़ निकाली गई हैं क्या इसी तरह से अरबन लैण्डज़ में से भी सरप्लस ज़मीनें निकाल कर हरिजनों को और दूसरे लैंडलेस टैनेंटस को एलाट की गई हैं, या की जाएंगी ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सवाल के जवाब में कहा है कि एक्ट की प्रोवीज़न के मुताबक सब की सरप्लस ज़मीन ली जायेगी। (He has already stated in reply to the question that all surplus land will be taken in accordance with the provision of the Act.)

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहब, मैं पालिसी के बारे में पूछ रहा हूँ। रूरल लैण्डज़ तो सिर्फ देहात में होती हैं। मैं इन से पूछना चाहता हूँ कि आया सरकार की यह पालिसी है कि जो शहरों में सरप्लस लैण्डज़ हैं उनको भी निकाल कर उन पर हरिजन मुज़ारों को बसाया जाएगा ?

मंत्री : स्पीकर साहब, मेरा इस बारे में बड़ा क्लियर जवाब है कि जो एक्ट सरकार ने बनाए हुए हैं वह तमाम इसकी पालिसी के मुताबिक हैं और उन पर यह अमल करती है।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪਲਸ ਲੈਂਡਜ਼ ਡੀਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

Mr. Speaker : The Honourable Member should please confine himself to Jind Tahsil.

Comrade Bhan Singh Bhaura : Sir, it is a matter of policy.

Mr. Speaker : No, please. The Honourable Member should please resume his seat.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या माल मंत्री जी बताएंगे कि तहसील जींद में रामगढ़ गांव में और दूसरे दो तीन गांवों में सरप्लस जमीन निकाल तो ली गई है लेकिन वहां के हरिजनों को वह एलाट नहीं की गई और बाहर से कुछ हरिजन मुजारों को लाकर वहां पर बसा दिया गया है तो क्या यह सरकार की पालिसी के मुताबिक है ?

(जवाब नहीं दिया गया)

DAMAGE TO CROPS IN KARNAL DISTRICT DUE TO FLOODS IN 1964

*7079. **Sardar Piara Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the extent of damage caused to crops in Karnal District by the floods during the year, 1964;

(b) the total amount given as grant by the Government to the people affected and the amount of land revenue and abiana remitted by the Government ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Rs. 2,45,47,174.

(b) GRANTS

		Rs.
(i) Concessional supply of food and shelter including free ration	..	64,604
(ii) Repair of houses	..	1,14,200
(iii) *Adhoc* grants for village protection bunds to village Panchayats	..	16,000
Total	..	1,94,804
Remission of Land revenue	..	2,10,841
Remission of abiana	..	3,34,624.81

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, may I ask the Honourable Minister for Revenue as to what measures have been adopted by the Government to save this district or this ilaqa from the ravages of floods which cause losses running into crores of rupees ?

मंत्री : स्पीकर साहिब, सवाल तो यह था कि कितना डेमेज जिला करनाल में हुआ है और कितना रिलीफ वहाँ दिया गया है । इस के बारे में तो पूछा ही नहीं गया इस । के लिए नोटिस चाहिए कि फ्लडज को चैक करने के लिए सरकार ने क्या २ मेइयर्ज वहां पर लिए हैं ।

लोक कार्य मंत्री : इस का जबाब मैं दूंगा ।

Mr. Speaker : Comrade Ram Piara.

Pandit Chiranji Lal Sharma : I rise on a point of Order, Sir. The honourable Minister for Public Works and Welfare has been pleased to say that he is prepared to anwer the question................

लोक कार्य मन्त्री : मैंने तो यह कहा है कि आज जब मैं इरीगेशन की डिमाण्ड पर हुई बहस का जवाब दूंगा तो उस में इस बात का भी जवाब आ जाएगा ।

कामरेड राम प्यारा : क्या माल मंत्री जी बताएंगे कि अभी जो उन्होंने बताया है कि वहां पर दो करोड़ रुपये का नास हुआ था और रिलीफ के बारे में भी बताया है कि वहां इतना रिलीफ सरकार ने दिया है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि रिलीफ की रकम मुकर्रर करने के लिये सरकार ने कौनसा कराईटेरिया रखा हुआ है और जो करायेटेरिया सरकार ने पंजाब के बाकी ज़िलों के लिये बना रखा है क्या करनाल में उसी करायेटीरिया के मुताबिक रिलीफ दिया गया था ?

मन्त्री : स्पीकर साहब, मुझे कोई ऐसी खास वजह नजर नहीं आती कि जिला करनाल के लोगों के साथ कोई वितकरा भरा सलूक किया जाए । सब को एक करायेटीरिया के मुताबिक रिलीफ दिया जाता है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : मिनिस्टर साहब ने अभी बताया है कि जिला करनाल में मकानात की रिपेयर के लिये 1,14,200 रुपए रिलीफ के तौर पर दिए गए हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यह जो रुपया मकानात की रिपेयर के लिये दिया गया है यह किस करायेटीरिया के मताबिक दिया गया है ? आया यह नुकसान को देख कर दिया गया है या किसी और बिना पर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : लाज़मी तौर पर नुकसान को ख्याल में रख कर यह दिया जाता है । (It is but natural that while giving relief the extent of loss sufferred is kept in view.)

श्री फतेह चन्द विज : क्या रैवेन्यू मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जिला करनाल में जो हर साल फ्लड्ज़ से खादड़ के इलाका में और उसके साथ लगते इलाकों में नुकसान होता है क्या इसकी वजह यही नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जमना के पास एक बांध बना कर पानी का रुख इधर को कर दिया है जिससे हर साल वहां बरबादी होती है ? क्या हर साल यह नुक्सान उत्तर प्रदेश सरकार की इस धक्केशाही की वजह से नहीं हो रहा ?

Mr. Speaker : The hon. Member should not please discuss the other Government in this House.

कामरेड राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि फ्लडज़दा इलाकों के लोगों को जो रिलीफ दिया जाता है उसके बेसिज़ क्या यही हैं कि क्राप्स को नुक्सान पहुंचा हो उस लास की कोई परसेन्टेज रिलीफ के तौर पर दी जाए और इसी तरह से जो मकानात को नुक्सान पहुंचा हो उस नुकसान के बेसिज़ पर दिया जाए? इस तरह के कौन कौन से बेसिज़ को मद्देनज़र रख कर रिलीफ दिया जाता है ?

मन्त्री : इसका जवाब तो काफी तफसील में दिया जा सकता है जिसका बयान करना तो मुश्किल है। अगर मैम्बर साहब इसके लिये नोटिस दे दें तो सारी तफसील इनको दे दी जाएगी या बेहतर होगा अगर वह मेरे पास बाद में आ जाएं तो मैं इनकी तसल्ली कर दूंगा ।

REPRESENTATION FROM IRRIGATION BOOKING CLERKS REGARDING INCREASE IN PAY SCALES

***7548. Dr. Baldev Parkash :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether Government has received any representation from the Irrigation Booking Clerks for revising their pay scales; if so, the action taken or proposed to be taken thereon ;

(b) whether it is a fact that Government had assured the said clerks that their pay scale would be brought at par with those of the Revenue Patwaris, if so, the reasons for which the said assurance has not been implemented ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) and (b) The scale of the Irrigation Booking Clerks has been revised from Rs. 50—1—60/2 -80 to Rs. 60—4—80/5—120/5—175 with effect from 1st April, 1965. Thus their pay scale has been brought at par with the Patwaris of the Revenue Department.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, may I ask the hon. Minister for Public Works and Welfare that in spite of this revision of the pay scale of Irrigation Booking Clerks, they are not satisfied and they have again approached the Government that this increase which is to take effect from 1st April,1965 does not satisfy their demands ?

मन्त्री : आज मुझे पटवारी इस सिलसिले में मिले हैं और उन्होंने कहा है कि यह कुछ पहले से लागू किया जाए, इस पर गौर हो रहा है ।

9 a. m.

डा० बलदेव प्रकाश : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने इस सवाल के 'बी' पार्ट में यह मांग की थी कि उनकी तनखाहों को रैवेन्यू

पटवारियों के बराबर कर दिया जाए, तो क्या ऐसा कर दिया गया है कि नहीं ?

मन्त्री : कर दिया गया है ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि क्या यह हकीकत है कि इस फैसले से पहले पटवारियान नहर का एक डैपुटेशन चीफ मिनिस्टर साहिब से मिला था और बीच में एक लैजिसलेटर भी थे। मैं नाम ले देता हूँ, चौधरी चांद राम। तो उस वक्त फैसला हुआ था कि चूंकि एशोरेंस सन् 1962 से दी थी इसलिये इस रिवीयन को पहली अप्रैल सन् 1965 से कुछ पहले से लागू किया जायगा। अगर ऐसा हुआ था तो क्यों इसपर अमल नहीं किया गया ?

मन्त्री : चीफ मिनिस्टर साहिब से वह मिले थे या नहीं इसका मुझे पता नहीं। मगर मुझे मिले थे, चौधरी चांद राम भी साथ थे, तो मैंने कहा था कि चूंकि आपकी मांग जायज़ नज़र आती है इस पर पूरी हमदर्दी से गौर करेंगे ।

BEAS DAM

***7647. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total amount of expenditure incurred on the Beas Dam up to the end of 1964 ;

(b) the approximate date by which the project is likely to be completed, together with the total estimated cost thereof ?

Chaudhri Rizaq Ram, : (a) Total amount of expenditure on Beas Dam at Pong (Unit II) up to 31st December, 1964 is Rs 21.08 crores.

(b) (i) Completion of the Beas Dam will be effected in the year 1971-72 whereas its power plant will be completed in 1972-73.

(ii) Estimated cost of Beas Dam is Rs 111 crores.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जिस तरह से भाखड़ा डैम के ऐस्टीमेट्स शरू से लेकर हर साल रीवाइज होते रहे और 50 करोड़ से बढ़ कर 178 करोड़ तक जा पहुंचे क्या ऐसी ही बात इस डैम पर तो नहीं होगी ?

मन्त्री : अगर ज़रूरत पड़ी तो यह भी रीवाइज किये जा सकते हैं, पेशीनगोई नहीं की जा सकती ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या इस खर्च में वह खर्च भी शामिल हैं जो कि बयास डैम के आउस्टीज को रीहैबिलीटेट करने पर खर्च किया जायेगा ?

मन्त्री : जो कैश कम्पैनसेशन उनको देनी है वह तो इसमें शामिल है मगर जो ग्रालटरनेट लैंड उनको देनी है उसका खर्च इस में शामिल नहीं है।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो कैश कम्पैनसेशन उनको देनी है उसकी कितनी रकम इसमें शामिल है ?

मन्त्री : इसके लिये तो ग्रलग नोटिस दें ।

एक ग्रावाज : कुछ ग्रटा सटा ही बता दें ।

मन्त्री : कुछ लाख या कुछ करोड़ होगा। (हंसी)

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह जो रकम रखीगई है क्या इसमें मुलाज़मों को देने के लिये हिल कम्पैनसेटरी एलाउंस की रकम भी शामिल है ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रगर वह एटाइटल्ड होंगे तो रखी गई होगी। (The amount must have been earmarked if they were entitled to it.)

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : जनाब, वहां पर इसके मुतािल्लक एजीटेशन हो रही है। (विघ्न) इन्होंने एशोरेंस दी थी (विघ्न) बड़ा ग्रहम मसला है।

Mr. Speaker : please taket your seat.

RIGHT BANK POWER HOUSE AT BHAKRA

*7648. **Shri Balramji Dass Tandon** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state -

(a) the date when the first Generator in the Right Bank Power House of the Bhakra Dam is likely to be commissioned and also the date when the rest of the generators in the said Power House are expected to start working;

(b) the total estimated expenditure to be incurred on the said Project ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) The first unit is likely to be commissioned by 1st February, 1966 and subsequent units at an interval of 3 months each except 5th unit commissioning of which is yet to be finalised with the Russian Suppliers.

(b) Rs 59.32 crores.

श्री बलरामजीदास टंडन : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो ग्रनुमान उन्होंने बताया है वह सारे ऐंजनियर्ज़ से बात चीत करने के बाद बताया है कि हर तीन महीने के बाद एक यूनिट जैनरेट हो जायगा । लैफ्ट बैंक का पावर हाउस तो ग्रनुमान के मुताबिक कम्पलीट नहीं हुग्रा ? तो इस बारे में सरकार का क्या ग्रन्दाज़ा है ?

मिस्टर स्पीकर : प्लीज ेक यूग्रर सीट ।

मन्त्री : आपको किसने बताया है कि लैफ्ट बैंक का काम कम्पलीट नहीं है ? जो शडूल बनाया गया है राइट बैंक पर काम उसके मुताबिक चल रहा है और उम्मीद है कि शडूल के मुताबिक काम पूरा हो जायगा । पहला यूनिट फरवरी में पूरा हुआ है और जो ऐग्रीमेंट हुआ है नवम्बर तक उसके मुताबिक चार यूनिट और चालू हो जायेंगे, पांचवें के मुताल्लिक चूंकि ऐग्रीमेंट बाद में हुआ है और मशीनरी बाद में आनी शरू हुई है उसमें देर लगेगी, उसका टाइम मुकर्रर नहीं हुआ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਾਰਨ ਕਨਟਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਰਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਣੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਡੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

मन्त्री : वह शैडूल के मुताबिक पहुंच चुकी है ।

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਰਾਈਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰਪਜ਼ਿਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ 13%ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ?

मन्त्री : एग्रीकल्चर के लिये भी देंगे, घरों में ज़रूरत होगी तो घरों और इन्डस्ट्री को भी देंगे ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि राइट बैंक पर जो पावर हाउस बन रहा है उससे पैदा होने वाली बिजली की डिस्ट्रिब्यूशन का सूबे के अन्दर और इस सूबे से बाहर साथ वाली स्टेट्स के अन्दर क्या प्रोपोर्शन है ?

मन्त्री : इसके लये सैपेरेट नोटिस दें ।

सरदार रणजीत सिंह नैनेवालिया : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राइट बैंक वाले पावर हाउस के कम्पलीट हो जाने पर पंजाब के कितने गांवों को बिजली दी जायगी ?

मन्त्री : हमारी कोशिश तो यह है कि सारे ही देहात को बिजली पहुंच जाए मगर कब तक ऐसा हो सकेगा यह नहीं कहा जा सकता, कोशिश है ।

ENERGISING OF TUBEWELLS AND PUMPING-SETS IN GURGAON DISTRICT

*7802. **Chaudhri Har Kishan :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the total number of the Tube-wells and pumpingsets which are lying idle for want of power connection in each Block of the Gurgaon District and the time likely to be taken to energise them ?

Chaudhri Rizaq Ram : 190 in Gurgaon District. Block-wise information is not maintained. The connections will be given as soon as material becomes available.

चौधरी अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन ट्यूब-वैल्ज़ की टैस्ट रिपोर्ट जा चुकी हो और जो अभी तक एक साल से पैंडिंग हैं क्या वह उनको कनैक्शन देने के लिये तैयार हैं ?

मन्त्री : इस बारे में हिदायत यह है कि जिन ट्यूबवैल्ज़ के बारे में टैस्ट रिपोर्टस दिसम्बर सन् 1964 तक जा चुकी हैं उनको कुनैक्शन दे दिया जाए और इस तरह से कोई पांच चार हज़ार ट्यूबवैल्ज को कनैक्शन देने का प्रोग्राम है। उम्मीद है कि उससे कुछ ज्यादा ही दिये जाएंगे ।

श्री मंगल सेन : मन्त्री महोदय ने इस सदन में घोषणा की थी कि इस वर्ष में सब ट्यूबवैल्ज़ को बिजली दे दी जायगी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उसकी पूर्ति भी कर दी है या यह महसूस करते हैं कि उसमें कुछ कमी रही ?

मन्त्री : ऐसी घोषणा नहीं की गई कि सब ट्यूबवैल्ज़ को कनैक्शन दे दिये जायेंगे । मगर यह कहा था कि नए विल्लेजिज़ में कनैक्शन नहीं देंगे और जितनी पैंडिग ऐप्लीकेशन्ज़ हैं ट्यूबवैल्ज़ को कनैक्शन देने के लिये उनमें से जितने ज्यादा से ज्यादा कनैक्शन हम दे सकेंगे देंगे। ऐसी पैंडिग ऐप्लीकेशन्ज़ करीब 14,000 हैं। उम्मीद है कि 31 मार्च तक उनमें से 6,000 ट्यूबवेल्ज़ एनर्जाइज़ किये जा सकेंगे ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਗਰੋ ਮੋਰ ਫੂਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

मन्त्री : मैं ने पिछले साल के बारे में पड़ताल की थी कि जो रक्म 1964-65 के लिए दी गई थी वह खर्च कर दी गई है। इस के बाद 4 करोड़ रुपया के लिए और इन्तज़ाम किया गया । आगे के लिए भी इन्तज़ाम करेंगे कोई कर्ज़ा वगैरा ले कर।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ 6,000 ਟਯੂਬ ਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : How does it arise out of the main question ?

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि 14 हज़ार दरखास्तें पैंडिंग हैं तो क्या इनको कुनैक्शन न देने का कारण नान-अवेलेबिलिटी आफ फन्ड्ज़ था या नान-अवेलेबिलिटी आफ मैटीरियल भी था ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री फतह चन्द विज : क्या यह बात मिनिस्टर साहिब के नोटिस में है कि पलवल जिला गुड़गांवा में कुनैक्शन एक एक साल से पैंडिंग है और इन्होंने एलान किया

था कि बिजली का सामान नहीं है तो क्या अब बिजली दे दी जाएगी ? आपने वादा भी किया था ।

मन्त्री : जो वादे किये थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। 1–12–64 तक जो केस आए थे उनके बारे में हदायत कर दी गई है कि उन्हें प्रायरटी दे कर कुनैक्शन दिये जाएं । और अंदाजा था कि कोई 5,000 ट्यूब वैलों को हम एनरजाइज कर सकेंगे लेकिन अब हालत बेहतर होने के कारण 6,000 को एनरजाइज कर रहे हैं ।

राव निहाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि क्या कारण है कि जब मैटीरियल नहीं है तो फिर लोगों से सिक्योरिटी क्यों जमा कराई जाती है ?

मन्त्री : इसके बारे में कायदा ही ऐसा है ।

PHAGWARA-RANIPUR ROAD

*7340. **Shri Om Parkash Agnihotri :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the construction of the Phagwara-Ranipur Road has been provided for in the III Five Year Plan, if so, whether the construction work on this road has been taken in hand ;

(b) the steps being taken to complete the said road, and the time by which it is likely to be completed ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes, only preliminary work is to be done during the current and next financial year,

(b) The road is expected to be completed in the IV Five-Year Plan subject to availability of funds.

CONSTRUCTION OF REST HOUSES ETC. IN TEHSIL NARNAUL, DISTRICT MAHENDARGARH

*7470. **Shri Ram Saran Chand Mital :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Government had sanctioned the construction of one or two Rest Houses and two or three Hawaghars at Shivkund and Dhosi Hills, important places of pilgrimage and tourist centres, near villages Kultajpur and Thana, tehsil Narnaul, district Mahendragarh, within the last three years, if so, the time by which these are likely to be constructed ;

[Shri Ram Saran Chand Mital]

(b) whether Government received any representation from any legislator on this subject during the last three years; if so, a copy thereof be placed on the Table of the House;

(c) the action taken on the said representation ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

CONSTRUCTION OF JIND-BHIWANI AND JIND-SAFIDON ROAD

*7808. **Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether the Government proposes to construct the remaining portion of the Jind-Bhiwani Road, i. e., from Khanda Kheri to Jind; if so, the time by which the said portion of the road is likely to be completed;

(b) whether the Government intend to construct Jind-Safidon Road or a part thereof as announced by the Chief Minister at a public meeting at Jind, if so, the time by which construction work thereon is likely to be started ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) The question of inclusion of this road in the 4th Plan is under the consideration of Government and in case it is finally approved it would be completed as early as possible subject to the availability of funds.

(b) No.

चौधरी दल सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायें गे कि यह अन्डर कनसिड्रेशन कितने रोज़ तक रहेगी ?

मन्त्री : अभी फोर्थ प्लान के बारे में प्रोपोज़ल्ज़ आ रही हैं इसलिये इसको भी उनके साथ कनसिडर किया जा रहा है।

चौधरी दल सिंह : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि यह सड़क सैकन्ड फाइव ईयर प्लान में थी या नहीं थी ?

मन्त्री : सैकन्ड प्लान के बारे में बताना तो मुश्किल है लेकिन थर्ड प्लान में यह सड़क नहीं थी ।

चौधरी अमर सिंह : सवाल के जवाब में बताया गया है कि अन्डर कनसिड्रेशन है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि भिवानी-जींद रोड के फोर्थ फाईव-ईयर प्लान में या पांचवीं में या सिक्स्थ प्लान में बनाए जाने का विचार है ?

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जींद के हलके में खांडा खेड़ी से जींद तक की सड़क को सैकन्ड प्लान में शामिल किया गया था और यह तीसरी प्लान में भी इन्कम्पलीट पड़ी है । और जींद में बाई इलैक्शन में चीफ मिनिस्टर साहिब ने वहां पर जाकर कहा कि हम सफीदों जींद रोड को पूरा कर देंगे या कैनाल ब्रिज बना देंगे । तो इसका क्या हुआ ?

मन्त्री : आपको किसी ने गलत खबर दे दी है । नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं थी ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : जनाब, यह दूसरी प्लान में थी और तीसरी में थी और अब चौथी प्लान में भी यह नहीं बनाई जा रही।

श्री मंगल सैन : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इनकी याद ताज़ा कर दूं कि सवाल बिल्कुल स्पष्ट था जिस मैम्बर को बैठने के लिये कहा गया था। एक जलसे में जिसका ज़िक्र सवाल के पार्ट 'बी' में है हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने यह घोषित किया था कि इस सड़क को बनाया जाएगा तो मैं मन्त्री महोदय से यह निश्चित रूप में स्पैसिफिक तौर पर जानना चाहता हूँ कि उस वायदे को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

मन्त्री : इस तरह का कोई वायदा नहीं किया गया । अगर फिर भी किसी इलाके की कोई रिक्वैस्ट आती है और वह जैनविन हो तो उस पर गौर किया जा सकता है ।

चौधरी देवी लाल : इससे पहले मैंने भी सड़कों के बारे में सवाल दिया था और उसका जवाब आया था 'नो'। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्हें याद है कि एक मीटिंग इस इलाके में हुई और अफसरों के रूबरू इस सड़क के बारे में एलान किया था **और इलैक्शन के दौरान वायदा किमा था**। यह मीटिंग 18 तारीख को हुई थी। हज़ारों आदमियों के जलसा **में** वज़ीर साहिब ने हाथ बढ़ा कर कहा था कि हम अपने वादे पूरे करेंगे। मगर आज वह मुकर गये हैं। स्पीकर साहिब, आखिर ऐसे मिनिस्टर का क्या इलाज ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहिब, यह इलाज तो आपको ही मालूम है । मेरे से क्या पूछते हैं । (The hon. Member is very well aware of the remedy. What does he want me to say in this matter ?)

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ · ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is no supplementary.

चौधरी इंद्र सिंह मलिक : जींद–भिवानी रोड दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी थी और यह तीसरी पंच वर्षीय योजना में भी रखी गई है । **इसको आज तक कम्पलीट नहीं**

[चौधरी इन्दर सिंह मलिक]

किया गया यह अधूरी ही पड़ी है । मैं पूछना चाहता हूँ कि हरियाना के साथ इतना डिस-क्रिमिनेटरी सलूक आखर सरकार की तरफ से क्यों किया जाता है ?

मन्त्री : मैं इसके मुताल्लिक पहले जवाब दे चुका हूँ । अब और क्या अर्ज करूँ । *(Interruptions)*

चौधरी देवी लाल: On a point of order, Sir. मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि अगर किसी मैंबर को आखरी सप्लीमेंटरी पर क्वैश्चन पुट करने की इजाजत न मिले तो ऐसे हालात में मैं आपका रूलिंग चाहता हूँ कि वह क्या करे ।

श्री अध्यक्ष : यह कोई रूलिंग वाली बात नहीं है ।(This does not require any ruling.)

चौधरी देवी लाल : जब आप के रूलिंग पर हम क्वैश्चन करते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता । सप्लीमेंटरी पुट करने की आप इजाजत नहीं देते, हम क्या उम्मीद करें ।

श्री अध्यक्ष : आपको ऐसी हालत में कोई उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए । (The hon. Member need not expect a reply in such a case).

PURCHASE OF EVACUEE LAND BY HARIJANS

***7472. Shri Ram Saran Chand Mital :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether the Government decided in September,1964, that the Revenue Department should advance rupees two crores to Harijans out of the Harijan Welfare Fund to enable them to purchase surplus rural evacuee land acquired by State Government in the package deal; if so, whether this amount has anything to do with the tax collected under the Punjab Temporary Taxation Act, 1962;

(b) the area of the surplus rural evacuee land (acquired in the package deal) available for purchase by Harijans in each district of the State and each tehsil of Mahendragarh District;

(c) the terms under which the said land was acquired and the price paid for the acquisition thereof ;

(d) the terms under which the land is proposed to be sold to the Harijans ;

(e) whether Government proposes to secure agricultural land for Harijans in tehsils and districts in which little or no surplus land (acquired in the package deal) is available; if so, in what manner ;

(f) the number of Harijans of each district who have taken advantage of the aforesaid offer, the amount advanced so far and how much land has been sold in each district ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes; the ownership of land by the Harijans is expected to improve their social and economic condition and thus the scheme is covered by the purpose of t he Temporary Taxation Act.

(b) A Statement (Annexure I) is laid on the table of the House.

(c) Land was taken by the State Government from the Government of India in a package deal at the following rates—

(i) Cultivable at the rate of Rs. 445 per S.A.

(ii) Banjar at the rate of Rs. 5 per O.A.

(iii) Ghairmumkin at the rate of Rs. 100 token price.

(d) Lands in occupation of eligible Harijans are being transferred to them at the rate of Rs. 450 per S.A. Vacant lands barring a few categories, are being disposed of by auctions restricted to Harijans only.

(e) No; Government(in the Scheduled Castes and Backward Classes Department) advance only subsidies for purchase by beneficiaries of the agricultural land.

(f) A Statement (Annexure II) is laid on the table of the House.

ANNEXURE I

		Break-up of the surplus rural evacuee land available for disposal on Ist February 1965		
S. No.	Name of the district	Cultivated in Std. acres	Banjar in Ordinary acres	Ghairmumkin in Ordinary acres
1.	Amritsar	1,973	6,589	7,341
2.	Ambala	2,970	2,013	3,431
3.	Bhatinda	463	—	—
4.	Ferozepore	14,580	13 678	18,000
5.	Gurdaspur	2,918	4,329	12,211
6.	Gurgaon	969	632	466
7.	Hoshiarpur	—	688	4,036
8.	Hissar	2,442	236	87
9.	Jullundur	3,585	9,297	19,439
10.	Kapurthala	2,355	5,900	11,140
11.	Karnal	3,972	4,321	3,643
12.	Kangra	131	1,882	336
13.	Ludhiana	1,524	2,279	7,598
14.	Mohindergarh	321	192	—
15.	Patiala	14	606	828

[Public Works and Welfare Minister]

1	2	3	4	5
16.	Rohtak	825	578	2,076
17.	Sangrur	735	538	274
18.	Simla	—	—	—
	Total	39,777	53,758	90,886

Tehsil-wise figures are not available.

Excepting the following categories of areas, included in the above figures, the rest of the area will be sold to Harijans :—

(a) Land required for allotment to displaced land claimants:

(b) Lands retrieved by the Directory Organistaion:

(c) Lands already auctioned but sales set aside by the competent authorities;

(d) Lands in occupation of eligible occupants;

(e) Sub-urban lands, potential residential and commercial sites and areas in garden colonies;

(f) Small fragments of land not exceeding one acre in area surrounded by holdings of owners who are not members of Sch. Castes; and

(g) Land required by the Agr. Department for Sutlej Bed Reclamation Scheme and other Goverment Departments and Local Bodies etc. for public purposes.

ANNEXURE II.

Statement showing break-up of the rural evacuee land purchased by Harijans from 1st April, 1961 to 31st January, 1965 and the number of families benefitted.

Serial No.	Name of the district	BREAK-UP OF THE LAND SOLD/TRANSFERRED TO THE HARIJANS: *Cultivated in Std. acres*		*Banjar in Ordinary acres*		*Ghairmumkin in Ordinary acres*		*No. of families benefitted by*		Amount alocated for advancement of loans in the financial year 1964-65
		By auction	By Transfer	By auction	By Transfer	By auction	By Transfer	By auction	Transfer	(Rs. in lac.)
1.	Amritsar ..	844	13	913	—	190	—	514	6	10·00
2.	Ambala ..	1,094	98	638	—	642	—	1,071	26	15·00
3.	Bhatinda ..	1,027	—	—	—	—	—	355	—	8.00
4.	Ferozepore ..	3,218	465	1,171	110	130	21	904	611	28·00
5.	Gurdaspur ..	330	5	344	—	484	—	284	2	12·00
6.	Gurgaon ..	425	—	246	—	227	—	390	—	12·00

	1	2	3		4		5		6	7
7.	Hoshiarpur ..	531	63	1,333	—	242	—	675	30	12.00
8.	Hissar ..	1,027	932	127	—	10	—	899	471	12.00
9.	Jullundur ..	1,452	387	832	6	670	1	932	155	20.00
10.	Kapurthala ..	1,096	998	916	—	117	—	450	286	14.00
11.	Karnal ..	711	—	377	—	140	—	442	10	10.00
12.	Kangra ..	24	—	78	—	19	—	160	—	1.00
13.	Ludhiana ..	875	127	1,231	199	96	266	545	334	18.00
14.	Patiala ..	345	117	146	1	17	—	179	29	5.00
15.	Rohtak ..	318	20	143	—	338	—	322	8	10.00
16.	Sangrur ..	380	17	266	—	20	—	182	1	10.00
17.	Simla ..	—	—	—	—	—	—	—	—	Nil
18.	Mohindergarh ..	Figures included in Hissar district......								3.00
	Total ..	13,697	3,242	8,761	316	3,343	290	8,304	1,969	200.00
		16,939		9,077		3.633		10,273		

चौधरी अमर सिंह : क्या इरीगेशन तथा हरिजन कल्याण मंत्री यह बात बतायेंगे कि जैसा कि इन्होंने बताया है कि 2 करोड़ रुपया टैंपरेरी **टैक्सेशन** से निकाला गया है। सितंबर 1964 में इस मुआमले पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चौधरी रिजकराम, बाबू बृशभान और चौधरी सुन्दर सिंह मैंबर थे । इसमें यह फैसला किया गया था कि **टैंपरेरी टैपसेशन** का पैसा नहीं निकाला जायेगा, यह सैंटरल गवर्नमेंट के जरिये खर्च होगा। जब यह एक दफा दिया जा चुका है तो अब लेने के क्या कारण हैं ?

(No reply was given)

चौधरी देवी लाल : On a point of order Sir. मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हाउस में मिनिस्टर को आनरेबल मनिस्टर कहा जाता है । जो मिनिस्टर वादा पूरा न कर सके क्या उसको भी आनरेबल मिनिस्टर कहा जायेगा ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष : चौधरी देवी लाल जी, इस हाउस में हर मैम्बर को आनरेबल मैंबर या मिनिस्टर कहा जाता है । हंसी मजाक की बात एक दो दफा हो सकती है वार बार नहीं । (Chaudhri Devi Lal Ji, every member in this House is addressed as hon. Member or hon. Minister. Something may be said by way of Seoke once in a while, but not time and again.)

चौधरी देवी लाल : इस हाउस में, स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टर इस किस्म का स्टेटमेंट दें जो तमाम दुनियां में हंसी मजाक का मौजू बने । अगर हम कुछ कह लें तो क्या हर्ज है ।

श्री अध्यक्ष : आप जैसे मैम्बर के लिये ऐसी बातें करना ठीक नहीं है । कोई और मैम्बर कहे तो जुदा बात है । (It is not proper on the part of an hon. Member like you to say such things, while it could be an exemption in the case of any other Member.)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि हरिजनों के मुताल्लिक जितने भी सवाल हैं, वह चौधरी सुन्दर सिंह को देने चाहिए थे क्योंकि यह हरिजनों को रिप्रेजैंट करते हैं ।

Mr. Speaker : I pass to your request on the hon. Minister.

श्री मंगल सैन : मैं आपका रूलिंग चाहता हूँ इस बात पर कि आया जो वज़ीर जवाव देने के काबल न हों क्या वह भी वज़ीर रह सकता है ? चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी किसी एक सवाल का अच्छी तरह से जवाब नहीं दे सकते उनको जवाब देने को कहा जाता है मगर चौधरी सुन्दर सिंह जो हरिजनों के वाहिद कैबिनेट नुमायंदा हैं उनको मौका नहीं दिया जाता । हम पूछना चाहते हैं कि यह डिस्क्रिमीनेटरी ट्रीटमेंट उन के साथ आखिर क्यों किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : चौधरी रिज़क राम, चौधरी सुन्दर सिंह से पूछ कर सारी बातों का जवाव दे रहे हैं । (Replies are being given by the Minister with the consent of Ch. Sunder Singh (laughter)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਏਧਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੋਵੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

(No reply from the Chair)

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं एक और चीज़ प्वायंट आऊट करने लगा हूं। स्पीकर साहिब, वह यह कि एक हरिजन डिप्टी मिनिस्टर को तो पीछे बैठाया जा रहा है। उसको तो आगे बैठने की इजाज़त नहीं मगर आरडिनरी M.L.A.'s वज़ीरों के बराबर आकर बैठते हैं। यह कितना डिस्क्रिमीनेटरी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। क्या यह वाजब है ?

श्री अध्यक्ष : आप भी बराबर के मैम्बर हैं, आपके साथ भी इस तरह की डिस्क्रिमीनेशन हो सकती है। (The hon. Member holds an equally similar status and similar discrimination can be done to him also.) (शोर)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਜਦ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਫਰੰਟ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ?

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਸਿਮਪਥੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਸਪੈਰੀਟੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। (ਥੰਪਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਡੈਸਕਸ) (ਸ਼ੋਰ)

श्री अध्यक्ष : ऐसा नज़र आता है कि आप और कुछ बिज़नस करने के हक में नहीं हैं। Please allow me to carry on. (It appears that the hon. Members are not in favour of any more business being transacted. Please allow me to carry on.)

Question Hour is over. More supplementaries may be put in the next sitting.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

CANCELLATION OF APPOINTMENT OF AN ASSISTANT EMPLOYMENT OFFICER

***7348. Dr. Baldev Prakash** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether it is a fact that Shri Gurbachan Chand Kaushal was appointed as Assistant Employment Officer vide Government letter No. 5680-II-Lab-I-63/12282 dated 6th, August, 1963 but before his joining his appointment was cancelled and some one else appointed there to , if so, the reasons therefor ?

Chaudhri Rizaq Ram : Yes. A reserved vacancy of an Assistant Employment Officer was offered to Shri Gurbachan Chand Kaushal who belonged to Backward Classes as no candidate belonging to Scheduled Castes/ Tribes was available at the first instance. This offer was subsequently cancelled before Shri Gurbachan Chand Kaushal actually joined, because a candidate belonging to Scheduled Caste became available.

RECRUITMENT OF ASSISTANT EMPLOYMENT OFFICERS DURING, 1963

*7349. **Dr. Baldev Prakash :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) (i) whether any demand was sent to the Punjab Public Service Commission for the recruitment of Assistant Employment Officers in the State during the year, 1963;

(ii) if so, the names of persons recommended for the posts by the Commission to the Government;

(b) the names of the persons to whom letters of appointment were sent and of those who joined as such;

(c) whether it is a fact that in some cases letters of appointment were subsequently cancelled, if so, the reasons therefor ;

(d) whether it is a fact that Government recruited some Assistant Employment Officers in 1963 without making any reference to Public Service Commission, if so, the names of the persons directly recruited and the reasons for their recruitment ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) (i) Yes.

(ii) No person was specifically recommended by the Commission for appointment as Assistant Employment Officer. The candidates were, however, to be appointed on the basis of the result of the P. C. S. (Executive Branch) and other Services Examination, 1963 in order of merit.

(b) List is placed on the table of the House.

(c) Yes. Letter of appointment was cancelled in respect of Shri Harbhajan Lal Moudgil as he was offered the post of Tehsildar.

(d) No.

LIST

The offers of appointment as Assistant Employment Officers were issued to the following:—

1. Shri Harbhajan Lal Moudgil.
2. Shri Suraj Parkash Dudeja.
3. Shri Shubh Dev Sharma.
4. Shri Radhey Sham Chowdhary.
5. Shri Dev Raj Jain.
6. Shri Hardev Raj.
7. Shri Laxmi Narain Verma.
8. Shri Sham Lal Vig.

2. Subsequently Shri Harbhajan Lal Moudgil was considered for appointment as Tehsildar candidate and Shri Ved Parkash Mehta who was allocated for appointment as a

Assistant Employment Officer instead was issued offer of appointment accordingly. Out of these, Sarvshri Shubh Dev Sharma, Sham Lal Vig, Radhey Sham Chowdhary and V.P. Mehta, joined as Assistant Employment Officers in the Employment Department Punjab.

REPRESENTATION BY THE JAGATJIT KAPRA MILLS MAZDOOR UNION, PHAGWARA

***7654. Shri Om Parkash Agnihotri :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether Government have received any demand notice from Jagatjit Kapra Mill Mazdoor Union, Phagwara regarding re-instatement of some active workers and office-bearers of the Union, dearness allowance etc., if so, the action taken thereon ?

Chaudhri Rizak Ram : Yes. A demand notice was received from the Jagatjit Kapra Mill Mazdoor Union, Phagwara regarding re-instatement of some workmen and dearness allowance etc. The matter was taken up in conciliation and a settlement was arrived at between the parties on the major issues, i. e. re-instatement of some workers and dearness allowance on 12th February, 1965. The other issues are being examined on merit.

NUMBER OF HIGH/HIGHER SECONDARY SCHOOLS AND CO-EDUCATION

***7104. Chaudhri Net Ram :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the number of High and Higher Secondary Schools opened by Government in the State during the period from 1962 to 1964 ;

(b) the number of co-educational schools in the State at present ?

Shri Prabodh Chandra : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) **High/Higher Secondary Schools opened from 1962 to 1964.**

1952-53.—1. Government Co-educational Higher Secondary School, Talwara Township (District Hoshiarpur).

1953-54.—1. Government High School, Sukhpur (Mauran), District Sangrur.

1964-65.—Nil.

(b) **Co-Educational Schools in the State.**—

1.	Middle Schools	.. 481 (460 Government and 21 Non-Government).
2.	High Schools	.. 228 (Government 164, Non-Government 64)
3.	Higher Secondary Schools	.. 15 (Government 14, Non Governement 1)

TRANSFER OF PRINCIPALS OF GOVERNMENT COLLEGES

*7317. **Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether the Principals of some of the Government Colleges in the State were recently transferred, if so, the names of such Colleges and the reasons for such transfers;

(b) whether the transfer orders referred to in part (a)above were subsequently cancelled and the respective Principals asked to go back to their original places, if so, how long after the orders of transfer, together with the reasons therefor in each case?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes; these are the Principals of Government Colleges, Ludhiana, Rupar and Nabha and Sports College, Jullundur. These transfers were made on administrative grounds.

(b) Yes; the transfers were reviewed by Government and cancelled after about three weeks.

GRANTS-IN-AID GIVEN TO PRIVATELY MANAGED SCHOOLS

*7471. **Shri Ram Saran Chand Mital :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the number of privately-managed High Schools and Higher Secondary Schools in each district of the State and the amounts of grant-in-aid paid to them (district-wise) during the years 1961-62; 1962-63, 1963-64 and 1964-65 to-date ;

(b) the names of privately-managed High Schools and Higher Secondary Schools in Mahendragarh district and the amounts of grants-in-aid paid to each of them during each of the said years ?

Shri Prabodh Chandra : (a) and (b) Statement I and II are laid on the Table of the House.

Statement I showing the number of Private High & Higher Secondary Schools in each District and the amount of grant-in-aid Sanctioned to them during the years 1961-62 to 1964-65.

Serial No.	Name of the District		No. of High & Higher Secondary Schools to which grant-in-aid was sanctioned during				Amount of grant-in-aid sanctioned during			
			1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
							Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1.	Ambala	..	60	34	49	22	2,06,591	60,252	96,805	52,380
2.	Karnal	..	32	24	19	7	3,06,464	28,824	60,694	10,912
3.	Rohtak	..	30	15	24	10	1,50,684	44,388	88,612	28,108
4.	Hissar	..	11	6	10	2	1,42,331	8,556	28,947	3,852
5.	Gurgaon	..	19	5	12	6	1,00,074	21,294	28,507	22,618
6.	Simla	..	6	6	5	3	28,694	27,626	12,336	2,128
7.	Jullundur	..	84	47	46	24	2,42,280	68,886	1,09,835	36,664
8.	Ludhiana	..	51	34	42	25	2,28,665	61,362	1,23,244	46,708
9.	Amritsar	..	50	33	37	31	3,21,919	52,680	1,40,402	94,940
10.	Ferozepore	..	34	23	26	17	2,04,894	45,144	68,041	41,500
11.	Kangra	..	22	12	13	6	1,03,979	18,240	46,991	17,460
12.	Hoshiarpur	..	90	57	41	25	4,22,928	1,03,368	1,07,323	60,156
13.	Gurdaspur	..	35	24	30	10	1,82,118	20,940	1,26,005	18,224
14.	Kapurthala	..	12	5	11	12	1,17,449	10,510	50,167	33,588
15.	Patiala	..	25	9	23	27	1,58,001	11,407	56,442	55,620
16.	Bhatinda	..	14	6	20	19	99,127	22,736	66,266	62,364
17.	Sangrur	..	19	5	15	18	1,70,024	5,945	62,860	40,500
18.	Mohindergarh	..	3	—	—	—	4,346	—	—	—

[Education and Local Government Minister]

Statement II showing the names of privately managed High and Higher Secondary Schools in Mohindergarh District and the amount of grant-in-aid sanctioned to them during the year 1961-62 to 1964-65.

Serial No.	Name of the School	AMOUNT OF GRANT-IN-AID SANCTIONED DURING			
		1961-62	1962-63	1963-64	1964-65 upto 28th February. 1965
		Rs	Rs	Rs	Rs
1.	A. S. D. Higher Secondary School, Narnaual ..	349	—	—	—
2.	M. B. High School. Patikara ..	1,090	—	—	—
3.	R. R. High School, Bassai ..	2,907	—	—	—
	Total ..	4,346	—	—	—

PRIMARY AND MIDDLE SCHOOLS UP-GRADED IN DISTRICT KAPURTHALA

***7653. Shri Om Parkash Agnihotri :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the total number and names of Primary and Middle Schools Government and privately managed, in the Kapurthala District. which were upgraded during the period from 1st April, 1964 to 31st January, 1965 separately ;

(b) the total number and names of privately managed primary and Middle Schools which were taken over by the Government during the said period in the said District ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Only one school, namely, Government Primary School, Nurpur Lubana, has been sanctioned to be upgraded to Middle Standard in Kapurthala District on the condition that the local people will construct 8 rooms to house the upgraded School. They have, however, not provided the requisite accommodation so far with the result that the Middle Classes could not be started as yet.

(b) None.

UPGRADING OF GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL LIKHI; HODAL BLOCK DISTRICT GURGAON

***7798. Chaudhri Har Kishan :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Gram Panchayat, Likhi, Hodal Block, district Gurgaon has completed the construction of eight rooms and one staff quarter for the Government Primary School, Likhi;

(b) whether the Government or the Education Department has received any representation from any legislator of Gurgaon District and the inhabitants of Village Likhi for upgrading the said Primary School to the Middle Standard, if so, when and with what results ;

(c) the number of boys and girls at present studying in the said school separately ;

(d) whether the said Gram Panchayat has also assured the Education Department that it would fulfil all the conditions that may be laid down for upgrading the said school, if so, the time likely to be taken upgrade the said schools ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes.

(b) Yes, in August and October, 1964. The question of upgrading this school is under consideration.

(c) Boys 260, Girls 100.

(d) Yes. The question of upgrading of schools is under active consideration. No definite date can be specified.

EDUCATIONAL FACILITIES IN VILLAGES IN HODAL AND HATHIN BLOCKS (DISTRICT GURGAON)

*7799. **Chaudhri Har Kishan :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the names of villages in Hodal Block and Hathin Block district Gurgaon where no educational facilities exist, stating the number of students of each such village who go to other places for getting education and also of other children of schools going age in each village;

(b) whether the Education Officers have persuaded the inhabitants of the aforesaid villages to provide building etc. for opening schools, if so, with what results ;

(c) whether Government intend to provide atleast a Government Primary School in each of the said villages where it does not exist, if so, when ?

Shri Prabodh Chandra : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) Yes, every effort has been made to persuade the inhabitants of these villages to provide accommodation so that Branch Primary Schools could be set up but the response has not been encouraging.

(c) Yes, provided the village people give rent free accommodation and there are at least 30 children likely to attend the school.

[Education and Local Government Minister]

STATEMENT

Name of the Villages in Hodal and Hathin Blocks where no educational facilities exist	No. of students of each such village who go to other places for getting education	No. of other children of school going age in each village
Hathin Block		
1. Khenekauli	5	11
2. Kherli BX Brahman	10	20
3. Man Bake	8	15
4. Garhi Benoda	15	25
5. Mangnaka	10	40
6. Kuha Chali	7	20
7. Paharpur	15	40
8. Paunka	10	20
9. Ali Brahman	10	16
10. Bhoodpur	10	20
11. Aluka	5	10
12. Bhapauli	10	15
13. Gulessera	7	11
14. Murka	8	15
15. Ghingraka	5	14
16. Balampur	10	15
17. Daianchi	10	25
18. Kalinger	20	50
19. Thihanka	5	10
20. Karam Chand	6	15
Hodal Block		
21. Tappa Belochpur	20	25
22. Benwarika	15	28
23. Daina	17	30
24. Shikhsai	15	32
25. Machinpura	10	40

INCREASE IN T.B. PATIENTS

***7103. Chaudhri Net Ram :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state whether it is a fact that the number of T.B. patients in the State is on the increase; if so, the reasons therefor and the steps being taken by the Government to ckeck it ?

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE

Shri Prabodh Chandra : A statement is placed on the table of the House.

STATEMENT

No recent survey has been made to indicate that the number of T.B. patients in the State has increased, though it is generally believed the disease is on the increase on account of the stresses and strains of modern life. The number of cases coming up to the hospital has, of course, increased, but this by itself cannot be considered an indication of increased incidence of the disease, as with greater facilities for treatment more patients are availing the same. The only survey held in this connection was a sample survey held in 1955—58 and as a result thereof it was estimated that there might be 3,80,000 T.B. patients in the State, out of which about 1/4th may be infectious cases.

The steps taken to fight the disease are (i) Health Education, (ii) emphasis on nutrition, and (iii) greater facilities for treatment. The number of T.B. clinics has been gradually increasing. Two clinics have recently been sanctioned for Kulu and Bhatinda. Now we shall have a T.B. clinic, —Government or Government aided,—in each district of the State, except Lahaul and Spiti. The total number of hospitals and T.B. clinics where treatment is available is 35. The total bed strength for indoor patients is 1915. It is intended to increase the T.B. beds during the Fourth Plan. It is also intended to lay greater emphasis on domiciliary treatment, as after a patient has passed out the actual acute stage he can be treated at home. Financial assistance in the form of medicines to the tune of Rs. 50,000 is being given to out-patients. During the Fourth Plan we also intend to take over or give greater aid to T.B. clinics run by private bodies. All this, however, is subject to availability of funds.

RAIZADA HANS RAJ STADIUM, JULLUNDUR

***7482 Chaudhri Darshan Singh** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state :

(a) the total amount spent on the costruction of Raizada Hans Raj Stadium at Jullundur ;

(b) the names of persons and institutions who have contributed some amount for the said stadium and the amount contributed in each case ?

Shri Prabodh Chandra :

(a) Rs 1,82,000.
(b) The list of the contributors is given below :

List

Serial No.	Names of persons & institutions		Amount
			Rs
1.	Raizada Hans Raj Memorial Fund	..	37,500
	(Promised..............Rs 50,000)		
	(Due.................... Rs 12,500)		
2.	Through District Board, Jullundur	..	5,000
3.	Misc, Receipts through Shri Rajinder Bhanot	..	5,000
4.	Deputy Commissioner, Jullundur, Grant-in-aid	..	18,000

[Education and Local Government Minister]

1	2		3
5.	District Red Cross Society	..	10,000
6.	District Relief Fund	..	10,000
7.	District Cricket Association	..	10,000
8.	Ludhiana Engineering Works	..	2,500
9.	Municipal Committee, Jullundur	..	35,000
10.	Leader Engineering Works	..	5,000
11.	M/s Amin Chand Payare Lal (Rs 10,000 for materials) (Rs 1,500)	..	11,500
12.	Shri P. S. Jain, Jain Motors	..	5,000
13.	Wrestling Match	..	7,500
14.	Various Panchayat Samities	..	21,000
15.	District Olympic Association	..	10,000
16.	Shri G. W. Balker & Co.	..	2,500
17.	Punjab Government	..	10,000
18.	Sports Department	..	10,000
19.	Shri Dharam Pal Dada	..	1,000
20.	Shri K. K. Hitkari	..	1,000
21.	Shri Suraj Bhan	..	300
22.	Halwai, Dhobi, Tandoor, Dhaba Association	..	2,000
23.	Shri Darbara Singh, M.L.A., (Minister)	..	300
24.	Shri Hans Raj Mahajan & Sons	..	500
25.	Misc. Receipts, through Brick Killn Owners and other individuals	..	1,715
	Total	..	2,22,315

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

KURALI-SISWAN AND MULLANAPUR SISWAN ROAD DISTRICT AMBALA

2516. Babu Ajit Kumar : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some portion of Kurali-Siswan road has been left Kacha, if so, whether the Government intend to make it pucca ;

(b) whether it is also a fact that the Mullanpur-Siswan Road in district Ambala is being metalled, if so, the time by which the construction work on the said road is likely to be completed ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) The entire Kurali Siswan Road has already been completed in all respects except three bridges of about 1040 feet total length.

(b) Yes. The road is likely to be completed during the 3rd Plan subject to availability of funds.

LADWA-BRARA AND RADAUR-JATHIANA ROAD IN KARNAL DISTRICT

2517. Chaudhri Ran Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether the Government has ever considered the desirability of constructing Ladwa-Brara road and Radaur-Jathiana road in Karnal District, if so, the latest position regarding the construction of each of these road ?

Chaudhri Rizaq Ram : None of these roads could so far be included in any Five-Year Plan owing to the limited scope of funds. These are likely to be considered in some subsequent plan.

OPENING OF HIGH/HIGHER SECONDARY SCHOOL AT MODEL TOWN HISSAR

2518. Shri Hunna Mal : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether there are any High Schools or Higher Secondary Schools in the Model Towns at Rohtak, Sonepat, Panipat, Ambala, Rajpura, Ludhiana, Jullundur and Amritsar ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative,the reasons why no High School/Higher Secondary School has been opened in the Model Town, Hissar which is situated at the Head-quarters of the biggest district in the State ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of the Government to provide such educational facilities in Model Town Hissar, if so, when ;

(d) whether he is aware of the fact that there has been considerable increase in the population and the number of students boys and girls, seeking admission to the educational institutions in the town of Hissar;

(e) whether he is aware of the fact that there is at present a double shift system in the local girls higher Secondary School at Hissar ;

(f) whether it is a fact that the buildings of the Middle and High schools for boys at Hissar are quite inadequate for the number of boys seeking admission to these schools; if so, the steps, if any, proposed to be taken to meet this shortage ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes, except at Sonepat, Ludhiana and Amritsar.

(b) Because of inadequate accommodation in the Government Middle School, Model Town, Hissar. Besides, High/Higher Secondary Schools exist at a short distance in the Town.

(c) In view of (b) above question does not arise.

(d) and (e) Yes.

(f) Yes. The matter is under consideration.

NATIONAL DEFENCE FUND COLLECTED BY GRAM PANCHAYAT KHURD, TEHSIL MALERKOTLA, DISTRICT SANGRUR

2520. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount collected for the National Defence Fund by the Gram Panchayat Khurd, Tehsil Malerkotla, District Sangrur in 1963 together with the amount actually deposited by it with the Government ;

(b) whether it is a fact that the total amount actually collected for the said fund had not been deposited by the Gram Panchayat concerned;

(c) whether it is also a fact that an enquiry was conducted against the Ex-Sarpanch of the said village Panchayat in the year 1964, if so, the details of the report of the said enquiry ?

Comrade Ram Kishan : (a)

	Rs.
(i) Amount collected ..	3,076.65
(ii) Amount deposited with Treasury in 1963 ..	3,017.00

(b) Yes.

(c) The B.D. and P.O., Ahmedgarh, conducted an enquiry and recommended to S.D.M., Malerkotla that a case for embezzlement of Rs. 84.24 be instituted against the Sarpanch, Shri Tehal Singh. The S.D.M. Malerkotla has intimated that the said Sarpanch had since deposited Rs. 84.24 However, the case under section 409 I.P.C. is still under investigation with the police.

NATIONALISATION OF PATIALA-SIRHIND ROUTE

2521. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Chief Minister be pleased to state whether Government is considering any scheme to nationalise the Patiala-Sirhind Route, if so, the time likely to be taken to finalise the Scheme ?

Comrade Ram Kishan : (a) Yes.

(b) No time limit can be specified.

SETTING OF INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE AT MAHILPUR, DISTRICT HOSHIARPUR

2522. Shri Gurmail : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any Industrial Training Institute had been sanctioned to be established at Mahilpur, district Hoshiarpur;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the Government at any stage agred to take over six acres of vacant land donated by S.G.G.S., Khalsa College, Mahilpur and also proposed to acquire more land for the setting up of the said Institute;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the reasons for the delay in the construction of the building for the said Institute ?

Comrade Ram Kishan : (a) Not yet.

(b) No. The offer to donate some land is, however, under consideration.

(c) Does not arise.

RESTORATION OF VILLAGE RUHNAT IN DISTRICT HISSAR

2523. Shri Amar Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government have received any representations or deputations from the residents of Ruhnat in district Hissar from July, 1964 to-date, requesting for the restoration of the village Ruhnat which was forfeited by the British Government in 1857, if so, a copy of the representations be laid on the Table of the House;

(b) the action, if any, taken or proposed to be taken by the Government on the said representations stating the approximate date by which the matter is likely to be finalised ?

Comrade Ram Kishan : (a) Yes. Representations were received both in English as well as in Urdu. A copy of the representation made in English is laid on the Table of the House. As regards the representation made in Urdu, it can be seen by the Honourable Member in the W.G. II Branch of the Punjab Civil Secretariat.

[Chief Minister]

(b) (i) There is no way to help the applicants in getting back the possession of the confiscated land from the present owners, who are in its continuous possession since 1858 and have thus established proprietory rights;

(ii) It is not the policy of the Government to restore the properties confiscated in National movement launched prior to the year, 1913.

COPY OF THE REPRESENTATION

To

Comrade Ram Kishan Ji,
Chief Minister, Punjab State, Chandigarh.

Sir,

We the residents of Mauza Rohnat, Tehsil Hansi District Hissar beg to draw your kind attention to our village which is famous for taking keen and active part in the First Independent war, in 1857. The English, seized 24,000 bighas of land of this village and auctioned against Rs. 8,100. **Inspite of approaching every officer, none heard our humble request for restoration of land of our village.**

This is for your kind information that we have been called traitors but remained silent.

The population of this village converted the village in Model Gaon.

Please be kind enough to go through the history of our village and help us in getting back the seized land.

Hoping for early action in the matter.

Yours faithfully,

Dated the 2-7-1964

Panchayat Rohnat Village,
Tehsil Hansi District Hissar (Punjab).

(Sd) Hindi

DALIP SINGH
2-7-1964
Sarpanch.
(Seal)
Gram Panchayat Rohnat.

SPARE PARTS PURCHASED BY P.R.T.C., PATIALA

2524. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the firms at Delhi from whom spare parts are purchased at present by the Pepsu Road Transport Corporation, Patiala;

(b) a list containing the details of articles purchased by the said transport Corporation together with the names of the firms from whom purchased during the last four years be laid on the Table of the House;

(c) the total amount of Octroi duty paid on the articles mentioned in part (b) above ?

Comrade Ram Kishan : (a) List is attached.

(b) and (c) Time and labour involved in the collection of the information sought will not communsurate with the benefit proposed to be derived therefrom. Information will be supplied on any particular point, if sought.

FIRMS AT DELHI FROMS WHOM SPARE PARTS,INCLUDING ELECTRICAL EQUIPMENT AND HARDWARE ITEMS, ARE PURCHASED.

Manufactures

1. M/s India Tyre & Ruber Co., Delhi.
2. M/s Premier Tyres Ltd., Delhi.
3. M/s Ceat Tyres of India Ltd., Delhi.
4. M/s Indian Oxygen Ltd., Delhi.
5. M/s Imperial Chemical Industries. Delhi.
6. M/s Phillips India Ltd., Delhi.
7. M/s Shalimar Paints, Ltd., Delhi.
8. M/s St. John Ambulance Stores Depot, Delhi.
9. M/s Racman Koshatkin (Regd.), Delhi.
10. M/s Muraka Engineering Works, Delhi.
11. M/s Pradip Lamp Works, Delhi.
12. M/s Indo Glass Industries, Delhi.
13. M/s Khosla Automobile Co., Delhi.
14. M/s Bhagwan & Anand, New Delhi.
15. M/s Channey Engineering Works, Delhi.
16. M/s Path Darshak Industries, Delhi.
17. M/s R. P. Conduit Manufacturing Co., Delhi,
18. M/s G. N. J. Industries, Delhi.
19. M/s Janta Auto Agency, Delhi.
20. M/s Saini Motor Co., Delhi.
21. M/s Victor Industrial Corporation, Delhi.
22. M/s Sharaco Industries, (P) Ltd., Delhi.
23. M/s Associated Engg. Works, Ltd., Delhi.
24. M/s Auto Linkers, Delhi.
25. M/s Amta Industries, Delhi.

Authorised Dealers

1. M/s Globe Motors, Delhi,
2. M/s Siya Ram Bros., Delhi.
3. M/s Allied Motors, (P) Ltd., New Delhi.
4. M/s Allied Trading Co., Delhi

[Chief Minister]

5. M/s Jullundur Motor Agency, Delhi
6. M/s R. C. Edwards & Co., Delhi.
7. M/s Premier Auto Electric, Ltd., Delhi
8. M/s Machine Tools Corporation, Delhi.
9. M/s Sant Ram Parma Nand, Delhi.
10. M/s Narula Motor, Delhi.
11. M/s S. N. Kohli & Co., Delhi.
12. M/s Ramji Lal Ram Sarup, Delhi.

Firms Supplying on Competitive Rates

1. M/s General Auto Parts Co., Delhi.
2. M/s Highway Motor Stores, Delhi.
3. M/s Ashoka Autolines, Delhi.
4. M/s Rightway Motors, Delhi.
5. M/s Som Leylands Stores, Delhi.
6. M/s Sethi Auto and Tools Agency. Delhi.
7. M/s Jupitor Motor, Delhi.
8. M/s Kishore Motors, Delhi.
9. M/s Baisiwala Auto Spares, Delhi.
10. M/s B. C. D. Auto Parts, Delhi.
11. M/s Evergreen Auto Agency, Delhi.
12. M/s Friends Auto Agency, Delhi.
13. M/s Raj Motors, Delhi.
14. M/s Kayvee Motors, Delhi.
15. M/s Janta Corporation, Delhi.
16. M/s B. N. Dheer & Sons, Delhi.
17. M/s Aggarwal Electronics, Delhi.
18. M/s Jain Electric Store, Delhi.
19. M/s Narsinghsahay Madangopal Elect. Co. (P) Ltd., Delhi.
20. M/s Shad India Agencies, Delhi.
21. M/s Havela Singh Ujagar Singh, Hardawre Merchants, Delhi.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, मैं ने कल शाम को एक प्रार्थना की थी कि कल जब हाउस डिप्टी स्पीकर साहिबा के काबू से बाहर हो गया तो उन्होंने आवेश में आ कर हाउस को एडजर्न कर दिया और उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी देर के लिए या किस तारीख के लिए । यह हाउस आगस्ट हाउस है और उसकी सैंकटिटी को कायम रखने के लिए यह श्रेष्ठ है कि इसकी कार्रवाई नियमों अनुसार हो । कानून है कि जब हाउस एक बार इनडैफीनिट पीरियड के लिए एडजर्न हो जाए तो उसको गवर्नर साहब ही समन कर सकते हैं, स्पीकर भी काल नहीं कर सकता है । मैं समझता हूं कि यह अनकंस्टीचुशनल बात हुई है । आप इस पर अपनी रूलिंग दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, आपका व्यूप्वाइंट आ गया ।

(The Hon. Member may please sit down. He has already given his Point of view)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਬੜਾ ਡਿਸਆਰਡਰਲੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਜਦ ਹਾਊਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਊਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਐਡਜਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : जनाब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जब क्वैश्चन आवर बीत चुका तो अब इस प्वायंट को कैसे रेज़ किया जा सकता है। This could have arisen at the very outset before the beginning of Question Hour. Can this point be raised now ? मैं यह चाहता हूँ कि अब यह प्वायंट रिओपन नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मैं श्री चिरंजीलाल जी से ऐग्री करता हूँ । अगर कोई मेम्बर साहिबान यह समझते थे कि आज हाउस नहीं बुलाया जाना चाहिए था तो क्वैश्चन आवर से पहले उन्हें यह सवाल रेज़ करना चाहिए था । मैं कान्स्टीचुशनल पोज़ीशन हाउस के सामने रखता हूँ । अगर हाउस ऐडजर्न हो, प्रोरोग न हो तो उसको गवर्नर नहीं बल्कि स्पीकर ही बुलाता है । रूल 15 के मुताबिक सब क्लाज़ 3 में यह ज़रूरत नहीं है कि हाउस कितनी देर के लिये ऐडजर्न हो, सिर्फ एडजर्न हो जाए तो उसे एडजर्न ही समझा जाता है ।

इसके मुताबिक बिज़नेस ऐडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट ऐडाप्ट हो गई कि आज 8–30 बजे सुबह हाउस मिलेगा और नोटिस आफ मीटिंग और एजेंडा आपके पास पहुंच गया तो इसका मतलब यही है कि this sitting is quite in order.

(I agree with Mr. Chiranji Lal. If some of the hon. Members were of this veiw that the meeting of the House should not have been called for to-day, they should have raised this point before the Question hour. I would like to place the constitutional position in this regard before the House. If the House is adjourned and not prorogued then its meeting

[श्री अध्यक्ष]

is called by the Speaker and not by the Governor. No time Limit is required for the adjourment of the House under sub-clause (3) of rule 15. If the House is adjourned it is understood to have been adjourned. According to this the Report of the Business Advisory Committee was adopted that the House would meet to-days at 8-30 A.M. When the notices pertaining to to-day's meeting of the House and the agenda of business had been duly received by the hon. members, it all indicates that this sitting is quite in order.)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और उसको उन्होंने यहां हाउस में पढ़ भी दिया था ....

Mr. Speaker : You have drawn my attention. I am making my observations.

WITHDRAWAL OF STATEMENT

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮਰਡਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਇਹ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ?

Mr. Speaker : This means that the statement which was read or distributed to Members yesterday will be treated as withdrawn.

Home and Development Minister : Yes, sir.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਗਰ......

Mr. Speaker : Government has withdrawn it and I have agreed to it.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜਨਾਬ, ਇਹ ਗਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ।

Mr. Speaker : If it comes in the Press it will be a matter of privilege particularly. I say, it will not form part of the proceedings.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : स्पीकर साहिब, कल उन्होंने अपना स्टेटमेंट विदड्रा नहीं किया था ।

(Noise and interruptions in the House)

Mr. Speaker : I said "Whatever part of the statement has been read out, will not form part of the proceedings of the House".

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਤੀ । ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੰਨਸਲਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਧ ਵਿਚੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : I can expunge any proceedings of the meeting of the House. अगर वह स्टेटमेंट पढ़ा ही न जाता तो मैं एक्सपंज क्या करता । (I can expunge any proceedings of the meeting of the House. If he had not read out his statement what would have been expunged?)

It was expunged in deference to the wishes and opinion of hon. Members of the House. This decision of the Government should rather be appreciated. In view of the strong opinion of the House, the Government considered the matter and also consulted the Advocate-General and had withdrawn the statement. I also consulted the Advocate-General. In view of the strong feelings of the hon. Members, we should not come into conflict with judicial cases and we should not take any step which in any way comes into conflict or prejudice the case which is sub-judice. The statement has been withdrawn by Government. I am fully competent to expunge any proceedings of the House.

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਉ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਏਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : Please resume your seat.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट विदड्रा किया है यह अच्छी बात की है । इसके बारे में दो राएं नहीं हो सकतीं । स्पीकर साहिब, जब से यह हाउस शुरू हुआ है ऐसी ही चीजें दुहराई जा रही हैं । मैं आपको दरखास्त करूँगा कि यह नई नई वजारत है, आप इनकी क्लासिज लगाएं और उनको बताएं कि कौन सा मामला सबज्यूडिस होता है, कौन सी बात यहां पर कहनी चाहिए, कौन सी नहीं कहनी चाहिए । स्पीकर साहिब, आपोजीशन वाले कब तक इनको गाईड करते जायेंगे । इनको चाहिए जसटिस गुरनाम सिंह जी का धन्यवाद करें । बाकी आप हाउस के बाहिर एक आधा घण्टा इनको गाईड किया करें नहीं तो यह ऐसा इस हाउस को लेटडाऊन करेंगे कि कोई रास्ता नहीं मिलेगा ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : स्पीकर साहिब, गवर्नमैंट ने जो फैसला बदल लिया है कि स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था यह अच्छी बात की है । स्टेटमेंट का जो भाग मुख्य मंत्री साहिब ने दे दिया उसको तो आपने एक्सपंज कर दिया लेकिन जो प्रिंटिड कापी यहां पर तकसीम हो चुकी है उसके बारे में मैंने कल यहां पर प्वायंट आफ आर्डर रेज किया था और आपने कहा था कि मैं कल को अपना रूलिंग दूंगा । उस वक्त आपने नहीं कहा था कि circulated part of the statement will not form part of the proceedings । इसके पेशेनज़र यह कैसे प्रिविलेज का मामला बन सकता है ?

Mr. Speaker : If any thing relating to a case which is *sub-judice* has been published in the Press, they must have done it at their own responsibility. I will see to it if any such case is brought to my notice. It will be referred to the Privileges Committee which will fully thrash it.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, may I know whether it amounted to have been withdrawn yesterday ? The Government took a decision to withdraw the statement after the adjournment of the House. Till then, there was no announcement to this effect either from the hon. Chief Minister or from any other Member of the Council of Ministers. Sir, you were pleased to observe that you would give your ruling the next day. What I want to know, Sir, is whether it amounted to withdrawal of the statement yesterday ?

Mr. Speaker : A statement which is laid on the Table of the House becomes the property of the House. But a statement which is meant to be read out and until and unless that is read out, it does not form part of the proceedings of the House. About that portion of the statement which was read out by the hon. Chief Minister, I gave my ruling that it would not form part of the record of the proceedings of the House. We cannot take official cognizance of that portion of the statement which was not read out. Since the Government has announced the withdrawal of the statement, the whole of the statement will be treated as having been withdrawn.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I would like to have your ruling whether this principle will also apply to that portion of Governor's Address which was not read out by him on the Floor of the House. In that case, only that part of the Address which was read out by the Governor will form part of the proceedings of the House.

Mr. Speaker : The hon. Member Pandit Chiranji Lal Sharma will agree that the Governor delivers his Address to both the Houses assembled together. It is not an Address to the Members of the Assembly or the Council alone. After the Governor has delivered his Address, I lay it on the Table of the House, and then it becomes the property of the House.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਕਲ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ । ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ part of the proceedings of the House ਸਮਝੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

Mr. Speaker : Yes, it is a part of the proceedings of the House.

ਸਰਦਾਰ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

Mr. Speaker : If the Press has published any such thing, they have done it at their own cost.

(At this stage, some hon. Members rose on points of Order.)

Mr. Speaker : I would request the hon. Members not to re-open this matter.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਪਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਪਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ? ਮੈਂ ਪਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker : Let me find out the facts as to whether the Deputy Speaker as Presiding Officer allowed it to be laid on the Table of the House or not.

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, मेरी गुजारिश यह है कि कल मैंने उस पोस्टर को यहां हाउस में...........

Mr. Speaker : Please take your seat. Let me first find out the facts and then I will give my ruling.

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। कल लीडर आफ दी हाउस ने यहां पर एक स्टेटमैंट पढ़ी जिसके बारे में उन्होंने ऐल. आर. को और ऐडवोकेट जनरल को कन्सल्ट किया जिसका हशर यह हुआ कि उस स्टेटमैंट को हाउस में बांटने के बाद उसे ऐक्सपंज करना पड़ा। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि उसी स्टेटमैंट के बारे में लीडर आफ दी हाउस को पार्टी मीटिंग में बुला कर उन के कान खींचे गए और कोठी पर भी लानतान की गई। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है कि इस तरह उनको हाउस में ब्यान देने से रोका जाए जिसकी वजह से वह राम किशन की बजाए अनजान किशन और ब्यान किशन बन गए हैं। यह हाउस की इन्सलट है आया यह हाउस का ब्रीच आफ प्रिविलेज है या नहीं और क्या प्रिविलेज मोशन आ सकती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : कोई मोशन आ सकती है या नहीं यह आप सरदार गुरनाम सिंह जी से पूछ लें। But I know one thing that it is a responsive and co-operative attitude of the Govt. कि जो पुजीशन उन्होंने ली उसे आपोज़ीशन के कहने पर reconsider करके किसी, खास नतीजे पर पहुंचने के बाद बदल लिया और स्टेटमैंट को विदड्रा कर लिया। (The hon. Member may consult Sardar Gurnam Singh on the point whether a particular motion can be moved or not. But I know one thing that it is a responsive and co-operative attitude of the Govt. to reconsider the position taken by it at the request of the opposition and change a definite decision arrived at by it and withdraw the statement.)

सरदार लछमन सिंह गिल : अगर वह वापस न लेते तो कैद हो जाते। केस हाई कोर्ट में चला जाता तो वह अन्दर हो जाते.........(शोर)

पंडित सुरेन्द्र नाथ गौतम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहिब, कल जो गर्मजोशी हाउस में पैदा हुई और हाउस एडजर्न करना पड़ा वह इस इश्तेहार की वजह से सब कुछ हुआ लेकिन आपने उसके बारे में कोई रूलिंग नहीं दिया कि वह पार्ट आफ दी प्रोसीडिंग्ज़ होगा या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : मुशिकल यह है कि मैम्बर साहिबान जो मैं आब्ज़र्वेशन करता हूँ उसे सुनने समझने की कोशिश नहीं करते । Let me find out the facts and then I will give the ruling. (The difficulty is that the hon. Members do not take the trouble of listening and under-standing the observations made by me. Let me find out the facts and then I will give the ruling)

ADJOURNMENT MOTION

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : मैं ने एक एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया हुआ है ।

Mr. Speaker : If I do not admit an adjournment motion in my Chamber,it is deemed to have been disallowed and is not referred to in the House. There is a Call Attention Notice No. 22 by Comrade Babu Singh Master

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहिब, मेरी भी एक एडजर्नमेंट मोशन है......

Mr. Speaker : No, please take your seat. I have given my ruling and that applies to that motion also. (Noise)

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहिब, यह मामला बड़ा अहम है जिसकी वजह से सारे पंजाब में बेचैनी फैली हुई है। विधान सभा के सैशन के दौरान में ही गवर्नमेंट ने नोटीफिकेशन जारी करके एक करोड़ बीस लाख के टैक्स लागू कर दिए हैं जिसकी वजह से दस हजार ट्रकों वाले यकम अप्रैल से हड़ताल पर जा रहे हैं। देहली में भी ट्रांस्पोर्ट बन्द होने का ऐलान हो गया है...............(शोर)

Mr. Speaker : Order please, No more speech. Take your seat now. (Noise)

श्री बलरामजी दास टंडन : आप क्राइटेरिया तो बता दें कि ऐडजर्नमेंट मोशन किस तरह की होनी चाहिए अगर यह इतनी अहम बात पर भी एडमिट नहीं हो सकती है। आखिर यह तरीका क्या है..............(शोर)

Mr. Speaker : I have already explained the position and I do my best to be impartial in such matters.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, विधान सभा का सैशन चालू है और बजट पेश है । सरकार ने जो तरीका है उसके मुताबिक बजट के अन्दर टैक्सेशन का

ज़िकर न करके अब चोर रास्ते से एक करोड़ 20 लाख के टैक्स लगाये हैं जिसकी वजह से हड़ताल हो रही है और रोड ट्रांस्पोर्ट पैरालाइज़ होने जा रही है। हम कल भी आपके नोटिस में एक निहायत ज़रूरी बात लाए थे कि सारे पंजाब की इन्डस्ट्री पैरालाइज़ हो गई है लेकिन उसे किसी बहाना से टाला गया लेकिन आज फिर जब हम एक और अहम बात यहां लाए हैं कि ट्रकों वाले हड़ताल पर जा रहे हैं जिसकी वजह से सारे पंजाब का रहा सहा कारोबार भी ठप हो जाएगा । खैर कल वाली बात तो यह कह कर टाल दी गई कि चूंकि इन्डस्ट्री की मांग पर बहस होने जा रही है इसलिये यह मामला उस वक्त उठाया जा सकता है। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ कि ट्रांस्पोर्ट की डिमांड पर कोई बहस नहीं होने जा रही है इसलिये यह उस वक्त डिसकस नहीं हो सकती है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब न तो ट्रांसपोर्ट की डिमांड डिस्कस हो रही है जिसके दौरान हम इस मामला को उठा सकें और न ही आप एडजर्नमैंट मोशन एडमिट कर रहे हैं तो फिर हमारे लिये और कौन सा फोरम रह गया जहां कि हम इस मामला को उठाएं । इसलिये मैं अर्ज़ करता हूँ कि यह मामला अब ऐडजर्नमेंट मोशन के ज़रिये ही उठाया जा सकता है । आप इस मोशन को ऐडमिट करें ।

Shri Fateh Chand Vij : On a point of Order, Sir.

Mr. Speaker : You have already risen on a point of Order. I will not allow you any more Point of Order on the same subject.

श्री बलरामजी दास टंडन : आखिर आप बेसिज तो बताएं कि किस तरह की मोशन एडमिट हो सकती है । इसका कोई क्राइटेरिया तो बताएं । हम यहां किस लिए आए हैं? क्या हम यहां इसलिये आए हैं कि जो बात यहां हो उस पर हाथ खड़ा कर दें। हर बात को एक ही लाठी से हांका जा रहा है और यह नहीं देखा जाता कि कौनसी बात कितनी ज़रूरी है। चाहे कोई भी कितनी अहम बात हो अगर चैम्बर में नहीं गए तो कहते हैं नहीं आ सकती है। आखिर यह क्या तरीका है (शोर). अगर आप चैम्बर में हाथ जोड़ें पांव पकड़ें तो ऐडमिट होगी वैसे नहीं होगी..........शोर (विघ्न)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਉ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਉ । ਇਹ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਤਿਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ.......

Mr. Speaker : Please do not discuss the merits. Please, tell if any legal point is involved in it.

ਸਰਦਾਰ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਭਾਰੀ ਧਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰਖ ਕੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਐਡਮਿਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ?

श्री मोहन लाल : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर । स्पीकर साहिब, मैं किसी एडजर्नमेंट मोशन को एडमिट करने या न करने के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। यह ग्रापका हक है कि ग्राप किसी मोशन को एडमिट करें या न करें । लेकिन मुझे गवर्नमेंट के एटीचूड की कोई समझ नहीं ग्राई है।

Mr. Speaker : The hon. Member should not discuss the merits of the matter sought to be raised through the Adjournment Motion. He may please give points in favour or against the admissibility of the Motion.

श्री मोहन लाल : स्पीकर साहिब, मैं एक बात ग्रर्ज करना चाहता हूँ जहां पर हाउस के मैम्बरों के दिलों में इतनी स्ट्रोंग फीलिंग्ज हो ग्रौर गवर्नमेंट इस बारे में कोई स्टेटमेंट देना न चाहती हो यह उचित दिखाई नहीं देता । इसलिये सरकार को हाउस को कांफीडेंस में लेना चाहिए । मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि यह मोशन एडमिट नहीं की गई । यह तो ग्रापका राइट है । The Government should volunteer themselves and clarify the position. Therefore, I would request the Government to kindly intervene and inform the House by making a statement on the situation that has arisen.

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : स्पीकर साहिब, एडजर्नमेंट मोशन ग्रौर काल एटेंटशन मोशन्ज के बारे में बिजनैस एडवाइज़री कमेटी में यूनेनीमसली पास हुग्रा था ग्रौर उसके लिये रूल्ज सैट किये गए थे लेकिन जिस प्रकार से डाक्टर बलदेव प्रकाश ग्रौर श्री बलरामजी दास टंडन ने हाथ बांध कर प्रार्थना करने की बात कही है, ऐसी बातें ग्रच्छी नहीं लगती (शोर) मैं ग्रर्ज कर रहा था कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में फैसला हो गया था कि किस तरह से यह मोशन्ज़ होंगी । दूसरे ग्रापने रूलिंग दे दी कि स्ट्राइक एडजर्नमेंट मोशन का बेसिज नहीं बन सकती है । तीसरे ग्रगर गवर्नमेंट को इस बारे में बयान देने के लिये कहा जाए तो सरकार को बयान देने में कोई एतराज नहीं हैं। (तालियां)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਸਰੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਾਲਿਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਆਪਣਾ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ । ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇੰਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ

ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿੰਗੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਝਾਓ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਜੇਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇ । (ਸ਼ੋਰ)

(Some hon. Members rose to raise Points of Order for the second time).

Mr. Speaker : I will not allow an hon. Member to raise a point of Order for the second time on the same matter.

ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਲ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । (ਤਾਲੀਆਂ)

Shri Fateh Chand Vij : On a point of Order, Mr. Speaker.

Mr. Speaker : I am sorry, I will not allow you to raise a point of Order on this matter for the second time. Please take your seat.

Sardar Lachhman Singh Gill : On a point of Order, Sir.

Mr. Speaker : No, please. I have once allowed you to raise point of Order on the matter.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 2 ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਊਟ ਹੈ । (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : अन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहिब, इस एडजर्नमेंट मोशन का तो फैसला हो गया है मैंने भी एक एडजर्नमेंट मोशन दी थी, उसका क्या बना है ?

Mr. Speaker : Let me dispose of this adjournmeut Motion first. क्या होम मिनिस्टर साहिब कुछ कहना चाहते हैं ?
(Let me dispose of this adjournment motion first· Would the Home Minister like to say some thing on the issue before the House ?)

गृह मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैंने कुछ नहीं कहना ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿੰਗੇ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਟੈਂਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker : I will not allow you for the second time. Please, take your seat.

जहां तक एडजर्नमेंट मोशन या काल एटेंशन मोशन एडमिट करने की बात है, उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हुई। इसके बारे में रूल्ज़ भी हैं। लोक सभा की भी रूलिंग हैं कि किस तरह से यह मोशन्ज़ एडमिट होनी चाहिएँ। यह सवाल ऐसा नहीं है जिस तरह से श्री बलरामजी दास टंडन ने ऊपर और नीचे हाथ कर के कहा। (विघ्न) उन्होंने कहा कि एडजर्नमेंट मोशन हाथ बंधवा कर एडमिट की जाती है। यह ठीक बात नहीं है। (विघ्न) आर्डर, प्लीज। मैं कहना चाहता हूँ कि यहां पर एडजर्नमेंट मोशन के बारे में फाइंडिंग्ज़ यह हैं और लोक सभा में भी यही फाइंडिंग्ज़ हैं कि बजट सेशन में एडजर्नमेंट मोशन एडमिट नहीं होती हैं। मैम्बरों ने कहा कि यहां पर ट्रांस्पोर्ट डिमांड पर डिस्कशन नहीं होगी और यह टैक्स इनडायरैक्ट तरीके से लगाया जा रहा है। बजट पर डिस्कशन इसी लिये होती है कि उन दिनों में आनरेबल मैंबर सब बातें कह सकते हैं। उसमें किसी पर किसी विषय में बांईडिंग नहीं होती है और काफी मौका मिल जाता है। इस तरह से जनरल डिस्कशन पर 5 दिन फिक्स किए जाते हैं ताकि मैम्बर्स अपनी बातें कह सकें। अभी हाउस में एप्रोप्रिएशन बिल आएगा और मैम्बर्ज़ अपने सब विचार रख सकते हैं। इसके साथ यह मामला कंट्रोवर्शियल हो गया है। कुछ मैम्बर्ज़ कहते है कि पंजाब में इस बारे में स्ट्राइक हो रही है और कुछ मैम्बरों ने कहा कि स्ट्राइक नहीं हो रही है। इस आनरेबल मैम्बर का ट्रांस्पोर्ट के साथ बहुत सम्बन्ध है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। मझे मालूम नहीं कि डायरैक्ट या इनडायरैक्ट तरीके से टैक्स लगाया जा रहा है या कि नहीं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने डायरैक्ट या इनडायरैक्ट तरीके से टैक्स लगाना हो तो भी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वह हाउस को कानफीडैंस में लेकर टैक्स लगाए। (आपोजीशन की तरफ से तालियां)

(I will not allow you for the second time. Please take your seat. Some understanding was arrived at with regard to the admittance of adjournment motions and call attention notices. There are rules governing it. There are rulings from the Lok Sabha as to how these motions should be

admitted. The manner in which Shri Balramji Das Tandon raised the point and tried to say something about it by the movements of his hands is not proper. (Interruptions) The hon. Member stated that adjournment motions are admitted by requests, but it is not the true picture. (Interruptions) Order please. I want to say that adjournment motions are not admitted during the Budget Session as per practice followed in the Lok Sabha and in this House. The hon. Members stated that there would be no discussion on the demand of transport, and this tax is being levied indirectly. The days for general discussion on Budget are allotted only for this purpose that hon. Members can refer to all the matters in their speeches. The discussion is not restricted to a specific matter and hon. Members find ample opportunity to discuss all the matters in the House. Therefore, 5 days are earmarked for the general discussion so that hon. Members may say whatever they like. The Appropriation Bill is still to be introduced and hon. Members will be able to refer this matter at that time . Moreover, this matter has become controversial. Some hon. Members say that strike is being launched and some hon. Members do not agree. The hon. Member Sardar Dilbagh Singh has got some connection with the transport. But I would like to say some thing. I do not know whether the tax is being levied directly or indirectly. But what I want to say is that if the Government wants to levy the tax directly or indirectly, it should try to take the House into confidence before levying the tax. (Cheers from the Opposition.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहिब आपने अपनी रूलिंग देते हुए बताया है कि यहां यह कन्वेन्शन है और लोक सभा में भी यही कन्वेन्शन है । इसी तरह से बिज़नेस् एडवाइज़री कमेटी में भी यही अंडरस्टैंडिंग हुई कि बजट सैशन में एडजर्नमेंट मोशन एडमिट नहीं होती । यह सब को मालूम ही है कि लोक सभा के अन्दर बजट सैशन के दौरान ही प्रैजीडेंट के एड्रैस के बाद लेंगुएज़ पर एडजर्नमेंट मोशन एडमिट हुई और उस पर डिस्कशन हुई । अगर स्टेट में किसी प्रकार के हंगामी हालात पैदा हो जाते हैं, स्टेट में आग लग जाती है जनता डूबती है, जनता लूटती है तो क्या हम आंखें बन्द करके और बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के लायल बन कर बैठे रहें ....हम बिज़नेस एडवाईज़री कमेटी के वफादार बन कर जनता को धोकदें...........

Mr. Speaker : The hon. Member said that he will not say on this point but he is again doing so. He may take his seat.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बिज़नेस एडवाईज़री कमेटी की जो कन्वेनशन्ज़ हैं या जो रूल्ज़ हैं वह जनता के हित के लिये ही बनाए गए हैं जनता के अहित के लिये नहीं बनाए गए । अगर किसी प्रकार के हंगामी हालात पैदा हो जाते हैं... एक मैम्बर कुछ कहता है और दूसरा कुछ कहता है, मुझे मालूम नहीं कि किसी को कालका और शिमला लाईन के परमिट मिले हुए हैं ।........

Mr. Speaker : Please take your seat, Previously the hon. Members wanted to hear Sardar Dilbagh Singh. Since he has not supported the hon. Members, they are against him.

डाकटर बलदेव प्रकाश : सारे ट्रांस्पोर्ट वालों ने सारे मैंबरों को यह अपील की है अगर जनता के नुमाइंदे आएं और हम उनकी बात को न मानें तो भी गलत बात है और अगर उसके मुताबिक हमने उनकी बात आपके सामने रखी है .....हमारी समझ में नहीं आता कि क्या बात यह कहते हैं कि ग़लत फहमी हो गई थी। उन्होंने कहा कि दूर हो गई है। जिस बात से सारी की सारी ट्रांस्पोर्ट स्ट्राइक करने के लिये तैयार हो गई थी अगर वह ग़लत फहमी दूर न होती तो स्टेट में हंगामी हालात बन जाते। इसलिये सरकार को स्टेटमेंट देनी चाहिए तभी हमारी सैटिसफैक्शन होगी।

Mr. Speaker : The hon. Member rmay please take his seat. I am sorry, I do not agree with him.

Shri Fateh Chand Vij : On a point of Personal Explanation, Sir......

Mr. Speaker : I am sorry. There has been absolutely no allegation against him. How can I allow a point of Personal Explanation when no allegation has been made against the hon. Member ? He may please take his seat.

Now we take up call attention notices. Comrade Babu Singh Master may please read out his Call attention Notice No. 22.

CALL ATTENTION NOTICES

Comrade Babu Singh Master : Sir, I draw the attention of the Minister concerned to the fact that 10,000 workers have been affected by the declared lay off by the powerloom Factories Association Ludhiana on the plea that the Industry could not afford to pay Rs. 175 p.m. to the weavers as minimum wage as required by the Minimum Wages Act, enforced on 4th March, 1965. The decision of the Association is a clear challenge to the Government and Labour Laws and amounts to breach of industrial peace. The Defence of India Rules need to be applied to these industrialists who declared 10,000 workers job-less.

Mr. Speaker : The next motion (No. 23) is by Comrade Shamsher Singh Josh.

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I draw........

Babu Ajit Kumar : Sir, your ruling has not come on the previous motion.

Mr. Speaker : The next two or three motions are on the same subject. I will give my ruling after them.

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I draw the attention of the Chief Minister to the serious situation created by the deliberately planned lock-out declared and enforced by owners of woollen and silk loom factories in Ludhiana and Amritsar throwing many thousands of workers out of

employment disturbing industrial peace and suspending production of essential consumer goods, in a calculated move to scuttle the just dicisions of the State Government, in regard to fixation of Minimum Wage for workers in the said industries. The game of the employers to pressuries and black mail the Government should be vigorously countered and if need be a law be passed forthwith to take over the industrial units concerned and to run them with the co-operation of workers.

Should the Government, unfortunately, succumb to employers' pressure, the workers may be compelled to go on an indefinite strike.

Mr. Speaker : In next motion No. 25, stands in the names of Dr. Baldev Parkash and Shri Balramji Dass. Any one of them may read it out.

Dr. Baldev Parkash : Sir, I draw the attention of the Government towards the serious situation created by the strike of Textile Industry throughout the State. A wrong and unjustified notification by the Labour Department is responsible for this unpleasant situation which will lead to worst type of class struggle between employee and employer. Immediate steps should be taken to withdraw the notification for necessary amendment.

Mr. Speaker : These three motions relate to the same subject and are admitted. The Government may please make a statement about these.

Public Works and Welfare Minister : Sir, I rise to make a statement..

ਸਰਦਾਰ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : On a point of order Sir, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਤਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Yes. They have sent a copy to me.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ?

Mr. Speaker : It is not sub-gudice.

Public Works and Welfare Minister (Chaudhri Rizaq Ram) : Sir, relations between some workers engaged in the textile industry and the factory owners have got strained of late as a result of the enforcement of the revised minimum rates of wages with effect from 4th March, 1965. Both the parties have put forth their respective points of view before government in the matter and the Labour Department is considering the same with a view to effecting an amicable settlement of the issue. Meanwhile, there is in evidence a lamentable tendency on the part of certain factory owners and workers to precipitate the matters by resorting to lock-outs, lay off and strikes.

None who has the well-being of the State and the people at heart would approve of such methods. Agitational approach is highly undesirable under the existing circumstances when production needs being stopped up. Our State has enjoyed comparative industrial peace all these years and it ill-behoves anyone to create discord and disharmony. Given the

[Public Works and Welfare Minister]

proper approach and a calm consideration of the issue involved, it should be possible to remove the genuine difficulties of both the employers and the workers. The sole aim of Government is to promote understanding between the two in the interests of the country.

I would appeal to the industrialists as well as the workers to help Government in finding out a suitable solution of the problem. They should in particular eschew the agitational approach and resume normal working in the factories.

I also make a similar appeal to the hon. Members of this House.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ? The Government should make a specific statement and take the House into confidence.

Mr. Speaker : Sardar Ajaib Singh's Call Attention Motion No. 24 comes next.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : I draw the attention of the Minister concerned towards the order of the Estate Officer, Chandigarh for demolishing the Gurdwara constructed in village Chahar Majra, Tehsil Kharar, District Ambala. This is an act of discrimination of the Punjab Government against the Sikhs which can disturb the peace of the State.

Mr. Speaker : This is admitted. The Government may please make a statement about it.

Dr. Baldev Parkash : May please read out.

Then call attention notice No. 26 please. Dr. Baldev Parkash May read it out.

Dr. Baldev Parkash : I draw the attention of the Minister concerned towards the forced collection of small saving deposits by the Government Departments in general and Registraion authorities in particular. People who go for registration or renewal of some licence are not attended unless they pay some money in one collection or other. Such a harassment is illegal, unjust and criminal. A large number of complaints have been received from Fazilka in this respect. Government should take immediate measures to stop this practice and clarify its position in the House.

Mr. Speaker : This is admitted. The Government may please make a statement.

Now the House will proceed with the normal business.

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ । ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

Mr. Speaker : It can not be Discussed .

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ...

Mr. Speaker: The hon. Member should please take his seat. A statement given in connection with a Call Attention Motion cannot be discussed.

Now discussion on the Demands for Grants will be resumed.

DEMANDS FOR GRANTS

(Resumption of Discussion)

*42—Multipurpose River Schemes.

*43—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)

*44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (non-Commercial)

*—Charges on Irrigation Establishment.

*98.—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

*99—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commerial)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਮਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਜੋ ਇਹ ਡੀਮਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ । ਕਈ ਜਗਾਹ ਨਾਲੇ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੀ. ਡਬਲਿਯੂ. ਡੀ. ਦੀ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਨਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲ ਸਾਲ ਜਾਂ ਡੇਢ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤਹਿ ਕਰੇ । ਪੀ. ਡਬਲਿਯੂ. ਡੀ. ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ । ਜਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਨਾਲੇ ਪੁਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਸੋ ਉਸ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਫੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

Note :—For previous discussion on the subject please see P.V.S. Debates Vol. I, No. 20 dated the 24th March, 1965.

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਤੀਜੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ । ਪਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਨਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਐਸੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ । ਕਿਸਾਨ ਰੇਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਤਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਤਲਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ । ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਫਲਾਣੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖਾਲੇ ਕਢਣੇ ਹਨ । ਨਵੇਂ ਖਾਲ ਕਢਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲ ਕਢ ਦੇਣ । ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਜਗਾਹ 107/151 ਦਫਾ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਥੋਂ ਨਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਢਾਏ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ੍ਹੇ ਕਢਵਾ ਦੇਣ । ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਖਾਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਢਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੈਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਿੰਡ ਸੇਲਬਰਾ ਦੇ 22 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 107/151 ਦਫਾ ਹੇਠ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ-ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਚਕਬੰਦੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਇਸ਼ਤਿਮਾਲ ਅਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਚਕਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਾਬੰਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਨਵੀਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਲਮਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ

ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਜਗਾਹ 1,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 4 ਕਿਊਸੈਕਸ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ 1,000 ਏਕੜ ਲਈ 2 ਜਾਂ 3 ਕਿਊਸੈਕਸ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਿਆਨਾ ਇਕੋ ਸ਼ਰਾਹ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਕਬੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇਕੋ ਪਧਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਛੇ-ਮਾਹੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜਿਨੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਨਵੇਂ ਨਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੇ ਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਟੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਓਥੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਆਬਿਆਨਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਖੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਹੀ ਝੱਖੜ ਝੁਲਿਆ ਸੀ । ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੱਟੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲਿਫਟ ਨਾਲੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਲਿਫਟ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ ਕਢੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਨਾਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸੀਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਪੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਪੀ. ਡਬਲਿਯੂ ਡੀ. ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟੇ । ਉਸ ਪੁਲ ਤੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਇਆ । ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਮਿੰਟ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ 15 ਰੁਪਏ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਘਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ । ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਦੂਜਾ ਰੇਹ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪਾਣੀ । ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏਥੋਂ ਤਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਜਿਥੇ ਨਹਿਰ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਜੇ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਜਿਥੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਲਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਦਲਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ $5\frac{1}{2}$ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੇਮ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੇਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਊਬਵੈਲ ਲਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਾ ਥਲੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਥੇ ਨਿਚਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਔਰ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਘਿਆਂ ਦੀ ਰੀਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ

ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੇਮ ਜ਼ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਟੀਊਬਵੈਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਲੀ ਸਤਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker : Chaudhri Rizaq Ram.

(इस वक्त चौधरी रणबीर सिंह श्रौर कई दूसरे मेम्बर बोलने के लिएँ खड़े हुए ।)

श्री श्रध्यक्ष : कल श्री जोगा जी ने 6 बज कर चार मिनट पर बोलना शुरु किया था । श्रगर हाउस एडजर्न न कर दिया जाता तो उन के बाद मिनिस्टर साहब ने जवाब देना था श्रौर उसके बाद यह डीमांड पास हो गई होती । इसलिये श्रब मिनिस्टर साहब जवाब देंगे । The hon. Member should please finish within 5 minutes. (The hon. Member, Comrade Joga commenced his speech at 6-04 P.M. yesterday. Had the House not been adjourned, the hon. Minister would have replied to the Debate and the Demands for Grants would have been carried. The hon. Minister will, therefore, now reply to the debate. The hon. Member should please finish within 5 minutes.)

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, श्राप से मेरी प्रार्थना है कि मैंने कल भी टाइम लेने की कोशिश की थी श्रौर श्राज भी कोशिश की है । मैंने कुछ जरूरी बातें कहनी हैं इसलिये मुझे कुछ समय जरूर मिलना चाहिए।

श्री श्रध्यक्ष : क्या श्राप पांच मिनट में खत्म कर देंगे । (Will the hon. Member finish his speech within five minutes?)

चौधरी रणबीर सिंह : जी मुझे पांच मिनट ही बोलने के लिये दे दें । मैं इस वक्त में बोल लूंगा ।

(Some hon. Member rose. Noise in the House).

Mr. Speaker : The hon. Member Chaudhri Ranbir Singh has been Minister-in-charge of Irrigation and Power Departments and that is why I have allowed him to speak for 5 minutes. He might give some useful suggestions.

चौधरी रणबीर सिंह (कलानौर) : श्रध्यक्ष महोदय, साल 1963–64 के श्रामदनी श्रौर खर्च खाते को श्रगर देखा जाए तो पता चलता है कि उस साल श्रसल श्रामदनी जो नहर के इस महकमे की हुई थी 8 करोड़ 86 लाख थी श्रौर जो साल 1964-65 के रीवाइज़्ड एस्टीमेट्स के मुताबिक श्रामदनी होगी वह 7 करोड़ श्रौर 68 लाख

[चौधरी रणबीर सिंह]

होने की आश है। जिस के मायने हैं कि 1963-64 की निसबत 1964-65 की आमदनी लग भग एक करोड़ और 18 लाख कम हो गई और साल 1965-66 के बजट एस्टीमेटस के मुताबिक जो इस बजट में हिसाब लगाया गया है यह आमदनी 8 करोड़ और 36 लाख होगी जिसके मायने हैं कि 1963-64 के मुकाबिला में इस आने वाले साल में इस महकमा की आमदनी 50 लाख रुपया कम होगी। इसी तरह से आप अगर खर्च को देखें तो पता चलता है कि इस महकमा का जो असल खर्च जिसमें इस महकमा की एस्टेबलिशमेंट का भी खर्च शामल है, 1963-64 में 2 करोड़ 24 लाख रुपए था और 1964-65 के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स के हिसाब से जो खर्च हुआ या होना है 2 करोड़ 77 लाख रुपये होगा यानी 1963-64 के मुकाबिला में इस महकमा का खर्च 1964-65 में लग भग 53 लाख ज्यादा हुआ और इस साल का बजट एस्टीमेट 2 करोड़ 86 लाख रुपये होगा जिससे साफ ज़ाहर है कि यह खर्च 1963-64 और 1964-65 के मुकाबिला में ज्यादा होगा। यानी खर्च तो बढ़ रहा है और जो आमदनी है वह कम हो रही। इसी तरह से इस बजट में जो बयाज के आदादोशमार दिए गए हैं आप जरा उनको भी देखें। 1963-64 में जो व्याज इस सरकार को देना पड़ा था वह 2 करोड़ 59 लाख रुपये था और जो इसे 1964-65 के रिवाईज्ड एस्टीमेट्स के मुताबिक देना पड़ा था वह 3 करोड़ 6 लाख था और जो 1965-66 के बजट एस्टीमेटस में प्रोवीज़न की गई है वह 3 करोड़ और 43 लाख रुपये है तो इससे साफ ज़ाहर है कि व्याज का खर्च भी बढ़ रहा है। जहां हमारा खर्च बढ़ गया है वहां आमदनी कम हुई है हालांकि हमारी पानी की मिकदार भाखड़ा के बन जाने से बढ़ी है। फिर आप उस कर्ज़े को देखें जो 1-4-1965 को पंजाब के सर पर था। यह 361 करोड़ रुपये था और इसमें से मल्टी प्रपज़िज इरीगेशन स्कीम्ज़ के तहत कर्ज़ा आता है वह 211 करोड़ रुपए है। यह है हमारी माली पोज़ीशन। एक तरफ तो खर्च बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आमदनी कम हो रही है और फिर हमारे ऊपर इतना कर्ज़ा है.... (**श्री बलरामजी दास टण्डन**: आप कोई सुझाव दें, यह फिगर्ज़ तो बजट में दी हुई हैं)। माननीय सदस्य श्री बलरामजी दास टण्डन ने ठीक कहा है कि मैं कुछ सुझाव दूं। मैं आप के द्वारा स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि पंजाब के अन्दर जो कूएं आज तक लगाये जा चुके हैं जिनसे सिंचाई होती है उनकी गिनती 241,090 है यह सारे पंजाब के कूओं की तादाद है और पंजाब में एक पम्प लगाने पर एक हजार से 1100 रुपये तक खर्च आ जाता है, इसी तरह से जो पंजाब में बिजली के कूएं हैं वह 25 हजार से कुछ ज्यादा हैं और वह किसी एक ही ज़िला में नहीं बल्कि सारे पंजाब के हिस्सों में हैं। माननीय सदस्य लेफ्टीनेंट भाग सिंह ने एक सवाल यहां पर किया था कि एक फर्लांग पर जहां पहले कूआं है और वहां पहले बिजली आई हुई है तो उस कूएं के लिये बिजली दी जायेगी कि नहीं दी जाएगी। तो मन्त्री महादय ने उस के जवाब में कहा था कि इसके लिये कम्पैक्ट एरिया चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खतरा है कि

कम्पैक्ट एरिया कह कर ही कहीं वैसी हालत न की जाए जैसे सड़कों के बारे में की गई है। सड़कें बनाने के लिये एक ही तहसील तथा एक ही हल्के के लिये दो लाख रुपए और रख दिये गये हैं इन कामों को पुरा करने के लिये तो $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया चाहिए। हमें खतरा है कि इस सरकार के काम इसी तरह से चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय यहां पर पहली पांच साला योजना में और दूसरी पांच साला योजना में जितने बिजली के कूओं के लिये कुनैकशन्ज़ दिये गए थे उनकी कुल तादाद 14,278 साल 61-62 के अन्त तक पहुंची थी जोकि 30-6-64 को बढ़कर 24,456 हो गयी थी और इसी तरह बिजली के कुनैक्शनों की कुल तादाद जो 31-3-62 को 4,79,537 थी वह बढ़ कर 30-6-64 को 7,19,527 तक पहुंच गयी थी। आप देखें 1961-62 में कुल बिजली के कुनेकशन्ज़ 65,127 दिये गए थे लेकिन साल 1963-64 में 109,897 कुनेकशन्ज़ दिये गए थे। इसी तरह जहां तक बिजली से चलने वाले कुओं का ताल्लुक है 1961-62 में इनकी गिनती 2,224 थी और 1963-64 में उनकी तादाद 5,326 हो गई थी। जहां तक हमारे वित मंत्री की बजट स्पीच का सम्बन्ध है उन्होंने कहा है कि इस साल 64-65 में इनकी गिनती पांच हज़ार ही होगी लेकिन आप जानते हैं कि 64-65 के बजट के अन्दर लिखा गया था और बताया था कि हम इस साल दस हज़ार लगाना चाहते लेकिन लगा सिर्फ पांच हज़ार ही है। स्पीकर साहब, मैं उन्हें आपकी मार्फत बताना चाहता हूँ कि अगर हमें मौका मिलता तो यह दस हजार लगाए जा सकते थे और अगर यह मैं न लगा सका होता तो मैं अस्तीफा देने के लिये तैयार हो जाता। लेकिन मुझे दुःख है कि आज पंजाब तरक्की की तरफ नहीं बल्कि दूसरी ही तरफ जा रहा है। इन दो महकमों में पंजाब में जो आमदनी हुई उस के आंकड़े मैं आप के सामने रखता हूँ। सन: 1961-62 में 15 करोड़ 15 लाख रुपये की आमदनी हुई जबकि साल 1963-64 में जिस साल कि हमने इसको छोड़ा रीवाइज्ड ऐस्टीमेट्स से पहले आमदनी थी 25 करोड़ 50 लाख रुपये और असल खर्च आमदनी के आंकड़ों के हिसाब से आमदनी 26 करोड़ 50 लाख हुई तो इन दो साल में 11 करोड़ 35 लाख के करीब रुपये आमदनी में इजाफा हुआ। तो एक वह जमाना था तरक्की का और अब यह जमाना है कि आमदनी में कमी हो रही है।

स्पीकर साहिब, जिस तरीके से सरकार का काम चलाया जा रहा है उसको देख कर दुख होता है। वज़ीर साहिब की कोशिश है कि एक सदस्य जिसके पास पहले यह महकमा था उसके गांव में से ड्रेन जानी ही चाहिए चाहे एंजनियंज़ कुछ ही कहें, चाहे दूसरी जगह जमीन सरकार को मुफ्त ही मिल रही हो मगर वहां से ड्रेन नहीं जानी चाहिए बल्कि इसको वहां भेजना है जहां से उस सदस्य का गांव है जिसको मौका मिला यहां पर पंजाब की सेवा का। स्पीकर साहिब, मैं आपकी मारफत कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने इस महकमे में पंजाब की कुछ दिन सेवा की है तो क्या उसका सिला मुझे इस तरह से मिलेगा? मन्त्री महोदय जानते हैं कि मेरे गांव से ड्रेन निकालने की

[चौधरी रणबीर सिंह]

एंजनियर्ज़ इजाजत नहीं देते मगर यह उसको वहीं से निकालना चाहते हैं । मैंने इन पर यह बड़ा गम्भीर इल्जाम लगाया है और मैं आशा रखता हूँ कि मन्त्री महोदय अपनी स्पीच में इसका जवाब देंगे । (घंटी) स्पीकर साहिब, मैंने बातें तो बहुत सी कहनी थीं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप समय दें तो जितनी बातें मैं आपके सामने रखता वह बड़े काम की होतीं । तो भी एक आखिरी बात कह कर मैं बैठ जाता हूँ ।

मैं समझता हूँ कि अगर हमारे इलाके ने तरक्की करनी है तो किशाऊ डैम जिसके मुताल्लिक पंजाब यू.पी. राजस्थान और दिल्ली की सरकारों ने बनाने का फैसला किया था उसके लिये चौथी योजना में एक कौड़ी भी नहीं रखी गई । मुझे अफसोस है कि इन्होंने मन बदल लिया है । मैं जानता हूँ कि पानी की इन के गांव में भी कमी है और यह जो कहा गया है कि पानी ज्यादा है तो मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब का काश्तकार अपने खेत से तीन फसलें लेना चाहता है। जो नहरें खोदी हुई हैं उनमें दो सौ फीसदी पानी और चाहिए, ऐसा मेरा अन्दाजा है । तो कैसे कहा जा सकता है कि नहरों में पानी ज्यादा है । पानी की कमी है और यह पानी की कमी बिजली के पम्पों द्वारा ही पूरी की जा सकती है । मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार एक साल के अन्दर 15 हजार कूओं को बिजली दे सकती है और अगर इसने इस आने वाले साल में इतने कूओं को बिजली दे दी तो मुझे बड़ी खुशी होगी ।

WALK-OUT

Mr. Speaker : Now the Minister for Public Works and Welfare will speak.

(सरदार रणजीत सिंह तथा कुछ माननीय सदस्य स्पीकर साहब से समय लेने के लिये खड़े हुए)

Mr. Speaker : We have no time. (Interruptions)

चौधरी अमर सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर ।

Mr. Speaker : I will not allow.

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर ।

Mr. Speaker : Please take your seat (Interruptions).

सरदार रणजीत सिंह : जनाब, यह तो बड़ी बेइनसाफी है.......(विघ्न)

Mr. Speaker : You can leave the House. I have to go by the Schedule. No hon. Member should obstruct the proceedings.

(At this stage Sardar Ranjit Singh staged a walk-out)

DEMANDS FOR GRANTS

(RESUMPTION OF DISCUSSION)—(CONCLD)

लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री (चौधरी रिज़क राम) : स्पीकर साहिब, कल और आज इस मुअज़्ज़िज़ हाउस में मैंबर साहिबान ने कुछ शिकायतें रखीं और कुछ माकूल तजवीजें रखीं। यह जो सुझाव दिये गए हैं मैं इन के लिये उनका मशकूर हूँ। अभी अभी चौधरी रणवीर सिंह जी ने कुछ बातें कीं। यह भी जिक्र किया कि कोई ड्रेन जान बूझ कर उन के गांव के रकबे में से निकालने की कोशिश की जा रही है, कुछ सड़कों के मुताल्लिक भी चर्चा की और किशाऊ डैम के बारे में भी बात की। यह भी बताया कि पिछले साल की निस्वत इस साल खर्च ज्यादा और आमदनी में कमी हुई है। उन्होंने यह भी फरमाया कि अगर वह मन्त्री रहते तो कहीं ज्यादा काम कर सकते थे। स्पीकर साहिब, इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि चौधरी रणबीर सिंह जी का तजरुबा इस हाउस में सब से ज्यादा है बतौर पार्लियामेंटेरियन के भी और वैसे भी मैं उनकी लियाकत को पहुँच नहीं सकता और न ही मैं ने दावा किया है कि मैं उन के बराबर पहुंच सकता हूँ और न ही मैंने कभी उनकी लियाकत को बिलिटल करने की कभी कोशिश ही की है। उन्होंने जो, बुन्यादें रखीं मैं तो उन से ही कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और आशा है कि कुछ सीखता भी हूँ और अगर वक्त मिला तो आगे चलने की कोशिश करूँगा (तालियां) जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उन के लिये मैं उनका बड़ा ममनून हूँ मगर उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे कभी दिल में भी यह ख्याल नहीं आया कि उन के गांव में से नाजायज़ तौर पर कोई ड्रेन निकाली जाए और कि जिस जगह पर एंजनियर साहिबान की राए हो उस से किसी दूसरी जगह पर निकाली जाए, इसका सवाल पैदा नहीं होता। मैंने चौधरी साहिब से पहले इस बारे अर्ज की थी और अब फिर दोहरा देता हूँ........

चौधरी रणवीर सिंह : उसके बाद भी अलाइनमैंट की जा रही है इसलिये बात की है।

लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री : छिपड़ा ड्रेन, जिसका इससे ताल्लुक है, के बारे में एंजनियर साहबान ने कहा यह मिरज़ापुर खेड़ी गांव से निकाली जाए क्योंकि वहां पर और सांगी का इश्तेमाल हो चुका है। इसी मियार से वहां पर एलाइनमेंट हुई है। अगर उसमें कहीं कुछ लूप्स हों तो, अगर कहीं पर सीधी वगैरह करने के लिये बीघा, आधा बीघा रकबा इधर उधर से लिया हो तो लिया हो वरना इनको विश्वास रखना चाहिए कि हमारे दिल में उन के खिलाफ ज़रा सा विचार भी पैदा नहीं होता। अगर कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो वह हर वक्त मेरे से बात करके साफ कर लें। उन्हों ने अच्छा किया कि जो उनको गलतफहमी पैदा हो गई थी उसको साफ कर दिया। इसके लिये मैं उनका मशकूर हूँ। सड़कों के मुताल्लिक भी उन्होंने चर्चा किया। इस वक्त सारे फैक्टस ऐंड फिगर्ज इस बारे में मेरे पास नहीं हैं वरना अगर यह थोड़ा टाइम दे

[लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री]

के बात करते तो मैं इनकी तसल्ली करा सकता था कि उसमें भी कोई बेइन्साफी नहीं हुई है। फिर भी मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले साल सोनीपत तहसील के 241 गांवों में से 231 गांव ऐसे थे जोकि तकरीबन बरबाद हो गए थे, मकानात भी गिर गए, गुजारे का जरिया भी न रहा, वहां पर कतई तबाही हुई। उस इलाके के लिये सन 1964-65 के बजट में सिर्फ तीस हजार रुपये सड़कों के लिये रखे गये थे और जहां तक मेरे हलके का ताल्लुक है उसके लिये सिर्फ 6 हज़ार रुपये का प्रोवियन था। राड़गढ़ां जो गांव है वहां पर बड़े बड़े लोग जिनमें श्री कामराज जी भी हैं और चौधरी साहब भी हैं उस गांव में गए हुए हैं। तो ऐसे इलाके में अगर कहीं तहसील में जहां सड़कें नहीं थीं पांच सात मील की सड़क दे दी तो कोई बेइनसाफी की बात नहीं की। वहां पर फ्लड आए हैं। हर एक हल्के का ध्यान रखते हुए कि कहां कहां पर सड़कें मौजूद हैं और कहां पर नहीं हैं और किन इलाकों के लिये बजट में प्रोवियन नहीं था उनको सड़कें दी हैं। मैं चौधरी साहिब की पूरी तसल्ली करा सकता हूँ कि कहीं पर कोई बेइन्साफी नहीं हुई है। मगर इस वक्त इसका मौका नहीं था और मैं इसके लिये तैयार हो कर नहीं आया, वरना मैं उनको इस बात की तसल्ली करा देता कि कहीं पर कोई बेइनसाफी नहीं हुई है। मुझे खुशी होती अगर मैं उन लोगों के बारे में जो गमज़दा हैं और तबाही का शिकार हुए हैं चौधरी साहिब से हमदर्दी के अलफ़ाज़ सुनता। मुझे इस बात का गिला नहीं कि इन्होंने अलाइनमेंट करके रोहतक के शहर को बचाया। मैं मानता हूँ कि इन्होंने अपने घर और गांव को बचाया और सारा वबाल सोनीपत के इलाके की तरफ भेज दिया। (विघ्न)

चौधरी साहिब ने किशाऊ ड्रेन के बारे में ज़िक्र किया है इसके बारे में मुझे भी और गवर्नमेंट को भी चिन्ता है और इस सम्बन्ध में हमने यू. पी. गवर्नमेंट के ज़िम्मे लगाया था कि वह इन्वेस्टीगेशन करके हमें रिपोर्ट जल्दी भेज दें। उनकी रिपोर्ट पन्दरह बीस दिन हुए मौसूल हुई थी इस पर गौर किया गया है। हमने प्लानिंग कमिशन को लिखा है। यू. पी गवर्नमेंट को भी लिखा है और अपने फिनांस डिपार्टमेंट से भी रुपया लेने की कोशिश की जा रही है और जो खर्चा इसमें हो उसमें हमारा हिस्सा अगले साल के बजट में डाला जा सके। इसके बारे में जो चौधरी साहिब ने सरकार की अगवाई की है मैं उसके लिये उनका मशकूर हूँ।

कुछ बातें और मैम्बरान ने भी कहीं हैं। कल भी इस डिमांड पर बहस हुई और इस बहिस के दौरान दो अमूर सामने रखे गए। एक तो सैलाब के मुताल्लिक और दूसरे इरीगेशन के बारे में। जहां तक सैलाब का ताल्लुक है मैं इस मोअज़्ज़ज़ इवान का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सिर्फ दो बातें ही अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो यह कि जब से नई सरकार बनी है सब जानते हैं कि इस बात की कोशिश की गई है कि जितने कदम उठाने चाहिएं उठाए जाएं ताकि सैलाब को रोका जा सके। किसी तरह की लापरवाही इस सरकार की तरफ से नहीं की गई। जुलाई में

नई मिनिस्टरी बनी थी और बारिशें शुरू हो गई थीं जो काम सैलाब को रोकने के लिये पहले किए जा चुके थे उनमें इस सरकार ने दखल नहीं दिया । बारिश भी 1962 और 1963 के मुकाबले में कम थी और सैलाब भी कम था। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां पहले 42 लाख ऐकड़ में वाटर-लागिंग थी और अब की २६ लाख एकड़ में रह गई है । इससे भी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है । पिछले पांच छे साल यह मसला लगातार चल रहा है और यह महकमा इस सैलाब की रोकथाम के लिये लगातार कोशिश कर रहा है । इसके बारे में बहुत से कदम इस सरकार ने उठाए हैं। मैम्बर साहिबान की वाकफियत के लिये बताना चाहता हूँ कि सैलाब के सिलसिले में तमाम जिलों के डी. सीज़. ऐस. पीज़, लैजिस्लेटर्ज़ और एम. पीज़. की मीटिंग बुलाई और उन से जो मालूमात और हिदायात ले सकते थे ले ली गई । उनसे सलाह मश्विरा किया गया। और उसके मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी । एक कमेटी बना दी गई जिसको फ्लैचर कमेटी कहा जाता है । इसके चेयरमैन हमारे सूबे के फिनांशल किमिश्नर हैं उनकी सरकर्दगी में यह कमेटी काम करती रही । इसमें लैजिलेटर्ज़ और इलाके के एम. पीज. को भी शामिल कर लिया गया था । इस कमेटी ने सारे पंजाब के ज़िलों का दौरा किया हरेक डी. सी . से तजावीज़ हासिल की । पब्लिक को इसके साथ असोसिएट किया गया और सारी पड़ताल की गई । जहां पर ड्रेनज़ की अलाइन्मेंट गलत कही जाती थी उन सारी बातों की पड़ताल की गई । और जो काम इस संबंध में हम कर सकते हैं उसके लिये सरकार तैयार है ।

सरदार गुरचरन सिंह ने कहा कि भागी ड्रेन की अलाइन्मेंट का झगड़ा है । इसके नुकाइस को दूर किया जाए तो इलाके को बचाया जा सकता है । इसकी जांच पड़ताल के लिये एक कमेटी बना दी गई । इस में लैजिस्लेटर्ज़ शामिल हुए । और यह पहला कदम था जो हमने उठाया ।

दूसरा पंजाब में फ्लड्ज़ की पोज़ीशन का एक खास अमूर है। इस का संबंध दूसरे सूबों में भी है । यह एक इन्टर स्टेट सवाल है । एक तरफ दिल्ली का बारडर है राजस्थान की इन्टर स्टेट प्राबलम है । इस लिये यह कोशिश की गई है कि इंटरस्टेट मसले को हल करने के लिये कोआरडीनेटिड पालेसी इख्तयार की जाए। हम यह नहीं चाहते कि किसी हमारे कदम से दूसरी स्टेट को कोई नुक्सान हो। इससे बचने के लिये एक कोआरडीनेटिड कमेटी बनाई गई है इसको मोतीराम कमेटी कहा जाता है । जिसके चेयरमैन राजस्थान के चीफ इन्जीनियर और हमारे चीफ इन्जीनियर और सैंट्रल पावर बोर्ड के मैम्बर भी शामिल हैं।

बहुत से और भी मसले हैं जैसा कि धासा बंद का है। इस के पानी को रोक लिया गया था और फिर डिस्चार्ज को जो थोड़ा था बंद कर दिया गया और बाद में खोला नहीं गया। इससे नजफगढ़ झील के रकबे में गुड़गांव ज़िला में नुकसान हुआ । इस बात की मुझे खुशी है कि इसका हल इस दफा निकाला जा रहा है । सब से बातचीत

[लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री]

करने के बाद फैसला किया गया कि इसकी कैपेसिटी 3000 क्यूसेक्स कर दी जाए। और इसके लिये नजफगढ़ नहर को चौड़ा और गहरा किया जाए। वहां पर इन्जीनियर हैं और कई डिवीजन दो शिफ्टों में काम कर रहे हैं। काम मुशकिल है और हर एक इन्जीनियर इस काम को नहीं कर सकता। इस काम को जो इस नहर पर किया जा रहा है सैंटर के इन्जीनियर्ज़ ने और सैंटर की मिनिस्टरी ने इन के काम की सराहना की हैं। वहां पर हमें 12 या 13 फुट पानी के अन्दर जा कर मिट्टी खोदनी पड़ रही है। जहां पर ड्रेन लाइन लगाने हैं वहां पर पानी भरा पड़ा है वहां पर बाहर दूर से मिट्टी ला कर भरनी पड़ती है ताकि ड्रेन लगा कर नदी को चौड़ा किया जा सके और 3000 क्यूसैक्स के निकास का इन्तज़ाम किया जा सके।

इसके साथ ही धांसा पर 3000 क्यूसैक्स का रैगूलेटर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। टैन्डर दिये गए थे और तामीर का काम शुरू है। धांसा बांध का काम ज़रा पेचीदा सा मसला बन गया था अब एक तरह से उसका हल निकल आया है। और जो आपत्ति पैदा हुई थी वह अब ठीक हो गई है।

उजीना ड्रेन का झगड़ा राजस्थान से था और जो ड्रेन बनी थी उसकी कपैसेटी 200 क्यूसैक्स की थी और वहां की सरकार ने अपने हिस्से में पानी को रोक लिया था। उन से बातचीत करने के बाद यह तय किया गया कि इसको 200 से 600 क्यूसैक्स तक बढ़ा दिया जाए। इस पर काम होने के बाद नूह और फिरोज़पुर झिरका का मसला हल हो जाएगा और दुबारा इस इलाके को नुक्सान नहीं होगा। गुड़गांव ज़िले के मुताल्लिक महता रूप लाल जी और दूसरे मैंबर साहिबान ने अपने ख्यालात ज़ाहिर करते हुए यह खदशा जाहिर किया था कि उन के ज़िले के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। मैं उन मैंबर साहिबान को यह बात बता देनी चाहता हूं कि जहां तक इस जिले का तअल्लुक है, गवर्नमेंट का इस तरफ पूरा पूरा ध्यान है। गौंचीड रेन और इसकी जो भी दूसरी ड्रेन्ज़ हैं हमने इन सब को मुकम्मल करने के लिये बड़ा काम किया है। इन ड्रेन्ज का ज्यादा ताल्लुक यू. पी. और राजस्थान से है, क्योंकि इन सब का पानी उधर ही जाता है। वहां पर खर्च करने के लिये हमारे जिम्मे 75 लाख रुपया लगाया गया था जिसको देने के लिये हम इकरार कर चुके हैं। जो जो मुशकलात गौंची डरेन के मुकम्मल होने में हो रही हैं उसके ऊपर हमारे इंजनियर्ज़ लगे हुए हैं।

ज़िला करनाल के मुताल्लिक श्रीमती ओम प्रभा जैन ने कहा है कि मैं करनाल के मुताल्लिक भी कुछ अर्ज़ करूँ। मैंने एक एक जगह पर 5–6 दिन तक लगा कर देखा है कि ज़िला करनाल में पानी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कैथल डरेन पूरे ज़ोर से चालू है। अमीन डरेन बनाने का फैसला किया गया है। इसके इलावा खेडी राम नवार डरेन के बन जाने से जो किरमच गांव से रुकावट होती थी वह भी दूर कर दी गई है। करनाल ज़िला के अंदर जितनी भी ऐसी ज़रूरी स्कीमें हैं

उनको हम ने शुरू करने की पूरी कोशिश की है। इसी तरह से अंबाला डरेन के मुताल्लिक भी हम फैसला कर चुके हैं। नाई नाला डरेन की वजह से गोहाना में बड़ा भारी नुक्सान होता रहा है, हमने इसके पानी को यूटिलाइज़ करने के लिये बड़ी इनवैस्टीगेशन की है। कुछ पानी हांसी बरांच की तरफ डाईवर्ट किया है और कुछ बुटाना बरांच की तरफ डाईवर्ट करने के लिये हमारी स्कीम है। यह स्कीम तैयार कर लीं गई है लेकिन इसके मुताल्लिक ऐक्सपर्ट से जांच पड़ताल करवाई जा रही है उमीद है ऐसा हो जाने से हम इस पानी को इरद गिरद के तमाम इलाके को सैराब करने में ज़रूर कामयाब होंगे। इसके इलावा सरस्वती डरेन के मुताल्लिक भी हम कुछ स्टेप्स उठाने जा रहे हैं। सरस्वती डरेन के मुताल्लिक भी हमारा इसी तरह से खेतों के लिये पानी इस्तेमाल करने का इरादा है। करनाल और संगरूर जिले के मुताल्लिक फ्लड् की जो हमारी समस्या है वह राजस्थान से ही तअल्लुक रखती है। अगर हम इधर का पानी उधर निकालते हैं तो इसका राजस्थान पर बुरा असर पड़ता है। पिछले साल इस तरह से पानी के जाने की वजह से सूरतगढ़ फारम का काफी नुक्सान हुआ था। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए भी हम ज़िला करनाल और संगरूर के ज़िलों में पानी की निकासी का बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाये हैं। जहां तक ज़िला संगरूर के कैथल तहसील का सवाल है, जहां कि वाटर लैवल ऊपर चढ़ता चला आ रहा है हम इसको घटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। । आज जिला संगरूर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां वाटर लेवल 1 फुट से भी कम है। अगर इस इलाके के मुताल्लिक, जैसा कि कैथल और गोहाना का इलाका, ज़िला संगरूर में है, सही मानों में देखा जाये तो आज यह इलाका पानी में तैर रहा है। इस इलाके के मुताल्लिक मैंने प्राईम मिनिस्टर साहिब से भी और डाक्टर के. एल. राव से भी साफ लफ्जों में हालात ब्यान किये कि अगर आप ज़िला करनाल और संगरूर के लिये कोई खास स्कीम्ज़ बना कर हमारी हैल्प नहीं करेंगे तो ऐसे हालात में हो सकता है कि यहां की हालत हमारे बेकाबू हो जाये। मैं इस बात के लिये सैंटर के प्राईम मिनिस्टर साहिब का और खास तौर पर, हमारे इरीगेशन मिनिस्टर श्री के. ऐल. राव का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने पंजाब की मुशकलात को महसूस किया है और इस सम्बन्ध में हो रहे काम को ऐप्रीशियेट भी किया है। खुद प्राईम मिनिस्टर ने रुड़का के मुकाम पर फ्लड्ज़ की समस्या को नैश्नल प्राबलम कहा है और कहा है कि हमें इसको वार फुटिंग पर हल करना चाहिए। पिछले दिनों में पलैनिंग कमिशन की एक मीटिंग हुई थी। वहां पर भी इस प्राबलम को नैशनल प्राब्लम समझ कर ही डिसकस किया गया और मुनासब कदम उठाने के लिये तहैया किया गया। हमारी प्रेरणा से यहां पर वर्लड बैंक टीम आई। हमें इन सारी स्कीम्ज़ को कामयाब करने के लये रुपये की ज़रूरत थी। हमने इन सारी स्कीम्ज़ को कामयाब बनाने के लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना में 15 करोड़ रुपये की प्राविज़न रखी है। इसके इलावा और दूसरी स्कीमों के लिये हमने $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का प्राविज़न किया है। हालांकि हमारे रिसोरसज़ इतने नहीं हैं लिमिटिड से हैं मगर फिर भी हमने आज तक 28 करोड़ के करीब रुपया फ्लड्ज़ की रोक थाम के ऊपर खर्च किया है। इस से आप बखूबी अंदाज़ा लगा

[लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री]

सकते हैं कि आज गवर्नमेंट इस तकलीफ को दूर करने के लिये कितनी तुली हुई है। हमने वर्ल्ड बैंक की टीम को बुलावा दिया था। उन्होंने यहां पर आकर हमारी स्कीम्ज़ को स्टडी किया, हमारे जारी किये हुए प्रोजैक्ट्स देखे। उनकी यह राये थी कि जिन स्कीम्ज़ पर आज पंजाब में काम हो रहा है वह सराहनीय है। उन्होंने 21 करोड़ तक की रक्म पंजाब स्टेट को देने का वादा किया है। (तालियां)

इस सिलसिला में कल एक मीटिंग दिल्ली में भी हुई थी जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी शिर्कत फरमाई थी। इसमें यू.ऐस.ए. से कुछ अमरीकन ऐक्सपर्ट और दीगर सैंटर के लीडर्ज़ फूड मिनिस्टर साहिब भी शामल हुए इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी शामिल थे, और यह फैसला हुआ था कि यू.एस.ए. की टीम पंजाब में भेजी जाएगी और वह वहां जाकर इस बात का मुताल्या करेगी कि पंजाब की वाटर लागिंग को दूर करने की दिशा में किस किस किस्म की सहायता दरकार है।

On an indication from the Government, U.S.A.I.D. Mission has expressed its interest in the Northern India regional land and water management programme for formulating plans for maximum agricultural production. The U.S.A.I.D. Mission is, therefore, considering bringing to India of a large development and technical consulting firm with an established background of successful planning and execution in river basin development. This firm, the Development Corporation is headed by David Lilienthal, former head of the T.V.A.Mr. Lilienthal accompanied by Mr. Leo Ander son an Agricultural Technician, who is Corporation Vice-President, arrived in India on March 15, 1965. Mr. Lilienthal and Mr. Anderson along with a party of other experts visited Punjab from the 19th to the 21stMarch in order to see the conditions and agricultural practices at site. A meeting has been held at Delhi and it has been decided in that meeting that Mr. Lilienthal will arrange to formulate a plan in about 2 to 2½ months for land, water management, etc.

यू.एस.ए.आई.डी. की तरफ से टैक्नीकल और माली इमदाद जो भी संभव होगी वह पंजाब गवर्नमेंट हासिल करेगी चाहे वह वर्ल्ड बैंक से लेना पड़े, चाहे सैंटर से लेना पड़े चाहे, यू.एस.आई. डी.से हो। गर्ज़ यह कि इस मीनेस को दूर करने के लिये हमारी सरकार हर ममकिन कोशिश करेगी।

बाबू बचन सिंह : गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में एक फ्लैचर कमेटी बिठाई थी जिसकी रिपोर्ट इस सैशन में आ जानी चाहिए थी लेकिन वह अब तक नहीं आई। क्या मिनिस्टर साहब, यह रोशनी डालेंगे कि वह इस सैशन के खत्म होने से पहले पहले आ जायगी या नहीं ?

लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री : यह कहना अभी मेरे हाथ में नहीं क्योंकि उसमें सैंटर के लोग भी शामिल हैं। उसके लिये तो जितनी कोशिश मैं करूँगा, उतनी ही आप कर सकते हैं। कल बाबू बचन सिंह जी ने एक तजवीज़ दी थी कि वाटर लागिंग का पानी इस तरह से निकाला जाए कि वह सिंचाई के लिये भी इस्तेमाल हो सके ताकि पैदावार

में इज़ाफा हो सके। मैं उनकी इस तजवीज़ से सहमत हूँ क्योंकि यह बड़ी माकूल है। इस पर सरकार ने गौर किया है और हमने एक झील नशारा नाला के पानी से तैयार की है जो घग्गर के साथ साथ के कई हज़ार एकड़ के रकबे को सैराब करने की स्कीम के तहत है। यही नहीं इसके अलावा भी और कई स्कीमें तैयार हो रही हैं जो इस पानी को इस्तेमाल करने के लिये होंगी। जैसे सरस्ती ड्रेन और ड्रेन नंबर 8 में से दादरी के लिये स्कीम बनी है। झज्जर, गुड़गांव, और राजस्थान के इलाके को जो नुकसान पहुंचता है उसको बचाने के लिये और रेवाड़ी के इलाके को पानी देने के लिये भी एक स्कीम तैयार की जा रही है और राजस्थान और पंजाब गवर्नमेंट ने यह मुश्तरका फैसला किया है कि बांध तामीर किया जाए जिस पर एक करोड़ 50 लाख के करीब खर्च आना है। यह स्कीम सैंट्रल वाटर वर्क्स कमीशन को जा चुकी है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस पानी को यूटीलाइज़ करें।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : यह लम्बी लम्बी स्कीमें तो बना दीं, लेकिन हमारे यहां दो रजबाहे हैं उनको पानी क्यों नहीं मिलता।

लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री : मैंने फ्लड्ज़ के मुताल्लिक कहा है, आबपाशी का जहां तक सवाल है, उसकी तरफ मैं बाद में कहूँगा। स्पीकर साहब, जैसा कि आपको पता है, इरीगेशन का मामला बड़ा पेचीदा मामला बना हुआ है ——

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : आपने सवां नदी का ज़िक्र क्यों नहीं किया ?

लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री : स्पीकर साहब, यह दुरुस्त है कि होशियारपुर ज़िला में चोओं की वजह से और नदियों की वजह से तबाही होती रही है लेकिन अब सरकार ने इस ओर बहुत सफलता प्राप्त की है और जिन चोओं को ट्रेन करने का काम बाकी है उनकी तरफ भी सरकार इस साल कोशिश करके ध्यान देगी और मुकम्मल करेगी। अभी मुकम्मल करने का इरादा है। जहां तक फ्लड्ज़ का सवाल है, स्पीकर साहब, यह बड़ा पेचीदा मामला होता जाता है। यह जो मसला है, अगर हम कहीं ज्यादा पानी देते हैं तो उससे सेम का खतरा पैदा हो जाता है। इस सारे मसले को सांइटिफिक तरीके से ही हल किया जा सकता है। आज सिर्फ नहरों और ड्रेनों को बनाना ही सांइटिफिक नालेज डीमांड नहीं करता बल्कि उनमें पानी चलाने के लिये भी सांइटिफिक तरीकों की ज़रूरत है और वह जारी हो चुके हैं। 10 साल पहले जिन इलाकों में डीमांड की जाती थी कि वाटर टेबल और ऊंचा होना चाहिए, आज वह ज़मीनें बिल्कुल सेम से तबाह हो गई हैं। इसलिये सिंचाई का जो मसला है यह बहुत अहम मसला है। जहां तक पानी में अज़ाफा करने का ताल्लुक है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पार्टीशन के वक्त सिर्फ 30 लाख एकड़ रकबा ही इरीगेट हो सकता था। लेकिन भाखड़ा डैम बनने से, ब्यास डैम चालू है और इसके इलावा और भी ऐसी स्कीम्ज़ हैं उनके ज़रिये वाटर का पुटैंशल बढ़ता जा रहा है। गुड़गांवा कैनाल के मुताल्लक

[लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री]

श्री रूपलाल जी बड़े बेताब हैं। उनके यह खदशात हैं कि गुड़गावां कैनाल पर कभी काम शुरू हो जाता है कभी बंद हो जाता है । उसकी सही पुज़ीशन यह है कि इस वक्त 2 करोड़ 13 लाख रुपया उस काम पर खर्च हो चुका है और 73 लाख के करीब अब प्रोवाइड किया है। इस तरह से 2 करोड़ 86 लाख रुपया हमने अपने पास से खर्च किया है और 92 लाख राजस्थान सरकार ने अपने हिस्से का देना था जो कि अभी तक हमें नहीं मिला । अगले साल में उन्होंने 50 लाख रुपया देने का यकीन दिलाया है । मेहता रूपलाल जी ने कहा था कि चौधरी रणबीर सिंह ने जब वह मिनिस्टर थे तो यकीन दिलाया था कि दिसम्बर, 1965 में पानी दे देंगे। मैं भी उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उस एशोरेंस से हम, बैकआउट नहीं करते, शैड्यूल के मुताबिक तब तक 300 क्युसैक्स पानी हम उनको दे दें और फिर मार्च 1966 में शैड्यल के मुताबिक बाकी का पानी भी दे देंगे। यह भी उनका खदशा ग़लत है कि 110000 की बुर्जी के आगे 168000 तक का जो एरिया है उसमें काम नहीं होगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम काम करेंगे । मुमकिन यह हो सकता है कि अगर राजस्थान से पूरा पैसा न मिला तो उस एरिया की लाईनिंग न कर सकें लेकिन जहां तक खुदाई का ताल्लुक है वह काम हम शैड्यूल के मुताबिक पूरा करेंगे और पानी चलाने का काम मार्च 1966 तक करेंगे । इस के इलावा मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर कैनाल जिसमें से पानी की गुज़रगाह होगी उसके लिये एक करोड़ रुपया हमने यू. पी गवर्नमेंट को देना है ताकि उसकी रीमार्डलिंग का काम भी साथ ही साथ हो जाए और कोई रुकावट गुड़गांव ज़िले में पानी पहुंचने में न हो । इसी तरह रिवाड़ी की लिफ्ट स्कीम के लिए बड़ी तेज़ी से लगे हुए हैं । वहां हम बिजली का काम अपने हाथ में ले रहे हैं ताकि ब्रेक डाऊन्ज़ न हों । उस से 65 हजार एकड़ के करीब आबपाशी होगी । महिन्द्रगढ़ और लोहारू के जो खुश्क इलाके हैं उनको पानी देने के लिये दादरी की जो स्कीम बनी है उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं । दोहान नदी और कृष्णा नदी के पानी को सिंचाई के लिये इस्तेमाल करना है और उसके लिए हम एक हज़ार फुट ऊंचाई का बांध लगा रहे हैं। 10 लाख रुपया इस बांध के लिये प्रोवाईड किया है। इसके इलावा गुड़गांव जिले के लिये बांध लगाने के लिए आठ लाख रुपया प्रोवाइड किया है। अभी हमने ज़िक्र किया था कि साहिबी नदी से रिवाड़ी को नहर पहुंचाई है, उसे और रेगुलेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो 18 ट्यूबवेल हमने रिवाड़ी में लगाए हैं वह भी चालू हो जायेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पंजाब सरकार सिंचाई के लिये बहुत काम कर रही है । गुड़गांव कैनाल से जो आबपाशी होगी उससे पलवल, बलबगढ़, फीरोज़पुर झिरका और नूह का 1,68,889 एकड़ एरिया इरीगेट होगा । इसी तरह लो लिफ्ट से 153,804 एकड़ में आबपाशी होगी, इसके इलावा, हाई लिफ्ट से 81,680 एकड़ रकबा, इरीगेट होगा। गुड़गांव कैनाल बनाने में 8 करोड़ 31 लाख के करीब अंदाज़ा है खर्च का । 2 करोड़ 42 लाख हम इस साल के आखिर तक खर्च कर देंगे, बाकी जो राजस्थान से लेना है वह खर्च करेंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ : ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਉ ।

लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री : बहुत अच्छा जी मैं बता दूंगा उसके बारे में भी । पहले जो बात कह रहा हूँ उसे पूरा कर लूं। जहां तक इरीगेशन के पोटैंशल के बढ़ाने का सवाल है उसके बारे में जो स्कीम्ज़ थीं या जो जो तजावीज थीं वह मैंने अर्ज़ कर दी हैं। जोगा साहिब ने बताया था कि कल्टीवेटर्ज़ की कुछ और भी दूसरी छोटी छोटी मुश्किलात होती हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनकी तरफ भी सरकार ने ध्यान दिया है । काफी ऐसे केसिज़ हमारे नोटिस में आए हैं। जहां एक तरफ ज्यादा पानी पैदा करने का सवाल है वहां यह भी सवाल है कि उस पानी का मैनेजमेंट किस तरह से हो। जो आर्ज़ी मोघाजात और फ्लड चैनल्ज़ 20 सितम्बर तक चलती थी हमने उन की पड़ताल की है । उनको बंद करने का मतलब यह होता था कि किसान की फसल जब पकने के करीब पहुंचती थी तो उसे पानी नहीं मिलता था मगर आब्याना वह देते थे। और न दूसरी फसलों के लिए उस पानी को इस्तमाल कर सकते थे । इस लिये हमने फैसला किया और इस दफा 31 दिसम्बर तक आरज़ी मोघे और जो फ्लड चैनल्ज़ थे उनको जारी रखा है । इसके बाद हमने यह भी फैसला किया है कि यह जो माइनर टैक्नीकल दिक्कतें किसानों को शूट्स लेने में और बाराबंदी के सिलसिले में पेश आती हैं उनको भी रिमूव किया जाए । पहले दसतूर था कि आर्ज़ी मोघों के लिये मार्च में दरखास्त दी जाए लेकिन वह बात हमने खत्म की और हमने कहा कि जहां तक किसान की पानी की मांग का संबंध है उस पर कोई ऐसी म्याद नहीं होनी चाहिए। अगर पास में पानी है तो जिस वक्त मांगा जाए उसे पानी दिया जाए चुनांचि इस साल फिरोज़पुर और अमृतसर की तरफ से मांग आई कि जितने नान पैरेनियल चैनल्ज़ हैं उनको अगर फरवरी से चला दें तो नैशकर काश्त कर सकते हैं। हमने इस मांग को माना और जहां जहां से ऐसी मांग आई हमने उन्हें चैनल्ज़ चला दिये । यही नहीं बल्कि नहरी अफसरों की ड्यूटी लगाई कि वह पड़ताल करते रहें कि किस डिस्ट्रीब्यूटरी की मांग पूरी हो चुकी है और किस की बाकी है और जहां मांग पूरी हो चुकी है वहां से पानी बंद करके दूसरी जगह जहां ज़रूरत है पानी दिया जाए इस तरह से हमने पानी को रैगुलेट किया है और इस तरह करने से हम 3½ लाख एकड़ ज़मीन की और आबपाशी कर सके हैं। यह कोई थोड़ा रकबा नहीं है । इसके साथ हमने यह भी देखा है कि कितना रकबा जो सेमज़दा है और जहां पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहां क्राप पैट्रन बदल चुका है । इस लिये हमने इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिये किस इलाके में किस वक्त पानी चाहिए ताकि उसे उसके मुताबिक रैगूलेट किया जाए और यह देखने के लिये कि उसका कौनसा रेट हो वगैरह वगैरह उसके लिये एक कमेटी बना दी है जिस के चेयरमैन हमारे एक चीफ इन्जीनियर हैं, एक मैम्बर ऐग्रीकल्चर के एसिस्टंट डायरैक्टर हैं और एक तीसरे और हैं। यह कमेटी सारी जांच पड़ताल करेगी कि कितना एरिया ऐसा है जहां सेम की वजह से पानी की ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी उसमें पानी डालते जा रहे हैं जिससे सेम बढ़ रही है उसके पानी को बन्द करके वहां

[लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री]

अगर ज़रूरत हो और अगर ट्यूबवैल्ज़ के ज़रिये पानी दे सकें तो दें ताकि इस तरह सेम का मसला हल कर सकें । जिस वक्त इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम सारे मैम्बर साहिबान से सलाह मश्विरा करेंगे । हम पानी की रिडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं ताकि जहां पानी की कम ज़रूरत हो वहां से पानी खारज करके जहां ज्यादा ज़रूरत हो वहां ज्यादा पानी दे सकें । दो तीन मैम्बर साहबान ने ठीक फरमाया कि फलां इलाके में अगर 4 क्यूसिक्स फी हज़ार एकड़ के हिसाब से पानी देते हों तो फलां में 1.9 क्यों हो। ठीक है यह बात नहीं रहनी चाहिए । इस पानी को बढ़ाने के लिये हम भाखड़ा कैनाल्ज़ और दूसरे सिस्टम्ज़ जो हैं उनको इन्ट्रलिंक करने के लिये लिंकिंग चैनल्ज बनाने की स्कीम को इन्वैस्टीगेट कर रहे हैं ताकि जहां पानी की ज्यादा ज़रूरत हो वहां पानी को रैगूलट करके ज्यादा पानी दे सकें । हम नहीं चाहते कि रीज़नल लाइन्ज़ पर पानी के सवाल को देखा जाए बल्कि हम चाहते हैं ज़रूरत के हिसाब से पानी दिया जाए (घंटी) जहां तक रिमार्डलिंग की बात है वह ईस्ट सर्कल की तो हो चुकी है अब वैस्ट सरकल की कर रहे हैं। उस पर अगले प्लान में एक करोड़ 40 लाख रुपये खर्च करेंगे । पानी देने का जहां तक सवाल है मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि हम इन सारे सिस्टम्ज़ को इन्टरलिंक करना चाहते हैं ताकि ज़रूरत के मुताबिक पानी को रैगूलेट करके दिया जा सके। और किसी को यह गिला करने का मौका न मिले कि फलां जगह इतने क्यूसिक्स फी हज़ार एकड़ का पानी मिलता है और फलां जगह इतना कम मिलता है। कोशिश हमारी यही है कि ज़िला हिसार को जहां पानी की ज़रूरत और खपत ज्यादा है वहां अगर 4.5 क्यूसिक्स तक पानी दे सकें तो दें (विघ्न) भिवानी और लुहारू के लिय कोशिश की थी कि सिद्धमुख की तरफ से पानी दें लेकिन वहां लैवल ऊंचा मिला है और पानी चढ़ नहीं सकता है । हम कामयाब नहीं हो सके। अब दहान नदी की तरफ से चलो इरीगेशन के ज़रिए पानी देने की स्कीम को इन्वैस्टीगेट करना चाहते हैं। आशा है कि इस साल उस स्कीम पर काम चालू करके वहां भिवानी और लुहारू में जहां पानी इन ब्रेकेज मिलता है फ्लो इरीगेशन के लिये पानी दे सकेंगे। फिर हम बुटाना ब्रांच के ज़रिए नाई नाला का पानी भी वहां पहुंचाना चाहते हैं। अगर ज्यादा खर्च न हुआ तो लिफ्ट इरीगेशन के ज़रिए भी पानी देने की स्कीम को देखेंगे और सिद्धमुख वाली स्कीम भी अभी ज़ेरेगौर ही है । हम हर तरीका से कोशिश कर रहे हैं कि वहां पानी दिया जाए। हम अपनी औकात के मुताबिक लगे हुए हैं। और पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि भिवानी में 60 गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है.............

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : हिल्ली एरियाज़ के बारे भी बता दें।

लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री : हिल्ली एरियाज़ में आप जानते हैं कि दो स्कीमों पर 4 लाख रुपया खर्च करके पानी दे चुके हैं। अगले साल के लिये भी अगर आपने बजट देखा हो तो 6/7 स्कीमें ज़ेरे गौर हैं और उनके लिये रुपया रखा हुआ है ।

उस तरफ हमारा पूरा ध्यान है और लिफ्ट इरीगेशन के ज़रिये वहां भी पानी देने की कोशिश में लगे हुए हैं । बाकी जहां तक वैस्टर्न जमुना ट्रैक्ट का सवाल है वहां भी हम लिफ्ट इरीगेशन के लिये पानी देना चाहते हैं । आज पंजाब में 1400 के करीब सरकार के ट्यूबवैल्ज़ हैं और उन पर हम फ्लो रेट चार्ज कर रहे हैं। (घंटी) नहरी रेट चार्ज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें 60 लाख रुपये सालाना का खसारा बरदाश्त करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी हम समझते हैं कि यह इन्साफ की बात है कि वैस्टर्न जमुना ट्रैक्ट जहां नहरी पानी कम हैं और उसे सप्लीमेंट करने के लिये जो ट्यूबवैल्ज़ लगे हैं उनकी वजह से अगर खसारा भी पड़ता है तो बरदाश्त करें लेकिन पानी वहां ज़रूर दें। चौधरी रणवीर सिंह जी ने कहा कि खर्चा बढ़ गया है । कोई बात नहीं है अगर बढ़ गया है । फिर उन्होंने यह कहा कि नहरी महकमा में ऐस० ईज़० की ज़रूरत नहीं है फ़ज़ूल की पोस्टें हैं। मैं समझता हूँ कि चैक्स ऐंड बैलेंसिज़ के लिये और काम खुश-असलूबी से चलाने के लिये इनका होना ज़रूरी है क्योंकि गलत कार्रवाइयां होने का अन्देशा रहता है । इसलिये मैं एस. ईज को गैर ज़रूरी नहीं समझता यही वजह है कि आठ पोस्टें जो एबौलिश कर दी गई थीं वह मैंने रीवाइव कर दी हैं। आप जानते हैं कि एस. ई ट्यूबवेल की अलहदा पोस्ट थी जो अबोलिश कर दी गई थी । उसका नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं। ट्यूबवैल्ज़ की हिस्टरी को अगर आप देखें तो जब से यह लगे हैं चले ही नहीं हैं, काफी ऐसे हैं जो खराब हुए पड़े हैं, काफी एसे हैं जिनके खाल ही नहीं खुद सके हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहरों के साथ overlap करते हैं । अब उसके लिए एस. ई. को लगाया है जो देखेगा कि हर एक ट्यूबवैल्ज़ के कमांडिंग एरिया में खाल बने होने चाहिए । इसके लिये उसे मियाद भी दी है कि इतने अर्से के अन्दर वह देखे कि खाल खुद कर पानी चालू किया जाए। हमने किसानों को कहा है कि वह खाल खुद तैयार करें । जहां पर पानी की ओवर लैपिंग है वहां पर नहरों का पानी बन्द कर दिया जाएगा और वहां पर ट्यूबवैलों के द्वारा पानी सप्लाई किया जायगा ।

स्पीकर साहिब, यहां पर बैटरमैंट लैवी का सवाल उठाया गया । उसके बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसके मुताल्लिक एक कमेटी बनी थी और उसके चेयरमैन सरदार दरबारा सिंह थे । उन्होंने इस के बारे में रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के हर पहलू को एग्ज़ामिन किया जा रहा है। इनमें दो तीन बातों को सरकार ने मान लिया है । जैसा कि सूद का सवाल है । सरकार ने फैसला किया है कि किसानों से 3 प्रतिशत ही सूद लिया जाएगा । इस तरह से कई ऐसी बातें—जैसा कि इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, लोकल रेटस हैं, इसके बारे में सरकार सोच रही है । इसी तरह से सतलुज नदी के किनारों पर जमीन को रिक्लेम किया जा रहा है। वहां पर सरकार सोच रही है कि और क्या मदद दी जानी चाहिए । इस तरह से एक और कमेटी बैटरमैंट लेवी के लिये मुकर्रर की जा रही है जोकि इस बारे में जांच पड़ताल करेगी कि किस तरह से यह सिफारिशें लागू की जाएं । मैं हाउस में कहना चाहता हूँ कि यह मामला अभी तै नहीं हुआ है । इस वक्त मैं यह नहीं कह सकता कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी । लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं।

[लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री]

स्पीकर साहिब, ब्यास डैम के ग्राउस्टीज के मुताल्लिक जितनी ग्रानरेबल मैम्बर को चिन्ता है, उतनी हमें भी चिन्ता है। इसके बारे में एक इम्पलीमेंटेशन कमेटी बनाई थी। उसके जरिए बहुत सी बातें उन के बारे में तै हो चुकी हैं। इसके लिये राजस्थान सरकार ने जमीन देनी थी लेकिन उन्होंने उन के लिये प्रायर्टी नम्बर 5 दिया है। उन से क्वांटिम एग्रीमेंट हुग्रा था ग्रौर हमने कहा कि उसमें तबदीली होनी चाहिए। लेकिन वह रज़ामन्द नहीं हुए। इसके बारे में सैंट्रल गवर्नमेंट के इरीगेशन मिनिस्टर की ग्रध्यक्षता में मीटिंग हुई। उसमें चीफ मिनिस्टर साहिब ग्रौर मैं भी शामिल हुग्रा। हमने वहां पर कहा कि इन को फर्स्ट प्रायरटी दी जाए। चुनांचि यह मामला केन्द्रीय सरकार को रैफर हुग्रा ग्रौर प्लैनिंग कमीशन की एक प्राजैक्ट ग्रथॉरिटी की कमेटी इस महीने तक मुकर्रर हो जाएगी जोकि इन सारी बातों पर गौर करेगी। मैंने उनको चिट्ठियां भी लिखीं ग्रौर खुद भी वहां पर मिला ग्रौर इसके विषय में प्रबन्ध हो रहा है।

स्पीकर साहिब, मैं ग्रापका शुक्रिया ग्रदा करता हूँ कि ग्राप ने मुझे गवर्नमेंट की पोज़ीशन वाज़ेह करने के लिये वक्त दिया। मैं सारे ग्रानरेबल मैम्बरों की बातों पर डिटेल्ज में नहीं जा सका क्योंकि वक्त बहुत कम है लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिलाता हूँ कि उनकी सुजैशन्ज पर ज़रूर गौर किया जाएगा।

Mr. Speaker : I will put the cut motion in the name of Comrade Jangir Singh Joga to Demand No. 26 to the vote of the House.

Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 5,88,52,620 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head 42—Multipurpose River Schemes.

The motion was carried.

Mr. Speaker : There is one cut motion by Shri Roop Lal Mehta to Demand No. 27.

Shri Roop Lal Mehta : I withdraw it, Sir.

Mr. Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the motion ?

(Voices : Yes).

The motion was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 5,23,98,910 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head 43—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)

44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,75,33,150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head Charges on Irrigation Establishment.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 19,59,48,620 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head 98—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

The motion was carried.

Mr. Speaker : There is one cut motion to Demand No. 48 by Sardar Pritam Singh Sahoke.

Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 5,50,02,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head 99—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

The motion was carried.

DEMANDS FOR GRANTS (No. 41)

71—MISCELLANEOUS

Education and Local Government Minister (Shri Prabodh Chandra) : Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs. 3,49,68,100 *be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payement for the year* 1965-66 *in respect of charges under head* 71—*Miscellaneous.*

(*Note.*—Discussion on the Local Government only).

Mr. Speaker : Motion moved—

That a sum not exceeding Rs. 3,49,68,100 *be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year* 1965-66 *in respect of charges under head* 71—*Miscellaneous.*

(*Note.*—Discussion on the Local Government only).

Cut motions received from various hon. Members to this demand will be deemed to have been read and moved and can be discussed alongwith the main motion.

1. **Comrade Shamsher Singh Josh :** That the demand be reduced by Rs. 100.

2. **Chaudhri Ran Singh :**

3. **Sardar Pritam Singh Sahoke :** That the demand be reduced by Rs. 100.

श्री बलरामजी दास टंडन (अमृतसर) स्पीकर साहिब, इस सदन में आज लोकल बाडीज के बारे में बहस हो रही है। जहां तक देखने में आया है कि पिछले 8,10 सालों के अन्दर यह पहली बार ही इस डिमांड पर डिस्कशन हो रही है । पिछली सरकार इस महकमे को यतीम समझती रही है और इसी कारण से यह महकमा लावारिस बन कर रह गया है । मैं समझता हूँ कि पिछली सरकार ने इस बारे में अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी । जहां तक इस नयी सरकार का सम्बन्ध है, जो कुछ इस सरकार ने इनके बारे में किया है, उससे अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सरकार ने कुछ ही ध्यान दिया है लेकिन वह भी नहीं के बराबर है । मैं यह नहीं कह सकता कि यह गवर्नमेंट भी पिछली गवर्नमेंट के फुटपाथ पर चलने की कोशिश करगी या नहीं । मैं नहीं कह सकता कि यह सरकार इस महकमे के तरीकों को बदलने की कोशिश करेगी या नहीं लेकिन अभी तक इस सरकार की तरफ से इन तरीकों को बदलने की झलक नज़र नहीं आई है। जहां तक इस महकमे का सम्बन्ध है, उसके अन्दर बेसिक कमियां हैं और उनको दूर करने की बहुत ही ज़रूरत है । पहली म्युनिसिपल कमेटियों के इलैक्शनों में तबदीली लाने की ज़रूरत है । म्युनिसिपल कमेटी के एक्ट के मुताबिक 3 साल के बाद म्युनिसिपल कमेटी के इलैक्शन होने चाहिए लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां तक म्युनिसिपल कमेटियों के इलैक्शनों का ताल्लुक है, सरकार कभी भी सीरियस नहीं हुई । मैं समझता हूँ कि सरकार तभी सीरियस हो सकती है जब म्युनिसिपल कमेटियों के इलैक्शन्ज़ खत्म हो जाएं, तब म्युनिसिपल कमेटियों के नए वार्डज़ बनाने के लिये काम शुरू हो जाना चाहिए और बाकी का सारा काम भी उसी वक्त

से शुरू हो जाना चाहिए ताकि तीन साल के अन्दर दोबारा रिकार्ड बन कर तैयार हो जाए और वक्त पर इनकी इलैक्शन्ज़ हो जाएं । यह इलैक्शन्ज़ भी दूसरे सूबों की तरह एक वक्त पर हो जानी चाहिएं । इस मामले में देखा जाता है कि सरकार इस मामले में बिलकुल सीरियस नहीं है । पंजाब में कई ऐसी म्युनिसिपल कमेटियां हैं जहां पर पिछले 10,12,17 या 21 साल से इलेक्शन्ज़ नहीं हुए इस से साफ ज़ाहिर है कि सरकार इन संस्थाओं को इगनोर करती रही है और इस महकमें को कोई अहमीयत नहीं देती है । वैसे तो कहने के लिये यही कहते हैं कि यह महकमा बेसिक डैमोक्रेसी की ट्रेनिंग देने वाला है लेकिन गवर्नमेंट का नज़रिया इससे बिल्कुल उल्ट है । अगर सरकार इन कमेटियों के इलेक्शन्ज वक्त पर इस महकमे के द्वारा नहीं करा सकती है तो मैं चाहता हूँ कि यह इलैक्शन्ज़ भी इलैक्शन कमिश्नर के ज़ेर कर देने चाहिएं ताकि वक्त पर इलैक्शन्ज हो सकें । जिसको बेसिक डैमोक्रेसी की ट्रेनिंग समझा जाता है वह बिल्कुल राटन है । मिनिस्टर साहिब को चाहिए कि कोशिश करें कि वक्त पर इलैक्शन हो सके । कितनी हैरानी की बात है कि अमृतसर का इलक्शन हुए बारह साल हो चुके हैं । पंजाब गवर्नमेंट पिछले आठ दस साल से कह रही है कि कार्पोरेशन बनेगी, कार्पोरेशन बनेगी, इसके बारे में रोज़ स्टेटमेंट्स आती रहीं । पिछले चीफ मिनिस्टर साहिब जोकि लोकल बाडीज़ के मिनिस्टर भी थे, असैम्बली के अन्दर भी और बाहर भी यही बात कहते रहे और हमारी इस गवर्नमेंट ने भी कहा कि कार्पोरेशन बनेगी लेकिन आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वह बिल अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है । एक साल से सब कमेटी भी बनी है, लेकिन उस की कोई मीटिंग अभी तक नहीं हुई । उसके बाद रिजनल कमेटियों में जाएगा । अगर इसी ढंग से यह बात चलती रही तो यह सारा प्रोसीजर दो तीन साल में भी पूरा नहीं होगा । पहले सब कमेटी रिजिनल कमेटी को रीपोर्ट करेगी, रिजिनल कमेटी में बहस होगी फिर मामला असैम्बली के अन्दर जाएगा । पास होने के बाद गवर्नर साहिब अपनी असैंट देंगे और बाद में रूल्ज़ बनेंगें । मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आज भी सीरियसली शुरू करें तो भी यह प्रोसीजर तीन साल में पूरा होगा । लेकिन ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अभी तक भी इस बात के बारे में सीरियस नहीं है । सारा मामला खटाई में पड़ा है । 12 साल हो गए हैं अमृतसर के म्युनिसिपल कमेटी के इलैक्शन हुए अब मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि मई के महीने में होगा । लेकिन अभी तक वार्डों की गज़िट नोटीफिकेशन्ज नहीं हुई, उसके बाद वोटर्ज़ की लिस्ट बनेगी, फिर पबलिश होगी । उस पर एतराजात होंगे कि कौन से जायज़ हैं और कौनसे नाजायज़ हैं कौन से और ऐड होने चाहिएं । उस में भी महीना डेढ़ महीना लग जाएगा । फिर अनाउंसमेंट होगी उसमें भी एक महीना लग जायगा । अब मार्च का महीना खत्म हो रहा है बीच में अप्रैल का महीना रहा है मालूम नहीं है कि मई के महीने में यह कैसे इलैक्शने करवा देंगे । यह कहां तक युक्ति-संगत है कहा नहीं जा सकता ।

इसके बाद जो मैम्बरों का नाम गज़िट होता है उसके बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ । चाहिए तो यह कि रूल्ज़ के मुताबिक जो मैम्बर बन गए हों उन मैम्बरों

[श्री बलरामजी दास टण्डन]

का गज़िट नोटीफिकेशन हो जाए मगर जो हालत आज है कई बार दो दो, और तीन तीन महीने तक गैज़िट नोटीफिकेशन नहीं होता । चाहिए तो यह कि जो मैम्बर चुने जाएं उनके नाम की नोटीफिकेशन ज्यादा से ज्यादा एक हफता नहीं तो 15 दिन में हो जानी चाहिए । यह रूल्ज के अंदर प्रोवीज़न होनी चाहिए कि 15 दिन के अंदर सब मैम्बरों की नोटीफिकेशन हो जाए ताकि किसी प्रकार की इररैगुलैरिटी न हो । फिर प्रैज़ीडैंट का नोटीफिकेशन होता है । हालत यह है कि जब कोई प्रैज़ीडेंट चुना जाता है तो कई कई जगह तीन तीन चार चार और 6,6 महीने तक उनका गैज़िट नोटीफिकेशन नहीं होता । राजपुरा के प्रैज़ीडैंट को चुने हुए 4,6 महीने होने लगे हैं लेकिन अभी तक गज़िट नोटीफिकेशन नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है ? अगर कोई आदमी मैंबर बनने और मैम्बर रहने के काबल है और वह चुना गया है तो उन मैम्बरों में से ही कोई मैम्बर प्रैज़ीडेंट चुना जाता है तो उसके लिये स्पेशल नोटीफिकेशन की क्या जरूरत है, जैसे वाईस प्रैज़ीडेंट को ट्रीट किया जाता है वैसे ही प्रैज़ीडेंट को भी किया जाना चाहिए । जो चीज अंग्रेजों के वक्त से चली आ रही है वही आज भी चलाई जा रही है । यहां पर हाउस का स्पीकर चुना जाता है एक मिनट में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और पावर्स संभाल लेता है। इसी तरह से कौंसिल का चेयरमैन चुना जाता है वह भी एक मिनट में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और पावर्स संभाल लेता है। लेकिन म्यूनिसिपल कमेटियों के प्रैज़ीडेंट चुने जाते हैं तो उन के नाम की गज़िट नोटीफिकेशन होन में 6,6 महीने लग जाते हैं वह मुंह उठा कर गवर्नमेंट की तरफ देखते रहते हैं। कब जाकर गज़िट नोटीफिकेशन हो और कब जाकर वह प्रैज़ीडेंट बने । इसलिये मैं कहता हूँ कि जिस तरह से वाइस प्रैज़ीडेंट का केस है वैसा ही प्रैज़ीडेंट का होना चाहिए । यह गज़िट नोटीफिकेशन सुपरफलुअस है, नहीं होनी चाहिए । इसकी कोई जरूरत नहीं है । इसमें तबदीली करने की जरूरत है । कई कई महीने तक सारा काम ससपैंड रहता है ।

(At this stage Rao Nihal Singh, a member of the Panel of Chairmen, occupied the Chair).

जहां तक म्युनिसिपल एक्ट का ताल्लुक है वह तीन चार साल से पैंडिंग पड़ा हुआ है । कुछ मीटिंगें सब कमेटी की हुई होंगी लेकिन कब वह रिजनल कमेटी में आएगा और वहां से पास होकर कब हाउस में आएगा, कौंसिल में कब पास होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता । 1911 का अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ है और 55 साल इस एक्ट को बने हुए हो गए हैं। अभी तक वही लागू है, राट एक्ट। तीन चार साल से उस पर विचार हो रहा है लेकिन अभी तक उसको फाईनल शेप नहीं मिल पा रही इसमें तबदीली की आवश्यकता है । जहां तक एग्ज़ैक्टिव अफसरों की अप्वायंटमेंट का ताल्लुक है वह पैप्सु के अंदर अलग है और पंजाब के अंदर अलग है । दूसरे सारे एक्ट हो चुके हैं लेकिन यह एक्ट मुख्तलिफ है। मैं मिनिस्टर साहिब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। पंजाब में तो यह प्रैक्टिस है कि कोई भी म्युनिसिपल

कमेटी अपनी एबसोल्यूट मजारिटी के साथ अपना एग्जैक्टिव अफसर मुकर्रर कर सकती है। लेकिन पैप्सू में एग्जैक्टिव अफसर गवर्नमेंट ही अपवायंट करती है । जो भी उनको मुनासिब आदमी मालूम होगा उसी को मुकर्रर कर देंगे, चाहे वह ठीक हो या न ठीक हो। आज भी यही प्रैक्टिस चल रही है। मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहिब इस तरफ ध्यान दें ताकि नया ऐक्ट जो बन रहा है उसमें किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन न रह जाए । जब तक नया ऐक्ट लागू नहीं होता उस वक्त तक गवर्नर साहिब के नोटीफिकेशन से जो प्रैक्टिस पंजाब में लागू है वही पैप्सू में भी लागू करनी चाहिए ।

पंडित सुरेन्द्र नाथ गौतम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । हाउस का कोरम नहीं है ।

श्री सभापति : कोरम है । (There is quorum in the House)

श्री बलरामजी दास टंडन : चेयरमैन साहिब, मैं कह रहा था कि गवर्नर के आडरे के जरिये इस पुराने ऐक्ट को रीपील किया जाना चाहिए और जिस तरह से पंजाब में चल रहा है वैसे ही पैप्सू में भी लागू होना चाहिए।

इससे आगे मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट किस तरह से म्युनिसिपल कमेटी की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है । वह बड़ा अजीब तरीका है। कमेटियों में ट्रिपल कंट्रोल है । डी.सी. के पास अगर कोई रैज़ोल्यूशन जाता है तो वह उसको सुप्रसीड कर सकता है उनको वक्तन फवक्तन आर्डर भेज सकता है । दूसरी तरफ कमिश्नर साहिब का 'ए' क्लास कमेटियों पर कंट्रोल होता है । वह उनका बजट पास करते हैं चाहे कितनी देर तक वह रख छोड़ें । उन के रैज़ोल्यूशन को भी वह देखते हैं। तीसरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है जिस तरह चाहे, म्यनिसपल कमेटी को सुप्रसीड कर सकती है। इस तरह से कमेटियों पर ट्रिपल कंट्रोल चल रहा है। कोई भी पालिसी मैटर की बात हो, डी० सी. कुछ लिखता है, गवर्नमेंट कुछ लिखती है । इसमें यूनीफार्मिटी नहीं है अलग अलग ढंग से सब काम करते हैं। मैं मिनिस्टर साहिब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अगर वे वाकई ही म्युनिसिपल कमेटियों के काम में सुधार लाना चाहते हैं अगर गवर्नमेंट सीरियस है कमेटियों के काम में सुधार करने के लिये तो जैसा कि सब-कमेटी ने रिपोर्ट की है' सारे का सारा काम डायरैक्टोरेट के नीचे लाना चाहिए। अगर डायरैक्टोरेट नहीं होगा, जब तक कोई एक तरह की पालिसी सारी स्टेट में लागू न हो, यह मुमकिन नहीं कि डिप्टी कमिशनर्ज़ अपने अपने व्हिम्ज पर न चलते रहें । कभी पालिसी यूनिफार्मिटी में चल सकेगी यह मुमकिन नहीं । म्युनिसिपल कमेटियों पर से इस ट्रिपल कंट्रोल को जितनी जल्दी खत्म किया जाए भला है। जो आज ऐक्ट लागू है उसके मुताबिक गवर्नमेंट को वाईड पावर्ज हैं। चेयरमैन साहिब, गवर्नमेंट किसी वक्त भी ऐक्ट की धारा 14 के मुताबिक रीजन्ज़ देकर कोई ऐक्शन ले सकती है, चाहे वह नाजायज है या फिर धारा 16 के तहत ऐक्शन ले सकती है। यह दोनों धाराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यह गवर्नमेंट को इम्पावर

[श्री बलरामजी दास टण्डन]

करती है कि बगैर पूछे किसी मैम्बर को जहां गवर्नमेंट की मर्जी हो हटा दे और हमेशा के लिये उसकी मैम्बरी खत्म कर दें । चेयरमैन साहिब आजकल की दुनिया के अंदर जब हम डैमोक्रसी के बारे में इतना कुछ करते हैं, वोटें लेकर किसी जगह पर बैठे हैं तो उसके लिये पूरे अधिकार न दिये जायें तो यह ठीक नहीं । क्या गवर्नमेंट ने इसके बारे में महसूस किया है? उसे यह भी पता नहीं कि वह मैम्बर रहेगा या नहीं । किसी जगह पर फारमैलिटी पूरी कर ली और किसी जगह पर वह भी पूरी नहीं की । चेयरमैन साहिब, मैं यह महसूस करता हूँ कि यह जो रैट्रोग्रेड स्टैप अंगरेजों के वक्त से चला आ रहा है इस नए ऐक्ट में तबदील होना चाहिए । जब तक नया ऐक्ट लागू नहीं होता इस ऐक्ट में तबदीली होनी चाहिए । कोई मैंबर रिमूव न किया जा सके । कोई भी एक्शन लेने से पहले उसे पूरा चांस नहीं दिया जाता । कोई मैजिसटीरियल इन्क्वायरी नहीं होती, न ही इन्क्वायरी में यह बताया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये चार्जिज़ हैं और यह चार्जिज़ प्रूव हुए हैं और ये चार्जिज़ इस्टैबलिश हुए हैं । जब तक यह प्रोसीजर न हो ठीक नहीं । बटाला की म्युनिसिपल कमेटी के मैम्बरों के बारे में सुन कर आप हैरान होंगे । पिछली गवर्नमेंट ने उन के नाम गज़ट भी नहीं किए उन्होंने ओथ भी नहीं ली । लेकिन उनको हटा दिया । उनके खिलाफ ये चार्जिज़ थे कि उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया है। उन्होंने ओथ नहीं ली, उनका गज़ट नोटफिकेशन नहीं हुआ, इसलिये वे असली मानों में मैंबर नहीं बने । उन के खिलाफ यह चार्ज था कि वहां एक डेमान्स्ट्रेशन हुई, उस डेमान्स्ट्रेशन में वे हिस्सेदार थे । बगैर एक्सप्लेनेशन लिए उनको हटा दिया । पहले तीन साल के बाद टेन्योर खत्म हो जाता था, अब तो बढ़ा दिया है। अब तीन साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से उनका फैसला हुआ है । सरकार इलैक्शन करवाने के लिये कितना रुपया सर्फ करती है जब मैम्बर बन गए तो तीन साल तक उनका केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रहा । यह तरीका गवर्नमेंट के लिये कहां तक मुनासब है । जिन के नाम गजट भी नहीं हुए उन के साथ ऐसा किया गया है । ये तरीके हमें लागू नहीं करने चाहिएं मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर साहिब अच्छी भावना लेकर बैठे हैं कि डैमोक्रेसी को पनपने दिया जाए । मुझे उम्मीद है कि यह इसमें तरमीम करेंगे, इस एक्ट को नए एक्ट में बदलेंगे । ऐसी सारी की सारी क्लाज़िज को खत्म करेंगे । म्युनिसपल कमेटियों को सुपरसीड कर दिया जाता है, उन पर ग्रास नेग्लीजैंस के चार्जिज़ लगाते हैं। ग्रास नेग्लीजेंस के चार्जिज़ की इन्क्वायरी इन्डीपेंडेंट एजेंसी करे। अगर किसी जगह पर दूसरी पार्टी की मैजारिटी है तो कमेटी का प्रैजीडेंट उनका बन जाता है । हैरानी इस बात की है कि अगर गवर्नमेंट पार्टी के बगैर किसी दूसरी पार्टी का प्रैज़ीडेंट बन जाता है तो गवर्नमेंट उस कमेटी को सुपरसीड कर देती है । यह बहुत नामुनासिब बात है। पहले उस बात की इन्क्वायरी होनी चाहिए । डिस्ट्रिक्ट जज इन्क्वायरी करे और अपनी रिपोर्ट दे। उसके बाद अगर सरकार उस कमेटी को सुपरसीड करे तो 6 महीने में दोबारा इलैक्शन हो। लुध्याना म्युनिसिपल कमेटी की मिसाल आप के सामने है । पांच पांच सात सात साल हो जाते हैं कोई चुनाव नहीं

होता । ये चीजें निहायत बुरी हैं। मलोट की म्युनिस्पल कमेटी की मिसाल आप के सामने है। अगर उन्होंने कोई भी रैजोल्यूशन पास कर दिया जोकि सरकार न चाहती हो तो उस म्युनिसपल कमेटी को सस्पेंड कर देते हैं। वहां पर दूसरी म्युनिसिपल कमेटी आ जाती है। वे लाठियां और पिस्तौल लेकर आते हैं। एस. डी. ओ. साहिब को मजबूर किया कि उन के खिलाफ एक्शन लें। उन्होंने जा कर कहा कि हमें धमकियां देते हैं। अपनी नारमल फंकशन को डिस्चार्ज करने के लिये वे एक रैज़ोल्यूशन पास करते हैं। उस एस. डी. ओ. को मजबूर करते हैं कि रैज़ोल्यूशन मान ले। इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं मिनिस्टर साहिब से कहूँगा कि ज़िला फिरोजपुर में म्युनिसिपल कमेटी मलोट की तरफ ध्यान दिया जाए। वहां इस तरह की धांधली मची हुई है। उसकी तरफ ध्यान दें। इसके साथ कुछ और बातें हैं। म्युनिसपल कमेटियां अपने बजट बनाती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से डाइरैक्शन है कि 7 जनवरी तक वह अपना बजट कमिशनर या डिप्टी कमिश्नर, जैसा भी म्युनिसपल कमेटी का स्टेटस हो, उसके पास भेज दे। 30 नवम्बर के एक्चुअल फिगर्ज देने पड़ते हैं। इस तरह वे 20 या 25 दिसंबर तक यह काम कर पाते हैं। उसके बाद 14 या 15 दिन में उनको बजट पास करवाना होता है। आप यह जान कर हैरान होंगे कि व बजट तो 7 जनवरी को पास करवा के भेजते हैं लेकिन 31 मार्च या पहली अप्रैल तक कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर कन्सर्न्ड उसको पास कर के नहीं भेजता। उनको आर्डर दे दिया जाता है कि आपका बजट अंडर कंसिडरेशन है, आप अपने मुलाज़मों को तनखाह दे सकते हैं। यह सैंक्शन वहां से मिलती है। यह कितनी अजीब बात है। म्युनिसपल कमेटी एक पैसा खर्च नहीं कर सकती जब तक आडिटर की कलम न चल जाए, प्री-आडिट होता है। हर कमेटी अपना रैजोल्यूशन पास करती है। जहां 1 रुपये या 10 रुपए का खर्च होता है, वह उसको 3 दिन के अंदर अंदर डिप्टी कमिश्नर को भेजना पड़ता है। तो बजट के संबंध में ये फार्मैलिटीज़ चलती हैं। जब तक कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर उसे पास नहीं करता कमेटी खर्च नहीं कर सकती। किसी भी ढंग से इसे मुनासिब समझा जा सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं अपने मिनिस्टर साहिब से कहूँगा कि वह इन बातों की तरफ ध्यान दें यह जो गलत बातें चल रही हैं उनको दूर किया जाए।

दूसरा प्वायंट है रिसोर्सिज़ का कि म्युनिसपल कमेटियों के रिसोर्सिज़ कैसे हैं। मिनिस्टर साहिब भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जो म्युनिसिपल कमेटियों की हालत है इससे बदतर हालत तो शायद ही मेरे ख्याल में किसी जगह पर होगी। जो म्युनिसपल कमेटियां बनी हुई हैं और जिस ढंग से गवर्नमेंट उन को चला रही है उसको देख कर और भी हैरानगी होती है। पिछले दिनों जब आज़ादी मिली थी तो उसके बाद 1959 में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक लोकल फंडज़ कमेटी कायम की जिसने 1951 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उसने सुझाव दिये और महता कमेटी ने भी अपने सुझाव दिये, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी तरफ

[श्री बलरामजी दास टण्डन]
पहली गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया । अब इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि नया ऐक्ट बन रहा है ।

म्युनिसिपल कमेटियों के रिसोर्सिज के बारे में सेंटर गवर्नमेंट ने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को डाइरैक्टिव भी दिया है । लोकल फंडज़ कमेटी के चेयरमैन मिस्टर बिट्ठल थे। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको इम्पलीमेंट करें । यह 1949 की बात है। मैं मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूँगा कि वह इसको ज़रूर देखें और अपने डिपार्टमेंट से कहें कि इसको देखने की कोशिश करें । गवर्नमेंट को चाहिए कि लोकल बाडीज के रिसोर्सिज़ को बढ़ाने की कोशिश करे, उन के रिसोरसिज़ को ठीक तरह से वाईडन करने की कोशिश करें । रिसोर्सिज़ भी बढ़ाएं और इनके जो फंक्शन्ज़ हैं उनको भी डिवेल्प करने की कोशिश करें । लेकिन, चेयरमैन साहब जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल उल्ट है। (घंटी की आवाज़) चेयरमैन साहब, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ कहनी हैं इस लिये मुझे अभी और समय दिया जाए। तो मैं अर्ज़ कर रह था कि जहां तक गवर्नमैंट के प्रापर्टी टैक्स लगाने का ताल्लुक है उससे जितनी वसूली हो वह सारी की सारी कमेटियों को दी जानी चाहिए और यह गवर्नमैंट के पास न जाए जोकि इस वक्त सिर्फ पंजाब में और बम्बई के दो प्रान्तों में जा रही है । लेकिन इस सिफारिश के बावजूद हुआ यह कि गवर्नमेंट यह सारी आमदनी अपने हाथों में रखे हुए है। हमने भी यही चीज़ गवर्नमेंट को कही है कि यह सारे का सारा जितना रुपया प्रापर्टी टैक्स से गवर्नमेंट को मिलता है यह सारा म्युनिसिपल कमेटियों को मिलना चाहिए ताकि उनकी माली हालत सुधर सके। क्योंकि उनकी इस वक्त माली हालत यह है कि बहुत सारी कमेटियां पैसे न होने की वजह से आनरेरी एग्ज़ैक्टिव अफसर और आनरेरी सैक्रेटरी रखे हुए हैं क्योंकि उन के पास उनकी तनखाहें पे करने के लिये फण्डज़ नहीं होते । इस बारे में गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए। अब तक इसने इस बारे में सोचने की कोशिश ही नहीं की आखिर इनको अपने फंक्शन्ज़ पूरे करने के लिये जो पैसा चाहिए वह इन के पास कहां से आए ।

इस सरकार ने कमेटियों के रिसोरसिज़ बढ़ाए तो है नहीं बल्कि इस की तरफ से कोशिश यह की जाती है कि इनके रिसोर्सिज कट करके इन के फाईनांसिज़ को क्रिपल डाऊन कर के इनको खत्म किया जाए । आप देखें पिछली गवर्नमेंट ने आक्ट्राए को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर से हटा कर इनकी आमदनी को कम किया। मुझे इस बात में एतराज़ नहीं है कि उन्होंने यह आक्ट्राए क्यों हटाया बल्कि मुझे इस बात पर एतराज़ है कि इसने यह नहीं सोचा कि आकट्राए के हटाने से जो घाटा उन कमेटियों को पड़ने वाला है वह कहां से पूरा कर सकेंगी और उस कमी को पूरा करने के लिये हमने किसी किस्म की कोई एड उनको देने के लिये नहीं सोचा । आप देखें अगर एक कमेटी को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर लगे आक्ट्राए से अगर सालाना आमदनी 5 लाख होती थी जोकि अब हट गई है उस कमी को वह कमेटी किस तरह से पूरा करेगी । इस गवर्नमेंट ने

इस बारे में सोचा ही नहीं और खास तौर पर पिछली गवर्नमेंट ने तो कभी इस बारे में सोचने की कोशिश ही नहीं की थी। आज भी, चेयरमैन साहब क्या हो रहा है। अगर एक सैक्शन के लोग इनको आकर कहते हैं कि इस चीज़ पर बड़ा भारी टैक्स है तो यहां से फौरन हुक्म चला जाता है कि इसकी वसूली बन्द कर दी जाए। यह नहीं सोचा जाता कि इस तरह इनके हुकम कर देन से उन कमेटियों की रिसोर्सिज पर कितना असर पड़ता है। यह देखने की कोशिश ही नहीं की जाती और इसका नतीजा यह होता है कमेटियां क्रिपल हो जाती हैं और फिर वह छोटे छोटे कामों के लिये गवर्नमेंट के सामने हाथ पसारती फिरती हैं।

फिर उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि इनको अपने फंक्शनज़ बढ़ाने का मौका दिया जाए लेकिन इन्होंने बजाए इसके कि यह उनको इस तरह का कोई मौका देते इन्होंने यह फैसला किया कि जितने स्कूल पहले वह कमेटियां चला रही थीं उनको इन्होंने प्रोविंशलाईज़ कर दिया लेकिन आप देखें कि उनके साथ कितने मज़ाक की बात की गई है। उनके स्कूलों की बिल्डिंग्ज़ और बाकी फर्नीचर आदि तो अपने हाथ में ले लिया है, मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ली है और जो बच्चों से फीसें पहले कमेटियां वसूल करती थीं वह भी यह खुद वसूल कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद जो रुपया वह कमेटियां हर साल अपने स्कूलों पर खर्च करती थीं वह भी उन से लिया जा रहा है। इस बार में मिनिस्टर साहब ने जो ब्यान दिया था उस पर मुझे दुख हुआ था ऐसा मालूम होता है कि अब भी कुछ नीचे के लोग बगैर सोचे समझे सरकार को कुछ ऐसी चीजें कहने के लिये मजबूर करते हैं। मैं पूछता हूँ कि आखिर म्युनिसिपल कमेटियां करें क्या। 1957-58 में जब वह अपने स्कूल चलाती थीं तो उस वक्त वह फीसें वसूल करती थीं क्योंकि उस वक्त तो सारी क्लासों की फीसें चलती थीं। वह फीसें तो अब गवर्नमेंट ले रही है यह ठीक है—कि छोटी क्लासों की फीसें तो नहीं ली जा रहीं पर हाई स्कूलों के बच्चों से तो फीसें अब सरकार ले रही है और मज़े की बात यह है कि इसके बावजूद सरकार ने यह एक हुकम निकाल दिया हुआ है कि जितना रुपया कोई कमेटी अपने बजट में एजुकेशन के लिये रखती थी उतना रूपये वह सरकार को उसके स्कूल चलाने के लिये अब भी दे। मैं समझता हूँ कि यह म्यूनिसपल कमेटियों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। यह नाजायज़ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे यह रुपया लेना बन्द कर दे और उन से जो स्कूलों की बिल्डिंग्ज़ वगैरा इसने ली है उनकी कंपेनसेशन उनको दे ताकि उस रुपये से वह अपना काम कुछ सालों तक तो अच्छी तरह से चला सकें। (घंटी की आवाज़) चेयरमैन साहब, मैंने अभी कुछ बातें और कहनी हैं। उस कमेटी ने यह भी कहा है कि कमेटियों की रिसोर्सिज बढ़ाई जाएं ताकि वह अपने पांव पर खुद खड़ा होने के काबल हो सकें मगर यह उल्ट बातें कर रहे हैं। जहां तक एन्टरटेनमेंट टैक्स का ताल्लुक है वह सारे का सारा टैक्स लोकल बाडीज़ के एरियाज़ के अन्दर ही इकट्ठा किया जाता है। पहले तो लोकल बाडीज़ के नुमायन्दों की कान्फ्रेंस हुआ करती थी लेकिन अब इस सरकार के वक्त वह बन्द कर दी गई है। मुझे याद है कि पीछे इसी तरह की एक कान्फ्रेंस में गवर्नमेंट से यह मांग

[श्री बलरामजी दास टण्डन]

की गई थी कि एन्टरटेनमेंट टैक्स का सबस्टांशल हिस्सा वह म्युंनिसिपल कमेटियों को दे ताकि वह अपने पांव पर खड़ी होने के काबल हो सकें लेकिन हालत आज यह है कि गवर्नमेंट ऐसा करने के लिये तैयार नहीं हो रही । आप देखें कि कई म्युनिसिपल कमेटियां ऐसी हैं जिनकी सड़कों पर दिन रात वेहेकलज़ चलते रहते हैं और उनकी सड़कें तोड़ते रहत हैं लकिन उन पर जो टैक्स वसूल किया जाता है वह सारा गवर्नमेंट अपने पास रखती है। उन सड़कों को बनाने की जिम्मेवारी कमेटियों की है। गवर्नमेंट यह भी नहीं करती कि कम अज़ कम इस टैक्स का रुपया तो कमेटियों को दिया जाए ताकि वह अपने पांव पर खड़ी होने के काबल बनें । मैं सरकार की तवज्जुह इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि वह इस बारे में सोचे और उन के रिसोर्सिज बढ़ाने की कोशिश करे। लकिन हो इसके उल्ट रहा है । हो यह रहा है कि अगर कोई कमेटी सरकार से लोन लेकर अपना कोई काम करती है तो बजाए इसके कि सरकार उनको ऐसे कामों के लिये ग्रांट दे, यह लोन देती है और उस पर इस बात की पाबन्दी लगा देती है कि उसे यह सारा काम पी. डब्ल्यू. डी के ज़रिये कराना होगा । चेयरमेन साहब, आप यह सुन कर हैरान होंगे कि जिस दिन से कमेटी को लोन सेंक्शन किया जाता है उसी दिन से उससे उस लोन पर सूद शुरू हो जाता है। चेयरमेन साहब, मैं आपकी मारफत इस तरफ मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट किसी कमेटी को लोन किसी काम के लिये लोन सेंक्शन करती है तो उस पर यह कनडीशन लगा दी जाती है कि उसने यह काम पी. डब्ल्यू डी० के ज़रिये एग्ज़ीक्यूट कराना होगा और जिस दिन से वह लोन सेंक्शन करती है उसी रोज़ से उस पर इन्ट्रेस्ट शुरू हो जाता है । इसका नतीजा यह होता है कि पी. डब्ल्यू. डी. अपने डिपार्टमेंटल चारजिज़ 18 परसेंट के हिसाब से उन से ले लेता है । चारजिज़ लगने तो शुरू हो जाते हैं लकिन पी. डब्ल्यू. डी उसको तीन तीन साल तक एकाऊंट तैयार करके नहीं देता इसका नतीजा यह होता है कि उस पर दुगना तिगना खर्च पड़ जाता है । अजीब बात है यह कोई प्राईवेट काम नहीं होता जो कमेटी उन से कराती है लेकिन इस पर भी 18 परसट चारजिज़ वसूल कर लिये जाते हैं। बस जी एक मिनट में बैठ जाऊंगा ।

चेयरमैन साहिब, जहां तक कमटियों में डवेल्पमेंट के काम का ताल्लुक है यह दो तरह से चल रहा है। किसी जगह तो सिर्फ अकेली म्युनिस्पैलिटी ही काम करती है और किसी जगह पर साथ साथ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी बन हुए हैं। मगर इसकी वजह से वह पौलिटिक्स के अखाड़े भी बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्टस भी म्युनिसिपैलिटी के ही विंग होने चाहिए । अगर ऐसा कर दिया जाए तो जो आज कल डबल एंजनियर्ज, असिस्टैंट इंजनियर्ज़, एकाउंटेंट और उनका मातहत जो अमला है इस पर डबल खर्च से बचा जा सकता है । यह जो लोगों पर डबल बोझ डाला जा रहा है इसमें बच्चत हो सकती है । इसलिये मैं सजैस्ट करता हूँ कि इन इम्परूवमेंट ट्रस्ट्स को भी म्युनिसिपैलिटी का ही विंग बना दिया जाए ।

फिर चेयरमैन साहिब, डिवैलपमैंट का जो काम है और उसके लिये जो रुपया रखा जाता है वह सारे का सारा गांवों के लिये ही रखा हुआ है। जो 'बी' क्लास या 'सी' क्लास की छोटी म्युनिसिपैलिटियां हैं यह काम उन के बस का नहीं है। इसलिये मैं समझता हूँ कि उनको भी डिवैलपमेंट ब्लाक्स का हिस्सा बना दिया जाना चाहिए। इनके भी उसी तरह से ब्लाक्स बनाए जाने चाहिएं ताकि वहां पर भी डिवैलपमैंट का काम हो सके। आज यह हालत है कि सरकार की तरफ से उन कमेटियों की कोई मदद नहीं हो रही उनको कोई पूछता ही नहीं। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जो बड़ी कमेटियां हैं उनके दो ब्लाक्स और जो छोटी कमेटियां हैं उनको तीन चार और मिला कर ब्लाक बनाए जाने चाहिएं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि यह भी आगे बढ़ सकें। अगर इसके लिये ऐक्ट में तबदीली करनी ज़रूरी हो तो वह करके और अगर यह काम आर्डर के जरिए किया जा सकता हो तो आर्डर करके इस काम को करेंगे, ताकि यह कमेटियों को भी अच्छी शकल दे सकें।

श्री सागर राम गुप्ता (भिवानी): चेयरमैन साहिब, आज हम लोकल बाडीज़ की डिमांड पर बहस कर रहे हैं (विघ्न) मैं इस डिसकशन के दौरान दो चार बातें खास तौर पर रखना चाहता हूँ।

सब से पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि पंजाब में सौ के करीब म्युनिसिपैलिटी बनी हुई हैं और उनमें बहुत हद तक लेबर लैजिसलेशन बनी हुई है मगर वह इम्पलीमैंट नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर बहुत सी कमेटियों ऐसी हैं जिनमें स्वीपर्ज़ बाईलाज बने हुए हैं मगर वह उन पर नहीं चलतीं। बहुत सी ऐसी हैं जहां मिनिमम वेजिज मुकर्रर कर रखी हैं। कई किस्म के मुलाज़मों के लिय, मगर यह उनको अदा नहीं की जातीं। कई कमेटियां कानून के मुताबिक अपने मुलाज़मों को वर्दियां नहीं देतीं या दूसरी अमैनेटीज़ नहीं देतीं। कई बार यह बात उठाई गई है कि वह अपने मुलाज़मों को मुनासिब चीज़ें दें या कम से कम उन कानूनों का तो पालन करें जोकि बने हुए हैं। कई बार यह बात सरकार के नोटिस में लाई गई है, लेबर एडवाजरी बोर्ड के नोटिस में लाई गई है, लोकल बाडीज़ कान्फ्रेंस में लाई जा चुकी है मगर दुख की बात है कि इस सरकार ने इसका नोटिस नहीं लिया जोकि कहती है कि वह यहां पर सोशलिज्म लाना चाहती है, जो आनैस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन देना चाहती है मगर वह इन गरीब मुलाजमों की तरफ तवज्जुह नहीं देती। मैं अर्ज़ करूँ कि तीन चार साल पहले शिमला में एक लोकल बाडीज़ कान्फ्रेंस हुई और उसने एक युनानीमस सा ही फैसला किया कि जो म्युनिसिपैलिटियां इस हालत में हो कि अपने मुलाजमों को ग्रैचुटी स्कीम दे सकती हो वह इस मतलब का अगर रैज़ोल्यूशन पास करें और सरकार के पास भेजें तो सरकार उसको मन्जूर कर लेगी और उस कमेटी के मुलाज़मों को यह स्कीम मिल जायेगी। मगर दुःख से कहना पड़ता है कि कई कमेटियों ने ऐसे रैज़ोल्यूशन पास करके भेजे मगर सरकार ने उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की।

[श्री सागर राम गुप्ता]

यही नहीं बल्कि कई झगड़े होते हैं एम्प्लाइज़ के, डिमांड नोटिस होते हैं, कनसलटेशन वगरह होती है मगर म्युनिसिपैलिटी नहीं मानती तो वह झगड़ा सरकार के पास लेबर डिपार्टमेंट के पास जाता है मगर लोकल सैल्फ डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं वह लेबर डिपार्टमेंट को उस डिसप्यूट को फैसले के लिये ट्रिब्यूनल को सौंपने नहीं देते बल्कि इन झगड़ों को सुलझाने के रास्ते में एक बड़ी भारी दीवार बन कर खड़े हो जाते हैं और मज़दूरों बेचारों की सुनवाई नहीं होती । यह ठीक है कि अगर सरकार का कोई महकमा किसी बात को न माने तो दूसरा उसको मनवा लेता है लेकिन अगर किसी जायज़ बात और लीगल बात के रास्ते में कोई लोकल सैल्फ डिपार्टमेंट का आदमी रुकावट डाले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए और अगर कोई ऐसा अफसर है जो गरीब मजदूरों के हक छीनता है तो लेबर डिपार्टमेंट को इस बात का हक होना चाहिए कि वह उसका चालान कर सके । उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सके । मैं भिवानी का जिक्र करता हूँ । चैयरममैन साहिब, भिवानी म्युनिसिपैलिटी के चुनाव को तीन साल का अर्सा हो चुका है मगर दुख की बात है कि अभी तक नई कांस्टीचुएंसीज़ जो बननी हैं उसका ड्राफ्ट इस सरकार ने पब्लिश नहीं किया । कब ड्राफ्ट पब्लिश होगा कब औबजैक्शन्ज़ मांगी जायेंगी और कब इलैक्शन्ज़ का इन्तजाम किया जायगा शायद सरकार यह चाहती है कि वह म्यूनिसिपलिटी इसी तरह से वहां पर चलती रहे और आयंदा पांच साल तक चुनाव न कराये जाएं वरना अगर ऐसी बात न होती तो बहुत सी म्युनिसपैलिटीज़ के हलके गज़ट भी हो चुके हैं मगर भिवानी के नहीं किये गए । मैं सरकार से दरखास्त करूँगा कि वह इस बारे में फौरी कार्यवाही करे । जहां तक मुझे मालूम हुआ है जो अड़चन इसके रास्ते में आ रही है वह उन फैक्टरी ओनर्ज़ की तरफ से हैं जो वहां पर फैक्टरीज़ लगाए बैठे हैं । अगर यह बात है तो यह मेरे लिये और सरकार के लिये बायसे शर्म है कि हम कुछ पूंजीपतियों की वजह से रीडीमार्किकेशन नहीं कर रहे । यह गलत बात होगी । हम तो यहां पर सोशलिज्म लाना चाहते हैं, मजदूरों और गरीबों की बात को सुनना चाहते हैं । मैं चाहूँगा कि सरकार वहां पर इस बारे में जल्दी ही इन्तज़ाम करे ।

चेयरमैन साहिब, वहां पर अभी हाल ही में एक वाका हुआ । यहां पर म्युनिसिपैलिटी द्वारा हाउस टैक्स लागू करने का जिक्र आया । जनाब सन् 1956 में गज़ट में एक नोटीफिकेशन छापी गई और उसके मुताबिक भिवानी के शहरियों से हाउस टैक्स लेने की बात की । वहां के शहरियों ने उसकी मुखालिफत की । लोगों ने टैक्स न दिया । कमेटी भी बैठी रही, उसने कोई कार्यवाही न की कुछ नोटिस भेजे भी तो कमेटी के खिलाफ मुकदमे चले और उनमें खास तौर पर मिलों वालों और एक आध ट्रस्ट वालों की जीत हुई । कमेटी ने उन फैसलों के खिलाफ अपील भी नहीं की । अब 8–10 साल के बाद सरकार म्युनिसिपैलिटी को मजबूर कर रही है

सारा का सारा पुराना हाउस टैक्स शहरियों से वसूल किया जाए । तो वहां के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से बात की आज से साल भर पहले तो आपस में यह समझौता हुआ कि आठ दस साल के हाउस टैक्स के एरियर्ज़ हैं उनमें से पिछले तीन चार साल का ही लिया जाए बाकी तीन चार साल का छोड़ दिया जाए । कुछ लोगों ने इसके मुताबिक टैक्स अदा भी किया मगर इसके बावजूद सरकार सारे पुराने टैक्स वसूल करने की कोशिश कर रही है और इसके लिये शहरियों की कुरकियां कर रही है । तो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर से फिर मिले और उन से कहा कि यह समझौता हुआ था पिछले साल, कि यह फेमिन रिडन इलाका है, लोग गरीब हैं बैकवर्ड हैं । फिर अगर कमेटी ने टैक्स लोगों से वसूल निहीं किया तो यह कसूर कमेटी का है शहरियों का नहीं है । उसने साल बसाल क्यों नहीं वसूली की और उसकी गलती का खम्याज़ा शहरियों पर नहीं डालना चाहिए । मैं यह सरकार के नोटस में लाना चाहता था और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से लोगों को दबाने की कोशिश नहीं करना चाहिए । हम आज डैमोक्रेसी के दौर से गुज़र रहे हैं इस लिये लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए । अगर हम इन हालत में लोगों की आवाज़ को नहीं सुनते तो इसके नताइज बहुत बुरे हो सकते हैं । अगर पिछले आठ दस साल के अन्दर कमेटियों में कुछ गलतियां हुई हैं या उन से कोई लैपसिज़ हो गए हैं तो उनका खम्याज़ा गरीब शहरियों पर नहीं पड़ना चाहिए ।

चेयरमैन साहिब मैं एक बात इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में करना चाहता हूँ । यह बात मानी हुई है कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ठीक काम नहीं कर रहे हैं । और इन पर हर साल लाखों रुपया ज़ाया किया जा रहा है । मैं यह नहीं कहता कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को कायम करने का या इन्हें बनाने का या चलाने का मुद्दा गलत है । मुद्दा तो मुनासिब है लेकिन जिस ढंग से इस की वरकिंग चल रही है या जिस ढंग से इनको बनाया जा रहा है, जिस ढंग से इन ट्रस्टों के चेयरमैन और मैम्बर नामीनेट किए जा रहे हैं वह गलत है और इससे कतई कामयाबी नहीं होने वाली । मैं समझता हूं कि जो लाखों रुपये इस पर खर्च किया जा रहा है वह ज़ाया हो रहा है । भिवानी के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को बने चार पांच साल हो गए हैं लेकिन भिवानी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट का काम नहीं किया गया । लाखों रुपया वक्त पर नोटिस देने और सर्वे करने में खर्च हो जाता है । इसका कोई फायदा शहर को नहीं हो रहा है । फिर दिक्कत की बात यह है कि सरकार ऐसे लोगों को चेयरमैन बना देती है जिन के पास कोई भी क्वालीफिकेशन न हो । मैंने पिछली दफा भी सरकार की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाई थी । इस हलका का मैम्बर होने के नाते मैंने सरकार के सामने इस बात को रखा था कि इस सरकार का न तो कोई असूल है और न कोई रूल और न ही कोई और लिहाज़ नजर आता है जिसकी वजह से भिवानी इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैन को नामीनेट किया गया हो ।

[श्री सागर राम गुप्ता]

जहां तक उनकी कुआलीफिकेशन्ज़ का ताल्लुक है उन की इतनी ही कुआलीफिकेशनज़ हैं कि पिछली बार उन्हें कांग्रेस टिकट न दिया गया तो वह कांग्रेसी उम्मीदवार के खिलाफ इलैक्शन लड़े थे और हार गए थे। इसके इलावा जो कुआलीफिकेशन्ज़ सरकार ने बना रखी ह और जो होनी चाहिएं वह इनमें नहीं हैं। हालांकि कोई काबल इन्जीनियर चेयरमैन होना चाहिएं। इसके इलावा जहां तक तजुरबे का तअल्लुक है उनका तजुरबा इतना है कि वह दो दफा म्युनिस्पल कमेटी के मैम्बर बने। एक बार तो नो कानफीडेन्स वोट पास करवा कर निकाल दिये गए और दूसरी बार उनके खिलाफ मुज़ाहरे हुए और वह खुद ही भाग गए। मुझे दुख है कि हमारी सरकार किस तरह के आदमी चेयरमैन मुकर्रर करती है। मैं खुद भी कांग्रेस में हूँ और मुझे इस तरह की हालत देख कर शर्म आती है कि ऐसे शख्स को जो खुल्लमखुल्ला कांग्रेस उम्मीदवार को गालियां देता रहा हो और कांग्रेस पार्टी को गाली देता हो। कांग्रेस के असूलों को तोड़ता हो और जो पार्टी का प्लन हो उसको तोड़े उसे आप चेयरमैन बना दें और तीन एम. एल. एज़, जितनी तनखाह देनी शुरू कर दें। मैंने अपनी बजट स्पीच में भी इस बात का जिक्र किया था। सरकार ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को नेशनेलाइज़ करने के लिये कुआलीफिकेशन्ज़ ले डाऊन की हुई हैं और यह कुआलीफिकेशन्ज़ सरकार ले डाऊन करती है लेकिन इसके बावजूद मैट्रिक आदमी को चेयरमैन मुकर्रर कर देना और हजारों रुपया उस पर खर्च कर देना हमारी समझ से बाहर है (विघ्न)

मैं तो इस बात की मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को कैसे रन किया जा रहा है। इस तरह के बिना किसी कुआलीफिकेशन्ज़ के इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों के चेयरमैन लगाने से तो अच्छा होगा कि हम इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों को बंद कर दें और डिवैलपमेन्ट का सारा काम म्यूनिस्पल कमेटियों को ही दे दें। इन अलफाज़ के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ (ਹਰਿਆਣਾ ਐਸ. ਸੀ.) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, 3,49,68,111 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬੜੇ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਧਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਪਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਢੇ ਸਤਾਨਵੇ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਰਹਾਨਾ ਯੋਗ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ $97\frac{1}{2}$ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਵੀਪਰ 9 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਰ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ

ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ । ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੰਜ ਛੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਆਪ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ $97\frac{1}{2}$ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ । ਉਸ ਲਈ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਪਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ $97\frac{1}{2}$ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਵਲ 70 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਵਾਕਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਟਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਨੂੰ ਸਵੀਪਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਉ, ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਵੀਪਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ । ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਫਲਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੀਂ ਕਲਰਕ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਵੀਪਰ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਵੀਪਰ ਇਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ 300 ਜਾਂ 400 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਉਲਟਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਮਾਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਵੀਪਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਦੂਸਰੇ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ $97\frac{1}{2}$ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 40 ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣਾ।

ਸਵੀਪਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੁਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ 10 ਆਦਮੀ

[ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ]
ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 20-25 ਆਦਮੀ ਐਕਸਟਰਾ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕਤ ਪੈਣ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਅੱਜ ਇਕ ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ 97½ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ੮ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇ । ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤਕ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਅੱਧ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ 10-15 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਪਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਧ-ਬੁਧ ਲੈ ਸਕਣ ।

(At this stage Deputy Speaker occupied the Chair.)

ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 97½ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਗਵਾੜੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਚਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਛੁਟੀ ਮਿਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਇਜ਼ਤ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਵਡਿਆਂ ਵਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਲ ਅਟੈਂਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਨੀਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵੀਪਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 97½ ਤੋਂ ਘਟ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਹਰੀਜਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 220 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਪਰ ਅੱਜ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ । ਜੇਕਰ ਹਰੀਜਨ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ

ਦੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨਤ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਕੁਝ ਸਿਖਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ । ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਕ ਕੁਕੜਾਂ ਦਾ ਖੁਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੌਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ, 10ਵੀਂ ਤਕ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਫਰੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਹੋਰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਔਰ ਸਵੀਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜਦ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੰਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (Interruption) ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਆਨੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ 50-2-60 2-80 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਲਾਸ 4 ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 60,000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ । ਉਥੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੁਰਿੰਡਾ--ਐਸ. ਸੀ.) : ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਜਿਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ।

ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਡਨ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕ-ਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ । ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਜੁਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਜਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਵਿਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਉਂਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ...

उपाध्यक्षा : आप अम्बाले का जिक्र कीजिए ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਾ ਮਾਰੇ । ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਅਕਾਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਗਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਮਿਉਂਨਿਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਉਨਵਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਪਾਵਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰ ਸਕੇ ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਉਂਨਿਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜ ਵਿਚ 12 ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਉਥੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਰਪਲਸ ਹੈ । ਜਦ ਉਥੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਖੁਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹਨ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਉਂਨਿਸਪੈਲਟੀ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਉ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਮਿਉਂਨਿਸਪੈਲਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਉਂਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਡੂਲ ਕਾਸਟ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਊਂਨੀਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ । ਮਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਮਿਊਂਨੀਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਏਥੇ 10% ਰਿਜ਼ਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

(The hon. member was still on his legs when the House adjourned.)

1.00 p.m.

Deputy Speaker : The House stands adjourned till 2.00 P.M. to-day for the second sitting.

(The Sabha then adjourned till 2.00 P.M. on Thursday,the 25th March, 1965.)

1391 PVS—366—21-8-65—C. P. and S. Pb., Patiala

APPENDIX

to

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I, NO. 21

Dated the 25th March, 1965 (*Morning Sitting*)

Water Rates in Sangrur, Bhatinda, Ludhiana, Rohtak and Amritsar Canal Divisions..

2519. Comrade Jangir Singh Joga : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to State —

(a) the rate of canal water per thousand acres in the Canal Divisions of Sangrur, Bhatinda, Ludhiana, Rohtak and Amritsar;

(b) if the rate is different in the above-mentioned divisions, the reasons therefor;

(c) whether the Government proposes to make applicable a uniform rate, throughout the State ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) The rate of Canal Water (Water Allowance) per thousand acres in the Canal Divisions of Sangrur, Bhatinda, Ludhiana, Rohtak and Amritsar is as follows :—

Name of Divisions :

(1) Sangrur Division perennial area north east of straight line joining Ferozepur Jakhal 2.04cs.	Rate of Canal water per thousand acres. Perennial areas South West of Straight line joining Ferozepur Jakhal 2.4 cs.
(2) Bhatinda Division ..	Rate of Canal water per thousand **Acres at Outlet head.** Non-Perennial area 2.125cs. Perennial area south west of Straight Line joining Ferozepur-Jakhal 2.40 cs. Perennial area North-East of St. Line joining Ferozepur-Jakhal 2.04 cs.
(3) Ludhiana Division. ..	Non-perennial area 2.125 cs. Perennial areas 2.04 cs.
(4) Rohtak Division. ..	2.4 cs except on Butana and Gangesar distributaries where it is 3.01 and 2.86.

(5) Amritsar Division .. 3.5 cs. except Jathowal Disty : Where it is 6cs. This Disty irrigates Urban Areas of Amritsar City.

(b) The rate of canal water per thousand acre is different in different divisions as it depends on the actual requirements of each tract as well as on the crop pattern of each tract. It also depends upon supplies available, climate, rainfall and sub-soil water level.

(c) There is no such proposal to make applicable a uniform rate throughout the State. However the question of rationalising the water allowance in different areas is under consideration.

Punjab Vidhan Sabha

Debates

25th March, 1965

(Afternoon Sitting)

Vol. I—No. 22

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thurdsay, the 25th March, 1965

Rs. 4.20

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 25th March, 1965
(Afternoon Sitting)

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan Sector 1, Chandigarh at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 7472

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜ਼ ਡੀਲ ਵਿਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਔਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री : जहां जिस जमीन पर हरिजन आबाद हैं वहां तो फिक्सड रेट पर दी जाती है दूसरी जगह ओपन आकशन में बिकती है । उस में कीमत कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है ।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि पंजाब सरकार का यह जो फैसला था कि यह जमीन जो पैकेज डील में हिन्द सरकार से कम कीमत पर मिली है जिसके आकशन में ज्यादा पैसे मिलते हैं उसका जो हिन्द सरकार को कीमत देने का और आकशन में कीमत वसूल करने का फर्क निकलेगा या मुनाफा होगा उसे हरिजन कल्याण फंड में शामिल किया जाएगा उस पर कितना अमल हुआ है और कितना ऐसा रुपया उस फंड में शामिल हुआ है ?

मन्त्री : जहां तक मुझे मालूम है गवर्नमैंट का यह फैसला था कि एक करोड़ 14 लाख रुपया इस में से हरिजन कल्याण फंड में डाला जाए और उस पर गवर्नमैंट पूरी तरह पाबन्द है ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 450 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਭਾਉ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 450 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ?

मन्त्री : इस के लिए सैपेरेट नोटिस दें इस वक्त कुछ नहीं कह सकता ।

श्री अमर सिंह : पार्ट ए के जवाब में बताया गया है कि हरिजनों का इकनौमिक और सोशल स्टेटस ऊंचा करने के लिए टैम्परेरी टैक्सेशन ऐक्ट के ज़रिए दो करोड़ रुपया दिया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि उन में से पहले पैसा लेकर फिर उन को कर्ज़ की शकल में वापस देकर उनका इकनौमक और सोशल स्टेटस कैसे ऊंचा हो जाएगा ?

मन्त्री : जब यह रुपया उनके कल्याण के लिये खर्च होगा तो तरक्की तो होनी ही है । इस में कौन सी रुकावट है ।

***Note*:** Starred Question No. 7472 alongwith its reply appears in the P. V. S. debate Vol 1 No. 21 dated the 25th March, 1965 (Morning Sitting)

ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਰਤਨ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਉ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਉਸੇ ਭਾਉ ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ?

मन्त्री : इस में दिक्कत यह है कि अलाटमैंट किस को की जाए और किसे न की जाए। पिक ऐंड चूज़ करने में दिक्कत होगी। अगर ए सिलैक्ट करते हैं तो बी. सी नाराज़ हो जाएंगे और एतराज़ होगा कि उसे क्यों सिलैक्ट किया गया है। इस लिए यही बेहतर समझा कि हरिजनों के लिए ओपन आकशन कर दी जाए ताकि जो बिड दे वह ले ले और फेवरिटिज़म की बात किसी को कहने की गुंजाइश न हो।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਰਾਈਸ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਸਕੀਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 8-10 ਆਦਮੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : This is no point of order.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇਸੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

मन्त्री : सब कमेटी ज़रूर बनी थी और उसने कुछ सिफारिशात भी की थीं जो मुझे इस वक्त जबानी याद नहीं हैं लेकिन जहां तक मुझे याद है कुछ सिफारिशात पर कैबिनट में गौर हुआ ; कुछ मान ली हैं, कुछ नहीं मानी हैं।

ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ : ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

Mr. Speaker : This has already been replied to.

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जब यह ज़मीन सैंटर से सस्ते भाव पर ली गई तो उस वक्त यह आरगूमैंट दी गई थी कि अगर यह ज़मीन सस्ते भाव पर मिले तो इस से पंजाब के हरिजनों को आबाद करने में मदद मिलेगी और क्या गवर्नमैंट उस वायदा पर कायम है या नहीं ?

मन्त्री: हरिजनों को रीहैबलीटेट करने का उस वक्त सवाल नहीं था। उस वक्त सवाल यह था कि चूंकि पंजाब का पार्टीशन की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है इस लिये कुछ मुआवज़े के तौर पर उसे दिया जाए।

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰੀਜਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

मन्त्री : यह जो हरिजन कल्याण फंड कायम किया है इसमें से विचार कर रहे हैं कि मुजारों को ऐसी जमीनें खरीदने के लिए अगर कुछ दिया जा सकता है तो दें लेकिन यह अभी विचाराधीन है; फाईनल बात कोई नहीं है ।

चौधरी रण सिंह : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जब से सिर्फ हरिजनों के लिये ही आकशन शुरू हुई है उस के बाद पहले की निस्बत रेट बढ़ गए हैं । और अगर बढ़ गए हैं तो इसकी क्या वजह है ?

मन्त्री : इस के लिए सैपेरेट नोटिस दें ।

श्री जगन्नाथ : इस में कुछ ऐसी इवैकुई लैंड है जिस पर बोगस अलाटी बैठे थे और अब उन के नाम से अलाटमैंट कैंसल हो गई है और जमीन खाली हो गई हैं । सरकार इस अच्छी जमीन को तो नीलाम नहीं कर रही है लेकिन इन्फीरियर लैंड को ही कर रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस अच्छी जमीन को भी जिसकी अलाटमैंट कैंसल हो चुकी है, सरकार हरिजनों को नीलाम करने के लिए तैयार है ?

Mr. Speaker : Next question by Shri Roop Lal Mehta.

Voices : On a point of Order, Sir.

Mr. Speaker : No, I will not allow any points of Order on this question.

Next question by Shri Roop Lal Mehta please.

(Question No. *7230 not put)

Voices : On a point of Order.

Mr. Speaker : No please.

(*Noise and interruptions*)

Mr. Speaker : Next question by Shri Surinder Nath Gautam please.

(*Noise and interruptions*)

Mr. Speaker : Next question please. If the hon. Members do not put their questions I will go on to the next question.

Shri Surinder Nath Gautam : Question No. 7364, Sir.

Voices : We want more supplementaries on starred Question No. 7472.

Mr. Speaker : Order, please. I will not allow further supplementaries on this question.

श्री अमर सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहिब यह सवाल हरिजनों के साथ संबंध रखता है इसलिए इस सवाल पर और सप्लीमैंटरी करने की इजाजत दी जानी चाहिए ।

(*Noise and interruptions*)

Mr. Speaker : Order please, order. No further supplementaries on this question will be allowed.

Voices : On a point of Order, Sir.

Mr. Speaker : I will not allow any point of Order on this question.

Babu Ajit Kumar : On a point of Order, Mr. Speaker.

Mr. Speaker : The hon. Member is obstructing the proceedings of the House.

Babu Ajit Kumar : No, I am not obstructing.

(*At this stage Sardar Ajaib Singh Sandhu rose on a point of Order*)

Mr. Speaker : I am sorry, I will not allow any point of Order to be raised relating to this question. I will not allow any more supplementaries on this question as I have already allowed a sufficient number of supplementaries.

(*Interruptions and Noise*)

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय यह जमीन एक्वायर की गई थी तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर सरदार प्रताप सिंह कैरों ने एक एलान किया था कि अगर यह ज़मीन साढ़े चार सौ रुपये से ज़्यादा पर बेची जाएगी तो उस से ऊपर का सारा रूपया कल्याण फंडज में शामल किया जाएगा ?

मन्त्री: इस के लिये सैपेरेट नोटिस दिया जाए। पता करके बताया जा सकता है।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 16939 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਹੈ 9077 ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 3633 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। 8304 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1969 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 39777 ਏਕੜ ਕਲਟੀਵੇਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ; ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 445 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। 53758 ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ। 90.886 ਏਕੜ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਾਈਸ 100 ਰੁਪਏ ਰਖੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 28649 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ?

मन्त्री : इस के बारे में रूपये का प्रबन्ध करेंगे। कुछ तो अपने पास से देंगे और कुछ रिज़र्व बैंक से कर्ज़े के रूप में लेंगे।

(शोर और विघ्न)

(इस वक्त बहुत से आनरेबल मैंबर प्वायंट आफ आर्डर्ज़ रेज़ करने के लिये खड़े हुए। सदन में बहुत शोर था)

श्री अमर सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, यह बहुत ही अहम सवाल है। इस में 10 करोड़ रूपये की अमाउंट इन्वाल्वड है। इस लिये मैं चाहता हूं कि आप इस पर और सप्लीमेंटरी करने की इजाज़त दें। अगर आप सप्लीमेंटरी करने की इजाज़त नहीं देना चाहते तो इस सवाल के लिये हाफ एन आवर डिस्कशन करने के लिए इजाज़त दें।

(शोर) (विघ्न)

Minister for Education and Local Government : Sir, if the Chair is pleased, the Government will have no objection to have half-an-hour discussion on this question.

Mr. Speaker : If a request is made in writing in accordance with the Rules, I will allow half-an-hour discussion on this question (*7472).

इन को मालूम नहीं कि हाफ एन आवर डिस्कशन में केवल एक आदमी ही बोल सकता है ।
(If a request is made in writing in accordance with the Rules, I will allow half-an-hour discussion on this question (*7472). They do not know that during half-an-hour discussion only one hon. Member can speak.)

Retrenchment of workers in Bhakra Dam Administration

*7364. **Shri Surinder Nath Gautam :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total number of workers retrenched upto 31st January, 1965 in the Bhakra Dam Administration, with details thereof, category-wise ;

(b) whether all the retrenched workers referred to in part (a) above have been provided with alternative jobs on the other projects ; if so, the details of such workers, category-wise upto date together with the names of the projects where they have been absorbed :

(c) whether there is any likelihood of further retrenchment of workers in the Bhakra Dam Administration in 1965 ;

(d) if the answer to part (c) above be in the affirmative, the number of workers likely to be retrenched category-wise, and the details of the schemes, if any formulated to provide alternative jobs to such workers on other projects ?

Chaudhry Rizaq Ram : I beg to lay a statement on the Table of the House.

STATEMENT

(a) 487 workmen were retrenched by the Bhakra Dam Administration from January, 1964 to 31st January, 1965 as per details given below :—

Superivsory staff	..	98
Skilled staff		356
Semi-skilled staff	..	14
Un-skilled staff	..	19
Total	..	487

(b) Out of the 487 retrenched workmen, 160 workmen were absorbed at Beas Project, Beas Sutlej Link, Hydel Uhl Project, Punjab State Electricity Board, and within the Bhakra Dam Administration as per detsails given below :—

Supervisory staff	..	15
Skilled staff	..	123
Semi skilled staff	..	3
Un-skilled staff		19
Total	..	160

(c) Yes.

(d) The workmen detailed below are likely to be reduced during the year 1965 :—

Supervisory staff	..	109
Skilled staff	..	575
Semi-skilled staff	..	100
Un-skilled staff	..	278
Total		1.062

[Public Works And Welfare Minister]

Following procedure is followed in the deployment of surplus workmen :—

(i) Lists of surplus workmen are prepared about three months in advance and circulated to all the Projects under construction and other prospective employers.

(ii) All the vacancies on the Beas Dam Project that can be filled with surplus workmen of Bhakra are offered to senior most workmen of Bhakra ;

(iii) Such workmen as are not absorbed at Beas Project and Uhl Project, are retrenhced and are requested to register themselves with the local Employment Exchange at Nangal.

(iv) Efforts for employment of retrenched workmen continue and they are offered jobs on other projects, officers of other projects are invited to come to Nangal and interview and recruit retrenched workmen.

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : मंत्री महोदय ने बताया है कि 31 जनवरी, 1965 तक 487 आदमी रीट्रैंच किए गए और उन में से 160 को आल्टरनेटिव जाब्ज़ प्रोवाइड की हैं। बाकी 233 वर्कर्ज़ रह गए हैं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन का सरकार क्या सोच रही है ?

Minister : Out of 487 workmen retrenched, 18 were absorbed by the Ram Ganga Project in U.P. and 2 by the National Projects Construction Corporation. 302 got their names registered in the local Employment Exchange.

The postion regarding those persons who got their names registered with the Employment Exchange is as under :—

No. of persons who secured employment through the Employment Exchange	..	6
No. of persons who intimated subsequently that they did not need jobs	..	54
No. of persons who failed to report to the Employment Exchange when called for employment	..	129
No. of persons who declined offers of appointment	..	37
No. of persons who still required to be employed	..	76

All out efforts are being made by this Administration to secure alternative employment to the surplus hands before their actual retrenchment.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब माननीय सदस्य ने तो पूछा है कि जिन लोगों को अभी तक आल्टरनेटिव जाब्ज़ नहीं दी गईं उनका क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री बनवारी लाल : क्या मन्त्री महोदय कृपया बताएंगे कि रीट्रैंच्ड वर्कर्ज़ में कितने हरिजन हैं और कितने नान-हरिजन हैं ?

मन्त्री : इस के लिए सैपेरेट नोटिस दिया जाए।

(श्री बनवारी लाल ने 'आन ए प्वायंट आफ आर्डर', —— बहुत ही जोर से कहा और सदन में शोर हो गया)

श्री अध्यक्ष : इन को ऊंचा बोलने की इजाज़त है ताकि इन्हें अपना प्वायंट आफ आर्डर रेज़ करने का मौका मिल सके। (हंसी) (The hon. Member is allowed to speak loudly so that he may get an opportunity of raising his point of order.) (Laughter)

श्री बनवारी लाल : आन ए प्वाएंट आफ आर्डर, सर। जिस वक्त वर्कर्ज़ की छंटनी की जाती है क्या उस वक्त सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि हरिजनों को रीट्रेंच न किया जाए क्योंकि उन की 21 प्रतिशत संख्या पूरी नहीं हुई है ? वह किस तरह से छंटनी करते हैं ?

Mr. Speaker : Not allowed.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री: मैं मन्त्री साहिब से जानना चाहता हूं कि जितने वर्कर्ज़ रीट्रेंच किये गए हैं उन को रीट्रेंचमैंट बैनिफिट दिया गया है या नहीं। अगर उन को कहीं दूसरी जगह पर ऐम्पलाए किया गया है तो क्या उन की पहली सर्विस काऊंट की गई है या नहीं ?

मन्त्री : रीट्रेंचमैंट बैनिफिट देने के बारे में रूज़ हैं। लेकिन अगर स्पैसिफिकली पूछा जाएगा तो मालूम कर लिया जाएगा। लेकिन अंदाज़ा यह है कि न देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दो तीन कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिन को अगर रीड्यूस किया जाए तो पहली सर्विस उन की कांउट की जाती है। रीडक्शन के वक्त तो सर्विस कांउट की जाती है लेकिन रीट्रेंचमेंट के बारे में नहीं कह सकता।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : वज़ीर साहबि ने फरमाया है कि 31 जनवरी, 1965 तक 487 आदमी भाखड़ा डैम से निकाले गए थे और उन में से 160 को मुख्तलिफ जगहों पर जाब दे दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी जो कि अभी बेकार फिर रहे हैं उन का क्या बना है ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जो जवाब देना था वह दे दिया है। (The hon. Minister has already stated whatever he had to say.)

श्री मंगल सेन : क्या मन्त्री महोदय फरमाएंगे कि कुछ और भी कारीगरों को/कर्मचारियों को वह निकालने जा रहे हैं या बेकार करने जा रहे हैं ?

मन्त्री : इस में बेकारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग ऐम्पलाए किये गए थे ज्यों ज्यों काम खत्म हो रहा है उन को जवाब तो मजबूरन देना ही पड़ेगा। वरना खर्चा कैसे पूरा होगा। जिन को निकालना होता है उन को तीन महीने पहले इत्तलाह दी जाती है। और कई जगहों पर भी ऐसे ही काम हैं अगर हो सके तो उन को वहां पर एबज़ार्ब कर लिया जाता है वरना ऐम्पलाएमैंट एक्सचेंज की मार्फत उन को नौकरी दिलवा दी जाती है।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री: जिन वर्कर्ज़ को रीट्रेंच किया गया और जिन को कोई आलटर्नेटिव जाब्ज़ नहीं दी गई क्या उन के पास रहने के लिये क्वार्टर्ज़ भी रहने दिये हैं या कि उन को बाहर निकाल दिया गया है ?

मन्त्री : आप अलग नोटिस दें।

Chaudhri Darshan Singh : Sir, the number of skilled and un-skilled workers retrenched is 356 and 14 respectively. May I know from the Hon. Minister why skilled workers have been retrenched instead of un-skilled and semi-skilled ?

मन्त्री : चूंकि उन की जरूरत नहीं रही थी इस लिये उन को हटा दिया गया है।

श्री मंगल सेन : मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि कई लोगों को ऐम्पलाएमैंट ऐक्सचेंज के द्वारा नौकरी दिलवा देते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उस हालत में उन की पहली सर्विस कांउट की जाती है या कि नहीं ?

मन्त्री : मैं ने श्री अग्निहोत्री के सवाल का जवाब दिया था कि मेरा ख्याल है कि जो रीडक्शन में आते हैं उन की सर्विस कांउट की जाती है और जो रीट्रैंच किये जाते हैं शायद उन की सर्विस कांउट नहीं की जाती।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम: मन्त्री साहिब ने उत्तर में लिख कर दिया है कि 1965 में 1,062 आदमी और रीट्रैंच किये जाएंगे। अगर उन को दूसरे डैम पर जगह नहीं मिलेगी तो उन को अपना नाम ऐम्पलाएमैंट ऐक्सचेंज में दर्ज करवाना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि अगर वह अपना नाम ऐम्पलाएमेंट ऐक्सचेंज में दर्ज करवाएंगे तो क्या उन को दूसरे प्रोजैक्टस पर प्रेफ्रेंस दी जाएगी ?

मन्त्री : हम नें यह बात सैटल की हुई है कि उन को प्रेफ्रेंस दी जाएगी। ट्रांस्पोर्ट और दूसरे डिपार्टमैंट्स के साथ यह बात तय पाई हुई है कि ऐसे वर्कर्ज़ को प्रेफ्रेंस दी जाए। जो आदमी कन्डक्टर्ज़ के तौर पर या ड्राईवर्ज़ के तौर पर या मकेनिक्स के तौर पर एबजार्ब हो सकते हों तो उन को प्रेफ्रेंस दी जाए, इस के बारे में गवर्नमैंट ने पहले से ही फैसला किया हुआ है।

Electrification of Villages in Una Block, district Hoshiarpur

***7523. Shri Surinder Nath Gautam :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the names of villages in Una Block, district Hoshiarpur which are proposed to be electrified in the year 1965 ?

Chaudhri Rizaq Ram : Programme for electrification of villages for the year 1965-66 has not been prepared, due to paucity of funds. It is not possible to indicate the names of villages proposed to be electrified in Una Block during 1965.

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि फंड न होने की वजह से ऊना ब्लाक में गांव को बिजली देने के लिये प्रोग्राम तैयार नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमैंट की पालिसी के पेशेनज़र कि हिली एरियाज़ को बिजली देने के लिये तरजीह दी जाएगी, बैकवर्ड होने की वजह से, इस करेंट इयर में उन को बिजली देने के लिये कोई पासिबिलीटी है ?

मन्त्री: कई बार तो प्रैफ्रेंस दी जाती है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि एग्रीकलचरल प्रोडक्शन में इज़ाफा किया जाए वहां तो प्रैफ्रेंस दी जाती है। जहां पर इस बात का इमकान न हो वहां पर रुटीन में ही काम होता है।

Opening new Electricity Sub-Division in Tehsil Una, district Hoshiarpur

***7524. Shri Surinder Nath Gautam :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Punjab State Electricity Board for opening a new Electricity Sub-Division in tehsil Una, district Hoshiarpur ; if so, the number and names of villages likely to be served by it ;

(b) the time by which the said proposal is likely to be implemented ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes. A statement of the villages to be included in the Sub-Division is laid on the Table of the House.

(b) The proposal is under consideration of the Board and if found justified, will be implemented as early as possible.

List of villages to be included in the Proposed Sub-Division

1. Dalwan.
2. Baheri.
3. Diara.
4. Seri.
5. Hoboli.
6. Satothai.
7. Bahera.
8. Saluri.
9. Duhosara.
10. Chandwa.
11. Bhaloh.
12. Gandhowal.
13. Batuni.
14. Dhawara.
15. Barera.
16. Satieta.
17. Panon.
18. Badoli.
19. Tiuri.
20. Badsala.
21. Salangri.
22. Sajhot.
23. Nangala.
24. Chalola.
25. Dadial.
26. Basal.
27. Surchara.
28. Jhambar.
29. Taka (covered under Sub-electrified project)
30. Kuriala
31. Raisiri.
32. Dhalera.
33. Dangera.
34. Samurkalan (covered under electrified project).
35. Kotlakhurd (covered under electrified project).
36. Barnoh (covered under electrified project).
37. Dangoli (covered under electrified project).
38. Ajonoli (covered under Porject).
39. Kotlan Kalan (electrified).
40. Arniala (electrified).
41. Lansinghi (electrified).
42. Lamblehri (electrified).
43. Una (electrified).
44. Rampur (covered under project)
45. Malahat (electrified).
46. Madanpur.
47. Basoli (covered under project).
48. Chutara (covered under project).
49. Tabu (electrified).
50. Bharalian (Una) (electrified).
51. Katharkhurd.
52. Katharkalan.
53. Abadawairon.
54. Sunehra.
55. Babsara.
56. Jankaur.
57. Bharolian (electrified).
58. Behdala (electrified).
59. Delan (electrified).
60. Lamhera (covered under project).
61. Sasan (covered under project).
62. Nangrain (covered under project).
63. Raipur (electrified).
64. Bangarh.
65. Jakhera (electrified).
66. Mathpur (covered).
67. Udepur (covered).
68. Bhotoli (electrified).
69. Babhaur (electrified).
70. Kalsera (electrified).
71. Barori (electrified).
72. Bans (covered).
73. Kathera.

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : जो स्टेटमेंट वज़ीर साहिब ने दिया है उस में कुछ गांव की लिस्ट दी गई है जो कि प्रोपोज़्ड प्रोजैक्ट में रखे गए हैं। उन को कितनी जल्दी बिजली देने का इन्तज़ाम हो जाएगा ?

मन्त्री : आप ने तो इलैक्ट्रिक सब-डिवीज़न खोलने के बारे में पूछा है यह तो नहीं पूछा कि बिजली कब तक दी जाएगी ।

Construction of Road from Shaikhpura to Betwar via Thurana and from Majra to Bas in Hissar District

***7175. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to construct a road from Shaikhpura to Petwar *via* Thurana and from Majra to Bas in Hissar District ; if so, the date by which it is likely to be implemented ?

Shri Rizaq Ram : Part I : No.
Part II : Question does not arise.

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहिब, यह वाटरलाग्ड एरिया है और बरसात के दिनों में वहां हर साल गांव के अन्दर जाने के लिये लोगों को रास्ता भी नहीं मिलता, इस अरजैंसी को महसूस करते हुए क्या मिनिस्टर साहिब वहां पर सब सड़क बनाने की ज़रूरत महसूस करते हैं या नहीं ?

मन्त्री : ज़रूरत तो जब आप महसूस करते हैं तो मुझे भी करनी चाहिये लेकिन सवाल तो फंडज़ का है ।

श्री अमर सिंह : फोर्थ फाइव इयर प्लैन में जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो इस तरफ भी खर्च कर लेना चाहिये । क्या मन्त्री साहिब फरमाएंगे कि यह जो दो दो तीन तीन मील के टुकड़े हैं इन के बनने से 5-5, 6-6 गांव को फायदा हो सकता है, बरसात के दिनों में आने जाने के रास्ते मिल सकते हैं । जब एमरजैंसी में डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं तो देहात में सड़कें बनाने में लोगों को आराम पहुंचाने में क्या दिक्कत है ?

Mr. Speaker : The reply has come.

Barwala to Jind and Hansi to Baroda Roads in Hissar District

***7176. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the approximate date by which the roads from Barwala to Jind *via* Kharak Punia and from Hansi to Baroda via Sisai in Hissar District are likely to be completed ?

Shri Rizaq Ram : These roads have not been included in any Plan so far. The question of their completion does not, therefore, arise.

श्री अमर सिंह : हर साल बजट में देखने में आता है कि हमारे इलाके में कोई सड़क प्रोवाईड नहीं की गई.............

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंटरी करना चाहते हैं तो कीजिये । (If the hon. Member wants to ask supplementaries, he may do so.)

श्री अमर सिंह : मेरा सप्लीमेंटरी तो यह है कि आनरेबल मन्त्री महोदय ने कहा है कि क्वैसचन डज़ नाट अराईज़ । मैं यह पूछना चाहता हूं कि बडवाला से जींद बरास्ता खड़कपुन्या के मुतअल्लिक कमिटमैंट की थी कि एसटीमेटस पिछले दिनों में बन रहे हैं, यह एसटीमेटस गलत बताए जा रहे हैं, यह मिनिस्टर साहिब गलत जवाब दे रहे हैं ।

मंत्री: इस के मुतालिलक तो मुझे पता नहीं कि कोई कमिटमैंट की थी या नहीं। अगर की थी तो पता करके बता दूंगा ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਣਗੇ ?

Mr. Speaker : Please.

श्री मंगल सेन: हमारे ग्रानरेबल मैंबर जिन्होंने सवाल किया है सड़कों के बारे में क्या उन की इस इलतजा ग्रौर गुज़ारिश के बारे में वज़ीर साहिब सोचने के लिए तैयार हैं ? उन्होंने ग्रपना दीन इमान भी खराब किया, क्या जो सड़कें उन्होंने कहीं हैं वह बनाने के लिये तैयार हैं ?

श्री ग्रमर सिंह: क्या ग्रानरेबल मन्त्री साहिब फरमायेंगे कि हांसी से बड़ौदा 12 या 14 मील पड़ता है जिस में से 6 मील सड़क बनी हुई है वाकी 6 मील बनने से 8 गांव को फायदा होता है, क्या इस तरफ सड़क बनाने के लिये ध्यान देंगे ?

मन्त्री : ध्यान न देने की कोई बात नहीं, ध्यान देंगे । फंडज़ का सवाल है ध्यान देने से ग्रगर सड़क बनती हो तो ग्राप बतायें ।

Metalled Roads Constructed in Kangra District

*7355. **Bakhshi Partap Singh** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the number, names and mileage of the metalled roads so far constructed during the Third Five-Year Plan period, in Kangra District ?

Chaudhri Rizaq Ram : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

List of Roads provided in Third Five Year Plan in Kangra District which are under construction

Serial No.	Name of Road	Length provided in Third Plan (miles)	Length constructed upto-date (miles)	REMARKS
1	2	3	4	5
1	Una-Aghar-Mandi Road (excluding section Bhota to Jahu)	39.71	..	Work in progress, Earth work, construction of Bridges and Culverts and collection of material done in most of the length
2	Jawalamukhi-Dera Gopipur	5.50	5.50	Completed.

[Public Works And Welfare Minister]

Serial No.	Name of Road	Length provided in Third Plan (miles)	Length constructed upto date (miles)	REMARKS
1	2	3	4	5
3	Palampur-Thural ...	13.00	11.75	Work in progress. Earth work and Bridges and Culverts completed in entire length.
4	Hamirpur-Bhota-Bilaspur (Section Hamirpur Bhota)	9.00	7.00	Work in progress.
5	Hamirpur-Nadaun-Mubarakpur	31.75	16.75	Work in progress.
6	Sujanpur-Bhaghera road ...	..	...	Earth work and road structures done.
7	Improving Luri-Aut Road (Truckable road.)	5.00	5.00	Completed.
8	Bhuntar-Manikaran Road (Jeepable road) (mile 1—10)	1.00	1.00	Completed.
9	Kulu-Manali left bank road (jeepable road)	20.00	18.00	Work in progress.
10	Jeepable road to hot water Spring at Vashisht	0.75	0.75	Completed.
11	Link to Jawalamukhi temple	0.20	0.20	Completed.
12	Hamirpur-Sujanpur ...	12.50	...	Work is in progress.
13	Mohal Khad Bridge to join A.P.K. road with Rajpura near Palampur	0.90	...	Only preliminaries to be done in this Plan period.
14	Andaura to Ghiala Railway Station	5.00	...	Ditto
15	Constructing link road from Gajanwala Group to village to Droh Khas on Thakar Dwara-Thural Road	4.00	...	Ditto
16	Dharmsal Cantt to Dal Lake	2.50	...	Only preliminaries to be done in this Plan period.
17	Kangra to Tanda Sanatorium	2.00	...	Work in progress. Earth work and construction of Bridges and culverts completed.
18	Behna Dalash to Qanda Ghai	7.00	...	Not yet started.
19	Palampur R.H. to Bundla Tea Estate	0.75	...	Ditto

Serial No.	Name of Road	Length provided in Third Plan (miles)	Length constructed upto date (miles)	REMARKS
1	2	3	4	5
20	Bhota-Jahu Road ..	14.00	..	Only preliminaries to be done in this Plan.
21	Thural-Sujanpur ...	9.50	...	Ditto
22	Bhota-Bilaspur (up to Ukhli)	7.00	...	Ditto
23	Raja-ka-Talab to Jwali ..	10.00	...	Ditto
24	Bhuntar-Manikaran Road (11—21) (Jeepable road)	11.00	10.00	Work in progress.
25	Dharamsal-Yol-Dadh-Palampur	20.00	...	Work in progress. Earthwork done in 6 miles.
26	Dharamsala-Chambi Road	10.00	3.00	Work in progress.
27	Nurpur-Fatehpur-Dhaneta Reh road	30.00	..	Work in progress. Soling laid in 3 miles.
28	Palampur-Holta-Chadhiar ..	20.00	..	Only preliminaries to be done in this Plan.
29	Nurpur-Suliali ...	7.00	...	Ditto
30	Thana-Mandi-Bhakra Dam...	18.00	...	Ditto
31	Andawa-Mothli ...	5.70	...	Ditto
32	Palampur to Bir via Bundlas Chandpur, Kandheri, Dewel Khas	25.00	...	Ditto
33	Bridge over Sutlej near Datt Nagar and road from there to Nirmand (Truckable road)	9.00	6.00	Work in progress.
34	Bye pass in mile 1 of Kulu-Manali road	1.00	1.00	Completed.
35	Approach road to Wah and and Holta Estates	2.50	2.50	Completed.

बक्शी प्रताप सिंह : जो स्टेटमैंट मुझे दी गई है इस में सड़कें बताई गई हैं। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन सड़कों को जल्दी पाया तक मील तक पहुंचाने के लिये कोई सपैशल फंडज़ मक्सूस किए जा रहे हैं ?

मंत्री : कोई कमी तो इस में नहीं है। इस में फंड्ज़ हैं और फंड्ज़ की कोइ कमी की इतलाह नहीं ।

Setting up Advisory Committee to Suggest Ways and Means for The Uplift of Backward Areas

*7190. **Shri Jagan Nath :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether there is any proposal to set up an Advisory Committee to suggest ways and means for the uplift of back ward areas as has been done in the case of Hilly areas ; if so, the approximate time by which it is likely to be implemented ?

Chaudhari Rizaq Ram : A special Hariana Development Committee has been constituted under the chairmanship of Shri Sri Ram Sharma to appraise the economic deficiencies, assess the material resources and recommend measures to secure expeditiously an integrated socio- economic development of the entire Hariana area which is comparatively backward area of the State. No other Advisory Committee on the lines of Hill Areas Advisory Committee is being set up.

श्री जगन्नाथ : मैं ने सारे पंजाब के लिये पूछा है और यह सिर्फ हरियाणा के बारे में जवाब दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बैकवर्ड एरियाज के लिए कोई कमेटी मुकर्रर नहीं की ।
(No Committee has been set up for the backward areas.)

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब, इस गवर्नमैंट की यह आदत बन गई है और हिली एरिया और बैकवर्ड एरिया से डिस्क्रीमिनेशन हो रही है । मैं गवर्नमेंट से यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बैकवर्ड एरियाज में कोई कमेटी बनाने की कोई तजवीज़ की है कि बैकवर्ड एरियाज में कोइ प्रचार हो सके ?

मन्त्री : बैकवर्ड एरियाज के लिये पहले ही सर्विसिज में और डिवैलपमेंट में ख्याल रखा गया है । बाकी ख्याल यह है कि डिवैलपमेंट के लिहाज से जो बैकवर्ड हैं उनकी जांच पड़ताल के लिए कमेटी मुकर्रर की जाए ।

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ?

चौधरी खुरशीद अहमद : वज़ीर साहिब ने अभी फरमाया है कि बैकवर्ड एरियाज की जो प्राब्लम्ज़ हैं उन्हें हरियाना कमेटी कनसिडर करेगी । मेरा ख्याल है कि जवाब यह था कि बैकवर्ड एरियाज में कोई कमेटी बनाने की ज़रूरत इस लिए महसूस नहीं हुई कि हरियाना डिवैल्पमेंट कमेटी की जो सब-कमेटी यह देखने के लिये बनी है कि हरियाना को क्यों बैकवर्ड एरिया तसव्वर किया जाता है, उनकी प्राब्लम्ज़ को वह कनसिडर करेगी और बैकवर्ड एरियाज़ एंज़ सच जो स्टेट के हैं उन्हें डिक्लेयर कर सकेगी । क्या झज्जर ही बैकवर्ड एरिया है जिस में से 11 मेंबरो में से 6 मेंबर लिए गए हैं ?

मन्त्री : मेरा यह बिल्कुल जवाब नहीं था कि मैंने कहा था कि बैकवर्ड एरियाज़ के लिये कोई कमेटी मुकरर नहीं की । स्टेट में कुछ एरियाज़ हैं जिनको गवर्नमेंट ने बैकवर्ड

एरियाज डिक्लेयर किया हुआ है, उन के लिये कमेटी मुकर्रर नहीं की। साथ ही यह है कि हरियाना के लिये कमेटी मुकर्रर की है। जनरली बैकवर्ड एरियाज के लिये कोई कमेटी मुकर्रर नहीं की। 11 में से ज्झजर के ही 6 मेंबर हैं इस का सवाल नहीं।

श्री मंगल सेन : क्या मन्त्री महोदय सवाल को दोबारा पढ़ कर जवाब देने की कोशिश करेंगे कि सवाल में जब के पूछा गया था कि पिछड़े हुए इलाकों की डिवेलपमेंट के लिये कोई एडवाईज़री कमेटी बनाई गई है तो इस के जवाब में आप ने कहा है कि हरियाना की डिवेलपमेंट के लिये एक कमेटी बनाई गई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पंजाब के वह इलाके जो पाहड़ी हैं और पिछड़े हुए हैं उन के विकास के लिये कोई रास्ता ढूढ़ने के लिए क्या सरकार कोई एडवाईज़री कमेटी बनाएगी ?

मन्त्री : पहाड़ी इलाकों की डिवैलपमेंट के लिये पहले ही एक एडवाईज़री कमेटी बनी हुई हैं और उस के लिये फण्डज़ भी अलग मखसूस किए हुए हैं इस लिये और कोई कमेटी बनाने के लिये ज़रूरत नहीं है।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਹਰੀਆਣੇ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ?

(Not replied.)

श्री फकीरिया : स्पीकर साहिब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हरिजन मेंबरों को अपने हल्के के बारे में कोई डिमांड यहां पुट करने का हक हासल है या नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : यह कोई स्पलीमेंट्री नहीं हैं। आप बैठ जाएं। (This is no Supplementary Question. The hon Member may please resume his seat.)

कंवर राम पाल सिंह : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जैसा कि उन्होंने अभी बताया है कि हिल्ली एरियाज़ को डिवैलपमेंट के लिये एक एडवाईज़री कमेटी बनाइ हुई है और इसी तरह से हरियाने की डिवैलपमैंट के लिये भी एक कमेटी बनाई गई है लेकिन इस सवाल में साफ तौर पर बैकवर्ड एरियाज़ की डिवैलपमेंट के लिये पूछा गया था तो क्या सरकार बाकी के बैकवर्ड एरियाज़ के लिये कोई कमेटी बनाने के बारे में सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष : जवाब में क्लीयर आ चुका है कि बैकवर्ड एरियाज़ के लिये कोई कमेटी बनाने के कोई प्रपोज़ल नहीं है। ((It has been clearly stated in the reply that there is no proposal to set up a Committee for the backward areas.)

श्री जगन्नाथ : जो बैकवर्ड एरियाज़ डिकलेयर किए गए हुए हैं पंजाब के अन्दर, उन को ऐसा हुए काफी अरसा हो चुका है और उन में से कुछ ऐसे इलाके हैं जो उस वक्त तो बैकवर्ड थे लेकिन अब बैकवर्ड नहीं रहे लेकिन बाकी बैकवर्ड इलाकों की तरह सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो इस वक्त बैकवर्ड नहीं हैं उन को छोड़ कर बाकी के इलाकों के लिये सरकार कोई कमेटी बनाने का विचार रखती है ?

Mr Speaker : It does not arise.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ?

Mr. Speaker : That is a matter of opinion.

श्री फतेह चन्द विज : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि वह जो हरियाने को डिवैल्पमैंट कमेटी का ज़िक्र यहां कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट आने तक क्या सरकार अपनी फोर्थ फाईव इयर प्लान को फाइनल टच नहीं देगी ताकि वह कमेटी अपनी जो सिफारशें करे वह इस प्लान में आ जाएं ?

श्री अध्यक्ष : ऐसे सवाल तो बहुत आ चुके हैं। नो प्लीज़ । (Many such questions and have already been asked. No please.)

Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister for Public Works and Welfare has just now stated that Haryana Development Committee has been set up by Government. May I know from him, the emoluments and other facilities proposed to be given to the non-M.L.A. Members of that Committee ?

Mr. Speaker : This supplementary question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅੋਰ ਨਾ ਹੀ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker : The reply has already come.

श्री हीरा लाल : मैं मिनिस्टर साहिब से यह पूछना चाहता हूं कि जिला गुड़गांवां बैकवर्ड एरियाज़ में आता है कि नहीं आता ?

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में गज़िट नोटीफिकेशन पढ़ लें। (The hon. Member may go through the Gazette Notification.)

श्री फकीरिया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि नरवाना, जो बैकवार्ड एरियाज़ में शुमार है, वहां से हरियाना की डिवैल्पमैंट कमेटी में कितने मेंबर लिए गए हैं और कितने हरिजन मेंबर उस में लिए गए हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल इस से पैदा नहीं होता । (This question does not arise out of this question.)

J.B.T. Units Opened in the State

***7353. Bakshi Partap Singh :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) the total number of J.B.T., Units opened, district-wise, in the State during the year 1964-65 to date ;

(b) the number of such J.B.T., Units opened, tehsilwise, in district Kangra and the names of the places where these have been opened ;

(c) the exact number of girls and boys admitted in the J.B.T., Units, districtwise, separately for boys and girls ?

Shri Prabodh Chandra : (a) & (b) Statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

(c) Information is being collected and will be supplied separately.

Statement

Total number of Units opened, in the State		J.B.T. District-Wise during 1964-65	The number of such J.B.T. Units opened, tehsil-wise in District Kangra		Names of Places where these have been opened in Kangra		
1.	Ambala ..	21	Kangra ..	3	Dharamsala ..	3	(Kangra)
2.	Karnal ..	21	Hamirpur	6	Hamirpur	3	
3.	Rohtak ..	32	Dehra Gopi-pur	4	Nadaun ..	1	Bani
4.	Gurgaon ..	22	Palampur	4	Bani ..	1	
5.	Hissar ..	18	Nurpur	2	Sujanpur Tira	1	Hamirpur
6.	Simla ..	3			Pragpur ..	1	
7.	Jullundur ..	18			Rakkar ..	1	Dehra Gopipur
8.	Amritsar ..	15			Garli ..	2	
9.	Gurdaspur ..	17			Rajpur	1	
10.	Kangra ..	19			Chudhiar	1	Palampur
11.	Hoshiarpur ..	24			Baij Nath ..	2	
12.	Ferozepore ..	16					
13.	Ludhiana ..	19			Nurpur ..	1	Nurpur
14.	Kapurthala	9			Indora ..	1	
15.	Kulu ..	2					
16.	Patiala ..	15					
17.	Bhatinda ..	21					
18.	Sangrur ..	22					
19.	Mohindergarh	10					
	Total ..	324					

Bakshi Partap Singh : Sir, it has been stated in the reply given by the hon. Minister for Education and Local Government that the information is being collected and will be supplied separately. In how much time will I get this information ?

Minister : It will take some time before the information is collected. I do not know why the hon. Member is interested to know the exact number of boys and girls admitted in the J.B.T. units districtwise separately for boys and girsls

---

National Loan Scholarship Scheme

*7923. **Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state whether it is a fact that applications for the award of scholarships under the Government of India National Loan Scholarship Scheme were invited by the Director of Public Instruction, Punjab, in June, 1964, but the final sanction for the award of the scholarships has not been released so far; if so, the reasons therefor and the date by which it is likely to be issued ?

Shri Prabodh Chandra : Yes. The sanction could not be released earlier because, in spite of the widest possible publicity, the number of applications received was too small and accordingly the last date for the receipt of applications had to be extended four times so as to utilize the maximum quota of scholarships allocated by Government of India to this State . The requisite sanction is likely tobe issued before the end of March, 1965.

कामरेड राम प्यारा : क्या एजूकेशन मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जब इन्होंने पहले एप्लीकेशनज़ काल की थीं और जो एप्लीकेशनज़ न को मौसूल हो चुकी हैं उन को लोनज़ सैंक्शन न करने की क्या वजह है ?

मन्त्री : जनाबे आली, जो एप्लीकेशनज़ पहले आई थीं उन का नम्बर इतना थोड़ा था कि गवर्नमैंट ने मुनासब नहीं समझा कि पहले उन को लोन दिया जाए और इस तरह से पीसमील बार बार डील किया जाए । इस लिए यही मुनासब समझा कि दोबारा एप्लीकेशनज़ मांगी जाएं और जब और एप्लीकेशनज़ आ जाएं तो एक बार ही सब के बारे में फैसला किया जाए ।

कामरेड राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो एप्लीकेशनज़ पहले इनवाईट की गई थीं और उन के लिये जो कराएटीरिया रखा गया था और बाद में जब दूसरी बार एडवर्टाईज़ किया गया था तो उस पहले वाले कराएटीरिया को कुछ रिलैक्स कर दिया गया था ताकि लोगों को कुछ इनसेंटिव मिल सके और वह एप लाइ करें ?

मन्त्री : इनसेंटिव तो फरदर नहीं दिया गया लेकिन पबलिसिटी बार बार की गई थी ताकि अगर किसी के नोटिस में यह चीज़ न आई हो तो वह एपलाई कर सके । and that is why we have advertised again and again.

श्री अमर सिंह : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि स्कालरशिप देने के लिये किन २ बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

मन्त्री : गवर्नमैंट आफ इण्डिया जब स्कालरशिप्स एवार्ड करती है तो वह खुद ही कुछ कण्डीशनज़ रख देती है कि यह इस इस तरह के स्टूडेंट्स ले सकेंगे ।

कामरेड राम प्यारा : मिनिस्टर साहिब ने अभी फरमाया है कि उन्होंने चार दफा एडवर्टाइज किया था तो मैं पूछना चाहता हूं कि पहली दफा एडवटाईज करने पर कितनी अर्ज़ीयां आई थीं, दूसरी बार करने पर कितनी आई थीं और इसी तरह तीसरी और चौथी बार कितनी आई यानी आज तक चार दफा एडवर्टाईज़ करने के बाद कितनी अर्जियां आई हैं ?

मन्त्री : इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि यह सारी डिटेल्ड इनफर्मेशन दे सकूं। अगर आनरेबल मेंबर इस बारे में नोटिस दे दें तो बता सकूंगा ।

कामरेड राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बतलाएंगे कि इन लोनज़ से जिन लोगों ने फायदा उठाना था वह लग भग एक साल तक इस का फायदा नहीं उठा सके क्योंकि इन लोनज़ की रकम तकरीबन एक साल से आई हुई है, तो क्या गवर्नमैंट उन लोगों को कम्पैनसेट करने के लिये कोइ कदम उठा रही है ?

Minister : According to the rules and regulations laid down by the Government of India, scholarships are awarded.

यह कोई ज्यादा देर का सवाल नहीं है । डेट 31 अगस्त, 1964 तक थी, इट इज़ ए क्वैश्चन आफ फोर फाइव मन्थस ओनली ।

श्री मंगल सैन : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने कुल कितनी रकम सकालरशिप्स की देनी स्वीकार की थी ?

मंत्री : सात लाख रुपया ।

High Schools in Dharam Kot Block, District Ferozepore

*7939. **Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) the total number at present of high Schools in Dharamkot Block, district Ferozepore ;

(b) the number of teachers of the High Schools referred to in part (a) above whose service Books are lying in the office of the District Education Officer and the period for which they have been lying incomplete together with the number of teachers who have suffered loss as a result thereof ;

(c) the names of the officials responsible for the said loss and the action, if any, being taken against them ;

(d) the time by which the said service books are likely to be received in the offices concerned ?

Shri Prabodh Chandra : (a) 5.

(b) Nil.

(c) & (d) In view of (b) above the questions does not arise.

Visit of B.E.O., Dharamkot Circle I, to Government Primary School, Nasirewala, on 11th December, 1964

*7940. **Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the B.E.O., Dharamkot Circle I, paid a surprise visit to Government Primary School, Nasirewala, on 11th December, 1964 ;

[Sardar Kultar Singh]

(b) whether it is also a fact that a teacher of the said school was found to be absent for three/four days, if so, the actual number of days for which he remained absent ;

(c) a copy of the Inspection Note in the log book of the said school dated 11th December, 1964, be laid on the Table of the House ;

(d) action taken or proposed to be taken against the said teacher and the officers, if any, who shielded him ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes.

(b) Yes, from 8th December, 1964 to 11th December, 1964.

(c) It will not be desirable to lay a copy of the Inspection Note on the Table of the House.

(d) The teacher was warned. He was not shielded by any officer.

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यह जो उन्होंने कहा है कि टेबल पर नोट रखना पब्लिक इंटरैस्ट में नहीं है । अगर किसी केस में ऐसा इशू इनवाल्वड हो और उस को सजा देना मतलूब न हो तो ऐसे नोट को टेबल पर रखने में क्या एतराज़ हो सकता है ?

मन्त्री : इस केस में टीचर को वारनिंग दी गई है । आम तौर पर ऐसी जितनी इन्क्वायरीज़ होती हैं गवर्नमैंट कोशिश करती है कि जो रिपोर्ट्स हैं वह अपने तक ही रखे, मेज पर न रखे ।

कामरेड राम प्यारा : क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि जब वह इस नोट को टेबल पर रखने के लिये तैयार नहीं हैं तो हम किस तरह देख सकते हैं कि कितना उसका कसूर था उस को उस के मुताबिक सजा दी गई है ?

Mr. Speaker: No please. You can get facts only.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕੇਸਿਜ਼ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਉਣ ਤੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ?

मन्त्री : मेरी नौलिज में तो ऐसी हार्डशिप का केस नहीं है । (विघ्न) मैं उन के राज की बात नहीं करता । आज वह चीज़ें बदल गई हैं । मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को सर्विसिज़ एक घंटा लेट आने की वजह से टर्मिनेट कर दी गई हों । अगर कोई खास केस उन को पता हो तो बता दें, ज़रूर गौर किया जायगा ।

T.A. drawn by D.E.O. and Deputy D.E.Os. of District Ferozepur

***7941. Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state the amount of travelling allowance drawn by the District Education Officer and the Deputy Education Officers of Ferozepur District, during the period from 1st April, 1964 to 28th February, 1965 stating the purpose of the journey performed by each ?

Shri Prabodh Chandra : District Education Officer—Rs 474.70
Deputy Education Officers (3) Rs 1425.26

The journeys related to Inspection of Schools, conducting of enquiries and attending of meetings.

Funds allocated to Kurukshetra/Punjabi Universities out of Education Cess Fund

***8012. Sardar Gurbaksh Singh** Gurdaspuri : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) whether any special education cess was levied in the State for the creation of the Punjabi and Kurukshetra Universities; if so, the total amount realised on this account ;

(b) the share allocated out of the said amount to each of the said universities and the amount paid to each of them ;

(c) whether it is a fact that the full share of the Punjabi University has not been given to it so far ; if so, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes, for the development and not for the creation) of the Universities. The estimated income and the actual **realiza**tion from the cess come to Rs 1,55,16,869 and Rs. 1,45,85,626 respectively.

(b) 50 per cent to each University. The amount paid is as follows :

(1) Kurukshetra University .. Rs 77.61 lakhs.

(2) Punjabi University .. Rs 42.50 lacs.

(c) Yes; the cess share is released to the Universities in accordance with their actual requirements.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਝਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ 77 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਜੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 80 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਦਸ ਲਖ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ 90 ਲਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਵਿਚ ਸੀ ?

मन्त्री : यह जो जवाब दिया गया है यह जिस डेट को आया है उस तारीख तक है, उस के बाद और भी रुपया सैंक्शन हुआ है। कन्ट्राडिक्शन का सवाल नहीं है, इस सवाल का जवाब आने के बाद कुछ और रुपया लिया होगा।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪਰ : ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੇ ਤਾਂ 77 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੇ 42 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

मन्त्री : आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी से बहुत पहले चालू हुई है। किसी पर ज्यादा या कम खर्च करने का सवाल नहीं है। फैसला यह है कि सैस का बराबर रुपया देना है। उन का रुपया जमा होगा। जहां 2 बिल्डिंग्ज़ बन रही हैं उन को रुपया मिलता जायगा। ऐसी कोइ बात नहीं है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी का हिस्सा ले कर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को दे दिया गया है। चूंकि वह पहले बनी है इस लिये उन को ज्यादा खर्च हुआ है।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰੁਪਏ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਐਂਜਨੀਅਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ?

मन्त्री : अर्ज़ है कि जब भी कभी भाई जोध सिंह जी, जो पहिले वाईस चांसलर थे, मुझे इस बारे में मिले तो मैं उन को अपने साथ ले जाकर फिनांस मिनिस्टर साहिब से उन को रिक्वायरमैंट्स पूरी कराता रहा हूं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी चूंकि अपना हिस्सा ले चुकी है इसलिये फरदर गवर्नमैंट से लेने में मुश्किल हो रही है। बाकी ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने कहा हो कि चूंकि रुपया नहीं मिलता हमारे ऐंजनियर्ज़ खाली बैठे हैं और पैसा न दिया गया हो।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ 50 : 50 ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੈਸ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ;

Minister : I have not got the exact figures. However, I may state for the information of the honourable Member that the Kurukshetra University has since exhausted its share; rather it has received in excess a sum of Rs 2,565.50 Paise, a small amount. The Punjabi University has to its credit a sum of Rs 35,08,434.50 paise. A sum of rupees forty lakhs has been provided in the S.N.E., 1965-66 for payment as grant-in-aid to the Punjabi University. With the payment of Rs 40 lakhs during 1965-66, the share of the Punjabi University will stand paid in excess by rupees five lakhs approximately.

Medium of Instruction in Government Primary Schools in Tehsil Pathankot, District Gurdaspur

*8020. **Sardar Gurbaksh Singh** Gurdaspuri : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) Whether it is a fact that Gurdaspur district including the tehsil Pathankot is in the Punjabi Region of the State ;

(b) the medium of instruction in tehsil Pathankot and whether the Punjabi language is being taught as the first language in to Government Primary Schools there; if not, the reasons therefor ;

(c) whether the Government has received any complaint in this connection; if so, the action taken thereof ;

(d) the steps being taken for the introduction of Punjabi as the first language in tehsil Pathankot and other areas included in the Punjabi Region ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes.

(b) The medium of instruction in tehsil Pathankot is Punjabi and it is being taught as the first language. But in accordance with the provisions of the Sachar Language Formula arrangements for teaching of Hindi as the first language in tehsill Pathankot have also been made where 10 students in a class or 40 such students in the whole school desire to study this language.

(c) No.

(d) Covered under (b) above.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 10 ਬਚਿਆਂ ਯਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਹੈ ਸੱਚਰ ਫਾਮੂਲੇ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 10 ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 40 ਬਚੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਗ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਸ ਰਿਜਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Mr. Speaker : The Question Hour is over now. More supplementaries will be allowed tomorrow on this Question.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS PLACED ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Representation from a Legislator Regarding Improvement Trusts

*7612. **Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) whether he received any communication from any Legislator of Karnal district during the month of October, 1964 on the subject of "Improvement Trusts, Acquisition of lands and their disposal"; if so, from whom and a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(b) whether any reply to the said communication has been sent to the Legislator concerned; if so, a copy thereof be laid on the Table ;

(c) whether the proposals contained in the said communication have been considered; if so, when, by whom and with what result ;

(d) whether Government intends to constitute any Committee to examine the said points/proposals thoroughly and submit its report to the Government; if so, the composition of the proposed Committee and the time by which it is likely to be appointed ;

(e) the number of meetings, if any, held for the purpose of examination of the proposals made by the said Legislator together with the dates of each meeting and the details of the proceedings of the meetings ;

(f) whether Government has fixed any date to finalise the examination of the proposals ; if so, what ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes. It was received from Comrade Ram Piara. Copy is laid on the Table of the House .

(b) Yes. Copy is laid on the Table of the House.

(c) Under consideration by the Government.

(d) No decision has yet been taken to appoint a Committee for the purpose.

(e) Does not arise.

(f) No.

Copy of letter dated 19th October, 1964, form Shri Ram Piara Comrade, M.L.A., Model Town, Karnal, to Shri Prabodh Chandra Ji, Education and Local Government Minister, Punjab, Chandigarh.

Subject.— Improvement Trusts, Acquisition of land and then disposal.

I would like to draw yourkind attention towards my Registered letter, dated 27th/30th July, 1964 and your acknowledgement No. 1673 A.E.L. G.M. /64 A/3369, dated 29th August, 1964 on the above noted subject.

[Education and Local Government Minister]

I would again sub it that the Improvement Trusts present policy is causing anxiety to the poor and improvement of the Town no doubt is there being the lot of the poor instead of any improvement is deteriorated which is against all cannons of justice, socialistic pattern and other committed policies of the Government.

In Karnal an area in Subash Gate previously known as Nawab Gate, the land of the locality inhabited by Jheenwars is being acquired for some improvement. I am in favour of improvement but do not relish that the poor are ousted, thrown away and area is improved which is given to the comparatively richer class which has money to puschase the areas after an improvement and development. If these poor are financed the area is developed and handed over to them. Their lot can visibly be changed and Government, can claim credit for raising the standard of the poor and improving the lot of the poor.

I am very very particular on this issue. I am afraid that some of the officers and public men including the politicians can not even imagine and judge such things because they have no such information and contacts.

If you deem it fit I shall suggest to appoint a Committee which may suggest some changes in the working of the Improvement Trusts so that the poor is benefited. I shall be grateful for an acknowledgement and speedy action.

Thanking you.

No. 7386/STP/ELLM/64.

Education & Local Government,

31st October, 1964.

My dear Comrade,

I have received your registered letter dated 19th October, 1964, on my return from Srinagar yesterday. I have passed on the same to the Secretary, Local Government Department, to examine your suggestions. On hearing from him I will take appropriate action.

Yours sincerely,

(Sd) Prabodh Chandra.

Shri Ram Piara Comrade,
M.L.A.,
Model Town, Karnal.

Election of President and Vice-President, Municipal Committee, Qadian, district Gurdaspur

*7327. **Shri Mohan Lal** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) whether it is a fact that after the issue of the Gazette notification of the names of the Municipal Commissioners, Qadian, Gurdaspur District, the Deputy Commissioner, Gurdaspur issued written instructions to the S.D.O., Batala, to administer the oath to the newly eletced Municipal Commissioners and hold elections of the President and Vice-President of the said Committee ; if so, the date when these instructions were issued ;

(b) whether any date was fixed by the S.D.O., Batala for this purpoes; if so, what ;

(c) whether the oath was administered and elections held on the date so fixed by the S.D.O., if the date was postponed the name of the authority under whose order it was postponed ;

7/ PUS 307

(d) if the date was postponed, whether the oath has been administered and the election held; if so, when ;

(e) whether he paid a visit to Qadian before the election of the President and the Vice-President on the date mentioned in part (d) above ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes, on 4th July, 1964.

(b) Yes, 30th July, 1964.

(c) No. The meeting for election of President and Vice-President was postponed under orders of Government.

(d) Yes, on 27th August, 1964.

(e) No.

Water-supply Schemes in Kangra District

***7294. Shri Amar Nath Sharma** ; Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state —

(a) the progress so far made in the execution of the Water-supply Scheme in the rural areas of Kangra District, tehsilwise;

(b) whether Government propose to accelerate the speed of execution of the said schemes ;

(c) whether any more Water-supply Schemes for the said district are under consideration of the Government ; if so, the details thereof ?

Shri Prabodh Chandra : (a) A list of the schemes in the State already executed /completed and in the couse of completion is placed on the Table of the House, vide Annexure 'A'.

(b) Yes.

(c) Yes. The lists of such schemes are at Annexure 'B'. Since there is acute shortage of funds it is not certain when these new schemes will be taken up as the intention is to complete the schemes in hand first.

ANNEXURE A

SHOWING WATERSUPPLY SCHEMES (RURAL) OF KANGRA DISTRICT ALREADY EXECUTED AND IN THE COURSE OF COMPLETION

Serial No.	Name of Scheme	Estimated cost	Progress
1	2	3	4
	TEHSIL DEHRA GOPIPUR	in lakhs	
1	Providindg Water Supply in villages Channaur, Paniwal etc., tehsil Dehra Gopipur	4.43	Completed
2	Providing Water Supply in village Harpankhar, tehsil Dehra Gopipur		
3	Providing Water Supply in Tikka Kharoti, Tappa, Kaloha etc., tehsil Dehra Gopipur		
4	Providing Water Supply in tikka Khadwana and Matumaran etc., tehsil Dehra Gopipur		

[Education and Local Government Minister]

1	2	3	
	TEHSIL HAMIRPUR	Rs in lacs	
5	Hamirpur group of villages in tehsil Hamirpur ..	1.35	In the course of completion
6	Bagh Sarai, Kasora, etc. in tehsil Hamirpur ..	0.72	Completed
7	Tikka Changer of Tapa Dhaned and Nehlu, etc., tehsil Hamirpur	0.44	In the course of completion
8	Group of villages Dhangota, Khas and Ghumrath, tehsil Hamirpur	0.32	Ditto
	TEHSIL PALAMPUR		
9	Chadiar Group of villages, tehsil Palampur ..	5.84	Completed
10	Tikka Barhan, Mauza Sansal, tehsil Palampur ..	0.29	Do
11	Tikka of Lanaud etc., tehsil Palampur ..	0.27	Do
12	Chhurala and Bhalta in tehsil Palampur ..	0.36	Do
13	Baij Nath in tehsil Palampur ..	1.06	Do
14	Bundla group of villages in tehsil Palampur ..	0.83	Do
15	Bari, Khas, Nanher and Ram Chair, etc. in tehsil Palampur	0.76	Do
16	Sungal pipe line extension for village Godira, tehsil Palampur	0.32	In the course of completion
	TEHSIL NURPUR		
17	Bhadwar and adjoining villages in tehsil Nurpur ..	1.65	Completed
18	Nurpur group of villages in tehsil Nurpur ..	0.30	In the course of completion
19	Gurkari, Barita and Katecheri, tehsil Nurpur ..	1.13	Completed
20	Sadhata area Jawali and adjoining villages in tehsil Nurpur, district Kangra under WHO/Unicef assisted rural W/S Project, Punjab	29.06 (Combined scheme for Kangra and Gurdaspur Districts)	
	TEHSIL KANGRA		
21	Pathai, Chari and Ambri villages in tehsil Kangra ..	1.19	Completed
22	Mant Area (Dharamsala) in tehsil Kangra ..	0.16	Do
23	Rehlu, Rait, etc. in tehsil and district Kangra ..	3.55	Do

ANNEXURE B

Showing water-supply schemes of Kangra District under consideration (which have been approved by the Sanitary Board and have been referred to the Panchayat Department for obtaining the acceptance of the Panchayats concerned)

Serial No.	Name of Scheme	Estimated cost (Rs in lakhs)
1	2	3
	TEHSIL NURPUR	
1	Water-supply Scheme for Sadhata area Jawali and adjoining villages in tehsil Nurpur, district Kangra ..	17.14
2	Providing Water-supply Scheme to group of villages Bronda, Dhar, Sameli, Basa, Bit Hatahrakhas, Kotal and Sarian etc. in Block and tehsil Nurpur ..	4.02
3	Providing Watersupply Scheme for group of villages Tolara Khas, Panjihera and Sukhar Chodhrian in Block Nurpur, tehsil Nurpur, district Kangra ..	4.76
4	Providing Watersupply Scheme for villages Gangath, Charur-Rnek, Karol, Ropar, Gharo, Purani, Gumnth, Pirthipur Basa and Bhadrut in Block Nurpur ..	2.60
5	Providing piped Water-supply Scheme to the group of villages Kangru, Chasota, Bhuint, Dhalot, Colala, Bhartian, Dharota and other villages in Block Hamirpur, tehsil Hamirpur, district Kangra ..	2.60
6	Providing piped Water-supply Scheme to group of villages Neri, Khagal, Ganotla, Degura, Barota, Dugh in Block and tehsil Hamirpur, district Kangra ..	1.58
7	Providing piped Water-supply Scheme to group of villages Ghariana, Brahmina, Bassi Khasgran, Ghariana, j Jaswalan, Karshat, Dadroo, Bahal, Mathwen, Chamiaran Matiana, Jendiala in Block and tehsil Hamirpur district Kangra ..	0.90
8	Providing piped Watersupply Scheme to the group of villages Loharu, Baral, Dugneri, Chartheri in Block and tehsil Harmirpur, district Kangra ..	1.02
9	Providing piped Water-supply Scheme for villages Pulers, Bajeari and Rara in tehsil Hamirpur, district Kangra ..	0.20
10	Providing Water-supply Scheme for villages Sorar, Goleshpur, Main Shemkar etc., in Block Nedaun , tehsil Hamirpur and district Kangra ..	0.92
11	Providing Watersupply Scheme for villagess in Panchayat Sarkar Annu and Dai-Ka-Naim in Block Hamirpur, tehsil Hamirpur, district Kangra ..	2.57
	TEHSIL PALAMPUR	
12	Providing piped Water-supply to the group of villages Bhagotla, Kusunal, Rani Rachan, Latwal and Nanyat in Block and tehsil Palampur District Kangra ..	0.66

[Education and Local Government Minister]

1	2	3
13	Providing Water-supply Scheme to the group of villages in Panchayat Golalpur and Lahlain Block and tehsil Palampur, district Kangra ..	3.16
14	Providing Water-supply Scheme to the group of villages Lachhuns Band Purani Palam, etc. in Block and tehsil Palampur, district Kangra ..	5.38
15	Providing piped Water-supply Scheme to the group of villages Sidhpur, Serkari, Sidhpur Rani, Khilru, Chauddar, Bindrahan Differpat, etc. in Block andtehsil Palampur, district Kangra ..	1.57
16	Providing Water-supply Scheme for Khalet group of villages in tehsil Palampur, district Kangra ..	7.23
17	Providing Water-supply Scheme to group of villages Rajpura, Khrenda, Gerat and Malehtar in Gramsabha Rajpura, Block Palampur, tehsil Palampur, district Kangra ..	0.94
18	Providing Water-supply Scheme for villages in Gramsabha Nauri, Rajot, Sagoor and Tarchad in Block Palampur, tehsil Palampur, district Kangra ..	5.11
19	Providing Water-supply Scheme for group of villages Deogran, Char and Ladoh in Block Palampur, tehsil Palampur ..	2.51
20	Providing Water-supply Scheme of villages Bodhal, Kothi, Qasha, Daraman in Panchayat Pahra, Block and tehsil Palampur, district Kangra ..	1.85
	TEHSIL KANGRA	
21	Providing piped Water-supply cheme to the group of villages Mamdru, Khart,DehrF Chaklu, and Patti in Block and tehsil Kangra, district Kangra ..	6.12
22	Providing Water-supply Scheme for group of villages Shahpur in tehsil Kangra, district Kangra ..	2.47
23	Providing piped Water-supply Scheme for village Chari in tehsil Kangra, district Kangra ..	0.98
24	Providing Water-supply to group of villages Sener, Uprehr, Kohala Khopar in Gram Sabha Kohala in Boock district and tehsil Kangra ..	0.81
25	Providing Water-supply Scheme for group of villages Janyarkar, Kanjru, Karwal,Jhat, Chatera, etc. in Gram Sabha Jaleri, Takkipur Khas Daulatpur in Block, tehsil and district Kangra ..	2.23
26	Providing Water-supply Scheme for group of villages Lohar, Lohari, Dhoaru Jai, Mud Tharal, etc. in Panchayat Balogaloa, Jasika Kharat in Block Kangra ..	1.92
	TEHSIL KULU. PALAMPUR	
27	Providing Water-supply in village Bhattu, teshil Palampur ..	0.35
28	Providing Water-supply in village Mauze Bir, Tikka Chogan, Tehsil Palampur ..	0.73
29	Providing Water-supdly in village Halta (Panchayat) Tikka Panthekar, tehsil Palampur ..	0.25

30	Providing Watersupply to Mauza Salloh in tehsil Palampur ..	0.94
31	Providing Water-supply Scheme to Tikkas Chanthaugi Bandu Bharwada, Gohar and Kandhowal of Salina village and tehsil Palampur	0.52
32	Providing Watersupply to village Deol and Tikka of Kamartage and Phatrer in tehsil Palampur ..	0.72
33	Providing water-supply in village Rajehr tehsil Palampur.	0:17
34	Providing Watersupply in village Ghugar tehsil Palampur ..	0.58
35	Extension of Watersupply Chadhiar Village in tehsil Palampur to villages Majhoti, Mungal, Chi hrawal, Mungal Guluwala Kasba Kohian, Kasba Chandigran and Katocheri Behra etc. ..	2.28
36	Providing Watersupply Scheme for village Timber Darang, Tamber Nazar Mangodra, Bhowana, Kilhi Dagoh and Bijapur ..	11.49
	TEHSIL PALAMPUR	
37	Providing Water-supply Scheme for village Darang tehsil Palampur ..	0.75
38	Providing Watersupply to group of villages Tappa Dharchmukha in tehsil Palampur ..	2.58
39	Providing Watersupply Scheme in Bundle Group of villages, tehsil Palampur ..	0.32
40	Providing water-supply to groups of villages Upper Khera and Tika Bankun in tehsil Palampur ..	0.90
41	Providing pipe Watersupply Scheme to Tikka Group of villages in tehsil Palampur ..	2.59
42	Providing and installing duplicate set of Water-supply Scheme village Chadhiar in tehsil Palampur ..	0.35
43	Providing viped Water -supply Scheme for village Tikka Dharang of Darang Panchayat in tehsil Palampur ..	0.75
	TEHSIL DEHRA GOPIPUR	
44	Providing Water-supply Scheme for villages Badhal, Jhor, Belin etc. tehsil Dehra Gopipur ..	4.56
45	Providing piped Water-supply to village Dehra Gopipur ..	1.62
46	Providing Watersupply to group of villages Pragpur, tehsil Dehra Gopipur ..	4.10
47	Providing Watersupply in group of villages Dhabra in tehsil Gopipur ..	1.82
48	Providing pumping arrangement forWatersupply Scheme of villages Kharoti Rakkar, Naloti. etc. tehsil Dehra Gopipur ..	0.50
	TEHSIL HAMIRPUR	
49	Providing Water -supply Scheme in villages Tajar upper and lower Loihiani Roghli Chepru Tapa Nero etc., tehsil Hamirpur ..	0.64

[Education and Local Government Minister]

1	2	3
50	Providing piped Water-supply Scheme for villages Bajauri and Para in tehsil Hamirpur ..	0.20
	TEHSIL KANGRA	
51	Providing Water-supply in village Kandi Dhalroo group of villages in tehsil Kangra ..	2.52
52	Providing piped Water-supply Scheme for village Charri in tehsil Kangra ..	2.68
53	Providing piped Water-supply to group of villages Kilhi, Bhowana and Makale, tehsil Palampur ..	14,956
54	Providing Water-supply scheme for group of villages Paprola, tehsil Palampur ;	2,40,675
55	Providing Water-supply Scheme of village Salliali in Nurpur Teusil ..	1,61,581
56	Peoviding Water-supply Scheme for Logwalti and Bomsom Area in tehsil Hamirpur ..	22,79,949
57	Providing Water-supply Scheme to villages Spanu, Naddi, Dal Tota Rani and Talnoo in tehsil and district Kangra ..	1,53,125

Communications from a Legislator regarding selection of Excise and Taxation Sub-Inspectors/Inspectors

***7768. Comrade Ram Piara** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether the Chief Minister or the Excise and Taxation Commissioner, Punjab, received any communications from any legislator of Karnal District during the period from Ist September, 1964, todate on the subject of " unfair selection of Taxation Sub-Inspectors/Excise Sub-Inspectors by the Subordinate Services Selection Board, Chandigarh " ; if so, a copy each of these communications to gether with a copy/copies of reply/replies, if sent, be laid on the Table ofthe House;

(b) whether the points raised in the said communictions of the legislator have been examined ; if so, by whom, when and the details threof ;

(c) the action, if any, taken as a result of the examination of the said points ;

(d) whether Government is considering any proposal to annul the selection mentioned in the said communications ; if so, when if not, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Part I. Yes.

Part II. A copy each of the communications received and replies sent is laid on the Table of the House.

(b), (c) and (d). The matter is being examined by Government.

Registered

Copy of letter No. Nil, dated 20.9.1964 from Shri Ram Piara Comrade, M.L.A. to the Excise and Taxation Commissioner, Punjab.

Subject—Un-fair selection of Taxation Sub Inspectors/Excise Sub Inspectors by the Subordinate Services Selection Board, Chandigarh.

On pain I am to say that the selection of Taxation Sub Inspectors/Excise Sub Inspectors by the Subordinate Services Selection Board, dated 11.8.1964 in which your representative also participated, in selection, is un-fair, unjustified and slur upon the administration. Such type of selection will badly damage efficiency in the officials discharge of duties. I have learnt that deputation in this connection has already met you and you have also made certain enquiries. If my information is correct and your enquiries support this contention then I would be justified in expecting from you a bold stand of writing the facts to the Government so, as to get the unfair changed into fairness. You will agree with me that some of the officials with unblemished record and of long service have been ignored whereas officials of spotted record and of less service have been selected. Such practice can no longer be appreciated. Will you please be so good enough to bring it to the notice of the Government and oblige.

Hoping to be favoured with a line of reply.

Thanking you.

Yours faithfully,

(Sd.) RAM PIARA, M.L.A.
Karnal.

Telephone No. 172.
L/309 Model Town,
Karnal.

September 20, 1964.

RAM PIARA COMRADE, M.L.A.

To

Comrade Ram Kishan,
Chief Minister, Punjab, Chandigarh.

Subject.—Un-fair selection of Taxation Sub-Inspectors/Excise Sub-Inspectors by the S.S.S. Board, Punjab, Chandigarh.

Dear Friend,

On pain I am to bring to your kind notice that the recent selection by the Subordinate Services Selection Board, interview of which was held on 11th August, 1964, has proved to be very un-fair and against all cannons of justice according to the best information received by me. This Subordinate Services Selection Board was constituted so as to eliminate chances of favouritism but this selection has proved that the Board has become institution of favouritism. In the past my faith had never been shakened as now perhaps it is due to the Chairmanship of S. Ujagar Singh. This Chairman Shri Ujagar Singh is well-known to every one and this appointment was no more a secret except the expression of ill intention of Shri Kairon. To ignore officials of integrity and long standing and selection of persons with blemished record and of few years standing is totally a bad picture painted with bad colour. In this way the efficiency in the offices is fastly disappearing and I am afraid it will further badly damage the efficiency if conditions are changed.

Let us make selection as a test case. If my above said contention is proved, this selection may please be cancelled and instead new is made on the basis of merits. this Board may be dissolved and members particularly Chairman of better Further integrity may kindly be nominated for which not only the services but the coming generation will be grateful to you.

Hoping to be favoured with a line in reply and oblige.

Thanking you.

Yours faithfully,

(Sd.) RAM PIARA, M.L.A.
Karnal.

[Education and Local Government Minister]

No. 11512-CMP-64/

Chandigarh dated the 26th September, 1964.

My Dear,

I have received your letter dated the 20th September, 1964, regarding unfair selection of Taxation Sub Inspectors/Excise Sub Inspectors by the Subordinate Services Selection Board and dissolution of the said Board. I am having the matter looked into.

With regards,

Yours sincerely,

(Sd/) RAM KISHAN.

Shri Ram Piara, M.L.A.,
L/309, Model Town,
Karnal.

No. 5690/E.IV.

Excise and Taxation Commissioner's Office, Patiala, dated the 26th September, 1964.

From
The Excise and Taxation Commissioner,
Punjab.

To
Shri Ram Piara Comrade, M.L.A.,
L/309, Model Town,
Karnal.

Subject.—Unfair selection of Taxation Sub-Inspectors/ Excise Sub-Inspectors by the Subordinate Services Selection Board, Punjab, Chandigarh.

SIR,

I am to acknowledge receipt of your letter, dated the 20th September, 1964, and to say that the matter is being examined.

Yours faithfully,

(Sd/-) R.P. OJHA,
Joint Excise and Taxation Commissioner,
Punjab.

REGISTERED

Copy of letter No. nil, dated 26th/28th December, 1964, from Shri Ram Piara Comrade, M.L.A. to the Excise and Taxation Commissioner, Punjab.

Subject.—Unfair selection of Taxation Sub-Inspectors etc. by the Subordinate Services Selection Board, Punjab.

Please refer to your letter No. 5690-E VI, dated the 26th September, 1964, which was received by me in response to my letter dated 20th September, 1964.

I am also thankful to the Chief Minister for his letter No. 11512-CM/64, dated the 26th September, 1964, on the same subject and in response to my same letter.

I presume that the matter must have been looked into but it appears to me that courage is not coming forward and you are changing your mind or have changed your mind due to the different type of pressure which you or the Government has not been able to resist.

There is a vast difference of Record between the selected and ignored, certainly good in a number of candidates ignored and bad in a number of candidates selected. Of course I fail to appreciate and you shall agree with me that none shall appreciate in case the facts come to the Notice of any one.

For God sake, do not allow yourself to be swayed by certain pressures. Truth and Moral values have a great force and the wrong always pricks. Deserving may have a deep sigh.

May I expect a line in reply and oblige.

Thanking you.

REGISTERED

Ram Piara Comrade, M.L.A.

Phone No. 172,
L/309 Model Town,
Karnal 26/28-12-1964.

To

The Excise and Taxation Commissioner,
Punjab, Patiala.

Subject.—Unfair selection of Taxation Sub-Inspectors etc., by the Subordinate Services Selection Board, Punjab.

DEAR SIR,

Please refer to your letter No. 5690-E-IV-dated the 26th September, 1964, which was received by me in response to my letter dated the 20th September, 1964.

I am also thankful to the Chief Minister for his letter No. 11512-CM/64, dated the 26th September, 1964, on the same subject and in response to my same letter.

I presume that the matter must have been looked into but it appears to me that courage is not coming forward and you are changing you mind or have changed your mind due to the different type of pressure which you or the Government has not been able to resist.

There is a vast difference of Record between the selected and ignored certainly good in a number of candidates ignored and bad in a number of candidates selected. Of course I fail to appreciate and you shall agree with me that none shall appreciate in case the facts come to the Notice of any one.

For God sake do not allow yourself to be swayed by certain pressures. Truth and moral values have a great force and the wrong always pricks. Deserving may have a deep sigh.

May I expect a line in reply and oblige.

Yours faithfully,

(Sd/) RAM PIARA, M.L.A.

Copy to :
Comrade Ram Kishan Ji,
Chief Minister.

S.L. Kapur, I.A.S.
Joint Excise and Taxation Commissioner,
Punjab (III).

D.O. No. 265/EIV.
Dated, Patiala, the 12th January, 1962.

DEAR SHRI,

Please refer to your letter No. Nil, dated the 28th December, 1964.

2. The matter regarding alleged unfair selection of Taxation Sub-Inspectors etc., by the Subordinate Services Selection Board, Punjab, has been examined carfrefully and action, as necessary, taken.

Yours sincerely,

(Sd/) S.L. Kapur,

Shri Ram Piara Comrade, M. L. A.
L/309, Model Town.
Karnal.

[Education and Local Government Minister]

Copy of letter No. Nil, dated 14th January, 1965, from Comrade Ram Piara, M.L.A., to the Excise and Taxation Commissioner, Punjab.

Subject. Unfair Selection of Taxation Sub-Inspectors, etc., by the Subordinate Services Selection Board, in consultation with your department.

I am in receipt of your letter No. 265/EIV, dated the 12th instant written by Shri S.L. Kapur, I.A.S., Joint Excise and Taxation Commissioner (III) and noted the contents with great surprise.

2. The language or the draft has very intelligently been drafted. At least it does not satisfy and I shall remain unsatisfied till you apprise me.

My query is very simple whether you find some faults, favouratism and unjustice in the selection or not. If you do not find any lapses, irregularities, then I have challenged the facts and would like to know whether you want the instances and in case you agree with my contention that lapses and favouritism did exist and those I would like to know the details or the action taken. If you or the Government has warned the Board for future and have not thought it fit to disturb the present selection then I may be informed accordingly. This may be treated as most urgent and I shall not appreciate to lose time in mere correspondence. Let us be straight forward and to be fair-minded whose right have been usurped.

Hoping to be favoured with an immediate reply and oblige.

Thanking you.

Copy of letter No. 6404, dated the 28th December, 1964, from Comrade Ram Piara M.L.A., addressed to the Chief Minister, Punjab.

DEAR FRIEND

I have learnt that the Excise and Taxation Commissioner has not been able to resist pressure. Such policy will shake the confidence and shall set a very bad example.

Your immediate attention is invited. On record I have good material.

Thanking you.

(Sd/-) RAM PIARA, M.L.A.

Comrade Ram Kishan Ji,
Chief Minister.

No. 16315-CMP-64

Chandigarh,
December, 30, 1964.

Subject.—Unfair selection of Taxation Sub-Inspectors, etc., by the Subordinate Services Selection Board, Punjab.

DEAR FRIEND,

I have received your letter of the 28th December, 1964, with which you have enclosed a copy of your letter dated 26th, 28th December, 1964, to the address of the Excise and Taxation Commissioner, Patiala, on the subject noted above. I am looking into the matter.

Yours sincerely,

(Sd.) RAM KISHAN

Comrade Ram Piara, M.L.A.,
Model Town,
Karnal.

Ram Piara Comrade.

L/309, Model Town,
Karnal, 23-1-1965.

To

Comrade Ram Kishan,
Chief Minister, Punjab,
Chandigarh.

Subject. Unfair selection of Taxation Sub-Inspectors/Excise Sub-Inspectors, etc., by the S.S.S. Board, in consultation with Excise and Taxation Department.

DEAR FIERND,

I would like to draw your kind attention towards your letter No. 16315-CMP-64, dated 30th December, 1964, in response to my letter, dated 28th December, 1964,

addressedto the Excise and Taxation Commissioner, Patiala. I presume that number of irregularities in selection must have cone to your notice.

I received a demi-official letter No. 265/E. IV, dated 12th January,1965, from Shri S.L. Kapur, Joint Excise and Taxation Commissioner, Patiala, which is re-produced as under:—

"The matter regarding the alleged selection of Taxation Sub-Inspectors, etc. by the Subordinate Services Selection Board, Punjab, has been examined carefully and action, as necessary, taken ."

This reply was and is very much surprising as it discloses nothing to me. I at once responded and wrote him a registered letter on 14th January, 1965, the reply of which is yet to be received.

According to the best of my information the Excise and Taxation Commissioner and the Government is fully convinced that the selection is unfair and the Department as well as the Subordinate Services Selection Board are responsible for this unfairness.

Now I have learnt that alround pressure are being thrown on the Government to accept this very selection as it is being pleaded that the department as well as the Board will get bad name.

I am afraid, justice will be hampered if the interest of any Officer or the Board is kept in view. Why the officials with clean and appreciative record and comparatively long service at their back should suffer for the miss doing of selection body.

I would suggest that the Government should be bold enough to take a just decision purely on merit being unmindful of the interest of any Officer of the Excise and Taxation Department and Subordinate Services Selection Board.

Side by side strict action against the wrong doers must be taken so as to create confidence amongst the services as well as public.

I am in a position to quote a number of examples in which underserving have been selected and deserving ignored.

Your won't mind if I am determined to make this as a test case.

Hoping to be favoured with an immediate reply and immediate action.

Thanking ou.

Yours faithfully,

(Sd.) RAM PIARA, M.L.A.,
Karnal.

Formation of New Sirsa District

***7210. Shri Jagan Nath :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal to create a new Sirsa District by bifurcating the existing Hissar District ; if so, the approximate time by which it is likely to be implemented ?

Sardar Harinder Singh Major : There is a proposal to create a new district with headquarters at Sirsa. As the question regarding fixing of exact limits of Sirsa District is yet to be finalised, it is not possible to fix the time by which the proposal will be implemented.

Unallotted Evacuee Land in the State

***7182. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of unallotted land in the State district-wise ;

(b) whether any area of the land referred to in part (a) above has been auctioned ; if so, the names of the persons, who purchased the said land and the area of land so purchased by each from July, 1964, to-date ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) A statement showing the total available rural evacuee land, in each district, as on 1st February, 1965, is placed on the Table of the House.

(b) The time and labour involved in the collection of this information will not be commensurate with the possible benefit to be derived.

STATEMENT

Serial No.	Name of the District		*Break-up of the surplus rural evacuee land available for disposal on 1st February, 1965*		
			Cultivated in Standard Acres	Banjar in Ordinary Acres	Ghairmumkin in Ordinary Acres
1	Amritsar	..	1,973	6,589	7,341
2	Ambala	..	2,970	2,013	3,431
3	Bhatinda	..	463	..	..
4	Ferozepore	..	14,580	13,678	18,000
5	Gurdaspur	..	2,918	4,329	12,211
6	Gurgaon	..	969	632	446
7	Hoshiarpur	..	Nil	688	4,036
8	Hissar	..	2,442	236	87
9	Jullundur	..	3,585	9,297	19,439
10	Kapurthala	..	2,355	5,900	11,140
11	Karnal	..	3,972	4,321	3,643
12	Kangra	..	131	1,882	336
13	Ludhiana	..	1,524	2,279	7,598
14	Mohindergarh	..	321	192	Nil
15	Patiala	..	14	606	828
16	Rohtak	..	825	578	2,076
17	Sangrur	..	735	538	274
18	Simla	..	Nil	Nil	Nil
	Total	..	39,777	53,758	90,886

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

Liquor Contracts

*7990. **Shri Balramji Dass Tandon** (Put by Dr. Baldev Parkash) : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the date when the system of allotment of liquor contracts in the State was changed to that of open auction ;

(b) the total amount of additional income which accrued to the Government as a result of the said change up-to-date ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of the Government to revert to the old system ; if so, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra : (a) 1st October, 1964.

(b) Rs 2,06,69,340 in the shape of license fee.

(c) No.

00P.M. **ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ** : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 6 ਲਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਠ ਦਸ ਆਨੇ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਪਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ: ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਈ ਆਕਸ਼ਨ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 6 ਲਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਸਤ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਕ ਬੋਤਲ ਜਿਨੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਤਲ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਤਲ ਪੁਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਭਾ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਵੇਚੇ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : वज़ीर साहिब ने अभी फरमाया है कि शराब पर सरकार को सिस्टम बदलने से आमदन ज़्यादा हुई है तो क्या शराब की दुकानों को कमशर्ल शाप्स ऐक्ट की ज़द से मुस्तसना इसी लिए किया गया है कि शराब की सेल को बढ़ाया जा सके या और कोई बात है ?

मन्त्री : गवर्नमेंट सेल को बढ़ाने में इन्ट्रैस्टिड नहीं। इस के बारे में सरकार के पास रिप्रेजन्टेशन्ज भी आई हुई हैं। इस लिये यह ख्याल था कि सरकार के पास रुपया ज्यादा आए, दुकानदारों के पास न चला जाए।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि बाबू बचन सिंह का यह सवाल था कि जितने रुपये में उनको शराब की एक बोतल पड़ती है उस पर तो वह बेच नहीं सकते तो क्या उन्हें पता है कि जो शराब आज कल बिक रही है उस के पीने में नशा कम होता है ? (हंसी)

श्री मोहन लाल दत्त : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि क्या सरकार की नीति रुपया कमाने की है या शराब को बन्द करने की भी है ? तरह तरह के तरीके आमदन बढ़ाने के सोचे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस से तो यह सवाल एराइज़ नहीं होता। (It does not arise out of the question.)

कामरेड राम प्यारा : क्या एजूकेशन मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि उन्होंने जो फरमाया है कि सिस्टम बदलने से गवर्नमेंट को फायदा हुआ है तो क्या जिन अफसरों ने सरकार के पुराने आक्शन के सिस्टम को उल्टा किया था ताकि चन्द पार्टीशनों को फायदा पहुंचाया जाए उन के खिलाफ कोई कारवाई और कोई इन्क्वायरी कराने का इरादा है ?

मन्त्री : इस तरह तो सारा वक्त ही इन्क्वायरियों में लग जाएगा। Government has no intention to hold such an enquiry. हम ने आफिसर्ज़ कनसर्न्ड को कहा था कि that it was a wrong decision. तो अफसरों ने इस बात को माना है कि that was a wrong decision.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਸਤਸਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਥੇ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜ਼ਦ ਤੋਂ ਮੁਸਤਸਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Expunction of Matter from the Proceedings of the House

Mr. Speaker : Since the hon. Minister for Education wants to go early, the Call Attention Motions, etc. will be taken up to-morrow. Now we will resume discussion on the Demands for Grants (71—Miscellaneous).

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to move—

> *That an obscene poster which was laid on the Table of the House by an hon. Member, Shri Mangal Sein be withdrawn and should not form part of the proceedings of this House.

---

*For previous reference please *see* Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I, No. 20, dated 24th March, 1965.

Mr. Speaker : I also agree that this should be expunged and accordingly it is expunged from the proceedings of the House.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, यह खुशी की बात है कि गवर्नमेंट के नोटिस में यह बात आई है और मैं इसे वैलकम करता हूं। लेकिन इस तरह के पोस्टर और तरह तरह की आबसीन लिट्रेचर इस सूबे में आती है जिस तरह कि आबजर्वर हिन्दी आब्जर्वर वगैरा। इसी तरह आज एक पोस्टर अपर हाउस के एक आनरेबल मेम्बर के बारे में बहुत वाहयात सा लिखा हुआ था और नाम ले कर कहा गया था तो इस की तरफ सरकार को सरगरमी से ध्यान देना चाहिए और ऐसी चीजों का सूबे में आना बन्द होना चाहिए

Mr. Speaker : I agree that some of the papers do publish obscene literature and I hope Government will take some action in this regard.

गृह तथा विकास मन्त्री (सरदार दरबारा सिंह) : जनाब स्पीकर साहिब, डाक्टर बलदेव प्रकाश ने बिलकुल सही सवाल उठाया है कि इस तरह के आबसीन इश्तिहार और बदइखलाकी पैदा करने वाले लिट्रेचर को सूबे में लाए जाने का तदारक करना चाहिए और खत्म करना चाहिए। अगर इस के बारे में एक्ट मौजूद है तो उस को सामने रख कर और अगर कोई तबदीली करनी पड़े तो तबदीली करके एकशन लेने के लिये कोइ न कोई जराये अख्तियार किए जाएंगे।

Demand for Grant

71—Miscellaneous

(*Resumption of Discussion*) (*concld.*)

Mr. Speaker : Now the House will resume discussion on the Demands for Grants (71—Miscellaneous) partcularly relating to the Local Government only. Earlier when the House rose, Sardar Ajaib Singh Sandhu was in its possession. He may resume his speech.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : (ਮੋਰਿੰਡਾ ਐਸ. ਸੀ.) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਖਰੜ ਦੀ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 12 ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪਾਈਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਜੀਨ ਨੂੰ ਤਰਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇ-ਟੂ-ਡੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਉਂਸਪਿਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰਜ਼ ਉਥੇ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 7/8 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਲਾਸ ਤਿੰਨ ਦੇ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੈਚੂਅਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 97/8 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਆਰਡਰਜ਼ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟੀਟੇਰੀਏਟ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਾਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ । ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਜੈਨੂਇਨ ਮਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 97/8 ਰੁਪਏ ਤਕ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜ ਦਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਟੈਪਸ ਉਠਾਉਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੇ। ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੀ. ਸੀ. ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2/- ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ 1/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20/- ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ....

डाक्टर बलदेव प्रकाश : On a point of order, Sir. आज के ऐजंडा के मुताबिक आईटम नं० 2 पर जो बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट है वह आनी चाहिये थी ।

श्री सपीकर : कयोंकि मनिसटर साहिब को जल्दी जाना था इस लिये आज एजंडे का नैकस्ट आईटम टेक अप कर लिया गया है। (The next item on the agenda has been taken up as the Minister had to leave early.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਰੈਸਟਹਾਉਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 97/8/- ਰੁਪਏ ਰੀਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਐਸੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਸ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਜ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਉਪਰ ਚਕਣ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਫਸਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਨੂੰ 97/8/- ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੇ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

कोई अच्छी नहीं है। इस लिये वहां की हालत को सुधारने के लिये पंजाब सरकार ने उस कमेटी को 6 लाख रुपया सालाना सहायता के रूप में देने का प्रबन्ध किया है।

स्पीकर साहिब, यहां पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की डिवैल्पमैंट के बारे में ज़िक्र किया गया। मुझे यह बात मानने में बिलकुल झिझक नहीं है कि वहां पर जो एपवायंटमेंट हुई वह पोलीटीकल बेसिज़ में हुई थी और उन के मुकाबले में अच्छे मेम्बर नामज़द किये जा सकते थे इस में सरकार की मजबूरी है। वह चाहे अच्छे लोग हों या न हों उन को सरकार किसी भी तरह से निकाल नहीं सकती है। अगर सरकार उन को निकालने के लिये कोई प्रबन्ध करे तो वह एकदम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर भी कोशिश की जाती है कि जिस आदमी को किसी तरह से फेवर करके लगाया गया हो, अगर उस में किसी तरह का कोई नुक्स सरकार के नोटिस में आ जाए तो उस के बरखिलाफ ऐक्शन लेते हैं और हटाने का कोशिश करते हैं। श्री फतेह चन्द विज ने पानीपत के बारे में ज़िक्र किया था। पहली इंस्टांस में मौका मिला और एस्टैबलिशमैंट बोर्ड ने कहा कि इस में एप्वायंटमेंट के वक्त पोलीटीकल कन्सिड्रेशन हुई। हम ने फौरन इन की बात मान ली। इन्होंने शिकायत की थी कि वह कुछ काम नहीं करता और उस को हटा दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में एक आर्डीनेंस इशू करें जिस में सरकार को पावर्ज़ मिल जाएं कि अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो उन को ससपैंड किया जाए और वहां पर अच्छे आदमी लगाएं जाएं। मेरी यह ख्वाहिश है। लेकिन अभी तक इस को मैं प्रैक्टीकल शेप नहीं दे सकता हूं। मैं चाहता हूं कि इन इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों में अच्छे अफसर—आई० ए० एस० या सीनियर पी. सी. एस. ग्रेडज़ के आदमी लगाए जाएं ताकि वह लोकल पालेटिक्स में न फंसें और शहरों में अच्छा काम कर सकें।

यहां पर भिवानी के आनरेबल मेंबर ने शिकायत की कि वहां पर ऐसे आदमी को लगाया गया जो कि उन के मुकाबले में इलैक्शन में खड़ा हुआ था। चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी इस बारे में कहा था कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन किसी पार्टी बेसिज़ पर नहीं लगाया जाना चाहिए और यह पोस्ट सिर्फ कांग्रेस वालों के लिये निश्चित नहीं की गई है। इस माननीय सदस्य ने हमें तीन चार बार लिखा और शिकायत भी की। हमारी यही कोशिश है कि जो अच्छे से अच्छा आदमी हो उस को लगाया जाए। पार्टी बेसिज़ का ख्याल नहीं रखा जाता है। मैं हाउस को सूचना देना चाहता हूं कि इस चैयरमैन के बारे में वहां के 10, 15 म्युनिसिपल कमिश्नरों ने शिकायत को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यह ठीक आदमी है और इस को ही लगे रहना देना चाहिए। इस के साथ ही वहां के तीन एम० एल० एज़० ने भी उसी आदमी के बारे में सिफारिश की है और एक एम० पी० ने भी उसी आदमी को रहने देने के बारे में कहा। यहां पर कहा गया कि उस आदमी को ज्यादा तनखाह देने का वायदा किया है। मैं इस बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस के लिये 800 रुपए तनखाह होती है जबकि उस को सिर्फ 600 रुपया दिया जाएगा। मुझे पता नहीं लगा कि माननीय सदस्यों को ज्यादा रुपए देने की सूचना कहां से मिली है।

श्री गुरांदास हंस ने कहा कि म्युनिसिपल कमेटियों को हिदायतें इशू की जानी चाहिएं कि वह अपने स्वीपर्ज़ को भी गवर्नमेंट के स्वीपर्ज़ के रेट्स दें। इस के बारे में मैं अर्ज़

[शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री]
करना चाहता हूं कि हम ने म्युनिसिपल कमेटियों को हिदायतें जारी कीं और उन को यह ग्रेडज़ लागू करने के लिये कहा लेकिन इस में वह हमें अपनी मजबूरी शो कर देते हैं। वह उस की ज़िम्मेदारी सरकार के ऊपर डालना चाहते हैं और इस के लिये रुपया मांगते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन को किसी न किसी तरह से परसुएड किया जाए ताकि वह ग्रेडज़ वहां पर लागू कर सकें। हम उन को आर्डर्ज़ तो इशू ह कर सकते हैं।

श्री फतेह चन्द विज : आन ए प्वायंट आफ इन्फर्मेशन, सर। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों कहा कि जिन शहरों में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं और वह तीन चार सालों से बेफायदा ही तनखाह ले रहे हैं उन को सस्पैंड करने के लिये सरकार कुछ सोच रही है। इस के मुताल्लिक सरकार का क्या विचार है?

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री : माननीय सदस्य की सब से बड़ी शिकायत तो दूर हो गई है। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है मैं उस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार के पास इस वक्त कोई कानून नहीं जिस के द्वारा उन को सस्पैंड कर सके या सुपरसीड कर सके। गवर्नमेंट चाहती है कि उन नाअहिल ट्रस्टों के प्रैजीडेंट को हटाया जा सके। गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है कि जिस तरह से म्युनिसिपल कमिश्नरों को सस्पेंड किया जाता है उसी तरह से इन को भी सस्पैंड किया जा सके। इन के विरुद्ध भी बाकायदा इंक्वायरी की जाए और अगर वह ठीक साबित हो जाए तो उस को हटा दिया जाए। इस पर हम विचार कर रहे हैं। श्री बलरामजी दास टंडन ने कहा कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को भी म्युनिसिपल कमेटियों में मिला दिया जाए। इस के बारे में हम सोच रहे हैं ताकि मिला देने से इकानोमी हो सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके।

यहां पर कहा गया कि म्युनिसिपल कमेटियों में चुनाव पूंजीपतियों के दवाब के कारण नहीं कराए जा रहे हैं। मैं अपने मोहतरिम दोस्त को कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अमीर और गरीब का कोई सवाल नहीं है। पिछली सरकार ने जिन बड़े २ इंडस्ट्रीयलिस्टों के दवाब में आकर उन को लाभ पहुंचाने के लिये लोकल टैक्स मुआफ कर दिये, इस सरकार ने पहला कदम यह उठाया है कि उन को उस वक्त जो रियायतें मिली थीं वह रियायतें वापस ले ली हैं। यही कारण है कि यहां पर कुछ दिन हुए फरीदाबाद नोटीफाइड एरिया कमेटी का ज़िक्र हुआ। उस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं उस कमेटी में कुछ इंडस्ट्रीयलिस्ट मैम्बर बन गए और इस तरह उन्होंने उस कमेटी के द्वारा लाभ उठाने की कोशिश की जिस से पांच लाख रुपये के करीब सालाना आमदनी कमेटी की घट गई और जिन लोगों को फायदा हो रहा था वे लोग शायद इस बात से नाराज़ हैं कि जो नई गवर्नमेंट आई है, जो रियायतें उन को दी गई थीं वह वापस ले ली गई हैं। गवर्नमेंट यह चाहती है कि गरीबों को ऊंचा उठाया जाए। हमारा नज़रिया यह बिल्कुल नहीं है कि अमीरों के इन्ट्रैस्टस को सामने रख कर कोई गलत बात करें। श्री मंगल सेन ने सोनीपत के किसी बड़े आदमी का ज़िक्र किया है तो मैं ने उन से कहा कि जिस म्युनिसीपल कमेटी को 50 हज़ार

या 25 हज़ार मिलते हों तो हम चाहते हैं कि उस से सैंकड़ों आदमियों की बेहतरी हो, सैनीटेशन बेहतर हो। आप देख लेंगे कि जो एक्सटैंनशन हम ने करनी है वह जल्दी ही कर देंगे चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो हम पर कोई असर नहीं होगा। बड़े आदमियों के इन्ट्रैस्ट्स को हम सामने नहीं रखेंगे बल्कि आप चंद ही महीनों में देखेंगे कि बड़े बड़े आदमियों को हम निचोड़ कर रख देंगे और गरीबों की मदद करेंगे। (चीअर्ज़)

श्री मोहन लाल दत्त : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। नंगल टाऊनशिप में नोटीफाईड एरिया कमेटी बहुत देर से बनी हुई है। वही मेम्बर और वही कमेटी हमेशा के लिये कायम रहेगी या आप पुराने मेम्बरों की जगह पर नई इलैक्टिव कमेटी बनाने के लिये तैयार हैं ?

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री : मैं ने गौतम जी से भी पूछा था कि अगर कोई अच्छा आदमी है तो उस को नामीनेट किया जाए। क्योंकि वैसे तो नोटीफाईड एरियाज़ की लिस्ट बनाने में और उन की जगह पर म्युनिसिपल कमेटी बनाने में देर लगेगी, अगर कोई ऐसा आदमी हो जो अच्छा हो और किसी को रिप्रिज़ैंटेशन न मिली हो तो उन को मैम्बर बनाया जा सकता है। चंद ही दिनों में फैसला हो जाएगा। मैं पंडित मोहन लाल जी और दूसरे एम. एल. एज़. साहिबान को पूछ लूंगा चाहे वे किसी भी धड़े के आदमी हों उन से इत्तलाह ले लेंगे।

बाबू बचन सिंह : क्या आप नोटीफाईड एरियाज़ को खत्म करने के हक में हैं ?

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री : जहां पर आबादी बढ़ गई है और कानून के मुताबिक वहां पर म्युनिसिपल कमेटी होनी चाहिये वहां पर कोशिश करेंगे कि जल्दी ही म्युनिसिपल कमेटी बना दी जाए। मगर इस में साल छ: महीने लग जाएं तो जो गलत आदमी पहले बैठे हुए हैं, जिन पर लोगों को विश्वास नहीं रहा या किसी की पूरी रिप्रिज़ैंटेशन नहीं हो रही बे न रहें इस लिये गवर्नमैंट ने फैसला किया है कि जब तक कमेटी नहीं बन जाती तब तक कोई अच्छा आदमी आगे आ जाए ताकि हर तबके के लोगों को पूरी नुमाइंदगी मिले.....

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : अगर कोई कमेटी ऐसा रेजोल्यूशन पास करती है कि वह अपने वर्कर्ज़ को ग्रैच्यूटी देगी तो क्या इस के लिये सरकार इजाज़त देने को तैयार है ?

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਰ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ ?

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री : जहां जहां पर होल टाईम चेयरमैन की ज़रूरत है वहां पर होल टाईम चेयरमैन रखे हुए हैं। कई जगहों पर एस. डी. ओज़. ही चेयरमैन के तौर काम करते हैं और कई जगहों पर आनरेरी आदमी ही काम करते हैं। अगर किसी जगह पर कोई आदमी होल टाईम चेयरमैन लगा हुआ है अगर उस को कार की ज़रूरत

[शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री]

है या अलाउंस की जरूरत है तो उस को कार अलाउंस दिया जाता है, मेरा ख्याल है कि एक आध बड़े बड़े शहरों के अलावा किसी जगह पर कार अलाउंस नहीं दिया जाता। दूसरी फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत को मद्देनजर रख कर दी जाती हैं। सरदार जसदेव सिंह संधू ने कहा है कि राजपुरा को नोटीफाईड एरिया से अमैलगेमेंट करने का फैसला हुआ लेकिन किसी पोलिटीकल वजह से नहीं किया जा रहा है। यह उन की गलत फ़हमी है। हम पूरी तेज़ी के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं और जल्दी ही इस काबिल हो जायेंगे कि दोनों कमेटियों को मिला कर इलैक्टिड कमेटी बना लें। ग्रैचूटी के बारे में अर्ज़ करूंगा कि हमारी भी यह खाहिश है कि हम उन की इक्तसादी हालत अच्छी कर सकें लेकिन जब वे एक चीज़ का फैसला कर देती हैं तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि बाकी की कमेटियों पर इस का क्या असर होगा। अगर एक कमेटी अमीर है और ग्रैचूटी का फैसला करती है तो उस का रद्दे-अमल यह होता है कि बाकी कमेटियों के एम्लाईज़ भी कहते हैं कि हमें भी ग्रैचूटी मिलनी चाहिये तो हम यह चीज़ जरूर सामने रखते हैं और बाद में फैसला देते हैं। ऐसा फैसला नहीं देते जिस से दूसरी कमेटी के सामने कुछ मुश्किलात पैदा हो जाएं। यह चंद चीजें हैं जो कि मेरे इल्म में लाई गई थीं उन का मैं ने जवाब दे दिया है। इस के अलावा भी अगर किसी मैम्बर साहिब को म्यूनिसिपल कमेटियों के ऐडमिनिट्रेशन के बारे में या गलत इन्टरफियरेंस के बारे में कुछ पता लगे या कोई शिकायत उन को ही, बड़े से बड़े अफसर के बारे में कोई शिकायत हो कि उस ने सिवाए इमानदारी और ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐक्सपीडिएंसी को सामने रखे किसी और नज़रिये से कोई फैसला दिया है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि चाहे कितना भी बड़ा अफसर क्यों न हो, चाहे उस की कितनी भी पुल होगी मुझ पर उस का कोई असर नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इनसाफ कर सकें और यह जो ज़िम्मेदारी हमें आप लोगों और इस पार्टी की बदौलत मिली है इस को पूरी तरह से निभाएं। मेरा नज़रिया यही है कि आपोज़ीशन गवर्नमेंट का एक बड़ी ही ज़रूरी विंग है। यह नहीं होगा कि चूंकि कोई आपोज़ीशन में है इस लिये उस की बात को न सुना जाए। उस पर पूरी तवज्जोह दी जाएगी। जो हमारी मुश्किलात होंगी उन को भी हम सामने रख देंगे। एक दूसरे को सुनने के बाद अगर हम एक दूसरे को कनविंस करवा सकें तो हम हर वक्त ऐडमिनिस्ट्रेशन में तबदीली लाने के लिये, जिस से कि इम्प्रूवमेंट हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला ही सके, बेहतरी हो सके, इस की कोशिश करेंगे। जनाबे आली, मैं एक बार फिर आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का टाईम दिया है।

Mr. Speaker : Now I will put the cut motions to this demand to the vote of the House.

1.00 p. m.

The first motion is in the name of Comrade Shamsher Singh Josh.
Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The Motion was lost

Mr. Speaker : The next is in the name of Chaudhri Ran Singh.
Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The Motion was lost

Mr. Speaker : The other is in the name of Sardar Pritam Singh Sahoke.

Sardar Pritam Singh Sahoke : Sir, I withdraw it.

Mr. Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw it ?

Voices : Yes.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 3,49,68,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66. in respect of charges under head 71—Miscellaneous.

(*Note.*—Discussion on the Local Government only).

The motion was carried.

SIXTH REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Mr. Speaker : I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in their Sixth Report in regard to the various business during the current Session.

The Committee met at 4.00 *P.M. on Wednesday, the* 24*th March,* 1965

The Committee, after some discussion, recommended that on the 9th April, 1965, the House shall adjourn to meet again on Monday, the 19th April, 1965, at 2.00 P.M. onwards to transact the business as follows :—

Monday, the 19th April Tuesday, the 20th April	(1) Motions regarding discussion of the First Annual Report of the Punjab Agricultural University for 1962-63 and any other Report relating to this University (Two hours) (2) Motions regarding discussion of the Annual Accounts of the Pepsu Road Transport Corporation for the year 1962-63 and any other Report relating to Transport (Two hours) (3) Motions regarding discussion of the Eleventh Annual Report and Accounts for the year ended 31st March, 1964 of the Punjab Financial Corporation and any other Report relating to the said Corporation (Two hours) (4) Discussion of the three Reports of the Committee of Privileges

[Mr. Speaker]

Wednesday, the 21st April ..	Motions regarding discussion of— (i) the Annual Administration Report for the year 1963-64 ; (ii) the Annual Statements of Accounts for the year 1959-60 and Audit Report thereon ; and (iii) the Annual Financial Statement (Budget Estimates) for the year 1965-66 and the Supplementary Budget Estimates for the year 1964-65 ; of the Punjab State Electricity Boaird (1½ days—to continue on the 23rd April,
Thursday, the 22nd April ..	Non-official business.
Friday, the 23rd April ..	(1) Business shown against the 21st April) to continue for half day. (2) Motions regarding discussion of the First Annual Report and Accounts of the Punjab Export Corporation Ltd., for the year 1963-64 (half day).
Saturday, the 24th April ..	Off day.
Sunday, the 25th April ..	Holiday.
Monday, the 26th April ..	Motions regarding discussion of the Code of conduct for Ministers (One day).
Tuesday, the 27th April Wednesday, the 28th April..	Motion under Rule 84 regarding follow up action on the Dass Report (Two days). (This will also cover the pending motion of Sarvshri Makhan Singh Tarsikka and Hardit Singh Bhathal, M.L.A's., on the subject).
Thursday, the 29th April ..	Non-official business
Friday, the 30th April ..	(1) Motions for the discussion of the Annual Report on the working of the Punjab Public Service Commission for the year 1963-64 (2) Discussion of the Annual Report of the Punjab Khadi and Village Industries Board for the year 1963-64

Saturday, the 1st May	..	Off day
Sunday, the 2nd May,	..	Holiday
Monday, the 3rd May	..	Business left over

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

प्रिंसिपल रला राम : स्पीकर साहिब, 19 अप्रैल से यह हाउस फिर बुलाया गया है। मेरी आपकी सेवा में निवेदन है कि महात्मा हंस राज की सैंटीनरी 19 अप्रैल को है। अगर अभी इसका फैसला हो जाए तो अच्छा है ताकि बाद में तब्दीली न करनी पड़े।

श्री अध्यक्ष : वह तो आखिर कमेटी में आएगा।

(This matter will come before the committee.)

बाबू बचन सिंह : बात यह है कि हम छुट्टियां मनाने के बहुत ज्यादा आदि हो गए हैं। बात बात पे हम छुट्टी मनाने का जिक्र करते हैं। इस वक्त ज़रूरत देश को यह है कि हम लैजिस्लेटर्ज़ इस बात का सबूत दें कि हम दूसरों से ज्यादा मेहनत करते हैं और कर रहे हैं। मैं ने यह देखा है और अमली सबूत है, कि हम आज दो मीटिंग्ज़ कर रहे हैं। हमें इस बात के लिये तैयार होना चाहिये कि जो गज़ेटिड हौलीडेज़ हैं उनके बगैर कोई छुट्टी नहीं करनी चाहिये, सिवाए शनिवार के। अगर आप इस तरह छुट्टियां करेंगे तो हम बैड प्रैसिडैन्ट कायम करेंगे। जो मोशन आई है उसके मुताबिक करना चाहिये।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मैं तो यह पूछता हूं कि क्या 3 मई के बाद भी सैशन चलेगा ?

श्री अध्यक्ष: ख्याल है कि नहीं। (I think the Session will not go beyond that date).

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

The motion was adopted.

Demand for Grants

28—EDUCATION

Education and Local Government Minister (Shri Prabodh Chandra) : Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs 20,11,13,180 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66 in respect of charges under head 28—Education.

Mr. Speaker : Motion moved :—

That a sum not exceeding Rs 20,11,13,180 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66 in respect of chargss under head 28—Education.

The cut motions received from the various Members to this Demand shall be deemed to have been read and moved and may be discussed along with the Demand.

DEMAND NO. 16

(28—Education)

1. **Comrade Babu Singh Master :**

That the demand be reduced by Rs 100.

2. **Sardar Pritam Singh Sahoke :**

That the demand be reduced by Rs 100.

3. **Shri Ramsaran Chand Mittal :**

That the demand be reduced by Rs 100.

4. **Principal Rala Ram :**

That the demand be reduced by Re 1.

5. **Shri Rup Singh Phul :**

That the demand be reduced by Re 1.

6. **Shri Roop Lal Mehta :**

That the demand be reduced by Re 1.

7. **Chaudhri Ram Singh :**

That the demand be reduced by Re 1.

प्रिंसिपल रला राम (मुकेरियां) : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं गवर्नमैन्ट को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि ऐजुकेशन के लिये जो रुपया अलाट होता है वह . . . .

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ।

Mr. Speaker : The Chief Parliamentary Sectretary is there. ऐसा नज़र आता है कि अगर हाउस ठीक चलने लगे तो कुछ सुस्ती आ जाती है। देखिए Chief Parliamentary Secretary can represent the Government. (The Chief Parliamentary Secretary is there. It appears that when there is a smooth sailing in the House, some slackness sets in. I think the Chief Parliamentary Secretary can represent the Government.)

PUS.

REGISTERED

Ram Piara Comrade, M.L.A.

Phone No. 172,
L/309 Model Town,
Karnal 26/28-12-.964.

To

The Excise and Taxation Commissioner,
Punjab, Patiala.

Subject.—Unfair selection of Taxation Sub-Inspectors etc., by the Subordinate Services Selection Board, Punjab.

DEAR SIR,

Please refer to your letter No. 5690-E- IV-dated the 26th September, 1964, which was received by me in response to my letter dated the 20th September, 1964.

I am also thankful to the Chief Minister for his letter No. 11512-CM/64, dated the 26th September, 1964, on the same subject and in response to my same letter.

I presume that the matter must have been looked into but it appears to me that courage is not coming forward and your are changing you mind or have changed your mind due to the different type of pressure which you or the Government has not been able to resist.

There is a vast difference of Record between the selected and ignored certainly good in a number of candidates ignored and bad in a number of candidates selected. Of course I fail to appreciate and you shall agree with me that none shall appreciate in case the facts come to the Notice of any one.

For God sake do not allow yourself to be swayed by certain pressures. Truth and moral values have a great force and the wrong always pricks. Deserving may have a deep sigh.

May I expect a line in reply and oblige.

Yours faithfully,

(Sd/) RAM PIARA, M.L.A.

Copy to :
Comrade Ram Kishan Ji,
Chief Minister.

S.L. Kapur, I.A.S.
Joint Excise and Taxation Commissioner,
Punjab (III).

D.O. No. 265/EIV.
Dated, Patiala, the 12th January, 1962.

DEAR SHRI,

Please refer to your letter No. Nil, dated the 28th December, 1964.

2. The matter regarding alleged unfair selection of Taxation Sub-Inspectors etc., by the Subordinate Services Selection Board, Punjab, has been examined cafrefully and action, as necessary, taken.

Yours sincerely,

(Sd/) S.L. Kapur,

Shri Ram Piara Comrade, M. L. A.
L/309, Model Town,
Karnal.

[Education and Local Government Minister]

Copy of letter No. Nil, dated 14th January, 1965, from Comrade Ram Piara, M.L.A., to the Excise and Taxation Commissioner, Punjab.

Subject. Unfair Selection of Taxation Sub-Inspectors, etc., by the Subordinate Services Selection Board, in consultation with your department.

I am in receipt of your letter No. 265/EIV, dated the 12th instant written by Shri S.L. Kapur, I.A.S., Joint Excise and Taxation Commissioner (III) and noted the contents with great surprise.

2. The language or the draft has very intelligently been drafted. At least it does not satisfy and I shall remain unsatisfied till you apprise me.

My query is very simple whether you find some faults, favouratism and unjustice in the selection or not. If you do not find any lapses, irregularities, then I have challenged the facts and would like to know whether you want the instances and in case you agree with my contention that lapses and favouritism did exist and those I would like to know the details or the action taken. If you or the Government has warned the Board for future and have not thought it fit to disturb the present selection then I may be informed accordingly. This may be treated as most urgent and I shall not appreciate to lose time in mere correspondence. Let us be straight forward and to be fair-minded whose right have been usurped.

Hoping to be favoured with an immediate reply and oblige.

Thanking you.

Copy of letter No. 6404, dated the 28th December, 1964, from Comrade Ram Piara M.L.A., addressed to the Chief Minister, Punjab.

DEAR FRIEND

I have learnt that the Excise and Taxation Commissioner has not been able to resist pressure. Such policy will shake the confidence and shall set a very bad example.

Your immediate attention is invited. On record I have good material.

Thanking you.

(Sd/-) RAM PIARA, M.L.A.

Comrade Ram Kishan Ji,
Chief Minister.

No. 16315-CMP-64

Chandigarh,
December, 30, 1964.

Subject.—Unfair selection of Taxation Sub-Inspectors, etc., by the Subordinate Services Selection Board, Punjab.

DEAR FRIEND,

I have received your letter of the 28th December, 1964, with which you have enclosed a copy of your letter dated 26th, 28th December, 1964, to the address of the Excise and Taxation Commissioner, Patiala, on the subject noted above. I am looking into the matter.

Yours sincerely,

(Sd.) RAM KISHAN

Comrade Ram Piara, M.L.A.,
Model Town,
Karnal.

Ram Piara Comrade.

L/309, Model Town,
Karnal, 23-1-1965.

To

Comrade Ram Kishan,
Chief Minister, Punjab,
Chandigarh.

Subject. Unfair selection of Taxation Sub-Inspectors/Excise Sub-Inspectors, etc., by the S.S.S. Board, in consultation with Excise and Taxation Department.

DEAR FIERND,

I would like to draw your kind attention towards your letter No. 16315-CMP-64, dated 30th December, 1964, in response to my letter, dated 28th December, 1964,

addressedto the Excise and Taxation Commissioner, Patiala. I presume that number of irregularities in selection must have cone to your notice.

I received a demi-official letter No. 265/E. IV, dated 12th January,1965, from Shri S.L. Kapur, Joint Excise and Taxation Commissioner, Patiala, which is re-produced as under:—

"The matter regarding the alleged selection of Taxation Sub-Inspectors, etc. by the Subordinate Services Selection Board, Punjab, has been examined carefully and action, as necessary, taken ."

This reply was and is very much surprising as it discloses nothing to me. I at once responded and wrote him a registered letter on 14th January, 1965, the reply of which is yet to be received.

According to the best of my information the Excise and Taxation Commissioner and the Government is fully convinced that the selection is unfair and the Department as well as the Subordinate Services Selection Board are responsible for this unfairness.

Now I have learnt that alround pressure are being thrown on the Government to accept this very selection as it is being pleaded that the department as well as the Board will get bad name.

I am afraid, justice will be hampered if the interest of any Officer or the Board is kept in view. Why the officials with clean and appreciative record and comparatively long service at their back should suffer for the miss doing of selection body.

I would suggest that the Government should be bold enough to take a just decision purely on merit being unmindful of the interest of any Officer of the Excise and Taxation Department and Subordinate Services Selection Board.

Side by side strict action against the wrong doers must be taken so as to create confidence amongst the services as well as public.

I am in a position to quote a number of examples in which underserving have been selected and deserving ignored.

Your won't mind if I am determined to make this as a test case.

Hoping to be favoured with an immediate reply and immediate action.

Thanking ou.

Yours faithfully,

(Sd.) RAM PIARA, M.L.A.,
Karnal.

Formation of New Sirsa District

***7210. Shri Jagan Nath :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal to create a new Sirsa District by bifurcating the existing Hissar District ; if so, the approximate time by which it is likely to be implemented ?

Sardar Harinder Singh Major : There is a proposal to create a new district with headquarters at Sirsa. As the question regarding fixing of exact limits of Sirsa District is yet to be finalised, it is not possible to fix the time by which the proposal will be implemented.

Unallotted Evacuee Land in the State

***7182. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of unallotted land in the State district-wise ;

(b) whether any area of the land referred to in part (a) above has been auctioned ; if so, the names of the persons, who purchased the said land and the area of land so purchased by each from July, 1964, to-date ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) A statement showing the total available rural evacuee land, in each district, as on 1st February, 1965, is placed on the Table of the House.

(b) The time and labour involved in the collection of this information will not be commensurate with the possible benefit to be derived.

STATEMENT

Serial No.	Name of the District	*Break-up of the surplus rural evacuee land available for disposal on 1st February, 1965*		
		Cultivated in Standard Acres	Banjar in Ordinary Acres	Ghairmumkin in Ordinary Acres
1	Amritsar ..	1,973	6,589	7,341
2	Ambala ..	2,970	2,013	3,431
3	Bhatinda ..	463	..	..
4	Ferozepore ..	14,580	13,678	18,000
5	Gurdaspur ..	2,918	4,329	12,211
6	Gurgaon ..	969	632	446
7	Hoshiarpur ..	Nil	688	4,036
8	Hissar ..	2,442	236	87
9	Jullundur ..	3,585	9,297	19,439
10	Kapurthala ..	2,355	5,900	11,140
11	Karnal ..	3,972	4,321	3,643
12	Kangra ..	131	1,882	336
13	Ludhiana ..	1,524	2,279	7,598
14	Mohindergarh ..	321	192	Nil
15	Patiala ..	14	606	828
16	Rohtak ..	825	578	2,076
17	Sangrur ..	735	538	274
18	Simla ..	Nil	Nil	Nil
	Total ..	39,777	53,758	90,886

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

Liquor Contracts

*7990. **Shri Balramji Dass Tandon** (Put by Dr. Baldev Parkash) : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the date when the system of allotment of liquor contracts in the State was changed to that of open auction ;

(b) the total amount of additional income which accrued to the Government as a result of the said change up-to-date ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of the Government to revert to the old system ; if so, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra : (a) 1st October, 1964.

(b) Rs 2,06,69,340 in the shape of license fee.

(c) No.

3-00P.M. ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 6 ਲਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਠ ਦਸ ਆਨੇ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਪਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ: ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਈ ਆਕਸ਼ਨ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 6 ਲਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਸਤ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਕ ਬੋਤਲ ਜਿਨੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਤਲ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਤਲ ਪੁਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਭਾ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੇਚੇ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : वज़ीर साहिब ने अभी फरमाया है कि शराब पर सरकार को सिस्टम बदलने से आमदन ज़्यादा हुई है तो क्या शराब की दुकानों को कमर्शल शाप्स ऐक्ट की ज़द से मुस्तसना इसी लिए किया गया है कि शराब की सेल को बढ़ाया जा सके या और कोई बात है ?

मन्त्री : गवर्नमेंट लेवल को बढ़ाने में इन्ट्रेस्टिड नहीं। इस के बारे में सरकार के पास रिप्रेज़न्टेशन्ज़ भी आई हुई हैं। इस लिये यह ख्याल था कि सरकार के पास रुपया ज्यादा आए, दुकानदारों के पास न चला जाए।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि बाबू बचन सिंह का यह सवाल था कि जितने रुपये में उनको शराब की एक बोतल पड़ती है उस पर तो वह बेच नहीं सकते तो क्या उन्हें पता है कि जो शराब आज कल बिक रही है उस के पीने में नशा कम होता है ? (हंसी)

श्री मोहन लाल दत : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि क्या सरकार की नीति रुपया कमाने की है या शराब को बन्द करने की भी है ? तरह तरह के तरीके आमदन बढ़ाने के सोचे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस से तो यह सवाल एराइज़ नहीं होता। (It does not arise out of the question.)

कामरेड राम प्यारा : क्या एजूकेशन मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि उन्होंने जो फरमाया है कि सिस्टम बदलने से गवर्नमेंट को फायदा हुआ है तो क्या जिन अफसरों ने सरकार के पुराने आक्शन के सिस्टम को उलटा किया था ताकि चन्द पार्टीज़/शनों को फायदा पहुंचाया जाए उन के खिलाफ कोई कारवाई और कोई इन्क्वायरी कराने का इरादा है ?

मन्त्री : इस तरह तो सारा वक्त ही इन्क्वायरियों में लग जाएगा। Government has no intention to hold such an enquiry. हम ने आफिसर्ज़ कन्सर्न्ड को कहा था कि that it was a wrong decision. तो अफसरों ने इस बात को माना है कि that was a wrong decision.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਸਤਸਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਥੇ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜ਼ਦ ਤੋਂ ਮੁਸਤਸਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Expunction of Matter from the Proceedings of the House

Mr. Speaker : Since the hon. Minister for Education wants to go early, the Call Attention Motions, etc. will be taken up to-morrow. Now we will resume discussion on the Demands for Grants (71—Miscellaneous).

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to move—

*That an obscene poster which was laid on the Table of the House by an hon. Member, Shri Mangal Sein be withdrawn and should not form part of the proceedings of this House.

---

*For previous reference please *see* Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I, No. 20, dated 24th March, 1965.

Mr. Speaker : I also agree that this should be expunged and accordingly it is expunged from the proceedings of the House.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, यह खुशी की बात है कि गवर्नमेंट के नोटिस में यह बात आई है और मैं इसे वेलकम करता हूं। लेकिन इस तरह के पोस्टर और तरह तरह का आबसीन लिट्रेचर इस सूबे में आता है जिस तरह कि आबजर्वर हिन्दी आबजर्वर वगैरा। इसी तरह आज एक पोस्टर अपर हाउस के एक आनरेबल मेम्बर के बारे में बहुत वाहियात सा लिखा हुआ था और नाम ले कर कहा गया था। तो इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसी चीजों का सूबे में आना बन्द होना चाहिए।

Mr. Speaker : I agree that some of the papers do publish obscene literature and I hope Government will take some action in this regard.

गृह तथा विकास मन्त्री (सरदार दरबारा सिंह) : जनाब स्पीकर साहिब, डाक्टर बलदेव प्रकाश ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि इस तरह के आबसीन इश्तिहार और बदइखलाकी पैदा करने वाले लिट्रेचर का सूबे में लाए जाने का तदारक करना चाहिए और खत्म करना चाहिए। अगर इसके बारे में एक्ट मौजूद है तो उसको सामने रख कर और अगर कोई तबदीली करनी पड़े तो तबदीली करके एक्शन लेने के लिये कोई न कोई जराये अख्तियार किए जाएंगे।

Demand for Grant

71—Miscellaneou;

(*Resumption of Discussion*) (*concld.*)

Mr. Speaker : Now the Ho s will resume discussion on the Demands for Gra ts (71—Miscellaneou) partcularly relatin to the Loc l Governme t only. Earlier when the Hou e rose, Sardar Ajaib Singh Sandhu was in its possessio . H may esu ne his speech.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : (ਮੋਰਿੰਡਾ ਐਸ. ਸੀ.) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਖਰੜ ਦੀ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 12 ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪਾਈਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਜੀਨ ਨੂੰ ਤਰਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇ-ਟੂ-ਡੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਉਂਸਪਿਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਨਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰਜ਼ ਉਥੇ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 7/8 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਲਾਸ ਤਿੰਨ ਦੇ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੈਚੂਅਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 97/8 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਆਰਡਰਜ਼ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟੀਟੇਰੀਏਟ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਾਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਜੈਨੂਇਨ ਮਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 97/8 ਰੁਪਏ ਤਕ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜ ਦਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਟੈਪਸ ਉਠਾਉਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੇ। ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੀ. ਸੀ. ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2/– ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ 1/– ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20/– ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ....

डाक्टर बलदेव प्रकाश : On a point of order, Sir. आज के ऐजंडा के मुताबिक अ ईटम नं० 2 पर जो बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट है वह आनी चाहिये थी।

श्री सपीकर : क्योंकि मनिसटर साहिब को जल्दी जाना था इस लिये आज एजंडे का नैकस्ट आईटम टेक अप कर लिया गया है। (The next item on the agenda has been taken up as the Minister had to leave early.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਰੈਸਟਹਾਉਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 97/8/- ਰੁਪਏ ਰੀਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਐਸੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਜ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਉਪਰ ਚਕਣ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਫਸਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਨੂੰ 97/8/- ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੇ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

श्री बलराम जी दास टंडन : चीफ पार्लियमैन्टरी सैक्रेटरी मिनिस्टर की जगह नहीं, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करता है।

Mr. Speaker : The Chief Parliamentary Secretary can represent the Government. Of course, it is desirable that one of the Ministers should be there.

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਇਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : Order, order. The Chief Parliamentary Secretary has already sent some message.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। जैसे ऐजुकेशन डिपार्टमैन्ट में स्कूलों के बच्चे मास्टर से इजाजत लेते हैं कि पेशाब करने जाना है या पानी पीने जाना है, क्या एजुकेशन मिनिस्टर साहिब भी आप से या हाउस से इजाजत ले कर गए हैं बाथरूम जाने के लिये ?

Mr. Speaker : He has gone out with some other purpose.

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहिब, यह दरुस्त है कि चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेट्री साहिब बैठे हैं, लेकिन आपके ही जिम्मे है इस सदन की इज्जत रखना। बजट की डिस्कशन हो और मन्त्री महोदय यहां न हों, मन्त्री मण्डल का एक भी मैम्बर न हो यह बेइज्जती है। मेरी आप से दरखास्त है कि मन्त्री महोदय को बुलवा लें।

Mr. Speaker : Shri Garg, keeping in view the feelings of the House you may request one of the a Ministers to be here.

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी: स्पीकर साहिब, आपने एक रूलिंग दी है कि चीफ पार्लियमेंट्री सेक्रेट्री गवर्नमैन्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन यह डिजायरेबल है कि कोई कैबिनेट का मैम्बर यहां हाजर हो। आपकी रूलिंग के बाद भी क्या यह आपकी रूलिंग को चैलेंज कर सकते हैं ?

डाक्टर बलदेव प्रकाश: स्पीकर साहिब, हाउस के अन्दर आगे भी ऐसी हालत एक दो दफा पैदा हुई और आपने खुद उस वक्त यह रूलिंग दी और मिनिस्टर को बुलावा भेजा।

(At this stage the Public Works Minister entered the House)

श्री अध्यक्ष : आप की बात मानी गई, Chaudhri Rizak Ram has come. (Your request has been granted Chaudhri Rizak Ram has come.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आगे से कोई ऐसी बात न हो। इतनी इम्पार्टेंट चीज डिस्कस हो रही हो और कोई भी कैबिनेट का मैम्बर मोजूद न हों तो प्वायंट्स आफ आर्डर रेज करने में आध घंटा लग जाता है। आपको चाहिये कि जब कोई मिनिस्टर न हो तो 10 या 15 मिनट के लिये हाऊस एडजर्न कर दें ताकि इनको सबक मिल जाये।

Mr. Speaker : Please take your seat.

प्रिंसिपल रला राम (: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात.......

श्रीमती सरला देवी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं आप से यह रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि इस वक्त हाऊस के सामने ऐजुकेशन की डीमांड पेश है और शिक्षा मन्त्री यहां पर हाजिर नहीं हैं और सिर्फ लोक कार्य मन्त्री हैं। इस वक्त इरीगेशन का मसला तो हाउस के सामने है नहीं जो यह कुछ इस बारे में नोट कर सकेंगे। हम सब ने अपने अपने इलाकों की डिमांड्ज़ पेश करनी हैं, उन का कोई फायदा नहीं होगा, अगर यहां पर शिक्षा मन्त्री हाजिर नहीं होंगे। इस लिये उन को यहां ज़रूर हाज़िर रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपोजीशन वालों का काम है आप उन पर ही रहने दीजिये। आप किस चक्र में पड़ गई हैं ? The hon. Lady Member cannot bind the Government like this. (It is for the Opposition to say. Please leave it to them Why has the hon. Lady Member enteredin to this controversy ? She cannot bind the Government like this.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि आप ने जो श्रीमती सरला देवी से, जब वे अपने प्वायंट आफ आर्डर पर बोल रही थीं, यह कहा है कि यह तो आपोजीशन वालों का काम है आप किस चक्र में पड़ गई हैं तो आपके ख्याल में हाउस की डिग्निटी को बढ़ाने वाले सिर्फ ट्रैज़री बैंचों वाले मैम्बर ही होते हैं और आपोजीशन के मैम्बर हाउस की डिग्निटी को क्या नहीं बढ़ाते हैं? आपके इस तरह कहने के दो मतलब हो सकते हैं एक तो यह कि आप वाकया ही ऐसा ही ख्याल रखते हैं या आप ने यह हियूमरसली कहा है।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि एक ही मसले पर जब डाक्टर बलदेव प्रकाश ने और श्रीमती सरला देवी दोनों ने प्वायंट आफ आर्डर रेज़ कर दिया तो यह मैं ने श्रीमती सरला देवी को हियूमरस वे में कह दिया था। जब आप ने प्वायंट आफ आर्डर रेज़ किया हुआ था और उन्होंने उसे रिपीट कर दिया तो मुझे यह कहना पड़ा वैसे मेरा कोई और मकसद नहीं था That was my purpose (The hon. Member Dr. Baldev Parkash and the hon. Lady Member Shrimati Sarla Devi raised their points of order on one and the same issue and I said this thing to Shrimati Sarla Devi in a humorous way. The hon. Member had raised the point of order and the hon. Lady Member repeated that. That is why I made these remarks otherwise I had no other purpose.)

That was my purpose.

(इस वक्त चेयर के पीछे डायस पर उपाध्यक्षा एक कुरसी पर जा कर बैठ गईं।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या एक ही वक्त स्पीकर साहिब के मंच पर स्पीकर साहिब और डिप्टी स्पीकर साहिबा दोनों जलवाफरोज़ हो सकते हैं ? (हंसी)।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪਵਾਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਕੇਬੀਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਆਪ ਰੂਲਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

Mr. Speaker : My previous ruling stands. The Chief Parliamentary Secretary technically represents the Government. It is, however, desirable that one of the Ministers should be present in the House.

प्रिंसिपल रला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये गवर्नमैन्ट को बधाई देता हूं जो वह ऐजुकेशन के महत्व को देख कर साल साल इस मद्द के लिये ज्यादा रुपया अलाट करती है लेकिन मैं आप के द्वारा अध्यक्ष महोदय सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह जो 20 करोड़ 11 लाख रुपये की रकम एजुकेशन के लिये रखी है यह बिल्कुल इनएडीकुएट है और नाकाफी है। अगर हालात को देखा जाये तो कहा जा सकता है कि एजूकेशन. . .

[*Deputy Speaker in the Chair.*]

(At this stage Shri Balramji Das Tandon went to the Minister for Public Works and Welfare and began to discuss something with him.)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ . . . .

उपाध्यक्षा : टंडन साहिब, आप अपनी सीट पर चलें जायें। (I request Shri Balramji Das Tandon to go to his seat.)

प्रिंसीपल रला राम : उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह कह रहा था कि 20 करोड़ और 11 लाख रुपये की रकम जो इस मद्द के लिये रखी गई है यह बिल्कुल नाकाफी है और यह इस लिये है क्योंकि जो इस वक्त हमारे सूबे का बजट है वह एक अरब और 29 करोड़ के करीब रकम का है और अगर इस मद की प्रसैंटेज वर्कआऊट की जाये तो यह साढ़े सोलह प्रसैन्ट बनती है जो मैं अर्ज करता हूं कि बिल्कुल नाकाफी है क्योंकि इस में जनरल ऐजूकेशन का खर्च और टैक्नीकल ऐजुकेशन के खर्च दोनों ही शामल हैं। दुनिया में जो प्रोग्रैसिव स्टेटस हैं जैसे यू. ऐस. ऐस. आर. और यू. एस. ए. हैं वे सब अपने बजट का 33 प्रसैंट से लेकर 40 प्रसैंट तक खर्च करती हैं। यह ठीक है कि हमारा देश बड़ा गरीब देश है और इतना खर्च करना एफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन इस का मतलब यह नहीं कि एजुकेशन स्टारवड रहे। यह ठीक है कि इस साल ऐजूकेशन के लिये पिछले साल के बजट के मुकाबले में 1 करोड़ 27 लाख रुपये का इजाफा किया गया है क्योंकि इस साल 20 करोड़ 11 लाख रुपये की रकम रखी गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल नाकाफी है। उपाध्यक्ष महोदया, इस की वजह मैं आप के द्वारा सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। 1957-58 में हमारे राज्य में जो सारे विद्यार्थियों की तादाद थी वह 19 लाख थी और 1962-63

[प्रिंसिपल रला राम]

में यह फिगर्ज जो डिपार्टमैन्ट ने दी हैं उन के मुताबिक 20 लाख से कुछ ज्यादा हो गई थी यानी पांच छः सालों में यह दस लाख बढ़ गई थी और 1962-63 के बाद अब दो साल और बीत चुके हैं तो यह संख्या और बढ़ कर मेरा ख्याल है 33 लाख से कम नहीं हुई होगी। इस लिये आप देखें कि जिस रफतार के साथ और जिस कदम के साथ पढ़ने वाले लड़कों की तादाद स्कूलों और कलेजों में बढ़ रही है उसी मिक्दार से हमारी गवर्नमैन्ट एजूकेशन के लिये रुपया फाइण्ड आऊट नहीं कर रही है इस लिये मैं आप के जरिये यह कहना चाहता हूं कि यह जो 20 करोड़ 11 लाख रुपया रखा गया है यह बिल्कुल नाकाफी है। और यह किसी सूरत में भी 25 प्रसैन्ट से कम नहीं रखना चाहियें। उपाध्यक्ष महोदया, आप भी समाचार पत्र पढ़ती हैं और आप ने कई बार पढ़ा होगा कि हमारे जो पब्लिक लीडरज़ हैं और पोलिटीकल लीडर्ज़ प्लेटफार्म्ज़ पर और समाचार पत्रों में हमेशा कहते रहते हैं कि हमारी शिक्षा का जो ढांचा है वह नातसल्लीबख्श है। एक तरफ तो हम कहते रहते हैं कि शिक्षा का जो ढांचा है वह ना तसल्लीबख्श है और दूसरी तरफ उसी ढांचे को ही चला रहे हैं। इस चीज़ के दो पहलू हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है वह ठीक हो दूसरा पहलू यह है कि जो इस के लिये रुपया फाइंड आऊट होना चाहिये अगर हम वह फाइंड आऊट नहीं करेंगे तो महज़ यह कहना कि यह गैरतसल्लीबख्श है इस से यह तसल्लीबख्श नहीं हो जायेगा। इस तरह से मैटरज़ जो हैं वह मैन्ड नहीं होंगे और हालात बेहतर नहीं होंगे। इस लिये मैं अपनी कैबिनेट के जो मैम्बर्ज़ हैं उन से कहूंगा कि इस तरह से कहे जाना कि यह ढांचा जो है यह नातसल्लीबख्श है और सारे हिन्दुस्तान के लीडरज़ भी यही कहें कि एजुकेशन का जो हमारा ढांचा है वह नातसल्लीबख्श है और इसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से यह बेहतर होने वाला नहीं है। कौन कहता है कि आज़ाद हिन्दुस्तान में इस को तसल्लीबख्श न बनाओ अंग्रेज़ के वक्त तो रुकावट हो सकती थी लेकिन अब क्या रुकावट हो सकती है। अब हम जैसा चाहें वैसा इस को कर सकते हैं। इस तरह से रिपीट करते जाना कि हमारे लिए शोभा नहीं देता कि यह ना तसल्लीबख्श है। अगर गैर तसल्लीबख्श है तो इसे तसल्ली बख्श बनाओ। बात यह है जैसा कि जर्मनी के मशहूर फिलासफर गेटे ने कहा है :—

"To think is hard and to act is easy."

जब हम एक दफा सोच लें विचार लें कि इस ढंग से चलना है तो फिर काम आसान हो जाता है। यही कमी है कि हम ने अभी तक पूरी तरह से इस बारे में विचार नहीं किया। मैं समझता हूं कि बीस करोड़ की जो रकम है यह बिल्कुल नाकाफी है क्योंकि पिछले 6, 7 सालों में विद्यार्थियों की तादाद इतनी बढ़ी है कि उन को ऐफीशैंटली शिक्षा देने के लिये यह रकम नाकाफी है। उपाध्यक्षा महोदया......

(इस समय कुछ सदस्य मंत्री महोदय से बातें करते हुए देखे गए)

खान अब्दुल गफार खां : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। अर्ज़ यह है कि यह इतना अहम मसला है और प्रिंसीपल साहिब निहायत खूबसूरती के साथ इस के मुतल्लिक ध्यान फरमा रहे हैं। मगर वजीर साहिब की तवज्जुह कतई नहीं है (विघ्न) उन्होंने

एक लफ़्ज़ नहीं लिखा तो जवाब क्या देंगे ? मेहरबानी करके आप इनको फरमायश कीजिये कि इस तरफ तवज्जो दें (विघ्न)।

उपाध्यक्षा : मैं ने इस आगस्ट हाउस के मैम्बरान से पहले ही दरखास्त की है और अब भी करूंगी कि हाउस में मिनिस्टर मुतालिलका से बातें न किया करें। वजीर साहिब भी तवज्जुह दें और नोट लिया करें। (I have already requested the hon. Members of this august House and repeat it now that they should not talk to the Ministers in the House. The hon. Ministers should also be attentive to the proceedings and take notes.)

खान अब्दुल गफार खां : अगर वजीर साहिब ही परवाह न करें (विघ्न) यह खाली बैठे थे, इन्होंने एक लफ़्ज़ नहीं लिखा (विघ्न)।

उपाध्यक्षा : अगर मैम्बर साहिबान अपने ऊपर जाबता लगा लें कि वजीर साहिब के पास नहीं जाना तो ज्यादा अच्छा हो। वजीर साहिब से दरखास्त करती हूं कि वह ध्यान से सुनें। (*Interruptions*) (It would be better if the hon. Members make it a point that they are not to go to any hon. Minister in the House. I request the hon. Minister to be attentive.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह आप के नोटिस में लाना चाहता हूं कि मैं ने मिनिस्टर साहिब से पूछा कि पंडित रला राम जी क्या कह रहे थे तो चौधरी साहिब ने कहा कि वह एग्जामीनेशन्ज़ के बारे में कह रहे थे। (विघ्न)।

लोक कार्य तथा कल्याण मन्त्री : कभी तो सीरियस होना चाहिये।

प्रिंसिपल रला राम : उपाध्यक्षा महोदया, यह ठीक है कि हमारा देश गरीब है मगर इस गरीबी को दूर करने के लिये ऐजुकेशन, जिस में जैनरल और टैक्नीकल दोनों प्रकार की शिक्षा आती है, एक बड़ा भारी साधन है इस के मुतालिलक एक अमरीकी लेखक ने लिखा है कि इस वक्त जो इन्डस्ट्री दुनिया में सब से ज्यादा तरक्की कर रही है वह है नौलेज इन्डस्ट्री यानी इल्म या शिक्षा की इन्डस्ट्री। इस बारे में वह लेखक कहता है :

> "The projection is not astounding at all when it is recalled that last year in the U.S.A. only nine per cent of the population, as farmers and factory production workers, produced all the food and manufactured goods. In the last twenty-three years the number of farmers and farm workers has decreased by more than forty-five per cent while the number of teachers has almost doubled."

उपाध्यक्षा महोदय, जो लोग वहां पर खेती का काम करते थे उन की तादाद 45 फीसदी से कम हो कर 9 फीसदी हो गई है और वह कहते हैं कि अगले पांच सालों में उन की तादाद दो फीसदी तक आ जायेगी और जितनी खुराक यू. एस. ए. और बाकी देशों को चाहिए वह सिर्फ दो फीसदी लोग ही पैदा कर सकेंगे लेकिन जो टीचर्ज की तादाद है वह 23 सालों के अन्दर डबल हो गई है। इस वजह से वह कहते हैं कि नौलेज इन्डस्ट्री यू. एस. ए. में सब से बड़ी इन्डस्ट्री है। इस लिये अगर हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा का ढांचा सुधरे तो हमें इस के लिये ज्यादा रुपया रखना होगा। हम देखेंगे कि पिछले सालों की निसबत शिक्षा के लिए बजट में बाकी बजट की रकम से जो परसैंटेज होती है वह इस साल कम हुई है। यह ठीक है कि रुपया बढ़ा है मगर परसैंटेज कम हुई है। बजट भी तो एक अरब 29 करोड़ का है। तो इस बात को देखते हुए मैं समझता हूं कि बीस करोड़ की जो रकम इस बार रखी गई है यह नाकाफी है। उपाध्यक्षा महोदया, कैलेफोर्निया यूनिवर्सिटी का ज़िक्र करते हुए उस अमरीकन लेखक ने लिखा है :—

> "The University of California's annual operating expenditure of over half a billion is a tiny part of what Princeton's Professor Fritiz Machulp calls "the knowledge industry."

[प्रिंसिपल रला राम]

तो आप देखें कि सिर्फ कैलेफोर्निया यूनिवर्सिटी में शिक्षा पर 50 करोड़ डालर खर्च होते हैं एक साल में, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में। यही कारण है कि वह लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि हमें यह शिकायत है और सही शिकायत है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अन्दर रिसर्च नहीं हो रही, यह ज्यादा होनी चाहिये। मगर उस के लिये हम पैसा भी तो नहीं जुटाते तो रिसर्च का काम कैसे आगे बढ़े। हमारा 45 करोड़ लोगों का देश है मगर इस में से दो तीन व्यक्तियों को छोड़ कर किसी हिन्दुस्तानी को पिछले 45 सालों में नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, सिवाए टैगोर और रामन के किसी और को नहीं मिला। हमारे हां रिसर्च अगर होनी है तो उस के लिये सरकार को सिन्यूज़ आफ वार प्रोवाइड करने होंगे।

फिर, उपाध्यक्ष महोदया, हमारे हां टीचरों के स्टेटस का बड़ा भारी सवाल है। मैं समझता हूं कि इस को बढ़ाने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है। मगर मैं समझता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तालीम का म्यार ऊंचा हो तो उन को पढ़ाने वाले टीचर्ज़ ऐसे होने चाहिएं जिन के अन्दर इनफीरियारिटी कम्पलैक्स, हीनता का भाव न हो और वह अपने गुजारे को ठीक तरह से चला सकें। इस लिये मैं कहता हूं कि यह जो बीस करोड़ की रकम है यह नाकाफी है। यह बजटिंग में नुक्स है। इस की परसैंटेज 25 प्रतिशत होनी चाहिये। उपाध्यक्षा महोदया, हम चाहते हैं कि रिफार्म आए मगर यह कैसे आयेगी। हम ने हायर सैकंड्री सिस्टम को जारी किया। मैं यह कह सकता हूं कि इस में फंडामैंटली कुछ भी गल्त नहीं है, बड़ा अच्छा सिस्टम है मगर हम पैसा नहीं दे सकते, टीचर्ज नहीं प्रोवाईड कर सकते, सामान नहीं दे सके तो कैसे यह कामयाब होगा। बाकी दुनिया में कुछ लोकल हालात के फर्क के साथ ऐसे ही सिस्टम लागू हैं, इस स्कीम में कोई नुक्स नहीं है। अब आप 12-ईयर सिस्टम लागू करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा है। इस से गांव के लोग और गरीब लोग भी हायर शिक्षा प्राप्त कर पायेंगे। अब गांव के लोग हायर शिक्षा नहीं पा सकते लेकिन अगर आप हायर स्कैंडरी सिस्टम को 12-इयरली सिस्टम कर देंगे तो रूरल इलाकों के लोगों को फायदा पहुंचेगा। (घंटी) मैं अभी खत्म करता हूं। इस तरह से हम उन लोगों का लैवल ऊंचा कर पायेंगे। इसे मैं ठीक समझता हूं अगर कोई कमी है तो वह इन स्कीम्ज़ की इम्पलीमैंन्टेशन में रहती है। इस की वजह ऐडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ढीलापन भी हो सकता है मगर बड़ा कारण यह है कि हम इन स्कीमों के लिये पैसा मुहैया नहीं कर पाए हैं। इस लिये यह अधूरी रह गई हैं। वरना ढांचा कोई बुरा नहीं है। ऐजुकेशन के अन्दर मेनूअल लेबर को कोआर्डीनेट करना चाहिये। वहां बेसिक ऐजुकेशन फेल हो गई है। मैं यह समझता हूं इस को पुनरजीवित नहीं करना चाहिये। यह आईडिया फन्डेमैन्टली साऊंड है कि बेसिक शिक्षा प्राइमरी से लेकर ऊपर तक होनी चाहिये। किताबी तालीम के साथ साथ हाथ की तालीम में पूरे तौर से कुआरडीनेशन होनी चाहिये। आज जो पढ़े लिखे आदमी के अन्दर भाव है वह दूर होना चाहिये और डिगनटी आफ लेबर के अभाव को दूर करना जरूरी है। इस के अलावा जहां तक टैक्निकल बायस का सम्बन्ध है इस को बढ़ाने के लिये सरकार ने नुमायां हिस्सा डाला है।

और इस सूबे ने टैक्नीकल एजुकेशन में खासी तरक्की की है। और इस बायस को लाने के लिए सही कामयाबी तब होगी कि इसको प्राइमरी स्टेज पर से ही शुरू कर दिया जाये। और जो तीन और हैं किताबी एजूकेशन है और हैंडवर्क है और डिगनटी ग्राफ लेबर है इनको कुग्रार्डीनेट कर दिया जाये। (घंटी) मैं पांच मिनट में ही खत्म कर दूगा। जैसा मैं ने कहा कुग्रार्डीनेशन इन में आनी चाहिये।

जहां तक कुरप्शन का सम्बन्ध है, उपाध्यक्षा महोदया, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि यह नहीं है। लेकिन कुरप्शन केवल सरकार के डन्डे से दूर हीं होगी। यह तब ही दूर हो सकती है अगर हम बेसिक शिक्षा में तबदीली करें और इस को इखलाकी रुख देने का प्रयत्न करें। यह बीमारी गहरी है और इसे दूर करने की आवश्यकता है। धर्म का नाम लेना बुरा नहीं, मैं समझता हुं कि सैक्टेरियनइज्म हम ला नहीं सकते क्योंकि हमारे देश का ढांचा ही और तरह का है। इस से बाहर रहना चाहिए। लेकिन नैतिक, मौरल और सपिरचुअल साइड पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ह्यूमेनिटेरियन साइड को निगलैक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरह की एजुकेशन को निगलैक्ट करेंगे तो कुरप्शन को दूर नहीं कर सकेंगे। यह ठीक है कि गवर्नमैन्ट डन्डे के साथ कन्ट्रोल कर सकती है लेकिन यह इफैक्टिव कन्ट्रोल नहीं होगा। मैं शिक्षा में सैक्टेरिएनिजम को लाने के खिलाफ हूं। लेकिन मौरल और इखलाकी पहलू की तरफ हमारी शिक्षा के अन्दर काफी ध्यान नहीं दिया जाता है। इस को हर स्टेज पर दूर करने की जरूरत है और प्राइमरी से ऊपर इस तरह की शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये।

एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक अंग्रेजी को हम अपने दिमाग से नहीं उतारेंगे आइडियल जीनस फलरिश नहीं करेगा। हम हर लिहाज से दुनिया का मुकाबला नहीं कर सके, इस की बड़ी वजह यह थी कि हमारे बच्चों के दिमाग पर अंग्रेजी बतौर मीडियम का दबाओ आज तक मौजूद है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीनस फलरिश करे और औरिजनल रिसर्च हो तो हमें अपनी लैंगवेजिज को तकवियत देने की तरफ ध्यान देना होगा (घंटी)।

यहां पर मैं यूनिवर्सिटी शिक्षा के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने खासी तरक्की की है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को देख कर प्रसन्नता होती है। वहां पर माना हुआ प्रोग्रैसिव व्यक्ति लगा हुआ है। जो यूनिवर्सिटी को आगे ले जा रहा है। पंजाबी यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है लेकिन इन में हमें यह देखना चाहिये कि अगर यह ओरिजनल रिसर्च को फोस्टर कर रही हैं तो मैं समझता हूं कि यह अपना फर्ज अदा नहीं कर रही हैं। आप का धन्यवाद।

श्रीमती सरला देवी (बरसर) : आज एजूकेशन के ऊपर बहस चल रही है। जैसा कि प्रिंसीपल साहिब ने बताया है हमारी एजूकेशन पर 20 करोड़ 11 लाख रुपया खर्च होने वाला है। मैं यह समझती हूं कि एजूकेशन के लिये जितना रूपया रखा गया है वह बहुत ही कम है। जब तक इस के लिये ज्यादा रकम न रखी जाए काम नहीं बन सकता।

[श्रीमती सरला देवी]

दूसरी बात यह है कि हमें इस बात की तो खुशी है कि एजूकेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है, स्कूलों को तादाद बढ़ा दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा एजूकेशन लोगों को दी जा सके और स तरह से बच्चे शिक्षा लेकर देश की उन्नति में हाथ बटा सकें। लेकिन मैं देखती हूं कि इस बात का चर्चा किया जा रहा है कि यह सरकार एजूकेशन के सिस्टम को बदलना चाहती है । छागला साहिब ने भी इस बारे में कहा था कि एजूकेशन सिस्टम को बदलना चाहिये। और यह स्कीम बनाई गइ है कि हायर ऐजूकेशन को सैंटर के अण्डर कर दिया जाये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस से इख्तलाफ रखती हूं। अगर हम एजूकेशन को, हायर एजूकेशन को सैंटर के अन्डर कर देंगे तो हमारे सूबे की अटानोमी खत्म हो जायेगी। इस लिये हमारी सरकार को चाहिये कि इस तरह का फैसला करने से पहले एजूकेशनिस्टों को एक कानफ्रेंस बुलाइ जाये ताकि उन से सलाह कर ली जाए कि हायर एजुकेशन को सैंटर को देना चाहिए या नहीं देना चाहिये। इस के साथ ही हमें दूसरी स्टेटों से पता लगा लेना चाहिये कि इस के बारे में और स्टेटें क्या कर रही हैं? क्या वह भी एजूकेशन को सैंटर के अन्डर रखने को तैयार हैं? यह ज्यादती होगी कि हमारा हक छीन कर सैंटर को दे दिया जाये। यह ठीक है कि सैंटर हमारी हर तरह से इमदाद करता है लेकिन इस का यह मायना नहीं कि हमारा हक उनके सुपुर्द कर दिया जाये।

फिर बात यह है, जैसा कि प्रिंसिपल साहिब ने कहा है कि हमारी एजूकेशन को ज्यादा साईन्टिस्ट पैदा करने चाहिएं ताकि हर तरफ तरक्की की जा सके। ऐग्रीक्लचर की तरक्की हो सके। हमारे देश की उन्नति का निर्भर एग्रीकलचर पर है इस लिए इस तरह के नौजवान ज्यादा से ज्यादा पैदा होने चाहिएं जो इस क्षेत्र में एजूकेशन हासिल करें। लेकिन इस के लिए रूपया कम रखा गया है। अगर हम एजूकेशन मिनिस्टर के पास जाते हैं तो वह कह देते हैं कि रूपया नहीं है इस लिए इस साल सिर्फ 45 स्कूलों को ही अपग्रेड किया जा सकेगा। इस से ज्यादा नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कहना चाहती हूं कि जितने बैकवर्ड इलाके हैं, मैं सिर्फ कांगड़ा ज़िला को ही नहीं लेती, हिन्दी रिजन सारा बैकवर्ड है और फिर हिल्ली एरिया भी बैकवर्ड है, मैं यह समझती हूं कि कम से कम इस इलाके में तो ज्यादा से ज्यादा स्कूल अपग्रेड होने चाहिएं। यह खुशी की बात है कि सरकार ने इस साल हमीरपुर में एक कालिज खोलने का फैसला किया है। यहां पर बच्चे 12 मील से आते थे फिर कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर लोगों ने इमारत के लिए 8,000 रूपया जमा करवाया हुआ है जैसे कि गमरू चखमो लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब सवाल सरकार के सामने यह है कि उन लोगों को रुपया वापिस कर दिया जाए। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि उन्होंने यह रूपया क्यों दिया है? अगर आप सोशीलिस्टिक स्टेट बनाना चाहते हैं तो यह बड़ी गलत बात होगी कि उनकी रकम को वापिस कर दिया जाए। इस का लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ता है और स्टेट के ऊपर भी। इस लिए जहां का रूपया जमा है वहां पर स्कूल खोल देने चाहिएं। नारकी में 26 हजार की लागत से स्कूल बनाया

ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਲਾਸ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਭਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਭਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲ ਮੈਨੇਜਡ ਸਨ, ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵਿੰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 30, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਲਿਸਟ ਕਢੀ ਗਈ ਹੈ । ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਉਨੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 9 ਲਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫਸਰ ਰਖੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਐਡਿਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਕ ਗਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਕਲਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਰ D. D. P. I. ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਹ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਕੇ ਉਥੇ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨਿਆਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ they should be made to work in the field and not at the Headquarters ਜਿਹੜੇ 2, 3 ਆਦਮੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ they should be sent to the field. ਕਾਲਿਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ 30.6 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਿਊ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰਜ਼ ਹਨ

[ਸਰਦਾਰ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ]
ਕਿ ਉਹ on behalf of the government by order ਰੁਪਿਆ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ amount should be recovered from the balance of credits with the Treasury or the Bank. ਮੈਨੂੰ ਮਸਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫ਼ਿਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। 181 ਸਫੇ ਤੇ ਨਾਨ ਪਲੈਂਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 9,20,600 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲੈਂਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 3,40,200 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 12,88 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਟੋਟਲ 12 ਲਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਫ਼ਾ 181, 182 ਤੇ ਇਹ ਫਿਗਰਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਗਰਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਫੌਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਆਦਮੀ ਵੀ ਰਖ ਕੇ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਦਮੀ ਰਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 1300 ਬਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਰੁਪਏ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਐਮ. ਏ. ਆਦਮੀ ਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਟੀ. ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਰਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚੂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਟ ਲਗਾ ਦਿਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਫਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਵਿਜ : ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਆਨੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ?

ਸਰਦਾਰ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ। ਚੇਅਰ-ਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਖਰਚ ਘਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਰਚ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 6,000 ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਰ 11,000 ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 11,000 ਰੁਪਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਉ, 6,000 ਦੀ ਹਦ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਗਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਅਗੇ ਕਾਲਿਜ ਸਨ ਉਥੇ ਹੋਰ ਕਾਲਿਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਾਇਰ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ ਉਥੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਵਿਜ : ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਖੀ ਸਿੰਘ ਚਧਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਆਜਾਉ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਹਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਟਾਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ because they have no use for it. ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ the amount should be spent before 31st of March, ਫਿਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੈਰੇਕਟਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਚਰ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਬ ਦੇ ਡਰ ਬਿਨਾ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਬ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਖ ਪਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਦੋਵੇਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰੈਲਟੀ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री जगन्नाथ (तोशाम) : चेयरमैन साहिब, यह शिक्षा पर बहस हो रही है । चौधरी साहिब, ने बजा कहा है वैसे ही देश में खास तौर पर देखा जाय तो शिक्षा की जरूरत नहीं है । चेयरमैन साहिब, अगर इस रूलिंग पार्टी के चेयरमैन को देखें तो वह अनपढ़ है । अगर पंजाब के मुख्य मन्त्री को देखें तो वह अंडर मैट्रीक है जहां हकुमत को चलाने वाले अनपढ़ हों वहां बाकी जनता को पढ़ाई की जरूरत नहीं । चैयरमैन साहिब, यहां बाहर का एक डैलिगेशन आया था उस ने युनिवर्सिटीज और स्कूलों को देखकर जायजा लिया । वह किसी कम्युनिस्ट देश का डैलिगेशन था । उन्होंने अपने देश में जा कर रिपोर्ट दी । वापस जाने पर उन से पूछा गया कि हिन्दुस्तान में क्या देखा है तो उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में एक चीज देखी कि भगवान है । वहां पर उन्होंने कहा कि हम तो भगवान को मानते नहीं वह कम्युनिस्ट थे । उन्होंने कहा कि भगवान हिन्दुस्तान में ही है । हिन्दुस्तान

[श्री जगन्नाथ]

में स्कूल ठीक नहीं, युनिर्वासिटियां ठीक नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं यानी कोई चीज़ प्रापर ढंग से डिसिपलंड ढंग से ठीक नहीं है । हकूमत भी ठीक ढंग से नहीं चलती । हिन्दुस्तान में भगवान के सहारे ही हकूमत चलती है वरना और कोई कारण नहीं । कहते थे कि प्रताप सिंह कैरों और मोहन लाल की गवर्नमेंट बदमाशों की गवर्नमेंट थी । वह गवर्नमेंट निकाली उस के बाद अब यह कहते हैं कि पंजाब में कोई गवर्नमें है या नहीं । (इस समय उपाध्यक्षा ने चेयर समभाली) डिप्टी स्पीकर साहिबा, कहीं टीचर्ज में हा हाकार मची हुई है । पिछले दिनों पंजाब के टीचर्ज़ ने हड़ताल की स्कूलों में न पढ़ाने वाले थे और न पढ़ने वाले थे । पंजाब के स्कूलों में बाबूदयाल जैसे छोटे छोटे मास्टर हैं । गांव में ऐसे मास्टर जाते हैं । उनको सौ रूपए माहवार मिलते हैं । सौ रुपए में उनका गुज़ारा नहीं होता । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो................

उपाध्यक्षा : श्री बाबू दयाल का जो लफ्ज़ कहा है, वापस ले लें । (The word "Shri Babu Dayal used by hon. Member should be withdrawn.

श्री जगन्नाथ : डिप्टी स्पीकर सहिबा, पता नही पिछले जन्म का कोई संस्कार है, जब भी मैं बोलता हूं उस वक्त आप चेयर में जरूर होती हैं ।

Deputy Speaker : Jagan Nath Ji, please withdraw your words.

श्री जगन्नाथ : मैंने जो कुछ कहा था विदड्रा किया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने बाबू दयाल जी के बारे में नहीं कहा । स्कूलों में और कालेजों में बुरी हालत है । 21 तारीख को ला कालेज में 200 लड़कों ने हड़ताल कर दी । दो महीने पहले 1,500 लड़कों ने दरखास्त की कि पहली अप्रैल की बजाए 15 अप्रैल या 1 मई को इमतिहान होना चाहिए । वाइस-चांसलर से मिले, चीफ मिनिस्टर से मिले और हरेक ने कहा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा । एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ, न ही कोई डेट फिक्स हुई है । 21 तारीख को 200 स्टूडेंटस ने ला कालेज के होस्टल में भूख हड़ताल की । उन्हें कहा गया कि तुम्हारा एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा । और अब कहते हैं कि 31 मार्च को तुम्हारा एग्ज़ाम जरूर होगा । अफससोस की बात है कि 31 मार्च को एग्ज़ाम है और आज तक डेट शीट नहीं लगी । कम अज़ कम महीना या 20 दिन पहले डेट शीट लग जाती है कि फलां तारीख को एग्ज़ाम होगा । यह उन लड़कों की हालत है । यह ला कालेज की हालत है । पंजाब के स्कूलों और कालेजों में ऐसा होता है । पंजाब के स्कूलों और कालेजों में लड़कों को यह पता नहीं कि उन का एग्जाम कब होगा । उनको यह नहीं बताया जाता कि कौन सा कोर्स लगा हुआ है । साल में 9 महीने तो वे अंधेरे मे ही रहते हैं दो चार चैप्टर पढ़ाए जाते हैं । 10 या 15 दिन में बाकी कोर्स कम्पलीट होता है । लैकचरर या टीचर इस तरह करते हैं । सारे का सारा साल इस तरह निकल जाता है और स्टूडेंटस को पता नहीं चलता कि कितना कोर्स खतम हुआ है और कितना बाकी है और कौन से कोर्स में से एग्जाम होगा । ला कालेज के 20 स्टूडेंटस ने भूख हड़ताल की हुई है ।

1,500 स्टुडेन्टस ने इस के बारे में पहले कहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जायें किया वह विधान सभा पर हमला करते, युनिवर्सिटी की बिल्डिंग को तोड़ते और सैक्रेटेरिएट को जलाते । इस पंजाब के स्टुडैन्टस की यह हालत है । बाकी टीचरों के बारे में तो यह उपदेश देते हैं । बाबू दयाल जी ने और भागीरथ लाल जी ने कहा और संस्कृत का उपदेश दिया कि हिन्दुस्तान में, पुराने समय में अध्यापक का, टीचर का बहुत आदर होता था । लेकिन आज के युग में या माजूदा पंजाब में देखा जाये तो गवर्नमेंट सरवैंट चाहे वह टीचर है या दूसरा उस का सतकार नहीं होता इ का मतलब यह कि पंजाब या हिन्दुस्तान में यदि किसी का सतकार होता है तो यह पैसे वाले का होता है । बड़े अफसरों का सत्कार होता है । जिस के पास ज्यादा पैसा हो उसी का सत्कार होता है । जिस मास्टर को 100 रुपया माहवार मिलता है वह गुजारा नहीं कर सकता । यदि बीबी जी ने कह दिया कि साढ़ी लानी है तो उस महीने सफाया ही है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, एजूकेशन के बारे में तो क्या कहूं । इस की ज्यादा जरूरत नहीं । पहले जमाने में कहते हैं कि संस्कृत के वेद के अन्दर लिखा है झूठ बोलने वाले मर जाया करते हैं । लेकिन इस कांग्रेस हकूमत के अन्दर यह रोजाना झूठ बोलते हैं और इन को कभी बुखार तक नहीं होता । (हंसी)

उपाध्यक्षा : यह कौन सी किताब मे लिखा है ? (In which book is this written ?)

श्री जगनाथ : मेरे इलाके में एक पुट्ठी मिडल स्कूल है । एक बार चौधरी सूरजमल जी वहां गये और उन्होंने कहा कि इसे मिडल स्कूल से हाई स्कूल बनाना है । वह उस का शिलान्यास रख आये और 7,000 रुपए की माला ड वा लाये । उस के बाद पंडित मोहन लाल जी गए यह उस वक्त होम मिनिस्टर थे यह 800 रुपए की माला डलवा लाये । फिर चौधरी रणबीर सिंह गये और 2,100 रुपये की माला डलवा लाये । दस साल हो गये लेकिन अभी तक वह हाई स्कूल नहीं बना । इसी तरह से जमोली की हालत है । पंडित मोहन लाल और दूसरे मिनिस्टर वहां हो आये हैं और मालायें डलवा लाये हैं । खड़क पुन्या में कैरों साहिब गये और उन का मीलों तक जलूस निकाला गया । मसूदपुर में चौधरी सूरजमल गये और 5,000 या 7,000 रुपए की माला डलवा लाये । नींव पत्थर रखा गया मगर मिडल स्कूल से हाई स्कूल नहीं बना । हांसी कालेज के लिए चीफ मिनिस्टर साहिब को पिछले साल कहा गया कि हांसी के अन्दर कालेज नहीं । वहां कालेज बनाया जाये । घनाना एक बड़ा गांव है, वहां भी कालेज होना चाहिये । इन दोनों जगह कालेज होना चाहिये । कहा गया कि तुम्हारे कालेज जरूर बन जायेगा, मैं वादा करता हूं । पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार प्रताप सिंह कहते हैं कि तुम्हारे कालेज बन जायेगा लेकिन आज वहां ईट तक नहीं रखी गई । इसी तरह से हांसी तहसील में कोई

[श्री ज .न्नाथ]

15 गांव ऐसे हैं जहां पर स्कूलों के पत्थर तो रखे गए हैं, मिडल स्कूल से हाई स्कूल करने के लिए और हर गांव में इनको दस दस और 15, 15 हज़ार रुपए के नोटों की मालाएं भी पहनाई गई हैं और लाख लाख और दो दो लाख रुपए की स्कूल बिल्डिंगस भी बनवा दी हैं लेकिन आज तक वहां स्कूल अपग्रेड नहीं किए गएं । इस तरह से यह झूठे वादे लोगों से करते हैं कि हम इस साल कर देंगे और अगले साल फिर कह देते हैं कि इस इस साल जरूर कर देंगे । इस तरह से यह उन्हें धोखा रोजाना देते रहते हैं । आप देखें आये से शन में महिन्दरगढ़, भिवानी, और हांसी से दस दस पन्दरह पन्दरह लोगों के डेप्युटेशन इन को इस बारे में मिलने आते रहते हैं। आप अन्दाज़ा लगाएं कि वे लोग कितना खर्च कर के यहां आते हैं जब कि वहां से आने जाने में एक आदमी का 40 या 50 रुपया खर्च हो जाता है लेकिन उन के स्कूल यह फिर भी अपग्रेड नहीं कर रहे । श्री राम किशन चीफ मिनिस्टर अब यहां बैठे नहीं हुए । तीन तारीख की बात है कि मेरे हल्के में से एक गांव के दस आदमी यहां डेपूटेशन की शकल में आए थे । उन्होंने मुझ से कहा कि हमें मुख्य मन्त्री से मिला दो । तो मैं उन को इन के पास ले गया। उन्होंने उन से एप्लीकेशन तो ले ली लेकिन कुछ नहीं पूछा कि क्या काम है, कहां से आए हो और क्या तकलीफ है या किस स्कूल के बारे में कहने आए हो । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने उन से कुछ नहीं पूछा और सिर्फ उन से अर्जी ले ली । तो अगर यह हालत हो कि लोग यहां इतने रुपए खर्च के मिनिस्टरों की अपनी तकलीफें बताने आएं और उन से यह भी न पूछा जाए कि किस काम के लिए आए हो तो आप बताएं कि पंजाब की जनता का इन से क्या भला होगा ।

मैंने डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले भी कहा था यहां पर कि एक तरफ तो पबिलक स्कूल चल रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे स्कूल हैं । जो पब्लिक स्कूल हैं वहां पर तो बड़े बड़े अफसरों के और अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और जो दूसरे आम स्कूल हैं वहां पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं । भला आप बताएं इस तरह से कैसे यह समाजबाद ला सकते हैं और कैसे गरीब लोगों के बच्चों में से इनफीरियरेटी कम्पलैक्स हट सकता है । इस लिए मैं समझता हूं कि जब इस देश में क्रांति आई तो अ.र किसी पब्लिक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते होंगे तो सब से पहले उन्हीं को लोग फूंक देंगे । इस लिए मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पब्लिक स्कूलों को यह तोड़ दें ताकि अमीरों और गरीबों के बच्चे एक जैसे स्कूलों में बढ़ें बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि गवर्नमेंट को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि तमाम बच्चों की एक जैसी ड्रेस हो और उन को वहां एक जैसा खाना मिले । अगर एक जैसा खाना देना अभी तक मुमकिन न हो तो ड्रेस तो जरूर एक जैसी कर दी जाए ताकि बच्चों में ऊंच नीच का भाव खत्म हो सके ।

फिर स्कूल टीचरों की यह हालत है कि आप को पंजाब मे 90 फीसदी ऐसे स्कूल मिलेंगे जहां पर या तो साइंस टीचर नहीं है, कहीं पर ड्राइंग मास्टर नहीं है, कहीं पर संस्कृत का मास्टर नहीं है और किसी में पंजाबी का मास्टर नहीं होगा । यानी हर स्कूल में किसी न किसी सबजैक्ट के मास्टर की कमी जरूर मिलेगी । इतनी लापरवाही

यह गवर्नमेंट एजूकेशन के बारे में करती है हालांकि यह दावे बड़े लम्बे चौड़े करते हैं जब कोई अलैकशन आती है चाहे यवह एसैम्बली का जनरल अलैकशन हो चाहे कोई बाई अलेकशन हो कोई भी अलेकशन हो तो उन दिनों में यह धड़ाधड़ देहात के मास्टरों को एक जगह से तबदील कर के दूसरी जगह पर भेज देते हैं क्योंकि इन को यह डर रहता है कि कहीं इन की पार्टी के कैण्डीडेटस को वह नुकसान न पहुंचा दें । उन की शिकायत पर इन बेचारों को तबदील कर दिया जाता है । अभी चौधरी अमर सिंह बतला रहे थे कि उन के हल्के के स्कूल मास्टरों को तबदील कर दिया गया था ।

चौधरी दल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह झूठ है । इन को झूठ बोलने की आदत है ।

श्री जगन्नाथ : डिप्टी स्पीकर साहिबा, वैसे तो हर इनसान कुछ न कुछ झूठ बोलता होगा पर जितना झूठ कांग्रेस पार्टी के मैम्बर बोलते हैं उतना कोई नहीं बोलता होगा । मैं इन को कहता हूं कि अगर पिछली अलैकशन में जिला महिन्दरगढ़ और तहसील हांसी में कई स्कूल मास्टरों की ट्रांसफरज न हुई हों तो मैं अस्तीफा दे दूंगा नहीं तो यह दे दें । मुझे यह कहते हुए शरम आती है कि टीचरज की हैरेसमेंट की जाती है ।

चौधरी दल सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मेडम । यह हमारी तहसील की बात कर रहे हैं और इस तरह से गलत बात करके हाउस की डिगनिटी को लो करने की कोशिश कर रहे हैं । मैं अर्ज करता हूं कि मेरी अलैकशन के दौरान इन के ग्रुप के लीडर चौधरी देवी लाल वहां झूठ बोल बोल कर वहां चैलेंज देते रहे हैं और जो इस का नतीजा निकला है वह आप सब के सामने है कि मैं यहां अलैकट होकर आया बैठा हूं ।

उपाध्यक्षा : श्री जगन्नाथ जो आप इतनी अच्छी तकरीर करते करते ऐसी बातें करने लग गए हैं और खाह मुखाह की इन्ट्रपशनज इनवाईट करने लग गए हैं । आप को ऐसा नहीं करना चाहिए । (Addressing Shri Jagan Nath. The Hon. Member has invited unnecessary interruptions while making such a good speech. He should not have done like that.)

श्री जगन्नाथ : तो मैं अर्ज कर रहा था कि पंजाब में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां टीचरज नहीं हैं । यहां पर एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि पंजाब में पांच हजार टीजरों की कमी है और हैरानी की बात यह है कि यह कमी देहात के स्कूलों मे होती है । हालत यह है कि पिछले साल पंजाब में कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया और अब मालूम हुआ है कि इस साल भी कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। चलो बाकी इलाकों में अगर कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया जाता तो इतनी बात नही लेकिन जो बैकवर्ड इलाके हैं, जहां पर दस दस मील के फासले तक भी कोई हाई स्कूल नहीं है, जहां पर सड़कें नहीं बनी हुई और रास्ते में बच्चों के पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता वहां तो जरूर कुछ स्कूल अपग्रेड किए जाने चाहिएं । जिला महिन्द्रगढ़ का इलाका, जिला गुड़गांव का कुछ

[श्री जगन्नाथ]
इलाका और तहसील भिवानी और तहसील हांसी में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हाई स्कूल बहुत कम हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर मिनिस्टर कनसर्नड हैं नहीं जो हमारी तकलीफों को नोट करते इस लिए और चीजें कहने का मैं फायदा नहीं समझता ।

लाला रुलिया राम (घरौण्डा) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, बात यह है कि हमारे बहुत सारे मेम्बर ऐसे हैं जो काफी बातें कहते हैं और खास तौर पर हमारे जो मैम्बर श्री जगन्नाथ हैं ....
वह मजाक भी बनाते हैं और ....

उपाध्यक्षा : आप उन को कुछ न कहें वह फिर खड़े हो जायेंगे ।

(The hon. Member should not say anything regarding the hon. Member Shri Jagan Nath otherwise he will again stand up)

लाला रुलिया राम : अच्छा जी, मैं उन के बारे में कुछ नहीं कहता । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा जो कोएजूकेशन का सिस्टम है जो इस वक्त पंजाब के अन्दर लागू है मैं उस के मुतअल्लिक कुछ रोशनी डालना चाहता हूं । मैंने को एजूकेशन के बारे में ही यहां पर पिछले साल कुछ आपने विचार रखे थे और मैं अब फिर कहना चाहता हूं कि यहां कोएजूकेशन हमारे स्कूलों में नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें कई ऐसे वाकियात रोजाना देखने में आते हैं जिन को यहां बयान करने में भी

6 00 p.m. शरम आती है । [*Chaudhri Mukhtiar Singh Malik a Member of the Panel of Chairmen in the Chair.*] इस बारे में चेयर मैन साहिब, मैं आप के सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं । मेरे हल्के में एक मौजा रेहका में एक स्कूल में एक मास्टर संत राम है उस ने एक लड़की को छेड़ा । जिस पर उस पर अदालत में मुकदमा चला पर वह सेशन कोर्ट में जा कर बरी हो गया । लेकिन अजीब बात तो यह है कि महकमे वाले यह समझ कर कि क्योंकि वह बरी हो गया है इस लिए उस के खिलाफ कोई एकशन नहीं लिया और उस को दोबारा नौकरी में रख लिया है और उन के खिलाफ कोई एकशन नहीं लिया गया हालांकि वह महकमा तालीम पर एक बदनुमा धब्बा है । इसी तरह से मौजा फरीदकोट में एक मास्टर करतार सिंह ने एक लड़की को अगवा कर लिया था लेकिन आज भी वह इसी डिपार्टमेंट मे काम कर रहा है और उस के खिलाफ कोई एकशन नहीं लिया जा रहा । मैं यह बात समझ नहीं सका कि क्यों ऐसे आदमियों को सर्विस में रहने दिया जा रहा है । ऐसे मास्टरों को क्यों रखा हुआ है जिन से पंजाब के लोगों की इस तरह से बेइज्जती होती है ।

फिर बैकवर्ड एरिया और फ्लड एरिया के मुतअल्लिक यह हुक्म है कि अपग्रेडिंग के मामला में उन का ख्याल रखा जाए, ऐसा सरकार कहती है । मैं अर्ज करूं कि

Punjab Vidhan Sabha Debates

26th March, 1965

Vol. I—No. 23

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 26th March, 1965

Rs. 6.35 Paise

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL I, No. 23, DATED THE 26TH MARCH, 1965.

Read	*For*	*Page*	*Line*
SUPPLEMENTARIES TO	SUPPLEMEN-TARIES	(23)3	1
Minister	Ministe	(23)4	1
Home Minister	Education Minister	(23)6	12-13
licenses	icenses	(23)11	15
your	you	(23)17	1
provisions	provislons	(23)17	2-3
think	thick	(23)17	4
इनफर्मेशन	इफरमेशन	(23)17	3 from below
Sardar Gian Singh Rarewala	Sardar Gian Singh Rarewla	(23)21	11
Delete line nine from below		(23)21	9 from below
Government	Goxernment	(23)24	1
of	af	(23)24	14
Legislators	Legislative	(23)29	24
Gratuitous	Gratuitious	(23)32	Under Col. 22
follows	fallows	(23)35	6
payments	ayments	(23)35	5 from below
he denied	had enied	(23)36	18
Enquiry	Enpuiry	(23)36	34
dilatory	dialatory	(23)40	23
Superintendent	Superindent	(23)40	34
taken	tken	(23)40	5 from below
Communist	Communit	(23)43	5 from below
Will	Wil	(23)44	5 from below
requisite	requisit	(23)45	5
involved	invloved	(23)47	31, 36
irregularity	irregurity	(23)48	17
properly	propertly	(23)48	21
not	note	(23)48	29
recorded	receorded	(23)50	8
on	in	(23)60	4
during	durin	(23)60	8
arrest	arrent	(23)60	27
or	of	(23)60	29
brother	brogher	(23)60	30
sustained	substained	(23)60	40
damages	damaged	(23)60	40
Besides	Besiedes	(23)61	27
पहले	पहल	(23)62	5

P. T. O.

Read	*For*	*Page*	*Line*
एलीगेशन्ज़	एलीगशनूज़	(23)75	5 from below
बैनीफिट	बनीफिट	(23)82	3
कालेजिज़	कालेजि	(23)89	7 from below
चाहता	चाहना	(23)97	12
एरियर्ज़	एरियज़	(23)97	18
person	perons	(23)101	18
rocket	r cket	(23)102	11
would	w uld	(23)103	27
सम्बन्ध	सम्बन्ध्ध	(23)106	17
ग्रौर	ग्रौ	(23)107	4, 27
डिवैल्पमेंट	डिबैल्पमट	(23)108	14
चेंज	चेंन	(23)108	23
सब	में सब	(23)108	31
फीसदी	पीसदी	(23)110	25
एक	ने एक	(23)111	2
नहीं	नह	(23)111	3
conventional	co ventional	(23)111	8
इम्तहान	इम्तहा	(23)112	15
महोदय	नहोदय	(23)116	15
ਹੁਣ	_ਣ	(23)118	5
ਰੰਗ	ਰਗ	(23)119	5
ਨਾਲ	ਨਾਲ ਨਾਲ	(23)120	19
लोगों	लोगें	(23)127	9
ਔਰ	ਅਰ	(23)127	22
ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼	ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼	(23)129	5
ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ	ਇੰਮਲੀਮੈਂਟ	(23)129	7 and 8 from below
ਕਮਿਊਨਲ	ਕਾਯੂਨਲ	(23)130	3
ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ	ਅ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ	(23)131	11
Thus	T us	(23)133	7
cess	ces	(23)133	8
[Minister for Education and Local Government]	[Minister for Education/कालेजिज़]	(23)134	1
में खोलेंगे	खोलेंगे	(23)135	1
and	nd	(23)135	17
कामरेड शमशेर सिंह जोश	कामरेड शमशर सिंह जोश	(23)136	19
डिसक्रीशनरी	डिक्री शनरी	(23)136	26

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, the 26th March, 1965

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh at 9.30 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

*SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION. NO. 7319

श्री मोहन लाल : मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस वक्त मिनिस्टर साहिब ने यह फैक्ट्री ली थी तो क्या यह evacuee property थी? अगर थी, तो आया उन्हों ने यह आकशन में ली थी या अलाटमैंट के जरिये से ली थी ?

शिक्षा मन्त्री: जनाब आली, मुस्लिम ईवैकुई प्रापर्टी अलाट हो जाया करती है। यह मैं ने 24,600 रुपये में हासल की थी जिस का २० प्रतिशत मुझे cash देना पड़ा था और बाकी का किश्तों में अदा हुआ . . . .

श्री मोहन लाल : कैसे कैश दिया था। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आया यह मुस्लिम इवैकुई प्रापर्टी थी। आप ने अलाटमैंट के जरिये ली थी या आकशन के जरिये ली थी ?

मन्त्री : यह एक मुस्लिम प्रापर्टी थी। 1948 में मैं इसे बना रहा था, 1947 में पार्टीशन हो गया था। इस में से कुछ जगह अलाट हुई थी और कुछ मैं ने किराए पर ली थी जिस के मुताल्लिक बाद में यह फैसला हो गया था कि यह भी इतना रुपया देकर ली जा सकती है।

श्री मोहन लाल : मुझे यह स्टेटमैंट मिला है कि 1956 से लेकर 1962 तक यह फैकटरी लीज पर रही। क्या यह हकीकत है कि फैकटरी में लैस्सी ने जो राईस शैल्लर लगाया हुआ था वह काम करता रहा ?

मन्त्री : फैकटरी के पिछले हिस्से के साथ जिस का फैकटरी से कोई ताल्लुक नहीं था राईस शैल्लर लगाया हुआ था।

श्री मोहन लाल : क्या यह बात उनके इल्म में है कि जितना अरसा इस फैकटरी में राईस शैल्लर लगा रहा था केवल वही काम करता रहा और फैकटरी वाला सैक्शन बंद रहा ?

मन्त्री : यह हिस्सा तो फैकटरी का ही है मगर इन की इमारत अलग है। एक तरफ राईस शैल्लर काम करता था और दूसरी तरफ फैकटरी का काम चलता था।

कामरेड राम प्यारा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कि सप्लीमैन्टरी करने वाले मैम्बर फूड एण्ड सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे, आया यह उस वक्त शैल्लर वालों को चावलों का पूरा हिस्सा देना पड़ता था वह सरकार को देते रहे या नहीं देते रहे ?

---

*Note.—Starred Question No. 7319 and reply thereto appear in P. V. S. Debate, Vol. 1, No. 4, dated 26th February, 1965

मन्त्री : जनाब हिस्से के अलावा कुछ और भी दिया, यह उस वक्त के सिविल सप्लाई मिनिस्टर ही बता सकते हैं, मुझे सारी डिटेल्ज़ का पता नहीं।

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि हिस्से के अलावा कुछ और भी दिया है। इसका क्या मतलब है ? यह एक बड़ी सीरियस बात है जो हाउस के नोटिस में आई है यह पहले क्लियर हो जानी चाहिये ?

मन्त्री : जनाब, अलावा से मेरा कोई और मतलब नहीं था। हर शैल्लर के लिये पंजाब गवर्नमैंट को कुछ न कुछ फिकस्ड कोटा देना पड़ता है। इस लिये, अलावा में चावलों की बात कर रहा था और इस से अगर कोई पैसे की बात समझी गई है तो यह गलत समझी गई है।

श्री बलरामजी दास टंडन : राईस शेल्लर जो लगाया गया था क्या यह सरकार की परमीशन से लगाया गया था या इजाज़त के बगैर ही लगाया गया था।

Mr. Speaker : It is clear that it was set up with the permission the Government.

श्री मोहन लाल : मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि लाईसैंस गवर्नमैंट ने इन राइटिंग दिया था या मिनिस्टर साहिब ने खुद हासिल किया था। Iron and Steel Central Order के तहत जो कोटा फैकटरी को मिलता रहा है क्या वह इसमें इस्तेमाल होता रहा है ?

मन्त्री : लाइसैंस अण्डर दी रूल्ज़ हासिल किया गया था। जहां तक कोटे का ताल्लुक है, जो मिलता रहा है उस के ठीक इस्तेमाल करने की जिम्मेवारी है, वह पंडित मोहन लाल जो 7-8 साल मिनिस्टर रहे हैं, यही बता दें कि इस अर्सा में आया कोई ऐसी बात इनके नोटिस में आई जिस से यह साबित हो सके कि कोटा का गल्त इस्तेमाल हुआ है।

श्री मोहन लाल : अगर मिनिस्टर साहिब कोई सप्लीमैण्टरी किसी मैम्बर से पूछ सकते हैं तो मैं इस का जवाब देने को तैयार हूं।

Mr. Speaker : No, no please.

चौधरी देवी लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आया कोई मंत्री भी किसी मैम्बर से सप्लीमैंटरी कर सकता है क्योंकि यह पहला मौका है जो आज देखने में आया है ?

मन्त्री : मेरा ऐसा जवाब देने से यह मतलब था कि पंडित जी इतना अर्सा वज़ीर रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात थी तो उन्हों ने उस वक्त क्यों मेरे खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया था।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर यह गुरदासपुर इजलास कब तक जारी रहेगा ? (हंसी)

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या गवर्नमैंट इस बात की एशोरैंस देने के लिये तैयार है कि जो जो पंडित मोहन लाल ने इरगुलैरेटीज़ बताई हैं क्या सरकार उनकी इन्क्वायरी करवाने के लिये तैयार है अगर उन के मुताल्लिक पंडित मोहन लाल जी हल्फिया ब्यान दे दें।

---

*SUPPLEMENTARIES STARRED QUESTION NO. 8020

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਆਰਡਰਜ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਭੇਜੇ ਕਿ ਉਥੇ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਟੀਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ? ਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਕੀ ਹਨ ?

ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ : ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ in contravention of Sachar Formula ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਨੀਆਂ ਜਗਾਹ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਗਾਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਗਾਹ ਪਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

During these nine to ten months that I have been in Office, I have not ordered that the medium of instruction in the schools should be changed.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿਘ ਜੋਸ਼ : ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਯਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇਨ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ।

ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਣ ਲਾਲ: ਕੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਹਿਦਾਇਤ ਯਾ ਆਰਡਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਨਰਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਗਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ।

Report received from the District Education Officer, Gurdaspur, reveals that both the languages, i.e., Hindi and Punjabi are being taught as the first languages, according to the Sachar Formula in the Pathankot Tahsil. If Hindi is taught as the first language, Punjabi is the second language and *vice versa*.

**Note.*—Starred Question No. 8020 and reply thereto appear in PVS Debate Vol. I, No. 22

[Education and Local Government Ministe]

The Sachar Formula is, thus, being faithfully implemented in the State and no complaint against these arrangements have been received in the Department so far as the Pathankot Tahsil is concerned.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਥੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖਣ ।

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੇਕੂਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ । ਮੈਂ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁਛ ਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਸਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ : ਇਹ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਕੁਐਸਚਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਸੀ । ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਹ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਸਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼, ਹਿਦਾਇਤ ਯਾ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ? ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ? ਇਸ ਦਾ ਕੈਟਗੋਰੀਕਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।

Minister : According to the Sachar Formula, the whole of Gurdaspur District falls in the Punjabi Region of the erstwhile Punjab State and teaching of languages in this area is governed by the Sachar Language Formula. This formula envisages the teaching of Punjabi as the medium of instruction and as the first language from the first primary class in all the Government Municipal/recognised private schools, in the Punjabi Region. The second language Hindi in the Punjabi Region and Punjabi in the Hindi Region is introduced from the 4th primary class.

Sachar Formula also gives an option to the parents to declare Hindi or Punjabi as the first language in either of the two areas. If in the Punjabi Region, 10 students in a class or 40 in a school opt for Hindi as the first language, arrangements have to be made for the teaching of Hindi as the first language in the Punjabi Region and Punjabi is started as the second language for such students from the 4th primary class. Similarly, in the Hindi Region, if 10 students in a class or 40 in a school opt for the Punjabi as the first language, Punjabi is taught as the first language to such students and Hindi as the second language from the 4th primary class.

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਸਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । (The hon. Member has asked whether any circular has been sent to the Pathankot Tehsil regarding the Sachar Formula.)

ਮੰਤਰੀ : ਸਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੋਵੇ । ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਸੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਣ ਲਾਲ : ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਣਗੇ ਯਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ ? Our information is that recently the Government have sent such instructions for Pathankot. Let the clarification be given by the hon. Minister for Education and Local Government either in the form of a statement or . . . .

श्री बलरामजी दास टंडन : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर । क्या कोई मैम्बर हाउस को इनफर्मेशन दे सकता है ?

श्री ग्रध्यक्ष: इस हाउस में ग्रनफार्चूनेटली दोनों चीजें होती रही हैं, but I have always insisted that the hon. Members should elicit information and should not give information. (Unfortunately, both the things have been going on in this House but I have always insisted that the hon. Members should elicit information and avoid giving information.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸਾਂਗਾ । ਉਹ ਇਥੇ ਦਸਣਗੇ ਯਾ ਬਾਹਰ ਦਸਣਗੇ ਯਾ ਐਵੇਂ ਟਾਲ ਦੇਣਗੇ ?

ਮੰਤਰੀ: ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦਸ ਦੇਵਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਥੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ।

Complaint against S.H.O., Police Station Rohtak

*6788. **Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether he received any complaint from any Legislator during the month of October/November, 1964 to the effect that the S.H.O., Police Station, Rohtak did not register a complaint lodged with him, if so, the action, if any taken thereon ?

Sardar Darbara Singh : Yes. No offence had been committed and so no case could be registered.

श्री मंगल सेन : गृह मंत्री जी ने पहले मेरे सवाल के जवाब में कहा है हां, ग्रौर बाद में कह दिया कि ग्रौर कोई गुनाह नहीं कि जिस के बारे में कोई एक्शन लिया जाता । मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने किस बात की हां भरी है ?

श्री ग्रध्यक्ष : कम्पलेंट मिलने के बारे में उन्हों ने कहा है, हां । (Regarding receipt of the complaint he has replied in the affirmation.)

श्री मंगल सेन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि किसी के ; को रजिस्टर कराने के लिये थाने में जाने पर ग्रगर पुलिस ग्रफसर उस केस को रजिस्टर करने से न कर दे तो कोई जुर्म होता है या नहीं ?

गृह मन्त्री : वह न नहीं कर सकता बशर्ते कि वह केस रजिस्टर करने के काबिल हो, बात यह है कि इस केस में हमारे ग्रानरेबल मैम्बर श्री मंगल सेन ने गवर्नर, चीफ मनिस्टिर,

[गृह मन्त्री]

इंस्पैक्टर जनरल ग्राफ पुलिस और मुझे तारें दीं कि सब इन्सपैक्टर पुलिस रोहतक उन की कम्पलेंट एंटरटेन नहीं कर रहा कि हीरा लाल-ओनर ग्राफ मैसर्ज़ सीता राम–हीरा लाल की ८ अक्तूबर को 4 बजे डेथ हुई। पुलिस ने इल्लगली उसे अपने कब्जे में रखा। हम ने डी.एस.पी. डियुटी लगायी, उस ने सारी इनक्वायरी की थी। वह कोई डिज़ारेवल ग्रादमी नहीं, जिस के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसा कोई जुर्म नहीं कि केस रजिस्टर न करने के बारे में कोई बात बन सके।

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं पूछना चाहता हूं कि ग्राया उसी वक्त इन्क्वायरी शुरू कर दी गई थी या जहां चंडीगढ़ से हिदायत जाने पर इन्क्वायरी शुरू की गई थी ?

मन्त्री : मुझे जो तार मिला और मुझे जब ज़बानी भी कहा गया तो मैं ने उसी वक्त वहां से ही कहा है कि किसी अफसर को मुकर्रर किया जाए जो इसकी इन्क्वायरी करे।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know, Sir, from the hon. Education Minister whether the refusal of a Police Officer, who is a Sub-Inspector, or an Assistant Sub-Inspector or even a Head Constable, to register a case, entails his dismissal under the Rules, or not ?

Mr. Speaker : If a police officer refuses to record a report or register a case, then action has to be taken against him according to the Rules.

श्री बलरामजी दास टंडन : उनकी शिकायत यह थी कि एक आदमी को पुलिस ने अपनी ग्रिफ्त में लिया लेकिन उसके बारे में किसी जगह भी कोई ऐन्ट्री नहीं की गई लेकिन जब ऐस.ऐच.ग्रो. ने देखा कि अब बात छिप नहीं सकती तो उसने कागजात में यह दिखा दिया कि उसने कहीं 25 मील दूर चोरी की है इसलिये उसे उस अलज़ाम में ग्रिफतार कर लिया गया।

मन्त्री : मैं अर्ज़ करता हूं कि उसके खिलाफ जो केस था जिस की इन्वैस्टीगेशन हुई वह under FIR No. 30 dated 16th June, 1964, under section 457/380 IPC था।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि बतौर होम मिनिस्टर के क्या उनके नोटिस में बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करते हैं और अगर ऐसी शिकायतें आई हों तो वह कितनी हैं और उन पुलिस अफसरों के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है ?

मन्त्री : इस बारे में तो मैं इस वक्त आफहैण्ड कुछ बता नहीं सकता हूं लेकिन जो डाक्टर मंगल सेन जी ने तार मुझे भेजी थी उसके ऊपर पूरी तहकीकात हुई और पता चला कि उसके खिलाफ कोई और केस दफा 457/380 का था और यह बात पुलाइटली एस.एच.ओ. ने डाक्टर मंगल सेन जी को बता दी कि वह इस केस में मतलूब था इसलिए ग्रिफतार किया गया।

श्री मंगल सेन : वजीर साहिब ने जो बात कही है वह तो फाईल पढ़ कर कही है लेकिन मैं अर्ज़ करता हूं कि यह गलत बात है। मैं इस ग्रानरेबल हाउस का मैम्बर हूं और मैं शपथ खा कर कह सकता हूं कि मुझे ऐस.ऐच.ओ. ने कुछ बताने से इन्कार किया वरना मुझे तार देने की क्या जरूरत थी। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जो पुलिस अफसर लेजिसलेटर्ज़ के साथ इस तरह का सलूक करते हैं उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लेंगे ?

मन्त्री : मेरी अर्ज़ है कि जो कुछ इन्होंने अब यह कहा है जहां तक तहकीकात का ताल्लुक है उस से ऐसा साबित नहीं हुआ। फिर भी अगर मैम्बर साहिब बज़िद हैं तो इन्क्वायरी की जा सकती है।

श्री मंगल सेन : यह नार्मल प्रोसीजर की बात है और यहां रोज़ कहा जाता है कि किसी की रिपोर्ट को दर्ज करने से इन्कार नहीं किया जा सकता लेकिन मैं अर्ज़ करता हूं कि एक लैजिसलेटर के साथ 40/50 आदमी गए और उन्होंने थानेदार को बताया कि इस किस्म के आदमी को एक सिपाही बुला कर ले आया था और अब उसका पता नहीं चलता। थानेदार कहने लगा कि मुझे पता नहीं वह कहां गया है। उसके बाद फिर मैंने तार दी। उसके बाद उसकी समझ में आया कि अब यह बात छिप नहीं सकती। फिर उसने उसके खिलाफ 457/380 का केस बना दिया। ऐसा काम आज आपके पुलिस अफसर करते हैं कि....

Mr. Speaker : After the assurance of the hon. Minister what more do you want now ?

श्री मंगल सेन : इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए और यह डी.आई.जी. से कराई जाए।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : वज़ीर साहिब के जवाब से मैं इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि किसी पुलिस अफसर के खिलाफ अगर कोई लैजिसलेटर शिकायत करता है तो उसके इमीजियेट बास से उस की इन्कवायरी कराते हैं। क्या वह यह विश्वास दिलाने के लिये तैयार हैं कि ऐसे मामला की इमीजियेट बास की बजाए यहां चंडीगढ़ से किसी बड़े अफसर या विजीलैंस के बड़े अफसर से इन्क्वायरी कराई जाएगी ?

मन्त्री : अगर आप मुनासिब नहीं समझते कि यहां शिकायत करने वाला लैजिसलेटर हो तो वहां इमीजिएट बास या डी. एस. पी. इन्क्वायरी न करे तो आयंदा के लिये ऐसे केसों में ऐस. पी. की ड्यूटी लगा देंगे कि वह इन्क्वायरी करे।

श्री खुरशीद अहमद : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, जैसे श्री मंगल सेन जी के साथ वहां हुआ वैसा ही वाक्या यहां कल हाउस के प्रिसिंकट्स में हुआ है। पुलिस कहती है कि वहां हमारी जियुरिसडिक्शन नहीं है। कल कोई 60 के करीब मैम्बर साहिबान ने लीडरशिप के चुनाव के सिलसिले में दस्तखत करके दिए लेकिन एक बड़े इम्पार्टैंट मैम्बर ने उस कागज़ को छीन कर फाड़ दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा, थाने में जाएं या आपके पास आएं ? (हंसी)

Mr. Speaker : You can lodge this report to me because it happened within the precincts of this House. (*laughter*)

श्री बलरामजी दास टंडन : अगर आपके पास पुलिस थाना कोई खुला है तब तो आपको रिपोर्ट करें वरना यह मामला बड़ा सीरियस है प्रीविलिज कमेटी को जाना चाहिए।

Mr. Speaker : Anything which happens within the precincts of the House can be reported to me.

———

Smugglers arrested in 1964-65

***7885. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the names and the addresses of smugglers arrested and detained in the State during 1964-65, alongwith the date of arrest and the period of detention of each ?

Sardar Darbara Singh : A statement showing the names, etc. of 10 persons, who were also reported to be smugglers, were arrested under rule 30(1)(b) of the Defence of India Rules for activities prejudicial to Defence of India and Civil Defence. According to rules no period of detention is mentioned in the detention orders. Their cases are, however, reviewed after every six months by the Reviewing Authority, consisting of the Chief Secretary and the Commissioner, Jullundur Division.

Statement showing the names and the addresses of smugglers arrested and detained in the State during 1964-65 alongwith the date of arrest

Serial No.	Name and addresses of smugglers arrested and detained during 1964-65	Date of arrest
1	Shri Santa Singh, son of Thakar Singh, resident of Havelian, police station Gharinda, district Amritsar	11th May, 1964
2	Mehan Singh, son of Udham Singh of Maluwal, police station Gharinda, district Amritsar	Ditto
3	Sarmukh Singh, son of Surain Singh, Jat, Maloutwala, police station Gharinda, City Amritsar	17th May, 1964
4	Shri Harpal Singh, son of Swarn Jat of Nowshera, police station Gharinda now Taylor Road, Amritsar	4th July, 1964. Released on 16th February, 1965. Again arrested on 18th February, 1965
5	Shri Jarnail Singh, son of Lachhman Singh of Jathaul, police station Gharinda now Bhartu Pura, police station Jandiala, district Amritsar	4th July, 1964. Released on 23rd January, 1965. Again arrested on 24th January, 1965
6	Ajit Singh, son of Jawahar Singh, resident of Burj, police station Gharinda, district Amritsar	6th July, 1964. Released on 16th February... 1965. Again arrested on 18th February, 1965
7	Swarne Shah, son of Wassan Singh Jat of Nowshera Dhalla, police station Gharinda, now Taylor Road, Amritsar	10th February, 1965
8	Naranjan Singh, son of Sher Singh *alias* Sardul Singh, resident of Buchar, police station Jhabal now Bhagtanwala Gate, Amritsar	19th July, 1964. Released on 16th February, 1965. Again arrested on 18th February, 1965
9	Manohar Lal, son of Panna Lal of Katra Bhai Sant Singh, police station 'D' Division, Amritsar	18th November, 1963
10	Karnail Singh, son of Ranga Singh , Jat, resident of Roranwala district Amritsar	Ditto

कामरेड राम चन्द्र : होम मिनिस्टर साहिब ने मुझे जो इस सवाल के बारे में स्टेटमैंट दी है उस में लिखा है कि the names etc of 10 persons who were also reported to be smugglers. मैं मंत्री महोदय से दरयाफत करना चाहता हूं कि ऐसे शख्स भी हैं जो कि समगलिंग के इलावा किसी इलज़ाम में गिरफतार नहीं किए गए ?

मन्त्री : सवाल में पूछा गया कि 1964–65 में कितने समगलर्ज़ अरैस्ट किए गए और कितने डिटेंड किए गए । उस के बारे में जवाब दे दिया गया है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਆਨਰੇਬਲ ਮੰਬਰਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿਘ ਤਰੱਸਿਕਾ ਅਤੇ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿਨੀ ਇਤਲਾਹ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣ ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि अजीत सिंह, पुत्र जवाहर सिंह, गांव बुर्ज, पुलिस थाना घारिंडा, ज़िला अमृतसर को पहले 6 जुलाई, 1964 को गिरफतार किया गया उस के बाद उस को 16 फरवरी, 1965 को रिलीज़ किया गया और 18 फरवरी, 1965 को दोबारा गिरफतार किया गया । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब उस को 16 फरवरी, 1965 को छोड़ा गया था तो उस वक्त सरकार को पूरी तसल्ली नहीं हुई थी कि वह स्मगलर नहीं है । और उस को 18 फरवरी, 1965 को दोबारा गिरफतार करने का क्या कारण है ।

मन्त्री : इस के लिए मेरा वही जवाब है जो कि मैं ने पहले दिया है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ 16 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ 18 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਏ ਗਏ । ਮੈਂ ਮਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਛਡਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ?

ਮਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਉਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰ ਪਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪਸੇਫਿਕ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, मिनिस्टर साहिब इस बारे में डिटेल्ड स्टेटमेंट देना चाहते हैं, इस लिए इस सवाल को आज पोस्टपोन कर दिया जाए ।

मन्त्री : नो स्टेटमेंट । इस के लिए सैपेरेट नोटिस दिया जाए ।

कामरेड राम प्यारा : मन्त्री महोदय ने जो लिस्ट इस के बारे में हाउस में रखी है उस से पता चलता है कि यह 10 स्मगलर्ज़ अमृतसर ज़िले के हैं । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इतनी मनाप्ली अमृतसर ज़िले को क्यों दी जा रही है और क्या बाकी ज़िलों में कोई भी स्मगलर्ज़ नहीं हैं ?

मन्त्री : क्योंकि करनाल ज़िले की हद पाकिस्तान से नहीं मिलती इस लिए वहां पर कम होंगे ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मन्त्री महोदय ने कामरेड राम प्यारा के सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि ज़िला करनाल की हद पाकिस्तान से नहीं मिलती, इस लिए वहां पर स्मगलर कम ही होंगे । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अमृतसर ज़िला के अलावा फिरोज़पुर ज़िला और बहुत सारे कई दूसरे ज़िले भी हैं जहां पर पाकिस्तान की हद मिलती है, वहां पर स्मगलर्ज़ क्यों पैदा नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष : पण्डित चिरंजी लाल, आप हरियाणा के बारे में ही ध्यान रखें (हंसी) (Let the hon. Member confine his attention to the affairs of Hariana only) (*Laughter*)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : स्पीकर साहिब, वैसे तो हम हर लिहाज़ से बैकवर्ड हैं लेकिन इस लूट में भी हमारा हिस्सा नहीं है (हंसी)

श्री मंगल सेन : क्या मन्त्री महोदय कृपया बताएंगे कि ज़िला अमृतसर में जय इन्द्र सिंह, एम. एल. ए. के विरुद्ध किसी ने भूख हड़ताल की और इस के विरुद्ध क्यों ऐक्शन नहीं लिया जा रहा इस से तो ऐसा लगता है कि यह काम अमृतसर वालों के लिए मौजूं है (हंसी)

बाबू अजीत कुमार : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਨੇ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ? (ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : Not allowed.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : 4 ਸਮਗਲਰਜ਼ 16 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਫੜ ਲਏ ਗਏ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੀਟਿਂਗ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : मन्त्री साहिब ने बताया है कि अमृतसर ज़िले के लोग ही समगलिंग में पकड़े गए हैं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या बाकी ज़िलों में स्मगलर्ज़ नहीं हैं ? क्या वहां पर पुलिस पकड़ने के लिए वारंट इशू करती है और क्या वह पकड़े नहीं जाते हैं ? अमृतसर डिस्ट्रिक्ट को क्यों इतनी प्रैफरेंस दी जा रही है ?

मंत्री : बाकी ज़िलों में समझदार आदमी होंगे (हंसी)

कामरेड राम चन्द्र : क्या मन्त्री महोदय कृपया बताएंगे कि क्या कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए थे जिन्होंने सोने, लौंग और कपड़े की स्मगलिंग की हो ?

मन्त्री : इन समगलरों को डिफैंस ग्राफ इंडिया रूल्ज़ के अधीन भी पकड़ा जाता है । अगर इस के विरुद्ध केस सब्सटांशिएट हो जाए तो मुकद्दमा चलाया जाता है ।

Mr. Speaker : Next question please.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਫਾਈਨਲ ਪੁੱਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ?

Mr. Speaker : He has demanded a separate notice.

Comrade Shamsher Singh Josh : He has said that he will give a statement . . . .

Minister : I have said that I will reply on a separate notice.

Arrest of persons using bogus import licenses

***7886. Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether any persons were arrested in Ludhiana, Jullundur or in any other districts in the Punjab on the charge of using bogus import icenses for iron and steel, etc., if so, their names and the value of the import licenses of each ;

(b) the details of the legal action, if any, taken in each case ?

Sardar Darbara Singh : (a) No.

(b) Nil, in view of (a) above.

कामरेड राम चन्द्र : मैं वज़ीर साहिब से यह दरयाफ्त करना चाहता हूं कि क्या यह अमर वाक्या नहीं है कि लुध्याना के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ आफिस से बहुत से लाइसैंस फार्मज़ चुराए गए और झूठे लाइसैंस बना कर लोहा और दूसरी धातें इम्पोर्ट की गई ?

गृह मन्त्री : जवाब बिल्कुल वाज़िह है इस में झगड़े की कोई बात ही नहीं है ।

बाबू अजीत कुमार : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟਸ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਗਸ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि यह इम्पोर्ट लाइसेंस अमृतसर, लुधियाना और गुरदासपुर में ही क्यों दिये जाते हैं, और कहीं क्यों नहीं दिये जाते ?

Mr. Speaker : It does not arise.

कामरेड राम चन्द्र : मैं वज़ीर साहिब से यह दरयाफत करना चाहता हूं कि क्या यह अमर वाक्या है या कि नहीं कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ ओफिस से इम्पोर्ट लाइसेंस फार्म्ज़ चुराई गई और इस के बारे में भारी तहकीकात भी हुई, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ आफिसर को तबदील भी किया गया, इस बारे में मिनिस्टर क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप का सवाल तो बोगस इम्पोर्ट लाइसेंस के बारे में है। फार्म्ज़ चोरी हुए कि नहीं यह तो सैपेरेट बात हो गई । (This question relates to the issue of bogus import licenses. A separate notice is required for the theft of forms.)

Comrade Ram Chandra : On the basis of those licence forms, they prepared the drafts and exported the material . . . . .

Mr. Speaker : The forms are applications for getting licences. The licences are given by the Government.

श्री मंगल सैन : क्या यह बात सच है कि जब सरदार प्रताप सिंह जी मुख्य मन्त्री थे तो उस वक्त बड़ी छान बीन हुई थी कि कौन कौन बोगस कोटा होल्डर हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उस रीपोर्ट की बिना पर कोई गरिफतारी हुई थी कि नहीं ?

मन्त्री : इस के लिये नोटिस चाहिये, कामरेड राम चन्द्र के सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं कि जवाब तो मैं ने वाज़िह दे दिया था । एक केस मेरे नोटिस में फीरोज़पुर का आया है वह मैं बताना चाहता हूं ।

It has been reported by the Senior Superintendent of Police, Ferozepur that a case of obtaining import licence for veg tables, etc., on the basis of forged certificates, etc., was detected and on the written report of the Deputy Registrar, Co-operative Society, Jullundur a case F.I.R. No. 120, dated 17th September, 1963, under section 120-B, 420/465 I.P.C. was registered at Police Station City Ferozepore. Shri Jasbir Singh, Secretary, etc., etc. and the Steno to the Assistant Registrar, Co-operative Society, Ferozepore were arrested in this connection on 16th December, 1964 and 21st January, 1965 respectively and have since been bailed out. The case is under investigation. This case involves comparison of the hand-writing of several persons which is a lengthy procedure.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਗਸ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਜਿਸਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿਟ ਦੀ ਏਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੈਂਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਖਤਰਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ।

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਡੀਟੇਲਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜੈਨਟਲ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ.. .

ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲਉ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਅਛਾ ਜੀ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਲੈਬ ਬਟਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਗਸ ਕੋਟਾ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਕ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ: ਇਨਸਿਨੂਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲਜ਼ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ।

श्री मंगल सेन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि चौधरी हरद्वारी लाल जी हमेशा इस हाउस में कहते हैं कि हरयाणा बड़ा बैकवर्ड है और उस को काफी हिस्सा मिलना चाहिये तो बोगस कोटे का और स्मगलिंग का हिस्सा क्यों नहीं हमें दिया जाता ।

श्री अध्यक्ष: मिलता तो होगा लेकिन पकड़े नहीं जाते । (There must be somebody receiving the share. Only their cases have not come to light.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਗਸ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬੋਗਸ ਕੋਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਗਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬੋਗਸ ਆਦਮੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਉਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗਲ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਿਉ। (Let the hon. Member Sardar Lachhman Singh leave this matter here. It is a long tale as from bogus quotas he will come to bogus men and there will be no end to it.)

कामरेड राम प्यारा : पंजाब गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट लाइसेंस दिये हैं और कोटे दिये हैं इस काम की निगहबानी करने के लिये कि आया इन की मिसयूटीलाइज़ेशन तो नहीं हो रही । क्या पंजाब गवर्नमेंट ने कोई एजेंसी मुकर्रर की हुई है कि नहीं ? अगर कोई बना रखी है तो क्या उस ने कोई ऐसी रिपोर्ट की है कि कुछ कोटा होल्डर्ज़ मिसयूटीलाइज़ कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : सवाल तो इम्पोर्ट लाइसेंस के बारे में है । (The scope of the question is limited to the issue of import licences only.)

Would the Home Minister like to say something ?

गृह मन्त्री : यह तो एक जनरल सा सवाल है । जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है वह है ही इस बात के लिए कि वह यह देखे कि जो कोटाज़ हैं वह मुनासिब आदमियों को मिलते हैं या नहीं और अगर इस सम्बन्ध में कोई शिकायत आए तो इनक्वायरी करें और इस बात की देखभाल करें कि वह शिकायत ठीक है या गलत ।

Commission to ascertain causes of Backwardness of the Hindi Region

*7274. **Chaudhri Hardwari Lal :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether Government has decided to appoint a Committee or Commission for ascertaining the causes and extent of the backwardness of the Hindi Region, if so, its terms of references and its personnel ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. The Government has set up a Committee named 'Haryana Develo~ment Committee' covering the districts of Hissar, Rohtak, Gurgaon, Karnal, Mahendragarh, Jind and Narwana tehsils of Sangrur District and Jagadhri, Naraingarh and Ambala tehsils of Ambala District.

(b) The terms of reference are as under :—

(i) to make a study of socio-economic conditions with a view to assessing the economic deficiencies as well as the prospective potentialities of the region ;

(ii) To make an assessment of the progress likely to be achieved by the end of the Third Plan ;

(iii) To recommend developmental measures for an accelerated and integrated socio-economic growth of the region, with particular reference to the Fourth Five-Year Plan.

(c) The Committee consists of the following members :—

(1) Shri Shri Ram Sharma ..	Chairman
(2) Shri Gajraj Singh, M.P. ..	Member
(3) Shri Sher Singh, M.L.C. ..	Do
(4) Shri Chand Ram, M.L.A. ..	Do
(5) Shri Hardwari Lal, M.L.A. ..	Do
(6) Shri Nihal Singh, M.L.A. ..	Do
(7) Shrimati Om Prabha Jain, M.L.A. ..	Do
(8) Shri Suraj Mal ...	Do
(9) Shri G. L. Bansal, Secretary-General, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, New Delhi	Do
(10) Shri Saroop Krishen, I.C.S., Financial Commissioner, Planning, Punjab	Do
(11) Shri R. S. Randhawa, I.A.S., Commissioner for Agricultural Production and Rural Development, Punjab	Do
(12) Shri A. N. Kashyap, I.A.S., Commissioner, Ambala Division	Do
(13) Shri Hoshiar Singh, Deputy Commissioner, Sangrur	Do
(14) Shri Gurdit Singh, Economic and Statistical Adviser, Punjab	Do
(15) Shri L. C. Gupta, I.A.S. ...	Member Secretary

चौधरी देवी लाल : क्या होम मनिस्टर साहिब बताएंगे कि आया यह कमेटी हरियाणा में जो अब तक डिवैलपमैंटल वर्क्स में बैकवर्डनैस रही है, उस के कारणों को भी देख सकेगी और क्या वह सर्विसिज़ में और पुलिटिकल रिप्रैज़ेंटेशन में जो कमी रही उन की भी जांच कर सकेगी ?

श्री अध्यक्ष : उस की टर्म्ज़ श्राफ रेफरैंस उन्होंने बता दी हैं। (He has already explained its terms of reference.)

चौधरी देवी लाल : मैं भी तो जनाब यही पूछ रहा हूं कि क्या वह इन बातों को भी उन टर्म्ज़ श्राफ रैंफरैंस में शामिल करने को तैयार हैं ?

गृह मन्त्री : अर्ज़ यह है कि यह सवाल तो इस से एराइज़ नहीं होता । लेकिन जिन को भी इस कारण किसी तरह की कोई शिकायत हो वह उसे सरकार के नोटिस में ला सकते हैं श्रौर उस शिकायत का तदारक करने के ज़रायें सरकार के पास मौजूद हैं ।

चौधरी खुरशीद ग्रहमद : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं वह पहले कितनी कमेटियों के चेयरमैन रह चुके हैं । क्या यह वही सज्जन हैं जो कि नान-ग्राफिशियल विजिलैंस कमेटी के चेयरमैन थे श्रौर बाद में इकनामिक कमेटी के चेयरमैन बने ? क्या उन्होंने इन के बारे में कोई रिपोर्ट पेश की या नहीं की श्रौर ग्रगर उन्होंने रिपोर्ट पेश की तो सरकार ने कोई ऐक्शन लिया या नहीं लिया ?

Mr. Speaker : This is beyond the scope of the Question. The hon. Member may please take his seat.

चौधरी खुरशीद ग्रहमद : उन को चेयरमैन ही इसीलिए बनाया जाता है । जो मामला खटाई में डालना हो उसके लिए वही रियल मैन होता है ।

श्रीमती श्रोम प्रभा जैन : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कमेटी बनाई गई है जिस पर नान-ग्राफिशियल श्रौर टाप रैंकिंग ग्राफिशियल्ज़ हैं, इस की रिपोर्ट एेडवाज़री कैपैसटी की समझी जाएगी या सरकार उस की सिफारिशात को मंज़ूर करेगी । क्या वह रिपोर्ट सरकार पर बाईंडिंग होगी या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

श्री श्रमर सिंह : जैसा कि मनिस्टर साहिब ने नाम पढ़े हैं उन से साफ जाहिर है होता है कि यह "झज्झर कमेटी" है । क्या यह फरमाएंगे कि हरियाणा की बैकवर्डनैस को दूर करने के लिए यह कमेटी कब तक रिपोर्ट दे देगी श्रौर यह कि सरकार उस पर किस ढंग से श्रमल करेगी ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਝੱਜਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਲੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ?

मन्त्री : अर्ज़ यह है कि इस के लिए जो पीरियड मुकर्रर किया गया है वह चार महीने का है कि इन चार महीनों के ग्रन्दर ग्रन्दर वह ग्रपनी टर्म्ज़ ग्राफ रैफरैंस के मुताबिक तहकीकात करके ग्रपनी रिपोर्ट दे दें ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या गृह मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह जो कमेटी बनाई गई है इस के चेयरमैन श्रौर मेम्बर्ज़ केलिए कोई डेली एलाऊंस वगैरा के रेट्स भी मुकर्रर किए गए हैं श्रौर ग्रगर किए गए हैं तो चेयरमैन के लिए क्या हैं श्रौर मेम्बर्ज़ के लिए क्या हैं ?

मन्त्री : अर्ज़ यह है कि कमेटी के जो मेम्बर हैं वह एम. एल. एज़. श्रौर ऐम. ऐल. सीज़. हैं, ज्यादातर वही हैं । इसलिए उन के बारे में तो यह तै करने की ज़रूरत नहीं । बाकी चेयरमैन श्रौर चौधरी सूरज मल जो कि लैजिस्लेचर के मेम्बर नहीं हैं उन के बारे में भी कोई फैसला लिया जा रहा है ।

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि गज़ट के अन्दर जो छपा है उसके अन्दर तो लिखा है कि वह सौ रुपया लेंगे, उन की डिस्पोज़ल पर एक कार होगी और उन को बंगला फ्री मिलेगा.....

मन्त्री : किस को ?

श्री बलरामजी दास टंडन : चेयरमैन को ।

मन्त्री : चेयरमैन के बारे में यह फैसला है कि वह चण्डीगढ़ हैडक्वार्टर पर रहेगा । उसके लिए एलाउंस और उस कमेटी से मुताल्लिका जो आने जाने का खर्च होगा उस के बारे में फैसला हो चुका है । यह ठीक बात है ।

श्री बलरामजी दास टंडन: स्पीकर साहिब, मैंने सवाल भी यही किया है कि पिछले सवाल का जवाब देते हुए मनिस्टर साहिब ने यह बात नहीं बताई जो कि साफ तौर पर गज़ट में आ चुकी हुई है ।

Mr. Speaker : When it has come in the Gazette the hon. Member need not put any question about it.

श्री बलरामजी दास टंडन : जवाब देते वक्त उन को यह कनफर्म तो कर लेना चाहिए कि इस में कोई कन्ट्राडिक्शन तो नहीं ।

Mr. Speaker : There is no contradiction. He has clarified the position.

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । अर्ज़ यह है कि गज़ट में तो मामूली सी ट्रांसफ़र्ज़ की बाबत भी नोटीफिकेशन आ जाता है । मैं आप की इस बात पर रूलिंग चाहता हूं कि क्या जो बात गज़ट में आ जाए क्या उसकी बाबत हाउस में सवाल न पूछे जाएं ?

श्री अध्यक्ष : जो इनफर्मेशन मेम्बर साहिबान के पास हो उसकी बाबत सवाल नहीं पूछा जा सकता । (The hon. members cannot seek information through supplementaries which they already possess.)

Mr. Speaker : Question Hour is over.

चौधरी देवी लाल : मेम्बर साहिबान को इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वह इन सब चीज़ों को पढ़ सकें । उन को आजकल फ़ुर्सत ही नहीं होती.....

Mr. Speaker : Question Hour is over. More supplementaries on this Question may be put in the next sitting.

Point of order

श्री बलरामजी दास टंडन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहब, आप ने फरमाया है कि जो चीज़ गज़ेट में नोटीफाई हो जाती है उस के बारे में यहां सप्लीमेंटरी नहीं पूछे जा सकते । मैं अर्ज़ करता हूं कि गज़ट के अन्दर तो हर छोटी मोटी चीज़ यानी अफसरों की ट्रांसफर्स के बारे में, या कोई एक महीने की छुट्टी पर ही जाए तो भी वह गज़ट में छापा जाता है अगर इस तरह से इजाज़त नहीं होगी यानी जो चीज़ गज़ट में छप गई है तो उस के बारे में सवाल नहीं पूछे जा सकते तो इस तरह तो सारे के सारे सवाल जो यहां पूछे जाते हैं वह रूल आऊट हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट की हर छोटी मोटी चीज़ गज़ट में छापी जाती है । मैं इस बारे में आप की रूलिंग चाहता हूं ।

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Mr. Speaker, I want to know you suling whether the Gazette is an accessible document according to the provisions of the Rules ?

Mr. Speaker : Yes, certainly. It is a public document and I thiek a copy of it is sent to every Member. Any information which is containd in the accessible documents, cannot form the basis of a question.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहब, अगर यह चीज़ है तो आप जितने भी सवाल सैक्रेटेरियट में जवाब देने के लिए भेजते हैं उन के जवाब में जो इनफरमेशन आनी होती है वह तकरीबन सारी की सारी गज़ेट हो चुकी होती है इस तरह तो वे सारे सवाल ही रूल आऊट हो जाएंगे ।

श्री अध्यक्ष : सारे नहीं होते । (All such information is not notified.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : नहीं स्पीकर साहब, वह सारे होते हैं और फिर तो उन का यही जवाब आ जाना चाहिए कि क्योंकि वह इनफरमेशन नोटीफाई हो चुकी है इस लिए इस का जवाब नहीं दिया जा सकता ।

Mr. Speaker : Rule 46 of the Rules of Business relates to the admissibility of Questions. The conditions in regard to their admissibility are given therein. These Rules have been framed by the House. Condition (12) of this Rule, lays down :

> "it shall not require information contained in documents ordinarily accessible to the people or in ordinary works of reference."

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहब, वैसे तो सब कुछ अखबारों में आता है जो कुछ हम यहां पूछते हैं । आप को तो मालूम ही है कि प्रिंसिपलज़ की ट्रांसफर के बारे में एक सवाल का नोटिस दिया गया था जो आप ने एडमिट भी किया है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले उन की ट्रांसफरज़ हुई और बाद में उन को वहीं पर रहने दिया गया । अगर गज़ट नोटिफिकेशन की बात मान ली जाए तब तो वह सवाल एडमिट नहीं होना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष : मैं यह देख कर सवाल एडमिट नहीं करता क्योंकि एक आदमी की ट्रांसफर हो गई है और न ही वह सवाल इस बिना पर एडमिट किया गया था । वह सवाल तो इस लिए एडमिट किया गया था क्योंकि उन की पहले ट्रांसफर के आर्डर हुए थे और बाद में वह कैनसल कर दिए गए थे । (I do not admit a Question because it relates to the transfers of certain persons nor was that particular question admitted on this very ground. I had admitted that question because at first the transfer orders had been passed and later on cancelled).

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । आप ने रूलज़ का हवाला दे कर फरमाया है कि जिस चीज़ की गज़ेट नोटीफिकेशन हो गई हो उस के बारे में सवाल एडमिट नहीं किया जा सकता लेकिन मैं आप का ध्यान अपनी कन्सटीच्यूशन की उस धारा की तरफ दिलाता हूं जिस में यह दिया हुआ है कि विधान सभा के अनपढ़ आदमी भी मेम्बर बन सकते हैं और बतौर मेम्बर के उन को हक हासल है कि वह इ फरमेशन हासल कर सकें । अगर वह गज़ेट नोटीफिकेशन न पढ़ सकें तो क्या वह अपनी वज़ाहत के लिए कोई स्पलीमैंटरी नहीं पूछ सकता ? इस बारे में मैं आप की रूलिंग चाहता हूं ।

Mr. Speaker : This point can be discussed in the Rules Committee. The Committee may amend the Rules, if so desired.

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, आप तो गजेट की ही बात कर रहे हैं । मैं आप का ध्यान इस बजट के इस पोथे की तरफ दिलाता हूं । इस में सारी इनफरमेशन दी हुई है लेकिन फिर भी आप इस पर कई दिनों से बहस की इजाजत दे रहे हैं अगर आप की.....

श्री अध्यक्ष : बजट के बारे में डिस्कशन तो हो सकती है लेकिन इस के बारे में कुछ इनफरमेशन हासल करने के लिए सवाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती । जो कुछ रूल्ज में है मैं तो उसी के मुताबिक इजाजत दे सकता हूं । (There can be a discussion on the Budget but Supplementaries cannot be allowed for seeking information already given there in. Whatever is provided in the Rules of Procedure, I have to permit things accordingly.)

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, अगर रूल्ज कमेटी ने रूल्ज अच्छे नहीं बनाए तो उन को बदल क्यों नहीं लिया जाता ।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में तो रूलज कमेटी ही फैसला कर सकती है । लेकिन मौजूदा हालात में बजट के मुताल्लिक कोई इनफरमेशन सवाल की शक्ल में नहीं आ सकती । (Only the Rules Committee can take any decision in this respect. But under the present circumstances, no information regarding the Budget can be allowed to be sought through questions.)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Backward Areas and their Development

***7496. Shri Sagar Ram Gupta :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the areas which have been declared as backward areas in the State together with the details of limits of such areas, in each case ;

(b) the detailed measures taken by the State Government during the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65 to date to bring the said backward areas at par with the other areas of the State, in the matter of development ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of the Government to appoint a Committee of experts to enquire into the conditions of the backward areas and to suggest measures for their development if not, the reasons therefor ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) A list is laid on the Table of the House.

(b) No separate accounts for expenditure incurred in backward areas have been maintained. However, special attention is being given in the matter of allotment of funds for execution of development schemes in these areas, such as rural development works, construction of roads, setting up of village industries, national sanitation and water-supply programmes, etc. In the matter of admissions the students belonging to the backward areas in the

State have been allowed special concession. In addition to the normal quota fixed for such admissions in Government Colleges and Institutions 10 per cent of the seats are reserved for students permanently residing in backward areas. For admission to J.B.T. classes 40 per cent seats are reserved for candidates who are bonafide residents of rural and backward areas.

(c) A special Hariana Development Committee has been constituted to apparise the economic deficiencies, assess the material resources and recommend measures to secure expeditiously an integrated socio-economic development of the entire Hariana area which is comparatively a more backward area of the State.

List of Backward Areas declared by the Punjab Government

Bet areas of the Sutlej in the districts of Hoshiarpur, Ludhiana, Jullundur, Ferozepore and Amritsar.

Khadar Area between the Jumna and the G. T. Road of Rohtak and Karnal Districts.

Rewari, Nuh and Ferozepore-Jhirka Tehsils of Gurgaon District.

The area falling between the Saggi Nullah and the river in the Ajnala Tehsil of Amritsar District.

The whole of Kangra District.

The whole of Una Tehsil and Sub-mountain areas of Dasuya and Garhshankar Tehsils in Hoshiarpur District.

Naraingarh Tehsil and the Sub-mountain areas of Rupar, Kharar and Jagadhri Tehsils of Ambala District.

In case of doubt the certificate o' th ; Deputy Commissioner that a person belongs to a backward area in his district and is a permanent resident of it will be conclusive.

Una Tehsil of Hoshiarpur District, Mukerian Police Station including the villages Nawshera, Harsa, Kalota, Kolian, Mehtabpur, Salerian, Simbli, Hehannpur, Sanyal, Salowal Haler, Janardhan, Mussahibeyr, Cheoran, Chaurian, Motla, Mansar, Chhantan, Janwal, Gurdaspur, Manjpur, Bhangal, Narchandan, Panoori Latipur, Ladpur, Palakhi, Bachupur, Budhabar, Khundpur, included in Bachawhi Illaqa, the Sub-mountain region of the Hoshiarpur Tehsil including big villages like Dholbaha and Janauri and the Kandi area, i.e., the area lying between the Shivalik Range and the Road connecting Talwara, Hajipur, Mukerian, Dasuya, Hariana, Hoshiarpur, Garhshankar, Balachaur and Rupar.

Areas of Gurdaspur District lying between Kiran Nallah and river Ravi.

Mohindergarh District.

Mansa Tehsil of Bhatinda District.

The bet areas of Kapurthala District, i.e., the entire area of Bholath Circle and the whole area of Kapurthala District towards the West of Kartarpur, Kapurthala and Dadwindi Old Road and Dadwindi, Dhalla New Ferozepore Road.

Sunam Sub-Tehsil of district Sangrur.

Jind Sub-Division, district Sangrur.

Kandaghat Sub-Division, District Patiala and Sub-Tehsil Samara of district Patiala.

[Minister for Public Works and Welfare]
Gohana Tehsil of district Rohtak.

Area covered by Police Station Lalru and Dera Bassi of Rajpura Tehsil, district Patiala.

Bet areas of the Chamkaur Sahib, the Rupar and the Manimajra Block in the Ambala District.

Bet area of Gurdaspur Tehsil.

Thirty-eight flood-affected villages in Gurdaspur District and 154 such villages in Amritsar District.

Areas in the villages comprising Zail and Dhamrai in district Gurdaspur.

Market Fee realised from Peasants in Faridkot Market

***7152. Comrade Didar Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether it has come to the notice of the Government that in the Faridkot Market 20 per cent market fee out of the fee realised from the peasants is pocketed by the Traders ; if so, the steps taken or proposed to be taken to stop this practice ?

Sardar Darbara Singh : No market-fee is realised from the peasants. The market-fee is leviable from licensee-buyers, and in case the buyer is a non-licensee, the market-fee is paid by the licensee-seller, after realising it from the buyer. During the course of inspection of accounts of certain dealers, the Secretary, Market Committee, Faridkot, has recently detected evasion of payment of market-fee by dealers. The matter has also been referred to the Market Committee, Faridkot, by the Secretary of the said Committee, for in assessment notices to the defaulters to determine the amount payable as market-fee.

Shortage of Chemical Fertilizer in the State

***7153. Comrade Didar Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether it has come to the notice of the Government that there is a big gap between the demand and the supply of chemical fertilizers in the State ; if so, the steps taken or proposed to be taken to remove this shortage ?

Sardar Darbara Singh : Yes. There is over-all shortage of fertilizers in the country. The Government of India is being requested for larger allocation of fertilizers for this State.

Transfer of Secretaries, Market Committees, Dabwali and Tohana

***7270. Chaudhri Devi Lal :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Shri Jagan Nath, Secretary, Market Committee, Dabwali, was transferred to Tohana in the month of November or December, 1964 ;

(b) whether it is also a fact that Shri Dhani Ram, Secretary, Market Committee, Tohana, actually arrived at Dabwali to relieve Shri Jagan Nath, if so, for how long he had to wait at Dabwali in order to assume charge;

(c) whether it is a fact that the transfers mentioned above were eventually cancelled ; if so, by whom and the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) Yes. Shri Dhani Ram reported himself for duty in Market Committee, Dabwali, on 16th or 17th November, 1964. He had to wait for about a week to assume charge.

(c) The transfers were not cancelled, but were stayed on 24th November, 1964.

Machine for Creating Artificial Growing Conditions for a Crop

***7410. Sardar Gian Singh Rarewla :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) Whether he is aware of the fact that tne Indian Agricultural Research Institute has acquired a machine which artificially creates the desired atmosphere and conditions for growing a crop ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the Punjab Government intend buying one such machine for use in the State ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) No.

Subject—Vidhan Sabha Question No. 7557 (Starred) regarding Foodgrains given to farmer for Seed purposes.

The answer to Vidhan Sabha Question No. 7557 appearing in the list of Starred Questions to be asked at the meeting of the Punjab Vidhan Sabha to be held on the 25th March, 1965, in the name of Shrimati Prasanni Devi, M.L.A., is not ready. This information is being conveyed to the Speaker, who is requested kindly to extend the time for answering the question.

2. The question may be included in the list of questions for any date after the 17th April, 1965.

(S.d) . . . ,
Home and Development Minister,
Punjab.

To

The Speaker,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.
U.O. No. 1574-Agr. II (X)-65/2506, dated the 25th March, 1965.

Crop Insurance Scheme

***7664. Sardar Gurmit Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of the Government to enforce Crop Insurance Scheme under the consideration of the Government to enforce Crop Insurance Scheme in the State in the near future; if so, the steps being taken by the Government in this respect, and the time by which it is likey to be implemented ?

Sardar Darbara Singh : First Part Yes.

Second Part : A skelton staff appointed under the scheme is busy in collecting the basic data.

Third Part : As soon as the Crop Insurance Act is passed by the Parliament.

Obtaining Supply of Diesel Oil and Tractor Fuel from the Union Government

***7665. Sardar Gurmit Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of the Government to approach the Union Government for the supply of diesel oil and other tractor fuel free from duty and supply it on a subsidized and rationed basis to the farmers of the State to enable them to step up food production ; if so, the time by which it is likely to be implemented ?

Sardar Darbara Singh : Part (i) : No.

Part (ii) Does not arise.

Starting Seed Testing Laboratories in the State

***7666. Sardar Gurmit Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under the consideration of the Government to start a Seed Testing Laboratory at each block headquarters so as to ensure a proper supply for pure seed to the farmers in the State ;

(b) if the reply to part (a) above in the affirmative, the total estimated cost likely to be incurred on the said laboratories and the time by which the said Scheme is likely to be implemented ?

Sardar Darbara Singh : (a) No.

(b) Does not arise.

Setting up of a Committee of Eminent Educationists

***7558. Shrimati Prasani Devi :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to set up a Committee of eminent educationists to examine the cases of those educational Institutions in the State which have been showing results below the pass percentage of the University Examinations for the last three years ; if so, the time by which it is likely to be implemented ; if not, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra : (i) No.

(ii) The quantum of the problem does not warrant this. Remedial measures are adopted in each case.

Installation of portrait of Guru Ram Dass Ji

***7408. Sardar Gian Singh Rarewala :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Municipal Committee, Amritsar had decided/passed a resolution to instal the portrait of Shri Guru Ram Dass Ji Maharaj, the founder of the City, in the Town Hall ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the order passed by the Government on the said decision/resolution of the Municipal Committee ;

(c) whether it is a fact that the Government refused the permission in May, 1964 and again in September or October, 1964, on the ground that portraits of National Leaders could only be put by the Municipal Committee ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes.

(b) The Government had in the first instance refused permission but later on necessary sanction for installing the portrait was accorded.

(c) The permission was refused in June, 1964. Sanction was later on accorded in October, 1964 for Rs. 1,000 and this amount was enhanced at the request of the Municipal Committee to Rs. 2,000 in December, 1964.

Chairman Improvement Trust, Bhiwani

***7494. Shri Sagar Ram Gupta :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the name of the Chairman, Improvement Trust, Bhiwani and the date on which he was appointed as such ;

(b) the academic qualifications of the said Chairman together with the details of experience, engineering or otherwise, if any, possessed by him.

Shri Prabodh Chandra : (a) Shri Banarsi Dass Gupta, Ex-President, Municipal Committee, Bhiwani, was appointed Chairman of Improvement Trust, Bhiwani, on the 16th January, 1965.

(b) He is matric and Prabhakar and has practical experience in municipal administration.

Result of Municipal Elections in Hissar

***7972. Shri Sagar Ram Gupta :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the date on which Municipal elections in Hissar were held ;

(b) the date on which the result of the said elections was declared and the names of the successful candidates ;

(c) the date on which the notification about the successful candidates was published in the Government Gazette together with the names of those notified ;

(d) whether it is a fact that the name of one of the successful candidates was not notified along with the others; if so, the reasons therefor ;

(e) whether it is a fact that the name of the candidate mentioned in part (d) above was later on notified in the Gazette; if so, when and the reasons therefor?

Shri Prabodh Chandra : (a) 15th November, 1964.

(b) and (c) Two statements (I &II) containing the requisite information are placed on the Table of the House .

(d) Yes. A case for taking action under section 16 (i) (e) of the Punjab Municipal Act, 1911 against one of the members was pending.

(e) Yes on 6th February, 1965. On examination it was found that no case was made out for refusing to notify his election.

Statement No I

The result of election was declared immediately after the poll was over. The names of the elected candidates are given below—

1. Shri Baldev Tayal
2. Shri Dharam Dev
3. Shri Raj Kishan
4. Shri Salig Ram
5. Shri Raj Kumar
6. Shri Arjan Dev
7. Shri Datta Ram
8. Shri Lal Chand
9. Shri Chandu Lal
10. Shri Richhpal Singh
11. Shri Parshotam Lal
12. Shri Hardeva

[Education and Local Goxernment Minister]

13. Shri Ram Parshad
14. Shri Ghisa Ram
15. Shri Girdhari Lal
16. Shri Surrinder Nath
17. Shri Radha Kishan
18. Shri Ram Singh
19. Shri Ram Dhari Mal
20. Shri Anand Parkash
21. Shri Lachhman Dass
22. Shri Partap Singh
23. Shri Narain Dass

Statement No. II.

The names af the notified persons along with dates of publication of notifications are given below :—

Serial No.	Name of persons	Date of the publication of notification
1	2	3
1	Shri Dharam Dev	5th January, 1965.
2	Shri Raj Kishan	
3	Shri Salig Ram	
4	Shri Raj Kumar	
5	Shri Arjan Dev	
6	Shri Datta Ram	
7	Shri Lal Chand	
8	Shri Chandu Lal	
9	Shri Richhpal Singh	
10	Shri Parshotam Lal	
11	Shri Hardeva	
12	Shri Ram Parshad	
13	Shri Ghisa Ram	
14	Shri Girdhari Lal	
15	Shri Surrinder Nath	
16	Shri Radha Kishan	
17	Shri Ram Singh	
18	Shri Ram Dhari Mal	
19	Shri Anand Parkash	
20	Shri Lachhman Dass	
21	Shri Partap Singh	
22	Shri Narain Dass	
23	Shri Baldev Tayal	6th February, 1965

Introduction of Contributory Health Scheme in the State

*7392. **Sardar Gian Singh Rarewala :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to introduce Contributory Health Scheme in the State; if so, the lines on which this scheme is proposed to be formulated.

Shri Prabodh Chandra : All the aspects of the Scheme are under consideration and a final decision will be taken after knowing the financial implications.

Liquor Licenses in Gurdaspur District

*7845. **Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state the names of Individuals or firms who hold liquor licenses in Gurdaspur district at present ?

Shri Prabodh Chandra : A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Serial No	Name of the Licensee	Name of the vend
1	2	3
	Country Liquor	
1	(i) Shri Magar Mal, son of Nihal Chand of Mukerian ..	Pathankot
	(ii) Shri Ved Parkash, son of Gokal Chand of Phagwara	Do
	(iii) Shri Madan Lal, son of Gokal Chand of Phagwara	Do
2	Shri Ved Parkash Madan Lal, sons of Gokal Chand of Phagwara	Sujanpur
3	(i) Shri Joginder Pal, son of Boote Ram, Dina Nagar ..	Dina Nagar
	(ii) Shri Kishan Chand, son of Chandu Lal, Gurdaspur	Do
4	Gurbaksh Rai, son of Ganga Bishan, Pathankot ..	Dalhousie
5	Shri Dewan Chand, son of Barkat Ram, Inner Bazar, Pathankot	Narot Jaimal Singh
6	(i) Shri Kidar Nath, son of Madho Ram, Jullundur	Batala Main
	(ii) Shri Mangal Sain, Excise Contractor, Hoshiarpur	Do
	(iii) Shri Madan Lal, son of Balmukand, Gurdaspur	Batala Simbal
	(iv) Shri Kans Raj, son of Nathu Ram, Vidola Chak	Do
	(v) Shri Hans Raj, son of Ramji Dass, Batala ..	Do
7	Sarup Singh, son of Dwan Singh, Hargobindpur ..	Siri Hargobindpur
8	Shri Dewan Cnand, son of Kishan Chand, Ghumtala, District, Amritsar	Fatehgarh Churian
9	(i) Shri Mangal Sain, Excise Contractor, Hoshiarpur ..	Quadian
	(ii) Shri Balwant Rai, son of Bansi Lal, Dale Chak ..	Do
	(iii) Shri Narinder Kumar, son of Balmukand Kohli, Gurdaspur	Do
10	(i) Shri Mangal Sain, Excise Contractor, Hoshiarpur ..	Gurdaspur
	(ii) Tilak Raj, son of Kans Raj, Dala Chak ..	Do
	(iii) Madan Lal, son of Balmukand Kohli, Gurdaspur	Do

[Education and Local Government Minister]

Serial No.	Name of the Licensee	Name of the Vend
1	2	3
11	(i) S.K. Kohli, son of Balmukand, Gurdaspur ..	Dhariwal
	(ii) Ajaib Singh, son of Bawa Singh, Kot Santokh Rai	Do
	(ii) Mangal Sain Excise Contractor Hoshiarpur ..	Do
	(iv) Tilak Raj, son of Kans Rai, Dala Chak ..	Do
12	(i) Inder Lal, son of Bhola Ram, Gurdaspur ..	Dera Baba Nanak
	(ii) Charanjit Singh, son of Ram Kishan, Gurdaspur ..	Do
13	Hari Ram, Spo Kulwant Rai, Zira, District, Feroze-Pur	Sarna
14	(i) Diwan Chand, son of Birbal, Banwal, Post Office Sujanpur	Dunera
	(ii) Bakshi Ram , son of Durga Dass, Banwal ..	Do
	(iii) Khushi Ram, son of Sant Ram, Banwal	Do
15	Gurbaksh Rai, son of Ganga Bishan, Pathankot	Mirthal
16	(i) Inder Lal, son of Bhola Ram, Gurdaspur ..	Nanoo Nangal
	(ii) Radha Krishan, son of Khazan Chand, Gurdaspur	Do
17	(i) Dev Raj, son of Bawa Ditta Mal, Gurdaspur ..	Taragarh
	(ii) Joginder Pal, son of Boote Ram, Dina Nagar	Do
18	Nagar Mal, son of Badri Dass, Murara ..	Behrampur
19	(i) Mangal Sain, Excise Contractor, Hoshiarpur	Dorangla
	(ii) Madan Lal Arora, son of Bhagat Ram, Batala ..	Do
	(iii)Tilak Raj, son of Kans Raj, Dala Chak	Do
20	(i) Mangal Sain, Ex-Contractor, Hoshiarpur ..	Aliwal
	(ii) N.K. Mohli, Son of Balmukand, Gurdaspur	Do
	(iii)Nand Kishore, son of Ram Ji Dass, Batala	Do
21	(i) Mangal Sain, Ex-Contractor, Hoshiarpur ..	Ghasitpura
	(ii) Sudarshan Kumar, son of Mulak Raj, Dharamkot Bagga	Do
	(iii) Surinder Kumar, son of Balmukand, Gurdaspur	Do
22	Surinder Kumar, son of Balmukand, Gurdaspur ..	Balpurian
23	(i) Hira Singh, son of Fauja Singh, Sheikhpur ..	Bhagowal
	(ii) Darshan Singh, son of Kehar Singh	Do
24	Diwan Chand, son of Kishan Chand, District, Amritsar	Khera
25	(i) Mangal Sain, Ex-Contractor, Hoshiarpur ..	Punjgarian

Serial No.	Name of the Licensee	Name of the vend
1	2	3
	(ii) Nand Kishore, son of Ramji Dass, Batala	Punjgarian
	(iii) N.K. Mohli, son of Balmukand, Gurdaspur	Do
26	N.K. Mohli, son of Balmukand, Gurdaspur ..	Wadhalagranthian
27	Ranjit Singh, son of Balwant Singh, Rampur, Tehsil Batala	Rangar Nangal
28	(i) Bhagat Singh, son of Man Singh, Sathola ..	Bhuma
	(ii) Charan Singh, son of Sucha Singh, District, Amritsar	Do
29	Bhagat Singh, son of Man Singh Sathola ..	Darewali
30	(i) Jagir Singh, son of Puran Singh, Village Teja ..	Villa Teja
	(ii) Jarnail Singh, son of Sarain Singh Chanda Maja ..	Do
31	Harjant Singh, son of Bhagat Singh, Tehsil Batala ..	Ganiake Bangar
32	(i) Mangal Sain Ex-Contractor, Hoshiarpur ..	Naushera Maja-Singh
	(ii) Sudarshan Kumar, son of Mulak Raj, Dharamkot, Bagga	Do
	(iii) S.K. Mohli, son of Balmukand Gurdaspur	Do
33	Ranjit Snigh, son of Balwant Singh, Rampur ..	Dhariwal
34	Devi Dass, son of Ralla Ram, Tehsil, Gurdaspur ..	Sekhwan
35	S.K. Kohli, son of Balmukand, Gurdaspur ..	Ghukankalan
36	(i) Mangal Sain, Ex-Contractor, Hoshiapur ..	Kahnuwan
	(ii) Narinder Kumar, son of Bal mukand Gurdaspur	Do
	(iii) Balwant Rai, son of Bansi Lal, Dala Chak	Do
37	(i) Mangal Sain Ex-Contractor, Hoshiarpur ..	Tibbar
	(ii) S.K. Mohli, son of Balmukand, Gurdaspur	Do
	(iii) Balwant Rai, son of Bansi Lal, Dala Chak	Do
38	Munshi Ram, son of Sankar Dass, Nangal ..	Adda Shalla
39	(i) Mangal Sain, Ex-Contractor, Gurdaspur ..	Jaurachitran
	(ii) Sudershan Kumar, son of Mulkh, Dharamkot Bagha	Do
	(iii) Surinder Kumar, son of Bal mukand Gurdaspur	Do
40	(i) Joginder Pal, son of Moti Ram, Dina Nagar ..	Kotli Suratmali
	(ii) Inder Lal, son of Bhola Ram ..	Do
	(iii) Kishan Chand, son of Chandu Lal, Gurdaspur	Do
41	(i) Pawan Kumar, son of Charandass Kalanaur ..	Kalanaur

[Education and Local Government Minister]

Serial No.	Name of the Licensee	Name of the vend
1	2	3
(ii)	Doalt Ram, son of Bishambar Dass, Kalanaur	Kalanaur
42	Dewan Chand, son of Kishan Chand District Amritsar	Talwandi Rama
	Foreign Liquor	
1	Ram Lal, son of Ghansham Dass, Jullundur ..	Pathankot
2	Ram Lal, son of Ghansham Dass, Jullundur ..	Dalhousie
3	D.C. Khanna of M/s D·C Khanna and sons, Dalhousie Cantt	Dalhousie Cantt
4 (i)	Santokh Singh, son of Bhagat Singh, Jullundur ..	Gurdaspur
(ii)	Sudesh Paul, son of Hans Raj, Batala	Do
5 (i)	Amolak Singh, son of Mula Singh, Ghumatala District Amritsar	Batala
(ii)	Ajit Singh, son of Labh Singh, Ghumtala District Amritsar	Batala
	Beer	
1 (i)	Amolak Singh, son of Mula Singh, Gumtala District Amritsar	Batala
(i)	Ajit Singh, son of Labh Singh, Gumtala District, Amritsar	Do

Setting up a Pay Commission for Revising Pay Scales of low-paid Government Employees

***6980. Thaker Mehar Singh :** Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to appoint a pay Commission to review the pay scales of low paid Government Employees in the State, if so, the details thereof ?

Sardar Kapur Singh : No, Sir. At present there is no such proposal under the consideration of Government .

Public Speeches made and Statements issued by Chief Minister

***7271. Chaudhri Devi Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state (i) the total number of public speeches made by him ; (ii) the number of written statements issued by him to the Press and (iii) the total number of Press Conferences Addressed by him since his assumption of office as Chief Minister ?

Shri Ram Kishan : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits sought to be achieved.

Contributions made by the Ministers towards the National Defence Fund

***7559. Shrimati Prasanni Devi :** Will the Chief Minister be pleased to state the names of the Ministers in the State who contributed towards

the National Defence fund during the period from July, 1964, to January 1965, together with the details of the amount contributed by each ?

Shri Ram Kishan : None.

Follow up action on Das Commission Report

***6932. Chaudhri Hardwari Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state the names of Government servants and of public men adversely commented upon by Mr. Krishanaswami, appointed to process the follow-up action on the Das Report, in his last report to the Government and also indicate the action taken by Government on the report of Mr. Krishanaswami ?

Shri Ram Kishan : Shri Krishnaswamy's Report is being treated as secret . It is regretted that its contents can not be divulged beyond that what I said in my Statement in the Vidhan Sabha on the 24th September, 1964. The Hon'ble member has given notice of a motion asking for discussion about the follow-up action on the Das Commission Report. The Hon'ble Speaker has allotted two days for this discussion. I will then be making a detail statement on the floor of the House about this matter.

Committees set up by Government

***7272. Chaudhri Devi Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of Government appointed Committees in existance at present alongwith the total number of members of each ;

(b) the total number of Legislative belonging to the Hindi Region (refugees and non-refugees separately) who are members of each of the said Committees separately ;

(c) the number of Committees appointed by the Government since July, 1964, alongwith the total number of Legislators on them and the number of Legislators from the Hindi Region on each of them ?

Shri Ram Kishan : The time and Labour involved, in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Resolution passed by Working Committee of Punjab Pradesh Congress regarding damage caused by floods in the State

***6747. Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister, be pleased to state whether Government has received a copy of the resolution recently passed by the working Committee of the Punjab Pradesh Congress in connection with the damage caused by floods in the State; if so, the action being taken or proposed to be taken by the Government thereon ?

Sardar Harinder Singh, Major (Revenue Minister) : Yes, a copy of the resolution passed by the Punjab Pradesh Congress Committee Executive during October, 1964 in connection with damage caused by floods was received by Government. Adequate relief has been sanctioned by Government to the flood affected people. A statement showing details and nature of relief sanctioned by Government is placed on the Table of the House. Besides this land revenue, abiana and electricity charges have been remitted and recovery of loans postponed.

Statement showing details and nature of Relief sanctioned by Government

1	2	3	4				5		6
			Supply of food				*Fodder*		
Serial No.	District	Adhoc grant for supply of food, shelter and house repair etc.	(i) Grants	(ii) Cooked and uncooked food	(iii) Free Lunger at base camps	(iv) Free ration in marooned and badly affected villages	Grants	Subsidy	Cash payment to indigent persons
1	Ferozepur ..	..	3,00,000	..	10,000	..	50,000	..	..
2	Patiala ..	..	..	..	..	..	..	2,00,000	..
3	Amritsar ..	..	20,000	10,000	10,000	..	50,000	..	..
4	Bhatinda ..	..	20,000	..	5,000	..	10,000	..	..
5	Sangrur ..	..	4,50,000	..	5,000	..	50,000	..	..
6	Hissar ..	..	40,000	..	10,000	..	50,000	..	..
7	Rohtak ..	..	6,50,000	1,00,000	50,000	13,37,330	1,00,000	5,00,000	10,000 +Rs 10,000 for Bread winners
8	Gurgaon ..	..	70,000	..	10,000	6,62,670	..	2,23,800	..
9	Karnal ..	1,00,000	35,000	..	5,000	..	..	2,00,000	..
10	Ludhiana ..	..	4,000	..	..	..	..	..	4,000
11	Ambala ..	..	..	..	..	..	..	..	..
12	D.A.F. Punjab ..	..	..	..	..	..	..	..	—
13	C.E.Pb. (Drainage) ..	..	..	..	..	..	..	..	..
14	D. C. Kapurthala ..	..	..	..	..	..	..	..	..
15	D.H.S. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	D.S.U. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
17	Jullundur ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Total ..	1,00,000	15,89,000	1,10,000	1,05,000	20,00,000	3,10,000	11 23,800	24,000

1	2	7		8	9	10	11	12
Serial No.	District	(i) Provision of drinking water	(ii) Construction of Karahas	Base Camps	Dug well type latrine	Craft Centres	Sewing Machines	Medical aid
1	Ferozepur ..	20,000	..	..	..	..	..	..
2	Patiala ..	2,500	..	..	..	..	..	..
3	Amritsar ..	5,000	..	..	..	..	..	..
4	Bhatinda ..	5,000	..	..	..	..	..	..
5	Sangrur ..	10,000	..	..	..	..	..	..
6	Hissar ..	10,000	..	..	..	..	..	..
7	Rohtak ..	55,000	..	50,000	..	..	..	..
8	Gurgaon ..	20,000	..	50,000	..	..	..	..
9	Karnal ..	5,000	..	..	..	..	..	..
10	Ludhiana ..	..	..	..	..	..	..	..
11	Ambala ..	..	..	..	..	..	..	..
12	D.A.F. Punjab ..	..	..	..	..	..	..	..
13	C.E. Pb. ..	..	..	..	..	..	..	..
14	D.C. Kapurthala ..	..	..	..	..	..	..	..
15	D.H.S. ..	..	50,000	..	1,50,000	..	..	..
16	D.S.U. ..	..	..	..	2,00,000	2,00,000	1,00,000	3,34,000
17	Jullundur ..	..	..	..	..	..	..	..
	Total ..	1,32,500	50,000	1,00,000	1,50,000	2,00,000	1,00,000	3,34,000

[Revenue Minister]

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Serial No.	District	Prevention of cattle epide-mics	Transport facilities	Repair of houses	Test Relief works	Sirkies	Misc.	Pumps for dewate-ring opera-tion	Grants for village protec-tion works	Costs of running pumping sets	Total Gra-tuitious relief	Loans
1	Ferozepur ..	..	45,000	8,00,000	..	50,000	20,000	40,000	50,000	..	13,85,000	10,00,000
2	Patiala ..	..	10,000	1,40,000	..	..	..	..	..	..	3,52,000	2,00,000
3	Amritsar ..	..	16,000	4,00,000	..	30,000	10,000	21,600	20,000	..	5,92,600	..
4	Bhatinda ..	..	15,000	1,00,000	..	10,000	5,000	35,000	20,000	..	2,25,000	7,65,000
5	Sangrur ..	..	30,000	1,00,000	..	..	10,000	50,000	50,000	..	7,55,000	6,50,000
6	Hissar ..	..	25,000	65,000	..	..	30,000	60,000	1,00,000	..	3,90,000	23,75,000
7	Rohtak ..	..	75,000	10,25,000	25,000	100,000	1,12 600	168,400	2,00,000	..	45,68,330	20,00,000
8	Gurgaon ..	..	30,000	7,00,000	..	..	20,000	70,000	1,00,000	..	19,56,470	16,00,000
9	Karnal ..	..	20,000	80,000	..	..	14,000	20,000	50,000	..	5,29,000	7,00,000
10	Ludhiana ..	..	..	5,000	..	..	..	..	..	..	13,000	1,50,000
11	Ambala ..	..	10,000	15,500	..	3,400	..	..	..	..	28,900	70,000
12	D.A.F. Punjab	5,10,000	..	..	..	..	..	..	..	..	5,10,000	..
13	C.E.Pb. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	10,00,000	10,00,000	..
14	D.C. Kapur-thala ..	..	..	10,000	..	..	..	..	..	..	10,000	..
15	D.H.S. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5,34,000	..
16	D.S.U. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3,00,000	50,000
17	Jullundur ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Total	5,10,000	2,76,000	34,40,500	25,000	1,93,400	2,21, 600	4,65,000	5,90,000	10,00,000	1,31,49,300	95,60,000

		Rs
Gratuitous Relief	..	1,31,49,300
Loans	..	95,60,000
Grand Total	..	2,27,09,300

Setting up Tractor Factory in the state

***7226. Comrade Didar Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether the installation of a Tractor Factory in the State has been sanctioned by the Union Government ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the phased programme for the said project and the place selected for its location ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes.

(b) The Government of India have issued a letter of intent to M/s Escorts Ltd., for the manufacture of 7,000 Tractors of 34.5 H. P. per annum at Faridabad.

Forest Based Industries

***7303. Thakur Mehar Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether Government is considering any proposal to start forest based industries in the State; if so, the Names of such industries proposed to be started during the ensuing Financial year ?

Shri Ram Kishan : The requisite information is laid on the Table of the House.

Information regarding Forest based indusrries.

Yes. The establishment of the followihg forest based industries is under the consideration of Government :—

1. Taking over of Shiwalik Cooperative Rosin and General Mill Ltd., Gagret and establishment of Punjab Rosin and General Mill in its place.
2. Establishment of Seasoning Plant.
3. Manufacture of packing cases.
4. Production of pencil slats.
5. Manufacture of Shuttles and Bobb in Blanks, shoes, Lasts, toys and furniture etc.
6. Oil Distillation Plant.
7. Tin Fabrication Plant.
8. Manufacture of Barbed wires.

Nangal-Mukerian and Nangal Daulatpur Routes

***6981. Thakur Mehar Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of route permits sanctioned at present to the Punjab Roadways, Pathankot, from Nangal to Mukerian and Nangal to Daulatpur ;

(b) the number of buses plying on the sanctioned routes referred to in part (a) above and the time of their departure from Nangal and *vice versa* ;

(c) whether the buses referred to in part (b) above ply at the scheduled timings, if not, the steps taken to ensure punctuality;

(d) whether there is any proposal under the consideration of Government to ply more buses on the said routes, if so, the details thereof.

Shri Ram Kishan : (a) Nil.

(b) and (c) Do not arise

(d) No.

Civil Aerodrome for Chandigarh

***7776. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether Government is considering any proposal to convert Sector 25 of Chandigarh, into Civil Aerodrome for the town in stead of constructing one, as originally proposed, near Mullanpore village;

(b) if so, the reasons therefor.

Shri Ram Kishan : (a) Yes, Sector 25 for the purposes of a temporary Civil Aifireld.

(b) (i) Sector 25 is more easily approachable from the town ;

(ii) Surface is fairly level and suitable for flying operations ;

(iii) Early commissioning of the airfield is expected ; and

(iv) Budget having been drastically cut by 54 per cent extreme economy in expenditure is to be exercised.

Gliding Club, Chandigarh

***7777. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount given as grant-in-aid to the Chandigarh Gliding Club so far;

(b) the names of the Secretary of the said Club and his monthly salary, including allowances, etc., together with the designation of the appointing authority of the said Secretary ;

(c) the approximate date when the said Gliding Club is likely to start functioning and give regular training in flying and gliding ?

Shri Ram Kishan : (a) Rs 3,34,260.00

(b) (i) Shri R. R. Bhanot.

(ii) Rs 1,200.

(iii) Managing Committee of the Chandigarh Gliding Club.

No date can be given as the progress upto-date is nil.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Death of a person in Civil Hospital, Panipat

2525. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether he, the Chief Minister and the Director of Health Services, Punjab received any complaint from Shri Romesh Chander C/O Shri Mulkh Raj, Cloth Merchant, Gharaunda in connection with the death of his father in the Civil Hospital, Panipat, if so, a copy thereof be laid on the Table of the House;

(b) whether it is a fact that Shri Behari Lal father of Shri Romesh Chander was admitted to Civil Hospital in serious condition on 22nd January, 1965 or afterwards, if so, the date and time when he was admitted and the number of room/ward in which he was accommodated;

(c) whether on the receipt of a complaint, any enquiry was held, if so, when and by whom, together with a copy of the enquiry report, if held and completed be laid on the Table of the House;

(d) whether any other representation after the said enquiry has been received by the Director of Health Services, if so, a copy thereof be laid on the Table of the House together with the details of the action so far taken thereon, if no action has been taken, the reasons therefor?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes. A copy of the complaint is as follows (Annexure A).

(b) Yes. Late Shri Bihari Lal was admitted in the general ward of the Civil Hospital at 1.30 P.M. on 22nd January, 1965.

(c) Yes. The enquiry was conducted by the Director Health Services, Punjab, on 15th February, 1965. It is not desirable at this stage to place a copy of the enquiry report at the table of the House.

(d) Yes. A copy of the representation is as fallows Since the representation merely repeats the allegations already inquired into by the Director, Health Services, it is not considered necessary to take any action thereon (Annexure B).

ANNEXURE 'A'

To

The Hon'ble Chief Minister, Punjab,
Chandigarh.

Sir,

With due respect and humble submission I beg to bring the following few facts to your kind notice and necessary action in the public interest.

That on 22nd January, 1965 my father Shri Behari Lal, resident of House No. 519 Model Town, Panipat who was travelling in a Bus from Rohtak to Panipat met with a serious accident and received serious injuries. He was removed to the Civil Hospital, Panipat by the Driver and Conductor of the Bus.

On receipt of information of the accident I along with my mother hurried to the hospital and found that his injuries had been attended to and stitched by the Doctor and my father was lying senseless. During the night, due to excess bleeding, condition of my father became worst and I rushed to call the Doctor but he put me off and did not see the patient during the night and thus we passed a very restless night. I went to him again in the morning and even he did not come to see the patient and demanded to be paid his fee. He thus extorted from me Rs 15 and it was only then, that the Doctor made up his mind to have a look at the patient and advised some injections. Next day he suggested a naema to be given to the patient but the Compounder Shri Amar Nath did not do so unless he was paid Rs 2. On the following night between 24th January, 1965 and 25th January, 1965 the condition of the patient became still more serious and I went to call the Dr. (Shri Sud) but he did not come unless he was paid Rs 20. The said doctor gave Morphia injection in spite of resistance of my mother. But the doctor just to keep himslef at ease lest he may not be distrubed in the night, gave this injection against the wishes of my mother, saying (are you doctor or I"). As a result of this carelessness and subsequently not attending the patient in time, in spite of our repeated requests, my father expired about one hour after the injection was given to himl Moreover, we people requested him to give blood to the patient but he put us off saying that he will do the needful if and when needed. Had the doctor acted in a right manner and attended the patient properly his life could have been saved. Later on I came to know that there was no blood arrangement in the hospital. If so, it was the duty of the doctor to refer the case to the Civil Hospital, Karnal for higher medical aid. From the above you will find that both the doctors (Shri Grover and Sud were not only unsympathetic but are also involved in corrupt practices. They play with the lives of the patients and the poor people and their aim is to fill pockets and do not good to the public as they did in the case of my father. It is therefore requested that an enquiry may be instituted in the matter and the delinquents be brought to book with a view to stop to such malpractices. The hospitals are meant to alleviate human sufferings and not to work as slaughter houses. I do realise that by sending this complaint I cannot get back life of my father but I think it my foremost duty to bring such inhuman act of the doctor to your kind notice to save the public from cruel deeds of the doctors concerned. I may add here that Ist and 2nd ayments were made by me in the presence of my uncle Shri Mulkh Raj while third in the presence of my brother-in-law Shri Manohar Lal.

Yours faithfully,

(Sd.) ROMESH CHANDER

[Education and Local Government Minister]

ANNEXURE 'B'

To

The Director, Health Services, Punjab,
Chandigarh.

Subject.—Complaint against the Medical Staff of Civil Hospital, Panipat.

Sir,

I am thankful to you for the prompt action taken by you on my complaint on the above noted subject.

I am sure during the course of your enquiry you were fully convinced that my complaint was based on 100 per cent facts and Doctor Grover himself admitted that he had charged from me Rs 15 as consultation fee. As the patient was admitted in the Hospital in General Ward and was an accidental case (Interferable by the Police) the Doctor was not authorised to charge consultation fee. Similarly when Shri Amar Nath was asked if he had to say anything in his defence he said that he had to say nothing. Hence my allegations against Dr. Grover and Shri Amar Nath, Compounder were proved according to their over statements and thus they stand guilty for suitable punishment. As far as Doctor Sud is concerned, had enied having received payment of Rs 20 made to him about one hour before the death of the patient. In this connection it is requested that he may kindly be directed to submit an affidavit in this respect and I may be given time to produce before you an eye witness Shri Manohar Lal in whose presence he had received Rs 20 from me. He could not appear before you on 15th February, 1964 at Panipat due to short notice. I can however produce more witnesses to prove that he did not attend the patient unless he was paid Rs 20.

From the above it is clear that the above said Doctors and the Compounder were not only unsympathetic but are also involved in currupt practice.

As far as issue of Medicines from the Hospital stock are concerned it has already been informed to you in the course of inquiry conducted on 15th February, 1964 that the patient was given only one or two injections such as Morphia and Penciline, etc. and all other injections were purchased from the Bazar. The bed Head ticket of the patient also seems to be reprepared. The clear proof of which is that all the prescription were written by Dr. Grover on rough paper at his Bangallow when I went to call him to see the patient. These prescriptions were produced to you at the time of Enquiry Had. the Dr. attended the patient regularly there was no necessity of writing prescription rough papers.

Under the circumstances explained above I would request that both the Drs. and the Compounder be suspended till conclusion of enquiry. They may be properly charge sheeted and the case be referred to the Vigilance Department for conducting further inquiry in the matter.

Yours faithfully,

(Sd.)

1. Copy to Hon'ble Chief Minister in continuation of my complaint already been submitted for his kind information and necessary action in the matter.

RAMESH CHANDER,
C/o Shri Mulkh Raj,
Cloth Merchant,
Gharaunda.

Application for correction of Girdawari of village Chusana, tehsil Karnal

2526. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any application for the correction of Girdawari of village Chusana, tehsil Karnal (near River Jamna) was received by the Deputy Commissioner, Karnal between 29th March, 1964 and 3rd April, 1964, from Sarvshri Jawahar Lal, Nartom, Manohar Lal, Ram Chand etc. if so a copy thereof be laid on the table of the House;

(b) whether any revenue authority has looked into the contents of the application and visited the spot for the correction desired, if so, when, if not, the reasons therefor;

(c) the date when the Girdawari of the fields of village Chusana was entered in the revenue records by the Patwari;

(d) whether any checking has been done by any Girdawar Field Kanungo or any other revenue authority, if so, when and by whom;

(e) whether any of the applicants mentioned in part (a) above was called by any revenue authority, if so when, his designation, the name of the person called and the place where he was called;

(f) whether any information or result of the enquiry for the correction of Girdawari as mentioned in part (a) has been covenyed to the applicants concerned. If so, when, by whom and a copy of the findings of the enquiry be laid on the Table of the House;

(g) whether any other application was given by the said applicants to the D.C. Karnal, during the month of July, 1964, if so, a copy thereof be laid on the Table of the House;

(h) the action, if any taken on the application mentioned in part (g) above?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Yes. An application dated 30th March, 1964 addressed to the Collector/Deputy Commissioner, Karnal, was submitted by Sarvshri Jawahar Lal etc. A copy of the same is enclosed.

(b) Yes. The said application was duly looked into by the subordinate field staff. The field Kanungo visited the spot on 10th April, 1964 and found that there was no dispute about the girdawari and the applicants were informed accordingly on 29th April, 1964 through Shri Ram Chand one of the applicants.

(c) The girdawari of the said village was duly entered into the Revenue Records on 22nd March, 1964.

(d) The Field Kanungo (Shri Dhup Singh) checked the girdawari of the village on 10th April, 1964.

(e) The parties were called by the said Field Kanungo to appear before him near the *Nalka* of the Estate on 10th April, 1964. However, no record is available showing the exact names of the persons who were then present in the general gathering.

(f) Yes. The result of the enquiry was converyed to the applicants through Shri Ram Chand, one of the applicants, on 29th April, 1964, by the Halqa Patwari. A copy of the findings of the enquiry is enclosed.

(g) Yes. An application dated 17th July, 1964, was submitted by the applicants to the Deputy Commissioner, Karnal. A copy of the said application is also enclosed.

[Revenue Minister[

(h) The application mentioned in para (g) above was examined and finally decided according to the law on 5th December, 1964.

श्री मान D. C. Sahib Badadur , (Collector Sahib) Karnal

दरखास्त दुरस्ती गिरदावरी, रब्बी 64

मौज़ा चौसाना, करनाल

श्रीमान जी,

1. देह हजा की गिरदावरी पटवारी देह ने गलत दर्ज करदी है सारे रकबे के हम ही मलिकान हैं हम को मौके पर भी बुलाया नहीं न ही मौका पर जा कर गिरदावरी की गई है । बारू राम वगैरा ने जन्होंने ने इस रकबा का शुफा किया हुआ है ने अपने मामा की गिरदावरी उस रकबा की करायी है जो कि हम ने 30-40 हज़ार रुपया खर्च करके नौतोड़ किया है और मौका पर हमारी फसल भी खड़ी है ।

2. कृपा करके मौका देखा जावे, और गिरदावरी दुरस्त कराई जावे ।

30-3-64

ज्वाहर लाल, पुत्र श्री गोधा राम,
व: नरोतम देव, पुत्र चौधरी तीरथ राम,
मनोहर लाल, पुत्र होता राम, राम चन्द,
पुत्र श्री सोभा राम वगैरा साकिन नलवी क्लांव,
वाजीद पुर

वजरये ज्वाहर लाल

(Sd.) Narutan Dass (Sd.) Jawahar Lal (Sd.) Ram Chand.

नकल रिपोर्ट गिरदावर हल्का मुवरखा 10-4-64

श्रीमान जी मुवरखा 22-3-64 को मौज़ा चौसाना की गिरदावरी हो चुकी है । अब गिरदावरी करने का स्वाल तो ही पैदा नहीं होता है । मैं ने अब मौका पर जाकर मालूम किया है कोई तनाज़ा नहीं पाया गया है । अगर सायल को दुरुस्ती गिरदावरी करवानी मतलूब है तो वकायदा दुरस्ती गिरदावरी बखिदमत जनाब तहसीलदार साहिब केस दायर करके करवा सकता है । काबले अदख़ाल दफ़तर है । रिपोर्ट अर्ज़ है । 10-4-64

दस्तखत अंग्रेज़ी धूप सिंह गिरदावर कानूंगो
नं० 5174

हुक्म मिनजानब जनाब नायब तहसीलदार साहिब करनाल मुवरखा 14-4-64 वापिस होवे कि सायल की इतलाह करवाई जाए । अगर वह दुरुस्ती करना चाहे वह वकायदा अदालत में दावा दायर करे । 14-4-64

दस्तखत अंग्रेज़ी नायब तहसीलदार साहिब,
करनाल

नकल इत्तलाह याबी राम चन्द सायल मवरखा 29-5-64

श्रीमान जी बाकी दरखास्त दहिन्दगान की तरफ से मैं जिम्मेवार हूं हुक्म हजूर से इतलाह पाई ।

दस्तखत अंग्रेजी राम चन्द 29-4-64

श्रीमान D. C. Sahib Bahadur, Karnal

दरखास्त वास्ते दरुस्ती गिरदावरी रबी 1964

मौजा चौसाना, तह: करनाल जिस की दरखास्त पहले भी 30-3-64 को दी थी अब तक कोई कारवाई न हुई

श्रीमान जी सेवा में निवेदन है ।

(1) हम ने 30-3-64 को 1 दरखास्त वास्ते दुरुस्ती गिरदावरी दी थी । जिस की आज तक कोई तहकीकात ना हुई है । इस लिये दूसरी दरखास्त पेश है ।

(2) भूमी अनदाजन 1013 बीघे वाका चोसाना जे कागजात में मलकियती शामलात देह दर्ज है रकबा बुरदी बरामदगी है मकबूजा हमारा है । जिस को हम ने नौतोर किया । रबी की हमने फसल बोई व काटी । अब भी हमारा कबजा है। लेकिन पटवारी देह ने अदावतन चूंकि हमें उस के खिलाफ दरखास्त शिकायती तहरीरी बतौर deputationदी थी । गिरदावरा भूमी-कतई गैर मुतलका आशखास के नाम शुफा वगैरा के जरये हम को नुक्सान पहुंचाने की गर्ज से करदी हालांके वह अशखास tehsil थानेसर, कैथल, U. P. etc., के रहने वाले हैं और उनका भूमि से ना वास्ता है और न ही उन्होंने भूमिको देखा ।

(3) इस भूमी में 200 बीघे हमारा ईख खड़ा है ।

(4) हमारे साथ झगड़ा करने की गरज से व कराने की गरज से 1 जबरदस्त लड़ाका शहेजोर पारटी के नाम बिलकुल फरजी गिरदावरी की गई है ।

(5) कृपा करके इस का फैसला फौरी किसी Special Officer से कराया जावे । 17-7-64

ज्वाहर लाल, वलद गोधा राम
वगैरा वगैरा, 15 मरदमान
नलवी क्लां व वाजीद पुर
बजरये ।
राम चन्द ज्वाहर लाल नरोतम देव

Ram Chand Jawahar Lal Narutam Dev.

Arrests of certain persons by Saddar Police Station, Karnal

2527. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state:—

(a) whether Shri Vir Bhan, Mohan Ram, Sher Singh, Ram Chand, Bhagwan Dass, Suba Ram and Ram Chand were arrested by the Police on 24th October, 1964 by the Saddar Police Station, Karnal if so, the time when and the place from where they were arrested;

[Comrade Ram Piara]

(b) whether it is a fact that some of the persons mentioned in part (a) above came to the Saddar Police Station to lodge a complaint, if so whether the complaint was recorded; if not, the reasons therefor;

(c) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the date when the challan against the persons referred to in part (a) was put up in the Court together with the names of the witnesses who have so far given evidence in support of the prosecution;

(d) whether he is aware of the fact that the police is not intentionally pursuing the cases, if so, the reasons therefor, if not, the reasons for the delay?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. They were arrested by the Sadar Police Karnal u/s 107/151 Cr.P.C. at Adda Kunjpura on 24th October, 1964

(b) No. No person mentioned in part (a) above came to P.S. Sadar Karnal to lodge any complaint.

(c) The challan of the case was put in Court of S.D.M. Karnal on 25th October, 1964, but no prosecution witness has been examined so far.

(d) It is not a fact that the Police is not intentionally pursuing the case in court. The delay in the disposal of the case was due to the absence of the Presiding Officer on leave on one hearing, dialatory tactics adopted by the respondents on two hearings, pre-occupation of the court with other work on one hearing and non-issue of summons of the P.Ws by the court on two hearings.

Demarcation of certain Fields in Dispute in village Ghausan, tehsil Karnal

2528. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Revenue be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that Shri Balu Ram Gulshan, Girdawar Qanungo visited the fields of village Chausana, tehsi Karnal, on 28th December, 1964 for the demarcation of certain fields in dispute, if so, under whose orders;

(b) whether it is a fact that the Deputy Superindent of Police was also there in the fields at the time of the visit of the said Girdawar Qanungo;

(c) whether it is a fact that the Girdawar Qanungo could not demarcate the lands/fields and issued a chit for calling the Patwari, if so, a copy of the chit (Purcha) written by him be laid on the Table of House;

(d) whether it is a fact that one party after the issue of the chit was advised to go and bring the Pawari and later on under the pressure of the D.S.P. the demarcation of the fields was made, if so, the details thereof and the reasons therefor;

(e) whether the patwari called by the Girdawar Qanungo met the Girdawar, if so, when, if not, the reasons therefor together with the action, if any, tken by the Girdwar Qanungo after consulting the Patwari;

(f) whether it has come to the notice of the Revenue authorities that the D.S.P. was mixed up with one party if so, the action taken by the revenue staff to deliver justice?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Yes, under the order of the Tahsildar, Karnal.

(b) No.

(c) No. Shri Ram Chand, however, wanted the presence of a particular Patwari, Shri Hira Lall, there, to whom the Kanungo sent a chit through the former, a copy of which is enclosed.

(d) No.

(e) No. The Kanungo did not require the assistance of Shri Hira Lal who was the Consolidation Patwari of the adjoining village, Bhari.

(f) No.

श्री हीरा लाल पटवारी चक भड़ी

पुलिस निशानदही मौजा चुसाना जिसकी सरहद मौजा चक भड़ी से मिलती है ले रहा है । यह निशानदही बड़ी जरूरी है । आप फौरन नक्शा और मौजा चक भड़ी ले कर दर्शन दें निहायत जरूरी है । 28-12-64

बहुक्म तहसीलदार साहिब और डी. एस. पी. साहिब बहादुर करनाल ।

बाबू राम गुलशन
गिरदावर कानूगों

नक्ल मुताबिक असल है
दस्तखत योगराज एच. सी.
सर्विस स्टाफ, करनाल ।
19-3-65 ।

Murders committed in the State

2530. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state the total number of murders committed in the state, district-wise, during the period from 1st January, 1958 to 1st July, 1964 together with the number out of those which could not be traced, district-wise, and year-wise ?.

Sardar Darbara Singh : A statement giving the requisite information is as follows

(From 1st January, 1959 to 1st July, 1964)

District		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964 upto 1st July	
		No. of murders		No. of murders		No. of murders		No. of murders		No. of murders		No. of murders		No. of murders	
		Regis-tered	Un-traced	Regis-tered	Un-traced	Regis-tered	Un-traced	Regis-tered	Un-traced	Regis-tered	Un-traced	Regis-tered	Un-traced	Regis-tered	Un-traced
Hissar	..	54	14	46	6	48	16	50	3	62	13	56	4	32	5
Rohtak	..	35	9	32	1	24	2	20	5	21	2	17	3	8	3
Gurgaon	..	15	1	18	2	20	4	15	1	17	1	12	2	6	1
Karnal	..	31	3	36	5	32	2	49	12	47	6	30	3	16	..
Ambala	...	16	2	27	2	22	..	28	2	25	1	15	2	7	..
Simla	...	3	3	..	..	2	1	4	..	1	..	..	..	2	1
Kulu	...	2	..	1	..	1	..	3	1	1	..	1	..	2	..
Kangra	...	6	1	8	..	6	4	3	..	7	1	15	..	1	..
Hoshiarpur	...	21	3	20	4	19	2	26	4	17	1	20	4	11	3
Jullundur	...	48	6	55	10	40	4	47	4	53	4	39	4	18	4
Ludhiana		38	4	45	4	32	5	30	3	35	1	23	2	14	...
Kapurthala	..	18	2	6	..	14	..	14	1	10	1	8	2	4	1
Lahaul Spiti	..	..	..	...	...	..	..	..	..	1	...	..	..	..	...
Amritsar	...	60	7	25	3	37	6	37	8	41	6	35	4	20	3
Ferozepore	...	94	15	97	13	83	8	98	9	86	7	82	8	43	5
Gurdaspur	...	22	5	28	6	22	2	18	2	16	2	21	4	11	1
Patiala	...	39	6	29	2	29	2	34	..	30	4	25	2	10	...
Sangrur	...	59	4	50	3	49	2	49	2	36	1	51	4	27	3
Bhatinda	...	48	4	69	...	61	5	45	3	51	3	83	..	30	3
Narnaul	...	4	...	10	..	6	1	6	1	7	...	4	..	1	...

Class given to certain detenus in Jails

2531. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the class in which (1) Comrade Bishan Singh, Gurdaspur, (2) Comrade Sarwan Singh Chima of Jullundur, (3) Comrade Mehar Singh of Khanpur (4) Comrade Karnail Singh Phide (5) Comrade Ram Singh of Harino (6) Comrade Devki Nandan (7) Comrade Janak Singh Bhathal (8) Comrade Ganda Singh of Sangrur (9) Comrade Kartar Singh Gujapur of Amritsar (10) Comrade Hajara Singh Jasar of Amritsar, Communist detenus have been placed in the Jails;

(b) whether the Government propose to give them better treatment as was given to all detenus during the years 1950 to 1952; if not, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan (Chief Minister) : (a) Sarvshri Bishan Singh, Sarwan Singh, Mehar Singh Karnail Singh Phide, Devki Nandan, Ganda Singh have been placed in 'C' Class.

Sarvshri Ram Singh Harino, Janak Singh Bhathal, Kartar Singh Gujapir, have been provisionally classified as 'B' Class. Hajara Singh Jasar has already been given 'B' class.

(b) No. The detenus in question have been placed in classes to which they are entitled, under the rules.

Loans given for Poultry Farms in Amritsar District

2532. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the names of persons and societies with their addresses who were given loans to run poultry farms in district Amrirsar during the years 1963-64 and 1964 -65 year-wise, together with the amount given to each ;

(b) the names of those loanees among those referred to in part (a) above, who have not repaid even one instalment of the loan?

Shri Ram Kishan : (a) It is not in Public interest to disclose the names of loanees as such a disclosure adversely affects their business.

(b) Recovery of such loans starts after two year from the date of disbursement. As such instalment has not yet fallen due in respect of any loan advanced during the year; 1963-64 and 1964-65.

Review of Cases of Communists Detenus

2533. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the names of the communist detenus who are still in 'C' Class with the reasons therefor in each case ;

(b) the details of the charge-sheets given to the Communits detenus recently arrested in the State under the D.I.R. ;

(c) the names of the members of the Tribunal with their designation who received the cases of the Communit detenus as mentioned in part (b) above ?

Shri Ram Kishan : (a) A statement giving the names of Communist detenus classified as 'C' class, is as follows. They have been classi-fied according to the rules on the subject.

[Chief Minister]

(b) According to rules, details of the charge-sheets are not furnished to the detenus. Only the authority competent to order detention has to satisfy itself with regard to the conduct of the person concerned.

(c) No such Tribunal is constituted under the rules.

List of persons who have been detained under rule 30(1)(b) of the Defence of India Rules, 1962 and classified as 'C' Class detenus

(1) Shri Mange Ram Vats, son of Hazari Lal Brahmin of village Mandauti, police station Sahlawas, district Rohtak.

(2) Shri Gurbakhsh Singh Dakota, son of Waryam Singh of Santa Majra, police station Kharar, district Ambala.

(3) Shri Mehar Singh Khanpuri, son of Tulsa Singh Ramdasia, village Khanpur, police station Kharar, district Ambala.

(4) Shri Bhajan Singh, son of Ram Singh of Jassar, police station Sadar Ludhiana now Canal Colony, Ferozepore Road, Ludhiana.

(5) Shri Kartar Singh Gujapir, son of Narain Singh of Gujapir, police station Ajnala, district Amritsar.

(6) Shri Vidya Dev Longowal, son of Kanshi Ram of village Longowal, district Sangrur.

(7) Shri Ghuman Singh Urgahan, son of Pala Singh of district Sangrur.

(8) Shri Janak Singh Bhattal, son of Hari Singh of village Bhattal, police station Dhanaula, district Sangrur.

(9) Shri Ganda Singh, son of Harnam Singh Kalia of Sangrur.

(10) Shri Gajjan Singh Tandiana, son of Bishan Singh of Tandiana, police station Sardulgarh, district Bhatinda.

(11) Shri Karnail Singh Phide, son of Sarwan Singh of Phide Kalan, district Bhatinda.

(12) Shri Ram Singh Harinau, son of Sawan Singh of Harinau, police station Kotkapura, district Bhatinda.

(13) Shri Gurnam Singh Sibbian, son of Dal Singh of village Sibbian, police station Sadar Bhatinda.

(14) Shri Dharam Singh Kasni, son of Sohan Singh of Kasni, police station Dadri, district Narnaul.

(15) Shri Satya Mandan, son of Rao Madho Singh of Mandi now Mohalla Nalapur, Narnaul District.

(16) Shri Devki Nandan, son of Ram Sarup Brahmin of Balauha, police station Narnaul, district Narnaul.

Quota of G.C. Sheets distributed in Amritsar District

2534. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Wil the Chief Minister be pleased to state—

(a) the quantity of quota of G.C. Sheets received in Amritsar and the manner in which it was distributed during the years 1961-62, 1962-63 and 1963-64, year-wise ;

(b) the names of the firms, societies or individials who were quota holders of G.C. Sheets in Amritsar district year-wise during the period mentioned in (a) above?

Comrade Ram Kishan : The time and labour invloved in collecting the requisit information is not commensurate with the benefit sought to be derived therefrom.

Joint Seniority Lists of Officers/Officials In Animal Husbandry Department

2535. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether the Government has prepared a Joint Seniority List of all Class I, Class II and Class III employees of the Animal Husbandry Department in the State ; if so, a copy of the list showing the names of the Gazetted and non-Gazetted Officers with their qualifications, designations, salaries, dates of appointments and the places where they are posted be laid on the Table of the House ?

Sardar Darbara Singh :—(a) No.

(b) Question does not arise.

Joint Seniority List of employees in Health and Medical Department

2536. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state whether the Government has prepared a joint seniority list of all Class I and II employees of the Health and Medical Department in the State, if so, a copy of the list showing their names, designations, qualifications, salaries and dates of appointment be laid on the table of the House.

Shri Prabodh Chandra : The Joint Seniority Lists of Class I and II Officers of the Health and Medical Department have not yet been finalised because the principles of integration of Medical and Health Services are still under consideration.

Conditions and Qualifications for Awarding 'A' Class to Detenus

2537. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the conditions and qualifications which entitled a detenus to 'A' class ;

(b) the total number of the communist detenus detained at present in the various jails of the State who fulfil the conditions referred to in part (a) above and have been in 'A' Class ?

Shri Ram Kishan : (a) No specific conditions /qualifications which entitle a detenu to 'A' class treatment have been laid down by the State Government.

(b) Question does not arise in view of reply to part (a) above.

Detenus in District Jail, Rohtak in Sub-Jail, Gurgaon

2538. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of communist detenus at present in District Jail, Rohtak and in Sub-Jail, Gurgaon ;

(b) whether winter and other clothings have been supplied to the said detenus in the said jails, if not, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : (a) District Jail, Rohtak .. Nil } As on 22nd March, 1965.
Sub-Jail, Gurgaon ... 4 }

(b) Yes.

(ii) Question does not arise.

Transfer of Detenus to some Spacious Jails in the State

2539. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the enclosures of the District Jail, Rohtak and the Sub-Jail Gurgaon where the detenus are detained at present have insufficient space and accommodation and do not allow free movement to them, if so, whether the Government intend transferring the said detenus to other spacious jails in the State ?

Shri Ram Kishan : The accommodation and space in the wards (enclosures) at District Jail, Rohtak and Sub-Jail, Gurgaon where the detenus have been/are being kept is not insufficient. However all 'B' class detenus of Sub-Jail, Gurgaon and District Jail, Rohtak have since been transferred to District Jail, Nabha, where better accommodation is available. At present no detenu is detained in the District Jail, Rohtak. Only four (C) Class detenus are in the Sub-Jail, Gurgaon.

Landowners and Tenants in District Gurgaon

2541. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of landowners in tehsils Palwal, Ballabgarh, Nuh and Ferozepur-Jhirka of district Gurgaon who own at present :—

(i) two acres of land or less and the total acreage of land thus owned ;

(ii) more than two but less than five acres and the total acreage of land thus owned ;

(iii) five acres or more but less than ten acres and the total acreage of land thus owned ;

(iv) ten acres or more but less than twenty acres and total acreage of land thus owned ;

(v) twenty acres or more and the total acreage of land thus owned ;

(b) the total number of tenants at present in each of the said tehsils who either own no land or own less than two acres of land each ;

(c) the total area of land under cultivation at present in each of the said tehsils separately ;

(d) the total acreage of land under self-cultivation of the landowners, is at present, in each of the said tehsils ;

(e) the total number of landowners who do not cultivate their land themselves either wholly or partially in each of the said tehsils ?

Sardar Harinder Singh Major : The time and labour involved in collecting and compiling the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained from the reply.

Ejectment of tenants in certain tehsils of district Gurgaon

2542. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of cases of ejectment of tenants from agricultural land filed in various courts and the acreage of land involved therein in each year since the coming into force of the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953 in the State todate in forms K-1 and L, separately under the said Act in tehsils Palwal, Ballabgarh, Nuh and Ferozepur-Jhirka of district Gurgaon ;

(b) the number of cases and acreage of land involved therein out of those referred to in part (a) above in which ejectment of tenants was ordered in each form in each tehsil year-wise;

(c) the number of cases and acreage of land involved therein out of those in form L referred to in part (a) above in which non-payment of rent on batai was taken as one of the grounds or the sole ground for ejectment and the number of cases and acreage of land involved therein out of such cases in which ejectment was ordered on this ground, since the coming into force of the said Act, todate in each tehsil referred to in part (a) above ;

(d) the number of cases and acreage of land involved therein out of these referred to in part (b) above in which the land in dispute after the actual dispossession of the tenant was (i) released that very year on tenancy or patta to the original tenant or others and was not at all self-cultivated by the landlords ; (ii) released on tenancy or patta after one year's self - cultivation by the landlord, (iii) released on tenancy or patta after 2/3 years self-cultivation by the landlord ;

(e) the number of cases and acreage of land invloved therein out of those referred to above in part (b) above in which the land in dispute after the actual dispossession of the tenant was self-cultivated by the landlords and is todate under self-cultivation ?

Sardar Harinder Singh Major : The time and labour invloved in collecting and compiling the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained from the reply.

Ejectment of Tenants in Gurgaon District

2543. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) The number of tenants ejected by various courts under the provisions of the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, since the coming into force of the said act in tehsils Palwal, Ballabgarh, Nuh and Ferozepur -Jhirka of Gurgaon District ;

(b) The number of tenants against whom ejectment proceedings are pending in the various courts in each of the tehsils mentioned in part (a) above ?

Sardar Harinder Singh Major :

Tehsils

	Palwal	Ballabgarh	Nuh	Ferozepur-Jhirka
(a) ...	1,150	709	157	113
(b) ...	227	9	75	3

Auditing of Accounts of Gram Panchayat

2544. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether the accounts of the Gram Panchayat Mandauthi, district Rohtak for the years 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 were audited by the Government auditors, if so, the details of irregularities, if any, detected in the course of the audit ?

Sardar Darbara Singh : Yes. A list of irregularities detected in the course of audit is attached.

Statement showing the list of irregularities detected by the Auditor in the course of the Audit of Gram Panchayat Mandauthi, District Rohtak

Serial No.	Nature of irregurity detected
1	The cash in hand of the Sarpanch generally exceeded Rs 50. This is against rule 21 of the Punjab Village Panchayat Rules, 1940.
2	The case book was not written propertly and in a chronological order. It contained many cuttings and overwriting. The cash book was not balanced and reconciled with the bank pass book. It was noticed that a second cash book was started though the first one was not fully used up. This should be justified.
3	The particulars of Rs 4.90 debited in the excess in the month of November, 1960 should be shown at the time of next audit.
4	Monthly goshawaras for March, 1964 onward were not prepared.
5	The tax register was note shown.
6	No income was derived from Panchayt's Shamlat Deh. The land should be got vacated from the unauthorised possessors.
7	The details of the work done and amount spent in connection with the construction of school building were not put up. The works rules were not observed.
8	Bricks costing Rs 391 and Rs 800 were purchased on 10th September, 1963 and in December, 1963 from a private individual. This should be justified.

Serial No.	Nature of irregularity detected
9	The details of the court fee amounting to Rs 36.25 realised were not put up. The same should be put up at the time of next audit.
10	Talbana was not recovered in the case filed by Nand Lal, son of Ram which should be recovered now.
11	The attendance registers to check the fees realised from the students of the Sewing Centre during the period under audit were not put up.
12	The details of Rs 26.56 paid on 20th November, 1961 as prizes at the time of tournament were not put up which should be shown at the time of next audit and the amount got re-imbursed from the tournament fund of the District Development and Panchayat Officer.
13	The expenditure noted below is not a fit charge on the Gram fund and should be refunded or regularised with Government sanction.

Date		Amount	Particulars
30th March, 1963	..	3.00	Register for Government Dispensary
5th August, 1963	..	9.00	Luddos (Sweetmeats) for team.
24th December, 1963	..	15.00	Election materials

Serial No.	Nature of irregularity detected
14	Rs 114.50 (out of which Rs 15 were refunded on 6th June, 1964 at the instance of audit) were charged on 16th March, 1964 on account of stationery (register and forms etc). The charge seems to be exhorbitant and should be justified by the Panchayat.
15	The Village Chowkidar was employed by the Panchayat for the service of summons. The appointment may be regularised with the sanction of the Panchayat Samiti under section 17 (1) of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952.
16	Rs 500 were paid to Shri Mehu Ram, Panch on 3rd April, 1962 on acount of cost of a Jhota he-buffalo purchased from him without sanction of the Panchayat. The B. D. and P. O. may verify that the purchase from the Panch was in order.
17	The rent of sewing centre was paid to Shri Pokhar Mal without any letter of authority from the owner of the house. As such, actual payees receipt from the owner for the rent paid so far should be obtained and shown at the time of next audit for scrutiny.
18	Individual receipts for the contributions of Rs 110 and Rs 250 received on 11th January, 1962 and 30th April, 1962, respectively were not issued. This is not in order. In future individual receipt should be issued to each payee.
19	A fair price shop for which license fee of Rs five paid on 31st March, 1964 and Rs 50 security invested in the F. D. F. Bond No. C/1 489242 was run jointly by the Panchayat and the shopkeeper. This may be regularised with the sanction of the State Government under section 19 (2) (G) of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952.
20	Rs 10 on account of subscription of a Jagrit Hariana, Delhi were paid on 23rd February, 1964/1st March, 1964. A regular register showing its periodical receipts should be maintained for facility of check.

[Home and Development Minister]

Serial No.	Name of irregularity detected
21	A. P. Rs in respect of Payments of Rs 15.30, 7.50, 2.00 and 1.00 made on 10th June 1960, 12th January, 1962, 31st July, 1962 and 18th December, 1963, respectively were not produced which should be shown at the time of next audit.
22	Counting of pages certificates were not receorded on the register and receipt books. The needful should be done now and invariably in future.

Statement of the Aviation Adviser to Punjab Government

2545. Shri Rup Singh Phul : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the statement made by the Advisor Civil Aviation as reported in the Press on 8th March, 1965 about the starting of a Workshop in the Northern India Flying Club, Jullundur for the repair of aircrafts engines, has come to the notice of the Government ;

(b) whether the said statement was issued with the approval of the Government ;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative the reasons for transferring the workshop from Government Management at Patiala, to the control of the Flying Club at Jullundur ;

(d) the total amount of expenditure already incurred on the construction of the workshop at Patiala and the use to which the buildings there are proposed to be put in case the workshop is shifted to Jullundur.

Shri Ram Kishan : (a) Yes.

(b) No.

(c) The workshop at Patiala is under the direct control of the Government and is not being shifted.

(d) (i) The total amount spent for the construction of the workshop is Rs 1,70,828.66.

(ii) Does not arise.

Paid Leave/holidays allowed to workers in Industrial and other concerns in the State

2546. Shri Sagar Ram Gupta : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) The names of the Industrial and other concerns in the State in which paid casual leave, paid sick leave and paid festival and national holidays are allowed to the workmen together with the copies of the awards or agreements through which these concessions were enforced separately in each factory or establishment which may be laid on the Table of the House ;

(b) the names of the places in the State where Employees State Insurance Scheme has so far been introduced and also the names of the places where it has still to be introduced ?

Chaudhri Rizak Ram : (a) It will take pretty long time to collect information asked for. Besides the number of copies of the awards/agreements relating to a period of last 15 years will run into thousands. The time and labour involved in collecting the desired information would not be commensurate with the possible benefit that might be derived from the same.

(b) Places where E. S. I Scheme has since been introduced in the Punjab State :—

Places	
(1) Amritsar including Chhehrata, Verka and Khasa ...	Through Panel System.
(2) Ludhiana ...	
(3) Batala ...	
(4) Jullundur City and Cantt. ...	
(5) Ambala City and Cantt ...	
(6) Yamunanagar and Jagadhri ...	
(7) Dhariwal ...	Through Service System.
(8) Bhiwani	
(9) Hissar ...	
(10) Sonepat ...	
(11) Kharar ..	
(12) Faridabad including Mathura Road ..	
(13) Phagwara ..	
(14) Kapurthala ..	
(15) Gobindgarh ..	
(16) Panipat ...	
(17) Patiala ...	
(18) Rajpura ..	
(19) Chandigarh ...	
(20) Abohar ...	
(21) Charkhi Dadri ...	
(22) Bahadurgarh (Patiala District) ..	

(ii) Places where the E. S. I. Scheme is still to be introduced :—

(1) Surajpur
(2) Pinjore
(3) Ballabgarh
(4) Bahadurgarh (Rohtak)
(5) Gurgaon
(6) Mallot Mandi
(7) Goraya
(8) Phillaur
(9) Khanna
(10) Sirhind
(11) Rohtak
(12) Nabha
(13) Nangal

Schools and Colleges

2547. Shri Sagar Ram Gupta : Will the Minister for Education and Local Government, be pleased to state—

(a) the total number of Government as well as privately-managed Primary, Middle and High Schools and Colleges for Boys and Girls at present in each Assembly Constitutency of the State ;

(b) the total number of Primary Schools upgraded to Middle Standard, Middle Schools upgraded to High Schools and High Schools upgraded to Higher Secondary Schools during the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65 Assembly Constituency-wise ;

(c) the total number and names of the Primary, Middle and High Schools proposed to be upgraded during the year 1965-66 in each such constituency.

Shri Prabodh Chandra : (a) and (b) Educational Statistics are not collected and maintained Assembly Constituency-wise. This information will be supplied later on.

(c) The question of upgrading of schools during 1965-66 is under consideration.

Joint Seniority Lists of Officers/Officials in the Jails Department

2548. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether the Government has prepared a Joint Seniority List of Class I, Class II and Class III employees of the Jails Department in the State, if so, a copy of such list showing their names, designations, qualifications, pay-scales, places of postings and dates of entry into service be laid on the Table of the House ;

(b) whether the Government received any representations during the last three years from Class I and Class II employees mentioned in part (a) above regarding supersession of their rights of promotion, if so, the details thereof be laid on the Table ;

(c) the details of promotions given to Class I and Class II employees in the said department during the last three years, year-wise ;

(d) whether Government has received any representations from the employees mentioned in part (a) above regarding the revision of their pay-scales due to heavy rise in prices etc., if so, the details thereof be laid on the Table of the House with the details of the action, if any, taken thereon so far ?

Shri Ram Kishan The time and labour involved in collecting the requisite information which is very voluminous will not be commensurate with any possible benefit sought to be derived therefrom.

Joint Seniority List of Officers in the Revenue Department

2549. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) Whether the Government has prepared a Joint Seniority List of Class I and Class II employees in the Revenue Department in the State, if so, a copy thereof showing their names, addresses, designations, qualifications, pay-scales, and the dates of their entry into service be laid on the Table of the House ;

(b) whether the Government has received any representation during the last eight months from the employees mentioned in part (a) above regarding supersession of their rights of promotion and getting of selection grade, if so, copies thereof be laid on the table of the House, with the action so far taken thereon ;

(c) whether the Government has received any representations from the Associations of Class I and Class II employees of the said Department regarding the revision of their pay-scales due to heavy rise in prices, if so, copies of such representations be laid on the Table of the House with the action so far taken thereon ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) No.

(b) No.

(c) No.

Complaints against Sub-Registrar, Narnaul

2552 Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether Government received any complaints against the Sub-Registrar at Narnaul during the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65, if so, the details thereof be laid on the Table of the House;

(b) whether any office-bearers of the District Congress Committee, Mahendragarh made any complaints of corruption against the said Sub-Registrar, if so, the details of the action, if any, taken thereon and the copies of the complaints be laid on the Table of the House?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Only one complaint was received and the same was filed being anonymous. A copy of this complaint is as follows.

(b) Not received and as such no action was required to be taken.

Copy of the Complaint

(नोट) तहसील नारनौल में जो आनरेरी सब-रजिस्ट्रार लग रहा है उसका नाम रतन लाल संघी है, जिसकी माहवारी आमदनी 1,000 माहवार और तनखाह अलहदा रही है। इसका भी इंतज़ाम फरमाया जावे। इसके अन्दर राम सरूप रजिस्टरी क्लर्क तहसील नारनौल भी शामिल है। ये दोनों गिरगट की तरह दिन में दस मरतबा कपड़े बदलते हैं और खूब आनंद से लूट मार मचा रखी है। जब कि तहसीलदार साहिब व नायब तहसीलदार साहिब मौजूद हैं, आनरेरी सब रजिस्ट्रार की क्या ज़रूरत है? क्या पैसे कमाने के वास्ते लगा रखे हैं?

आपका

खैरखाह सरकार

8-7-64

Residential/Industrial Plots sold at Faridabad Township, District Gurgaon

2553. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the residential and industrial plots sold at Faridabad Township, district Gurgaon during the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65, along with the rates at which those were sold and the names and addresses of persons or firms, etc. to whom these were sold ;

(b) whether the above-mentioned plots were sold by auction or otherwise ; if so, the details thereof be laid on the Table of the House ?

Shri Ram Kishan : (a) No residential plot has as yet been allotted. The number of industrial plots allotted in the Urban Estates at Faridabad is 93, of which 21 were allotted in 1963-64 and 72 in 1964-65. The rate per square yard is as under:—

(i) 5 acres plots (above 3 acres)—Rs. 8 per square yard plus 10 per cent frontage surcharge on price.

(ii) Above 1.5 to 3 acres plots —Rs. 9 per square yard.

(iii) 1.5 acre plot or below —Rs. 10 per square yard.

A list containing names and addresses of persons or firms, etc. to whom these plots were allotted is laid on the Table of the House.

(b) The allotment of these industrial plots was made by the Negotiating Committee after interviewing each applicant and examining relevant documents for ensuring that the demand for industrial plot was genuine, and the party would put up the factory within the specified period. Preference was also shown to the outsees of the area and ex-Military personnel.

List of Addresses of the Parties

1. M/s. R.C. Abrol and Co., Private Ltd., Post Box No. 556, New Delhi.
2. M/s. Industrial and Allied Products Corporation, E-70, South Extension -1, New Delhi.
3. M/s. Anand Automobile Ltd., Agra Road, New Land, Bombay-10.
4. M/s. Laldee Private Ltd., Regd. Vijay Bress Buildings, Naya Bazar, Delhi.
5. M/s. Will Cox (Buckwill) India Ltd., 32-Najafgarh Road, New Delhi.
6. M/s. Anil Rubber Mills, 6114, Sadar Delhi.
7. M/s. Hitkari Bros of Delhi, 68-Industrial Area, Faridabad.
8. M/s. Chopra Mining Corporation, care of Harbans Singh Chopra, G.T. Road, Asansole.
9. M/s. Kipi Photographics Industries, F. 21, Model Town, Delhi.
10. M/s. Laxmi Narain and Co., Army Canteen Contractors, Mohindergarh.
11. M/s. Alankrit, Defence Colony, Delhi.
12. M/s. Moti Electric Industries, 15-A, Najafgarh Road, New Delhi.
13. M/s. Sidhwal Refrigeration Private Ltd., care of Bhalwant Singh, Rajindera Hospital.
14. M/s. Vishwa Mittar Sekhri, Municipal Commissioner, Batala.
15. M/s. Lotus Chormous, 22/B, 16-B, Asaf Ali Road, New Delhi.
16. M/s. F.C. Mittal, care of Gama Acids and Chemicals, care of Funds Financiers and Traders Private, Ltd., 4-A, Sector 19-A, Chandigarh.
17. M/s. Kiddie Manufacturing Co., D-1 Odean Buildings, New Delhi.
18. Miss Shilla Sundra, 9-Kurzon Road, New Delhi.
19. M/s. New India Motors Private Ltd., Scindia House, New Delhi.
20. M/s. Botoni Lamos care of Machine Tools Corporation, Kashmire Gate, New Delhi.

21. M/s. Apricet Machine Tools, Railway Road, Batala.
22. M/s. Aute Metal Engineering, Industrial Plot No. 3, Faridabad.
23. M/s. B.K. Kapur, Industrial Area, 267, Faridabad, Township.
24. M/s. Man Chanda and Co., L-A, Industrial Area, Faridabad Township.
25. M/s. Sidhana Engineering Works, New Township, Faridabad.
26. Surinder Kumar, 7-Rakab Ganj Road, New Delhi.
27. M/s. Motorn India, 1/1421, Kashmiri Gate, Delhi.
28. M/s. Weldon Sale Corporation, 11-Narain Market, Sadar Bazar, Delhi-6.
29. M/s. Oheroi Traders R-559, Lane Sankar Road, New Delhi.
30. M/s. H.K. Joshi, Joshi Mansion Old Railway Road, Jullundur City.
31. M/s Jagjit Bhatia, Prep./M/s. United Traders, A-40, Defence Colony, New Delhi.
32. M/s. Universal Engineering Co., 5-D, Faridabad, N.I.T.
33. M/s Paras Ram-Budhiraja care of Allied Engineering Works, Mandi Road, Jullundur City.
34. M/s. D.C. Bharadwaj House, No. 17, Indraprashta Home, Faridabad.
35. M/s. Kanwal Lal, care of M/s. P. R. Budhiraja, and Sons, Mandi Road, Jullundur City.
36. Ms/. Hardaya Mal-Mohri Lal, Dera Baba Nanak Road, Batala.
37. M/s. Chand Ram, care of M/s. Chaggar Engineering Works, 118-G.T. Road, Jullundur City.
38. M/s. Bahadur Chand, care of Chaggar Engineering Works, 118-G.T. Road, Jullundur City.
39. M/s. Amar Son, 57-M.M. Road, New Delhi.
40. M/s. Harbans Lal-Ramkrishan. 111-D/9, Lajpat Nagar, New Delhi.
41. M/s. S.K. Engineering Works, 23-C, Industrial Area, Faridabad.
42. M/s. Chaudhri Ram, care of Chaudhri and Co., U/83, Pacca Bagh, Jullundur.
43. M/s. Bhola Nath Bali for Allied Rubber and Mach. Industries, 2/C/132-N.I.T., Faridabad.
44. M/s. Jayees Industries, 1/B/132, N.I.T., Faridabad.
45. M/s. Forward Ind. (India), E/27/1, New Rohtak Road, New Delhi.
46. M/s. Madan Lal Sharma, care of M/s. Everest Pharmaceuticals Works, Everest Nagar, Bhatinda.
47. Inder Singh, care of M/s. Bharat Mechanical Works, G.T. Road, Batala.
48. M/s. Harbans Lal, Prop. Vijay Cycle and Iron Steel Industries, Nakodar Road, Jullundur.
49. M/s. Contact India, 6-New Chandpur Building, Sadar Bazar, Delhi-6.
50. M/s. R.C. Kapur, V.K. Industries, 2930, Rajguru Road, New Delhi.

[Chief Minister]

51. M/s. Faridabad Kapila Machine Tools Production-cum-Sale Co-operative Industrial Society Ltd., Faridabad.
52. M/s. S. L. Malhotra, Prop., Meg India, Railway Road, Faridabad.
53. M/s. Vijay Kumar Vaid, 382-Model Town, Jullundur.
54. M/s. Jay Kay Engineering Works, Industrial Area, Jullundur.
55. M/s. Dharam Dass and Tirath Dass, care of Plastics Containers, 30-Jambur Waki West, P. O. No. 2248, Bombay-2.
56. M/s. Prithi Pal Singh-Mohan Singh Gate, Ghee-Mandi, Amritsar.
57. M/s. B.K. Bhardwaj, care of Om Dutt Shory, Advocate, Barnala.
58. M/s. Uppal Sale Corporation, 50-C, Model Town, Phagwara.
59. M/s. Grandley Electric India, 2656, Sadar Thana Road, Delhi.
60. M/s. Bhagwan Dass and Co., Private Ltd., 17-18, Gokhley Market, Delhi.
61. M/s. Rajinder Industries, 1/5, Industrial Plot, N.I.T., Faridabad.
62. M/s. Sakow Industries Ltd., 35-Chitranjan Avenue, Calcutta.
63. M/s. Alite Smelting and Associate Industries, 20-M, Jangpura Extension, New Delhi.
64. M/s. Datta Engineering Works, 3365, Teliwara, Delhi-6.
65. M/s. New Metal Meg. Co., 2206, Paharganj, New Delhi.
66. M/s. R.R. Verma, 4/14, Najafgarh Road, New Delhi.
67. M/s. Joginder Singh Sawhney, Sawhney Tent Store, Sector 22-C, Chandiarh.
68. M/s. Superior Electric Co., 17, Netaji Subhash Marg, Delhi.
69. M/s. Thakar Das, J. Bhatia, 8-D, Pusa Road, New Delhi-5.
70. M/s. Bee Gee Group of Industries, Patiala.
71. M/s. Consolidated Engineering Co., Chadhri Buiding, K-Blcck, C. Circus, New Delhi.
72. M/s. Inter Continental Business Mart, T/2470, Subhash Nagar, Karol Bagh, Delhi.
73. M/s. Bawa Singh Bharj Ltd., 10186, Arya Samaj Road, New Delhi.
74. M/s. K.C. Gupta and Sons, 8-Chanan Singh Park, Delhi Camp.
75. M/s. Niranjan Singh, C-66, South Extension 11, New Delhi.
76. M/s. Cinesales Corporation, Film Colony, Chandni Chowk, Delhi.
77. M/s. T.N. Kapur, care of Industrial Syndicate 138, Caning Street, Calcutta.
78. M/s. Azad Hind Tent House, Lal-Kunan, Delhi-6.
79 M/s. Wazir Singh and Sons, Subhash Marg, Darya Ganj, Delhi.
80. M/s. Vijay Batra, care of Associates Engineering Industries, Mathura Road, Faridabad.

81. M/s. J.K. Sehra, 29-N.W. Avenue, Punjab Bagh, New Delhi.

82. M/s. Amir Son, 33, Court Road, Amritsar.

83. Jose Puliken, care of Aero Industries, E/245, Greater Kailash, New Delhi.

84. M/s. Refrigeration Accessories, 13-I-B, Russelet, Calcutta.

85. M/s. G.S. Duggal and Sons, Jiwan Bihar, Parliament Street, New Delhi.

86. M/s. General Plastic India, 19, Ratandon Road, New Delhi.

87. M/s. Aggarwal and Sons, C-25, Nizamuddin East, New Delhi.

88. M/s. Wenz Alluminizers, 20-Feroze Gandhi Road, New Delhi-14.

89. M/s. Indian Refrigeration, 7/15, Kirti Nagar, Delhi.

90. M/s. Madho Ram, Pathri Works, Chowk Crori, Amritsar.

91. M/s. Makappa (India), S/41, Kirti Nagar, Delhi.

92. M/s. Surjit S. Sabharwal, 9 Ratandon Road, New Delhi.

93. M/s. Bhai Associates, 4/23-B, Asaf Ali Road, New Delhi.

Villages electrified in Nangal Chaudhri Panchayat Samiti

2554 Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total number of the villages at present in the area of Nangal Chaudhri Panchayat Samiti, district Mahendragarh, which have been electrified, and a list giving the names of the said villages be laid on the Table of the House.

(b) whether it is a fact that a scheme for electrifying 34 villages in the area of the said Samiti has since been sanctioned ; if so, the reasons for not starting the work under the said Scheme ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Nil. Does not arise.

(b) Yes, a scheme for electrifying 53 villages has been sanctioned. The work has not been started so far, for want of funds.

Representation from the Panchayat Samiti, Nangal Chaudhri

2555 Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether Government have received any representations from the Panchayat Samiti, Nangal Chaudhri and the inhabitants of village Kojinda in district Mohindergarh regarding the danger to their village on account of a dam being constructed on Krishnawati river near Narnaul, if so, the details of the action so far taken thereon, together with a copy each of the said representations be laid on the Table of the House ?

Chaudhri Rizaq Ram : Yes. A copy of the representation is placed on the table of the House. The representation is under consideration.

To

H. L. Uppal
The Direc or
Inve tig tion Division
D pa tment I igation and Power Amritsar.

नकल प्रस्ताव नं०————————तारीख 22-8-64 ग्राम पंचायत कोदिन्जा

(1) आज की बैठक में गांव के पास कृष्णा नदी पर जो बांध बनाया जा रहा है। उससे उत्पन्न समस्याओं पर विचार हुआ। इस बांध बनाया के लिये निम्न लिखित कठिनाईयां पैदा हो गई हैं।

(क) गांव जिस जगह बसा हुआ है उस ज़मीन का ढलान नदी की ओर है। अतः वर्षा का तमाम पानी बह कर नदी की ओर जाता है बांध की गांव की तरफ वाली पाल गांव से बिलकुल सट कर बनाई जा रही है। उस पाल के बन जाने से इस पानी का निकास रुक जायेगा और सारा पानी गांव की गलियों में ही रूक कर खड़ा रह जायेगा। जिस से मकानों को भी नुकसान है और खास कर खड़े हुए पानी से बिमारी फैलने का तो खतरा पैदा हो जायेगा।

(ख) बांध गांव के करीब दो फर्लांग उत्तर की ओर बन्ध रहा है। गांव का प्राइमरी स्कूल, पीने के पानी का कुआं, पशुओं को पानी पिलाने का बड़ा जोहड़, पशुओं की गोचर भूमि और गांव की लगभग सारी कृषि भूमि नदी के दूसरे पार है। बांध भर जाने से सारे गांव के लिये बड़ी भारी कठिनाई पैदा हो जायेगी क्योंकि आवगमन का सीधा रास्ता बंद हो जायेगा।

अतः पंचायत सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित कर सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से प्रार्थना करती है कि हमारी कठिनाइयों को ध्यान में रख कर उनका उचित हल निकालें और उसी के अनुसार बांध में योग्य परिवर्तन करे। पंचायत यह भी सर्व सम्मति से पारित करती है इस प्रस्ताव की प्रतिलिपियां सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों, उपायुक्त महोदय, नारनौल और विकास खंड अधिकारी नांगल चौधरी को भेजी जाये।

ग्राम पंचायत कोदिंजा,
गुल सिंह,
सरपंच ग्राम पंचायत कोदिंजा।
हस्ताक्षर महादा राम, पंच
बोवद राम, पंच
निशान अंगूठा

Rates for supply of water for irrigation purposes from the Narnaul Dam in District Mohindergarh

2556 Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the rate at which water is being supplied to the Cultivators from the Narnaul Dam in district Mohindergarh and the total area of the land being irrigated at present by the said Dam ;

(b) whether the said rates are at par with the rates being charged for the supply of Cannal water for irrigation puposes, if not, the reasons for disparity.

Chaudhri Rizaq Ram : (a) and (b) No area is being irrigated from the Dam at Narnaul as yet.

Cases of illicit liquor registered in Police Station, Nangal Chauhri, District Mohindergarh

2557 Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of cases of illicit liquor registered at Police Station, Nangal Chaudhri, district Mohindergarh during the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65 ;

(b) the number of cases out of those mentioned in part (a) above actually challaned together with the number and details of cases which resulted in convictions and acquittals ;

(c) whether he received any representation from one Shri Mangla Ram of village Iqbalpur Nangali, tehsil Narnaul, district Mohindergarh, during the period from 23rd September, 1964 to 15th October, 1964, alleging that he had been falsely implicated in an excise case by the Chairman, Panchayat, Samiti, Nangal Chaudhri and the Chairman, Zila Parishad, district Mohindergarh, if so, the action taken thereon and a copy thereof be laid on the table of the House ?

Sardar Darbara Singh : (a) No. of cases registered during the ear :—

Year		1962-63	1963-64	1964-65
1962-63	..	10	5	5
8963-64	..	17	13	4
1964-65	..	9	1	(8 cases pending investigation)

(c) Yes. Two applications dated the 1st October, 1964 and another undated application (October, 1964) from Shri Mangla, son of Shri Karan of Village Iqbal pur Nangal Chaudhri were received in this connection. On enquiry by S.P. Mohindergarh, the allegations were found to be false. He was rightly involved in case F.I.R. No. 28 dated 2nd October, 1964, under section 68/1/14 Excise Act. The case is pending trial in the court of Chief Judicial Magistrate, Narnaul.

Since the case is subjudice, it will not be in the public interest to lay a copy of the enquiry, report on the Table of the House.

Release of Shri Satya Mandan a Detenue in District Jail, Nabha, on Parole

2558 Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government received any representations from Shri Satya Mandan of Narnaul, district Mohindragarh, now a detenue in District Jail, Nabha, dated thd 8th Feburary, 1965

and 18th Feburary, 1965 sent from District Jail' Rohtak requesting for release on parole to attend to his ailing wife ; if so, the action so far taken thereon, and copies of representations be laid in the Table of the House ;

(b) whether it is a fact that Government also received a representation from Shrimati Bhup Kaur, the ailing wife of the said detenue for the releass of her husband on parole to enable him to attend on her durin her illness ; if so, the action so far taken there and a copy of her represenation be laid on the Table of the House ?

Sardar Darbara Singh : (a and b) Yes. The matter was enquired into and it was found that his wife who was ailing in the hospital was discharged after recovery on 10th Feburary, 1965 and therefore, the question of release on parole did not arise.

Copies of the three representations are as follow.

URGENT

IMPORTANT

The Home Secretary
Punjab State, Chandigarh

Through the Superintendent District Jail, Rohtak.

Subject.—For immediate release on parole to enable me to attend my seriously ailing wife Shrimati Bhup Kaur alias Sampati Devi—lying in Civil Hospital Narnaul.

Shrimanji.

I have been detained here under the D.I.R. *vide* your detention order No. 11216/WDSB, dated Chandigarh, the 29th December, 1964.

At the time of my arrent of 30th December, 1964, my wife Shrimati Bhup Kaur alias Sampti Devi was seriously ill at my house at Narnaul. And I was attending and nursihg her as there is no other person, either male of female, in my family except myself and my wife. I have only one real brogher and he too lives apart from me with his big family neither they are on good terms with me since long.

Not only this, even my wife has no means of subsistence with her in my absence. I have no such property, the income of which may provide her livelihood and maintenance.

Now, I have received information that she has been taken to hospital (Civil Hospital Narnaul) and is seriously ill there. There too, she is all alone and there is nobody to attend and nurse her and to arrange for her necessities and requirements such as medicine and diet etc. Hence, my presence besides her, is imperative during her serious illness which may prove fatal at any time and the whole responsibility lies in that case, shall be lying on the Government for the loss substained and damaged done to me in any manner.

So, please immediately release me on parole for a time, until my wife is completely cured and restored to her normal health.

Soliciting a favourable and immediate consideration and prompt act and prompt-action in view of the situation.

date 8-2-65
Handed over to the
Jail Authorities at
9.15 A.M.

Yours faithfully,
Satya Mandan Detenu,
District Jail, Rohtak.

COPY

VERY URGENT

Immediate

The Home Secretary,
Punjab State, Chandigarh.

Through the Superintendent, District Jail, Rohtak.

Subject.— For immediate release on Parole on account of the Serious sickness of my wife

Shrimanji,

Please refer my application dated the 8th Feburary, 1965 on the subject. I further submit as under—

1. That my wife was lying seriously ill in the Civil Hospital, Narnaul.

2. That she has also applied for my release on parole on account of her continued serious illness.

3. That on 9th Feburary, 1965 some officials, perhaps from D.C. office Narnaul as my wife has stated in her letter visited the said hospital and they pressed the medical officer incharge of the hospital to discharge my wife from the hospital. They asked the medical officer why he had admitted her. Why did not he evade her? They even asked the Civil Surgeon to discharge her forthwith. When my wife requested the Medical Officer, not to discharge her in the midst of her such sickness, he declined saying that he was running a risk by keeping her.

4. That on the very next day i.el, 10th February, 1965 the Medical Officer of the hospital discharged my wife from the hospital even while she was running temperature and had serious ear nose and throat trouble.

5. That my wife is still seriously ill and even unable to move out of her bed. She has developed serious throad trouble so much so that she is unable to swallow anything and speaks with difficulty. Likewise her ears are seriously affected and this has impaired her hearing. Besiedes running continuous temperature for the last several months she also seems to have lung and pulmonary troubles.

6. That my wife is all above in the midst of her serious sickness and there is a absolutely no one to look her after and serve her and arrange for her treatment. And so there is every danger to her life and her person.

Hence, it is requested that I may immediately be released on parole so that I may attend my wife and arrange for her proper treatment.

I am prepared to abide by all the restrictions during parole period.

Anticipating immediate consideration and action.

Dated the 18th February, 1965.

Yours etc.
(SATYA MANDAN),
son of Rao Madho Singh,
Village Shahpur I or Nalapur, Narnaul.
District, Mohindergarh,
Detenu,
District Jail, Rohtak,

सेवा में,

श्रीमान उपायुक्त महोदय,
नारनौल

श्री मान जी,

निवेदन है कि मैं भूपकौर बहुत पुराने दमे की बिमार हूं, पहल भी नारनौल सिवल हस्पताल में इलाज करा चुकी हूं, और भी कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, अब कुछ दिनों से बहुत जोर का दमे का दौरा हो रहा है, और अब मैं सिवल होस्पीटल में भरती हूं, मेरा पति सत्यमंडल न सुरिच्छा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द रोहतक जेल में है। मेरी देखभाल करने के लिये मेरा कोई बच्चा भी नहीं है और मेरा देवर ससुर बहुत अरसे से गांव में रहते हैं। इसलिये मेरे हाल पर रहम फरमा कर मेरे पति को तातकलीफ पैरोल पर छुट्टी देने की कृपा करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि मेरी इस बीमारी के दौरान मेरे पति पैरोल पर आकर मेरी देखभाल करेंगे तो उसी दौरान में उनको कम्युनिस्ट पार्टी से दूर करने का प्रयत्न करूंगी और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं अपनी कोशिश में सफल हूंगी और साथ ही उसकी एक्टीवीटीज पर सख्त निगरानी रखी जावे अगर कोई शासन विरोधी कार्यवाही करे तो उसको फिर नजरबन्द कर दिया जावे।

प्रार्थी,

नारनौल मिती 29-1-65

भूपकौर, पत्नी सत्यामंडन
नज़रबन्द नारनौल

Seniority List of Class I and Class II Employees of the Forest Department

2559. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether the Government has prepared a joint seniority list of Class I and Class II employees of the Forest Department, if so, the details thereof with their names, designations, qualifications and their present pay scales and the places of postings be laid on the Table of the House ;

(b) whether Government have received any representations from any employees mentioned in (a) above during the last eight months regarding supersession of their rights of promotion or to the selection grades during the period of last three years, if so, a copy each of the representations be laid on the Table of the House, stating the action so far taken on them ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No joint seniority list of PFS, Class I and Class II has been prepared nor is it necessary.

(b) In view of (a) above the question does not arise.

Financial Assistance to Handloom Weavers

2560. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state the details of the amount spent by the Government on

giving financial assistance to handloom weavers and their Co-operative Societies in the State, districtwise, in the years 1963-64 and 1964-65, with their full names and addresses.

Shri Ram Kishan : The Districtwise break-up of financial assistance given to the Handloom Weavers and their Co-operative Societies during the years 1963-64 and 1964-65 is enclosed.

2. It is not in public interest to disclose the names and full addresses of the loanees as it would adversely affect the business.

Financial assistance to Handloom Weavers

District		*Amount given as financial assistance to the Weavers and their Co-operative Societies, during 1963-64*			*Amount given as financial assistance to the Weavers and their Co-operative Societies during 1964-65*		
		Handloom Development Schemes	Punjab State Aid to Industries Act, 1935	Total	Handloom Development Schemes	Punjab State aid to Industries Act, 1935	Total
1		2	3	4	5	6	7
		Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
1.	Amritsar ..	34,970	10,100	45,070	45,115	16,000	61,115
2.	Jullundur ..	16,623	4,600	21,223	8,460	15,100	23,560
3.	Ludhiana ..	19,860	..	19,860	7,820	9,600	17,420
4.	Ambala ..	33,238	13,000	46,238	11,204	1,000	12,204
5.	Karnal ..	97,437	74,200	1,71,637	61,162	46,900	1,08,062
6.	Rohtak ..	5,800	13,900	19,700	10,150	6,100	16,250
7.	Gurgaon ..	1,406	2,000	3,406	1,910	..	1,910
8.	Mohindergarh ..	980	8,500	9,480	900	..	900
9.	Patiala ..	..	7,700	7,700	825	4,300	5,125
10.	Sangrur ..	4,600	3,200	7,800	1,040	9,000	10,040
11.	Bhatinda ..	2,800	2,200	5,000	4,155	9,800	13,955
12.	Kapurthala ..	732	500	1,232	..	2,500	2,500
13.	Gurdaspur ..	17,710	2,000	19,710	70,745	7,000	77,745
14.	Kangra ..	12,790	..	12,790	13,507	3,000	16,507
15.	Kulu ..	81,030	6,750	87,780	99,350	4,800	1,04,150
16.	Keylong ..	..	..	..	..	..	..

[Chief Minister]

1		2			3		
17. Simla	..	..	..	..	..	..	..
18. Ferozepore	..	3,960	4,300	8,260	6,435	1,000	7,435
19. Hissar	..	23,477	34,000	57,477	19,087	8,000	27,087
20. Hoshiarpur	..	15,785	3,600	19,385	23,292	6,000	29,292
Total	..	3,73,198	1,90,550	5,63,748	3,85,157	1,50,100	5,35,257

The Weavers Co-operative Societies also received assistance under the following schemes : as these are general purpose schemes. it is not possible to furnish the districtwise break-up in respect of these schemes

		1963-64	1964-65
		Rs	Rs
(i) Educative tours to Weavers	..	..	2,000
(ii) Setting up of inter-State Handloom Sales Depots	..	..	15,000
(iii) Credit facilities to Handloom Weavers subsidizing rate of interest of R B I Scheme	..	8,000	5,000
(iv) Rebate on the sale of Handloom Cloth	..	80,000	1,00,000
(v) Publicity, Propaganda, Exhibition and Shows	..	17,000	8,000
Total	..	1,05,000	1,30,000

Development of Fisheries in the State

2561. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the details of the amount given by the Government as grant, subsidy, etc. to individuals, societies or firms in the Amritsar District, Block-wise, for the development of Fisheries, in the year 1962-63, 1963-64 and 1964-65 ;

(b) the details of the steps so far taken by the Government to promote development of Fisheries in the State, district-wise, during the last three years, togetherwith the amount so far spent in this behalf ?

Sardar Darbara Singh : (a) No grant or subsidy is given for development of fisheries to individuals societies and firms.

(b) Following schemes have been taken up for development of fisheries in the State :—

(a) Development of fish in Bhakra Reservoir.

(b) Development of fish culture in Chandigarh Lake.

(c) Demonstration of fish culture in a large number of impounded waters in the State.

(d) Establishment of fish seed farms.

(e) Training of fisheries personnel.

(f) Appointment of additional ministerial staff in the State.

(g) Survey of culturable waters and spawning grounds in the State.

(h) Establishment of Research-cum-acquarium and Museum at Chandigarh.

(i) Intensification of fish production in ten Community Development Blocks in the State.

A statement showing the districtwise achievements and the amount spent during the last three years is enclosed.

[Home and Development Minister]

Statement showing the Districtwise Physical and Financial Achievement made during the year 1962-63, 1963-64 and for 1964-65 for the development of Fish Culture in the State

Serial No.	Item	Unit	Year	Hissar	Rohtak	Gurgaon	Karnal	Ambala	Jullundur	Ludhiana	Ferozepur	Amritsar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Production of fry ..	No. in lacs	1962-63 ..	..	..	..	..	0.06	..	..	..	..
			1963-64 ..	12.39	..	..	..	0.37	..	..	..	..
			1964-65 ..	13.00	0.50	1.00	0.50	1.40	..	..	..	..
2	Stocking of waters ..	Acres ..	1962-63 ..	15	15	16	15	18	16	16	15	16
			1963-64 ..	29	29	29	29	47	29	29	29	29
			1964-65 ..	42	42	80	80	149	42	80	42	80
3	Production of fish ..	Maunds	1962-63 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			1963-64 ..	150	100	100	100	120	100	100	100	140
			1964-65 ..	152	132	132	132	232	132	132	132	142
4	Establishment of fish seed farms	Number	1962-63 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			1963-64 ..	..	..	1	1	1	..	..	..	..
			1964-65 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	Training of Personnel ..	Do	1962-63 ..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
			1963-64 ..	..	..	1	..	1	..	..	..	..
			1964-65 ..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
6	Survey of culturable waters ..	Distts.	1962-63 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			1963-64 ..	..	..	1	1	1	..	..	..	..
			1964-65 ..	..	1	..	..	..	..	..	..	1
	Amount spent ..	Figures in lacs	1962-63 ..	0.08	0.33	0.08	0.21	0.90	0.10	0.10	0.10	0.09
			1963-64 ..	0.11	0.10	0.20	0.31	0.67	0.08	0.07	0.08	0.09
			1964-65 ..	0.23	0.22	0.38	0.19	0.65	0.13	0.20	0.14	0.14

Serial No.	Item	Unit	Year	Kapurthala	Gurdaspur	Hoshiarpur	Kangra	Kulu	Simla	Patiala	Sangrur	Bhatinda	Moninder-garh
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Production of fry ..	No. in lacs	1962-63 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			1963-64 ..	..	..	..	1.24	..	..	..	..	..	..
			1964-65 ..	..	..	..	4.00	..	..	..	..	..	..
2	Stocking of waters ..	Acres ..	1962-63 ..	15	15	15	5	..	..	20	19	15	..
			1963-64 ..	29	29	29	63	..	..	28	29	29	..
			1964-65 ..	42	42	105	280	..	..	80	42	42	..
3	Production of fish ..	Maunds	1962-63 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			1963-64 ..	100	100	100	150	..	..	130	110	100	..
			1964-65 ..	132	132	120	412	..	..	132	132	122	..
4	Establishment of fish seed farms	Number	1962-63 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			1963-64 ..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..
			1964-65 ..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
5	Training of Personnel	Do	1962-63 ..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..
			1963-64 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			1964-65 ..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
6	Survey of culturable waters	Distts.	1962-63 ..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..
			1963-64 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			1964-65 ..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
	Amount spent ..	Figures in lacs	1962-63 ..	0.09	0.35	0.10	2.13	..	..	0.15	0.41	0.09	..
			1963-64 ..	0.07	0.13	0.15	1.75	0.02	0.06	0.14	0.18	0.08	..
			1964-65 ..	0.14	0.15	0.21	2.02	0.25	0.25	0.18	0.27	0.17	..

Political Sufferers in Amritsar District

2562. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any political sufferers have been awarded any certificate in the Amritsar District during the year 1964-65, if so, their names and home addresses ;

(b) the names with home addresses of the political sufferers of the said district who have been getting pension since 1962-63 together with the names of those who have been given land after Independence.

Shri Ram Kishan : (a) Yes. A list containing their names and home addresses is at Annexure I.

(b) The time and labour involved in the preparation of the list containing the names with home addresses of the political sufferers of Amritsar District who have been getting financial assistance since 1962-63 will not be commensurate with any possible benefit to be accrued therefrom. A list containing the names and addresses of those political sufferers who have been allotted land after Independence is at Annexure II.

ANNEXURE I

Serial No	Name and Address
1	Shri Ajaib Singh, son of Shri Kishan Singh, village Bhure Gill, post office Chamyari, tehsil Ajnala, district Amritsar
2	Shri Bur Singh, son of Shri Bhan Singh, village and post office Pohuwind Khalra, tehsil Tarn Taran, district Amritsar
3	Shri Bhana Mall, son of Shri Kesar Harijan, village and post office Vallah, district Amritsar
4	Shri Bhagwan Singh, son of Shri Lachhman Singh, village Viran, post office Khalra, district Amritsar
5	Shri Bahadur Singh, son of Shri Inder Singh, village Chela, post office Bhikhiwind, district Amritsar
6	Shri Dalip Singh, son of Shri Jowahar Singh, village Karmowala, post office Kharka, district Amritsar
7	Shri Darshan Singh, son of Shri Sohan Singh, village and post office Kasel, district Amritsar
8	Shri Dalip Singh, son of Shri Karam Singh, village Jallaywala, post office Sarhali Kalan, tehsil Tarn Taran, district Amritsar
9	Shri Gurbux Singh, son of Shri Mangal Singh, village Dalawarpur, post office Pheloke, district Amritsar
10	Shri Gurcharan Singh, son of Shri Kehar Singh, village and post office Bhangwan, district Amritsar
11	Shri Gian Singh, son of Mihan Singh, village and post office Bhikhiwind, district Amritsar

Serial No	Name and Address
12	Shri Geja Singh, son of Shri Ganga Singh, village Burj Raika, post office Sarhali Kalan, district Amritsar
13	Shri Harnam Singh, son of Shri Mihan Singh, C/o Dr. Malkiat Singh, Gurusar Sadhar Bazar, post office Gurusar Sadhar, district Ludhiana
14	Shri Kundan Singh, son of Shri Tara Singh, village Lalla Afghana, post office Bhala Pind, tehsil Ajnala, district Amritsar
15	Shri Kundan Singh, son of Shri Banta Singh, village and post office Kot Dharam Chand, tehsil Tarn Taran, district Amritsar
16	Shri Puran Singh, son of Shri Deva Singh, village and post office Pheloke, district Amritsar
17	Shri Tara Singh, son of Shri Kesar Singh, village Phattu Bhila, post office Tahli Sahib, tehsil and district Amritsar
18	Shri Tara Singh, son of Shri Budh Singh, village and post office Naushehra Pannuan, tehsil Tarn Taran, district Amritsar
19	Shri Teja Singh Randhawa, son of Shri Jowala Singh, village Sarli Kalan, post office Sarli Khurd, district Amritsar
20	Shri Teja Singh, son of Shri Sawan Singh, village Lohar, post office Johal Dhaiwala, tehsil Tarn Taran, district Amritsar
21	Shri Ujagar Singh, son of Shri Sunder Singh, village and post office Butala, district Amritsar

ANNEXURE II

1. S. Attar Singh, son of S. Mit Singh, caste Jat Sikh, village and post office Khatra Kalan, tehsil Ajnala, district Amritsar.
2. S. Ajit Singh, son of S. Sadhu Singh, Jat, village andpost office Bhusa, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
3. S. Amar Singh, son of S. Wasava Singh, caste Mazhbi Sikh, House No. 8, Gali No. 5, tehsil Patti, district Amritsar.
4. S. Bhan Singh, son of S. Bagga Singh, caste Jat, village Bhari Kamboki, post office Khalra, tehsil Patti, district Amritsar.
5. Shri Bhawani Dass, son of Pt. Nanak Chand, caste Brahmin, Congress Worker C/o Shri Kanshi Ram, Assistant Accountant. The Central Bank of India Ltd., Amritsar.
6. Shri Jagiree Mal, Congress Worker, son of Shri Guranditta Mall, village Patti, House No. 309/3, tehsil Patti, district Amritsar.
7. Shri Bhag Din, son of Shri Labho, caste Marasi, village and post office Sathiala, district Amritsar.
8. Shri Bahadur Chand Malhotra, son of Malik Brij Lal Malhotra inside Khazana Gate, Amritsar.

[Chief Minister]

Serial No.	Name and Address
9.	S. Bhola Singh, son of L. Hem Raj, caste Khatri, House No. 1791, Lahori Gate, Gali Jatanwali, district Amritsar.
10.	Shri Diwan Singh, son of Shri Wasava Singh, Jat, village and post office Bhuller, tehsil Ajnala, district Amritsar.
11.	Shri Dharam Singh, Darshan Singh, sons of Baba Chattar Singh, caste Ahlowalia Sikh, House No. 2095/3, Kucha Kamboan, Katra Jalianwala, Amritsar.
12.	Shri Diwan Singh, son of Pt. Jyoti Ram, caste Brahmin, village and post office Patti, district Amritsar.
13.	S. Gurmukh Singh, son of S. Uttam Singh Jat, village and post office Nagoki, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
14.	S. Ganda Singh Jathedar, son of Nand Singh, caste Jat, village Khatrah Kalan, post office and tehsil Ajnala, district Amritsar.
15.	Shri Gopal Dass, son of Pt. Vir Bhan caste Brahmin, village Fatehwal, tehsil Ajnala, district Amritsar.
16.	Shri Girdhari Lal, son of Pt. Bhola Nath, caste Brahmin, House No. 2807, outside Sultanwind Road, Mohan Nagar, Amritsar.
17.	Shri Gurmukh Singh *alias* Ram Mohd. Singh, son of Ram Singh, caste Sikh, Painter, Akali Market, district Amritsar.
18.	Shri Amar Singh, son of Pal Singh, village and post office Dehriwala, tehsil and district Amritsar.
19.	S. Gian Singh, son of S. Kesar Singh, caste Jat Sikh, village Allowal, post office Khalohian, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
20.	S. Gurbaksh Singh Taur, son of S. Kesar Singh, caste Mazhbi Sikh, village and post office Bababakala, district Amritsar.
21.	Shri Bur Singh, son of Shri Sher Singh, village Harsu Chhina, district Amritsar.
22.	Shri Hari Singh Kakkar, son of S. Amar Singh, caste Jat Sikh, village and post office Mohalanwal, tehsil Ajnala, district Amritsar.
23.	Shri Haveli Ram, son of Pt. Kanshi Ram, caste Brahmin, village and post office Jathowal, tehsil and district Amritsar.
24.	Shri Hajara Singh, son of S. Sunder Singh, caste Jat Sikh, village Veroka, post office Preet Nagar, tehsil Ajnala, district Amritsar.
25.	S. Harnam Singh Panchi, son of S. Natha Singh, caste Rajput, village and post office Patti, district Amritsar.
26.	Shri Harnam Singh, son of Buta Singh, caste Jat Sikh, village and post office Pheruman, district Amritsar.
27.	Shri Ishar Dass, son of. Kirpa Ram, caste Pushkarana, House No. 4424/9, Gali Mohian Khazana Katra, Amritsar.
28.	S. Inder Singh, son of S. Jawala Singh, Jat Sikh, village and post office Gangoaha, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
29.	S. Inder Singh, son of Shri Kharak Singh, caste Jat Sikh, village and post office Mohan Bahndarian, tehsil Ajnala, district Amritsar.
30.	S. Inder Singh, son of Bhagwan Singh, caste Jat Sikh, village and post office Marhana, tehsil Patti, district Amritsar.

Serial No.	Name and Address
31.	Shri Joginder Singh, son of Shri Ganpat Ram, caste Brahmin, village and post office Khadur Sahib, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
32.	Shri Jagat Singh, son of Pal Singh, caste Jat Sikh, village and post office Virka, district Amritsar.
33.	Shri Joginder Singh, son of S. Sohan Singh, Jat Sikh, village China Karam Singh, post office Jasterwal, tehsi Ajnala, district Amritsar.
34.	Shri Jagat Singh, son of Shri Ishar Singh, caste Jat Sikh, village and post office Marhana, tehsil Patti, district Amritsar.
35.	Shri Karam Chand Sawney, son of Shri Gopi Nath Sawney, Municipal Commissioner, House No. 2685/11, Bihran Gali, Amritsar.
36.	Shri Kishori Lal Tandon, son of Shri Jagan Nath, caste Khatri, House No. 329/9, Kucha Jatan, Amritsar.
37.	Shri Dalip Singh, Sohan Singh, Minor through Dalip Singh, son of Shri Dharam Singh of Nagoki, tehsil Tarn Taran, district Amritsar at present Bir Babran, Hissar.
38.	S. Kartar Singh Valtoha, son of Sadhu Singh, caste Jat Sikh, village and post office Khas Valtoha, tehsil Patti, district Amritsar.
39.	Shrimati Kartar Kaur, w/o S. Bachan Singh, caste Jat, village and post office Terra Khurd, post office Chamari, tehsil Ajnala, district Amritsar.
40.	S. Khem Singh, son of S. Surain Singh, village and post office Suhal, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
41.	Shri Kundan Singh, son of S. Pal Singh, caste Jat, village and post office Mirgindpura, tehsil Patti, district Amritsar.
42.	S. Kesar Singh, son of S. Mehar Singh, caste Jat Sikh, village Saron Nigab, post office Batala, tehsil and district Amritsar.
43.	S. Lachhman Singh *alias* Avtar Singh, son of S. Dasondha Singh, caste Jat Sikh, village Thatti Jaimal Singh, post office Sankhetra, district Amritsar.
44.	S. Rattan Singh, son of Ram Singh Ahluwalia Sikh, House No. 2363, Kot Kanhaya Lal, Outside Sultanwind, district Amritsar.
45.	Shri Lahori Ram, son of Chint Ram, caste Brahmin, C/o Shri Mehar Chand, Cap Merchant, Swank Mandi, Amritsar.
46.	Shri Makhan Singh *alias* Rattan Singh, son of Dasonda Singh, caste Jat Sikh, village Thatti, Jaimal Singh, post office Sankhatra, tehsil Patti, district Amritsar.
47.	Giani Mehar Singh, son of S. Subal Singh, caste Jat Sikh, village and post office Dabowal, at present Meet Press, Katra Ram Garhian, district Amritsar.
48.	Shrimati Malan, widow of S. Ishar Singh, caste Jat Sikh, village and post office Mohan Bhandrian, tehsil Ajnala, district Amritsar.
49.	Shri Mota Singh, son of S. Gopal Singh, caste Sikh Jat, village and post office Jagdev Kalan, tehsil Ajnala, district Amritsar.
50.	Shri Mathura Dass, son of Shri Thakur Dass, caste Brahmin, district Sports Dealer, Lawrence Road, Amritsar.
51.	S. Niranjan Singh Nathwan, son of Lehna Singh, caste Ramgarhia, Sarwarpur, Sultanwind Road, Amritsar.

[Chief Minister]

Serial No.	Name and Address
52.	Shrimati Jaswant Kaur, widow of Shri Niranjan Singh Azad, village Gopal Pura, post office Majitha, district Amritsar.
53.	Shri Pal Singh, son of Shri Ishar Singh, caste Sikh, village and post office Jhabbal, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
54.	S. Pritam Singh, son of S. Nihal Singh, caste Jat, village Bhalojla, post office Beas, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
55.	Shrimati Bishan Kaur, widow of Shri Saudagar Singh, village Jura, post office Kairon, tehsil Patti, district Amritsar.
56.	Shri Surjan Singh, son of L. Siri Ram, caste Sikh, Guru Ram Dass Nagar, Gali No. 2, Outside Sultanwind, Amritsar.
57.	Shri Santa Singh, son of Shri Vir Singh, caste Sikh Jat, village and post office Sultanwind, district Amritsar.
58.	S. Santa Singh Panchi, son of S. Tara Singh, caste Jat Sikh, village Jallal Usman, post office Masumpura, tehsil and district Amritsar.
59.	Shri Sohan Lal Diwana, son of Shri Krishan Gopal Diwana, caste Brahmin, C/o Dr. Karam Chand, Dentist, Naya Bazar, Tarn Taran, district Amritsar.
60.	Shrimati Jaswant Kaur, widow of S. Niranjan Singh, village Gopal Pura, post office Majitha, district Amritsar.
61.	S. Surmukh Singh Chamak, son of S. Mangal Singh, caste Sikh, 4 Kot Baba Dip Singh, Amritsar.
62.	Shri Surat Singh, son of Shri Jawala Singh, caste Sikh, village and post office Kamalpur, tehsil Ajnala, district Amritsar.
63.	S. Santa Singh, son of S. Nihal Singh, caste Jat, village and post office Marhana, tehsil Patti, district Amritsar.
64.	S. Sohan Singh, son of S. Nand Singh, village and post office Sheron, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
65.	Shri Sohan Singh, son of Shri Sobha Singh Jat, village and post office Marhana, tehsil Patti, district Amritsar.
66.	Shri Sahib Dayal, son of Sewa Ram, care of Shri Khazan Chand Panwala, Chowk Nanak Mandi, Amritsar.
67.	Shri Surain Singh, son of Santa Singh, caste Sikh, village and post office Baba Bakala, tehsil and district Amritsar.
68.	Shri Singara Singh, son of S. Banta Singh, caste Kumhar Sikh, village Ahmadpura, tehsil Patti, district Amritsar.
69.	S. Teja Singh, son of S. Jawala Singh, caste Jat, village Chak Kamal Khan, post office Surian, tehsil Ajnala, district Amritsar.
70.	S. Tara Singh, son of S. Lehna Singh, caste Jat Sikh, village Butari, post office Khalohian, tehsil and district Amritsar.
71.	Shri Udham Singh, son of Shri Bhagwan Singh, caste Jat Sikh, village and post office Varpal, district Amritsar.
72.	Shri Udham Singh, son of S. Jagat Singh, Jat Sikh, village and post office Khatrai Kalan, tehsil Ajnala, district Amritsar.
73.	S. Ujjagar Singh, son of S. Santa Singh, caste Kumhar, Ward No. 4, Patti, Amritsar.

Serial No.	Name and Address
74.	S. Wasava Singh, son of Shri Mehtab Singh, caste Jat, village and post office Butala, tehsil and district Amritsar.
75.	S. Bela Singh, son of Ghasita Singh, village Bachoita, tehsil Ajnala, district Amritsar.
76.	S. Chanan Singh Darwesh, son of Shri Kishan Singh, caste Jat Sikh, village and post office Kalsian Kalan, tehsil Patti, district Amritsar.
77.	Shri Gurmukh Singh and Gurbaksh Singh, sons of S. Mangal Singh, village Jagdev Kalan, tehsil Ajnala, district Amritsar.
78.	S. Harnam Singh, son of S. Santa Singh, caste Jat Sikh, village Khojkipur, post office Beas, district Amritsar.
79.	S. Harnam Singh, son of S. Hukam Singh, caste Kamboh, House No. 2368/15/18, Gali No. 1, Sultanwind Gate, Amritsar.
80.	Jathedar Harnam Singh, son of Jiwan Singh, caste Jat, village Jons, post office Bagga, tehsil Ajnala, district Amritsar.
81.	S. Kartar Singh, son of S. Jawhar Singh, caste Sikh, village and post office Jabbowal, tehsil and district Amritsar.
82.	S. Raghbir Singh, son of S. Ram Singh, caste Sikh C/o Ram Mohd Singh, Painter, Akali Market, Amritsar.
83.	S. Sohan Singh, son of S. Wadhawa Singh, village Othian, post office Bagha, tehsil Ajnala, district Amritsar.
84.	S. Sunder Singh Lyallpuri, son of S. Lakhmir Singh, caste Sikh, village and post office Tara Garh, tehsil Amritsar, Now Quarter No. 23, 8 Marla Refugee Camp, Hissar.
85.	Shri Chanan Singh, son of Bur Singh Sikh, C/o Babu Gulab Singh Building near Power House, Hissar.
86.	Giani Shankar Singh, son of S. Sunder Singh, village and post office Tarn Taran, district Amritsar.
87.	Uttam Singh, son of S. Deva Singh, village Nawan Pind, post office Fatehpur, Rajputan, district Amritsar.
88.	S. Vir Singh, son of S. Lehna Singh, village and post office Lopoke, tehsil Ajnala, district Amritsar.
89.	S. Wassan Singh Gyani, son of S. Alla Singh, village Kanpur Kala, post office Cherta, district Amritsar
90.	Shri Joginder Singh, Kartar Singh, sons of Shri Mehar Singh *alias* Mohan Singh, caste Jat Sikh, village Marhana, post office Sarhali, tehsil Patti, district Amritsar
91.	S. Harnam Singh, son of S. Kehar Singh, village Bebbipura, post office Mahmud Pura, tehsil Patti, district Amritsar.
92.	Shri Amar Nath, son of Shri Prabh Dayal, House No. 921/9, Kucha Dohbian No. 4, Katra Khanzana, Amritsar.
93.	Shri Bihari Lal Dhawan, son of L. Ram Rakha Mal, village Vegpur, post office Kairon, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
94.	Shri Santa Singh, son of Shri Ganda Singh, village and post office Sathiala, district Amritsar.
95.	Shri Udham Singh, son of Shri Budha Singh, village ahd post office Mirgand pura, tehsil, Patti, district Amritsar.

Foodgrains supplied on Subsidised Basis

2563. Comrade Makhan Singh Tarsikka: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total quantity of foodgrains supplied on subsidised basis by the Government, during the current financial year, district-wise ;

(b) the total number of fair price shops at present in Amritsar District, giving the location of each such shop ?

Shri Ram Kishan : (a)—

(1) Kangra District (Bara Bhangal Area)		74.60 Quintals upto 15th February, 1965
(2) Kulu District (including Outer Seraj Area)		11,164.00 Quintals upto 15th February, 1965
(3) Lahaul and Spiti District	..	10,069.00 Quintals up to 15th February, 1965
Total	..	21,307.60 Quintals

(b) 1,551. The time and labour involved in collecting information relating to the location of each fair price shop will not be commensurate with any possible benefit to be derived from it.

Co-operative Societies in the State

2565. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state the names and full addresses of the Co-operative Credit, Banking, Processing, Farming, Warehousing, Labour and Construction Societies in the State, which were given financial assistance by the Government to improve their working during the years 1963-64 and 1964-65, with the amount given to each Society, categorywise, district-wise and year-wise ?

Sardar Darbara Singh : The labour time and expenses involved will not be commensurate with the benefit to be derived out of the information sought for.

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : Now there is a Call Attention Notice (No. 27) given by Pandit Mohan Lal Datta ?

Pandit Mohan Lal Datta : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the recent matter of urgent public importance, namely, the fatal motor boat accident in Govind Sagar near Bhakra Dam in which about hundred persons of Punjab State died due to drowning caused by the motor boat having turned down in Govind Sagar. This serious accident took place due to grave negligence of the officials of the Bhakra Dam Administration. An impartial judicial inquiry by a Sessions Judge is called for. The successors and relatives of the deceased deserve substantial compensation and immediate financial help.

Mr. Speaker : This Notice is admitted Government may make a statement about it.

Education and Local Government Minister: I have a feeling that a judicial probe has been ordered into the tragedy, and I think, it will be rather unfair to go into the matter and pre-judge the issue.

Mr. Speaker : Are you sure that a judicial probe has been ordered into this affair ; if so, then the Government may not divulge anything about it.

Education and Local Government Minister : The Himachal Pradesh Government has ordered a judicial proble into this tragedy.

Mr. Speaker : If the tragedy has occurred in the Himachal Pradesh territory, then it is a different matter and you can say that you are not concerned with it.

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : टैरेटरी तो स्पीकर साहब मिक्सड है क्योंकि वह आदमी किश्ती में हिमाचल प्रदेश एरिया से इधर आ रहे थे । अगर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ज्यूडीशल प्रोब का आर्डर कर दिया है तो यह नामुनासब बात होगी अगर इस ऐक्सीडेंट के बारे में यहां में कोई ब्यान दूं । since that will have some bearing on the enquiry. So, in case a judicial probe has not been ordered, then the Government will make a statement about it tomorrow, or at the next sitting of the House.

Pandit Chiranji Lal Sharma The Minister has stated that the tragedy occurred in the Himachal Pradesh territory. If that is so, will he still take cognizance of this incident and made a statement about it ?

Mr. Speaker : This incident has occurred in the jurisdiction of both the Governments.

QUESTION OF PRIVILEGE

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहब, रूल्ज़ के मुताबिक, कुएश्चन आवर के बाद पहले एडजर्नमेंट मोशनज़ और प्रिवेलेज मोशन्ज़ आनी चाहिएं और मेरी एक प्रिवेलेज मोशन थी लेकिन आप ने पहले उस को टेक अप करने की बजाए काल एटेन्शन मोशनज़ लेनी शुरू कर दीं है और वह नहीं ली ।

Mr. Speaker : Yes, there is a privilege motion by the hon. Member about the alleged mis-statement by an honourable Member of this House and not by the Minister. Before giving my ruling on it, I would like to go into the various aspects of this motion. It has to be examined whether a mis-statement by an hon. Member against another becomes a question of breach of privilege. I would request the hon. Members, Dr. Baldev Parkash and Chaudhri Mukhtiar Singh Malik, who have given notice of this motion, to contact me and discuss the whole matter with me.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहब, मैं आप से एक रिकुएस्ट करनी चाहता हूं, और वह यह है कि इस हाउस के अन्दर अब यह प्रैक्टिस सी बनती जा रही है कि कई मेम्बरज़ ऐसे हैं जो पहले दूसरे मैम्बरज़ के खिलाफ कुछ जनरल और वेग सी एलीगशनज़ विद नो ग्राऊण्डज़ लगा देते हैं । और बिलकुल गैर ज़िम्मेवारी के साथ लगाते हैं जो एलीगेशनज़ वह इस हाउस के बाहर डेफेमेशन के केस से डरते हुए लगा नहीं सकते । इस तरह से वह इस हाउस के फोरम को एक्सप्लाएट किया जाता है और इस लिब्रटी का जो इस हाउस के मेम्बर होने की हैसियत से उन्हें हासल है मिसयूज किया जाता है । इस तरह से वह ऐसी ऐसी बातें

यहां कह जाते हैं जो बाहर बल्कि में फार फीयर ग्राफ डिफेमेंशन कह नहीं सकते ग्रौर उन के ऐसा करने से इस हाउस की पोज़ीशन खराब होती है । ग्रभी उस दिन पंडित मोहन लाल जी ने कहा था.....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप उस का जिक्र न करें । मैं ने ग्रभी इस बात का फैसला नहीं किया कि इस तरह से वह ब्रीच ग्राफ प्रिवेलेज बनती है कि नहीं बनती । ग्रौर ग्राप ने एक मोशन का नोटिस दिया है, जब तक वह एडमिट न हो जाए उस वक्त तक उस बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है । ग्रभी इस बारे में मैं ने ग्रपनी कोई फाइनल रूलिंग नहीं दी । because I have myse'f not finally decided about it. मैं चाहता तो यह था कि इस बारे में फैसला करने से पहले ग्राप मुझ से मिल लें ग्रौर हम इस बारे में डिस्कस कर लें कि ग्राया इस में किसी किस्म की कोई प्रिविलेज बनती है कि नहीं बनती क्योंकि मिनिस्टरज़ के सिलसिले में तो इस बारे में लोक सभा में डेफीनेट रूलिंगज़ भी दी गई हैं ग्रौर डीसियनज़ भी हुए हैं जिन के बारे में मैं ने कई बार फैसला भी यहां दिया है कि जब मिनिस्टर कोई रांग स्टेटमेंट दे तो उस पर ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज नहीं बनता ग्रौर ग्रगर इस बारे में मेम्बर लिख कर लेटर भेजें तो मिनिस्टर भी ग्रपनी वर्शन दे दे । इस तरह से दोनों की वर्शनज़ जो हों वह टेबल ग्राफ दी हाउस पर रख दी जाएं and that is in keeping with the decisions of the Lok Sabha also. लेकिन एक मैंबर कोई बयान दे ग्रौर दूसरा कहे कि यह गलत है तो ग्राया वह प्रिविलेज बनता है या नहीं यह देखना है ।

(The hon. Member need not refer to that. In this connection I have not yet decided whether or not this is a fit case for breach of privilege. The hon. Member has given notice of a motion but until it is admitted it would not be proper to discuss it here. Since , I have not finally decided about it, therefore, I am reserving my ruling on it. As a matter of fact, I wished that before giving my ruling the hon. Member should have discussed this matter with me. As regards the wrong statement made by a Minister, definite rulings have been given in the Lok Sabha on such matters and decisions taken and on the basis of that I, too, had ruled that the alleged wrong statement made by a Minister did not involve any breach of privilege. I had stated for that if an hon. Member made allegations in writing, then the Minister should also send his version and both the versions be placed on the Table of the House, and that is in keeping with the decisions of the Lok Sabha. But now we have to decide whether or not it would involve a breach of privilege if an hon. Member makes a certain statement and the other challenges its correctness. Before I give my final Ruling, I would like to have a detailed discussion as to whether such a statement involves any breach of privilege and if the House desires to discuss this matter, without referring to the contents of the privilege motion given notice of by Dr. Baldev Parkash and Chaudhri Mukhtiar Singh Malik, I am prepared to allot some time for it. I would also like to discuss this matter with the Leaders of various Groups in the House.

Call Attention Notices (Resumption)

Mr. Speaker : There is a 'Call Attention Notice' given by Dr. Baldev Parkash about the obscene literature. There is also a Motion given notice of by Comrade Shamsher Singh Josh, Comrade Babu Singh Master and Comrade Bhan Singh Bhaura, on this subject which was kept pending. I wrote to the Government about that and was informed that necessary action was being taken.

लेकिन मैं समझता हूं कि यह मुनासिब है कि इट बी ऐडमिटिड । आप पढ़ दीजिए ।

(But I am of the view that it would be proper to admit it. Therefore, the hon. Member may read it out.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मेरे पास इस की कापी नहीं है ।

Mr. Speaker: All right, we will take it up on the next sitting.

श्री बलरामजी दास टंडन : इस के मुताल्लिक मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस बारे में ऐक्शन जरूर होना चाहिए । हम ने कितने ही पेपर्ज़ बैन किए हैं.....

Mr. Speaker: That is why I am admitting it.

श्री बलरामजी दास टंडन : दिल्ली के पेपर्ज़ का दाखला बैन किया । इन में जो नंगी बातें कही जाती हैं इन से यंग लड़के लड़कियों पर बुरा असर पड़ता है, इन के खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए ।

जनाब एक मेरी काल अटैनशन मोशन थी ।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नहीं है । (That is not with me.)

श्री बलरामजी दास टंडन : यहां हाउस में ही भेजी थी ।

Mr. Speaker: I will find out. Then there is a Call Attention Notice No. 28 Standing in the name of Sardar Ajaib Singh Sandhu. He may please read it out.

Sardar Ajaib Singh Sandhu (Morinda S.C.) : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the recent decision of the Punjab Government to disband the Subordinate Services Selection Board, in the near future, which was created for protecting the interests of the Rural and Scheduled Castes people of the State. This Board has tried that the interests of the Rural and Scheduled Castes people should remain in tact. If this Board is disbanded then the Rural and Scheduled Castes people will suffer a lot.

Mr. Speaker : This is admitted. Government may please make a statement.

चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी : सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि सबार्डीनेट सर्विसिज़ सिलैक्शन बोर्ड को एबोलिश किया जायेगा ।

Mr. Speaker : Then, it is all right.

Presentation of the Report of the Committee on Government Assurances

Pandit Chiranji Lal Sharma (Chairman, Committee on Government Assurances) : Sir, I beg to present the Tenth Report of the Committee on Government Assurances, 1964-65.

Bill (s) (Introduced)

THE PUNJAB EXCISE (AMENDMENT) BILL, 1965.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Excise (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Excise (Amendment) Bill

Mr. Speaker Question is—

That leave be granted to introduce the Puniab Excise (Amendment) Bill

The motion was carried

Chief Parliamentary Secretary : Sir, I introduce the Punjab Excise (Amendment) Bill, 1965.

DEMAND FOR GRANT

28—Education (Resumption of Discussion)

Mr. Speaker : Now we resume discussion on the Demand for Grant—28—Education. *Comrade Babu Singh Master was in possession of the House, when it adjourned yesterday. He may resume his speech.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ (ਫੂਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੀਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਛਾਗਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਐਟ ਦਾ ਹੈਲਮ ਆਫ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਯੂਸ਼ਨ ਇਹ 1929 ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਤੇ ਮੌਡਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿਤੇ ਪਰ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ, ਨਾ ਕਵਾਲੀਫਾਇਡ ਸਟਾਫ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ

---

*Note—For previous discussion on this demand please refer to P.V.S. Debates Vol. I No. 22, dated 25.3.65.

ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਬੂ ਤੇ ਕਲਰਕ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਐਪਟੀਚੂਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ।

ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ **M.A. Ph.D.** ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਲਗ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। **(Since a separate day has been allotted for discussion on the Agricultural University, the hon. Member may discuss these things on that day.)**

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਥੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਹਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਉ ਦੇ ਸਕੀਏ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ? **(Is the Agricultural University connected with Agriculture or Education on Agriculture.)**

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫੂਲ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਜੇ. ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂਪਣ ਲਈ ਗੰਨਾ ਦਿਤਾ। ਚੂਪ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿਠਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਢੀ ਦਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਾਲ ਮੋਢੀ ਦਾ ਹੀ ਗੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਢੀ ਦਾ ਗੰਨਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਲਬੇਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੁਰੈਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਨਾਲਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੌਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਊ ਮਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਔਬਸੀਨ ਅਤੇ ਔਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਅਤੇ ਅਬਨਾਕਸ਼ਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਇਕ

[ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ]

ਫਿਊਡਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਟ ਡਰੈਸਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰਸਾਲੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (1) ਇੰਡੀਅਨ ਆਬਜ਼ਰਬਰ, (2) ਸੂਰਤ, (3) ਕਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਲੇਖ ਕਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਪਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਗਾਣੇ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਭਾਗੀਰਥ ਲਾਲ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉ, ਮਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਵਾਕੇ ਤੇ ਚਿਪੀਆਂ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਦਿਉ। ਅਜ ਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁਗ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਰਾਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਚਾ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਚੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਚ ਡਰਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਚੀ ਸਪਿਰਟ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਚੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦੇ, ਗਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਫਾਹਸ਼ ਫਿਲਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਗਲ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਜੀਠਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮੈਟ੍ਰਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਹਾਈਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਜਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਦਿਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖ ਕੇ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਜ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਈਕੁਅਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਜ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਹੈ । ਜਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਵਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮਹਾਂਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ—

If you want to see real India go to the remotest corner.

ਅਜ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । **We have to better the condition of the masses.** ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਰਹੂਮ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਦਿਹਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਰਿਕਟਨੈਸ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਰਿਕਟਨੈਸ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਹਾਤ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸ-ਚੇਕਰ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਹਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੰਡਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਾਡੇ ਦੋ ਐਮ. ਐਲ. ਸੀ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ । ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ

[ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ]

ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਨਿੰਗ ਰੀਵਾਇਜ਼ਡ ਬੈਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਬਨੀਫਿਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਅਖਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिलों (तरन तारन) : स्पीकर साहिब, मुझे आज यह देख कर काफी बेहौसला होना पड़ा कि जब मैं देखता हूं कि इतनी अहम मद हो और इतनी अहम बहस हो रही हो और हाऊस तकरीबन तकरीबन खाली पड़ा हो खास तौर पर मेरे सामने वाले बैंच तो बिल्कुल खाली पड़े हैं और मायूसकुन नजारा पेश कर रहे हैं। एक दो अच्छे अच्छे बोलने वाले बैठे हैं। चौधरी मुख्तयार सिंह शायद बोलने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी कोई नजर नहीं आता, जो बोलने वाला हो।

श्री अध्यक्ष : ढिलों साहिब, इस हाऊस में सब बोलने वाले हैं सिर्फ मैं ही सुनने वाला हूं। (हंसी) (*Addressing Sardar Gurdial Singh Dhillon*)-- (All in this House are here to make speeches, and it is only I who is to hear them.) (*laughter*)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिलों : स्पीकर साहिब मुझे थोड़ी बहुत इस बात की खुशी है कि ऐजुकेशन का बजट बनाया गया है और अच्छा बनाया है लेकिन इस के साथ साथ कई तरह के और मसले पैदा हो गए हैं। और हैरानी होती है कि उन का हल क्या होगा ?

आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से इस हाऊस में प्राइमरी. और हायर सैकंड्री ऐजुकेशन के बारे में काफी बातीं होती रही हैं। और मैम्बर साहिबान ने कम्पलसरी ऐजुकेशन पर और हायर सैकंड्री सिस्टम पर अपनें अपने ख्यालात का इजहार किया है। और अब दूसरा साल आ गया है और पोजीशन वैसी ही है। हम हायर सैकंड्री सिस्टम को लाए हैं। और जिस साल हायर सैकंड्री सिस्टम को शुरू किया गया था तो इस उम्मीद से शुरू किया गया था कि इस से पढ़ाई अच्छी होगी और यह सिस्टम मुफीद साबित होगा, उस वक्त 40 के करीब हायर सैकंड्री स्कूल बनाये गये थे। कुछ गवर्नमैंट स्कूलों को और कुछ दूसरे स्कूलों को हायर सैकंडरी में तबदील करने का फैसला किया गया। और इस के लिये सरकार ने भी कहीं पर डेढ़ लाख, दो लाख और अढ़ाई लाख रुपया भी दिया। हैरानी यह होती है कि यह स्कूल 40 से बढ़ कर आज 450 तक पहुंच गए हैं और इन हायर सैकंड्री स्कूलों के बारे में आप इन की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि 234 में से 185 तो गवर्नमैन्ट स्कूल थे जिनको हायर सैकन्डरी में तबदील किया गया। इस के इलावा मिडल स्कूल भी थे जिन्हें अपग्रेड किया गया। अपग्रेडिंग

गवर्नमैन्ट स्कूलों की और प्राइवेट स्कूलों दोनों की की गई। और उम्मीद यह थी कि जितने स्कूल अपग्रेड होंगे उतना ही एजूकेशन को बेहतर बनाने में मदद देंगे। लेकिन आज यह हालत है कि सिर्फ नाम के स्कूल हैं बोर्ड बदल दिये हैं और इस के लिये फन्डज़ नहीं बिल्डिन्ग नहीं है न कोई इक्विपमेंट है और न ही स्टाफ में कोई बेहतरी की गई है। हायर सैकंडरी के लिये कोई क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ा। इस हालत को देख कर मायूसी होती है और मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करता मुझे खुद जा कर स्कूलों में देखने का मौका मिला है कि वहां कोई तबदीली नहीं आई। बिल्डिन्ग वही, स्टाफ वही और सामान वही सिर्फ नाम बदल दिया गया है। तो ऐसी हालत में काम किस तरह से चलेगा? अगर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते तो शायद बेहतर होता। नई डिवैलपमैन्ट थी इस के साथ ही इस तरफ भी डिवैलपमैन्ट की जाती। लेकिन हैरानी की बात है कि जब सन् 1962 के जनरल इलैक्शन्ज़ आये तो हायर सैकंडरी स्कूलों की तादाद में इज़ाफा हुआ। और फिर इलैक्शन्ज़ के दौरान तो यह मशरूम की तरह बढ़ गए। और इस हायर सैकंडरी ऐजुकेशन के सिस्टम को एक पोलीटीकल बायस दे दिया गया। हायर सैकन्डरी स्कूल बनाने के वायदे किये गये और स्कूलों को बगैर इस बात के देखे कि इन में पूरी इक्विपमैन्ट है कि नहीं, हायर सैकन्डरी बना दिया गया। और यह एक गल्त चीज़ थी जो की गई जिस का नतीजा यह हुआ कि आज हायर सैकन्डरी स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। और दूसरी तरफ आज इन्होंने यह फैसला कर लिया है कि एक स्कूल बोर्ड बना दिया जाये। पिछले साल शायद आपको यह याद होगा कि मैं ने मिनिस्टर साहिब से पूछा था और उन्होंने उसका जवाब देते हुए अपनी तकरीर में कहा था कि हम तीन लेवल पर बोर्ड बनाने की स्कीम पर विचार कर रहे हैं। प्राइमरी मिडल स्कूल बोर्ड, जूनियर सैकंडरी स्कूल बोर्ड और हायर सैकंडरी स्कूल बोर्ड अलग अलग बनाये जाने का ख्याल था लेकिन जैसा कि आखिरी फैसला हुआ सिर्फ हायर सैकंडरी स्कूल बोर्ड बनाने की बात तय हुई (विघ्न)।

(सरदार हरचन्द सिंह की तरफ से विघ्न)

अब तो मैं प्रजातन्त्र पार्टी से नहीं बोल रहा, अब तो खामोश रहें। (विघ्न)।

श्री बनवारी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहिब, इस से पहले कि मननीय मैम्बर अपनी तकरीर शुरू करें आपका ध्यान मैं इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने, अलग अलग प्राब्लम्ज़ हैं। इस लिए और कुछ नहीं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ एक एक मैम्बर को ज़रूर बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : डिस्ट्रिक्ट वाइज़ टाइम का एलाट किया जाना बड़ा ही मुश्किल है। बहरहाल टाइम के अन्दर मैं जितने मैम्बरों को बुला सका बुलाने की कोशिश करूंगा। (It is very difficult to allot time district-wise. Any how I will try to accommodate the maximum number of the hon. Members to speak within the time at my disposal.)

श्री बनवारी लाल : मेरे कहने का मतलब यह था कि कई डिस्ट्रिक्ट्स के कई कई मैम्बर्ज़ घंटों तक बोलते चले जाते हैं, और कई ऐसे ज़िले हैं जिन के मैम्बर्ज़ को बोलने का टाइम ही नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष : इस में क्या किया जाये, सीनियर मैम्बर्ज़ और बैक बैंचर्ज़ में डिस्टिंकशन करनी पड़ती है। (I am helpless as some distinction has to be made between senior Members and back benchers in alloting time.)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : मैं अर्ज़ कर रहा था कि मिनिस्टर साहिब ने इस बात के बारे में बताया था कि हम 3 लैवल्ज़ पर स्कूल बोर्ड बनाने का विचार रखते थे लेकिन आखिरी फैसला हायर सैकंडरी स्कूल बोर्ड बनाने का हुआ। इस से काफी पेचीदगी पैदा हो गई है। हायर सैकन्डरी स्कूल बोर्ड सारे देश में हैं सिर्फ जम्मूं और काश्मीर और पंजाब में नहीं हैं। यह मसला सरदार प्रताप सिंह कैरों के वक्त भी खड़ा हुआ था कि हायर सैकंडरी स्कूल बोर्ड कायम करना चाहिये या नहीं करना चाहिये। इस पर काफी गरमा गरमी और चर्चा हुई और सोच विचार किया गया और आखिर में यही फैसला किया गया था कि जो तरीका चल रहा है, वही रहने दिया जाये और उस वक्त से आज तक वही सिलसिला चला आ रहा है। इस बोर्ड की तश्कील को मैं ने देखा है। इस में डी. पी. आई. साहिब चेयरमैन हैं और उनके जूनियर आफिसर्ज़ को इस का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इस तरह से जो यह बोर्ड चलेगा उस पर एजूकेशन डिपार्टमैन्ट का खर्च आयेगा क्योंकि यह ट्रांज़ीश्नल पीरियड होगा इस लिये अगर इस तरीका को अपनाया गया तो काफी मुश्किलात और पेचीदगियां पैदा होंगी। पंजाब के स्कूलों की आमदनी जो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी को जाती थी वह इस बोर्ड के बन जाने से एजूकेशन डिपार्टमैन्ट को जाया करेगी और इस से यूनिवर्सिटी को काफी नुक्सान होगा।

इसी सम्बन्ध में स्टैंडिंग कमेटी आन हायर एजूकेशन की जो मीटिंग्ज़ हुईं उनकी प्रोसीडिंग्ज़ के ऐक्सट्रैक्ट मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। इस में वाइस-चांसलर, फाइनेंस मिनिस्टर और ऐजूकेशन डिपार्टमैन्ट के नुमायंदे थे। एक मीटिंग 30 अक्तूबर, 1964 को राज भवन शिमला में हुई। उस में यह बात कही गई—

Extract from the proceedings of the second meeting of the Standing Committee on Higher Education held on October 30, 1964 at Raj Bhawan Simla.

"The Education Minister assured the Vice Chancellor, Punjab University that Government would take all possible steps to ensure that the progress of the University was not, in any way adversely affected by the setting up of the proposed Board.

"The Finance Minister undertook to have the financial implications of the establishment of the proposed Board worked out in consultation with the Vice chancellor, Punjab University for the consideration of the said Committee.

इसी तरह दूसरी मीटिंग 8 जनवरी, 1965 को हुई जिस में फाइनैंस मिनिस्टर साहिब भी शामिल थे। उन्होंने कहा था—

Extract from the proceedings of the meeting of the Secondary Board Committee held on January 8, 1965.

To assess and recommend the annual grant-in-aid to be paid by the State Government to the Punjab University on account of the loss in income to be occasioned to the University by the Establishment of the Board.

The Finance Minister observed that it should be left to him to determine the quantum of loss in income that would be suffered by the Panjab University consequent upon the establishment of the Board and how best to reimburse it."

"The loss in income to the University during 1965-66 if a separate school Board is set up, would be of the order of Rs. 30 to 35 lakhs."

इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इस स्कीम पर चलने से पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोग्रैस और डिवैलपमैन्ट में कोई फर्क नहीं आयेगा और अगर स्विच ओवर करने से और बोर्ड बनाने से यूनिवर्सिटी को कोई लास होगा तो इस को पंजाब गवर्नमैन्ट पूरा करेगी। इस नुक्सान का अन्दाज़ा 30-35 लाख के करीब है। अगर आप कम से कम भी अन्दाज़ा लगायें तो यह किसी तरह भी 30 लाख से कम नहीं। इस के साथ ही आप खुद अन्दाज़ा लगायें कि पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के जो इतने एम्पलाइज़ काम पर रखे हुए हैं, उन्हें कैसे एडजस्ट किया जायेगा और बाकी जो डिसलोकेशन होगी वह किस तरह दूर की जायेगी। पंजाब गवर्नमैन्ट को यह भी एतराज़ था कि यूनिवर्सिटी कालेज ऐजूकेशन में ज्यादा दिल्चस्पी रखती है और स्कूलों को neglect करती है और इसी तरह स्कूलों की आमदनी भी कालेज ऐजूकेशन की तरफ ही ज्यादा खर्च हो जाती है। यूनिवर्सिटी एक अटानोमस बाडी है और इस में वाइस-चांसलर अटानोमस होता है। मिनिस्टरी या किसी पोलिटीकल इंटरफीयरैंस से यूनिवर्सिटी बची हुई होती है। इस में गवर्नमैन्ट किसी तरह का दखल नहीं दे सकती लेकिन दूसरी तरफ स्कूल बोर्ड बन जाने से उन का चेयरमैन डी० पी० आई० होगा और उसका वाइस चेयरमैन उसी महकमे का जूनियर आफिसर होगा। यूनिवर्सिटी एक सैट चीज़ है लेकिन यह बोर्ड अभी बनाया जाना है। इस लिये इस में कई खराबियां आ सकती हैं। जहां तक एग्ज़ामिनेशन्ज़ का ताल्लुक है मैं यह बताना चाहता हूं कि कई तरह के अनफेयर मीन्ज़ इख्तियार किये जाते हैं। उन को रोकने के लिये अनफेयर मीन्ज़ कमेटी बनी हुई है। इस का चेयरमैन किसी वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हुआ करता था और स्पीकर होता था और अब हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज है। जहां पर किसी तरह पोलिटीकल या दूसरा असर नहीं पड़ सकता और दूसरी तरफ लीकेज के बारे में भी अच्छी खासी एहतियात और पाबन्दियां हैं। स्कूल बोर्ड में डी. पी. आई. चेयरमैन होगा तो इस पर गवर्नमैन्ट का होल्ड होगा और इस तरह से यह एक पोलिटीकल सीन नज़र आयेगा। डी.पी.आई. को वाइस-चांस्लर की तरह काम करना पड़ेगा। स्कूल बोर्ड को अगर बनाना है तो इस को अटानोमस बनाना चाहिये। डी.पी.आई. को भी वाइस-चांस्लर की तरह से स्टेटस देना चाहिये। चाहे इस की तनखाह और स्टेटस वाइस-चांस्लर से कम हो लेकिन फिर भी वह इन्डिपैन्डैन्ट हो और मिनिस्टरी और पोलिटीकल इन्फलूएंस से आज़ाद हो। उसे इस पोज़ीशन में होना चाहिये जैसे कि वाइस-चांस्लर की पंजाब यूनिवर्सिटी में पोज़ीशन है। अगर इस बोर्ड को अटानोमस न बनाया गया तो परचों की नकल चलेगी और लीकेज होगी और मैं तो बल्कि यह भी कहूंगा कि पंडित मोहन लाल तो शायद कोशिश करने पर भी ऐजूकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन न करवा सकें लेकिन इस बोर्ड के बनने

[सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों]

के बाद काम का ठीक ढंग न होने की वजह से तो इन्हें ज़रूर रैज़िग्नेशन शायद देना पड़ जाए ।

मैसूर की यूनिवर्सिटी के बारे में ग्राप ने पढ़ा होगा। ग्रखबारों में छपा था कि वहां पर पेपर्ज़ की लीकेज का मसला उठा ग्रौर सारे एजूकेशन तो क्या सारी मिनिस्टरी ग्रौर गवर्नमैंट शेक हो गई थी। इस लिये मैं समझता हूं कि फरदर स्टैप्स हालात को देखते हुए उठाने चाहियें। कहीं ऐसा न हो कि हालात ही काबू में न रहें।

हायर सैकंडरी स्कूल्ज़ के बारे में भी एक बात करना चाहता हूं। पिछले साल ग्राल इन्डिया लैवल पर हायर सैकंडरी ऐजूकेशन कांफ्रैंस हुई थी ग्रौर उसके बारे में ग्रखबारों में खबरें भी ग्राईं थीं । इस कानफ्रैंस के चेयरमैन डाक्टर ए. सी. जोशी थे। उन्होंने यह कहा था कि हायर सैकंडरी सिस्टम के बारे में बड़ी उम्मीदें थीं। उन्होंने यह तसलीम किया कि इस सिस्टम को जिन उम्मीदों के साथ चलाया गया था वह परी नहीं हो पाईं। इस के लिये हमें कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा। मैं मिनिस्टर साहिब से ग्रर्ज़ करूंगा कि सिर्फ यह देखने से कि तादाद ऐसे स्कूलों की कितनी बढ़ गई है काम नहीं चलेगा। हमें कुछ न कुछ इस के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं मिनिस्टर साहिब से ग्रर्ज़ करूंगा कि इस सिस्टम पर काम तब ही चलेगा ग्रगर हम ग्रच्छे स्टैन्डर्ड कायम करें ग्रौर क्वालिटी को इम्प्रूव करें। जो हायर सैकंडरी स्कूल ग्रच्छी तरह से नहीं चलते उनको बंद कर दिया जाये । ग्राज गांव गांव में हायर सैकंडरी स्कूल खुलते जा रहे हैं ग्रौर न तो वहां कोई ट्रेंड स्टाफ है, न उनकी ट्रेनिंग का कोई इन्तज़ाम है। ग्रगर इस तरह से सैंकड़ों की तादाद में स्कूल खोले जायें तो इस का कोई फायदा नहीं होगा। हम इस तरह से ग्रपने ग्राप को धोखा दे रहे हैं ग्रौर ग्राने वाली नसलों से भी हम धोखा करेंगे ग्रगर इसी तरह से हालात को जारी रहने दिया गया।

यह भी कहा जा रहा है कि पहले वाले सिस्टम पर इस हायर सैकंडरी सिस्टम को रिवर्ट कर दो। एक राय यह भी है कि डिग्री कोर्स में एक साल निकाल कर हायर सैकंडरी में एक साल बढ़ा दो जैसा कि एफ. ए. तक हुग्रा करता था। यानी चार साल प्रियूनिवर्सिटी कोर्स में ग्रौर दो साल ग्रैजुएशन में हो जायें। ग्रौर कई ख्यालात इस सिस्टम में तबदीली लाने के लिये ग्रा रहे हैं। कनवोकेशन ऐड्रैस पर भी यही फैशन बन चुका है कि जो भी ग्राता है, कहता है कि हमारा ऐजूकेशन सिस्टम डिफैक्टिव है। मुझे हैरानी होती है कि महसूस तो सब करते हैं कि यह सिस्टम ठीक नहीं है लेकिन यह कोई नहीं कहता कि ग्राखिर फिर होना क्या चाहिये।

जहां तक बोर्ड बनाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि ग्रगर स्कूल बोर्ड बना दिया गया तो पंजाब यूनिवर्सिटी को बड़ा नुक्सान होगा। ग्रभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी मुल्क की टाप यूनिवर्सिटी है । ग्रौर यहां तक इसकी ग्रहमियत है कि इंगलैंड की ससैक्स यूनिवर्सिटी जो वन ग्राफ दी टापमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, इसके साथ ऐक्स्चेंज प्रोग्रांम बनाना चाहती है। इसके ग्रलावा भी ग्रच्छी से ग्रच्छी ग्रमैरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऐक्स्चेंज

प्रोग्राम चल रहा है। पर इस के डिवैल्प करने की तरफ मालूम होता है कि हमारा ध्यान उतना नहीं है जितना कि होना चाहिये, तभी तो ऐसी स्कीमें बन जाती हैं कि इससे यूनिवर्सिटी को घाटा पड़ने की संभावना है। अगर इस को नुक्सान पहुंचा तो यह अपना स्टैन्डर्ड कैसे मेनटेन कर सकेगी। मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार को भी इस की तरफ ध्यान देना चाहिये। और जहां तक उसके स्टेटस मेनटेन करने में मदद हो सके यह देनी चाहिये।

जो डिमांड्ज़ इम्पलाइज़ की तरफ से रखी गई हैं मैं समझता हूं कि उन पर गौर किया जाना चाहिये। उनके रहने वगैरह के लिये जो जगह चाहिये उस पर ख्याल किया जाना चाहिये।

मुझे हैरानी हुई जब ऐजूकेशन मिनिस्टर साहब ने बाहर यह कहा कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी और चेयर्ज़ बढ़ा ले और खर्च और बढ़ जाये तो सरकार उसके लिये कोई पाबन्द तो है नहीं। ठीक है कि सरकार पाबन्द नहीं है मगर इसकी जो इम्पार्टैंस है वह बढ़ती है और इस से फारेन कंट्रीज़ में भी मान बढ़ता है, वह सब हमारा ही तो मान है। इस के लिये हमें कोशिश करनी चाहिये कि उसको और बढ़ाया जाये। अगर हम ग्रांट्स की फिगर्ज़ देखें तो पता चलता है कि 1961 से ले कर 1964 तक हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी को डिवैलपमैन्ट के लिये दिया जाने वाला रुपया कम होता गया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 1961-62 में 13 लाख और पंजाब यूनिवर्सिटी को 10 लाख, 1962-63 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 24 लाख और पंजाब युनिवर्सिटी को 5 लाख इसी तरह 1964 में भी कम हो गया। मान लिया कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को रुपया दिया जाये लेकिन आखिर पंजाब ने क्या गुनाह किया है। यह ठीक है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नई बनी है और इसे डिवैल्प होना चाहिये। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी भी तो अभी डिवैल्पिंग स्टेज पर ही है। और ताज्जुब यह है कि यहां बहुत कुछ कहा गया मगर पंजाबी यूनि-वर्सिटी का ज़िक्र तक नहीं आया।

मैं ऐजूकेशन की हालत देखता हूं तो अफसोस होता है। ठीक है कम्पलसरी ऐजूकेशन बढ़ रही है और उसके बारे में यहां बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन जगह भी तो चाहिये जहां पर कि स्टूडैन्ट्स बैठ कर पढ़ सकें। एक ऐजूकेशन मिनिस्टर थे। वह कहा करते थे कि छप्परों और दरखतों के नीचे बैठ कर स्टूडैन्ट्स पढ़ा करेंगे। अगर छप्पर ही डाले गये होते, तो अब तक तो सारे ही छप्पर उड़ गए होते। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसी थिंकिंग है। अगर आज से 35 साल पहले लड़के छप्परों के नीचे या टाटों पर अथवा ज़मीन पर बैठते थे तो क्या इतने दिनों के बाद भी यही लाज़मी है कि वह वैसे हीं इनवायरनमैन्ट्स में तालीम पायें। कुछ न कुछ साथ के साथ चेंज होना चाहिए।

अजीब हालत हो रही है। अगर आप टीचर्ज़ को लें तो यह हालत है कि वे हड़ताल करने पर लगे हुए हैं। उनकी तनखाहों के बढ़ाये जाने का सवाल है। जब अभी कुछ दिन पीछे टीचर्ज़ ने हड़ताल की तो उनमें हमारे दो एम.एल.सीज़. भी थे। मुझे पता नहीं कि उन के यूनियन के साथ ताल्लुक क्या हैं लेकिन वह भी भूख हड़ताल कर

[सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों]

रहे थे। और उन से हड़ताल रुकवाने के लिये या तुड़वाने के लिये जो लोग दरखास्त करने गए उनमें मैं भी था। मैं ने जो कुछ सुना, उसके आधार पर कहने में ज़रा भी झिझक नहीं कि उनकी डिमांडज़ बिल्कुल जायज़ थीं। एक टीचर जो इतने साल खुद पढ़ कर बच्चों को पढ़ाता है और उनका निर्माण करता है उसको आप सिर्फ 60—4—110 का ग्रेड देते हैं जब कि एक स्वीपर की भी तनखाह उस से कहीं बढ़ कर है। स्वीपर का मुकाबिला करने में मैं यह नहीं समझता कि स्वीपर की कौम कम महत्व रखती है। सोशलिस्ट कंट्रीज़ में और कम्यूनिस्ट कंट्रीज़ में लेबर की डिगनिटी काफी हाई है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि टीचर्ज़ की इतनी कम तनखाह को आप कैसे जस्टीफाई करते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता। एक अनपढ़ आदमी जो सिर्फ पी. ए. पी. का सिपाही है, उसको तो हम ज्यादा तनखाह देते हैं लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले जो मास्टर हैं, वह इतने लो पेड रहते हैं कि किसी तरह अपना गुज़ारा भी नहीं कर सकते। यानी टीचरों की तनखाह 70 से शुरू होती है। टीचरों का एक और ग्रेड है जो 110—310 तक का है लेकिन उसके लिये जो क्वालिफिकेशन्ज़ मांगते हैं आप, वह है एम. ए. बी. टी. और न जाने क्या क्या। खैर यह किसी एक कैटेगरी का हाल नहीं। हैडमास्टरों का भी यही हाल है। उन की डिमांड्ज़ भी यही हैं कि उनका ग्रेड रिवाइज़ कर दिया जाये। मैं कहता हूं कि उनकी डिमांड्ज़ जितनी हैं, अगर उतनी पूरी नहीं कर सकते तो सिम्बालिक तौर पर एक रुपया ही बढ़ा दो लेकिन कुछ तो बढ़ा दो पांच या दस ही बढ़ा दो। उनकी यह मांग जायज़ है कि उनके रनिंग ग्रेड कर दो। इसी तरह से टीचर्ज़ सर्विस बैनिफिट भी मांगते हैं। और इस मांग से मिनिस्टर साहिब घबरा जाते हैं कि पता नहीं कि यह सर्विस बैनिफिट क्या हैं। यहां पर जितना बुरा हाल टीचर का है उतना शायद किसी देश में नहीं।

मैं जब आस्ट्रेलिया में गया तो मालूम हुआ कि प्रायमरी टीचर्ज़ की तनखाह 1,100 रुपया है। इथोपिया जैसा कंट्री जो हमारे से भी पीछे है उस की हालत यह है कि वहां पर प्रायमरी टीचर्ज़ की तनखाह 750 रुपये है। मेरी समझ में नहीं आता कि यहां पर टीचर को क्यों इतना लो पेड रखा हुआ है। अगर स्टैंन्डर्ड आफ लिविंग भी देखा जाए तो भी आप जस्टीफाई नहीं कर सकते कि उनकी तनखाहें इतनी कम रहें और तवक्को यह रखें कि हमारे बच्चे लायक बनें। बच्चे जो हैं वह देश की बुनियाद होते हैं और उनका निर्माण करना कोई मज़ाक नहीं है। मैं श्री प्रबोध चन्द्र जी से कहना चाहता हूं कि टीचर्ज़ को जवाब मिलना चाहिये। यह नहीं कि सिर्फ मज़ाक में उड़ा दिया जाये। यह तो बड़ा सीरियस मामला है। जो लोग उनसे मिलने गए थे और भूख हड़ताल तुड़वाने की उन्होंने अपील की थी उन में मैं भी शामिल था। उनको यह एश्योरैन्स दिलाई गई कि कुछ न कुछ होगा। तो मिनिस्टर साहिब को यह चाहिए कि इस बात को इतना लाइटली टेक-अप न करें। मैं वजीर साहिब से कहूंगा कि सर्विस बैनिफिट से घबरा नहीं जाना चाहिये कि पता नहीं यह क्या होते हैं। इस में रिवीज़न आफ पे या पैन्शन नहीं आती बल्कि सरविस बैनिफिट का मतलब यह है कि टीचर्ज़ में 15 परसैंट

ऐसे हैं कि जिनका ग्रेड 110—175 तक है, तो अगर आप रनिंग रिवाइज़्ड ग्रेड करेंगे जो कि उनकी जायज़ मांग है तो शुरू में तो ग्रेड बढ़ जायेगा पर जिनका ग्रेड पहले ही 175 तक पहुंच चुका है और ऐसे टीचर 15 परसैंन्ट के करीब हैं वह लूज़ करेंगे। इस लिए उनकी मांग यह है कि इन 15 परसेन्ट को कोई एडहाक रकम दी जाये ताकि इन्हें कोई नुक्सान न हो। जहां पर आप 85 परसैंन्ट टीचरों के लिये रिवाइज़्ड ग्रेड कर रहे हैं वहां पर जो 15 परसैंन्ट सिलैक्शन ग्रेड में हैं उन्हें भी compensation देना चाहिए। ग्रेड को एक जैसा रनिंग कर देने से उनका इन्सैंन्टिव खत्म हो जाता है। और उनकी यह मांग मैं समझता हूं कि जायज़ है। इस लिये इन्हें एडहाक रकम दी जानी चाहिये। हम उन से बात करके आये, उन्हें सैटिस्फाई करके आये, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं सैटिसफाई हो गया हूं अब क्या है। यह बात गलत है। सर्विस बैनिफिट क्या हैं? उनको पैन्शन या और ऐसी सहूलतें देने के लिये हैं। ऐजूकेशन मिनिस्टर साहिब ने मेरी बात भी नहीं सुनी, दस्तखत करते जा रहे थे। मैंने कहा कि सर्विस बैनिफिट्स के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने मेरी बात की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, आई फील टची ओवर इट। मैं मिनिस्टर के पास जाऊं तो पांच मिनट में से एक मिनट तो ध्यान से सुनें।

आवाज़ें : आप भी ऐसा ही करेंगे।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : हम आप को तब मिनिस्टर बनायेंगे जब एशोरैन्स देंगे कि ऐसा नहीं करोगे।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : आप का खतशा गलत है। इस को सीरियसली लें। स्टेट की प्राब्लम्ज़ होती हैं। उन प्राब्लम्ज़ पर माईंड अप्लाई न करें तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। यह चीज़ें चलती हैं। आज प्राईमरी स्कूलों के टीचर्ज़ और गवर्नमैंट कालेजिज़ के टीचर्ज़ जो हैं उनकी तनखाहों का सवाल आता है। पिछले सालों में, जो प्राईवेट कालेजिज़ के लैकचरर्ज़ और प्रोफैसर्ज़ हैं उनकी तनखाहों के बारे में कोशिश की गई कि गवर्नमैन्ट कालेजिज़ के बराबर की जायें। ताकि उनका काम रिस्पैक्टेबल हो। ऐसा चाहिये कि आधी रकम पंजाब सरकार दे और आधी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दे। एक दो साल से उन्होने अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं दी और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन भी नहीं देता। इस तरफ तवज्जोह देनी चाहिये। पिछले साल भी कहा था और अब भी कहता हूं कि इस तरफ तवज्जोह देनी चाहिये। प्राईवेट स्कूलज़ और प्राइवेट कालेजिज़ की बहबूदी करनी चाहिये। गवर्नमैन्ट स्कूलज़ में कम्पलसरी ऐजूकेशन और फ्री ऐजूकेशन रखी है। अगर दोनों सिस्टम्ज़ चलने हैं तो आप को प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन्ज़ को बन्द करना पड़ेगा, वरना क्वालिटी में फर्क आयेगा। टीचर्ज़ टिक नहीं सकेंगे, हैरस होंगे टीचर्ज़ की क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : सरदार गुरदयाल सिंह जी, कितना टाईम और लेंगे? (How much more time would the hon'ble Member take to finish his speech.)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। मैं ने तो किसी इंडीविजुअल की और न प्राईवेट की बल्कि मैं तो एजुकेशन डिपार्टमैन्ट की पालिसी पर विचार कर रहा हूं।

Mr. Speaker : That is right.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : एन. सी. सी. के नाम पर हमें फ़ख्र है। देश की एमरजैन्सी में इस ने बहुत काम किया। खास तौर पर हमारी यूनिवर्सिटियों ने। लेकिन एक बात होनी चाहिये कि अगर एन. सी. सी. की क्लास 3 साल हो जायें तो अच्छा है। जो सीनियर क्लासिज के स्टूडैन्ट्स हैं जैसे साइंस और एम. एस. सी., और ला वगैरा के उनके लिये मुश्कल है। आप जानते हैं कि कितना सख्त काम करना पड़ता है। एन. सी. सी. उस स्टेज से पहले पहले खत्म करनी चाहिये वरना मैं समझता हूं कि उनके फाइनल रीजल्ट्स पर इस बात का काफी असर पड़ेगा।

इन्होंने 35 मिडल स्कूल अपग्रेड किये हैं थर्ड प्लान में और आज भी मेरा ख्याल है कि बहुत सी दरखास्तें पैनडिंग पड़ी हैं। लोगों ने बिल्डिंगें बनाईं और बहुत पैसा खर्च किया है। मेरे अपने ज़िले के गांव गगोबुआ, ठरू, पंडोरी तख्त मल, खदूर साहिब, अलगो और कछ दूसरे गांवों की दरखास्तें पैन्डिंग पड़ी हैं। लोग यह समझते हैं कि अपना मैम्बर है यह बात कर के आता है। इन मेरे इलाके के स्कूलों को हर सूरत में इसी साल में अपग्रेड करना चाहिये। यूं तो हर एक मैम्बर को चिट्ठियां लिखी हैं कि कौन से हल्के की क्या प्राब्लम हैं और कौन कौन से स्कूल अपग्रेड करना चाहते हो लेकिन यहां तो मुझे इस बात का कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आता।

कल प्रिंसिपल रला राम ने बोलते हुए अंग्रेज़ी का ज़िक्र किया। मैं उन्हें बता दूं कि इस तरह लैंगुएज के बेसिज पर कोई बात करना अफसोसनाक है। हम ने इस सूबे में रिजनल फारमूला को ले कर कुछ फैसले किये हैं खाह वह गल्त थे या सही थे और आपको पता ही है कि मैं ने उसके खिलाफ राए दी थी लेकिन एक दफा उस फारमूला को एडाप्ट कर लिया तो फिर इस तरह के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिये। जिस ज़बान को हम ने एडाप्ट कर लिया है और जिस तरह की पालिसी चलती आ रही है उसे चलने देना चाहिये। एक बात होनी चाहिये कि जिस ज़बान में कोई दरखास्त आए उसी में उसका सरकार की तरफ से जवाब जाना चाहिये। जो चीज़ बैठ गई उसको जगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। अंग्रेज़ी के बगैर तो प्रिंसिपल साहिब काम नहीं चलेगा इस में साइंस और दूसरे Technical subjects हैं वही इसी ज़बान में अच्छे पढ़े जा सकते हैं। Printed Hindi तो हम पढ़ सकते हैं लेकिन शिकस्ता पढ़ना मुश्किल है। दो-दो चार-चार फारेनलैंगुवेजिज़ चलेंगी तो उस वक्त तो पढ़नी ही पड़ेंगी। लेकिन काम काज के लिये अगर किसी हिन्दी पढ़े हुए को पंजाबी नहीं आती तो अंग्रेज़ी में काम चल जायेगा और यदि पंजाबी वाले को हिन्दी नहीं आती तो अंग्रेज़ी में चल जायेगा लेकिन इसे बिल्कुल ही हटा दें तो मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। आप ने देखा है कि साऊथ में क्या हुआ है। लिंगुइस्टिक फैनाटिज़म में पड़

गये। हिन्दी के व्यू वाले आप लोग ही थे या हम ही थे। ऐसे मामलात में हमें रिंगल आऊट नहीं करना चाहिये। यह स्टेट के फायदे में होगा। स्पीकर साहिब, मैं आप का मशकूर हूं।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (गनौर) : स्पीकर साहिब, कल से ऐजूकेशन की डिमांड पर बहस जारी है। इस में सरकार 21 या 22 करोड़ के करीब रुपया मांग रही है और बहुत से मैम्बरान अपने विचार इस हाऊस में रख चुके हैं। कल प्रिंसिपल रला राम जी ने डिस्कशन को ओपन किया था और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्ज़ इस हाऊस को बताये कि 1957-58 में तुलबा की तादाद 21 लाख के करीब थी जब कि आज 32 या 33 लाख के करीब है और उस के हिसाब से ऐजुकेशन पर रुपया खर्च होना चाहिये। उस के साथ साथ कुछ कैलेफोरनिया यूनिवर्सिटी का भी ज़िकर किया, बाहिर के देशों के हवाले दिये। और आज आदरणीय ढिल्लों साहिब ने भी इथोपिया और दूसरे मुमालिक के हवाले देते हुए बताया। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि हम हिन्दुस्तान में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश के देहात में रूस है... (आवाज़ : जिस देश में गंगा बहती है।) और शहर में अमरीका है। इस देश में गंगा और यमुना सब बहती हैं।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : मेरे वाली बातें तो आप को कहनी चाहियें थीं, जो मैंने कही।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : हम देहात में तो फैसला कर देते हैं कि 30 स्टैन्डर्ड एकड़ की सीलिंग लगा दो लेकिन शहर में कोई सीलिंग नहीं बड़ी खुशी की बात है कि फारेन कंट्रीन्ज़ का ज़िक्र किया कि वहां टीचर्ज़ की तनखाह बहुत ज्यादा है। तो फिर हमें आमदनी के जरिये भी उसी तरह बढ़ाने चाहियें, स्टैंडर्ड आफ ऐजूकेशन ऊंचा हो और टीचर्ज के स्टैंडर्ड को रेज़ करने के लिये अगर हमारी कोशिश है तो हमें वह ज़राये भी बढ़ाने पड़ेंगे। आमदनी में इज़ाफा करने के लिये यह ज़राय ज़रूरी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्ज़ साहिबान को ज्यादा तनखाह मिले। हमारी डैमोक्रैटिक सोसायटी में क्वालिटीज़ को अच्छा करना है डैमोक्रैटिक सोसायटी में टीचर्ज़ के स्टैंडर्ड को हमें रेज़ करना पड़ेगा। हर एक मानता है और महसूस करता है कि टीचर्ज़ को वह रिस्पैक्ट नहीं मिल रही जो इन को मिलनी चाहिये और सुसायटी में उनको वह मुकाम हासिल नहीं जिसके वह हकदार हैं। टीचर जो कौम को बनाने वाले हैं अगर उनको पेट भर टुकड़ा भी न मिले तो आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि समाज में उनकी क्या इज्जत हो सकती है। मैं वज़ीर साहिब से मुखातिब हो कर एक बात खास तौर पर इन से अर्ज़ करनी चाहता हूं कि उनको पता है कि यहां दूसरे हाऊस के दो मैम्बर साहिबान ने भूख हड़ताल कर रखी है जिसका ज़िक्र अभी ढिल्लों साहिब ने भी किया है। उनको पता है कि किस तरह चन्द मैम्बर साहिबान जिन में मैं, ढिलों साहिब, मंगल सैन जी और देवी लाल जी भी थे बीच में पड़े ताकि बाइज्जत सोल्यूशन निकालने की बात निकले और भूख हड़ताल खत्म कराई गई लेकिन उसका अभी तक नतीजा मायूसकुन है। मैं नहीं कह सकता कि वज़ीर साहिब इस के लिये किस कदर कसूरवार हैं या हक बजानब हैं

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

लेकिन यह मैं ज़रूर कह देना चाहता हूं कि जब ऐसे हालात हो जायें कि बीच में किसी को डाल कर और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सोल्यूशन बनाया जाये तो फिर यह फर्ज़ बन जाता है कि उसका खातरखाह नतीजा निकाला जाये। इस लिये मैं अर्ज़ करता हूं कि जो एशोरेंस डाइरैक्टली या इनडायरैक्टली दी गई है वह पूरी कर दी जाये तभी यह हार्ट बर्निंग बन्द हो सकती है। हमारे सूबे में बड़ा दावा किया जाता है कि हम फ्री ऐजूकेशन दे रहे हैं पिछली हकूमत तो बुलंद बांग दावे करती थी और अब यहां प्रबोध चन्द्र जी के एक ब्यान का हवाला भी आया : मैं कहता हूं कि यह कहना कि मिडल स्टैन्डर्ड तक फ्री ऐजुकेशन दे रहे हैं बिल्कुल गल्त है और हकायक के खिलाफ है। आप फ्री ऐजूकेशन नहीं बल्कि इस बहाने से प्राइवेट एडिड और गवर्नमैंट स्कूलों में बड़ा भारी डिसक्रिमीनेशन कर रहे हैं। जो बच्चे गवर्नमैन्ट स्कूलों में पढ़ते हैं उन से तो आप फीस नहीं लेते हैं लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि प्राइवेट और एडिड स्कूलों में फीस ली जाती है। फिर आपके गवर्नमैन्ट स्कूल हैं भी कितने और जो हैं वह भी ज्यादातर शहरों में ही हैं। ज्यादा तादाद स्कूलों की प्राइवेट और एडिड स्कूलों क है। इसका मतलब यह है कि आप यह अपनी फ्री ऐजूकेशन कुछ बच्चों को ही दे रहे हैं और मैजारिटी फीस दे कर पढ़ रही है। आप और रुरल जगह को छोड़ें सोनीपत की ही मिसाल ले लें। आप हैरान होंगे कि वहां 60 हजार की आबादी है, इंडस्ट्रियल टाऊन है, सब-डिवीज़न है और रेलवे लाइन पर है लेकिन वहां कोई हाई या हायर सैकंडरी स्कूल गवर्नमैन्ट का नहीं है। वहां पर तीन प्राइवेट हाई स्कूल, हिन्दु हाई स्कूल, सी.आर. जैड. हाई स्कूल और हरियाणा हाई सकूल हैं और उन में $3\frac{1}{2}$ हज़ार तुल्बा पड़ते हैं। मैं इस सरकार से जो फ्री ऐजूकेशन का दावा करती नहीं थकती पूछना चाहता हूं कि आप इन $3\frac{1}{2}$ हजार तुलबा को कौनसी किस्म की फ्री ऐजूकेशन दे रहे हैं। सब बच्चे वहां फीस दे कर पढ़ते हैं। इसी तरह बाकी जगह है। देहात में तो हैं ही प्राइवेट स्कूल जहां बच्चे फीस देते हैं और पढ़ते हैं। तो फिर यह फ्री ऐजूकेशन का दावा महिज़ ढोंग नहीं तो और क्या है? मैं तो यह भी कहूंगा कि अगर यह एडिड और प्राइवेट स्कूल पंजाब में न हों तो आप ऐजुकेशन का मसला हल नहीं कर सकते। फिर आप क्रैडिट किस बात का लेते हैं? आप क्रैडिट क्लेम नहीं कर सकते कि आप ने पंजाब में तालीम का आला इंतजाम कर दिया है। आप स्कूलों में देखें कि टीचर्ज़ की कितनी डर्थ है। (At this stage Deputy Speak r occupied the Chair.) सौ सौ बच्चों की क्लास के लिये एक टीचर है। मैं मानता हूं कि हर जगह गवर्नमैंन्ट स्कूल तो खुल नहीं सकते और यह भी आप के लिये मुश्किल है कि सारे एडिड प्राइवेट स्कूलों को अपने हाथ में ले लें। आपकी भी मुशिकलात हैं और उनका हमें एहसास है लेकिन यह आप कर सकते हैं कि जो स्कूल तालीमी मैदान में इतना काम कर रहे हैं उन्हें ग्रांटस तो दें और जिस तरह गवर्नमेंट स्कूलों में मिडल तक मुफत तालीम देते हैं उसी तरह इन एडिड स्कूलों में भी मुफत तालीम करें तभी सही मायनों में फ्री ऐजूकेशन की बात हो सकती है। यह स्कूल बड़ी अच्छी तरह चल रहे हैं और गवर्नमन्ट स्कूलों के मुकाबले में अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप फ्री ऐजूकेशन

का क्रैडिट लेना चाहते हैं तो इन प्राइवेट स्कूलों को Substantial ग्रांटस दे कर इन में फ्री ऐजूकेशन करें और खास तौर देहाती और बैकवर्ड इलाकों के स्कूलों के लिये यह ग्रांटस जरूर दें। जहां तक अपग्रेडिंग का ताल्लुक है उसके लिये मैं वज़ीर साहिब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बगैर किसी पार्टी के भेद भाव के सारे मैम्बर साहिबान के जज़बात का एहतराम किया है। जे.बी.टी. यूनिटस खोलने थे तो भी उन्होंने मैम्बर साहिबान को कंफीडैन्स में लिया। मेरी तारीफ करने की कुछ आदत नहीं लेकिन सच बात यह है कि यह काबिले तारीफ है कि प्रबोध जी ने मैम्बरान को खुद पूछा। पहली दफा यह बात पंजाब में किसी वजीर ने की है। वरना तीन साल से मैं भी देखता रहा हूं कि वजीर साहिब के पीछे गिड़गिड़ाते रहे हैं लेकिन आंख भिड़ती बात चली रही है। मेरे इलाके को न मालूम इस वजह से कि मैं आपोजीशन का था या मैं जूतियां न चटखार सका किसी ने न पूछा। मैं प्रबोध जी की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने सारे मैम्बरान को कदर की निगाह से देखा और उन्होंने ठीक किया क्योंकि आखिर हर मैम्बर अपने इलाके के इंट्रैस्ट्स को रीप्रीजैन्ट करता है दुख-सुख और भला-बुरा जानता है। अगर एक मैम्बर के हल्के में 100 गांव हैं तो उन सब में तो स्कूल एक साथ-अपग्रेड नहीं किये जा सकते लेकिन वह यह तो जानता है कि कहां ज़रूरत ज्यादा है। उन्होंने ठीक कदम उठाया जो मैम्बर साहिबान को कन्फीडैन्स में लिया पहले तो कोई किसी को पूछता नहीं था कांग्रेस और आपोजीशन देखी जाती थी। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा डिसक्रिमीनेशन नहीं किया है और उसके लिये मैं उन्हें आपोजीशन की तरफ से बधाई देता हूं। इसके साथ साथ एक नुक्स की तरफ भी मैं उनकी तवज्जोह दिलाना चाहता हूं। पिछले साल कोई अप-ग्रेडिंग नही हुई खैर आप की अपनी फाइनैंशल मुश्किलात होंगी लेकिन एक चीज समझ नहीं आई कि प्राइमरी से मिडल करना है तो लोग 7,800 रुपया जमा करायें और मिडल से हाई करना है तो 18 हजार रुपया जमां करायें। यह किस लिये आप मांगते हैं जब कि लाखों रुपये इक्ट्ठे करके बिल्डिंग्ज़ बना कर आप को लोग देते हैं। क्या ऐजूकेशन देना आपकी ज़िम्मेवारी नहीं है? मैं अर्ज़ करता हूं कि तालीम का देना सरकार की ज़िम्मेवारी है। इस लिये जो लोग लाखों की बिल्डिंगज़ बना कर आपके हवाले करते हैं इन पर रहम करो और यह जो 7,800 और 18 हजार रुपये की शर्त उन पर आयद की है उसे हटायें। पुरानी हकुमत ने कुछ ऐसे फैसले किये थे जो काबिले मुज़म्मत थे और जिनको अनडू भी किया है और उसके लिये लोगों ने आप की तारीफ भी की है। यह भी एक निकम्मा काम पुरानी हकूमत ने किया था जो 7,800 और 18 हजार की शर्त लगाई थी। इसे भी आप अनडू करें। ठीक है आपकी भी माली दिक्कतें होंगी और अगर आप हटा नहीं सकते तो कम से कम जिन स्कूलों ने अभी हाल ही में आपको इमारतें बना कर दी हैं उन से ईज़ी इंस्टालमैन्ट्स में यह पैसे लें। वहां मेरे हलके में पुरखाश, पिन्हाना वगैरा में लोगों ने निहायत अच्छी बिल्डिंगज़ बना रखी हैं हालांकि फल्डज़ ने लोग मार रखे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, Education is the entire responsibility of the State under the Constitution, मैं आप के द्वारा मन्त्री साहिब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्कूलों के अपग्रेडेशन के बारे में नजर सानी करें। देहातों के अन्दर सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डज़ से जो स्कूल टेक ओवर

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]
किये उन की हालत बहुत ही खराब है । उन की मुरम्मत होने की ज़रूरत है। इस के लिये सब काम तैयार हो जाता है लेकिन उन को ठीक नहीं किया जा रहा है। खास तौर पर मैं अपने इलाके की बाबत अर्ज़ करना चाहता हूं । हमारे इलाके में फलड्ज़ आने के कारण उन बिल्डिंगज़ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है । लड़के वहां पर बैठते हैं तो वहां पर मच्छर ही उन को खाते हैं। इस की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इसी तरह से बच्चों को पानी पिलाने के लिये देहातों में ढाई या तीन रूपये में आदमी रखना चाहते हैं। आजकल के ज़माने में इतनी थोड़ी तनखाह पर कौन लग सकता है । मंत्री साहिब को इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, को-एजूकेशन के बारे में ज़िक्र करना चाहता हूं । इस के बारे में कल भी और आज भी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं । मैं भी इस के बारे में फिर कहना चाहता हूं । अगर सरकार ने को-एजूकेशन चौथी या पांचवी जमात तक ही सीमित रखनी हो तो कोई नुक्सान नहीं होगा । अगर सरकार इस के ऊपर भी रखना चाहती है तो मैं समझता हूं कि इस से बच्चों के करैक्टर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । उन का मोरेल नीचे ही गिरेगा । मैं मन्त्री महोदय से अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह कल्चरल प्रोग्राम को समाप्त कर दें । जो ड्रैस प्रस्क्राइबड की जाती है, वह किसी से छुपी हुई नहीं है। हर एक की टैंडसी बन चुकी है कि वह दूसरे मुल्कों की कापी करने की कोशिश करते हैं। इस से देश का वातावरण बिलकुल मुख्तिलफ बनता जा रहा है । अगर उन की नकल करनी है तो उस के लिए काफी अर्सा दरकार है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार को को-एजुकेशन सिस्टम खत्म करना चाहिए । लेला मजनू के किस्सों को छोड़ो । लेकिन यहां पर भी करैक्टर गिरते जा रहे हैं । मैं किसी इंडीविज्यूल या किसी स्कूल के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन को-एजूकेशन से सिर्फ स्कूल के बच्चों और लड़कियों में प्रेम की बातें नहीं होती बल्कि टीचर्ज़ और टीचरैसिज़ में भी मुहब्बत की पींगे पड़ती हैं । इस से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि स्टूडेन्टस पर क्या असर पड़ता है। (घंटी) मैं ने तो अभी 7-8 मिनट ही लिए हैं और अपने बिचार हाउस में रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्षा : माननीय सदस्य 14 मिनट बोल चुके हैं और वह जल्दी ही वाइंड अप करें। (The Hon. Member has spoken for 14 minutes. He may now wind up within a few minutes.)

Pandit Chiranji Lal Sharma : I am opening debate on behalf of the Opposition.

कुछ आनरेबल मेम्बर 44, 45 मिनट बोले हैं । मुझे तो अपने विचार प्रकट करने के लिए कम से कम 20, 25 मिनट दिए जाएं ।

Deputy Speaker He may wind up within 5 minutes.

पंडित चिरंजी लला शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां हायर सैकंडरी सिस्टम के बारे में ज़िक्र किया गया । श्री जोशी, वाईस चांसलर, पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी इस बारे में अपने

विचार प्रकट किए थे । टीचर्ज़ की ज़बानी भी हम सुनते हैं कि हायर सैकंडरी सिस्टम कामयाब होता दिखाई नहीं देता । सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने भी अपनी स्पीच में कहा है कि इस सिस्टम को लोगों के ऊपर थौंपा न जाए । उस से हाई स्कूल बेहतर हैं । अगर सरकार इस सिस्टम को चालू करना चाहती है तो सरकार को प्राइवेट स्कूलों को 90 प्रतिशत एड देनी चाहिए । इन को देहली पैंटरन पर चलाने चाहिएं । सरकार को साइंस के एप्रेटस के लिए प्राइवेट स्कूलों को एड देनी चाहिए । सरकार को इस के लिए खास इन्तज़ाम करना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं जे. बी. टी. टीचर्ज के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं । इन की ट्रेनिंग एक साल से दो साल कर दी गई है लेकिन अगर आज भी इन का मुकाबला नार्मल और एस. वी. टीचर्ज़ के साथ किया जाए तो मैं कह सकता हूं कि सही मायनों में नार्मल और एस. ए.वी. ही टीचर्ज़ हैं । मैं समझता हूं जो जे.बी. टी. पास करने के लिए टीचर्ज़ लग रहे हैं उन से शिक्षा का स्टैंडर्ड ऊपर नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहिब को पता ही होगा कि बच्चों की फाउंडेशन पहली जमात से बनती है । लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि पहली जमात के बच्चे फाउंटेनपैन के बगैर लिखते ही नहीं हैं । मुझे अपनी बात याद है कि जब हम पढ़ा करते थे तो हमें मास्टर कहते थे कि जी और जैड की निब से लिखें लेकिन आज जी और जैड की निबें मार्किट में दस्तयाब ही नहीं हैं । अगर हम कहीं आठवीं या दसवीं जमात में फाउनटेन पैन का इस्तेमाल कर लेते तो हमें मास्टर खूब पीटते थे । आजकल बच्चों का हैंड राइटिंग बिलकुल तबाह हो चुका है । इस का सब से बड़ा दोष मास्टरों के ऊपर है । जे. बी. टी. में क्राफट का सबजैक्ट होना चाहिए । आजकल बच्चे चार जमात पढ़ कर भी 40 या 50 रुपए देकर विद्या विनोदिनी का सर्टीफिकेट ले लेते हैं और जे. बी. टी. में दाखल हो जाते हैं । इस से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा होगा । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार को जे. बी. टी. में क्राफट का सबजैक्ट लागू करना चाहिए । अध्यापक बच्चों की अच्छी फाउंडेशन बनाने वाले हैं । इसलिए सरकार को इन की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए । बच्चों की फाउंडेशन को पक्का बनाने के लिए अच्छे आदमी रखने चाहिएं ताकि उन का स्टैंडर्ड ऊंचा हो सके ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां यूनिवर्सिटी का ज़िक्र किया गया । पंजाब में चार यूनिवर्सिटीज़ चण्डीगढ़, लुध्याना पटियाला और कुरुक्षेत्र में हैं । यहां पर भी कहा गया है कि डी. पी. आई. के दफतर में पालेटिक्स इन्वाल्व हो चुका है । मेरे इस बारे में बिलकुल विचार भिन्न हैं । यूनिवर्सिटी में 80, 90 सैनेटर्ज होते हैं और सिंडीकेट में भी 16-17 मेम्बर्ज़ होते हैं । उन में बहुत ही कम एजूकेशनिस्ट होते हैं और बाकी के सारे पब्लिक के नुमायंदें होते हैं । मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटीज़ के अन्दर पालेटिक्स का गढ़ बन चुका है । नतीजा यह है कि favour after favour is showered by University authorities on individuals. जितनी फेवरटिज्म रैड टैपइज्म और बाकी की इज़्म यूनिवर्सिटी में चल रही हैं उतनी अन्य किसी जगह नहीं हैं । गवर्नमेंट के दफतरों में इतनी फेवरटिज्म नहीं हो रही है । अगर महकमा तालीम में कोई ऐसी नाजायज़ बात होती है तो हम मिनिस्टर साहिब के नोटिस में ला सकते हैं, अपने ग्रीवैंसिज़ हाउस

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

में प्रकट कर सकते हैं लेकिन जब कोई बात यूनिवर्सिटी के बारे में आती है तो कहा जाता है कि इस पर डिस्कशन नहीं हो सकती क्योंकि यह अटानोमस बाडी है । सरदार गुरदयाल सिंह ने ठीक ही कहा है क्योंकि वह पंजाब यूनिवर्सिटी की सैनेट के मेम्बर हैं । उन्होंने कहा कि पिछले साल यूनिवर्सिटी को इतना रुपया दिया और इस साल इतना रुपया देने जा रहे हैं । मैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि हिन्दी रिजन में यह पहली यूनिवर्सिटी खोली गई है । That is a University in the making. That is a University which was started with the patronage of the Centre. मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी में हमारे लिए जगह नहीं है । इस रिजन के लैक्चरार्ज़ और प्रोफैसरों के लिए जगह नहीं है । पंजाब यूनिवर्सिटी में 90 मेम्बर्ज़ होंगे और उनमें हमारे 9 से अधिक मेम्बर्ज़ नहीं होंगे । हिन्दी रिजन को हर तरह से इग्नोर किया जा रहा है । फिर कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में दखल न किया जाए । पीछे नौमीनेशन के बारे में यहां पर सवाल आया था तो उस वक्त मिनिस्टर साहिब ने जवाब देते हुए कहा था कि गवर्नर साहिब ने टेलेंट के बेसिज पर लोगों की नौमीनेशन की । लेकिन हमारी नौमीनेशन उस में नहीं आई । मैं आप के द्वारा बताना चाहता हूं कि जाट कालिज रोहतक 50 साल पुराना इंस्टीच्यूशन है वहां की मैनेजिंग कमेटी का चेयरमन चौधरी राम धन सिंह वह शख्स है जो कि लायलपुर कालिज का प्रिंसिपल था । वह काबलियत का मुजिस्मा है । मैं पूछता हूं कि क्या वजह है कि उस को यूनिवर्सिटी में नहीं लिया गया । वैश्य हाई स्कूल की संगे बुनियाद महात्मा गांधी ने रखी थी उस के साथ एक गर्ल्ज़ स्कूल भी है वहां पर इतने पुराने पुराने टीचर्ज़ हैं जिन को चालीस चालीस साल और पचास पचास साल पुराना टीचिंग का और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरिएंस है । बड़ी एक्सपीरिएंस्ड मैनेजिंग कमेटी है । और अर्ज़ करूं चौधरी हरद्वारी लाल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर रह चुके हैं अब इस सदन के मेम्बर बन गए हैं उन को पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनेट में रखा जा सकता था । क्यों नहीं रखा गया हमें इस बात का कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिलेगा । इतने तजरुबाकार आदमियों से किसी को भी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रखा गया । हिन्दी रिजन को कुछ रीप्रेज़ैंटेशन नहीं दी जाती । न तो टीचर्ज़ में, न स्टूडैंट्स में और ना ही मैनेजमैंट में कोई नुमाइंदगी दी जाती है । मैं वज़ीर साहिब का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं (घंटी की आवाज़) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं दो तीन मिनट और लूंगा । पंजाब प्रांत में 65 नान-गवर्नमैंट कालिज हैं । पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ग्रांट देती थी और उस के मुताबिक कालिजिज़ ने अपने प्रोफैसरों, लैक्चरर्ज़ के ग्रेड ऊंचे कर के उन की तनखाहें बढ़ा दी थीं अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ने वह ग्रांट बंद कर दी है तो 65 कालिजों में से 25 कालिज ऐसे हैं जिन्हों ने ग्रेड रीवाइज़ कर दिये और तनखाहें कम कर दीं । लेकिन चालीस कालिज ऐसे हैं कि जिन्होंने बावजूद इस बात के कि ग्रांट विदड्रा कर ली गई है इस आशा में कि गवर्नमेंट रीइम्बर्स करेगी तनखाहें बदस्तूर उसी तरह से दीं । लेकिन ताज्जुब की बात है कि गवर्नमेंट ने उन चालीस कालिजों को बजाए क्रैडिट देने के और बजाए उन की हौसला अफज़ाई करने के पीनलाईज़ किया । दूसरे 25 कालिजों को तीन लाख रुपया ग्रांट देने का फैसला किया है मगर यह बात तो बेइनसाफी पर मबनी है । अगर उन्होंने रुपया देना है तो 65 के 65 कालिजों को

देना चाहिये नहीं तो प्रोफैसरों के जज़बात को ठेस पहुंचेगी । अगर तनखाहें नीचे से ऊपर की जाएं तो उन का पढ़ाने के लिये हौसला बढ़ता है लेकिन अगर ऊपर से तनखाह, जो कि वे पिछले दो तीन साल से ले रहे हों नीचे की जाए तो उन के जज़बात को ठेस पहुंचेगी । इस लिए मैं हकूमत का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं ।

इस से आगे, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं वज़ीर साहिब का ध्यान एग्ज़ामिनेशन्ज़ की तरफ दिलाना चाहता हूं । जो लड़के इम्तहानों में अनफेयर मीन्ज़ अडाप्ट करते हैं उन का रिज़ल्ट लेटर आन कर दिया जाता है लेकिन एक एक साल गुज़र जाता है और उन का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया जाता । अगर कोई अनफेयर मीन्ज़ अडाप्ट करता है तो उस को पीनलाईज़ किया जाए लेकिन यह तो ठीक नहीं है कि एक एक साल तक रिज़ल्ट ही न डिक्लेयर किया जाए । कई एक तो एग्ज़ानोरेट कर दिया जाता है । हम रोज़ वहां से टैलीफोन करते रहते हैं कभी निझावन साहिब को और कभी नारंग साहिब को, मैं यह बात प्रबोध चन्द्र जी के खास तौर पर नोटिस में लाना चाहता हूं......(घंटी की आवाज़) गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल प्राविंशलाईज़ किये थे सन् 1957 में, जो टीचर्ज़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में से गवर्नमेंट सर्विस में आए उन की अभी तक 1950 और 1951 की तनखाहें नहीं मिलीं । सैंकड़ों टीचर्ज़ ऐसे हैं । कई एक ने तो तंग आ कर गवर्नमैंट को नोटिस दे रखा है हकूमत के खिलाफ वे लोग दावा करेंगे । तनखाहें तो एक तरफ उन को प्रावीडैंट फंड भी अभी तक नहीं मिले । रोहणे स्कूल, तहसील रोहतक से राम कुमार टीचर सन 1959 में रीटायर हुआ था उस की अभी तक 50, 51 की तनखाह एरियज़ में पड़ी हुई है । उस ने कई बार रजिस्टरी करवा कर गवंनमैंट को अर्ज़ियां भेजी हैं उस को कोई इक्नौलिजमैंट नहीं मिलती । वह भी गवर्नमैंट के खिलाफ दावा करेगा और डिग्री होगी । इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है ।

आई. टी. आई. के दाखले के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं । पानीपत की मिसाल देना चाहता हूं गवर्नमैंट को क्रेडिट जाता है कि वहां पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिये स्कूल खोल रखा है। स्टेट में बहुत से ट्रेनिंग स्कूल खोले हैं । लेकिन वहां पर दाखले के वक्त बहुत शरारत होती है, रिश्वत चलती है । बदमाशी होती है और शराब की बोतलें मांगी जाती हैं । एक प्रिंसिपल बी. आर. भक्त, एट दी वर्ज आफ रीटायरमेंट हैं वह वहां पर बैठे हैं । जो लड़के दाखल नहीं हो सके उन को आज बुला बुला कर, चिठियां लिख कर घर से बुलाया जा रहा है और दाखल किया जा रहा है । वहां पर एक रेगुलरली कान्स्टीच्यूटिड बोर्ड भी बना हुआ है उस में एक फोरमैन है वह भी वहां पर बैठता है । सोनीपत में स्कूल में दाखले के लिये वे लोग वहां पर बैठते हैं चौधरी रिज़क राम जी, अब तो मिनिस्टर बन गए हैं, जब एम. एल. ए. थे तो यह भी उस कमेटी में बैठते थे । इन के बाद कोई एम. एल. ए. उस कमेटी पर नहीं लिया गया । क्या किया उन्हों ने दो आदमियों को बुला कर लगा लिया है । एक तो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेज़ीडैंट और दूसरे चौधरी फूल सिंह को टैलीफोन कर के घर से बुला कर उस कमेटी में बैठा लिया गया । वे लोग बुला बुला कर लड़कों को कहते हैं कि कौन है हमारे इलाके का चलो दाखल हो जाओ.। जिन लड़कों की दरखास्तें होती हैं उन को कोई पूछता नहीं है, जो क्वालीफाइड हैं उन को दाखल नहीं किया जाता, जिन का हक बनता है, जो पोलिटीकल सफरर हैं उन को कोई पूछता नहीं है । उस प्रिंसिपल और फोरमैन को लामहदूद ताकत दे रखी है । वे लोग

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]
अपनी मर्ज़ी से दाखला करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज़ को चलाना चाहते हैं तो लोगों के ज़ज़बात को मत भड़काओ नहीं तो वे इस के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे वे कभी बरदाश्त नहीं करेंगे। मैं मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह इस बात की इन्क्वायरी करें (घंटी की आवाज़) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं और आप से माफी चाहता हूं कि आप के कहने के बावजूद मैं ने एक दो मिनट ले लिये ।

उपाध्यक्षा : पेश्तर इस के कि मैं किसी मेम्बर को बोलने के लिये काल अपान करूं आई वुड लाईक टू सीक दी कोआप्रेशन आफ दी हाउस । मेरे पास सिर्फ एक घंटा बाकी है । मिनिस्टर साहिब ने भी जवाब देना है और डीमांड भी पुट करनी है । इस लिये मैं चाहती हूं कि हाउस के मेम्बरान तावन दें । जो साहिब बोलने के लिये खड़े हों अगर वे अपनी मर्ज़ी से ही बोलते जाएं तो चेयर को बड़ी मुश्किल पेश आती है । इस लिये मैं आप से मदद चाहती हूं । अगर हर एक बोलने वाले पर दस मिनट की पाबंदी लगा दें तो सारे 6 मेम्बर बोल सकते हैं । बार बार घंटी बजाना अच्छा नहीं लगता । मैं हाउस की कोआप्रेशन चाहूंगी । (Before calling upon any hon. member to speak, I would like to seek the co-operation of the House. We have only one hour left. The Minister has yet to reply and the demand is to be put. So I would like the members to co-operate with me otherwise the Chair's becomes a difficult job. I seek your help. Six Members will be able to speak if we limit the speeches to 10 minutes each. Repeated ringing of bells does not sound proper. I seek the co-operation of the House.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम । एक घंटे के अन्दर 6 मेम्बर बोलें यह कोई कानून नहीं है । कल से यह डीबेट चल रहा है, कोई मेम्बर आधा घंटा बोला, कोई पौना घंटा बोला उन पर कोई टाईम लिमिट नहीं लगाई तो आज दस मिनट के लिये टाईम लिमिट लगाई जा रही है । यह ठीक नहीं है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : On a point of order, Madam. ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਫਰਮਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਈਏ । ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ 20 ਮਿਨਟ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਅਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ? (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : मैंने तो आप की मदद मांगी है । अगर आप कोई टाईम लिमिट फिक्स नहीं करना चाहते तो इस टाईम के अन्दर अन्दर जितने मेम्बर साहिबान बोल सकते हों बोल लें । मुझे इस में क्या एतराज़ हो सकता है । लेकिन इस से दूसरे मेम्बर साहिबान के साथ बेइन्साफी होती है जिनको बोलने का मौका नहीं मिलता । (I have just sought your help. If the hon. Members are not in a mood to fix some time limit for the speeches then let only those

Members to speak who can do so within this time now left at our disposal. I have no objection to that. But it will be injustice to those hon. Members who do not get opportunity to speak.)

श्री रूप लाल मेहता: आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम । आप चाहे कोई टाईम लिमिट लगाएं । दस मिनट लगाएं या ज्यादा लेकिन हमें ज़रूर टाईम मिलना चाहिए (विघ्न)

(इस वक्त डाक्टर बलदेव प्रकाश बोलने के लिए खड़े हुए ।)

उपाध्यक्षा : मैं ने अभी किसी को काल अपान नहीं किया । श्री प्रबोध चन्द्र जी, आप से मैंने मदद मांगी थी । आप की तरफ से कोई जवाब नहीं आया । (I have not yet called upon any Member. I sought help from Shri Prabodh Chandra, but without response.)

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : जहां तक इस साईड के मेम्बर साहिबान का ताल्लुक है, उन से तो मैं दरखास्त कर सकता हूं कि आप के हुक्म का पालन करें और आप दस बारह मिनट जितना भी टाईम मुकर्रर करें उसी टाईम के अन्दर अपनी अपनी स्पीच को खत्म कर दें । बाकी जहां तक उधर का ताल्लुक है, आप ने सरदार गुरनाम सिंह जी से मदद मांगी है । वह आप की मदद कर देंगे ।

उपाध्यक्षा : सरदार गुरनाम सिंह जी, आप ने क्या कहना है ? आप बता दीजिए, फिर मैं अपना फैसला करूंगी । (What has Sardar Gurnam Singh Ji to say, then I will take my decision.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿਘ : ਉਪਰ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਇਧਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਉ । ਜਿਤਨਾ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਉ—ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਉ ।

Chaudhri Khurshed Ahmed (Nuh) : Madam, Deputy Speaker, we have been discussing the Demand for Grant in respect of "Education" for which we have provided near about Rs 20 crores. As other hon. Members have pointed out, I may initially state that this amount for such an important item/Department upon which the future of the Nation depends is absolutely inadequate. This Department should be granted certain percentage of the budget say atleast 25 per cent of the total budget of the State. After all this is the responsibility of the senior generation, who are sitting as Ministers or responsible Members of this House, to provide better opportunities for the younger generation, which is to come up. But what is happening in this Prant ? I am pained to say that most of the things which are being done by the elder generation here for the younger generation are absolutely inadequate.

The main responsibility of the Education Department is to teach the younger people and to train them as better citizens of the State. But this is not being done. There are reasons for it which are not good. Some are minor points which come up before the Members. For example, particular tracts of the State are not taken up by the Government in a responsible manner. I must say that some of the areas have been neglected by all the

[Chaudhri Khurshed Ahmed]

Departments of the Government and kept backward. At least this Department, i.e., the Education Department should not have neglected the areas which are backward. There are areas which are not provided even with the educational facilities, not to speak of industries or other things. What to speak of any other thing, at least this Government should have the courage of taking a bold stand of educating the people of backward areas; of giving them better education ; better schools and giving them preference over the advanced areas. There are some areas which have been singularly neglected in the matter of upgrading of schools because the people there were unable to fulfil certain conditions imposed by the Education Department. The Government should relax some of those conditions in regard to those areas . Rather I would suggest that the Education Department should have a separate formula for the areas which are advanced and which have plenty of schools and there should be another policy, completely distinct, for the backward areas.

Now I come to the higher education. We admit that there are four universities in our State. But with all respect for their autonomous character, I would dare say that the Universities are not working properly As far as the Education Department and its administration is concerned. it isdirectly under the charge of the Government which can be questioned, and the Department can be turned correct. But who is to tell these Universities; who is to correct them when they go on doing what they want. Many a time Government have been informed and the people have taken pains to point it out that corruption has been perpetrated in the Universties by the high officers or the high responsible persons there. If this corruption creeps in the Universities where, as our hon. Friend, Principal Rala Ram said that if you want to root out corruption, you have got to root it out from the institutions, the generation who is to come in the practical field is being trained, then it will be difficult to find a place without corruption. To have a better example, if there is corruption in the head of a University, then I do not think they can talk of any character building in that University. There are definite allegations against a Vice-Chancellor pending with the Government. But the Government has slept over all those allegations. There were memoranda submitted from different quarters at different intervals against that University. But nothing has happened and they have been allowed to do which as head of an institution, responsible officers of the University they should not do . Madam, Deputy Speaker, as I once pointed out, I have written to the Government —I have requested all the authorities concerned, to look into the grievances of some of the inmates of some of the Universities. I would talk about other Universities later ,and would refer to the Kurukshetra University first. As pointed out earlier, I have told this and asked to whosoever is concerned, not only verbally but in writing to look into the affairs of this University. Out of the four Universities established in our State, this is the only University which has been located in the unfortunate region known as Hariana Region. Against the Vice -Chancellor of this University, there have been repeated allegations. But defence has been prepared on political grounds.

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की मार्फत अपने साथी से अर्ज़ करूंगा कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के वाईस-चान्सलर का नाम लेकर उस के बारे में बुरा- भला कहा जाए तो अच्छा नहीं लगता । हमारे हाउस की यह कन्वैन्शन बनी हुई है कि चूंकि यूनिवर्सिटीज़ आटानोमस बाडीज़ है इसलिए उन के वाईस- चान्सलरज़ और दूसरों की बाबत नाम लेकर ज़िक्र

नही किया जाता । इस लिए अगर आप उन की ज़ात की बाबत कुछ कहेंगे तो मुनासिब नहीं होगा ।

Chaudhri Khurshed Ahmed : As far as the demand is concerned, we are giving something to that University also and this House, I think, has the right to question that the money is not squandered and I am maintaining that right. I pointed out time and again and it has been said by other Members also that political figures should not be appointed as Vice-Chancellors. Those who are concerned with politics have been thrust upon the Universities as Vice-Chancellors. Would they create an example as Principal Rala Ram has said, of a person looking at whom people or students working and studying in those institutions can formulate their, ideals ? If corruption is there with the Head of those educational institutions I think the students do not get a better ideal for being better students or being free from corruption. I point out that a politician, a mere politician has been appointed as a Vice-Chancellor of the Kurukshetra Univesity. Of course, he may have educational qualifications but those qualifications cannot be rated with the best qualifications of persons available in that region itself and, if so, why a perons should be imported from an other region and imposed on the other region. Not only that, remaining as the Vice-Chancellor of that University, if he meddles in politics that does not create good atmosphere in that University or in the State but such a practice has been continuing. When, one- Vice-Chancellor can indulge in Politics why should not the members have the right to question his activities and limit his sphere to education itself. I may point out that one of the Vice-Chancellors and to name him, the Vice-Chancellor of the Kurukshetra University, submitted an affidavit No. 262 before the Das Commission. He submitted that affidavit remaining as the Vice-Chancellor......

Deputy Speaker: As Vice-Chancellor of the Univerisity ?

Chaudhri Khurshed Ahmed : He submitted affidavit No. 262 in favour of late Sardar Partap Singh Kairon, remaining as the Vice-Chancellor..........

Pandit Chiranji Lal Shrarma : If it is a fact, he does not deserve to be a Vice-Chancellor of the University.

Chaudhri Khurshed Ahmed : Madam, Deputy Speaker, that affidavit was given against the charge-sheet drafted and submitted by our Hon. Education Mininister under his own name and the same was endorsed by the Memorialists and submitted to the Das Commission. Again, when Mr. Prabodh Chandra became the Education Minister, the same. Vice-Chancellor came to the Secretariat and invited the Education Minister. When our Education Minister entered into the Campus, he, the Vice Chancellor, while receiving him said in the meeting of the University student. and audience that "You , Sir, have always resisted the evil". Of course our Education Minister has resisted evil. But has the Vice Chancellor also done that ?

(Voices : No.).

He has not only filed an affidavit but has started a campaign of inviting all the Ministers to his University on flimsy excuses such as opening ceremonies of buildings which were in use for months, not only for months but for years.

उपाध्यक्षा : अब आप यूनिवर्सिटी को छोड़ दें और अगर और कुछ कहना है तो कह लें घड़ी तो चल रही है । (The hon. Member may now leave cussing the University. He may now say something else as the time at his disposal is very short)

Chaudhri Khurshed Ahmed : Most of the things have already been said about backward areas. I would, Madam, say something about this and then come to Schools.

Not only this, Madam, there is a complaint by the inmates of the University consisting of 16 pages (* * * *) That is not only about his indulgence in politics, but also about the purchase of library books. The racket he has created in the University speaks of the corruption he is interested in continuing in that University. Not only that, there are cases of false Travelling Allowance pending against him. (Voices ; *Shame, Shame*). There are other forms of corruption also, in the appointment of teaching staff, of favouritism, nepotism etc. If these things are not checked because of the guise of the autonomy of the University, we cannot create any example of character and character building. There are serious allegations against him from other quarters also. There is a letter addressed to the Education Minister by some contractor doing some work in that University, a copy of which I received yesterday. Madam, even a private firm having no concern with the Government has to approach the Minister against the corruption he is indulging in and trying to extract something from the people working in the University. If the things that he is doing are allowed to continue, how can we build character of our younger generation. I think you are betraying the trust if you are not checking such sort of things.

In Punjab University also there have been serious complaints of corruption directly involving no less than the Vice-Chancellor himself. Those have been listed in a separate memorandum which has been submitted to the Government and a copy of which has also been sent to us as members of the Vidhan Sabha. I lay this on the Table of the House.** If these allegations are not looked into, Madam, then we are talking all farce. If educational institutions are not free from corruption, we cannot hope for any better training grounds for our younger generation.

Then, Madam, there was a cry against English. How many languages are you determined to kill ? Urdu you have buried. English you are killing. Why can't our children learn more languages when students in other countries can learn several languages at the same time. In our State people are not prepared to learn English and Urdu. Further, in one region they are not prepared to learn even Hindi and in the other even Punjabi. This is a shameful bickering about languages. Teach the students as many languages as they can learn. Young people are not mentally unfit to learn many languages like the old ones. In Russia, a student starts with five languages. Why can't we, in Punjab, teach the students more than one language ?

Madam, there was some criticism about co-education . It is a serious thing. If co-education is to be stopped, have you got alternative arrangements, a separate machinery to teach the younger generation of girls and

*Note Expunged as ordered by the Chair on 11th June, 1965.

**Note Placed in the Library.

the future generation of mothers ? If you can't there is no alteranative but you have got to have co-education. As far as the evils about this type of education are concerned, they have to be remedied. It is no remedy that you stop it or kill it. Co-education has come as a system of education not only in this country but every where in the world. It is bound to stay and it ought to be supported. There are, nodoubt, evils. Those evils are travelling with us in every walk of life.
If you want to clean other walks of life first clean this atmosphere, this corruption, remove this example of corruption. Then only you can clean your boys and girls. You cannot blame them that they are something very very bad. I say, if you want to abolish this system of co-education do you have any other alternative arrangements for their teaching ? There are special classes and courses on sex in different countries. Can you take such a bold step of starting such a thing here ? You may start sex education, if you want to bring about reform in the co-education system. As a system, this system has not been condemned wholesale. This system has got to stay.

Madam, Deputy Speaker, coming to the upgrading of schools—my hon. Friends Shri Roop Lal Mehta and Shri Babu Dayal Sharma belong to my district. I would request that our district is absolutely backward in the matter of education. We have many a time requested that preference should be given to backward areas in the matter of up-grading of schools and I Would once again propose that those areas which have no schools should be given more schools. Madam, sometimes an argument is made that if there are no primary schools what for have a Middle School ? Likewise, if there is no Middle School what for have a High School ? Madam, Deputy Speaker, I would request the Government that for God's sake have as many Primary Schools, as many Middle Schools as those people are demanding. If they have constructed the buildings in the villages; if they have arragned every thing, then those institutions should be up-graded. If they are fit in all respects, they should be given preference. With these words, I thank you, Madam, Deputy Speaker and resume my seat.

उपाध्यक्षा : पेश्तर इसके कि मैं किसी और को काल अपोन करूं चूंकि डीमांड बड़ी ज़रूरी है और बहुत से सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं इस लिये मैं हाउस को एक घंटे के लिये ऐक्स्टैंड करती हूं । (तालियां) मगर मेम्बर साहिबान से दरखास्त करूंगी कि वह कम से कम टाइम में अपनी बात कहने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मेम्बर इस बहस में हिस्सा ले सकें। (The demand being very important a number of Members want to take part in the discussion. I, therefore, extend the sitting by one hour. (Cheers) I would request the Hon, Members to finish their speeches in the minimum time to enable me to accommodate the maximum number of members.)

श्री रूप लाल मेहता (पलवल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज सदन में ऐजूकेशन की डिमांड पर बहस चल रही है । मन्त्री महोदय ने इस विभाग के लिये 20 करोड़ रुपया मांगा है । हम यह देख रहे हैं कि हर साल इस मद पर खर्च करने के लिये हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं । जब से पंजाब में कम्पलसरी ऐजूकेशन नाफ़ज़ हुई है तब से सरकार का खर्च काफी बढ़ रहा है । और 6 साल से लेकर 11 साल की एज ग्रुप के काफी बच्चे स्कूलों मे जा रहे हैं । अगर मुकाबला किया जाए तो पता चलता है कि पार्टीशन से ले कर अब जैनरल और टैक्नीकल ऐजुकेशन

[श्री रूप लाल मेहता]

दोनों पर सरकर का बहुत ज्यादा खर्च होने लगा है । और इस बात की ज़रूरत भी है कि हम अपनी आने वाली जैनरेशन को सही मायने में तालीम दे कर उन को अपने पांव पर खड़ा करें । मगर इस के लिये पैसे की ज़रूरत पड़ती है इस लिये हमें अपने बजट को देखना पड़ता है कि हमारी माली हालत इस बोझ को बरदाश्त करने के काबिल है कि नहीं । किसी दोस्त ने कहा कि इस मद पर खर्च कुल खर्च का 70 फीसदी होना चाहिए और किसी ने कहा कि 25 फीसदी होना चाहिए । हम ने समाजवाद कायम करने का उद्देश्य बनाया है । इस के लिये यह ज़रूरी है कि यहां पर गरीब से गरीब बच्चे को भी तालीम दी जाए अगर कालिज तक नहीं तो कम से कम हायर सैकण्डरी तक तो ज़रूर उस को तालीम दी जानी चाहिए । गरीबों के पास साधन नहीं होते इस लिये उन के बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं । ठीक है आठवीं तक तालीम फ्री की गई है मगर देखना यह है कि इस से कितने बच्चों को गरीबों के बच्चों को फायदा पहुंचा है और आगे तालीम के मैदान में बढ़े है और इस तरह से अच्छे शहरी बने हैं । यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उन को अपने पांव पर खड़ा करे । हम देखते हैं कि अमीरों के बच्चों के लिए पब्लिक स्कूल हैं और भी दूसरी सहूलतें हैं मगर इन से सिर्फ अमीरों के बच्चे ही फायदा उठा सकते हैं सभी नहीं । अगर हमने यहां पर वाकई समाजवादी ढांचा बनाना है तो कालिज त क तालीम मुफत करनी होगी । आप देखें जब बर्मा में समाजवादी सरकार बनी तो उन्होंने बच्चों को मुफत तालीम दी, सरकारी खर्च पर उन को फौरेन मुल्कों में पढ़ने के लिये भेजा । इस तरह से मुल्क तरक्की कर सकते हैं न कि सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिये कुछ सहुलतें दे कर । स्टडी की सुविधाएं आम गरीब किसान और मज़दूर के बच्चों को मिलनी चाहिएं । उन को वज़ीफे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दिए जाने चाहिएं । इस लिये मैं समझता हूं कि यह 20 करोड़ रुपया भी काफी नहीं है ।

जहां तक टीचर्ज़ का सम्बन्ध है हम उन पर अपने बच्चों के बनाने के लिये भरोसा करते हैं । वह हमारी कौम को बनाने वाले हैं । मैं समझता हूं कि टीचर्ज़ को सब से ज़्यादा दर्जा और सुविधाएं मिलनी चाहिएं । आप देखें कि सरकार के दूसरे महकमे वाले जैसे कि पी. डब्ल्यू. डी., पुलिस, सिविल स्पलाइज़, इरीगेशन वगैरह में करप्शन चलती है मगर एक टीचर बेचारा क्या करेगा, उस ने तो अपनी तनखाह से ही रोटी खानी है या ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ट्यूशन कर के मेहनत करेगा । इस लिये इन को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी चाहिए । इन का स्टैंडर्ड ऊंचा तभी हो सकता है जब इन को सुविधाएं मिलेंगी । तब ही उन की क्वालिटी अच्छी होगी । हम देखते हैं कि आप की जे. बी. टी. क्लास में सैकन्ड और थर्ड डिवीज़न वालों को लिया जाता है । मैं समझता हूं कि पहली से लेकर पांचवीं तक लायक से लायक और बी. टी. टीचर्ज़ को लगाया जाना चाहिए क्योंकि इस उम्र में ही बच्चों ने बनना बिगड़ना होता है । जो सैकंड और थर्ड डिवीज़न लोग मास्टर लगाए जाते हैं उन को तो खुद नहीं पता होता कि चाय कहां पैदा होती है, उन को नहीं पता होता कि यह पालमपुर और आसाम में होती है । फिर आप देखें कि एक मैट्रिक पास लड़का सीधा ही अगर क्लर्क बन जाता है तो उस को सौ रुपया माहवार मिल जाता है मगर एक उस्ताद पहले मैट्रिक करे फिर जे. बी. टी. करे तब

भी सौ रुपया ही मिलता है यह ठीक बात नहीं है । साथ ही साथ उन को किसी गांव में जा कर काम करना होता है जहां का जीवन शहर के मुकाबले में कठिनाई से चलता है और कोई तरक्की भी नजर नहीं आती । तो ऐसी हालत में वह बच्चों की पढ़ाई में क्या दिलचस्पी लेगा । इन की हालत को सुधारा जाना चाहिए । इस के साथ ही मैं समझता हूं कि प्राइमरी तालीम को अच्छा बनाने के लिये यह बेहतर होगा कि प्राइमरी स्कूलों में लेडी टीचर्ज़ को लगाया जाए । वह ज़्यादा अच्छी तरह से उन का ख्याल रख सकती हैं, अच्छी बातें सिखा सकती हैं वरना हम ने देखा है कि दसवीं पास कर के मास्टर साहिब आ जाते हैं और सिग्रेट पीते रहते हैं और दूसरी बुरी बातें करते हैं । इसलिये प्राइमरी क्लासिज़ में हाईली क्वालीफाइड यानी बी. टी. या बी. ऐड. लेडी टीचर्ज़ लगाई जाएं । तब ही हमारे देश के बच्चे अच्छे बन सकेंगे और देश तरक्की कर सकेगा ।

फिर स्कूल बिल्डिंग्ज़ हैं । मैं अर्ज़ करता हूं कि हमारा इलाका बहुत पसमांदा है, लोग निहायत गरीब हैं । मगर सरकार ने अपग्रेड करने के लिये शर्तें लगा रखी हैं कि पहले इतने कमरे बनाओ, इतना रुपया दो तब अपग्रेड करेंगे । मैं समझता हूं कि जैसा हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है इन पर से यह सारी शर्तें उड़ा दी जानी चाहिएं वह लोग पिछले दो सौ साल से पसमांदा चले आ रहे हैं, यह शर्तें उन पर ज़ुल्म हैं । मेरे इलाके में कुछ मिडल स्कूल हैं जिन्होंने कमरे भी बना लिये हैं जैसा मन्डकोला है । इस का नींव पत्थर सरदार प्रताप सिंह कैरों ने रखा था दातौली है, अटाली है जिस का नींव पत्थर गवर्नर साहिब ने रखा था इसी तरह बतीर का स्कूल है । इन सब को अपग्रेड किया जाना चाहिए । डी. पी. आई. साहिब ने कहा कि तीन चार कमरे और बनवाओ । मैं अभी जब वहां दौरे पर गया था तो पत्थर रख आया हूं और कमरे बन रहे हैं इन सब को हाई स्कूल बना देना चाहिए । आप देखें कि अटाली स्कूल का फाऊंडेशन स्टोन गवर्नर साहिब ने रखा था लेकिन फिर भी इसे आज तक शुरू नहीं किया गया । मेरे ज़िला गुड़गावां में 4 ऐसे स्कूल हैं जिन के पत्थर महानुभावों ने रखे । दो के माननीय मुख्य मन्त्री और गवर्नर साहिब ने रखे लेकिन आज तक इन स्कूलों में काम शुरू नहीं किया गया । भगोला स्कूल पर पत्थर मैं ने खुद रखा । स्कूल का फन्ड भी दे दिया गया । अभी तक कमरे नहीं बनाए जा सके । इस लिए मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि ज़िला गुड़गावां को ग्रांट दी जाए ताकि स्कूलों को बनाया जा सके ।

जहां तक पलवल के हायर सैकंडरी स्कूल का सम्बन्ध है आज से 34 साल पहले इस को बनाया गया था । और जिन कमरों को अब बनाया जाना था वह आज तक नहीं बन सके । हालत यह है कि कमरे नहीं हैं जहां पर शिक्षा दी जा सके । इस के लिए माकूल ग्रांट दी जानी चाहिए ताकि कमरे बनाए जा सकें । इस पर छात्रों का बोझ भी ज्यादा है । अगर इस के आस पास के चार सकूलों को अपग्रेड कर दिया जाए तो इस मुश्किल को हल किया जा सकता है । यहां से 6 मील दूर भगोला है, 8 मील कोला और 12 या 13 मील अटाली है । इन स्कूलों को अगर अपग्रेड किया जाए तो पलवल के स्कूल की एक समस्या हल हो जाएगी ।

जहां तक छात्रों के लिबास का सम्बन्ध है भड़कीले लिबास पहनने की मनाही कर देनी चाहिए । ए.सी.सी. और एन.सी.सी. को छोड़ कर जिनकी अपनी वरदी है बाकी के लिए

[श्री रूप लाल मेहता]

एक समान यूनीफार्म होनी चाहिए । कोई तो कोट पैंट पहन कर आ जाता है और कोई फटे पुराने कपड़ों में स्कूल में चला जाता है । इस से एक छोटे बड़े का इम्तियाज़ पैदा होता है और इस तरह की बातों का छात्रों के मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है जो उनकी मानसिक उन्नित के राह में बाधा बनता है । इस लिये सरकार को एक आदेश जारी करना चाहिए कि सब लड़के एक ही यूनीफार्म पहन कर आएं । जो बिलकुल सादा हो—कुड़ता पेजामा या निक्कर वट ऐवर इज़ प्रेसक्राईबड ताकि स्कूलों के लड़कों में मुसावात की भावना पैदा हो सके । इस से उनके चलन में बेहतरी होगी और जो समाजवाद में कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा । बच्चों में ऊंच नीच की भावना को दूर किया जाना चाहिये । यूनीफार्म का कपड़ा सादा हो और सस्ता हो ताकि गरीब को भी खरीद करने में कोई दिक्कत न हो । इस के साथ साथ टीचरों के तंग और भड़कीले लिबास की बात है । इस का असर बच्चों के मन पर बहुत बुरा पड़ता है । इन के बारे में भी हदायत होनी चाहिए कि यह बिलकुल सादा लिबास पहनें । ताकि लड़कों की भावनाएं अच्छी हो सकें ।

जहां तक स्कूल खोलने का और अपग्रेड करने का सम्बन्ध है, इस में पसमांदा इलाके को और ऐसे इलाके का जहां पर आए साल फल्डज़ आते हों और जो इलाका तालीम के लिहाज़ से पीछे रह गया हो उनको तरजीह देनी चाहिए । इस लिए जो मिडल स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने शर्तें मुकरर कर दी हैं उन को ऐसे इलाकों के सम्बन्ध में वेव कर देना चाहिए । मेरा इलाका गुड़गावां भी इसी तरह का इलाका है इस में तालीम का फायदा तब ही हो सकता है कि अगर इस तरह की शर्तों को वेव कर दिया जाए ।

जहां तक मैडीकल कालेज और दूसरे टैक्नीकल कालेजों के खोलने का सम्बन्ध है हमारे इलाके को हर बार नज़र अन्दाज़ किया जाता रहा है । इस इलाके में ना तो कोई इस किस्म का कालेज ही खोला गया है और न ही कोई सरकारी लेबारेट्री ही कायम की गई है । हालांकि यह वह इलाका है जो हमेशा अंग्रेज़ के साथ लड़ता रहा । लोगों ने कैद काटी और हर तरह की कुरबानी दी । देश की जंगे आज़ादी में दूसरों से बढ़ कर हिस्सा लिया । 1857 के गदर में इस इलाके के लोगों ने नुमायां काम किया और फांसी के तख्ते पर लटकाए गए । और शहीद हुए । इस इलाके का तो ख्याल सरकार को करना चाहिए ताकि इस इलाके में तालीम आ सके । मैं इस सरकार से आशा रखता हू कि वह इस पसमांदा इलाके की काया को पलटने में मुनासिब कारवाई करेगी जिन स्कूलों का मैं ने ज़िक्र किया है उन्हें अपग्रेड किया जाए ताकि हमारी सरकार इस इलाके की बधाई ले सके ।

जहां तक पलवल के स्कूल का सम्बन्ध है बारिश में बच्चों को धर्मशाला में जाना पड़ता है । फिर किसी को सांप काट जाता है और किसी को और कई किस्म की कठनाइयों का सामना करना पड़ता है । फिर सरकार को लोगों की तरफ से तरह तरह की नुक्ताचीनी का शिकार होना पड़ता है । इस लिए इस स्कूल की बिलडिंग के लिए खास तौर पर रुपया देना चहिए ता कि पसमांदा इलाके के लोगों के दिल में इस सरकार के बारे में विश्वास पैदा हो सके । और यह इलाका तालीम के क्षेत्र में तरक्की कर सके ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर पूर्व) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐजूकेशन की डिमांड पर दो दिन से बहस चल रही है और बहुत से प्वाइंट आफ व्यू इस हाऊस के सामने आए हैं । अधिकतर इस बात पर बहस सैंट्रेलाइज़्ड रही कि टीचरों की तनखाह बढ़नी चाहिये और यूनीवर्सिटीज़ के अन्दर ठीक ढंग से काम हो लेकिन इस के साथ ही ऐजूकेशन की दूसरी साइड भी है । मैं यह समझता हूं कि ऐजूकेशन की जो मद है यह किसी भी स्टेट के लिये एक बहुत ही इम्पार्टेंट और महत्वपूर्ण मद है । देश के अन्दर लोगों को एक अच्छा शहरी बनाने के लिए ऐजूकेशन से बढ़ कर बड़ा काम नहीं हो सकता । लेकिन आज हम क्या देखते हैं आज जो ऐजूकेशन है इसे सही ऐजूकेशन नहीं कहा जा सकता । यह तो एक लिट्रेसी फैलाना है और अक्षर ज्ञान देना मात्र है । यह ऐजूकेशन तो साक्षरता देती है । लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बच्चों को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि वह पढ़ सकें । लेकिन इस के बाद ऐजूकेशन का और भी मकसद है । ऐजूकेशन का मकसद यह है कि वह शहरियों को पर्पज़फुल और यूज़फुल बनाने में कामयाब हो । ऐजूकेशन की कुआलीटेटिव साइड भी है । कुआन्टिटी के साथ कुवालीटेटिव साइड भी है और मैं यह कहूंगा कि हमारी ऐजूकेशन कुआलिटेटिव साइड को बेहतर बनाने में कामयाब नहीं रही है । अंग्रेज़ तो चाहता था कि ऐसा सिस्टम हमारे देश में ऐजूकेशन का हो कि यहां कलर्क पैदा हों सकें और पैट्रियाट और नेशनल माइन्डिड लोग पैदा न हो सकें । इस लिए सारे सिस्टम को इन्हों ने इस ढंग का बना रखा था । डिप्टी स्पीकर साहिबा आज हमारे देश को आज़ाद हुए 17 साल हो गए हैं और हर मन्त्री ने हर पढ़े लिखे आदमी ने और राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक सब ने कहा है कि जो ऐजूकेशन का सिस्टम आज हमारे हां है, यह कलर्क मेकन्ग मशीन है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह वही सिस्टम है जिस के बारे में हमारे शिक्षा मन्त्री जगह जगह जाते हैं स्कूलों में या उद्घाटनों पर तो यही कहते हैं कि यह ऐजूकेशन का सही तरीका नहीं है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो 20 करोड़ रुपये की रक्म खर्च की जा रही है इस में कौन सा तरीका निकाला गया है जिस से ऐजूकेशन का सिस्टम अच्छा हो सके ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ चीज़ें और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । हमें आज़ादी हासिल किये आज 17 साल हो गये हैं मगर अंग्रेज़ी का ज़ोर दिन बदिन बढ़ता जा रहा है । हमारे स्कूलों में यह बात इतनी ज़्यादा फैल गई है कि बच्चे पंजाबी या हिन्दी में बोलना तक पसंद नहीं करते, वह इन ज़बानों में बोलना एक तरह का घटिया पन सा महसूस करते हैं । क्या लड़के और क्या लड़कियां सभी अंगरेज़ी के अन्दर आपको गिट मिट करते नज़र आयेंगे । हमें आज़ादी मिलने के बाद अपने आप को इस देश की सभ्यता के साथ ऐडजस्ट करना चाहिए था । मैं समझता हूं कि अब कोई गैर हकूमत नहीं या कोई ऐसी ऐमरजेंसी नहीं कि जिस के कारण हमारा काम नहीं चल सकता । हमें स्कूलों में ऐसी ऐजूकेशन देनी चाहिये जो कम अज़ कम अपने मुल्क की सभ्यता के अनुकूल हो । ऐजूकेशन का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि अगर हम अंगरेज़ी नहीं बोलेंगे तो हम में किसी तरह का घटियापन आयेगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह एक बड़ी भारी तब्दीली है जो इस देश के ऐजुकेशन के सिसटम में आनी चाहिये । आज़ादी हासल करने के बाद हमारा दूसरा सटैप यही होना चाहिये कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि जिस से वह अपनी मातृभूमि से प्यार करने वाले, इस देश की सभ्यता से प्यार करने वाले और एक अच्छे शहरी बनें । जो ऐजूकेशन उन को आज दी जा रही है यह सही ऐजूकेशन नहीं डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस सिलसिले मे दो चीज़ें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं ।

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

पहली बात तो यह है कि गांव के स्कूलों में वह बच्चे पढ़ते हैं जिन के माता पिता अक्सर खेती का ही काम करते हैं । अगर हम इन बच्चों को बेसिक ऐजूकेशन के साथ ऐसी ऐजूकेशन दें जो ऐगरीकल्चरल ढंग की हो तो यह बच्चे मुल्क के अच्छे शहरी बनने के साथ साथ इस मुल्क के लिये अच्छे असेट भी साबित हो सकते हैं । मगर आज जब बच्चा खेत में अपने मां बाप के लिये रोटी लेकर जाता है जो कि खेत में काम कर रहे होते हैं, तो इस के साथ ही उस के दिमाग में अगर इंगलैंड की हिस्टरी या अलजेबरा घूम रहा हो तो उसका तवाज़न बिगड़ जाता है और वह अपने वातावरण से ज़रूर ही दूर चला जायेगा । हम उसको इस मुल्क के लिये यूज़फुल बनाने की कोशिश नहीं करते बल्कि हम उसकी रुचियां जो एक ऐगरीकलचरल बच्चे के पर्पज़ के लिये चाहिये उस से दूर ले जाते हैं । हम उसे मुल्क के लिये यूज़फुल बनाने की कोशिश नहीं करते । अगर हम ने उन की यूटिलटी बाननी है तो हमें उन बच्चों को ऐसी हायर ऐजूकेशन देनी चाहिए जो हमारी ऐगरीकलचर के लिये फायदामंद हो । जिनके माता पिता शहरों में बसते हैं उन के बच्चों को ऐसी तालीम मिलनी चाहिये जो इंडस्टरी के लिए या दूसरी टैकनीकल डिवैल्पमट के लिये मुफीद हो । आज देश की आबादी बढ़ रही है । सिवाये इसके कि 90 प्रतिशत विद्यार्थियों को आप कलर्क बनाएं और मौजूदा तालीम का कोई लाभ मालूम नहीं देता । आज सभी तालीमयाफता कलर्क बनते जा रहे हैं । बड़ी मुश्किल से 10-15 प्रतिशत लोग होंगे जो इंडस्टरी की तरफ जाते हैं । आज पढ़ने वाले हाथ से काम करना या इंडस्टरी में जाना बिलो-डिगनिटी समझते हैं । एक पढ़ा हुआ लड़का 60 रु० माहवार पर बड़ी खुशी से कलर्क का काम करने को तो तैयार हो जाता है मगर इंडस्टरी में उसे अगर 200 रु० महावार की भी इनकम होती है तो वह जाने के लिये तैयार नहीं होता । कौम की भलाई इसी में है कि समाज की दृष्टि में डिगनिटी आफ लेबर लाई जाए । मैं नहीं समझ सकता कि इस के बगैर कैसे हमारी कौम तरक्की कर सकती है । हमारे जवानों की मुल्क के लिये किस तरह युटिलटी बढ़ाई जा सकती है इस के लिये एक रैडीकल चेंज हमें मौजूदा तालीम के सिसटम में लाना होगा । हमारी सरकार यह आदर्श लेकर चली है कि हम ने मुलक में सोशलिज़्म लाना है मगर आज भी इस देश के अन्दर ऐसे स्कूल हैं जो दो तीन सौ रुपए माहवार तक एक बच्चे पर खर्च करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे स्कूल भी हैं जहां पूरी तरह से बच्चों को किताबें तक नहीं मिलतीं । इस तरह का टियूशनज़ में जो फर्क है यह सोशलिज़म लाने में एक बड़ी भारी रुकावट है । पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा और किसी को इनसान ही नहीं समझता ; वह अगर समझता है तो वह अपने पब्लिक स्कूल के स्टूडैंट्स को ही इनसान मानता है । हमें मुल्क में सोशलिज़म लाने के लिये अपने ऐजूकेशन के सिस्टम में यूनीफारमिटी लानी होगी । पुराने ज़माने में भी शिक्षा में सब को एक साथ बैठा कर दी जाती थी । श्री कृष्ण और सुदामा का प्यार जो उन्होंने दिखाया वह उस शिक्षा का ही नतीजा था जो उन्होंने बचपन में इकट्ठे रह कर एक शिक्षा केंद्र में हासिल की थी । एक तरफ 500 रु० माहवार तक एक बच्चे पर खर्च किया जाता है और दूसरी तरफ उसी क्लास का बच्चा 2 रु० माहवार फीस देता है । यह टाट पर बैठता है और दरखतों के नीचे जाकर पढ़ता है । हम लगातार 17 साल से इस मुल्क के अन्दर सोशलिज़म का नारा लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि यह कलर्क बनाने वाली शिक्षा खत्म होनी चाहिये ।

पब्लिक स्कूल्ज को जो भी ग्रांट्स मिलती हैं, यह बंद होनी चाहिये । प्राईमरी लेवल तक चाहे कोई भी इन्स्टीच्यूशन हो प्राईवेट या सरकारी तालीम होनी चाहिये । जिस तरह की फ्री ऐजुकेशन का हम नारा लगा रहे हैं वह ठीक नहीं । आज प्राईमरी कलासिज के बच्चों पर 6-7 रु० माहवार बतौर इलैकट्रिक चार्जिज़, लाईब्रेरी चार्जिज़ और कई तरह के दूसरे इनडायरेक्ट खर्चे डालते हैं । इस तरह फ्री ऐजुकेशन का नारा लगाना मैं समझता हूं कि अपने आप को धोखा देना है । कहने के लिये फ्री ऐजूकेशन कहते हैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मगर ऐक्चुअल पुज़ीशन कुछ और है ।

टैक्नीकल ऐजूकेशन के लिये भी मैं यहां पर कुछ अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूं । वह यह कि टैक्नीकल ऐजूकेशन के लिये सरकार ने एक कमेटी बनाई थी । मगर इस में कांग्रेसी एम. एल. ए. को ही शामिल करने की कोशिश की जाती रही अमृतसर के आपोज़ीशन के एम. एल. ए. जब तक रिटर्न होकर आते रहे उन को नहीं लिया गया । क्या इस कमेटी में महज़ कांग्रेसी एम. एल. एज़. ही को लिया जाना था और वह कांग्रेसी एम. एल. एज़. भी वह जिन के मुताल्लिक मैं इस हाउस में कुछ कहना नहीं चाहता । क्या यह सरकार का फर्ज़ नहीं है कि अगर वह कोई कमेटी बनाती है तो उसमें देखे कि आया इधर से भी कोई एम. एल. एज़. लिये जा सकते हैं या नहीं । फगवाड़ा का एम. एल. ए. तो लिया गया क्योंकि वह कांग्रेसी था मगर कपूरथले का इस लिए नहीं लिया गया क्योंकि वह अपोज़ीशन में था । अगर ऐजुकेशनल इन्स्टीच्यूशनज़ का यह हाल है तो हम क्या आदर्श कायम कर सकते हैं । इसका मतलब तो यह है कि हमारी करनी और कथनी में फर्क है । मैं समझता हूं कि इन कमेटियों को फौरन रिकांस्टीचूट किया जाना चाहिए । और किसी प्रिंसिपल को सामने रख कर किया जाना चाहिए ।

मैं अब लैंग्वेज़ डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं । जो हिन्दी और पंजाबी डिपार्टमैंट्स बने हुए हैं उनका काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा । क्योंकि इसके डाइरैक्टर्स अलग अलग नहीं हैं । इस लिए काम में गड़बड़ी होती है । अगर हिन्दी और पंजाबी की डिवलैपमैंट रीजनल फारमूले के मुताबिक करनी है तो यह लाज़िमी है कि दोनों भाषाओं के डाइरैक्टर्स अलग अलग हों ।

जहां तक ग्रांट का सवाल है मैं यह जानता हूं कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनको सरकार की तरफ से ग्रांट नहीं मिली । पुंडरी का ए. एस. स्कूल है जो करनाल ज़िले में है लेकिन उसके 11 हज़ार 900 रुपए एरियर्स के पड़े हुए हैं । अब बतलाइए कि वह अपना क्या स्टैंडर्ड मेनटेन करेगा । प्राइमरी स्कूलों में लड़कों को पानी तक पीने को नहीं मिलता । और सिर्फ पानी देने के लिए उनसे दो दो तीन तीन रुपए लिए जाते हैं । यही नहीं जो भी प्राइमरी स्कूल हैं वह इस तरह से बने हुए हैं जैसे कैदखाने होते हैं । अब बतलाइए कि जिस देश के बच्चों को जीवन के प्रारम्भ में यह अनुभव न हो कि वह स्वतन्त्र देश के बच्चे हैं और उनकी देखरेख करने वाली उनकी अपनी आज़ाद सरकार है तो उनकी क्या साइकालोजी बनेगी । जब कि साइकालोजी पांच सात साल की उम्र तक ही बन जाती है ।

मैं एक बात इंजीनियरिंग कालेज के बारे में खास तौर से मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं और वह यह है कि इंजीनियरिंग कोर्स और डिप्लोमा इन प्रोडक्टिव इंजीनियरिंग

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]
कोर्स के लिये क्वालिफिकेशन तो एक ही रखी गई हैं लेकिन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए डिग्री दी जाती है और प्रोडक्टिव इंजीनियरिंग के लिए डिपलोमा ही दिया जाता है । जब यह लड़के दूसरे सूबों में जाएंगे और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर होंगे तो क्या इम्प्रैशन पड़ेगा ? मेरा सुझाव है कि इसको फौरन डिग्री कोर्स के अन्दर तबदील कर देना चाहिए ।

टीचर्ज़ के बारे में जो एश्योरेंस उनको दिलाई गई थीं उस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं भी उन लोगों में से था जो उनकी डिमांड्ज़ को सुनने और उसके बाद, उनसे अपील करने गए थे कि वे अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें । यह बिलकुल जायज़ है कि उनकी तनखाहें बढ़ाई जाएं । जब हम स्वीपर्स के ग्रेड बढ़ा सकते हैं तो क्या वजह है कि टीचर्ज़ के ग्रेड बढ़ाने से गुरेज़ करते हैं । सरकार ने एक बार 1 मई, 1957 को टीचर्ज़ को एक इनक्रीमेंट दिया था लेकिन उसके बाद ए० जी० के यहां से आबजैकशन आया कि इनक्रीमट 14 जुलाई, 1958 से होना चाहिए था । जिसका नतीजा यह हुआ कि अब एक एक टीचर के ज़िम्मे 490 रुपए एरियर्ज़ के निकाल दिए । यह है नतीजा उस रिवीज़न का और इनक्रीमेंट के बढ़ाने का । सरकार को चाहिए तो यह कि गलती को रेगुलेराइज़ करे न कि टीचर्ज़ को पनिश करे ।

मैं सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि टीचर्ज़ देश के बनाने में सब से ऊपर हैं इस लिए उनको हम सारे बैनेफिटस जैसे हाउस-रैंट, सर्विस बैनफिट और पैंशन बैनिफिट दिये जाने चाहिएं । हाउस रैंट का अजीब किस्सा है । सरकार कहती है कि अगर इतने परसैंट टीचर खुद हाउस रैंट दे यानी 10 परसैंट वह खुद दे तो सरकार 5 या 7 परसैंट दे देगी । यह एक मज़ाक किया जा रहा है । इन चीज़ों की तरफ सरकार को गौर करना चाहिए और टीचर्ज़ की हार्डशिप को कम करना चाहिए । जहां तक ऐजूकेशन के बजट का ताल्लुक है मैं कह सकता हूं कि मद्रास में 25 परसैंट खर्च किया जाता है । और वैस्ट बंगाल में 30 परसैंट खर्च किया जाता है लेकिन पंजाब के अन्दर सिर्फ 15 परसेंट ही खर्च होता है । अब आप देख सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा उठ सकता है । इसलिए मैं (घंटी) मिनिस्टर साहब से इस बात की सिफारिश करूंगा कि अगर वह देश की उन्नति चाहते हैं तो ऐजूकेशन पर बजट का कम से कम 25 पीसदी तो ज़रूर खर्च करें ।

सरदार प्रेम सिंह प्रेम(राजपुरा) : डिप्टी स्पीकर साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया । इस डिमांड पर जो बहस हो रही है उससे पता चलता है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रही है । मैं कांग्रेस सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं कि मुल्क के आज़ाद होने के बाद ऐजूकेशन का बहुत फैलाव हुआ है ।

जहां तक ऐजुकेशन के सिसटम का ताल्लुक है उसके बारे में तो स्वयं छागला साहब ने और श्री प्रबोध चन्द्र जी ने कहा है कि यह सिसटम डिफैक्टिव है । मैं यह नहीं कहता कि आजकल जो सिसटम चल रहा है उसे राइट आफ कर दें बल्कि सोचने वाली बात यह है कि अगर डिफैक्टिव है तो सही क्या है । मैं एक बात कह सकता हूं कि हम इस में कलर्क पैदा करते हैं, जो बाद में ऐंप्लायमेंट ऐक्सचेंजिज़ के दरवाज़ों पर जगह जगह घूमते फिरते हैं । गांधी जी ने एक तरीका बताया था । उनका कहना था कि एजूकेशन सेल्फ सफीसैंसी के लिए होनी चाहिए और वह है right type of training in the

art of living हो और जो ज़िन्दगी की नीड्ज़ हैं, जरूरतें हैं वह आदमी पूरी कर सके । इस तरीके की ऐजूकेशन के लिये उन्होंने ने एक बेसिक ऐजूकेशन का तरीका बताया था । गांधी जी के हम जो फालोअर्ज़ हैं, हम ने संजीदगी से उसको टरायल नह दिया । पंजाब में जवाहर लाल जी के कहने पर नई तालीम के स्कूलों में फरीदाबाद और र.जपुर में कुछ बेसिक ऐजूकेशन शुरू की थी। उस ऐजूकेशन में एक तरीका है कि काम भी सब सीखते हैं ताकि रूरल इकानमी में खप जाएं और बाहर जा कर लोग कुछ काम कर के अपना पेट पाल सकें । 1957 में ऐसे 4 बेसिक स्कूलों को which were not in time with the coventional education ? टेक ओवर कर के ,इस स्सिटम को सक्रेप कर दिया और उन को ट्रैडीशनल तरीके पर ले आये । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे मरहूम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रशाद जी ने उस बेसिक इन्सटीच्यूट का नींव पत्थर रखा था । उस पर लाखों रुपया खर्च किया गया था । मतलब यह था कि बेसिक स्कूलों में कुछ स्टूडेंट्स आयें और कुछ नए ढंग से सीखें मगर अब वह वहीं जा कर पढ़ेंगे जिन बैसिक स्कूलों को पजाब गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिये और उन्हें तबदील कर लिय । उस सिस्टम को चलाने के लिये कुछ नहीं किया। कसतूरबा सेवा मन्दिर ने बाद में अपना स्कूल खोल लिया। इस सम्बन्ध में मैं तो यह बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को उसको ट्रायल देना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि जो वहां कस्तूरबा सेवा मन्दिर का स्कूल चलता है जिसमें सैंकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं यहां से पास हो कर उन्होंने पोस्ट बेसिक इन्सटीचूट में जाना है । इस सम्बन्ध में सारे हिन्दुस्तान की एक यूनीवर्सिटी कायम हो गई है यानी जहां जहां भी ऐसे इन्स्टीचूट्स हैं उनकी यूनीवर्सिटी अलहदा होगी । अब उनकी कुछ मांगे हैं। वह चाहते हैं कि वहां उनको सलेबस बना कर भेजा जाए । पंजाब सरकार ने कई सालों से वह बना कर नहीं भेजा था । उन्हों ने खुद अपना सिलेबस बना कर भेजा तो उसको मन्जूर नहीं किया गया । इस के अलावा जो लड़के मेरिट पर फर्स्ट और सैकन्ड आते हैं उनको स्कालरशिप के लिए दाखिल नहीं करते । आज तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया । मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त थोड़ा है। ऐजूकेशन मिनिस्टर साहिब इस बात की तरफ तवज्जोह दें।

एक और बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे एक रिवाज सा है, पेरन्ट्स की विश्ज़ होती हैं चाहे उन का लड़का हो या लड़की हो तो वह चाहते हैं कि वह डाक्टर या इन्जीनियर बने । तो उसी बेसिज़ पर चला जाताहै । इसके लिए उसे साइन्स या मैथेमेटिक्स ले देते हैं, चाहे उस लड़के या लड़की को मैथिमेटिक्स या साइन्स का कुछ आता हो या ना आता हो । मैं तजवीज करना चाहता हूं कि ऐजूकेशन डिपार्टमेंट में एक सैक्शन ऐसा होना चाहिए जो इन्टेलिजैन्स ब्यूरो का काम करे। उसमें शुरू से ही देखा जाए, जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है कि उस बच्चे को किधर की ट्रेनिंग देनी है । अगर उसका बाप उसे इन्जीनियर बनाना चाहता है और वह स्टूडेन्ट 6 साल में मैथेमेटिक्स में पास ही नहीं होता या उसे साइन्स आती ही नहीं तो वह इस तरफ कैसे जाएगा । उस बच्चे को ऐजुकेशन डिपार्टमेंट को ठीक तरह से स्टार्ट देने के लिए राए देनी चाहिए ताकि उसे पता लग सके कि वह किधर ठीक चलेगा ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे यह तसलीम करने में ज़रा भी झिझक नहीं कि हमारे देश का कैक्टर लो हो रहा है, हम कुरप्शन को रूट आऊट नहीं कर सके । इस का कारण यह है कि

[सरदार प्रेम सिंह प्रेम]

हमारा कैक्टर लो है । अगर इस कैक्टर को बनाया नहीं जाएगा तो काम कैसे चलेगा ? अपने आप तो यह बन नहीं सकता । जो आइन्दा जैनरेशन आ रही है अगर उसका कैक्टर नहीं बनाएंगे और उसमें से सैकूलर आउट लुक वाले और देश को प्यार करने वाले बच्चे नहीं निकलेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी । तब इस देश का क्या बनेगा ? इस की तरफ तवज्जोह देनी चाहिए । मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क पर चीन ने हमला किया तो उस वक्त महाराणा प्रताप और गुरू गोविन्द सिंह की वीर रस की बातें याद करवानी पड़ीं । क्यों न पहले से ही बच्चों को गुरू गोविन्द सिंह की ऐसी बातें हमारे डिपार्टमेन्ट की ओर से बताई जाएं । जैसे कि :

देह शिवा मोहे वर एहे शुभ कमर्न ते कबू न डरूं...

मैं ज्यादा लम्बा नहीं जाना चाहता । यह बातें कोर्स में आनी चाहिएं । (प्रशंसा) बच्चे यह देखें और समझें और उन में अपनी जान पर खेलने का हौसला हो । इसी तरह से शिवाजी और दूसरे जितने भी हमारे बड़े बड़े हुए हैं उनकी बातें इन किताबों में आनी चाहिएं । जो अब किताबों का सिस्टम बना रखा है वह यह है कि सारा साल तो वह बच्चे उसको कैम करते रहते हैं और याद करते रहते हैं और फिर जब इम्तहान में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं । इस लिए उन्हें ठोस चीज़ देनी चाहिए । तो यह जो सिलसिला, है यह गलत है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । इन बच्चों की किस्मत का फैसला आखीरी वक्त में यानी सालाना इम्तहान पर ही नहीं बेस करना चाहिए । जो इस से पहले तीन या चार इम्तेहान होते हैं उनके मुताबिक फैसला देना चाहिए । उसके लिए एक तरीका बना कर रखना चाहिए । फर्ज़ करो सलाना इम्तेहान में पास मार्क्स लेते वक्त वह दो या चार नम्बर पीछे रह गया तो देखना चाहिए कि उसने पीछे इम्तिहानों में क्या किया है । उस के मुताबिक फैसला करना चाहिए । इस बात की तरफ डिपार्टमेंट को तवज्जोह देनी चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सब बातें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूं यह सब बातें पालेसी की अर्ज़ कर रहा हूं और पालेसी गवर्नमेंट ने बनानी है, लैजिसलेटर्ज़ ने बनानी है ।

जहां तक ऐजूकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो अफसर लगे हुए हैं उनका ताल्लुक है मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मैं सैटिसफाइड हूं । उन्होंने तो जो पालेसी गवर्नमेंट बनाती है उस को ऐक्सीक्यूट करना है । प्रबोध जी भी कहें कि ऐजूकेशन सिस्टम खराब है और छागला जी ने भी कहा है कि यह सिस्टम खराब है तो इस को तब्दील कौन करेगा । कोई ऐक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाए जो इस की जांच करे । इस सिस्टम से बच्चों का नुक्सान होता है ।

एक बात और जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह है अपग्रेडिंग की । बात छोटी सी भी है और बड़ी भी । मुझे इस बात की खुशी है कि जे. बी. टी. यूनिटस एलाट करने के वक्त भी और अपग्रेडिंग आफ स्कूल्ज़ के वक्त भी हमारे ऐजूकेशन मिनिस्टर साहिब यह जांचने की कोशिश करते हैं और मेम्बरों से भी पूछते हैं कि कौन कौन से स्कूल अपग्रेड किए जाएं । यह बड़ी अच्छी बात है । मैं तारीफ करता हूं लेकिन एक बात, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन से हम आज़ाद हुए हैं उस दिन से अगर फैक्टस और फिगर्ज़ को देखा जाए तो एक खास ट्रेंड का पता चलता है । रोड्ज़ के मामले को देखें । इलैक्ट्रिसिटी के

बारे परसों तरसों फिगर्ज़ आए थे। अमृतसर में 58 फीसदी इलैक्ट्रिफिकेशन हो गई, जालन्धर में उस से कम और लुधयाना में उस से कम। पटियाला में 18 पर सैन्ट और अम्बाला में 12 परसैंट। इसी तरह करनाल में उस से भी कम। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी तो यह ठीक है पूछकर करते हैं मगर जो पिछली इतने फर्क वाली बात हुई है उस की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। 1957 से ऐसा ही चला आ रहा है। मैंने पहले भी कहा है और काफी अरसे से कहता आ रहा हूं कि हमारे राजपुरा तहसील में उगानी में जो स्कूल है उसे हाई स्कूल बनाया जाए लेकिन कोई नहीं पूछता है। मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह की यह जो चीज़ चली आ रही थी उसकी तरफ भी तवज्जुह होनी चाहिए

"गुल फैंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी,
ए खाना बर अंदाज़ कुछ तो इधर भी"

मेरी अर्ज़ है कि जब किसी अगली चीज़ का फैसला करना होता है तो जो चीज़ पीछे हुई हुई है उसकी तरफ ध्यान पहले दे लेना चाहिए। आप देखते है कि यहां रोज़ाना स्कूल के बारे में डैपूटेशनों पर डैपूटेशन आते हैं और कहते हैं कि हमारा स्कूल बनाया जाए हमारा स्कूल अपग्रेड किया जाए। मुझे खुशी है कि आज हमारे लोगों में तालीम के लिए इतनी कांशसनैस आ गई है कि खुद लाखों रुपए इकट्ठे करके बिलडिंगज़ बनाते हैं। हमारे नेता जवाहर लाल जी तो कहते थे कि तालीम दो चाहे दरख्तों के नीचे ही बच्चों को पढ़ाओ। मेरे एक गहरे दोस्त ने तो इस बात से इत्तफाक नहीं किया। मैं समझता हूं कि बिलडिंगज़ का अब कोई सवाल नहीं है क्यों कि हर एक जगह गांव वालों ने बिलडिंगें तैयार कर ली हैं और देने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के पास पैसे की तंगी है तो कोई वजह नहीं कि धर्मशालाओं या दूसरी जगहों में न चलते रहें। उनको तो स्कूल चाहिए क्योंकि वह अब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कोई ज़माना था जब हम लोगों के पीछे फिरते थे और उनकी मिन्नत समाजत करते थे कि अपने बच्चे पढ़ाओ लेकिन आज यह हालत है कि लोग बिलडिंगें तैयार करके सरकार के पीछे फिरते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल दो तो हम लाचारी का इज़हार करते हैं। मैं कहता हूं—

"पिला दे ओक से साकी गर हम से नफरत है
प्याला नहीं देता न दे शराब तो दे"

उपाध्यक्षा : प्रेम जी शराब की बातें न करें कोई और अच्छी बात करें। Kindly wind up now. (Let the hon. Member turn his attention to some topic better than drinking.) Kindly wind up now.

सरदार प्रेम सिंह प्रेम : मैं तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, बहुत कम बोलने वाला हूं, अगर नहीं मानते तो एक बात कह कर बैठ जाता हूं, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि राजपुरा में एक सरदार पटेल मैमोरियल कालिज की बिलडिंग के लिए कोई दो लाख रुपया खर्च किया गया और इस दो लाख में से शायद 1½ लाख रुपया सैंटर से रीहैबलीटेशन मिनिस्टरी ने दिया। पिछली हकूमत के चीफ मिनिस्टर साहिब वहां जब तशरीफ ले गए थे तो उन्होंने बिलडिंग को देख कर वायदा भी किया था कि कुछ करेंगे लकिन यहां आ कर कुछ नहीं किया। मैं अर्ज़ करता हूं कि वहां 30-35 हज़ार के नज़दीक आबादी है और पटेल साहिब जैसे आदमी के नाम पर वहां कालिज की बिलडिंग दो लाख की लागत से बनी हुई है। मैं अर्ज़ करूंगा कि उस कालिज को ज़रूर

[सरदार प्रेम सिंह प्रेम]

जल्दी चलाएं (घंटी) कम से कम चौथे प्लान में उसे ज़रूर शामिल करें । मैं ने अभी कुछ ज़रूरी बातें कहनी थीं लेकिन आपने घंटी बजानी शुरू कर दी है इस लिए मैं खड़ा न रह कर बैठ जाता हूं ।

चौधरी रण सिंह (राडौर, ऐस. सी.) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे समय दिया है । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ चन्द मिनट में अपने हलके की बात कह कर बैठ जाऊंगा । इस में शक़ नहीं है कि आज़ादी के बाद भारत में और खास तौर पर पंजाब में महकमा तालीम ने बहुत तरक्की की है । जगह जगह स्कूल खुल रहे हैं और छोटे स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं । यह बात भी काबिले तारीफ है कि सरकार ने जनता में तालीम का बहुत प्रचार किया है और दिहातों के लोग भी अब बहुत ऐजूकेशन माइंडड हो गए हैं । चाहे छोटे गांव हैं या बड़े उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके बिलडिंगें बना ली हैं और स्कूलों की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी सारी मांगें पूरी नहीं करती है और कहती है फंड्ज़ नहीं हैं इस लिए अपग्रेड नहीं कर सकते । इस से ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है कि लोग खुद अपने पल्ले से बिलडिंगें बना कर भी जब कहते हैं कि हमें अपने बच्चे पढ़ाने के लिए स्कूल दो तो सरकार न दे । एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि हम तालीम न होने की वजह से ही बैकवर्ड और गुलाम रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जब लोग कहते हैं कि हमें तालीम दो तो हम कहते हैं पैसे नहीं है । यह एक धब्बा है सरकार के ऊपर और यह तब ही दूर होगा जब सरकार लोगों की इस मांग को पूरा करेगी । मैं वज़ीर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि जहां जहां लोग स्कूल मांगते हैं खास तौर पर उन बैकवर्ड इलाकों में जहां पहले स्कूल कम हैं वहां फी हलका एक स्कूल वाली बात न करें बल्कि जितने स्कूल वहां लोग मांगते हैं उतने दें । हमारे वज़ीरे तालीम ने जब से यह महकमा अपने हाथ में लिया है उन्होंने जो खामियां उस में देखीं उन सब को दूर करने का यत्न किया है । उन्होंने बगैर यह देखे कि कौन कांग्रेसी है और कौन आपोज़ीशन का है सब मैम्बरान को चिट्ठी लिखी कि अपने अपने हलकों में जहां स्कूलों की बहुत ज़रूरत है लिख कर उन्हें भेजो । सारे मैम्बरान ने उनके इस कदम की सराहना की है और मैं भी उनको मुबारिकबाद पेश करता हूं जो उन्होंने ऐसा शानदार कदम उठाया है । आज तक किसी वज़ीर ने मैम्बरों को चिट्ठी नहीं लिखी कि अपने हलके की मांग भेजो । उन्होंने ही पहली दफा यह काबिले तारीफ काम किया है । मैं अब यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि वैसे तो पंजाब में कई इलाके पिछड़े हुए होंगे लेकिन करनाल का ज़िला बहुत ही पिछड़ा हुआ है । कई ज़िलों में तो यह हाल है कि लड़कों के लिए अलहदा सरकारी कालिज है और लड़कियों के लिए अलैहदा है जो गवर्नमेंट चला रही है लेकिन ज़िला करनाल में लड़कियों की तो बात ही कहां लड़कों की तालीम के लिए भी सरकार ने इन्तज़ाम नहीं किया है, वहां बिल्कुल कोई सरकारी कालेज नहीं है । यह ठीक है कि वहां एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है लेकिन वह तो स्टेट लैवल और आल इन्डिया लैवल की चीज़ है । कैथल के लोग कई साल से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि वहां का कालिज पानी में डूबा रहता है उसे अपने हाथ में सरकार ले कर चलाए लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है । उन्होंने तीन लाख रुपये की बिलडिंग खड़ी की हुई है जिसे वह सरकार को देने के लिए तयार हैं मगर सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है । मैं ने सुना है कि पंजाबी

रिजन में सरकार ने सठियाला का कालिज ले लिया है, take over कर लिया है लेकिन हिन्दी रिजन वालों की मांग को नहीं माना जाता । इस तरफ ध्यान दिया जाए । लोगों ने कई स्कूल देने के लिए offer किया हुआ है लेकिन सरकार ने कोई कदम इस तरफ नहीं उठाया है । हमारे यहां बाबैन (Babain) का स्कूल है । पंचायत की माली हालत कमज़ोर है इस लिए वह स्कूल चला नहीं सकती है । पंचायत ने भी और ब्लाक समिति ने भी लिख कर भेजा है और resolution पास किए हैं कि हम स्कूल देने के लिए तैयार हैं लेकिन उसे नहीं लिया गया है । सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि अब लोगों में अपने बच्चे पढ़ाने का बहुत शौक है । लोगों ने गरीबी के बावजूद लाखों रुपए इकट्ठे करके आलीशान इमारतें बनाई हैं और स्कूल चाहते हैं लेकिन सरकार दे नहीं रही है । वज़ीर साहिब को पता है कि कितने डैपूटेशन उनको इस काम के लिए रोज़ मिलने आते हैं । मेरे साथ हर दूसरे या तीसरे दिन एक डैपूटेशन इस मतलब के लिए उनके पास आता है । उनकी और कोई मांग नहीं होती है । वह स्कूल ही मांगते हैं । उन की ऐसी मांगों को पूरा करना चाहिए । यहां पर कई मेम्बरों ने, जिन में सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों का नाम लेना विशेष कर ज़रूरी समझता हूं, कहा कि विदेशों में मास्टरों की तंखाहें यहां की निस्बत बहुत ही ज़्यादा हैं । जब मास्टरों का इतनी थोड़ी तनखाह से गुज़ारा नहीं हो सकता है तो मैं समझता हूं कि वह पढ़ाई की तरफ कैसे ध्यान दे सकते हैं ।उन के सामने तो महंगाई की समस्या विद्यमान है । इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इन के ग्रेड्ज़ को बढ़ाए ताकि वह इस बेचैनी से बचकर देश के निर्माण में योगदान दे सकें। पार्टीशन के कुछ ही पहले की बात है कि हम स्कूलों में पढ़ा करते थे और हमारे गुरू हमें बहुत प्यार से और काफी देर तक पढ़ाया करते थे । हमें उस वक्त ट्यूशन रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी और न मास्टर्ज़ ही इस लालसा में पड़े हुए थे कि ट्यूशनों से रुपया कमाया जाए । लेकिन आजकल के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं । आजकल मास्टर्ज़ अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं । आजकल कोई भी बच्चा पहली श्रेणी में प्रवेश होता है तो उस के लिए ट्यूशन की मांग पहले हो जाती है और उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए मास्टर उस के घर आता है । और बहुत से मास्टर लोग ट्यूशन के लालची हो गए हैं । लेकिन हमारे समय में हम मास्टर के घर जाया करते थे और वह बिना ट्यूशन फी लिए हमें बड़ी खुशी से पढ़ाने में फख्र समझते थे लेकिन आजकल तो ट्यूशन का ज़माना आ गया है । अगर बच्चे को पहली जमात में ट्यूशन रख दी जाए तो क्या उस का करैक्टर ऊंचा होगा ? क्या ऐजूकेशन मिनिस्टर साहिब बतला सकते हैं कि उन पर मास्टरों के चरित्र का क्या प्रभाव पड़ेगा ? मैं समझता हूं कि इस तरह से देश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी सरकार ने ऐम. ए. पास किए हुए टीचरों में भी डिस्क्रीमीनेशन डाल दी है । सरकार ने फस्ट, सैकंड क्लास तथा थर्ड क्लास ऐम. ए पास मास्टरों के ग्रेड अलग अलग कर दिए हैं । मैं समझता हूं कि यह सरकार का सराहनीय कदम नहीं है । कई कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि ऐम. ए फस्ट क्लास टीचर्ज़ लड़कों को अच्छा नहीं पढ़ा सकते और ऐम. ए. थर्ड क्लास मास्टर अच्छा पढ़ा सकता है । यह तो पढ़ाने का ढंग है । इस में Division के बिना पर ग्रेडज़ फिक्स नहीं करने चाहिएं थे । सरकार फस्ट क्लास एम. ऐ. के लिए 210 रुपए, सैकंड क्लास के लिए 180 रुपए और थर्ड क्लास के लिए इस से

[चौधरी रण सिंह]

कम रुपए देती है । वह एक जैसा क्लासों में पढ़ाते हैं लेकिन तंखाह में डिस्पैरिटी रखी गई है । मैं समझता हूं कि इस की वजह से उन के दिलों में बर्निंग है । यह कोई सराहनीय काम नहीं है । सरकार को इस बारे में दोबरा सोचना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा खादर का इलाका है । हर गांव में बहुत से नाले हैं । एक गांव से दूसरे गांव में जाना हो तो उन नालों को पार करके जाना पड़ता है ।. बच्चे एक गांव से दूर गांव में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकते हैं । चाहे वह प्राइमरी के बच्चे हों या हायर स्कूलों के बच्चे हों उन को वहां पर जाना बहुत ही कठिन है । यहां पर मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि हर एक कांस्टीचुएंसी में एक ही स्कूल दिया जाएगा । इस से मुझे निराशा ही हुई है । मेरे हल्के में 300 गांव हैं और दलदल का इलाका है । साल के 4 महीने पानी ही पानी रहता है और वहां पर झील की शक्ल इख्तियार करता है । अगर वहां पर भी एक स्कूल दिया जाए और जिस हलके में 40, 50 गांव हों वहां पर भी एक स्कूल दिया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है हमारा इलाका तो पहले ही शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है । इस सूरत में इस की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । मन्त्री महोदय ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि जिन इलाकों में शिक्षा की कमी रही है उन की ओर ध्यान दिया जाएगा और स्कूल देते हुए इस बात का ध्यान रखा जाएगा । (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक और बात कह कर अपनी स्पीच वाइंड अप कर दूंगा । करनाल जिले में चाहे वह पानीपत करनाल या कैथल का इलाका है, वहां पर कोई कालिज नहीं है । इस लिए वहां पर कालिज खोला जाए ताकि वहां के स्टूडैंट्स को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सके । (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप का धन्यवाद करके अपनी सीट सम्भालता हूं ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਜਗਰਾਓਂ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਦ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਮਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦੇਹਾਤ ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਕੜੇ ਭੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਜਨਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਤੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁਕੇ ਸਨ । ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਜ਼ੱਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਓਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋ-ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਬਦਲੇਗਾ

ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ । ਅਜ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜਾਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਘਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲਖ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੇਤੂ ਕਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭੀ ਸੁਭਾਗ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏ ਹਨ ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਣ । ਮੈਂ 4-5 ਗਲਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਸਨਮਤੀ ਜਨਤਾ ਕਾਲਿਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸਨਮਤੀ ਜਨਤਾ ਕਾਲਜ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਲਜ ਹਿੰਦੂ, ਸਿਖਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤੇ 6 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 175 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ 25,000 ਰੁਪਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਟੀਕਲੀ ਐਨਾ ਗੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਗੇਗੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿਤਾ । ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਜਗਰਾਓਂ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਨਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 27,000 ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਜ਼ ਹਨ । ਮੈਂ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲਿਜ ਬਣ ਜਾਏ ਪਰ ਯਾਦ ਰਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜਿਸ ਕਾਲਿਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਇਟ ਨਾਲ ਇਟ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਬਚਨ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਲਿਜ ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਦਿਤਾ । ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਜੋਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਣ ਵੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਗਲ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸੋ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰ ਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਜਿਸ ਕਾਲਿਜ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ । ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕੋ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਪਰ ਉਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਪੜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦ ਇਹ ਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਰੀਟਰਨ ਕਰਨਗੇ ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਨ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਦੀ ਬਟਾਲੇ, ਕਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਦੀ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਚਲੇ ਗਏ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨਾ ਜਾਓ । ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਇਤਲਾਹ ਦਿਤਿਆਂ ਪਿਡਾਂ ਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾ ਵਿਚ ਜਾਉ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ । ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੀ ਹਨ, ਚੀਨ ਵਲ ਵੇਖੋ, ਬਰਮਾ ਵਲ ਵੇਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਹੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਏਟ ਵਿਚ ਜਾਉ, ਕਿਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਰਖੀ ਜਾਉ ਸਭ ਹਿੰਦੂ, ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਕੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਧੌੜੀ ਲਾਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਉ । ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਿਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਜਿਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕਰੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਹਨ । ਮੈਂ ਮੁਦਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਖ਼ੁਦ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਬੋਲੀਆਂ ਕਾਂਸਟੀਚਊਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰਗ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਹਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਿਨ ਅਤੇ ਹਿਂਦੀ ਰਿਜਿਨ । ਫਿਰ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਠੋਸ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ—ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਿਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਿਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ । ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਥੇ ਇਕ ਮਨੱਜ਼ਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦ੍ਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਮਤ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਕ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਕ ਮਨਜ਼ਮ ਸਾਜਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਾਲੂ ਰਾਮ : On a point of order Madam ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਲੈ ਆਏ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

(ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਮਿਨਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਖ਼ੁਦ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ-ਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਇਨਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ । ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ : ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ—

Grants from State Government

1962-63	Rs 4,00,000
1963-64	Rs 22,50,000 (Rs 7,00,000 for maintenance and Rs 15,50,000 for construction and cost of land).
1964-65	Rs 20,00,000 (Rs 9,95,425.33 P. for maintenance and Rs 10,04,574.67 for construction).
Estimated grant from State Government during 1964-65	Rs 33,28,880
Grant received	Rs 20,00,000
Balance to be received	Rs 13,28,880 (A great deal of correspondence has passed between the University and the State Government to release the balance Grant).

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅਗੇ ਫਿਗਰਜ਼ ਵੇਖੋ—

Budget for 1965-66

Total budgeted amount	..	Rs	81,53,230
(a) Maintenance expenditure	..	Rs	29,93,796
Income (including U.G.C. Grants)	..	Rs	8,50,977
Deficit	..	Rs	21,42,819
(b) Construction expenditure	..	Rs	51,49,534
Grants from U.G.C.	..	Rs	26,761,416
Deficit	..	Rs	24,75,118
Total Deficit	..	Rs	46,17,937

ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜੇ ਤਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ। ਸੈਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫਿਗਰਜ਼ ਹਨ—

Total cess released	..	Rs	1,45,85,626
Share of Punjabi University	..	Rs	72,92,813

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ..... ..ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 75,00,000 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਟਾਂਸ ਕੋਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਸਟਾਂਸ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਿਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖੁਦ ਜਾਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਅਰਜ਼ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਤਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਥੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਹਲੜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਗੜੇ ਪਏ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਜਾਉ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਾਰੇਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟਸ ਵਾਂਗ ਬੀਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਹੇਵੀਅਰ ਬੜਾ ਪੋਲਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਤੇ ਪੁਜ ਕੇ ਹੀ ਚੁਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬੜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੇਅਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰੋ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਜਗਾਹ ਉਤੇ ਬਣਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਆਦਮੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣ, 'ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਥਲੇ ਮਮ ਹੈ, ਕਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਲਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਨੂੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਫਾਰੈਸਟ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਟਰ ਢਿਲੋਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਉ ਉਥੇ ਵੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਲਗਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਸਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਦ ਇਥੇ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਉਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਿਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਘੰਟੀ) ਇਸ ਲਈ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੁਲਰ ਤੁਸਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਉ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦਿਲਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੀ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿਓ। (ਘੰਟੀ) ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ : On a point of order. ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਕਟ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ.. .. ..

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੈਠ ਜਾਉ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ (The hon. Member should please resume his seat. He will also get time to speak.)

श्रीमती ओम प्रभा जैन (कैथल) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज ऐजुकेशन पर बहस चल रही है जिस के तहत बीस करोड़ से भी ऊपर की मांग रखी गई है जो कि टोटल बजट का तकरीबन 16 परसैंट बनता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप को याद दिलाना चाहती

[श्रीमती ओम प्रभा जैन]

हूं कि सन् 1957-58 और 1958-59 में जो ऐजूकेशन के बजट पेश किए गए थे उन में इस मद के लिए टोटल प्रोवीज़न का 21 परसेंट का प्रोविज़न था और अब जब कि हमारे ऊपर ऐजूकेशन का बर्डन बढ़ रहा है बजाय इस के कि इस रकम को बढ़ाया जाता, इस परसेंटेज को कम कर दिया गया है । मैं आप के द्वारा यह भी कहना चाहती हूं कि दूसरे सूबों की निस्बत पंजाब में ऐजूकेशन पर जो खर्च होता है उसकी परसेंटेज उन से कहीं कम है और यह बात मैं आज और भी ज्यादा ज़ोर के साथ इस लिए कहना चाहती हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब आज देहली गए हुए हैं और वह सैंटर की फोर्थ फाइनैंस कमिशन के सामने इस बात का ज़ोर देने वाले हैं कि पंजाब की कुछ स्पैशल प्राब्लम्ज़ हैं । पंजाब की प्राब्लम्ज़ की बाबत जो मैमोरैंडम पेश किया गया है उस में खास तौर पर इस बात का भी ज़िक्र किया गया है कि ऐजूकेशन की मद के लिए हमें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और सैंटर से जितना हम डिज़र्व करते हैं उस से भी ज्यादा पैसा हमें ऐजूकेशन के लिए मिलना चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, ठीक है कि ऐजूकेशन की प्राब्लम्ज़ हिन्दुस्तान में सब जगह पर हैं लेकिन पंजाब के कुछ खास हालात हैं जिनका मैं ज़िक्र करना चाहती हूं । आप जानती हैं कि इस छोटे से सूबे के अन्दर इस वक्त चार यूनिवर्सिटीज़ फंकशन कर रही हैं । इन का बर्डन भी पंजाब के ऊपर है । हमारी स्टेट ने हायर सैकंडरी ऐजूकेशन को भी अपनाया है । हर साल सैंकड़ों स्कूलों की मांग बढ़ रही है । हर साल स्कूलों को अपग्रेड करने का काम बढ़ रहा है । इस के लिए भी रुपया की ज़रूरत है । हाई स्कूलों को हायर सैकंडरी स्कूलों में कन्वर्ट करने के लिए भी रुपए की ज़रूरत है । हम ने प्राइमरी ऐजूकेशन को फ्री और कम्पलसरी किया है । दस की बजाए 11 साल तक की उम्र के बच्चों को कम्पलसरी ऐजूकेशन देने का ज़िम्मा उठाया है । इस पर भी ज्यादा खर्चा होना है । सन् 1957 में लोकल बाडीज़ के स्कूलों को प्रोविंशियलाईज़ किया, उसके कारण भी स्टेट गवर्नमेंट पर खर्च का बर्डन बढ़ा । गर्जेकि पंजाब ने ऐजुकेशन के सिलसिले में ऐसी स्कीमों को अपनाया जिस के लिए पंजाब गवर्नमेंट को दाद दी जानी चाहिए । यहां पर माडल स्कूल खोले गए हैं, सैनिक स्कूलों का प्रबन्ध हो रहा है । ये सभी बातें ऐसी हैं जिन की वजह से पंजाब को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए । इस लिए इस डिमांड पर बोलते हुए, डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आप के द्वारा सैंट्रल गवर्नमेंट पर और फोर्थ फाइनैंस कमिशन पर इस बात का ज़ोर देना चाहती हूं कि फोर्थ प्लैन के लिए पंजाब को ऐजूकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दें ताकि हमारे सामने जो जो प्राबलमज़ हैं हम उन को अच्छी तरह से फेस कर सकें ।

उपाध्यक्षा : आप सैंट्रल गवर्नमैन्ट की बात न कीजिए, अपनी गवर्नमैन्ट को ही जो कहना है कह लीजिए। (Let the hon. lady Member refer to her own State Government instead of referring to the Central Government)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : चूंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब की यहां सैंट्रल गवर्नमैन्ट के साथ बातचीत हो रही है इस लिये मैं पंजाब गवर्नमैन्ट के हाथ मज़बूत करना चाहती हूं और इस सदन की आवाज़ को आप के द्वारा उन तक पहुंचाना चाहती हूं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर यूनिवर्सिटीज़ की बाबत बहुत कुछ कहा गया । हम जानते हैं कि पार्टीशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी यहां पर मेकिंग की स्टेज पर थी। इस के ऊपर भी हमारी बहुत ज़िम्मेदारी थी। ठीक है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ने भी पैसा दिया। (विघ्न) इस में कोई शुबा नहीं कि पंजाब गवर्नमैन्ट के ऊपर भी इसका बोझा है। लेकिन जहां पर यह यूनिवर्सिटी अभी बन ही रही थी, वहां दो यूनिवर्सिटीज़ किन्हीं हालात की वजह से और बनाई गईं । सरदार लछमन सिंह जी अगर मुझे माफ करें तो मैं यह कहूंगी कि मैं आनैस्टली फील करती हूं कि पंजाबी यूनिवर्सिटी किन्हीं मैरिट्स पर नहीं बल्कि पुलिटिकल रीज़न्ज़ की वजह से कायम हुई । पंजाबी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज़ अभी मेकिंग की स्टेज पर चल रही हैं। उन पर सरकार ने अब तक करोड़ों रुपया खर्च किया है। इस साल के बजट में भी चालीस लाख रुपया पंजाबी यूनिवर्सिटी और बीस लाख रुपया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिये रखा गया है। कुछ दिन हुए, कुछ दिन से भी ज्यादा समय हो गया, कोई दो साल पहले एक हाई पावर्ड कमेटी इन यूनिवर्सिटियों के लिये बनाई गई थी। यह इस चीज़ पर गौर करने के लिये बनाई गई थी कि इन यूनिवर्सिटियों के फंक्शंज़ क्या होंगे, इनके work का कोई demarcation होना चाहिये या नहीं, उनका स्फियर क्या होगा। कौन कौन सी चेयर्ज़ वह बनायेंगी, वह किस किस चीज़ को स्पैशियलाइज़ करेंगी, वगैरा वगैरा। वह हाई पावर्ड कमेटी इस लिये बनाई गई थी ताकि मौजूदा यूनिवर्सिटी में उन की ओवर-लैपिंग न हो। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक कोई बात अमल में नहीं लाई गई। अभी तक इस बात का फैसला नहीं हो सका कि पंजाबी यूनिवर्सिटी में किस किस सबजैक्ट में लोग स्पैशियलाईज़ करेंगे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्फियर क्या होगा। पंजाबी यूनिवर्सिटी में पटियाला के आठ दस लोकल कालेजिज़ को लिया गया है। उसके बाद किस तरीके से पंजाबी यूनिवर्सिटी को चलाया जायेगा, किस किस subject and language को स्पैशियल स्थान दिया जायेगा, इन बातों का फैसला नहीं किया गया। मैं चाहूंगी कि जो कोई हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी उसे दोबारा इस बारे में गौर करना चाहिये क्योंकि इस वक्त पोज़ीशन यह है कि तीनों यूनिवर्सिटियों को यह खदशा बना रहता है कि उन के पास क्या काम रहना है और क्या उन से ले लिया जाना है। पंजाब यूनिवर्सिटी को खतरा है कि उस से और क्या काम लिया जाना है, इसी तरह से पंजाबी यूनिवर्सिटी को खदशा बना हुआ है और यही हालत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की है। यह कमेटी इन तीनों के फंक्शन्ज़ को बाकायदा तौर पर डीमार्केट करे और इन को पता लग जाना चाहिये कि किस किस सबजैक्ट में उन्होंने स्पैशियलाईज़ करना है। अगर इस तरह कर दिया जाये तो इस का नतीजा यह होगा कि किसी में अच्छी लिट्रेचर प्रोड्यूस होगी, किसी में आर्टस को तरक्की मिलेगी और किसी में सायंस सबजैक्टस को तरक्की मिलेगी। एक university foreign languages की teaching को तरक्की दे सकती है, दूसरी ideology, ancient literature and history पर research कर सकती है। तीसरी university Oxford or Cambridge University के माडल पर अच्छी और standard books

[श्रीमती ओम प्रभा जैन]

publishing work ले सकती है। इन चीजों को मद्देनज़र रख कर उन को बता दिया जाये और वह उन को मद्देनजर रख कर अपने कालेज खोलें। अगर इस तरह कर दिया जाये तो मैं समझती हूं कि इस तरह से पंजाब की बहुत बड़ी सर्विस हो सकेगी।

पिछले 9 या 10 महीनों में जो कुछ अहम फैसले इस गवर्नमैन्ट ने किये हैं मैं उन के लिये इन को बधाई देती हूं। एक डिसीज़न तो यह किया गया जो बड़ा अहम फैसला है कि ऐजूकेशन में आल इन्डिया सरविसिज़ का सिलसिला लाया जाये। इस बारे में सैंट्रल गवर्नमैन्ट भी मान गई है और वह ऐजूकेशन की सर्विसिज़ का एक आल इण्डिया पैटर्न कायम करेगी। मैं समझती हूं कि इस से नैशनल इन्टैग्रेशन को बल मिलेगा और यहां हमारे देश में जो लिंगुइस्टिक or provincial बातें चलती हैं उन को सोचने और समझने में भी मदद मिलेगी। मैं समझती हूं कि यह एक बड़ा अच्छा फैसला है। इस के इलावा एक और फैसला पंजाब गवर्नमैन्ट ने किया है जो बड़ा अहम है। इस बारे में सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट अभी सोच रही है। इस फैसले के मुताबिक पंजाब गवर्नमैन्ट ने सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट को यह सुझाव दिया है कि जो हायर ऐजूकेशन है वह कन्करैंट लिस्ट में ले ली जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती हैं कि हम ने इण्डीपैन्डैन्स के बाद अपनी कनस्टीच्यूशन में प्रोवाइड किया हुआ है कि हम ने बच्चों को फ्री और कम्पलसरी ऐजूकेशन देनी है। तो इस का मतलब यह हो गया कि हम ने प्राइमरी ऐजूकेशन, हायर सैकन्डरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजूकेशन सबका इन्तजाम करना है। इस तरह से प्रान्त की सरकार का काम इतना वसीह हो गया है कि इस सारे काम को निभाना कोई आसान काम नहीं रहा। इस लिये पंजाब सरकार ने सैन्टर की सरकार को यह प्रोपोज़ किया है कि जो हायर एजूकेशन है वह कन्करैन्ट लिस्ट में ले लिया जाए जिस का मतलब यह है कि हायर एजूकेशन का जितना काम है वह सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट के पास भी कुछ हद तक चला जायेगा। यह ठीक है कि इस वक्त प्रान्त की सरकार कालेज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ पूरी पूरी तवज्जोह नहीं दे सकती। College teachers की pay का सवाल हमेशा हमारे सामने रहता है। इस लिये मैं समझती हूं कि इस में कोई बुराई नहीं है अगर यह सबजैक्ट कन्करैन्ट लिस्ट में आ जाए। बल्कि मैं तो समझती हूं कि इस से कई फायदे होंगे। एक तो यह एजूकेशन आल इण्डिया बेसिज़ पर दी जाने लगेगी जिस से हमारी नैशनल इन्टैग्रेशन में मदद मिलेगी। दूसरा इस से यह फायदा होगा कि आल इण्डिया फेम के आदमी और कई फारेन कंट्रीज से आदमी आ कर लैक्चर दिया करेंगे और एजुकेशन का स्कोप बड़ा वाइड हो जायेगा। साथ ही foreign experts की भी मदद मिलेगी। तीसरा फायदा इसका यह होगा कि हमारी स्टेट गवर्नमैन्ट से यह एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी हट जाने से यह प्रायमरी और हायर सैकंडरी एजूकेशन की तरफ और ज्यादा ध्यान दे सकेगी और काफी इम्प्रूवमैन्ट्स इस में कर सकेगी और नतीजे के तौर पर हम अपने स्कूलों से प्रैक्टीकल इनसान बना कर निकाल सकेंगे जो डैमोक्रेसी को मज़बूत बनायेंगे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी कुछ दिन हुए हैं जब से इस बात की बड़ी चर्चा चल रही है कि पंजाब के अन्दर एक हायर सैकंडरी बोर्ड बनाया जा रहा है। मैं इस बात के लिये भी सरकार को बधाई देती हूं। बड़ा मुबारिक कदम है। इस बोर्ड के बनाये जाने पर कई मैम्बर साहिबान ने इस बारे में कई खदशात जाहिर किये हैं। एक तो ढिल्लों साहब ने यह कहा है कि इस बोर्ड के बन जाने से पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत काम कम हो जायेगा और इसका नतीजा यह होगा कि वहां से बहुत सारा स्टाफ बेकार हो जायेगा। इस के लिये मैं गवर्नमैन्ट को यह सुझाव देती हूं कि जो स्टाफ इस यूनिवर्सिटी का इस बोर्ड के बनने से सरप्लस हो जाए उसे यह एबजार्व कर लें। दूसरा खदशा यह जाहिर किया गया है कि अगर यह बोर्ड गवर्नमैन्ट के अन्दर रखा गया तो इस से इस के काम में इन्टर्फियरैन्स होने लगेगी। तो मैं यह चाहती हूं कि इस बोर्ड को एक अटानोमस बोर्ड बनाना चाहिये क्योंकि अगर यह गवर्नमैन्ट के अन्डर रहे तो हो सकता है कि इस में पोलिटीकल इन्टर्फियरैन्स होने लगे। फिर कई दफा गवर्नमैन्ट के दफतरों में काम में देरी हो जाती है तो अगर इस बोर्ड को गवर्नमैन्ट ने अपने अन्डर रखा तो हो सकता है कि इस के काम में भी देरी होनी शुरू हो जाये और यह नतीजे ठीक समय पर न निकाले। पंजाब गवर्नमैन्ट के तहत J.B.T. Examination की जो Branch है, उसकी मैं एक मिसाल देना चाहती हूं। पिछले साल अप्रैल के महीने में J.B.T. के एग्ज़ाम हो चुके हुए हैं लेकिन उन में से कई लड़कों के नतीजे आज तक नहीं निकाले गये। इस में यह बात हो सकती है कि उन में कुछ अनफेयर मीन्ज़ एडाप्ट करने के केस हों। अगर तो ऐसा है तो मुझे अनफेयर मीन्ज़ एडाप्ट करने वालों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है लेकिन उनके केसों का जल्दी फैसला किया जाना चाहिये। इस तरह से एक साल तक के लिये उन बच्चों को इन डार्क रखना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। मैं कहती हूं कि उन में से जो बच्चे ऐग्ज़ानोरेट होने वाले हैं उन के साथ एक साल तक उन का रिज़ल्ट न बता कर कितनी भारी ज्यादती होगी। जितने तक उन के रिज़ल्ट नहीं निकाले जाते वह न तो आगे किसी क्लास में दाखिल ही हो सकते हैं और कई बच्चे अपने रिजल्ट का पता न होने की वजह से सबार्डीनेट सर्विसिज़ बोर्ड का कोई इम्तहान नहीं दे सकते। इस तरह से उन में डिमारलाइज़ेशन आती है। इन के साथ यह सरासर नाइन्साफी है जिस को psychological and education के view point से किसी तरह भी justify नहीं किया जा सकता। मैं समझती हूं कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाई में उत्साह नहीं मिल सकता। इस लिये मैं वजीर साहिब से कहती हूं कि वह नोट करें ताकि इन के रिजल्ट जो हैं वह जल्दी से जल्दी आऊट किये जायें। इस तरह से बच्चों के रिज़ल्ट आऊट न करके उन को सर्विस से और आगे किसी दाखले के लिये डिप्राइव करना किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। इस लिये मैं कहना चाहती हूं कि अगर आप ने हायर सैकंडरी एजूकेशन बोर्ड बनाना है तो उस को यूनिवर्सिटी की तरह ज़रूर अटानोमस बनाया जाये क्योंकि अगर इस को गवर्नमैन्ट के अन्डर रखा गया तो हो सकता है कि बच्चों के रिज़लटस 18, 18 महीनों तक न निकाले जाएं।

उपाध्यक्षा : अब आप वाइण्ड अप कर लें। (Please wind up now.)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : अभी मैं ने कई बातें कहनी हैं, इस लिये मुझे थोड़ा और समय दिया जाये।

एक बात मैं यह बताना चाहती हूं कि एजूकेशन डिपार्टमैन्ट जो है यह एक बहुत बड़ा डिपार्टमैन्ट है क्योंकि इस के नीचे तकरीबन 80 हज़ार के लगभग टीचर्ज़ काम कर रहे हैं और हरेक टीचर की अपनी अपनी प्राब्लम्ज़ होती हैं। किसी का प्रमोशन का केस होता है, किसी के एरियर्ज़ आफ पे का केस होता है, इसी तरह से किसी की कनफरमेशन का या सीनियारेटी का केस होता है? किसी का pay fixation का तो किसी का pension का। मैं सिर्फ शास्त्री टीचरों की बाबत कहना चाहती हूं। सरकार ने अभी कुछ मैट्रिक पास शास्त्री टीचरों की पोस्टों के लिये अर्ज़ियां मांगीं और उन का ग्रेड total 120 रुपये से शुरू होता है। लेकिन जो शास्त्री पास मैट्रिक टीचर इन के पास पहले सात सात आठ आठ सालों से काम कर रहे हैं उन को तो सरकार सिर्फ 100 रुपये दे रही है। वह इस नये ग्रेड की मांग कर रहे हैं उन को तो सरकार दे नहीं रही हालांकि वह इतनी देर से पहले यही काम कर रहें हैं लेकिन सरकार नये मैट्रिक पास शास्त्री टीचरों को जिन को कोई तजरुबा हासल नहीं है 120 रुपये पर लेने के लिये तैयार है। मैं वज़ीर साहिब से अर्ज़ करती हूं कि पुराने शास्त्री टीचरों को भी 120 रुपये का ग्रेड देकर उन के साथ इनसाफ करें। (घंटी की आवाज़) बस जी, मैं सिर्फ एक बात और जल्दी जल्दी कह कर बैठ जाती हूं।

सरकार ने क्लास फोर एम्पलाइज़ की तनखाह तकरीबन 95/100 रुपये तक कर दी है लेकिन मैं एक बात सरकार के नोटिस में लाना चाहती हूं कि जो Higher Secondary Schools में लेबारेटरी असिस्टैन्ट्स लगे हुए हैं जो आम तौर पर मैट्रिक पास होते हैं और सायंस के सबजैक्ट की वाकफियत रखते हैं और सायंस की लेबारेट्रीज़ में काम करते हैं, उन को यह सरकार सिर्फ total 60 रुपये दे रही है। आप ज़रा गौर फरमायें कि जो बिल्कुल अनपढ़ क्लास फोर एम्पलाइज़ हैं उन को तो यह 90 से 100 रुपये तक तनखाह दे रही है लेकिन जो मैट्रिक पास हैं और schools में लेबारेटरी असिस्टैन्ट्स का काम करते हैं उन्हें यह सिर्फ total 60 रुपये दे रही है। इस लिये वज़ीर साहब को उन की तरफ भी ध्यान देना चाहिये और उन के ग्रेड भी रिवाइज़ करने चाहियें। मैं यह मजबूर हो कर हाउस में कह रही हूं मुझे उम्मीद है; कि वज़ीर साहिब इस तरफ ज़रूर ध्यान देंगे।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं। फल्ड के दिनों में एक सरकूलर लैटर जारी हुई थी जो कि एजुकेशन डिपार्टमैन्ट की तरफ से जारी हुई थी। उस में यह कहा गया था कि जिन प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंग्ज़ फ्लड्ज़ में अफैक्टिड हुई हैं या गिर गई हैं या उनको नुक्सान पहुंचा है वह नकशे बनवा कर एप्लाई करें, उन्हें कुछ कम्पैनसेशन सरकार की तरफ से मिलेगी। इस पर उन लोगों ने ओवरसीयरों की खुशामदें कर के और पैसे खर्च कर के अपने नकशे बनवा कर भेजे थे और जब उन के केस इन के पास

यहां आ गये तो उन को अब कहा जा रहा है कि इस के लिए तो फण्ड्ज़ ही नहीं हैं, इस लिए वह अपनी अर्ज़ियां विदड्रा कर लें। मैं समझती हूं कि इस तरह से उन के साथ एक तरह का मज़ाक किया गया है। या तो सरकार पहले ही उन को अर्ज़ियां और नकशे भजने के लिये न कहती और जब उन्होंने नकशे बनवा कर अपनी अर्ज़ियां भेजी हैं तो उन को ज़रूर कम्पैनसेशन दी जानी चाहिए थी। इस तरह अब उन को अपनी अर्ज़ियां विदड्रा करने के लिये कहना, मैं समझती हूं, उन के साथ मज़ाक करने के सिवा और कुछ नहीं है। वह बेचारे इस बात के लिये चन्डीगढ़ भी हो गए हैं। (घंटी की आवाज़) पैसे की withdrawal चाहे Education Department ने की हो, चाहे Revenue Department ने, पर लोगों के साथ इस मामले में ठीक सलूक नहीं किया गया। ऐसी चीज़ expect नहीं होनी चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप बार बार घंटी बजा रही हैं इस लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करके बैठ जाती हूं।

ਸਰਦਾਰ ਪਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ (ਲਹਿਰਾ ਐਸ ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਮੁਚੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕ ਐਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ—ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਛੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਨਾਮ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਨਾਮ ਅਰ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਛੜੇ-ਪਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 8, 8 ਤੇ 9, 9 ਮੀਲ ਤੇ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਚੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਲੜਕੀਆਂ 8-9 ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਓਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਹੀ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕਈ ਡੂੰਨਾਂ ਹਨ, ਟਿਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ 9 ਮੀਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੁੜ 9 ਮੀਲ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਇੰਨੇ ਥਕੇ ਤੇ ਟੁਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਥਰਡ ਡਿਵੀਜਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚੂੰਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ

[ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ]

ਹੈ ਉਹ ਹਲ੍ਹ ਵਾਹੁਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਲ੍ਹ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਲ੍ਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹਲ ਲਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿਤੀਆਂ—ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਮੂਨਕ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਲੋਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਇਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ: ਸਾਹੋਕੇ, ਗਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੋਖਰ, ਰਾਹ ਬੜਿਆਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹਰੀ, ਭਟਾਲ ਕਲਾਂ, ਰੋਗਲਾ; ਮਾਂਡਵੀ, ਹਰਿਆਊ, ਬੰਗਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਕਲਾਂ, । ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਡਲ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਟਿਬੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਵੀ 9-10 ਮੀਲ ਚਲਕੇ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ। ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਰੁਪਏ, 3 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈ ਲਉ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਉ। ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਲਉ ਪਰ ਸਕੂਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਕਵਾਰਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਕੁਝ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। (ਘੰਟੀ) ਬਸ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸੀਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ 7 ਮੁੰਡੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਸੀਟਾਂ 5 ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ 7 ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।

उपाध्यक्षा : कामरेड शमशेर सिंह जोश मैंने आप के लिये माननीय मन्त्री से 10 मिनट मांग कर लिये हैं, 11 मिन्ट भी न लगाना। Please help me.

(Addressing Comrade Shamsher Singh Josh). (I have specially got 10 minutes for the hon. Member out of the hon. Ministers' time. So he must finish within this limit. He should please help me.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਸਟੀਚਿਯੂਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਰਡ ਜਿਵੇਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਬੋਰਡ, ਖਾਲਸਾ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੈਪਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਯੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ, ਰੀਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਤੈ ਨਹੀਂ, ਲੀਵ ਰੂਲਜ਼ ਤੈ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਜ਼ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਰਾਲਾ ਵਿਚ ਕਮਯੂਨਿਸਟ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 1957 ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਰਾਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰੇਡਜ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੀਵ, ਸਿਕਯੁਰਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਤੈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਡਿਮੋਕਰੈਟਿਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਟੀਟਯੂਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਮਯੂਨਲਿਜ਼ਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੈਯਰ ਲਿਆਉ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਖਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਾਹਨਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਮਯੂਨਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਵਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। (ਤਾੜੀਆਂ) ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 14 ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇੰਮਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਮਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਐਟ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੀ ਇਹ ਡਾਮੀਨੇਟਿੰਗ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਲ ਬਾਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕਹੇ ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਐਟ ਪਾਰ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 14 ਪਰਵਾਨਿਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਇਕ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 20 ਲਖ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਲਈ 70 ਲਖ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨੀਅਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮੇਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੀਸਰੀ ਗਲ ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟੈਰਮ ਰੀਲੀਫ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਰਲੀਫ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਸਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਇਸ ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਇਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਗਰੇਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ਨੂੰ 130 ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੇਵਲ 60 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਦਿਲੀ ਵਿਚ 160 ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਥੇ 110 ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਜੋ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਲਾਨ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੇਡ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨਰੇਪਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੁਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੇਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री (श्री प्रबोध चन्द्र) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले दो दिन से एजुकेशन की जो मद है इस पर बहस चल रही है। मैं उन सब दोस्तों का मशकूर हूं जिन्हों ने सुझाव दिये हैं। काफी अच्छे सुझाव आये हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम से कोई कभी गलती नहीं होती। इनसान गलतियों का पुतला है और हर इनसान गलती करता है। लेकिन मैं आप सब को यकीन दिलाता हूं कि जब भी और जहां पर भी किसी गलती को हमारे नोटिस में लाया जाता है तो हमें उस की उसी वक्त तलाफी करने में शर्म महसूस नहीं होती। हमें खुशी महसूस होगी कि उस को दरुस्त कर दिया जाए। (प्रशंसा) मेरे महकमा में अगर कोई ज्यादती हो गई हो, किसी अफसर से या और किसी से तो मैं यकीन दिलाता हूं कि कोई एम. एल. ए. या बाहर का भी कोई आदमी अगर मेरे नोटिस में लाये और मुझे कनविन्स करवा दे तो मैं उस ज्यादती को दूर करने की फौरन कोशिश करूंगा। मेरे नज़दीक किसी हिन्दु या सिक्ख का सवाल नहीं। अगर कोई यह तवक्कोह करे या इस तरह का इल्ज़ाम मेरे पर लगाए कि किसी बोली के साथ बेइंसाफी हो रही है तो यह गलत बात होगी। मैं ने न कभी ऐसा सोचा है और न ही कभी ऐसा किया है। (प्रशंसा)।

यहां पर इस बात की चर्चा की गई कि एजूकेशन डिपार्टमैन्ट की तरफ से सरकूलर जारी किया गया है कि पठानकोट में हिन्दी पढ़ाई जाए। इस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का कोई सरकूलर इस डिपार्टमैन्ट की तरफ से जारी नहीं किया गया। अगर कोई इस तरह का सरकूलर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में निकाला गया हो तो मैं कह नहीं सकता। सरदार गुरबख्श सिंह ने कहा था कि पठानकोट तहसील में यह सरकूलर जारी किया गया है कि पंजाबी की बजाए हिन्दी पढ़ाई जाये और यही मीडियम आफ इन्स्ट्रक्शन्ज़ हो। मैं ने इस के बारे में उसी वक्त वहां के अफसरों को कानटैक्ट किया और उन्होंने जवाब दिया कि इस तरह का कोई सरकुलर जारी नहीं किया गया और सच्चर फार्मूला के मुताबिक बोलियों की पढ़ाई चल रही है।

[शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री]

पठानकोट तहसील में पंजाबी पहली बोली है। और अगर किसी एक क्लास में 10 और किसी एक स्कूल में 40 लड़के दूसरी बोली में पढ़ना चाहें तो सरकार उस बोली के लिये इन्तजाम कर देती है। यह रियायत हिन्दी बोलने वाले इलाका में पंजाबी बोली के लिये है और पंजाबी रिजन में हिन्दी बोली के लिये है। हिन्दी एरिया में भी अगर किसी स्कूल में 10 लड़के और स्कूल में 40 लड़के पंजाबी पढ़ना चाहें तो गवर्नमैंट हर हालत में इस के लिए इन्तज़ाम करती है। इस लिये मुझे इस बात की खुशी है कि सच्चर फार्मूला पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है और जो इस तरह की शिकायात मैम्बरान ने की हैं इनका पहले से ही तदारक किया गया है।

यहां पर बहुत ज़ोर से इस बात का ज़िक्र किया गया कि पंजाबी यूनिवर्सिटी और कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी को क्यों बनाया गया। मैं इस वक्त इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि इन यूनिवर्सिटीज़ को क्यों कायम किया गया लेकिन जो बात जोश साहिब और गिल साहिब ने कही है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी को 40 लाख की ग्रांट दी गई है और कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 76 लाख के करीब ग्रांट दी गई है और इस तरह पंजाबी यूनिवर्सिटी के साथ इम्तयाज़ी स्लूक किया गया है इस बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि वाक्यात इस तरह के नहीं हैं। जब यह दोनों यूनिवर्सिटियां बनी थीं तो इस बात का फैसला किया गया था कि रैवेन्यू पर और प्रापर्टी टैक्स पर सैस लगाया जाये। इस तरह से 1 करोड़ 10 लाख की रकम लैन्ड रैवेन्यू पर सरचार्ज लगा कर वसूल की गई और 35,33,650 रुपये प्रापर्टी टैक्स पर सैस लगा कर वसूल किया गया। इस तरह से कुल 1,45,85,626 रुपया वसूल हुआ। इस पर यह फैसला किया गया था कि आधा रुपया पंजाबी यूनिवर्सिटी को और आधा हिस्सा कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी को दिया जायेगा। क्योंकि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2 साल पहले से चल रही थी और उसकी सारी बिल्डिंगें और दूसरी चीज़ें मुकम्मल थीं इस लिये इस को इस का आधा हिस्सा यानी 73 लाख के करीब रुपया जो बनता था दे दिया गया है।

Sardar Lachhman Singh Gill : On a point of Order, Madam.

Deputy Speaker : I have not allowed the hon. Member.

Sardar Lachhman Singh Gill : Madam, I am rising on a point of Order. As long as I am an hon. Member of this House, I am within my right to rise on a point of Order.

ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी पहले बनी है। यह एक फैक्ट है जो आप को मान लेना चाहिये। कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अब तक 42 लाख रुपया खर्च किया है। यह ठीक है कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ज्यादा रुपया खर्च किया है मगर पंजाबी यूनिवर्सिटी का रुपया गवर्नमैन्ट के पास जमा है। जैसे जैसे भी सरकार को ज़रूरत पड़ेगी यह रुपया दिया जायेगा। यह कहना कि एक को महज़ 40 लाख मिला है और दूसरे को 75 लाख दे दिया है यह सही नहीं होगा। दोनों को बराबर

का हिस्सा दिया गया है, दोनों को बराबर बराबर अलाटमैन्ट हुई है। मगर एक ने अभी इमारत बनानी है। इसे 12 लाख इस साल भी दिया जा रहा है।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

Education and Local Government Minister: According to the decision taken by Government, the cess income is to be disbursed to the Kurukshetra and Punjabi Universities in equal shares. T us, the share of each University in the ces; income comes to Rs 77,58,434.50 Paise. The amount so far given to both the Universities out of the cess fund is as follows :—

		Rs
Kurukshetra University	..	77.61 lacs
Punjabi University	..	42.50 lacs

The Kurukshetra Universi ty has since exhausted its share, rather it has received a small amount of Rs 2,565.50 Paise in excess of its share.

The Punjabi University has to its credit a sum of Rs 35,08,434.50 Paise. Of this a sum of Rs 12 lacs is proposed to be given during 1965-66. A sum of Rs 40 lacs has been provided for payment as grant-in-aid to the Punjabi University.

इस लिये यह आप को गलतफहमी है कि किसी यूनिवर्सिटी को कम दिया जायेगा। एक एक पाई उनकी अदा की जायेगी।

सरदार लछमन सिंह गिल : यह गलत ब्यानी है, मैं क्वैस्चन करता हूं।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : मैं जो कुछ भी कह रहा हूं यह लफ्ज़ बलफ्ज़ ठीक है। अगर आप को कोई शक है आप यह केस प्रिविलेज कमेटी को रैफर कर सकते हैं, I can convince any body. उन्होंने बिल्डिंगज़ में इस्तेमाल कर लिया है मगर इन का अभी बकाया पड़ा है।

सरदार लछमन सिंह गिल : मेरे पास सबूत है कि वह पैसे मांगते हैं मगर यह देते नहीं। A great deal of correspondence has been going on in this connection. I can quote the numbers of letters written. But in spite of it, the Government is not paying the money to them.

उपाध्यक्षा : अगर कोई डिफीकल्टी है तो आप पर्सनली क्यों नहीं बात करते ? (Why does not the hon'ble Member talk personally to the hon'ble Minister, if there is some difficulty ?)

सरदार लछमन सिंह गिल : मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर गलत ब्यानी क्यों की जाती है।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : यहां पर गिल साहिब ने एक फिरकादारी की बात की थी। अगर उनकी वाकफियत के लिये मैं उन को बता दूं कि वहां 5 डायरैक्टर हैं जिन में 3 सिख हैं। एक ज्वायंट डायरैक्टर है जो कि सिख है। इस तरह

[Minister for Education/कालेजिज]
की बात करना कि सरकारी अफसर सिख हों, हिन्दु न हों या हिन्दु हों और सिख न हों, मैं समझता हूं कि यह कोई मुनासिब बात नहीं है।

चौधरी देवी लाल : On a point of order, sir, यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि गुरदासपुर और पंजाबी यूनिवर्सिटी की लड़ाई है तो यह हम पर क्यों टूट रहे हैं कि हरियाना को ज्यादा दिया और पंजाबी यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं दिया । हमारी ही मौजूदगी में यह ऐसा क्यों कहते हैं।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : यहां पर एक ज़िक्र किया गया कि हम ने पंजाबी की बजाये हिन्दी को 1st language तसव्वर करने के लिये लिखा है । मैं इस को कैटेगौरीकली डीनाई करता हूं । हम ने कोई ऐसा सरकुलर इशू नहीं किया । ज्यादा तर मैंबर साहिबान की स्पीचिज़ के तीन हिस्से हैं । एक हिस्से में तो यह कहा गया कि हरियाना के साथ सौतेली मां का सलूक हुआ है । मगर इन की वाकफियत के लिये अर्ज़ कर दूं कि पापुलेशन की बिना पर 36.5 प्रतिशत इनके पास स्कूल होने चाहियें मगर थर्ड फाइव ईयर प्लैन में जितने सरकारी इन्स्टीच्यूशन्ज़ खुले इन में से हरियाना में 818 मिडल स्कूल खोले थे यानी 49.5 प्रतिशत स्कूल इसी तरह इनके हां हिन्दी रिजन के J. B. Teachers, units 226 खोली गई जो कि 46 प्रतिशत होती हैं । इसी तरह पंजाबी रिजन को Government Middle Schools 44 प्रतिशत लिए है और J. B. T. units 38.8 प्रतिशत दी गई हैं । यह कहना गलत बात होगी कि हिन्दी रिजन और पंजाबी रिजन में कोई फर्क समझा जा रहा है । गवर्नमेंट के सामने कोई ऐसी बात नहीं है । थर्ड फाइव ईयर प्लैन में 292 प्राईमरी स्कूल और 72 मिडल स्कूल अपग्रेड किये गये हैं out of which 41 primary schools and 38 middle schools fell to the share of Hindi Region and 151 primary schools and 34 middle schools fell to the share of Punjabi Region. जहां तक कालिजिज़ के टेक ओवर करने का सवाल है हम ने तीन कालिजिज़ टेक ओवर किये । यह तीनों के तीनों हिन्दी रिजन के ही हैं । हम जो कुछ भी किसी रिजन की बेहतरी के लिये कर सकते थे करने की कोशिश कर रहे हैं।

जगराओं के मुताल्लिक भी यह बात पहली बार नोटिस में लाई गई है कि वहां पर एक बिल्डिंग बन चुकी है जिस में कालिज खोलना है । मगर वहां पर दो कालिजिज़ का कोई स्कोप ही नहीं है । अगर बिल्डिंग पर इतना खर्च किया जा चुका है तो यह किसी और परपज़ के लिये भी इस्तेमाल की जा सकती है ।

Comrade Shamsher Singh Josh : I could request the hon. Education Minister to inform the House about the decision of the Government *vis--a-vis* the demands of the teachers.

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : जहां तक बैकवर्ड एरिया का ताल्लुक है, मैं सभी मेम्बर साहिबान से मिला हूं और जिस जिस जगह गया हूं यह अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया ऐजूकेशन के लिए इकट्ठा करें हमें 200 से ज्यादा स्कूल इन बैकवर्ड इलाकों

खोलेंगे । अगर रुपया पूरा इकट्ठा नहीं भी हो सका तो भी जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां पर स्कूल खोलेंगे और जे. बी. टी. यूनिट देने के बारे में भी यही ख्याल है । जिन स्कूलों ने रुपया जमा करवा दिया है और बिल्डिंग बना ली है, उनके बारे में यह आर्डर हैं कि उन्हें ज़रूर ही अपग्रेड कर दिया जाए (प्रशंसा) ।

जहां तक यह कहा गया कि यहां पर ऐजूकेशन पर बजट की कम परसैंटेज खर्च होता है, मैं इससे सहमत हूं लेकिन इसके कारण हैं । हमारे यहां जो ज्यादा रुपया खर्च हो जाता है वह वाटर लागिंग और फ्लड की रोक थाम पर खर्च होता है मैं ने सारी परिस्थिति छागला साहब के सामने रखी थी और सैंटर से दरखास्त की थी कि हमारी एलोकेशन बढ़ा दें । यादवेन्द्रा पब्लिक स्कूल की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए उन्होंने कहा था कि जहां तक पंजाब की ऐजूकेशन का ताल्लुक है उस के मुकाबिले हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है । इतना अच्छा हमारा स्तर है कि स्वयं यूनियन मिनिस्टर साहब ने यह स्वीकार किया है । (प्रशंसा)

जहां तक प्राइवेट कालेजिज़ के टीचर्ज़ का ताल्लुक है, पंजाब गवर्नमेंट ने 7 लाख से बढ़ा कर अब ग्रांट 10 लाख कर दी है ताकि वह यू. जी. के ग्रेड मेनटेन कर सकें ।

जहां तक टीचर्ज़ के ग्रेड बढ़ाने का ताल्लुक है । उनकी सबसे बड़ी डिमांड यह थी कि उनको रनिंग ग्रेड दिया जाए । उसके बारे में फैसला हो गया है । They have no objection to the unification of the existing scales of pay of Rs 60—4—80/5—100/5—120 nd Rs 120—5—175 of J.T. and J.B.T. Teachers in the Education Department into one scale of pay viz. Rs 60—4—80—5—100/5—120/5—175. तो यह उनकी जो मांग थी कि यूनीफार्म रनिंग ग्रेड हो जाए वह गवर्नमेंट ने मान लिया है (प्रशंसा) ।

यही नहीं बल्कि जब से हम आए हैं तो इस बात का हर सूरत में ख्याल रखा गया है कि टीचर्ज़ को फैसिलिटीज़ मिलें । पहले यह था कि जिनकी तनखाह 1,200 रुपए सालाना है उनके बच्चों को फ्री ऐजूकेशन मिले, अब यह कर दिया गया है कि जिनकी 3,000 रुपए तक सालाना इनकम है उनके बच्चों को भी फ्री ऐजूकेशन मिलनी चाहिए । जहां तक प्रोफैशनल टैक्स का ताल्लुक है उसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी कोई फैसाल नहीं किया है क्योंकि ऐसा करने से ज़िला परिषद और पंचायत समितियों के साथ नाइंसाफी होगी ।

कामरेड शमशेर सिंह जोश : अगर ज़िला परिषद और ब्लाक समितियां इस बात का रैज़ोल्यूशन पास कर दें कि प्रोफैशनल टैक्स नहीं लगना चाहिए तो क्या गवर्नमेंट गौर करेगी ?

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : ज़रूर गौर करेगी । लेकिन मैं यह नहीं समझता कि एक पटवारी पर तो प्राफैशनल टैक्स लगा होवे और टीचर्ज़ पर न हो, यह नामुनासिब बात है ।

जहां तक स्कूलों की संख्या का ताल्लुक है यह बहुत हद तक बड़ी है । आजकल प्रायमरी स्कूलों की तादाद 12,939 के करीब है, मिडिल स्कूल 1,145 से लेकर 1,635 कर दिए गए हैं । हाई स्कूल 309 से लेकर 1,071 कर दिए गए हैं । हायर सैकंडरी स्कूलों की संख्या 506 हैं । टीचर्ज़ ट्रेनिंग स्कूल पहले 4 थे अब 22 कर दिए गए हैं । यूनिवर्सिटी एक थी अब 4 कर दी गई हैं । और ट्रेनिंग यूनिट जो थे उनकी संख्या पहले 207 थी जो अब 350 कर दी गई है । मेरे कहने का मतलब है कि अब ऐजूकेशन में काफी विस्तार हुआ है ।

[शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री]

जहां तक जोश साहब की इस बात का ताल्लुक है कि सारे स्कूल नेशनेलाइज़ कर दिए जाएं उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं क्योंकि गवर्नमेंट इस पोज़ीशन में नहीं है कि वह सारा का सारा बोझ अपने ऊपर ले ले । यह हो सकता है कि प्राइवेट इंस्टीच्यूशन्ज़ की कमज़ोरियां दूर कर दी जाएं । जहां तक प्राइवेट या रिलीजस इंस्टीच्यूशन्ज़ का ताल्लुक है, मैं मानता हूं कि जितनी शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने काम किया है उस के मुकाबिले में गवर्नमेंट ने पासंग भी नहीं किया है। अब हमारी पालेसी यह है कि इन इंस्टीचूशन्ज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मदद दी जाए ताकि इनका स्टैंडर्ड ऊंचा हो सके ।

हम ग्रेड्ज़ के बारे में भी कुछ कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा काबल आदमी ऐजूकेशन डिपार्टमेंट में आएं । अब आई. ए. एस. और आई. पी. ऐस. वगैरा में जब हर जगह वह ठुकराए जाते हैं तो ऐजूकेशन डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते हैं । यही वजह है कि ऐजूकेशन का मयार नीचे गिर रहा है । इस में कोई शक नहीं, मैं यह मानता हूं । जहां तक स्पिरिचुअल और मारल वैल्यूज़ का ताल्लुक है हम तालीम के ज़रिए लोगों में कुछ ज़्यादा प्रचार नहीं कर सके । हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े आदमियों की पुस्तकें और मारैलिटी के बारे में किताबें लाइब्रेरीज़ में रखें और स्कूलों में भी यह लगाई जाएं । इस के अलावा गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो ऐसे लीडर्ज़ हैं कि जिन की मारल फोर्स हो उनको बुला कर इन्सटीच्यूशन्ज़ में लगाया जाए ।

चौधरी देवी लाल : मोहन लाल को लगा दें ।

(इस समय कामरेड शमशर सिंह जोश प्वायंट आफ इन्फारमेशन पर खड़े हुए)

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : जोश साहिब, मैं ज्यादा से ज़्यादा अकमोडेट करने की कोशिश करूंगा । दस मिनट में से अगर पांच या सात मिनट इस में लग जाएं तो बाकी क्या रह जाएगा ?

बाकी गिल साहिब ने कहा है कि मैं शहरों में ही जाता हूं और देहात में नहीं जाता । अगर वह मेरा प्रोग्राम देखें तो पता चले कि मैं देहात में ज़्यादा जाता हूं । देहात में प्रैस रिपोटर्ज़ नहीं होते इस लिए वहां जाने की खबर नहीं छपती । शहर में वह होते हैं इस लिए वहां जाने की खबर छप जाती है । आप डिस्क्री शनरी फन्ड को ले लें । जितनी भी इन्स्टीचूशन्ज़ हैं, जहां मुझे बुलाया गया है, हर इन्स्टीचूशन को रुपया दिया है ।

फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त तालीम दी जाती है, यहां पर उस के मुतालिक भी कहा गया । 81 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारी मुफ्त तालीम का फायदा उठा रहे हैं । सारे पंजाब में 23 लाख 81 हज़ार बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं । मैंने मिडल तक की फिग्र पहले बताई है । टीचर्ज़ को कुछ ऐसी सहूलतें हैं । whose basic pay does not exceed Rs 3,000 per annum will receive free education up to the High and Higher Secondary stage in all Government schools. There is already free education up to the middle standard in these schools. Formerly this concession was allowed on the basis of total emoluments of Rs 1,200 per annum.

For honouring and recognising merit of outstanding teachers the Government has instituted State Award like those of the Government of India. Their number has been increased by the Government from 5 to 20. Teachers of both the Government as well as privately-managed schools can compete for these awards.

A sum of Rs 2.25 lacs has been collected for the Teachers' Welfare Fund. This amount will be utilised for giving financial assistance to teachers and their dependents who are in financial difficulties.

Another scheme of foster parent for owning outstanding student is under-active consideration under which some generously disposed phillanthropists will bear the entire expenditure of education of these students.

इसके मुताल्लिक, जनाब मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ दोस्तों को चिट्ठियां लिखी थीं कि जहां वह अपने बच्चों को तालीम देते हैं, वहां एक एक गरीब बच्चे को अपना बच्चा बनाएं और तालीम दें । मुझे खुशी है कि इसकी रिसपान्स अच्छी आई है । 200 के करीब ऐसे आदमी हैं जो दो साल के लिए एक एक गरीब बच्चे को 50 रुपए महीना देंगे । (प्रशंसा) इस के अलावा गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि कुछ ब्रिलियन्ट स्टूडेंट्स की तालीम का सारा खर्च सरकार दे जिनकी तादाद 150 या 200 होगी । शुरू में शायद हम 50 रखें । फिर उन के लिए एक अलहदा कालेज बना दिया जाएगा जो ऐसे स्टूडेन्ट्स, जो साइन्स के होंगे या दूसरे जो उस कालेज में होंगे उनका सारा खर्च गवर्नमेंट देगी ताकि वह महसूस करें कि उनकी ज़िम्मेदारी अपने खानदान की तरफ ही नहीं बल्कि स्टेट की तरफ भी है । ब्रिलियन्ट स्टूडेन्ट्स के लिए एक कालेज होगा । अगले साल में गवर्नमेंट उसकी बुनयाद रखेगी ।

श्री चिरन्जी लाल जी ने कहा कि आइ. टी. आई. में ठीक तरह से काम नहीं होता, जो भी गवर्नमेंट बनी उसने अपने मैम्बरों को वहां सिलेक्शन के लिए लगा दिया । मगर मैं हाऊस को अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं ने यह बिलकुल नहीं किया । जो एम. एल. ए. उस जगह का है वही उसमें होना चाहिए, यह नहीं कि अपोज़ीशन का है तो न लिया जाए । अभी ऐसी कमेटियां नहीं बनाई । अब जो बनाएंगे आपको उस में पूरी परोपोरशन में रीप्रेज़ेंटेशन मिलेगी । श्री चिरन्जी लाल जी ने आई. टी. आई. के बारे में बड़े ज़ोर से चर्चा की । अगर वह मेरे इल्म में कोई बुराई लाएं तो मैं बड़े से बड़े अफसर से इन्क्वायरी कराऊंगा और जो सज़ा हम डिपार्टमेन्टली दे सकेंगे वह देने में गुरेज़ नहीं करूंगा । (प्रशंसा)

पार्टीशन के वक्त टेक्नीकल ऐजूकेशन के 40 डिगरी कोर्स थे और 140 डिप्लोमा कोर्स के स्कूल थे । आज वह स्कूल 870 डिगरी के लिए हैं और 2,950 डिप्लोमा कोर्स के हैं ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश ने प्रोडक्शन इन्जीनियरिंग क्लास का ज़िक्र किया कि उनको डिगरी नहीं मिलती कि डिप्लोमा मिलता है इस बारे अर्ज़ है जो क्वालिफिकेशन्ज़ इन्जीनियरिंग के लिए हैं प्रोडक्शन कोर्स के लिए उस से कम हैं । प्रोडक्शन कोर्स के लिए सिर्फ हायर सैकण्ड्री पास लड़के दाखल होते हैं । जो इन्जनीरिंग के लिए दाखल होने के लिए रिजैक्ट हो जाते हैं वह प्रोडक्शन इन्जनियरिंग का कोर्स लेते हैं । इसको अब सर्टिफिकेट देने के लिए ऊपर ला रहे हैं । उस को भी डिगरी की लैवल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं । यह कोशिश की गई है ।

[शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री]

कोऐजूकेशन के बारे में हम ने यह मैथड अडाप्ट किया है कि प्राईमरी तक कोऐजूकेशन हो ; उस के बाद लोग चाहें तो मिड्ल तक कर देते हैं । हम कोशिश करते हैं कि हाई क्लासों में अलहदा अलहदा स्कूल खोले जाएं । जो भी बातें कही गई हैं उनमें से 80 फीसदी बातें ठीक हैं । स्कूलों की कमी है, स्टाफ की कमी है, स्टाफ़ की काबलियत अच्छी नहीं । हर चीज के लिए रुपया ज़रूरी है ।

दूसरे सूबों में ऐजूकेशन पर खर्च का मुकाबला पंजाब से किया गया । मैं चाहूंगा कि अपोजीशन वाले और दूसरे साथी जितना रुपया मुझे देंगे उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी । यह नहीं होगा कि कोई हल्का रह जाए । हर मेम्बर के हल्का में स्कूल खोले जाएंगे शराब से जितना रुपया बचेगा उतना ज्यादा स्कूलों को दे सकेंगे । (एक आवाज़ : शराब और ऐजूकेशन को जोड़ दें ।)

जनाब पिछले थोड़े अर्से में जो स्टेप्स लिए गए हैं, उन में से एक यह है एक बात टीचर्ज़ को बहुत तंग कर रही थी । उनकी कन्फरमेश्न्ज़ के केसिज़ थे । मैं अर्ज करूं कि 41,000 टीचर्ज़ कन्फर्म कर दिए गए हैं । This is more than 80 per cent of the total.

बाकी टैम्प्रेरी पोस्ट्स के इलावा जल्दी ही तीन महीनों के अन्दर कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी कन्फरमेशन ड्यू है कोई भी ऐसा टीचर न रह जाए जो कि कन्फर्म न हुआ हो ।

कहा गया है कि हमने स्कूल तो ले लिए लेकिन फिर भी लोकल बाडीज़ से पैसे मांगते हैं । मुझे अफसोस है कि यह जानते हुए भी कि जितना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है उसके मुकाबले में बहुत insignificant रकम हम उन से मांग रहे हैं ऐसी बात की गई । यह काबिले एतराज़ बात नहीं है । स्कूलों की मुरम्मत और बिल्डिंगों के बारे में कहा गया है । मैं मानता हूं और इस में शक नहीं कि 80 फीसदी इमारतों की हालत ऐसी नहीं है जो अच्छे स्कूलों का नमूना पेश कर सकें । यह बात भी वहीं पर आ जाती है कि फंड्ज़ की कमी है । फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर साल बजट में 15/20 लाख रुपया इस काम के लिए रखा जाए । लेकिन मैं अर्ज़ करता हूं कि जो बिल्डिंगें खराब हैं अगर उनकी मुरम्मत पर खर्च का अंदाज़ा लगाया जाए तो 25 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी उन बिल्डिंगों को ठीक करने के लिए हम शायद 10 साल में भी इतना रुपया न निकाल सकें । लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि जो हम कर सकते हैं वह ज़रूर करेंगे । टीचर्ज़ की स्टेट्स बढ़ाने के लिए पे के इलावा महकमे की तरफ से डी. सीज़. और कमिश्नर्ज़ को लिखा गया है कि हर सोशल फंकशन में जो वह करें टीचर्ज़ को उनकी शान के शायां जगह मिलनी चाहिए । साहोके साहिब से मैं अर्ज़ करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कूल ज़िला संगरूर के लिए अलाट कर रहा हूं, क्योंकि वह बैकवर्ड एरिया है । मैं तो यह चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हम ऐसे हालात कर दें कि पांच छः मील के एरिया में कोई ऐसी जगह न रहे जहां कम से कम एक मिड्ल स्कूल न हो । जो सुजैशन्ज़ मेरे कुछ दोस्तों ने दी हैं उनके लिए मैं उनका मशकूर हूं इन के इलावा भी जो सुजैशन देना चाहें दें । जिस भाई ने अपग्रेड करने के बारे में सुजैशन न दी हो वह दे दें क्योंकि अगले हफ्ते में अपग्रेड करने का फैसला करना है

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਜਾਕੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : मैं स्कूलों में भी गया हूं । सौ फीसदी तो हालत तसल्ली बख्श नहीं हैं लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है जितनी आप कहते हैं । मैं ने एक चीज़ यह भी की है कि हर स्कूल के लिए obligatory कर दिया जाए कि वह स्कूल के प्रिमिसेज़ में 12 पौदे लगाएं और देख रेख के लिए बच्चों के नाम उन को अलाट कर दिए जाएं जैसा कि दूसरे मुल्कों में है । मैं ने आक्सफोर्ड और कैम्बरेज में देखा है कि वहां दो-दो सौ तीन-तीन सौ साल के पौदे लगे हुए हैं और उन पर तख्तियां लगी हुई हैं । बच्चे मुकाबले में आ कर उनकी रखवाली करते हैं । इसी तरह हम स्कूलों में flower beds वगैरा बिना किसी खर्च के लगा सकते हैं (घंटी) यह मोटी मोटी बातें मैं इस थोड़े से वक्त में कर सका हूं । मैं सारे मैम्बर साहिबान का, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, उनके लिए मशकूर हूं । मुझे उमीद है कि उनकी मेरे साथ इसी तरह कोआप्रेशन रहेगी और मैं भी उनके सुझावों को पूरा करूंगा । अब टाईम न होने की वजह से यहीं बन्द करता हूं और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां कहीं कमी हो मेरे नोटिस में लाएं उसे न सिर्फ दूर करने की कोशिश, करूंगा बल्कि उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗੱਲ ਜਾਨਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸੈਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ 70 ਲਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਲਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਉ।

ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਇਕ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਵੇਗੀ money will be paid to them.

Deputy Speaker : There are seven cut-motions on this Demand. The first cut motion is in the name of Comrade Babu Singh.

Deputy Speaker ; Question is —

That the Demand be reduced by Rs. 100/-

The motion was lost.

Deputy Speaker : The second cut motion is in the name of Sardar Pritam Singh Sahoke.

Sardar Pritam Singh Sahoke : Madam, I beg to withdraw my cut motion.

Deputy Speaker : Is it the pleasure of the House ?

(*Voices : Yes*)

The motion was, by leave, withdrawn

Deputy Speaker : The third cut motion is in the name of Shri Ramsaran Chand Mital.

Shri Ram Saran Chand Mital : Madam, I beg to withdraw my cut motion.

Deputy Speaker : Is it the pleasure of the House ?

(*Voices: Yes*)

The motion was, by leave, withdrawn

Deputy Speaker : The fourth cut motion is in the name of Principal Rala Ram.

Deputy Speaker : Question is—

That the Demand be reduced by Rs 1/-

The motion was lost

Deputy Speaker : The fifth cut motion is in the name of Shri Rup Singh Phul.

Deputy Speaker : Question is—

That the Demands be reduced by Rs 1/-

The motion was lost.

Deputy Speaker : The sixth cut motion is in the name of Shri Roop Lal Mehta.

Shri Roop Lal Mehta : Madam, I beg to withdraw my cut motion.

Deputy Speaker : Is it the pleasure of the House ?

(*Voices : Yes*)

The motion was, by leave, withdrawn

Deputy Speaker : The last cut motion is in the name of Chaudhri Ran Singh.

Chaudhri Ran Singh : Madam, I beg to withdraw my cut motion.

Deputy Speaker : Is it the pleasure of the House ?

(*Voices : Yes*)

The motion was, by leave, withdrawn

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 20,11,13,180 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66 in respect of charges under head 28 Education.

The motion was carried

Deputy Speaker : The House stands adjourned till 2.00 p.m. on Monday, the 29th March, 1965.

2.56 p.m.

(*The Sabha then adjourned till* 2.00 *p.m. on Monday the 29th March,* 1965)

5979PVS 382-65—C., P. & S., Pb., Chd.

Punjab Vidhan Sabha Debates

29th March, 1965

Vol. I, No. 24

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 29th March, 1965

Price: Rs. 5.35 Paise

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL, I, NO. 24,
DATED THE 29TH MARCH, 1965.

Read	*For*	*Page*	*Line*
*7462	7462	(24)8	17
the	t e	(24)9	5
pleased	pleaed	(24)9	5 from below
Dhillon	Dillon	(24)42	17
सारे	सा `	(24)42	6 from below
टू	`	(24)43	17
मिनिस्टर	मिनि टर	(24)50	10
जल्दी	ज दी	(24)50	12
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।	ਚਾਹੀਦੀ ।	(24)50	6 from below
ਬਦ ਅਨੁਵਾਨੀਆਂ	ਬਦਉਨ ਵਾਲੀਆਂ	(24)51	15 from below
ਓਮ	ਓਮ	(24)52	1
ਰੂਲਜ਼	ਰੁਲਜ਼	(24)53	2
ਚੀਜ਼ਾਂ	ਜ਼ੀਜਾਂ	(24)53	5
ਜਾਵੇ	ਜਾ `	(24)54	10
ਹਾਊਸ	ਹਾਓਸ	(24)62	3
ਆਉਂਟਲੁਕ	ਆਓਂਟਲੁਕ	(24)63	6
ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ	ਪਾਪਲੇਸ਼ਨ	(24)63	7 from below
ਸਿੰਘ	ਜ਼ਿੰਘ	(24)66	Last but one
ਹੋਇਆ	ਹੇਇਆ	(24)67	16
ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ	ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰ	(24)68	12
भौरा	ोरा	(24)68	19
कुछ	छ	(24)68	23
ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼	ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ	(24)68	27
लुध्याना	सुधियाना	(24)73	12

Read	*For*	*Page*	*Line*
बाहिर	बहार	(24)73	13
ਮੈਂ	ਮੋਂ	(24)76	13
ਸਟੈਂਡਰਡ	ਸਟੈਡਟਤ	(24)76	15-16
पीतल	पीलत	(24)77	9
इस	स	(24)78	19
पीछे	पीछ	(24)78	21
आगे	आग	(24)78	5 from below
रोजगार	रोगगार	(24)81	6
(24)84	(4)84	(24)84	Page No.
[मुख्य मन्त्री]	[चौधरी नेत राम]	(24)84	1
कन्ट्रोलड	कन्ट्रेलड	(24)89	18 from below
को	ो	(24)91	Last
आप	अपा	(24)92	Last but one
remaining	remainiug	(24)93	11 from below
Delete the word 'of' before the word for'		(24)95	10
Governor	Gonernor	(24)96	2
will	wil	(24)96	3
the	ihe	(24)96	13

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 29th March, 1965

The Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh, at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Memorandum submitted by Subordinate Services Federation

*6801. **Comrade Shamsher Singh Josh** (Put by Chaudhri Darshan Singh) : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the present Ministry has received from the Subordinate Services Federation any Memorandum containing their demands ; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(b) the action, if any, taken or proposed to be taken on the said Memorandum ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes, Sir. Many Memoranda were received. A statement 'A' containing the main demands of Punjab Subordinate Services Federation is laid on the Table of the House.

(b) A statement containing the requisite information is laid down on the Table of the House.

STATEMENT 'A'

(1) Grant of interim relief of 25 per cent of the pay to all employees.

(2) Appointment of Pay Commission.

(3) Linking of Dearness Allowance with Price Index.

(4) Grant of 10 per cent House Rent Allowance to all Employees.

(5) Opening of subsidised stores exclusively for Government employees and grant of one month's pay to clear the outstandings.

(6) Dropping the anti-employees proposed amendment in Punishment and Appeal Rules.

(7) Stoppage of Victimisation of certain workers of the Punjab Subordinate Services Federation.

(8) Abolition of the system of A.S.O.

STATEMENT 'B'

Demand	Action taken by the Government	
1. Grant of interim relief of 25 per cent of the pay to all employees	Considered and additional Dearness Allowance given to the employees as under :—	
	(i) Employees getting pay below Rs. 51	Rs. 7.50 per mensem
	(ii) From Rs. 51 to Rs100	Rs. 10 per mensem
	(iii) From Rs. 101 to Rs. 300	Rs. 15 per month (with marginal adjustment up to Rs. 315)

[Chief Minister]

	Demand	Action taken by the Government
2.	Appointment of Pay Commission	Considered and rejected
3.	Linking of Dearness Allowance with Price Index	Ditto
4.	Grant of 10 per cent House Rent Allowance to all employees	Considered and accepted to the following extent :— (i) 7½ per cent of the pay of those employees who are stationed at Chandigarh and other cities with a population of one lac or above (ii) 5 per cent of the pay to those employee s at places with a population below one lac but above 25,000
5.	Opening of subsidised stores exclusively for Government employees and grant of one month's pay to clear the outstanding	Considered and sanctioned interest free-wheat loan equal to two months pay subject to maximum of Rs. 200 to all Government employees drawing pay upto Rs. 500 per mensem. This is recoverable in 8 monthly instalments
6.	Dropping the anti-employees proposed amendment in Punishment and Appeal Rules	There is nothing anti-employees in the proposed Punishment and Appeal Rules
7.	Stoppage of victimisation of certain workers of the Punjab Subordinate Services Federation	There was no victimisation to the employees
8.	Abolition of the A.S.O. system ..	The matter is under consideration

Chaudhri Darshan Singh : May I know, Sir, from the honourable Chief Minister the reasons for rejecting the demand for the appointment of Pay Commission ?

मुख्य मन्त्री : चौधरी साहिब ने शायद सारा जवाब नहीं पढ़ा है । जो कुछ पूछा है जवाब दे दिया गया है ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : चीफ मिनिस्टर साहिब ने चौधरी दर्शन सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने सारा जवाब नहीं पढ़ा है। मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री साहिब ने स्वयं सवाल नहीं देखा है । मैं मुख्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि सेंट्रल सरकार ने अपने मुलाज़मों के लिए पे कमीशन मुकर्रर कर दिया है और पंजाब सरकार के अपने मुलाज़मों के लिए पे कमीशन मुकर्रर न करने की क्या वजह है ?

मुख्य मन्त्री : पंजाब सरकार की अपने मुलाज़मों के साथ पूरी हमदर्दी है। इस चीज़ को देखते हुए जितने भी हमारे रिसोर्सिज़ थे उस के अनुसार सरकारी मुलाजमों की बढ़चढ़ कर मदद की है ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : एम्पलाइज़ की रनिंग रीवाइज्ड ग्रेडज़ और सर्विसज़ बैनिफिट की डिमांडज़ थीं । इस के बारे में चीफ मिनिस्टर साहिब से एक डैपूटेशन भी मिला था और उन्होंने एशोरेंस दी थी कि इन के मुताल्लिक जल्दी ही फैसला

किया जाएगा । सरकार सर्विसज़ को बैनिफिटस देने के लिए और उन को रनिंग रीवाइज्ड ग्रेडज़ की सहूलतें देने के लिए कब तक फैसला करेगी और कब तक लागू किए जाएंगे ?

मुख्य मन्त्री : सरकार ने फैसला किया है, उस पर जितनी भी एम्पलाइज़ की यूनियन हैं, उन सब ने सराहना की है ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਐਂਮਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : जिन मुलाज़मों के बर्खलाफ एजीटेशन की वजह से ऐक्शन लिया गया उस के लिए मुनासिब हिदायतें सारी अथारिटीज़ के लिए जारी की गई हैं और उस पर अमल हो रहा है ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : इसके लिए डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज़ को हिदायतें जारी की गई हैं। केसिज़ मैरिटस पर डिसाइड किए जाएंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

मुख्य मन्त्री : मैं व्यक्तिगत के बारे में नहीं कह सकता हूं । जैसा कि आनरेबल मेम्बरों को पता है कि 17 में से 13 रीइंस्टेट कर दिए गए हैं और बाकी के केसिज़ रीकन्सिडर किए जा रहे हैं ।

'Himalayan Exhibition' organised by Public Relations Department at Chandigarh

***7707. Sardar Ajaib Singh Sandhu :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any "Himalayan Exhibition" was recently organised by the Public Relations Department, Punjab, in Sector 22, Chandigarh ; if so, the dates on which it was organised ;

(b) the total expenditure incurred on the said Exhibition ;

(c) the total number of persons who visited the said exhibition on each day ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes please ; from 7th to 9th December, 1964.

(b) (i) Cost of exhibits comprising of panels, models, paintings, stands and material of permanent nature .. Rs. 16,000

[Chief Minister]

(ii) Cost of setting up the exhibition inclusive of labour, carpentry, chowkidara, electricity consumption and fitting charges .. Rs. 200

(c) About two thousand daily. This exhibition will now go to five places.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਬੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਜਾਵੇਗੀ ?

मुख्य मन्त्री : हमारी कोशिश है कि पंजाब के ज्यादा से ज्यादा शहरों के अन्दर लोगों को दिखायी जाए ।

Truck Route Permit-holders in Kapurthala District

*8035. **Sardar Lakhi Singh Chaudhri :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the list of holders of route permits for trucks in Kapurthala District as on 31st January, 1964 ;

(b) the list of persons/institutions whose route permits for trucks in the said district were cancelled between 1st June, 1964 and 31st December, 1964 ;

(c) the list of persons out of those mentioned in part (b) above whose permits have since been revived and the reasons therefor ;

(d) whether any applications of persons mentioned in part (b) above for the revival of their permits are pending at present ; if so, their list ;

(e) whether Government propose to re-issue permits to the applicants referred to in part (d) above ; if so, the reasons therefor ;

(f) whether any ex-legislator from Kapurthala District applied for a route permit for a truck in the month of January and February, 1965 ; if so, his name and the action taken on his application ?

Shri Ram Kishan : (a) A list is laid on the Table of the House.

(b) Nil.

(c) Nil.

(d) No.

(e) Question does not arise.

(f) No.

Statement showing the Holders of Route Permits for Trucks in Kapurthala District as on 31st January, 1964

Serial No.	Name of the Permit-holder
1	Shri Bakhshish Singh, son of Lal Singh, village Naurangabad, post office Phagwara, district Kapurthala
2	Shri Sukh Ram, son of Mehtab Ram, Chaheru, tehsil Phagwara, district Kapurthala
3	S. Kartar Singh, son of Shri Harnam Singh, Railway Road, Phagwara, district Kapurthala

Serial No.	Name of the Permit-holder
4	Gurmej Singh, son of Ujagar Singh, Railway Road, Phagwara
5	S. Suchet Singh, son of Shri Harnam Singh, Amrit Bazar, Kapurthala
6	S. Nirbhal Singh, son of Atma Singh, Phagwara
7	Shri Madan Lal, son of Shri Gokal Chand, Phagwara
8	S. Sarwan Singh, son of Basant Singh, 59 C, Model Town, Phagwara
9	Harnam Singh, son of Hari Singh, Railway Road, Phagwara
10	Gurdev Singh, son of Manga Singh, 3.C, Model Town, Phagwara
11	Jagjit Singh, son of Bhagat Singh, village Chachaki, tehsil Phagwara, district Kapurthala
12	Shri Ajit Singh, son of Shri Harnam Singh, Phagwara
13	Mohar Singh, son of Maya Singh, 26-B, Model Town, Phagwara
14	Shori Lal, son of Maini Lal, Mohalla Khazanchian, Kapurthala
15	Harbans Lal-Janak Raj, Motor Stand, Phagwara
16	M/s Ujjar Singh-Battan Singh, C/o Janta Motor Store, G.T. Road, Phagwara
17	Nishan Singh, son of Kesar Singh, Phagwara
18	Karam Singh, son of Jaswant Singh, Railway Road, Phagwara
19	Yagya Paul, son of Chandu Lal, G. T. Road, Phagwara
20	Jaswant Singh, son of Jawala Singh, Kartar Building, Phagwara
21	M/s Atma Ram Jagir Singh, Railway Road, Kapurthala
22	Om Parkash, son of Hans Raj, 53, Model Town, Phagwara
23	Bikram Singh, son of Jaswant Singh, Kartar Buildings, Phagwara
24	Santa Singh, son of Hari Singh, Railway Road , Phagwara
25	Shri Inderjit Singh, son of Balwant Singh Chadha, C/o Chadha Transport Co., Ltd., Phagwara
26	Shri Bhola Ram Anand, son of Massi Ram, Mohalla Khazanchian, Kapurthala
27	Shri Rashem Singh, son of Partap Singh, C/o Ex-Servicemen Motor Transport Co-operative Society, Kapurthala
28	Shri Malkiat Singh, son of Mehanga Singh, village Khera, tehsil Phagwara
29	Harnam Singh, son of Wasawa Singh, village Begowal, tehsil Phagwara
30	Shri Dilbagh Singh, son of Atma Singh, Mandi Road, Phagwara
31	Shri Surjit Singh, son of Bawa Singh, G.T. Road, Phagwara
32	Bawa Singh, son of Ralla Singh, House No. 10-B, Model Town, Phagwara
33	Shri Sadhu Singh, son of Atma Singh, village Bidipur, district Kapurthala
34	Shri Shangara Singh, son of Narain Singh, I/C Model Town, Phagwara

[Chief Minister]

35 Shri Sukhdev Lal, son of Shri Hans Raj, 46-C, Model Town, Phagwara

36 M/s Mohan Lal-Nasib Singh, Mohalla Khazanchian, Kapurthala

37 Shri Daulat Singh, son of Shri Dasondha Singh, 25-B, Model Town, Phagwara

38 M/s Sucha Singh-Balwant Singh, C/o Patiala Goods Booking Agency (P) Ltd., Kapurthala

39 M/s Ajit Singh-Surjit Singh, Mohalla Darzian, Kapurthala

40 Shri Prem Singh, son of Santa Singh, village Lokhankhan, district Kapurthala

41 Shri Kartar Singh, son of Maya Singh, Phagwara

Sardar Lakhi Singh Chaudhri : May I know, Sir, whether all these persons are still holding the permits ?

मुख्य मन्त्री : जो लिस्ट माननीय सदस्यों को दी गई है उसके मुताबिक ही ट्रक परमिट दिए गए हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?

(No reply)

Chaudhri Darshan Singh : May I know, Sir, from the honourable Chief Minister the criteria for the allotment of these route permits ?

Chief Minister : Government policy regarding the issue of public carrier permits is very liberal. Every person, possessing a truck, can obtain a truck permit very easily after showing the registration book of the vehicle in his name, with a valid certificate of fitness, in the office of the Regional Transport Authority for either of the following sets of roads :—

(i) Jullundur, Ambala and Patiala Regions except hill, closed and contribution roads ;

or

(ii) Hill roads of Hoshiarpur and Kangra Districts except Pathankot Manali Road and Roads of Kulu Sub-Division, but including Una-Nangal and Garhshankar-Nawanshehr.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इन में कुछ ऐसे भी परमिट होल्डर्ज़ हैं जिन के अपने ट्रक्स नहीं है और परमिटस किन्हीं दूसरों को बेचे हुए हैं और सरकार उन के बखिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार है ?

मुख्य मन्त्री : अगर माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी सूचना है तो वह मेरे नोटिस में लाएं । मैं उस को चैक अप करूंगा । लेकिन जहां तक मुझे इल्म है कुछ ऐसे परमिट होल्डर्ज़ हैं, जिन के पास ट्रक्स नहीं हैं उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए हुए हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि ट्रक देने की लिबरल पालिसी अख्तियार की हुई है । मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से बसें नेशनलाइज़ की हैं क्या उसी तरह सरकार ट्रकों को भी नेशनलाइज़ करना चाहती है ?

Mr. Speaker : It is a general question.

Case of Smuggling of Iron Sheets registered at Kapurthala

*7461. **Sardar Ajaib Singh Sandhu** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether any case of smuggling of iron sheets was registered against any person or firm at Kapurthala during the year 1964-65 ; if so, when and against whom ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the stage at which the said case is at present and further steps being taken in this respect ;

(c) the total number of iron sheets smuggled in the said case together with value thereof ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. A case F.I.R. No. 133, dated 9th November, 1964, under section 7 of Essential Commodities Act was registered at Police Station Kotwali, Kapurthala, against the firm known as Hira Lal Anand & Sons.

(b) The case is still under investigation.

(c) 28 black iron sheets of 14 gauge worth Rs. 8,640.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि कुल 28 चादरें गेज की जिन की मालियत 8,600 रुपये के लगभग थी ब्लैक में बेची गईं और 9 नवम्बर को यह केस रजिस्टर हुआ था, इस केस के अब तक लटके रहने की क्या वजह है ?

मन्त्री : इनवेस्टीगेशन हो रही है।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ।

कामरेड राम प्यारा : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह चादरें कहां से स्मगल होकर कहां पहुंची, दी वर्ड 'स्मगलिंग' हैज़ बिन यूज्ड दैट इज़ व्हाई आई एम पर्टीकुलर अबाउट इट।

मन्त्री : केस की इनवेस्टीगेशन हो रही है। लेकिन यह चादरें कहां से आईं यह इनफर्मेशन इस सवाल से कुनैक्टिड नहीं है।

Mr. Speaker : All questions standing in the name of Comrade Makhan Singh Tarsikka will be converted into Unstarred questions.

Next question please.

मन्त्री : यह पता लग गया कि कहां से आई हैं तो पकड़ कर अन्दर दे देंगे ।

Comrade Ram Piara : Mr. Speaker, my question was quite different. What I want to know is whether the said iron sheets were smuggled ; if so, how were they smuggled ? If they were not smuggled , how has this word 'smuggling' been used ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has stated that the matter is still under investigation and, therefore, nothing can be said at this stage.

Comrade Ram Piara : I would like to know, Sir, whether these sheets were actually smuggled ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟ 'ਸੀ' ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ :—

(c) the total number of iron sheets smuggled in the said case together with value thereof ?

ਤੁਸਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਮਗਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ?

Mr. Speaker : The case is under investigation.

Case registered against Ex-President , Municipal Committee, Patiala

7462. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether any case involving mis-use of power and funds was registered against any Ex-President of Municipal Committee, Patiala, during the year 1964-65 ; if so, when, together with the details of allegations or charges levelled against him ;

(b) whether the said case has been withdrawn ; if so, under what circumstances ; if it has not been withdrawn, the present stage of the case ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. A case F.I.R. No. 198, dated 27th July, 1964 under section 409, I. P. C. and 5(2) Prevention of Corruption Act was registered in P.S. Kotwali, Patiala, against Shri Sat Parkash Kapoor, the then President, M.C., Patiala for claiming T.A. dishonestly and fraudulently.

(b) No. The case is still under examination.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ 27-7-64 ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਸ ਐਲ. ਆਰ. ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਉਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਐਲ. ਆਰ. ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ 409 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਐਲ. ਆਰ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਕਈਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਇਆ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

Sardar Gurnam Singh : At what stage was the case when it was sent to the Advocate-General for his advice ?

ਮੰਤਰੀ : ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Sardar Gurnam Singh : I have asked the hon. Minister to let us know whethei, when the case was referred to t e Advocate-General, the investigation had been completed ; or whether the investigation had actually been started oı not ? So at what stage was the case when it was sent to the Advocate-General for his opinion ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਡੀਸੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੇਂਟ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ?

Comrade Ram Piara : Will the hon. Home Ministeı be pleased to state if the person against whom the case was registered applied to the Government that the case be referred to the Advocate-General for his advice, or it was referred to him by the Government of their own accord ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਲਿਉਂ ਸਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि पटियाला म्यूनिसिपल कमेटी के साबिका सदर के खिलाफ जो केस रजिस्टर हुआ है उस के बारे में पटियाला म्यूनिसिपल कमेटी ने विदड्राल के लिए कोई रेज़ोल्यूशन पास कर के भेजा है ? अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आया है तो सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया है ?

मन्त्री : मेरे दोस्त बता रहे हैं कि उन्होंने यूनानिमस रेज़ोल्यूशन भेजा है मैं आफ हैंड नहीं कह सकता कि दुरुस्त है या कि नहीं ।

कामरेड राम प्यारा : क्या मन्त्री साहिब फरमाएंगे कि जिस पुलिस स्टेशन में यह केस रजिस्टर हुआ था वही इनवैस्टीगेशन कर रहा है या कि उस के अलावा किसी और इनवैस्टीगेटिंग अथारिटी को हैंडल करने के लिए भेज दिया गया है ?

मन्त्री : इस के लिए अलग नोटिस दरकार है ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 409 ਦਫਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ? ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Jails in the State

††*6988. **Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleaed to state—

(a) the income that accrued to the Government under the Head (i) Agriculture and (ii) Handicıafts, from each of the Jails in the State duıing the years 1963-64 and 1964-65 (todate), ıespectively ;

††*Note*—Treated as Unstarred Question under directions of the hon. Speaker.

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

(b) the details of the annual expenditure incurred by the Government during the said peiiod on (i) Administiation and (ii) Food, Clothes and Medical aid provided to the prisoners in each jail in the State ;

(c) the total number of prisoners lodged in each jail of the State duiing the said period ?

Shri Ram Kishan : Statements 'A', 'B' and 'C' giving the requisite information are placed on the Table of the House.

STATEMENT 'A'

(a)

Name of Jails in the State		(a) Income accrued to the Government under Head :			
		(*i*) *Agriculture*		(ii) *Handicrafts*	
		1963-64	1964-65 (Upto 31st December, 1964)	1963-64	1964-65 (Upto 31st December, 1964)
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Ambala	..	1,12,406	1,16,526	5,15,628	2,17,580
Ferozepore	..	1,42,154	51,226	4,86,574	4,26,975
Patiala	..	1,11,521	1,11,905	6,41,461	3,96,594
Jullundur	..	30,216	29,619	1,13,110	1,26,390
Ludhiana	..	64,890	51,969	2,30,136	1,95,482
Amritsar	..	1,09,704	90,120	1,70,232	1,20,379
Rohtak	..	4,835	4,972	98,277	45,851
Hissar	..	'87,822	1,18,756	5,58,231	1,70,513
Nabha	..	20,136	33,320	73,312	65,542
Bhatinda	..	31,527	28,442	69,476	60,468
Gurdaspur	..	6,735	3,858	72,023	41,039
Sangrur	..	24,899	21,111	81,327	53,278
Faridkot	..	70,129	57,426	2,22,346	2,05,176
Special Jail Hissar	..	4,230	4,069	..	..

Name of Jails in the State	(a) Income accrued to the Government under Head :			
	(i) *Agriculture*		(*ii*) *Handicrafts*	
	1963-64	1964-65 (Up to 31st December, 1964)	1963-64	1964-65 (Up to 31st December, 1964)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Karnal ..	17,036	13,613	..	..
Gurgaon ..	8,583	10,940	..	...
Kapurthala ..	2,446	2,458	..	...
Mohindergarh ..	447	132	..	..
Hoshiarpur ..	20,377	14,974	..	..
Dharamsala ..	1,653	2,099	..	...
Palwal ..	..	..	..	...
Rupar ..	..	..	..	...
Muktsar ..	10,323	10,986	..	..
Sirsa ..	..	..	..	..
Moga ..	472	541	..	...
Fazilka ..	75	75	..	..
Patti ..	1,613	1,296	..	...
Simla ..	..	..	..	...
Kulu ..	31	12	..	...
Dadri ..	96	337	..	..
Malerkotla ..	469	401	..	..
Dasuya ..	..	16	..	...
Bassi Pathana ..	228	117	..	..
Mansa ..	..	367	..	..
Hamirpur ..	60	81	..	...
Panipat ..	77	43	..	..
Bhiwani ..	218	139	..	..
Phagwara ..	140	168	..	..
Pathankot ..	1,307	2,092	..	..
Barnala ..	..	..	..	..

[Chief Minister]

STATEMENT 'B'

(b)

Details of annal expenditure incurred by Government on

Names of Jails in the State	(i) Administration 1963-64		(ii) Food	Clothes	Medical aid	(i) Administration 1964-65 (up to 31st December 1964)		(ii) Food 1964-65 (up to 31st December, 1964)	Clothes	Medical aid
	Maintenance side	Factory side				Maintenance side	Factory side			
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Ambala ..	1,97,243	25,440	96,512	12,981	22,019	1,57,229	21,081	1,29,201	57,671	36,881
Ferozepore ...	1,87,080	23,062	2,17,633	53,349	53,457	1,49,167	17,138	1,34,234	57,346	36,604
Patiala ...	2,01,713	26,208	1,58,434	86,268	87,794	1,54,618	21,400	1,43,986	39,105	28,638
Ludhiana ..	1,13,116	14,240	99,674	14,552	31,279	91,835	10,741	81,032	7,860	14,831
Jullundur ...	86,614	5,914	57,187	21,713	30,004	69,225	5,649	46,238	3,981	13,958
Amritsar ..	1,30,465	5,769	1,86,595	91,293	40,363	43,350	4,651	78,028	29,707	9,905
Rohtak ..	78,421	3,570	59,058	7,045	8,218	59,415	3,778	35,014	19,086	6,049
Hissar ...	1,46,926	13,292	89,911	11,696	32,229	1,14,821	10,839	74,806	7,927	17,280
Sangrur ...	75,600	1,682	48,342	13,472	6,592	57,709	2,084	38,958	1,008	8,185
Gurdaspur ...	79,719	2,771	44,653	14,991	5,940	60,633	2,564	48,694	8,123	6,026
Faridkot ...	1,12,303	13,374	70,892	19,174	9,172	97,942	14,739	49,703	23,158	7,536

Bhatinda	77,019	1,742	55,859	18,849	8,603	59,840	2,338	56,086	7,281	8,661
Nabha	66,592	3,670	25,154	3,310	17,728	51,324	3,334	31,817	5,587	13, 906
Special Jail, Hissar	16,817	..	2,586	2,270	5,063	14,023	..	2,401	2,162	2,043
Karnal	29,937	..	35,479	1,328	3,076	24,903	..	23,500	1,237	1,966
Kapurthala	33,321	..	12,100	493	4,451	25,577	..	6,745	466	1,228
Dharamsala	32,281	..	6,980	759	1,169	33,410	..	9,080	2,947	3,176
Hoshiarpur	33,551	..	14,238	41	2,595	25,601	..	1,041	94	1,382
Gurgaon	31,048	..	20,455	3,585	2,205	22,425	..	15,395	230	734
Mohindergarh	19,760	..	4,017	284	221	13,208	..	4,288	..	..
Moga	26,044	..	5,206	2,623	..	19,863	..	3,223	395	..
Fazilka	15,204	..	12,866	1,688	..	12,487	..	6,064	344	..
Muktsar	20,527	..	7,560	2,450	623	14,824	..	7,133	288	..
Simla	12,912	..	17,548	87	..	11,337	..	2,094	..	..
Kulu	13,166	..	1,599	..	..	9,107	..	2,496	..	..
Patti	17,635	..	683	1,169	..	15,946	..	2,187	392	..
Palwal	13,755	..	505	..	..	10,952	..	3,832	..	..
Sirsa	17,655	..	11,206	..	..	13,549	..	13,513	35	82
Rupar	13,089	..	4,002	..	..	9,272	..	1,191	..	..
Bhiwani	15,279	..	3,464	..	346	11,563	..	2,236	..	369
Malerkotla	15,388	..	2,697	182	478	11,854	..	1,809	52	18
Hamirpur	11,999	..	1,663	15	—	9,720	—	4,070	—	..

[Chief Minister]

Names of Jails in the State	Details of annual expenditure incurred by Government on									
	(i) *Administration* 1963-64					(i) *Administration* 1964-65 (*up to 31st December*, 1964		(ii) Food 1964-65 (upto 31st December, 1964)	Clothes	Medical aid
	Mainte-nance side	Factory side	(ii) Food	Clothes	Medical aid	Mainte-nance side	Factory side			
	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
Pathankot ..	10,637	..	1,491	17	243	8,477	..	1,145	291	2
Bassi Pathana	11,332	..	392	..	61	8,714	..	1,402	..	56
Phagwara ..	12,048	..	4	..	137	9,998	..	347	..	249
Panipat ..	11,373	..	2,102	164	105	9,589	..	1,252	..	95
Mansa ..	12,063	..	5,815	43	11	8,672	..	6,692	43	12
Dadri ..	11,479	..	2,203	168	..	9,076	..	1,202	197	..
Barnala ..	16,297	..	5,312	..	913	13,103	..	11,282	..	..
Dasuya ..	11,514	..	834	830	102	9,528	..	510	64	4

Note.—The figures of expenditure in respect of food shown against District Jail, Jullundur include the expenditure on food in respect of Sub-Jail, Phagwara also as the latter jail receives its supplies of ration from the former jail.

STATEMENT 'C'

(c)

Names of Jails in the State		(c) Total No. of prisoners lodged in each Jail of the State	
		1963-64	1964-65 (Up to 31st December, 1964)
Ambala	..	1,111	940
Ferozepur	..	1,125	1,197
Patiala	..	903	918
Jullundur	..	378	361
Ludhiana	..	547	519
Amritsar	..	784	669
Rohtak	..	266	281
Hissar	..	559	534
Nabha	..	188	203
Bhatinda	..	318	348
Gurdaspur	..	254	283
Sangrur	..	245	254
B.I.J. Jail Faridkot	..	513	473
Special Jail, Hissar	..	39	34
Karnal	..	168	185
Gurgaon	..	110	114
Kapurthala	..	50	48
Hoshiarpur	..	89	101
Mohindergarh	..	15	12
Dharamsala	..	37	63
Rupar	..	13	13
Palwal	..	27	43
Muktsar	..	39	60
Sirsa	..	44	61
Moga	..	31	32
Fazilka	..	59	70

Names of Jails in the State		(c) Total No. of prisoners lodged in each Jail of the State	
		1963-64	1964-65 (Up to 31st December, 1964)
Patti	..	38	32
Kulu	..	4	13
Simla	..	5	8
Dadri	..	7	7
Malerkotla	..	14	14
Dasuya	..	13	12
Bassi Pathana	..	10	18
Mansa	..	53	43
Hamirpur	..	4	2
Panipat	..	18	22
Bhiwani	..	14	17
Phagwara	..	6	9
Pathankot	..	11	10
Barnala	..	67	58

Package Programme

††*6990. **Comrade Makhan Singh Tarsikka** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the year in which the 'Package Programme' was started in the Ludhiana District together with the targets fixed at the time of starting this Programme ;

(b) the extent to which the said targets have been achieved and the details thereof ;

(c) whether the District Package Programme Officer has submitted any progress reports in respect of the said Programme ; if so, a summary of the defects and deficiencies, if any, pointed out therein be laid on the Table of the House ;

(d) the expenditure incurred by the Government on the Programme referred to in part (a) above since its inception together with the main Heads under which the said expenditure has been incurred ;

(e) the details and percentage of the increase in production achieved yearwise, as a result of the implementation of the said Programme ?

††Note ;—Treated as unstarred question under the direction of the hon. Speaker.

Sardar Darbara Singh : (a) 1960-61. To raise the production of food crops by 50—60 per cent in a period of five years.

(b) The targets have already been exceeded in the case of wheat, maize and ground-nut by 68.2 per cent, 73.2 per cent and 125.4 percent, respectively

(c) The annual reports of the Programme are being submitted in the *pro-forma* prescribed by the Government of India and the Ford Foundation but there is no column in the said *pro forma* for the indication of the defects and deficiencies encountered in the implementation of the Programme. The main difficulty, however, experienced has been that of shortage of fertilizers/experienced technical staff.

(Rupees in lacs)

	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65
Part I ..	1.60	6.29	8.61	8.60 (Estimated)	11.65

Part II 31—Agriculture.

(e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement referred to in part (e)

Part I : Details of production.

Name of crops	TOTAL PODUCTION IN MAUNDS			
	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64
(i) Maize ..	1,442,105	2,070,861	1,237,798	2,497,636
(ii) Groundnut ..	675,022	826,102	864,090	1,521,434
(iii) Cotton ..	662,483	599,843	363,622	787,303
(iv) Wheat ..	4,540,582	5824,372	5727,654	6,739,201
(v) Gram ..	1,178,651	1,385,922	1,197,093	1,081,339

Part II : Percentage increase or decrease over 1960-61

Name of crops	1961-62	1962-63	1963-64
(i) Maize ..	43.5	—14.2	73.2
(ii) Groundnut ..	22.4	28.0	125.4
(iii) Cotton ..	—9.5	—45.1 ..	18.8
(iv) Wheat ..	28.3	25.1	68.2
(v) Gram ..	17.6	1.6	—8.2

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Superintendents of Police

2566. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the names of the Superintendents of Police of each district at present together with the date when each of them was posted as an S.P. at any district Headquarters ;

(b) the cadre to which each of the said S.Ps. belong, in the case of those belonging to the I.P.S. the date when each of them joined the I.P.S. ;

(c) the number and name of each of the officers belonging to the I.P.S. and I.P. cadres in the State together with the name of the post being held by each at present and the length of their service in each case in each of the said cadres ;

(d) whether at the time of promotion of officers from the Punjab Police cadre to the I.P.S. cadre as mentioned in part (b) above, the recommendations were called for from the I.G. of Police ; if so, in which cases ; if not the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House as Appendix (A).

(c) A statement is laid on the Table of the House as Appendix (B).

(d) Promotions from the State Police Service to the I.P.S. are made under the I.P.S. (Appointment by Promotion) Regulations, 1955. A Selection Committee meets every year and considers the names of officers who have completed 8 years of service as D.S.P. on the 1st of January of the year in which the meeting is held and brings the names of suitable D.S.Ps. on the Select List. The State Government forwards the list to the Union Public Service Commission with its comments. The list as finally approved by the U.P.S.C. becomes the Select List. Appointments to the I.P.S. are made from the Select List by the Government of India generally in the order in which the names of the officers occur on this list.

APPENDIX 'A'

List of Superintendents of Police posted in districts, with the dates of their postings and the cadre to which they belong etc

Name of the districts	Name of the Superintendent of Police	Date of postings	Cadre to which he belongs	Date of appointment to the I.P.S.
Hissar	Shri M.K. Luthra	9-7-64 (After noon)	I.P.S.	15-2-61
Rohtak	Shri Bahal Singh	3-2-64 (After noon)	S.P.S.	...
Gurgaon	Shri S.S. Palta	7-1-63	I.P.S.	29-10-63
Karnal	Shri Brijinder Singh	25-5-64	I.P.S.	31-7-58
Ambala	Shri Birbal Nath	22-5-62	I.P.S.	9-7-51
Simla	Shri J.S. Dulat	3-3-63	S.P.S.	...
Jullundur	Shri Amar Singh	14-6-62 (After noon)	I.P.S.	29-10-63

Name of the districts	Name of the Superintendent of police	Date of posting	Cadre to which he belongs	Date of appointment to the I.P.S.
Ludhiana ..	Shri Harjit Singh ...	13-12-61	I.P.S.	1-11-50
Hoshiarpur ..	Shri Inderjit Verma ...	23-12-62 (Afternoon)	I.P.S.	28-10-54
Kangra ..	Shri Avinash Chandra ..	2-2-64 (After noon)	I.P.S.	31-7-58
Kulu ..	Shri B.L. Chhibber ...	12-4-64 (After noon)	S.P. S.	...
Lahaul and Spiti	Shri P.S. Bhinder ..	14-10-63	I.P.S.	24-10-58
Kapurthala ..	Shri Dalip Singh ..	24-2-63	I.P. S.	19-11-59
Amritsar ..	Shri Gurbhagat Singh Sr. S.P. ..	13-12-62 (After noon)	I.P.S.	6-4-61
	Shri Sukhpal Singh Addl.S.P. ..	21-3-64	S.P.S.	...
Ferozepur ..	Shri P.A. Rosha Sr. S.P. ..	1-7-63	I.P.S.	14-9-48
	Shri Ranbir Singh Yadav ..	15-2-65	S.P.S.	...
Gurdaspur ..	Shri V.K. Kalia ..	31-12-62 (After noon)	I.P.S.	14-10-54
Patiala ..	Shri Harjit Singh ...	8.2.63	S.P.S.	..
Bhatinda ..	Shri C.K. Sawhney ..	14-2-64 (After noon)	I.P.S.	7-10-55
Sangrur ..	Shri M.S. Bawa ..	9-2-65	I.P.S.	7-10-55
Narnaul ..	Shri Inderjit Singh Sodhi ..	19-2-65 (After noon)	I.P.S.	7-10-55

N.B.—(i) S.P.S. means State Police Service.
(ii) I.P.S. means Indian Police Service.

APPENDIX 'B'

List of II.P/I.P.S. officers borne on the Punjab State Cadre together with the name of the post held by them at present and the length of their service in I.P./I.P.S. cadres as on 29th March, 1965.

Serial No.	Name of the officer	Cadre to which he belongs	Post held	Length of service in I.P./I.P.S. Y. M. D.
1	Shri Gurdial Singh	I.P.	Inspector General of Police, Punjab	30 11 16
2	Shri Shamsher Singh	I.P.	Additional I.G. Police, Punjab	29 1 22
3	Shri Balbir Singh ..	I.P.	On deputation to Government of India	28 1 13

[Minister for Home and Development]

Serial No.	Name of the officer	Cadre to which belongs	Post held	Length of service in I.P./I.P.S.
				Y. M. D.
4	Shri Ram Singh ..	I.P.S.	Deputy Inspector General of Police, Patiala Range	17 7 04
5	Shri F.B. Manley	I.P.	On leave preparatory to retirement upto 31st March, 1965	25 2 25
6	Shri Piara Lal Sharma	I.P.S.	Assistant Inspector General of Police, Punjab	12 3 11
7	Shri A. Kumar ..	I.P.	Deputy Inspector General of Police, P.A.P. and Border Range	21-11-03
8	Shri J.R. Chhabra..	I.P.S.	On deputation to Government of India	16 8 20
9	Shri H.C. Saxena ..	I.P.S.	Ditto	14 11 16
10	Shri B.S. Rosha ...	I.P.S.	Deputy Inspector General of Police, C.I.D. Punjab	15 5 18
11	Shri A.S. Midha ...	I.P.S.	On Deputation to Government of India	16 9 11
12	Shri Ajaib Singh ..	I.P.S.	Deputy Inspector General of Police, Jullundur Range	15 5 18
13	Shri D.S. Grewal ...	I.P.S.	Comdt. P.A.P. Bn. 22 Jullundur Cantt.	15 5 18
14	Shri B.N. Muttoo	I.P.S.	On deputation to Government of India	14 11 18
15	Shri M.L. Puri ...	I.P.S.	On Deputation to Government of India	14 11 18
16	Shri J.C. Vachher	I.P.S.	Comdt. General Home Guards and Director Civil Defence, Punjab	14 11 18
17	Shri B.R. Chadha	I.P.S.	Additional Deputy Inspector General of Police, P.A.P.	14 11 18
18	Shri Randip Singh	I.P.S.	Principal P.T.S. Phillaur	13 2 16
19	Shri V.N. Bakshi ...	I.P.S.	On deputation to Government of India	14 11 18
20	Shri P.A. Rosha ...	I.P.S.	Sr. Superintendent of Police, Ferozepore	16 6 05
21	Shri Hem Raj Talwar	I.P.S.	S.P./C.I.D.	16 6 05
22	Shri S.N. Mathur ...	I.P.S.	Deputy Inspector General of Police, Ambala Range	16 6 05
23	Shri Gurpuran Singh	I.P.S.	Comdt. P.A.P. Bn. No. 2	11 3 0

1	2	3	4	5
				Y M D
24	Shri Puran Singh ..	I.P.S.	Assistant Inspector General Government Railway Police, Punjab	9 3 0
25	Shri Madan Gopal Singh	I.P.S.	On deputation to Government of India	9 5 19
26	Shri Ranjit Singh	I.P.S.	On leave	11 1 1
27	Shri S.S. Bajwa ..	I.P.S.	On deputation to Government of India	15 2 4
28	Shri Harjit Singh ..	I.P.S.	Superintendent of Police, Ludhiana	14 4 18
29	Shri Surindra Nath	I.P.S.	On deputation to Govt. of India	14 4 18
30	Shri B.S. Danewalia	I.P.S.	Comdt. P.A.P. Bn. No. 17	14 4 15
31	Shri Birbal Nath	I.P.S.	Superintendent of Police, Ambala	13 8 10
32	Shri J.S. Bawa ..	I.P.S.	Assistant Inspector General of Police, Punjab	13 8 6
33	Shri M.S. Bhatnagar	I.P.S.	On deputation to Government of India	12 6 7
34	Shri P.C. Wadhwa ..	I.P.S.	S.P./C.I.D. ..	12 5 16
35	Shri Dalip Singh	I.P.S.	S.P./Kapurthala ..	5 4 0
36	Shri A.C. Pushong ..	I.P.S.	Assistant Inspecter General of Police Technical and Training, Punjab	4 7 16
37	Shri J.S. Bakshi ..	I.P.S.	S.P./Vigilance	4 6 09
38	Shri Parkash Chand	I.P.S.	Assistant to D.I.G./C.I.D. ..	11 4 14
39	Shri Brijinder Singh	I.P.S.	S.P., Karnal ..	6 7 18
40	Shri Manmohan Singh	I.P.S.	On deputation to Government of India	6 7 18
41	Shri Dharam Singh ..	I.P.S.	Ditto ..	6 7 18
42	Shri Inder Mohan Mahajan	I.P.S.	Ditto	6 7 18
43	Shri Avinash Chandra	I.P.S.	S.P. Kangra ..	6 7 18
44	Shri V.K., Kalia ..	I.P.S.	S.P., Gurdaspur ..	10 5 05
45	Shri Inderjit Verma ..	I.P.S.	S.P., Hoshiarpur ..	10 4 21
46	Shri Baljit Rai Sur ..	I.P.S.	S.P .C.I.D ..	10 5 05
47	Shri Bakhtawar Singh	I.P.S.	Comdt P.A.P. Battalian No 1	4 2 08
48	Shri M.K. Luthra ..	I.P.S.	S.P., Hissar ..	4 1 04
49	Shri Harpal Singh ..	I.P.S.	A.I.G./Traffic, Punjab ..	2 1 23

[Home and Development Minister]

Serial No.	Name of the officer	Cadre to which he belongs	Post held	Length of service in I.P./I.P.S.
				M. Y. D.
50	Shri V.S. Seigell ..	I.P.S.	On deputation to Government of India	9 4 29
51	Shri C.K. Sawhney ..	I.P.S.	S.P./Bhatinda ..	9 5 12
52	Shri Daljit Singh ..	I.P.S.	Comdt, 7th Battalian P.A.P.	2 11 16
53	Shri Gurbhagat Singh	I.P.S.	Sr. Superintendent of Police, Amritsar	2 11 13
54	Shri Ram Sarup ..	I.P.S.	Comdt, P.A.P. Battalian No. 11	1 4 20
55	Shri Surendra Nath..	I.P.S.	Comdt, P.A.P. Battalian, No. 33, Amritsar	1 4 20
56	Shri M.S. Bawa ..	I.P.S.	S.P./Sangrur	9 5 12
57	Shri Shiv Dass Kapur	I.P.S.	On deputation to Government of India	1 4 20
58	Shri Amar Singh ..	I.P.S.	S.P./ Jullundur ..	1 4 20
59	Shri Inderjit Singh Sodhi	I.P.S.	S.P./Narnaul	9 5 12
60	Shri B.S. Dhaliwal ..	I.P.S.	On leave ..	9 5 12
61	Shri S.S. Palta ..	I.P.S.	S.P./Gurgaon ..	1 4 20
62	Shri Krishan Kumar	I.P.S.	S.P./C.I.D. ..	8 4 24
63	Shri Tarlok Singh ..	I.P.S.	Comdt, 35th Battalian, P.A.P.	1 2 09
64	Shri D.D. Kashyap ..	I.P.S.	On deputation to Government of India	8 4 24
65	Shri M.L. Bhanot ..	I.P.S.	Ditto	7 4 23
66	Shri G.S. Mander ..	I.P.S.	Ditto	7 4 23
67	Shri P.S. Shukla ..	I.P.S.	Ditto	7 3 05
68	Shri K.L. Dewan ..	I.P.S.	Ditto	7 3 14
69	Shri H.R. Swan ..	I.P.S.	Under Training, CPTC, Abu	7 4 23
70	Shri P.S. Bhinder ..	I.P.S.	S.P. /Keylong	6 4 25
71	Shri J.S. Anand ..	I.P.S.	Comdt, 5th Battalian, P.A.P., Gurdaspur	6 4 25
72	Shri S.S. Brar ..	I.P.S.	Comdt, 25th Battalion, P.A.P., Ajnala	5 4 19
73	Shri Dalbir Singh ..	I.P.S.	Comdt, 27th Battalian, P.A.P., Jalalbad	5 4 19

Serial No.	Name of the Officer	Cadre to which he belongs	Post held	Length of service in I.P./I.P.S.
74	Shri K.K. Zutshi ..	I.P.S.	Comdt, 39th Battalian, P.A.P., (in transit)	M. Y a19 5 4
75	Shri H.C. Jatav ..	I.P.S.	Deputy Commandent, P.A.P., Battalian No. 11	5 4 19
76	Shri Kalyan Rudra ..	I.P.S.	On deputation to Government of India	4 8 07
77	Shri Rattan Lal ..	I.P.S.	On deputation to Government of India	4 8 02
78	Shri H.S. Sekhon ..	I.P.S.	A.S.P./Ambala	3 9 13
79	Shri R.R. Singh ..	I.P.S.	A.S.P./Patiala ..	3 9 18
80	Shri Surjit Singh ..	I.P.S.	A.S.P./Patiala ..	2 8 10
81	Shri P.S. Hura ..	I.P.S.	A.S.P./Ferozepore ..	2 2 23
82	Shri Lachhman Dass	I.P.S.	A.S.P./Ambala ..	2 8 07
83	Shri J.P. Atray ..	I.P.S.	A.S.P.,Amritsar ..	1 8 09
84	Shri Inderjit Singh Bindra	I.P.S.	A.S.P., Bhatinda ..	1 8 09
85	Shri Ramesh Sehgal	I.P.S.	A.S.P., Ferozepore ..	1 8 09
86	Shri R.C. Sharma ..	I.P.S.	A.S.P., Patiala ..	1 8 09
87	Shri Sube Singh ..	I.P.S.	A.S.P., Ambala ..	1 8 05
88	Shri Lekh Ram Bhagat	I.P.S.	A.S.P., Karnal ..	1 6 20

Recommendations of Officers for I.P.S.

2567. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some of the officers of the Police namely D.S.Ps. and S.Ps. were recommended during the period 1st January, 1958 to date by the I.G., Police/Home Minister/ Chief Minister for the I.P.S. Cadre ; if so, their names and their status at present, together with the designation of the recommending authority in each case ;

(b) whether it is a fact that some of the officers referred to in part (a) above were recommended by the I.G., Police/Home Minister and Chief Minister despite adverse enteries in their character rolls; if so, the names of such officers and the reasons, for recommending them ;

(c) the length of service of each of the said officers in the Punjab Police Service at the time of the said recommendation ?

Sardar Darbara Singh : (a), (b) and (c) A statement showing the names of the State Police Service Officers, their present designations the dates of their appointments to the State Police Service and the IPS, together with the length of service at the time of appointment to IPS is placed on the table of the house.

Appointments to the IPS from the State Police Service are made by the Government of India under the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955. A se ection committee consisting of Chairman/Member of the U.P..S.C, Chief Secretary, I.G., and Home Secretary meets every year and considers the names of officers who have completed 8 years of service as D.S.P. on the 1st of January of the year in which the meeting is held, and recommends the names of suitable D.S.Ps. for being included in the Select. List. The State Government forwaids the list to the Union Public Service Commission with its comments. The list as finally approved by the U.P.S.C. becomes the Select List. Appointments to the IPS, are made from the Select List by the Government of India generally in the order in which the names of the officers occur on the list.

Appointments to the junior scale of IPS, under the Special Recruitment Scheme were also made by the Government of India in 1958 in accordance with more or less the above noted procedure.

The entire record of officers is considered by the Selection Committee and the Union Public Service Commission while bringing the names of the officers on the Select List/Special S elect List. It will not be in public interest to disclose the contents of the confidential records of officers.

List of officers of the State Police Service appointed to the I.P.S. since 1st January, 1958 to-date under promotion quota

Serial No.	Name	Date of continuous officiation in State Police service	Date of appointment to I.P.S.	Length of service in State Police service at the time of appointment to I.P.S.		
				Year	Month	Days
1	Shri Rajinder Singh Bhindra, IPS (Retd)	2-9-47	31-5-59	11	8	29
2	Shri Dalip Singh, IPS., SP/Kapurthala	6-6-46	19-11-59	13	5	13
3	Shri Lachhman Dass, IPS (Retd.) ..	8-8-47	15-1-60	12	5	7
4	Shri A.C. Pushong, IPS., AIG/T&T, Pb.	2-8-47	3-8-60	13	0	1
5	Shri Jaswant Singh Bakshi, IPS, S.P./ Vigilance, Punjab ..	12-6-48	10-9-60	12	2	18
6	Shri Bakhtwar Singh, IPS, Comdt, PAP Bn. I ..	30-11-43	11-1-61	17	1	11
7	Shri M.K. Luthra, IPS, S.P./Hissar ..	8-6-48	15-2-61	12	8	07
8	Shri Harpal Singh, IPS, AIG/Traffic, Punjab ..	1-12-42	26-2-61	18	2	25

Serial No.	Name	Date of continuous officiation in State Police service	Date of appointment to I.P.S.	Length of service in State police service at the time of appointment to I.P.S.		
				M.	Y.	D.
9	Shri Daljit Singh, IPS, Comdt, 7th Bn. P.A.P. ..	20-4-41	3-4-61	19	11	13
10	Shri Gurbhagat Singh, IPS., Senior Superintendent of Police, Amritsar ..	2-10-48	6-4-61	12	6	04
11	Shri Ram Sarup, IPS., Comdt. 11 Bn. P.A.P. ..	22-10-48	29-10-63	15	0	07
12	Shri Surinder Nath, IPS, Comdt. 33rd Bn. P.A.P. ..	18-4-48	29-10-63	15	6	11
13	Shri Shiv Dass, IPS, (on deputation to GOI) ..	18-5-48	29-10-63	15	5	11
14	Shri Amar Singh, IPS, SP/Jullundur ..	18-5-48	29-10-63	15	5	11
15	Shri S.S. Palta, IPS, SP/Gurgaon ..	1-11-49	29-10-63	13	11	28
16	Shri Tarlok Singh, IPS, Comdt. 35th Bn. P.A.P. ..	9-8-46	10-1-64	17	5	01

The following five officers were appointed to the Junior scale of IPS, under the Special Recruitment Scheme.

Serial No.	Name	Date of continuous officiation in State Police service	Date of appointment to I.P.S.	M.	Y.	D.
1	Shri Brijinder Singh, IPS, S.P., Karnal	15-1-49	31-7-58	9	6	16
2	Shri Manmohan Singh, IPS (On deputation to GOI) ..	7-3-49	31-7-58	9	4	24
3	Shri Dharam Singh, IPS (On deputation to GOI) ..	20-3-49	31-7-58	9	4	11
4	Shri I.N. Mahajan, IPS (On deputation to GOI) ..	4-4-49	31-7-58	9	3	27
5	Shri Avinash Chandra, IPS, SP/Kangra	1-9-49	31-7-58	8	10	26

The Karnal Co-operative Consumers Stores

2568. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of members of the Karnal Co-operative Consumers Store at present together with its share capital, loan money and other deposits and the date when it started functioning in Karnal Town ;

(b) the names of the Directors of the said Stores together with the names of the directors, if any, who have since been removed stating the reasons for his/their removal ;

(c) whether any person has been recommended by the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Karnal for nomination in place of the Directors who have been removed ; if so, a copy of the recommendations be laid on the Table of the House ;

[Comrade Ram Piara]

(d) whether any correspondence between the said Assistant Registrar and any legislator of Karnal regarding the nomination of any Director has taken place ; if so, a copy of the correspondence be laid on the Table of the House ;

(e) whether any action on the basis of the correspondence referred to in part (d) above has so far been taken ; if so, the details thereof ; if no action has been taken, the reasons therefor ;

(f) the total amount of grant given to the said co-operative consumer store together with the approximate amount of profit earned by it ;

(g) the total number of meetings so far held by the Executive or the Managing body and the General body of the said Co-operative Store, respectively ;

(h) whether the said meetings had been held according to the rules, conventions or other decision ; if not, the reasons therefor together with the action, if any, taken against those responsible for this irregularity ?

Sardar Darbara Singh : (a) to (h) The requisite information as per Statement is enclosed.

STATEMENT

(a) (i) 3,391 on 28th February, 1965.

(ii) Share capital Rs 34,764 on 28th February, 1965.

Government share capital Rs 50,000 on 28th February, 1965.

(iii) Loans—

Central Co-operative Bank, Karnal .. Rs 40,000

Cash Credit .. Rs 1,00,000

State Bank of India .. Rs 6,549.29

(iv) Nil.

(v) 2nd October, 1963

(b) (i) (a) Deputy Commissioner, Karnal—*President*

(b) Assistant Registrar, Co-operative Societies, Karnal.

(c) District Food Controller, Karnal.

(d) Shiri Multan Singh, M.L.A.

(e) Shri B.R. Seth.

(f) Shri Shiv Ram.

(g) Shri Rattan Singh Bedi.

(h) Shri Joginder Singh.

(ii) One Director Shri Kartar Singh was removed from the Board of Directors on 5th February, 1965 as he was arrested by the Police in connection with embezzlement in the Karnal Co-operative Marketing Society. One other Director Shri M.M. Sharma, Welfare Officer of the Central Dairy Research Institute, Karnal, resigned on his transfer from Karnal.

(c) (i) One Shri Tajinder Paul was recommended by the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Karnal for being nominated in place of Shri Kartar Singh.

(ii) A copy of the Assistant Registrar, Karnal's D.O. No. 551/K, dated 8th January, 1965, in this behalf is enclosed.

(d) (i) Comrade Ram Piara, M.L.A., wrote a letter, dated 13th January, 1965, to the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Karnal, in which he inter alia had commented on the recommendations of Assistant Registrar, Karnal, relating to nomination on the Board of Directors of the Karnal Central Consumers Co-operative Store Ltd., fo-

llowing the removal of Shri Kartar Singh. Before receipt of this letter the Assistant Registrar had already made his recommendation to the Registrar Co-operative Societies, in consultation with the Deputy Commissioner, Karnal, who is also President of the said Store.

(ii) A copy of letter dated 13th January, 1965 of Shri Ram Piara, M.L.A., and a copy of letter dated 25th January, 1965, sent by Assistant Registrar, Karnal, in reply to the said letter to Shri Ram Piara, M.L.A., are enclosed.

(e) On the recommendation of the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Karnal, Shri Kartar Singh was removed from the Directorship of the Karnal Central Consumers' Co-operative Store Ltd., by the Registrar, Co-operative Societies but none was nominated in his place. Shri Ram Piara, M.L.A., was duly informed about this fact on 19th March, 1965 by the Registrar, Co-operative Societies.

(f) (i) Managerial and rent subsidy .. Rs 19,800
Purchase of furniture and fixture .. Rs 1,250
(ii) Rs 3,370 up to 31st January, 1965.

(g) Details of meetings held upto 20th March, 1965—

(i) General body .. 1
(ii) Board of Directors/Managing Committee .. 14
(iii) Executive Committee .. 12

(h) According to bye-laws of the Store, general body meeting is to be held once in a year within three months from the close of the co-operative year, Managing Committee meeting once a month and the Executive Committee meetings when considered necessary by the President or the General Manager/Secretary.

No doubt according to provisions in the bye-laws of the Store, Managing Committee meetings are required to be held once a month but in some months these were not held. Such meetings are to be summoned by the President or the General Manager of the Store, if so desired by the President or the Managing Committee. The Managing Committee meetings are now being held regularly in this Store.

Copy

Shiv Avtar Singh Bajwa D. O. No. 551/K

Assistant Registrar,
Co-operative Societies, Karnal

January, 8th, 1965

Subject. —Nomination on the Board of Directors of the Karnal Central Co-operative Consumers' Store Ltd., Karnal

My dear,

Shri Kartar Singh, ex-president, the Karnal Co-operative Marketing-cum-processing Society Ltd., is one of the Directors of the Karanl, Central Co-operative Consumers Store Ltd. Karnal. He is believed to be mainly responsible for huge embezzlements and misappropriations in the Society. As you know the case was reported to the Police Shri Kartar Singh along with others was arrested and is at present on bail. The case is pending in the Court. However, he has committed offence involving dishonesty and under Rule 26 sub-section (f) read with sub-rule 25 subsection (d) he cannot continue on the Board of Directors of the Karnal Central Co-operative Consumers Store Ltd., Karnal.

2. I hope you remember I discussed it with you at the time of your visit to Karnal and you had asked me to contact the Deputy Comissioner in this context and request him to give some other name for nomination to fill up the vacancy caused by the removal of Shri Kartar Singh.

It is recommended that Shri Kartar Singh may kindly be removed and Shri Tajinder Paul be nominated in his place as Director of the Karnal Central Co-operative Consumers' Store Ltd., Karnal. I have discussed the matter with the Deputy Commissioner and my proposal bears his concurrence also.

Yours sincerely,

(Sd.) (Shiv Avtar Singh Bajwa)

[Home and Development Minister]

Shri V. P. Johar, I. A. S.,
Registrar, Co-operative Societies,
Punjab, Chandigarh.

Attested
(Sd.)
Shiv Avtar Singh Bajwa,
Assistant Registrar,
Co-operative Societies, Karnal.

Ram Piara Comrade,
M. L. A.

Phone No. 172,
L/309, Model Town,
Karnal
13-1-65

To

The Assistant Registrar,
Co-operative Societies, Karnal.

Subject.—Co-operative Consumers' Stores, Karnal

Dear Sir,

Please refer to your letter No. 6171/K, dated the 31st December, 1964, and also I want to draw your attention towards my letter dated 26th December, 1964 which stands unreplied for the reasons best known to you.

I have learnt that S. Kartar Singh has been removed from the Directorship of Consumers Stores for which I am grate-ful but do not know, who is to be thanked whether-the Assistant Registrar, D. C. Karnal, or Registrar/Joint Registrar Chandigarh. Any how it is a good step which must be appreciated. G. M. is also being changed and this step is also good.

I presume that you must have taken some decisions in the interest of Consumers Stores in your meeting which was proposed to be held on 7th January and if taken, I should have been informed at least on the points raised by me in my letter, dated 1st December, 1964 and further in my letter dated 26th December, 1964.

Now I have learnt that you are proposing the name of one Tejinder Singh or of the son of late Ch. Randhir Singh, Advocate, to be nominated Director in the vacancy caused by the removal of Shri Kartar Singh.

If it is correct, it is really very surprising for me that how it has come to your mind except an attraction towards a moneyed man. Do you find any co-operative character in him/them. Have you tried to find out the antecedents of this family at least in the Co-operative side Do you know that both the Societies (Man Brothers Co-op. Farming Society and Karnal Co-op. Multipurpose or something) of this family were wound up under orders of the Government.

Do you know that late Ch. Randhir Singh, Advocate, had to resign from the Directorship of the Panipat Co-op. Sugar Mill on account of certain lapses. No doubt the family and group has certain dominance on the Bank but that does not give licence. Even today this Tejinder Singh is facing a trial of tax evasion of his Card Board factory. Ch. Randhir Singh is not in this world now otherwise on these about the irregularities and lapses can easily be written. I do not want to write much more on this.

Hence in no way I think that your proposal for Tejinder Singh or the son of Shri Randhir Singh or of his family member or any other whose antecedents are not good or whose any society is defaulter, is be fitting to the time and not the least tolerant for me.

After all this Co-op. Movement is mainly for the benefit of common man. Cannot you find any commoner who may devote some time, may save the store from loss and has his antecedents satisfactory. This capitalistic trend on this sacred movement shall have to be ignored at all. I do not want to suggest any name but certainly have my right to object to the inclusion of undesireables. If any undesireable is to de substituted by another undesirable then what reform do you expect ?

You have rightly pointed out in para 5 of your letter of 31st that as far as you are aware the G. M. has not been charge-sheeted. A contradiction has already been published in the Nagar Pukar that he has been reported against in that and not charge-sheeted so far. I have the least hesitation in withdrawing that and accepting my folly where I get the correct information but some times in some cases information is not posted by certain Officers and in this connection I must say that I should have been informed clear in position in furtherance of your own letter and of my letter already pointed above.

It is good that on your proposal now the Board of Directors shall meet every month and you will do your best that the Consumers Store does not loose the confidence. The result of this can be good profit as well as the maintenance of prices.

I hope to receive a detailed reply so that I may be able to satisfy many quarters.

In the end, I may again assert that some other such suitable personnel may be suggested whose antecedents are not bad and whose contribution can be a bit useful to the Consumers Stores.

Hoping to be favoured with an acknowledgement at the earliest and detailed reply within the reasonable time.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Sd.) Ram Piara, M.L.A.

You have perhaps ignored the advice of the H. Q. in connection with the Karnal Co-op. Marketing Society, I do not know why and so I had to remind and further point out certain more irregularites and also of the D. W. S. for which the Registrar has deputed Deputy Registrar, Rohtak, vide his letter No. MKG/MAI/10-DWS/343, dated 2nd January. 1965.

(Sd.)
Ram Piara.

Copies to :

(1) Registrar, Co-operative Societies, Chandigarh.

(2) Deputy Commissioner, Karnal.

Attested

(Sd.) Shiv Avtar Singh Bajwa,

Assisstant Registrar, Co-operative Societies, Karnal.

No. 1101/K, dated Karnal, the 25th January, 1965.

From

The Assistant Registrar,
Co-opeartive Societies, Karnal.

To

Shri Ram Piara Comrade,
M. L. A.,
L/309-Model Town, Karnal.

Subject.—Co-operative Consumers Store, Karnal.

Memorandum

Please refer to your letter dated 13th January, 1965. In my letter dated 31st December, 1964, I have replied to some of the points raised in your letter dated 26th December, 1964, also and I had requested you to come and discuss any thing you like

[Home and Development Minister]

regarding the working and present position of the Karnal Central Co-oprative consumers Store Ltd., Karnal. But you neither came nor wrote back anything in this connection. I have to request you again to come and see me whenever convenient to you. I will be simply glad to discuss anything you like and I am confident that you will have a different impression of the Stores after you have met me.

2. It is also to inform you that whatever action I have taken in respect to the Karnal Co-op. Marketing-cum-Processing Society Ltd. now under winding up orders has the approval of the higher officers and I have no hesitation to say that information passed on to you is incorrect.

(Sd.) . . .
Assistant Registrar,
Co-operative Societies,
Karnal.

No. 1102/K, dated Karnal, the 25th January, 1965.

Copy to the Deputy, Commissioner, Karnal, for favour of information with reference to his endst. No. 134, dated 16th January, 1965 (enclosed).

(Sd.) . . .
Assistant Registrar,
Co-operative Societies,
Karnal.

Attested

(Sd.) Shiv Avtar Singh Bajwa,
Assistant Registrar,
Co-operative Societies,
Karnal

Appointments of Superintendents, etc. in the Office of the Financial Commissioner, Revenue

2569. Chaudhri Ran Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the total number of posts of Assistants, Deputy Superintendents and Superintendents filled in the office of the Financial Commissioner, Revenue, after the 12th September, 1963 to date together with the date(s) on which these were filled, categorywise ;

(b) the total number of posts among those mentioned in part (a) above reserved for the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, etc., categorywise ;

(c) whether all the said posts mentioned in (b) above have since been filled up by promoting members of the Scheduled Castes etc., if so, their names categorywise ;

(d) if the reply to part (c) above in respect of any of the said categories of services be in the negative, the reasons therefor ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) The total number of posts of Assistants/Deputy Superintendents/Superintendents filled in *by promotion* in the Financial Commissioner's Office after 12th September, 1963 to date together with the dates on which these were filled are, categorywise, given in the enclosed statement.

(b) (i) Assistants .. 4
(ii) Deputy Supeiintendents .. 1
(iii) Superintendents .. 1

	Part first	Part Second
(c) (i) Assistant	No.	Question does not arise
(ii) Deputy Superintendents	Yes	Shri Mani Ram
(iii) Superintendent ..	No.	Question does not arise

(d) (i) Assistants .. Appointment to the posts of Assistants are made as a result of passing the Assistant Grade Test held by the S. S. S. Board. None of the officials who qualified the test belonged to Scheduled Castes, etc. Hence no one could be promoted against the reserved post of Assistant

(iii) Superintendent .. Matter is under consideration

STATEMENT

Serial No.	Category	Number of posts filled in by promotion	Date of filling of post
1	Assistant ..	6	13-9-63
2	Do ..	1	19-9-63
3	Do ..	4	9-3-64
4	Do ..	4	10-4-64
5	Do ..	2	18-4-64
6	Do ..	3	30-4-64
7	Do ..	2	16-5-64
8	Do ..	4	21-9-64
9	Do ..	4	29-9-64
10	Do ..	1	13-10-64
11	Do ..	1	20-1-65
	Total ..	32	

[Minister for Revenue]

Serial No.	Category		Number of posts filled in by promotion	Date of fillig of post
1	Deputy Superintendent	..	4	28-4-64
2	Ditto	..	1	11-5-64
3	Ditto	..	1	9-11-64
4	Ditto	..	1	22-2-65
	Total	..	7	
1	Superintendent	..	1	7-3-64
2	Do	..	1	9-3-64
3	Do	..	1	24-3-64
4	Do	..	1	21-4-64
5	Do	..	1	20-2-65
6	Do	..	1	2-7-64 *2-1-65
	Total	..	6	

*The official was re-promoted after reversion.

P. S. S. (Class II) Service Rules

2570. Chaudhri Ran Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether the P. S. S. (Class II) Service Rules for the office of the Financial Commissioner, Revenue, have since been framed ; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(b) if the reply to part (a) above be in negative, the title of the rules applicable to the said service and a copy thereof be laid on the Table of the House ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Part first—No. These are being framed.

Part Second— Does not arise.

(b) The Punjab Civil Services Rules, which are applicable to the categories of Government employees, who are under the administrative control of the Punjab Government and whose pay is debitable to the Consolidated Fund of the State of Punjab, are also applicable to the members of P. S. S. (Class II) Service of the Office of the Financial Commissioner, Revenue. These rules are contained in the Punjab Civil Services Rules (Volume I - III), the copies of which are available in the library of the Vidhan Sabha.

Buses plying on certain Routes

2572. Sardar Kulbir Singh, Chaudhri Satya Dev: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of buses being plied on (i) Dabwali to Fazilka, (2) Abohar to Ganga Nagar ; (3) Abohar to Malout ; (4) Abohar to Hanumangarh routes by the private transport companies ;

(b) the names of the partners of the said companies, the registration number of each bus plying on each of the said routes, separately, along with their time-tables on these routes ;

(c) the number of the Punjab Roadways buses plying on the routes mentioned in part (a) above along with the time-table being observed on each route, separately ;

(d) whether the 50 : 50 formula has been fully implemented on the above routes ?

Shri Ram Kishan : (a) to (d) A statement is enclosed.

STATEMENT

(a) The number of trips plied on the following routes are as under:—

(1)	Dabwali-Fazilka	.. No direct service
(2)	Abohar-Ganga Nagar	.. 17
(3)	Abohar to Malout	.. 2
(4)	Abohar-Hanumangarh	.. 2½

(b) The names of the partners of the said companies and the registration No. of vehicles along with their time-tables are given below :—

Name of the Company	Names of the share-holders
Fazilka-Dabwali Transport Co., Abohar	1. Shri Daulat Ram Nagpal
	2. Shri Shankar Dass Nagpal
	3. Shri Milkhi Ram Nagpal
	4. Shri Madan Lal Nagpal
	5. Shri Manohar Lal Nagpal
	6. Shri Krishan Lal Nagpal
	7. Shri Shiv Charan Dass Nagpal
	8. Shri Jagdish Chander Nagpal
	9. Shri Parma Nand Ahuja

Name of Company	Names of share-holders
Fazilka-Dabwali Transport Co., Abohar—*concld*	10. Shri Ved Parkash Ahuja
	11. Shri Subash Chander Satia
	12. Shri Nathu Ram Narang
	13. Shri Bhopinder Rai Narang
	14. Shri Naunihal Singh
	15. Shri Mathra Dass
	16. Shri Vassan Dai
	17. Shri Shankar Dass Satia
	18. Shri Ramesh Chander Satia
Janta Transport Co-op. Society, Abohar	1. Shri Banwari Lal
	2. Shri Ram Partap
	3. Shri Jagraj Singh
	4. Shri Raja Ram
	5. Shri Hanuman
	6. Shri Indubala
	7. Shri Hari Ram
	8. Shri Dhaunkal Ram
	9. Shri Dev Karan
	10. Shri Balwant Singh
	11. Shri Brij Lal
	12. Shri Sada Sukh
	13. Shri Mani Ram
	14. Shri Hari Ram
	15. Shri Ram Chand
	17. Shri Krishan Kumar
	18. Shri Lalpat
	19. Shri Hira Lal
	20. Shri Inderjit
	21. Shri Het Ram
Abohar Pursharthi Transport Co-op. Society Ltd., Abohar	Annexure 'A'
Jai Transport Co-op. Society Ltd., Abohar	Annexure 'B'

(ii) Name of the Company	Registration No. of vehicles held	
Fazilka Dabwali Transport Co., Abohar	PNR-1983 PNF-6086 PNF-6087 PNF-6255 PNF-6258 PNF-6454 PNF-6455 PNF-6496 PNF-6626 PNF-6748 PNF-6749 PNF-6774 PNF-6775 PNF-6776 PNF-6800 PNF-6801 PNF-6824 PNF-6845 PNF-6846 PNF-6862 PNF-6996 PNF-7979 PNF-9645 PNF-9646	(The company has a sanctioned fleet of 24 vehicles and any vehicle on any route sanctioned to them out of the said fleet can be plied).
Janta Transport Co-op. Society, Abohar	PNF-6848 PNF-6807 PNF-5547 PNF-5548 PNF-6964 PND-234 PND-236 PNF-9708	(The society has a sanctioned fleet of 8 vehicles and any vehicle on the routes sanctioned to them out of the said fleet can be plied
Abohar Pursharthi Transport Co-op. Society Ltd., Abohar	PNF-6851 PNF-9562	
Jai Transport Co-op. Society Ltd., Abohar	PNF-3566	

(iii) Name of the Company	Name of the route	Time-table	
Fazilka-Dabwali Transport Company	Abohar-Ganga Nagar	*Abohar*	*Ganga-Nagar*
		6.15	9.00
		12.00	11.30
		14.00	14.30
	Abohar to Malout ..	*Abohar*	*Malout*
		14.15	9.00
		17.00	17.45

Name of the Company	Name of the Route	Time Table	
		Abohar	*Hanumangarh*
	Abohar—Hanumangarh	Services on Abohar-Hanumangarh route are operating in rotation with Rajasthan operators. The time-table of the joint route is approved by Rajasthan Transport authorities, as the share of Rajasthan State is 12 trips and 5 of Punjab State	
		Abohar	*Ganganagar*
Janta Transport Co-operative Society, Abohar	Abohar—Ganganagar ...	7.20 9.15 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30	7.45 9.45 11.30 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.15
		Abohar	*Ganganagar*
Abohar Pursharthi Transport Co-operative	Abohar-Ganganagar ...	13.00 18.15	10.30 15.30
		Abohar	*Ganganagar*
Jai Transport Co-operative Society	Abohar-Ganganagar ...	10.00 15.00	12.30 16.45

	Time-table		No. of buses
(c) (1) Dabwali to Fazilka ...	Nil		Nil
	Abohar	*Ganganagar*	
(2) Abohar to Ganganagar ...	16.45	8.15	One
	Abohar	*Malout*	
(3) Abohar to Malout ...	9.00 13.40	14.45 15.50	One
	Abohar	*Hanunmahgarh*	
(4) Abohar to Hanumangarh ...	16.10	7.45	One
	(1½ return trip is being operated in rotation with private operators).		

(d) Yes, to the extent done in the case of other routes.

ANNEXURE 'A'

List of members or Share-holders of the Abohar Pursharthi Co-operative Transport Society Limited, Abohar, as on 25th March, 1965

Serial No.	Name of the Member	Father's name
1	Shri Ganpat Ram	... Shri Sohan Lal
2	Smt. Saraswati	... W/o Ganpat Ram
3	Shri Ganpat Ram	... Shri Rati Ram
4	Shri Mani Ram	... Shri Kanha Ram
5	Shri Dalip Singh	... Shri Ganpat Ram
6	Shri Hanuman Dass	... Shri Ganpat Ram
7	Shri Ganpat Ram	... Shri Jai Raj
8	Shri Jung Singh	... Shri Partap Singh
9	Shri Sheo Karan	... Shri Ram Rakha
10	Shri Raja Ram	... Shri Sohan Ram
11	Smt. Raismi Devi	... Widow of Phoola Ram
12	Shri Gopi Ram	... Shri Hira Ram
13	Shri Bhajan Lal	... Shri Ganesha Ram
14	Shri Kanshi Ram	... Shri Ganga Ram
15	Shri Gopi Ram	... Shri Kumbha Ram
16	Shri Harnaik Singh	... Shri Gian Singh
17	Shri Rattana Ram	... Shri Kaloo Ram
18	Shri Prahlad	... Shri Ganesha Ram
19	Shri Sohan Lal	... Shri Raisma Ram
20	Shri Ganpat Ram	... Shri Ram Lal
21	Shri Mani Ram	... Shri Ram Karan

ANNEXURE 'B'

List of members or Share-holders of the Jai Transport Co-operative Society Limited, Abohar

Serial No.	Name of the Member	Father's name
1	Shri Bachan Singh	... Kapoor Singh
2	Shri Mohan Singh	... Kapoor Singh
3	Shri Jaspal Singh	... Bachan Singh

[Chief Minister]

Serial No.	Name of the Member		Father's name
4	Shri Baldev Singh		Bachan Singh
5	Shri Mohinder Singh	..	Mohan Singh
6	Shri Rajinder Singh	..	Mohan Singh
7	Shri Jarnail Singh	...	Nazar Singh
8	Shri Surjit Singh	..	Nazar Singh
9	Shri Mukhtiar Singh	...	Kartar Singh
10	Shri Sher Singh	...	Mal Singh
11	Shri Bagar Singh	...	Mal Singh

Electrification of villages in Block Khuyan Sarwar, district Ferozepore

2575. Chaudhri Satya Dev : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the villages in Block Khuyan Sarwar, district Ferozepore, scheduled to be eletrified during the year 1964, have not been electrified so far; if so, the reasons therefor ;

(b) whether the villages Chuhriwala Dhanna, Patrewala, Dametwala, Khiyanwali, etc. in the said Block are proposed to be electrified during 1965; if so, the time by which work for the electrification of each village is likely to be started and completed separately ;

(c) whether in addition to the villages mentioned in part (b) above which are at a distance of 1½ miles from the Electric Line, any other villages in the said Block are proposed to be electrified during the year 1965; if so, their names ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No programme for the Electrification of fresh villages during the year 1964-65, had been finalised by the Board due to paucity of funds. As such no particular villages were scheduled to be electrified during 1964-65.

(b) and (c) No. The electrification of villages during 1965-66 depends upon the availability of funds for rural electrification. At present nothing can be said regarding the time by which the above said villages will be electrified.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWERS

Government Securities

***8142. Sardar Gurbaksh Singh :** Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state —

(a) the amount invested by the Government in the Government Securities as it stood immediately before the present Ministry took over charge ;

(b) the total amount invested in the said Securities as at present ;

(c) whether there is any decrease in the investment in such securities; if so, the reasons therefor and the manner in which the amount withdrawn from the said investment has been utilised and the authority under which it has been utilized ?

Sardar Kapoor Singh : (a) Rs 10,92,61,900
(b) Rs 13,33,69,000

(c) There is no decrease in the investment since the present Ministry took over charge.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਕੀ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਗ 'ਬੀ' ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ 13 ਕਰੋੜ ਦਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 19 ਕਰੋੜ -ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ 19 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 19 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਦਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। (Perhaps he is allergic to No. 10.) (Laughter)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਅਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁਛ ਲਵਾਂਗਾ।

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : Comrade Babu Singh Master.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਤੁਸੀਂ ਹੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਉ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29 ਔਰ 30 ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਬਾਰੇ। (Both the Call Attention notices at Nos. 29 and 30 relate to an identical subject regarding Indian Observer).

They are admitted. Perhaps the Government would like to make a statement.

मुख्य मन्त्री : उस पर होम सैक्रेटरी की तरफ से कार्यवाही हो रही है। हम जानते हैं कि उस में बड़ी फोहश बातें आती हैं। उसके बारे में रूल्ज़ के मुताबिक हम जो भी कार्यवाही कर सकते होंगे ज़रूर करेंगे।

कुछ आवाज़ : जल्दी करो।

(*Chief Parliamentary Secretary rose to make a statement.*)

Mr. Speaker : The Chief Minister has already made a statement.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਿਚ ਬੜੀ ਫਿਲਥੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। Government is competent to ban its entry in the State.

Mr. Speaker : The hon. Member may please take his seat.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ।

Chief Minister : Home Secretary is taking action in the matter.

Mr. Speaker : Next Call Attention Notice (No. 31) is in the name of Sarvshri Mohan Lal Datta and Om Parkash Agnihotri.

श्री श्रोम प्रकाश श्रग्निहोत्री : स्पीकर साहिब, अभी तक तो हमें कोई काल अटेंशन मोशन सरकुलेट नहीं हुई । किसी को सरकुलेट नहीं हुई । अगर आप इजाजत दे दें तो जबानी पढ़ देता हूं ।

Mr. Speaker : I will look into it and take appropriate action. There is another call attention motion in the name of the hon. Member.

श्री श्रोम प्रकाश श्रग्निहोत्री : अभी तक तो कोई सरकुलेट नहीं हुई । इसकी कापी भी नहीं दी गई ।

Mr. Speaker : We will take these Call Attention Notices on the next day.

Next Call Attention Notice (No. 34) is in the name of Sardar Ajaib Singh Sandhu.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I beg to draw the attention of the Government to the fact that burning of Shri Guru Granth Sahib at Doraha caused great resentment in Sikh Circles by a mischief of so me anti-social element. The matter needs immediate action and enquiry into this unsacred action of some mischief monger. Hence the notice of Call Attention Motion is served.

Mr. Speaker : This is admitted. Government may please make a statement.

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, हमें खुद इस बात का बड़ा दुख है । जिस भी शख्स ने, शरारती आदमी ने ऐसा नाज़ेबा और कमीना फेल किया है हम उसकी पूरी तरह से मुरम्मत करते हैं । हालात को दरियाफत करने की हमने कोशिश की है और आई० जी० की हम ड्यूटी लगा रहे हैं.............

सरदार गुरनाम सिंह : यह तो दोराहा की बाबत है ।

मुख्य मन्त्री : दोराहा का केस तो रजिस्टर हो गया है और उसकी इन्क्वायरी भी आर्डर हो गई है । डी० सी० ने जूडीशल इन्क्वायरी आर्डर करा दी है ।

Mr. Speaker : Then it is all right.

The next Call Attention Notice (No. 33) is again in the name of Sardar Ajaib Singh Sandhu.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I beg to draw the attention of the Government towards the act of great sacrilige that has been done by the authorities at Ludhiana by forcibly pulling the Granthi and stopping the Akhand Path of Shri Guru Granth Sahib. This action of the authorities caused great resentment in Sikh circles . The matter being of utmost importance in view of the law and order situation of the State needs immediate attention of the House.

Mr. Speaker : This is admitted.

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, इस सम्बन्ध में आई० जी० इन्क्वायरी कराएंगे । जिस वक्त हमें यह इतलाह मिली थी उसी वक्त डी० आई० जी० सी० आई० डी०, डी० सी० और एस० पी० को डिप्यूट किया गया । हमें अफसोस है कि ऐसा वाक्या हुआ है । इस की पूरी तरह से तहकीकात करके हम हाउस के सामने स्टेटमेंट दे देंगे ।

PRESS REPORTS OF THE PROCEEDINGS OF THE HOUSE

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : स्पीकर साहिब, मैं आज आप से एक बात जरूर करना चाहता हूं । उस के बारे में मैंने न तो काल अटैनशन मोशन का नोटिस देना मुनासिब समझा और न ही प्रिविलेज मोशन का । मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि असेम्बली की जो प्रोसीडिंग्ज प्रैस में आती है आप को उसका कोई न कोई मयार जरूर रखना चाहिए । प्रैस के अन्दर इस हाउस की प्रोसीडिंग्ज की बड़ी फेथफुल रीप्रोडक्शन होनी चाहिए और उस में किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए । मैं हैरान हुआ कि टीचर्ज के यहां पर कुछ मुतालबात थे उनके बारे में आनरेबल मैम्बर साहिबान ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया और उस सिलसिले में मैंने भी कुछ बातें इस हाउस में अर्ज कीं. . .हायर सैकंडरी सिस्टम के बारे में भी और यूनिवर्सिटी के बारे में भी लेकिन ट्रिब्यून के इशु में उसका कोई जिक्र तक नहीं आया । ऐसे ख्यालात का इज़हार करने वालों का जिक्र तक नहीं आया। ट्रियून एक आला पाए का अखबार है लेकिन मुझे हैरानी हुई कि अगर यहां पर फ्रंट बैंचिज पर बैठने वाले मेम्बरान की स्पीचिज के साथ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है तो बाकियों के साथ क्या होता होगा । हम आम तौर पर देख रहे है कि दो मेम्बरज का नाम आ जाता है और दो को छोड़ दिया जाता है । और फिर मेम्बरों की स्पीचिज को पूरी तरह से कवर भी नहीं किया जाता । जो टीचर्ज की डिमांडज के साथ हमदर्दी का इज़हार किया गया उस बारे में किसी के ख्यालात का जिक्र तक नहीं किया गया । इस लिए मैं इस बात को आप के नोटिस में लाना जरुरी समझता था कि आप को किसी तरह की कोई लाईन रखनी चाहिए । कई बार ऐसा होता है कि कोई मेम्बर बड़े अच्छे ढंग से अपने ख्यालात रखता है लेकिन जो दो चार लाइनें अखबारों में दी जाती है उन में उन बातों को लाया नहीं जाता। इसलिए मैं प्रिविलेज का सवाल इस लिए नहीं लाया क्योंकि यह प्रैस गैलरी का मामला है । यह आप के और उन के दरम्यान की बात है । मेरा ख्याल है कि आप उन से इस सिलसिले में बात करेंगे और वह एक अच्छी लाईन आफ ऐक्शन इस में एडाप्ट करेंगे ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਅਗੇ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

बाबू बचन सिंह : स्पीकर साहिब, मेरी यह सबमिशन है कि आप के महकमे को एक अफसर इस डियूटी पर लगाना चाहिए जो यह देखे कि इस असेम्बली की जो प्रोसीडिंगज हों वह फेथफुली और कोरैकटली प्रैस में आती हैं कि नहीं आतीं हैं और वह आप को रिपोर्ट करे । अगर किसी प्रेस में गलत छपी हों और जिस अखबार में वह गलत छपी हों उस को आप बुला कर अपने चेम्बर में कह सकें। मेरे ख्याल में इतना ही काफी होगा ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहिब, मेरी यह गुजारिश है कि हम जो बैंक बैंचिज पर बैठते हैं उन को अव्वल तो बोलने के लिए बहुत कम चान्स मिलते हैं और अगर हमें कुछ टाईम मिलता है तो जो बात हम यहां पर कहते हैं वह प्रेस में बिल्कुल नहीं छापी जाती। इस लिए ढिल्लां साहिब ने जो प्वायंट उठाया है वह बड़ा रीज़नेबल है है और आप इस बारे में मुनासिब कार्यवाही करें ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

श्री अध्यक्ष : सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने जो प्वायंट रेज़ किया है यह एक बड़ा इम्पार्टेंट प्वायंट है लेकिन इस बारे में हम कहां तक प्रेस वालों को डाईरेक्शन्ज़ ईशू कर सकते हैं इस चीज को एग्ज़ामिन करना पड़ेगा । लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्रेस के मेम्बरान हैं, जिन को हम परमानेंट कार्ड ईशू करते हैं, उन से मैं आशा करता हूं कि वह बड़ा फेथफुली यहां की प्रोसीडिंग्ज को रिप्रोडियूस करेंगे और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे और ऐसे नहीं होने देंगे कि अगर कोई इम्पार्टेंट स्पीच हो तो वह रह जाए और दूसरे माईनर प्वायंटस छापे जाएं। आयंदा के लिए वह इस बात का ध्यान रखेंगे । जहां तक हम कोई इनस्ट्रकशन्ज़ ईशू कर सकते हैं इस बारे में मैं प्रेस वालों से भी और कुछ मेम्बर साहिबान से भी सोच विचार कर लूंगा ।

(The point raised by Sardar Gurdial Singh Dillon is a very important cne. But in this ccnnection we will have to examine the extent to which we can issue directions to the Press. However, I feel and expect from the members of the Press to whom permanent passes have been issued that they will reproduce the proceedings of this House faithfully and without any discrimination. They will also take care in future that no important speech is omitted whereas minor points thereof are given publicity. As regards issue of instructions and the extent to which this can be done, I shall disscuss the matter with the Press Gallery Committee and certain Members of the House.)

बाबू बचन सिंह : थैंक यू, सर ।

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब, आप ने उस दिन यह रूलिंग मेरी काल एटेन्शन नोटिस पर दी है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी एक अटानोमस बाडी है इस लिए गवर्नमेंट उस की अन्दरूनी वर्किंग में दखल नहीं दे सकती लेकिन वहां पर स्टूडेंट्स हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि ला स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम परसों शुरू होने वाले हैं लेकिन आज तक उन को अपने रोल नम्बर नहीं मिले । उन में से बहुत सारे लड़कों ने अपने घरों के एड्रेस दे रखे हुए हैं जो गांव में रहने वाले हैं । भला उन को कैसे वक्त पर रोल नम्बर पहुंच सकेंगे क्योंकि परसों तो उन के इमतहान शुरू होने हैं और आज तक यह जारी नहीं किए गए । इस तरह ला स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती हो रही है और ....

श्री अध्यक्ष : आप को मेरी रूलिंग मिल गई है कि नहीं मिली ? (Has the hon. Member got my ruling or not ?)

श्री जगन्नाथ : वह तो मिल गइ है लेकिन मैं यही आप के जरिए हाउस और गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहता हूं कि उन के साथ वहां पर बड़ी ज्यादती की जा रही है ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : स्पीकर साहिब, यह मामला यूनिवर्सटी का अन्दरूनी मामला है क्योंकि वह आटानोमस बाडी है ।लेकिन यह जो इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है मैं समझता हूं कि यूनिवर्सटी ने उन की बात मान ली थी कि इमतहान परसों शुरू किए जाएं लेकिन अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि डेट शीट को दुरुस्त किया जाए । इस बारे में अभी पांच सात दिन ही हुए हैं कि यह फैसला हुआ था ।

श्री जगन्नाथ : रोल नम्बर तो उनको मिलने चाहियें जो आज तक नहीं मिले ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹ ਹਨ ? (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ।

श्री अध्यक्ष : क्योंकि यूनिवर्सटी एक आटानोमस बाडी है इस लिए इस की डे टु डे वर्किंग में गवर्नमेंट दखल नहीं दे सकती । यहां यह मामला तब ही उठाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट इस की जवाब देह हो। (As the University is an autonomous body, the Government cannot interfere in its day-to-day working. This matter can only be raised here if the Government is answerable therefor.)

Otherwise the Government cannot interfere in the working of the Universities. The matter cannot be taken up here so far as the technical aspect is concerned. That motion cannot be admitted. But I do feel that there are certain serious matters which have come to my notice also and they are not being attended to by the Universities. I hope, the Government will take due notice of those things and somehow get into touch with the Universities to get all such matters settled.

DEMANDS FOR GRANTS

35-INDUSTRIES. (Demand No. 22)
(Demand No. 46)

96-CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Chief Minister (Shri Ram Kishan) : Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs 2,57,40,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head '35-Industries'.

[Chief Minister]

That a sum not exceeding Rs 1,99, 24,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66 in respect of charges under head '96-Capital Outlay on Industrial and Economic Development'.

Mr. Speaker : Motions moved—

That a sum not exceeding Rs 2,57,40,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66 in respect of charges under head '35-Industries.'

That a sum not exceeding Rs. 1,99,24,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66 in respect of charges under head '96-Capital Outlay on Industrial and Economic Development'.

I have received notices of cut-motions from the various hon. Members. These will be deemed to have been read and moved—

1. **Comrade Babu Singh Master :**

2. **Comrade Bhan Singh Bhaura :**

That the demand be reduced by Rs. 100

3. **Comrade Ram Chandra :**

That the demand be reduced by Rs. 10

4. **Shri Rup Singh Phul :**

That the demand be reduced by Re. 1

5. **Chaudhri Ran Singh**

That the demand be reduced by Re. 1

6. **Shri Babu Dayal Sharma :**

That the demand be reduced by Re. 1

Guillotine will be applied at 5.00 p.m.

श्री मंगल सेन : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर सर। स्पीकर साहब, मैं ने 26 तारीख को काल एटेनशन का नोटिस दिया था जिस में कहा था कि ज़िला ग्रमृतसर में वहां बलाक समितियों ग्रौर ज़िला परिषद के चुनाव के लिए चार समगलरों को रिहा किया गया है। स्पीकर साहब, एक तरफ तो यह गवर्नमेंट समगलर्ज़ को चुनाव लड़ने के लिये रिहा कर रही है ग्रौर ऐसा करने में पब्लिक से डरती नहीं है ग्रौर दूसरी तरफ हमारे देश के गृह मन्त्री रोज़ कहते नहीं थकते कि एडमिनिस्ट्रेशन में से कुरप्शन को दूर करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह कुरप्शन नहीं है कि इन्होंने जो समगलरों को चुनाव लड़ने के लिये छोड़ दिया है ?

श्री ग्रध्यक्ष : मेरी रूलिंग इस बारे में ग्राप के पास पहुंच गई है न ? (Has the hon. Member received my ruling in this connection ?)

श्री मंगल सेन : रूलिंग तो पहुंच गई है लेकिन आप देखें न—

श्री अध्यक्ष : नो प्लीज़ । (No, please)

बाबू बचन सिंह : स्पीकर साहब, आप ने फरमाया है कि पांच बजे गिलोटिन एप्लाई हो जाएगी लेकिन मेरी अर्ज़ है कि इण्डस्टरी एक बड़ा अहम स्बजेक्ट है और इस का पंजाब के फियूचर के साथ बड़ा सम्बन्ध है और मैं यह भी जानता हूं कि आज गिलोटिन भी ज़रूर होनी चाहिए मगर इस पर डिसकशन के लिए अगर आप एक घंटा सिटिंग बढ़ा दें तो बेहतर होगा ।

Chief Minister : I have no objection.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the sitting of the Assembly be extended by one hour ?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : But there are some meetings of the Partliamentary Association. Those meetings will have to be postponed.

All right, the duration of the sitting of the House is extended by one hour.

Guillotine will now be applied at 6.00 P.M.

श्री निहाल सिंह (महेन्द्रगढ़) : स्पीकर साहब, अभी अभी चीफ मिनिस्टर साहिब ने मूव किया है कि इण्डस्ट्रीज़ के लिए 2,57,40,300 रुपए की एक रकम और 1,99,24,000 रुपए की दूसरी रकम मन्ज़ूर की जाए कैपीटल आऊट-ले आन इण्डस्ट्रियल एण्ड इकनामिक डिवैल्पमैंट के लिए ।

स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि पंजाब ने इन्डस्ट्री में जितनी तरक्की पिछले चन्द सालों में की है वह काबिले फख्र है । हिन्दोस्तान के इन्डस्ट्रियल मैप पर पंजाब का जिक्र बड़ी अहम जगह रखता है । इस नई सरकार ने इन्डस्ट्री को बढ़ाने के लिये जो सब से अच्छा काम किया है वह यह है कि इस महकमे के काम को एक ऐसे अफसर के हाथ में दिया है जिस को हम पैप्सू से जानते हैं कि उस की इस बारे में कितनी कन्ट्रीब्यूशन है ।

स्पीकर साहिब, अब मैं अर्ज करता हूं कि पंजाब ने कौन सी इन्डस्ट्री में और कितनी तरक्की की है । इस सिलसिले में मैं आप के सामने कुछ फिगर्ज रखना चाहता हूं कि जिन से यह पता चलेगा कि पंजाब में यह काम किस रफतार से चल रहा है । अगर शूगर की पैदावार को देखें तो पता चलेगा कि जहां हम सन 1955-56 में 22514 टन शूगर पैदा करते थे वहां सन 1962-63 में हम ने 62804 टन पैदा की । फिर सीमेंट जो हम पहले तीन लाख 43 हजार टन पैदा करते थे वह 6 लाख 22 हजार टन तक पहुंच गया । इसी तरह से अगर हम पेपर और काटन टैक्सटाइल्ज़ को देखें तो पता चलता है कि दूसरी प्लैन के एंड से लेकर तीसरी प्लैन के एंड तक इन की पैदावार दुगनी या तिगुनी हो गई है ।

जहां तक स्माल स्केल इन्डस्ट्री का ताल्लुक है उस में पंजाब ने सारे हिन्दुस्तान में एक माना हुआ दर्जा हासिल किया हुआ है । दूसरी स्टेटस से अगर मुकाबला किया जाए तो यह बड़ी काबिले फख्र बात है । पंजाब में दूसरी प्लैन के खात्मे पर 3866 फैक्टरीज़ रजिस्टर्ड थीं जबकि तीसरी प्लैन के ऐंड तक इन की तादाद 5200 हो जायगी । अगर इन

[श्री निहाल सिंह[

फैक्ट्रीज़ की आउटपुट को देखें तो यह दूसरी प्लैन तक 123 करोड़ रुपए की थी यह तीसरी प्लैन के आखीर तक 180 करोड़ हो जायगी। सूती कपड़ा भी हम पहले से ज्यादा तैयार करने लगे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम ने स्माल सकेल इन्डस्ट्री में बड़ी तरक्की की है।

मगर जहां तक हैवी इन्डस्ट्री का ताल्लुक है उस में पंजाब को बहुत कम शेयर मिला है। सारे हिन्दुस्तान में हैवी इन्डस्ट्री के सैंट्रल प्राजैक्टस पर 2,130 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है जिस में से पंजाब को सिर्फ 30 करोड़ रुपया ही मिला है और अगर परसैंटेज निकालें तो यह सिर्फ 1.4 बनती है। मैं पंजाब सरकार से अर्ज़ करता हूं कि इस बारे में हमें हिन्द सरकार को ऐपरोच करना चाहिए कि जो पंजाब को हैवी इन्डस्ट्री के सिलसिले में इगनोर किया हुआ है इस कमी को चौथी प्लैन में पूरा किया जाए और इस तरह से पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा हैवी इन्डस्ट्री लोकेट कराने के लिये कोशिश करें।

स्पीकर साहिब, तीसरी प्लैन में हम ने स्माल स्केल इन्डस्ट्री को सिर्फ दो करोड़ के करीब रुपया कर्ज़ दिया। पंजाब में स्माल सकेल इन्डस्ट्री की तादाद को देखते हुए और इस बारे में लोगों के जोश को देखते हुए यह रकम काफी नहीं है। सूबे में इस बात की बड़ी मांग है कि उन को कर्ज़ मिले और वह नए कारखाने लगा सकें। सरकार को इस तरफ जल्द ध्यान देना चाहिए।

स्पीकर साहिब, जहां तक टैक्नीकल ऐजुकैशन का ताल्लुक है दूसरी प्लैन में सरकार ने इस पर 170 लाख रुपया खर्च किया। इस के मुकाबिले में अकेले मौजूदा साल ही के लिये जिस का कि हम बजट पास करने जा रहे हैं 174 लाख रुपया खर्च करने की विचार है। इस तरह से आप देखें कि इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमैंट ने काफी तरक्की की है। मगर इस बारे में मैं यह बात कहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इस बारे में जो खर्च किया जाए वह सारे सूबे में बराबर 2 बांट कर किया जाए। हम देखते हैं कि महकमा की जो इन्डस्ट्री लगाने की स्कीम्ज़ हैं वह ऐसी हैं कि जहां पर इन्डस्ट्रीज़ पहले से लगी हैं वहां पर ही नई भी लगाई जाएं। इन की इस पालिसी की वजह से नए इलाकों में इन्डस्ट्रीज़ शुरू करने वालों को ऐनकरेजमैंट नहीं मिलती बल्कि उन को डिस्करेजमैंट मिलती है। इस महकमें ने ऐसा क्रायटीरिया फिक्स किया हुआ है कि जहां पर पांच सात साल पहले कोई इन्डस्ट्री चलती थी उन लोगों को ही कोटा दिया जाता है, दूसरा अगर कोई नया काम करना चाहे तो उन को कोटा नहीं मिलता। आप जानते हैं कि हमारे बैकवर्ड इलाके में पहले से कोई इन्डस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं हैं। अब अगर उस इलाके पर यह बेस यीअर वाली शर्त लागू हो तो वहां वालों को न तो कोटा और न ही लाइसैंस मिल सकता है। इस पालिसी का नतीजा यह निकलता है कि उस इलाके में इन्डस्ट्री नहीं लग सकती। इसी तरह की एक और शर्त है जिस से उस बैकवर्ड इलाके को नुक्सान पहुंचता है। वह यह है कि कोटा जो मिलता है वह सेल बेसिज़ पर मिलता है। जिन लोगों को पहले हो कोटा कम मिलता है उन को कहा जाता है कि चूंकि आप की सेल कम है इस लिये आप को फरदर कोटा नहीं मिलेगा। तो जब तक यह क्राइटेरिया मुकर्रर है हमारा इलाका तरक्की नहीं कर सकता। इन दोनों शर्तों से हमारे इलाकों को नुक्सान पहुंचता है, वहां पहले ही इन्डस्ट्री नहीं है और नई लग नहीं सकती। इस लिए दरखास्त है कि बैकवर्ड इलाकों के हक में इस पालिसी में तब्दीली की जानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को भी इन्डस्ट्री लगाने का मुनासिब मौका मिल सके।

इस इन्डस्ट्रीज़ महकमे का एक और पहलू है जिस का ज़िक्र करना चाहता हूं। दफतर जो महकमे का है उस में यह तरीका नहीं है कि जो नई इन्डस्ट्री लगाने की स्कीम पहले आई है उस को पहले सैंक्शन किया जाए। इन के पास जब कोई स्कीम कोई इन्डस्ट्रिलिस्ट ले कर आता है तो वह दफतर वालों को अपनी स्कीम देता है। जब यह दफतर वालों के पास पहुंचती है तो नीचे वाले कुछ लोग अपने दोस्तों को उस स्कीम की नक्ल करवा देते हैं तो इस तरह से जिस ने वह स्कीम इनीशियेट की होती है उस को तो बैकग्राउंड में रख दिया जाता है और जिस की मदद करनी होती है, जिस को उस को नक्ल करवा दी गई होती है, उस की स्कीम एपरूव कर दी जाती है।

तो मैं यह चाहूंगा कि एक रैगूलर रजिस्टर मेनटेन किया जाए। जो कोई भी नई स्कीमें इन्डस्ट्री डिपार्टमैंट में आएं इस रजिस्टर में दर्ज की जाएं और इस के मुताबिक ही सब को प्रायर्टी दी जाए। अगर किसी की स्कीम में कोई कमी रह गई हो या कोई टैक्नीकल फला रह गया हो तो पहले उसी पार्टी को मौका मिलना चाहिए ताकि वह उस टैक्नीकल कमी को पूरा कर दें और जब तक वह पूरा न करें दूसरे किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज कल इस तरह से नहीं किया जाता और एक गलत बात चल रही है जिसको दरूस्त करने की जरूरत है।

स्पीकर साहिब, एक बात मैं अपने ज़िले के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। वह पिग आयरन प्लांट के बारे में है। इस के लिये सारे का सारा कच्चा माल, ए-मैटिरियल तो महेन्दरगढ़ ज़िला में मिलता है लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से बजट स्पीच में इस बात का एलान किया गया है कि इस को 7 करोड़ रुपया की लागत से हिसार में कायम किया जा रहा है। और यह जो स्कीम है और प्रोजैक्ट है इस को प्राइवेट सैक्टर में कारखाना लगा कर कायम किया जा रहा है। मेरी राए है कि जब इस तरह का कोई हैवी प्राजैक्ट लगाया जाना हो तो सारे एकनामिक एसपैक्टस को स्टडी करने की ज़रूरत है। एकनामिक वायाबिलिटी को जानने की ज़रूरत है। हमारे ज़िला महेन्द्रगढ़ में सारा रा मैटियर्ल मौजूद है। लाइम स्टोन है और आयरन ओर भी बड़ी भारी मिकदार में है। इस के बावजूद 5 करोड़ रुपया कारखाने पर हिसार ज़िले में खर्च करने जा रहे हैं। फिर बाहिर से जो माल आएगा वह महेन्द्रगढ़ में भी आ सकता है और सस्ता रहता है। मैं ने रेलवे वालों से भी दरयाफत किया है कि जो कोयला बिहार से आएगा वह महेन्द्रगढ़ में सस्ता पड़ेगा। आयरन ओर और लाइम स्टोन यहां पर भी सस्ता मिलता है। इन सब बातों के होते भी अगर कारखाने को महेन्द्रगढ़ में ना बना कर दूसरी जगह बनाना हो तो मेरे इलाके के लोगों से सरासर ज़्यादती होगी। इन लोगों की आर्थिक हालत को सामने रख कर भी इस तरह का फैसला नहीं करना चाहिए था। इतना कच्चा माल होते भी कारखाना को हिसार में कायम करने से इस मेरे इलाके के लोगों में रोष है और वह एजीटेटिड फील करते हैं। फिर हिसार में इस कारखाने को कायम करने के हक में यह दलील दी जाती है कि यह मीटर गेज पर है। स्पीकर साहिब, इस में मीटर और ब्राड गेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप से अर्ज़ करूं कि सैंट्रल गवर्नमैंट भिलाई की तरह का एक कारखाना कापर का नारनौल से 30 मील दूर खेतड़ी में मीटर गेज पर ही बनाने जा रही है। खेतड़ी कापर प्राजैक्ट पर कई करोड़ की लागत से एक नया टाऊनशिप भिलाई की तरह का कायम किया जा रहा है और हिन्दुस्तान में सब से बड़ा कापर का प्राजैक्ट होगा। अगर इतने बड़े प्राजैक्ट में मीटर गेज़ की कोई रुकावट नहीं तो समझ नहीं आता कि हमारे इस छोटे से पिग आयरन

[श्री निहाल सिंह]

प्राजैक्ट प्लांट के लिए मीटर गेज की क्या रुकावट है। यहां पर यह कहना ना वाजब नहीं होगा कि महेन्द्रगढ़ के लोगों को इस बात की तसल्ली करवानी चाहिए। और इन्हें कानफीडेन्स में लेना चाहिए कि क्या कारण है कि इस कारखाने को महेन्द्रगढ़ से दूसरी जगह ले जाया गया है। वहां के लोग सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं कि इस कारखाने को उनके इलाके में ही कायम किया जाना चाहिए। और अगर इस कारखाने को कायम करने में कोई खास दिक्कत है जिसका उन्हें पता लग जाए तो इस के इलावा उन्हें आलटरनेट दूसरी इन्डस्ट्री दी जानी चाहिए। वहां पर रा मैटिरियल है, लाईम स्टोन बहुत है और दो मील के फासला पर राजिस्थान का इलाका है उस में भी लाइम स्टोन है जो कि मंगवाया जा सकता है। इस लिए मैं यह समझता हूं कि यह महेन्द्रगढ़ का इलाका सीमैंट की फैकटरी के लिए मौजुं है। वहां पर जिस मिट्टी की ज़रूरत है वह भी मौजूद है और लाइम स्टोन भी है। और इतना बाअफरात है कि और जगह नहीं मिल सकता। इस लिए इस इलाके में सीमैंट की फैक्टरी लगाने का फैसला करना चाहिए। फिर सीमैंट हमारे डिवैल्पमैंट के कामों के लिए ज़रूरी है और जितना कन्सट्रकशन का काम हो रहा है इस फैक्टरी के होने से और तेज़ हो सकता है।

इस के इलावा, मैं स्पीकर साहिब, एक अर्ज़ मिनरलज़ के बारे में करना चाहता हूं। मिनरल्ज़ महेन्दरगढ़ में बहुत होती है और थोड़ी कांगड़ा जिला में होती हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्डस्ट्री डिपार्टमैंट की स्लैकनेस की वजह से सरकार को नुक्सान हुआ है। और इस की कोई हद नहीं। पिछले 6 साल से इस तरह हो रहा है। पहले 6 या 7 लाख रुपया सरकार के खज़ाने में रायल्टी के तौर पर और लीज़ मनी की शकल में जमा होता था। लेकिन सरकार ने रूल्ज़ ऐसे बना दिए हैं कि 6 लाख की बजाए अब 20 हज़ार रुपया सालाना सरकार को मिलता है। या तो मैं समझता हूं कि रूल्ज़ पर अमल नहीं किया जाता या उन रूल्ज़ को उठा कर उनकी जगह दूसरे रूलज़ रख दिए गए हैं। और तो और, पिछले साल इस महकमे ने माइन्ज़ और क्वेरीज़ को नीलाम किया और 3 लाख रुपया सरकार को मिला जहां कि पहले सिर्फ 20 हज़ार ही आता था। लेकिन इस बात को 8 महीने हो चुके हैं और महकमा का तरीका कार यह है कि आज तक इस को फाइनेलाइज़ नहीं किया गया। शर्त यह थी कि रुपया उस डेट से वसूल होगा जिस डेट से लैसीज़ के साथ एग्रीमैंट मुकम्मल होगा। नीलाम लेने वाले कोई एक आदमी नहीं। 200 रुपया पर किसी ने लीज़ लिया है किसी ने 1 हजार पर और किसी ने 10 हज़ार पर लीज़ लिया है। लेकिन सारे के सारे लीज़ अभी तक धरे पड़े हैं। और आज तक सरकार की तरफ से एग्रीमेन्ट पूरा नहीं हो सका। इस का यह असर पड़ा है कि जिन लोगों को रोज़गार मिलना था वह नहीं मिल सका। क्वारीज़ बेकार पड़ी है और इल-लीगल तरीके से एक्सक्वेशन्ज होती हैं। इस लिए मैं अर्ज़ करूंगा कि माइन्ज और मिनरेल्ज़ के रूल्ज़ को अमेन्ड किया जाए। कागज़ यहां से वापिस चले जाते हैं, कभी किसी एतराज़ पर कभी किसी एतराज़ पर कि खसरा नम्बर गलत है कहीं कटिंग पर दस्तखत रह गए हैं। इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस लिए इस तरह के इख्तियार डी.सी. को या डिस्ट्रक्ट इन्डस्ट्री अफसर को दे देने चाहिएं कि वह सब फारमेलेटीज़ को पूरा कर के एग्रीमेन्ट साइन कर सकें ताकि सरकार को नुक्सान न हो। महकमा का तो यह हाल है कि इनको आप को भी खसरा नम्बर वगैरा का पता नहीं। नीलामी के वक्त

ज़मीन चाही के तौर पर नीलाम कर दी तो वहां मौके पर जा कर देखा तो वह पहाड़ था। जब डी.सी. को कागज़ पेश किए गए तो उस ने कहा कि चलो मौका देखें। तो जहां पर कागज़ात पर पहाड़ था वहां मौके पर चाही कूंआ था। इस से साफ़ ज़ाहिर है कि महकमा ने पूरी तरह से सर्वे नहीं किया। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ता कि जो देरी एग्रीमेन्ट को पूरा करने में लग रही है उसे दूर किया जाए।

एक बात टाइम्ज़ के बारे में, स्पीकर साहिब, आप की मार्फत अर्ज़ करना चाहता हूं। सरकार ने बगैर किसी इलाके की आबोहवा को देखे और हालात को देखे फलैट तरीका से दफतरों का वक्त 10 से 5 तक कर दिया है। यह टाइमज़ मेरे ज़िला महेन्द्रगढ़ को सूट नहीं करते। हमारे हां अब जो यह टाइम्ज़ बदल दिए गए हैं, इस से हमारे इलाका का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं किया गया। जिन इलाकों में 10–11 बजे के बाद बाहिर निकलना भी मुश्किल होता है, इतनी लू चलती है वहां पर काम तो क्या, ठहरा भी नहीं जा सकता। दफतर का क्या काम हो सकता है? जब से इस इलाके में इस तरह के टाईम रखे गये हैं इस से इस इलाके में बड़ी परेशानी हो गई है। मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से यह अर्ज़ करूंगा कि अगर वहां पर 10 से 5 बजे तक का ही टाईम रखा गया तो दफतरों में कोई काम नहीं हो सकेगा। ना कोई हमारे हां Air conditioned Building है और ना ही हमारे दफतरों में कूलर वगैरा लगे हुए हैं। इस लिये मेरी यही गुज़ारिश है कि मई, जून और जुलाई के लिये अगर टाईम 7 बजे से $1\frac{1}{2}$ बजे तक कर दिया जाए तो ठीक होगा। आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

Mr. Speaker: I would like to draw the attention of the hon. Members to Rule 97 i. e.—

(iii) shall bow to the Chair while entering or leaving the Assembly, and also when taking or leaving his seat;

(iv) shall not pass between the Chair and any Member who is speaking, nor between the Chair and Table of the Assembly ;

(v) shall not leave the Assembly when the speaker is addressing it ;

(vi) shall always address the Chair ;

बहुत सारे मैम्बर जब स्पीकर बोल रहा होता है, क्रास करने की कोशिश करते हैं। यह एक ना मुनासिब बात है। मैम्बर साहिबान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं यह डिफीकलटी भी महसूस करता हूं कि मिनिस्टर के लिये यह बड़ा मुश्किल है कि वह जो आये उस से बात न करे। यह मैम्बर साहिबान को चाहिए कि वह बोलने वाले और चेयर को क्रास ना करें। अगर कोई ऐसा करेगा that will be my unplesant duty to check it. अगर कोई मैम्बर दरम्यान में आयेगा तो उसको वापिस अपनी सीट पर जाना पड़ेगा। किसी भी मैम्बर को अब से 15 मिनिट से ज्यादा टाईम बोलने के लिये नहीं दिया जायेगा। (When the Speaker is on his legs, many hon. Members try to cross the floor. This is not proper and they should be careful to avoid this. I realise the difficulty of a Minister as it is well nigh impossible for him to refuse to talk to an hon. Member who comes to him. However, it is incumbent on the Members that

[Mr. Speaker]

they should not cross the floor between the Chair and the Member who is speaking. If anybody does so it will be my unpleasant duty to check it. If any Member, who so ever he may be, crosses the floor, he shall have to go back to his own seat. The next thing, they may bear in mind is that no hon. Member will be given more than 15 minutes each to speak.)

श्री मंगल सेन: आप ने बजा फरमाया है। हम आपके हुकम की तामील करेंगे। मगर मिनिस्टर साहिब को भी कहें कि वह कम से कम अपना नम्बर तो बढ़ा लें। लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ भीड़ लगी रहती है। अगर ज्यादा हो जाएंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा और हम भी उन के पीछे नहीं पड़ेंगे।

श्री स्पीकर: मैं ने आपकी रैफरेंस उन के पास आन कर दी है। (I have passed on the reference of the hon. Member to him.)

ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ (ਫਗਵਾੜਾ): ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71,11,046 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਲਟੀਵੇਟਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੇਬਰਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼, ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 65 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ 44.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ 79.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿਚ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅਜ ਸਨਅਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੋਂ ਭਾਰ ਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਨਅਤੀ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 15 ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ planning towards share in the management ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ

ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇ। ਤਦ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧ ਫੁਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ, ਕਪੜਾ, ਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਅੜਚਣ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਰਾ-ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਈਂਧਨ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈਵੀ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਗੁਡਜ਼, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ 2130 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਥਰਡ ਫਾਈਵ ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਰਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 30 ਕ੍ਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕੁਲ ਆਊਟਲੇ ਦਾ 1.4 ਪਰਸੈਂਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਫਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਪੀ. ਏ. ਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 34 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਦਊਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ, 1963 ਵਿਚ ਇਕ ਜਗਾਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਿਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ 262 ਰੁਪਿਆ ਕਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਮੇਂਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਚਾਬੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਕ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੋ ਚਾਬੀਆਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵਜੋਹ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ। Rules and orders regarding handling etc. of cash had not been observed.

There are also irregularities in regard to the grant of loans and subsidies under the Punjab State Aid to Industries Act, 1935.

ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

[ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ]
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਲੀ ਰੁਪਿਆ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਟਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫੀ ਮੁਰੱਬਾ ਗਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਦਿਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਖ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਸ਼ੈਡ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 150 ਰੁਪਿਆ ਮਾਹਵਾਰ ਰਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸੂਦ ਹੀ ਸੂਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਕਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 150 ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਟਾਊਨਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 1/5 ਹਿੱਸਾ ਰੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ 6 ਸਪਿਨਿੰਗ ਔਰ ਵੀਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਰੂਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਪਿਨ ਹੋ ਕੇ ਇਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਿੰਨਿੰਗ ਔਰ ਵੀਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਗੁਡਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਰਟਾਲਾਈਜ਼ਰ, ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਵਾਂਗ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡਿਸਕਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਉ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਉਠਣ ਲਈ ਸੋਫੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਟ੍ਰਾਂਸ-ਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਉ ਤਾਂ ਟੁਟੇ ਫੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। (ਘੰਟੀ)

ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰਲੂਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਅਗਸਤ, 1964 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਇਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿਲਿਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀ. ਏ. ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ 4 ਮਾਰਚ

ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 75 ਪਰਸੈਂਟ ਗੰਨਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਥੇ ਅਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਾਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਤੀਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਾਈ ਮਗਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਣੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵਈਆ ਰਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਭੈਰੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪਾਲੀਸੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ।

Mr. Speaker : Please resume your seat now.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ (ਸਮਾਣਾ ਐਸ. ਸੀ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮਗਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਚਾਰਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਸ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 50 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੱਥੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਫੁਲਦੀ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਜਗਾਹ ਐਸੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਡ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਗੁਸਲਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟਸ ਐਸੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਉਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ। ਮਾਲੇਰ ਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿਤਨੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਵਧ ਫੁਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇਸ ਗਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ]

ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵੇ ਐੇਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸੂਦ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕਈ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨ, 1963 ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾਈ ਜਾ`? 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਟੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਇਨੈਂਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੂਦ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੂਦ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਏਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਨੇ ਆਨੰਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੰਬਈ ਨਾਲ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਚਦਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੱਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ 20—30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਦਰਾਂ ਭੇਜ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੱਦਰਾਂ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਦਰਾਂ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਲੇਕਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ 11 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਦਾ ਸੂਦ ਖਾਈ ਜਾਉ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੋ। ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ 29 ਫੌਂਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ 1964 ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਫੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੈਡ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੇਲਜ਼ ਗਰਲਜ਼ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਨਬਾ-ਪਰਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਮਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਨਤੀਜਾ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁਛਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਈ। ਜਿਤਨੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 150—300 ਦੇ ਗਰੇਡ ਦਾ ਸਟੈਨੋਗਰਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸੈਕਟਰੀ 700 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 500 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਰਖੇ ਹਨ। ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਣ ਲਈ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਂਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਚੱਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਬ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਨੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ ਲੇਕਨ ਅੱਜ ਐਨਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਨਦਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਕਢ ਕੇ ਇਸ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਕ ਫਲੈਚਰ ਸਾਹਬ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਿਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਖਣ ਵਿਚ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਬ ਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਾਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ. ਸੀ. ਸ਼ੀਟਸ ਦਾ 8 ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰਾਜ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। (ਚੀਅਰਜ਼) ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਗੈਰਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਕਲੀਅਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਅਤ ਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਕਈ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। (ਚੀਅਰਜ਼) ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਜਾਉ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕੋਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। (ਘੰਟੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕਾਠ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਕ 70—80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਈ ਪੁਛਣ ਲਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਡੂ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ]

ਮਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਘੜੇ ਦੀ ਚਪਣੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੈਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਡੁਬ ਕੇ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ-ਕਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਜਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਚੀਅਰਜ਼) ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਇੰਨਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਉ। (This demand does not relate to the formation of Ministry but to the Industry. The hon. Member may, therefore, confine his speech to the demand under discussion. He should now resume his seat.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਲੜਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬੇਮਾਇਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਘੰਟੀ) ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਜੋ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। (ਘੰਟੀ)

कामरेड राम प्यारा (करनाल): स्पीकर साहिब, पंजाब गवर्नमेंट सोशलिज्म लाने के लिए committed है और इस नुक्ता निगाह से इन्डस्ट्री ऐसा महकमा है जिस के ज़रिए अमीर और गरीब में जो इतना भारी फर्क है उसे कम किया जा सकता है अगर इस महकमा की तरफ से रा मैटीरियल, कोटाज़, परमिट्स, लोन्ज़ और दीगर सहूलतों की डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि अगर 10/15 साल की इस महकमा की वर्किंग को देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ है जिस का नतीजा यह हुआ है कि जिनके पास एक इन्डस्ट्री थी उनके पास 10 हो गई हैं और जिन के पास नहीं थीं वह अब भी उसी तरह खाली हाथ बैठे हैं। पंजाब में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्टस हैं जिन्हें हर बात में ही पूछा गया और दूसरे किसी आदमी को इन्सैंटिव नहीं दिया गया। उन्हीं आदमियों को नए इंडस्ट्रियल प्राजैक्ट सैट अप करने के लिए रिकमैंड किया गया और चाहे उन्होंने कोई नई इन्डस्ट्री सैट अप नहीं की मगर उनको कोटे परमिट और लाखों के इम्पोर्ट लाईसेंस दिए गए जो उन्होंने बलैक में बेचे लेकिन इसके बावजूद वह परमिट कैंसल नहीं होते और न उनको कोई पूछता है।

असल बात यह है कि वह इण्डस्ट्रीयलिस्ट इतने पावरफुल और रिसोर्सफुल हैं कि वह छोटे से लेकर बड़े तक चाहे प्रताप सिंह हो चाहे कामरेड राम किशन हो सब को खरीद सकते हैं । मैं नहीं कहता कि कामरेड को खरीद लिया है लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उन इंडस्ट्रियलिस्टस के रिसोर्सिज इतने हैं कि बड़े बड़े आदमियों की आंखें चुन्धिया जाती हैं कि यह जो इतना रुपया है शायद हमारे इलैकशन में काम आए या और कहीं मदद मिल सके । मैं इस बारे में एक तजबीज देता हूं कि जितने कोटे और परमिट दिए हुए हैं उन सब को scrutnise करने के लिए कि वह ठीक यूज हो रहे हैं या नहीं गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए ताकि जहां जहां मिस युटलाईजेशन हो रही है वहां के कोटे कैंसल किए जाएं और इसके अलावा जहां बहुत ज्यादा कोटे दिए हुए हैं उनको कुछ कम किया जाए और छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्टस को दिए जायें जिस से उनका रोज़गार भी चले न कि बड़े आदमी और बड़े होते चले जायें । मिसाल के तौर पर जिंक कापर सटेनलैस सटील के कोटे हैं जो एक एक आदमी को 20/30 टन तक मिले हुए हैं । एक टन सटेनलैस सटील में 8 हज़ार रुपए तक बचत हो जाती है तो अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो 20/30 टन एक आदमी को देने की बजाए 2 टन दिया जाए और इस से एक फैमली का गुज़ारा चल सकता है । जब तक आप पिछली गवर्नमेंट के खड़े किए हुए मीनारों को खत्म नहीं करेंगे बेरोजगारी और गरीबी का मसला हल नहीं हो सकता । इस के साथ एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जो पंजाब के सारे जिलों में जा कर देखे कि कहां कौनसा रा मैटिरियल अवेलेबल है और उसके मुताबिक कहां कौनसी इन्डस्ट्री लगानी चाहिए ताकि उन ,इलाकों की तरक्की हो । इस के अलावा देखा गया है कि जब अंडर डिवैलपड और बैकवर्ड एरियाज को डिवैलप करने की बात होती है तो वहां के ही रहने वाले लोगों को उसके लिए सहूलतें नहीं दी जाती है । इण्डस्ट्री लगानी हो तो अमृतसर से लोग उठा कर सोनीपत बिठा दिए जाते हैं और गुरदासपुर से लोगों को भठे लगाने के लिए करनाल लाया जाता है । इस तरह करने से तो उन इलाकों की तरक्की नहीं हो सकती है । अगर वाक्या ही आप चाहते हैं कि अंडरडिवैलपड इलाकों की तरक्की हो तो वहां के ही लोगों को सारी सहूलतें मिलनी चाहिए । मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं । यहां पंजाब में गनौर के पास भारत ट्यूब्ज फक्टरी लगी हुई है । मेरी इतलाह है और मैं कह नहीं सकता कि वह गलत है या सही है लेकिन चीफ़ मिनिस्टर साहिब जो आपने कमरे में सुन रहे होंगे इस बात की तरदीद करें अगर मेरी इतलाह गलत है । मेरी इतलहा के मुताबिक उस के लिए जो प्लांट मंगाया गया था उसकी दो तीन दफा जो फारन कंट्रीज से कुटेशनज आई वह थोड़ी थीं । फिर उसके लिए साबिक डायरैकटर इन्डस्ट्रीज़ को उनको लाने के लिए भेजा गया तो उस वक्त कई लाख रुपया उस में और ऐड कर दिया गया और फिर मशीनरी मंगाई गई । फिर पंजाब के फिनांस डिपार्टमेंट के सैक्रेटरी और इन्डस्ट्रीज़ के सैक्रेडरी उसकी मैनेजिंग कमेटी के मैम्बर हैं ।

मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहता हूं कि उस में इंडियन करंसी का कितने लाखों का नुक्सान हुआ है । स्पीकर साहिब, मैं ने चीफ मिनिस्टर साहिब को

[कामरेड राम प्यारा]

4 नवम्बर को चिट्ठी लिखी थी इस का सबजैक्ट भारत टयूब्ज इंडियन करंसी और केरों फैमली था । इस का कोई जवाब नहीं आया । मैं ने 3 दिसम्बर को फिर चिट्ठी लिखी उस का सबजैक्ट भी यही था । 15 दिसम्बर को चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया उस में लिखा है कि

"Thank you for your letter of the 3rd December, 1964, on the subject noted above. I am having the matter looked into."

स्पीकर साहिब, साढ़े तीन महीने हो चुके हैं । मुझे पता नहीं कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस के बारे में कुछ देखा है या कि नहीं । दिल्ली में एक बहुत ही इम्पार्टेंट आदमी जिस का नाम सरदार नौनक सिंह है, मुझे यकीन है कि हिन्दुस्तान से बहुत सी करंसी फारेन मुल्क में भेजी गई है और यह लाखों रुपए में है । मैं जानता हूं कि सरकार इस बारे में यहां पर कोई बयान नहीं देगी । यह रुपया फैकटरी के प्लांट के खरीद के सिलसिल में है । मैं अर्ज कर रहा था पंजाब गवर्नमेंट के दो आफिसर, एक फिनांस सैक्रेटरी और दूसरा इंडस्ट्रीज सेक्रैटरी, इस मैनेजिंग कमेटी के मैम्बर हैं । जब तक वह कोई बयान नहीं देते उस वक्त तक मैं कोई आगे बात बताने के लिए तैयार नहीं हूं । हो सकता है कि मेरे बयान देने से वहां पर फाईल्ज टैम्पर हो जाएं । मैं सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस कनसर्न को रिलीफ भी दिया, शेयर्ज़ अन्डर राइट किए थे ताकि उन को इंन्सेंटिव मिल सके और सरकार ने जो शैयर्ज इन के बिके नहीं थे, वह खरीद लिए थे । सरकार सिर्फ चन्द मोटे मोटे इंडस्ट्रयलिस्टों को रिलीफ देना चाहती है । रिलीफ देने की फेयर डिस्ट्रिब्यूशन सरकार तक पहुंचनी चाहिए । जितनी इंडस्ट्रीज़ की डिवैल्पमेंट हुई है, उस के लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं । इस वक्त चन्द आदमी ही इंडस्ट्रीज से फायदा उठा रहे हैं जैसा कि यहां पर श्री आर. के. सोनी का नाम लिया गया है । अगर उन्होंने एक लाख रुपए चन्दे के रूप में दिया होगा तो सरकार ने उस के एवज लाखों रुपए का काम होजरी और वूलन गुडज के बनाने के लिए दिया । गवर्नमेंट बड़े आदमियों को ही पैट्रोनाईज कर रही है । गरीब आदमियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है । सरकार का असूल तो यह होना चाहिए कि छोटे आदमियों और गरीब आदमियों की मदद करे ताकि वह अपना रोजगार कमा सके । यहां बेकारी दूर हो । अमीर और गरीब के दरम्यान फर्क कम हो । लेकिन आज हालत यह है कि अमीर और गरीब के दरम्यान फर्क पहले से बढ़ता जा रहा है । देश की बदकिस्मती है कि कुछ इंडस्ट्रीयलिस्टस इतने मजबूत हो गए है कि अफसर भी उन के सामने कहने की हिम्मत नहीं रखते । मुझे एक डिस्ट्रक्ट हैडक्वाटर्ज के अफसर ने कहा था कि कामरेड साहिब, यहां पर पुलिस कप्तान और डिप्टी कमिश्नर को कोई नहीं पूछता है । क्योंकि इंडस्ट्रीयलिस्टों का सीधा सम्बन्ध आई. जी., चीफ सैक्रेटरी, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहिब के साथ है और उनके काम टैलिफोन के द्वारा हो जाते हैं चाहे वह काम गलत भी हो । स्पीकर साहिब, कौन नहीं जानता कि लुधियाना में सेल्ज टैक्स इन्कम टैक्स वालों ने कहीं पर छापा मारा तो वहां पर अफसरों की ही पिटाई हुई थी और कुछ नहीं बना ।

25, 26 लाख रुपए अब कैरों फैमिली के जिम्मे थे और इसी तरह से लाखों की संख्या में सेल्ज टैक्स था जो कि अब वसूल किया गया है। लेकिन उस वक्त सेल्ज टैक्स इन्कम टैक्स के अफसर और बाकी के अफसर्ज़ बोल नहीं सकते थे। अगर यह सरकार कोई क्रेडिट लेना चाहती है तो वह ढिलमिल की पालिसी छोड़ दे क्योंकि पिछली गवर्नमेंट के मुताबिक बसों में, होटलों में यही चर्चा है that the Government is a nin compoop Government जब इस सरकार को लोग निनकम्पूप कह रहे हैं मैं इस को रिजिस्ट भी नहीं कर सकता हूं और कंट्राडिक्ट भी नहीं कर सकता हूं। अगर यह सरकार चाहती है कि प्रोपोगंडा बन्द हो तो सरकार को हिम्मत से काम लेना होगा।

सरकार बड़े बड़े आदमियों को ही सबसिडी दे कर फायदा पहुंचा रही है। सरकार छोटे आदमियों को इंसैंटिव नहीं देना चाहती है। मेरी सजैशन है कि सरकार गांवों में लोगों को 500 रुपए भैंस खरीदने के लिए दे ताकि वह भैंस खरीद कर दूध इकट्ठा कर कर मिल्क पैस्चेराईज प्लांट को दें। इस से गरीब आदमियों को भी रोजगार मिल सकेगा और यह इंडस्ट्री भी अच्छी तरह से पनप सकेगी। गवर्नमेंट इन गरीब आदमियों को तो देना नहीं चाहती लेकिन इस के बिपरीत बड़े बड़े इंडस्ट्रयलिस्टों को तो लाखों की तादाद मे रुपया दे देती है और वह रुपया वापस भी नहीं मिलता है। सरकार उन से नुक्सान उठा सकती है लेकिन जिन को असूली तौर पर फायदा पहुंचना चाहिए उन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता यहां तक कि बड़े इंडस्ट्रीलिस्टों से काफी संख्या में वसूल नहीं किया जाता है। सरकार इस खिसारे को बर्दाशत करने के लिए तैयार है लेकिन 500 रुपए भैंस खरीदने के लिए नहीं देना चाहती है। सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए।

पंजाब में राईस पालिश से तेल निकालने की कुछ फैक्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं। इस के मुताबिक तेल निकालने के बाद खलें जो बचती है, वह फारेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रही है। वहां पर खली पोलटरी के लिए इस्तेमाल हो रही है। यहां पर राईस पालिश को पोल्टरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर फारेन कंट्रीज खली से गुजारा कर सकते हैं तो हमें भी खली यहां पर इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह नैशनल वेस्ट है। तेल का क्या हो रहा है? यहां पर तेल निकाला जाए। मैं पंजाब सरकार से डिमांड करता हूं कि पंजाब सरकार सेंट्रल सरकार से जो इस के लिए दो फैक्ट्रीज लगाने के लिए मांग कर रही है, वह दोनों फैक्ट्रीज करनाल जिला में लगानी चाहिएं। करनाल जिला चावल की पैदावार में सब से अव्वल है। मैं कहना चाहता हूं कि चावल की पैदावार में यह जिला कई जिलों के मुकाबले में बहुत ही आगे है। इस लिए यह फैक्ट्रीज़ करनाल में ही लगाई जानी चाहिएं। करनाल जिला का 80, 85 मील खादर एरिया है जिस में गन्ना बहुत ही पैदा होता है। जगाधरी और पानीपत शूगर मिल्ज इस गन्ने को उठा नहीं सकती हैं। इस लिए करनाल जिले में शूगर मिल बहुत जरूरी लगानी चाहिए। इस से किसानों

[कामरेड राम प्यारा]

को फायदा होगा । वहां पर रोजगार बढ़ेगा और पंजाब में खांड की पैदावार भी अधिक होगी । इस तरह से बेकारी भी दूर होगी और लोगों का स्टेंडर्ड आफ लिविंग ऊँचा होगा ।

(*Deputy Speaker in the Chair*)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कुछ कहना भूल गया था । मैं भारत ट्यूबज के बारे अर्ज़ करना चाहता हूं । गवर्नमेंट ने इस फैक्ट्री के लिए 127 एकड़ जमीन एक्वायर की थी । इस वक्त तक इस फैक्टरी वालों न ज़्यादा से ज़्यादा 27 एकड़ जमीन इस्तमाल की है । उन के पास अभी तक 100 एकड़ जमीन तीन साल से बन्जर, गैर-आबाद और गैर-काश्त पड़ी हुई है । इस से पंजाब को बहुत नुक्सान हो रहा है । यहां जनता दाने दाने के लिए मुहताज हो रही है । गवर्नमेंट को चाहिए कि इस फैक्ट्री के लिए जितनी ज़मीन दरकार हो वह दे देनी चाहिए और बाकी की ज़मीन उन लोगों को वापस कर देनी चाहिए जिन की यह थी ताकि वह काश्त करके वहां पर अनाज पैदा कर सकें । इस के साथ मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि वह फैक्टरी वालों से दरयाफत करे कि उन्होंने 3 साल से इतनी जमीन क्यों बर्बाद कर रखी है क्योंकि वहां पर अगर अनाज पैदा किया जाता तो काफी अनाज पैदा होता और जनता को लाभ होता । इंडस्टरी वाले जो डिफरेंट ब्लाक हैडज़ पर बैठे हैं अगर लोन उन की डिसपोजल पर हो तो छोटे छोटे एरियाज में पांच पांच सात सात सौ रूपया लोन दे कर लोगों का म्यार ऊंचा किया जा सकता है और लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं । बहुत सारे टैक्सिज़ कनज्यूमर्ज़ पर लगे हुए हैं । लेकिन जिन लोगों ने इतनी बड़ी कमाई बलैक मार्किट और स्मगलिंग के जरिए की है उन पर सिवाये इनकम टैक्स के कोई टैक्स नहीं है । जब हम कहते हैं तो कहा जाता है कि उन के कोटे में कट नही लगाया जा सकता । अगर उन के कोटे में कट नहीं लगाया जा सकता और सिवाए इनकम टैक्स के उन पर और कोई टैक्स भी नहीं लगाया जा सकता तो इस तरह से लाखों रुपया उन के पास बलैक मनी का होता है । उन रुपयों से वे लोग बड़े बड़े आदमियों का इमान गिराते है, स्टेट को डीमोरेलाईज किया जाता है, पोलिटीकल लाईफ को पौल्यूट किया जा ता है और एडमिनिस्ट्रेशन को पोल्यूट किया जाता है । फिर जितने कोटे दे रखे हैं उन में से 25 से 50 परसेंट तक मेरे ख्याल के मुताबिक बोगस हैं । जगह जगह पर झूटे फट्टे उन्हों ने लगा रखे हैं । जब कोई महकमे वाला या कोई और इनक्वायरी करने के लिये जाता है तो कहा जाता है कि इतना हिस्सा तुम भी ले लो और हमारा कोटा मत बन्द करवाओ । जब हम गवर्नमेंट से पूछते हैं तो जवाब यह मिलता है कि इट इज नाट इन पबलिक इन्ट्रेस्ट टू डिस्क्लोज इट । गवर्नमेंट बड़े बड़े ब्लैक मार्किटियर्ज़ और स्मगलर्ज़ को इस फिक्रे से शेलटर देती है । मैं चहता हूं कि एक कमेटी बनाई जाए जो कि इनक्वायरी करे और ऐसे आदमियों की एक लिस्ट तैयार की जाए जिन पर ब्लैक मार्किटिंग या स्मगलिंग का केस बन चुका है, उन को पब्लिक में लाया जाए। जो शख्स पांच दफा चोरी करता है या कोई और जुर्म करता है तो थाने में ऐसे आदमियों की लिस्ट बनी होती

है और उस को दस नम्बर का बदमाश गिना जाता है । इसी तरह से जिस आदमी ने पांच दफा बलैक मार्किट की हो, चार पांच दफा स्मगलिंग का केस उस पर बन चुका हो या कोटे की मिसयूटीलाईजेशन के इल्जाम में पकड़ा गया हो तो क्यों नहीं उस आदमी के खिलाफ एक्शन लिया जाता । इस के उल्ट जब कोई फंक्शन होती है तो बड़े बड़े अफसर उठ कर उन को रीसीव करते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर उन को नमस्कार करते हैं । हमें यह टैंडेंन्सी बदलनी चाहिए । जब तक हम इस टेन्डेन्सी को नहीं बदलते उस वक्त तक हमारे अन्दर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी । आखिर में मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से मुतालिबा करूंगा कि जो दो तीन प्वायंटस मैंने कुरप्शन के बारे में अर्ज़ किए हैं उन का जवाब दें, अगर वे जवाब नहीं देंगे तो मैं समझूंगा कि इंडियन करंसी का बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है वह फारन कंटरी में गई है और इस काम में बड़े बड़े हिस्सेदार हैं । आप का शुक्रिया ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਾਭਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੀਪਾਰ-ਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰ ਲਿਆ । ਉਹੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ । ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 2,130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1.4 ਫੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ । ਸਾਥ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿਉ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ । ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਹ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੇਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ । ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਥੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾ ਡਿਵੀਯਨਾਂ ਹਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਾਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ । ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 M.I. 1963

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਯਨ ਵਿਚ 429 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,525 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ । ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਦਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 815 ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ । ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਿ ਜਿਸ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਆਏ ਸਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੈਕਸ਼ਨ M-2-M ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਡੀਵੀਯਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 90 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 44 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ । ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਡੀਵੀਯਨ ਵਿਚ 156 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ 432 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 199 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰਿਜਿਸਟਰਡ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1956 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕੋਈ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਨਿਸਟਰ ਕਦੀ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਦਸ ਸਕੀਏ । ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ—ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਾਫੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਇਟਸ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਲਾਇਤੋਂ ਆਕੇ ਇਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਟਲ ਐਪੈਥੀ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਲੈਕਚੂਅਲ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜਿਹੀ

4.00 p.m.

ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ । ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਕੀਏ । ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬੀਲਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ।

ਜੇ ਅਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਟਰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ । ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਅਗੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲ ਕਾਫੀ ਅਗੇ ਵਧ ਚੁਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਉਟਲੁਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਡੀਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਇਕ ਛੋਟੀ ਜੇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਟਨ ਫੀਲਡਜ਼ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਸ ਦਸ ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਕਾਟਨ ਜਿਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦਸ ਕਾਟਨ ਜਿਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਇਕ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਲ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਸ ਨਾਲ ਕਾਨਟੈਕਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦੇ ਤਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਉ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਥੇਂ ਜਿਥੇ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਿ-ਸਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਹਨ ਉਥੇ ਉਥੇ ਰਾਈਸ ਹਸਕਿੰਗ ਮਿਲਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਪਲਾ-ਏਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ । ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਐਟੀਚਿਊਡ ਇਤਨਾ ਰੁਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੈਕਵਰਡ ਇਅਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੋਬੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲ ਪਾਪਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹੁਜਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ । ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਸੈਨਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਸੈਨਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗੇ ਅਤੇ ਫਲੇ ਫੁੱਲੇ । ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਥੇ ਰਾ-ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਜਦ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਗੋਏਟਸ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ? ਜਦ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਲ ਤਵਜੁਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਲਈ, ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡ-ਸਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਦੋਂ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇ ਹੀ ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੈਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਉ ਮੈਂ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

Deputy Speaker : I would request the honourable Members to try to follow Sardar Gurdarshan Singh. His speech was quite brief and to the point. Shri Surindra Nath Gautam:

श्रीमती चन्द्रवती : आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम ।

उपाध्यक्षा : यह बड़ी नामुनासिब बात है कि अगर आप को काल अपान ना किया जाए तो आप उसी वक्त प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हो जाएं । (It is very improper that in case the hon. Members are not called upon to speak, they rise on a point of order.)

श्रीमती चन्द्रावती : देखिए, मैं तीन चार बार खड़ी भी हुई हूं । मैंने अपना नाम भी भिजवाया है । मैं आज जरूर बोलना चाहती हूं । मैं तो तीन चार दिन से बोली भी नहीं हूं । इस लिए रिक्वैस्ट है कि आप मुझे ज़रूर टाईम दीजिए ।

Deputy Speaker : Please take your seat.

श्रीमती चन्द्रावती : मुझे बताएं कि आप मुझे टाईम देंगी या नहीं ।

उपाध्यक्षा : मैं कुछ नहीं कह सकती। (I cannot say anything.)

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम (ऊना) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज इन्डस्टरी की डिमांड पर बहस हो रही है और इस पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैं सरकार को इस बात की बधाई देता हूं कि पंजाब के अन्दर इंडस्टरी की बहुत तरक्की हुई है ।

इस पर बोलते हुए काफी दोस्तों ने अपने अपने विचार रखे हैं । असली मकसद, जैसा कि सरकार चाहती है, इंडस्ट्रीज़ के जरिए गांव में हाथ से काम करने वालों को उत्साह देना है जिस से कि गांव भी तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ सकें। लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार ने पिछड़े हुए इलाकों में इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया । गांव के अन्दर जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जब उन को किसी चीज़ के, टीन वगैरा के कोटे की जरूरत पड़ती है तो उन को कहा जाता है कि आप लोगों को कोई कोटा नहीं दिया जा सकता क्योंकि आप ने कोई काम ऐसा नहीं किया है जिस से कि आप को यह कोटा दिया जा सके । इस के मुकाबिले में होता यह है कि वही कोटा बड़े बड़े कारखानेदारों को दे दिया जाता है। इस से सरकार का जो मनशा था कि हाथ से काम करने वालों को तरक्की देनी है वह पूरा नहीं हो सकता । इसलिए मैं आप के द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो भी पालिसी आप ने बनाई है वह सही है लेकिन उस पर अमलदरामद नहीं होता । इसलिए सरकार को चाहिए कि अगर आप ने दस्तकारी को तरक्की देनी है तो इन्डस्ट्रीज़ को गांव के अन्दर भी ले जाईए क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जमीन दिन ब दिन घटती जा रही है, सड़कों और दूसरे प्राजैक्टस के कारण जमीन कम होती जा रही है। इस लिए जरूरत है कि पंजाब के अन्दर गांव और पिछड़े हुए इलाकों के लोगों की अवस्था को इन्डस्ट्री के जरिए सुधारा जाए ।

अब मैं आप के द्वारा अपने हिल्ली एरिया की बाबत भी कुछ निवेदन करता हूं । सरकार नें नंगल में छोटे छोटे ट्रेक्टर बनाने की स्कीम बनाई। काफी गौरोखोज के बाद यह फैसला किया गया था कि छोटे छोटे जमींदारों को जिन की पांच पांच छ: छ: एकड़ जमीन है, ऐसी कम कीमत के ट्रेक्टर मुहैया किए जा सकें जिन को वह आसानी से खरीद कर सकें । बड़े बड़ जमींदार तो दस दस और बारह बारह हजार के ट्रैक्टर भी खरीद कर सकते हैं, उन को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक छोटा जमींदार इतना पैसा कहां से लाए । उस छोटे जमींदार की मुश्किल को आसान करने के लिए यह फैसला किया गया था कि नंगल में छोटे ट्रैक्टर बनाने की फैकटरी लगाई जाए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मुझे यह पता लगा है कि उस फैकटरी को, जिस को नंगल में लगाने की स्कीम पूरी हो चुकी थी, अब लुधियाना की तरफ ले जाया जा रहा है जिस से वहां के लोगों में बड़ी भारी डिसकन्टैंटमेंट फैली हुई है । लुधियाना तो पहले ही इन्डस्टरी के मामला में काफी तरक्की पर है। अगर वहीं पर सरकार इस फैकटरी को लगाने का फैसला करेगी तो यह उस इलाके के लोगों के साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा जब बैकवर्ड हिल्ली एरियाज़ को ऊपर उठाने का सवाल आता है तो सरकार की तरफ से यह विश्वास दिलाया जाता है कि वहां पर लोगों को पूरी तरह से फैसिलिटीज़ दी जायेंगी वहां पर इन्डस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी । लेकिन जब सरमाया लगाने का सवाल आता है तो जो बड़े बड़े फाईनैनशर्ज़ हैं वह पिछड़े हुए इलाकों में अपना पैसा लगाना नहीं चाहते । वहां पर वह आने के लिए तैयार नहीं होते । वह लुधियाना , अमृतसर, और दूसरे शहरों की तरफ भागते हैं । इस के नतीजे के तौर पर हमारा जो पिछड़े हुए, इलाकों को ऊपर उठाने का मकसद है वह पूरा नहीं हो सकता । शहरों ने इन्डस्टरी में काफी तरक्की की है । वहां

[श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम]
पर इन्डस्ट्रीज काफी फैली हुई हैं। उस के मुकाबले में हम ने देखा है कि जो देहाती है, जमींदार है वह 6 महीने के बाद बेकार हो जाता है, उसके पास कोई धन्धा नहीं रहता तो फिर वह शहर की तरफ दौड़ता है मजदूरी हासिल करने के लिए। ऐसी स्कीमें बनाई जानीं चाहिएं कि उस को इन 6 महीनों में वहां पर अपने गांव में ही काम मिल जाए और शहर की तरफ न दौड़ना पड़े।

फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार ने हरिजन भाईयों को काफी सहूलियात दी हैं कि वह जूते वगैरह बनाने के लिए या ऐसी ही दूसरी काटेज इन्डस्ट्रीज के लिए सरकार से लोंन लें। मगर हम ने देखा है कि यह सारी कागजी कार्यवाही है। अगर इस काम के लिए कोई एक हज़ार रुपया मांगता है तो पहले सरपंच से तसदीक करवाता है, फिर तहसीलदार साहिब के पास जाता है मगर वहां से उस को वापस कर दिया जाता है कि जामिनी और लाओ। मुझे ऐसी बातें आठ दस केसों में देखने को मिली हैं। कागज तैयार किए गए, वक्त पै भेजे गए, तहसीलदार साहिब ने काउंटर सिगनेचर भी कर दिए मगर डिस्ट्रिक्ट इन्स्पैक्टर ने कहा कि तहसीलदार ने असली दस्तखत नहीं किए और कागज वापस कर दिए। वह बेचारा किसी तरह से रोजी कमाना चाहता है मगर उस को आखिर में यह जवाब मिल जाता है कि इस बार तो बजट में आप के लिए पैसा नहीं है अगले बजट में देखा जायगा। ऐसी बातें होती हैं। इस तरफ ध्यान दिया जाए और हरिजन मज़दूर के रास्ते की अड़चनों को दूर किया जाए ताकि वह अपना कारोबार चला सकें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने अपनी बजट स्पीच मे भी कहा था कि मेरे हलके में इलाका बीत है जहां पर पत्थर पाया जाता है। जब यह पत्थर दूसरे इलाकों को ले जाया जाता है तो वहां के लोगों को दुःख होता है। इस से शीशा बनता है, सीमेंट बनता है, चूना बनता है। जब हम कहते हैं कि हमारे ही इलाके में कोई छोटी सी फैक्टरी लगा दो तो कहते हैं कि इस पर सरमाया बहुत लगेगा इस लिए कोई सरमायादार इस के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से उस से फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। हम कहते हैं कि सरकार क्यों नहीं पब्लिक सैक्टर में एक छोटी सी फैक्टरी लगा देती तो कहा जाता है कि यह बड़ा मुश्किल है (घंटी) क्योंकि वहां पर ट्रांस्पोर्ट नहीं है, रेल नहीं, पानी और बिजली नहीं है। हमें घाटा पड़ेगा। इसी बिना पर बिजली भी नहीं दी जाती, जो कि नो लास, नो, प्राफिट पर दी जानी चाहिए। मैं कहता हूं कि जब तक इस पिछड़े हुए इलाके को प्राफरेंन्स नहीं दी जाती यह इलाका आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार को चाहिए कि वहां की तरक्की के लिए स्कीमों को प्रैक्टीकल शेप दे वरना लोगों को कोई सहारा नहीं होगा। वहां पर कोई सरमायादार अगर आता है तो बिजली मांगता है, पानी देखता है तो इस का इन्तजाम सरकार ही कर सकती है। (घंटी) अगर चीफ मिनिस्टर साहिब उस इलाके को तरक्की देना चाहते हैं तो इस बात की जरूरत है। उस इलाके को नजर में रखा जाए। आप का धन्यवाद।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ (ਪੂਰੀ ਐਮ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ

ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮਗਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕੇ (ਵਿਘਨ) ਪਕੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟਾ ਕੈਪੀਟਲਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਪਲੈਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 46,42,40,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ 44,16,86,000 ਰੁਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,40,00,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 9,40,00,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ 4,80,00,000 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਮਗਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4,80,00,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਊਟ ਲੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ । ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲ ਹੋਵੇ । ਮਗਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਟੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਫੰਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ . . . .

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ । (ਵਿਘਨ) (Now the hon. Member has become an experienced Parliamentarian. He should remain within the bounds of Parliamentary propriety.) (*Interruptions*).

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ (* * * *) ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗੇ. . . . .

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਉ । (The hon. member should not refer to the officers by name.)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਉਸ ਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਿਜਿਜ਼ ਲਗੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ [* * * *] ਨੇ . . . .

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : This is in bad taste. ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਛਡ ਦਿਉ ।(This is in bad taste. He should avoid any reference to Sardar Partap Singh's family.)

Note.—*Expunged as ordered by the Chair.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਮਪੁਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਢਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਥੇ ਲਗਾਂ ਦਿਤਾ । ਇਹੋ ਜਹੇ ਕੁਰਪਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ । ਅਫਵਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡੈਇਰੈਕਟਰ ਹੈ * * * * * * * *

(ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਗਲ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਵਾਪਸ ਲਉ । (This is improper. (*Interruption*) He should withdraw these words about the share).

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : On a point of order, Madam...... (*Interruption*) ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ?

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰ : ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ [* * * *]

(ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾ ਲਉ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰੋ । (I have asked the hon. Member not to mention the names of officers as they cannot defend themselves here. He should talk things in a general way.)

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम, भोरा जी ने ऐसे आफीसर्ज का नाम इस हाउस में लिया है जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते । मैं पूछना चाहता हूं कि आया वह ऐसे लोगों को यहां डिसकस कर सकते हैं ?

उपाध्यक्षा : यह ऐसा नहीं कर सकते । जो छ इन्होंने कहा है that will not form the part of the proceedings. (He can not do so. Whatever he has said would not form part of the proceedings.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੂੰ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕੁਰਪਸਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਹੋਣ ਇਸ ਹਾਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕਹਿਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

उपाध्यक्षा : जो आफीसर अपने आपको यहां पर डीफैंड ही नहीं कर सकते मैं उन का नाम लेने की इजाजत नहीं दे सकती । (The officers who cannot defend themselves here will not be allowed to be referred to by names.)

Note.—*Expunged as ordered by the Chair.

चौधरी इन्दर सिंह मलिक: भौरा साहिब ने आप के कहने पर उस अफसर का नाम लिया जब कि गर्ग साहिब ने पूछा। ऐसी हालत में यह प्रोसीडिंग ऐक्सपंज नहीं होनी चाहिये।

उपाध्यक्षा: ऐसी बात नहीं है। भौरा साहिब के नाम लेने पर गर्ग साहिब ने नाम दुबारा पूछा था, मैं ने नाम लेने को नहीं कहा। यह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। (This is not the case. When Mr. Bhaura mentioned the name of the officer, Mr. Garg asked him to repeat it. I never asked him to mention the name. It will not form part of the proceedings).

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇ-ਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੰਬਈ ਦੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਕ ਟਿਨ, ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਗਣ ਮੈਟਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਟਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਕਰੈਪ ਗਨ ਮੈਟਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰਜ਼ਿ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿਚ ਯੂ. ਐਸ. ਏਜੈਂਸੀ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ "There was now an atmosphere unfavorable to the public sector".

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਰਮ ਤੇ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਯਾਰੀ ਰਖਣ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲਿਸਟਸ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

[ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ]
ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।

ਇਕ ਗਲ ਮੈਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 4 ਅਗਸਤ, 1964 ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਉ ਥੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ । ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਥੱਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਬਜਾਏ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿ [× × × ×] ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਲੇਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਤਆਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਲੇਬਰ ਹੈ । ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

उपाध्यक्षा : मैंने बार बार कहा है कि आप यहां पर आफीसर्ज़ का नाम नहीं ले सकते । आप फिर रिपीट करते हैं । (I have repeatedly told that the hon. Members cannot refer to officers by name. The hon. Member is again doing the same thing.)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਂਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਉ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਹਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਰੀ ਸਨਅਤ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮਾਈਂਡਿਡ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਸਭ ਢੌਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਧਨੰਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

Note—Expunged as ordered by the Chair.

श्रीमती चन्द्रावती (दादरी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ने जो मुझे समय दिया इस के लिये मैं आप का धन्यवाद करती हूं। मैं आपके सामने इन्डस्ट्री की डीमांड पर बोलने से पहले जैसा कि भाई निहाल सिंह जी ने कहा है, सरकार का ध्यान आप के द्वारा इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि दफतरों के लिये जिस ने 10 से 5 बजे तक का फ्लैट टाइम रखा है, मैं समझती हूं कि उसको सूबे की क्लाइमेट का जरा भी पता नहीं। ज़िला महेन्द्रगढ़ में मई के महीने में हम बाहर भी नहीं निकल सकते, इतनी जबर्दस्त वहां पर लू चलती है कि काम हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूं कि अगर अफसर इन दिनों में 3 दिन के लिये भी आकर काम कर जायें तब मैं मानूंगी कि यहां पर इन दिनों काम हो सकता है। अगर इन का मुलाज़िमों को कैदियों की तरह बिठाने से ही मतलब है तो जुदा बात है। इस लिये डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आप के द्वारा सरकार से यह रिक्वैस्ट करूंगी कि वहां पर गर्मी के मौसम में इतनी गर्मी होती है कि दुपहर के बाद काम हो ही नहीं सकता। इस लिये वहां के लिये अगर 7 से 1 बजे तक का टाइम कर दिया जाये तो बड़ी मेहरबानी होगी।

इंडस्ट्री के मुताल्लिक जो मैं एक दो बातें करना चाहती हूं वह यह हैं। यहां पर एक प्वायंट भाई गुरदर्शन सिंह जी ने उठाया था कि हमारे यहां बड़ी इंडस्ट्री दी है। मैं तो कहती हूं कि इंडस्ट्री अगर जा कर देखें तो आप को फरीदाबाद या गुड़गांव में में लगी हुई नजर आयेगी, हमारे हां तो अगर कुछ मिला है तो नुक्सान मिला है जो ज़मीन देने से हुआ। पंजाब सरकार को भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि इन्कम टैक्स इस का दिल्ली को जाता है। हरियाणा के गरीब लोगों की ज़मीन फूस के भाव बेची गई। जो इंडस्ट्री लगी उसका हमें कोई विशेष फायदा नहीं हुआ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि अटेली के पहाड़ से बढ़िया क्वालटी का कांच बरामद किया जा सकता है। यह बात तो हमारे नालिज में नहीं आई कि सर्वे डिपार्टमैन्ट ने कोई सर्वे भी किया है या नहीं, मगर यहां तक मेरा अपना ख्याल है हमें इस जगह से बढ़िया किस्म का कांच मिल सकता है जिस से यहां पर एक बढ़िया किस्म की गलास फैक्ट्री लगाई जा सकती है। एक बात जो मैं दूहराना चाहती हूं, जिसको श्री मित्तल जी ने और राव निहाल सिंह ने कहा था, वह यह है कि पिग आइरन का जो कारखाना है, वह हमारे यहां होना चाहिये। जब उसके लिये हमारे यहां रा मैटीरियल मिलता है, तो आपको कारखाना लगाने में क्या दिक्कत होती है। पानी की दिक्कत बताई जाती है, मगर मैं समझती हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिये दुबारा जांच कराई जा सकती है।

एक और बात मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि कुछ चीज़ों की अपन सूबे में चन्द लोगों की मनोपली है जिसका नतीजा यह होता है कि जिस चीज़ की ज्यादा डिमांड होती है, वही चीज़ मार्कित से गायब हो जाती है। मेरा सुझाव यह है कि जिन चीज़ों की मानोपली है उसके लिये पब्लिक सैक्टर में कोई फर्मज़ लगवाई जानी चाहिए। यह बताया जाता है कि जहां जहां बिजली लानी है, उस के लिये बिजली का सामान नहीं मिल रहा लेकिन हकीकत यह है कि बिजली के सामान की एक आदमी की मानोपली है। यह जब चाहता है, तब बन्द कर देता है। इसी तरह से खाद की कमी का कारण बताया जाता

[श्रीमती चन्द्रावती]

है। मैं यह कहना चाहती हूं कि जिन चीजों की दिक्कत है उनके कारखाने गवर्नमैन्ट को पब्लिक सैक्टर में लगाने चाहियें।

एक बात और है कि आज कल हमारे यहां क्वान्टिटी को प्रधानता दी जा रही है, क्वालिटी को नहीं। एडवर्टाइज़मैन्ट के नए नए तरीके ढूंड कर चीज़ें चलाई जा रही हैं लेकिन क्वालिटी पर जोर नहीं दिया जाता। मुझे याद है बचपन से ही कि जर्मनी की कोई भी चीज हो, वह बढ़िया से बढ़िया बनती है लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता है, इस ओर ख्याल होना चाहिये। हमें चाहिये कि नुमाइश और कम्पीटीशन के जरिये बढ़िया चीजें बनाने वालो को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि अगर हम रद्दी किस्म की चीज़ें पैदा करते रहेंगे तो वर्लड के मार्किट में खड़े नहीं हो सकते। अच्छी चीजें और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाने वालों को अगर सरकार सबसिडी भी दे तो भी अच्छी बात है। अगर हमारी चीजें नम्बर वन पैदा होने लगें तो हमारी क़द्र वर्ल्ड मार्किट में बढ़ सकती है।

मैं देखती हूं कि यहां जो चंडीगढ़ में दूध आता है वह पाउडर से तैयार होता है। जब यही हालत है तो यह पाउडर बाहिर से ही क्यों मंगवाया जाये, यहीं क्यों न तैयार किया जाये। इसके लिये दादरी, हिसार, महेंद्रगढ़ आदि जगहों में जहां अच्छे क्वालिटी के पशु हैं, वहां पर पाउडर बनाने की स्कीम तैयार की जाये ताकि वहां के लोगों को और सारे देश के लोगों को फायदा हो सके। जो लोग अनइम्पलाइड हैं उन को काम भी मिल सकता है। इस लिये, इस किस्म की फैक्टरी लगाई जानी चाहिये। (घंटी) मैं यह जरूर कहना चाहूंगी अखीर में कि जो लोग मनोपली कायम कर लेते हैं, उसको तोड़ दिया जाना चाहिये। जैसे कोकाकोला है, अगर इसकी मनोपली बनी रही तो सीज़न पर इसकी ब्लैक हो जायेगी। इसे ब्रेक करना चाहिये। आपका धन्यवाद।

कंवर राम पाल सिंह (पुंडरी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज इंडस्ट्रीज़ की डिमांड पर बहस हो रही है। मैं समझता हूं और जैसा कि पहले बोलने वालों ने कहा है इंडस्ट्री में हमारे सूबे ने कुछ सालों में ही बहुत तरक्की की है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी कि होना चाहिये थी

मैं गवर्नमैन्ट का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि देहात में लोगों को कोई काम नहीं मिलता है इसलिय उनके सामने केवल ज़मीन दिखाई देती है और वह उसी तरफ भागते हैं। लेकिन ज़मीन कोई रबड़ तो है नहीं जो बढ़ जाये इसलिये उसका आलटरनेटिव यह है कि इंडस्ट्री को बजाये शहरों के देहात में भी लगाया जाए। लेकिन हो यह रहा है कि इंडस्ट्री को ऐसी जगह में ज्यादा तरजीह दी जा रही है जहां पर पहले से ही बड़ी इंडस्ट्री लागू है। उनका कहना है कि अगर देहात में इंडस्ट्री लगाई जाये तो पनप नहीं सकती है। और यह भी कहा जाता है कि जहां पर रा मैटीरियल होता है वहीं पर इंडस्ट्री उससे सम्बन्धित कायम की जा सकती है। लेकिन कांगड़े वाले न जाने कब से यह कहते हैं कि वहां पर रा मैटीरियल होता है, इसलिये वहां पर इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिये, मगर ऐसा नहीं होता। और माल वहां से ले जा कर दूसरी जगर पर इंडस्ट्री चलाई जाती हैं।

हरियाने में जहां तक स्माल स्केल इंडस्ट्री का सवाल है, वह चालू नहीं की गई है। अगर कहा जाता है तो जवाब मिलता है कि हमने खादी इंडस्ट्री वहां पर लागू की है। मगर देखा जाये तो खादी की इंडस्ट्री भी सिर्फ शहरों में ही रायज़ हुई है।

पब्लिक एकाऊंट्स कमेटी में यह देखने में आया कि रुपया तो कई जगह के लिये खर्च किया गया कि फलां जगह इंडस्ट्री लग रही है, मगर उसका यह पता नहीं चला कि रुपया गया कहां। जो थोड़े बहुत छोटे छोटे जुलाहे थे उनका भी काम बन्द हो गया क्योंकि वह कम्पीटीशन में नहीं आ सकते क्योंकि मिल की चीज़ सस्ती और अच्छी बनती है। मैं इस लिलसिले में यह कहना चाहूंगा कि उनको यह तसल्ली मिलनी चाहिये कि वह जो माल पैदा करेंगे वह बिकेगा जरूर। तो छोटे काम करने वाले टिक सकते हैं वरना वह फेल हो जायेंगे, बहुत सारे तो हो ही गए।

जहां तक ऐग्रीकल्चर इम्पलीमैन्टस का ताल्लुक है मैं पूछना चाहता हूं कि क्या लुधियाना और फगवाड़ा ही ऐसी जगहें हैं जहां उनके बनाने के सैंटर हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते हैं? लुधियाना, फगवाड़ा में लोहा कहां पैदा होता है बहार से ही आता है और वहां के लिये कोटा परमिट दिया जाता है और फिर उस के बाद वहां चीजें बनाते हैं। अगर ज़मींदारों ने ऐग्रीकल्चर इम्पलीमैन्ट लेने हों तो उन्हें वहां इतनी दूर पैसे खर्च करके जाना पड़ता है। आप क्यों नहीं कोटा देकर दिहात में इन इम्पलीमैंट्स की और दूसरी ऐसी चीज़ों की इन्डस्ट्री चलाते। वहां अगर आप ऐसी छोटी इंडस्ट्री चलायें तो लोगों को सहूलत भी मिल सकती है और देहात में रोजगार भी मिल सकता है। (घंटी) अब मैं कुछ सजैशनज़ देना चाहता हूं कि दिहात में कौनसी इन्डस्ट्रीज़ चल सकती हैं। और तो और मिल्क ऐंड डैरी के प्लांट भी शहरों में लगाये जाते हैं हालांकि दूध गावों में मिलता है। मेरा जितना एरिया है वहां से सारा दूध देहली जाता है और देहली मिल्क सप्लाई के लिये रिजर्व कर लिया गया है। क्या वहां हमारे इलाके में मिल्क प्लांट लगा दें तो हमारे इलाके की तरक्की हो सकती है। अगर यह दूध इस तरह देहली में जाता रहेगा तो पंजाब का क्या हाल होगा और पंजाब की आगे आने वाली नसलों का क्या हाल होगा। जहां हमारी चीज़ों पर सैंट्रल गवर्नमैन्ट छापा मारती है तो चुप नहीं बैठ जाना चाहिये बल्कि उन से लड़कर भी अपने हकूक की हिफाजत करनी चाहिये। फिर देहात में लैदर सोप मेकिंग वगैरा कई ऐसी छोटी इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं। पिछले दिनों डाल्डा की कितनी भारी दिक्कत हुई है और किस तरह ब्लैक में बिकता रहा है, हमारे हां इतनी मूंगफली और बिनौला होता है कि हम पंजाब के गांव में ही डाल्डा घी की बड़ी भारी इंडस्ट्री चला सकते हैं लेकिन यह सारी मूंगफली और बिनौला बाहिर भेज दिया जाता है। मैं गवर्नमैन्ट से कहूंगा कि जब हमारे जहा इतना काफी इ न के लिये मैटीरियल पैदा होता है तो फिर आप क्यों डाल्डा की इंडस्ट्री गांव में नहीं लगाते हैं। फिर मेरे ज़िला में कार्डबोर्ड के लिये बहुत रा मैटीरियल होता है। यह अच्छी बात है कि एक प्राइवेट मिल वहां इसके लिये लगी है लेकिन वहां रा मैटीरियल इतना है कि वहां दो मिलें और लग सकती हैं। (घंटी) कामरेड राम प्यारा ने भी बताया है और मैं भी अर्ज करता हूं, कि हमारा कैथल का एरिया काटन का था और वहां कैथल में एक टैक्सटाइल मिल लगाने की प्रोपोज़ल थी, लेकिन पता नहीं वह स्कीम अब कहां गई है और क्यों वह खत्म कर दी गई है। और

[कंवर राम पाल सिंह]

गवर्नमैन्ट की ऐसी मर्ज़ी भी थी तो भगवान ने भी ऐसा ही सोचा कि वहां फल्ड आने लग पड़े और सेम की वजह से वह काटन की बजाये शूगरकेन एरिया बन गया। एक मिल खांड की पानीपत में लगी है लेकिन वह हमारे एरिया का गन्ना नहीं उठा सकती। इस लिये मैं अर्ज़ करता हूं कि हमारे कैथल में एक शूगर मिल लगाई जाये जिस से लोगों का गन्ना भी वहीं जा सके और लोगों को मज़दूरी का काम भी मिल सके (घंटी) अच्छा जी मैं अब इन शब्दों से अर्ज़ करता हूं कि मेरा कैथल सब-डिवीजन बहुत बैकवर्ड है उसका ख्याल रखा जाये। अगर बड़ी इन्डस्ट्री नहीं जा सकती तो समाल स्केल इन्डस्ट्री ही लगाई जाए।

Shri Amar Singh : On a Point of Order, Madam.

Deputy Speaker. : I do not allow your Point of Order. Please take your seat.

Shri Amar Singh : Madam, I want to raise a Point of Order.

Deputy Speaker : I have already asked you to please take your seat. I will not allow any Point of Order.

अमर सिंह : अगर आप मुझे प्वायंट आफ आर्डर भी रेज़ नहीं करने देतीं तो मैं एज़ एप्रोटैस्ट वाक आऊट करता हूं (शोर)।

Mr. Speaker : I name Shri Amar Singh. He is not behaving properly. (noise)

(Shri Amar Singh resumed his seat)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੋਰਿੰਡਾ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਟਰੇਯਰੀ ਬੈਂਚਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੱਵਜੁਹ 'ਪੰਜਾਬ ਆਨ ਦੀ ਮਾਰਚ' ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁਪ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, 'ਪੰਜਾਬ ਆਨ ਦੀ ਮਾਰਚ' ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ :

"The Punjab Government has been allotted only two central projects with total capital investment of about Rs 30 crores which constitute only 1.4 per cent of the total financial outlay of Rs 2,130 crores planned for Central Projects during the period of three Five-Year Plans...."

ਸਾਨੂੰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਰਫ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਿਚ ਫਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਜਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਜੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਗੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸੁਹਲਤਾਂ ਜੋ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੋਆਪਰੇਇਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼, ਕਾਟਨ ਐਂਡ ਸਪਿੰਨਿੰਗ ਮਿਲਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਕਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਮਿਲ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਹ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਗੰਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਗੰਨਾ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਭਰੇ ਸਨ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਚੀਨੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਫਰਟਾਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਲਗੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਉ ਤੇ ਬੀਜ ਤੇ ਫਰਟਾਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਹੈ ਉਥੇ ਤਾਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੇਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਉਥੋਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਜੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਘੰਟੀ)। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਗੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਾਏ ਤਾਂਕਿ ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਰੀਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਲੈਦਰ ਜਾਂ ਵੀਵਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਘੰਟੀ) । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਘਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ ਕਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਡੀ ਵਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਪਿਆ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

राजकुमारी सुमित्रा देवी (रिवाड़ी) : उपाध्यक्षा महोदय, इस में संदेह नहीं है कि हमारी सरकार ने दस्तकारी के क्षेत्र में पिछले वर्षों से काफी उन्नित की है। जहां पानीपत, बटाला, फरीदाबाद, लुधियाना में जितना इंडस्ट्रीज़ का काम हुआ है, उस से हम सबको गर्व होता है। चंडीगढ़, पंजौर में जो इंडस्ट्रीज़ खोली हैं उन को देख कर आश्चर्य भी होता है और साथ में खुशी भी होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि इस के अन्दर उस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है जहां पर दस्तकारी स्थापित की जा सकती है, जिस से वहां की जनता उन्नत हो सके। जहां पर जीविका के लिये दूसरे साधन नहीं हैं वहां पर सरकार ने दस्ताकरी नहीं खोली है। जिस इलाके से मैं सम्बन्ध रखती हूं वह रिवाड़ी का इलाका है। यह पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां पर कोई दस्तकारी अब तक खोली नहीं गई जिस से वहां के मजदूर अपना पेट पाल सकें। वहां पर काफी संख्या में मजदूर उपलब्ध है। इस लिये मैं सरकार से आप के द्वारा निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार को ऐसी पालिसी बनानी चाहिये जिस से वह इलाका उन्नत हो सके। वहां पर जो अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वहां पर जौ से सम्बन्धित इन्डस्ट्री स्थापित करनी चाहिये। इस के अतिरिक्त रिवाड़ी में कांसी और पीतल के बर्तन बनते हैं। यह शहर इस उद्योग के लिये प्रसिद्ध है। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जहां पर पंजाब में

अधिक उन्नति करने की कोशिश की जा रही है वहां पर रिवाड़ी को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। वहां पर कांसे और पीतल के बर्तन बनते थे लेकिन अब सरकार उन की सहायता नहीं कर रही है। देहातों की बात तो छोड़िये, शहर के अन्दर भी इस बारे में जो कारखाने हैं, वह बन्द होते जा रहे हैं क्योंकि उन को पीतल, कांसे और स्टेनलैस स्टील का कोटा पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहा है। वहां पर इस सम्बन्ध में दस्तकारी खोली जानी चाहिए ताकि वहां के लोग अपने काम को बढ़ा सकें और वहां के इलाके की तरक्की हो सके। अगर उस इलाके की तरक्की होगी तो मैं समझती हूं कि इस से हमारे प्रांत की तरक्की होगी। वहां पर देहातों से मज़दूर काफी मात्रा में मिल सकते हैं और वहां पर इंडस्ट्री अच्छी तरह से चमक सकती है। कांसे और पीतल के बर्तन यहां पर तैयार करके दूसरे मुल्कों में भेजने चाहियें इससे हमारी स्टेट को भी लाभ होगा और इलाके की भी उन्नति होगी। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि वहां पर कांसे पीतल, स्टेनलैस स्टील का कोटा अधिक मात्रा में लोगों को दिया जाये ताकि वहां के लोगों को यह उद्योग चलाने के लिये उत्साह मिल सके। वहां की जनता में इस वक्त जो निराशा है, वह दूर हो सके। उपाध्यक्षा महोदया, मैं आप के द्वारा सरकार से अन्त में प्रार्थना करना चाहती हूं कि सरकार इस आधार की पालिसी बनाये, जहां पर जिस प्रकार की वस्तु पर्याप्त होती है, उसी प्रकार का कारखाना खोला जाये। जो इलाका दूसरे इलाकों से पिछड़ा हुआ है, उस को ऊपर उठाया जाये क्योंकि उन के पास साधन कम होते हैं। इस लिये उन की हर प्रकार से सहायता की जानी चाहिये। उस इलाके के अन्दर विशेष तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और वहां पर दस्तकारी खोलनी चाहिये। रिवाड़ी अब तक कांसे और पीतल के बर्तनों के लिये प्रसिद्ध रहा है। इस लिये, सरकार को इस उद्योग को बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये ताकि वह इलाका उन्नत हो सके।

श्री मोहन लाल (बटाला) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस में दो राय नहीं हो सकतीं हैं कि किसी भी देश के लिये, खास तौर पर आर्थिक उन्नति के लिये, लोगों की आमदन बढ़ाने के लिये और लोगों को रोज़गार देने के लिये इंडस्ट्री एक बहुत ही अहम साधन है और इस के साथ ऐग्रीकल्चर भी है। इस लिये सरकार की और लोगों की तवज्जोह इस तरफ होनी चाहिये। अभी अभी आपोजीशन की तरफ से मैम्बर साहिबान जो कुछ कह रहे थे, मैं उन से इत्तफाक रखता हूं। जहां तक इंडस्ट्री का सम्बन्ध है वहां पर कोई पालटिक्स इन्वाल्वड नहीं होना चाहिये। इस में गवर्नमैन्ट, आपोजीशन और सरकारी कर्मचारियों को मिल कर काम करना चाहिये। इस में किसी भी तरीके से सरकार, सरकारी कर्मचारियों और आपोजीशन की तरफ से कोई अनुचित बात नहीं करनी चाहिये। अगर कोई ऐसी बात होती है तो यह बुरी बात होगी। इस लिये मैं उन मैम्बर साहिबान से खास तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिन्होंने यहां पर नुक्ताचीनी की, उन्हें बहुत ही एहतयात से काम लेना चाहिये था। मैं ने कुछ मैम्बरों की बातें सुनीं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के नाम लेकर नुक्ताचीनी की। उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्टों के नाम ले कर नुक्ताचीनी की। मैं समझता हूं कि यह बात इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डिवैल्पमैन्ट के लिये बहुत ही रुकावटें पैदा करेगी। यहां पर सरकारी कर्मचारियों का नाम लिया गया है। मैं समझता हूं कि इन का इस तरह से नाम लेने से उन में इंसेंटिव बिल्कुल खत्म हो जायगा और

[श्री मोहन लाल]

उन में काम करते हुए झिझक पैदा होगी। सरकार को तो दोनों ही सैक्टरों को बढ़ावा देना चाहिये। यहां प्राइवेट सैक्टर की इस प्रकार से नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिये। अगर इसी तरह से नुक्ताचीनी की गई तो मैं समझता हूं कि पंजाब में लोग इंडस्ट्री लगाने से झिझकेंगे। इस लिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इंडस्ट्रीज़ के महकमे और इंडस्ट्री के बारे में यहां पर बातें करते हुए एक बात अपने सामने बिल्कुल साफ और वाज़ह रखनी चाहिये कि नुक्ताचीनी वाजिब और प्रापर करनी चाहिये। यहाँ पर पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट 5.00 p.m. | सैक्टर की बातें हुईं। इस में शक नहीं है कि सोशल इकानोमी में पब्लिक सैक्टर का अहम पार्ट है। इस को इन्क्रेज करना चाहिये। (Mr. Speaker in the Chair) और सरकार को इस तरफ खास तौर पर ध्यान देना है। मैं जानता हूं कि राज्य सरकार की उस में कितनी मजबूरियां हैं लेकिन फिर भी पब्लिक सैक्टर में हमें खास तौर पर ध्यान देना होगा। हमारे जो फैसले सोशलिस्ट इकानोमी लाने के हैं और उसको बढ़ावा देने के लिये हमें पूरी तवज्जोह देनी होगी। आपोजीशन के मैम्बर साहिबान ने भी इस बात को सही तौर पर तस्लीम किया है कि तब तक पब्लिक सैक्टर के साथ साथ हमारी इंडस्ट्रीयल इकानोमी भली भांति नहीं चल सकती जब तक कि प्राइवेट सैक्टर को जो ज़रूरी एनक्रजमैन्ट मिलनी चाहिये वह न दें। इस लिये जहां सरकार के सामने प्रायरटी बेसिज़ पर पब्लिक सैक्टर का ध्यान होना चाहिये वहां पर हमें प्राइवेट सैक्टर को भी ज़रूर इनसैंटिव और इनक्रेजमैन्ट देना चाहिये। अगर हम पंजाब को इंडस्ट्रियलाइज़ करना चाहते हैं तो यह एक हकीकत है, स में कोई दो राय नहीं हो सकतीं।

जहां तक स्माल स्केल इंडस्ट्री का सम्बन्ध है पंजाब ने काफी तरक्की की है और आज भी कर रहा है। लार्ज स्केल और हैवी इंडस्ट्री में हम पीछे थे, पिछड़े हुए थे, यह हकीकत है। इस लिये यह एक अहम और ज़रूरी बात है कि हमारी सरकार का लार्ज स्केल और बेसिक इंडस्ट्री की तरफ ध्यान हो। मैं आपके ज़रिये सरकार से प्रार्थना करूंगा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के सिलसिले में सरकार ने कुछ फैसले किये थे। वह चन्द एक अहम फैसले थे। उन के मुताल्लिक कुछ शकूक पैदा हुए हैं और कुछ पैदा हो रहे हैं। वह शकूक यहां पर दूर होने चाहियें। मैं आप के द्वारा अर्ज़ करना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट टाइम्ज़ आफ इंडिया में 22 जनवरी को छपी थी :

> "Several Projects shelved. Several industrial projects allotted to the Punjab have either been shelved or lost by the State because of the Government's inaction and indecision"

आगे कुछ मिसालें दी हैं, यह एक लम्बी रिपोर्ट है इस में मैं नहीं जाना चाहता। स्पीकर साहिब, मैं यह बात इस लिये अर्ज़ करना चाहता हूं क्योंकि मैं ने इस बात की काफी चर्चा सुनी है कि राज्य के जो बड़े बड़े प्रोजैक्टस हैं उन्होंने आगे तरक्की नहीं की, कुछ छोड़ दिये गये हैं कुछ रुके पड़े हैं और इस बात का हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की एक्सपेन्शन पर बुरा असर पड़ा है। इस लिये मैं चाहूंगा कि जो चंद एक बड़े बड़े प्रोजैक्टस हैं उन के मुताल्लिक सरकार हाउस को और पबलिक को कानफीडैंस में ले ताकि शक दूर हों। जहां तक मुझे याद है कि 26 करोड़ की ऐसी चालू स्कीम्ज़ थीं जो कुछ पूरी हो चुकी

थीं और कुछ ऐसी थीं जो कि अच्छी स्टेज पर पहुंच चुकी थीं । अब उन में क्या हुआ इस के बारे में मेरी राय है कि सरकार को हाउस को और पब्लिक को कानफीडैंस में लेना, चाहिए। इस में एक स्कीम थी सीमलैस टयूब की, दस करोड़ रुपये की जिस में कोलैबोरेशन जो थी, उस के लिये एग्रीमेंट साईन हो चुका था। उस की टर्म्ज़ के मुताबिक पांच करोड़ रुपये का लोन भी गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया की तरफ से इन प्रिंसीपल मंजूर हो चुका था और बोर्ड ग्राफ डायरैक्टर्ज़ भी बन चुका था । ज़मीन एक्वायर करने के लिये नोटीफिकेशन भी इशू हो चुका था, प्रोजैक्ट रीपोर्ट बन चुकी थी और रा मैटीरियल भी एग्ज़ोयर हो चुका था । दस करोड़ रुपये की यह पब्लिक सैक्टर स्कीम है तो मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहिब से चाहूंगा कि वह इस के बारे में पोज़ीशन वाज़ेह करें कि इस में कहां पर रुकावट पड़ गई, क्यों वह आगे नहीं बढ़ी । यह एक बड़ी ज़रूरी बात बतलाने की है । इसी तरह से स्टील कासटिंग्ज़ की डेढ़ करोड़ रुपये की एक स्कीम थी। इस के बारे में तमाम फार्मेलेटीज़ जैसे कि मैं ने ऊपर बयान की हैं, वह पूरी हो चुकी थीं लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि इस के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है और यह भी पता चला है कि सरकार प्रिंसीपल कोलैबोरेशन को तबदील करने के लिये उस में परिवर्तन लाने की बात सोच रही है। पिछले बजट में 85 लाख रुपया इस स्कीम के लिये, प्रोवाईडिड था और वह लैप्स हो गया है। मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहिब हाउस को कानफीडैंस में ले कर वाज़ेह करें कि क्या वाकई ऐसा हुआ और इस के क्या कारण हैं, क्या मजबूरियां हैं। ग्राप जानते हैं कि एक हमारी पंजाब एयर राईफल फैक्टरी बननी थी उस के लिये 50 लाख रुपया रखा गया था और उस के लिये लैंड भी एक्वायर कर ली गई थी, टैक्नीशन्ज़ भी रैकरूट हो चुके थे। लेकिन मुझे पता चला है कि वह स्कीम सरकार ने छोड़ दी है। यह भी पता चला है कि सरकार के पास ग्रौफर भी ग्राई थी कि अगर सरकार इस स्कीम को पब्लिक सैक्टर में चालू रखना या लगाना नहीं चाहती तो और पार्टीज़ हैं जो कि फैक्टरी को लगाने के लिये तैयार हैं। फिर भी इस प्राजैक्ट को ड्राप कर दिया गया है यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहिब इस के बारे में भी प्रकाश डालें । इस से आगे चार करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट पिग ग्रायरन के नाम का था उस में भी तमाम फार्मेलैटीज़ सरकार की तरफ से पूरी हो चुकी थीं और एग्रीमेंट भी एक यू. के. फर्म के साथ साईन हो चुका था, प्रिलीमीनरी प्रोजैक्ट रीपोर्ट बन रही थी लेकिन अब सरकार सोच रही है कि कोलैबोरेशन को तबदील किया जाए। इस लिये रुकावट पड़ रही है। यह बहुत बड़ी स्कीम चार करोड़ रुपये की थी, अभी तक क्यों आगे नहीं बढ़ सकी, इस पर क्यों अमल नहीं हो सका ? मैं चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर इस के मुताल्लिक तफसीलन बयान दें। अगली स्कीम तीन करोड़ रुपये की फोर्जिंग की थी, इस में कोलैबोरैशन एग्रीमेंट भी साईन हो चुका था और फारिन इनवैस्टमेंट का अरेंजमेंट भी हो चुका था और लैटर ग्राफ इनटैंट भी गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया की तरफ से इश्यू हो चुका था लेकिन इस में भी जहां तक मैं जानता हूं कोई प्रोग्रैस नहीं हुई। दो करोड़ रुपये की मैशीन टूल्ज़ फैक्टरी थी इस के बारे में भी गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया की तरफ से लैटर ग्राफ इनटैंट जारी हो चुका था और नैगोशीएशन्ज भी जारी थीं कोलैबोरेशन के लिये। मैं तफसील में न जाता हुआ सरकार से आशा करूंगा कि इस बारे में कुछ रोशनी डालें। मैं केवल दूसरी स्कीमों का नाम ही ले देना चाहता

[श्री मोहन लाल]

हूं। ट्रैक्टर्ज़ एंड टिल्लर्ज़ की तीन करोड़ रुपये की स्कीम थी। मालूम होता है कि उस के लिये सरकार अभी लाइसेंस भी हासिल नहीं कर सकी हालांकि सरकार खुद कीन है, चीफ मिनिस्टर साहिब खुद कीन हैं। यह बयान वह देते हैं कि जालन्धर के करीब लगाने के लिये वह कीन हैं। एक और टफटिड कार्पिट्स की पचास लाख रुपये की स्कीम थी, वूल कोमर्ज़ प्रोजैक्ट पचास लाख रुपये का था। दस लाख रुपये का प्राजैक्ट प्रिसीयन कास्टिंग्ज़ का था यह भी आगे नहीं लाया गया, यह भी गवर्नमेंट आफ इंडिया से एप्रूव हो चुका था। पंचशील कोआप्रेटिव सोसाइटी में तीस लाख रुपये का वर्किंग कैपिटल था, क्या वजह है कि उस में रुकावट पड़ी हुई है? लैंड रोवर एंड स्माल कार प्रोजैक्ट में सरकार ने क्या किया है? स्पीकर साहिब, 26 करोड़ रुपये की यह बड़ी स्कीम्ज़ थीं जिन से पंजाब की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काफी तरक्की होने वाली थी (घंटी की आवाज़) मैं केवल एक बात कह कर खत्म कर दूंगा। मैं ने आपोज़ीशन के मैम्बर साहिबान से यह अर्ज़ किया है कि जहां तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सम्बन्ध है, इस बात पर हमें बिला वजह किसी किस्म की कोई नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए जिस से कोई रुकावट पैदा हो। सरकारी कर्मचारियों पर भी नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए और प्राईवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे भी नहीं। इस तरह से इस के रास्ते में बड़ी भारी रुकावट पड़ती है। कुछ बदकिस्मती से ऐसा वायुमंडल पैदा हुआ है, मेरा जो अनुभव है, मेरी जो वाकफियत है मैं उस के आधार पर यह बात कहता हूं कि ऐसी नुक्ताचीनी से, चाहे वह किसी तरह से भी हो, सरकारी कर्मचारियों में झिझक पैदा होती है और सब से बड़ी बात यह है कि प्राईवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में भी पंजाब के अन्दर आने में झिझक पैदा होती है। कुछ ऐसा वायुमंडल बन गया है, कुछ ऐसी बातें चलती हैं। इस लिये मैं चाहूंगा और चीफ मिनिस्टर साहिब से खास तौर पर प्रार्थना करूंगा कि हमारे लिये करने को अभी बड़े काम हैं। जहां हम ने पब्लिक सैक्टर को फरोग देना है, जो जो हमारी स्कीमें हैं उन को पूरा करना है वहां पर, प्राईवेट सैक्टर को भी पंजाब में खींचने के लिये हमें मुनासिब वायुमंडल पैदा करना होगा। जो किसी किस्म के शकूक प्राईवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स के मन में पैदा होते हैं उन को दूर करना होगा। हमें उन को इंन्सैन्टिव देने होंगे, उन को यकीन दिलाना होगा कि यहां पर प्राईवेट इंडस्टरी की एक बड़ी फील्ड है। हम प्राईवेट इंडस्ट्री को यहां पर हर लिहाज़ से फरोग देना चाहते हैं। इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि वह वाज़या तौर पर पालिसी का एलान करें कि वह किस तरह से प्राईवेट इंडस्टरी को यहां पर इंसैन्टिव देने जा रहे हैं। आप का शुक्रिया।

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : स्पीकर साहिब, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि इस इंडस्टरी की डिमांड के ऊपर इस हाउस के मोअज़िज़ मेम्बर साहिबान ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। जैसा कि मैम्बर साहिबान ने अपनी तकरीर के अन्दर कहा है, मैं मानता हूं इस बात को कि किसी भी राज की खुशहाली का दारोमदार इस बात पर है कि उस राज के अन्दर उद्योगधन्धे कितनी तरक्की करते हैं। वह उद्योगधन्धे छोटे पैमाने के हों या बड़े पैमाने के हों, बहर हाल हर राज की तरक्की का इनहिसार इस बात पर है कि वहां पर इन्डस्टरी ज्यादा से ज्यादा पनपे। श्री अग्निहोत्री साहिब ने अपनी तकरीर के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया कि हमारे राज के अन्दर जहां पर कि इकानोमी का

दारोमदार इस वक्त ऐगरीकल्चर पर है जब तक लोगों को इस लैंड प्रैशर से हटाया नहीं जाता तब तक पंजाब के अन्दर खुशहाली नहीं आ सकती । स्पीकर साहिब, मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे इस राज की प्रैक्टिकली ऐग्रीकल्चरल इकानोमी ही है। यहां की 64 फीसदी आबादी ऐसी है जिसका दारोमदार डायरैक्टली ऐग्रीकल्चर और कल्टीवेशन पर है। अगर हम ने अपने राज को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना है, हमने नेशनल इनकम को बढ़ाना है, लोगों को रोज़गार देना है, उन के स्टैंडर्ड आफ लिविंग को ऊंचा करना है तो लाज़मी है कि इस राज में हमें इंडस्टरी को ज्यादा से ज्यादा तरक्की देनी होगी (प्रशंसा) इंडस्ट्री पब्लिक सैक्टर में भी हो सकती है, प्राईवेट सैक्टर में भी हो सकती है। दोनों सैक्टरों में उन को पूरी तरह से ज्यादा से ज्यादा उत्साह देना होगा। मैं जानता हूं कि आज दुनिया में जो बड़े बड़े मुल्क हैं, खाह वह वैस्ट्रन कंट्रीज हैं खाह वह सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, उन की तरक्की का इनहिसार इसी बात पर है कि किस तरह से उन्होंने लोगों, अपनी पापुलेशन को लेंड प्रैशर से हटा कर इंडस्ट्रीज की तरफ लगाया है। अगर आप पिछले साठ सत्तर साल के सारी दुनिया के इतिहास को देखें तो उस से आप को पता चलेगा कि यू. ऐस. ए. के अन्दर पिछले साठ सालों के अन्दर वह उस पापुलेशन को जिसका इनहिसार ऐग्रीकल्चर पर था 54 से ले कर नीचे 8 परसेंट तक ले गए । सिर्फ यू. ऐस. ए. की ही बात नहीं। दुनिया के अन्दर जितने भी धनवान देश हैं उन्होंने अपनी ऐग्रीकल्चर पापुलेशन को इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट किया है। जापान के अन्दर पिछले बीस तीस सालों के अन्दर ऐग्रीकल्चर पर पापुलेशन 80 परसेंट से 48 परसेंट पर ले आए हैं । इसी तरह से यू. के. में वह पापुलेशन 16 से 7 परसेंट तक आ गई है। फ्रांस जैसे बड़े देश ने भी इसे 42 परसेंट से 25 परसेंट पर ला दिया है । तो कहने का मतलब यह है कि वहां की तरक्की का दारोमदार ही इस बात पर है कि वहां पर ऐग्रीकल्चर पर दबाव को कम करके किस कदर इंडस्टी की तरक्की की है। स्पीकर साहिब, जहां तक हमारे इस राज का ताल्लुक है मैं तो ऐग्रीकल्चर को भी एक इंडस्टरी के तौर पर ट्रीट करता हूं। जितने मैम्बर साहिब बोले हैं उन सब ने इसी बात पर स्ट्रैस ले किया है कि जहां पर पंजाब ने समाल स्केल इंडस्टरी के अन्दर तरक्की की है वहां वह लार्ज हैवी इंटडस्टरी के लिहाज़ से बहुत पीछे है। स्पीकर साहिब, जहां सारे हिन्दुस्तान के अन्दर सरकार ने पहली, दूसरी और तीसरी पांच साला पलानों में इस हैवी इंडस्टरी पर 2130 करोड़ रुपया रखा था उस में हमारे हिस्से में सिर्फ 30 करोड़ यानी 1.4 परसेंट आया। इस पर ज्यादा ज़ोर देने की जरूरत है। और यही वजह है कि जब मैं अपने राज के बाकी सारे हालात को देखता हूं, आर्गेनाईज़ड इंडस्टरी के अन्दर एम्पलायमेंट को देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि यहां पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस लिये इस सिलसिले में हमें राज के अन्दर काफी हिम्मत दिखानी होगी। मैं और मेरे साथी इस बात पर बिल्कुल मुतफिक है और हमें आशा है कि हमें इस दिशा में कामयाबी हासिल होगी। स्पीकर साहिब, जहां तक आर्गेनाईज्ड इंडस्टरी का ताल्लुक है, जहां तक लार्ज स्केल और हैवी इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक है, हमारे राज की सिर्फ 0.6 परसेंट आबादी है जो कि इस में हिस्सा ले रही है हालकि इसके मुकाबले में वैस्ट बंगाल के अन्दर 2.20 आबादी और महाराष्ट्र और गुजरात में 1.7 परसेंट आबादी का इनहिसार इस हैवी इंडस्ट्री के ऊपर है। इसी तरह अगर हम

[मुख्य मंत्री]
पर कैपिटा इंडस्ट्रियल इन्वैस्टमैंट के लिहाज से देखें तो यह पंजाब के अन्दर सिर्फ 42.5 रुपये है जबकि वैस्ट बंगाल के अन्दर 163 रुपये 50 पैसे और महाराष्ट्र के अन्दर 170 रुपये 50 पैसे है। इस लिहाज से भी हमारा सूबा बहुत पीछे है। इसी तरह से अगर हम सारे पंजाब के अन्दर इंडस्ट्रीज़ की, चाहे वह छोटे उद्योगधन्धे हैं, चाहे मीडियम हैं, चाहे विलेज इंडस्ट्रीज हैं, चाहे समाल-स्केल की हैं या कुछ थोड़े बहुत लार्ज-स्केल इंडस्ट्रीज हैं, प्रोडयूस के लिहाज से टोटल आउटपुट को देखें तो वह हमारी नैशनल इनकम की सिर्फ 11 पर सेंट बनती है। जहां तक टोटल एम्पलायमेंट का ताल्लुक है, हमारे राज के अन्दर जैसा कि मैंने पहिले अर्ज़ किया जहां ऐग्रीकल्चर पर हमारी 64 पर सेंट आफ दी पापुलेशन का दारोमदार है, वहां इंडस्ट्रीज के अन्दर अब तक सिर्फ 9.3 पर सेंट लोग ही काम कर पाए हैं। ऐसी हालत में हमें पंजाब को इंडस्टरी के लिहाज़ से आगे ले जाना है और यकीनन आगे ले जाना है। मैं जानता हूं कि हमारे सूबा के लोग बड़े एंटरप्राइजिंग स्पिरिट के हैं, उन के अन्दर इनिशिएटिव है, हिम्मत है, उन के अन्दर स्किल है, ताकत है, मैनुअल लेबर करने की स्पिरिट है और उन्होंने पंजाब को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने में पहिले ही बड़ा इम्पार्टेंट पार्ट पले किया है। वहां पर सैकंड पलैन के आखिर तक हमारे सूबा के अन्दर इंडस्टरी के सैक्टर में सारी आउटपुट 123 करोड़ रुपये की थी वहां हम यह आशा रखते हैं कि चौथी पलैन के आखिर तक हम इस को 285 करोड़ रुपये के करीब तक ले जाएंगे।

अब मैं आप के सामने उन बातों का ज़िक्र करना चाहता हूं जो कि हमने आगे करनी हैं और करना चाहते हैं। मैम्बर साहिबान ने कुछ सवाल उठाए हैं और वाकई बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं ताकि पंजाब इस लिहाज़ से तरक्की करे। मैं उन बातों का भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। स्पीकर साहिब, जब हमारे पंजाब का पार्टीशन हुआ तो हमारे यहां जितनी भी थोड़ी बहुत इंडस्टरी थी वह बिखर गई। जब हमारी पिछली पलैन खत्म हुई तो उस वक्त पंजाब के अन्दर 35,500 आदमी ऐसे थे जो कि इंडस्टरी पर काम करते थे। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि जब तीसरी पलैन के आखिर तक हमारी सभी स्कीम्ज़ पर जो कि हाथ में हैं अमलदरामद हो जाएगा और हम चौथी पलैन के अन्दर दाखिल होने वाले होंगे तो उस वक्त हमारे पंजाब राज्य के अन्दर दो लाख के करीब आदमी ऐसे होंगे जिन को इंडस्टरी के अन्दर एम्पलायमेंट मिल सकी होगी। मैं मानता हूं कि हम ने इस बात को और भी ज्यादा अहमियत देनी है। जहां तीसरी पलैन के अन्दर इंडस्टरीज़ पर हमारे राज में 13 करोड़ के करीब रुपया इन्वैस्ट हुआ वहां आप को यह जानकर खुशी होगी कि चौथी पलैन के अन्दर इस मक्सद के लिये हम 32 करोड़ रुपये के करीब इन्वैस्टमैंट करने जा रहे हैं। और 30 करोड़ में से 13 करोड़ तीसरी प्लैन के अन्दर इन्वैस्टमेंट हुई थी। स्माल-स्केल इन्डस्ट्री को हम इस तरह से ज्यादा से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। स्पीकर साहिब, मुझे यह कहने में खुशी है कि आज सारे पंजाब के अन्दर टैक्नीकल ऐडवांसमैंट हो रही है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के सिलसिले में नया जोश आया है। हम चाहते हैं कि पंजाब में ऐन्सीलरी और फीडर इन्डस्ट्रीज़ लेंगे और हम लार्ज-स्केल इन्डस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं। इस बारे में पंडित मोहन लाल जी ने पुराने कुछ केसिज़ का जिक्र किया। इस

बारे अर्ज है कि इस हकूमत ने चार्ज लेते ही सारी स्कीम्ज़ पर पूरी तरह से गौर किया, उन को ऐग्जामिन किया और यह देखने की कोशिश की कि उन में स कौन सी फीज़ीबल हैं और राज्य के फायदे के लिये हैं । उन्होंने टाइम्ज़ आफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला दिया हालांकि वह गलत खबर थी और उस की तरदीद भी कर दी गई थी मगर उस तरदीद की तरफ इन का ध्यान नहीं गया । उन स्कीम्ज़ में से जो एयर राइफल फैक्टरी की स्कीम थी उस को हम ने पूरी तरह से ऐग्जामिन किया । रेवियू करने के बाद जो रिपोर्ट आई उस से पता चला कि यह हमारे राज्य के लिये किसी तरह से भी फायदामंद नहीं हो सकती । उस की जो राइफलें तैयार होनी थीं वह टायज़ जैसी लगती थीं जो कि बिल्कुल छोटे पक्षियों को शूट कर सकतीं । उस की जो एक लाख 80 हजार पीसिज़ तैयार होने थे उन की मार्किट भी नहीं थी । तो इस तरह से जो राय हमारे पास पहुंची उस की हर एक चीज़ को हम ने देखा, किसी पुलीटीकल प्वायंट आफ वियू से नहीं बल्कि टैकनीकल प्वायंट आप वियू से उस पर जो 47 लाख रुपया खर्च होने वाला था उस का फायदा नहीं होने वाला था इस लिये सारे पहलुओं से उस को सोच कर एअर राइफल फैक्टरी को ड्राप कर दिया गया ।

जहां तक सीमलैस ट्यूब्ज़ का ताल्लुक है और स्टील कास्टिंग्ज़ प्लांट का ताल्लुक है उस के मुतालिक हम ने फैसला किया है कि इस स्कीम को न सिर्फ चालू ही करना है बल्कि उस को और बेहतर तरीके से चलाना है । (तालियां) इस के मुताल्लिक बहुत से फारेन कोलैबोरेटर्ज से दरखास्तें आई हैं । सारी चीज़ पर गौर किया गया है कि जो ऐग्रीमैंट्स किये गये वह सारे राज्य के लिये मुफीद थे या नहीं । जो भी ऐग्रीमैंट्स होंगे उन में राज्य के हित को सामने रखा जायगा । और जितना रुपया पहले ऐग्रीमैंट के मुताबिक खर्च होने वाला था उसे कम खर्च करके और ज्यादा फायदा राज्य के लिये हासिल किया जायगा । (तालियां) राज्य सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी को समझती है और इस को निभायगी । जहां तक पिग आयरन प्लाट का ताल्लुक है.......

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि सरकार हर जिम्मेदारी को निभायेगी । मगर जो इन्होंने ऐक्सपोर्ट, प्रोमोशन कार्पोरेशन के बारे में बयान दिया था कि उन को हटाया जायगा, मैनेजमैंट को तबदील किया जायगा क्या उस बारे में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, पिग आयरन प्लांट के बारे में राओ निहाल सिंह, पंडित मोहन लाल, बहन चन्द्रावती वगैरह ने ज़िक्र किया । स्पीकर साहिब, इस सरकार ने आते ही इस तरफ ध्यान दिया । चुनांचि इंगलैंड की जो भारी पार्टी है "मैसर्ज़ ऐशोर बांड्ज़ पीस, जिन के साथ इस बारे में ऐग्रीमैंट हुआ था उन को कन्टैक्ट करने की कोशिश की । और हम ने इस बारे में जो हाई लैवल पर इस स्कीम का गवर्नमैंट आफ इंडिया ने इस का जो ऐग्जामीनेशन किया था उस को देखा, टैक्नीकल टीम, मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्रीज़ के सैक्रेटरी और मुताल्लिका मिनिस्टर से भी बात की । दिसम्बर 1964 में टैक्नीकल कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास पहुंची और उस के मुताबिक हम ने फैसला किया है कि इस प्लांट को पब्लिक सैक्टर में लगाना है । इस प्लैन के मुताबिक इस पर कोई चार करोड़ 80 लाख रुपया खर्च होगा । इस की दो फेज़िज़ होंगी, एक तो 1967 के आखीर तक होगी

[चौधरी नेत राम]

इस पर दो करोड़ 89 लाख रुपया खर्च होगा और बाकी का एक करोड़ 61 लाख रुपया बाद में खर्च होगा। और ऐसा अन्दाजा है कि अगले ढाई तीन साल के अन्दर कोई एक लाख टन के करीब प्रोडक्शन शुरू हो जायगी और इस से जितनी पंजाब की फाउंडरीज़ हैं उन को पिग आयरन दे सकेंगे। यह अपनी किस्म का पहला पब्लिक सैक्टर का प्राजैक्ट होगा। कुछ सवाल उठाए गए और वाजिब उठाए गए बहन चन्द्रावती और राम्रो निहाल सिंह वगैरह की तरफ से कि रा मैटीरियल तो महेन्द्रगढ़ से आता है और इस को सतरौड़ खुर्द, हिसार, में लगा रहे हैं। इस का हक तो महेन्द्रगढ़ को है कि यह वहां लगे। इस बारे में मैंने पहली तारीख को मैम्बरान की मीटिंग बुलाई है ताकि इस के बारे उन से बात-चीत कर सकूं मगर इस बारे में अर्ज़ है कि हिन्द सरकार की टैकनीकल टीम ने तीन ज़रूरियात बताई हैं। मैम्बरान देखें कि इस बारे में कोई फैसला अपने आप नहीं किया है यह फौरन कनसलटैंट्स की रिपोर्ट की बिना पर फैसला किया गया है। यूनाइटिड किंगडम की जो कम्पनी मैसर्ज़ ए. डी. पी. है उस ने पूरी तरह से जांच कर के तीन ज़रूरियात बताई हैं। उन्होंने कहा है और यह सब से बड़ा रीज़न है कि इस प्राजैक्ट के सिलसिले में रोज़ाना 7 लाख गैलन पानी आयरन बलास्ट फरनेस में सरकुलेशन के लिये दरकार हैं। इतना पानी महेंद्रगढ़ में अवेलेबल नहीं है, सतरौड़ में अवेलेबल है। ब्राडगेज़ और मीटर गेज़ रेल का भी सवाल है। ऐसी फैक्ट्रीज़ ब्राडगेज़ पर हैं। कोक वगैरह को भी देखा है। हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महेंद्रगढ़ में चीप मिलती हैं। मगर यह भी देखा गया है कि वहां पर कोक और दूसरी चीज़ें दस फीसदी ज़ाया हो जाती हैं इस के साथ ही एक और चीज़ है जिसे देखना है।

जहां पर आज हम इंडस्ट्री में इतने आगे होने की कोशिश में हैं, हम इंडस्ट्री के लिये एक सब से ज़रूरी आईटम पर भी ध्यान देते हुए पंजाब में एक पिग आयर न प्लांट लगा रहे हैं और इस के साथ साथ एक प्राजैक्ट लगाने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। यह सारी चीज़ इस सूबे के अन्दर बहुत जल्द चालू हो जायगी। मैं हाउस को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस प्लांट के लिये जितनी भी ऐस्टैब्लिशमैंट और लेबर होगी उस के लिये हम महेंद्रगढ़ के एरिये को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देंगे। मैं, स्पीकर साहिब, अर्ज़ कर रहा था कि पिग आरयन प्राजैक्ट पर हम पूरी तरह से अमल दरामद करने जा रहे हैं। इस के साथ ही मैं हाउस की वाक्फीयत के लिये यह भी बता देना चाहता हूं कि इन के इलावा हम और भी प्राजैक्ट्स इस सूबे में खोलने की कोशिश में हैं। इन के मुताल्लिक लाइसैंसिज़ ओबटेन किये जा चुके हैं और इन के मुताल्लिक गवर्नमैंट आफ इंडिया से मनज़ूरी ली जा चुकी है। हम एक इंडस्ट्रियल कारपोरेशन भी बनाना चाहते हैं जो तीसरी फाईव-इयर प्लैन के आखरी साल तक पूरी तरह से मुकम्मल हो जायगी। हम ने कुछ ऐसे स्टेट सपान्सर्ड प्राजैक्ट्स भी तैयार करने का फैसला किया है, जिन के मुताल्लिक हमें गवर्नमैंट आफ इंडिया से लाईसैंस भी मिल चुका है (तालियां)। इन के ऊपर हमारी कोई एक करोड़ रुपये की इनवैस्टमैंट होगी। इस साल से इन को स्टार्ट करने के लिये हम ने काफ़ी रुपए का प्रोवियन किया है।

मशीन टूल प्राजैक्ट के ऊपर हमारी कोई एक करोड़ रुपये की इनवैस्टमैंट होगी। इस साल के बजट में हम ने दो लाख रुपया प्रोवाईड किया है, ताकि टूलज़ और छोटी मोटी मशीनरी खरीद कर कोई ऐडवांस ऐक्शन ले सकें।

इस के इलावा हम एक स्टील फोर्जिग्ज़ प्राजैक्ट $4\frac{1}{2}$ करोड़ की लागत का बनाने जा रहे हैं। इस साल हम ने इस के ऊपर कोई 8 लाख रुपया खर्च करने के लिये इस बजट में प्रोविज़न किया है। बाकी जो ज़्यादा खर्च करने की अगर हमें ज़रूरत होगी तो वह चौथी 5 साला प्लैन से यह सारी रकम हासल की जायेगी।

हम एक हैवी इलैक्ट्रिक प्लांट भी पंजाब में लगाने जा रहे हैं, यह हमारा बिगैस्ट प्राजैक्ट होगा जो कि 20 करोड़ रुपये की लागत से इस सूबे में बनाया जायेगा। दो लाख रुपये की प्रावीज़न ऐडवांस स्टडी के लिये इस के लिये प्रोवाईड करने का विचार है। इस के मुताल्लिक अभी गवर्नमैंट से लैटर आफ इनटैंट का इन्तज़ार किया जा रहा है। गवर्नमैंट आफ इंडिया ने हमें यकीन दिलाया है कि इस के लिये हम निसैसरी इन्स्ट्रक्शन्ज़ इशू कर रहे हैं।

इस के इलावा हम ने हिंद सरकार को कुछ और प्राजैक्ट्स के लाईसैंस देने के लिये लिखा है। वह यह है :—

(1) Oscilloscope. यह इलैक्ट्रिकल इन्स्ट्रूमैंट्स की मैनूफैकचर करने के लिये एक प्राजैक्ट है जिस पर कुल 55 लाख रुपये के करीब खर्च आयेगा। (विघ्न)

पंडित मोहन लाल दत्त : आप तो अकेले महेंद्रगढ़ ज़िले का ही ज़िक्र कर रहे हैं, क्या दूसरे इलाकों को भी कुछ देने दिलाने की बात होगी ?

मुख्य मंत्री : पंडित जी, आप सबर से काम लें, टर्न बाई टर्न मैं आपके इलाके की तरफ भी आ रहा हूं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम इंडस्ट्री में और क्या क्या करने जा रहे हैं। हम पावर टिलरज़ की मैनूफैकचर के लिये भी एक प्लांट लगाने जा रहे हैं जिस में से 12,000 के करीब पावर टिलर सालाना तैयार हुआ करेंगे। इस का लाईसैंस लेने के लिये हम ने गवर्नमैंट आफ इंडिया को लिखा हुआ है। इस के इलावा हम ने एक स्टेनलैस स्टील का प्राजैक्ट बनाने के लिये गवर्नमैंट आफ इंडिया को एप्लाई किया है। इस के ऊपर भी हम 5 करोड़ रुपये की टोटल इनवैस्टमैंट करेंगे।

एक हम कोक ओवन प्लांट 4 : 5 करोड़ रुपये की लागत से पंजाब के लिये लगाने जा रहे हैं। गवर्नमैंट आफ इंडिया ने प्रिंसिपली हमारी मांग को ऐग्री कर लिया है। हम इसे जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं हाऊस की इनफरमेशन के लिये यह बात भी अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूं कि हम प्राईवेट सैक्टर में एक इंडस्ट्रियल प्राजैक्ट जो कि न्यूज़प्रिंट फैक्टरी के लगाने के मुताल्लिक लगाने लगे हैं। यह फैक्टरी फारेस्ट रिसोर्सिज़ पर लगाई जायेगी और यह M/s K.C. ABITIBI Group की तरफ से लगाई जा रही है। इस पर हमारी 10 करोड़ रुपये की इनवैस्टमैंट होगी और इस के लिये जो रा मैटीरियल दरकार है वह हमें आसानी से मिल सकता है इस के लिये हम ने रिसर्च की है कि कुल्लू और कांगड़ा में 75 प्रतिशत के करीब यह रा मैटीरियल हमें मिल सकता है। एक चीज़ मैं जो कहनी भूल गया था कि हमें यह इण्डस्ट्रीज़ पंजाब में इन्स्टाल करने के लिये दिक्कत थी, मगर यह बात जान कर हाउस को खुशी होगी कि यह फारन एक्सचेंज पंजाब में इन्डस्ट्रीज़ इन्स्टाल करने के लिये

[मुख्य मंत्री]
हमें बखूबी मिलता रहेगा। हम अब पंजाब में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाने के काबल हो गये हैं।

हम इस बात की तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट के वक्त एक प्राईवेट कनसर्न की फैक्ट्री लगाने के लिये गवर्नमेंट की बात चीत हो रही थी। मगर सिलसिला और ज्यादा उस वक्त चल नहीं सका। उन्होंने जो लाईसैंस था वह सरंडर कर दिया था। हम इस को दो बारा इशू कराने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब में इनडस्ट्री ज़रूर लगे चाहे यह प्राईवेट सैक्टर में हो और चाहे यह पब्लिक सैकटर में हो। इस के इलावा कुछ और प्राजैक्टस भी हैं जिन को हम स्टडी कर रहे हैं और इन में से कुछ और आने वाली चौथी पांच-साला पलैन में इन को इन्स्टाल करने के हम काबल हो जायेंगे। वह यह है (i) Centrifugal pumps, (ii) power sprayers (iii) submersible electric motors and pumps and cellar drainer pump motors (iv) particle boards and clip boards and ready made garments के मुताल्लिक हम इन सब को स्टडी कर रहे हैं; जो फोर्थ पलेन तक हम मुनासिब समझेंगे इनस्टाल करने की कोशिश करेंगे।

मैं यहां पर एंगलो इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन के मुताल्लिक भी कुछ अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूं कि यह कारपोरेशन का आथोराईज़ड कैपीटल 5 करोड़ रुपये होगा और एग्रीकलचर और इंडसट्री के ज्यादा से ज्यादा कलोज़र कांटैक्ट कायम करने में हमारी इमदाद करेगी। यह इस तरह से एग्रो-इंडस्ट्रीयल एकानमी भी पंजाब के अंदर कायम करेगी। हम इस तरह से ऐग्री कलचर में भी इंडसट्रीयल इमपीटस देना चाहते हैं। हमें इस तरह की कारपोरेशन से एक तरह ऐग्रीकलचर के लिये फर्टेलाईजर मिल सकता है और दूसरी चीज़ें भी दसत्याब हो सकेंगी जो हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगी। इस के लिये हम ने इस साल के बजट में 20 लाख रुपये का प्राविज़न किया है। यह दूसरे प्राजैक्टस को भी फिज़ीबिलटी स्टडी करेंगे और प्राईवेट ऐंटरपराईज़ को इंडस्ट्रियल यूनिटस बनाने में भी यह एक तरह से इमदाद देगी। मैं हाऊस को आप के ज़रिये यकीन दिलाता हूं कि हम इंडस्ट्री की तरफ मुकम्मल तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि पंजाब में इंडसट्री की काफी कमी है।

पंजाब में इन्डस्ट्री इनस्टाल करने के मुताल्लिक मैं ने चेयरमैन, पलैनिंग कमिशन, प्राईम मनिस्टर साहिब और यूनियन के इन्डस्ट्री मिनिस्टर साहिब से पूरी तरह से बात चीत की है। और यह बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि उन्होंने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है इंडस्ट्री के मुताल्लिक जितनी भी पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम्ज़ हैं उन के लिये हिंद सरकार की तरफ से फुल कन्सिडरेशन दी जाएगी और उन की तरफ से जहां तक भी इमदाद हो सकेगी वह की जायेगी। इस के इलावा नैशनल डिवलपमैंट कौंसिल के अन्दर हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब को ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री मिले। स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि हमें पंजाब के अन्दर एक नाइलौन प्लांट भी मिलेगा। और ऐसी भी कोशिश हो रही है कि पेपर मेकिंग मशीनरी प्लांट भी हम को मिले। स्पीकर साहब, 1964-65 के अन्दर बहुत से लाइसेंस मिले हैं, जिनमें लैटर आफ इंटैंट भी हैं और मेरा ख्याल है कि 80 के करीब गवर्नमैंट आफ इंडिया से लैटर आफ इंटैंट

मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ 7 मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिये भी बात चल रही है। आशा है कि यह हमको मिल जाएंगी ।

कभी कभी हमारे दोस्त हरियाणे का सवाल उठाते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हम उन को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देना चाहते हैं। हम उनकी तरक्की के लिये फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोनीपत, गनौर, बहादुरगढ़ जो कि इंडस्ट्रियल बैल्ट है, इन में नए नए यूनिट इंडस्ट्री के लिहाज़ से दे रहे हैं। जैसे स्कूटर के पार्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, ट्रैक्टर्स के पार्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, रबर टायर्स, इलेक्ट्रोनिक्स, ऐक्सरे वगैरह के प्लांट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज हम इन शहरों को दे रहे हैं। और सोनीपत के अन्दर गनौर में स्टील ट्यूब प्लांट लगाने की बातचीत चल रही है। और यह बातचीत अमेरिका की एक बड़ी भारी कम्पनी के साथ हो रही है। इसके लगने पर 1 लाख 20 हज़ार टन स्टील ट्यूब सालाना तैयार होगी । हमें स्टील ट्यूब प्लांट का लाइसेंस मिल चुका है। इसी तरह तीन और प्राजैक्ट्स के लिये लाइसेंस मिला है। क्रेन बनाने के लिये और ट्रैक्टर्स बनाने के लिये हमारी कोशिश हो रही है और उसका लाइसेंस मिल चुका है (प्रशंसा)

पंडित चिरंजीलाल शर्मा : गनौर में जो सीमलैस टयूब फैक्ट्री लगाने का फैसला किया था उसका क्या हुआ ?

मुख्य मन्त्री : वह मैं कह चुका। हरियाने में महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिये इन्सैक्टेसाइड के लिये 5 लाख का प्लांट नारनौल में लगेगा। और जींद के अन्दर टैक्सटाइल मिल लगा रह हैं। (विघ्न)

कामरेड शमशेर सिंह जोश : जो 50 हज़ार टैक्सटाइल वर्कर्स के मुताल्लिक कहा गया था उसका भी ज़िक्र कर दीजिए। (शोर)

मुख्य मन्त्री : सारी चीज़ को देखते हुए स्पीकर साहिब, मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूं कि हरियाना के अन्दर हम 46 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। (शोर) एक स्टील प्राडक्शन का कारखाना जर्मन डैमाक्रेट रिपब्लिक के कालोब्रेशन से हम लगाने जा रहे हैं जिस पर 2 करोड़ 50 लाख रुपया लगेगा। और जब यह कारखाने लग जायेंगे तो 6 हज़ार आदमी इम्पलाए होंगे ।

कामरेड भान सिंह भौरा : इतनी स्पीड से समझ में नहीं आता और न जवाब मिलता है।

चौधरी खुरशीद अहमद : आज का ज़माना स्पीड और स्पीच दोनों का है, वह दोनों ही मिल रही हैं।

मुख्य मन्त्री : जहां तक हरियाना का सवाल है, मैं समझता हूं कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। हरियाने के लिये इस साल 56 लाख रुपया लोन दिया है और उन में 1,714 पार्टीज़ पंजाबी रिजन की हैं और 1,858 पार्टीज़ हिन्दी रिजन की हैं। यह जो सुनार बेकार हो गये थे न को रोज़गार देने के लिये पिछली दफा 9 लाख 50 हज़ार रुपये लोन के लिये दिये गये थे ताकि उनकी मदद हो सके।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैनेजमैंट्स वर्करज़ को शेयर देने के लिये गवर्नमैंट ने कोई पालिसी बनाई है और अगर बनाई है

[श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री]
तो उसका यहां ऐलान करें ताकि पंजाब के वर्करज़ की तसल्ली हो सके। इस के अलावा 50 हज़ार टैकसटाइल वर्करज़ के बारे में जो कुछ कहा गया है उस पर भी रौशनी डालें।

मुख्य मन्त्री : फिर जो भाई दूसरे मुलकों से अफरीका वगैरा से आ रहे हैं अगर वह पंजाब में बसना चाहते हैं और इन्डस्ट्रीज़ चलाना चाहते हैं उन को हम यह सारे कनसैशन्ज़ और सहूलतें जो इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ प्वायंट्स में दे रहे हैं दी जाएंगी चाहे वह अपनी फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीयल ग्रोथ प्वायंट से बाहर भी सैट अप करें। यह सारे इनसैंटिव्ज़ उन को दिये जायेंगे। और मज़ीद डिटेलज़ इस इनसेन्टिवज़ के बारे में और इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ प्वायंट के सिलसिले में वर्क आउट की जा रही है। मैं हाउस को यह भी बताना चाहता हूं कि किस इलाके में कौनसी इन्डस्ट्री जानी चाहिए और इन इन्डस्ट्रियल ग्रोथ प्वायंटस की सिलैक्शन के बारे एक कमेटी भी बनाई जा रही है जो गवर्नमैंट को इस बारे में सलाह मश्विरा देगी। यह कमेटीज़ ज़िला लेवल पर होंगी। इन कमेटीज़ के चेयरमैन डी.सी. होंगे और मैम्बर एक्स. ई. एन., पी. डब्ल्यू डी, एक्स, ई. एन. पब्लिक हैल्थ, एक्स. ई. एन. इलैक्ट्रीसिटी होंगे और इन में एक नुमाईंदा टाउन एण्ड कंट्री प्लैनिंग वालों का होगा, एक प्रोग्रेसिव इन्डस्ट्रियलिस्ट होगा, ज़िला का इन्डस्ट्रीज़ आफिसर होगा और दो ऐम. एल. एज़. भी उस ज़िला के उसके मैम्बर होंगे। इन सब के सलाह मश्विरे से ही हम यह इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ प्वायंटस कायम करेंगे। मैम्बर साहिबान उस में अपनी पूरी तरह से राए दे सकते हैं इसी लिए उनको बीच में रखा गया है। (चीयर्ज़) कामरेड राम प्यारा जी ने एक भाई का ज़िक्र किया कि उसके पास 180 एकड़ ज़मीन है वगैरा वगैरा। ठीक है उसके पास इतनी ज़मीन है लेकिन जो उसके मुख्तलिफ प्राजैक्टस हैं उनके बारे में जो रिपोर्ट है जिनका मैं ने ज़िक्र किया है उनके मुताबिक उन प्राजैक्टस के लिए 150 एकड़ ज़मीन दरकार है। पांच हज़ार के करीब इन्डस्ट्रियल लेबर के मकानात भी बनाए जा रहे हैं। इसलिए इस ज़मीन की ज़रूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन का गवर्नमैंट आफ इन्डिया से ताल्लुक है। स्पीकर साहिब, मुझे यह एलान करने में खुशी होती है कि जितनी हमारी फाउंडरीज़ बटाला, गुराया, जालन्धर, लुधियाना वगैरा में हैं वहां से जो माल बाहिर भेजा जाता है उस के लिए गवर्नमैंट आफ इन्डिया ने मन्ज़ूर कर लिया है कि जो माल कांडला के रास्ते से जाएगा उसके ऊपर 50 फीसदी फ्रेट माफ कर दिया जाएगा।

EXTENSION OF TIME

Chief Parliamentary Secretary : Sir, I beg to move that the Guillotine be applied at 6.15 p.m. insted of 6.00 p.m.

Mr. Speaker : Does the House agree that the Guillotine be applied at 6.15 p.m. instead of 6.00 p.m. ?

(*Voices : Yes, Yes*)

Mr. Speaker : All right. Now the Guillotine will be applied at 6.15 p.m. instead of 6.00 p.m.

DEMANDS FOR GRANTS

35—Industries—96—Capital outlay on Industrial and Economic Development. (Resumption of Discussion concld.)

श्री मंगल सैन : मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जगाधरी में पिछले 15 दिनों से जो मैटल इन्डस्टरी ठप पड़ी है क्योंकि सैंट्रल गवर्नमैंट ने एक्साइज़ रेट ज्यादा कर दिया है उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, जो प्वायंट उन्हों ने उठाया मैं उसके बारे अर्ज़ करता हूं कि जगाधरी रेवाड़ी वगैरा के जो ठठेरे हैं उनका कोटा हम ने डब्ल कर दिया है और भी उनकी जो जो तकलीफें हैं हम उन को दूर करना चाहते हैं। कुछ दोस्त मुझे जगाधरी के मिले थे। हम उनकी प्राबलम्ज़ पर पूरा हमदर्दी से गौर कर रहे हैं कि किस हद तक उनको हम दूर कर सकते हैं।

श्री अमर सिंह : हरिजनों के बारे में भी कुछ बता दें कि उनकी प्राबलम्ज़ का क्या कर रहे हैं।

मुख्य **मन्त्री :** हरिजनों के लिए भी बहुत सारी स्कीमें हमारे ज़ेरे गौर हैं और वह स्कीमें लैदर इन्डस्ट्री से सम्बन्ध रखती हैं। अन्दाजा है कि $8\frac{1}{2}$ लाख के करीब मवेशी यहां पंजाब में हर साल मरते हैं। उनकी फलेइंग वगैरा के सिलसिले में युगोसलेविया गवर्नमैंट हमारी मदद करने जा रही है और हम ऐसा प्राजैक्ट शुरू करना चाहते हैं जिसमें कोई $1\frac{1}{2}$ हजार के करीब हरिजन भाइयों को काम दे सकेंगे लेकिन वह स्कीमें अभी वर्क आउट हो रही हैं फिर यहां रा मेटीरियल के सिलसिले में सवाल उठाया गया है कि इस के देने के लिए कुछ सेल का बेसिज़ और वक्त वगैरा की शर्त आयद हैं। मैं अर्ज़ करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। रेयर इन्डस्टरीज़, कु-आप्रेटिव और रूरल जो इन्डस्टरीज़ शुरू की जाएं उन पर कोई ऐसी पाबन्दी नहीं है। हम उनकी पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार हैं। यहां जो कन्ट्रोल्ड रा मेटिरियल के सिलसिले में शिकायत होती है कि इस में मालप्रैक्टिस होती है उसके सम्बन्ध में गवर्नमैंट ने कुछ जरूरी मेयर्ज़ लिए हैं। हम सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज़िला लैवल पर डीसैंट्रलाइज़ कर रहे हैं ताकि इस में जो देर होती है वह दूर हो। यह जो मुख्तिलफ चीजों की कुटेशन्ज़ होती हैं उनको हम सारे इन्डस्ट्रीयलिस्ट को वाइड पब्लिसिटी देंगे। सिर्फ यही नहीं है कि रा मैटीरियल के सिलसिले में जो सारे कोटा होल्डर्ज हैं हम उनकी लिस्टें प्रिंट करा रहे हैं। वह बल्कि लिस्टें मैम्बर साहिबान को दे दी जाएंगी और वह ज़िला इन्डस्ट्रीज़ अफसर के दफतर में भी होंगी जिन को हर कोई देख सकता है ताकि किसी को शिकायत करने का मौका न मिले कि किसी को नाजायज़ कोटा दिया है। आपके सामने सारी चीज होगी और आप देख सकते हैं कि कहां कोई नाजायज बात हुई है और हमारे नोटिस में ला सकते हैं (चीयर्ज़)।

6.00 p.m.

इस के मुताबिक हमारी तरफ से भी सक्रूटिनी हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि मैम्बर साहिबान जिन का यहां पर पूरी तरह से राइट है, और उनका इंट्रैस्ट है, वह भी इस बात को पूरी तरह से देख सकें। वक्त कम है मैं चाहता हूं कि सारी चीज हाऊस में रखूं ताकि माननीय सदस्यों को कोई गलत फहमी न रह। मैं माननीय सदस्यों से आशा रखता हूं कि वह इस बारे में पूरी तरह से सहयोग देंगे। मैं जनवरी के महीने में दुर्गापुर सेशन एटैंड करने के लिये गया था। मैं रा मैटीरियल की कमी के बारे में आइरन ऐंड स्टील कंट्रोलर, और चीफ सेल्ज़ मैनेजर आफ दी हिन्दुस्तान सटील से पर्सनली मिला। मैं ने उन को पंजाब के लिये कोयला, पिग आयरन और स्टील जल्दी सप्लाई करने के लिये

[मुख्य मन्त्र]

इम्प्रैस किया। इस सिलसिले में 15 हजार टन पिग आयरन हम नार्मल एलोकेशन से अधिक प्रोक्योर कर सकेंगे। इसी तरह से रशियन पिग आयरन काफी क्वांटिटी में देने का वायदा किया। यह प्रोपोजल गवर्नमैंट आफ इंडिया कंसिडर कर रही है। हमें जल्दी ही 4 रेक्स आफ काई प्रोडक्टस के मिल रहे हैं जोकि हमें फाउंडरी इंडस्ट्री के लिये अति जरूरत है। राओ निहाल सिंह ने माइनर वैल्थ के लिये जिक्र किया है। उस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि लाहौल स्पिति, कांगड़ा, महिन्द्रगढ़, अम्बाला ज़िला की मोरनी के इलाके की तरफ सरकार की तवज्जोह जा रही है। वहां पर एक्सपलोरेशन की जा रही है ताकि वहां पर पता चल सके कि वहां पर कच्चा लोहा, लाइम स्टोन और दूसरे पदार्थों की कितनी मिकदार है। तांबा लाहौल स्पिति में पाया गया है और वहां पर इस बारे में जांच की जा रही है। गैम्पसम लाहौल और स्पिति में है। कोयले के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। कोयला कालका से लेकर धर्मशाला तक हिमालया की छोटी छोटी पहाड़ियों में पाया गया है। इस के लिये एक्सपलोरेशन हो रही है। जोलोजीकल डिपार्टमैन्ट इस के बारे में स्टडी कर रहा है। इन सब चीज़ें का एम्पलायमैन्ट प्वायंट आफ व्यू से, इंडस्ट्रीज़ के प्वायंट आफ व्यू से पता लगाया जा रहा है। गुड़गांव के अन्दर सरकार साल्ट इंडस्ट्रीज़ के बारे में तवज्जोह दे रही है। इसके बारे में डीपार्टमैन्ट ऐक्सपलोरेशन कर रहा है। सरकार साल्ट इंडस्ट्रीज़ के लिये जो मदद दे सकेगी, देगी। महिन्द्रगढ़ और रिवाड़ी के इलाके में जो रा मैटीरियल मिलता है, उसका सरकार प्रयोग करेगी। सरकार की इस तरफ पूरी तवज्जोह है। वहां पर इंडस्ट्रीज़ लगाने की सोच रही है।

स्पीकर साहिब, मैं पोल्टरी की इंडस्ट्री के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। इस की ओर सरकार पूरी तवज्जोह देना चाहती है। इस में कुछ इम्पार्टैंट स्कीमों के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। यहां पर दो एयर कंडीशन्ड ट्रक ले रहे हैं जिस से पंजाब के अंडे इन ट्रकों में देहली भेजे जायेंगे। सरकार लोगों से कोई चार्जिज़ नहीं लेगी। इस तरह से पंजाब में अंडों की कीमत कम मिलती है और इस पर बुरा असर पड़ता है। उस से जनता को प्रोत्साहन ही मिलेगा। वहां पर अंडों की उचित कीमत मिलेगी। इसी तरह से पोल्टरी फीड के बारे में भी हम जनता की यथा सम्भव मदद करेंगे ताकि उन को इस इंडस्ट्री को चलाने में उत्साह मिल सके (विघ्न)।

श्री फतेह चन्द विज : आन ए प्वायंट आफ इन्फरमेशन, सर। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पानीपत में 1962 में पेपर मिल लगानी थी लेकिन बाद में वह स्कीम छोड़ दी गई थी। इस का मतलब यह है कि क्या पानीपत हरियाणा प्रान्त में नहीं है। इस के बारे में चीफ मिनिस्टर साहिब कुछ रोशनी डालें।

मुख्य मन्त्री : मैसर्ज़ बेदी ऐंड कम्पनी जिसने वहां पर पेपर मिल्ज़ लगानी थी, उस ने तीन साल से अपना वायदा पूरा नहीं किया। लेकिन गवर्नमैन्ट अभी इस बात के लिये तैयार है। वहां पर कोई आदमी मिल लगाने के लिये आगे हो और सरकार उस को लाइसेंस दिलवाने में पूरी मदद करेगी। (विघ्न)।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : वहां पर तो सब टटपूंजिये हैं। वहां पर और कोई बड़ा और मोटा आदमी लाना चाहिये ताकि वहां पर यह काम चालू कर सके।

मुख्य मन्त्री : मैं तो हरियाणा प्रान्त वालों को इस काम को चलाने के लिये कहता हूं। वहां से कोई भी आदमी आगे आए और सरकार उस की यथा-सम्भव मदद करेगी। (विघ्न)।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगल सैन हरियाणा प्रान्त के मोटे आदमी हैं (हंसी) (Shri Mangal Sein is a 'mota adami' of Hariana Prant) (*Laughter*)

श्री मंगलसैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। आपने ठीक फरमाया है कि मैं मोटा हूं लेकिन मेरे पास भी कोई रुपये नहीं हैं जिससे वहां पर पेपर का मिल लगा सकूं (हंसी)।

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हरियाणा प्रान्त वाले आगे आएं और सरकार उनकी पूरी तरह से यथा सम्भव सहायता करेगी। गवर्नमैंट उन को उचित फैसिलिटीज देने के लिए तैयार है। हमें 2 लाख 57 हजार स्पिंडल्ज मिले थे और उसके मुताबिक 2 लाख 16 हज़ार के करीब स्पिंडल्ज़ दे दिए हैं। (विघ्न) (शोर)

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ इन्फारमेशन, सर। चीफ मिनिस्टर साहिब ने बार बार कहा है कि हरियाना को सब प्रकार की मदद देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब में 28 इंडस्ट्रीज़ आफिसर हैं। उन में हरियाना प्रान्त का कोई भी नहीं है। हम इंडस्ट्रीज के बारे में किस से इन्फार्मेशन लें। इसी तरह सैक्रेटेरिएट के अन्दर भी हमारे इलाके के आदमी कम हैं। अगर चीफ मिनिस्टर साहिब इस तरह की गलत बयानी करें तो हम कहां से और किस तरह से सही बात का पता लगाएं। सरकार इंडस्ट्रीज की मद में सारे पंजाब में 458 लाख रूपए खर्च करने जा रही है लेकिन हरियाना में बहुत ही कम राशि खर्च करने जा रही है। इस तरह से यह गलतबयानी कर रहे हैं। जींद में इंडस्ट्रीयल एस्टेट बनाने का फैसला किया गया था। वहां पर इस काम के लिए ज़मीन भी एक्वायर कर ली थी। चौधरी दल सिंह की कोठी के पास सफेदी भी डाली गई थी लेकिन अब वहां पर इंडस्ट्रीयल एस्टेट नहीं बनाई जा रही है। इस की क्या वजह है ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि होशियारपुर ज़िले के अन्दर कार्ड बोर्ड इंडस्ट्री लगाई जा रही है (तालियां) स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर रहा था कि हमें 2 लाख 57 हजार स्पिंडल्ज़ मिले थे और उस में से 2 लाख 16 हज़ार के करीब थर्ड प्लान के अन्दर दे चुके हैं। हमने 17 के करीब नई मिल्ज़ के लाईसेंस दिए हैं और पांच में हम ने एक्सपैनशन के लिए स्पिंडल्ज दिए हैं। वह 53,000 हैं। यह सारे के सारे हरियाना के अन्दर भिवानी, हिसार, सिरसा, गुड़गांवां और बाकी जगहों पर लगा रहे हैं (विघ्न) (शोर)

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। इन्होंने सिरसा का नाम लिया है। वहां पर अबोहर के राए साहिब लाला कुंदन लाल की मिल है। सरकार ने उस को 80 लाख रुपया कर्ज दिया है। कपास तो हमारी होगी लेकिन फायदा फीरोज़पुर को पहुंचेगा। (विघ्न) हरियाना में जितनी भी टैक्सटाईल मिल्ज हैं वह अमृतसर

[चौधरी देवी लाल]
और फिरोजपुर के लोगों के पास हैं । हमारे इलाके के किसी आदमी के पास नहीं हैं । कपास हमारी पैसा हमारा और मुनाफा उठाते हैं इधर के लोग ।

श्री अध्यक्ष : यह मुनासिब नहीं है । (This is not proper.)

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, सात के करीब हम नई फैक्टरियां लगाना चाहते हैं । वह बठिंडा संगरुर और जींद के इलाके में लगाने के लिए तरजीह देंगे । मेरे पास टाईम नहीं है वरना मैं तफसीलन अर्ज करता । अग्निहोत्री और जोश साहिब ने पावर लूम्ज फैक्टरियों की तरफ ध्यान दिलाया है । मुझे खुशी है कि अमृतसर और लुधियाना के अन्दर बहुत भारी तादाद में फैक्टरियों ने काम शुरू कर दिया है। पहले जो कमेटी बनाई थी उस ने जो रिकुमैंडेशन्ज की हैं कि पीस मील के मुताबिक जो काम करते हैं उनके लिए एक अलग कमेटी बना दी जाए क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है । इस सारी चीज पर हम सब गौर करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले को हम ने लागू कर दिया और कमेटी बनाई है । हम सारी चीज पर गौर कर रहे हैं। टर्म्ज़ आफ रेफ्रेंस का जो नोटिफिकेशन चार मार्च को हुआ था उस को विद रीट्रासपैक्टिव इफैक्ट लागू किया जाएगा। हम चाहते हैं कि पंजाब की लेबर और फैक्टरी ओनर्ज के दरम्यान अच्छे ताल्लुकात पैदा किए जाएं ताकि पंजाब की इंडस्ट्री बढ़े पंजाब की लेबर को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और पंजाब की दौलत भी बढ़े । हम यह भी चाहते हैं कि पंजाब में फैक्टरियों की प्रोडक्शन ज्यादा हो और लेबर का भी फायदा हो । मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि पंजाब में सारी चीज अमनो-अमान से, शान्ति से चले और यहां पर अच्छा वायु मण्डल कायम हो। हम पंजाब की सनअत को तरक्की देना चाहते हैं । इस के लिए जरूरी है कि पावर मिल्ज को ज्यादा बिजली मिले और इस सिलसिले में हम ने फैसला किया है कि जहां पर 15 मैगावाट स्टीम जैनरेशन प्लांट थे उनको डबल किया जाए, और कर रहे हैं, वह काम मुकम्मल होने वाला है। 25 के करीब ऐसी जगहें हैं जहां पर ट्रांसफार्मर्ज की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है । सोनीपत में पहले 6 की कपैसिटी थी आज वहां पर ट्रांसफार्मर्ज की कैपेसिटी को दस कर दिया गया है, बहादुरगढ़ में 2 से 4 कर दी गई है , शाहाबाद में तीन से पांच कर दी गई है । नाभा में दस से डेढ़ी कर दी है । मुरिंडा में दुगुनी कर दी गई है हांसी में तीन गुना कर रहे हैं इसी तरह से सुनाम में डबल कपेसिटी कर दी गई है । स्पीकर साहिब, हम उन सारी बातों पर गौर कर रहे हैं जिन से इंडस्ट्री को नुक्सान पहुंचता है । हम इनक्वायरी करवा रहे हैं । अगले हफ्ते ही स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन, चीफ इंजीनियर और दूसरे अफसर एक एक जगह पर जाएंगे और यह मालूम करेंगे कि किस कारण से पावर ब्रेक होती है और इंडस्ट्री को क्यों धक्का पहुंचता है । हम उन कारणों को दूर करने की कोशिश करेंगे । स्पीकर साहिब, कुछ कमियां हैं लेकिन हम जल्दी ही उन को दूर करके पंजाब की इंडस्ट्री को तरक्की देने में कामयाब हो जाएंगे। आपका शुक्रिया ।

(Applause)

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100

The motion was lost

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 10

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1

The motion was lost

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1

The motion was lost

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1

The motion was lost

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 2,57,40,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66 in respect of charges under head 35-Industries.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,99,24,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 96-Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

The motion was carried.

Other Demands for Grants

Mr. Speaker : Now guillotine will be applied for the disposal of the remaining Demands for Grants.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 2,36,55,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 9-Land Revenue.

That a sum not exceeding Rs 13,62,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 10-State Excise Duties.

That a sum not exceeding Rs 8,69,610 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 11-Taxes on Vehicles.

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding Rs 31,58,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66 in respect of charges under head 12-Sales Tax.

That a sum not exceeding Rs 35,10,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under Head 13-Other Taxes and Duties.

That a sum not exceeding Rs 6,85,440 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 14-Stamps.

That a sum not exceeding Rs 94,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 15-Registration Fees.

That a sum not exceeding Rs 40,66,920 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 18-Parliament State and Union Territory Legislatures.

The motions were carried

Mr. Speaker : Question is—

That s a sum not exceeding Rs 73,55,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of Charges under head 21-Administration of Justice.

That a sum not exceeding Rs 88,74,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 22-Jails.

The motions were carried.

Mr. Speaker. : Question is—

That a sum not exceeding Rs 4,31,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 25-Supplies and Disposals.

That a sum not exceeding Rs 39,48,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 26-Miscellaneous Departments.

That a sum not exceeding Rs. 4,12,740 be granted to the Governor to defray the chages that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 27-Scientific Departments.

The motions were carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 5,32,23,640 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 29-Medical.

That a sum not exceeding Rs 3,58,33,420 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 30-Public Health.

The motions were carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,48, 25,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 33-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs 1,49,26,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment of for the year, 1965-66 in respect of charges under head 34-Cooperation.

The motions were carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 3,94,73,380 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 37-Community Development Projects, N.E.S. and Local Development Works.

That a sum not exceeding Rs 3,02,88,710 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 38-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs 45,05,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 39-Miscellaneous, Social and Developmental Organisations.

The motions were carried

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 7,50,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 47-Capital Outlay on Multipurpose River schemes.

That a sum not exceeding Rs 3,64,95,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 50-Public Works.

That a sum not exceeding Rs 1,70,15,520 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head Charges on Buildings and Roads Establishment.

That a sum of not exceeding Rs 3,08,43,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66 in respect of charges under head 52-Capital Outlay on Public Works.

That a sum not exceeding Rs 3,70,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 56-Aviation.

That a sum not exceeding Rs 5,72,04,240, be granted to the Governor to defray, the charges that will come in the course of payment for the year 1965-66, in respect of charges under head 57-Road and Water Transport Schemes.

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding Rs 13,01,930 be granted to the Gonernor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year, 1965-66,in respect of charges under head 61-Capital Outlay on Rail Road Co-ordination schemes.

That a sum not exceeding Rs 2,08,12,530 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 64-Famine Relief.

That a sum not exceeding Rs. 2,06,54,150 be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 65-Pension and other Retirement Benefits.

That a sum not exceeding Rs 7,83,830 be granted to the Governor to defray the charges that will come in ihe course of payment for the year 1965-66 in respect of charges under head 67-Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

That a sum not exceeding Rs 1,44,49,420 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 68-stationery and Printing.

That a sum not exceeding Rs 2,50,90,000 be granted to the Govenor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 70—Forest.

The motions were carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 6,46,210 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 76-Other Miscellaneous Compensations and Assignments.

That a sum not exceeding Rs. 8,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 78-Preparation Payments.

That a sum not exceeding Rs 16,34,950 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 78-A-Expenditure connected with National Emergency, 1962.

The motions were carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 9,79,54,200 be granted to the Governor todefray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 103-Capital Outlay on Public Works.

That a sum not exceeding Rs 2,03,16,880 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 105-Chandigarh Capital Outlay.

That a sum not exceeding Rs 3,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 109-Capital Outlay on other Works.

That a sum not exceeding Rs 7,80,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 112-Capital Outlay on Aviation.

That a sum not exceeding Rs 1,05,92,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66,in respect of charges under head 114-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs 1,68,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66, in respect of charges under head 120-Payment of Commuted Value of Pensions.

That a sum not exceeding Rs 23,38,77,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1965-66 in respect of charges under head 124-Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

That a sum not exceeding Rs 38,22,88,740 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course for payment of the year, 1965-66, in respect of charges under head Loans to Local Funds—Private Parties, etc. Loans to Government Servants.

The motions were carried.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 8.30 A.M. on Tuesday, the 30th March, 1965.

(*The House then adjourned till* 8.30 *a.m. on Tuesday, the* 30*th March*, 1965.)

4604 PVS —367—17-7-65—C. P. & S. Pb., Chandigarh

APPENDIX

to

Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. 2, No. 24, dated the 29th March, 1965

Buses plying on Certain Routes

2572. Sardar Kulbir Singh
Chaudhri Satya Dev } : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of buses being plied on (i) Dabwali to Fazilka, (2) Abohar to Ganga Nagar, (3) Abohar to Malout, (4) Abohar to Hanumangarh by the private transport companies ;

(b) the names of the partners of the said companies, the registration number of each bus plying on each of the said routes separately along with their time-tables on these routes ;

(c) the number of the Punjab Roadways buses plying on the routes mentioned in part (a) above along with the time-table being observed on each route separately ;

(d) whether the 50 :50 formula has been fully implemented on the above routes ?

Shri Ram Kishan : (a) to (d) A statement is as follows :—

STATEMENT

(a) The number of trips plied on the following routes are as under:—

(1) Dabwali-Fazilka	..	No direct service
(2) Abohar-Ganga Nagar	..	17
(3) Abohar to Malout	..	2
(4) Abohar-Hanumangarh	..	2½

(b) The names of the partners of the said companies and the registration No. of vehicles alongwith their time tables are given below:

Name of the Company	*Names of the share-holders*
Fazilka-Dabwali Transport Co., Abohar	1. Shri Daulat Ram Nagpal
	2. Shri Shankar Dass Nagpal
	3. Shri Milkhi Ram Nagpal
	4. Shri Madan Lal Nagpal
	5. Shri Manohar Lal Nagpal
	6. Shri Krishan Lal Nagpal
	7. Shri Shiv Charan Dass Nagpal
	8. Shri Jagdish Chandar Nagpal
	9. Shri Parma Nand Ahuja
	10. Shri Ved Parkash Ahuja
	11. Shri Subash Chander Satia
	12. Shri Nathu Ram Narang
	13. Shri Bhopinder Rai Narang
	14. Shri Naunihal Singh
	15. Shri Mathra Dass
	16. Shri Vassan Dai
	17. Shri Shankar Dass Satia
	18. Shri Ramesh Chander Satia

Janta Transport Co-operative Society, Abohar

1. Shri Banwari Lal
2. Shri Ram Partap
3. Shri Jagraj Singh
4. Shri Raja Ram
5. Shri Hanuman
6. Shri Indubala
7. Shri Hari Ram
8. Shri Dhaunkria Ram
9. Shri Dev Karan
10. Shri Balwant Singh
11. Shri Brij Lal
12. Shri Sada Sukh
13. Shri Mani Ram
14. Shri Hari Ram
15. Shri Ram Chand
16. Shri Krishan Kumar
17. Shri Lalpat
18. Shri Hira Lal
19. Shri Inderjit
20. Shri Het Ram

Abohar Pursharthi Transport Co-operative Society Ltd., Abohar.

ANNEXURE 'A'

Jai Transport Co-operative Society Ltd., Abohar

ANNEXURE 'B'

(ii) Name of the Company	Registration held	Number of vehicles
Fazilka -Dabwali Transport Co. Abohar	PNR-1983 PNF-6086 PNF-6087 PNF-6255 PNF-6258 PNF-6454 PNF-6455 PNF-6496 PNF-6626 PNF-6748 PNF-6749 PNF-6774 PNF-6775 PNF-6776 PNF-6800 PNF-6801 PNF-6824 PNF-6845 PNF-6846 PNF-6862 PNF-6996 PNF-7979 PNF-9645 PNF-9646	(The company has a sanctioned fleet of 24 vehciles and any vehicle on any route sanctioned to them out of the said fleet can be plied)
Janta Transport Co-operative Society Abohar	PNF-6848 PNF-6807 PNF-5547 PNF-5548 PNF-6964 PND-234 PND-236 PNF-9708	(The Society has a sanctioned fleet of 8 vehciles and any vehcile on the routes sanctioned to them out of the said fleet can be plied)
Abohar Pursharthi Transport Co-operative Society Ltd. Abohar	PNF-6851 PNF-9562	
Jai Transport Co-operative Socieety Ltd. Abohar	PNF-3566	

Name of the Company	*Name of the route*	*Time-table*	
Fazilka-Dabwali Transport Company	Abohar-Ganga Nagar	Abohar	Ganga Nagar
		6.15	9.00
		12.00	11.30
		14.00	14.30
	Abohar to Malout	Abohar	Malout
		14.15	9.00
		17.00	17.45
	Abohar-Hanumangarh	Abohar	Hanuman-garh
		Services on Abohar-Hanumangarh route are operating in rotation with Rajasthan operators. The time-table of the joint route is approved by Rajasthan Transport Authorities. State, as the share of Rajasthan State is 12 trips and 5 of Punjab State	
Janta Transport Co-operative Society Abohar	Abohar -Ganganagar	Abohar	Ganganagar
		7.20	7.45
		9.15	9.45
		10.30	11.30
		11.30	12.30
		12.30	13.00
		13.30	14.00
		14.30	15.00
		15.30	16.00
		16.30	17.30
		17.30	18.15
Abohar Pursarthi Transport Co-operative	Abohar-Ganganagar	Abohar	Ganganagar
		13.00	10.30
		18.15	15.30
Jai Transport Co-operative Society	Abohar-Ganganagar	Abohar	Ganganagar
		10.00	12.30
		15.00	16.45

(c) 1. Dabwali to Fazilka .. Time table Nil — No. of buses Nil

2. Abohar to Ganganagar	..	Abohar 16.45	Ganganagar 8.15	One
3. Abohar to Malout	..	Abohar 9.00, 13.40	Malout 14.45, 15.50	One
4. Abohar to Hanumangarh	..	Abohar 16.10	Hanumangarh 7.45	One

(1½ return trip is being operated in rotation with private operators)

(d) Yes to the extent done in the case of other routes.

ANNEXURE 'A'

List of members of share-holders of the Abohar Pursharthi Co-operative Transport Society Ltd., Abohar as on 25th March, 1965

Serial No.	Name of the Member		Father's name
1	Shri Ganpat Ram	..	Shri Sohan Lal
2	Shrimati Saraswati	..	Wife of Ganpat Ram
3	Shri Ganpat Ram	..	Shri Rati Ram
4	Shri Mani Ram	..	Shri Kanha Ram
5	Shri Dalip Singh	..	Shri Ganpat Ram
6	Shri Hanuman Dass		Shri Ganpat Ram
7	Shri Ganpat Ram		Shri Jai Raj
8	Shri Jung Singh	..	Shri Partap Singh
9	Shri Sheo Karan	..	Shri Ram Rakha
10	Shri Raja Ram	..	Shri Sohan Ram
11	Shrimati Raismi Devi	..	Widow of Phoola Ram
12	Shri Gopi Ram	..	Shri Hira Ram
13	Shri Bhajan Lal	..	Shri Ganesha Ram
14	Shri Kanshi Ram		Shri Ganga Ram
15	Shri Gopi Ram	..	Shri Kumbha Ram
16	Shri Harnaik Singh	..	Shri Gian Singh
17	Shri Ratna Ram	..	Shri Kaloo Ram
18	Shri Prahlad	..	Shri Ganesha Ram
19	Shri Sohan Lal	..	Shri Raishma Ram
20	Shri Ganpat Ram	..	Shri Ram Lal
21	Shri Mani Ram	..	Shri Ram Karan

ANNEXURE 'B'

List of members of share-holders of the Jai Transport Co-operative Society Ltd., Abohar

Serial No.	Name of the Member		Father's name
1	Shri Bachan Singh	..	Kapoor Singh
2	Shri Mohan Singh	..	Kapoor Singh
3	Shri Jaspal Singh	..	Bachan Singh
4	Baldev Singh	..	Bachan Singh

5	Mohinder Singh	..	Mohan Singh
6	Rajinder Singh	..	Mohan Singh
7	Jarnail Singh	..	Nazar Singh
8	Surjit Singh	..	Nazar Singh
9	Mukhtiar Singh	..	Kartar Singh
10	Sher Singh	..	Mal Singh
11	Bagar Singh	..	Mal Singh

Teachers appointed in district Ferozepore

2573. Sardar Kulbir Singh :
Chaudhri Satya Dev : } Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) the number of teachers appointed by the Government in Schools in district Ferozepore during the period from 1st July, 1957 to 30th September, 1957 on six months basis ;

(b) the number of the teachers out of those mentioned in part (a) above whose services have so far been regularised, year-wise, during the years 1960-61, 1961-62, 1962-63 and 1963-64 ;

(c) the list of the teachers with their addresses out of those mentioned in part (a) above, whose services have not so far been regularised although they fall in the same category as those mentioned in part (b) above, along with the reasons for not finalising their cases ;

(d) whether the department has prepared the seniority list of the said teachers, if not, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra : (a) 87 teachers appointed by the Local Bodies and not by Government.

(b) 1960-61	..	61
1961-62	..	17
1962-63	..	Nil
1963-64	..	9

(c) Nil.

(d) They have been included in the Seniority List of Provincialised Teachers.

APPLICATIONS PENDING FOR TUBEWELL CONNECTIONS IN TEHSIL FAZILKA

2574. Chaudhri Satya Dev: Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total number of applications for tubewell connections in tehsil Fazilka which are pending at present together with their details village-wise giving the names and address of each applicant ;

(b) the period for which the applications mentioned in part (a) above have been pendin , and the time by which the connections are likely to be given to the applicants?

Chaudhri Rizaq Ram : (a and b) 161

(A statement is as follows)

Pending Tube-well applications in tehsil Fazilka (P.S.E.B. Sub-Division Fazilka)

Serial No.	Name and Address	Date of Application	Probable date up to which connection is likely to be given
1	2	3	4
1	Shri Jagan Nath, village Ghrumi ..	30-1-63	Instructions have been issued to all the field Officers to give tube-well connections within three months from the receipt of test Reports. This is subject to availability of funds.
2	Shrimati Karmo Devi, village Chananwala	7-12-63	Ditto
3	Shri Khushal Chand, village Rampura ..	3-1-64	Ditto
4	Shri Bhag Singh, Windwala ..	6-1-64	Ditto
5	Shri Jamna Dass, Mohammad Pira ..	11-2-64	Ditto
6	Shri Nihal Chand, Mohammad Pira ..	11-2-64	Ditto
7	Shri Mangat Ram, Sultanpura ..	12-2-64	Ditto
8	Shri Tilak Raj, Sultanpura ..	12-2-64	Ditto
9	Shri Boota Singh, Pacca Chiste ..	18-2-64	Ditto
10	Shri Ram Singh, Pacca Chiste ..	18-2-64	Ditto
11	Shri Des Raj, Pacca Chiste ..	18-2-64	Ditto

Serial No.	Name and address	Date of Application	Probable date up to which connection is likely to be given
1	2	3	4
12	Shri Des Raj, Pacca Chiste ..	22-2-64	Instructions have been issued to all the field Officers to give tube-well connections within three months from the receipt of test Reports. This is subject to availability of funds.
13	Shri Ram Paul, Mohammad Pira ..	24-2-64	Ditto
14	Shri Kawahya Ram, village Morariwali	24-3-64	Ditto
15	Shri Dogar Ram, village Murariwali ..	24-2-64	Ditto
16	Shri Lal Chand, village Murariwali ..	24-2-64	Ditto
17	Shri Karim Chand, village Mohammad Pira	7-3-64	Ditto
18	Shri Sat Paul, village Khokhar ..	13-3-64	Ditto
19	Shri Roop Singh, village Awa ..	30-3-64	Ditto
20	Shri Hazoora Singh, village Awa ..	30-3-64	Ditto
21	Shri Shankar Dass, village Amirkhas ..	5-6-64	Ditto
22	Shri Ram Chand, Rampura ..	10-6-64	Ditto
23	Shri Rajinder Singh, Tallian Wali ..	20-6-64	Ditto
24	Ditto	20-6-64	Ditto
25	Ditto	20-6-64	Ditto
26	Ditto	20-6-64	Ditto
27	Ditto	20-6-64	Ditto
28	Shri Om Parkash, village Odian ..	1-7-64	Ditto
29	Shri Ram Chand, village Odian ..	1-7-64	Ditto
30	Shri Bhim Sen Rana, village Odian ..	13-8-64	Ditto
31	Shri Amar Dass, village Odian ..	13-8-64	Ditto
32	Shri Dev Mitter, village Odian ..	13-8-68	Ditto
33	Shri Bal Kishan ..	13-8-64	Ditto
34	Ditto ..	13-8-64	Ditto
35	Shri Mohri Ram, village Odian ..	13-8-64	Ditto
36	Shri Sewa Ram, village Odian ..	13-8-64	Ditto
37	Shri Om Parkash, village Odian ..	13-8-64	Ditto

Serial No.	Name and address	Date of Application	Probable date up to which connection is likely to be given
1	2	3	4
38	Shri Suraj Parkash, village Odian ..	13-8-64	Instructions have been issued to all the field Officers to give tube-well connections within three months from the receipt of test Reports. This is subject to availability of funds.
39	Shri Chela Ram, village Odian ..	13-8-64	Ditto
40	Shrimati Kailashwati, village Odian ..	13-8-64	Ditto
41	Shri Kewal Krishan, village Odian ..	13-8-64	Ditto
42	Shri Kundan Lal , village Odian ..	13-8-64	Ditto
43	Shri Kundan Lal, village Odian ..	13-8-64	Ditto
44	Shri Dev Mitter ..	13-8-64	Ditto
45	Shri Dev Mitter ..	13-8-64	Ditto
46	Ditto ..	13-8-64	Ditto
47	Ditto ..	13-8-64	Ditto
48	Shri Kashmiri Lal, village Odian ..	13-8-64	Ditto
49	Shri Gopal Dass, village Odian ..	13-8-64	Ditto
50	Shri Karam Chand, village Odian ..	13-8-64	Ditto
51	Shri Karam Chand, village Odian ..	13-8-64	Ditto
52	Shri Bura Ram, village Rana ..	13-8-64	Ditto
53	Shri Gohana Ram, village Rana ..	13-8-64	Ditto
54	Shri Munshi Ram village Rana ..	13-8-64	Ditto
55	Shri Bal Kishen, village Rana ..	13-8-64	Ditto
56	Shri Jaggu Ram, village Rana ..	13-8-64	Ditto
57	Shri Gohana Ram, village Rana ..	13-8-64	Ditto
58	Shri Jaggu Ram, village Rana ..	13-8-64	Ditto
59	Shri Jatha Ram,village Rana ..	13-8-64	Ditto
60	Shri Balkishan, village Rana ..	13-8-64	Ditto
61	Shrimati Lajwanti, village Rana ..	13-8-64	Ditto
62	Shri Ram Nath , village Ramkala ..	1-9-64	Ditto
63	Shri Harcharan Singh, village Sher Mohd.	14-9-64	Ditto
64	Shri Harbans Singh, village Chak Kath Gar	14-9-64	Ditto

Serial No.	Name and Address	Date of Application	Probable date up to which connections is likely to be given
1	2	3	4
65	Shri Hari Ram, Khippanwali ..	18-9-64	Instructions have been issued to all the field Officers to give tube-well connections within three months from the receipt of test Reports. This is subject to availability of funds.
66	Shi Jagir Singh, village Chakkathgarh	24-9-64	Ditto
67	Shri Chotu Ram, Khippanwali ..	18-9-64	Ditto
68	Shri Rattan Singh, village Chakathgarh	24-9-64	Ditto
69	Shri Gurbachan Singh, village Chakathgarh	24-9-64	Ditto
70	Shri Bhagat Singh, village Chakathgarh	24-9-64	Ditto
71	Shri Hoshiar Singh, Chakkathgarh ..	24-9-64	Ditto
72	Shri Uttam Singh, village Chakkathgarh..	24-9-64	Ditto
73	Shri Dalip Singh, village Chakkathgarh ..	24-9-64	Ditto
74	Shri Ram Parkash, village Odian ..	28-9-64	Ditto
75	Shri Om Parkash, Village Odian ..	28-9-64	Ditto
76	Shrimati Durga Devi, village Odian ..	28-9-64	Ditto
77	Shri Mohan Lal, village Odian ..	28-9-64	Ditto
78	Shri Chand Singh, village Odian ..	28-9-64	Ditto
79	Shri Harnarain, village Odian ..	28-9-64	Ditto
80	Shrimati Narain Devi ..	28-9-64	Ditto
81	Shri Mohan Lal Aggarwal, village Jallabad	23-10-64	Ditto
82	Shri Ujjagar Singh, village Sher Mohd ..	29-10-64	Ditto
83	Shri Amir Singh, village Sher Mohd. ..	29-10-64	Ditto
84	Shrimati Ram Piari, village Panchawali	30-10-64	Ditto
85	Shri Dewan Chand, village Ghumri ..	30-10-64	Ditto
86	Shri Jot Ram, village Churianwali ..	5-11-64	Ditto
87	Shri Giana Ram, village Churianwali ..	5-11-64	Ditto
88	Shri Beg Chand, village Churianwali ..	5-11-64	Ditto
89	Shri Hans Raj, Jallabad ..	5-11-64	Ditto
90	Shri Baldev Singh, village Jorke Kaukar Wali	6-11-64	Ditto
91	Shri Joginder Singh, village Jorke Kaukar Wali	6-11-64	Ditto

Serial No.	Name and Address	Date of Application	Probable date up to which connection is likely to be given
1	2	3	4
92	Shri Rachhpal Singh, village Jorke Kaukar Wali	6-11-64	Instructions have been issued to all the field Officers to give tube-well conncections within three months from the receipt of test Reports. This is subject to availability of funds
93	Shri Sukhpal Singh ..	6-11-64	Ditto
94	Shri Gurdip Singh, village Jorke Kaukar Wali	6-11-64	Ditto
95	Shri Jagir Singh, village Chaurianwali ..	23-11-64	Ditto
96	Shri Ajaib Singh, village Korianwali ..	23-11-64	Ditto
97	Shri Iqbal Chand, village Moranwali ..	23-11-64	Ditto
98	Shri Daulat Ram, village Moranwali ..	23-11-64	Ditto
99	Shri Jai Chand, village Moranwali ..	23-11-64	Ditto
100	Shri Harbhagwan Dass, village Amirkhas	24-11-64	Ditto
101	Shri John Ram, village Pir Mohal. ..	24-11-64	Ditto
102	Shri Pehalwan, village Pir Mohd. ..	24-11-64	Ditto
103	Shri Basawa Ram, village Amirkhas ..	24-11-64	Ditto
104	Shri Kishan Singh, village Amirkhas ..	26-11-64	Ditto
105	Shri Nathu Ram, Mauzam ..	1-12-64	Ditto
106	Shri Sunder Lal, village Mauzam ..	1-12-64	Ditto
107	Shri Manphool, village Beganwali ..	1-12-64	Ditto
108	Shri Barkat Lal Kamra, Jallabad ..	14-12-64	Ditto
109	Shri Kartar Singh, Jallabad ..	19-12-64	Ditto
110	Shri Ram Saran Dass, village Rampura ..	30-12-64	Ditto
111	Shri Lal Chand, village Pinchwali ..	31-12-64	Ditto
112	Shri Khushal Chand, village Rampura ..	31-12-64	Ditto
113	Shri Rajinder Singh, village Banwala ..	7-1-65	Ditto
114	Shri Mohla Ram, village Kananwal ..	8-1-65	Ditto
115	Shri Brij Lal, village Khippanwali ..	12-1-65	Ditto

Serial No	Name and Address	Date of Application	probable date up to which connection is likely to be given
1	2	3	4
116	Shri Chamba Ram, village Salemshah ..	12-1-65	Instructions have been issued to all the field Officers to give tube-well connoections within three months from the receipt of test Reports. This is subject to availability of funds.
117	Shri Mohan Lal, village Muthaianwali ..	12-1-65	Ditto
118	Shri Joginder Singh, village Banwala ..	1-2-65	Ditto
119	Ditto ..	1-2-65	Ditto
120	Shri Santokh Singh, village Jatwali ..	1-2-65	Ditto
121	Shri Kundan Lal, village Asafwali ..	1-2-65	Ditto
122	Shri Amar Nath, village Rampura ..	5-2-65	Ditto
123	Shri Lal Chand, village Salemshah ..	12-2-65	Ditto
124	Shri Ram Chand, village Gagankee ..	16-2-65	Ditto
125	Shri Hakim Singh village Gagankee ..	16-2-65	Ditto
126	Ditto ..	16-2-65	Ditto
127	Shri Inder Singh, village Gauguana ..	16-2-65	Ditto
128	Shri Balik Singh, village Moombaki ..	17-2-65	Ditto
129	Shri Nehal Singh, village Moombeki ..	17-2-65	Ditto
130	Shri Ganda Singh, village Moombeki ..	17-2-65	Ditto
131	Shri Bhajan Lal, village Qadar Box ..	19-2-65	Ditto
132	Shri Shopat Ram, village Beganwali ..	22-2-65	Ditto
133	Shri Hira Singh, village Kotha ..	22-2-65	Ditto
134	Shri Surja Ram, village Beganwali ..	22-2-65	Ditto
135	Shri Kishori Chand, village Kotha ..	22-2-65	Ditto
136	Smt. Kartar Kaur, village Khokhar ..	23-2-65	Ditto
137	Shri Gurbachan Singh, village Jaki Kankarwali	24-2-65	Ditto
138	Shri Gurbax Singh, village Jaki Kankarwali	24-2-65	Ditto
139	Ditto ..	24-2-65	Ditto
140	Shri Balwant Singh, village Jaki Kankarwali	24-2-65	Ditto
141	Shri Gurdarshan Singh, village Jaki Kankarwali	24-2-65	Ditto
142	Shri Kashmiri Lal, village Qabul Shah Hithar	24-2-65	Ditto

Serial No.	Name and Address	Date of Application	Probable date up to which connection is likely to be given
1	2	3	4
143	Shri Nathu Ram, village Karui Khera ..	2-3-65	Instructions have been issued to all the field Officers to give tube-well connections within three months from the receipt of test Reports. This is subject to availability of funds.
144	Shri Hakim Rai, village Rampura ..	3-3-65	Ditto
145	Shri Mohan Lal, village Awa ..	6-3-65	Ditto
146	Shri Mehar Chand, village Rampura ..	6-3-65	Ditto
147	Shri Murari Lal, Panchwali ..	8-3-65	Ditto
148	Shri Kartar Singh, village Mohammad ..	8-3-65	Ditto
149	Shri Banwari Lal, village Chananwala ..	10-3-65	Ditto
150	Shri Khushal Chand, village Ghamira ..	16-3-65	Ditto
151	Shri Choth Ram, village Sureshwala ..	16-3-65	Ditto
152	Shri Ram Chand, village Salemshah ..	16-3-65	Ditto
153	Shri Boota Ram, village Salemshah ..	16-3-65	Ditto
154	Shri Bhagwan Dass, village Salemshah ..	16-3-65	Ditto
155	Shri Baga Ram, village Salemshah ..	16-3-65	Ditto
156	Shri Malkiat Singh, village Korian Wali ..	20-3-65	Ditto
157	Shri Tilak Raj, village Mohammad Pira	20-3-65	Ditto
158	Shri Bachan Singh, village Moombeki	22-3-65	Ditto
159	Shri Balwant Singh, village Awa ..	22-3-65	Ditto
160	Shri Lachman Singh, village Bakhu Shah	23-3-65	Ditto
161	Shri Bhag Singh, village Bakhu Shah ..	23-3-65	Ditto

4604PVS—367—17-7-65—C.P. & S., Pb., Chandigarh.